CET-2026

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)

समान पात्रता परीक्षा

स्नातक स्तर – (हिन्दी माध्यम)

भाग - 4

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था
INDIAN POLITICAL SYSTEM

NODIA

अध्यायवार MCQs

Nodia

Scan QR for Demo PDF

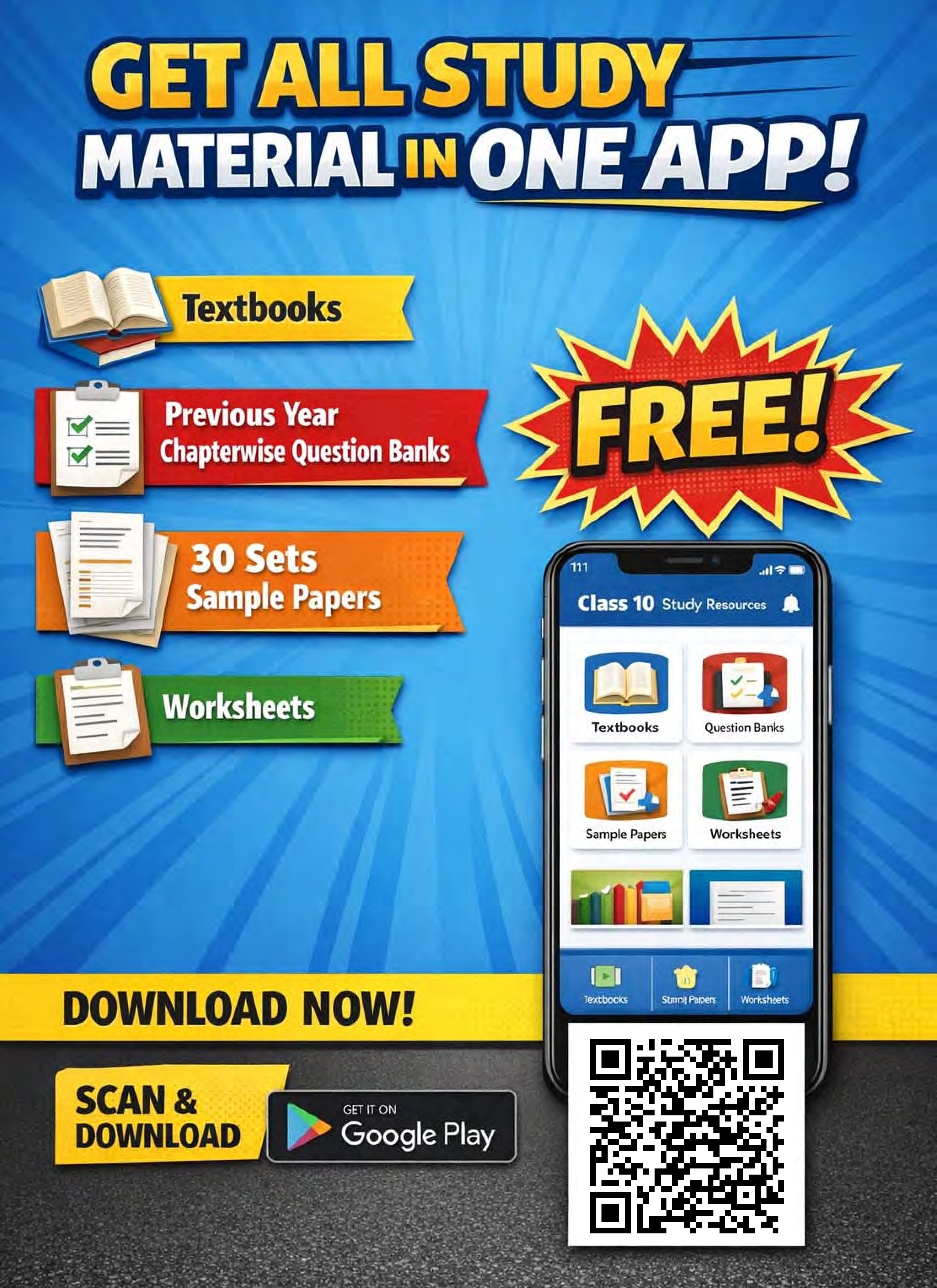
GET ALL STUDY
MATERIAL IN ONE APP!
Textbooks
Previous Year
Chapterwise Question Banks
30 Sets
Sample Papers
Worksheets
FREE!
Class 10 Study Resources
Textbooks
Question Banks
Sample Papers
Worksheets
DOWNLOAD NOW!
SCAN &
DOWNLOAD
GET IT ON
Google Play

RSSB 2026
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

COMMON ELIGIBILITY TEST (CET)
GRADUATE LEVEL
समान पात्रता परीक्षा
स्नातक स्तर

PART 4
INDIAN POLITICAL SYSTEM
भाग 4
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था

अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक
नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार

Nodia

Downloaded from www.pdf.tube

RSSB CET स्नातक स्तर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था भाग 4
Edition July 2026
Published by :Nodia
An Imprint of NODIA EDITIONS LLP

इस पुस्तक में निहित जानकारी लेखक द्वारा ऐसे स्त्रोतों से प्राप्त की गई है जिन्हें विश्वसनीय माना गया है। तथापि, Nodia तथा इसके लेखक इस पुस्तक में दी गई किसी भी जानकारी की शुद्धता, पूर्णता अथवा अद्यतनता की कोई गारंटी नहीं देते हैं। इस पुस्तक में किसी प्रकार की त्रुटि, चूक अथवा इसमें निहित जानकारी के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हानि के लिए Nodia तथा इसके लेखक उत्तरदायी नहीं होंगे। यह पुस्तक इस समझ के साथ प्रकाशित की गई है कि Nodia तथा इसके लेखक केवल सामान्य जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। इसका उद्देश्य अभियांत्रिकी (Engineering) अथवा किसी अन्य व्यावसायिक या विशेषज्ञ सेवा अथवा परामर्श प्रदान करना नहीं है।

NODIA

© NODIA EDITIONS LLP

MRP ₹450.00

NODIA EDITIONS LLP
125, Sector 6, Vidyadhar Nagar, Jaipur 302039
Phone :+91 9001005245
email : mail@nodia.in

विषय-सूची

अध्याय 1.	संविधान सभा	5
अध्याय 2.	भारतीय संविधान की प्रकृति एवं विशेषताएँ	30
अध्याय 3.	संघीय संरचना एवं केंद्र–राज्य संबंध	55
अध्याय 4.	प्रस्तावना एवं मौलिक कर्तव्य	82
अध्याय 5.	मौलिक अधिकार	111
अध्याय 6.	राज्य के नीति-निदेशक तत्व	139
अध्याय 7.	संवैधानिक संशोधन	164
अध्याय 8.	आपातकालीन प्रावधान	192
अध्याय 9.	केंद्रीय कार्यपालिका	221
अध्याय 10.	भारत की संसद	248
अध्याय 11.	भारत का सर्वोच्च न्यायालय एवं जनहित याचिका	275
अध्याय 12.	संघ के संवैधानिक एवं वैधानिक निकाय	303
अध्याय 13.	राजस्थान की राज्य कार्यपालिका	330
अध्याय 14.	राजस्थान की राज्य विधानसभा	358
अध्याय 15.	राजस्थान उच्च न्यायालय	386
अध्याय 16.	राजस्थान के राज्य निगरानी एवं वैधानिक निकाय	415

****

Click Here to Buy book on Amazon

NODIA

अध्याय 01
संविधान सभा

1. निम्नलिखित में से किसने 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था?
(A) जवाहरलाल नेहरू
(B) एम.एन. रॉय
(C) महात्मा गांधी
(D) सरदार वल्लभभाई पटेल

2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार किस वर्ष आधिकारिक रूप से भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की थी?
(A) 1928
(B) 1935
(C) 1940
(D) 1942

3. किस ब्रिटिश प्रस्ताव ने पहली बार सिद्धांत रूप में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था?
(A) अगस्त प्रस्ताव
(B) क्रिप्स मिशन
(C) कैबिनेट मिशन योजना
(D) वेवेल योजना

4. मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा से संबंधित क्रिप्स मिशन (1942) के प्रस्ताव को क्यों खारिज कर दिया गया था?
(A) इसने पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय तत्काल डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव रखा था।
(B) इसने देशी रियासतों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया।
(C) इसने दो अलग-अलग संविधान सभाओं के साथ दो स्वायत्त राज्यों की मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
(D) इसने प्रस्ताव रखा कि सभा के सभी सदस्यों को वायसराय द्वारा मनोनीत किया जाए।

5. भारत की संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई योजना के तहत किया गया था?
(A) कैबिनेट मिशन योजना, 1946
(B) माउंटबेटन योजना
(C) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
(D) क्रिप्स प्रस्ताव, 1942

6. कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी?
(A) 296
(B) 389
(C) 345
(D) 299

7. कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधियों का चुनाव संविधान सभा के लिए किस प्रकार किया जाना था?
(A) सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
(B) प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित
(C) भारत के गवर्नर-जनरल द्वारा मनोनीत
(D) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक विशेष समिति द्वारा चयनित

8. कैबिनेट मिशन योजना के तहत, प्रांतों और देशी रियासतों को सीटें आवंटित करने के लिए जनसंख्या का मानक अनुपात क्या रखा गया था?
(A) प्रत्येक एक लाख की जनसंख्या पर एक सीट
(B) प्रत्येक दस लाख की जनसंख्या पर एक सीट
(C) प्रत्येक बीस लाख की जनसंख्या पर एक सीट
(D) प्रत्येक पचास हजार की जनसंख्या पर एक सीट

9. संविधान सभा के चुनावों के उद्देश्य से, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को किन मान्यता प्राप्त समुदायों के बीच विभाजित किया गया था?
(A) हिंदू, मुस्लिम और ईसाई
(B) हिंदू, मुस्लिम, सिख और पारसी
(C) अनुसूचित जाति, मुस्लिम और सामान्य
(D) सामान्य, मुस्लिम और सिख

10. संविधान सभा के चुनावों में अपनाई गई मतदान पद्धति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधान सभा में उसी समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था।
II. मतदान एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति द्वारा होना था।
III. प्रतिनिधियों के चुनाव में गुप्त मतदान पूर्णतः प्रतिबंधित था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) I और II

Downloaded from www.pdf.tube

(B) II और III
(C) I और III
(D) I, II और III

11. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन 1946 में गठित संविधान सभा की प्रकृति का सबसे सही वर्णन करता है?
(A) सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित एक पूर्णतः निर्वाचित निकाय
(B) आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय
(C) पूर्णतः मनोनीत निकाय
(D) सीमित मताधिकार पर आधारित एक पूर्णतः निर्वाचित निकाय

12. जुलाई-अगस्त 1946 के दौरान ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए हुए चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थीं?
(A) 73
(B) 208
(C) 211
(D) 299

13. राजपूताना (राजस्थान) की निम्नलिखित में से किस देशी रियासत ने सर वी.टी. कृष्णमाचारी को संविधान सभा में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था?
(A) जयपुर
(B) जोधपुर
(C) उदयपुर (मेवाड़)
(D) बीकानेर

14. संविधान सभा की संरचना के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) सभा में ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों दोनों के प्रतिनिधि शामिल थे।
(B) संविधान सभा में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व था।
(C) महात्मा गांधी और एम.ए. जिन्ना सभा के प्रमुख सदस्य थे।
(D) प्रांतीय सभा के सदस्यों को चुनने के लिए मताधिकार सीमित था।

15. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (1946 में आवंटित/जीती गई सीटें)
P. कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित कुल सदस्य संख्या
Q. ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित सीटें
R. देशी रियासतों को आवंटित सीटें
S. मुस्लिम लीग द्वारा जीती गई सीटें
सूची II: (संख्या)
1. 296
2. 389
3. 73
4. 93
(A) P-2, Q-1, R-4, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-2, Q-1, R-3, S-4

16. संविधान सभा में एक-एक सीट आवंटित किए जाने वाले मुख्य आयुक्तों के चार प्रांत कौन-से थे?
(A) दिल्ली, अवध, कुर्ग और सिंध
(B) अजमेर-मेरवाड़ा, अवध, पेशावर और कुर्ग
(C) दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान
(D) दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, अंडमान और ब्रिटिश बलूचिस्तान

17. राजस्थान के किस प्रमुख नेता ने संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया और बाद में राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने?
(A) जयनारायण व्यास
(B) हीरालाल शास्त्री
(C) माणिक्य लाल वर्मा
(D) मोहन लाल सुखाड़िया

18. संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. प्रारंभ में उन्हें 93 सीटें आवंटित की गई थीं।
II. उनके प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों की प्रजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना था।
III. प्रारंभ में, उन्होंने संविधान सभा से अलग रहने का निर्णय लिया।
IV. माउंटबेटन योजना को स्वीकार किए जाने के बाद, अधिकांश देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) I, II और IV
(B) I, III और IV
(C) II, III और IV
(D) I, II, III और IV

19. माउंटबेटन योजना (1947) के तहत भारत के विभाजन के बाद, भारत की संविधान सभा की संशोधित कुल सदस्य संख्या कितनी थी?
(A) 284
(B) 299
(C) 318
(D) 389

20. किस प्रांत ने भारत की संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजे थे?
(A) मद्रास
(B) बॉम्बे
(C) संयुक्त प्रांत
(D) बिहार

NODIA

21. संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
(A) 15 अगस्त, 1946
(B) 26 नवंबर, 1946
(C) 9 दिसंबर, 1946
(D) 26 जनवरी, 1947

22. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष क्यों चुना गया था?
(A) कैबिनेट मिशन द्वारा उनकी सिफारिश की गई थी।
(B) वह उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
(C) उनका चुनाव सर्वसम्मति से गुप्त मतदान द्वारा हुआ था।
(D) फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए, वह सबसे वरिष्ठ सदस्य थे।

23. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया।
कारण (R): मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की अपनी मांग पर बल दिया।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

24. संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए थे?
(A) 208
(B) 211
(C) 284
(D) 389

25. निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा के उपाध्यक्ष (उप-सभापति) के रूप में चुना गया था?
(A) एच.सी. मुखर्जी
(B) के.एम. मुंशी
(C) वी.टी. कृष्णमाचारी
(D) (A) और (C) दोनों

26. 13 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक "उद्देश्य प्रस्ताव" किसने प्रस्तुत किया था?
(A) जवाहरलाल नेहरू
(B) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
(C) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
(D) सरदार वल्लभभाई पटेल

27. संविधान सभा ने किस तिथि को सर्वसम्मति से 'उद्देश्य प्रस्ताव' को स्वीकार किया था?
(A) 13 दिसंबर, 1946
(B) 22 जनवरी, 1947
(C) 15 अगस्त, 1947
(D) 26 नवंबर, 1949

28. उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की स्पष्ट घोषणा नहीं की गई थी?
(A) भारत का एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होना
(B) द्वि-दलीय राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत
(C) अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के लिए पर्याप्त संरक्षण
(D) सभी शक्तियों और अधिकारों का स्रोत जनता में निहित होना

29. उद्देश्य प्रस्ताव में निहित दर्शन और मूलभूत सिद्धांतों ने भारतीय संविधान के किस भाग के निर्माण को अत्यधिक प्रभावित किया?
(A) प्रस्तावना
(B) राज्य के नीति निदेशक तत्व
(C) आपातकालीन प्रावधान
(D) अनुसूचियां

30. संविधान सभा की घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) पहली बैठक → स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन → उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करना → उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करना
(B) उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करना → पहली बैठक → स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन → उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करना
(C) स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन → पहली बैठक → उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करना → उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करना
(D) पहली बैठक → उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करना → स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन → उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करना

31. संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे?
(A) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
(B) सरदार वल्लभभाई पटेल
(C) के.एम. मुंशी
(D) जवाहरलाल नेहरु

32. संविधान सभा की किस समिति ने केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित कार्य किया?
(A) संचालन समिति
(B) कार्य संचालन समिति
(C) संघ शक्ति समिति
(D) अल्पसंख्यक उप-समिति

33. संघ शक्ति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

Click Here to Buy book on Flipkart

I. इसने मूल रूप से कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार अपेक्षाकृत कमजोर केंद्र का समर्थन किया था।
II. विभाजन की घोषणा के बाद, इसने एक मजबूत केंद्र की वकालत की।
III. इसने संस्तुति की कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) I और II
(B) II और III
(C) I और III
(D) I, II और III

34. संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे?
(A) सरदार वल्लभभाई पटेल
(B) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
(C) जे.बी. कृपलानी
(D) जवाहरलाल नेहरू

35. संघ संविधान समिति ने भारतीय सरकार के लिए किस प्रकार की प्रणाली की सिफारिश की थी?
(A) संसदीय प्रणाली
(B) अध्यक्षात्मक प्रणाली
(C) एकात्मक केंद्रीय प्रणाली
(D) संवैधानिक राजतंत्र

36. संसदीय ढांचे के संबंध में संघ संविधान समिति की रिपोर्टों को किस संवैधानिक ढांचे ने अत्यधिक प्रभावित किया था?
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका का संवैधानिक ढांचा
(B) सोवियत संघ का संविधान
(C) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(D) फ्रांसीसी गणराज्य का संविधान

37. प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे?
(A) सरदार वल्लभभाई पटेल
(B) पंडित जवाहरलाल नेहरू
(C) डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर
(D) हरेंद्र कुमार मुखर्जी

38. प्रांतीय संविधान समिति ने प्रारंभ में सिफारिश की थी कि प्रांत का राज्यपाल होना चाहिए:
(A) भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत
(B) राज्य विधानमंडल द्वारा नामों के एक पैनल से चयनित
(C) एक वंशानुगत पद
(D) प्रांत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित

39. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): संविधान सभा ने अंततः निर्णय लिया कि राज्यपाल को निर्वाचित करने के बजाय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए।
कारण (R): एक निर्वाचित राज्यपाल, मनोनीत मुख्यमंत्री के साथ टकराव पैदा कर सकता है और राज्य में संसदीय लोकतंत्र को बाधित कर सकता है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

40. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: प्रांतीय संविधान समिति ने प्रांतीय कार्यपालिका और विधानमंडलों के ढांचे का प्रस्ताव रखा।
कथन II: प्रांतीय संविधान समिति की सिफारिशों को संघ संविधान समिति से परामर्श किए बिना पूरी तरह अंतिम रूप दिया गया था।
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

41. प्रारूप समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसका गठन 29 अगस्त, 1947 को किया गया था।
II. इसकी अध्यक्षता डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने की थी।
III. इसमें कुल 7 सदस्य थे।
IV. महात्मा गांधी इसके सलाहकार सदस्यों में से एक थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) I, II और III
(B) I, II और IV
(C) II, III और IV
(D) I, II, III और IV

42. निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था?
(A) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
(B) एन. गोपालस्वामी अयंगर
(C) अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
(D) डॉ. के.एम. मुंशी

43. 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति में उनका स्थान किसने लिया?
(A) एन. माधव राव
(B) टी.टी. कृष्णमाचारी
(C) बी.एल. मित्तर
(D) सैयद मोहम्मद सादुल्लाह

44. खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा देने के बाद प्रारूप समिति में बी.एल. मित्तर का स्थान किसने लिया?
(A) टी.टी. कृष्णमाचारी
(B) एन. माधव राव

Downloaded from www.pdf.tube

(C) के.एम. मुंशी
(D) एच.सी. मुखर्जी

45. प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप किस महीने और वर्ष में प्रकाशित किया था?
(A) अगस्त 1947
(B) फरवरी 1948
(C) अक्टूबर 1948
(D) नवंबर 1949

46. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मूल रूप से किस प्रांत से संविधान सभा के लिए चुने गए थे?
(A) बॉम्बे प्रेसीडेंसी
(B) मद्रास प्रेसीडेंसी
(C) बंगाल प्रांत
(D) मध्य प्रांत

47. भारत के विभाजन के बाद, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने बंगाल से अपनी सीट खो दी। इसके बाद वे किस प्रांत से पुनः संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए?
(A) आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत
(B) पंजाब प्रांत
(C) बिहार प्रांत
(D) बॉम्बे प्रेसीडेंसी

48. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (समिति)
P. संचालन समिति
Q. मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति
R. प्रारूप समिति
S. कार्य संचालन समिति
सूची II: (अध्यक्ष)
1. के.एम. मुंशी
2. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
3. सरदार वल्लभभाई पटेल
4. डॉ. राजेंद्र प्रसाद
(A) P-4, Q-3, R-2, S-1
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-4, Q-1, R-2, S-3
(D) P-1, Q-3, R-2, S-4

49. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को "संविधान की आत्मा और हृदय" कहा था?
(A) अनुच्छेद 14
(B) अनुच्छेद 19
(C) अनुच्छेद 21
(D) अनुच्छेद 32

50. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में दिए गए अपने प्रसिद्ध "अराजकता का व्याकरण" भाषण में किस विषय के प्रति चेतावनी दी थी?
(A) संवैधानिक राज्यों पर संघ (केंद्र) सरकार का अत्यधिक प्रभुत्व
(B) सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणालियों को निरंतर बनाए रखना
(C) राष्ट्रपति को प्रदान की गई अनियंत्रित कार्यपालिका शक्ति का संकेंद्रण
(D) सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा जैसे असंवैधानिक तरीके

51. डॉ. राजेंद्र प्रसाद को किस तिथि को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था?
(A) 9 दिसंबर, 1946
(B) 11 दिसंबर, 1946
(C) 13 दिसंबर, 1946
(D) 22 जनवरी, 1947

52. संविधान सभा के अध्यक्ष होने के अलावा, डॉ. राजेंद्र प्रसाद निम्नलिखित में से किस समिति के प्रमुख भी थे?
(A) संघ संविधान समिति
(B) अल्पसंख्यक उप-समिति
(C) प्रक्रिया नियम समिति
(D) प्रांतीय संविधान समिति

NODIA

53. राजस्थान के किस प्रमुख नेता, जो संविधान सभा के सदस्य थे, ने 'मेवाड़ प्रजामंडल' की स्थापना की थी?
(A) माणिक्य लाल वर्मा
(B) जयनारायण व्यास
(C) गोकुलभाई भट्ट
(D) बलवंत सिंह मेहता

54. सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. उन्होंने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों पर सलाहकार समिति की अध्यक्षता की।
II. उन्होंने भारतीय संघ में देशी रियासतों के विलय का कड़ा विरोध किया।
III. उन्होंने देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) I और II
(B) II और III
(C) I और III
(D) I, II और III

55. संविधान सभा की बहसों के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान की "राजनीतिक कुंडली" कहा था?
(A) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
(B) के.एम. मुंशी
(C) जवाहरलाल नेहरू
(D) सर बी.एन. राव

56. भारत का संविधान तैयार करने में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था?
(A) 2 वर्ष, 9 महीने और 15 दिन
(B) 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन
(C) 3 वर्ष, 1 महीना और 10 दिन
(D) 3 वर्ष, 11 महीने और 5 दिन

57. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): प्रारुप समिति ने संविधान को सभा में प्रस्तुत करने से पहले उसके प्रारुप की सूक्ष्मता से जांच और परिमार्जन किया।
कारण (R): संविधान का मूल प्रारुप संवैधानिक सलाहकार, सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

58. संविधान का प्रारुप पूरा करने के लिए संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित किए गए?
(A) 9 सत्र
(B) 11 सत्र
(C) 13 सत्र
(D) 15 सत्र

59. संविधान के निर्माण पर विचार-विमर्श करने और उसे तैयार करने के लिए संविधान सभा की कुल लगभग कितनी बैठकें (दिन) हुईं?
(A) 114 दिन
(B) 166 दिन
(C) 215 दिन
(D) 284 दिन

60. बहसों के दौरान, किस सूत्र ने भारत की राजभाषा के अत्यधिक विवादास्पद मुद्दे को हल किया?
(A) नेहरू-पटेल सूत्र
(B) मुंशी-आयंगर सूत्र
(C) अम्बेडकर-प्रसाद सूत्र
(D) कृपलानी-मुखर्जी सूत्र

61. राजभाषा से संबंधित समझौते के तहत, संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी को कितने वर्षों तक बनाए रखा जाना था?
(A) 10 वर्ष
(B) 15 वर्ष
(C) 20 वर्ष
(D) अनिश्चित काल के लिए

62. भाषा संबंधी बहस के दौरान संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रसिद्ध रुप से कहा था, "जो लोग हिंदुस्तानी नहीं जानते, उन्हें इस सभा में रहने का कोई अधिकार नहीं है"?
(A) सेठ गोविंद दास
(B) पुरुषोत्तम दास टंडन
(C) आर.वी. धुलेकर
(D) के.एम. मुंशी

63. अल्पसंख्यक अधिकारों के संबंध में, संविधान सभा ने निर्णायक रुप से क्या निर्णय लिया?
(A) सभी मान्यता प्राप्त धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली को बनाए रखना
(B) धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए स्थायी आरक्षित सीटों की गारंटी देते हुए पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करना
(C) केवल आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान करना
(D) पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करना और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करना

64. संविधान सभा में अल्पसंख्यक उप-समिति की अध्यक्षता किसने की थी?
(A) सरदार वल्लभभाई पटेल
(B) जे.बी. कृपलानी
(C) एच.सी. मुखर्जी
(D) गोपीनाथ बोरदोलोई

65. संविधान सभा में संघवाद पर बहस मुख्य रूप से किस कारण से एक मजबूत केंद्र की ओर स्थानांतरित हुई?
(A) कैबिनेट मिशन योजना में निर्धारित अनिवार्य वैधानिक निर्देश
(B) विभाजन की प्रशासनिक वास्तविकताएं और त्रासदी
(C) देशी रियासतों के शासकों द्वारा की गई निरंतर संवैधानिक मांगें
(D) ब्रिटिश इंपीरियल संसद द्वारा डाला गया प्रत्यक्ष राजनीतिक दबाव

66. संविधान सभा के किस सदस्य ने वित्तीय संघवाद के पक्ष में जोरदार तर्क दिया और चेतावनी दी कि यदि वित्तीय शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया तो प्रांत "केंद्र के दरवाजे पर भिखारी" बन जाएंगे?
(A) एच.एन. कुंजरू
(B) टी.टी. कृष्णमाचारी
(C) अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
(D) के. संथानम

67. संघवाद पर हुई बहसों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. डॉ. अम्बेडकर ने संविधान को सामान्य समय में संघात्मक लेकिन आपातकाल के दौरान एकात्मक बताया।

Click Here to Buy book on Amazon

II. क्षेत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए अवशिष्ट शक्तियां प्रांतीय विधानमंडलों को सौंपी गईं।
III. संघात्मक ढांचे के बावजूद सभा एकीकृत न्यायपालिका पर सहमत हुई।
IV. राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए केंद्र की क्षमता को मजबूत करने हेतु आपातकालीन प्रावधान जोड़े गए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) I, II और IV
(B) I, III और IV
(C) II, III और IV
(D) I, II, III और IV

68. भारत के संविधान को किस तिथि को औपचारिक रूप से अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था?

(A) 15 अगस्त, 1947
(B) 26 नवंबर, 1949
(C) 24 जनवरी, 1950
(D) 26 जनवरी, 1950

69. 26 नवंबर, 1949 को अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए संविधान सभा के कितने सदस्य भौतिक रूप से उपस्थित थे?

(A) 211
(B) 284
(C) 299
(D) 389

70. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:

सूची I: (प्रावधान)

P. नागरिकता संबंधी प्रावधान
Q. चुनाव संबंधी प्रावधान
R. मूल अधिकार
S. राज्य के नीति निदेशक तत्व

सूची II: (लागू होने की तिथि)

1. 26 नवंबर 1949
2. 26 जनवरी 1950

(A) P-1, Q-1, R-2, S-2
(B) P-2, Q-2, R-1, S-1
(C) P-1, Q-2, R-1, S-2
(D) P-2, Q-1, R-2, S-1

71. संविधान को अंगीकृत किए जाने के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।

(A) प्रारूप संविधान पर अंतिम औपचारिक प्रस्ताव 26 नवंबर, 1949 को पारित घोषित किया गया था।
(B) प्रस्तावना को संविधान के शेष भाग से पहले अंगीकृत किया गया था।
(C) भारतीय संविधान का पूरा मूल पाठ अंग्रेजी में पूरी तरह से हस्तलिखित था।
(D) अंतिम रूप से अंगीकृत संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थीं।

72. संविधान लागू होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी, 1950 को विशेष रुप से क्यों चुना गया था?

(A) यह भारत छोड़ो आंदोलन की आधिकारिक राष्ट्रव्यापी वर्षगांठ थी।
(B) यह वही ऐतिहासिक दिन था जब कैबिनेट मिशन योजना प्रकाशित हुई थी।
(C) 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति में।
(D) यह लॉर्ड माउंटबेटन के जन्मदिन के आधिकारिक सार्वजनिक उत्सव के साथ मेल खाता था।

73. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 को निरस्त करने का प्रावधान किया?

(A) अनुच्छेद 368
(B) अनुच्छेद 393
(C) अनुच्छेद 394
(D) अनुच्छेद 395

NODIA

74. संविधान सभा ने अंतरिम संसद में परिवर्तित होने से पहले अपना अंतिम सत्र कब आयोजित किया था?

(A) 26 नवंबर, 1949
(B) 24 जनवरी, 1950
(C) 26 जनवरी, 1950
(D) 15 अगस्त, 1950

75. संविधान सभा में प्रारूप संविधान के निम्नलिखित वाचनों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:

1. प्रथम वाचन (सामान्य चर्चा)
2. तृतीय वाचन (अंतिम पारित प्रस्ताव)
3. द्वितीय वाचन (खंडवार विचार-विमर्श)

सही कूट का चयन कीजिए:

(A) 1, 2, 3
(B) 1, 3, 2
(C) 3, 1, 2
(D) 2, 1, 3

76. 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य नहीं किया गया था?

(A) राष्ट्रगान को अंगीकार करना
(B) राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन
(C) राष्ट्रगीत को अंगीकार करना
(D) डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुनना

77. संविधान सभा ने दोहरी भूमिका में कार्य किया। जब यह एक विधायिका (विधायी निकाय) के रूप में मिलती थी, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता था?

(A) जी.वी. मावलंकर
(B) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
(C) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
(D) एच.सी. मुखर्जी

78. भारत की अंतरिम संसद का कार्यकाल क्या था?
(A) 1947 से 1950
(B) 1950 से 1952
(C) 1950 से 1955
(D) 1946 से 1952

79. अंतरिम संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसमें संविधान सभा के सदस्य शामिल थे।
II. इसने 1951 में संविधान का पहला संशोधन अधिनियम पारित किया।
III. इसने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 पारित किया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) I और II
(B) II और III
(C) I और III
(D) I, II और III

80. संविधान सभा की एक प्रमुख आलोचना यह थी कि यह एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। इस आलोचना का मुख्य तथ्यात्मक आधार क्या है?
(A) इसने भारतीय देशी रियासतों के सभी आधिकारिक प्रतिनिधियों को पूरी तरह से बाहर रखा।
(B) यह ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार द्वारा सीधे चुनी गई एक पूरी तरह से मनोनीत सलाहकार परिषद थी।
(C) इसके सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थे।
(D) इसने प्रमुख धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के सभी आधिकारिक प्रतिनिधियों को व्यवस्थित रूप से बाहर कर दिया।

81. किस विद्वान ने संविधान सभा के बारे में यह प्रसिद्ध टिप्पणी की थी कि "संविधान सभा मूलतः एक-दलीय देश में एक-दलीय निकाय थी। सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था"?
(A) आइवर जेनिंग्स
(B) ग्रैनविल ऑस्टिन
(C) विंस्टन चर्चिल
(D) लॉर्ड विकाउंट साइमन

82. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): विंस्टन चर्चिल ने यह कहकर संविधान सभा की आलोचना की कि यह "भारत के केवल एक बड़े समुदाय" का प्रतिनिधित्व करती है।
कारण (R): मुस्लिम लीग के सदस्यों ने सभा का बहिष्कार किया था, जिससे यह काफी हद तक हिंदू-बहुसंख्यक कांग्रेस सदस्यों के वर्चस्व वाली बन गई थी।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

83. संविधान सभा के "वकील-राजनीतिज्ञ" वर्चस्व वाले निकाय होने की आलोचना का अर्थ है कि:
(A) कानूनी भाषा और संविधान का आकार उनके प्रभाव को दर्शाता है।
(B) सभी निर्वाचित सदस्यों के लिए इंग्लैंड से कानून की डिग्री होना अनिवार्य था।
(C) केवल अभ्यास करने वाले कानूनी विशेषज्ञों को ही संवैधानिक धाराओं का प्रारूप तैयार करने की अनुमति थी।
(D) सक्रिय राजनीतिक नेताओं को प्रमुख प्रारूप समितियों में सेवा करने से सख्ती से बाहर रखा गया था।

84. भारत की संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं?
(A) 9
(B) 11
(C) 15
(D) 21

85. निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य थीं?
(A) दक्षायाणी वेलायुधन
(B) सरोजिनी नायडू चट्टोपाध्याय
(C) हंसा जीवराज मेहता
(D) श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन

86. संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला प्रतिनिधि कौन थीं?
(A) लेडी फातिमा जिन्ना
(B) तजामुल हुसैन
(C) कुदसिया एजाज
(D) बेगम एजाज रसूल

87. संविधान सभा की किस महिला सदस्य ने भारत की महिलाओं की ओर से सभा को राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तुत किया था?
(A) सरोजिनी नायडू
(B) हंसा मेहता
(C) दुर्गाबाई देशमुख
(D) सुचेता कृपलानी

88. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: संविधान सभा ने आंग्ल-भारतीय, पारसी और भारतीय ईसाइयों सहित अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया।
कथन II: फ्रैंक एंथनी ने संविधान सभा में पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया।
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

Downloaded from www.pdf.tube

(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

89. अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. एच.सी. मुखर्जी ने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया।
II. एच.पी. मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया।
III. फ्रैंक एंथनी ने आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किया।
IV. जयपाल सिंह मुंडा ने जनजातीय समुदायों का प्रतिनिधित्व किया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) I और II
(B) II, III और IV
(C) I, III और IV
(D) I, II, III और IV

90. संविधान सभा के किस प्रमुख नेता ने आदिवासी अधिकारों की वकालत की और आदिवासी महासभा का नेतृत्व किया?
(A) जयपाल सिंह मुंडा
(B) अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर
(C) गोपीनाथ बोरदोलोई
(D) जे.जे.एम. निकोलस रॉय

91. संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप-समिति के अध्यक्ष कौन थे?
(A) सरदार वल्लभभाई पटेल
(B) जे.बी. कृपलानी
(C) के.एम. मुंशी
(D) अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर

92. मौलिक अधिकारों का प्रारूप तैयार करते समय, संविधान सभा ने किस शब्दावली के स्थान पर जानबूझकर "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" शब्द को चुना?
(A) विधि का शासन
(B) विधि की सम्यक प्रक्रिया
(C) विधि के समक्ष समता
(D) प्राकृतिक न्याय

93. अधिकारों को न्यायोचित (मौलिक अधिकार) और गैर-न्यायोचित (नीति निदेशक तत्व) में विभाजित करने का विचार किसके सुझाव से अत्यधिक प्रभावित था?
(A) सर बी.एन. राव
(B) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
(C) के.एम. मुंशी
(D) महात्मा गांधी

94. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (महिला सदस्य)
P. सरोजिनी नायडू
Q. हंसा मेहता
R. दुर्गाबाई देशमुख
S. अमृत कौर
सूची II: (राज्य/प्रांत)
1. बॉम्बे
2. मद्रास
3. बिहार
4. मध्य प्रांत / संयुक्त प्रांत
(A) P-3, Q-1, R-2, S-4
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-1, R-2, S-3
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

95. संविधान सभा ने किस सामाजिक बुराई को पूरी तरह से समाप्त करने पर आम सहमति बनाई और इसे मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया?
(A) बाल विवाह
(B) दहेज प्रथा
(C) सती प्रथा
(D) अस्पृश्यता (छुआछूत)

NODIA

96. संविधान सभा द्वारा अंगीकृत राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से अत्यधिक प्रेरित थे?
(A) अमेरिका
(B) कनाडा
(C) आयरलैंड
(D) सोवियत संघ

97. संविधान सभा के किस सदस्य ने नीति निदेशक तत्वों की आलोचना करते हुए उन्हें "एक ऐसा चेक कहा जिसका भुगतान बैंक के संसाधनों पर निर्भर करता है"?
(A) टी.टी. कृष्णमाचारी
(B) के.टी. शाह
(C) के.सी. व्हीयर
(D) एच.वी. कामथ

98. राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा को समाहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिद्धांतों को नीति निदेशक तत्वों में जानबूझकर शामिल किया गया था?
(A) साम्यवादी सिद्धांत
(B) धर्मतांत्रिक सिद्धांत
(C) साम्राज्यवादी सिद्धांत
(D) गांधीवादी सिद्धांत

99. संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप दिए गए अनुच्छेद 37 के अनुसार, नीति निदेशक तत्व हैं:
(A) देश के शासन में मूलभूत
(B) सर्वोच्च न्यायालय में पूर्णतः न्यायोचित
(C) किसी भी न्यायालय द्वारा सीधे लागू करने योग्य
(D) देश के सभी सामान्य कानूनों के अधीन

100. संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसने कार्य किया?
(A) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
(B) के.एम. मुंशी
(C) सर बी.एन. राव
(D) एस.एन. मुखर्जी

101. उदयपुर के किस प्रमुख राजस्थानी व्यक्तित्व ने संविधान सभा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए?
(A) बलवंत सिंह मेहता
(B) शाहपुरा के गोकुल लाल असावा
(C) भूरिलाल बया
(D) मोतीलाल तेजावत

102. संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे?
(A) सर बी.एन. राव
(B) प्रेम बिहारी नारायण रायजादा
(C) एन. गोपालस्वामी अयंगर
(D) एस.एन. मुखर्जी

103. भारतीय संविधान के मूल अंग्रेजी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था?
(A) आचार्य नंदलाल बोस
(B) प्रेम बिहारी रायजादा
(C) बियोहर राममनोहर सिन्हा
(D) वसंत कृष्ण वैद्य

104. शांतिनिकेतन के निम्नलिखित कलाकारों में से कौन संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि को अलंकृत और चित्रित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था?
(A) अवनिंद्रनाथ टैगोर
(B) जामिनी रॉय
(C) नंदलाल बोस
(D) अमृता शेरगिल

105. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी।
कारण (R): यह ब्रिटिश संसद द्वारा बनाई गई थी और भारत के लिए बनाए गए किसी भी ब्रिटिश कानून को रद्द या परिवर्तित नहीं कर सकती थी।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

106. संविधान सभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया के रूप में "सामंजस्य" की अवधारणा का अर्थ था कि:
(A) एक सामान्य मध्य मार्ग तक पहुँचने के लिए विरोधी दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित किया गया।
(B) निर्णय सख्ती से और विशेष रूप से औपचारिक बहुमत मतदान प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित किए गए थे।
(C) सभा ने ब्रिटिश वायसराय द्वारा जारी राजनीतिक मांगों को पूरी तरह से समायोजित किया।
(D) सभा ने उपस्थित सभी सदस्यों को मुफ्त आवासीय आवास सुविधाएं प्रदान कीं।

107. राजस्थान की निम्नलिखित में से किस देशी रियासत के संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि थे?
(A) जोधपुर
(B) जयपुर
(C) बीकानेर
(D) उदयपुर

108. संविधान सभा द्वारा अपनाई गई सील (मुहर) में किस पशु का प्रतीक था?
(A) शेर
(B) हाथी
(C) बाघ
(D) बैल

109. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (राजस्थान के प्रतिनिधि)
P. मुकुट बिहारी लाल भार्गव
Q. माणिक्य लाल वर्मा
R. जयनारायण व्यास
S. वी.टी. कृष्णमाचारी
सूची II: (देशी रियासत/क्षेत्र)
1. जोधपुर
2. अजमेर-मेरवाड़ा
3. जयपुर
4. उदयपुर
(A) P-2, Q-4, R-1, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

110. कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलावा, कौन सा राजनीतिक दल 1946 में संविधान सभा के चुनावों में सीट जीतने में सफल रहा?
(A) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
(B) यूनियनिस्ट पार्टी
(C) कृषक प्रजा पार्टी
(D) उपर्युक्त सभी ने कम से कम एक सीट जीती

111. वह सटीक तिथि क्या थी जिस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुसमर्थन किया था?
(A) अगस्त 1947
(B) मई 1949

Click Here to Buy book on Flipkart

(C) नवंबर 1949
(D) जनवरी 1950

112. संविधान सभा में सिख प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. पंजाब प्रांत में सिखों के लिए विशेष रुप से सीटें आरक्षित थीं।
II. सरदार हुकम सिंह और उज्ज्वल सिंह प्रमुख सिख प्रतिनिधि थे।
III. सिख प्रतिनिधियों ने सभा ढाँचे के भीतर एक अलग सिख राज्य की मांग की।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) I और II
(B) II और III
(C) I और III
(D) I, II और III

113. 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया था। इसे निम्नलिखित में से कौन-सी शक्ति प्रदान की गई थी?
(A) ब्रिटिश क्राउन की ओर से विदेशी संप्रभु राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना।
(B) भारत के लिए बनाए गए किसी भी ब्रिटिश कानून को रद्द करने या बदलने की।
(C) यूनाइटेड किंगडम के लिए एक व्यापक बाध्यकारी संविधान तैयार करने की।
(D) पाकिस्तान के गवर्नर-जनरल को आधिकारिक रूप से मनोनीत और नियुक्त करने की।

114. संविधान सभा का पहला सत्र किस तिथि को समाप्त हुआ था?
(A) 23 दिसंबर, 1946
(B) 31 दिसंबर, 1946
(C) 22 जनवरी, 1947
(D) 15 अगस्त, 1947

115. किस देशी रियासत ने प्रारंभ में संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया था और केवल पुलिस कार्रवाई (ऑपरेशन पोलो) के बाद ही इसका विलय हुआ?
(A) हैदराबाद
(B) जूनागढ़
(C) कश्मीर
(D) त्रावणकोर

116. संविधान सभा के सचिव कौन थे?
(A) एस.एन. मुखर्जी
(B) के.एम. मुंशी
(C) एच.वी.आर. अयंगर
(D) बी.एन. राव

117. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: संविधान सभा ने अपने सत्र संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किए।
कथन II: जनता और प्रेस को संविधान सभा के सत्रों में भाग लेने से पूरी तरह से रोक दिया गया था।
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

NODIA

118. किस प्रमुख नेता और स्वतंत्रता सेनानी ने संविधान सभा का सदस्य न बनने का दृढ़ निर्णय लिया था?
(A) मौलाना अबुल कलाम आजाद
(B) राजेंद्र प्रसाद
(C) सी. राजगोपालाचारी
(D) महात्मा गांधी

119. संविधान सभा की निम्नलिखित प्रमुख समितियों को उनके सामान्य रिपोर्टिंग चरण (प्रारुपण प्रक्रिया में सबसे पहले से अंतिम) के कालानुक्रमिक क्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए:
1. प्रारुप समिति
2. संघ शक्ति समिति
3. मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति
सही कूट का चयन कीजिए:
(A) 2, 3, 1
(B) 1, 2, 3
(C) 3, 2, 1
(D) 2, 1, 3

120. संविधान सभा के संदर्भ में, 'निर्देशों के साधन' शब्द किसे संदर्भित करता है?
(A) ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्रतिनिधिमंडल द्वारा जारी प्रत्यक्ष राजनीतिक दिशा-निर्देश
(B) डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा तैयार किए गए प्रक्रियात्मक नियम और आंतरिक दिशा-निर्देश
(C) 1935 के अधिनियम के वे प्रावधान जिन्होंने नीति निदेशक तत्वों को प्रभावित किया
(D) ब्रिटिश वायसराय द्वारा सभा को जारी किए गए बाध्यकारी प्रशासनिक आदेश

121. संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे?
(A) कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी
(B) जे.बी. कृपलानी
(C) एच.सी. मुखर्जी
(D) बी. पट्टाभि सीतारमैया

122. गांधीवादी आदर्शों को दर्शाते हुए किस सदस्य ने संविधान में ग्राम पंचायतों को शामिल करने की जोरदार वकालत की थी?
(A) के. संथानम
(B) जवाहरलाल नेहरु
(C) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

(D) बी.एन. राव

123. मौलिक अधिकारों पर बहस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. आर्थिक अधिकारों को न्यायोचित बनाने पर गहन बहस हुई थी।

II. सभा प्रारंभ में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से बाहर रखने पर सर्वसम्मति से सहमत हुई थी।

III. निवारक निरोध के प्रावधान के संभावित दुरुपयोग पर अत्यधिक बहस हुई थी।

IV. सभा ने वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने का निर्णय लिया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) I, II और III
(B) I, III और IV
(C) II, III और IV
(D) I, II, III और IV

124. किस भारतीय राज्य का संविधान भारत की संविधान सभा द्वारा तैयार नहीं किया गया था?

(A) हैदराबाद देशी रियासत
(B) जम्मू और कश्मीर
(C) मैसूर देशी रियासत
(D) जूनागढ़ देशी रियासत

125. संविधान सभा की प्रत्यय-पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे?

(A) अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
(B) सरदार वल्लभभाई झवेरभाई पटेल
(C) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
(D) पंडित जवाहरलाल नेहरु

126. संविधान सभा की विरासत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. इसने बिना किसी बड़े निष्कासन या विभाजन के विविध दृष्टिकोणों का सफलतापूर्वक समायोजन किया।

II. अधिकांश निर्णय साधारण बहुमत से मतदान के बजाय सर्वसम्मति के सिद्धांत द्वारा लिए गए थे।

III. इसके कामकाज ने स्वतंत्र भारत की संसद के लिए मजबूत लोकतांत्रिक परंपराएं स्थापित कीं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) I और II
(B) II और III
(C) I और III
(D) I, II और III

127. संविधान सभा के प्रमुख संरचनात्मक मील के पत्थरों का सही कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन-सा है?

(A) कैबिनेट मिशन योजना → उद्देश्य प्रस्ताव → प्रारुप समिति का गठन → संविधान को अंगीकार करना
(B) उद्देश्य प्रस्ताव → कैबिनेट मिशन योजना → प्रारुप समिति का गठन → संविधान को अंगीकार करना
(C) कैबिनेट मिशन योजना → प्रारुप समिति का गठन → उद्देश्य प्रस्ताव → संविधान को अंगीकार करना
(D) प्रारुप समिति का गठन → कैबिनेट मिशन योजना → उद्देश्य प्रस्ताव → संविधान को अंगीकार करना

128. संविधान निर्माण में संविधान सभा द्वारा कुल कितना अनुमानित खर्च किया गया था?

(A) ₹34 लाख
(B) ₹64 लाख
(C) ₹1 करोड़
(D) ₹2.5 करोड़

129. संविधान सभा की मांग को अंततः अंग्रेजों ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में 'सिद्धांत रुप से' स्वीकार कर लिया था। उस समय भारत का वायसराय कौन था?

(A) लॉर्ड वेवेल
(B) लॉर्ड लिनलिथगो
(C) लॉर्ड माउंटबेटन
(D) लॉर्ड इरविन

130. राजपूताना के निम्नलिखित नेताओं में से कौन संविधान सभा के लिए चुने गए थे और बाद में प्रसिद्ध पुस्तक "पंचायती राज" के लेखक बने?

(A) हीरालाल शास्त्री
(B) जयनारायण व्यास
(C) तिरुवल्लूर थट्टै कृष्णमाचारी
(D) बलवंत सिंह मेहता

www.nodia.in

NODIA

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) एम.एन. रॉय
भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1934 में मानवेन्द्र नाथ रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वह भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। उनके इस व्यावहारिक सुझाव के पश्चात वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अंततः वर्ष 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इस ऐतिहासिक विचार को व्यावहारिक रूप में क्रियान्वित किया गया।

2. (B) 1935
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार वर्ष 1935 में आधिकारिक रूप से भारत के संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा के गठन की मांग की थी। इससे पूर्व वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा यह विचार व्यक्तिगत रूप से रखा गया था। कांग्रेस के इस आधिकारिक संकल्प के पश्चात वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित सभा द्वारा बनाया जाएगा।

3. (A) अगस्त प्रस्ताव
ब्रिटिश सरकार ने पहली बार वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव में सिद्धांत रूप से भारतीय संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव में कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात मुख्यतः भारतीयों को मिलाकर एक संविधान निर्मात्री परिषद गठित की जाएगी। यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने विभिन्न राजनीतिक कारणों से इस प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया था।

4. (C) उसने दो अलग-अलग संविधान सभाओं के साथ दो स्वायत्त राज्यों की मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
वर्ष 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आए क्रिप्स मिशन ने एकल संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था। मुस्लिम लीग ने इस योजना को इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में विभाजित करके दो पृथक संविधान सभाओं की स्थापना चाहती थी। मुस्लिम लीग की मुख्य राजनीतिक मांग पृथक देश पाकिस्तान के निर्माण की थी, जिसे क्रिप्स प्रस्तावों में स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया था।

5. (A) कैबिनेट मिशन योजना, 1946
भारत की संविधान सभा का गठन वर्ष 1946 में आई कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था। इस मिशन में तीन ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर शामिल थे। कैबिनेट मिशन ने दो पृथक संविधान सभाओं की मांग को तो खारिज कर दिया, किंतु उसने एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट किया और भारत में संविधान सभा के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।

6. (B) 389
कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए और 93 सीटें देशी रियासतों के लिए आवंटित की गई थीं। ब्रिटिश भारत को दी गई 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन ग्यारह गवर्नर वाले प्रांतों से और 4 सदस्यों का चयन चार मुख्य आयुक्तों के प्रांतों (दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान) से प्रत्येक से एक-एक किया जाना तय हुआ था।

7. (B) प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाना था। इस चुनाव में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ था क्योंकि उस समय प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव स्वयं सीमित मताधिकार पर आधारित थे। प्रांतीय विधान सभाओं में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों ने एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करके अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया।

8. (B) प्रत्येक दस लाख की जनसंख्या पर एक सीट
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रांत और देशी रियासत (या रियासतों के समूह) को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थीं। इसके लिए मोटा मानक यह रखा गया था कि प्रत्येक दस लाख (एक मिलियन) की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक सीट आवंटित की जाएगी। इस प्रणाली का उद्देश्य सभी क्षेत्रों और प्रांतों को उनकी आबादी के अनुसार न्यायसंगत और संतुलित प्रतिनिधित्व प्रदान करना था।

9. (D) सामान्य, मुस्लिम और सिख
संविधान सभा के चुनावों के लिए प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में तीन मुख्य मान्यता प्राप्त समुदायों में विभाजित किया गया था। ये तीन समुदाय सामान्य, मुस्लिम और सिख (केवल पंजाब में) थे। 'सामान्य' वर्ग के अंतर्गत मुस्लिम और सिख समुदायों को छोड़कर शेष सभी धार्मिक और सामाजिक वर्गों को शामिल किया गया था, ताकि प्रांतीय स्तर पर सभी प्रमुख जनसमूहों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

Downloaded from www.pdf.tube

10. (A) I और II
प्रांतीय विधान सभाओं में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव उसी समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। यह मतदान प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर संपन्न हुई थी। हालांकि, चुनाव में गुप्त मतदान का प्रयोग किया गया था, इसलिए खुला या प्रतिबंधित मतदान का कथन असत्य है। इस प्रकार केवल पहला और दूसरा कथन पूरी तरह से सही और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुकूल हैं।

11. (B) आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय
वर्ष 1946 में गठित भारत की संविधान सभा एक आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी। इसके ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का मनोनयन वहां के देशी राजाओं या प्रमुख शासकों द्वारा किया जाना तय हुआ था। इस प्रकार यह निकाय पूरी तरह से प्रत्यक्ष निर्वाचित या पूर्णतः मनोनीत नहीं था।

12. (B) 208
जुलाई-अगस्त 1946 में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे। इन चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 208 सीटों पर जीत दर्ज की। दूसरी ओर, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीतीं और छोटे समूहों तथा स्वतंत्र उम्मीदवारों को शेष 15 सीटें प्राप्त हुईं। कांग्रेस की इस विशाल जीत ने संविधान सभा में उसके प्रभाव को अत्यधिक मजबूत बना दिया था।

13. (A) जयपुर
राजपूताना की प्रतिष्ठित जयपुर देशी रियासत ने सर वेगल तिरुवेन्कट कृष्णमाचारी (सर वी.टी. कृष्णमाचारी) को संविधान सभा में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। वह एक अत्यंत योग्य प्रशासक और दीवान थे जिन्होंने जयपुर रियासत का प्रतिनिधित्व करते हुए संविधान निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाद में वह संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में भी चुने गए थे और उन्होंने विभिन्न संवैधानिक बैठकों का कुशलतापूर्वक संचालन किया था।

14. (C) महात्मा गांधी और एम.ए. जिन्ना सभा के प्रमुख सदस्य थे।
संविधान सभा में भारत के लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व शामिल थे, किंतु महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना इसके सदस्य नहीं थे। गांधी जी ने जानबूझकर इस सभा से दूर रहने का निर्णय लिया था, जबकि जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को लेकर सभा का बहिष्कार किया था। सभा में ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि तथा महिलाएं शामिल थीं और प्रांतीय सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार पर आधारित था।

15. (A) P-2, Q-1, R-4, S-3
कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इसमें से ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को 296 सीटें और देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की गई थीं। 1946 के प्रांतीय चुनावों के दौरान मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। इन सभी आंकड़ों का सही मेल P-2, Q-1, R-4 और S-3 के रूप में पूरी तरह स्पष्ट और सटीक है।

16. (C) दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत मुख्य आयुक्तों के चार विशेष प्रांतों को संविधान सभा में एक-एक स्थान आवंटित किया गया था। ये चार प्रांत दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान थे। इन चारों मुख्य आयुक्तों के प्रांतों को ब्रिटिश भारत की कुल 296 सीटों के हिस्से के रूप में ही शामिल किया गया था, जहां से एक-एक प्रतिनिधि चुनकर संविधान सभा के महत्वपूर्ण विचार-विमर्श में भाग लेने दिल्ली पहुंचे थे।

17. (B) हीरालाल शास्त्री
राजस्थान के प्रसिद्ध जननेता हीरालाल शास्त्री ने संविधान सभा के सदस्य के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता के पश्चात जब विभिन्न देशी रियासतों को मिलाकर वृहत राजस्थान संघ का गठन किया गया, तब 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री (प्रधान) बने। उन्होंने राज्य के प्रशासनिक एकीकरण और लोक कल्याणकारी नीतियों की नींव रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरदर्शी योगदान दिया था।

18. (B) I, III और IV
देशी रियासतों को प्रारंभ में 93 सीटें आवंटित की गई थीं और उनके प्रतिनिधियों का मनोनयन रियासतों के शासकों द्वारा किया जाना था, न कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से। प्रारंभ में रियासतों ने सभा से अलग रहने का निर्णय लिया था, किंतु 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना स्वीकार होने के बाद अधिकांश रियासतों के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में अपने स्थान ग्रहण कर लिए थे।

19. (B) 299
जून 1947 की माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत के विभाजन के बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के प्रतिनिधि पृथक पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। इसके परिणामस्वरूप भारत की संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई। इनमें से भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधियों की संख्या 229 और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या 70 रह गई थी, जिन्होंने मिलकर भारत के संविधान का निर्माण किया।

NODIA

20. (C) संयुक्त प्रांत
भारत की संविधान सभा में प्रांतीय प्रतिनिधियों के अंतर्गत सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) से आए थे। संयुक्त प्रांत को कुल 55 सीटें आवंटित की गई थीं, जो सभी प्रांतों में सबसे अधिक थीं। इसके पश्चात मद्रास प्रांत का स्थान था, जिसे 49 सीटें प्राप्त थीं। संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधियों

ने संविधान सभा की विभिन्न बहसों और समितियों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

21. (C) 9 दिसंबर, 1946
संविधान सभा की पहली ऐतिहासिक बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैंबर के पुस्तकालय भवन में प्रातः ग्यारह बजे प्रारंभ हुई थी। मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहते हुए इस पहली बैठक का पूर्ण बहिष्कार किया था। इस कारण बैठक में केवल 211 सदस्य ही उपस्थित हो सके थे, जिन्होंने भारत के नए संविधान के निर्माण की दिशा में कार्य प्रारंभ किया।

22. (D) फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए, वह सबसे वरिष्ठ सदस्य थे।
संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई प्रथम बैठक में डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इस चुनाव हेतु फ्रांसीसी विधान सभा की उस सर्वमान्य परंपरा का पालन किया गया था, जिसके अनुसार सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को स्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन तक सभा का संचालन करने हेतु कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाता है। तत्पश्चात 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न हुआ।

23. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मुस्लिम लीग ने 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक का पूर्ण बहिष्कार किया था। बहिष्कार का मुख्य कारण यह था कि मुस्लिम लीग भारत से अलग एक पृथक संप्रभु राज्य पाकिस्तान के निर्माण और उसके लिए अलग संविधान सभा की अपनी मांग पर अड़ी हुई थी। अतः कथन और कारण दोनों पूरी तरह सत्य हैं तथा कारण, कथन की सही और तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करता है।

24. (B) 211
संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को आयोजित पहली बैठक में कुल 211 सदस्य ही उपस्थित हुए थे। यद्यपि कैबिनेट मिशन योजना के तहत कुल 389 सदस्य होने थे, किंतु मुस्लिम लीग के 73 सदस्यों ने पृथक पाकिस्तान की मांग को लेकर बैठक का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया था। इसके अलावा देशी रियासतों के अधिकांश प्रतिनिधियों ने भी प्रारंभ में संविधान सभा की इस पहली बैठक से दूरी बनाए रखी थी।

25. (D) (A) और (C) दोनों
संविधान सभा में दो उपाध्यक्ष (उप-सभापति) चुने गए थे। प्रसिद्ध शिक्षाविद और ईसाई समुदाय के नेता हरेंद्र कुमार (एच.सी.) मुखर्जी तथा जयपुर रियासत के प्रतिनिधि सर वेगल तिरुवेन्कट (वी.टी.) कृष्णमाचारी दोनों को ही संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में सेवा देने का गौरव प्राप्त हुआ था। इन दोनों नेताओं ने अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अनुपस्थिति में सभा की कार्यवाहियों का कुशल संचालन किया था।

26. (A) जवाहरलाल नेहरू
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक "उद्देश्य प्रस्ताव" प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव में भारतीय संविधान के मूल दर्शन, मूलभूत सिद्धांतों और भावी संप्रभु गणराज्य के राजनीतिक एवं सामाजिक ढांचे की रुपरेखा रेखांकित की गई थी। इस प्रस्ताव ने संविधान सभा को मार्गदर्शन प्रदान किया और यही आगे चलकर स्वतंत्र भारत के संविधान की सुप्रसिद्ध प्रस्तावना का मुख्य आधार और संबल बना।

27. (B) 22 जनवरी, 1947
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए 'उद्देश्य प्रस्ताव' को संविधान सभा ने गहन विचार-विमर्श के पश्चात 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अंगीकार कर लिया था। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में कुछ समय इसलिए लगा ताकि मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल होने का अवसर मिल सके। इस प्रस्ताव ने संविधान के भावी स्वरुप को निश्चित दिशा दी।

28. (B) द्वि-दलीय राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करने, अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों को सुरक्षा देने तथा समस्त शक्ति का स्रोत जनता को मानने जैसे सिद्धांतों को शामिल किया गया था। हालांकि, इसमें देश के लिए किसी द्वि-दलीय राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत या बाध्यता का कोई उल्लेख नहीं था। भारतीय संविधान ने बहुदलीय लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी।

29. (A) प्रस्तावना
उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित दर्शन, उच्च आदर्शों और मूलभूत सिद्धांतों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना (उद्देशिका) के निर्माण को प्रत्यक्ष और सर्वाधिक प्रभावित किया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किए गए इस प्रस्ताव के परिमार्जित एवं आधुनिक रूप को ही संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना के रूप में जोड़ा गया। यह प्रस्तावना भारतीय संविधान के मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना को स्पष्ट व्यक्त करती है।

30. (A) पहली बैठक $\rightarrow$ स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन $\rightarrow$ उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करना $\rightarrow$ उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करना
संविधान सभा की घटनाओं का सही क्रम इस प्रकार है: सर्वप्रथम 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तत्पश्चात 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे अंततः 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अतः यह कालानुक्रमिक क्रम पूरी तरह से ऐतिहासिक रूप से सही है।

31. (D) जवाहरलाल नेहरू
संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कई समितियों का गठन किया था। इनमें से अत्यंत महत्वपूर्ण "संघ शक्ति समिति" के अध्यक्ष पंडित

Click Here to Buy book on Amazon

जवाहरलाल नेहरु थे। इस समिति का मुख्य कार्य केंद्र सरकार की शक्तियों, उसके अधिकार क्षेत्र और भावी भारतीय संघ के अंतर्गत केंद्रीय सत्ता के संवैधानिक ढांचे का स्पष्ट निर्धारण करना और सभा के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था।

32. (C) संघ शक्ति समिति
पंडित जवाहरलाल नेहरु की अध्यक्षता वाली संघ शक्ति समिति ने केंद्र और प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण का खाका तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि कैबिनेट मिशन में कमजोर केंद्र का सुझाव था, किंतु विभाजन के पश्चात इस समिति ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्य से त्रि-स्तरीय विधायी सूचियों (संघ, राज्य और समवर्ती सूची) का प्रस्ताव रखकर मजबूत केंद्र की वकालत की।

33. (A) I और II
संघ शक्ति समिति ने प्रारंभ में कैबिनेट मिशन योजना के अनुरुप सीमित शक्तियों वाले कमजोर केंद्र की परिकल्पना की थी। परंतु देश के विभाजन के बाद समिति ने अपना रुख बदलते हुए भारत की रक्षा और स्थिरता के लिए एक मजबूत केंद्र का समर्थन किया। समिति ने सिफारिश की कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के बजाय केंद्र सरकार में निहित होनी चाहिए, इसलिए तीसरा कथन ऐतिहासिक रुप से गलत है।

34. (D) जवाहरलाल नेहरु
भारतीय संविधान सभा की "संघ संविधान समिति" के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरु थे। यह समिति स्वतंत्र भारत के केंद्रीय सरकार के ढांचे, राष्ट्रपति की शक्तियों, मंत्रिपरिषद तथा केंद्र-राज्य संबंधों की रुपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी थी। पंडित नेहरु के योग्य नेतृत्व में इस समिति ने भारत के लिए एकीकृत और सुदृढ़ संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण करने हेतु कई महत्वपूर्ण दूरदर्शी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं।

35. (A) संसदीय प्रणाली
पंडित जवाहरलाल नेहरु की अध्यक्षता वाली संघ संविधान समिति ने स्वतंत्र भारत के लिए उत्तरदायी संसदीय शासन प्रणाली की सिफारिश की थी। समिति का मानना था कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सरकार का जनता के प्रति जवाबदेह होना आवश्यक है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) विधायिका के प्रति प्रत्यक्ष रुप से उत्तरदायी होती है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों और स्थिरता के बीच बेहतर संतुलन बना रहता है।

36. (C) भारत सरकार अधिनियम, 1935
संघ संविधान समिति की रिपोर्टों और संसदीय ढांचे की सिफारिशों पर 'भारत सरकार अधिनियम, 1935' का गहरा प्रभाव था। भारतीय नेताओं को 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय स्तर पर लागू उत्तरदायी सरकार और प्रशासनिक तंत्र का पूर्व अनुभव था। यद्यपि अन्य देशों के संविधानों से भी विचार लिए गए, किंतु प्रशासनिक और विधायी संरचना के मामले में 1935 का अधिनियम ही मुख्य आधार और प्रेरणा बना था।

37. (A) सरदार वल्लभभाई पटेल
संविधान सभा की "प्रांतीय संविधान समिति" के अध्यक्ष भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल थे। इस महत्वपूर्ण समिति का मुख्य कार्य स्वतंत्र भारत के प्रांतों के प्रशासनिक और संवैधानिक ढांचे, प्रांतीय कार्यपालिका (राज्यपाल और मंत्रिपरिषद) तथा प्रांतीय विधानमंडलों की शक्तियों से संबंधित नियम तय करना था। सरदार पटेल के कुशल मार्गदर्शन में इस समिति ने एक संतुलित प्रांतीय शासन संरचना तैयार की थी।

38. (D) प्रांत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रुप से निर्वाचित
सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता वाली प्रांतीय संविधान समिति ने प्रारंभ में यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक प्रांत का राज्यपाल सीधे राज्य की जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रुप से निर्वाचित होना चाहिए। समिति का उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्तता को मजबूत करना था। हालांकि, बाद में संविधान सभा में व्यापक बहस के पश्चात इस व्यवस्था को बदलकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया।

39. (C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
संविधान सभा ने अंततः यह निर्णय लिया कि राज्यपाल का चुनाव प्रत्यक्ष रुप से जनता द्वारा कराने के बजाय उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह था कि निर्वाचित राज्यपाल और निर्वाचित (न कि मनोनीत) मुख्यमंत्री के बीच अधिकारों को लेकर टकराव पैदा हो सकता था। चूंकि मुख्यमंत्री मनोनीत नहीं बल्कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, इसलिए कारण में दिया गया विवरण गलत है।

NODIA

40. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
प्रांतीय संविधान समिति ने प्रांतीय शासन, कार्यपालिका और विधानमंडलों के ढांचे का व्यापक प्रस्ताव तैयार किया था, इसलिए पहला कथन सही है। हालांकि, प्रांतीय संविधान समिति ने संघ संविधान समिति के साथ संयुक्त बैठकें की थीं और आपस में विचार-विमर्श करके ही अपनी सिफारिशों को अंतिम रुप दिया था ताकि केंद्र और प्रांतों के प्रावधानों में सामंजस्य बना रहे। अतः दूसरा कथन पूरी तरह असत्य है।

41. (A) I, II और III
संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को प्रारुप समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अम्बेडकर थे और इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य शामिल थे। महात्मा गांधी संविधान सभा या इसकी किसी भी समिति के सदस्य नहीं थे, इसलिए चौथा कथन गलत है। प्रारुप समिति को भारत के नए संविधान का प्रारुप तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था।

42. (A) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, किंतु वह सात-सदस्यीय प्रारुप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारुप समिति के सदस्यों में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (अध्यक्ष), एन. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, डॉ. के.एम. मुंशी, सैयद

मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्तर (जिनके स्थान पर एन. माधव राव आए) और डी.पी. खेतान (जिनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी आए) शामिल थे।

43. (B) टी.टी. कृष्णमाचारी
प्रारुप समिति के मूल सदस्यों में से एक देवीप्रसाद (डी.पी.) खेतान का वर्ष 1948 में असमय निधन हो गया था। उनके निधन के पश्चात तिरुवल्लूर थट्टै (टी.टी.) कृष्णमाचारी को प्रारुप समिति में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। टी.टी. कृष्णमाचारी ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के परिमार्जन और प्रारुप को अंतिम रूप देने में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का सराहनीय सहयोग किया था।

44. (B) एन. माधव राव
प्रारुप समिति के प्रारंभिक सदस्य बी.एल. मित्तर ने अपने खराब स्वास्थ्य और निरंतर अस्वस्थता के कारण पद से त्यागपत्र दे दिया था। उनके स्थान पर एन. माधव राव को प्रारुप समिति का नया सदस्य नियुक्त किया गया था। एन. माधव राव ने बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा करने और उनका कानूनी प्रारुप तैयार करने में महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिका निभाई थी।

45. (B) फरवरी 1948
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारुप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारुप तैयार करके फरवरी 1948 में प्रकाशित किया था। इस प्रारुप पर भारत के नागरिकों, समाचार पत्रों, प्रांतीय विधानमंडलों और विभिन्न विशेषज्ञों को अपनी टिप्पणियां, आलोचनाएं और संशोधन सुझाव भेजने के लिए आठ महीने का समय दिया गया था। जनता से प्राप्त सुझावों पर विचार करके दूसरा प्रारुप तैयार किया गया।

46. (C) बंगाल प्रांत
डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर मूल रुप से वर्ष 1946 में आयोजित चुनावों के माध्यम से अविभाजित बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। हालांकि, अगस्त 1947 में भारत के विभाजन के पश्चात वह क्षेत्र (पूर्वी बंगाल) पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जिसके कारण डॉ. अम्बेडकर को संविधान सभा में अपनी सदस्यता की सीट खोनी पड़ी थी।

47. (D) बॉम्बे प्रेसीडेंसी
विभाजन के बाद बंगाल वाली सीट पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की संविधान सभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। उनकी प्रतिभा को देखते हुए बॉम्बे प्रेसीडेंसी की पुणे सीट से कांग्रेस के एम.आर. जयकर से त्यागपत्र दिलवाया गया और उप-चुनाव के माध्यम से डॉ. अम्बेडकर को बॉम्बे प्रेसीडेंसी से पुनः संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित कराकर भेजा गया।

48. (A) P-4, Q-3, R-2, S-1
संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों पर सलाहकार समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभभाई पटेल ने की थी। प्रारुप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अम्बेडकर थे, जबकि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉ. के.एम. मुंशी थे। अतः P-4, Q-3, R-2 और S-1 का मिलान पूरी तरह सत्य और सटीक है।

49. (D) अनुच्छेद 32
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात "संवैधानिक उपचारों के अधिकार" को भारतीय संविधान का "हृदय और आत्मा" कहा था। उनका मानना था कि यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है और उन्हें लागू करने का कोई प्रभावी कानूनी उपाय न हो, तो शेष अधिकार निरर्थक हो जाते हैं। अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है।

50. (D) सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा जैसे असंवैधानिक तरीके
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में "अराजकता का व्याकरण" शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जब संवैधानिक और कानूनी रास्ते उपलब्ध हों, तब सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और गैर-कानूनी आंदोलनों जैसे असंवैधानिक तरीकों का सहारा लेना लोकतंत्र के लिए घातक है और इन्हें पूरी तरह से त्याग दिया जाना चाहिए।

51. (B) 11 दिसंबर, 1946
डॉ. राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इससे पूर्व 9 दिसंबर 1946 को हुई पहली बैठक में डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के निर्माण की पूरी अवधि के दौरान सभा की बैठकों की अध्यक्षता की और अत्यंत धैर्य, कुशलता और निष्पक्षता से सदन का संचालन किया था।

52. (C) प्रक्रिया नियम समिति
डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष होने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण समितियों के प्रमुख भी थे। वह "प्रक्रिया नियम समिति" और "संचालन समिति" के अध्यक्ष थे। इन समितियों का मुख्य उत्तरदायित्व संविधान सभा के दैनिक कामकाज, बहसों के संचालन और बैठकों की कार्यप्रणाली के संबंध में नियम एवं प्रक्रियाएं निर्धारित करना था, ताकि संविधान निर्माण का कार्य सुचारु और अनुशासित रूप से संचालित हो सके।

53. (A) माणिक्य लाल वर्मा
राजस्थान के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी माणिक्य लाल वर्मा ने वर्ष 1938 में 'मेवाड़ प्रजामंडल' की स्थापना की थी। उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और मेवाड़ क्षेत्र में जनजागृति फैलाई। बाद में वह उदयपुर रियासत की ओर से संविधान सभा के सदस्य चुने गए और उन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद वे राजस्थान के प्रमुख जननेताओं में गिने गए।

Downloaded from www.pdf.tube

54. (C) I और III
सरदार वल्लभभाई पटेल ने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों पर सलाहकार समिति की अध्यक्षता की थी। उन्होंने भारत की एकता के लिए देशी रियासतों के विलय का कड़ा विरोध करने के बजाय उनका भारतीय संघ में ऐतिहासिक विलय कराया था, अतः दूसरा कथन गलत है। उन्होंने देशी रियासतों के राजाओं को समझा-बुझाकर उनके प्रतिनिधियों को संविधान सभा में लाने में अत्यंत निर्णायक भूमिका निभाई थी।

55. (B) के.एम. मुंशी
संविधान सभा के प्रमुख सदस्य और प्रसिद्ध कानूनविद डॉ. कन्हैयालाल माणिकलाल (के.एम.) मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की "राजनीतिक कुंडली" (Political Horoscope) की संज्ञा दी थी। उनका मानना था कि जिस प्रकार कुंडली किसी व्यक्ति के भविष्य और विशेषताओं को दर्शाती है, उसी प्रकार प्रस्तावना भारत के लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणराज्यीय स्वरुप के भविष्य तथा राजनीतिक मूल्यों का निर्धारण करती है।

56. (B) 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन
भारत का ऐतिहासिक और विस्तृत संविधान तैयार करने में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इस पूरी अवधि के दौरान संविधान सभा के सदस्यों ने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया, विभिन्न मुद्दों पर व्यापक बहस की और कई संशोधनों के पश्चात अंतिम दस्तावेज तैयार करके 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया।

57. (B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
प्रारुप समिति ने संविधान का प्रारुप प्रस्तुत करने से पूर्व उसके प्रत्येक अनुच्छेद की गहनता से जांच और परिमार्जन किया था, जो सत्य है। संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला मूल प्रारुप तैयार किया गया था, यह कथन भी पूर्णतः सत्य है। हालांकि, प्रारुप समिति द्वारा सूक्ष्म जांच का कारण केवल बी.एन. राव का प्रारुप होना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक चर्चा और कानूनी सटीकता सुनिश्चित करना था।

58. (B) 11 सत्र
भारत के संविधान का प्रारुप तैयार करने और उसे अंतिम रुप देने के लिए संविधान सभा के कुल 11 औपचारिक सत्र (अधिवेशन) आयोजित किए गए थे। पहला सत्र 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक चला था, जबकि 11वां सत्र 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक आयोजित हुआ था, जिसमें संविधान को अंगीकृत किया गया। (24 जनवरी 1950 को केवल हस्ताक्षर हेतु विशेष बैठक हुई थी)।

59. (B) 166 दिन
संविधान के निर्माण पर गहन विचार-विमर्श करने, प्रस्तावों पर चर्चा करने और प्रारुप को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा की कुल 166 दिनों की बैठकें आयोजित की गई थीं। इन 166 दिनों में से 114 दिन केवल संविधान के प्रारुप पर चर्चा करने में व्यतीत हुए थे। सदस्यों ने प्रत्येक धारा और संशोधन पर अत्यंत गंभीरता से बहस करके लोकतांत्रिक और सर्वमान्य संविधान तैयार किया।

60. (B) मुंशी-आयंगर सूत्र
संविधान सभा में भारत की राजभाषा के अत्यंत संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दे को हल करने के लिए "मुंशी-आयंगर सूत्र" अपनाया गया था। इसे के.एम. मुंशी और एन. गोपालस्वामी आयंगर ने मिलकर तैयार किया था। इस समझौते के तहत देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया, किंतु गैर-हिंदी भाषी राज्यों के हितों की रक्षा हेतु अंग्रेजी के प्रयोग को भी जारी रखा गया।

61. (B) 15 वर्ष
राजभाषा संबंधी समझौते (मुंशी-आयंगर सूत्र) के अंतर्गत यह तय किया गया कि संविधान लागू होने की तिथि (26 जनवरी 1950) से अगले 15 वर्षों की अवधि (1965 तक) के लिए संघ के सभी आधिकारिक और सरकारी प्रयोजनों हेतु अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 15 वर्षों के बाद भी कानून बनाकर अंग्रेजी के उपयोग को आगे बढ़ा सकती है।

62. (C) आर.वी. धुलेकर
भाषा संबंधी बहस के दौरान संयुक्त प्रांत के संविधान सभा सदस्य आर.वी. धुलेकर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का जोरदार समर्थन किया था। उन्होंने सदन में कड़ा रुख अपनाते हुए प्रसिद्ध टिप्पणी की थी कि "जो लोग हिंदुस्तानी नहीं जानते, उन्हें इस सभा में रहने का कोई अधिकार नहीं है।" उनके इस बयान पर सदन में काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी और अंततः भाषा मुद्दे पर मध्य मार्ग निकाला गया।

NODIA

63. (D) पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करना और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करना
संविधान सभा ने भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा शुरु की गई धर्म-आधारित सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर, ऐतिहासिक रुप से वंचित और सामाजिक रुप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा हेतु केवल अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए विधायिकाओं में सीटें आरक्षित करने का ऐतिहासिक और सर्वसम्मत निर्णय लिया।

64. (C) एच.सी. मुखर्जी
संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अंतर्गत गठित "अल्पसंख्यक उप-समिति" की अध्यक्षता हरेंद्र कुमार (एच.सी.) मुखर्जी ने की थी। एच.सी. मुखर्जी स्वयं भारतीय ईसाई समुदाय के एक प्रमुख नेता और बंगाल के विख्यात शिक्षाविद थे। उन्होंने देश के धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों,

सुरक्षात्मक उपायों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े विषयों का गहन अध्ययन किया था।

65. (B) विभाजन की प्रशासनिक वास्तविकताएं और त्रासदी
प्रारंभ में कैबिनेट मिशन योजना के तहत कमजोर केंद्र और शक्तिशाली प्रांतों की व्यवस्था का विचार था। परंतु अगस्त 1947 में हुए देश के विभाजन की भीषण त्रासदी, सांप्रदायिक दंगों और प्रशासनिक संकट के कारण संविधान सभा का ध्यान एक अत्यधिक मजबूत केंद्र बनाने की ओर स्थानांतरित हो गया। सदस्यों ने महसूस किया कि देश की अखंडता, आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए शक्तिशाली केंद्र अनिवार्य है।

66. (D) के. संथानम
संविधान सभा के सदस्य के. संथानम ने वित्तीय शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण का विरोध करते हुए प्रांतीय वित्तीय स्वायत्तता के पक्ष में जोरदार तर्क प्रस्तुत किए थे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि सभी राजस्व स्रोत केंद्र के पास रहेंगे, तो प्रांत अपनी विकास योजनाओं के लिए "केंद्र के दरवाजे पर भिखारी" बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने राज्यों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन और कर अधिकार सौंपने की मांग की थी।

67. (B) I, III और IV
डॉ. अम्बेडकर के अनुसार संविधान सामान्य समय में संघात्मक और आपातकाल में एकात्मक बन जाता है। भारत ने एकीकृत न्यायपालिका और केंद्र को मजबूत करने वाले आपातकालीन प्रावधानों को स्वीकार किया। परंतु अवशिष्ट शक्तियां प्रांतीय विधानमंडलों को नहीं, बल्कि केंद्र सरकार (संसद) को सौंपी गईं, इसलिए दूसरा कथन गलत है। इस प्रकार पहला, तीसरा और चौथा कथन पूरी तरह से सत्य और ऐतिहासिक दृष्टि से सही हैं।

68. (B) 26 नवंबर, 1949
भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इस ऐतिहासिक अवसर की याद में भारत सरकार प्रतिवर्ष 26 नवंबर को "संविधान दिवस" के रूप में मनाती है। इसी दिन संविधान के प्रारूप पर कार्य पूर्ण हुआ और इसके कुछ अनुच्छेद तुरंत प्रभावी हो गए, जबकि पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

69. (B) 284
26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकृत किया गया, उस समय संविधान सभा में कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्य भौतिक रूप से उपस्थित थे। उपस्थित इन सभी 284 सदस्यों ने भारत के मूल संविधान के आधिकारिक दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम व्यक्ति संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे।

70. (A) P-1, Q-1, R-2, S-2
26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत होते ही नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद और अस्थायी प्रावधानों से जुड़े कुछ अनुच्छेद (जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 आदि) तुरंत लागू कर दिए गए थे। जबकि मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व तथा शेष पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अतः P-1, Q-1, R-2 और S-2 का मिलान सही है।

71. (B) प्रस्तावना को संविधान के शेष भाग से पहले अंगीकृत किया गया था।
संविधान को अंगीकृत करने के संबंध में यह कथन असत्य है कि प्रस्तावना को शेष संविधान से पहले अंगीकृत किया गया था। वास्तव में, प्रस्तावना को संपूर्ण संविधान के अन्य सभी भागों को पारित करने के बाद सबसे अंत में अंगीकृत किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह संविधान के प्रावधानों के अनुकूल हो। अंगीकृत संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थीं और यह हस्तलिखित था।

72. (C) 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति में।
संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तिथि का चयन विशेष ऐतिहासिक कारण से किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन (1929) में पारित संकल्प के अनुसार, 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहली बार "पूर्ण स्वराज दिवस" मनाया गया था। उस ऐतिहासिक स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति को अमर बनाए रखने के लिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया था।

73. (D) अनुच्छेद 395
भारतीय संविधान के अंतिम अनुच्छेद 395 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया कि इसके लागू होने के साथ ही 'भारत सरकार अधिनियम, 1935' और 'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947' तथा इनसे संबंधित अन्य सभी पूरक अधिनियमों को पूरी तरह निरस्त (निरसित) कर दिया जाएगा। हालांकि, 'प्रीवी कौंसिल क्षेत्राधिकार उन्मूलन अधिनियम, 1949' को इस निरसन प्रक्रिया से अलग रखते हुए कानूनी रूप से बनाए रखा गया था।

74. (B) 24 जनवरी, 1950
संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया था। इसी दिन सदस्यों ने संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए, राष्ट्रगान 'जन गण मन' और राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को अंगीकार किया तथा डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना। इसके पश्चात 26 जनवरी 1950 से संविधान सभा ने नए आम चुनावों के बाद बनने वाली पहली संसद तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया।

75. (B) 1, 3, 2
संविधान सभा में प्रारूप संविधान को पारित करने के लिए तीन वाचन आयोजित किए गए थे। सबसे पहले प्रथम वाचन (सामान्य चर्चा: 4 से 9 नवंबर 1948) हुआ। इसके बाद द्वितीय वाचन (खंडवार गहन विचार-विमर्श एवं संशोधन: 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949) संपन्न हुआ। अंत में तृतीय वाचन

Click Here to Buy book on Flipkart

(अंतिम पारित प्रस्ताव: 14 से 26 नवंबर 1949) हुआ। अतः सही कालानुक्रमिक क्रम 1, 3, 2 है।

76. (B) राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अंगीकार किया गया था तथा डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। जबकि राष्ट्रमंडल (Commonwealth) में भारत की सदस्यता का अनुमोदन संविधान सभा द्वारा बहुत पहले, मई 1949 के सत्र में ही पूरा कर लिया गया था। अतः यह कार्य 24 जनवरी 1950 को आयोजित अंतिम बैठक में नहीं किया गया था।

77. (A) जी.वी. मावलंकर
1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के पश्चात संविधान सभा को दोहरी भूमिकाएं सौंपी गई थीं। जब यह निकाय संविधान निर्माण के कार्य हेतु मिलता था, तब इसकी अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद करते थे। किंतु जब यह देश के लिए सामान्य कानून बनाने वाली विधायिका (संसद) के रूप में कार्य करता था, तब इसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव (जी.वी.) मावलंकर करते थे। मावलंकर आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने।

78. (B) 1950 से 1952
संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 से लेकर वर्ष 1952 में प्रथम आम चुनावों के बाद निर्वाचित नई संसद के गठन तक, संविधान सभा ने भारत की "अंतरिम संसद" (Provisional Parliament) के रूप में कार्य किया। इस 1950 से 1952 की अवधि के दौरान अंतरिम संसद ने देश के लिए कई आवश्यक कानून पारित किए, जिनमें वर्ष 1951 का पहला संविधान संशोधन अधिनियम भी प्रमुख रूप से शामिल था।

79. (D) I, II और III
भारत की अंतरिम संसद में संविधान सभा के ही सदस्य शामिल थे जिन्होंने 26 जनवरी 1950 से कार्य संभाला। इस निकाय ने वर्ष 1951 में देश का पहला संविधान संशोधन अधिनियम (जिसके द्वारा नौवीं अनुसूची जोड़ी गई) सफलतापूर्वक पारित किया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1952 के आम चुनावों की कानूनी रूपरेखा तैयार करने हेतु अंतरिम संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 भी पारित किए। अतः तीनों कथन पूरी तरह सही हैं।

80. (C) इसके सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थे।
आलोचकों का मुख्य तथ्यात्मक तर्क यह था कि संविधान सभा एक पूर्णतः प्रतिनिधि निकाय नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव देश की आम जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था। इसके सदस्य 1946 में सीमित मताधिकार (संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर केवल लगभग 28% आबादी) द्वारा चुनी गई प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे।

81. (B) ग्रैनविल ऑस्टिन
प्रसिद्ध अमेरिकी संवैधानिक विशेषज्ञ और इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक 'द इंडियन कॉन्सिटट्यूशन: कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन' में संविधान सभा की राजनीतिक संरचना पर यह टिप्पणी की थी। उन्होंने लिखा था कि "संविधान सभा मूलतः एक-दलीय देश में एक-दलीय निकाय थी। सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था।" उनका यह वक्तव्य सभा में कांग्रेस पार्टी के अत्यधिक बहुमत और प्रभाव को रेखांकित करता है।

82. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत की संविधान सभा की आलोचना करते हुए कहा था कि यह निकाय "केवल भारत के एक बड़े समुदाय" का प्रतिनिधित्व करता है। उनके इस कथन का मुख्य आधार यह था कि मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण सभा में अधिकांश प्रतिनिधि हिंदू समुदाय से जुड़े कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। अतः कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

83. (A) कानूनी भाषा और संविधान का आकार उनके प्रभाव को दर्शाता है।
संविधान सभा में वकीलों और राजनेताओं के अत्यधिक वर्चस्व की आलोचना अक्सर की जाती है। इस आलोचना का मुख्य अर्थ यह है कि कानूनविदों की भारी उपस्थिति के कारण संविधान की भाषा अत्यधिक जटिल, विधिक शब्दावली से भरी हुई और आम नागरिकों की समझ से थोड़ी दूर हो गई। इसके अलावा, सभी संभावित कानूनी पहलुओं को समाहित करने के प्रयास में भारत का संविधान अत्यंत विस्तृत और विशाल आकार का बन गया।

84. (C) 15
भारत की संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य शामिल थीं। इन महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक एवं लैंगिक समानता के मुद्दों पर अपने मूल्यवान विचार रखे। इन प्रमुख महिला सदस्यों में सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख और बेगम एजाज रसूल जैसी महान विदुषी महिलाएं शामिल थीं।

85. (A) दक्षायाणी वेलायुधन
दक्षायाणी वेलायुधन भारत की संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य थीं। वह मद्रास प्रेसीडेंसी से निर्वाचित होकर आई थीं और मात्र 34 वर्ष की आयु में सभा की सबसे युवा सदस्यों में से एक थीं। उन्होंने संविधान सभा में अस्पृश्यता के पूर्ण उन्मूलन, सामाजिक न्याय, अनुसूचित जातियों के अधिकारों तथा मानव गरिमा को मौलिक अधिकारों में शामिल कराने के लिए अत्यंत प्रभावशाली और ओजस्वी भाषण दिए थे।

Downloaded from www.pdf.tube

86. (D) बेगम एजाज रसूल
बेगम एजाज रसूल भारत की संविधान सभा में चुनी गई एकमात्र मुस्लिम महिला प्रतिनिधि थीं। वह संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) से निर्वाचित होकर आई थीं। उन्होंने संविधान सभा में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का कड़ा विरोध किया था और राष्ट्र की एकता हेतु अल्पसंख्यकों को सामान्य राजनीतिक मुख्यधारा में शामिल होने का आह्वान किया था। उनका मानना था कि पृथक निर्वाचन अल्पसंख्यकों के हित में नहीं है।

87. (B) हंसा मेहता
14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को आयोजित संविधान सभा के विशेष ऐतिहासिक सत्र में प्रसिद्ध समाजसेविका और स्वतंत्रता सेनानी हंसा जीवराज मेहता ने भारत की समस्त महिलाओं की ओर से राष्ट्र को पहला आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) भेंट किया था। हंसा मेहता संविधान सभा की मौलिक अधिकारों की उप-समिति की भी सक्रिय सदस्य थीं और उन्होंने महिलाओं के समान अधिकारों और लैंगिक न्याय की पुरजोर वकालत की थी।

88. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
संविधान सभा ने देश के सभी प्रमुख अल्पसंख्यक समुदायों जैसे आंग्ल-भारतीय, पारसी, सिख और भारतीय ईसाइयों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया था, इसलिए कथन I पूरी तरह सही है। हालांकि, कथन II गलत है क्योंकि फ्रैंक एंथनी ने आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से नवल होर्मसजी (एच.पी.) मोदी और डॉ. के.एम. मुंशी ने किया था।

89. (D) I, II, III और IV
संविधान सभा में विविध समुदायों का कुशल प्रतिनिधित्व था। एच.सी. मुखर्जी ने भारतीय ईसाइयों की आवाज़ उठाई, एच.पी. मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया, फ्रैंक एंथनी ने आंग्ल-भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व किया और प्रख्यात हॉकी खिलाड़ी एवं जननेता जयपाल सिंह मुंडा ने देश के जनजातीय समुदायों और आदिवासियों के अधिकारों की वकालत की। अतः दिए गए सभी चारों कथन पूरी तरह से सत्य और ऐतिहासिक हैं।

90. (A) जयपाल सिंह मुंडा
प्रसिद्ध ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में भारत के मूल निवासी आदिवासियों के अधिकारों की पुरजोर वकालत की थी। वह 'अखिल भारतीय आदिवासी महासभा' के संस्थापक थे। उन्होंने संविधान सभा में बहस के दौरान जनजातीय क्षेत्रों की स्वायत्तता, उनकी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा, जल-जंगल-जमीन के अधिकारों और विधायिकाओं में आदिवासियों हेतु आरक्षण सुनिश्चित कराने में अत्यंत अग्रणी भूमिका निभाई थी।

91. (B) जे.बी. कृपलानी
संविधान सभा की "मौलिक अधिकार उप-समिति" की अध्यक्षता जीवतराम भगवानदास (जे.बी.) कृपलानी ने की थी। यह उप-समिति सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता वाली मुख्य 'सलाहकार समिति' के अंतर्गत कार्य करती थी। जे.बी. कृपलानी के नेतृत्व में इस उप-समिति ने नागरिकों के नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की विस्तृत सूची तैयार की, जिसे बाद में भारतीय संविधान के भाग 3 (अनुच्छेद 12 से 35) के रूप में शामिल किया गया।

92. (B) विधि की सम्यक प्रक्रिया
संविधान सभा ने मूल अधिकारों (विशेषकर अनुच्छेद 21) का प्रारूप तैयार करते समय अमेरिकी संविधान की शब्दावली "विधि की सम्यक प्रक्रिया" (Due Process of Law) के स्थान पर जापानी संविधान से प्रेरित "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" (Procedure Established by Law) शब्द का चयन किया। सभा का मानना था कि इससे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति संतुलन बना रहेगा और अदालतों को विधायी नीतियों में अत्यधिक हस्तक्षेप का अवसर नहीं मिलेगा।

93. (A) सर बी.एन. राव
संवैधानिक सलाहकार सर बेनेगल नरसिंग (बी.एन.) राव ने संविधान सभा को सुझाव दिया था कि व्यक्तिगत अधिकारों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए: प्रथम न्यायोचित अधिकार जिन्हें न्यायालयों द्वारा सीधे लागू कराया जा सके (मौलिक अधिकार) और द्वितीय गैर-न्यायोचित अधिकार जिन्हें राज्य के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर रखा जाए (राज्य के नीति निदेशक तत्व)। इस व्यावहारिक सुझाव को प्रारुप समिति ने स्वीकार कर लिया।

NODIA

94. (A) P-3, Q-1, R-2, S-4
संविधान सभा की महिला सदस्यों के प्रतिनिधित्व का सही मिलान इस प्रकार है: प्रसिद्ध कवयित्री सरोजिनी नायडू बिहार (एवं संयुक्त प्रांत) से चुनी गई थीं, हंसा मेहता बॉम्बे प्रेसीडेंसी से निर्वाचित हुई थीं, जी. दुर्गाबाई देशमुख मद्रास प्रेसीडेंसी का प्रतिनिधित्व करती थीं और राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत (तथा संयुक्त प्रांत) से जुड़ी थीं। अतः P-3, Q-1, R-2 और S-4 का सही उत्तर पूरी तरह उपयुक्त है।

95. (D) अस्पृश्यता (छुआछूत)
संविधान सभा ने भारत से अस्पृश्यता (छुआछूत) की सदियों पुरानी सामाजिक बुराई को पूरी तरह समाप्त करने पर पूर्ण आम सहमति बनाई। इसे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में एक दंडनीय अपराध और मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अनुच्छेद 17 घोषित करता है कि अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है और इससे उत्पन्न किसी भी अयोग्यता को लागू करना कानूनन अपराध होगा।

96. (C) आयरलैंड
भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) मुख्य रूप से वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से अनुप्राणित और प्रेरित थे। (आयरलैंड ने स्वयं इन्हें स्पेनिश संविधान से ग्रहण किया था)। संविधान सभा ने इन सिद्धांतों को भाग 4 (अनुच्छेद 36 से 51) में

इसलिए जोड़ा ताकि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) बनाया जा सके और सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हो।

97. (B) के.टी. शाह
संविधान सभा के अर्थशास्त्री और सदस्य प्रोफेसर के.टी. शाह ने नीति निदेशक तत्वों के गैर-न्यायोचित (अदालत द्वारा अप्रवर्तनीय) होने की तीखी आलोचना की थी। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध टिप्पणी में कहा था कि "राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसे चेक के समान हैं, जिसका भुगतान बैंक की सुविधा या संसाधनों पर छोड़ दिया गया है।" उनका तर्क था कि बिना कानूनी बाध्यता के ये निर्देश मात्र नैतिक उपदेश बनकर रह जाएंगे।

98. (D) गांधीवादी सिद्धांत
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक और आर्थिक विचारों को साकार करने के लिए नीति निदेशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांतों को विशेष रूप से शामिल किया गया। इनमें ग्राम पंचायतों का गठन (अनुच्छेद 40), कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना (अनुच्छेद 43), नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 47) और गोवध पर रोक तथा पशुपालन का विकास (अनुच्छेद 48) जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार के विषय शामिल किए गए।

99. (A) देश के शासन में मूलभूत
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि यद्यपि नीति निदेशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा सीधे लागू (न्यायोचित) नहीं कराए जा सकते, फिर भी ये सिद्धांत "देश के शासन में मूलभूत" (Fundamental in the Governance of the Country) हैं। अनुच्छेद 37 यह निर्देश देता है कि कानून बनाते समय और नीतियां तैयार करते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का परम कर्तव्य होगा।

100. (C) सर बी.एन. राव
प्रख्यात भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश सर बेनेगल नरसिंग (बी.एन.) राव ने संविधान सभा के "संवैधानिक सलाहकार" के रूप में कार्य किया। उन्होंने विश्व के प्रमुख संविधानों का गहन अध्ययन किया और भारतीय संविधान का पहला प्राथमिक मूल प्रारूप तैयार किया, जिस पर बाद में प्रारूप समिति ने विचार-विमर्श किया। बी.एन. राव ने बिना किसी मानदेय के इस सेवा को निष्ठापूर्वक पूरा किया था।

101. (A) बलवंत सिंह मेहता
उदयपुर (मेवाड़) के स्वतंत्रता सेनानी और प्रजामंडल के संस्थापक नेता बलवंत सिंह मेहता ने संविधान सभा के सदस्य के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह उदयपुर रियासत का प्रतिनिधित्व करते हुए संविधान सभा में पहुंचे थे। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार, बलवंत सिंह मेहता ऐसे प्रथम राजस्थानी व्यक्तित्व थे जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति पर अपने हस्ताक्षर अंकित किए थे।

102. (D) एस.एन. मुखर्जी
संविधान सभा में शचींद्र नाथ (एस.एन.) मुखर्जी ने संविधान के "मुख्य प्रारूपकार" (Chief Draftsman) के रूप में कार्य किया था। उन्होंने जटिल से जटिल कानूनी और राजनीतिक प्रस्तावों को अत्यंत सटीक, स्पष्ट और कानूनी रूप से सुदृढ़ अनुच्छेदों की भाषा में ढालने की अद्भुत क्षमता का परिचय दिया। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने स्वयं संविधान सभा में एस.एन. मुखर्जी के इस उत्कृष्ट कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी।

103. (B) प्रेम बिहारी रायजादा
भारतीय संविधान का मूल अंग्रेजी संस्करण मुद्रित या टाइप नहीं किया गया था, बल्कि इसे पूरी तरह हाथ से लिखा गया था। इसके सुलेखन (Calligraphy) का ऐतिहासिक कार्य प्रसिद्ध सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा संपन्न किया गया था। उन्होंने इटैलिक शैली में संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को बहती हुई सुंदर लिखावट में लिखा। पंडित जवाहरलाल नेहरु के अनुरोध पर उन्होंने इस महान कार्य हेतु कोई शुल्क नहीं लिया था।

104. (C) नंदलाल बोस
शांतिनिकेतन के प्रसिद्ध महान चित्रकार आचार्य नंदलाल बोस और उनके शिष्यों (जिनमें बियोहर राममनोहर सिन्हा शामिल थे) ने भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ को अलंकृत, चित्रित और सुसज्जित करने का ऐतिहासिक दायित्व निभाया। उन्होंने भारत की वैदिक संस्कृति, मोहनजोदड़ो, रामायण, महाभारत, बुद्ध, महावीर, अशोक, गुप्त काल और स्वतंत्रता संग्राम के दृश्यों से संविधान के विभिन्न अध्यायों को कलात्मक रूप से सजाया।

105. (C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 6(1) द्वारा संविधान सभा को एक पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया था, इसलिए कथन (A) सही है। कारण (R) पूरी तरह से गलत है क्योंकि संप्रभु निकाय बनने के बाद सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाए गए किसी भी पूर्व कानून को निरस्त करने या बदलने का पूरा अधिकार प्राप्त हो गया था और यह ब्रिटिश निर्देशों से पूरी तरह मुक्त थी।

106. (A) एक सामान्य मध्य मार्ग तक पहुँचने के लिए विरोधी दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित किया गया।
संविधान सभा के कामकाज में "सामंजस्य" (Accommodation) और सहमति की प्रक्रिया का अर्थ यह था कि विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और प्रांतीय विचारधाराओं के विरोधी दृष्टिकोणों में टकराव पैदा करने के बजाय एक संतुलित मध्य मार्ग तलाशा जाए। सभा ने कठोर बहुमत मतदान के बजाय आपसी बातचीत, सिद्धांतों के समन्वय और सभी वर्गों के हितों को संतुष्ट करने वाली सर्वसम्मति की अनूठी लोकतांत्रिक परंपरा को प्राथमिकता देकर संविधान का निर्माण किया।

Click Here to Buy book on Amazon

107. (B) जयपुर
राजपूताना (वर्तमान राजस्थान) की विभिन्न देशी रियासतों में से 'जयपुर' रियासत के संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि थे। जयपुर रियासत को उसकी अधिक जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थीं। जयपुर के प्रतिनिधियों में सर वी.टी. कृष्णमाचारी और पं. हीरालाल शास्त्री जैसे दिग्गज व्यक्तित्व शामिल थे, जिन्होंने संविधान सभा की बहसों और विभिन्न समितियों की कार्यवाहियों में अत्यंत सक्रिय एवं रचनात्मक भागीदारी निभाई थी।

108. (B) हाथी
भारत की संविधान सभा द्वारा अपनी आधिकारिक मुहर (Seal) या प्रतीक चिन्ह के रूप में 'हाथी' (Elephant) के प्रतीक को अपनाया गया था। हाथी को भारत की विशालता, शक्ति, बुद्धिमत्ता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में मुहर पर उकेरा गया था। संविधान सभा के सभी आधिकारिक दस्तावेजों, पत्रों और मुद्रित प्रपत्रों पर हाथी के इस विशेष प्रतीक चिन्ह का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता था।

109. (A) P-2, Q-4, R-1, S-3
संविधान सभा में राजस्थान के प्रतिनिधियों और उनके क्षेत्रों का सही मिलान इस प्रकार है: मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर-मेरवाड़ा के मुख्य आयुक्त प्रांत से चुने गए थे, माणिक्य लाल वर्मा ने उदयपुर (मेवाड़) रियासत का प्रतिनिधित्व किया था, जयनारायण व्यास जोधपुर रियासत से आए थे और सर वी.टी. कृष्णमाचारी जयपुर रियासत के प्रतिनिधि थे। अतः P-2, Q-4, R-1 और S-3 का मिलान सत्य है।

110. (D) उपर्युक्त सभी ने कम से कम एक सीट जीती
जुलाई-अगस्त 1946 के संविधान सभा चुनावों में कांग्रेस (208 सीटें) और मुस्लिम लीग (73 सीटें) के अलावा कई छोटे क्षेत्रीय और राजनीतिक दलों ने भी सफलता प्राप्त की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (1 सीट), पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी (3 सीटें) और बंगाल की कृषक प्रजा पार्टी (1 सीट) तथा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एवं सिख समूहों ने कम से कम एक-एक सीट जीती थी। अतः विकल्प D सही है।

111. (B) मई 1949
भारत की संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल (Commonwealth) में भारत की सदस्यता का औपचारिक अनुसमर्थन किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरु ने सभा में स्पष्ट किया था कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करने से भारत की पूर्ण संप्रभुता, स्वतंत्रता या गणराज्यीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत ने एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्वेच्छा से राष्ट्रमंडल देशों के साथ व्यापारिक एवं राजनयिक सहयोग हेतु यह संबंध बनाए रखा।

112. (A) I और II
कैबिनेट मिशन योजना के तहत पंजाब प्रांत में सिख समुदाय के लिए पृथक रूप से सीटें आरक्षित की गई थीं। सरदार हुकम सिंह और सरदार उज्ज्वल सिंह जैसे दिग्गज नेता संविधान सभा में सिखों के प्रमुख प्रतिनिधि थे। हालांकि, उन्होंने एकीकृत और अखंड भारत के भीतर अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा की मांग की थी, न कि किसी अलग सिख राज्य की। अतः पहला और दूसरा कथन पूरी तरह सत्य हैं।

113. (B) भारत के लिए बनाए गए किसी भी ब्रिटिश कानून को रद्द करने या बदलने की।
1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय बनाया गया था। इसके तहत सभा को यह असीमित शक्ति प्रदान की गई थी कि वह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी पूर्व कानून या अधिनियम (जिसमें 1935 का अधिनियम भी शामिल था) को पूरी तरह से रद्द कर सकती थी, संशोधित कर सकती थी या उसमें कोई भी आवश्यक परिवर्तन कर सकती थी।

114. (A) 23 दिसंबर, 1946
संविधान सभा का पहला ऐतिहासिक सत्र 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था और यह सत्र 23 दिसंबर 1946 को समाप्त हुआ था। इस प्रथम सत्र के दौरान ही 11 दिसंबर को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरु द्वारा ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर सदस्यों ने गहन प्रारंभिक चर्चाओं में भाग लिया था।

115. (A) हैदराबाद
हैदराबाद की विशाल देशी रियासत के निज़ाम ने प्रारंभ में अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने की ज़िद्द के कारण संविधान सभा में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि, भारत की स्वाधीनता और अखंडता के हित में सितंबर 1948 में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान "ऑपरेशन पोलो" (पुलिस कार्रवाई) के पश्चात हैदराबाद का भारत में विलय हुआ और इसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हुए थे।

NODIA

116. (C) एच.वी.आर. अयंगर
प्रख्यात भारतीय सिविल सेवा (ICS) अधिकारी एच.वी.आर. अयंगर (एच.वी. रंगनाथ अयंगर) ने भारत की संविधान सभा के "सचिव" (Secretary) के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। उन्होंने संविधान सभा के विशाल प्रशासनिक ढांचे, बैठकों के आयोजन, कार्यवाहियों के मुद्रण, अभिलेखों के रखरखाव तथा विभिन्न समितियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में अत्यंत कुशल, अनुशासित और सराहनीय प्रशासनिक भूमिका निभाई थी।

117. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
संविधान सभा ने अपने सभी ऐतिहासिक सत्र नई दिल्ली स्थित संसद भवन (तत्कालीन काउंसिल चैंबर) के केंद्रीय कक्ष (Central Hall) में आयोजित किए थे, अतः पहला कथन सही है। हालांकि, दूसरा कथन असत्य है क्योंकि संविधान सभा के सत्रों में आम जनता, दर्शकों और प्रेस के संवाददाताओं को प्रवेश दीर्घाओं से बैठकों की कार्यवाहियों को देखने और समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की पूरी अनुमति दी गई थी।

118. (D) महात्मा गांधी
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने संविधान सभा का सदस्य न बनने का स्पष्ट और कड़ा निर्णय लिया था। यद्यपि संविधान सभा के अधिकांश सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे और गांधी जी के विचारों से गहराई से प्रभावित थे, फिर भी गांधी जी ने स्वयं को किसी भी औपचारिक सरकारी या संवैधानिक पद से दूर रखा। उन्होंने अपना पूरा ध्यान देश के सांप्रदायिक सौहार्द, दंगा पीड़ितों की सेवा और रचनात्मक कार्यों पर केंद्रित रखा।

119. (A) 2, 3, 1
संविधान सभा की समितियों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया का सही कालानुक्रमिक क्रम 2, 3, 1 है। जवाहरलाल नेहरू की संघ शक्ति समिति और पटेल की मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति ने संविधान निर्माण के शुरुआती चरण (मई-जुलाई 1947) में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इन सभी मुख्य समितियों की रिपोर्टों और सिफारिशों का अध्ययन करने के बाद ही अंत में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित की गई थी।

120. (C) 1935 के अधिनियम के वे प्रावधान जिन्होंने नीति निदेशक तत्वों को प्रभावित किया
संविधान सभा के संदर्भ में 'निर्देशों के साधन' (Instruments of Instructions) शब्द भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित उन अनुदेशों को संदर्भित करता है जो ब्रिटिश क्राउन द्वारा गवर्नर-जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को जारी किए जाते थे। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इन निर्देशों को राज्य के नीति निदेशक तत्वों (भाग 4) के रूप में ढाला ताकि वे स्वतंत्र भारत की सरकारों के लिए नीतिगत मार्गदर्शन का कार्य कर सकें।

121. (D) बी. पट्टाभि सीतारमैया
संविधान सभा की "सदन समिति" (House Committee) के अध्यक्ष प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस नेता डॉ. भोगराजू पट्टाभि सीतारमैया थे। इस समिति का मुख्य कार्य संविधान सभा के सदस्यों के रहने के प्रबंध, आवासीय सुविधाओं, भोजन व्यवस्था तथा सभा भवन के परिसरों के प्रशासनिक प्रबंधन से जुड़े व्यावहारिक कार्यों को देखना था, ताकि सभी प्रतिनिधि बिना किसी परेशानी के संविधान निर्माण कार्य में संलग्न रह सकें।

122. (A) के. संथानम
संविधान सभा के प्रमुख सदस्य के. संथानम ने महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' के आदर्शों को साकार करने हेतु संविधान में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (ग्राम पंचायतों) को शामिल करने की जोरदार वकालत की थी। उनके इस प्रबल प्रयास और तर्कों के परिणामस्वरूप संविधान सभा ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 को शामिल किया, जो राज्यों को ग्राम पंचायतों का संगठन करने का स्पष्ट निर्देश देता है।

123. (B) I, III और IV
मौलिक अधिकारों की बहसों में आर्थिक अधिकारों की प्रकृति पर विचार हुआ, निवारक निरोध की धाराओं के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की गई और वाक् स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने का निर्णय लिया गया। हालांकि, दूसरा कथन गलत है क्योंकि संविधान सभा ने प्रारंभ में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19 और 31 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया था (जिसे 1978 के 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया)।

124. (B) जम्मू और कश्मीर
भारत के राज्यों में से 'जम्मू और कश्मीर' एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका अपना पृथक संविधान था और वह संविधान भारत की संविधान सभा द्वारा तैयार नहीं किया गया था। अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त विशेष संवैधानिक दर्जे के कारण जम्मू और कश्मीर के लिए एक अलग संविधान सभा गठित की गई थी, जिसने 1956 में राज्य का अपना संविधान अंगीकृत किया था (जिसे वर्ष 2019 में निरस्त कर दिया गया)।

125. (A) अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
संविधान सभा की "प्रत्यय-पत्र समिति" (Credentials Committee) के अध्यक्ष मद्रास के प्रसिद्ध कानूनी विशेषज्ञ और प्रारूप समिति के सदस्य सर अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर थे। इस विशेष समिति का मुख्य उत्तरदायित्व संविधान सभा में चुनकर आने वाले विभिन्न सदस्यों के निर्वाचन पत्रों, क्रेडेंशियल्स और उनकी योग्यता संबंधी आधिकारिक दस्तावेजों की वैधानिकता की जांच करना था, ताकि सदन में अनधिकृत प्रवेश रोका जा सके।

126. (D) I, II और III
संविधान सभा ने बिना किसी निष्कासन के विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक दृष्टिकोणों को समाहित किया। निर्णयों में बहुसंख्यक मतदान के स्थान पर सर्वसम्मति और सहमति की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा, इसकी अनुशासित एवं गंभीर बहसों ने स्वतंत्र भारत की संसद के लिए उच्च लोकतांत्रिक मूल्य, सहिष्णुता और मजबूत परंपराएं स्थापित कीं। अतः दिए गए तीनों कथन संविधान सभा की विरासत के संदर्भ में पूरी तरह सही हैं।

127. (A) कैबिनेट मिशन योजना → उद्देश्य प्रस्ताव → प्रारुप समिति का गठन → संविधान को अंगीकार करना
संविधान सभा के संरचनात्मक पड़ावों का सही क्रम इस प्रकार है: सर्वप्रथम मई 1946 में 'कैबिनेट मिशन योजना' आई। इसके पश्चात 13 दिसंबर 1946 को 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत हुआ। फिर स्वतंत्रता के बाद 29 अगस्त 1947 को 'प्रारुप समिति का गठन' किया गया। अंततः 26 नवंबर 1949 को 'संविधान को अंगीकार' किया गया। अतः यह कालानुक्रमिक क्रम ऐतिहासिक दृष्टि से पूर्णतः सत्य है।

128. (B) ₹64 लाख
भारत के विस्तृत संविधान का निर्माण करने, विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करने, सदस्यों के यात्रा भत्तों, आधिकारिक मुद्रण और 166 दिनों की बैठकों के संचालन में संविधान सभा द्वारा कुल अनुमानित खर्च लगभग 64 लाख रुपये (सटीक रूप से ₹63,96,729) किया गया था। लगभग तीन वर्षों तक चले इस महायज्ञ के माध्यम से भारत को एक संप्रभु और लोकतांत्रिक संविधान प्राप्त हुआ।

Downloaded from www.pdf.tube

129. (B) लॉर्ड लिनलिथगो
वर्ष 1940 के प्रसिद्ध 'अगस्त प्रस्ताव' के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो (1936-1943) था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो ने एक आधिकारिक घोषणा की, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने पहली बार स्वीकार किया कि भारत का नया संविधान तैयार करना मुख्य रूप से स्वयं भारतीयों का अधिकार और उत्तरदायित्व है।

130. (D) बलवंत सिंह मेहता
राजस्थान के प्रख्यात जननेता और उदयपुर (मेवाड़) प्रजामंडल के संस्थापक बलवंत सिंह मेहता संविधान सभा के सदस्य थे। स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विकास, ग्रामीण स्वशासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर अत्यंत गहराई से कार्य किया तथा प्रसिद्ध पुस्तक "पंचायती राज" की रचना की। उन्होंने समाज के पिछड़े और जनजातीय वर्गों के उत्थान हेतु जीवन भर कार्य किया था।

NODIA

अध्याय 02
भारतीय संविधान की प्रकृति एवं विशेषताएँ

1. किस राजनीतिशास्त्री ने भारतीय संविधान की प्रकृति को "अर्ध-संघीय" (quasi-federal) के रूप में वर्णित किया था?
   (A) के.सी. व्हीयर
   (B) ग्रैनविल ऑस्टिन
   (C) आइवर जेनिंग्स
   (D) मॉरिस जोन्स

2. निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का पूर्णतः एकात्मक लक्षण माना जाता है?
   (A) संविधान का लिखित स्वरूप
   (B) राष्ट्रीय स्तर पर द्विसदनीयता
   (C) सभी राज्यों के लिए एकल नागरिकता
   (D) केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन

3. निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा भारतीय संविधान का वर्णन करने के लिए "सहकारी संघवाद" शब्द का प्रयोग किया गया था?
   (A) ग्रैनविल ऑस्टिन
   (B) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
   (C) के.सी. व्हीयर
   (D) विंस्टन चर्चिल

4. भारतीय संदर्भ में "एकात्मक झुकाव वाला संघवाद" शब्द का क्या अर्थ है?
   (A) राज्यों के पास संघ सरकार की तुलना में अधिक शक्तियाँ हैं
   (B) संघ और राज्यों के पास पूर्णतः समान और स्वतंत्र शक्तियाँ हैं
   (C) संविधान हर समय पूरी तरह से एकात्मक राज्य के रूप में कार्य करता है
   (D) ढांचा संघीय है लेकिन केंद्र संरचनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली है

5. भारतीय संविधान की कौन-सी विशिष्ट संरचनात्मक विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाने वाले संघवाद के शास्त्रीय मॉडल से मूलभूत रूप से असंगत है?
   (A) संविधान की सर्वोच्चता
   (B) एकीकृत एवं एकल न्यायपालिका
   (C) लिखित संविधान
   (D) संघीय विशेषताओं के लिए कठोर संशोधन प्रक्रिया

6. अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, भारतीय संविधान का स्वरूप किसमें परिवर्तित हो जाता है?
   (A) बिना किसी औपचारिक संशोधन के एकात्मक से संघीय में
   (B) अर्ध-संघीय से परिसंघीय में
   (C) बिना किसी औपचारिक संशोधन के संघीय से पूर्णतः एकात्मक में
   (D) अध्यक्षात्मक से संसदात्मक में

7. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार, भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाने का प्राथमिक कारण क्या था?
   (A) देशी रियासतों की माँगों को संतुष्ट करना
   (B) ब्रिटिश प्रशासनिक मॉडल का पूर्ण अनुकरण करना
   (C) प्रधानमंत्री के हाथों में अधिकतम शक्ति केंद्रित करना
   (D) एक विशाल और विविधतापूर्ण देश में कुशल प्रशासन सुनिश्चित करना

8. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
   कथन (A): भारतीय संविधान स्वरूप में संघीय है किन्तु भावना में एकात्मक है।
   कारण (R): संघ सरकार आपातकाल के दौरान राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है और यहाँ तक कि कार्यकारी शक्तियाँ भी ग्रहण कर सकती है।
   निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
   (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
   (B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
   (C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
   (D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

9. संघीय-एकात्मक बहस के संदर्भ में, राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसे दर्शाती है?
   (A) एक विशुद्ध संघीय सिद्धांत जो पूर्ण राज्य स्वायत्तता सुनिश्चित करता है
   (B) एक एकात्मक विशेषता जो केंद्रीय पर्यवेक्षण को सक्षम बनाती है
   (C) अमेरिकी संवैधानिक ढांचे से सीधे ली गई एक परंपरा
   (D) एक संवैधानिक विशेषता जो संघ सरकार को अत्यंत कमजोर करती है

10. भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस ऐतिहासिक निर्णय में संघवाद को संविधान के "मूल ढाँचे" का हिस्सा घोषित किया था?

Click Here to Buy book on Flipkart

(A) केशवानंद भारती मामला
(B) एस.आर. बोम्मई मामला
(C) मिनर्वा मिल मामला
(D) गोलकनाथ मामला

11. किस दस्तावेज ने भारतीय संविधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक ढाँचे के रूप में कार्य किया?
(A) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(B) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
(C) भारत सरकार अधिनियम, 1919
(D) नेहरू रिपोर्ट, 1928

12. भारतीय संविधान में "न्यायिक पुनरावलोकन" (Judicial Review) की अवधारणा मुख्य रूप से किस देश के संविधान से प्रेरित थी?
(A) यूनाइटेड किंगडम
(B) डोमिनियन ऑफ कनाडा
(C) संयुक्त राज्य अमेरिका
(D) ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल

13. निम्नलिखित में से कौन-सी संवैधानिक विशेषता ब्रिटिश संविधान से ली गई थी?
(A) समवर्ती सूची से संबंधित विस्तृत प्रावधान
(B) भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की सटीक पद्धति
(C) मौलिक कर्तव्यों का संवैधानिक प्रावधान
(D) अध्यक्ष (स्पीकर) का पद

14. भारतीय संविधान के भाग IV में अंतर्निहित राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) कहाँ से अपनाए गए थे?
(A) जर्मनी का वाइमर संविधान
(B) दक्षिण अफ्रीका का संविधान
(C) आयरलैंड का संविधान
(D) सोवियत संविधान

15. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (लिया गया प्रावधान)
P. समवर्ती सूची
Q. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
R. मौलिक कर्तव्य
S. स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श
सूची II: (स्रोत देश)
1. जापान
2. ऑस्ट्रेलिया
3. फ्रांस
4. सोवियत संघ (USSR)
निम्नलिखित में से कौन-सा सही मिलान है?
(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-2, Q-3, R-1, S-4
(D) P-1, Q-2, R-4, S-3

16. एक सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई थी?
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका
(B) ऑस्ट्रेलिया
(C) स्विट्ज़रलैंड
(D) कनाडा

17. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किससे प्रेरित है?
(A) जर्मनी का वाइमर संविधान
(B) सोवियत संघ (USSR) का संविधान
(C) दक्षिण अफ्रीका का संविधान
(D) 1867 का ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट

18. कौन-सी संवैधानिक विशेषता अपने स्रोत के साथ सही सुमेलित है?
(A) शासन का गणतांत्रिक रूप - ब्रिटिश संविधान
(B) विधि के शासन का सिद्धांत - संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान
(C) संविधान संशोधन प्रक्रिया - दक्षिण अफ्रीका का संविधान
(D) सरकार की कैबिनेट प्रणाली - कनाडा का संविधान

19. राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति किस देश के संविधान से प्रभावित है?
(A) दक्षिण अफ्रीका
(B) आयरलैंड
(C) ऑस्ट्रेलिया
(D) यूनाइटेड किंगडम

20. संविधान के स्रोत के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसने संघीय योजना और प्रशासनिक विवरणों के लिए ढाँचा प्रदान किया।
II. इसने मौलिक अधिकारों का दार्शनिक ढाँचा प्रस्तुत किया।
III. इसने राज्यपाल के पद का आधार स्थापित किया।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

21. भारत ने किस देश के संविधान से अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित करने की अवधारणा ली है?
(A) ऑस्ट्रेलिया
(B) कनाडा
(C) अमेरिका
(D) आयरलैंड

NODIA

22. राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया प्रावधान है?
(A) यूनाइटेड किंगडम
(B) संयुक्त राज्य अमेरिका
(C) आयरलैंड
(D) कनाडा

23. निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता अमेरिकी संविधान से नहीं ली गई है?
(A) न्यायपालिका की स्वतंत्रता
(B) राष्ट्रपति पर महाभियोग
(C) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना
(D) संसदीय विशेषाधिकार

24. भारतीय संविधान में समाविष्ट "विधि का शासन" (Rule of Law) का सिद्धांत मूल रूप से किस विधिक प्रणाली की प्रमुख विशेषता है?
(A) ब्रिटिश विधिक प्रणाली
(B) अमेरिकी विधिक प्रणाली
(C) फ्रांसीसी विधिक प्रणाली
(D) कनाडाई विधिक प्रणाली

25. प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श मुख्य रूप से किससे प्रेरित थे?
(A) फ्रांसीसी क्रांति
(B) रूसी क्रांति
(C) अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा
(D) आयरिश होम रूल आंदोलन

26. भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?
(A) गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस से ली गई थी
(B) परमाधिकार रिटों का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था
(C) उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार कनाडा से लिया गया था
(D) मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ (USSR) से ली गई थी

27. भारत के उच्चतम न्यायालय की कार्यप्रणाली का ढाँचा सबसे अधिक किससे प्रभावित है?
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान
(B) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(C) ब्रिटिश संवैधानिक परंपराएं
(D) ऑस्ट्रेलिया का संविधान

28. भारतीय संविधान के भाग XVIII में आपातकालीन प्रावधानों के प्रारूपण को किस संवैधानिक स्रोत ने गहराई से प्रभावित किया?
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान
(B) डोमिनियन ऑफ कनाडा का संविधान
(C) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(D) आयरलैंड गणराज्य का संविधान

29. भारत में अंतरराज्यीय "व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता" की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित थी?
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान
(B) यूनाइटेड किंगडम का संवैधानिक ढाँचा
(C) डोमिनियन ऑफ कनाडा का संविधान
(D) ऑस्ट्रेलिया का संविधान

NODIA

30. भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. उच्च न्यायालय की संस्था की उत्पत्ति पूर्णतः अमेरिकी संविधान से हुई थी।
II. केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 में मौजूद एक विशेषता थी।
III. विधि के समान संरक्षण का सिद्धांत अमेरिकी संविधान से लिया गया है।
IV. DPSP की अवधारणा आयरलैंड से ली गई थी, जिसने इसे स्पेन से लिया था।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, III और IV
(D) I, II, III और IV

31. 26 नवंबर, 1949 को अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ शामिल थीं?
(A) 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ
(B) 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ
(C) 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ
(D) 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ

32. निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान होने का प्राथमिक कारण माना जाता है?
(A) इसमें प्रत्येक राज्य के लिए अलग विस्तृत संविधान शामिल हैं।
(B) यह संपूर्ण दंड संहिता को सीधे अपने मुख्य पाठ में रेखांकित करता है।
(C) इसे आधिकारिक तौर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एक साथ प्रारूपित किया गया था।
(D) इसमें विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान शामिल हैं।

33. संविधान सभा में किस व्यवसाय के प्रभुत्व को आलोचकों द्वारा प्रायः संविधान के विशाल आकार और जटिल भाषा का कारण बताया जाता है?
(A) वकील
(B) शिक्षाविद
(C) सिविल सेवक

(D) पत्रकार

34. वर्तमान में, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है?
(A) 22
(B) 24
(C) 25
(D) 21

35. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (संविधान के भाग)
P. भाग II
Q. भाग III
R. भाग IV
S. भाग IVA
सूची II: (विषय वस्तु)
1. मौलिक कर्तव्य
2. नागरिकता
3. राज्य के नीति निदेशक तत्व
4. मौलिक अधिकार
निम्नलिखित में से कौन-सा सही मिलान है?
(A) P-2, Q-4, R-3, S-1
(B) P-4, Q-2, R-1, S-3
(C) P-2, Q-3, R-4, S-1
(D) P-1, Q-4, R-3, S-2

36. मूल संविधान को अंगीकृत किए जाने के पश्चात् सबसे पहले कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई थी?
(A) आठवीं अनुसूची
(B) दसवीं अनुसूची
(C) ग्यारहवीं अनुसूची
(D) नौवीं अनुसूची

37. संवैधानिक पाठ में मौलिक अधिकारों, नीति निदेशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों का एक साथ समावेश इसके किस पहलू में महत्वपूर्ण योगदान देता है?
(A) संरचनात्मक लचीलापन और अनुकूलन क्षमता
(B) लंबाई और विस्तृत विवरण
(C) मजबूत संरचनात्मक और प्रशासनिक एकात्मक झुकाव
(D) शिथिल रूप से गठित परिसंघीय व्यवस्था

38. सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित भागों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था:
(A) भाग IVA, भाग IXA, भाग IXB, भाग XIVA
(B) भाग IVA, भाग XIVA, भाग IXA, भाग IXB
(C) भाग XIVA, भाग IVA, भाग IXB, भाग IXA
(D) भाग IXA, भाग IVA, भाग XIVA, भाग IXB

39. संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विपरीत, भारतीय संविधान:
(A) में कोई परिचयात्मक प्रस्तावना नहीं है
(B) पूरी तरह से कठोर है और किसी भी परिस्थिति में संशोधित नहीं किया जा सकता है
(C) कोई भी लागू करने योग्य मौलिक अधिकार प्रदान करने में विफल रहता है
(D) संघ और राज्यों के लिए एक एकल संविधान प्रदान करता है

40. भारतीय संविधान का ढांचागत भाग काफी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इस ढांचागत भाग में शामिल है:
(A) प्रशासनिक विवरण
(B) वाद-योग्य मौलिक अधिकारों का पूरा ढांचा
(C) गैर-वादयोग्य राज्य के नीति निदेशक तत्व
(D) राष्ट्रपति के निर्वाचन की सटीक प्रक्रियात्मक पद्धति

41. निम्नलिखित में से कौन-सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख एकात्मक विशेषता है?
(A) स्वतंत्र न्यायपालिका
(B) अखिल भारतीय सेवाएं
(C) कठोर संशोधन प्रक्रिया
(D) सातवीं अनुसूची के माध्यम से शक्तियों का विभाजन

42. संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, संसद को नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। यह रेखांकित करता है कि:
(A) भारत एक पूर्णतः संघीय राज्य है
(B) भारतीय संविधान में एक मजबूत एकात्मक झुकाव है
(C) राज्य विधानमंडलों के पास अपने क्षेत्रों पर सर्वोच्च अधिकार है
(D) भारत शासन के परिसंघीय मॉडल का पालन करता है

43. कौन-सा प्रावधान संघ सरकार को सामान्य काल के दौरान भी राज्य सूची के विषयों पर प्रत्यक्ष विधायी नियंत्रण रखने की अनुमति देता है, जो एकात्मक झुकाव को प्रदर्शित करता है?
(A) अनुच्छेद 249 (राज्यसभा का प्रस्ताव)
(B) अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा)
(C) अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन का लगाया जाना)
(D) अनुच्छेद 368 (संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया)

44. भारतीय संविधान की निम्नलिखित संरचनात्मक विशेषताओं पर विचार कीजिए:
I. एकल नागरिकता
II. एकीकृत न्यायिक प्रणाली
III. केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति
IV. द्विसदनीयता
उपर्युक्त में से कौन-सी विशेषता एकात्मक विशेषता नहीं है?
(A) केवल I और II
(B) केवल III
(C) केवल IV
(D) I, II और III

Downloaded from www.pdf.tube

45. राज्यपाल की कुछ राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने की शक्ति (अनुच्छेद 200) किसे दर्शाती है?
(A) राज्यपाल द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक विशुद्ध रूप से औपचारिक कार्य
(B) केंद्र के विरुद्ध राज्य की कानूनी स्वायत्तता का स्पष्ट दावा
(C) स्विस संविधान से ली गई एक विशिष्ट संवैधानिक विशेषता
(D) राज्य विधान पर केंद्रीय नियंत्रण

46. भारत का संवैधानिक ढांचा राज्यों को अपना अलग संविधान रखने की अनुमति नहीं देता है; वर्ष 2019 से पूर्व किस राज्य का ऐतिहासिक अपवाद था?
(A) पंजाब
(B) तमिलनाडु
(C) जम्मू और कश्मीर
(D) नागालैंड

47. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाने की शक्ति किस प्राधिकारी के पास है?
(A) राज्य के राज्यपाल
(B) भारत के राष्ट्रपति
(C) राज्य के मुख्यमंत्री
(D) राज्य विधानसभा

48. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): भारतीय संविधान शास्त्रीय अर्थों में पूर्णतः संघीय नहीं है।
कारण (R): संसद राज्यों की बाध्यकारी सहमति के बिना उनकी सीमाओं, नामों और क्षेत्रों को एकतरफा रूप से परिवर्तित कर सकती है।
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

49. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) किसके लेखाओं का अंकेक्षण (ऑडिट) करते हैं?
(A) केंद्र और राज्य सरकारें
(B) केवल भारत की केंद्र सरकार
(C) केवल विभिन्न राज्य सरकारें
(D) केवल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

50. भारत का निर्वाचन आयोग किसके चुनावों का संचालन करता है?
(A) केवल संघ संसद के दोनों सदनों के चुनाव
(B) केवल राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के चुनाव
(C) संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव
(D) संसद, राज्य विधानमंडल और स्थानीय पंचायतों के चुनाव

51. भारत द्वारा अपनाई गई संसदीय शासन प्रणाली को व्यापक रूप से किस रूप में भी जाना जाता है?
(A) वेस्टमिंस्टर मॉडल
(B) अध्यक्षात्मक प्रणाली
(C) कॉलेजिएट प्रणाली
(D) प्रत्यक्ष लोकतंत्र मॉडल

52. सरकार के संसदीय रूप का मौलिक आधारभूत सिद्धांत क्या है?
(A) कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का कठोर और पूर्ण पृथक्करण
(B) सभी मतदान करने वाले नागरिकों द्वारा सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख का प्रत्यक्ष चुनाव
(C) नाममात्र के कार्यकारी प्रमुख में निहित पूर्ण वैधानिक वीटो शक्ति
(D) विधायिका के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व

53. भारतीय संसदीय प्रणाली में, "नाममात्र की कार्यपालिका" कौन है?
(A) प्रधानमंत्री
(B) भारत के राष्ट्रपति
(C) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(D) लोकसभा अध्यक्ष

54. भारत में संसदीय प्रणाली की एक विशिष्ट विशेषता "दोहरी सदस्यता" की आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि:
(A) एक नागरिक के पास भारत और उसके गृह राज्य दोनों की दोहरी नागरिकता होनी चाहिए
(B) मंत्रियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक साथ सदस्यता होना आवश्यक है
(C) मंत्री कार्यपालिका और विधायिका दोनों के सदस्य होते हैं
(D) प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों में मतदान करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है

NODIA

55. भारतीय और ब्रिटिश संसदीय प्रणालियों की तुलना करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. भारत में गणतांत्रिक प्रणाली है जबकि ब्रिटेन में राजशाही प्रणाली है।
II. ब्रिटिश संसद के विपरीत, भारतीय संसद पूर्णतः संप्रभु नहीं है।
III. भारत में, प्रधानमंत्री का केवल निचले सदन (लोकसभा) से होना अनिवार्य है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

56. निचले सदन (लोकसभा) का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व विघटन किसकी एक विशिष्ट विशेषता है?
(A) एक संसदीय लोकतंत्र
(B) एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र
(C) एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र
(D) एक सत्तावादी शासन

57. भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में "वास्तविक कार्यपालिका" के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है?
(A) स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति
(B) मंत्रिपरिषद
(C) भारत की द्विसदनीय संसद
(D) भारत का उच्चतम न्यायालय

58. भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अध्यक्षात्मक प्रणाली की तुलना में संसदीय प्रणाली को मुख्य रूप से इसलिए प्राथमिकता दी क्योंकि:
(A) इसने सरकारी शक्तियों का अत्यधिक कठोर और पूर्ण पृथक्करण प्रदान किया
(B) इसने कार्यपालिका की दैनिक जवाबदेही प्रदान की
(C) इसने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए एक निश्चित, अपरिवर्तनीय कार्यकाल की सख्ती से गारंटी दी
(D) इसने एक ही पद में सभी संवैधानिक, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों को केंद्रित कर दिया

59. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है?
(A) अनुच्छेद 75
(B) अनुच्छेद 74
(C) अनुच्छेद 78
(D) अनुच्छेद 81

60. छाया मंत्रिमंडल (Shadow Cabinet) किस देश की संसदीय प्रणाली की विशिष्ट संस्था है, जिसका औपचारिक भारतीय प्रणाली में कोई सटीक समकक्ष नहीं है?
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका
(B) फ्रांस गणराज्य
(C) ब्रिटेन
(D) जर्मनी का संघीय गणराज्य

61. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कौन-सा संवैधानिक प्रावधान तैयार किया गया है?
(A) वे विधायी स्वीकृति के बिना सीधे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं
(B) वे पूरी तरह से राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं
(C) उन्हें सेवा के प्रत्येक पांच वर्ष में जनता के पुनर्निवार्चन का सामना करना पड़ता है
(D) उनके वेतन संचित निधि पर भारित होते हैं

62. संविधान संसद में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा पर रोक लगाता है, सिवाय तब जब:
(A) किसी भी सदन में दैनिक शून्यकाल की कार्यवाही के दौरान
(B) वार्षिक संसदीय बजट सत्र के विचार-विमर्श के दौरान
(C) न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हो
(D) प्रधानमंत्री द्वारा दी गई स्पष्ट पूर्व अनुमति प्राप्त हो

63. न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों पर प्रतिबंध है:
(A) सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी आधिकारिक संवैधानिक पद धारण करने से
(B) भारत के भीतर किसी भी अदालत में वकालत करने से
(C) किसी सरकारी आयोग या जांच समिति की अध्यक्षता करने से
(D) किसी राजनीतिक दल में शामिल होने या सक्रिय रूप से भाग लेने से

64. उच्चतम न्यायालय की अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति न्यायपालिका को किससे बचाने के लिए प्रदान की गई है?
(A) कार्यपालिका से सीधे राजनीतिक हस्तक्षेप से
(B) बाध्यकारी न्यायिक निर्णयों के विधायी निरसन से
(C) दैनिक अदालत की कार्यवाही को प्रकाशित करने वाले मीडिया संगठनों से
(D) इसके अधिकार पर अनुचित हमलों से

65. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (न्यायिक विशेषताएं)
P. न्यायिक पुनरावलोकन
Q. एकीकृत न्यायपालिका
R. शक्तियों का पृथक्करण
S. अभिलेख न्यायालय
सूची II: (विवरण)
1. संविधान का अनुच्छेद 50
2. कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति
3. वही अदालतें केंद्रीय और राज्य कानूनों को लागू करती हैं
4. निर्णयों का साक्ष्य मूल्य होता है और अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है
निम्नलिखित में से कौन-सा सही मिलान है?
(A) P-2, Q-3, R-1, S-4
(B) P-3, Q-2, R-1, S-4

Click Here to Buy book on Amazon

(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-1, Q-3, R-4, S-2

66. भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को अनुमति देती है:
(A) प्रस्तावित सभी विधायी मामलों पर राष्ट्रपति को नियमित रूप से सलाह देने की
(B) संविधान के पाठ को समय-समय पर फिर से लिखने और अद्यतन करने की
(C) संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों को अमान्य करने की
(D) केंद्रीय कार्यकारी शाखा के प्रमुख सदस्यों को सीधे नियुक्त करने की

67. भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे को संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में कुछ संकीर्ण माना जाता है क्योंकि भारतीय संविधान किस पर निर्भर करता है?
(A) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
(B) विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत
(C) संवैधानिक सर्वोच्चता के स्थान पर संसदीय संप्रभुता
(D) एक अलिखित और लचीला संवैधानिक ढांचा

68. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): भारतीय संविधान संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच एक संश्लेषण का प्रयास करता है।
कारण (R): संसद संविधान के प्रमुख भागों में संशोधन कर सकती है, जबकि उच्चतम न्यायालय उन कानूनों को रद्द कर सकता है जो मूल ढाँचे का उल्लंघन करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

69. कौन-सा संवैधानिक सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका मनमाने ढंग से न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में उनके अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती है?
(A) शक्तियों का पृथक्करण
(B) पद की सुरक्षा
(C) मूल क्षेत्राधिकार
(D) न्यायिक सक्रियता

70. न्यायिक स्वतंत्रता के संदर्भ में, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 50 राज्य को क्या निर्देश देता है?
(A) त्वरित और किफायती आपराधिक और नागरिक सुनवाइयाँ सुनिश्चित करना
(B) सभी निर्धन नागरिकों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करना
(C) कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना
(D) एक समान नागरिक संहिता स्थापित और लागू करना

71. भारतीय संविधान के भाग III, जिसमें मौलिक अधिकार शामिल हैं, को प्रायः किस रूप में संदर्भित किया जाता है?
(A) संविधान की आत्मा
(B) संविधान की अंतरात्मा
(C) संवैधानिक मेहराब की आधारशिला
(D) भारत का मैग्ना कार्टा

72. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारत में मौलिक अधिकारों की प्रकृति का सटीक वर्णन करता है?
(A) वे राज्य द्वारा लगाए गए युक्तियुक्त निबंधनों के अधीन हैं।
(B) वे निरपेक्ष हैं और किसी भी प्रतिबंध से मुक्त हैं।
(C) वे न्यायालयों द्वारा गैर-वादयोग्य हैं।
(D) वे बिना किसी अपवाद के केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं।

73. यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो उसे किस अनुच्छेद के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है?
(A) अनुच्छेद 226
(B) अनुच्छेद 32
(C) अनुच्छेद 13
(D) अनुच्छेद 14

74. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का वर्णन किस रूप में किया था?
(A) आधुनिक भारतीय राज्य की आवश्यक परिभाषित विशेषता
(B) संविधान की अनोखी (नवीन) विशेषताएँ
(C) गैर-आवश्यक और विशुद्ध रूप से विवेकाधीन नैतिक नियम
(D) अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स की एक सीधी संरचनात्मक प्रतिकृति

75. मौलिक अधिकारों (FR) और राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. मौलिक अधिकारों का उद्देश्य सामान्यतः राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।
II. नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।
III. मौलिक अधिकार वाद-योग्य हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व गैर-वादयोग्य हैं।
IV. टकराव की स्थिति में, नीति निदेशक तत्व हमेशा बिना किसी अपवाद के मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्राप्त करते हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल III

NODIA

(C) केवल IV
(D) II, III और IV

76. मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढाँचे की एक अनिवार्य विशेषता है। यह निश्चित रुप से किस वाद में स्थापित किया गया था?
(A) ए.के. गोपालन मामला (1950)
(B) गोलकनाथ मामला (1967)
(C) मिनर्वा मिल्स मामला (1980)
(D) एस.आर. बोम्मई मामला (1994)

77. चूंकि राज्य के नीति निदेशक तत्व गैर-वादयोग्य हैं, इसका अर्थ है कि:
(A) देश के शासन में उनका कोई मूल्य नहीं है
(B) संसद उनके आधार पर कोई कानून नहीं बना सकती है
(C) वे केवल राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी हैं, केंद्र सरकार के लिए नहीं
(D) उनके उल्लंघन के लिए उन्हें न्यायालयों द्वारा कानूनी रुप से लागू नहीं कराया जा सकता है

78. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा भाग III से किस मौलिक अधिकार को पूरी तरह से हटा दिया गया था?
(A) संवैधानिक उपचारों का अधिकार
(B) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
(C) संपत्ति का अधिकार
(D) समता का अधिकार

79. राज्य के नीति निदेशक तत्वों का समग्र लक्ष्य किसे स्थापित करना है?
(A) एक अहस्तक्षेपवादी पूंजीवादी राज्य
(B) एक कल्याणकारी राज्य
(C) एक पुलिस राज्य
(D) एक सत्तावादी राज्य

80. भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी किसके कृत्यों के विरुद्ध दी गई है?
(A) केवल निजी व्यक्तियों के कृत्यों के विरुद्ध
(B) केवल विधायिका के कृत्यों के विरुद्ध
(C) केवल न्यायपालिका के कृत्यों के विरुद्ध
(D) राज्य के कृत्यों के विरुद्ध

81. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी?
(A) 61वां संशोधन अधिनियम, 1988
(B) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
(C) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
(D) 73वां संशोधन अधिनियम, 1992

82. भारत में एकल नागरिकता की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. दोहरी राजव्यवस्था के बावजूद, भारत अपने सभी लोगों के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है।
II. भारत में, एक नागरिक केवल संघ के प्रति निष्ठा रखता है, अपने संबंधित राज्य के प्रति नहीं।
III. एकल नागरिकता राज्यों को निवास-आधारित कोई भी लाभ देने से पूरी तरह से रोकती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

83. संघीय संरचना होने के बावजूद एकल नागरिकता अपनाने का संवैधानिक औचित्य मुख्य रुप से क्या है?
(A) बंधुत्व और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना
(B) पासपोर्ट जारी करने से जुड़े प्रशासनिक बोझ को काफी कम करना
(C) राज्यों को एकतरफा प्रादेशिक स्वतंत्रता घोषित करने से रोकना
(D) संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक ढांचे का सीधे अनुकरण करना

84. भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक को जाति, नस्ल, धर्म, लिंग या संपत्ति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के मताधिकार प्राप्त है, जब तक कि वे विधि द्वारा अयोग्य न ठहराए गए हों। यह सिद्धांत किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है?
(A) अनुच्छेद 324
(B) अनुच्छेद 19
(C) अनुच्छेद 15
(D) अनुच्छेद 326

85. नागरिकता के प्रावधान, जो भारतीय राजव्यवस्था की एकीकृत और एकजुट प्रकृति को दर्शाते हैं, संविधान के किस भाग में निहित हैं?
(A) भाग I
(B) भाग II
(C) भाग III
(D) भाग IV

86. भारतीय न्यायिक प्रणाली एकीकृत है, जिसका अर्थ है कि:
(A) कार्यपालिका सभी अदालतों के कामकाज को नियंत्रित करती है
(B) उच्च न्यायालय केवल राज्य के विधियों को लागू करते हैं और उच्चतम न्यायालय केवल केंद्रीय विधियों को लागू करता है
(C) केंद्रीय और राज्य दोनों विधियों को लागू करने वाली अदालतों का एक एकल पदानुक्रम है
(D) जिला अदालतें उच्च न्यायालयों से पूरी तरह स्वतंत्र हैं

Downloaded from www.pdf.tube

87. एकीकृत न्यायिक प्रणाली के पदानुक्रम में, भारत के उच्चतम न्यायालय के ठीक नीचे कौन-सा न्यायालय आता है?
(A) जिला न्यायालय
(B) अधीनस्थ न्यायालय
(C) लोक अदालतें
(D) उच्च न्यायालय

88. आरोही क्रम में (निम्नतम से उच्चतम तक) भारतीय न्यायिक पदानुक्रम की सही व्यवस्था का चयन कीजिए:
I. उच्चतम न्यायालय
II. उच्च न्यायालय
III. अधीनस्थ/जिला न्यायालय
IV. ग्राम न्यायालय (जहाँ लागू हो)
निम्नलिखित में से कौन-सा सही क्रम है?
(A) IV, III, II, I
(B) III, IV, II, I
(C) I, II, III, IV
(D) IV, II, III, I

89. भारत की एकीकृत न्यायिक प्रणाली अमरीका की न्यायिक प्रणाली से भिन्न है क्योंकि:
(A) अमरीकी संवैधानिक ढांचे में संघीय सर्वोच्च न्यायालय का पूरी तरह से अभाव है
(B) अमरीका में अलग-अलग संघीय और राज्य अदालत प्रणालियां हैं
(C) भारत में, उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालय की अपीलों पर सुनवाई करने से संवैधानिक रूप से रोका गया है
(D) अमरीका का कानूनी ढांचा किसी भी प्रकार की न्यायिक समीक्षा को सख्ती से प्रतिबंधित करता है

90. भारतीय संविधान में एकीकृत एवं एकल न्यायपालिका की अवधारणा मुख्य रूप से कहाँ से अपनाई गई थी?
(A) 1867 का ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट
(B) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(C) संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान
(D) 1833 का इंपीरियल चार्टर एक्ट

91. भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है?
(A) अनुच्छेद 368
(B) अनुच्छेद 352
(C) अनुच्छेद 356
(D) अनुच्छेद 370

92. भारतीय संविधान की कौन-सी विशेषता इसे कठोरता और लचीलेपन का अनूठा मिश्रण बनाती है?
(A) संविधान के किसी भी हिस्से या प्रावधान को साधारण बहुमत से कभी संशोधित नहीं किया जा सकता है
(B) संवैधानिक संशोधनों को शुरु करने और पारित करने की अनन्य शक्ति राज्य विधानमंडलों के पास है
(C) यह साधारण, विशेष और राज्यों द्वारा अनुसमर्थित संशोधन विधियां प्रदान करता है
(D) सभी संवैधानिक संशोधनों के लिए देशव्यापी प्रत्यक्ष जनमत संग्रह की अनिवार्य स्वीकृति आवश्यक है

NODIA

93. संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण में परिवर्तन करने वाले संविधान संशोधन के लिए क्या आवश्यक है?
(A) संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत
(B) केवल संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्यता का विशेष बहुमत
(C) भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष प्रशासनिक स्वीकृति और समर्थन
(D) आधे राज्यों के अनुसमर्थन के साथ विशेष संसदीय बहुमत

94. अनुच्छेद 3 के तहत किसी नए राज्य के निर्माण या किसी मौजूदा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है?
(A) संसद में एक विशेष बहुमत
(B) सभी राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन
(C) संसद में एक साधारण बहुमत
(D) अनुच्छेद 368 के तहत एक संवैधानिक संशोधन

95. निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों और उनकी संशोधन आवश्यकताओं पर विचार कीजिए:
I. नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
II. मौलिक अधिकार
III. राष्ट्रपति का निर्वाचन
IV. राज्य विधान परिषदों का उत्सादन
उपर्युक्त में से किस प्रावधान के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन राज्यों के अनुसमर्थन की नहीं?
(A) केवल I और IV
(B) केवल II
(C) केवल II और III
(D) केवल III

96. संविधान संशोधनों की तुलना करने पर, भारतीय प्रक्रिया अमेरिकी प्रक्रिया के समक्ष कैसी है?
(A) भारतीय संशोधन प्रक्रिया अमेरिकी प्रक्रिया की तुलना में काफी अधिक कठोर है
(B) दोनों संवैधानिक संशोधन प्रक्रियाएं संरचनात्मक कठोरता में पूरी तरह से समान हैं
(C) न तो भारतीय और न ही अमेरिकी संविधान को किसी भी परिस्थिति में औपचारिक रूप से संशोधित किया जा सकता है
(D) भारतीय प्रक्रिया अधिक लचीली है

97. निम्नलिखित में से कौन-सा निकाय भारत में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकता है?
(A) राज्य विधानसभा
(B) लोकसभा
(C) राज्यसभा
(D) केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक मंत्री

98. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित संविधान में किए गए परिवर्तनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है।
कारण (R): ऐसे परिवर्तन संसद द्वारा साधारण बहुमत के साथ एक सामान्य विधायी प्रक्रिया के माध्यम से पारित किए जा सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

99. यदि अनुच्छेद 368 के तहत किसी संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न होता है:
(A) विधेयक समाप्त हो जाता है क्योंकि संयुक्त बैठक की अनुमति नहीं है
(B) राष्ट्रपति को गतिरोध को हल करने के लिए एक अनिवार्य संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है
(C) लोकसभा का निर्णय स्वचालित रूप से राज्यसभा की आपत्ति पर प्रभावी होता है
(D) संवैधानिक गतिरोध तुरंत निर्णय के लिए उच्चतम न्यायालय को भेजा जाता है

100. विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से संविधान में संशोधन करने की अवधारणा संविधान को क्या बनने से रोकती है?
(A) एक निरंतर विकसित होने वाला और गतिशील जीवंत दस्तावेज
(B) एक मजबूत और पूरी तरह से कार्यरत लोकतांत्रिक ढांचा
(C) एक आधिकारिक और सार्वभौमिक रूप से बाध्यकारी संप्रभु पाठ
(D) अचल या जल्दबाज़ी में किए गए परिवर्तनों के प्रति प्रवण

101. किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में "पंथनिरपेक्ष" शब्द स्पष्ट रूप से जोड़ा गया था?
(A) 24वां संशोधन अधिनियम
(B) 42वां संशोधन अधिनियम
(C) 44वां संशोधन अधिनियम
(D) 73वां संशोधन अधिनियम

102. भारतीय संविधान द्वारा अपनाई गई पंथनिरपेक्षता की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया गया है?
(A) नकारात्मक पंथनिरपेक्षता, जो राज्य और धर्म के बीच पूरी तरह से अलगाव को दर्शाती है
(B) नास्तिक पंथनिरपेक्षता, जो धार्मिक प्रथाओं को सक्रिय रूप से हतोत्साहित करती है
(C) सकारात्मक पंथनिरपेक्षता, जो सभी धर्मों को समान सम्मान और समान संरक्षण देती है
(D) धर्मतांत्रिक पंथनिरपेक्षता, जो किसी एक राज्य धर्म को प्राथमिकता देती है

103. भारतीय संविधान में अनुच्छेदों का कौन-सा समूह विशेष रूप से धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जो राष्ट्र के पंथनिरपेक्ष ताने-बाने को सुरक्षित करता है?
(A) अनुच्छेद 14 से 18
(B) अनुच्छेद 19 से 22
(C) अनुच्छेद 29 और 30
(D) अनुच्छेद 25 से 28

104. भारतीय पंथनिरपेक्षता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राज्य किसी भी विशेष धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में नहीं मानता है।
II. सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने और उसका आचरण करने की विचार की स्वतंत्रता प्राप्त है।
III. राज्य को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से रोका गया है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

105. संविधान के पंथनिरपेक्ष ढांचे के तहत, किस प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी?
(A) धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित
(B) पूरी तरह से राज्य निधि से पोषित
(C) राज्य द्वारा सहायता प्राप्त लेकिन किसी धर्मार्थ ट्रस्ट के तहत स्थापित
(D) एक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल के रूप में संचालित

106. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे?
(A) केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग
(B) स्वर्ण सिंह समिति
(C) राष्ट्रीय कोठारी शिक्षा आयोग
(D) भ्रष्टाचार पर संथानम समिति

107. संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है?

Click Here to Buy book on Flipkart

(A) भाग IVA, अनुच्छेद 51A
(B) भाग III, अनुच्छेद 35
(C) भाग IV, अनुच्छेद 51
(D) भाग V, अनुच्छेद 52

108. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (विशिष्ट मौलिक कर्तव्य)
P. महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना
Q. समृद्ध विरासत का मूल्य समझना और उसका संरक्षण करना
R. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना
S. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना
सूची II: (मुख्य अवधारणा)
1. सामासिक संस्कृति
2. मानववाद और जिज्ञासा की भावना
3. स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष
4. वन, झीलें, नदियां और वन्यजीव
निम्नलिखित में से कौन-सा सही मिलान है?
(A) P-1, Q-3, R-2, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

109. मौलिक कर्तव्यों की प्रवर्तनीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
(A) वे रिट के माध्यम से अदालतों द्वारा सीधे लागू करने योग्य हैं।
(B) वे भारत में रहने वाले नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिए बाध्यकारी हैं।
(C) किसी नागरिक को बिना किसी विशिष्ट कानून के किसी भी मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करने पर स्वचालित रूप से जेल में डाला जा सकता है।
(D) वे गैर-वादयोग्य हैं लेकिन संसद उपयुक्त विधान द्वारा उन्हें लागू कर सकती है।

110. मूल रूप से, 42वें संशोधन ने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। शिक्षा से संबंधित 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?
(A) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
(B) 92वां संशोधन अधिनियम, 2003
(C) 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
(D) 97वां संशोधन अधिनियम, 2011

111. संविधान तीन प्रकार के आपातकाल का प्रावधान करता है। कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है?
(A) अनुच्छेद 356
(B) अनुच्छेद 352
(C) अनुच्छेद 360
(D) अनुच्छेद 365

112. भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का सबसे अनूठा पहलू यह है कि:
(A) वे संविधान के पाठ को पूरी तरह और स्थायी रूप से निलंबित कर देते हैं
(B) वे राज्यों को संघ से एकतरफा अलग होने का कानूनी अधिकार देते हैं
(C) उन्हें संयुक्त राष्ट्र के प्रशासनिक हस्तक्षेप की सख्त आवश्यकता होती है
(D) वे संशोधन के बिना संघीय ढांचे को एकात्मक में बदल देते हैं

113. द्विसदनीयता संघ संसद की एक संरचनात्मक विशेषता है। कौन-सा सदन संघीय ढांचे में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है?
(A) राज्यसभा
(B) लोकसभा
(C) विधानसभा
(D) जिला परिषद

114. केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका का अस्तित्व मुख्य रूप से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है?
(A) सभी आवश्यक वित्तीय विधानों के समय पर पारित होने में जानबूझकर देरी करना
(B) यह विशेष रूप से सुनिश्चित करना कि केवल मनोनीत सदस्यों के पास कानून पारित करने का अधिकार हो
(C) राज्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व करके संघीय संतुलन बनाए रखना
(D) न्यायिक प्रणाली के विकल्प के रूप में एक स्वतंत्र शाखा के रूप में कार्य करना

115. आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, केंद्र किसी भी मामले पर राज्यों को कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त कर लेता है।
II. अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल भारत में केवल एक बार, 1991 के आर्थिक संकट के दौरान घोषित किया गया है।
III. यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है (अनुच्छेद 365), तो राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लगाया जा सकता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

116. लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा के लिए, संविधान स्वतंत्र निकायों का प्रावधान करता है। संघ और राज्य सरकारों के लेखाओं का अंकेक्षण (ऑडिट) करने के लिए कौन-सा निकाय उत्तरदायी है?

Downloaded from www.pdf.tube

(A) भारत का वित्त आयोग
(B) नीति आयोग
(C) संसदीय लोक लेखा समिति
(D) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

117. भारत का निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। यह अपनी शक्ति सीधे कहाँ से प्राप्त करता है?
(A) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
(B) संविधान का अनुच्छेद 324
(C) विधि एवं न्याय मंत्रालय
(D) भारत का उच्चतम न्यायालय

118. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के सदस्यों को पद की सुरक्षा प्राप्त है।
कारण (R): यह सुनिश्चित करता है कि वे कार्यकारी दबाव के बिना विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर सिविल सेवकों की भर्ती कर सकें।
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

119. स्थानीय स्वशासन की त्रि-स्तरीय प्रणाली (पंचायतों और नगर पालिकाओं) की शुरुआत भारतीय संवैधानिक संरचना को अद्वितीय बनाती है। यह किसके माध्यम से स्थापित किया गया था?
(A) 1वें और 2वें संवैधानिक संशोधन
(B) 42वें और 44वें संवैधानिक संशोधन
(C) 86वें और 97वें संवैधानिक संशोधन
(D) 73वें और 74वें संविधान संशोधन

120. ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज) को संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए संविधान में कौन-सा भाग जोड़ा गया था?
(A) भाग IX
(B) भाग VIII
(C) भाग IX-A
(D) भाग X

121. उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित ऐतिहासिक निर्णयों का सही कालानुक्रमिक क्रम चुनिए जिन्होंने संविधान के "मूल ढाँचे" के सिद्धांत को आकार दिया:
(A) शंकरी प्रसाद मामला, गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला
(B) गोलकनाथ मामला, शंकरी प्रसाद मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, केशवानंद भारती मामला
(C) केशवानंद भारती मामला, गोलकनाथ मामला, शंकरी प्रसाद मामला, मिनर्वा मिल्स मामला
(D) शंकरी प्रसाद मामला, केशवानंद भारती मामला, गोलकनाथ मामला, मिनर्वा मिल्स मामला

122. भारतीय संविधान को अक्सर एक "जीवंत दस्तावेज़" कहा जाता है क्योंकि:
(A) इसे विरासत में मिलने के बजाय असेंबली में जीवित व्यक्तियों द्वारा सीधे तैयार किया गया था
(B) यह संशोधनों और व्याख्या के माध्यम से बदलती जरूरतों के अनुकूल ढलता है
(C) इसमें पूर्ण कठोरता है और स्थापना के बाद से एक बार भी संशोधित नहीं किया गया है
(D) यह कानून द्वारा स्वचालित रूप से समाप्त हो जाता है और प्रत्येक 50 वर्षों में पूरी तरह से नवीनीकृत किया जाना चाहिए

123. "मूल ढाँचा सिद्धांत" (Basic Structure Doctrine), जो संविधान की मुख्य विशेषताओं को विधायी संशोधनों द्वारा नष्ट होने से बचाता है, किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था?
(A) 1950
(B) 1967
(C) 1973
(D) 1980

124. भारतीय संविधान की एक बार-बार की जाने वाली आलोचना यह है कि यह किसकी एक "कार्बन कॉपी" या "संवर्धित संस्करण" है?
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान
(B) 1928 की नेहरु रिपोर्ट
(C) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(D) ब्रिटिश अलिखित संविधान

NODIA

125. शुरुआती आलोचकों द्वारा भारतीय संविधान के खिलाफ की गई निम्नलिखित आलोचनाओं पर विचार कीजिए:
I. यह "गैर-भारतीय" या "भारतीयता-विरोधी" है क्योंकि यह स्वदेशी लोकाचार को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
II. अपने अत्यधिक आकार के कारण यह एक विशालकाय दस्तावेज़ है।
III. अपनी जटिल कानूनी भाषा के कारण यह "वकीलों का स्वर्ग" है।
IV. यह अंतर्निहित रूप से अस्थायी है और प्रत्येक दशक में पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता होती है।
उपर्युक्त में से कौन-सी आलोचनाएं संविधान सभा की बहसों में ऐतिहासिक रूप से मान्य हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I और IV
(D) I, II, III और IV

126. निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को "वकीलों का स्वर्ग" कहा था?

(A) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

(B) महात्मा गांधी

(C) सर आइवर जेनिंग्स

(D) के.एम. मुंशी

127. यह आलोचना कि भारतीय संविधान "गैर-भारतीय" है, मुख्य रूप से इस धारणा पर आधारित है कि:

(A) इसे विशेष रूप से और पूरी तरह से विदेशी संवैधानिक कानून विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया था

(B) यह प्राचीन भारतीय परंपराओं के बजाय विदेशी मॉडलों पर निर्भर करता है

(C) यह मूल रूप से स्वदेशी भारतीय भाषाओं के बजाय अंग्रेजी में लिखा गया था

(D) यह विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता देने में पूरी तरह से विफल रहता है

128. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:

सूची I: (विद्वान/आलोचक)

P. के.सी. व्हीयर

Q. आइवर जेनिंग्स

R. ग्रैनविल ऑस्टिन

S. मॉरिस जोन्स

सूची II: (भारतीय संविधान पर टिप्पणी)

1. सहकारी संघवाद
2. सौदेबाज़ी वाला संघवाद
3. एक मजबूत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ
4. अर्ध-संघीय

निम्नलिखित में से कौन-सा सही मिलान है?

(A) P-3, Q-4, R-2, S-1

(B) P-4, Q-3, R-2, S-1

(C) P-1, Q-2, R-4, S-3

(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

129. अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने में शामिल प्रक्रियात्मक चरणों का सही क्रम चुनिए:

I. प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से विधेयक का पारित होना

II. संसद के किसी भी सदन में विधेयक को पेश किया जाना

III. राष्ट्रपति की सहमति

IV. आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन (यदि आवश्यक हो)

निम्नलिखित में से कौन-सा सही क्रम है?

(A) II, I, IV, III

(B) I, II, III, IV

(C) II, IV, I, III

(D) IV, II, I, III

130. विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद, भारत के मूल संवैधानिक ढाँचे की समकालीन प्रासंगिकता और सफलता का सबसे अच्छा प्रमाण क्या है?

(A) समय के साथ पूरी तरह से नए संवैधानिक पाठों द्वारा इसका बार-बार प्रतिस्थापन

(B) इसकी पूर्ण संरचनात्मक कठोरता और नए अधिकारों को शामिल करने में मौलिक असमर्थता

(C) 1950 से निरंतर लोकतांत्रिक कामकाज और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण

(D) संघ के पास सभी प्रशासनिक शक्तियों का पूर्ण और पूर्ण केंद्रीयकरण

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Amazon

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (A) के.सी. व्हीयर
भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताओं और एकात्मक झुकाव का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए प्रसिद्ध संवैधानिक विशेषज्ञ के.सी. व्हीयर ने इसे अर्ध-संघीय प्रणाली के रूप में रेखांकित किया था। उनका तर्क था कि भारत में एकात्मक राज्य की भावना अधिक प्रबल है जिसमें संघात्मक तत्व केवल सहायक रूप में विद्यमान हैं। केंद्र सरकार को दी गई अत्यधिक शक्तियाँ और राज्यों की सीमित स्वायत्तता इस विशिष्ट संरचनात्मक व्यवस्था का मुख्य आधार बनती हैं।

2. (C) सभी राज्यों के लिए एकल नागरिकता
भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में एकल नागरिकता का प्रावधान प्रशासनिक अखंडता तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शामिल किया गया है। अमेरिका जैसी दोहरी नागरिकता वाली संघीय प्रणालियों के विपरीत, भारत में प्रत्येक व्यक्ति केवल देश का नागरिक होता है। किसी भी राज्य के लिए पृथक नागरिकता की व्यवस्था न होना संविधान के पूर्णतः एकात्मक लक्षण को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है तथा क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करता है।

3. (A) ग्रैनविल ऑस्टिन
प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद का गहन अध्ययन करने के पश्चात इसके लिए सहकारी संघवाद शब्द का प्रयोग किया था। उनका मानना था कि भारतीय संविधान ने एक मजबूत केंद्रीय सरकार का निर्माण किया है, फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य केवल केंद्र के प्रशासनिक एजेंट बनकर रह गए हैं। यह व्यवस्था केंद्र तथा राज्यों के मध्य आपसी सहयोग और सामंजस्य पर आधारित है।

4. (D) ढांचा संघीय है लेकिन केंद्र संरचनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली है
भारतीय राजव्यवस्था का आधारभूत ढाँचा संघात्मक है, जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। हालाँकि, राष्ट्रीय अखंडता, सुरक्षा और प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने हेतु संविधान में केंद्र सरकार को अत्यंत व्यापक और प्रभावी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसी विशिष्ट संरचनात्मक असंतुलन और केंद्रीय वर्चस्व के कारण भारतीय व्यवस्था को स्पष्ट रूप से एकात्मक झुकाव वाला संघवाद कहा जाता है।

5. (B) एकीकृत एवं एकल न्यायपालिका
शास्त्रीय अमेरिकी संघीय मॉडल में संघ और प्रत्येक राज्य की अपनी स्वतंत्र तथा पृथक न्यायपालिका होती है जो अपने-अपने कानूनों को लागू करती है। इसके विपरीत, भारत में शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय और उसके अधीन उच्च न्यायालयों वाली एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली स्थापित की गई है। यह संपूर्ण देश में केंद्रीय तथा राज्य दोनों प्रकार के कानूनों को एक समान रूप से लागू करती है।

6. (C) बिना किसी औपचारिक संशोधन के संघीय से पूर्णतः एकात्मक में
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान का व्यावहारिक स्वरूप बिना किसी औपचारिक संशोधन के स्वतः ही एकात्मक प्रणाली में बदल जाता है। इस अवधि में संघ सरकार को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने और राज्यों को प्रशासनिक निर्देश देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह व्यवस्था देश की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता की रक्षा के लिए केंद्र को सर्वोपरि शक्तियाँ प्रदान करती है।

NODIA

7. (D) एक विशाल और विविधतापूर्ण देश में कुशल प्रशासन सुनिश्चित करना
भारत भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत विशाल होने के साथ-साथ भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं से परिपूर्ण देश है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का स्पष्ट विचार था कि इतने बड़े और विविध राष्ट्र को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण अनिवार्य है। इसलिए, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति और कुशल प्रशासनिक तंत्र की स्थापना हेतु भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया था।

8. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
भारत का ढांचा संघात्मक रूप से निर्मित है जिसमें शक्तियों का विभाजन मौजूद है, किंतु संकटकाल में केंद्र अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। आपातकाल के समय संघ सरकार राज्यों के विधायी और कार्यकारी मामलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर सकती है। यह विशिष्ट प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि सामान्य परिस्थितियों में संघीय दिखाई देने वाला यह संविधान संकट के समय अपनी भावना में पूर्णतः एकात्मक रूप धारण कर लेता है।

9. (B) एक एकात्मक विशेषता जो केंद्रीय पर्यवेक्षण को सक्षम बनाती है
भारत में राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है। यह व्यवस्था केंद्र सरकार को राज्यों के प्रशासन पर निरंतर पर्यवेक्षण और नियंत्रण बनाए रखने का अवसर प्रदान करती है। इसलिए राज्यपाल का पद संघात्मक सिद्धांतों के विपरीत भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण एकात्मक विशेषता माना जाता है।

10. (B) एस.आर. बोम्मई मामला
वर्ष 1994 के प्रसिद्ध एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था। इस निर्णय में न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि संघवाद भारतीय संविधान के मूल ढाँचे का एक अनिवार्य अंग है। इसके अनुसार राज्यों की अपनी स्वतंत्र संवैधानिक स्थिति है और केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 का मनमाना प्रयोग करके राज्यों की स्वायत्तता को समाप्त नहीं कर सकती।

11. (A) भारत सरकार अधिनियम, 1935
भारतीय संविधान का मुख्य प्रशासनिक और ढांचागत आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इस अधिनियम ने भारत में एक संघीय योजना, राज्यपाल के पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोगों और आपातकालीन प्रावधानों का विस्तृत ढाँचा प्रदान किया था। वर्तमान संविधान के लगभग दो-तिहाई प्रावधान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी ऐतिहासिक कानूनी दस्तावेज के व्यापक प्रावधानों पर ही आधारित हैं।

12. (C) संयुक्त राज्य अमेरिका
भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था से ग्रहण किया गया है। यह शक्ति न्यायपालिका को विधायिका द्वारा पारित कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करने का अधिकार देती है। यदि कोई कानून या नीति संविधान के मौलिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तो न्यायालय उसे असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकता है।

13. (D) अध्यक्ष (स्पीकर) का पद
भारत की संसदीय प्रणाली और उससे संबंधित अनेक संस्थागत ढाँचे ब्रिटिश संवैधानिक परंपराओं से गहराई से प्रभावित हैं। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के संचालन हेतु अध्यक्ष का पद, उनकी निष्पक्ष भूमिका और विशेषाधिकार सीधे ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स की परंपराओं से अपनाए गए हैं। यह व्यवस्था विधायिका की कार्यवाही को सुचारु, सुव्यवस्थित और लोकतांत्रिक ढंग से संचालित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

14. (C) आयरलैंड का संविधान
संविधान के भाग IV में शामिल राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड ने स्वयं इन्हें स्पेनिश संविधान से ग्रहण किया था। ये तत्व एक सामाजिक और आर्थिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हालाँकि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, फिर भी देश के शासन में मूलभूत माने जाते हैं।

15. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के उत्कृष्ट प्रावधानों का समावेश किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का विचार लिया गया है, जबकि जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ली गई है। सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तथा फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेते हुए प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के महान आदर्शों को शामिल किया गया है।

16. (D) कनाडा
भारत में एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का मॉडल कनाडाई संविधान से प्रेरित होकर अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ सौंपी गई हैं और अवशिष्ट शक्तियाँ भी केंद्र सरकार में ही निहित की गई हैं। यह ढाँचा देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत उपयुक्त माना गया है।

17. (A) जर्मनी का वाइमर संविधान
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित हैं। इस व्यवस्था के तहत संकटकालीन स्थिति में राष्ट्र की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त होता है, हालांकि अनुच्छेद 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता।

18. (C) संविधान संशोधन प्रक्रिया - दक्षिण अफ्रीका का संविधान
भारतीय संविधान में संशोधन की विशेष प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। यह प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है जो संविधान को परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में सक्षम बनाती है। इसके विपरीत, गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस से, विधि का शासन ब्रिटेन से तथा कैबिनेट प्रणाली भी ब्रिटिश संविधान से ही ग्रहण की गई है।

19. (A) दक्षिण अफ्रीका
भारतीय संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विशिष्ट प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। यह व्यवस्था संसद में राज्यों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का एक प्रमुख संवैधानिक साधन है।

20. (B) केवल I और III
भारत सरकार अधिनियम 1935 ने देश के प्रशासनिक ढांचे, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल के पद और न्यायपालिका का मुख्य आधार तैयार किया था। हालाँकि, मौलिक अधिकारों की दार्शनिक और वैचारिक प्रेरणा 1935 के अधिनियम से नहीं, बल्कि मुख्य रूप से अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्राप्त हुई थी। इसलिए पहला और तीसरा कथन पूरी तरह से सही हैं जबकि दूसरा कथन असत्य है।

21. (B) कनाडा
भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने का प्रावधान कनाडाई संविधान से लिया गया है। इस व्यवस्था के अनुसार, जो विषय संघ, राज्य या समवर्ती सूची

Downloaded from www.pdf.tube

में स्पष्ट रुप से शामिल नहीं हैं, उन पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार केंद्रीय संसद के पास होता है। यह प्रावधान देश की राष्ट्रीय अखंडता को मजबूत करने हेतु केंद्र को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है।

22. (C) आयरलैंड
भारत के राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करने की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है। यह प्रावधान संसद में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और गुणी व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है ताकि वे राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होकर देश के विधायी कार्यों में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें।

23. (D) संसदीय विशेषाधिकार
भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग तथा उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया अमेरिकी संविधान से ली गई है। इसके विपरीत, संसद और उसके सदस्यों के संसदीय विशेषाधिकारों का प्रावधान ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ग्रहण किया गया है। इसलिए संसदीय विशेषाधिकार की अवधारणा अमेरिकी संविधान से संबंधित नहीं है, बल्कि यह ब्रिटिश परंपरा पर आधारित है।

24. (A) ब्रिटिश विधिक प्रणाली
भारतीय संविधान में निहित विधि के शासन का सिद्धांत मूल रुप से ब्रिटिश विधिक प्रणाली का एक मुख्य स्तंभ है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध ब्रिटिश विधिवेत्ता ए.वी. डायसी ने किया था। इसके अनुसार कानून सर्वोपरि है और सभी व्यक्ति, चाहे उनका पद या स्थिति कुछ भी हो, कानून के समक्ष समान हैं तथा साधारण न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन आते हैं।

25. (B) रुसी क्रांति
संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के उदात्त आदर्श मुख्य रुप से 1917 की रुसी क्रांति से प्रेरित थे। इस क्रांति ने समाज के वंचित और शोषित वर्गों के अधिकारों, समानता और न्याय पर विशेष बल दिया था। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इन आदर्शों को अपनाकर देश में एक न्यायपूर्ण और समतावादी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण की नींव रखी थी।

26. (B) परमाधिकार रिटों का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था
नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जारी की जाने वाली परमाधिकार रिटों का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से नहीं, बल्कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से केवल समवर्ती सूची और व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणाएं ली गई हैं। फ्रांस से गणतंत्र, कनाडा से उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार तथा सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, जो पूरी तरह सही सुमेलित हैं।

NODIA

27. (A) संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान
भारत में उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता, उसकी संरचना और शक्ति का मूल स्वरुप अमेरिकी संविधान से गहराई से प्रभावित है। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में अमेरिकी प्रणाली की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। यह प्रभाव भारत में एक मजबूत, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ है।

28. (C) भारत सरकार अधिनियम, 1935
संविधान के भाग XVIII में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधानों का संरचनात्मक ढाँचा मुख्य रुप से भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इस अधिनियम ने केंद्र सरकार को असाधारण परिस्थितियों में राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के कानूनी अधिकार दिए थे। हालाँकि, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का विशिष्ट सिद्धांत जर्मनी के वाइमर संविधान की प्रेरणा से जोड़ा गया था।

29. (D) ऑस्ट्रेलिया का संविधान
भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अंतरराज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की संवैधानिक अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। संविधान का भाग XIII यह सुनिश्चित करता है कि राज्यों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आवागमन पर कोई अनावश्यक प्रतिबंध न लगाया जाए। यह प्रावधान देश के भीतर एक एकीकृत आर्थिक बाजार और राष्ट्रीय आर्थिक सहभागिता को बढ़ावा देने में मदद करता है।

30. (B) केवल II, III और IV
भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान 1861 के अधिनियम से हुई थी, इसलिए पहला कथन गलत है। द्विसदनीय विधायिका 1919 और 1935 के अधिनियमों में मौजूद थी, कानून का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से लिया गया है, और आयरलैंड ने DPSP स्पेन से अपनाए थे। अतः दूसरा, तीसरा और चौथा कथन पूरी तरह से सत्य और ऐतिहासिक रुप से सटीक हैं।

31. (B) 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ
संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए गए मूल भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ शामिल थीं। यह दस्तावेज अपने व्यापक प्रशासनिक विवरणों और विस्तृत प्रावधानों के कारण अत्यंत विस्तृत था। बाद में विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से इसमें नई अनुसूचियाँ और अनुच्छेद जोड़े गए, जिससे वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है।

32. (D) इसमें विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान शामिल हैं।
भारतीय संविधान का आकार अत्यधिक विशाल होने का प्रमुख कारण इसमें केवल संवैधानिक सिद्धांतों का ही नहीं, बल्कि विस्तृत प्रशासनिक विवरणों का भी समावेश होना है। 1935 के अधिनियम से सीधे ली गई प्रशासनिक व्यवस्थाओं, केंद्र-राज्य संबंधों, न्यायपालिका और आपातकालीन प्रावधानों का गहराई से वर्णन किया गया है। इस गहन विस्तार ने संविधान

को दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत लिखित दस्तावेज बना दिया।

33. (A) वकील
संविधान सभा में कानूनविदों और वकीलों का अत्यधिक बाहुल्य था, जिसके कारण आलोचकों ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा। वकीलों के प्रभाव के कारण ही संविधान की भाषा अत्यंत क्लिष्ट, कानूनी बारीकियों से परिपूर्ण और अत्यधिक विस्तृत हो गई। इस कानूनी शब्दावली और विस्तृत व्याख्याओं ने संविधान के आकार को अभूतपूर्व रूप से बड़ा और जटिल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

34. (C) 25
1949 में अपनाए गए मूल संविधान में 22 भाग थे। समय-समय पर किए गए विभिन्न संवैधानिक संशोधनों द्वारा इसमें नए भाग जैसे 4A (मौलिक कर्तव्य), 9A (नगर पालिकाएं), 9B (सहकारी समितियां) और 14A (अधिकरण) जोड़े गए, जबकि भाग 7 को निरसित कर दिया गया। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरुप वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है।

35. (A) P-2, Q-4, R-3, S-1
भारतीय संविधान के विभिन्न भाग विशिष्ट विषयों का निरूपण करते हैं। भाग II में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद शामिल हैं, जबकि भाग III में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। भाग IV राज्य के नीति निदेशक तत्वों का मार्गदर्शन करता है और भाग IVA मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करता है। यह स्पष्ट वर्गीकरण संविधान की संरचनात्मक स्पष्टता और व्यवस्था को प्रदर्शित करता है।

36. (D) नौवीं अनुसूची
मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ शामिल थीं। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में नौवीं अनुसूची को सबसे पहले जोड़ा गया था। इस अनुसूची को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य भूमि सुधारों और राज्य सरकारों द्वारा किए गए अन्य सामाजिक-आर्थिक कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्रदान करना था ताकि जमींदारी उन्मूलन को सुचारु रुप से लागू किया जा सके।

37. (B) लंबाई और विस्तृत विवरण
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों, नीति निदेशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों का एक साथ विस्तृत समावेश इसकी विशालता को बढ़ाता है। यह त्रिस्तरीय ढांचा केवल नागरिक अधिकारों को ही रेखांकित नहीं करता, बल्कि राज्य के दायित्वों और नागरिकों के कर्तव्यों की भी गहन व्याख्या करता है। इन सभी पहलुओं के व्यापक और स्पष्ट वर्णन के कारण संविधान का आकार अत्यंत लंबा और विस्तृत हो गया है।

38. (B) भाग IVA, भाग XIVA, भाग IXA, भाग IXB
संविधान के भागों का सही कालानुक्रमिक क्रम उनके संशोधन वर्ष पर आधारित है। भाग IVA (मौलिक कर्तव्य) और भाग XIVA (अधिकरण) दोनों को 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके पश्चात भाग IXA (नगर पालिकाएं) को 1992 के 74वें संशोधन द्वारा और भाग IXB (सहकारी समितियां) को 2011 के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया था।

39. (D) संघ और राज्यों के लिए एक एकल संविधान प्रदान करता है
अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में संघ और प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान होता है, जो दोहरी राजव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इसके सर्वथा विपरीत, भारतीय संविधान संपूर्ण देश अर्थात संघ और सभी राज्यों के लिए केवल एक ही एकीकृत संविधान का प्रावधान करता है। यह विशिष्ट विशेषता भारत की राष्ट्रीय अखंडता, प्रशासनिक एकरूपता और संप्रभुता को सुदृढ़ आधार प्रदान करती है।

40. (A) प्रशासनिक विवरण
भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत और प्रशासनिक भाग सीधे भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसमें संघीय योजना, न्यायपालिका की संरचना, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय और विस्तृत प्रशासनिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। हालाँकि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व मुख्य रूप से अन्य विदेशी संविधानों से प्रेरित हैं, फिर भी प्रशासनिक स्वरुप का मुख्य आधार 1935 का अधिनियम ही है।

41. (B) अखिल भारतीय सेवाएं
भारतीय संविधान में आईएएस और आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाएं एक प्रमुख एकात्मक विशेषता हैं। यद्यपि ये अधिकारी राज्यों में तैनात होते हैं और राज्य प्रशासन का संचालन करते हैं, किंतु उन पर अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। यह व्यवस्था केंद्र को राज्यों के प्रशासनिक ढांचे पर सीधा प्रभाव बनाए रखने में सक्षम बनाती है, जो एकात्मकता को दर्शाता है।

42. (B) भारतीय संविधान में एक मजबूत एकात्मक झुकाव है
संविधान का अनुच्छेद 3 केंद्रीय संसद को यह असाधारण शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी भी राज्य की सहमति के बिना उसके नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। यह प्रावधान यह सिद्ध करता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। राज्यों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जो भारतीय संविधान के मजबूत एकात्मक झुकाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

43. (A) अनुच्छेद 249 (राज्यसभा का प्रस्ताव)
संविधान का अनुच्छेद 249 राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि यदि वह उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों के विशेष बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि कोई राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। यह प्रावधान सामान्य काल में भी केंद्र सरकार को राज्यों के विधायी मामलों में प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति देता है।

Click Here to Buy book on Flipkart

44. (C) केवल IV
एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति ये तीनों भारतीय राजव्यवस्था की एकात्मक विशेषताएं हैं जो केंद्र को मजबूत बनाती हैं। इसके विपरीत, द्विसदनीयता अर्थात विधायिका में दो सदनों का होना एक अनिवार्य संघीय विशेषता है जो उच्च सदन में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। इसलिए केवल द्विसदनीयता ही यहाँ एकात्मक विशेषता का हिस्सा नहीं है।

45. (D) राज्य विधान पर केंद्रीय नियंत्रण
संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सके। इस प्रावधान के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों की समीक्षा कर सकती है और उन्हें रोक सकती है। यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से राज्य के विधायी कार्यों पर केंद्रीय नियंत्रण और एकात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करती है।

46. (C) जम्मू और कश्मीर
भारतीय संविधान के तहत सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान लागू होता है। हालाँकि, वर्ष 2019 से पूर्व अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका अपना पृथक संविधान और विशेष संवैधानिक दर्जा था। अगस्त 2019 में संसद द्वारा किए गए ऐतिहासिक विधायी परिवर्तनों के पश्चात इस विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया और अब वहां भी भारतीय संविधान लागू होता है।

47. (B) भारत के राष्ट्रपति
यद्यपि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु उन्हें पद से हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति उन्हें केवल उच्चतम न्यायालय की जाँच रिपोर्ट के आधार पर ही पदमुक्त कर सकते हैं। यह संवैधानिक व्यवस्था केंद्र के प्रशासनिक वर्चस्व को रेखांकित करती है, जो एकात्मकता का एक स्पष्ट उदाहरण है।

48. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
भारतीय संविधान शास्त्रीय अर्थों में पूर्ण संघात्मक नहीं है क्योंकि इसमें राज्यों की प्रादेशिक अखंडता की गारंटी नहीं दी गई है। संसद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य की सहमति के बिना उसकी सीमाओं और नामों में एकतरफा परिवर्तन कर सकती है। यही कारण है कि भारत को अनश्वर संघ का नश्वर राज्य कहा जाता है, जो यह साबित करता है कि यह पूर्णतः संघीय न होकर एकात्मक झुकाव वाला है।

49. (A) केंद्र और राज्य सरकारें
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है जो केंद्र सरकार तथा सभी राज्य सरकारों के वित्तीय खातों और व्यय का अंकेक्षण करता है। यह एकीकृत वित्तीय लेखापरीक्षा प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि संपूर्ण देश में वित्तीय अनुशासन और सार्वजनिक धन का उत्तरदायित्व बनाए रखा जाए। इसलिए यह तंत्र केंद्र और राज्यों दोनों के खातों पर एक समान रूप से लागू होता है।

50. (C) संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव
भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है जो देश की लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन करती है। यह आयोग संघ संसद के दोनों सदनों, सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानमंडलों, तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के चुनावों का निष्पक्ष संचालन करता है। पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोगों के पास होती है।

51. (A) वेस्टमिंस्टर मॉडल
भारत में अपनाई गई संसदीय शासन प्रणाली को व्यापक रूप से वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से जाना जाता है। यह नाम लंदन स्थित ब्रिटिश संसद के स्थान वेस्टमिंस्टर के आधार पर पड़ा है। इस प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, जहाँ कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है और उसके प्रति उत्तरदायी रहती है, जो इस मॉडल की पहचान है।

52. (D) विधायिका के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व
सरकार के संसदीय स्वरूप का सबसे मौलिक आधारभूत सिद्धांत कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री और उनकी पूरी मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यों और नीतियों के लिए संयुक्त रूप से संसद के निचले सदन के प्रति जवाबदेह होती है। यदि निचले सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पूरी सरकार को तुरंत अपना त्यागपत्र देना पड़ता है।

53. (B) भारत के राष्ट्रपति
भारतीय संसदीय प्रणाली में भारत के राष्ट्रपति देश के संवैधानिक एवं नाममात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियाँ औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती हैं, किंतु वे इन शक्तियों का प्रयोग व्यावहारिक रूप से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख हैं, जबकि प्रधानमंत्री सरकार के वास्तविक प्रमुख होते हैं।

54. (C) मंत्री कार्यपालिका और विधायिका दोनों के सदस्य होते हैं
भारतीय संसदीय व्यवस्था में दोहरी सदस्यता का सिद्धांत एक अनिवार्य शर्त है। इसके अनुसार प्रत्येक मंत्री का संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना कानूनी रूप से आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है, तो उसे छह महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होती है, अन्यथा उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है।

NODIA

55. (A) केवल I और II
भारत में निर्वाचित राष्ट्रपति होने के कारण गणतांत्रिक प्रणाली है जबकि ब्रिटेन में वंशानुगत राजशाही है। ब्रिटिश संसद के

विपरीत भारतीय संसद की शक्तियाँ लिखित संविधान द्वारा सीमित हैं। भारत में प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, जबकि ब्रिटेन में उनका निचले सदन से होना अनिवार्य है। इसलिए पहला और दूसरा कथन सही हैं तथा तीसरा कथन असत्य है।

56. (A) एक संसदीय लोकतंत्र
निचले सदन का उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले विघटित किया जाना संसदीय लोकतंत्र की एक प्रमुख और विशिष्ट विशेषता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि सरकार जनता के विश्वास पर टिकी रहे और राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति में पुनः जनादेश प्राप्त किया जा सके।

57. (B) मंत्रिपरिषद
भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालिका का दर्जा प्राप्त है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सभी शक्तियों का व्यावहारिक प्रयोग वास्तव में मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। देश की नीतियों का निर्धारण, प्रशासनिक निर्णय लेना और शासन का संचालन करना मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य है, जिससे यह वास्तविक कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करती है।

58. (B) इसने कार्यपालिका की दैनिक जवाबदेही प्रदान की
संविधान निर्माताओं ने अध्यक्षात्मक प्रणाली की स्थिरता की तुलना में संसदीय प्रणाली की जवाबदेही को अधिक प्राथमिकता दी। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका केवल निश्चित अवधि के बाद जवाबदेह होती है, जबकि संसदीय व्यवस्था में प्रश्नों, प्रस्तावों और चर्चाओं के माध्यम से संसद द्वारा सरकार की दैनिक जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। यह प्रणाली विविधतापूर्ण भारत में निरंकुशता को रोकने के लिए अत्यधिक उपयुक्त समझी गई।

59. (A) अनुच्छेद 75
संविधान का अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका तात्पर्य यह है कि पूरी सरकार एक इकाई के रूप में कार्य करती है और एक मंत्री के निर्णय के लिए पूरी परिषद जिम्मेदार होती है। लोकसभा में बहुमत खोते ही पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य हो जाता है।

60. (C) ब्रिटेन
छाया मंत्रिमंडल ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की एक अत्यंत अनूठी और उपयोगी संस्था है। इसमें विपक्ष द्वारा सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल के समानांतर एक औपचारिक दल बनाया जाता है जो सरकार के मंत्रियों के कार्यों की निगरानी करता है और वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करता है। भारतीय संसदीय प्रणाली में राजनीतिक विपक्ष मौजूद है, किंतु औपचारिक रूप से छाया मंत्रिमंडल जैसी कोई संस्थागत व्यवस्था यहाँ शामिल नहीं की गई है।

61. (D) उनके वेतन संचित निधि पर भारित होते हैं
न्यायाधीशों को निष्पक्ष और निडर होकर न्याय करने में सक्षम बनाने हेतु उनके वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित किए गए हैं। इन पर संसद में वार्षिक मतदान नहीं कराया जा सकता, जिससे कार्यपालिका या विधायिका अनुचित वित्तीय दबाव नहीं बना सकती। यह संवैधानिक व्यवस्था न्यायपालिका की वित्तीय स्वायत्तता और स्वतंत्रता को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का एक प्रमुख साधन है।

62. (C) न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हो
संविधान का अनुच्छेद 121 संसद में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के कर्तव्य पालन के दौरान आचरण पर चर्चा करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। इस नियम का एकमात्र अपवाद केवल तब होता है जब न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या असमर्थता के आधार पर पद से हटाने से संबंधित महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी सदन के समक्ष विचाराधीन और चर्चा के लिए प्रस्तुत हो।

63. (B) भारत के भीतर किसी भी अदालत में वकालत करने से
न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों पर कुछ वैधानिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी अदालत या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य करने से सख्ती से रोका गया है। यह व्यवस्था पूर्व निर्णयों के पक्षपातपूर्ण होने की संभावनाओं को पूरी तरह समाप्त करती है।

NODIA

64. (D) इसके अधिकार पर अनुचित हमलों से
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की संवैधानिक शक्ति प्रदान की गई है। यह प्रावधान न्यायपालिका की गरिमा, निष्पक्षता और न्यायिक प्राधिकार की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। यह शक्ति अदालत को उन व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार देती है जो अदालत के आदेशों की अवहेलना करते हैं या न्यायिक व्यवस्था पर अनुचित हमला करते हैं।

65. (A) P-2, Q-3, R-1, S-4
न्यायिक प्रणाली के प्रमुख सिद्धांतों में न्यायिक पुनरावलोकन कानूनों की संवैधानिकता की जाँच करता है, एकीकृत न्यायपालिका केंद्रीय व राज्य दोनों कानूनों को लागू करती है, और अनुच्छेद 50 शक्तियों के पृथक्करण का निर्देश देता है। अभिलेख न्यायालय के निर्णय साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं और उसे अवमानना पर दंडित करने का अधिकार होता है, जो सही मिलान को प्रदर्शित करता है।

66. (C) संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों को अमान्य करने की
न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को यह सर्वोच्च शक्ति प्रदान करती है कि वह विधायिका द्वारा निर्मित अधिनियमों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता

की समीक्षा कर सके। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों या संविधान के किसी मूल प्रावधान का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक, अमान्य और शून्य घोषित कर सकते हैं।

67. (A) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
भारतीय संविधान मूल रूप से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत पर बल देता है, जिससे भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा अमेरिका की तुलना में कुछ सीमित हो जाता है। अमेरिका में न्यायपालिका विधि की सम्यक प्रक्रिया का प्रयोग करती है, जिसमें कानून की प्रक्रियात्मक और मौलिक दोनों औचित्य की जाँच की जाती है, जबकि भारतीय प्रणाली में मुख्य रूप से प्रक्रियात्मक वैधता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

68. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता और अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता के बीच एक सुंदर संतुलन स्थापित किया है। एक तरफ संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, तो दूसरी तरफ उच्चतम न्यायालय को मूल ढाँचे का उल्लंघन करने वाले विधायी कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। यह दोहरी व्यवस्था दोनों अंगों के मध्य सामंजस्य बनाती है।

69. (B) पद की सुरक्षा
न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा की संवैधानिक गारंटी प्रदान की गई है, जिससे कार्यपालिका उन्हें मनमाने ढंग से पद से नहीं हटा सकती। उनकी नियुक्ति के पश्चात उनकी सेवा शर्तों, वेतनों और भत्तों में उनके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह सुरक्षा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि न्यायधीश बिना किसी बाहरी दबाव या राजनीतिक हस्तक्षेप के निष्पक्ष न्याय प्रदान कर सकें।

70. (C) कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना
भारतीय संविधान के भाग IV में शामिल राज्य के नीति निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 50 राज्य को यह स्पष्ट निर्देश देता है कि वह राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इस पृथक्करण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायपालिका किसी भी प्रशासनिक दबाव या हस्तक्षेप से मुक्त होकर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करे।

71. (D) भारत का मैग्ना कार्टा
भारतीय संविधान का भाग III, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है। 1215 के ऐतिहासिक ब्रिटिश मैग्ना कार्टा की भांति, यह भाग भी नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की गारंटी देता है और राज्य की मनमानी शक्तियों पर नियंत्रण लगाता है। यह संवैधानिक ढाँचा प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण और स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है।

72. (A) वे राज्य द्वारा लगाए गए युक्तियुक्त निबंधनों के अधीन हैं।
भारत में मौलिक अधिकार निरपेक्ष या असीमित नहीं हैं, बल्कि वे राज्य द्वारा लगाए जाने वाले युक्तियुक्त निबंधनों के अधीन हैं। समाज के व्यापक हित, सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा और नैतिकता बनाए रखने के लिए संसद इन अधिकारों पर कानूनी सीमाएं तय कर सकती है। न्यायालय यह तय करते हैं कि सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध वैध और तर्कसंगत हैं या नहीं।

73. (B) अनुच्छेद 32
यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उसे अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार प्राप्त करने हेतु सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार है। डॉ. अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश जैसी प्रभावी रिटें जारी करने का अधिकार प्रदान करता है।

74. (B) संविधान की अनोखी (नवीन) विशेषताएँ
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी या नवीन विशेषताएँ कहकर संबोधित किया था। इनका मुख्य उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र तक सीमित न रहकर देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये तत्व आने वाली सरकारों के लिए लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण संवैधानिक निर्देश के रूप में कार्य करते हैं।

75. (C) केवल IV
मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं तथा न्यायालय द्वारा वाद-योग्य हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र का निर्माण करते हैं और गैर-वादयोग्य हैं। टकराव की स्थिति में नीति निदेशक तत्व हमेशा मौलिक अधिकारों पर वरीयता नहीं पाते हैं, बल्कि दोनों में संतुलन अनिवार्य है। इसलिए केवल चौथा कथन गलत है क्योंकि नीति निदेशक तत्वों को अनन्य वरीयता प्राप्त नहीं है।

76. (C) मिनर्वा मिल्स मामला (1980)
वर्ष 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढाँचे का एक अनिवार्य हिस्सा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इन दोनों के बीच का संतुलन भारतीय संविधान की आधारशिला है और इनमें से किसी एक को दूसरे पर पूर्ण प्राथमिकता देकर नष्ट नहीं किया जा सकता।

77. (D) उनके उल्लंघन के लिए उन्हें न्यायालयों द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता है
नीति निदेशक तत्वों के गैर-वादयोग्य होने का स्पष्ट अर्थ यह है कि यदि सरकार इन नीतियों को लागू करने में विफल रहती है, तो नागरिक इसके खिलाफ अदालत में मुकदमा नहीं चला सकते। ये अधिकार कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं,

Downloaded from www.pdf.tube

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from
PRINTED BOOKS has up to
4× HIGHER RETENTION
than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY
PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

फिर भी संविधान यह घोषणा करता है कि ये देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाते समय इनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है।

78. (C) संपत्ति का अधिकार
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी (भाग III) से पूरी तरह हटा दिया गया था। इसे अनुच्छेद 31 और 19(1)(f) से निकालकर संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300A के तहत केवल एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस बदलाव का उद्देश्य देश में सामाजिक-आर्थिक भूमि सुधारों और विकास परियोजनाओं को सुचारु रूप से लागू करना था।

79. (B) एक कल्याणकारी राज्य
राज्य के नीति निदेशक तत्वों का समग्र और प्राथमिक लक्ष्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यह ढाँचा केवल एक पुलिस राज्य तक सीमित न रहकर नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने पर बल देता है। यह धन के सकल संकेंद्रण को रोकता है और सभी के लिए आजीविका, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

80. (D) राज्य के कृत्यों के विरुद्ध
भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार मुख्य रूप से राज्य के मनमाने कृत्यों और विधायी या कार्यकारी अतिक्रमण के विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में केंद्र व राज्य सरकारें, संसद, विधानमंडल और अन्य सभी सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल हैं। यदि राज्य का कोई भी अंग इन अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है।

81. (A) 61वां संशोधन अधिनियम, 1988
भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत मताधिकार की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा किया गया था, जो 1989 में लागू हुआ। इस ऐतिहासिक विधायी सुधार ने देश की युवा पीढ़ी को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी लोकतांत्रिक इच्छा व्यक्त करने का अवसर दिया, जिससे भारतीय लोकतंत्र का जनाधार और अधिक व्यापक हो गया।

82. (A) केवल I और II
भारत में दोहरी राजव्यवस्था होने के बावजूद सभी नागरिकों के लिए केवल एक ही एकीकृत राष्ट्रीय नागरिकता का प्रावधान है। नागरिक केवल भारतीय संघ के प्रति निष्ठा रखते हैं, किसी राज्य विशेष के प्रति नहीं। हालाँकि, राज्यों को निवास के आधार पर विशेष शैक्षणिक या रोजगार संबंधी लाभ देने से पूरी तरह नहीं रोका गया है, इसलिए पहला और दूसरा कथन पूरी तरह से सही हैं।

83. (A) बंधुत्व और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना
भारत में विविध भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचानों के बीच राष्ट्रीय अखंडता और बंधुत्व की भावना को मजबूत करने हेतु एकल नागरिकता का प्रावधान अपनाया गया था। यह व्यवस्था प्रांतीयता, संकीर्णता और पृथकतावादी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिक, चाहे उनका जन्म या निवास किसी भी राज्य में हो, संपूर्ण देश में समान अधिकार और अवसर प्राप्त कर सकें।

84. (D) अनुच्छेद 326
संविधान का अनुच्छेद 326 भारत में लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है। यह अनुच्छेद गारंटी देता है कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका प्रत्येक नागरिक बिना किसी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या जन्मस्थान के भेदभाव के मतदाता के रूप में पंजीकृत होने और अपने मत का प्रयोग करने का पूर्ण हकदार है।

85. (B) भाग II
नागरिकता से संबंधित कानूनी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग II में अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत विस्तृत रूप से समाविष्ट हैं। ये अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न नियमों और संसद को नागरिकता के अधिकार को कानून बनाकर विनियमित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। यह भाग भारतीय राजव्यवस्था की एकीकृत और एकजुट प्रकृति को सुदृढ़ आधार प्रदान करता है।

86. (C) केंद्रीय और राज्य दोनों विधियों को लागू करने वाली अदालतों का एक एकल पदानुक्रम है
भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली का तात्पर्य यह है कि शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय, मध्य में उच्च न्यायालय और सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालयों का एक एकल पदानुक्रम मौजूद है। अमेरिका के विपरीत, जहाँ संघीय और राज्य की अदालतें अलग-अलग होती हैं, भारत में यही एकल अदालत प्रणाली केंद्रीय कानूनों और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों दोनों को एक समान रूप से लागू करती है।

87. (D) उच्च न्यायालय
भारत की एकीकृत एकल न्यायिक प्रणाली में शीर्ष स्थान पर भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है। इस पदानुक्रम में उच्चतम न्यायालय के ठीक नीचे राज्यों के उच्च न्यायालय आते हैं। उच्च न्यायालय अपने संबंधित राज्यों के न्यायिक प्रशासन का नेतृत्व करते हैं और उनके निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। यह संरचना पूरे देश में न्यायिक एकरूपता बनाए रखती है।

88. (A) IV, III, II, I
भारतीय न्यायिक प्रणाली के पदानुक्रम को निम्नतम से उच्चतम स्तर की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय आते हैं। उनके ऊपर जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय स्थित होते हैं, जो राज्य स्तर पर कार्यरत उच्च न्यायालयों के नियंत्रण में होते हैं। इस संपूर्ण न्यायव्यवस्था के शीर्ष पर भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है, जो देश की सर्वोच्च अदालत है।

NODIA

89. (B) अमरीका में अलग-अलग संघीय और राज्य अदालत प्रणालियां हैं
भारत और अमेरिका की न्यायिक प्रणालियों के बीच मुख्य अंतर यह है कि अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका लागू है, जहाँ संघीय कानूनों के लिए अलग और राज्यों के कानूनों के लिए अलग अदालतें होती हैं। इसके विपरीत, भारत ने एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को अपनाया है जहाँ एकल अदालत पदानुक्रम के माध्यम से ही केंद्रीय और राज्य दोनों प्रकार के कानूनों को एक साथ लागू किया जाता है।

90. (B) भारत सरकार अधिनियम, 1935
भारतीय संविधान में एकीकृत एवं एकल न्यायपालिका की संरचनात्मक अवधारणा मुख्य रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। इस अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय का ढाँचा ही स्वतंत्रता के पश्चात वर्तमान उच्चतम न्यायालय और एकीकृत न्यायिक पदानुक्रम का आधार बना। इस व्यवस्था ने पूरे देश में एक समान न्यायिक प्रशासन और कानूनों का सुचारु प्रवर्तन सुनिश्चित करने में मदद की।

91. (A) अनुच्छेद 368
भारतीय संविधान के भाग XX में स्थित अनुच्छेद 368 संसद को संविधान और इसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। यह अनुच्छेद संविधान में संशोधन शुरू करने, विभिन्न प्रकार के बहुमत की आवश्यकताओं और प्रक्रियात्मक चरणों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। यह शक्ति संसद को बदलते समय और परिस्थितियों के अनुसार संविधान को अद्यतन और प्रासंगिक बनाए रखने की अनुमति देती है।

92. (C) यह साधारण, विशेष और राज्यों द्वारा अनुसमर्थित संशोधन विधियां प्रदान करता है
भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का एक अनूठा मिश्रण है क्योंकि इसमें संशोधन की तीन अलग-अलग विधियाँ मौजूद हैं। कुछ प्रावधानों को संसद में सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा साधारण बहुमत से बदला जा सकता है, जबकि कुछ के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, संघीय ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में विशेष बहुमत के साथ-साथ आधे राज्यों की स्वीकृति भी अनिवार्य होती है।

93. (D) आधे राज्यों के अनुसमर्थन के साथ विशेष संसदीय बहुमत
संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे या सातवीं अनुसूची जैसे संघीय ढांचे से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन करने के लिए एक कठोर प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।

94. (C) संसद में एक साधारण बहुमत
संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित कानून संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित किए जा सकते हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों के लिए अनुच्छेद 368 के तहत किसी विशेष संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। यह व्यवस्था भारतीय संसद को राज्यों के पुनर्गठन के मामले में अत्यधिक लचीलापन प्रदान करती है।

95. (B) केवल II
मौलिक अधिकारों (भाग III) में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत केवल संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, इसके लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती। इसके सर्वथा विपरीत, नए राज्यों का प्रवेश साधारण बहुमत से होता है तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में संशोधन के लिए राज्यों का अनुसमर्थन भी अनिवार्य होता है। अतः केवल दूसरा विकल्प सही है।

96. (D) भारतीय प्रक्रिया अधिक लचीली है
अमेरिकी संविधान संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत कठोर है, जिसमें तीन-चौथाई राज्यों की मंजूरी अनिवार्य होती है, जिसके कारण वहां अब तक बहुत कम संशोधन हुए हैं। इसके विपरीत, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया अधिक लचीली है क्योंकि इसमें कई प्रावधानों को केवल संसदीय बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। यह लचीलापन भारतीय संविधान को बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य के साथ तेजी से ढलने में मदद करता है।

97. (A) राज्य विधानसभा
भारत में संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने की शक्ति केवल संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) के पास ही निहित है। कोई भी राज्य विधानसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक को पेश या प्रारंभ नहीं कर सकती है। राज्य विधानमंडलों की भूमिका केवल उन विशिष्ट संशोधनों तक सीमित है जिन्हें संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद अनुसमर्थन के लिए राज्यों के पास भेजा जाता है।

98. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
अनुच्छेद 2 और 3 के तहत नए राज्यों के प्रवेश, स्थापना या पुनर्गठन से संबंधित विधायी परिवर्तनों को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। संविधान स्वयं यह निर्दिष्ट करता है कि इस प्रकार के संशोधनों को संसद द्वारा एक सामान्य कानून की भांति साधारण बहुमत से ही पारित किया जा सकता है, जो दोनों कथनों के परस्पर सही होने की पुष्टि करता है।

99. (A) विधेयक समाप्त हो जाता है क्योंकि संयुक्त बैठक की अनुमति नहीं है
अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में यदि संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के बीच कोई असहमति या गतिरोध उत्पन्न होता है, तो विधेयक समाप्त हो जाता है। साधारण विधेयकों की तरह संविधान संशोधन विधेयकों के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, क्योंकि दोनों सदनों को इसमें समान शक्तियाँ प्राप्त हैं।

Click Here to Buy book on Amazon

100. (D) अचल या जल्दबाज़ी में किए गए परिवर्तनों के प्रति प्रवण
भारतीय संविधान में परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग संशोधन प्रक्रियाओं का समावेश किया गया है। यह व्यवस्था संविधान को एक तरफ अत्यधिक कठोर और अचल होने से बचाती है, तो दूसरी तरफ इसे सत्ताधारी दल द्वारा किए जाने वाले जल्दबाज़ी या मनमाने परिवर्तनों के प्रति भी सुरक्षित रखती है। यह अनूठा संतुलन संविधान के स्थायित्व और उसकी गतिशील प्रकृति के मध्य बेहतरीन सामंजस्य सुनिश्चित करता है।

101. (B) 42वां संशोधन अधिनियम
वर्ष 1976 में पारित 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया था। इस ऐतिहासिक संशोधन द्वारा पंथनिरपेक्षता के साथ-साथ समाजवादी और अखंडता शब्दों को भी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इस बदलाव ने भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को औपचारिक और स्पष्ट रूप से संवैधानिक पाठ में रेखांकित कर दिया।

102. (C) सकारात्मक पंथनिरपेक्षता, जो सभी धर्मों को समान सम्मान और समान संरक्षण देती है
भारतीय संविधान ने पंथनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को अपनाया है, जो पश्चिमी मॉडल की भांति राज्य और धर्म के बीच पूर्ण अलगाव पर आधारित नहीं है। यहाँ राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है और सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत का पालन करते हुए सभी धार्मिक समुदायों को समान सम्मान, संरक्षण और स्वतंत्रता प्रदान करता है। राज्य आवश्यकता पड़ने पर धार्मिक सुधारों हेतु हस्तक्षेप भी कर सकता है।

103. (D) अनुच्छेद 25 से 28
भारतीय संविधान के भाग III में अनुच्छेद 25 से 28 तक का समूह विशेष रूप से धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। ये अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। यह व्यवस्था भारत के पंथनिरपेक्ष और बहुसांस्कृतिक ढांचे को कानूनी मजबूती प्रदान करती है।

104. (A) केवल I और II
भारतीय राज्य का अपना कोई आधिकारिक राजधर्म नहीं है और यह सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की पूर्ण गारंटी देता है। राज्य अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और राज्य निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने से नहीं रोकता है। इसलिए पहला और दूसरा कथन सत्य हैं, जबकि सहायता पर रोक लगाने वाला तीसरा कथन पूरी तरह से असत्य और गलत है।

105. (B) पूरी तरह से राज्य निधि से पोषित
संविधान के अनुच्छेद 28(1) के अनुसार, जो भी शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से राज्य निधि या सरकारी धन से संचालित और पोषित होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों का स्वरूप पूर्णतः पंथनिरपेक्ष बना रहे और वहां किसी विशेष धर्म का प्रचार या शिक्षण न हो सके।

106. (B) स्वर्ण सिंह समिति
वर्ष 1976 में गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इस समिति का विचार था कि नागरिकों को अपने अधिकारों का लाभ उठाने के साथ-साथ राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। इन्हीं अनुशंसाओं को लागू करते हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था।

107. (A) भाग IVA, अनुच्छेद 51A
नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का समावेश संविधान के भाग IVA के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इस नए भाग और अनुच्छेद को जोड़ा गया था। इसमें राष्ट्रध्वज का सम्मान करने, देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने तथा पर्यावरण का संरक्षण करने जैसे महत्वपूर्ण नागरिक दायित्वों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

108. (C) P-3, Q-1, R-4, S-2
मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों का पालन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है, जबकि सामासिक संस्कृति का मूल्य समझना हमारी साझा विरासत से संबंधित है। प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण का सीधा संबंध वनों, झीलों और वन्यजीवों से है, तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास मानववाद और जिज्ञासा से जुड़ा है, जो दिए गए सही मिलान का निरूपण करता है।

109. (D) वे गैर-वादयोग्य हैं लेकिन संसद उपयुक्त विधान द्वारा उन्हें लागू कर सकती है
मौलिक कर्तव्य प्रत्यक्ष रूप से न्यायालयों द्वारा गैर-वादयोग्य हैं, जिसका अर्थ है कि इनके उल्लंघन पर सीधे कोई रिट जारी नहीं की जा सकती। हालाँकि, संसद के पास यह शक्ति है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर विशिष्ट मौलिक कर्तव्यों के पालन को अनिवार्य बना सकती है और उनके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान कर सकती है, जैसे पर्यावरण संरक्षण या राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम।

NODIA

110. (C) 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
मूल रूप से 42वें संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके पश्चात 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों पर यह कर्तव्य आयोजित किया गया कि वे अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें, जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा है।

111. (B) अनुच्छेद 352
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है। इस आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या इसके किसी विशिष्ट भाग के लिए की जा सकती है, जिसके पश्चात केंद्र सरकार की शक्तियाँ अत्यधिक व्यापक और प्रभावी हो जाती हैं।

112. (D) वे संशोधन के बिना संघीय ढांचे को एकात्मक में बदल देते हैं
भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों की सबसे अनूठी और असाधारण विशेषता यह है कि वे बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन के देश के संघीय ढांचे को पूर्णतः एकात्मक प्रणाली में बदल देते हैं। संकट के समय केंद्र सरकार सर्वोच्च हो जाती है और राज्यों की विधायी तथा कार्यकारी शक्तियों पर सीधा नियंत्रण स्थापित कर लेती है, जिससे राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।

113. (A) राज्यसभा
संसद का उच्च सदन अर्थात राज्यसभा भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यह सदन यह सुनिश्चित करता है कि केंद्रीय स्तर पर कानून बनाते समय राज्यों के हितों और उनकी आकांक्षाओं का ध्यान रखा जाए और संघीय संतुलन बना रहे।

114. (C) राज्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व करके संघीय संतुलन बनाए रखना
केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य राज्यों की इकाइयों को संसद में उचित प्रतिनिधित्व देना और संघीय संतुलन बनाए रखना है। राज्यसभा राज्यों के हितों की संरक्षक के रूप में कार्य करती है और निचले सदन द्वारा जल्दबाज़ी में पारित किए गए कानूनों का पुनरीक्षण करती है। यह व्यवस्था विविधतापूर्ण राष्ट्र में सभी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित करती है।

115. (C) केवल I और III
राष्ट्रीय आपातकाल में केंद्र को राज्यों को निर्देश देने की पूर्ण शक्ति मिलती है और अनुच्छेद 365 का पालन न करने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भारत में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल आज तक कभी भी घोषित नहीं किया गया है, इसलिए दूसरा कथन असत्य है और केवल पहला व तीसरा कथन पूरी तरह से सही हैं।

116. (D) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी हैं जो संघ और राज्य सरकारों के सभी वित्तीय खातों और व्यय का अंकेक्षण करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सार्वजनिक धन का उपयोग संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार ही हो। CAG को देश की वित्तीय व्यवस्था का संरक्षक और प्रहरी माना जाता है।

117. (B) संविधान का अनुच्छेद 324
भारत का निर्वाचन आयोग अपनी सभी शक्तियाँ और अधिकार सीधे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से प्राप्त करता है। यह अनुच्छेद आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पदों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की अनन्य संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है। यह स्वतंत्रता चुनाव आयोग को किसी भी कार्यकारी या राजनीतिक दबाव से पूरी तरह मुक्त रखती है।

118. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों को पद की संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है ताकि वे बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप या निष्कासन के भय के निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकें। यह सुरक्षा गारंटी यह सुनिश्चित करती है कि देश की सिविल सेवाओं में योग्य अधिकारियों की भर्ती पूरी तरह से निष्पक्षता, पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर की जा सके।

119. (D) 73वें और 74वें संविधान संशोधन
भारत में स्थानीय स्वशासन की त्रि-स्तरीय प्रणाली को 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 73वें संशोधन ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया, जबकि 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों अर्थात नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी। इसने लोकतंत्र को बिल्कुल निचले स्तर तक पहुँचाने में मदद की।

120. (A) भाग IX
ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और आधार प्रदान करने के लिए संविधान में 73वें संशोधन द्वारा भाग IX को पुनः जोड़ा गया था। इस भाग का शीर्षक द पंचायत्स है और इसमें अनुच्छेद 243 से 243O तक के प्रावधान शामिल हैं। इसके साथ ही पंचायतों के कार्यों के लिए 11वीं अनुसूची को भी संविधान में शामिल किया गया था।

121. (A) शंकरी प्रसाद मामला, गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला
मूल ढाँचा सिद्धांत के विकास से जुड़े मामलों का सही कालानुक्रमिक क्रम शंकरी प्रसाद मामला (1951), गोलकनाथ मामला (1967), केशवानंद भारती मामला (1973) और मिनर्वा मिल्स मामला (1980) है। शंकरी प्रसाद में संशोधन शक्ति को असीमित माना गया, गोलकनाथ में रोक लगाई गई, केशवानंद भारती में मूल ढाँचा सिद्धांत प्रतिपादित हुआ और मिनर्वा मिल्स में इसे पुनः सुदृढ़ किया गया।

Downloaded from www.pdf.tube

122. (B) यह संशोधनों और व्याख्या के माध्यम से बदलती जरूरतों के अनुकूल ढलता है
भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज इसलिए माना जाता है क्योंकि यह कोई जड़ या अपरिवर्तनीय पाठ नहीं है। यह समय और समाज की बदलती आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरुप संशोधनों और न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से स्वयं को ढालने की अद्भुत क्षमता रखता है। इसका लचीलापन और प्रासंगिकता ही इसे इतने दशकों से सफलतापूर्वक गतिशील और प्रभावी बनाए हुए है।

123. (C) 1973
संविधान की मूल आत्मा और मुख्य विशेषताओं की रक्षा करने वाला मूल ढाँचा सिद्धांत वर्ष 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में प्रतिपादित किया गया था। 13 न्यायाधीशों की पीठ ने यह व्यवस्था दी थी कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु वह इसके मौलिक या आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती।

124. (C) भारत सरकार अधिनियम, 1935
भारतीय संविधान की एक प्रमुख आलोचना यह की जाती है कि यह औपनिवेशिक काल के भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही एक विस्तृत संवर्धित संस्करण या कार्बन कॉपी है। आलोचकों का मानना है कि संविधान निर्माताओं ने 1935 के अधिनियम की संरचनात्मक योजनाओं, प्रशासनिक विवरणों और कानूनी शब्दावली को बिना किसी बड़े बदलाव के व्यापक रूप से नए संविधान में अपना लिया था।

125. (A) केवल I, II और III
संविधान सभा के दौरान आलोचकों ने इसे भारतीय परंपराओं के अनुकूल न होने के कारण गैर-भारतीय, अत्यधिक विशाल आकार के कारण विशालकाय और क्लिष्ट कानूनी भाषा के कारण वकीलों का स्वर्ग कहा था। हालाँकि, इसे कभी भी अस्थायी नहीं माना गया और न ही प्रत्येक दशक में पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता बताई गई। इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प ही ऐतिहासिक रूप से मान्य हैं।

126. (C) सर आइवर जेनिंग्स
प्रसिद्ध ब्रिटिश संविधानविद सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान की अत्यधिक लंबाई, क्लिष्ट कानूनी शब्दावली और विस्तृत प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए इसे वकीलों का स्वर्ग कहा था। उनका मानना था कि संविधान की जटिल भाषा और कानूनी बारीकियों के कारण आम नागरिकों के लिए इसे समझना कठिन है, जिससे अदालती मुकदमों और कानूनी विवादों में अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना बनी रहती है।

127. (B) यह प्राचीन भारतीय परंपराओं के बजाय विदेशी मॉडलों पर निर्भर करता है
संविधान पर गैर-भारतीय होने का आरोप मुख्य रूप से इसलिए लगाया गया क्योंकि आलोचकों का तर्क था कि इसमें भारत की प्राचीन राजनीतिक और सामाजिक परंपराओं के स्थान पर पश्चिमी देशों के संवैधानिक मॉडलों का अत्यधिक अनुकरण किया गया है। 1935 के अधिनियम, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और अमेरिकी अधिकारों जैसे विदेशी स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण ही इसे स्वदेशी लोकाचार से रहित माना गया।

128. (D) P-4, Q-3, R-1, S-2
भारतीय संघवाद पर विभिन्न विद्वानों की टिप्पणियां सुप्रसिद्ध हैं। के.सी. व्हीयर ने भारतीय संविधान को अर्ध-संघीय कहा था, जबकि आइवर जेनिंग्स ने इसे मजबूत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ माना। ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसके लिए सहकारी संघवाद शब्द का प्रयोग किया और मॉरिस जोन्स ने भारतीय प्रणाली की अनूठी प्रकृति को रेखांकित करते हुए इसे सौदेबाज़ी वाला संघवाद कहा था।

NODIA

129. (A) II, I, IV, III
संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में सबसे पहले विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है। तत्पश्चात प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से विधेयक को पारित कराया जाता है। यदि मामला संघीय ढांचे से जुड़ा हो, तो आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक होता है। अंत में, राष्ट्रपति की औपचारिक सहमति प्राप्त होने पर संशोधन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाती है।

130. (C) 1950 से निरंतर लोकतांत्रिक कामकाज और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण
तमाम आलोचनाओं के बावजूद भारतीय संविधान की वास्तविक सफलता और प्रासंगिकता का सबसे बड़ा प्रमाण 1950 से लेकर आज तक देश में निरंतर चल रही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस संविधान ने विविधताओं से भरे भारत में चुनावों का निष्पक्ष संचालन, कानून का शासन और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित किया है। इसने राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखते हुए सामाजिक-आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है।

www.nodia.in

अध्याय 03
संघीय संरचना एवं केंद्र–राज्य संबंध

1. के.सी. व्हीयर द्वारा भारत के संघवाद के स्वरूप का वर्णन निम्नलिखित में से किस रुप में सबसे सटीक रुप से किया गया है?
(A) सहकारी संघवाद
(B) अर्ध-संघवाद
(C) प्रतिस्पर्धी संघवाद
(D) दोहरा संघवाद

2. भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत किस विशेषता ने भारत के संविधान में अपनाए गए संघीय ढांचे की प्राथमिक नींव रखी?
(A) केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का त्रि-स्तरीय विभाजन
(B) पूरे देश में एक एकीकृत समान न्यायिक प्रणाली की स्थापना
(C) सर्वोच्च विधायी प्राधिकार के साथ एक केंद्रीकृत एकात्मक सरकार का निर्माण
(D) नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों और संवैधानिक उपचारों का प्रत्यक्ष समावेश

3. भारतीय संघवाद के संदर्भ में, "असममित संघवाद" की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे स्पष्ट रुप से दर्शाया गया है?
(A) उच्च सदन में सभी घटक राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व का प्रावधान
(B) सामान्य राष्ट्रीय विधान के लिए समवर्ती सूची का अस्तित्व
(C) अनुच्छेद 371 के तहत कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान
(D) क्षेत्रीय परिषदों जैसे वैधानिक निकायों का निर्माण

4. भारत में केंद्र-राज्य संबंधों के विकास के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) 1950 से 1967 तक की अवधि को सामान्यतः एक दल के प्रभुत्व वाले सहकारी संघवाद के चरण के रूप में देखा जाता है।
(B) 1967 के बाद क्षेत्रीय दलों के उद्भव ने प्रवृत्ति को बहु-दलीय प्रतिस्पर्धी संघवाद की ओर स्थानांतरित कर दिया।
(C) अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना संघीय संबंधों को संस्थागत रुप देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी।
(D) 42वें संशोधन अधिनियम ने संघ सूची से कई विषयों को राज्य सूची में स्थानांतरित करके सत्ता का विकेंद्रीकरण किया।

5. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: भारतीय संविधान के मूल पाठ में कहीं भी "फ़ेडरेशन" (संघ) शब्द का स्पष्ट रुप से उल्लेख नहीं किया गया है।
कथन II: अनुच्छेद 1 भारत को "राज्यों का संघ" (यूनियन ऑफ स्टेट्स) के रूप में वर्णित करता है ताकि इस बात पर बल दिया जा सके कि यह संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है।
(A) कथन I सही है, कथन II गलत है
(B) कथन I गलत है, कथन II सही है
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

6. निम्नलिखित में से कौन-सा विषय सातवीं अनुसूची की संघ सूची (सूची I) में विशेष रुप से परिगणित है?
(A) लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और राज्य के चिकित्सा संस्थानों का रखरखाव
(B) परमाणु ऊर्जा और इसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संसाधन
(C) वनों, जंगली जानवरों का संरक्षण और प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा
(D) जेलों, सुधारगृहों और बंदीगृहों का प्रशासन

7. अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन और विकास को सातवीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है?
(A) राज्य सूची
(B) समवर्ती सूची
(C) अवशिष्ट शक्तियां
(D) संघ सूची

8. संघ सूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसमें मूल रुप से 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं।
II. रक्षा, विदेश मामले और मुद्रा संघ सूची के प्रमुख विषय हैं।
III. संसद को संघ सूची में परिगणित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है।
उपर्युक्त कथनों का कौन-सा संयोजन सही है?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III

Click Here to Buy book on Flipkart

(D) I, II और III

9. संघ सूची की कौन-सी प्रविष्टि केंद्र सरकार को भारत की जनगणना कराने की शक्ति प्रदान करती है?
(A) प्रविष्टि 69
(B) प्रविष्टि 97
(C) प्रविष्टि 69
(D) प्रविष्टि 69

10. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था?
(A) शिक्षा
(B) लोक व्यवस्था
(C) स्थानीय सरकार
(D) कृषि

11. राज्य सूची के अनुसार, "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" पर प्राथमिक विधायी अधिकार किस संस्था के पास है?
(A) केंद्रीय संसद
(B) संसद और राज्य विधानमंडल दोनों
(C) अंतर-राज्यीय परिषद
(D) राज्य विधानमंडल

12. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): सामान्य परिस्थितियों में राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची में परिगणित विषयों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति होती है।
कारण (R): राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, संसद पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त कर लेती है।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

13. राज्य सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है?
(A) निगम कर
(B) सीमा शुल्क
(C) पथकर (टोल)
(D) रेल भाड़े और माल भाड़े पर कर

14. निम्नलिखित में से कौन-सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है?
(A) सट्टेबाजी, जुआ और राज्य लॉटरी का विनियमन
(B) स्थानीय बाजारों, मेलों और व्यापार प्रदर्शनियों पर नियंत्रण
(C) अंतर्देशीय मत्स्य पालन का संरक्षण, सुरक्षा और विनियमन
(D) दिवाला और शोधन अक्षमता

15. राजस्थान के प्रशासनिक तंत्र के संदर्भ में, पंचायती राज संस्थाओं का विनियमन किस विधायी सूची के अंतर्गत आता है?
(A) राज्य सूची
(B) संघ सूची
(C) समवर्ती सूची
(D) अवशिष्ट शक्तियां

16. भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा को किस देश के संविधान से अपनाया गया था?
(A) कनाडा
(B) ऑस्ट्रेलिया
(C) संयुक्त राज्य अमेरिका
(D) आयरलैंड

17. यदि समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी विषय पर केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच प्रत्यक्ष टकराव होता है, तो सामान्य संवैधानिक स्थिति क्या है?
(A) राज्य कानून केंद्रीय कानून पर प्रभावी होता है।
(B) केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होता है।
(C) मामला अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाता है।
(D) सर्वोच्च न्यायालय स्वतः ही दोनों कानूनों को अमान्य कर देता है।

18. निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए:
I. आपराधिक कानून और प्रक्रिया
II. ट्रेड यूनियन; औद्योगिक और श्रम विवाद
III. जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण
IV. प्रतिव्यक्ति कर (कैपिटेशन टैक्स)
कौन-सा संयोजन समवर्ती सूची में शामिल विषयों को दर्शाता है?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, III और IV
(D) I, II, III और IV

19. किस विशिष्ट स्थिति के तहत समवर्ती सूची के विषय पर राज्य का कानून उस राज्य में केंद्रीय कानून पर प्रभावी हो सकता है?
(A) यदि राज्य कानून राज्य विधानसभा द्वारा दो-तिहाई पूर्ण बहुमत से पारित किया गया हो।
(B) यदि राज्य के राज्यपाल विशेष अध्यादेश के माध्यम से केंद्रीय विधान को स्पष्ट रूप से निरस्त करते हैं।
(C) यदि राज्य कानून को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने के बाद उनकी सहमति प्राप्त हुई हो।
(D) यदि केंद्रीय कानून संविधान के लागू होने से पहले बनाया गया था।

Downloaded from www.pdf.tube

20. सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से किस विषय को रखा गया है?
(A) अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य का विनियमन
(B) अपराधियों, भगोड़ों और विदेशी नागरिकों का प्रत्यर्पण
(C) लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सार्वजनिक अस्पतालों का प्रबंधन
(D) बाट और माप (मानकों की स्थापना को छोड़कर)

21. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 विधान की अवशिष्ट शक्तियां विशेष रूप से किसे प्रदान करता है?
(A) भारत के राष्ट्रपति को
(B) भारत के सर्वोच्च न्यायालय को
(C) संसद को
(D) राज्य विधानमंडल को

22. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: विधायी शक्ति
P. संघ सूची
Q. राज्य सूची
R. समवर्ती सूची
S. अवशिष्ट शक्ति
सूची II: विषय/विशेषता
1. साइबर कानून
2. आर्थिक और सामाजिक नियोजन
3. कृषि
4. डाक और तार
(A) P-4, Q-3, R-2, S-1
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-2, R-3, S-1
(D) P-1, Q-3, R-2, S-4

23. यदि कोई नया विषय उत्पन्न होता है जो सातवीं अनुसूची की तीनों सूचियों में से किसी में भी परिगणित नहीं है, तो उस विषय से संबंधित कर लगाने की शक्ति किसके पास है?
(A) राज्य विधानमंडल
(B) वित्त आयोग
(C) जीएसटी परिषद
(D) संसद

24. निम्नलिखित में से कौन-सा संसद द्वारा अपनी अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके बनाए गए कानून का एक उत्कृष्ट उदाहरण है?
(A) संपत्ति कर अधिनियम, 1957
(B) हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
(C) भारतीय दंड संहिता
(D) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

25. भारतीय संविधान में केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना किस प्रणाली की ओर झुकाव को दर्शाता है?
(A) एक विशुद्ध रूप से विकेंद्रीकृत संघीय प्रणाली
(B) अमेरिकी संघीय मॉडल
(C) एक मजबूत एकात्मक केंद्र सरकार
(D) स्विस परिसंघीय मॉडल

26. अनुच्छेद 249 के तहत, राज्यसभा संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वह किस बहुमत से समर्थित प्रस्ताव पारित करती है?
(A) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा
(B) सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा
(C) राज्यसभा की कुल सदस्यता के पूर्ण बहुमत द्वारा
(D) सदन की कुल वैधानिक सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत द्वारा

27. अनुच्छेद 252 संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति देता है यदि:
(A) राष्ट्रपति इस आशय का एक आपातकालीन कार्यपालक अध्यादेश जारी करते हैं।
(B) सर्वोच्च न्यायालय एक आधिकारिक परामर्श के माध्यम से संसद को सलाह देता है।
(C) पूरे राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो।
(D) दो या दो से अधिक राज्य संकल्प पारित करके संसद से ऐसा अनुरोध करते हैं।

28. विधायी संबंधों (अनुच्छेद 249 से 253) के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का सही अनुक्रम चुनें।
1. दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर कानून बनाने की संसद की शक्ति
2. राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति
3. अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति
4. आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति
(A) 2, 4, 1, 3
(B) 2, 1, 4, 3
(C) 1, 2, 4, 3
(D) 4, 2, 1, 3

29. अनुच्छेद 249 के तहत (राष्ट्रहित में) संसद द्वारा बनाया गया कानून राज्यसभा के प्रस्ताव की प्रभावशीलता समाप्त होने के बाद अधिकतम कितनी अवधि तक लागू रहता है?
(A) तीन महीने
(B) छह महीने
(C) एक वर्ष
(D) जब तक राज्य विधानमंडल द्वारा निरस्त न कर दिया जाए

NODIA

30. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद संसद को किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के लिए भारत

के पूरे राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई भी कानून बनाने की अनन्य शक्ति देता है?
(A) अनुच्छेद 248
(B) अनुच्छेद 250
(C) अनुच्छेद 252
(D) अनुच्छेद 253

31. संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करना आवश्यक है जिससे निम्नलिखित में से किसका अनुपालन सुनिश्चित हो सके?
(A) संसद द्वारा बनाए गए कानून
(B) राष्ट्रीय नीति के लिए अंतर-राज्यीय परिषद द्वारा जारी निर्देश
(C) नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए सामाजिक-आर्थिक नीति दिशानिर्देश
(D) संबंधित क्षेत्रीय परिषद द्वारा पारित बाध्यकारी प्रस्ताव

32. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): संघ सरकार किसी राज्य को राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के घोषित संचार साधनों के निर्माण और रखरखाव के संबंध में निर्देश दे सकती है।
कारण (R): अनुच्छेद 257 राष्ट्रीय सुरक्षा और संपर्कीयता सुनिश्चित करने के लिए संघ की कार्यपालिका को राज्यों को ऐसे निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

33. अनुच्छेद 258 के तहत, कौन राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को किसी ऐसे विषय से संबंधित कार्य सौंप सकता है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है?
(A) कार्यपालक सिफारिश पर कार्य करते हुए प्रधानमंत्री
(B) संबंधित राज्य सरकार की सहमति से राष्ट्रपति
(C) संबंधित राज्य सरकार से परामर्श किए बिना संसद
(D) संबंधित राज्य सरकार की ओर से कार्य करते हुए राज्यपाल

34. प्रशासनिक संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि यदि कोई राज्य संघ के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती।
II. केंद्र राज्य के भीतर रेलवे की सुरक्षा के संबंध में राज्यों को निर्देश जारी नहीं कर सकता है।
III. संविधान केंद्र के कार्यपालक कार्यों को राज्यों को सौंपने का प्रावधान करता है, लेकिन राज्यों के कार्यों को केंद्र को सौंपने का नहीं।
उपर्युक्त कथनों का कौन-सा संयोजन गलत है?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

35. केंद्र और राज्यों के बीच कार्यपालिका शक्ति का आपसी हस्तांतरण निम्नलिखित में से किस माध्यम से हो सकता है?
(A) केवल संसद द्वारा पारित औपचारिक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से
(B) भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रत्यक्ष न्यायिक आदेश के माध्यम से
(C) राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच परस्पर सहमति से
(D) केवल राज्यसभा के दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव के माध्यम से

36. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों के शुद्ध आगमों के वितरण का प्रावधान करता है?
(A) अनुच्छेद 268
(B) अनुच्छेद 275
(C) अनुच्छेद 280
(D) अनुच्छेद 270

37. संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ करों और शुल्कों पर अधिभार (अनुच्छेद 271):
(A) वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों के बीच वितरित किए जाते हैं
(B) संघ और राज्यों के बीच समान रूप से साझा किए जाते हैं
(C) पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा रखे जाते हैं
(D) राज्यों द्वारा एकत्र किए जाते हैं लेकिन संघ को दिए जाते हैं

38. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): संविधान उन राज्यों को वैधानिक सहायता-अनुदान का प्रावधान करता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।
कारण (R): अनुच्छेद 275 वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देने के लिए संसद को अधिकृत करता है।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

Click Here to Buy book on Amazon

39. निम्नलिखित में से कौन-सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है (अनुच्छेद 268)?
(A) आयकर
(B) निगम कर
(C) सीमा शुल्क
(D) विनिमय पत्रों पर मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी)

40. केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) राज्यों के पास बिना किसी प्रतिबंध के विदेशों से असीमित ऋण लेने की शक्ति है।
(B) संघ की संपत्ति को राज्य या राज्य के भीतर किसी भी प्राधिकार द्वारा लगाए गए सभी करों से छूट प्राप्त है।
(C) राज्य की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट प्राप्त है।
(D) यदि पिछले केंद्रीय ऋण का कोई भाग बकाया है, तो राज्य केंद्र की सहमति के बिना ऋण नहीं जुटा सकता है।

41. भारत के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है?
(A) अनुच्छेद 275
(B) अनुच्छेद 282
(C) अनुच्छेद 280
(D) अनुच्छेद 360

42. भारत के वित्त आयोग की संरचना क्या है?
(A) एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य
(B) एक अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य
(C) एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य
(D) एक अध्यक्ष और पांच अन्य सदस्य

43. निम्नलिखित में से कौन-सा वित्त आयोग का मुख्य कार्य नहीं है?
(A) संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण की सिफारिश करना।
(B) उन सिद्धांतों का निर्धारण करना जो राज्यों को दिए जाने वाले सहायता-अनुदान को शासित करेंगे।
(C) पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव देना।
(D) विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों को वार्षिक योजना परिव्यय आवंटित करना।

44. 15वें वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसकी अध्यक्षता एन.के. सिंह ने की थी।
II. इसने करों के विभाज्य पूल का 41% राज्यों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की।
III. इसने अपने जनसांख्यिकीय मानदंडों के लिए विशेष रुप से 2011 के जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग किया।
IV. इसने बिना किसी परिवर्तन के हस्तांतरण हिस्सेदारी को 14वें वित्त आयोग के समान रखने की सिफारिश की।
उपर्युक्त कथनों का कौन-सा संयोजन सही है?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I और III
(D) I, II, III और IV

45. वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें होती हैं:
(A) भारत की केंद्र सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी
(B) सभी संबंधित राज्य सरकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी
(C) सलाहकारी प्रकृति की, जो केंद्र सरकार की स्वीकृति के अधीन हैं
(D) नीति आयोग के अनिवार्य अनुमोदन के अधीन

NODIA

46. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं?
(A) अनुच्छेद 262
(B) अनुच्छेद 265
(C) अनुच्छेद 268
(D) अनुच्छेद 263

47. अंतर-राज्यीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है?
(A) भारत के प्रधानमंत्री
(B) भारत के राष्ट्रपति
(C) केंद्रीय गृह मंत्री
(D) भारत के मुख्य न्यायाधीश

48. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: अंतर-राज्यीय तंत्र
P. अंतर-राज्यीय परिषद
Q. अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिकरण
R. राज्यों को सहायता-अनुदान
S. वित्त आयोग
सूची II: संवैधानिक प्रावधान
1. अनुच्छेद 262
2. अनुच्छेद 263
3. अनुच्छेद 280
4. अनुच्छेद 275
(A) P-2, Q-1, R-4, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

49. किस आयोग की सिफारिश के आधार पर 1990 में औपचारिक रूप से अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी?
(A) राजमन्नार समिति
(B) सरकारिया आयोग
(C) पुंछी आयोग
(D) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग

50. भारत में क्षेत्रीय परिषदें हैं:
(A) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय
(B) संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत निर्मित संवैधानिक निकाय
(C) केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा निर्मित कार्यपालक निकाय
(D) अंतर-राज्यीय परिषद के तहत संचालित स्वायत्त उप-समितियां

51. राजस्थान राज्य किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है?
(A) मध्य क्षेत्रीय परिषद
(B) पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद
(C) उत्तरी क्षेत्रीय परिषद
(D) दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद

52. भारत में सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है?
(A) प्रधानमंत्री
(B) केंद्रीय वित्त मंत्री
(C) राष्ट्रपति
(D) केंद्रीय गृह मंत्री

53. किस क्षेत्रीय परिषद का गठन 1971 में संसद के एक अलग अधिनियम द्वारा किया गया था, जो मूल पांच क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं थी?
(A) मध्य क्षेत्रीय परिषद
(B) पूर्वी क्षेत्रीय परिषद
(C) पूर्वोत्तर परिषद
(D) तटीय क्षेत्रीय परिषद

54. निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए:
1. तमिलनाडु
2. राजस्थान
3. उत्तर प्रदेश
4. बिहार

कौन-सा संयोजन उनकी संबंधित क्षेत्रीय परिषदों (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, दक्षिणी) के सही क्रम को दर्शाता है?
(A) 2, 3, 4, 1
(B) 3, 2, 4, 1
(C) 2, 4, 3, 1
(D) 4, 3, 2, 1

55. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का अधिकार देता है?
(A) अनुच्छेद 315
(B) अनुच्छेद 320
(C) अनुच्छेद 324
(D) अनुच्छेद 312

56. अखिल भारतीय सेवाओं को भारतीय संघवाद की एक अनूठी विशेषता क्यों माना जाता है?
(A) ये केंद्र द्वारा भर्ती की जाती हैं तथा केंद्र और राज्य दोनों की सेवा करती हैं
(B) ये राज्यों द्वारा भर्ती की जाती हैं लेकिन केवल केंद्र की सेवा के लिए प्रतिनियुक्त की जाती हैं
(C) ये स्थानीय स्तर पर भर्ती की जाती हैं और पूरी तरह राज्य सरकार के नियंत्रण में होती हैं
(D) ये राज्य लोक सेवाओं का स्थान लेने के लिए बनाई गई हैं

57. राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी पर तत्कालीन अनुशासनात्मक नियंत्रण किसके पास होता है?
(A) भारत के राष्ट्रपति
(B) केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(C) राजस्थान सरकार
(D) संघ लोक सेवा आयोग

58. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: अखिल भारतीय सेवाओं के अस्तित्व को अक्सर एक एकात्मक विशेषता के रूप में देखा जाता है जो राज्यों की स्वायत्तता को सीमित करती है।
कथन II: राज्य सरकारों के पास केंद्र सरकार के अनुमोदन के बिना अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को पदच्युत या हटाने की शक्ति है।
(A) कथन I सही है, कथन II गलत है
(B) कथन I गलत है, कथन II सही है
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

59. निम्नलिखित में से कौन-सी वर्तमान में अखिल भारतीय सेवा नहीं है?
(A) भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)
(B) भारतीय पुलिस सेवा (IPS)
(C) भारतीय वन सेवा (IFoS)
(D) भारतीय विदेश सेवा (IFS)

60. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह तब लगाया जा सकता है जब राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार न चलाई जा सके।
II. राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
III. एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद, राष्ट्रपति शासन बिना किसी अग्रिम विस्तार के अनिश्चित काल के लिए जारी रह सकता है।

उपर्युक्त कथनों का कौन-सा संयोजन सही है?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III

Downloaded from www.pdf.tube

(C) केवल I और III
(D) I, II और III

61. राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्तियां सामान्यतः किसके द्वारा प्रयोग की जाती हैं?
(A) राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा
(B) संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
(C) राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा
(D) अंतर-राज्यीय परिषद की स्थायी समिति द्वारा

62. प्रत्येक छह महीने में संसदीय अनुमोदन के साथ किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है?
(A) एक वर्ष
(B) दो वर्ष
(C) तीन वर्ष
(D) पांच वर्ष

63. राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य विधानसभा की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है?
(A) इसे निलंबित या भंग किया जा सकता है।
(B) यह स्वतः ही भंग हो जाती है।
(C) यह सामान्य रूप से कार्य करती रहती है लेकिन वित्तीय विधेयक पारित नहीं कर सकती।
(D) इसे अस्थाई रूप से संसद में मिला दिया जाता है।

64. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाना न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
कारण (R): एस.आर. बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति पूर्ण है और इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

65. केंद्र-राज्य संबंधों की व्यापक समीक्षा के लिए किस वर्ष सरकारिया आयोग का गठन किया गया था?
(A) 1973
(B) 1983
(C) 1993
(D) 2003

66. राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में सरकारिया आयोग की प्रमुख सिफारिश निम्नलिखित में से कौन-सी थी?
(A) राज्यपाल संबंधित राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए।
(B) वह केंद्र में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का सक्रिय राजनीतिज्ञ होना चाहिए।
(C) उसकी नियुक्ति राज्य विधानमंडल में मतदान द्वारा होनी चाहिए।
(D) राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

67. सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का उपयोग किया जाना चाहिए:
(A) राज्य प्रशासनों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से
(B) जब भी राज्य में गठबंधन सरकार बने
(C) केवल असाधारण मामलों में अंतिम विकल्प के रूप में
(D) यदि राज्य अपना वार्षिक बजट पारित करने में विफल रहता है तो स्वतः ही

68. समवर्ती सूची के संबंध में सरकारिया आयोग ने क्या सुझाव दिया था?
(A) समवर्ती सूची को संविधान से समाप्त कर दिया जाना चाहिए
(B) समवर्ती सूची के सभी विषयों को राज्य सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिए
(C) राज्यों के पास समवर्ती विषयों पर केंद्रीय कानूनों पर वीटो शक्ति होनी चाहिए
(D) केंद्र को समवर्ती विषयों पर कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श करना चाहिए

69. सरकारिया आयोग ने अनुच्छेद 263 के तहत किस स्थायी संस्थागत ढांचे को स्थापित करने की सिफारिश की थी?
(A) नीति आयोग
(B) राष्ट्रीय एकता परिषद
(C) अंतर-राज्यीय परिषद
(D) क्षेत्रीय परिषदें

NODIA

70. निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार कीजिए:
I. राज्यपालों के लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल।
II. राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का प्रावधान।
III. अनुच्छेद 355 और 356 के तहत स्थानीयकृत आपातकालीन प्रावधान।
IV. अखिल भारतीय सेवाओं का उन्मूलन।
कौन-सा संयोजन केंद्र-राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग की सिफारिशों का प्रतिनिधित्व करता है?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I और III
(D) I, II, III और IV

71. केंद्र-राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग का गठन 2007 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था?
(A) आर.एस. सरकारिया
(B) के. हनुमंतैया

(C) एम.एन. वेंकटचलैया
(D) मदन मोहन पुंछी

72. राज्यपाल के पद के दुरुपयोग को रोकने के लिए, पुंछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने हेतु संविधान में किस प्रक्रिया के संशोधन का प्रस्ताव रखा था?
(A) राष्ट्रपति के समान राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग
(B) निर्वाचित राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित साधारण प्रस्ताव
(C) राज्य में आयोजित जनमत संग्रह के माध्यम से
(D) अंतर-राज्यीय परिषद के निर्देश के आधार पर

73. पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के बजाय, राज्य के किसी विशिष्ट भाग में शासन व्यवस्था ठप होने की स्थितियों से निपटने के लिए पुंछी आयोग ने किस अवधारणा का प्रस्ताव रखा था?
(A) वित्तीय आपातकाल
(B) क्षेत्रीय आपातकाल
(C) स्थानीयकृत आपातकाल
(D) नगरपालिक आपातकाल

74. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: आयोग/समिति
P. सरकारिया आयोग
Q. पुंछी आयोग
R. राजमन्नार समिति
S. आनंदपुर साहिब प्रस्ताव
सूची II: वर्ष/घटना
1. 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित
2. 1973 में अकाली दल द्वारा अपनाया गया
3. 1983 में केंद्र द्वारा गठित
4. 2007 में केंद्र द्वारा गठित
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-4, R-2, S-1
(D) P-1, Q-2, R-3, S-4

75. भारतीय संघीय व्यवस्था के विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं?
(A) संघीय सरकार में
(B) सर्वोच्च न्यायालय में
(C) स्थानीय काउंटी में
(D) राज्यों में

76. भारत और अमेरिका की संघीय प्रणालियों के बीच प्रमुख अंतर निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) अमेरिका में एकीकृत न्यायपालिका है, जबकि भारत में दोहरी न्यायपालिका है।
(B) अमेरिका दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, जबकि भारत एकल नागरिकता प्रदान करता है।
(C) अमेरिकी संविधान में समवर्ती सूची है, जबकि भारत में नहीं।
(D) अमेरिका में राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जबकि भारत में वे चुने जाते हैं।

77. संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के विपरीत, जहाँ सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, भारतीय राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर निर्धारित होता है?
(A) प्रत्येक राज्य के लिए समान 5 सीटें
(B) राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल
(C) राज्य की जनसंख्या
(D) राज्य का कर राजस्व में योगदान

78. अमेरिका में कम-से-कम तीन-चौथाई राज्यों के अनुसमर्थन के बिना संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत, भारत में संविधान के अधिकांश भागों का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है?
(A) सभी राज्यों की सहमति और अनुसमर्थन द्वारा
(B) राष्ट्रपति द्वारा सीधे जारी अध्यादेश द्वारा
(C) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय द्वारा
(D) राज्यों के अनुसमर्थन के बिना केवल संसद द्वारा

79. भारत की तुलना में अमेरिकी संघ के संदर्भ में "अविनाशी राज्य" की अवधारणा का क्या अर्थ है?
(A) अमेरिकी कांग्रेस संबंधित राज्य की सहमति के बिना उसकी सीमाओं को नहीं बदल सकती।
(B) अमेरिकी राज्य संघ से अलग होने का अधिकार रखते हैं।
(C) अमेरिकी राज्य अपनी स्वतंत्र सेना रखते हैं।
(D) अमेरिकी राष्ट्रपति के पास आपातकाल घोषित करने की शक्ति नहीं है।

80. उनके पारित होने के वर्ष के अवरोही क्रम (नवीनतम से पुराना) में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को दर्शाने वाले संवैधानिक संशोधनों के सही क्रम का चयन कीजिए:
1. 101वां संशोधन (जीएसटी)
2. 42वां संशोधन (समवर्ती सूची में विषयों का स्थानांतरण)
3. 97वां संशोधन (सहकारी समितियां)
(A) 1, 3, 2
(B) 2, 3, 1
(C) 1, 2, 3
(D) 3, 1, 2

81. निम्नलिखित में से किस प्रावधान की राज्यों द्वारा अक्सर केंद्रीकरण के साधन के रूप में आलोचना की जाती है?
(A) क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना
(B) विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति
(C) राज्य वित्त आयोग का गठन
(D) वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित वित्तीय हस्तांतरण की योजना

82. वित्तीय संसाधनों के लिए केंद्र पर राज्यों की बढ़ती निर्भरता का मुख्य कारण क्या है?

Click Here to Buy book on Flipkart

(A) संघ सूची में अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाले करों का संकेंद्रण
(B) राज्यों की वित्तीय शक्तियों का उन्मूलन
(C) राज्यों को आंतरिक कर लगाने से रोकने वाला संवैधानिक प्रतिबंध
(D) राज्य प्रशासनिक तंत्र द्वारा कर संग्रह में अक्षमता

83. किसी राज्य में उसकी सहमति के बिना केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की तैनाती को केंद्र द्वारा किस अनुच्छेद के तहत उचित ठहराया जाता है?
(A) अनुच्छेद 352
(B) अनुच्छेद 360
(C) अनुच्छेद 355
(D) अनुच्छेद 365

84. कृषि क्षेत्र के संदर्भ में भारतीय संघवाद में केंद्रीकरण के कदम के रूप में विश्लेषकों द्वारा हाल के किस घटनाक्रम को देखा गया?
(A) राज्य एपीएमसी (APMC) अधिनियमों को सख्ती से लागू करना
(B) कृषि को पूरी तरह संघ सूची में स्थानांतरित करना
(C) केंद्रीय कृषि मंत्रालय को समाप्त करना
(D) तीन केंद्रीय कृषि कानूनों का निर्माण (जो बाद में निरस्त कर दिए गए)

85. विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों ने लोकतांत्रिक शासन का तीसरा स्तर बनाया।
II. योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के निर्माण का उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना था।
III. वित्त आयोगों ने निरंतर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा घटाया है।
उपर्युक्त कथनों का कौन-सा संयोजन सही है?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

86. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थानीय निकायों को शक्तियां प्रदान करने हेतु किस अनुसूची को जोड़ा गया था?
(A) दसवीं अनुसूची
(B) ग्यारहवीं अनुसूची
(C) बारहवीं अनुसूची
(D) नौवीं अनुसूची

87. विकेंद्रीकरण के संदर्भ में, राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को किसके संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करता है?
(A) केंद्र से राज्य को मिलने वाले वित्तीय अनुदान के संबंध में
(B) राज्य सरकार की ऋण लेने की सीमा के संबंध में
(C) राज्य सरकार के खातों के लेखा-परीक्षण के संबंध में
(D) राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों के वितरण के संबंध में

88. किस कालखंड को भारतीय संघवाद में राजनीतिक विकेंद्रीकरण और राज्यों के बढ़ते प्रभाव के दौर के रूप में देखा जाता है?
(A) 1950 - 1964
(B) 1975 - 1977
(C) 1989 - 2014
(D) 2014 - वर्तमान

89. संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत, किसी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करने का अधिकार किसे प्राप्त है?
(A) भारत के सर्वोच्च न्यायालय को
(B) भारत के राष्ट्रपति को
(C) संसद को
(D) अंतर-राज्यीय परिषद को

90. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): जब संसद किसी अंतर-राज्यीय जल विवाद के लिए अधिकरण स्थापित कर देती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास सामान्यतः उस विवाद पर मूल क्षेत्राधिकार नहीं रहता।
कारण (R): अनुच्छेद 262 संसद को जल विवादों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित करने का कानून बनाने की अनुमति देता है।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

91. राजस्थान निम्नलिखित में से किस नदी जल विवाद में एक पक्षकार राज्य है?
(A) कावेरी
(B) कृष्णा
(C) गोदावरी
(D) रावी और ब्यास

92. जल विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु अधिकरणों की स्थापना के लिए संसद द्वारा अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
(A) 1950
(B) 1956
(C) 1976
(D) 1990

NODIA

93. भारत में अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिकरणों की मुख्य आलोचना क्या है?
(A) तटीय राज्यों के प्रति पूर्वाग्रह
(B) विशेषज्ञों की कमी
(C) अधिकरण के गठन, निर्णय और प्रवर्तन में अत्यधिक विलंब
(D) निर्णयों पर राज्यों की वीटो शक्ति

94. राज्य का राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन-सी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है?
(A) स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना
(B) बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा भंग करना
(C) लोकसभा के सदस्यों को नामित करना
(D) राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना

95. निम्नलिखित परिदृश्यों पर विचार कीजिए जहाँ राज्यपाल की भूमिका केंद्र-राज्य संबंधों को प्रभावित करती है:
I. अनुच्छेद 356 की सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना।
II. पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को धन विधेयक वापस भेजना।
III. राज्य के किसी विधेयक पर सहमति को अनिश्चित काल के लिए रोकना।
IV. राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करना।
कौन-सा संयोजन उन क्षेत्रों को दर्शाता है जो निर्वाचित राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच तनाव का कारण बनते हैं?
(A) केवल I और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II और IV
(D) I, II, III और IV

96. कौन-सा संवैधानिक प्रावधान यह अनिवार्य करता है कि उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाले राज्य विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाना चाहिए?
(A) अनुच्छेद 213
(B) अनुच्छेद 200
(C) अनुच्छेद 256
(D) अनुच्छेद 161

97. राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है। इसका तात्पर्य है कि:
(A) राज्यपाल का कार्यकाल राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है।
(B) राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है।
(C) राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले नहीं हटाया जा सकता।
(D) राज्यपाल केंद्र सरकार का एक अधीनस्थ कर्मचारी है।

98. राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच विवाद उत्पन्न हुए हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत करते हैं?
(A) अनुच्छेद 174
(B) अनुच्छेद 163
(C) अनुच्छेद 356
(D) अनुच्छेद 200

99. जीएसटी परिषद को सहकारी संघवाद के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। इसकी स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी?
(A) अनुच्छेद 246A
(B) अनुच्छेद 269A
(C) अनुच्छेद 279A
(D) अनुच्छेद 280

100. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: जीएसटी परिषद का घटक
P. केंद्र सरकार का मत भार
Q. राज्य सरकारों का संयुक्त मत भार
R. बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति (कोरम)
S. निर्णय हेतु आवश्यक बहुमत
सूची II: आवश्यकता/अनुपात
1. कुल डाले गए मतों का दो-तिहाई
2. कुल डाले गए मतों का एक-तिहाई
3. कुल सदस्यों का आधा (50%)
4. कुल भारित मतों का तीन-चौथाई (75%)
(A) P-2, Q-1, R-3, S-4
(B) P-1, Q-2, R-4, S-3
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

101. जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है?
(A) भारत के प्रधानमंत्री
(B) भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर
(C) केंद्रीय वित्त मंत्री
(D) राज्यों के वित्त मंत्रियों में से चुना गया व्यक्ति

102. जीएसटी परिषद में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व आमतौर पर किसके द्वारा किया जाता है?
(A) राज्य के मुख्यमंत्री
(B) वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री
(C) राज्य सरकार के मुख्य सचिव
(D) राज्य के राज्यपाल

NODIA

103. जीएसटी व्यवस्था में राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए कौन-सा तंत्र बनाया गया था?
(A) आयकर अधिभार का बंटवारा
(B) अनुच्छेद 282 के तहत विशेष अनुदान

(C) वित्त आयोग हस्तांतरण का समायोजन
(D) जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर (सेक)

104. एस.आर. बोम्मई मामला (1994) में सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय मुख्य रूप से किस अनुच्छेद के दुरुपयोग से संबंधित था?
(A) अनुच्छेद 356
(B) अनुच्छेद 32
(C) अनुच्छेद 360
(D) अनुच्छेद 370

105. संघवाद से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख मामलों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम (पुराने से नया) चुनिए:
1. एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ
2. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
3. आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
(A) 3, 2, 1
(B) 2, 3, 1
(C) 1, 2, 3
(D) 3, 1, 2

106. एस.आर. बोम्मई निर्णय के अनुसार, किसी राज्य सरकार के बहुमत का परीक्षण करने के लिए उपयुक्त मंच कौन-सा है?
(A) विधानसभा का पटल (फ़्लोर टेस्ट)
(B) राजभवन
(C) राष्ट्रपति सचिवालय
(D) सर्वोच्च न्यायालय

107. एस.आर. बोम्मई मामले में दिए गए निर्णयों के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) राज्य सरकार को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति निरपेक्ष नहीं है।
(B) धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है, और धर्मनिरपेक्षता विरोधी कृत्यों के आधार पर राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है।
(C) जब तक संसद राष्ट्रपति की उद्घोषणा को स्वीकृति नहीं देती, तब तक विधानसभा को भंग नहीं किया जाना चाहिए।
(D) सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अदालतें असंवैधानिक रूप से बर्खास्त राज्य सरकार को पुनस्थापित नहीं कर सकती हैं।

108. एस.आर. बोम्मई फैसले के अनुसार, यदि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को असंवैधानिक मानकर रद्द कर दिया जाता है, तो न्यायपालिका क्या कार्रवाई कर सकती है?
(A) केंद्र सरकार पर जुर्माना लगा सकती है
(B) बर्खास्त राज्य सरकार और निलंबित विधानसभा को बहाल कर सकती है
(C) तुरंत नए चुनाव कराने का आदेश दे सकती है
(D) नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकती है

109. राजकोषीय संघवाद के संदर्भ में, "ऊर्ध्वाधर असंतुलन" (वर्टिकल इम्बलेंस) का तात्पर्य है:
(A) विभिन्न राज्यों के बीच कर राजस्व सृजन में असमानता
(B) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास कोष का असमान आवंटन
(C) केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व शक्तियों और व्यय दायित्वों का बेमेल होना
(D) वैश्विक आर्थिक दबावों के कारण उत्पन्न वित्तीय अनिश्चितता

110. करों के क्षैतिज हस्तांतरण के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा उपयोग किए गए निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कीजिए:
I. आय की दूरी (इंकम डिस्टेंस)
II. जनसांख्यिकीय प्रदर्शन
III. वन और पारिस्थितिकी
कौन-सा संयोजन आयोग द्वारा प्रयुक्त मानदंडों का सही प्रतिनिधित्व करता है?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

111. 15वें वित्त आयोग द्वारा करों के क्षैतिज वितरण के सूत्र में किस मानदंड को सर्वाधिक भारांक (वेटेज) दिया गया है?
(A) आय की दूरी (इंकम डिस्टेंस)
(B) जनसंख्या
(C) क्षेत्रफल
(D) कर एवं राजकोषीय प्रयास

112. केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले "सशर्त अनुदान" का तात्पर्य है:
(A) वह धनराशि जिसका उपयोग राज्य अपने विवेक से कर सकते हैं
(B) वह धनराशि जो जल या स्वच्छता जैसे विशिष्ट क्षेत्रों या योजनाओं के लिए निर्धारित होती है
(C) वह विकास ऋण जिसे ब्याज सहित वापस चुकाना अनिवार्य है
(D) वह अनुदान जो राज्य की जीडीपी वृद्धि दर से सीधे जुड़ा होता है

113. अनुच्छेद 293 के तहत राज्य सरकारें ऋण ले सकती हैं:
(A) सीधे विदेशी स्रोतों से
(B) केवल भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर से
(C) केंद्र की सहमति के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक से
(D) विदेशी सरकारों से (राष्ट्रपति को सूचित करके)

114. जांच एजेंसियों के संदर्भ में वर्तमान में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का प्रमुख कारण क्या है?
(A) राज्यों में सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) जैसी केंद्रीय एजेंसियों का क्षेत्राधिकार
(B) राज्य पुलिस बलों का शस्त्रीकरण

Downloaded from www.pdf.tube

(C) ग्राम न्यायालयों का संचालन
(D) राज्य लोक सेवकों की पदोन्नति नीति

115. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): कई राज्यों ने अपने राज्यक्षेत्र में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई "सामान्य सहमति" वापस ले ली है।
कारण (R): सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम द्वारा शासित होती है, जिसके तहत किसी राज्य में जांच हेतु संबंधित राज्य सरकार की पूर्व सहमति आवश्यक है।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

116. राज्य अक्सर "केंद्र प्रायोजित योजनाओं" (CSS) की आलोचना करते हैं क्योंकि:
(A) ये राज्यों को अत्यधिक बिना शर्त वित्तीय अनुदान देती हैं
(B) इनमें केंद्र का कोई वित्तीय योगदान नहीं होता
(C) ये राज्यों को असीमित स्वायत्तता प्रदान करती हैं
(D) ये मैचिंग फंड की आवश्यकता और केंद्रीय शर्तों के कारण राज्यों की राजकोषीय प्राथमिकता को प्रभावित करती हैं

117. केंद्र सरकार द्वारा उपकर (सेस) और अधिभार (सरचार्ज) लगाया जाना राज्यों के विरोध का कारण क्यों है?
(A) इन्हें एकत्र करने का बोझ राज्यों पर पड़ता है
(B) ये केवल राज्य की संपत्ति पर लगाए जाते हैं
(C) इनसे प्राप्त राजस्व राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले विभाज्य पूल में शामिल नहीं होता है
(D) इनके लिए राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है

118. राज्य विश्वविद्यालयों के संदर्भ में राज्यपाल की पारंपरिक भूमिका क्या होती है?
(A) राज्य उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख
(B) राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति (चांसलर)
(C) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष
(D) छात्र कल्याण के अधिष्ठाता

119. योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति (NITI) आयोग की स्थापना की गई। 'NITI' का पूर्ण रूप क्या है?
(A) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
(B) न्यू इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल इंटीग्रेशन
(C) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजिकल इंडिया
(D) नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया

120. नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह 'सहकारी संघवाद' के सिद्धांत पर कार्य करता है।
II. इसके पास राज्यों को वित्तीय कोष आवंटित करने की शक्ति नहीं है।
III. इसकी गवर्निंग काउंसिल (शासी परिषद) में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं।
IV. यह एक विचार मंच (थिंक टैंक) और सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।
कथनों का कौन-सा संयोजन सही है?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, III और IV
(D) I, II, III और IV

121. नीति आयोग किस माध्यम से राज्यों के बीच 'प्रतिस्पर्धी संघवाद' को बढ़ावा देता है?
(A) खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों पर वित्तीय जुर्माना लगाकर
(B) केंद्रीय विकास अनुदान रोककर
(C) स्वास्थ्य, शिक्षा और सुशासन जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शन सूचकांक व रैंकिंग जारी करके
(D) राज्य सरकारों को भंग करने की सिफारिश करके

122. नीति आयोग की कौन-सी संरचना राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय नीति निर्माण पर विचार-विमर्श का मंच प्रदान करती है?
(A) गवर्निंग काउंसिल (शासी परिषद)
(B) वित्त आयोग
(C) अंतर-राज्यीय परिषद
(D) क्षेत्रीय परिषदें

123. शिक्षा विषय को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था?
(A) 24वां संशोधन अधिनियम
(B) 44वां संशोधन अधिनियम
(C) 73वां संशोधन अधिनियम
(D) 42वां संशोधन अधिनियम

124. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 जैसी केंद्रीय नीति की संवैधानिक प्रकृति क्या है?
(A) यह एक बाध्यकारी कानून है जो सभी राज्य नीतियों को निरस्त करता है
(B) यह एक मार्गदर्शक ढांचा है जिसे अपनाना राज्यों के स्वविवेक पर निर्भर करता है
(C) यह तब तक अमान्य है जब तक इसे अंतर-राज्यीय परिषद द्वारा मंजूरी न मिले
(D) यह राज्यों के विधायी अधिकार को पूरी तरह समाप्त करती है

125. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: संवैधानिक प्रावधान

NODIA

P. अनुच्छेद 131
Q. अनुच्छेद 262
R. अनुच्छेद 263
S. अनुच्छेद 279A

सूची II: विषय
1. अंतर-राज्यीय जल विवादों का न्यायनिर्णयन
2. केंद्र-राज्य विवादों में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार
3. वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद
4. अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना

(A) P-2, Q-1, R-4, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

126. यदि कोई राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के विषय पर बने केंद्रीय कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करता है, तो उस प्रस्ताव का विधिक प्रभाव क्या होता है?
(A) केंद्रीय कानून उस राज्य में तुरंत अमान्य हो जाता है
(B) मामला स्वतः ही सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा हेतु चला जाता है
(C) राष्ट्रपति कानून वापस लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं
(D) इसका केवल राजनीतिक एवं प्रतीकात्मक महत्व होता है, कोई बाध्यकारी कानूनी प्रभाव नहीं होता

127. भारतीय संदर्भ में "सहकारी संघवाद" का मुख्य अर्थ क्या है?
(A) राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों का मिलकर कार्य करना
(B) केंद्र के खिलाफ राज्यों का गठबंधन
(C) क्षेत्रीय दलों का राजनीतिक गठबंधन
(D) राज्यों द्वारा अपनी कर शक्तियां केंद्र को सौंपना

128. भारत में "प्रतिस्पर्धी संघवाद" का एक प्रमुख उदाहरण कौन-सा है?
(A) केंद्रीय कानूनों को निरस्त करने के लिए राज्य कानून पारित करना
(B) 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग के माध्यम से निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों के बीच होड़
(C) वित्त आयोग से अधिक वित्तीय हिस्सेदारी की मांग करना
(D) सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र के खिलाफ याचिकाएं दायर करना

129. केंद्र-राज्य समन्वय स्थापित करने वाले निकायों के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए:
(A) राष्ट्रीय विकास परिषद - आयोजन एवं योजना
(B) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) - केंद्र-राज्य समन्वय निकाय
(C) अंतर-राज्यीय परिषद - संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय
(D) नीति आयोग शासी परिषद - नीतिगत समन्वय

130. वर्तमान में भारत के केंद्र-राज्य संबंधों का सबसे सटीक वर्णन कौन-सा है?
(A) सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धी तंत्रों के साथ-साथ राजनीतिक सौदेबाजी वाला संघवाद
(B) पूर्णतः केंद्रीकृत एकात्मक व्यवस्था
(C) पूर्ण वित्तीय और राजनीतिक विकेंद्रीकरण
(D) 1967 से पूर्व का एकदलीय प्रभुत्व वाला संघवाद

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Amazon

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) अर्ध-संघवाद
के.सी. व्हीयर ने भारतीय संविधान की प्रकृति का अध्ययन करने के उपरांत इसे अर्ध-संघीय ढांचा कहा था। उनके अनुसार भारत का संविधान एकात्मक विशेषताओं से युक्त एक संघात्मक प्रणाली का निर्माण करता है। इसमें एकात्मक राज्य की भावना अधिक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है जिसमें संघात्मक तत्व गौण हैं। केंद्रीय सत्ता की प्रबलता और राज्यों की तुलना में अधिक अधिकार केंद्र को प्रदान किए जाने के कारण इसे अर्ध-संघवाद की श्रेणी में रखा गया है।

2. (A) केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का त्रि-स्तरीय विभाजन
भारत सरकार अधिनियम 1935 ने देश में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया था। इस अधिनियम के तहत केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों के माध्यम से किया गया था। यह विभाजन संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची के रूप में लागू किया गया था। यही त्रि-स्तरीय विभाजन स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघीय ढांचे का मूल आधार बना।

3. (C) अनुच्छेद 371 के तहत कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान
असममित संघवाद का अर्थ ऐसी संघीय व्यवस्था से है जहाँ विभिन्न घटक राज्यों को समान अधिकार देने के बजाय उनके ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर भिन्न शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। भारतीय संविधान का भाग 21 तथा अनुच्छेद 371 से 371-जे के प्रावधान महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्यों को विशेष दर्जा देते हैं। यह व्यवस्था देश की विविधता, सांस्कृतिक संरक्षण और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को संतुलित करने में सहायक सिद्ध होती है।

4. (D) 42वें संशोधन अधिनियम ने संघ सूची से कई विषयों को राज्य सूची में स्थानांतरित करके सत्ता का विकेंद्रीकरण किया।
वर्ष 1976 में पारित 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ सूची से राज्य सूची में विषयों का हस्तांतरण नहीं किया गया था, बल्कि राज्य सूची से पांच महत्वपूर्ण विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। स्थानांतरित किए गए विषयों में शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप-तौल तथा न्याय का प्रशासन शामिल थे। इस संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार की विधायी शक्तियों का विस्तार हुआ और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला था।

5. (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
भारतीय संविधान के मूल पाठ में कहीं भी अंग्रेजी शब्द फ़ेडरेशन का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा। डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार भारत का संघ राज्यों के मध्य किसी संविदा या समझौते का परिणाम नहीं है। किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए संघ को अविनाशी तथा राज्यों को विनाशी माना गया है।

6. (B) परमाणु ऊर्जा और इसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संसाधन
सातवीं अनुसूची की संघ सूची उन विषयों से संबंधित है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिन पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है। परमाणु ऊर्जा और उसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संसाधन संघ सूची की प्रविष्टि 6 के तहत शामिल हैं। इसके विपरीत, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, जबकि वनों का संरक्षण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जेलों और सुधारगृहों का प्रशासन राज्य सूची के दायरे में सम्मिलित है।

7. (D) संघ सूची
सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अंतर्गत अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन तथा विकास को सूचीबद्ध किया गया है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह जनहित में अंतर-राज्यीय जलमार्गों, नदियों और घाटियों के प्रबंधन हेतु नियम और नीतियां निर्मित करे। इस विषय का नियंत्रण संघ सूची के अंतर्गत रखने का मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच जल संसाधनों के उपयोग को लेकर विवादों को रोकना और एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है।

8. (D) I, II और III
संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में कुल 97 विषय शामिल किए गए थे, जिनकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 100 हो गई है। रक्षा, विदेश मामले, नौसेना, नागरिकता, मुद्रा, रेलवे और डाक सेवा संघ सूची के प्रमुख राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। अनुच्छेद 246 के अनुसार, भारत की संसद को इस सूची में परिगणित किसी भी विषय पर कानून बनाने की अनन्य और सर्वाधिकार शक्ति प्राप्त है, जिसमें राज्यों का हस्तक्षेप स्वीकृत नहीं है।

9. (C) प्रविष्टि 69
संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 69 में भारत की जनगणना कराने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। जनगणना का कार्य राष्ट्रीय आंकड़े एकत्र करने और जनसांख्यिकीय अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, इसीलिए यह संघ सरकार का दायित्व है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त का

NODIA

कार्यालय देश भर में जनगणना की योजना तैयार करता है और दस वर्षों के अंतराल पर इसका नियमित संचालन करता है।

10. (A) शिक्षा
1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। इस संशोधन के माध्यम से पांच प्रमुख विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। इन विषयों में शिक्षा, वन, जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण, बाट और माप तथा न्याय का प्रशासन शामिल हैं। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने का उद्देश्य केंद्र और राज्यों दोनों को राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के निर्माण में समान भूमिका प्रदान करना था।

11. (D) राज्य विधानमंडल
संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 1 में लोक व्यवस्था और प्रविष्टि 2 में पुलिस को शामिल किया गया है। सामान्य परिस्थितियों में राज्य विधानमंडल को इन विषयों पर कानून बनाने तथा प्रशासनिक नियंत्रण रखने का अनन्य विधायी अधिकार प्राप्त होता है। राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों की रोकथाम करना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिक रूप से राज्य सरकार का संवैधानिक कर्तव्य और कार्यक्षेत्र माना जाता है।

12. (B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल सामान्य समय में राज्य सूची के विषयों पर अनन्य रूप से कानून निर्मित करते हैं। आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 250 के तहत संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त कर लेती है। हालाँकि, यह आपातकालीन शक्ति सामान्य परिस्थितियों में राज्यों के पास मौजूद अनन्य विधायी शक्तियों का कारण या व्याख्या प्रस्तुत नहीं करती है। दोनों कथन अपने-अपने संवैधानिक संदर्भ में पूरी तरह सही हैं, परंतु उनमें कारण संबंधी संबंध नहीं है।

13. (C) पथकर (टोल)
सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची की प्रविष्टि 59 में पथकर (टोल) लगाने और उसे एकत्र करने का अधिकार राज्यों को सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त भू-राजस्व, कृषि आय पर कर, शराब पर आबकारी शुल्क तथा वाहनों पर कर भी राज्यों द्वारा वसूले जाते हैं। जबकि निगम कर, सीमा शुल्क और रेल भाड़े तथा माल भाड़े पर कर संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ये कर केवल केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किए जाते हैं।

14. (D) दिवाला और शोधन अक्षमता
दिवाला और शोधन अक्षमता विषय सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 9 में सूचीबद्ध किया गया है। इस विषय पर केंद्र संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को विधान निर्मित करने का अधिकार प्राप्त है। इसके विपरीत, सट्टेबाजी और जुआ राज्य सूची की प्रविष्टि 34 में, स्थानीय बाजार और मेले प्रविष्टि 28 में तथा अंतर्देशीय मत्स्य पालन प्रविष्टि 21 में शामिल हैं। अतः ये तीनों विषय पूर्णतः राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं।

15. (A) राज्य सूची
सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय सरकार और पंचायती राज संस्थाओं का विनियमन पूर्णतः राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। राजस्थान प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं का गठन, चुनाव और कार्यप्रणाली राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों से संचालित होती है। यद्यपि 73वें संविधान संशोधन ने इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, परंतु इनके नियमन और शक्तियों के हस्तांतरण का अंतिम अधिकार संबंधित राज्य सरकार के पास ही निहित रहता है।

16. (B) ऑस्ट्रेलिया
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकरूपता बनाए रखने के साथ-साथ राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बनाने का लचीलापन प्रदान करना है। वर्तमान में इस सूची में 52 विषय सम्मिलित हैं, जो केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी सहयोग को सुदृढ़ बनाते हैं।

17. (B) केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होता है।
संविधान के अनुच्छेद 254(1) के अनुसार, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा निर्मित कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच कोई असंगति उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय कानून राज्य के कानून पर प्रभावी होता है। टकराव की स्थिति में राज्य का कानून उस सीमा तक शून्य माना जाता है जिस सीमा तक वह केंद्रीय विधान का विरोध करता है। यह संवैधानिक प्रावधान संघ की सर्वोच्चता और राष्ट्रीय एकरूपता बनाए रखने हेतु निर्मित किया गया है।

18. (A) केवल I, II और III
सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आपराधिक कानून और प्रक्रिया (प्रविष्टि 1 व 2), ट्रेड यूनियन एवं औद्योगिक विवाद (प्रविष्टि 22), तथा वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण (प्रविष्टि 17ए) शामिल हैं। इन तीनों विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने की शक्ति है। इसके विपरीत, प्रतिव्यक्ति कर (कैपिटेशन टैक्स) राज्य सूची की प्रविष्टि 61 का विषय है। इसलिए प्रतिव्यक्ति कर को छोड़कर शेष तीनों विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं।

19. (C) यदि राज्य कानून को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने के बाद उनकी सहमति प्राप्त हुई हो।
संविधान के अनुच्छेद 254(2) में यह अपवाद प्रस्तुत किया गया है कि यदि समवर्ती सूची के विषय पर पारित राज्य कानून को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया हो और राष्ट्रपति ने उस पर अपनी सहमति प्रदान कर दी हो, तो वह राज्य कानून उस संबंधित राज्य में केंद्रीय कानून पर प्रभावी होगा। हालाँकि, इसके पश्चात भी संसद को यह अधिकार होता

Downloaded from www.pdf.tube

है कि वह उसी विषय पर पुनः कानून बनाकर राज्य के कानून को संशोधित या निरस्त कर सके।

20. (D) बाट और माप (मानकों की स्थापना को छोड़कर)
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा बाट और माप (मानकों की स्थापना को छोड़कर) को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33ए में जोड़ा गया था। बाट और माप के मानकों की स्थापना संघ सूची की प्रविष्टि 50 का विषय बनी रहती है। अंतर-राज्यीय व्यापार संघ सूची में आता है, प्रत्यर्पण संघ सूची की प्रविष्टि 18 में है तथा लोक स्वास्थ्य और अस्पताल प्रबंधन राज्य सूची की प्रविष्टि 6 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

21. (C) संसद को
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 संसद को स्पष्ट रूप से अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ प्रदान करता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो विषय सातवीं अनुसूची की तीनों सूचियों (संघ, राज्य या समवर्ती सूची) में परिगणित नहीं किए गए हैं, उन विषयों पर कानून निर्मित करने की सर्वाधिकार शक्ति केवल भारत की संसद के पास है। इसमें ऐसे विषयों पर कर लगाने की शक्ति भी सम्मिलित है। यह व्यवस्था भारतीय संघवाद में केंद्र सरकार की मजबूती को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

22. (A) P-4, Q-3, R-2, S-1
संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न विधायी विषयों का सटीक विभाजन किया गया है। डाक और तार सेवा राष्ट्रीय महत्व का विषय होने के कारण संघ सूची में सम्मिलित है। कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक आधार होने के कारण राज्य सूची में शामिल है। आर्थिक और सामाजिक नियोजन देश के संतुलित विकास हेतु समवर्ती सूची का विषय है। इसके अतिरिक्त, आधुनिक समय के साइबर कानून तीनों सूचियों में अनुपस्थित होने से संसद की अवशिष्ट शक्ति में आते हैं।

23. (D) संसद
संविधान के अनुच्छेद 248 के साथ सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 97 यह निर्धारित करती है कि कोई भी ऐसा विषय या कर जो तीनों सूचियों में उल्लिखित नहीं है, वह अवशिष्ट शक्तियों का भाग बनता है। भारत में अवशिष्ट शक्तियों का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से संसद के पास निहित है। इसलिए, यदि भविष्य में कोई नया कर या विषय उभरता है, तो केवल संसद ही उस पर विधायी अधिनियम पारित करके कर लगाने या नियम बनाने का सर्वाधिकार रखती है।

24. (A) संपत्ति कर अधिनियम, 1957
संसद ने 1957 में संपत्ति कर अधिनियम लागू करने के लिए अपनी अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग किया था, क्योंकि उस समय संविधान की तीनों सूचियों में संपत्ति कर लगाने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। अनुच्छेद 248 के तहत संसद को किसी भी ऐसे कर का अधिरोपण करने का अनन्य अधिकार है जो राज्य या समवर्ती सूची में वर्णित न हो। हिंदू विवाह अधिनियम, भारतीय दंड संहिता तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम समवर्ती सूची में वर्णित विषयों के आधार पर बनाए गए विधान हैं।

25. (C) एक मजबूत एकात्मक केंद्र सरकार
भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के बजाय केंद्र संसद को प्रदान की गई हैं, जो कनाडाई मॉडल पर आधारित प्रणाली है। इसके विपरीत, अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई संघीय प्रणालियों में अवशिष्ट शक्तियाँ घटक राज्यों को दी गई हैं। भारत में केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ सौंपने का मुख्य संवैधानिक ध्येय देश की एकता, अखंडता को बनाए रखना तथा उग्र क्षेत्रीय प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना था। यह प्रावधान भारतीय संघवाद को एकात्मकता की ओर झुकाव वाला एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है।

NODIA

26. (A) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा
संविधान का अनुच्छेद 249 राज्यसभा को यह विशेष अधिकार देता है कि यदि वह उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। यह संकल्प एक समय में अधिकतम एक वर्ष तक प्रभावी रहता है, किंतु इसे बार-बार एक-एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

27. (D) दो या दो से अधिक राज्य संकल्प पारित करके संसद से ऐसा अनुरोध करते हैं।
अनुच्छेद 252 के अनुसार, यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल यह संकल्प पारित करते हैं कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाए, तो संसद उस विषय पर उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। ऐसा कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होता है जिन्होंने संकल्प पारित किया है या जो बाद में इसे स्वीकार करते हैं। इस प्रकार बने कानून में संशोधन या निरसन करने की शक्ति केवल संसद के पास होती है, राज्यों के पास नहीं।

28. (A) 2, 4, 1, 3
भारतीय संविधान के भाग 11 के अंतर्गत विधायी संबंधों के अनुच्छेदों का सही क्रम अत्यंत स्पष्ट है। अनुच्छेद 249 में राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर संसद की कानून बनाने की शक्ति वर्णित है। अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर संसदीय शक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति पर संसद को शक्ति देता है। अंततः, अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों व संधियों को लागू करने हेतु कानून बनाने का अनन्य अधिकार प्रदान करता है।

29. (B) छह महीने
अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रस्ताव के समाप्त होने के बाद अधिकतम छह महीने की अवधि तक लागू रहता है। इसके पश्चात वह कानून स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है। यदि राज्यसभा प्रस्ताव की अवधि समाप्त होने से पूर्व उसे पुनः एक वर्ष के लिए विस्तारित नहीं करती है, तो छह महीने बीत जाने के बाद संसद द्वारा बनाई गई वह विधि राज्य सूची के उस विषय पर निष्प्रभावी मानी जाती है।

30. (D) अनुच्छेद 253
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को यह विशेष अधिकार देता है कि वह किसी अन्य देश के साथ की गई संधि, करार या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने के लिए पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। इस कार्य हेतु संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर भी विधान बनाने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है, और इसके लिए संबंधित राज्यों की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होता। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के पालन को सुनिश्चित करता है।

31. (A) संसद द्वारा बनाए गए कानून
संविधान का अनुच्छेद 256 केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट करता है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित कानूनों और उस राज्य में लागू विद्यमान विधानों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो केंद्र सरकार द्वारा निर्मित कानूनों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक और उचित प्रतीत होते हों।

32. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अनुच्छेद 257 में यह प्रावधान है कि राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरह होना चाहिए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा न आए। अनुच्छेद 257(2) के अंतर्गत केंद्र सरकार किसी भी राज्य को राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के संचार साधनों के निर्माण और रखरखाव के संबंध में निर्देश जारी कर सकती है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण स्पष्ट रूप से अभिकथन की सही संवैधानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है।

33. (B) संबंधित राज्य सरकार की सहमति से राष्ट्रपति
अनुच्छेद 258(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति संबंधित राज्य सरकार की सहमति से उस राज्य सरकार को या उसके अधिकारियों को सशर्त या बिना शर्त कोई भी ऐसा प्रशासनिक कार्य सौंप सकते हैं जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार में आता हो। इसके विपरीत, अनुच्छेद 258(2) के अंतर्गत संसद कानून बनाकर भी राज्य की सहमति के बिना उसे कार्य सौंप सकती है। हालाँकि, राष्ट्रपति द्वारा सौंपा जाने वाला कार्य सदैव राज्य की सहमति पर निर्भर करता है।

34. (B) केवल II और III
कथन II गलत है क्योंकि अनुच्छेद 257(3) के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों को रेलवे की सुरक्षा हेतु निर्देश जारी कर सकती है। कथन III भी गलत है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 258ए राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र सरकार की सहमति से राज्य के कार्यपालक कार्य केंद्र को सौंप सकता है। अतः दोनों कथन गलत हैं। कथन I पूरी तरह सही है क्योंकि अनुच्छेद 365 निर्देशों का अनुपालन न करने पर अनुच्छेद 356 लागू करने का आधार बनता है।

35. (C) राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच परस्पर सहमति से
संविधान के अनुच्छेद 258 और 258ए के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच कार्यपालिका शक्तियों का परस्पर हस्तांतरण किया जा सकता है। राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से संघ के कार्य राज्य को सौंप सकते हैं, जबकि राज्यपाल केंद्र सरकार की सहमति से राज्य के प्रशासनिक कार्य संघ को सौंप सकते हैं। यह प्रक्रिया किसी औपचारिक संवैधानिक संशोधन या अदालती आदेश के बिना केवल दोनों स्तरों की आपसी सहमति और प्रशासनिक समन्वय के माध्यम से संभव होती है।

36. (D) अनुच्छेद 270
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 270 संघ द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए करों के शुद्ध आगमों के वितरण का प्रावधान करता है। इन करों को भारत सरकार और राज्यों के बीच साझा किया जाता है। इस वितरण का अनुपात वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें कृषि आय को छोड़कर अन्य सभी कर शामिल होते हैं, जिससे राज्यों को उनके वित्तीय संसाधनों की आपूर्ति हेतु विभाज्य पूल का हिस्सा प्राप्त होता है।

37. (C) पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा रखे जाते हैं
संविधान के अनुच्छेद 271 के तहत संसद किसी भी समय संघ के प्रयोजनों के लिए करों या शुल्कों पर अधिभार (सरचार्ज) लगा सकती है। इस अधिभार से प्राप्त संपूर्ण आय भारत की संचित निधि का हिस्सा बनती है और इसे पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा अपने पास रखा जाता है। इस राशि का राज्यों के साथ कोई बंटवारा नहीं किया जाता है और यह वित्त आयोग द्वारा वितरित किए जाने वाले विभाज्य पूल से बाहर रखी जाती है।

38. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अनुच्छेद 275 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह राज्यों को वित्तीय आवश्यकता के अनुसार सहायता-अनुदान (ग्रांट-इन-एड) दे सकती है। यह अनुदान भारत की संचित निधि पर भारित होता है और प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की जा सकती है। संसद यह अनुदान वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत करती है। इसलिए अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण अभिकथन की पूर्ण और स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत करता है।

39. (D) विनिमय पत्रों पर मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी)
संविधान के अनुच्छेद 268 के अंतर्गत विनिमय पत्रों, चेक, प्रोमीसरी नोट्स और शेयर हस्तांतरण पर लगाए जाने वाले स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किए जाते हैं। परंतु इन शुल्कों का संग्रह और विनियोजन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्य क्षेत्र में किया जाता है। इनसे प्राप्त संपूर्ण राजस्व भारत की संचित निधि का भाग न बनकर सीधे संबंधित राज्यों के खातों में जमा होता है जहाँ पर वे वसूले जाते हैं।

Click Here to Buy book on Flipkart

40. (A) राज्यों के पास बिना किसी प्रतिबंध के विदेशों से असीमित ऋण लेने की शक्ति है।
संविधान का अनुच्छेद 293 स्पष्ट करता है कि राज्य सरकारें सीधे विदेशी स्रोतों या विदेशी सरकारों से ऋण नहीं ले सकती हैं। राज्यों की ऋण लेने की शक्ति केवल भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर तक सीमित है। इसके अलावा, यदि राज्य पर केंद्र सरकार का कोई पिछला बकाया ऋण बाकी है, तो राज्य केंद्र की पूर्व अनुमति के बिना कोई नया घरेलू ऋण भी नहीं जुटा सकता है। अतः विदेशी ऋण लेने संबंधी दावा गलत है।

41. (C) अनुच्छेद 280
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक पांच वर्ष में या आवश्यकतानुसार उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। यह एक अर्ध-न्यायिक और संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। वित्त आयोग करों के शुद्ध आगमों के वितरण, राज्यों के सहायता-अनुदान के सिद्धांतों और स्थानीय निकायों के संसाधनों को मजबूत करने के उपायों की सिफारिश राष्ट्रपति को करता है।

42. (C) एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य
संविधान के अनुच्छेद 280(2) के अनुसार वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद को कानून बनाकर वित्त आयोग के सदस्यों की अहर्ताओं और चयन की प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। संसद द्वारा बनाए गए वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों का अनुभवी तथा सदस्यों को अर्थशास्त्र, सार्वजनिक वित्त, न्यायपालिका व लेखा का ज्ञान होना आवश्यक है।

43. (D) विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों को वार्षिक योजना परिव्यय आवंटित करना।
विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों को योजना परिव्यय आवंटित करना वित्त आयोग का संवैधानिक कार्य नहीं है, बल्कि यह कार्य पूर्व में योजना आयोग द्वारा और वर्तमान में वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग के प्रमुख संवैधानिक कार्यों में संघ और राज्यों के बीच करों के बंटवारे का सुझाव देना, राज्यों के लिए सहायता-अनुदान के सिद्धांत तय करना तथा पंचायतों व नगरपालिकाओं के वित्तीय संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य संचित निधि बढ़ाने के उपाय बताना शामिल है।

44. (A) केवल I, II और III
15वें वित्त आयोग का गठन एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग ने विभाज्य कर पूल में राज्यों का हिस्सा 42% से घटाकर 41% करने की सिफारिश की, जिसमें 1% की कमी जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण की गई। आयोग ने जनसांख्यिकीय प्रदर्शन के आकलन हेतु केवल 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया। अतः कथन IV गलत है क्योंकि हस्तांतरण हिस्सा 14वें आयोग के समान नहीं रहा।

45. (C) सलाहकारी प्रकृति की, जो केंद्र सरकार की स्वीकृति के अधीन हैं
संविधान में वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की प्रकृति को केवल सलाहकारी या परामर्शदात्री माना गया है। केंद्र सरकार पर इन सिफारिशों को लागू करने की कोई कानूनी या संवैधानिक बाध्यता नहीं होती है। हालाँकि, चूंकि वित्त आयोग एक उच्चस्तरीय संवैधानिक निकाय है, इसलिए भारत सरकार द्वारा इसकी वित्तीय सिफारिशों को सामान्यतः स्वीकार कर लिया जाता है और संसद के पटल पर इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

46. (D) अनुच्छेद 263
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान करता है कि यदि उन्हें ऐसा प्रतीत हो कि सार्वजनिक हित में एक अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना आवश्यक है, तो वे आदेश जारी करके ऐसी परिषद का गठन कर सकते हैं। यह एक संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय विवादों की जांच करना, उन पर विचार-विमर्श करना तथा नीतिगत समन्वय को बेहतर बनाकर सहकारी संघवाद को मजबूत करना है।

47. (A) भारत के प्रधानमंत्री
1990 में गठित अंतर-राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। परिषद की संरचना में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक, तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत छह कैबिनेट स्तर के केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। यह संस्था देश में नीतिगत समन्वय, साझा हितों के विषयों पर चर्चा और केंद्र-राज्य संबंधों में सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित करने के लिए एक शीर्ष मंच के रूप में कार्य करती है।

48. (A) P-2, Q-1, R-4, S-3
भारतीय संविधान में अंतर-राज्यीय संबंधों और राजकोषीय ढांचे हेतु स्पष्ट अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। अनुच्छेद 262 में अंतर-राज्यीय नदियाँ और जल विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान निहित है। अनुच्छेद 275 संसद को वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को अनुदान देने के लिए अधिकृत करता है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है।

49. (B) सरकारिया आयोग
केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने अपनी सिफारिशों में अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर-राज्यीय परिषद स्थापित करने का पुरजोर समर्थन किया था। इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा मई 1990 में औपचारिक रुप से अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। आयोग का मुख्य तर्क यह था कि केंद्र और राज्यों के मध्य निरंतर संवाद स्थापित करने के लिए एक संवैधानिक मंच का होना अनिवार्य है।

Downloaded from www.pdf.tube

50. (A) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय
भारत में क्षेत्रीय परिषदें (जोनल काउंसिल्स) संवैधानिक निकाय न होकर वैधानिक (संवैधानिक रूप से गैर-संवैधानिक) निकाय हैं। इनकी स्थापना संसद द्वारा पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। इस अधिनियम ने देश को पांच क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य में विभाजित करके पांच क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया था। इनका मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक-सामाजिक समन्वय और भावात्मक एकीकरण को बढ़ावा देना है।

51. (C) उत्तरी क्षेत्रीय परिषद
राजस्थान राज्य उत्तरी क्षेत्रीय परिषद (नॉर्दर्न जोनल काउंसिल) का एक प्रमुख सदस्य है। इस परिषद में राजस्थान के अतिरिक्त हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब राज्य तथा जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इस परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद इन सभी उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अंतर-राज्यीय परिवहन, सुरक्षा, जल वितरण और विकास योजनाओं में सहयोग बढ़ाने का कार्य करती है।

52. (D) केंद्रीय गृह मंत्री
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित सभी पांचों क्षेत्रीय परिषदों के पदेन अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री की यह साझा अध्यक्षता सभी परिषदों के मध्य प्रशासनिक निरंतरता और समन्वय बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा संबंधित क्षेत्रों के राज्यों के मुख्यमंत्री बारी-बारी से एक वर्ष के कार्यकाल के लिए उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। यह व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच सीधे संवाद का मंच प्रदान करती है।

53. (C) पूर्वोत्तर परिषद
1956 के अधिनियम द्वारा गठित मूल पांच क्षेत्रीय परिषदों के अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों की विशिष्ट समस्याओं को संबोधित करने के लिए 'पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971' द्वारा पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना की गई थी। इस परिषद में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और बाद में 2002 में शामिल किया गया सिक्किम राज्य सम्मिलित हैं। यह परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के एकीकृत आर्थिक, सामाजिक और अवसंरचनात्मक विकास के लिए विशेष योजना निकाय के रूप में कार्य करती है।

54. (A) 2, 3, 4, 1
प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्रीय परिषदों के क्रम (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, दक्षिणी) के अनुसार राज्यों का सटीक मिलान इस प्रकार है: राजस्थान उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है, बिहार पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है तथा तमिलनाडु दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत सम्मिलित है। अतः 2, 3, 4, 1 का संयोजन इन चारों राज्यों और उनकी संबंधित परिषदों की भौगोलिक स्थिति का सही निरूपण करता है।

55. (D) अनुच्छेद 312
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की शक्ति प्रदान करता है। हालाँकि, यह प्रक्रिया केवल तभी प्रारंभ हो सकती है जब राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है। राज्यसभा को प्राप्त यह विशेषाधिकार भारत के राज्यों के हित संरक्षक के रूप में उसकी संघीय भूमिका को रेखांकित करता है।

56. (A) ये केंद्र द्वारा भर्ती की जाती हैं तथा केंद्र और राज्य दोनों की सेवा करती हैं
अखिल भारतीय सेवाएं (जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) भारतीय संघवाद का एक अनूठा लक्षण प्रस्तुत करती हैं। इन सेवाओं के अधिकारियों की भर्ती और प्रशिक्षण केंद्र सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है, परंतु वे सेवाएं केंद्र और राज्यों दोनों के कैडर में प्रदान करते हैं। यह व्यवस्था देश भर में उच्च प्रशासनिक मानकों की एकरूपता बनाए रखने तथा केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक सेतु का कार्य करने में सहायक होती है।

57. (C) राजस्थान सरकार
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर दोहरा नियंत्रण स्थापित होता है। जब कोई आईएएस अधिकारी राजस्थान कैडर में तैनात होता है, तो उस पर तत्कालीन (तत्काल) प्रशासनिक व अनुशासनात्मक नियंत्रण राजस्थान सरकार का होता है। राज्य सरकार अधिकारी का स्थानांतरण, निलंबन और कार्य आवंटन कर सकती है। हालाँकि, अंतिम या प्रमुख अनुशासनात्मक कार्रवाई (जैसे सेवा से बर्खास्तगी या हटाना) केवल केंद्र सरकार द्वारा ही संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जा सकती है।

58. (A) कथन I सही है, कथन II गलत है
अखिल भारतीय सेवाओं को अक्सर एकात्मक लक्षण माना जाता है क्योंकि इन पर अंतिम नियंत्रण केंद्र का होता है, जिससे राज्यों की प्रशासनिक स्वायत्तता प्रभावित होती है। अतः कथन I सही है। परंतु कथन II पूरी तरह गलत है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 311 के अनुसार राज्य सरकारों के पास अखिल भारतीय सेवा के किसी भी अधिकारी को पदच्युत करने या हटाने की शक्ति नहीं है। यह अंतिम दंडात्मक अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास ही सुरक्षित रहता है।

NODIA

59. (D) भारतीय विदेश सेवा (IFS)
वर्तमान में भारत में केवल तीन सेवाएं ही अखिल भारतीय सेवाओं की श्रेणी में आती हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFoS)। भारतीय वन सेवा को 1966 में तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में जोड़ा गया था। इसके विपरीत, भारतीय विदेश सेवा (IFS) एक केंद्रीय सेवा (Central Service) है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और राज्यों में कैडर के रूप में तैनात नहीं होती।

60. (A) केवल I और II
अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। इसे जारी होने की तिथि से दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित होना अनिवार्य है। अतः कथन I और II सही हैं। परंतु कथन III गलत है क्योंकि संसद के अनुमोदन के बाद भी यह एक बार में केवल छह महीने तक लागू रहता है और अधिकतम तीन वर्षों से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।

61. (C) राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा
जब किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है। इस अवधि में राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग राज्य के राज्यपाल के माध्यम से करते हैं। राज्यपाल राज्य के मुख्य सचिव तथा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सलाहकारों की मदद से राज्य का संपूर्ण प्रशासनिक संचालन करते हैं, जिससे शासन व्यवस्था बाधित न हो।

62. (C) तीन वर्ष
अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को संसद के प्रत्येक छह महीने के अनुमोदन के साथ अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए विस्तार केवल दो स्थितियों में संभव है: यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, या चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि राज्य में विधानसभा चुनाव कराना कठिन है। तीन वर्ष समाप्त होने के बाद संवैधानिक आपातकाल की निरंतरता संभव नहीं होती।

63. (A) इसे निलंबित या भंग किया जा सकता है।
राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के समय राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को या तो निलंबित कर सकते हैं या पूरी तरह भंग कर सकते हैं। सामान्यतः जब तक संसद द्वारा राष्ट्रपति की उद्घोषणा को दो महीने के भीतर मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक विधानसभा को भंग न करके केवल निलंबित रखा जाता है। संसद का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात राष्ट्रपति विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी कर सकते हैं या उसे निलंबित स्थिति में बनाए रख सकते हैं।

64. (C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थापित किया था कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति निरपेक्ष नहीं है, बल्कि यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अदालत यह जांच कर सकती है कि फैसला दुर्भावनापूर्ण या अप्रासंगिक साक्ष्यों पर तो आधारित नहीं है। इसलिए अभिकथन सही है, परंतु कारण गलत है क्योंकि अदालत ने इस शक्ति को चुनौती योग्य माना था।

65. (B) 1983
केंद्र सरकार ने जून 1983 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया था, जिसे सरकारिया आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं और संबंधों की व्यापक समीक्षा करना था। आयोग ने 1988 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी, जिसमें संघवाद को मजबूत करने और प्रशासनिक सुधारों हेतु 247 महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की गई थीं।

66. (A) राज्यपाल संबंधित राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए।
सरकारिया आयोग ने राज्यपाल पद की निष्पक्षता और गरिमा बनाए रखने के लिए यह सिफारिश की थी कि राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। वह स्थानीय राजनीति से गहराई से न जुड़ा हो और हाल के वर्षों में सक्रिय राजनीति में भाग न लिया हो। इसके अलावा, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करने की परंपरा का सख्ती से पालन होना चाहिए।

67. (C) केवल असाधारण मामलों में अंतिम विकल्प के रूप में
सरकारिया आयोग ने अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के बार-बार होने वाले दुरुपयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। आयोग ने स्पष्ट सिफारिश की थी कि इस प्रावधान का प्रयोग केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में, जब शासन के सभी संवैधानिक विकल्प विफल हो जाएं, अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को बर्खास्त करने से पहले चेतावनी दी जानी चाहिए और राज्य को अपना रुख स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

68. (D) केंद्र को समवर्ती विषयों पर कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श करना चाहिए
सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र सरकार को समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने या अध्यादेश जारी करने से पहले अंतर-राज्यीय परिषद के माध्यम से राज्यों से परामर्श करना चाहिए। इससे केंद्र और राज्यों के बीच टकराव कम होगा और कानूनों का क्रियान्वयन सुचारु रूप से हो सकेगा। आयोग का मानना था कि समवर्ती सूची केंद्र और राज्यों के बीच एक सहयोगात्मक क्षेत्र है, इसलिए इस पर एकतरफा कार्रवाई के बजाय विचार-विमर्श की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

69. (C) अंतर-राज्यीय परिषद
सरकारिया आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी और स्वतंत्र अंतर-राज्यीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया था। आयोग का विचार था कि इस परिषद को अंतर-सरकारी परिषद के रूप में नामित किया जाना चाहिए ताकि यह केंद्र और राज्यों के साझा हितों वाले विषयों पर विचार-विमर्श करने और विवादों को सुलझाने के लिए एक नियमित संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य कर सके। इसी सिफारिश के आधार पर 1990 में अंतर-राज्यीय परिषद बनी।

Click Here to Buy book on Amazon

70. (A) केवल I, II और III
पुंछी आयोग (2007) ने केंद्र-राज्य संबंधों को बेहतर बनाने हेतु कई महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थीं। इसमें राज्यपालों के लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल तय करना, राज्यपालों को हटाने हेतु राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया बनाना तथा पूरे राज्य के बजाय विशिष्ट क्षेत्रों में 'स्थानीयकृत आपातकाल' लागू करना शामिल था। अतः कथन I, II और III सही हैं। कथन IV गलत है क्योंकि आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने के बजाय मजबूत करने की सिफारिश की थी।

71. (D) मदन मोहन पुंछी
केंद्र सरकार ने अप्रैल 2007 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए द्वितीय आयोग का गठन किया था। इसे सामान्यतः पुंछी आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने बदलती सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलन, राज्यपाल की भूमिका, आपातकालीन प्रावधानों तथा वित्तीय संबंधों का गहन अध्ययन किया और 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

72. (A) राष्ट्रपति के समान राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग
पुंछी आयोग ने राज्यपाल के पद को राजनीतिक मनमर्जी और केंद्र के अनुचित प्रभाव से मुक्त करने के लिए एक क्रांतिकारी सिफारिश की थी। आयोग का प्रस्ताव था कि राज्यपालों को राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त हटाने की व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए। इसके स्थान पर उन्हें हटाने के लिए संविधान में संशोधन करके राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग चलाए जाने की प्रक्रिया जोड़ी जानी चाहिए, जो ठीक उसी प्रकार हो जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए अपनाई जाती है।

73. (C) स्थानीयकृत आपातकाल
पुंछी आयोग ने यह देखा कि कभी-कभी राज्य के किसी एक विशिष्ट जिले या छोटे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, जबकि शेष राज्य शांत रहता है। इसके समाधान हेतु आयोग ने 'स्थानीयकृत आपातकाल' (लोकलाइज्ड इमरजेंसी) की अवधारणा प्रस्तुत की। इसके तहत अनुच्छेद 355 और 356 में संशोधन करके केंद्र को पूरे राज्य की सरकार गिराने के बजाय केवल प्रभावित विशिष्ट क्षेत्र में सीमित अवधि के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार देने का प्रस्ताव था।

74. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित आयोगों का सही कालक्रम इस प्रकार है: सरकारिया आयोग का गठन 1983 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। पुंछी आयोग की स्थापना 2007 में केंद्र द्वारा की गई थी। राजमन्नार समिति का गठन 1969 में तमिलनाडु की राज्य सरकार द्वारा राज्यों की स्वायत्तता की समीक्षा हेतु किया गया था। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में शिरोमणि अकाली दल द्वारा अपनाया गया था, जिसमें राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की मांग की गई थी।

75. (D) राज्यों में
संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ (रेसिड्यूअरी पावर्स) राज्यों के पास निहित हैं। अमेरिकी संविधान का 10वां संशोधन स्पष्ट करता है कि जो शक्तियाँ संघ सरकार को नहीं सौंपी गई हैं और न ही राज्यों से छीनी गई हैं, वे सभी शक्तियाँ राज्यों और जनता के पास सुरक्षित रहेंगी। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के विपरीत है, जहाँ अनुच्छेद 248 के माध्यम से अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार यानी भारत की संसद को दी गई हैं।

76. (B) अमेरिका दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, जबकि भारत एकल नागरिकता प्रदान करता है।
अमेरिकी और भारतीय संघीय प्रणालियों के बीच नागरिकता का प्रावधान एक प्रमुख मूलभूत अंतर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, जहाँ एक व्यक्ति अमेरिका का नागरिक होने के साथ-साथ अपने संबंधित राज्य का भी नागरिक होता है। इसके विपरीत, भारत में एकीकृत और एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होता है, किसी विशिष्ट राज्य का नहीं। यह भारत की एकता और अखंडता को संवर्धित करता है।

NODIA

77. (C) राज्य की जनसंख्या
संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में सभी 50 राज्यों को समान प्रतिनिधित्व (प्रत्येक राज्य से 2 सीटें) दिया गया है, चाहे राज्य का आकार या जनसंख्या कुछ भी हो। इसके विपरीत, भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आवंटित किया जाता है। संविधान की चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन निर्दिष्ट है, जिसके कारण अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक सीटें मिलती हैं।

78. (D) राज्यों के अनुसमर्थन के बिना केवल संसद द्वारा
अमेरिकी संविधान अत्यधिक कठोर है जहाँ किसी भी संशोधन के लिए कम से कम तीन-चौथाई (38) राज्यों की मंजूरी आवश्यक होती है। इसके विपरीत, भारतीय संविधान में लचीलेपन और कठोरता का अनूठा मिश्रण है। भारत में संविधान के एक बड़े हिस्से में संशोधन राज्यों के अनुसमर्थन के बिना केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष या साधारण बहुमत से किया जा सकता है। केवल वही संशोधन राज्यों के पास जाते हैं जो संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं।

79. (A) अमेरिकी कांग्रेस संबंधित राज्य की सहमति के बिना उसकी सीमाओं को नहीं बदल सकती।
अमेरिकी संघ को "अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ" कहा जाता है, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस (संसद) संबंधित राज्य की सहमति के बिना उस राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल, सीमाओं या नाम में कोई बदलाव नहीं कर सकती है। इसके विपरीत, भारत को "विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ" माना जाता है, जहाँ भारतीय संसद अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य की सहमति के बिना भी उसकी सीमाओं, क्षेत्रफल या नाम को अपनी इच्छा से परिवर्तित कर सकती है।

80. (A) 1, 3, 2
प्रश्न में दिए गए संशोधनों को उनके पारित होने के नवीनतम से पुराने (अवरोही) वर्ष क्रम में सजाने पर सही अनुक्रम प्राप्त होता है: 101वां संशोधन अधिनियम (जीएसटी) वर्ष 2016 में पारित हुआ था। 97वां संशोधन अधिनियम (सहकारी समितियां) वर्ष 2011 में लागू किया गया था। 42वां संशोधन अधिनियम (राज्य सूची से समवर्ती सूची में विषयों का स्थानांतरण) वर्ष 1976 में पारित किया गया था। अतः सही अवरोही क्रम 1, 3, 2 है।

81. (B) विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति
संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की राज्यपाल की शक्ति की आलोचना अक्सर राज्य सरकारें केंद्रीकरण के साधन के रूप में करती हैं। राज्यों का तर्क है कि केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल इस शक्ति का दुरुपयोग कर राज्य के कानूनों में अनावश्यक देरी करते हैं या उन्हें रोकते हैं। इससे राज्य विधानमंडल की विधायी स्वायत्तता और जनमत द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन होता है।

82. (A) संघ सूची में अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाले करों का संकेंद्रण
भारतीय राजकोषीय ढांचे में अत्यधिक राजस्व उत्पन्न करने वाले कर साधन (जैसे आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क) संघ सूची में केंद्रीय सरकार के पास संकेंद्रित हैं। इसके विपरीत, राज्यों को नागरिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस जैसे भारी व्यय वाले दायित्व सौंपे गए हैं, जबकि उनके पास कर राजस्व के सीमित स्रोत हैं। इस संवैधानिक असंतुलन के कारण राज्यों को अपनी बजटीय आवश्यकताओं और विकास योजनाओं के लिए निरंतर केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है।

83. (C) अनुच्छेद 355
संविधान का अनुच्छेद 355 यह स्पष्ट संवैधानिक कर्तव्य संघ सरकार पर आरोपित करता है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके केंद्र सरकार राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की तैनाती कर सकती है। केंद्र सरकार इस कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा और संविधान की रक्षा के लिए आवश्यक मानती है।

84. (D) तीन केंद्रीय कृषि कानूनों का निर्माण (जो बाद में निरस्त कर दिए गए)
वर्ष 2020 में संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों को विश्लेषकों द्वारा भारतीय संघवाद में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के उदाहरण के रूप में देखा गया था। यद्यपि कृषि संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है, केंद्र सरकार ने समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के तहत व्यापार और वाणिज्य के अधिकार का प्रयोग कर इन कानूनों को बनाया था। राज्यों ने तर्क दिया था कि इस कदम से राज्य सूची के संवैधानिक क्षेत्राधिकार का उल्लंघन हुआ और उनकी वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई।

85. (A) केवल I और II
73वें और 74वें संशोधन ने पंचायती राज व नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देकर शासन के तीसरे स्तर का निर्माण किया। 2015 में स्थापित नीति आयोग ने 'टॉप-डाउन' मॉडल को समाप्त कर 'सहकारी संघवाद' को बढ़ावा दिया। अतः कथन I और II सही हैं। परंतु कथन III गलत है क्योंकि 14वें और 15वें वित्त आयोगों ने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को पहले के 32% से बढ़ाकर क्रमशः 42% और 41% किया है।

86. (B) ग्यारहवीं अनुसूची
1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इस अनुसूची का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से सशक्त बनाना और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना था। ग्यारहवीं अनुसूची में कुल 29 कार्यकारी विषय शामिल किए गए हैं, जैसे कृषि, ग्रामीण विकास, पेयजल, सड़कें और स्वास्थ्य। इन विषयों पर काम करने और योजनाएं बनाने की शक्तियाँ राज्य विधानमंडलों द्वारा पंचायतों को सौंपी जाती हैं।

87. (D) राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों के वितरण के संबंध में
संविधान के अनुच्छेद 243-आई के तहत गठित राज्य वित्त आयोग प्रत्येक पांच वर्ष में राज्य के राज्यपाल को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। इसका मुख्य कार्य राज्य सरकार द्वारा वसूले जाने वाले करों, शुल्कों, पथकर और फीस के शुद्ध आगमों का राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगरपालिकाओं) के बीच वितरण के सिद्धांत तय करना है। यह आयोग स्थानीय स्वशासी निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राज्य की संचित निधि से सहायता-अनुदान का निर्धारण भी करता है।

88. (C) 1989 - 2014
1989 से 2014 के मध्य के कालखंड को भारतीय राजनीति और संघवाद में 'गठबंधन राजनीति का दौर' माना जाता है। इस अवधि में केंद्र में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यंत निर्णायक हो गई थी। इस काल में राजनीतिक सत्ता का स्पष्ट विकेंद्रीकरण हुआ, जिससे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रभाव राष्ट्रीय नीतियों के निर्धारण में काफी बढ़ गया और सौदेबाजी का संघवाद सशक्त हुआ।

89. (C) संसद को
संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को यह अनन्य शक्ति प्रदान करता है कि वह कानून बनाकर अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद के न्यायनिर्णयन का प्रावधान कर सकती है। संसद इस अनुच्छेद के तहत कानून बनाकर ऐसे विवादों को सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रख सकती है। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया था।

Downloaded from www.pdf.tube

90. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
संविधान का अनुच्छेद 262(2) संसद को यह अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर अंतर-राज्यीय जल विवादों में सर्वोच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित (समाप्त) कर दे। जब संसद अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम के तहत विशेष जल अधिकरण (ट्रिब्यूनल) का गठन कर देती है, तो उस विवाद का निपटारा केवल वही अधिकरण करता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाता है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है।

91. (D) रावी और ब्यास
राजस्थान रावी और ब्यास नदी जल विवाद में पंजाब और हरियाणा के साथ एक प्रमुख पक्षकार राज्य है। इस जल विवाद के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 1986 में रावी एवं ब्यास जल अधिकरण (इराडी ट्रिब्यूनल) का गठन किया था। राजस्थान इस तंत्र के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर (राजस्थान नहर) परियोजना के लिए अपने हिस्से का पानी प्राप्त करता है। कृषि सिंचाई और पेयजल आपूर्ति की दृष्टि से यह जल बंटवारा राजस्थान राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

92. (B) 1956
संसद ने संविधान के अनुच्छेद 262 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1956 में 'अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम' पारित किया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य अंतर-राज्यीय नदियों के जल बंटवारे को लेकर उत्पन्न विवादों को सुलझाने के लिए तदर्थ (एड-हॉक) जल विवाद अधिकरणों की स्थापना करना है। इस अधिनियम के तहत गठित अधिकरण का निर्णय अंतिम होता है और विवाद में शामिल राज्यों पर बाध्यकारी माना जाता है।

93. (C) अधिकरण के गठन, निर्णय और प्रवर्तन में अत्यधिक विलंब
भारत में अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिकरणों की सबसे बड़ी विफलता और मुख्य आलोचना उनके गठन, न्यायिक कार्यवाही और अंतिम निर्णय देने में लगने वाला अत्यधिक समय है। कई अधिकरणों को अपना निर्णय सुनाने में दशकों का समय लग जाता है, जिससे राज्यों के बीच तनाव बढ़ता है। इसके अतिरिक्त, निर्णय आने के बाद भी राज्यों द्वारा उसे लागू न करने या सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने के कारण अंतर-राज्यीय जल विवाद लंबे समय तक अनिर्णीत रहते हैं।

94. (D) राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना
अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना राज्यपाल की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक विवेकाधीन शक्ति है। इसके लिए राज्यपाल को राज्य के मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री की सलाह मानना अनिवार्य नहीं होता है। राज्यपाल यदि यह अनुभव करते हैं कि कोई विधेयक संविधान के प्रावधानों के विपरीत है या उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरे में डालता है, तो वे अपने विवेक का प्रयोग करके उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं।

95. (B) केवल I, III और IV
निर्वाचित राज्य सरकारों और राज्यपाल के बीच तनाव के मुख्य बिंदुओं में अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश, राज्य के विधेयकों पर सहमति रोके रखना या उन्हें अटकाना, तथा राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कुलपतियों की नियुक्ति में मनमर्जी करना शामिल हैं। कथन II तनाव का कारण नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 207 के अनुसार राज्यपाल धन विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा ही नहीं सकते।

96. (B) अनुच्छेद 200
संविधान के अनुच्छेद 200 के दूसरे परंतुक में यह स्पष्ट और अनिवार्य रूप से उल्लिखित किया गया है कि यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों या उसकी संवैधानिक स्थिति को इस प्रकार कम करता है कि उससे अदालत की स्वतंत्र भूमिका संकटापन्न होती हो, तो राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देंगे। ऐसे किसी भी विधेयक को राज्यपाल द्वारा अनिवार्य रूप से भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा ही जाना चाहिए। यह संवैधानिक प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता को सुरक्षित रखने हेतु बनाया गया है।

97. (B) राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 156(1) के अंतर्गत यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के 'प्रसादपर्यन्त' अपना पद धारण करेगा। इसका सीधा विधिक तात्पर्य यह है कि यद्यपि राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु केंद्र सरकार यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति उसे 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले किसी भी समय बिना कोई कारण बताए पद से हटा सकते हैं। इसमें महाभियोग जैसी प्रक्रिया शामिल नहीं है।

98. (A) अनुच्छेद 174
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 174 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर आहूत (बुलाने), सत्रावसान करने और विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। सामान्य संवैधानिक स्थिति के तहत राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। हालाँकि, विधानसभा सत्र बुलाने और बहुमत परीक्षण की मांग को लेकर राजस्थान सहित कई राज्यों में राज्यपाल की शक्तियों पर विवाद खड़ा हुआ है।

99. (C) अनुच्छेद 279A
101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 279A जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद का

NODIA

गठन करने का अधिकार दिया गया है। जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच एक साझा मंच के रूप में कार्य करती है। यह संस्था कर दरों, छूट की सीमाओं और जीएसटी से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर सर्वसम्मति से निर्णय लेती है।

100. (A) P-2, Q-1, R-3, S-4
जीएसटी परिषद में मतदान और निर्णय प्रक्रिया हेतु स्पष्ट संवैधानिक मापदंड निर्धारित हैं। परिषद में केंद्र सरकार के मतों का भार कुल डाले गए मतों का एक-तिहाई (33.33%) होता है। सभी राज्य सरकारों के मतों का कुल संयुक्त भार डाले गए मतों का दो-तिहाई (66.67%) होता है। परिषद की बैठक आयोजित करने के लिए कुल सदस्यों का आधा (50%) कोरम होना अनिवार्य है, तथा कोई भी निर्णय कुल भारित मतों के तीन-चौथाई (75%) बहुमत से ही लिया जाता है।

101. (C) केंद्रीय वित्त मंत्री
संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद का पदेन अध्यक्ष भारत का केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। परिषद के अन्य सदस्यों में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत वित्त मंत्री या कराधान प्रभारी मंत्री या कोई अन्य मंत्री शामिल होते हैं। अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री बैठक की अध्यक्षता करते हैं और केंद्र तथा राज्यों के मध्य अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में बेहतर सामंजस्य स्थापित करते हैं।

102. (B) वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री
जीएसटी परिषद की संरचना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व उस राज्य सरकार द्वारा मनोनीत मंत्री द्वारा किया जाता है। राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व आमतौर पर राज्य के वित्त मंत्री या कराधान विभाग का प्रभार संभालने वाले कैबिनेट मंत्री द्वारा किया जाता है। यदि मुख्यमंत्री स्वयं वित्त पोर्टफोलियो रखते हैं, तो वे स्वयं भाग ले सकते हैं या किसी अन्य नामित मंत्री को परिषद की बैठकों में राजस्थान के वित्तीय हितों और रुख का प्रतिनिधित्व करने हेतु भेजते हैं।

103. (D) जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर (सेक)
जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को होने वाले संभावित राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए जीएसटी (क्षतिपूर्ति अधिनियम) 2017 के तहत जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर (कंपन्सेशन सेस) का प्रावधान किया गया था। यह उपकर विलासिता और अहितकर (सिन) वस्तुओं (जैसे तंबाकू, वाहित पेय, महंगी कारें) पर लगाया जाता है। इससे एकत्रित राशि का उपयोग राज्यों को जीएसटी अपनाने से हुए राजस्व घाटे की पांच वर्षों की शुरुआती संक्रमण अवधि के दौरान शत-प्रतिशत भरपाई करने के लिए किया गया था।

104. (A) अनुच्छेद 356
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) का मामला भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक मील का पत्थर निर्णय माना जाता है। कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई की सरकार को बर्खास्त किए जाने के विरोध में यह याचिका दायर की गई थी। इस फैसले में न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत दिया तथा राज्यों में राजनीतिक दुर्भावना से चुनी हुई सरकारों को गिराने की प्रवृत्ति पर कड़ा अंकुश लगाया था।

105. (A) 3, 2, 1
भारतीय संघवाद और संवैधानिक व्याख्या से संबंधित ऐतिहासिक मामलों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम (पुराने से नया) 3, 2, 1 है। आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का फैसला 1967 में आया था जिसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन पर रोक लगाई गई थी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में तय हुआ था जिसने संविधान के 'मूल ढांचे का सिद्धांत' दिया। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामला 1994 का है जिसने अनुच्छेद 356 की सीमाएं तय कीं।

106. (A) विधानसभा का पटल (फ़्लोर टेस्ट)
एस.आर. बोम्मई मामले (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह ऐतिहासिक और संवैधानिक रूप से बाध्यकारी नियम स्थापित किया कि किसी राज्य सरकार के पास विधानसभा में बहुमत है या नहीं, इसका परीक्षण केवल और केवल 'विधानसभा के पटल' (फ्लोर टेस्ट) पर ही किया जाना चाहिए। राजभवन में राज्यपाल के समक्ष विधायकों की परेड या राज्यपाल का व्यक्तिगत आकलन बहुमत का फैसला करने का वैध माध्यम नहीं हो सकता। यह निर्णय लोकतंत्र और संसदीय मर्यादा की रक्षा करता है।

107. (D) सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अदालतें असंवैधानिक रूप से बर्खास्त राज्य सरकार को पुनस्थापित नहीं कर सकती हैं।
एस.आर. बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया था कि यदि राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा को अदालत द्वारा असंवैधानिक और अवैध ठहराया जाता है, तो न्यायपालिका के पास यह पूर्ण अधिकार है कि वह असंवैधानिक रूप से बर्खास्त की गई राज्य सरकार को पुनस्थापित (बहाल) कर सके और भंग की गई विधानसभा को पुनः पुनर्जीवित कर सके। अतः यह कहना गलत है कि अदालतें बर्खास्त सरकार को बहाल नहीं कर सकती हैं।

108. (B) बर्खास्त राज्य सरकार और निलंबित विधानसभा को बहाल कर सकती है
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि यदि अदालत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा को असंवैधानिक घोषित करती है, तो वह न केवल उस उद्घोषणा को रद्द करेगी बल्कि असंवैधानिक रूप से बर्खास्त की गई मंत्रिपरिषद और निलंबित या भंग की गई राज्य विधानसभा को तुरंत पूर्व स्थिति में बहाल कर देगी। यह संवैधानिक व्यवस्था राज्यों की स्वायत्तता की रक्षा करती है तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को सुरक्षित रखती है।

Click Here to Buy book on Flipkart

109. (C) केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व शक्तियों और व्यय दायित्वों का बेमेल होना

राजकोषीय संघवाद में 'ऊर्ध्वाधर असंतुलन' (वर्टिकल इम्बलेंस) उस स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ केंद्र सरकार के पास कर राजस्व जुटाने के व्यापक अधिकार और संसाधन होते हैं, जबकि राज्यों के पास जन कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और नागरिक सुविधाओं जैसे क्षेत्रों में व्यय करने की अत्यधिक जिम्मेदारियां होती हैं। इस संरचनात्मक बेमेल को दूर करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के माध्यम से केंद्रीय करों का वितरण और राज्यों को सहायता-अनुदान प्रदान करने का प्रावधान करता है।

110. (D) I, II और III

15वें वित्त आयोग ने राज्यों के बीच करों के क्षैतिज वितरण (हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन) के लिए एक बहु-मानदंडीय सूत्र का उपयोग किया है। इसमें आय की दूरी (इंकम डिस्टेंस - कम आय वाले राज्यों की मदद हेतु), जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस - जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों को पुरस्कृत करने हेतु), तथा वन और पारिस्थितिकी (फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी - पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु) शामिल हैं। अतः ये तीनों मानदंड कर बंटवारे के सूत्र में महत्वपूर्ण भारांक के साथ सम्मिलित हैं।

111. (A) आय की दूरी (इंकम डिस्टेंस)

15वें वित्त आयोग ने करों के क्षैतिज वितरण (राज्यों के आपस में बंटवारे) के सूत्र में सर्वाधिक भारांक 'आय की दूरी' (इंकम डिस्टेंस) मानदंड को प्रदान किया है, जो कुल भारांक का 45 प्रतिशत है। आय की दूरी किसी राज्य की प्रतिव्यक्ति आय की तुलना उच्चतम प्रतिव्यक्ति आय वाले राज्य से करती है। इस मानदंड को सर्वाधिक महत्व देने का मुख्य संवैधानिक उद्देश्य निर्धन और पिछड़े राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर अंतर-राज्यीय राजकोषीय असमानताओं को कम करना है।

112. (B) वह धनराशि जो जल या स्वच्छता जैसे विशिष्ट क्षेत्रों या योजनाओं के लिए निर्धारित होती है

केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले 'सशर्त अनुदान' (कंडीशनल या टाइड ग्रांट्स) का तात्पर्य उस वित्तीय सहायता से है जिसे केंद्र सरकार विशिष्ट उद्देश्यों, योजनाओं या क्षेत्रों (जैसे पीने का पानी, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा या स्वास्थ्य अवसंरचना) के लिए प्रदान करती है। राज्य इन निधियों को किसी अन्य मद में खर्च नहीं कर सकते हैं। वे केवल उन्हीं शर्तों और दिशानिर्देशों के तहत इस धन का उपयोग करने के लिए बाध्य होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित किए गए हैं।

113. (B) केवल भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर से

संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार, राज्य सरकारों को केवल भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर से ही ऋण (उधार) जुटाने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है। राज्य सरकारें भारत की संचित निधि की जमानत पर केंद्र सरकार से अथवा खुले बाजार से घरेलू बॉन्ड जारी करके वित्तीय संसाधन जुटा सकती हैं। राज्यों को किसी भी विदेशी सरकार, विदेशी वित्तीय संस्थान या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से सीधे ऋण लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि विदेशी ऋण लेने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास सुरक्षित है।

114. (A) राज्यों में सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) जैसी केंद्रीय एजेंसियों का क्षेत्राधिकार

हाल के वर्षों में केंद्र और गैर-शासित राज्यों के बीच केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद बढ़ा है। चूंकि 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सरकारें आरोप लगाती हैं कि केंद्र सरकार इन केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग राज्य के प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने और विपक्षी दलों के नेताओं को राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए कर रही है, जिससे संघीय स्वायत्तता प्रभावित होती है।

115. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।

सीबीआई की स्थापना दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम 1946 के तहत हुई थी। इस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, सीबीआई को किसी राज्य के क्षेत्राधिकार में अपराधों की जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकार की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है। कई राज्यों ने केंद्र पर राजनीतिक दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सीबीआई को दी गई 'सामान्य सहमति' (जनरल कंसेंट) वापस ले ली है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, तथा कारण अभिकथन की बिल्कुल सटीक व्याख्या करता है।

NODIA

116. (D) ये मैचिंग फंड की आवश्यकता और केंद्रीय शर्तों के कारण राज्यों की राजकोषीय प्राथमिकता को प्रभावित करती हैं

केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) की मुख्य आलोचना राज्यों द्वारा यह की जाती है कि ये योजनाएं केंद्र द्वारा एक-समान रूप से तैयार की जाती हैं, जो राज्यों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं होतीं। इन योजनाओं के निष्पादन हेतु राज्यों को अपने सीमित बजट से मैचिंग फंड (जैसे 60:40 या 50:50 का अनुपात) लगाना पड़ता है। इसके कारण राज्यों की अपनी प्राथमिकता वाली विकास योजनाओं के लिए धन की कमी हो जाती है और उनकी राजकोषीय स्वायत्तता सीमित हो जाती है।

117. (C) इनसे प्राप्त राजस्व राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले विभाज्य पूल में शामिल नहीं होता है

राज्य सरकारें केंद्र द्वारा उपकर (सेस) और अधिभार (सरचार्ज) के बढ़ते प्रयोग का कड़ा विरोध करती हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 271 के तहत इनसे एकत्रित सारा राजस्व केंद्र सरकार की झोली में जाता है। उपकर और अधिभार से प्राप्त राशि उस विभाज्य कर पूल (डिविजिबल पूल) का हिस्सा नहीं बनती जिसे वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्यों के साथ साझा किया जाता है। इससे केंद्र का कुल कर संग्रह तो बढ़ता है, परंतु राज्यों को मिलने वाला वास्तविक वित्तीय हिस्सा घट जाता है।

118. (B) राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति (चांसलर)
राज्य विश्वविद्यालयों के संदर्भ में राज्यपाल की पारंपरिक और संवैधानिक भूमिका संबंधित राज्य के विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति (चांसलर) के रूप में होती है। कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल के पास कुलपतियों (वाइस चांसलर) की नियुक्ति करने, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करने तथा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक मामलों और नियमों की समीक्षा करने का विधिक अधिकार होता है। हाल के दिनों में कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच विवाद देखा गया है।

119. (D) नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर 'नीति आयोग' की स्थापना की थी। 'NITI' का पूर्ण रूप 'नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' (National Institution for Transforming India) है। यह भारत सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है जिसका ध्येय सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। यह संस्था केंद्र और राज्यों दोनों को तकनीकी और नीतिगत सलाह प्रदान करने का कार्य करती है।

120. (D) I, II, III और IV
नीति आयोग से संबंधित चारों कथन पूरी तरह सही हैं। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है जहाँ केंद्र और राज्य समान भागीदार हैं। पूर्ववर्ती योजना आयोग के विपरीत, नीति आयोग के पास राज्यों को वित्तीय कोष आवंटित करने की शक्ति नहीं है (यह कार्य वित्त मंत्रालय करता है)। इसकी शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हैं। यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में नीतियां तैयार करता है।

121. (C) स्वास्थ्य, शिक्षा और सुशासन जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शन सूचकांक व रैंकिंग जारी करके
नीति आयोग देश में 'प्रतिस्पर्धी संघवाद' को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव ढांचा प्रस्तुत करता है। यह संस्था स्वास्थ्य (हेल्थ इंडेक्स), स्कूली शिक्षा (एसक्यूईआई), सुशासन (गुड गवर्नेंस इंडेक्स) और नवाचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करके सार्वजनिक रैंकिंग और सूचकांक जारी करती है। इन सूचकांकों के माध्यम से राज्यों के बीच बेहतर सेवाएं प्रदान करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की एक स्वस्थ और पारदर्शी होड़ उत्पन्न होती है।

122. (A) गवर्निंग काउंसिल (शासी परिषद)
नीति आयोग की शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) एक शीर्ष संस्थागत ढांचा है जो देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों एवं उपराज्यपालों तथा केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को शामिल करता है। इसकी बैठकों की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। यह शासी परिषद राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, विकास रणनीतियों और नीति निर्माण पर सीधे अपने विचार रखने, चर्चा करने और अंतर-सरकारी सहयोग स्थापित करने का एक सशक्त मंच प्रदान करती है।

123. (D) 42वां संशोधन अधिनियम
वर्ष 1976 में पारित 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 'शिक्षा' विषय को राज्य सूची से हटाकर सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानकों, एकरूपता और गुणवत्ता को बढ़ावा देना था। समवर्ती सूची में शामिल होने के कारण अब संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, किंतु टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून प्रभावी रहता है।

124. (B) यह एक मार्गदर्शक ढांचा है जिसे अपनाना राज्यों के स्वविवेक पर निर्भर करता है
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी केंद्रीय नीतियां प्रकृति में कोई बाध्यकारी कानून या अनिवार्य विधिक विधान नहीं होती हैं, बल्कि वे एक व्यापक मार्गदर्शक ढांचा और दृष्टिकोण पत्र प्रस्तुत करती हैं। चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्यों के पास अपनी स्थानीय भाषाई, सांस्कृतिक और भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुसार इस नीति के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने, संशोधित करने या अपनाने का पूर्ण स्वविवेक और संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहता है।

125. (A) P-2, Q-1, R-4, S-3
भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद संघवाद और अंतर-सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 131 के तहत भारत सरकार और राज्यों के बीच विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 262 में अंतर-राज्यीय नदियों के जल विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान है। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना करने का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 279A के तहत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद का गठन किया गया है।

126. (D) इसका केवल राजनीतिक एवं प्रतीकात्मक महत्व होता है, कोई बाध्यकारी कानूनी प्रभाव नहीं होता
यदि कोई राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के विषय पर विधिवत बने केंद्रीय कानून के विरोध में कोई संकल्प या प्रस्ताव पारित करता है, तो उसका कोई बाध्यकारी कानूनी या संवैधानिक प्रभाव नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत केंद्रीय कानून ही सर्वोपरि रहता है। राज्य द्वारा पारित ऐसा प्रस्ताव केवल राज्य सरकार की असहमति व्यक्त करने का एक राजनीतिक और प्रतीकात्मक माध्यम होता है, जो केंद्र पर नैतिक दबाव बनाने हेतु उपयोग किया जाता है।

127. (A) राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों का मिलकर कार्य करना
सहकारी संघवाद (कोऑपरेटिव फेडरलिज्म) की अवधारणा का मूल अर्थ यह है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक-दूसरे की विरोधी न बनकर राष्ट्रीय विकास, सामाजिक-आर्थिक कल्याण और जनहित के साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करें। यह व्यवस्था आपसी सहयोग, परामर्श, विचार-

NODIA

विमर्श और समन्वय पर बल देती है। इसमें केंद्र और राज्य अपनी संवैधानिक सीमाओं में रहते हुए एक सहयोगात्मक साझेदारी के रूप में देश के समग्र विकास हेतु नीतियों का निष्पादन करते हैं।

128. (B) 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग के माध्यम से निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों के बीच होड़
प्रतिस्पर्धी संघवाद (कंपेटिटिव फेडरलिज्म) का तात्पर्य राज्यों के बीच व्यापार, निवेश, अवसंरचना और सुशासन के क्षेत्रों में एक स्वस्थ और रचनात्मक प्रतिस्पर्धा स्थापित होने से है। भारत में 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग, नीति आयोग के प्रदर्शन सूचकांक तथा स्वच्छता सर्वेक्षण जैसी पहलें इसका प्रमुख उदाहरण हैं। इस व्यवस्था में राज्य अपने प्रशासनिक सुधारों, बेहतर नीतियों और व्यापारिक सुगमता के आधार पर निजी निवेश और संसाधनों को आकर्षित करने के लिए एक-दूसरे से होड़ करते हैं।

129. (B) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) - केंद्र-राज्य समन्वय निकाय
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) केंद्र-राज्य समन्वय निकाय नहीं है, बल्कि यह केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली एक प्रमुख केंद्रीय जांच एजेंसी है। इसका मुख्य कार्य भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और गंभीर अंतर-राज्यीय अपराधों की जांच करना है। इसके विपरीत, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर-राज्यीय परिषद तथा नीति आयोग की शासी परिषद वास्तविक संवैधानिक और अंतर-सरकारी निकाय हैं जो केंद्र और राज्यों के मध्य नीतिगत सामंजस्य स्थापित करते हैं।

130. (A) सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धी तंत्रों के साथ-साथ राजनीतिक सौदेबाजी वाला संघवाद
वर्तमान में भारतीय संघवाद एक बहुआयामी और गतिशील रूप प्रस्तुत करता है। यह एक ओर जीएसटी परिषद और नीति आयोग के माध्यम से 'सहकारी संघवाद' को प्रोत्साहित करता है, तो दूसरी ओर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के ज़रिए 'प्रतिस्पर्धी संघवाद' को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही, विविध क्षेत्रीय आकांक्षाओं, वित्तीय आवंटन और राजनीतिक मतभेदों के कारण केंद्र और राज्यों के बीच निरंतर राजनीतिक सौदेबाजी और बातचीत चलती रहती है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था का सबसे सटीक विवरण प्रस्तुत करती है।

Downloaded from www.pdf.tube

अध्याय 04

प्रस्तावना एवं मौलिक कर्तव्य

1. निम्नलिखित में से किस संवैधानिक दस्तावेज को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्राथमिक स्रोत माना जाता है?
(A) ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित भारत सरकार अधिनियम, 1935
(B) 1946 में जवाहरलाल नेहरु द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव
(C) ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
(D) संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा

2. प्रस्तावना में "हम, भारत के लोग" वाक्यांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संवैधानिक सिद्धांत को दर्शाता है?
(A) संसदीय संप्रभुता
(B) संघवाद
(C) शक्तियों का पृथक्करण
(D) लोकप्रिय संप्रभुता

3. निम्नलिखित आदर्शों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हैं:
1. समता
2. स्वतंत्रता
3. बंधुता
4. न्याय
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम का चयन कीजिए:
(A) 4, 2, 1, 3
(B) 4, 1, 2, 3
(C) 2, 4, 1, 3
(D) 1, 2, 4, 3

4. बेरुबाड़ी यूनियन मामले (1960) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है।
II. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान के विभिन्न प्रावधानों के पीछे के सामान्य उद्देश्यों को दर्शाती है।
III. उच्चतम न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि प्रस्तावना किसी मौलिक शक्ति का स्रोत नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

5. प्रस्तावना में "समाजवादी" शब्द के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: "समाजवादी" शब्द 1949 में अपनाई गई मूल प्रस्तावना में मौजूद था।
कथन II: भारतीय समाजवाद साम्यवादी समाजवाद की तुलना में लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर अधिक झुका हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

6. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रकृति में पूरी तरह से गैर-न्यायसंगत है।
कारण (R): प्रस्तावना के प्रावधानों को न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है।
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

7. भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा विशेष रूप से गारंटीकृत स्वतंत्रता के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा असंगत है?
(A) विचार और मत की स्वतंत्रता
(B) आर्थिक उद्यम की स्वतंत्रता
(C) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
(D) विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता

8. किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में "समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष" और "अखंडता" शब्द जोड़े गए थे?
(A) 24वां संशोधन अधिनियम, 1971
(B) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
(C) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
(D) 86वां संशोधन अधिनियम, 2002

NODIA

9. निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है?
(A) संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों तथा संस्थाओं का आदर करना
(B) देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना
(C) हमारी सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका परिरक्षण करना
(D) ईमानदारी और नियमित रूप से करों का भुगतान करना

10. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: संवैधानिक शब्दावली
P. संप्रभु
Q. गणराज्य
R. पंथनिरपेक्ष
S. लोकतांत्रिक
सूची II: अर्थ
1. राज्य का प्रमुख हमेशा एक निर्वाचित व्यक्ति होता है
2. भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर है और न ही किसी अन्य राष्ट्र का डोमिनियन है
3. सर्वोच्च शक्ति अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता में निहित होती है
4. राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है
(A) P-2, Q-1, R-4, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

11. प्रस्तावना के पाठ में निर्दिष्ट संविधान को अंगीकृत करने की सही तिथि क्या है?
(A) 15 अगस्त 1947
(B) 26 नवंबर 1949
(C) 26 जनवरी 1950
(D) 24 जनवरी 1950

12. प्रस्तावना के संदर्भ में, "गणराज्य" शब्द यह दर्शाता है कि:
(A) राज्य अपने सभी नागरिकों के बीच समान धन वितरण की गारंटी देता है
(B) राज्य का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है
(C) सभी नागरिकों को किसी भी धार्मिक आचरण का पालन करने का पूर्ण अधिकार है
(D) राजनीतिक संप्रभुता पूरी तरह से एक एकल वंशानुगत सम्राट में निहित है

13. स्वर्ण सिंह समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसका गठन 1976 में आंतरिक आपातकाल के दौरान किया गया था।
II. इसने मूल कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय को शामिल करने की सिफारिश की थी।
III. इसने सुझाव दिया कि मूल कर्तव्यों का पालन न करने के लिए नागरिकों को दंडित किया जाना चाहिए।
IV. सरकार ने बिना किसी संशोधन के इसकी सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I, II और III
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

14. 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अनुच्छेद 51A में कौन-सा नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया था?
(A) वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना
(B) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा के सभी रूपों का त्याग करना
(C) 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना
(D) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना

15. केशवानंद भारती मामले (1973) के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: उच्चतम न्यायालय ने बेरुबाड़ी यूनियन मामले में लिए गए अपने पहले के रुख को उलट दिया और घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है।
कथन II: उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि मूल ढाँचे में कोई संशोधन न किया जाए।
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

16. निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना में भारतीय राज्य का वर्णन करने के लिए उपयोग किए गए विशेषणों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है?
(A) संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, गणराज्य
(B) संप्रभु, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य
(C) संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य
(D) संप्रभु, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य

17. निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना में उल्लेखित "बंधुता" का सबसे उपयुक्त अर्थ प्रदान करता है?
(A) एक शासन प्रणाली जहाँ राज्य के सभी आर्थिक संसाधन समान रूप से वितरीत होते हैं
(B) व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली भ्रातृत्व की भावना
(C) किसी भी कानूनी प्रतिबंध के बिना कार्य करने की एक

Click Here to Buy book on Amazon

नागरिक की पूर्ण स्वतंत्रता
(D) सभी राज्य सरकारों पर केंद्र सरकार की संवैधानिक सर्वोच्चता

18. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): कुछ मूल अधिकारों के विपरीत, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित हैं और विदेशियों तक विस्तारित नहीं हैं।
कारण (R): मूल कर्तव्यों को नागरिकों को राज्य के प्रति उनके पारस्परिक दायित्वों की निरंतर याद दिलाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था।
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

19. निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की आलोचना के रुप में उद्धृत नहीं किया जाता है?
(A) उनकी गैर-न्यायसंगत प्रकृति के कारण उन्हें नैतिक उपदेशों की एक मात्र संहिता बताया गया है।
(B) कुछ कर्तव्य 'महान आदर्श' और 'सामासिक संस्कृति' जैसे अस्पष्ट और संदिग्ध शब्दों का उपयोग करते हैं।
(C) भाग III के बाद के बजाय भाग IV के एक परिशिष्ट के रूप में उनका समावेश उनके कथित महत्व को कम करता है।
(D) वे न्यायिक समीक्षा में कर्तव्यों को प्राथमिकता देकर मूल अधिकारों के प्रवर्तन को गंभीर रुप से सीमित करते हैं।

20. भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित थी?
(A) पूर्व सोवियत संघ
(B) संयुक्त राज्य अमेरिका
(C) यूनाइटेड किंगडम
(D) आयरलैंड

21. मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों के बीच संबंध के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) अस्पष्ट कानूनों की व्याख्या करते समय न्यायालय मूल कर्तव्यों पर विचार कर सकते हैं।
(B) मूल अधिकारों के विपरीत, मूल कर्तव्यों को न्यायालयों द्वारा रिटों के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है।
(C) जबकि मूल अधिकार राज्य की शक्ति पर अंकुश हैं, मूल कर्तव्य नागरिकों पर दायित्व हैं।
(D) मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों 1949 में अधिनियमित मूल संविधान का हिस्सा थे।

22. अनुच्छेद 51A के तहत विशिष्ट मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. झीलों, नदियों और वन्यजीवों की रक्षा और सुधार करना एक कर्तव्य है।
II. राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना एक कर्तव्य है।
III. स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में मतदान करना एक कर्तव्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

23. प्रस्तावना द्वारा गारंटीकृत 'न्याय' के आयामों का वर्गीकरण करते समय निम्नलिखित में से कौन-सा असंगत है?
(A) सामाजिक न्याय
(B) आर्थिक न्याय
(C) राजनीतिक न्याय
(D) कानूनी न्याय

NODIA

24. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: उच्चतम न्यायालय के मामले
P. बेरुबाड़ी यूनियन मामला (1960)
Q. केशवानंद भारती मामला (1973)
R. एलआईसी ऑफ इंडिया मामला (1995)
S. एस. आर. बोम्मई मामला (1994)
सूची II: प्रस्तावना के संदर्भ में महत्व
1. पुनः पुष्टि की गई कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है
2. यह माना गया कि पंथनिरपेक्षता संविधान की एक मूल विशेषता है
3. यह माना गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है
4. प्रस्तावना को मूल ढाँचे में परिवर्तन किए बिना संशोधन के अधीन संविधान का भाग घोषित किया गया
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-4, R-2, S-1
(D) P-1, Q-2, R-3, S-4

25. प्रस्तावना सभी नागरिकों को "प्रतिष्ठा और अवसर की समता" सुरक्षित करती है। संवैधानिक ढाँचे में इसका मुख्य अर्थ है:
(A) किसी भी वर्ग के लिए विशेष विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और पर्याप्त अवसरों का प्रावधान
(B) समाज में सभी नागरिकों के लिए समान बैंक बैलेंस और वित्तीय संपत्ति वितरण सुनिश्चित करना
(C) सभी नागरिकों के बीच संज्ञानात्मक और शारीरिक क्षमताओं में सभी प्राकृतिक अंतरों को समाप्त करना
(D) बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियां और प्रशासनिक रोजगार प्रदान करना

26. मूल कर्तव्यों के कानूनी प्रवर्तन के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: संसद किसी भी मूल कर्तव्य को सख्ती से लागू करने के लिए कानून नहीं बना सकती है।
कथन II: वर्मा समिति (1999) ने कई पूर्व-मौजूद कानूनी प्रावधानों की पहचान की जो कुछ मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन में मदद करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

27. मूल कर्तव्यों के न्यायिक दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. एम्स स्टूडेंट्स यूनियन मामले (2001) में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मूल कर्तव्य उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि मूल अधिकार।
II. न्यायालय किसी कानून की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने के लिए मूल कर्तव्यों का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
III. अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार करने के लिए मूल कर्तव्यों का उपयोग एक व्याख्यात्मक उपकरण के रूप में किया जा सकता है।
IV. उच्चतम न्यायालय ने यह अनिवार्य किया है कि मूल कर्तव्य का पालन करने में विफल रहने पर नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और III
(B) केवल I, II और IV
(C) केवल II और III
(D) केवल I, III और IV

28. अनुच्छेद 51A के अनुसार, कौन-सा मूल कर्तव्य विशेष रूप से स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने पर जोर देता है?
(A) समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देने का कर्तव्य
(B) स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को संजोने और उनका पालन करने का कर्तव्य
(C) वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का कर्तव्य
(D) हमारी सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने का कर्तव्य

29. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): भारतीय संविधान पंथनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को समाहित करता है।
कारण (R): राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देता है और सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करता है।
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

30. 42वें संशोधन के दौरान सरकार द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की निम्नलिखित में से कौन-सी सिफारिश स्वीकार नहीं की गई थी?
(A) भारतीय संविधान के भीतर एक बिल्कुल नए भाग IVA को अनिवार्य रूप से शामिल करना
(B) सभी भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों की एक विस्तृत सूची का विवरण
(C) युद्ध के दौरान देश की रक्षा करने के मूल कर्तव्य का अनिवार्य समावेश
(D) कर्तव्यों का पालन न करने के लिए जुर्माना या दंड लगाना

31. प्रस्तावना को अक्सर संवैधानिक व्याख्या का एक आवश्यक उपकरण माना जाता है क्योंकि:
(A) यह कार्यपालिका को प्रत्यक्ष, कानूनी रूप से प्रवर्तनीय विधायी और प्रशासनिक शक्ति प्रदान करता है।
(B) यह किसी भी प्रत्यक्ष संवैधानिक टकराव के मामले में भारतीय संविधान के भाग III को पूरी तरह से निरस्त कर देता है।
(C) यह संवैधानिक अस्पष्टताओं की व्याख्या का मार्गदर्शन करने वाले उदात्त दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करता है।
(D) यह राष्ट्रीय संसद के लिए पूरक विधायी शक्ति के एक स्वतंत्र स्रोत के रूप में कार्य करता है।

32. प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित ऐतिहासिक उच्चतम न्यायालय के मामलों को उनके सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. एलआईसी ऑफ इंडिया मामला
2. बेरुबाड़ी यूनियन मामला
3. केशवानंद भारती मामला
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम का चयन कीजिए:
(A) 2, 3, 1
(B) 1, 2, 3
(C) 3, 2, 1
(D) 2, 1, 3

33. "लोकप्रिय संप्रभुता" का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है?
(A) सभी स्थानीय नगर निकायों पर राज्य विधानमंडलों की अनन्य विधायी शक्ति
(B) घरेलू राष्ट्रीय कानूनों पर अंतरराष्ट्रीय संधियों की पूर्ण संवैधानिक सर्वोच्चता
(C) सभी अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यक समुदाय का अनियंत्रित सामाजिक-राजनीतिक प्रभुत्व

Downloaded from www.pdf.tube

(D) अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करने की जनता की अंतिम सत्ता

34. 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसने अब तक पहली और एकमात्र बार प्रस्तावना में संशोधन किया।
II. इसने प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और बंधुता।
III. इसने मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 51A अंतःस्थापित किया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

35. अनुच्छेद 51A से मूल कर्तव्य और इसकी अंतर्निहित अवधारणा के सही युग्म की पहचान कीजिए:
(A) अनुच्छेद 51A(h) – वनों सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार
(B) अनुच्छेद 51A(f) – वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना का विकास
(C) अनुच्छेद 51A(i) – बच्चों को शिक्षा के अनिवार्य अवसर प्रदान करना
(D) अनुच्छेद 51A(b) – स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को संजोना

36. प्रस्तावना की संशोधनयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
कथन II: केशवानंद भारती मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि मूल ढाँचा परिवर्तित न हो।
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

37. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: अनुच्छेद 51A के खंड
P. अनुच्छेद 51A(a)
Q. अनुच्छेद 51A(c)
R. अनुच्छेद 51A(e)
S. अनुच्छेद 51A(g)
सूची II: मूल कर्तव्य की विषय-वस्तु
1. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे
2. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे
3. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे
4. समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा दे
(A) P-2, Q-1, R-4, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

38. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के मूल कर्तव्य [अनुच्छेद 51A(g)] के तहत, निम्नलिखित में से किसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है?
(A) प्राकृतिक वन
(B) अंतर्देशीय झीलें
(C) प्राकृतिक नदियां
(D) समुद्र तल

NODIA

39. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): मूल कर्तव्य प्रकृति में गैर-न्यायसंगत हैं।
कारण (R): संविधान रिटों के माध्यम से न्यायालयों द्वारा उनके प्रत्यक्ष प्रवर्तन का प्रावधान नहीं करता है।
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

40. किस प्रख्यात संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रसिद्ध रूप से प्रस्तावना को "संविधान का परिचय पत्र" कहा था?
(A) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
(B) एन.ए. पालकीवाला
(C) के.एम. मुंशी
(D) सर अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर

41. निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता के रूपों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है?
(A) विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना
(B) विश्वास, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना
(C) अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, विश्वास, उपासना
(D) विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म

42. प्रस्तावना में "लोकतांत्रिक गणराज्य" शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह दर्शाता है कि जनता राजनीतिक शक्ति का सर्वोच्च स्रोत है।
II. यह इंगित करता है कि राज्य का प्रमुख एक वंशानुगत सम्राट है।
III. यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा चुनी गई सरकार की उपस्थिति का प्रतीक है।

IV. यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए खुले हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

43. प्रस्तावना में "समता" के आदर्श के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।

(A) यह प्रतिष्ठा की व्यापक समता के साथ-साथ अवसर की समता का वादा करता है।
(B) यह तीन अलग-अलग सामाजिक आयामों को पूरी तरह से शामिल करता है: नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक।
(C) इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए पूर्ण धन समानता स्थापित करना है।
(D) यह समाज के किसी भी वर्ग को दिए गए सभी विशेष विशेषाधिकारों को समाप्त करना चाहता है।

44. मूल कर्तव्यों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों की तुलना करते समय निम्नलिखित में से कौन-सा असंगत है?

(A) दोनों प्रशासनिक नीतियां बनाने में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं।
(B) दोनों आम तौर पर गैर-न्यायसंगत हैं।
(C) मूल कर्तव्य नागरिकों की ओर निर्देशित हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व राज्य की ओर निर्देशित हैं।
(D) दोनों का उपयोग न्यायालयों द्वारा कानूनों की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने के लिए किया गया है।

45. 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: इसने प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिए अनुच्छेद 21A अंतःस्थापित किया।

कथन II: इसने अनुच्छेद 51A के तहत 11वां मूल कर्तव्य पेश किया, जिसके तहत माता-पिता या अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना आवश्यक है।

निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

46. मूल कर्तव्यों पर सिफारिशें देने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस वर्ष किया गया था?

(A) 1974
(B) 1975
(C) 1976
(D) 1978

47. प्रस्तावना में 'बंधुता' के आदर्श के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. इसका उद्देश्य सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और जातिवाद जैसी बाधाओं को दूर करना है।
II. इसे संविधान में एकल नागरिकता की प्रणाली द्वारा बढ़ावा दिया जाता है।
III. इसके लिए राज्य को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बीच आर्थिक समानता की गारंटी देना आवश्यक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

48. भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का सबसे उपयुक्त प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

(A) संदिग्ध नागरिकों की निवारक हिरासत के लिए अतिरिक्त कानूनी आधार प्रदान करना
(B) नागरिकों को समाज और राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों की याद दिलाना
(C) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की वैधानिक कार्यपालक शक्तियों का विस्तार करना
(D) राज्य के नीति निदेशक तत्वों के पूर्ण विकल्प के रूप में कार्य करना

49. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची I: टिप्पणीकार

P. के.एम. मुंशी
Q. अर्नेस्ट बार्कर
R. ठाकुरदास भार्गव
S. एम. हिदायतुल्ला

सूची II: प्रस्तावना का विवरण

1. संविधान की आत्मा
2. हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्मकुंडली
3. संविधान का की-नोट (मुख्य स्वर)
4. अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान

(A) P-2, Q-3, R-1, S-4
(B) P-1, Q-2, R-4, S-3
(C) P-3, Q-1, R-2, S-4
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

50. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रस्तावना और संविधान द्वारा परिकल्पित भारतीय पंथनिरपेक्षता का लक्षण नहीं है?

(A) राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान सम्मान, सुरक्षा और मान्यता दी जाती है
(B) व्यक्तियों को किसी भी धार्मिक विश्वास को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है
(C) सभी धार्मिक मामलों की उपेक्षा करते हुए, धर्म और राज्य का पूर्ण पृथक्करण
(D) राज्य निधि से पूरी तरह पोषित स्कूलों में धार्मिक शिक्षा का पूर्ण निषेध

Click Here to Buy book on Flipkart

51. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:

अभिकथन (A): राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस) में भारत की सदस्यता उसकी संप्रभु स्थिति से समझौता नहीं करती है।

कारण (R): प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु राज्य घोषित करती है, और राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारतीय संप्रभुता पर बिना किसी कानूनी बाध्यकारी बल के एक स्वैच्छिक जुड़ाव है।

नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

52. अनुच्छेद 51A(h) के अनुसार, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह विकसित करे:

(A) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना
(B) बिना किसी आलोचना के गहरी धार्मिक भक्ति और पारंपरिक आध्यात्मिकता की भावना
(C) प्राचीन धार्मिक परंपराओं और रुढ़िवादी रीति-रिवाजों के प्रति पूर्ण आदर
(D) सत्ता में जो भी राजनीतिक दल हो, उसके प्रति पूर्ण राजनीतिक निष्ठा

53. एलआईसी ऑफ इंडिया मामले (1995) के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है।

कथन II: उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान के विशिष्ट प्रावधानों पर अंतिम सर्वोच्चता रखती है।

निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

54. मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. मूल अधिकार मुख्य रूप से राज्य पर नकारात्मक दायित्व हैं, जबकि कर्तव्य नागरिकों पर सकारात्मक दायित्व हैं।
II. मूल अधिकार न्यायसंगत हैं, जबकि मूल कर्तव्य गैर-न्यायसंगत हैं।
III. मूल अधिकार विदेशियों सहित सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं, जबकि सभी मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं।
IV. अधिकार और कर्तव्य दोनों 1949 में अपनाए गए मूल संविधान का हिस्सा थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल I और II
(B) केवल I, II और III
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

55. भारतीय संविधान की प्रस्तावना मौलिक रूप से "उद्देश्य प्रस्ताव" पर आधारित है। संविधान सभा में यह प्रस्ताव किसने पेश किया था?

(A) जवाहरलाल नेहरु
(B) सरदार वल्लभभाई पटेल
(C) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
(D) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

56. निम्नलिखित में से किस मूल कर्तव्य में "राष्ट्रीय ध्वज" का आदर करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है?

(A) संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों तथा संस्थाओं का आदर करना
(B) देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना
(C) अनुच्छेद 51A(a) के तहत कर्तव्य
(D) (B) और अनुच्छेद 51A(g) के तहत कर्तव्य दोनों

57. निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द असंगत है क्योंकि यह 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई मूल प्रस्तावना में मौजूद था?

(A) समाजवादी
(B) पंथनिरपेक्ष
(C) लोकतांत्रिक
(D) अखंडता

58. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची I: संवैधानिक विशेषताएं

P. मूल अधिकार
Q. राज्य के नीति निदेशक तत्व
R. मूल कर्तव्य
S. प्रस्तावना

सूची II: संविधान में संबंधित भाग

1. भाग IV
2. भाग III
3. भाग IVA
4. किसी विशिष्ट भाग संख्या का आवंटन नहीं किया गया है

(A) P-2, Q-1, R-3, S-4
(B) P-1, Q-2, R-4, S-3
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-3, R-1, S-4

59. प्रस्तावना में "आर्थिक न्याय" शब्द निम्नलिखित में से किस विचार का सबसे उपयुक्त प्रतिनिधित्व करता है?

(A) समाज में सभी पेशेवर व्यवसायों के लिए पूरी तरह से समान निश्चित वेतन की गारंटी देना
(B) आर्थिक कारकों के आधार पर गैर-भेदभाव और धन की असमानताओं को समाप्त करना
(C) सभी निजी औद्योगिक उद्यमों और संपत्तियों का राज्य

Downloaded from www.pdf.tube

द्वारा पूर्ण राष्ट्रीयकरण
(D) देश भर में सभी नागरिकों को अनिश्चित काल के लिए मुफ्त आवश्यक उपभोग वस्तुएं प्रदान करना

60. 1991 के बाद के भारत के संदर्भ में 'समाजवादी' शब्द के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत ने राज्य समाजवाद के मूल सख्त अनुप्रयोग को कमजोर कर दिया है।
II. आर्थिक सुधारों के बावजूद, कल्याणकारी राज्य और वितरणात्मक न्याय का संवैधानिक लक्ष्य बरकरार है।
III. उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भारतीय समाजवाद का मुख्य उद्देश्य गरीबी, अज्ञानता और अवसर की असमानता को समाप्त करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

61. मूल कर्तव्यों के कानूनी प्रवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम (1971) राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करने पर दंडित करता है, जो अनुच्छेद 51A(a) को लागू करता है।
II. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (1972) अनुच्छेद 51A(g) के तहत प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने के कर्तव्य के प्रवर्तन का समर्थन करता है।
III. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के कर्तव्य के प्रत्यक्ष प्रवर्तन को सक्षम बनाता है।
IV. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (1955) अस्पृश्यता को दंडित करके भ्रातृत्व को बढ़ावा देने के कर्तव्य को बल प्रदान करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, II और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

62. 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा मूल रूप से संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे?
(A) 8
(B) 10
(C) 11
(D) 12

63. प्रस्तावना में निहित "राजनीतिक न्याय" का मौलिक अर्थ है:
(A) समान राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक पद तक समान पहुंच और सरकार में समान आवाज
(B) प्रत्येक नागरिक का राजनीतिक दल बनाने और राज्य से वित्तपोषण प्राप्त करने का मूल अधिकार
(C) राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक विपक्षी दलों का राज्य द्वारा पूर्ण उन्मूलन
(D) सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए संसद में सीटों का अनिवार्य संवैधानिक आरक्षण

NODIA

64. बेरुबाड़ी यूनियन मामले और केशवानंद भारती मामले की तुलना करते समय गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) दोनों मामलों का फैसला भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया था।
(B) बेरुबाड़ी मामले ने प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इंकार कर दिया, जबकि केशवानंद मामले ने इसे स्वीकार किया।
(C) दोनों मामलों ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रस्तावना विधायिका को मौलिक शक्तियां प्रदान करती है।
(D) केशवानंद मामले ने संविधान के मूल ढांचे की व्याख्या करने में प्रस्तावना के महत्व पर जोर दिया।

65. नागरिकता और मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: संविधान मूल अधिकारों के उपभोग को स्पष्ट रूप से मूल कर्तव्यों के निष्पादन के अधीन बनाता है।
कथन II: किसी नागरिक से केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में विफल रहने के कारण उसकी भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है।
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

66. क्या प्रस्तावना कानून बनाने की संसद की शक्तियों को सीमित करती है?
(A) हां, प्रस्तावना सभी विधायी शक्तियों पर एक प्रत्यक्ष संवैधानिक सीमा के रूप में कार्य करती है।
(B) नहीं, यह न तो विधायी शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका पर कोई प्रतिबंध है।
(C) हां, यह केवल मूल अधिकारों से संबंधित राष्ट्रीय कानूनों के संबंध में एक प्रतिबंध के रूप में कार्य करती है।
(D) हां, संसद उन मामलों पर कानून नहीं बना सकती जिनका स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है।

67. निम्नलिखित में से किसका प्रस्तावना के पाठ में एक मुख्य आदर्श या आकांक्षा के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है?
(A) निजता
(B) न्याय
(C) स्वतंत्रता
(D) समता

68. मूल कर्तव्यों के दायरे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा असंगत है?
(A) राज्य द्वारा अधिग्रहित संपत्ति के लिए पर्याप्त मुआवजा देना
(B) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना
(C) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना
(D) समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना

69. अनुच्छेद 51A(k) के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) यह राज्य सरकार को सभी नागरिकों को मुफ्त विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा प्रदान करने का जनादेश देता है।
(B) इसके तहत माता-पिता या अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना आवश्यक है।
(C) इसे 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अंतःस्थापित किया गया था।
(D) यह प्रत्येक गांव में स्कूल बनाने का एकमात्र प्रशासनिक बोझ केंद्र सरकार पर डालता है।

70. शेष संविधान के संबंध में संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब अधिनियमित किया गया था?
(A) सर्वोपरि मार्गदर्शक ढांचा स्थापित करने के लिए शेष संविधान से पहले अधिनियमित किया गया
(B) मूल अधिकारों के अध्याय के प्रारूपण के साथ-साथ एक साथ अधिनियमित किया गया
(C) अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए शेष संविधान के अधिनियमित होने के बाद
(D) 1946 में संविधान सभा के सबसे पहले उद्घाटन सत्र के दौरान अधिनियमित किया गया

71. प्रस्तावना में "व्यक्ति की गरिमा" वाक्यांश अनुच्छेद 51A के तहत किस मूल कर्तव्य से निकटता से जुड़ा हुआ है?
(A) स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना
(B) वनों और नदियों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना
(C) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा के सभी रूपों का पूरी तरह से त्याग करना
(D) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना

72. कौन-सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जाता है, जो प्रस्तावना की 'लोकतांत्रिक' प्रकृति को दर्शाता है?
(A) प्रसाद का सिद्धांत
(B) विधि का शासन
(C) शक्तियों का पृथक्करण
(D) सर्वोपरि अधिकार

73. भारतीय संविधान में 'पंथनिरपेक्ष' शब्द के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: 42वें संशोधन से पहले, भारतीय संविधान में कोई पंथनिरपेक्ष विशेषताएं मौजूद नहीं थीं।
कथन II: अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता के मूल अधिकार की गारंटी देते हैं, जो प्रस्तावना में शब्द जोड़े जाने से बहुत पहले राज्य की पंथनिरपेक्ष प्रकृति को दर्शाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

74. निम्नलिखित में से प्रस्तावना में पाई जाने वाली "स्वतंत्रता" की सबसे उपयुक्त व्याख्या कौन-सी है?
(A) किसी भी व्यक्ति के लिए बिना किसी कानूनी प्रतिबंध के जो भी वह चाहता है उसे करने की पूर्ण अबाध स्वतंत्रता
(B) अनुचित प्रतिबंधों की अनुपस्थिति और व्यक्तिगत विकास के लिए अवसरों का प्रावधान
(C) व्यक्तिगत धार्मिक मामलों में स्वेच्छा से हस्तक्षेप करने का सरकार का पूर्ण कानूनी अधिकार
(D) राज्य के कराधान के बिना असीमित धन संचय करने का निजी नागरिकों का पूर्ण कानूनी अधिकार

75. एक्सेल वेयर बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार, प्रस्तावना में "समाजवादी" शब्द का जोड़:
(A) सामाजिक-आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालयों को उद्योग के राज्य स्वामित्व का पक्ष लेने की अनुमति देता है
(B) राज्य सरकार को बिना किसी शर्त के सभी निजी औद्योगिक उद्यमों का राष्ट्रीयकरण करने में सक्षम बनाता है
(C) पूरे भारत में निजी संपत्ति के स्वामित्व के सभी रूपों को पूरी तरह से गैर-कानूनी और आपराधिक बनाता है
(D) संवैधानिक न्यायनिर्णयन में कोई कानूनी, न्यायिक या व्याख्यात्मक मूल्य नहीं रखता है

76. मूल कर्तव्यों की प्रकृति के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) वे राष्ट्रविरोधी और समाजविरोधी गतिविधियों के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं।
(B) वे नागरिकों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।
(C) वे स्वतः ही ऐसे किसी भी कानून को अमान्य कर देते हैं जो उनके अनुरूप नहीं है।
(D) उनका उपयोग न्यायालयों द्वारा किसी कानून की संवैधानिक वैधता का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है।

Click Here to Buy book on Amazon

77. निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द असंगत है क्योंकि यह प्रस्तावना के संकल्पों की "हम भारत के लोग" घोषणा का हिस्सा नहीं है?
(A) शासन
(B) न्याय
(C) स्वतंत्रता
(D) बंधुता

78. प्रस्तावना के संदर्भ में, भारत के आंतरिक मामलों के संबंध में "संप्रभु" स्पष्ट रूप से क्या दर्शाता है?
(A) भारत बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपने आंतरिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है।
(B) केंद्र सरकार का संवैधानिक सीमाओं के बिना राज्य सरकारों पर पूर्ण नियंत्रण है।
(C) भारत को अपनी घरेलू नीतियों में संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
(D) संसद न्यायिक समीक्षा के बिना मूल अधिकारों में बदलाव कर सकती है।

79. राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के बारे में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: अनुच्छेद 51A(a) के तहत उनका आदर करना एक मूल कर्तव्य है।
कथन II: उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि किसी व्यक्ति को उसके धार्मिक विश्वासों के विरुद्ध राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य करना उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है।
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

80. प्रस्तावना में "बंधुता" के आदर्श के लिए दो बातों के आश्वासन की आवश्यकता होती है। एक है "व्यक्ति की गरिमा"। दूसरी क्या है?
(A) व्यक्तिगत आय की पूर्ण सामाजिक-आर्थिक समानता
(B) राष्ट्र की एकता और अखंडता
(C) पूरे देश में अत्यधिक गरीबी का पूर्ण उन्मूलन
(D) भारतीय संविधान की पूर्ण कानूनी सर्वोच्चता

81. संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतःस्थापित करने का आधार किस समिति की सिफारिशें थीं?
(A) स्वर्ण सिंह समिति
(B) कोठारी आयोग
(C) सरकारिया आयोग
(D) संथानम समिति

82. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सबसे अच्छा औचित्य प्रदान करता है कि मूल कर्तव्यों को न्यायालयों द्वारा सीधे प्रवर्तनीय क्यों नहीं बनाया गया है?
(A) मूल संविधान निर्माता भाग IVA में एक स्पष्ट प्रवर्तन खंड जोड़ना भूल गए थे।
(B) महान आदर्शों को संजोने जैसे कर्तव्य अमूर्त अवधारणाएं हैं जिन्हें कानूनी रूप से लागू करना कठिन है।
(C) कर्तव्यों को सख्ती से लागू करना मूल अधिकारों के अध्याय की गारंटियों का पूरी तरह से खंडन करेगा।
(D) उच्चतम न्यायालय ने संसद को कर्तव्यों को कभी भी प्रवर्तनीय बनाने से स्पष्ट रूप से मना किया था।

83. संविधान के अनुच्छेद 51A(f) में उल्लिखित 'सामासिक संस्कृति' शब्द दर्शाता है:
(A) भारत में सदियों से घुली-मिली विविध भाषाई और धार्मिक परंपराएं
(B) बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय की अनन्य सांस्कृतिक प्रथाएं और सामाजिक रीति-रिवाज
(C) प्राचीन भारतीय परंपराओं में पश्चिमी संस्कृति का पूर्ण आत्मसातीकरण और एकीकरण
(D) राज्य सरकार द्वारा सभी भारतीय नागरिकों के लिए अनिवार्य एक समान, एकल राष्ट्रीय संस्कृति

84. मूल कर्तव्यों के संबंध में 42वें संशोधन अधिनियम के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) इसने संविधान में एक नया भाग IV जोड़ा।
(B) इसने दस मूल कर्तव्यों को निर्दिष्ट करते हुए एक एकल अनुच्छेद 51A पेश किया।
(C) इसने मूल कर्तव्यों को गैर-नागरिकों पर भी लागू किया।
(D) इसने न्यायालयों को सभी कर्तव्यों के सख्त प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की अनुमति दी।

NODIA

85. प्रस्तावना के अनुसार, किस प्रकार के न्याय को प्राथमिकता दी गई है?
(A) आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक
(B) सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
(C) राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक
(D) सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक

86. निम्नलिखित में से कौन-सा संविधान की प्रस्तावना में सूचीबद्ध उद्देश्य नहीं है?
(A) सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षित करना
(B) विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना
(C) व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देना
(D) पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देना

87. भारत की गणराज्य स्थिति के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: भारत 26 नवंबर 1949 को एक गणराज्य बना।
कथन II: गणराज्य का दर्जा यह सुनिश्चित करता है कि देश

का सर्वोच्च पद वंशानुगत न हो।
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

88. अनुच्छेद 51A(j) के तहत, नागरिकों का यह मूल कर्तव्य है कि वे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। इस कर्तव्य का घोषित संवैधानिक लक्ष्य क्या है?
(A) ताकि भारतीय नागरिक उच्च वेतन वाली विदेशी नौकरियों के लिए वैश्विक बाजारों में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकें
(B) ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयत्न और उपलब्धि के नए स्तरों की ओर बढ़े
(C) ताकि केंद्र सरकार अमीर व्यक्तियों से अधिक व्यक्तिगत कर एकत्र कर सके
(D) ताकि भारत अपने सभी पड़ोसी क्षेत्रीय देशों पर सैन्य प्रभुत्व स्थापित कर सके

89. कौन-सा मूल कर्तव्य नागरिकों से "हिंसा से दूर रहने" का आह्वान करता है?
(A) अनुच्छेद 51A(e)
(B) अनुच्छेद 51A(f)
(C) अनुच्छेद 51A(i)
(D) अनुच्छेद 51A(h)

90. संवैधानिक मामलों में प्रस्तावना की भूमिका की गलत व्याख्या की पहचान कीजिए।
(A) प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को समझने की कुंजी है।
(B) प्रस्तावना संविधान के मूल ढाँचे का एक हिस्सा है।
(C) प्रस्तावना संसदीय कानून को रद्द करने के लिए एक स्वतंत्र उपकरण के रूप में कार्य कर सकती है।
(D) संवैधानिक पाठ के अस्पष्ट होने पर प्रस्तावना के शब्द न्यायालय का मार्गदर्शन करते हैं।

91. प्रस्तावना में "न्याय" (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) का आदर्श कहाँ से लिया गया है?
(A) रूसी क्रांति
(B) फ्रांसीसी क्रांति
(C) अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा
(D) आयरिश संविधान

92. प्रस्तावना में "स्वतंत्रता, समता और बंधुता" के आदर्श किससे प्रेरित हैं?
(A) फ्रांसीसी क्रांति
(B) रूसी क्रांति
(C) गौरवशाली क्रांति
(D) औद्योगिक क्रांति

93. भारतीय राज्य की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है।
कथन II: भारतीय लोकतंत्र विशुद्ध रूप से एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में कार्य करता है जहाँ नागरिक सभी प्रमुख विधानों पर मतदान करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

94. नागरिकों से "देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने" की अपेक्षा करने वाला मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A के किस विशिष्ट खंड के अंतर्गत आता है?
(A) 51A(b)
(B) 51A(c)
(C) 51A(d)
(D) 51A(e)

95. स्वर्ण सिंह समिति ने मूल रूप से कितने मूल कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था?
(A) 8
(B) 10
(C) 11
(D) 12

96. प्रस्तावना में व्यक्त "सामाजिक न्याय" का सबसे अच्छा विवरण कौन-सा है?
(A) जाति, नस्ल या लिंग के सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार
(B) सभी नागरिकों के बीच सभी निजी भूमि और संपत्तियों का अनिवार्य समान भौतिक विभाजन
(C) निजी स्वामित्व को समाप्त करके एक वर्गविहीन समाजवादी समाज की तत्काल स्थापना
(D) विशेष रूप से आर्थिक गरीबी के मानदंडों के आधार पर सार्वजनिक नौकरियों में वैधानिक आरक्षण प्रदान करना

97. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद 51A(e) के तहत समरसता को बढ़ावा देने के मूल कर्तव्य का तत्व नहीं है?
(A) धार्मिक विविधताओं से परे जाना
(B) भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से परे जाना
(C) स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना
(D) व्यक्तिगत गतिविधियों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना

98. मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में निहित हैं?
(A) भाग III
(B) भाग IV
(C) भाग IVA

Downloaded from www.pdf.tube

(D) भाग V

99. मूल कर्तव्यों की प्रवर्तनीयता के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) वे अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे प्रवर्तनीय हैं।
(B) संसद उपयुक्त विधान द्वारा उन्हें लागू करने के लिए स्वतंत्र है।
(C) संसद को उनमें से किसी को भी लागू करने के लिए कानून बनाने से प्रतिबंधित किया गया है।
(D) राष्ट्रपति संसदीय स्वीकृति के बिना अध्यादेशों के माध्यम से उन्हें सीधे लागू कर सकते हैं।

100. प्रस्तावना में "पंथनिरपेक्ष" शब्द का अर्थ है कि राज्य:
(A) सक्रिय रूप से धर्म-विरोधी है और सभी सार्वजनिक धार्मिक प्रथाओं को सख्ती से हतोत्साहित करता है
(B) सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करता है और धर्म के प्रति तटस्थता बनाए रखता है
(C) बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय के धर्म को आधिकारिक रूप से संरक्षण और वित्तपोषित करता है
(D) एकल बहुसंख्यक धर्म के आधार पर एक सख्त अनिवार्य समान नागरिक संहिता लागू करता है

101. माता-पिता या अभिभावक द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने से संबंधित मूल कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?
(A) 42वां संशोधन अधिनियम
(B) 44वां संशोधन अधिनियम
(C) 73वां संशोधन अधिनियम
(D) 86वां संशोधन अधिनियम

102. प्रस्तावना में उल्लिखित 'प्रतिष्ठा की समता' और 'अवसर की समता' के बीच मौलिक अंतर क्या है?
(A) प्रतिष्ठा का तात्पर्य केवल आर्थिक धन से है, जबकि अवसर का तात्पर्य केवल औपचारिक उच्च शिक्षा तक पहुंच से है।
(B) प्रतिष्ठा का अर्थ विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति है, जबकि अवसर का अर्थ व्यक्तिगत विकास के लिए समान अवसर है।
(C) प्रतिष्ठा केवल सार्वजनिक कर्मचारियों पर लागू होती है, जबकि अवसर केवल निजी नागरिकों पर लागू होता है।
(D) कोई मौलिक कानूनी अंतर नहीं है; संवैधानिक कानून में उनका उपयोग पूरी तरह से समानार्थी शब्दों के रूप में किया जाता है।

103. प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: प्रस्तावना संविधान का समापन भाग है।
कथन II: प्रस्तावना संविधान की भूमिका या परिचय है, जिसमें इसके मूल मूल्य और दर्शन शामिल हैं।
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

104. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान विशेष रूप से "राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण" पर जोर देता है?
(A) यह अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक नागरिक का एक स्पष्ट मूल कर्तव्य है।
(B) यह अनुच्छेद 49 के तहत राज्य के नीति का निदेशक तत्व है।
(C) यह अनुच्छेद 29 के तहत एक कानूनी रूप से प्रवर्तनीय मूल अधिकार है।
(D) यह प्रस्तावना से प्राप्त एक अलिखित अंतर्निहित संवैधानिक कर्तव्य है।

105. "हमारी सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका परिरक्षण करना" एक है:
(A) मूल अधिकार
(B) राज्य का नीति निदेशक तत्व
(C) मूल कर्तव्य
(D) संवैधानिक परिपाटी

106. भारत के संवैधानिक दर्शन के स्रोतों की पहचान करते समय निम्नलिखित में से कौन-सा असंगत है?
(A) उद्देश्य प्रस्ताव
(B) भारत सरकार अधिनियम, 1919
(C) प्रस्तावना
(D) राज्य के नीति निदेशक तत्व

107. मूल कर्तव्यों को भाग IV (निदेशक तत्व) के तुरंत बाद भाग IVA में रखने का सबसे सटीक औचित्य कौन-सा कथन प्रदान करता है?
(A) न्यायालयों को स्पष्ट रूप से यह इंगित करना कि कर्तव्य कानूनी रूप से निदेशक तत्वों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं
(B) यह दिखाना कि नागरिकों के दायित्व नीति निदेशक तत्वों के तहत राज्य के दायित्वों के समानांतर हैं
(C) क्योंकि मूल अधिकारों को नियंत्रित करने वाले भाग III में संरचनात्मक रूप से संशोधनों के लिए कोई स्थान नहीं बचा था
(D) यह सुनिश्चित करना कि कर्तव्य सभी मूल अधिकारों से पूरी तरह से अलग और पृथक हैं

108. प्रस्तावना भारत को एक 'संप्रभु' राज्य घोषित करती है। इसका अर्थ है कि भारत:
(A) अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी नए विदेशी क्षेत्र को अधिग्रहित करने से संवैधानिक रूप से प्रतिबंधित है
(B) किसी भी शर्त के तहत किसी विदेशी राज्य के पक्ष में अपने संप्रभु क्षेत्र के किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ सकता

NODIA

है
(C) आंतरिक और बाहरी मामलों पर पूर्ण अधिकार के साथ स्वतंत्र है
(D) अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों में कम से कम एक वैश्विक महाशक्ति के साथ आधिकारिक रूप से संरेखित होना चाहिए

109. निम्नलिखित में से किस मामले ने यह स्थापित किया कि प्रस्तावना के मुख्य मूल्यों सहित संविधान के "मूल ढाँचे" को संसद द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है?
(A) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला (1967)
(B) मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला (1980)
(C) केशवानंद भारती मामला (1973)
(D) शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला (1951)

110. प्रस्तावना के आदर्श और संविधान में इसके कार्यान्वयन के बीच गलत सुमेल की पहचान कीजिए।
(A) आर्थिक न्याय – अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17)
(B) राजनीतिक न्याय – सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (अनुच्छेद 326)
(C) अवसर की समता – सार्वजनिक रोजगार में समता (अनुच्छेद 16)
(D) धर्म और उपासना की स्वतंत्रता – धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25-28)

111. प्रस्तावना के शब्दों के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: प्रस्तावना "हम, भारत के लोग" से शुरु होती है और "एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं" पर समाप्त होती है।
कथन II: प्रारुप समिति ने सार्वभौमिक स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावना में किसी विशिष्ट राजनीतिक दल या नेता का नाम लेने से जानबूझकर परहेज किया।
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

112. मूल कर्तव्यों के अनुसार, नागरिकों से किसे संजोने और उनका पालन करने की आवश्यकता है?
(A) प्राचीन भारतीय समाज के कठोर पारंपरिक मानदंडों और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों को
(B) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को
(C) एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सख्त बाजार सिद्धांतों को
(D) औपनिवेशिक प्रशासनिक नियमों और कानूनों को

113. अनुच्छेद 51A के तहत, वन्यजीवों की रक्षा करना किसके रूप में संरचित है?
(A) वन्यजीवों का मूल अधिकार
(B) नागरिकों के लिए राज्य का नीति निदेशक तत्व
(C) प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य
(D) विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता के तहत एक कानूनी अधिकार

114. प्रस्तावना में 'लोकतांत्रिक' शब्द का प्रयोग इसके व्यापक अर्थ में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र शामिल है, बल्कि निम्नलिखित भी शामिल हैं:
(A) सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र
(B) सैन्य और संरचनात्मक लोकतंत्र
(C) अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक लोकतंत्र
(D) न्यायिक और कार्यपालक लोकतंत्र

115. निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावना से प्राप्त संविधान के मूल ढाँचे का भाग नहीं माना जाता है?
(A) भारतीय राज्य की संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य प्रकृति
(B) भारतीय संविधान का पंथनिरपेक्ष चरित्र
(C) संविधान की समग्र सर्वोच्चता
(D) निजी संपत्ति का पूर्ण अधिकार

116. निम्नलिखित में से कौन "देश की रक्षा करने" [अनुच्छेद 51A(d)] के मूल कर्तव्य पर एक स्पष्ट सीमा का प्रतिनिधित्व करता है?
(A) यह केवल घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लागू होता है।
(B) यह केवल सशस्त्र बलों में सेवारत नागरिकों पर लागू होता है।
(C) इसे राज्य द्वारा "आह्वान किए जाने पर" निष्पादित किया जाना चाहिए।
(D) इसके लिए व्यक्तियों को अपने स्वयं के रक्षा उपकरण खरीदने की आवश्यकता होती है।

117. किस विद्वान ने प्रस्तावना को "हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्मकुंडली" के रूप में वर्णित किया था?
(A) के.एम. मुंशी
(B) जवाहरलाल नेहरु
(C) बी.आर. अम्बेडकर
(D) राजेन्द्र प्रसाद

118. मूल कर्तव्यों पर वर्मा समिति (1999) के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) इसका गठन नागरिकों को मूल कर्तव्य सिखाने के सुझावों को व्यावहारिक रूप देने के लिए किया गया था।
(B) इसने कुछ मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा कानूनी प्रावधानों की पहचान की।
(C) इसने संविधान से गैर-न्यायसंगत कर्तव्यों को हटाने की सिफारिश की।
(D) इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जैसे अधिनियम भ्रातृत्व के कर्तव्य को लागू करते हैं।

Click Here to Buy book on Flipkart

119. प्रस्तावना के संदर्भ में, "प्रतिष्ठा की समता" किसे समाप्त करने का प्रयास करती है?
(A) कृत्रिम वर्ग की उपाधियाँ और विशेषाधिकार
(B) व्यक्तियों पर लगाए गए राज्य और स्थानीय कराधान के सभी रूप
(C) सार्वजनिक रोजगार के लिए आवश्यक प्रतियोगी योग्यता परीक्षाएं
(D) निजी वाणिज्यिक संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व

120. कानूनों की संवैधानिक वैधता और मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: उच्चतम न्यायालय ने माना कि यदि कोई कानून मूल कर्तव्य को प्रभावी करने का प्रयास करता है, तो इसे अनुच्छेद 14 या 19 के तहत 'युक्तियुक्त' माना जा सकता है।
कथन II: किसी कानून को केवल इसलिए तुरंत रद्द किया जा सकता है क्योंकि वह किसी मूल कर्तव्य का उल्लंघन करता है।
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

121. 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में "अखंडता" शब्द को शामिल करने का उद्देश्य क्या था?
(A) विभाजनकारी क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता पर काबू पाना
(B) संप्रभु पड़ोसी देशों का भारत में जबरन विलय सुनिश्चित करना
(C) नागरिकों को देश से बाहर प्रवास करने से पूरी तरह रोकना
(D) राज्य सरकारों को अंतर-राज्य परिषदों की स्थापना से रोकना

122. अनुच्छेद 51A(i) के तहत, एक नागरिक का कर्तव्य है:
(A) प्राकृतिक झीलों, नदियों, वनों और वन्यजीवों की रक्षा करना
(B) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना
(C) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार का विकास करना
(D) देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना

123. संविधान की व्याख्या करने में प्रस्तावना उपयोगी है क्योंकि:
(A) यह संवैधानिक नियमों के उल्लंघन के लिए सभी वैधानिक दंडों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करती है।
(B) इसमें प्रत्यक्ष अधिनियमन खंड शामिल है जो राष्ट्रपति को कार्यपालक शक्तियां प्रदान करता है।
(C) यह संविधान के मौलिक मूल्यों और दर्शन को समाहित करती है।
(D) यह संविधान में संशोधन के लिए आवश्यक सटीक प्रक्रियात्मक तंत्र प्रदान करती है।

124. मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा असंगत है?
(A) संविधान का पालन करना
(B) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना
(C) सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना
(D) न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

125. प्रस्तावना सभी नागरिकों को "विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता" सुरक्षित करती है। संविधान का कौन-सा भाग मुख्य रूप से इन स्वतंत्रताओं को लागू करने के लिए कानूनी तंत्र प्रदान करता है?
(A) भाग II (नागरिकता)
(B) भाग III (मूल अधिकार)
(C) भाग IV (राज्य के नीति निदेशक तत्व)
(D) भाग IVA (मूल कर्तव्य)

126. मूल कर्तव्यों के लागू होने के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) वे केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं।
(B) वे भारत में काम कर रहे निगमों और विदेशी कंपनियों पर समान रूप से बाध्यकारी हैं।
(C) वे नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं।
(D) वे केवल सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं।

NODIA

127. किस न्यायिक निर्णय ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि पंथनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता है?
(A) एस. आर. बोम्मई मामला (1994)
(B) बेरुबाड़ी यूनियन मामला (1960)
(C) ए.के. गोपालन मामला (1950)
(D) गोलकनाथ मामला (1967)

128. संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग के अनुसार, मूल कर्तव्यों के संबंध में क्या सिफारिश की गई थी?
(A) संविधान के भाग IVA में सभी मूल कर्तव्यों को तुरंत निरस्त कर दिया जाना चाहिए।
(B) राज्य को नागरिकों के बीच उनके कर्तव्यों के बारे में सक्रिय जागरूकता पैदा करनी चाहिए।
(C) पूर्ण प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें मूल अधिकार वाले अध्याय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
(D) केवल सरकारी कर्मचारी ही कानूनी रूप से मूल कर्तव्यों से बंधे होने चाहिए।

129. "हम, भारत के लोग" वाक्यांश के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: यह दर्शाता है कि संविधान 1949 में प्रत्येक वयस्क नागरिक के प्रत्यक्ष वोट द्वारा तैयार किया गया था।
कथन II: यह दर्शाता है कि संविधान अपनी सत्ता संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करने वाले भारत के लोगों से प्राप्त करता है।

निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

130. "वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करने" का मूल कर्तव्य मुख्य रुप से किस पर लक्षित है?
(A) तर्कसंगत सोच, अंधविश्वास से लड़ने और प्रगतिशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर
(B) समाज से सभी संगठित धार्मिक संस्थाओं और प्रथाओं को समाप्त करने पर
(C) नागरिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में औपचारिक विश्वविद्यालय की डिग्री हासिल करने के लिए बाध्य करने पर
(D) राष्ट्रीय सरकार के वित्तपोषण को विशेष रुप से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवंटित करना सुनिश्चित करने पर

www.nodia.in

NODIA

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव
भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्राथमिक स्रोत 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में उन मूलभूत मूल्यों, आदर्शों तथा सिद्धांतों का समावेश था, जो भावी संविधान के निर्माण के मार्गदर्शक बने। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव अंततः सूक्ष्म संशोधनों के साथ स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना का आधार बना।

2. (D) लोकप्रिय संप्रभुता
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त "हम, भारत के लोग" वाक्यांश लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को रेखांकित करता है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि भारत में अंतिम राजनीतिक सत्ता और संप्रभुता किसी बाहरी शक्ति या किसी सम्राट में नहीं, बल्कि भारत की जनता में निहित है। संविधान सभा ने भारतीय जनता के प्रतिनिधि के रूप में संविधान का निर्माण किया तथा इसे अंगीकृत एवं अधिनियमित किया। इस प्रकार देश में सरकार का अंतिम आधार जनता की सहमति और उसकी संप्रभु शक्ति ही है।

3. (A) 4, 2, 1, 3
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले मुख्य आदर्शों को एक निश्चित और विचारपूर्वक तय किए गए क्रम में रखा गया है। प्रस्तावना के पाठ के अनुसार, सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इसके पश्चात् विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है और अंत में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता का उल्लेख आता है।

4. (B) केवल II और III
बेरुबाड़ी यूनियन मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है और यह संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के पीछे के सामान्य उद्देश्यों को दर्शाती है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। हालांकि, इस मामले में न्यायालय का यह निष्कर्ष था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जिसे बाद में केशवानंद भारती मामले में बदला गया।

5. (D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
भारतीय संविधान की 1949 में अपनाई गई मूल प्रस्तावना में "समाजवादी" शब्द शामिल नहीं था। इसे वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। भारतीय समाजवाद मार्क्सवादी या साम्यवादी समाजवाद से भिन्न लोकतांत्रिक समाजवाद का पक्षधर है। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है जहाँ सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों साथ-साथ सह-अस्तित्व में रहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना तथा जन-कल्याण सुनिश्चित करना है।

6. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना गैर-न्यायसंगत अथवा अ-प्रवर्तनीय प्रकृति की है। इसका अर्थ यह है कि प्रस्तावना में निहित सिद्धांतों, आदर्शों और घोषणाओं को सीधे तौर पर किसी न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता है। इसके प्रावधानों के उल्लंघन का दावा करके कोई नागरिक अदालत से किसी प्रशासनिक निर्देश या आदेश की मांग नहीं कर सकता। न्यायालय केवल संवैधानिक अनुच्छेदों की अस्पष्टता को दूर करने तथा वैधानिक व्याख्या के लिए प्रस्तावना के सिद्धांतों का सहारा लेते हैं।

7. (B) आर्थिक उद्यम की स्वतंत्रता
भारतीय संविधान की प्रस्तावना नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए पांच विशिष्ट प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी देती है। इनमें विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता शामिल हैं। प्रस्तावना में आर्थिक उद्यम की स्वतंत्रता का उल्लेख अलग से नहीं किया गया है, हालांकि व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में दिया गया है। प्रस्तावना में आर्थिक संदर्भ केवल आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के संबंध में आता है।

8. (B) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पहली और एकमात्र बार संशोधन किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए: "समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष" और "अखंडता"। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य भारत के संवैधानिक ढांचे में सामाजिक-आर्थिक समानता, धार्मिक तटस्थता तथा राष्ट्रीय एकता के प्रति राज्य की दृढ़ प्रतिबद्धता को अधिक स्पष्ट और सुदृढ़ रूप से अभिव्यक्त करना था। यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल के दौरान किया गया था।

9. (D) ईमानदारी और नियमित रूप से करों का भुगतान करना
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्यों की सूची दी गई है। इन कर्तव्यों में संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की

Downloaded from www.pdf.tube

रक्षा करना, तथा सामासिक संस्कृति का संवर्धन शामिल है। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने करों का भुगतान करने को एक मूल कर्तव्य के रूप में शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन संसद द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था। अतः करों का भुगतान करना एक वैधानिक दायित्व तो है, परंतु मूल कर्तव्य नहीं।

10. (A) P-2, Q-1, R-4, S-3
भारतीय संविधान में प्रयुक्त शब्दावलियों के विशिष्ट अर्थ हैं। 'संप्रभु' का तात्पर्य है कि भारत किसी अन्य राष्ट्र का डोमिनियन नहीं है और अपने निर्णय स्वयं लेता है। 'गणराज्य' का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख कोई वंशानुगत राजा नहीं बल्कि निर्वाचित व्यक्ति होता है। 'पंथनिरपेक्ष' का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और सभी धर्म समान हैं। 'लोकतांत्रिक' का तात्पर्य है कि सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सीधे जनता में निहित होती है।

11. (B) 26 नवंबर 1949
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतिम भाग में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। यही तिथि भारत के संविधान को अपनाने की आधिकारिक तिथि मानी जाती है। यद्यपि संविधान के अधिकांश मुख्य प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, परंतु नागरिकता और चुनावों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही प्रभावी हो गए थे।

12. (B) राज्य का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है
प्रस्तावना में प्रयुक्त "गणराज्य" शब्द यह निर्दिष्ट करता है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। ब्रिटेन की तरह भारत में राजतंत्र या वंशानुगत पद प्रणाली नहीं है, जहाँ राजा या रानी राष्ट्राध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्षों के लिए होता है। इसके अतिरिक्त, गणराज्य व्यवस्था में राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति में नहीं बल्कि जनता में निहित होती है और सभी सार्वजनिक पद हर नागरिक के लिए खुले होते हैं।

13. (B) केवल I, II और III
कांग्रेस पार्टी ने 1976 में आपातकाल के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति की मुख्य सिफारिश मूल कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय संविधान में शामिल करने की थी। समिति ने कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या दंड लगाने का सुझाव भी दिया था। हालांकि, सरकार ने समिति की कुछ सिफारिशों जैसे कर चुकाने का कर्तव्य और दंड प्रावधानों को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए यह कहना गलत है कि सभी सिफारिशें बिना संशोधन स्वीकार की गई थीं।

14. (C) 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना
86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। इसके तहत अनुच्छेद 51A में 11वां मूल कर्तव्य खंड (k) के रूप में जोड़ा गया। इसके अनुसार प्रत्येक माता-पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य बनाया गया कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसी संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार भी बनाया गया था।

15. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक ऐतिहासिक निर्णय था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने बेरुबाड़ी यूनियन मामले के अपने पूर्व रुख को बदलते हुए निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अति आवश्यक भाग है। न्यायालय ने यह भी स्थापित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, परंतु यह संशोधन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकता। इस प्रकार प्रस्तावना में संशोधन योग्य सीमाएं तय की गईं।

NODIA

16. (C) संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य के स्वरूप को व्यक्त करने वाले विशेषणों का एक विशिष्ट क्रम निर्धारित है। प्रस्तावना घोषणा करती है कि भारत एक "संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य" है। मूल प्रस्तावना में संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य शब्द शामिल थे, जबकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष" शब्दों को संप्रभु और लोकतांत्रिक के बीच में जोड़ा गया था। इसलिए सही क्रम संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है।

17. (B) व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली भ्रातृत्व की भावना
प्रस्तावना में निहित "बंधुता" का सीधा अर्थ है देश के सभी नागरिकों के बीच भ्रातृत्व अथवा भाईचारे की भावना का विकास करना। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में बंधुता का आदर्श दो प्रमुख बातों का आश्वासन देता है: पहला, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान और दूसरा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को बनाए रखना। एकल नागरिकता की संवैधानिक व्यवस्था और अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्य भी देश में बंधुता की भावना को बढ़ावा देने के लिए ही बनाए गए हैं।

18. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारतीय संविधान के भाग IVA में अंतर्निहित मूल कर्तव्य विशेष रूप से केवल भारत के नागरिकों के लिए ही निर्धारित किए गए हैं। ये विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होते हैं, जबकि कुछ मूल अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं। मूल कर्तव्यों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को यह चेताना था कि अपने अधिकारों का आनंद लेते समय उन्हें समाज, देश तथा

साथी नागरिकों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को भी याद रखना चाहिए। अतः दोनों कथन सही हैं और कारण अभिकथन की व्याख्या करता है।

19. (D) वे न्यायिक समीक्षा में कर्तव्यों को प्राथमिकता देकर मूल अधिकारों के प्रवर्तन को गंभीर रूप से सीमित करते हैं।
मूल कर्तव्यों की आलोचना विभिन्न आधारों पर की जाती है, जैसे उनकी अ-न्यायसंगत प्रकृति जिसके कारण उन्हें केवल नैतिक उपदेश माना जाता है। आलोचक सामासिक संस्कृति और उच्च आदर्श जैसे शब्दों की अस्पष्टता पर भी प्रश्न उठाते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें भाग III के बाद जोड़ने के बजाय भाग IV के बाद रखने पर भी आपत्ति जताई जाती है। हालांकि, यह आलोचना गलत है कि वे मूल अधिकारों को सीमित करते हैं, क्योंकि वास्तव में कर्तव्य और अधिकार एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं।

20. (A) पूर्व सोवियत संघ
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा तत्कालीन पूर्व सोवियत संघ (यूएसएसआर) के संविधान से ली गई थी। प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के मूल संविधानों में नागरिकों के कर्तव्यों की स्पष्ट सूची शामिल नहीं थी। इसके विपरीत, सोवियत संघ जैसे समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों दोनों को समान संवैधानिक महत्व प्रदान किया था। भारत ने वर्ष 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से इस अवधारणा को अपनाया।

21. (D) मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों 1949 में अधिनियमित मूल संविधान का हिस्सा थे।
मूल अधिकार 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए मूल संविधान के भाग III का हिस्सा थे, जबकि मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था। मूल कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान के नए भाग IVA (अनुच्छेद 51A) में अंतःस्थापित किया गया था। इसलिए यह कहना पूरी तरह से गलत है कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों 1949 के मूल संविधान में एक साथ मौजूद थे।

22. (A) केवल I और II
संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत विशिष्ट मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। खंड (g) में झीलों, नदियों, वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करने का निर्देश है। खंड (a) में संविधान का पालन करने तथा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने का उल्लेख है। हालांकि, चुनावों में मतदान करना या करों का भुगतान करना अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है, यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने मतदान के कर्तव्य का सुझाव दिया था।

23. (D) कानूनी न्याय
भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों को तीन भिन्न और विशिष्ट आयामों में न्याय सुरक्षित कराने का संकल्प व्यक्त करती है। ये तीन आयाम हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इन तीनों प्रकार के न्याय को मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तावना के पाठ में पृथक रूप से "कानूनी न्याय" शब्द को एक अलग आयाम के रूप में उल्लिखित नहीं किया गया है।

24. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
बेरुबाड़ी मामला 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती मामला 1973 में न्यायालय ने पूर्व निर्णय को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना तथा इसे मूल ढांचे का हिस्सा घोषित किया। एलआईसी मामला 1995 में पुनः पुष्टि की गई कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक अंग है। एस. आर. बोम्मई मामला 1994 में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्णय दिया कि पंथनिरपेक्षता भारतीय संविधान का एक मूल ढांचा है।

25. (A) किसी भी वर्ग के लिए विशेष विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और पर्याप्त अवसरों का प्रावधान
प्रस्तावना में "प्रतिष्ठा और अवसर की समता" का वादा भारतीय समाज से नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य को दर्शाता है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज के किसी भी वर्ग के पास जन्म, जाति, लिंग या धर्म के आधार पर विशेष विशेषाधिकार नहीं होंगे। साथ ही, प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए पर्याप्त और निष्पक्ष अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह समानता कानून के समक्ष समानता और समान अवसर सुनिश्चित करती है।

26. (D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कानून बनाकर किसी भी मूल कर्तव्य को लागू कर सकती है और उनके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान कर सकती है। इसलिए पहला कथन गलत है। वर्मा समिति (1999) ने कई ऐसे पूर्व-मौजूद कानूनों की पहचान की थी जो मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन में सहायता करते हैं, जैसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। अतः दूसरा कथन पूरी तरह सत्य है।

27. (A) केवल I और III
एम्स स्टूडेंट्स यूनियन मामले 2001 में उच्चतम न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी कि मूल कर्तव्य उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि मूल अधिकार। इसके अतिरिक्त, न्यायालय किसी कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करते समय या अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते समय मूल कर्तव्यों का सहारा ले सकते हैं। हालांकि, कर्तव्य का पालन न करने पर नागरिकता स्वतः समाप्त नहीं होती है और न ही न्यायालय केवल कर्तव्यों के आधार पर किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करते हैं।

Click Here to Buy book on Amazon

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from **PRINTED BOOKS** has up to **4× HIGHER RETENTION** than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS** move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND** in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

28. (A) समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देने का कर्तव्य
अनुच्छेद 51A(e) के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह मूल कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं से परे हटकर भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे। इसी खंड में स्पष्ट रूप से यह भी अनिवार्य किया गया है कि नागरिक ऐसी सभी प्रथाओं का पूरी तरह से त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। यह प्रावधान महिला गरिमा की सुरक्षा और लैंगिक समानता पर बल देता है।

29. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारतीय संविधान पंथनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को अपनाता है, जो पश्चिमी देशों की धर्म और राज्य के पूर्ण पृथक्करण की नकारात्मक अवधारणा से भिन्न है। भारतीय संदर्भ में सकारात्मक पंथनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, परंतु वह सभी धर्मों को समान आदर देगा और उनका समान रुप से संरक्षण करेगा। राज्य किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है।

30. (D) कर्तव्यों का पालन न करने के लिए जुर्माना या दंड लगाना
स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में सिफारिश की थी कि संविधान में मूल कर्तव्यों के उल्लंघन या उनका पालन न करने पर जुर्माना अथवा सजा देने का विधायी प्रावधान किया जाना चाहिए। हालांकि, तत्कालीन सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो भाग IVA जोड़ा गया, उसमें किसी भी दंड या शास्ति का उल्लेख नहीं किया गया। इस प्रकार मूल कर्तव्यों को प्रकृति में गैर-न्यायसंगत ही बनाए रखा गया।

31. (C) यह संवैधानिक अस्पष्टताओं की व्याख्या का मार्गदर्शन करने वाले उदात्त दृष्टिकोण की रुपरेखा तैयार करती है।
प्रस्तावना को संविधान की व्याख्या का एक अनिवार्य उपकरण माना जाता है क्योंकि इसमें उन उदात्त मूल्यों, दर्शन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण का समावेश है जिन्हें संविधान निर्माता प्राप्त करना चाहते थे। जब संविधान के किसी विशिष्ट अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द अस्पष्ट या बहुअर्थी होते हैं, तब न्यायपालिका उन प्रावधानों के वास्तविक अर्थ और मंशा को समझने के लिए प्रस्तावना में व्यक्त किए गए सिद्धांतों का सहारा लेती है। यह संवैधानिक न्यायनिर्णयन में एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है।

32. (A) 2, 3, 1
प्रस्तावना की विधिक स्थिति से संबंधित ऐतिहासिक मामलों का सही कालानुक्रमिक क्रम बेरुबाड़ी यूनियन मामला (1960), केशवानंद भारती मामला (1973) और एलआईसी ऑफ इंडिया मामला (1995) है। 1960 में न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। इसके पश्चात् 1973 में ऐतिहासिक पीठ ने बेरुबाड़ी निर्णय को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग स्वीकार किया। अंततः 1995 के एलआईसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद निर्णय की पुनः पुष्टि करते हुए प्रस्तावना को अंग माना।

33. (D) अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करने की जनता की अंतिम सत्ता
"लोकप्रिय संप्रभुता" का सिद्धांत यह स्थापित करता है कि राज्य में सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता और प्रभुत्व किसी शासक या बाहरी संस्था में नहीं बल्कि जनता में निहित होता है। सरकार का अधिकार और उसकी वैधता केवल नागरिकों की सहमति से ही उत्पन्न होती है। भारतीय लोकतंत्र में जनता अपने इस संप्रभु अधिकार का प्रयोग आवधिक चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनकर करती है, जो सरकार चलाते हैं और कानून का निर्माण करते हैं।

34. (B) केवल I और III
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने प्रस्तावना में अब तक की पहली और एकमात्र बार संशोधन किया। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग IVA तथा अनुच्छेद 51A जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। हालांकि, इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए तीन नए शब्द "समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष" और "अखंडता" थे, न कि "बंधुता"। बंधुता शब्द 1949 की मूल प्रस्तावना में पहले से ही मौजूद था। अतः केवल पहला और तीसरा कथन ही सत्य हैं।

35. (D) अनुच्छेद 51A(b) – स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को संजोना
अनुच्छेद 51A के विभिन्न खंडों में विशिष्ट कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 51A(b) स्पष्ट रुप से यह निर्देश देता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अन्य विकल्पों में: वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख 51A(h) में है, प्राकृतिक पर्यावरण का उल्लेख 51A(g) में है, तथा शिक्षा के अवसर का उल्लेख 51A(k) में है। अतः केवल अंतिम युग्म सही सुमेलित है।

36. (D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
प्रस्तावना में संशोधन की स्थिति पर केशवानंद भारती मामला 1973 एक ऐतिहासिक मोड़ था। इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है क्योंकि यह संविधान का एक भाग है। हालांकि न्यायालय ने यह शर्त लगाई कि संशोधन द्वारा प्रस्तावना के मूल ढांचे या मौलिक तत्वों को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए पहला कथन कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता, असत्य है जबकि दूसरा कथन पूरी तरह सही है।

37. (A) P-2, Q-1, R-4, S-3
अनुच्छेद 51A के अंतर्गत विभिन्न खंडों में कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 51A(a) में संविधान का पालन करने तथा राष्ट्रीय ध्वज का आदर करने का कर्तव्य है। अनुच्छेद 51A(c) में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा

NODIA

करने का उल्लेख है। अनुच्छेद 51A(e) में धार्मिक और भाषाई विविधताओं से परे समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना बढ़ाने का निर्देश है। अनुच्छेद 51A(g) में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करने का उल्लेख है।

38. (D) समुद्र तल
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के अंतर्गत नागरिकों के लिए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का मूल कर्तव्य उल्लिखित है। इस विशिष्ट संवैधानिक पाठ में चार प्राकृतिक घटकों का स्पष्ट रूप से नाम लेकर उल्लेख किया गया है: वन, झीलें, नदियाँ और वन्यजीव। इस अनुच्छेद के मूल पाठ में "समुद्र तल" का उल्लेख अलग से नहीं किया गया है, हालांकि व्यापक पर्यावरण संरक्षण के विधायी कानूनों के अंतर्गत समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण भी शामिल होता है।

39. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारतीय संविधान के भाग IVA में शामिल मूल कर्तव्य प्रकृति में अ-न्यायसंगत या गैर-प्रवर्तनीय हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई नागरिक अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो संविधान स्वयं अदालतों को इसके प्रत्यक्ष प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण या परमादेश जैसी रिट जारी करने का अधिकार नहीं देता है। प्रत्यक्ष न्यायिक प्रवर्तन का अभाव ही इनके गैर-न्यायसंगत होने का मुख्य कारण है। अतः दोनों कथन सही हैं और कारण सही व्याख्या प्रस्तुत करता है।

40. (B) एन.ए. पालकीवाला
भारत के प्रसिद्ध संवैधानिक वकील और न्यायविद एन.ए. पालकीवाला ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को "संविधान का परिचय पत्र" कहा था। उनका मानना था कि जिस प्रकार एक परिचय पत्र किसी व्यक्ति की पहचान और मूल विवरण को संक्षेप में प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार प्रस्तावना भी संपूर्ण संविधान के मूल दर्शन, सिद्धांतों, उद्देश्यों और आत्मा का संक्षिप्त सार प्रस्तुत करती है। इस कथन के माध्यम से उन्होंने प्रस्तावना के अद्वितीय महत्व को रेखांकित किया था।

41. (A) विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता के पांच रूपों की घोषणा की गई है। प्रस्तावना के मूल पाठ में इनका सही और निश्चित क्रम है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रताएं नागरिकों के बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इन स्वतंत्रताओं को कानूनी रूप से प्रवर्तनीय बनाने के लिए संविधान के भाग III में अनुच्छेद 19 से 28 के तहत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।

42. (B) केवल I, III और IV
प्रस्तावना में प्रयुक्त "लोकतांत्रिक गणराज्य" शब्द भारत की राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करता है। यह दर्शाता है कि सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर अपनी सरकार चुनती है। गणराज्य का अर्थ है कि राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है और कोई वंशानुगत सम्राट नहीं होता। इसलिए कथन II असत्य है क्योंकि यह भारत में सम्राट की उपस्थिति बताता है। सार्वजनिक पद सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध होना भी गणराज्य का मुख्य लक्षण है।

43. (C) इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए पूर्ण धन समानता स्थापित करना है।
प्रस्तावना में "प्रतिष्ठा और अवसर की समता" का उद्देश्य समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष विशेषाधिकारों को समाप्त करना और बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को विकास के समान अवसर प्रदान करना है। इसमें नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक समानता शामिल है। हालांकि, इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के बीच पूर्ण धन समानता या समान बैंक बैलेंस स्थापित करना नहीं है, बल्कि आर्थिक विषमताओं को कम करना और अवसर की निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।

44. (A) दोनों प्रशासनिक नीतियां बनाने में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं।
मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निदेशक तत्व दोनों ही भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग हैं, परंतु उनके लक्ष्य अलग हैं। नीति निदेशक तत्व (भाग IV) राज्य के लिए नीतियां बनाने और कानून लागू करने के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जबकि मूल कर्तव्य (भाग IVA) सीधे नागरिकों के आचरण और दायित्वों से संबंधित हैं। इसलिए यह कहना असंगत है कि मूल कर्तव्य भी प्रशासनिक नीतियां बनाने में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि वे नागरिकों पर लक्षित हैं।

45. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 भारत में शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में एक ऐतिहासिक विधायी कदम था। इस संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A अंतःस्थापित किया गया, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया। इसके साथ ही, अनुच्छेद 51A में खंड (k) जोड़कर 11वां मूल कर्तव्य पेश किया गया, जिसके तहत माता-पिता या अभिभावकों पर अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर देने का संवैधानिक दायित्व डाला गया।

46. (C) 1976
वर्ष 1976 में आंतरिक आपातकाल के दौरान तत्कालीन केंद्र सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति का मुख्य कार्य संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को शामिल करने के संबंध में आवश्यक सिफारिशें देना था। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही सरकार ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया और संविधान के भाग IVA में अनुच्छेद 51A के तहत दस मूल कर्तव्यों को जोड़ा।

47. (A) केवल I और II
प्रस्तावना में निहित 'बंधुता' का आदर्श भारत में भाईचारे की भावना पैदा करके सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसी सामाजिक बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है। इसे

Downloaded from www.pdf.tube

बढ़ावा देने के लिए संविधान एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है। हालांकि, इसके लिए राज्य को सभी भौगोलिक क्षेत्रों के बीच पूर्ण आर्थिक समानता की संवैधानिक गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह सामाजिक और भावनात्मक संकीर्णताओं को समाप्त करने पर केंद्रित है। अतः केवल कथन I और II सही हैं।

48. (B) नागरिकों को समाज और राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों की याद दिलाना
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को यह स्मरण दिलाना है कि अपने मौलिक अधिकारों का उपभोग करते समय उन्हें अपने देश, समाज और सह-नागरिकों के प्रति अपने दायित्वों का भी सचेत रूप से पालन करना चाहिए। ये कर्तव्य नागरिकों के लिए एक अनुशासन, प्रेरणा और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं, जिससे अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक स्वस्थ संतुलन स्थापित हो सके।

49. (A) P-2, Q-3, R-1, S-4
संविधान विशेषज्ञों ने प्रस्तावना की विभिन्न रूपों में प्रशंसा की है। के.एम. मुंशी ने इसे "हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्मकुंडली" कहा। ब्रिटिश राजनीतिविद् अर्नेस्ट बार्कर ने इसे "संविधान का की-नोट (मुख्य स्वर)" कहा। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने इसे "संविधान की आत्मा" और "संविधान का आभूषण" कहा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्ला ने प्रस्तावना की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से की, जो संविधान के मूल दर्शन को व्यक्त करती है।

50. (C) सभी धार्मिक मामलों की उपेक्षा करते हुए, धर्म और राज्य का पूर्ण पृथक्करण
भारतीय पंथनिरपेक्षता पश्चिमी पंथनिरपेक्षता से भिन्न है। पश्चिमी मॉडल में धर्म और राज्य के बीच पूर्ण पृथक्करण तथा तटस्थता होती है, जहाँ राज्य धार्मिक मामलों से पूरी तरह अलग रहता है। इसके विपरीत, भारतीय मॉडल सकारात्मक पंथनिरपेक्षता पर आधारित है, जहाँ राज्य सभी धर्मों को समान आदर और सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए यह कहना गलत है कि भारतीय पंथनिरपेक्षता में धार्मिक मामलों की उपेक्षा करते हुए धर्म और राज्य का पूर्ण पृथक्करण शामिल है।

51. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारत मई 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना, परंतु यह सदस्यता भारत की संप्रभुता को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। प्रस्तावना में भारत को एक पूर्ण संप्रभु राज्य घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि भारत अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता एक स्वैच्छिक समझौता है जो भारतीय संविधान या संसद की शक्तियों पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं लगाता है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं।

NODIA

52. (A) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(h) के अनुसार, प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह स्पष्ट मूल कर्तव्य है कि वह अपने जीवन और विचार में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का निरंतर विकास करे। इस कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य समाज से अंधविश्वासों, रूढ़िवादी कुरीतियों और अज्ञानता को समाप्त करके तर्कसंगत सोच, वैज्ञानिक चेतना और निरंतर सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना है, जिससे एक आधुनिक और तार्किक समाज का निर्माण हो सके।

53. (C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी ऑफ इंडिया) मामला 1995 में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के केशवानंद भारती निर्णय को दोहराते हुए स्पष्ट रूप से पुनः स्थापित किया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न भाग है। हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान के विशिष्ट अनुच्छेदों के ऊपर सर्वोच्चता नहीं रखती है और न ही यह व्यक्तिगत रूप से प्रवर्तनीय है। इसलिए पहला कथन सही है और दूसरा कथन पूरी तरह असत्य है।

54. (A) केवल I और II
मूल अधिकार मुख्य रूप से राज्य की शक्तियों पर नकारात्मक सीमाएं हैं जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों पर सकारात्मक दायित्व हैं। इसके अतिरिक्त मूल अधिकार न्यायसंगत हैं जबकि कर्तव्य गैर-न्यायसंगत हैं। हालांकि, कथन III और IV गलत हैं क्योंकि कुछ मूल अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं लेकिन सभी कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं, तथा मूल कर्तव्यों को 1949 के मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था बल्कि उन्हें 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।

55. (A) जवाहरलाल नेहरु
भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरु द्वारा पेश किए गए ऐतिहासिक "उद्देश्य प्रस्ताव" पर मौलिक रूप से आधारित है। इस प्रस्ताव ने भावी स्वतंत्र भारत के संविधान के मूलभूत सिद्धांतों, दर्शन, संरचनात्मक संरचना और सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को रेखांकित किया था। संविधान सभा ने विचार-विमर्श के पश्चात 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को अपनाया, जो बाद में सूक्ष्म संशोधनों के साथ संविधान की प्रस्तावना बना।

56. (D) (B) और अनुच्छेद 51A(g) के तहत कर्तव्य दोनों
राष्ट्रीय ध्वज का आदर करने का स्पष्ट उल्लेख केवल अनुच्छेद 51A(a) में किया गया है, जो कहता है कि नागरिक संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अनुच्छेद 51A(d) में देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 51A(g) में प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण का उल्लेख है। इन दोनों प्रावधानों में "राष्ट्रीय ध्वज" शब्द का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं किया गया है।

57. (C) लोकतांत्रिक
26 नवंबर 1949 को अपनाई गई मूल प्रस्तावना में भारत को एक "संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य" घोषित किया गया था। इस प्रकार "लोकतांत्रिक" शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में प्रारंभ से ही मौजूद था। इसके विपरीत, "समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष" और "अखंडता" शब्दों को मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था; इन्हें काफी समय बाद वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना के पाठ में अंतःस्थापित किया गया था।

58. (A) P-2, Q-1, R-3, S-4
भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों को विशिष्ट भागों में विभाजित किया गया है। मूल अधिकार संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35) में स्थित हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में शामिल हैं। मूल कर्तव्यों को 1976 में एक नए भाग IVA (अनुच्छेद 51A) के रूप में जोड़ा गया था। प्रस्तावना संविधान के प्रारंभ में एक भूमिका के रूप में स्थित है और इसे कोई विशिष्ट भाग संख्या आवंटित नहीं की गई है।

59. (B) आर्थिक कारकों के आधार पर गैर-भेदभाव और धन की असमानताओं को समाप्त करना
प्रस्तावना में उल्लिखित "आर्थिक न्याय" का अर्थ है कि केवल संपत्ति, आय या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में धन, आय और संपत्ति के अत्यधिक संकेंद्रण तथा असमानताओं को दूर करना है। यह सभी व्यक्तियों को अपनी आजीविका कमाने और आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने में निष्पक्षता प्रदान करने की अवधारणा पर आधारित है, न कि सभी संपत्तियों के पूर्ण राष्ट्रीयकरण पर।

60. (D) I, II और III
1991 के बाद उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) की नीतियों ने भारत में पारंपरिक राज्य-नियंत्रित समाजवाद के सख्त स्वरूप को उदार बनाया है। इसके बावजूद, भारत में कल्याणकारी राज्य, सामाजिक न्याय और आर्थिक असमानता को कम करने का संवैधानिक लक्ष्य आज भी पूर्णतः प्रासंगिक है। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया है कि भारतीय लोकतांत्रिक समाजवाद का मूल लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की विषमता को समाप्त करना है। अतः तीनों कथन सत्य हैं।

61. (B) केवल I, II और IV
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के आदर सम्बंधी कर्तव्य (51A-a) को लागू करता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पर्यावरण संरक्षण सम्बंधी कर्तव्य (51A-g) का समर्थन करता है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 अस्पृश्यता को समाप्त करके भ्रातृत्व (51A-e) को बल प्रदान करता है। हालांकि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 मुख्य रूप से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने से संबंधित है, न कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण (51A-h) के प्रत्यक्ष प्रवर्तन से।

62. (B) 10
वर्ष 1976 में पारित 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के भाग IVA में अनुच्छेद 51A अंतःस्थापित किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से मूल रूप से दस मूल कर्तव्यों को नागरिकों के लिए शामिल किया गया था। बाद में, वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा से संबंधित 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अतः 1976 में मूल रूप से जोड़े गए कर्तव्यों की संख्या दस ही थी।

63. (A) समान राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक पद तक समान पहुंच और सरकार में समान आवाज
प्रस्तावना में निहित "राजनीतिक न्याय" का मौलिक तात्पर्य यह है कि देश के सभी नागरिकों को बिना किसी धर्म, जाति, लिंग या स्थान के भेदभाव के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। इसके अंतर्गत सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार, बिना किसी बाधा के किसी भी सार्वजनिक या राजनीतिक पद के लिए चुनाव लड़ने का अवसर तथा सरकार के निर्णयों में अपनी बात रखने की समान स्वतंत्रता शामिल है। इसे अनुच्छेद 326 द्वारा सुदृढ़ किया गया है।

64. (C) दोनों मामलों ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रस्तावना विधायिका को मौलिक शक्तियां प्रदान करती है।
बेरुबाड़ी यूनियन मामला (1960) और केशवानंद भारती मामला (1973) दोनों ही भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किए गए थे। बेरुबाड़ी मामले ने प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इनकार किया, जबकि केशवानंद मामले ने इसे संविधान का अभिन्न अंग स्वीकार किया। हालांकि, दोनों मामलों में न्यायालय ने यह समान रुख अपनाया कि प्रस्तावना विधायिका को कोई स्वतंत्र मौलिक शक्ति प्रदान नहीं करती है और न ही उसकी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाती है।

65. (B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उपभोग मूल कर्तव्यों के निष्पादन पर शर्त के रूप में निर्भर नहीं करता है; दोनों स्वतंत्र अवधारणाएं हैं। किसी नागरिक को उसके मौलिक अधिकारों से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने किसी मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया है। इसके अलावा, केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में विफल रहने जैसी अमूर्त बात पर किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। अतः दोनों कथन पूरी तरह असत्य हैं।

66. (B) नहीं, यह न तो विधायी शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका पर कोई प्रतिबंध है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना संसद या राज्य विधानमंडलों की कानून बनाने की विधायी शक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से सीमित नहीं करती है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, प्रस्तावना न तो विधायिका के लिए किसी शक्ति का स्वतंत्र स्रोत है और न ही यह उसकी शक्तियों पर कोई कानूनी प्रतिबंध लगाती है। यह केवल संविधान के उद्देश्यों और दर्शन का सार प्रस्तुत करती है। हालांकि, यदि कोई कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, तो उसे असंवैधानिक ठहराया जा सकता है।

Click Here to Buy book on Flipkart

67. (A) निजता
भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य पाठ स्पष्ट रूप से चार प्रमुख सामाजिक-राजनीतिक आदर्शों की घोषणा करता है: न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक), स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना), समता (प्रतिष्ठा और अवसर) तथा बंधुता। इस पाठ में "निजता" शब्द का उल्लेख एक स्वतंत्र आदर्श के रूप में कहीं भी नहीं किया गया है। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने के.एस. पुट्टस्वामी मामले में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है।

68. (A) राज्य द्वारा अधिग्रहित संपत्ति के लिए पर्याप्त मुआवजा देना
संविधान के अनुच्छेद 51A में उल्लिखित 11 मूल कर्तव्य मुख्य रूप से नागरिकों के नैतिक, सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण संबंधी उत्तरदायित्वों से संबंधित हैं। इनमें सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता का प्रयास करना और समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना स्पष्ट रूप से शामिल हैं। हालांकि, राज्य द्वारा अधिग्रहित संपत्ति के लिए मुआवजा देना सरकार से संबंधित एक कानूनी प्रावधान है, न कि नागरिकों का मूल कर्तव्य।

69. (B) इसके तहत माता-पिता या अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना आवश्यक है।
अनुच्छेद 51A(k) भारतीय संविधान में शामिल किया गया 11वां मूल कर्तव्य है। इसे वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित किया गया था। इस प्रावधान के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि जो भी माता-पिता या संरक्षक हों, वे 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य बच्चों के शैक्षणिक विकास में अभिभावकों के उत्तरदायित्व को रेखांकित करता है।

70. (C) अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए शेष संविधान के अधिनियमित होने के बाद
संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को पूरे शेष संविधान के पारित हो जाने के बाद अंत में अधिनियमित किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावना में व्यक्त किए गए आदर्श, दर्शन और मूल्य संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए अनुच्छेदों और प्रावधानों के पूरी तरह से अनुकूल और अनुरूप हों। संविधान सभा के अध्यक्ष ने इसे अंत में मतदान के लिए रखा और यह पूरे संविधान के एक स्वीकृत भाग के रूप में पारित हुआ।

71. (A) स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना
प्रस्तावना में प्रयुक्त "व्यक्ति की गरिमा" की अवधारणा प्रत्येक मनुष्य के आंतरिक मूल्य और सम्मान की रक्षा पर बल देती है। अनुच्छेद 51A(e) के तहत शामिल मूल कर्तव्य, जो नागरिकों से ऐसी सभी प्रथाओं का पूरी तरह से त्याग करने का आह्वान करता है जो स्त्रियों के सम्मान और गरिमा के विरुद्ध हैं, प्रस्तावना की इसी गरिमापूर्ण भावना से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। यह कर्तव्य महिलाओं के प्रति सामाजिक आदर और लैंगिक गरिमा सुनिश्चित करता है।

72. (B) विधि का शासन
"विधि का शासन" (रूल ऑफ लॉ) वह मौलिक संवैधानिक सिद्धांत है जो यह सुनिश्चित करता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और कोई भी नागरिक या प्राधिकारी कानून से ऊपर नहीं है। यह सिद्धांत प्रस्तावना में निहित 'लोकतांत्रिक' और 'समता' की भावना को साकार करता है। लोकतंत्र में निरंकुश या मनमाना शासन नहीं हो सकता; सभी सरकारी कार्यपालिकाएं और नागरिक संविधान तथा कानून की सीमाओं के भीतर ही कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं।

73. (D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
यद्यपि "पंथनिरपेक्ष" शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया था, परंतु यह कहना पूरी तरह गलत है कि इससे पहले संविधान में पंथनिरपेक्ष विशेषताएं मौजूद नहीं थीं। संविधान सभा ने प्रारंभ से ही भाग III के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार शामिल किए थे, जो राज्य के पंथनिरपेक्ष चरित्र को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इसलिए पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सत्य है।

74. (B) अनुचित प्रतिबंधों की अनुपस्थिति और व्यक्तिगत विकास के लिए अवसरों का प्रावधान
प्रस्तावना में निहित "स्वतंत्रता" का अर्थ केवल अनुचित, मनमाने या असीमित प्रतिबंधों का न होना ही नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए अनुकूल अवसर प्रदान करना भी है। हालांकि, स्वतंत्रता का अर्थ कुछ भी करने की असीमित छूट या लाइसेंस नहीं है। इसे संविधान द्वारा निर्धारित युक्तियुक्त सीमाओं और अन्य नागरिकों के समान अधिकारों के दायरे के भीतर ही उपभोग किया जा सकता है।

75. (A) सामाजिक-आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालयों को उद्योग के राज्य स्वामित्व का पक्ष लेने की अनुमति देता है
एक्सेल वेयर बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना में निहित "समाजवादी" शब्द के प्रभाव का विश्लेषण किया। न्यायालय ने माना कि समाजवाद शब्द का जोड़ अदालतों को सामाजिक और आर्थिक न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्योगों के राज्य स्वामित्व अथवा राष्ट्रीयकरण के पक्ष में झुकाव रखने की अनुमति देता है। हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इसका अर्थ निजी उद्योगों का पूर्ण उन्मूलन या निजी संपत्ति को अवैध बनाना नहीं है।

76. (C) वे स्वतः ही ऐसे किसी भी कानून को अमान्य कर देते हैं जो उनके अनुरूप नहीं है।
मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणादायी और अनुशासन वर्धक दिशानिर्देश हैं। वे समाजविरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं और अदालतें किसी कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने में इनकी सहायता लेती हैं। हालांकि, मूल कर्तव्य गैर-न्यायसंगत प्रकृति के हैं, इसलिए वे किसी भी ऐसे विधायी कानून को स्वतः या सीधे तौर

Downloaded from www.pdf.tube

पर अमान्य या असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते जो इनके विपरीत प्रतीत होता हो। अतः तीसरा कथन गलत है।

77. (A) शासन
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संकल्प व्यक्त करते हुए कहा गया है कि "हम, भारत के लोग... इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समता... तथा बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर..." इसे अंगीकृत करते हैं। इस संकल्प खंड में न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता का स्पष्ट उल्लेख है, जबकि "शासन" शब्द इस संकल्प घोषणा का हिस्सा नहीं है।

78. (A) भारत बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपने आंतरिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है।
प्रस्तावना में प्रयुक्त "संप्रभु" शब्द यह घोषित करता है कि भारत एक पूरी तरह से स्वतंत्र देश है। इसका अर्थ यह है कि भारत न तो किसी अन्य विदेशी राष्ट्र पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। भारत को अपने आंतरिक मामलों का संचालन करने तथा अपनी विदेश नीति तय करने का पूर्ण अधिकार है, जिसमें कोई भी विदेशी शक्ति या अंतर्राष्ट्रीय संस्था हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भारत अपने भूभाग का विस्तार या हस्तांतरण भी कर सकता है।

79. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
अनुच्छेद 51A(a) के तहत राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। वहीं, बिजॉय इमैनुएल बनाम केरल राज्य मामला (1986) में उच्चतम न्यायालय ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया कि यदि किसी व्यक्ति के सच्चे धार्मिक विश्वास उसे राष्ट्रगान गाने से रोकते हैं (जैसे यहोवा के साक्षी), तो उसे इसे गाने के लिए बाध्य करना अनुच्छेद 19(1)(a) और 25 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

80. (B) राष्ट्र की एकता और अखंडता
भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से यह घोषणा करती है कि बंधुता का आदर्श दो मुख्य बातों का निष्ठापूर्वक आश्वासन प्रदान करता है: पहली, "व्यक्ति की गरिमा" और दूसरी, "राष्ट्र की एकता और अखंडता"। मूल प्रस्तावना में केवल "राष्ट्र की एकता" शब्द मौजूद था, परंतु 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें "और अखंडता" शब्द भी जोड़ा गया, ताकि देश की भौगोलिक और सांस्कृतिक अखंडता को मजबूती दी जा सके।

81. (A) स्वर्ण सिंह समिति
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश वर्ष 1976 में गठित स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई थी। आपातकाल के समय कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था। समिति ने सुझाव दिया कि अधिकारों के साथ-साथ नागरिकों के कर्तव्यों का भी संविधान में उल्लेख होना चाहिए। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग IVA और अनुच्छेद 51A संविधान में जोड़ा गया।

82. (B) महान आदर्शों को संजोने जैसे कर्तव्य अमूर्त अवधारणाएं हैं जिन्हें कानूनी रूप से लागू करना कठिन है।
मूल कर्तव्यों को अदालतों द्वारा सीधे प्रवर्तनीय न बनाने का सबसे उपयुक्त तर्क यह है कि इनमें से कई कर्तव्य नैतिक, दार्शनिक और अमूर्त प्रकृति के हैं। उदाहरण के लिए, "स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को संजोना" या "वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना" जैसे कर्तव्यों का कानूनी रूप से मूल्यांकन करना या उल्लंघन साबित करना अत्यधिक कठिन है। इसलिए इन्हें अदालतों द्वारा सीधे लागू करने के बजाय नागरिकों के नैतिक दायित्व के रूप में रखा गया है।

83. (A) भारत में सदियों से घुली-मिली विविध भाषाई और धार्मिक परंपराएं
अनुच्छेद 51A(f) में उल्लिखित "सामासिक संस्कृति" (कंपोजिट कल्चर) का तात्पर्य भारत की उस समृद्ध सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत से है, जो सदियों से विभिन्न धर्मों, भाषाओं, जातियों, नस्लों और क्षेत्रों के मेलजोल से विकसित हुई है। यह बहुलतावादी और सह-अस्तित्व की भावना का प्रतिनिधित्व करती है। यह कर्तव्य प्रत्येक नागरिक को यह सीख देता है कि वह किसी एक विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को थोपने के बजाय इस मिली-जुली सामासिक संस्कृति की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे।

84. (B) इसने दस मूल कर्तव्यों को निर्दिष्ट करते हुए एक एकल अनुच्छेद 51A पेश किया।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग IVA जोड़ा गया, जिसमें केवल एक एकल अनुच्छेद 51A शामिल था। इस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल रूप से दस मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि ये कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं, गैर-नागरिकों पर नहीं, और ये सीधे तौर पर रिटों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। अतः विकल्प (B) में दिया गया कथन पूर्णतः सत्य और सटीक है।

85. (B) सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले न्याय को एक विशिष्ट और निश्चित क्रम में रेखांकित किया गया है। प्रस्तावना का पाठ स्पष्ट रूप से "सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय" को प्राथमिकता देता है। यह क्रम इस संवैधानिक दर्शन को दर्शाता है कि राजनीतिक न्याय तब तक अधूरा और प्रभावहीन रहेगा जब तक कि समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय की नींव मजबूत न हो। इसलिए सामाजिक न्याय को सबसे पहले स्थान दिया गया है।

86. (D) पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देना
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक), पांच प्रकार की स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना), समता और बंधुता

NODIA

को मुख्य उद्देश्यों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देना प्रस्तावना का सीधा पाठ नहीं है, बल्कि यह संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 39(d) के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्वों का एक प्रावधान है।

87. (D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
भारत 26 जनवरी 1950 को एक गणराज्य बना, जब भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था, परंतु गणराज्य का दर्जा 1950 में मिला। गणराज्य होने का मुख्य अर्थ यह है कि राज्य का सर्वोच्च प्रमुख निर्वाचित होता है, न कि कोई वंशानुगत सम्राट। इसलिए कथन I गलत है और कथन II सही है।

88. (B) ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयत्न और उपलब्धि के नए स्तरों की ओर बढ़े
अनुच्छेद 51A(j) नागरिकों से यह अपेक्षा करता है कि वे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का निरंतर प्रयास करें। इस कर्तव्य का स्पष्ट घोषित संवैधानिक उद्देश्य यह है कि जब प्रत्येक नागरिक अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करेगा, तो समग्र रूप से पूरा राष्ट्र निरंतर प्रयत्न और उपलब्धि के नए और उच्चतर स्तरों को छुएगा। यह कर्तव्य व्यक्तिगत विकास को राष्ट्रीय प्रगति और विकास से जोड़ता है।

89. (C) अनुच्छेद 51A(i)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(i) के तहत प्रत्येक नागरिक का यह स्पष्ट मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह "सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे"। यह प्रावधान सार्वजनिक आंदोलनों या प्रदर्शनों के दौरान होने वाली तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा की घटनाओं को रोकने तथा सरकारी व सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करने के उद्देश्य से जोड़ा गया है। नागरिक समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कर्तव्य अत्यंत आवश्यक है।

90. (C) प्रस्तावना संसदीय कानून को रद्द करने के लिए एक स्वतंत्र उपकरण के रूप में कार्य कर सकती है।
प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मंशा को समझने की कुंजी है और इसे केशवानंद भारती मामले के बाद संविधान के मूल ढांचे का भाग माना जाता है। जब अनुच्छेदों की भाषा अस्पष्ट होती है, तब अदालतें प्रस्तावना से मार्गदर्शन लेती हैं। हालांकि, प्रस्तावना गैर-न्यायसंगत है, इसलिए यह किसी संसदीय कानून को सीधे रद्द या अवैध घोषित करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक उपकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकती है। अतः विकल्प (C) गलत व्याख्या है।

91. (A) रूसी क्रांति
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय के तीन रूप—सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय—का आदर्श 1917 की रूसी क्रांति (बोल्शेविक क्रांति) से लिया गया था। रूसी क्रांति ने सामाजिक असमानताओं को दूर करने, संसाधनों के न्यायसंगत वितरण और आम लोगों के राजनीतिक अधिकारों पर बल दिया था। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इन मानवीय और समानतावादी आदर्शों को भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक माना और इन्हें प्रस्तावना में उच्च स्थान दिया।

92. (A) फ्रांसीसी क्रांति
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित "स्वतंत्रता, समता और बंधुता" के प्रसिद्ध आदर्श 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हैं। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा ही "स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व" था, जिसने विश्व भर में लोकतंत्र और मानव अधिकारों की नींव रखी। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इन महान मानवीय मूल्यों को भारतीय लोकतंत्र की आत्मा के रूप में स्वीकार किया और इन्हें प्रस्तावना में शामिल करके नागरिकों के सर्वांगीण विकास का आधार बनाया।

93. (C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। हालांकि, भारतीय लोकतंत्र एक अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतांत्रिक प्रणाली है, न कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में नागरिक सीधे कानूनों पर मतदान (जैसे जनमत संग्रह या उपक्रम) नहीं करते, बल्कि वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों (सांसदों और विधायकों) को चुनते हैं, जो उनकी ओर से शासन चलाते हैं। इसलिए कथन I सही है और कथन II असत्य है।

94. (C) 51A(d)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(d) में नागरिकों का यह मूल कर्तव्य निर्दिष्ट किया गया है कि वे "देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें"। यह कर्तव्य नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय निष्ठा और संकट के समय देश के प्रति समर्पण की भावना को जागृत करता है। इसके तहत युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थितियों में जब भी सरकार नागरिकों का आह्वान करे, उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा और सेवा में तत्पर रहना चाहिए।

95. (A) 8
सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने वर्ष 1976 में संविधान में शामिल करने के लिए मूल रूप से केवल 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। हालांकि, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने समिति की सिफारिशों का विस्तार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग IVA में कुल 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया था। बाद में 2002 में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। अतः समिति द्वारा सुझाई गई मूल संख्या केवल 8 ही थी।

96. (A) जाति, नस्ल या लिंग के सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार
प्रस्तावना में निहित "सामाजिक न्याय" का तात्पर्य एक ऐसे समाज के निर्माण से है जहाँ जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई सामाजिक भेदभाव न किया जाए। इसका अर्थ है कि समाज के

Click Here to Buy book on Amazon

सभी वर्गों को समान सामाजिक स्थिति प्राप्त हो और पिछड़े या वंचित वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। यह किसी संपत्ति के जबरन वितरण या निजी संपत्ति के खात्मे की बात नहीं करता है।

97. (D) व्यक्तिगत गतिविधियों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना
अनुच्छेद 51A(e) का मुख्य ध्यान भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देने पर है। इसमें धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं से परे जाने तथा स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने का स्पष्ट उल्लेख है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना अनुच्छेद 51A(j) के तहत एक अलग मूल कर्तव्य है, जो समरसता वाले 51A(e) का हिस्सा नहीं है।

98. (C) भाग IVA
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को एक विशिष्ट नए भाग में रखा गया है जिसे "भाग IVA" के नाम से जाना जाता है। इस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल है। मूल संविधान (1949) में यह भाग मौजूद नहीं था; इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था। भाग III में मौलिक अधिकार और भाग IV में राज्य के नीति निदेशक तत्व निहित हैं।

99. (B) संसद उपयुक्त विधान द्वारा उन्हें लागू करने के लिए स्वतंत्र है।
यद्यपि मूल कर्तव्य स्वयं में गैर-न्यायसंगत हैं और सीधे अदालतों द्वारा रिटों के माध्यम से प्रवर्तनीय नहीं हैं, परंतु संसद के पास यह पूर्ण अधिकार है कि वह उपयुक्त कानून या विधान बनाकर किसी भी मूल कर्तव्य को लागू कर सकती है। संसद ऐसे कानूनों के माध्यम से कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान भी कर सकती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आदि इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। अतः विकल्प (B) बिल्कुल सही है।

100. (B) सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करता है और धर्म के प्रति तटस्थता बनाए रखता है
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में "पंथनिरपेक्ष" शब्द का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक या राज्य-धर्म नहीं है। राज्य धार्मिक मामलों में पूर्ण तटस्थता बनाए रखता है और भारत में मौजूद सभी धर्मों को समान सम्मान, संरक्षण और समर्थन प्रदान करता है। इसका तात्पर्य धर्म-विरोध नहीं है, बल्कि यह सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने तथा उसका प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

101. (D) 86वां संशोधन अधिनियम
माता-पिता या अभिभावकों द्वारा अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने से संबंधित 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। इस संशोधन ने अनुच्छेद 51A में खंड (k) को अंतःस्थापित किया। इसी संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A को जोड़कर प्राथमिक शिक्षा को बच्चों का एक मौलिक अधिकार भी बनाया गया था, जिससे देश में शिक्षा का प्रसार हो सके।

102. (B) प्रतिष्ठा का अर्थ विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति है, जबकि अवसर का अर्थ व्यक्तिगत विकास के लिए समान अवसर है।
'प्रतिष्ठा की समता' और 'अवसर की समता' में स्पष्ट अंतर है। प्रतिष्ठा की समता का अर्थ है समाज में जन्म, जाति या वंश के आधार पर मिलने वाले विशेष विशेषाधिकारों का पूर्ण अभाव होना, ताकि हर नागरिक समान सामाजिक सम्मान प्राप्त कर सके। वहीं, अवसर की समता का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के अपने कौशलों और क्षमताओं के पूर्ण विकास के लिए निष्पक्ष और समान परिस्थितियाँ उपलब्ध कराई जाएँ।

NODIA

103. (D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
प्रस्तावना संविधान का समापन भाग न होकर उसकी भूमिका या प्रारंभिक परिचय है। यह संपूर्ण संविधान के प्रारंभ में स्थित है और इसके मुख्य दर्शन, उद्देश्यों तथा संवैधानिक मूल्यों को संक्षेप में व्यक्त करती है। संविधान निर्माताओं के मूलभूत विचारों और राष्ट्र के दीर्घकालिक लक्ष्यों का समावेश इसी में है। इसलिए पहला कथन कि प्रस्तावना समापन भाग है असत्य है, जबकि दूसरा कथन कि यह संवैधानिक मूल्यों का परिचय है, पूरी तरह सत्य है।

104. (B) यह अनुच्छेद 49 के तहत राज्य के नीति का निदेशक तत्व है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 राज्य पर यह दायित्व डालता है कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक संस्मारक, स्थान या वस्तु का विरूपण, विनाश या निर्यात से संरक्षण करे। यह प्रावधान संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का एक हिस्सा है, न कि नागरिकों का अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्य।

105. (C) मूल कर्तव्य
"हमारी सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका परिरक्षण करना" भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(f) के तहत स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध एक मूल कर्तव्य है। यह प्रावधान प्रत्येक भारतीय नागरिक से यह अपेक्षा करता है कि वह भारत की बहुलवादी, विविधतापूर्ण और मिली-जुली सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करे और उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखे। यह राज्य का नीति निदेशक तत्व या मूल अधिकार नहीं बल्कि नागरिक कर्तव्य है।

106. (B) भारत सरकार अधिनियम, 1919
भारत के संवैधानिक दर्शन के प्राथमिक स्रोतों में 1946 का उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान की प्रस्तावना और भाग IV में निहित राज्य के नीति निदेशक तत्व प्रमुखता से शामिल हैं। ये दस्तावेज स्वतंत्रता, समानता, न्याय और कल्याणकारी राज्य के मूलभूत दर्शन को अभिव्यक्त करते हैं। इसके विपरीत, औपनिवेशिक

काल का भारत सरकार अधिनियम 1919 मुख्य रूप से सीमित प्रशासनिक संरचना से संबंधित था और इसे स्वतंत्र भारत के उदार संवैधानिक दर्शन का स्रोत नहीं माना जाता।

107. (B) यह दिखाना कि नागरिकों के दायित्व नीति निदेशक तत्वों के तहत राज्य के दायित्वों के समानांतर हैं
मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग IV (राज्य के नीति निदेशक तत्व) के ठीक बाद भाग IVA में रखने का मुख्य तार्किक औचित्य यह दर्शाना था कि जिस प्रकार भाग IV राज्य के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाने के मार्गदर्शक दायित्व निर्धारित करता है, उसी प्रकार भाग IVA नागरिकों के लिए राष्ट्र निर्माण में उनके समानांतर दायित्व तय करता है। यह व्यवस्था राज्य और नागरिकों के कर्तव्यों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन स्थापित करती है।

108. (C) आंतरिक और बाहरी मामलों पर पूर्ण अधिकार के साथ स्वतंत्र है
प्रस्तावना द्वारा भारत को 'संप्रभु' घोषित करने का स्पष्ट तात्पर्य यह है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों के संचालन में पूरी तरह स्वतंत्र और सर्वोच्च है। भारत पर किसी भी विदेशी देश, संस्था या बाहरी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। भारत अपनी इच्छा अनुसार नीतियां बनाने, अंतरराष्ट्रीय संधियां करने, अपने क्षेत्र में कानून लागू करने तथा आवश्यकता पड़ने पर अपने भूभाग को किसी अन्य देश को सौंपने या अर्जित करने के लिए पूर्णतः सक्षम है।

109. (C) केशवानंद भारती मामला (1973)
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान के "मूल ढांचे का सिद्धांत" (बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन) प्रतिपादित किया था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है और वह संविधान के मूल ढांचे या प्रस्तावना में निहित उसके मौलिक मूल्यों को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती है। यह निर्णय भारतीय संविधान की रक्षा में एक मील का पत्थर है।

110. (A) आर्थिक न्याय – अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17)
प्रस्तावना के विभिन्न आदर्शों को संविधान के अनुच्छेदों के माध्यम से साकार किया गया है। अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17) मुख्य रूप से "सामाजिक न्याय" और सामाजिक समता स्थापित करने से संबंधित है, न कि केवल "आर्थिक न्याय" से। अन्य सभी युग्म सही सुमेलित हैं: राजनीतिक न्याय का संबंध सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (अनुच्छेद 326) से है, अवसर की समता का संबंध अनुच्छेद 16 से है और धार्मिक स्वतंत्रता का संबंध अनुच्छेद 25-28 से है।

111. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभिक वाक्य "हम, भारत के लोग" है और इसका समापन वाक्य "एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं" पर होता है। यह दर्शाता है कि संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत जनता है। प्रारुप समिति ने प्रस्तावना को सर्वसमावेशी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए इसमें जानबूझकर किसी विशिष्ट राजनीतिक दल, नेता या धर्म का नाम शामिल नहीं किया। अतः दोनों कथन पूरी तरह सत्य हैं।

112. (B) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को
अनुच्छेद 51A(b) के तहत नागरिकों का यह एक प्रमुख मूल कर्तव्य है कि वे "स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें"। इन उच्च आदर्शों में अहिंसा, राष्ट्रीय एकता, पंथनिरपेक्षता, देशभक्ति, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व शामिल हैं। इस कर्तव्य का उद्देश्य भावी पीढ़ियों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के त्याग, बलिदान और मूल्यों से निरंतर जोड़े रखना तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है।

113. (C) प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के तहत वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना तथा सभी जीव-जंतुओं के प्रति दयाभाव रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का एक स्पष्ट मूल कर्तव्य बनाया गया है। यद्यपि वन्यजीव संरक्षण के लिए संसद ने पृथक कानून भी बनाए हैं, परंतु संविधान के ढांचे में इसे नागरिकों के एक मौलिक नैतिक और पर्यावरण उत्तरदायित्व के रूप में संरचित किया गया है।

114. (A) सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र
प्रस्तावना में प्रयुक्त "लोकतांत्रिक" शब्द केवल चुनाव या सरकार चुनने जैसे राजनीतिक लोकतंत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ है जीवन में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को एक साथ स्वीकार करना तथा विषमताओं को समाप्त करना।

115. (D) निजी संपत्ति का पूर्ण अधिकार
प्रस्तावना से प्राप्त संविधान के मूल ढांचे में भारत की संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य प्रकृति, पंथनिरपेक्ष चरित्र, संविधान की सर्वोच्चता, तथा न्याय और स्वतंत्रता के आदर्श शामिल हैं, जिन्हें संसद भी समाप्त नहीं कर सकती। इसके विपरीत, निजी संपत्ति का अधिकार कभी भी मूल ढांचे का हिस्सा नहीं रहा है। वास्तव में, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर केवल एक विधिक अधिकार (अनुच्छेद 300A) बना दिया गया था।

116. (C) इसे राज्य द्वारा "आह्वान किए जाने पर" निष्पादित किया जाना चाहिए।
अनुच्छेद 51A(d) नागरिकों से "देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने" की अपेक्षा करता है। इस मूल कर्तव्य की एक स्पष्ट संवैधानिक सीमा यह है कि नागरिक अपनी मर्जी से स्वतः सैन्य या रक्षा संबंधी कदम नहीं उठा सकते, बल्कि इस कर्तव्य का पालन तब अनिवार्य होता है जब

Downloaded from www.pdf.tube

राज्य या सरकार द्वारा औपचारिक रूप से ऐसा करने का आह्वान या निर्देश दिया जाए। यह व्यवस्था अनधिकृत गतिविधियों को रोकती है।

117. (A) के.एम. मुंशी
संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक प्रमुख सदस्य डॉ. के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को "हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्मकुंडली" (हॉरोस्कोप) के रूप में वर्णित किया था। उनका मानना था कि जिस प्रकार एक जन्मकुंडली किसी व्यक्ति के भावी जीवन और उसके मूलभूत लक्षणों का खाका प्रस्तुत करती है, उसी प्रकार प्रस्तावना भी भारत के भावी लोकतांत्रिक राज्य के स्वरूप, सिद्धांतों और अंतिम लक्ष्यों का स्पष्ट खाका प्रस्तुत करती है।

118. (C) इसने संविधान से गैर-न्यायसंगत कर्तव्यों को हटाने की सिफारिश की।
वर्ष 1999 में गठित न्यायमूर्ति वर्मा समिति का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को मूल कर्तव्य सिखाने और उनके क्रियान्वयन के लिए रणनीतियाँ सुझाना था। समिति ने कई मौजूदा कानूनी प्रावधानों की पहचान की जो कर्तव्यों को लागू करने में मदद करते हैं, जैसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। हालांकि, यह कहना गलत है कि समिति ने संविधान से गैर-न्यायसंगत कर्तव्यों को हटाने की सिफारिश की थी; वास्तव में समिति ने कर्तव्यों की जन-जागरूकता और प्रवर्तन का समर्थन किया था।

119. (A) कृत्रिम वर्ग की उपाधियाँ और विशेषाधिकार
प्रस्तावना में निहित "प्रतिष्ठा की समता" का मुख्य उद्देश्य समाज में जन्म, वंश, जाति या वर्ग के आधार पर निर्मित कृत्रिम विशेषाधिकारों और उपाधियों को समाप्त करना है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून की नज़र में सभी नागरिक समान प्रतिष्ठा रखते हैं और किसी भी व्यक्ति को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। इसे लागू करने के लिए ही संविधान के अनुच्छेद 18 द्वारा सेना और विद्या संबंधी सम्मानों को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों का अंत किया गया है।

120. (C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया है कि किसी कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करते समय, यदि वह कानून किसी मूल कर्तव्य को प्रभावी बनाता है, तो अदालत उसे अनुच्छेद 14 या 19 के तहत 'युक्तियुक्त प्रतिबंध' मान सकती है। हालांकि, केवल किसी मूल कर्तव्य का उल्लंघन होने के आधार पर किसी कानून को स्वतः रद्द नहीं किया जा सकता। इसलिए पहला कथन सही है और दूसरा कथन असत्य है, क्योंकि कानून की रद्दीकरण प्रक्रिया संवैधानिक अनुच्छेदों पर आधारित होती है।

121. (A) विभाजनकारी क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता पर काबू पाना
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में "अखंडता" (इंटीग्रिटी) शब्द को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य देश में पनपने वाली पृथकतावादी प्रवृत्तियों, विभाजनकारी क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और भाषावाद पर काबू पाना था। यह शब्द भारत की भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक अखंडता को अक्षुण्ण रखने का दृढ़ संवैधानिक संकल्प व्यक्त करता है। यह स्पष्ट करता है कि भारत विविधताओं के बावजूद एक अविभाज्य राष्ट्र है जिसकी प्रादेशिक अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

122. (B) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना
अनुच्छेद 51A(i) के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह स्पष्ट मूल कर्तव्य है कि वह "सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे"। यह कर्तव्य देश की राष्ट्रीय और सार्वजनिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा पर बल देता है। वनों और नदियों का संरक्षण अनुच्छेद 51A(g) के अंतर्गत आता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास अनुच्छेद 51A(h) में शामिल है, तथा देश की रक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 51A(d) में किया गया है।

NODIA

123. (C) यह संविधान के मौलिक मूल्यों और दर्शन को समाहित करती है।
प्रस्तावना संविधान की व्याख्या करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी साधन के रूप में कार्य करती है क्योंकि यह संविधान के मौलिक मूल्यों, आदर्शों और अंतर्निहित दर्शन को संक्षेप में समाहित करती है। जब संविधान के किसी विशिष्ट अनुच्छेद का अर्थ अस्पष्ट, संदिग्ध या बहुअर्थी प्रतीत होता है, तब न्यायपालिका निर्माताओं के वास्तविक उद्देश्यों को समझने और सही अर्थ निकालने के लिए प्रस्तावना में निहित प्रकाश स्तंभ रूपी सिद्धांतों की सहायता लेती है।

124. (D) न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना
अनुच्छेद 51A के तहत सूचीबद्ध मूल कर्तव्यों में संविधान का पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना, तथा सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रयास करना शामिल है। हालांकि, "न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना" नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं के लिए राज्य के नीति का एक निदेशक तत्व (डीपीएसपी) है।

125. (B) भाग III (मूल अधिकार)
प्रस्तावना नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की गारंटी का संकल्प देती है। इन स्वतंत्रताओं को धरातल पर उतारने और कानूनी रूप से प्रवर्तनीय बनाने के लिए संविधान का भाग III (मूल अधिकार) प्राथमिक कानूनी तंत्र प्रदान करता है। विशेष रूप से अनुच्छेद 19 (वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 25 से 28 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) प्रस्तावना में घोषित इन स्वतंत्रताओं को अदालतों के माध्यम से सीधे सुरक्षा और प्रवर्तनीयता प्रदान करते हैं।

126. (A) वे केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं।
भारतीय संविधान के भाग IVA (अनुच्छेद 51A) में निहित मूल कर्तव्यों के लागू होने की सीमा अत्यंत स्पष्ट है; वे केवल और केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं। ये कर्तव्य भारत में रहने या कार्य करने वाले विदेशी नागरिकों, विदेशी

निगमों अथवा अंतरराष्ट्रीय कंपनियों पर बाध्यकारी नहीं हैं। यह व्यवस्था कुछ मौलिक अधिकारों से भिन्न है, जो भारत की भूमि पर विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। अतः विकल्प (A) सही है।

127. (A) एस. आर. बोम्मई मामला (1994)
एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामला (1994) में उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से यह सिद्धांत स्थापित किया कि 'पंथनिरपेक्षता' (सेकुलरिज्म) भारतीय संविधान की एक "मूल विशेषता" (बेसिक स्ट्रक्चर) है। न्यायालय ने यह माना कि यदि कोई राज्य सरकार पंथनिरपेक्षता के विरुद्ध कार्य करती है या सांप्रदायिक नीतियां अपनाती है, तो उसके विरुद्ध अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि पंथनिरपेक्षता संविधान की आत्मा है।

128. (B) राज्य को नागरिकों के बीच उनके कर्तव्यों के बारे में सक्रिय जागरूकता पैदा करनी चाहिए।
संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग (एनसीआरडब्ल्यूसी) ने मूल कर्तव्यों के संदर्भ में यह सिफारिश की थी कि सरकार और राज्य को नागरिकों के बीच उनके कर्तव्यों के बारे में सक्रिय रूप से जागरूकता पैदा करनी चाहिए। आयोग ने सुझाव दिया कि शिक्षा प्रणाली और जनसंचार के माध्यम से इन कर्तव्यों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि नागरिक अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग हों, न कि इन्हें हटाने या सीमित करने की बात कही थी।

129. (D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
प्रस्तावना का "हम, भारत के लोग" वाक्यांश यह दर्शाता है कि संविधान की अंतिम सत्ता और संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, जिसने संविधान सभा में अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान का निर्माण किया। 1949 में प्रत्येक नागरिक द्वारा प्रत्यक्ष वोट नहीं डाला गया था, क्योंकि संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। इसलिए पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सत्य है कि सत्ता प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता से प्राप्त हुई है।

130. (A) तर्कसंगत सोच, अंधविश्वास से लड़ने और प्रगतिशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर
अनुच्छेद 51A(h) के तहत "वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करने" के मूल कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में तर्कसंगत सोच को बढ़ाना, अंधविश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ना और एक प्रगतिशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। यह नागरिकों को बिना सोचे-समझे पुरानी रूढ़ियों को मानने के बजाय तार्किक विचार अपनाने और निरंतर सुधार की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, न कि धर्म को नष्ट करने के लिए।

Click Here to Buy book on Flipkart

अध्याय 05
मौलिक अधिकार

NODIA

1. भारत के संविधान का कौन-सा भाग मूल अधिकारों से विस्तृत रूप से संबंधित है?
(A) भाग II
(B) भाग III
(C) भाग IV
(D) भाग IVA

2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारत में मूल अधिकारों की प्राथमिक प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) ये निरपेक्ष हैं और किसी भी स्थिति में इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।
(B) ये न्याययोग्य नहीं हैं और राज्य के लिए केवल दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करते हैं।
(C) ये केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं।
(D) ये कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका के मनमाने कानूनों पर सीमा के रूप में कार्य करते हैं।

3. वर्तमान में भारत के संविधान द्वारा मूल अधिकारों की कितनी श्रेणियाँ प्रदान की गई हैं?
(A) पाँच
(B) छह
(C) सात
(D) आठ

4. निम्नलिखित में से कौन-सा मूल अधिकार नागरिकों और विदेशियों (शत्रु देश के नागरिकों को छोड़कर) दोनों को प्राप्त है?
(A) लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता
(B) अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण
(C) प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
(D) वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

5. मूल संविधान में मूल अधिकारों की सात श्रेणियाँ थीं। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस श्रेणी को हटा दिया गया था?
(A) संपत्ति का अधिकार
(B) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
(C) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(D) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

6. अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसमें भारत की सरकार और संसद शामिल हैं।
II. इसमें प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल शामिल हैं।
III. इसमें नगरपालिका और पंचायत जैसे स्थानीय प्राधिकारी शामिल नहीं हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

7. अनुच्छेद 12 की न्यायिक व्याख्याओं के अनुसार, न्यायपालिका कब "राज्य" की परिभाषा के अंतर्गत आती है?
(A) जब वह दो निजी पक्षों के बीच विवाद में कोई न्यायिक आदेश पारित कर रही हो
(B) जब वह अपने प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करती हो
(C) जब वह अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो
(D) अनुच्छेद 12 के तहत न्यायपालिका को कभी भी राज्य नहीं माना जाता है

8. अनुच्छेद 12 के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किसे राज्य की संस्था के रूप में कार्य करने वाला "अन्य प्राधिकारी" नहीं माना जाता है?
(A) राज्य के नियंत्रण के तहत तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी)
(B) राज्य के नियंत्रण के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)
(C) बिना किसी सार्वजनिक वित्तपोषण या राज्य नियंत्रण वाली एक निजी कंपनी
(D) राज्य के नियंत्रण के तहत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

9. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 "विधि के समक्ष समता" और "विधियों के समान संरक्षण" की गारंटी देता है। "विधियों के समान संरक्षण" की अवधारणा किस संविधान से ली गई है?
(A) ब्रिटिश संविधान
(B) आयरिश संविधान
(C) कैनेडियन संविधान
(D) अमेरिकी संविधान

10. अनुच्छेद 14 के तहत "विधि के समक्ष समता" की अवधारणा एक नकारात्मक अवधारणा है, जिसका तात्पर्य है:

(A) किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी विशेष विशेषाधिकार का न होना
(B) समान परिस्थितियों में समान व्यवहार
(C) हाशिए पर स्थित समुदायों के लिए विशेष आरक्षण
(D) पूर्ण समता जहाँ किसी भी वर्गीकरण की अनुमति नहीं है

11. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत विधि के समक्ष समता के सामान्य नियम का एक संवैधानिक अपवाद है?
(A) संसद सदस्यों को उनके संपूर्ण कार्यकाल के दौरान सिविल कार्यवाहियों से छूट प्राप्त है।
(B) राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने आधिकारिक कर्तव्यों के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं।
(C) विदेशी राजनयिक बिना किसी अपवाद के घरेलू आपराधिक कानूनों के अधीन हैं।
(D) लोक सेवकों को औपचारिक संसदीय प्रस्ताव के बिना बर्खास्त नहीं किया जा सकता है।

12. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: अनुच्छेद
P. अनुच्छेद 14
Q. अनुच्छेद 15
R. अनुच्छेद 16
S. अनुच्छेद 17
सूची II: मूल विषय
1. अस्पृश्यता का अंत
2. लोक नियोजन में अवसर की समता
3. विधि के समक्ष समता
4. विशिष्ट आधारों पर भेदभाव का निषेध
(A) P-3, Q-4, R-2, S-1
(B) P-3, Q-2, R-4, S-1
(C) P-4, Q-3, R-1, S-2
(D) P-1, Q-4, R-2, S-3

13. अनुच्छेद 14 कानून द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन-देन के बोधगम्य वर्गीकरण की अनुमति देता है। ऐसे वर्गीकरण के वैध होने के लिए, यह किस पर आधारित होना चाहिए?
(A) बोधगम्य अंतरक (इंटेलिजेंट डिफरेंशिया) और साध्य उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध (रैशनल नेक्सस)
(B) विधायी दिशा-निर्देशों के बिना प्रयोग किया जाने वाला पूर्ण और मनमाना कार्यपालकीय विवेकाधिकार
(C) क्षेत्र में मौजूद दीर्घकालिक ऐतिहासिक परंपराएँ और सामाजिक रीति-रिवाज़
(D) सभी वर्गीकृत विषयों पर लागू की गई कठोर और विशुद्ध गणितीय समता

14. संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को केवल किन आधारों पर किसी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव करने से रोकता है?
(A) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या निवास
(B) धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या जन्मस्थान
(C) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान
(D) धर्म, जाति, लिंग, उद्भव या जन्मस्थान

15. अनुच्छेद 15(3) के तहत, भेदभाव के सामान्य निषेध के बावजूद, राज्य को निम्नलिखित में से किस समूह के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है?
(A) केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग
(B) केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
(C) केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
(D) महिलाएँ और बच्चे

16. सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में विशेष प्रावधान करने हेतु राज्य को सक्षम बनाने के लिए संविधान में अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया था। किस संशोधन द्वारा यह खंड शामिल किया गया था?
(A) 42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976
(B) 44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978
(C) 93वाँ संशोधन अधिनियम, 2005
(D) 103वाँ संशोधन अधिनियम, 2019

17. कौन-सा मूल अधिकार यह गारंटी देता है कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के संबंध में कोई भी नागरिक किसी भी अयोग्यता या शर्त के अधीन नहीं होगा?
(A) अनुच्छेद 14
(B) अनुच्छेद 15(2)
(C) अनुच्छेद 16(2)
(D) अनुच्छेद 17

18. अनुच्छेद 16 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह राज्य के अधीन नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता की गारंटी देता है।
II. यह धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान या निवास के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।
III. यह संसद को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ नियोजनों के लिए निवास को एक शर्त के रूप में निर्धारित करने की अनुमति देता है।
IV. यह राज्य को पिछड़े वर्गों के पक्ष में पदों के आरक्षण का कोई प्रावधान करने से रोकता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, III और IV
(D) I, II, III और IV

19. मंडल आयोग, जिसने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी, किस संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में गठित किया गया था?
(A) अनुच्छेद 15(3)

NODIA

(B) अनुच्छेद 16(4)
(C) अनुच्छेद 17
(D) अनुच्छेद 18(1)

20. किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16(4A) जोड़ा गया, जो राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति के मामलों में आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार देता है?
(A) 77वाँ संशोधन अधिनियम, 1995
(B) 81वाँ संशोधन अधिनियम, 2000
(C) 85वाँ संशोधन अधिनियम, 2001
(D) 89वाँ संशोधन अधिनियम, 2003

21. अनुच्छेद 16(5) लोक नियोजन में समता के नियम का एक अपवाद प्रदान करता है, जिसके तहत अनुमति दी गई है कि:
(A) धार्मिक संस्थाएँ अपने पदाधिकारियों के लिए उस विशिष्ट धर्म को मानने की शर्त रख सकती हैं
(B) राज्य सरकारें निजी क्षेत्र की नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान कर सकती हैं
(C) राज्य सरकारें समूह D के सभी निचले स्तर के सार्वजनिक पदों के लिए केवल स्थानीय निवासियों को नियुक्त कर सकती हैं
(D) देश के सशस्त्र बल महिला उम्मीदवारों को सक्रिय लड़ाकू भूमिकाओं से पूरी तरह बाहर कर सकते हैं

22. इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला (1992) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 16(4) के तहत कुल आरक्षण सामान्यतः किस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए?
(A) 33%
(B) 50%
(C) 60%
(D) 69%

23. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किसके अंत से संबंधित है?
(A) उपाधियों
(B) अस्पृश्यता
(C) बाल श्रम
(D) बलात् श्रम

24. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): अनुच्छेद 17 घोषित करता है कि अस्पृश्यता का आचरण कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है।
कारण (R): भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में "अस्पृश्यता" शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

25. अनुच्छेद 17 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, संसद ने 1955 में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम पारित किया था। 1976 में इस अधिनियम में व्यापक संशोधन किया गया और इसका नया नाम रखा गया:
(A) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
(B) सामाजिक अयोग्यता उन्मूलन अधिनियम
(C) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम
(D) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम

26. अधिकांश अन्य मूल अधिकारों की तुलना में अनुच्छेद 17 के तहत प्रदान किए गए अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से क्या अद्वितीय है?
(A) यह पूर्ण (निरपेक्ष) है और किसी भी युक्तियुक्त प्रतिबंध के अधीन नहीं है।
(B) राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान इसे स्वतः निलंबित किया जा सकता है।
(C) यह केवल राज्य के विरुद्ध लागू करने योग्य है, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं।
(D) इसका प्रयोग केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय नागरिकों तक सीमित है।

27. संविधान का अनुच्छेद 18 राज्य को कोई भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है। हालाँकि, यह निषेध किस पर लागू नहीं होता है?
(A) कुलीनता की वंशानुगत उपाधियाँ
(B) सैन्य या शैक्षणिक सम्मान
(C) विदेशी राज्यों द्वारा प्रदान की गई उपाधियाँ
(D) जमींदारी जैसी बड़ी भू-संपत्ति से जुड़ी उपाधियाँ

28. बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामला (1996) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा?
(A) रियासतों द्वारा वंशानुगत उपाधियाँ प्रदान करना
(B) राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे भारत रत्न और पद्म विभूषण
(C) भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशी उपाधियों का स्वीकार किया जाना
(D) आधिकारिक दस्तावेजों में नामों के पीछे शैक्षणिक उपाधियों का उपयोग करना

29. अनुच्छेद 18 के अनुसार, यदि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करना चाहता है तो:
(A) कोई भी नागरिक किसी भी परिस्थिति में किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता
(B) भारत की संसद के दोनों सदनों से पूर्व औपचारिक अनुमति प्राप्त करनी होगी
(C) स्वीकार करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की अनिवार्य पूर्व सहमति प्राप्त करनी होगी

Downloaded from www.pdf.tube

(D) विदेश मंत्रालय से एक आधिकारिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा

30. अनुच्छेद 18 के तहत अपवादों और नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई विदेशी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता।
II. पद्म श्री जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के आगे (उपसर्ग) या पीछे (प्रत्यय) के रूप में किया जा सकता है।
III. राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट या उपलब्धि स्वीकार नहीं कर सकता।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

31. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 मूल रूप से नागरिकों को सात स्वतंत्रताओं की गारंटी देता था। इस सूची से किस स्वतंत्रता को हटा दिया गया था?
(A) सम्मेलन की स्वतंत्रता
(B) कोई भी वृत्ति या व्यापार करने की स्वतंत्रता
(C) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता
(D) संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की स्वतंत्रता

32. भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह निम्नलिखित में से किस अधिकार के अंतर्गत अंतर्निहित रूप से गारंटीकृत है?
(A) अनुच्छेद 19(1)(a) - वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
(B) अनुच्छेद 19(1)(b) - शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता
(C) अनुच्छेद 19(1)(g) - कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता
(D) अनुच्छेद 21 - प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

33. अनुच्छेद 19(2) के तहत, राज्य कई आधारों पर वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। निम्नलिखित में से कौन-सा प्रतिबंध का वैध आधार नहीं है?
(A) राज्य की सुरक्षा और संप्रभुता
(B) बहुसंख्यक राजनीतिक समर्थन का अभाव
(C) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
(D) न्यायालय का अवमान या मानहानि

34. क्या अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता में हड़ताल करने का मूल अधिकार शामिल है?
(A) हाँ, हड़ताल का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत ट्रेड यूनियन बनाने में अंतर्निहित एक मूल अधिकार है।
(B) हाँ, हड़ताल का अधिकार विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए गारंटीकृत एक मूल अधिकार है।
(C) नहीं, संघ बनाने का मूल अधिकार ही 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था।
(D) नहीं, हड़ताल का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, बल्कि यह वैधानिक कानूनों द्वारा शासित होता है।

35. किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में "सहकारी समितियाँ" बनाने का अधिकार स्पष्ट रूप से जोड़ा गया था?
(A) 73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992
(B) 86वाँ संशोधन अधिनियम, 2002
(C) 97वाँ संशोधन अधिनियम, 2011
(D) 102वाँ संशोधन अधिनियम, 2018

36. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद 19(1) के तहत गारंटीकृत पहली चार स्वतंत्रताओं का सही क्रमानुसार क्रम दर्शाता है?
(A) वाक् और अभिव्यक्ति → सम्मेलन → संघ/संगम → संचरण
(B) वाक् और अभिव्यक्ति → संघ/संगम → सम्मेलन → संचरण
(C) सम्मेलन → वाक् और अभिव्यक्ति → संचरण → संघ/संगम
(D) वाक् और अभिव्यक्ति → संचरण → सम्मेलन → संघ/संगम

37. अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। कौन-सा विशिष्ट संरक्षण "कार्योत्तर विधि" (ex post facto laws) से संबंधित है?
(A) किसी व्यक्ति को तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय लागू विधि का उल्लंघन न किया हो।
(B) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सक्षम न्यायालय द्वारा अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।
(C) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
(D) गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा।

NODIA

38. अनुच्छेद 20(2) में निहित "दोहरे दंड से संरक्षण" (double jeopardy) के सिद्धांत का अर्थ है कि:
(A) यदि नए साक्ष्य मिलते हैं तो किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए दो बार मुकदमा चलाया जा सकता है।
(B) किसी व्यक्ति को अपराध के समय लागू दंड से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता।
(C) आपराधिक न्यायालय द्वारा बरी किए जाने पर व्यक्ति को विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ सकता।
(D) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से

अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।

39. अनुच्छेद 20(3) के तहत स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने से संरक्षण (आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार) किस प्रकार की कार्यवाहियों पर लागू होता है?
(A) सिविल और आपराधिक दोनों कार्यवाहियों पर
(B) केवल आपराधिक कार्यवाहियों पर
(C) केवल सिविल कार्यवाहियों पर
(D) केवल विभागीय कार्यवाहियों पर

40. क्या अनुच्छेद 20 के तहत संरक्षण विदेशियों को उपलब्ध है?
(A) नहीं, यह केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है।
(B) यह केवल गृह मंत्रालय की अनुमति से विदेशियों को उपलब्ध है।
(C) हाँ, यह नागरिकों, विदेशियों और निगमों जैसे कानूनी व्यक्तियों तक विस्तारित है।
(D) यह केवल नागरिकों और भारत में निगमित निगमों को उपलब्ध है।

41. 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद, सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी कौन-से मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं?
(A) अनुच्छेद 14 और 15
(B) अनुच्छेद 19 और 20
(C) अनुच्छेद 20 और 21
(D) अनुच्छेद 21 और 22

42. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: अनुच्छेद 21 के तहत अंतर्निहित अधिकार
P. निजता का अधिकार
Q. आजीविका का अधिकार
R. विदेश जाने का अधिकार
S. प्राथमिक शिक्षा का अधिकार
सूची II: संबंधित ऐतिहासिक मामला
1. मेनका गांधी मामला
2. उन्नीकृष्णन मामला
3. के.एस. पुट्टस्वामी मामला
4. ओल्गा टेलिस मामला
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-1, Q-2, R-3, S-4
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

43. अनुच्छेद 21 स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से किसके अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं:
(A) विधि की सम्यक प्रक्रिया
(B) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
(C) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत
(D) कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम

44. ऐतिहासिक ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार करते हुए इसमें किसे शामिल किया?
(A) त्वरित सुनवाई का अधिकार
(B) आजीविका का अधिकार
(C) नि:शुल्क कानूनी सहायता का अधिकार
(D) स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार

45. किस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से "निजता के अधिकार" को अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग घोषित किया?
(A) के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ
(B) विशाखा बनाम राजस्थान राज्य
(C) नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ
(D) ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला

46. सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण मुक्त जल और वायु के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा घोषित किया है। यह विस्तार राज्य के नीति निदेशक तत्व के किस अनुच्छेद के साथ अत्यधिक सुसंगत है?
(A) अनुच्छेद 39A
(B) अनुच्छेद 44
(C) अनुच्छेद 48A
(D) अनुच्छेद 50

47. शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाले अनुच्छेद 21A को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था?
(A) 44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978
(B) 73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992
(C) 86वाँ संशोधन अधिनियम, 2002
(D) 97वाँ संशोधन अधिनियम, 2011

48. शिक्षा के अधिकार (अनुच्छेद 21A) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह राज्य को 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का आदेश देता है।
II. इसमें उच्च और पेशेवर शिक्षा का अधिकार शामिल है।
III. इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2009 में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम लागू किया गया था।
IV. इसने अनुच्छेद 45 में मौजूद मूल नीति निदेशक तत्व को प्रतिस्थापित किया, जिसे बाद में शैशवावस्था की देखरेख को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV

Click Here to Buy book on Amazon

(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

49. अनुच्छेद 21A के तहत, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी दी गई है?
(A) 0 से 6 वर्ष
(B) 6 से 14 वर्ष
(C) 6 से 18 वर्ष
(D) 14 से 18 वर्ष

50. अनुच्छेद 21A के शामिल होने से पूर्व, बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मुख्य रूप से संविधान के किस भाग में स्थित था?
(A) भाग IVA के तहत नागरिकों के मूल कर्तव्य
(B) भारत के संविधान की उद्देशिका (प्रस्तावना)
(C) पंचायतों से संबंधित ग्यारहवीं अनुसूची
(D) भाग IV में राज्य के नीति निदेशक तत्व

51. अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। संवैधानिक ढांचा हिरासत को दो श्रेणियों में विभाजित करता है, जो हैं:
(A) दंडात्मक और निवारक हिरासत (निरोध)
(B) सिविल हिरासत और आपराधिक हिरासत
(C) कार्यपालकीय हिरासत और न्यायिक हिरासत
(D) अस्थायी हिरासत और स्थायी हिरासत

52. अनुच्छेद 22 में दंडात्मक हिरासत के तहत प्राप्त संरक्षण के अनुसार, गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को यात्रा के समय को छोड़कर अधिकतम कितनी अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए?
(A) यात्रा का समय छोड़कर 12 घंटे
(B) यात्रा का समय छोड़कर 24 घंटे
(C) यात्रा का समय छोड़कर 48 घंटे
(D) यात्रा का समय छोड़कर 72 घंटे

53. अनुच्छेद 22 के निवारक निरोध (हिरासत) के प्रावधानों के तहत, किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना सामान्यतः कितने समय से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है?
(A) 1 माह
(B) 2 माह
(C) 3 माह
(D) 6 माह

54. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): सामान्य गिरफ्तारी से संबंधित अनुच्छेद 22 के संरक्षण किसी शत्रु देश के नागरिक (शत्रु अन्य देशीय) पर लागू नहीं होते हैं।
कारण (R): भारत का संविधान किसी शत्रु देश के व्यक्तियों को दंडात्मक गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रक्रियात्मक संरक्षण देने से इनकार करता है।
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

55. संविधान का अनुच्छेद 23 स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस प्रथा का निषेध करता है?
(A) जोखिम भरे कारखानों में छोटे बच्चों का नियोजन
(B) मानव दुर्व्यापार और बेगार (जबरन श्रम)
(C) राज्य द्वारा वित्तपोषित विद्यालयों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा
(D) राज्य द्वारा गैर-शैक्षणिक उपाधियाँ प्रदान किया जाना

56. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद 23 के तहत अनुमति प्राप्त एक संवैधानिक अपवाद है?
(A) राष्ट्रीय आर्थिक संकट के दौरान राज्य कानूनी रूप से व्यक्तियों को बिना वेतन के वाणिज्यिक श्रम के लिए बाध्य कर सकता है।
(B) निजी जमींदार पारंपरिक खेतिहर किरायेदारों से प्रथागत अवैतनिक कृषि श्रम करा सकते हैं।
(C) राज्य सैन्य या सामाजिक सेवा जैसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है।
(D) निजी निगम डिग्री पूरी करने की शर्त के रूप में दीर्घकालिक अवैतनिक इंटर्नशिप अनिवार्य कर सकते हैं।

57. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 और बंधुआ श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 मुख्य रूप से अपना संवैधानिक जनादेश कहाँ से प्राप्त करते हैं?
(A) अनुच्छेद 21
(B) अनुच्छेद 23
(C) अनुच्छेद 24
(D) अनुच्छेद 39(a)

NODIA

58. क्या अनुच्छेद 23 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार गैर-नागरिकों को उपलब्ध है?
(A) हाँ, यह नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों को उपलब्ध है।
(B) नहीं, यह केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित है।
(C) यह गैर-नागरिकों को केवल तभी उपलब्ध है जब उनके पास एम्प्लॉयमेंट वीजा हो।
(D) यह केवल राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों को उपलब्ध है।

59. अनुच्छेद 24 किसी कारखाने, खान या अन्य जोखिम वाले नियोजन में एक निश्चित आयु से कम के बच्चों के नियोजन का निषेध करता है। यह आयु सीमा क्या है?
(A) 12 वर्ष

(B) 14 वर्ष
(C) 16 वर्ष
(D) 18 वर्ष

60. अनुच्छेद 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह जोखिम वाले उद्योगों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है।
II. यह वर्ष 2016 से पूर्व, सुरक्षित और नुकसान न पहुँचाने वाले कार्यों में भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता था।
III. यह जोखिम-रहित घरेलू उद्यमों में बाल श्रम के निषेध को स्पष्ट रूप से कवर नहीं करता है।
मूल संवैधानिक पाठ के आधार पर उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

61. बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 ने किसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नियोजित करने को संज्ञेय अपराध बना दिया?
(A) स्कूल के बाद पारिवारिक उद्यमों में मदद करने को छोड़कर, किसी भी व्यवसाय में
(B) केवल जोखिम वाले व्यवसायों और खतरनाक औद्योगिक प्रक्रियाओं में
(C) बिना किसी अपवाद के किसी भी व्यवसाय या औद्योगिक प्रक्रिया में
(D) केवल सरकारी क्षेत्रों और राज्य द्वारा प्रबंधित सार्वजनिक उद्यमों में

62. बच्चों से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत किस वैधानिक आयोग की स्थापना की गई थी?
(A) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
(B) राष्ट्रीय महिला आयोग
(C) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
(D) केंद्रीय सतर्कता आयोग

63. अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। हालाँकि, यह अधिकार किसके अधीन है?
(A) केवल लोक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा
(B) केवल सदाचार और राष्ट्र की एकता
(C) केवल भारत की संप्रभुता और अखंडता
(D) लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य

64. अनुच्छेद 25 के तहत अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का अर्थ है:
(A) किसी अन्य व्यक्ति को बलपूर्वक या धोखे से अपने धर्म में परिवर्तित करने का पूर्ण अधिकार।
(B) ऐसे धार्मिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार जो पूरी तरह से राज्य द्वारा वित्तपोषित हों।
(C) अपने धार्मिक विश्वासों के सिद्धांतों का दूसरों के समक्ष प्रसार या व्याख्या करने का अधिकार।
(D) किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने और उसका प्रचार करने के लिए सार्वजनिक कर धन का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने का अधिकार।

65. अनुच्छेद 26 के तहत, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धर्म के मामलों में अपने कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी समूह को "धार्मिक संप्रदाय" माने जाने के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा एक अनिवार्य मानदंड नहीं है?
(A) यह विश्वासों की प्रणाली वाले व्यक्तियों का एक संग्रह होना चाहिए।
(B) इसके पास कम से कम 1,00,000 पंजीकृत अनुयायी होने चाहिए।
(C) इसका एक सामान्य संगठन होना चाहिए।
(D) इसे एक विशिष्ट नाम से अभिहित किया जाना चाहिए।

66. मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के मामलों को उनके निर्णय के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
II. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
III. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
IV. मेनका गांधी बनाम भारत संघ
निम्नलिखित में से कौन-सा सही कालानुक्रमिक क्रम है?
(A) II, III, IV, I
(B) III, II, I, IV
(C) II, IV, III, I
(D) IV, II, III, I

67. अनुच्छेद 27 राज्य को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि या रख-रखाव के लिए कोई कर देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य करने से रोकता है। यह अनुच्छेद मुख्य रूप से किसका निषेध करता है?
(A) किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर राजस्व खर्च करने का।
(B) धार्मिक तीर्थयात्रियों को धर्मनिरपेक्ष सेवाएँ प्रदान करने के लिए नियामक शुल्क लगाने का।
(C) धार्मिक संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा अर्जित व्यक्तिगत आय पर सामान्य कराधान का।
(D) निजी व्यक्तिगत नागरिकों को सार्वजनिक धार्मिक ट्रस्टों में स्वेच्छा से धन दान करने का।

68. अनुच्छेद 28 के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से प्रतिबंधित है?
(A) राज्य द्वारा प्रशासित लेकिन किसी बंदोबस्त (एन्डोमेंट) या ट्रस्ट के तहत स्थापित संस्थान

Downloaded from www.pdf.tube

(B) राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान
(C) पूर्णतः राज्य-निधि से पोषित संस्थान
(D) राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान

69. अनुच्छेद 29 प्रावधान करता है कि भारत के राज्यक्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे किसका अधिकार होगा?
(A) उसे बनाए रखने (संरक्षित करने) का
(B) भारत के भीतर स्वायत्त राज्यों की स्थापना करने का
(C) विशेष आर्थिक पैकेज की मांग करने का
(D) पड़ोसी समुदायों पर अपनी भाषा थोपने का

70. भारत का संविधान अनुच्छेद 29 और 30 के प्रयोजनों के लिए "अल्पसंख्यक" शब्द को किस प्रकार परिभाषित करता है?
(A) केवल 50% जनसंख्या से कम की संख्यात्मक शक्ति के आधार पर।
(B) एक अलग अनुसूची में विस्तृत धर्म और भाषा के मानदंडों के संयोजन के आधार पर।
(C) यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान की गई परिभाषा को अपनाता है।
(D) संविधान में कहीं भी "अल्पसंख्यक" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।

71. अनुच्छेद 30 किसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है?
(A) भारत में मान्यता प्राप्त सभी धार्मिक संप्रदायों को
(B) धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को
(C) भारत में मान्यता प्राप्त सभी भाषाई अल्पसंख्यकों को
(D) राज्य में नागरिकों के किसी भी विशिष्ट वर्ग को

72. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: प्रावधान
P. कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता
Q. अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण
R. धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
S. शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अल्पसंख्यकों का अधिकार
सूची II: अनुच्छेद
1. अनुच्छेद 26
2. अनुच्छेद 28
3. अनुच्छेद 29
4. अनुच्छेद 30
(A) P-2, Q-3, R-1, S-4
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-1, Q-2, R-3, S-4
(D) P-2, Q-1, R-3, S-4

73. जब राज्य शिक्षण संस्थाओं को सहायता देता है, तो अनुच्छेद 30(2) के तहत वह किसी शिक्षण संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि:
(A) यह विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए कार्य करती है।
(B) यह राज्य की निर्दिष्ट आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने से स्पष्ट रूप से इनकार करती है।
(C) यह नियमित रूप से योग्य विदेशी नागरिकों को पूर्णकालिक शैक्षणिक शिक्षकों के रूप में नियुक्त करती है।
(D) यह किसी धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।

NODIA

74. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने "संविधान का हृदय और आत्मा" कहा था?
(A) अनुच्छेद 14
(B) अनुच्छेद 19
(C) अनुच्छेद 21
(D) अनुच्छेद 32

75. अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को प्रवर्तित (लागू) कराने के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति किसे प्रदान करता है?
(A) भारत की केंद्रीय संसद
(B) भारत का सर्वोच्च न्यायालय
(C) भारत का राष्ट्रपति
(D) भारत के उच्च न्यायालय

76. अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार के बीच मुख्य अंतर क्या है?
(A) सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानूनी उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए रिट जारी करने तक सीमित हैं।
(B) उच्च न्यायालय मूल अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के लिए रिट जारी करते हैं; सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के लिए जारी करता है।
(C) उच्च न्यायालयों को अधिकार-पृच्छा रिट जारी करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के पास इसे जारी करने की अनन्य शक्ति है।
(D) सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सभी मामलों में विशुद्ध रूप से विवेकाधीन है, जबकि उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।

77. मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है:
(A) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश द्वारा।
(B) संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा।

(C) घोषित न्यायिक संकट के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा।
(D) इसे किसी भी परिस्थिति में कभी निलंबित नहीं किया जा सकता है।

78. अनुच्छेद 32 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह स्वयं में एक मूल अधिकार है।
II. सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक और गारंटीदाता है।
III. संसद किसी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने के लिए सशक्त बना सकती है।
IV. अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनन्य (Exclusive) है और यह उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निष्प्रभावी करता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, II और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

79. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) रिट का शाब्दिक अर्थ है:
(A) हम आदेश देते हैं
(B) प्रमाणित होना
(C) किस अधिकार से
(D) शरीर को प्रस्तुत किया जाए

80. बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है?
(A) केवल सार्वजनिक प्राधिकारियों और राज्य एजेंसियों के विरुद्ध
(B) केवल निजी व्यक्तियों और निगमों के विरुद्ध
(C) सार्वजनिक और निजी दोनों निकायों के विरुद्ध
(D) केवल न्यायिक निकायों और निचले अधिकरणों के विरुद्ध

81. परमादेश (Mandamus) रिट न्यायालय द्वारा किसी लोक अधिकारी को उनके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया गया आदेश है। इसे किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है?
(A) कोई अधीनस्थ न्यायिक न्यायालय
(B) कोई निजी व्यक्ति या निकाय
(C) कोई सार्वजनिक वैधानिक निगम
(D) कोई प्रशासनिक अधिकरण

82. निम्नलिखित में से किस महानुभाव के विरुद्ध उनके आधिकारिक कर्तव्यों के प्रयोग के लिए परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती है?
(A) उनके कार्यकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री
(B) संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री
(C) सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
(D) राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल

83. जहाँ कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान प्रतिषेध (Prohibition) रिट उपलब्ध है, वहीं उत्प्रेषण (Certiorari) रिट जारी की जा सकती है:
(A) अंतिम आदेश जारी होने के बाद
(B) केवल कोई औपचारिक न्यायिक कार्यवाही शुरू होने से पहले
(C) केवल विधायी निकायों और समितियों के विरुद्ध
(D) केवल अशासकीय निजी निगमों के विरुद्ध

84. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध उत्प्रेषण (Certiorari) रिट जारी की जा सकती है।
कारण (R): 1991 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि उत्प्रेषण रिट प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, जिससे इसका दायरा केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों से आगे बढ़ गया।
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

85. अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto) रिट का उपयोग किस लिए किया जाता है?
(A) किसी सार्वजनिक पद के दावे की वैधानिकता की जाँच करने के लिए
(B) किसी सार्वजनिक प्राधिकारी या अधिकारी को अनिवार्य वैधानिक कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने के लिए
(C) किसी निचले न्यायालय या न्यायिक अधिकरण को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकने के लिए
(D) किसी निचले अधिकरण के गैर-कानूनी न्यायिक या प्रशासनिक आदेश को रद्द करने के लिए

86. अन्य रिटों के विपरीत, जिनमें सामान्यतः याचिकाकर्ता का पीड़ित व्यक्ति होना (लोकस स्टैंडाई) आवश्यक होता है, कौन-सी रिट किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा माँगी जा सकती है, भले ही वह सीधे तौर पर पीड़ित न हो?
(A) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(B) परमादेश
(C) प्रतिषेध
(D) अधिकार-पृच्छा

Click Here to Buy book on Flipkart

87. वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के तहत, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति किसमें निहित है?
(A) केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
(B) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में
(C) केवल राज्यों के उच्च न्यायालयों में
(D) स्थानीय जिला न्यायालयों सहित सभी न्यायिक न्यायालयों में

88. संपत्ति का अधिकार, जो प्रारंभ में अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत गारंटीकृत था, किस संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था?
(A) 42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976
(B) 44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978
(C) 73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992
(D) 86वाँ संशोधन अधिनियम, 2002

89. मूल अधिकार के रूप में हटाए जाने के बाद, संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत एक संवैधानिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था?
(A) अनुच्छेद 300A
(B) अनुच्छेद 301
(C) अनुच्छेद 326
(D) अनुच्छेद 350A

90. संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह अब मूल अधिकार नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक अधिकार बना हुआ है।
II. यह कार्यपालकीय कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, लेकिन विधायी कार्रवाई के विरुद्ध नहीं।
III. इसके उल्लंघन के लिए कोई व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

91. भले ही अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया था, फिर भी अनुच्छेद 31A, 31B और 31C को संविधान में बनाए रखा गया। ये अनुच्छेद किसके रूप में कार्य करते हैं?
(A) राज्य को निजी संपत्ति के स्वामित्व को पूरी तरह से समान बनाने का आदेश देने वाले निर्देश
(B) विशिष्ट कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने वाले अपवाद
(C) धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देने वाले संवैधानिक विस्तार
(D) गंभीर आर्थिक स्थितियों के प्रबंधन के लिए विशेष आपातकालीन प्रावधान

92. संविधान के भाग III में सूचीबद्ध मूल अधिकारों की पहली चार श्रेणियों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
(B) स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
(C) समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार
(D) समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार

93. अनुच्छेद 31A कानूनों की पाँच श्रेणियों को अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने से बचाता है। यह मुख्य रूप से किससे संबंधित कानूनों से जुड़ा है?
(A) संपदाओं का अर्जन और संबंधित कृषि सुधार
(B) बैंकों का राष्ट्रीयकरण
(C) शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण नीतियाँ
(D) आंतरिक आपातकाल का लागू होना

94. अनुच्छेद 31B संविधान की एक विशिष्ट अनुसूची में शामिल कानूनों और विनियमों को मान्यता प्रदान करता है, जिससे उन्हें किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने से सुरक्षा मिलती है। यह कौन-सी अनुसूची है?
(A) सातवीं अनुसूची
(B) आठवीं अनुसूची
(C) नौवीं अनुसूची
(D) दसवीं अनुसूची

95. किन विशिष्ट नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 के तहत चुनौती दिए जाने से बचाने के लिए संविधान में अनुच्छेद 31C जोड़ा गया था?
(A) अनुच्छेद 39(a) और 39(d)
(B) अनुच्छेद 39(b) और 39(c)
(C) अनुच्छेद 40 और 43
(D) अनुच्छेद 44 और 45

96. संपत्ति के अधिकार को अंतिम रूप से हटाए जाने से पहले उसमें महत्वपूर्ण बदलाव करने वाले संवैधानिक संशोधनों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) 1वाँ संशोधन → 4वाँ संशोधन → 17वाँ संशोधन → 25वाँ संशोधन
(B) 4वाँ संशोधन → 1वाँ संशोधन → 25वाँ संशोधन → 17वाँ संशोधन
(C) 17वाँ संशोधन → 1वाँ संशोधन → 4वाँ संशोधन → 25वाँ संशोधन
(D) 1वाँ संशोधन → 17वाँ संशोधन → 4वाँ संशोधन → 25वाँ संशोधन

Downloaded from www.pdf.tube

97. अनुच्छेद 33 संसद को निम्नलिखित में से किस समूह के कर्तव्यों के उचित पालन और उनमें अनुशासन बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए उनके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित या निरसित करने का अधिकार देता है?
(A) संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्य
(B) सशस्त्र बलों और पुलिस बलों के सदस्य
(C) अल्पसंख्यक और हाशियाकृत समुदाय
(D) अनिवासी भारतीय और भारत के प्रवासी नागरिक

98. युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 किस मूल अधिकार के स्वतः निलंबन से संबंधित है?
(A) अनुच्छेद 14
(B) अनुच्छेद 19
(C) अनुच्छेद 21
(D) अनुच्छेद 32

99. अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकृत करता है। इस निलंबन के लिए किसकी आवश्यकता होती है?
(A) निलंबित अधिकारों को निर्दिष्ट करने वाले एक राष्ट्रपति के आदेश की
(B) बिना किसी राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता के स्वतः संवैधानिक लागू होने की
(C) सभी राज्य विधानमंडलों के बहुमत द्वारा पारित एक पूर्व औपचारिक प्रस्ताव की
(D) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी एक आधिकारिक कार्यपालकीय आदेश की

100. 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने यह घोषित करके अनुच्छेद 358 के दायरे को सीमित कर दिया कि अनुच्छेद 19 के तहत छह स्वतंत्रताओं को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर घोषित किया गया हो?
(A) व्यापक आंतरिक अशांति
(B) आसन्न या सक्रिय सशस्त्र विद्रोह
(C) युद्ध या बाह्य आक्रमण
(D) गंभीर वित्तीय अस्थिरता

101. यदि राष्ट्रपति अन्य अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करते हुए अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करते हैं, तब भी कौन-से मूल अधिकार लागू (प्रवर्तनीय) रहते हैं?
(A) अनुच्छेद 14 और 15
(B) अनुच्छेद 19 और 20
(C) अनुच्छेद 20 और 21
(D) अनुच्छेद 21 और 22

102. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: अनुच्छेद
P. अनुच्छेद 31C
Q. अनुच्छेद 33
R. अनुच्छेद 34
S. अनुच्छेद 358
सूची II: अपवाद/निलंबन से संबंधित प्रावधान
1. मार्शल लॉ लागू रहने के दौरान अधिकारों पर प्रतिबंध
2. आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन
3. सशस्त्र बलों के लिए अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति
4. कुछ नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति (संरक्षण)
(A) P-4, Q-3, R-1, S-2
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-4, Q-1, R-3, S-2
(D) P-2, Q-3, R-1, S-4

103. ऐतिहासिक गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि:
(A) संसद के पास संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की असीमित संप्रभु शक्ति है।
(B) मूल अधिकार अपरिवर्तनीय हैं और इन्हें छीनने के लिए संशोधन नहीं किया जा सकता है।
(C) राज्य के नीति निदेशक तत्व मूल अधिकारों पर पूर्ण सर्वोच्चता रखते हैं।
(D) उद्देशिका (प्रस्तावना) केवल परिचयात्मक है और इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता है।

NODIA

104. गोलकनाथ निर्णय (1967) ने मूल अधिकारों में संशोधन की क्षमता के संबंध में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए अपने पूर्व रुख को उलट दिया?
(A) शंकरी प्रसाद मामला (1951)
(B) मिनर्वा मिल्स मामला (1980)
(C) वामन राव मामला (1981)
(D) एस.आर. बोम्मई मामला (1994)

105. गोलकनाथ निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने और मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की अपनी शक्ति का दावा करने के लिए संसद ने कौन-सा संवैधानिक संशोधन अधिनियमित किया?
(A) 24वाँ संशोधन अधिनियम, 1971
(B) 25वाँ संशोधन अधिनियम, 1971
(C) 39वाँ संशोधन अधिनियम, 1975
(D) 42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976

106. गोलकनाथ मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने "भविष्यलक्ष्यी निर्णय का सिद्धांत" (Doctrine of Prospective Overruling) लागू किया। इसका तात्पर्य है कि:
(A) यह निर्णय केवल भविष्य के मामलों पर लागू होता है, जिससे अतीत के संवैधानिक संशोधन सुरक्षित रहते हैं।
(B) न्यायिक निर्णय अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी

कानूनों पर भूतलक्षी और भविष्यलक्ष्यी रूप से लागू होगा।
(C) यह निर्णय संसद के मार्गदर्शन के लिए केवल एक गैर-बाध्यकारी सलाहकारी राय के रूप में कार्य करता है।
(D) इस संवैधानिक निर्णय को निकट भविष्य में किसी छोटी न्यायिक पीठ द्वारा स्वतंत्र रूप से बदला जा सकता है।

107. संविधान के "मूल ढाँचे" (Basic Structure) की अवधारणा, जो संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करती है, किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित की गई थी?
(A) ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)
(B) आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
(C) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
(D) एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997)

108. निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए:
I. संविधान की सर्वोच्चता
II. संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र
III. विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण
IV. संविधान का परिसंघीय (संघीय) चरित्र
उपर्युक्त में से किन तत्वों को भारत के संविधान के "मूल ढाँचे" के हिस्से के रूप में पहचाना गया है?
(A) केवल I और II
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, III और IV
(D) I, II, III और IV

109. केशवानंद भारती मामला (1973) भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ द्वारा सुना गया था। इस पीठ का गठन कितने न्यायाधीशों ने किया था?
(A) 9
(B) 11
(C) 13
(D) 15

110. केशवानंद भारती मामले में 24वें संशोधन अधिनियम के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय था?
(A) इसने 24वें संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक और संसदीय शक्ति से परे मानते हुए पूरी तरह से रद्द कर दिया।
(B) इसने निर्णय दिया कि 24वें संशोधन के प्रावधान सख्ती से और केवल नीति निदेशक तत्वों पर लागू होते हैं।
(C) इसने 24वें संशोधन को वैध ठहराया, जिससे संसद को मूल ढाँचे के अधीन रहते हुए अधिकारों में परिवर्तन करने की अनुमति मिली।
(D) इसने कहा कि 24वें संशोधन के लिए सभी राज्य विधानमंडलों के बहुमत से औपचारिक अनुसमर्थन की आवश्यकता है।

111. मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) मामले ने मुख्य रूप से किस मूल अधिकार के दायरे का विस्तार किया?
(A) अनुच्छेद 14
(B) अनुच्छेद 19
(C) अनुच्छेद 21
(D) अनुच्छेद 25

112. मेनका गांधी निर्णय (1978) ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 के बीच एक अंतर्निहित संबंध स्थापित किया, यह जोर देते हुए कि वे परस्पर एक-दूसरे से अलग नहीं हैं। इस अंतर्संबंधित पाठ को प्रसिद्ध रूप से किस नाम से जाना जाता है?
(A) मूल ढांचा सिद्धांत
(B) सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का सिद्धांत
(C) मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज
(D) सार और तत्व का सिद्धांत

113. मेनका गांधी मामले के बाद, किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाले कानून को न केवल "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" का पालन करना चाहिए, बल्कि वह प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए?
(A) संविधान की नौवीं अनुसूची में औपचारिक रूप से संहित
(B) उचित, न्यायसंगत, तर्कसंगत और अ-मनमाना
(C) एक प्रत्यक्ष जनमत संग्रह प्रक्रिया के माध्यम से अनुमोदित
(D) संसद में दो-तिहाई बहुमत द्वारा औपचारिक रूप से अनुसमर्थित

114. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): मेनका गांधी मामले के माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्य रूप से अनुच्छेद 21 में "विधि की सम्यक प्रक्रिया" (Due process of law) की अमेरिकी अवधारणा को पेश किया।
कारण (R): न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया तर्कसंगत, निष्पक्ष और न्यायसंगत होनी चाहिए।
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

115. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने किसके बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन पर बल दिया?
(A) मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच
(B) कार्यपालिका शाखा और केंद्रीय न्यायपालिका के बीच
(C) केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच
(D) केंद्रीय संसद और भारत के राष्ट्रपति के बीच

Click Here to Buy book on Amazon

116. मिनर्वा मिल्स निर्णय ने 42वें संशोधन अधिनियम के उस प्रावधान को रद्द कर दिया जिसने किसे प्राथमिकता देने का प्रयास किया था?
(A) भाग III के सभी मूल अधिकारों पर मूल कर्तव्यों को
(B) न्यायिक समीक्षा शक्तियों पर प्रधानमंत्री के चुनाव को
(C) अनुच्छेद 14 और 19 के अधिकारों पर सभी नीति निदेशक तत्वों को
(D) केंद्रीय संसदीय कानूनों पर राज्य के विधायी अधिनियमों को

117. मिनर्वा मिल्स मामले में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे संविधान की मूल विशेषता (मूल ढाँचा) के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई थी?
(A) संसद की सीमित संशोधन शक्ति
(B) संविधान में संशोधन करने की संसद की पूर्ण संप्रभुता
(C) राज्य के नीति निदेशक तत्वों की प्राथमिकता
(D) मूल अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार

118. "भारतीय संविधान भाग III और भाग IV के बीच संतुलन की नींव पर आधारित है। एक को दूसरे पर पूर्ण प्राथमिकता देना संविधान के सामंजस्य को बिगाड़ना है।" यह टिप्पणी किस मामले में की गई थी?
(A) केशवानंद भारती मामला
(B) गोलकनाथ मामला
(C) वामन राव मामला
(D) मिनर्वा मिल्स मामला

119. मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति में एक मुख्य अंतर जो अक्सर टकराव का कारण बनता है, वह है:
(A) मूल अधिकार केवल केंद्र सरकार पर लागू होते हैं जबकि नीति निदेशक तत्व केवल राज्य सरकारों पर लागू होते हैं।
(B) मूल अधिकार न्याययोग्य हैं जबकि नीति निदेशक तत्व न्याययोग्य नहीं हैं।
(C) मूल अधिकार न्याययोग्य नहीं हैं जबकि नीति निदेशक तत्व न्याययोग्य हैं।
(D) मूल अधिकार समुदायों की रक्षा करते हैं जबकि नीति निदेशक तत्व व्यक्तियों की रक्षा करते हैं।

120. निम्नलिखित मामलों पर विचार कीजिए:
I. चंपकम दोराइराजन मामला (1951)
II. गोलकनाथ मामला (1967)
III. मिनर्वा मिल्स मामला (1980)
उपर्युक्त में से कौन-से मामले मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच टकराव और प्राथमिकता से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित थे?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

121. मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराइराजन (1951) मामले में, मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संबंध के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय था?
(A) नीति निदेशक तत्व भाग III के मूल अधिकारों को पूरी तरह से निष्प्रभावी करते हैं।
(B) वे पूरी तरह से स्वतंत्र प्रावधान हैं और कानूनी रूप से उनकी तुलना नहीं की जा सकती।
(C) संसद को यह तय करना होगा कि मामला-दर-मामला आधार पर कौन-सा प्रभावी होगा।
(D) मूल अधिकार नीति निदेशक तत्वों पर प्रभावी होंगे।

122. मिनर्वा मिल्स के बाद की वर्तमान संवैधानिक स्थिति के तहत, अनुच्छेद 31C किन मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने से अनुच्छेद 39(b) और (c) में निर्दिष्ट नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाले कानूनों की रक्षा करता है?
(A) अनुच्छेद 14 और 19
(B) अनुच्छेद 20 और 21
(C) अनुच्छेद 25 और 26
(D) अनुच्छेद 32 और 226

123. मूल अधिकारों में संशोधन की क्षमता से संबंधित निम्नलिखित प्रमुख संवैधानिक मामलों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
II. सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य
III. आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
IV. शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ
निम्नलिखित में से कौन-सा सही कालानुक्रमिक क्रम है?
(A) IV, II, III, I
(B) IV, III, II, I
(C) II, IV, I, III
(D) III, IV, II, I

124. केशवानंद भारती मामले के बाद स्थापित संवैधानिक कानून के अनुसार, क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है?
(A) नहीं, मूल अधिकार किसी भी परिस्थिति में संसद द्वारा पूर्णतः असंशोधनीय हैं।
(B) हाँ, बशर्ते संविधान का मूल ढांचा नष्ट न हो।
(C) हाँ, संसद बिना किसी संवैधानिक प्रतिबंध या सीमा के स्वेच्छा से उनमें संशोधन कर सकती है।
(D) हाँ, लेकिन केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश और सभी राज्यों द्वारा पूर्ण अनुसमर्थन के साथ।

NODIA

125. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: मामला
P. गोलकनाथ मामला (1967)
Q. केशवानंद भारती मामला (1973)
R. मेनका गांधी मामला (1978)

S. मिनर्वा मिल्स मामला (1980)

सूची II: प्रमुख सिद्धांत/निर्णय

1. मूल ढाँचा सिद्धांत
2. भाग III और भाग IV के बीच संतुलन
3. भविष्यलक्ष्यी निर्णय (Prospective Overruling)
4. विधि की सम्यक प्रक्रिया (युक्तियुक्त, निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रक्रिया)

(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-1, R-3, S-2

126. 24वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में अनुच्छेद 13(4) जोड़ा। यह खंड क्या कहता है?

(A) मूल अधिकारों से असंगत सभी संविधान-पूर्व विधियाँ पूरी तरह से शून्य मानी जाती हैं।
(B) राष्ट्रपति द्वारा जारी कार्यपालकीय अध्यादेशों को अनुच्छेद 13 के नियमों के तहत 'विधि' नहीं माना जाता है।
(C) अनुच्छेद 368 के तहत बनाए गए कानून अनुच्छेद 13 के अधीन नहीं हैं।
(D) भारत का सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित किसी भी संवैधानिक संशोधन की समीक्षा नहीं कर सकता है।

127. विशिष्ट मूल अधिकारों की तुलना करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. अनुच्छेद 15 केवल नागरिकों को उपलब्ध है।
II. अनुच्छेद 16 नागरिकों और विदेशियों दोनों को उपलब्ध है।
III. अनुच्छेद 21 नागरिकों और विदेशियों दोनों को उपलब्ध है।
IV. अनुच्छेद 29 केवल नागरिकों को उपलब्ध है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, II और IV

128. निम्नलिखित में से कौन-सा मूल अधिकार पूरी तरह से राज्य के विरुद्ध निर्देशित है और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध लागू नहीं होता है?

(A) अनुच्छेद 15(2) (सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच)
(B) अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता)
(C) अनुच्छेद 18(1) (उपाधियों का अंत)
(D) अनुच्छेद 23 (मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम)

129. अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित या निरसित करने की शक्ति देता है। इस प्रावधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-से बल शामिल हैं?

(A) केवल थल सेना, नौसेना और वायु सेना शाखाओं में सेवारत नियमित कर्मी
(B) सशस्त्र बल, पुलिस बल, गुप्तचर एजेंसियाँ और संबद्ध संचार प्रणाली
(C) केवल सक्रिय संघर्ष क्षेत्रों में सीधे सेवारत सक्रिय-ड्यूटी लड़ाकू कर्मी
(D) विशेष रूप से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जबकि राज्य पुलिस बलों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है

130. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:

कथन (A): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34 भारत के राज्यक्षेत्र में किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ (सैन्य शासन) लागू होने के दौरान मूल अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान करता है।

कारण (R): भारत का संविधान अनुच्छेद 34 के भीतर "मार्शल लॉ" शब्द की सटीक शर्तों और मापदंडों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) भाग III
भारतीय संविधान का भाग 3 मुख्य रूप से मूल अधिकारों से संबंधित है। यह भाग अनुच्छेद 12 से 35 तक फैला हुआ है और इसे भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान निर्माता अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर इन अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए प्रेरित हुए थे। भाग 3 में नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक बुनियादी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।

2. (D) ये कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका के मनमाने कानूनों पर सीमा के रूप में कार्य करते हैं।
मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य राज्य की शक्ति को सीमित करना और नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। ये अधिकार कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका द्वारा बनाए जाने वाले मनमाने कानूनों पर एक प्रभावी प्रतिबंध के रूप में कार्य करते हैं। भारत में मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं, बल्कि इन पर उचित सीमाएँ लगाई जा सकती हैं। ये अधिकार देश में राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने और कानून का शासन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3. (B) छह
भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में नागरिकों को छह मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल संविधान में कुल सात मूल अधिकार शामिल किए गए थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। वर्तमान में उपलब्ध छह श्रेणियों में समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल हैं।

4. (C) प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है। यह मूल अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है, जिसमें शत्रु देश के नागरिक शामिल नहीं हैं। इसके विपरीत, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में दिए गए अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। अनुच्छेद 21 का विस्तार बहुत व्यापक है और न्यायपालिका ने इसमें कई मानवीय अधिकारों को शामिल माना है।

5. (A) संपत्ति का अधिकार
मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत एक केवल कानूनी या संवैधानिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, जिससे अब छह मूल अधिकार ही शेष बचे हैं।

NODIA

6. (A) केवल I और II
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य शब्द की विस्तृत परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद, राज्यों की सरकारें, राज्य विधानमंडल और सभी स्थानीय प्राधिकारी शामिल हैं। स्थानीय प्राधिकारियों में नगरपालिकाएँ, पंचायतें, जिला बोर्ड और सुधार ट्रस्ट आदि आते हैं। इसलिए स्थानीय निकायों को बाहर रखने का विचार असत्य है। इसके अतिरिक्त, राज्य के नियंत्रण में काम करने वाले अन्य वैधानिक प्राधिकारी भी इसमें आते हैं।

7. (B) जब वह अपने प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करती हो
अनुच्छेद 12 के तहत न्यायपालिका की स्थिति विशेष है। न्यायपालिका जब अपने प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करती है, जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति या नियम बनाना, तब उसे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत माना जाता है। हालाँकि, जब न्यायालय अपनी न्यायिक क्षमता में कार्य करता है और दो पक्षों के विवाद में फैसला सुनाता है, तब उसे राज्य नहीं माना जाता है। इस प्रकार प्रशासनिक और गैर-न्यायिक कार्यों के लिए न्यायपालिका अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की श्रेणी में आती है।

8. (C) बिना किसी सार्वजनिक वित्तपोषण या राज्य नियंत्रण वाली एक निजी कंपनी
सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसार, कोई भी संस्था अनुच्छेद 12 के तहत अन्य प्राधिकारी या राज्य मानी जाती है यदि उस पर राज्य का गहरा और व्यापक प्रशासनिक या वित्तीय नियंत्रण हो। ओएनजीसी, एलआईसी और सेल जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। इसके विपरीत, जिस निजी कंपनी में कोई सार्वजनिक वित्तपोषण नहीं होता और न ही कोई सरकारी नियंत्रण होता है, उसे अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं माना जा सकता है।

9. (D) अमेरिकी संविधान
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 दो मुख्य सिद्धांतों को समाहित करता है। पहला सिद्धांत विधि के समक्ष समता है, जो कि ब्रिटिश कानूनी परंपरा से लिया गया है। दूसरा सिद्धांत विधियों का समान संरक्षण है, जिसे अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है, जिसका तात्पर्य समान परिस्थितियों वाले

व्यक्तियों के साथ समान कानून लागू करने और समान व्यवहार करने से है, ताकि समाज में वास्तविक न्याय स्थापित किया जा सके।

10. (A) किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी विशेष विशेषाधिकार का न होना
अनुच्छेद 14 में निहित विधि के समक्ष समता की अवधारणा एक नकारात्मक विचार प्रस्तुत करती है। इसका अर्थ है कि राज्य के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं और किसी भी व्यक्ति या वर्ग के पक्ष में कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं होगा। सामान्य कानून के तहत समाज का कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे उसका सामाजिक या आर्थिक पद कुछ भी हो। यह अवधारणा सभी व्यक्तियों के साथ साधारण न्यायालयों द्वारा साधारण कानून के समान अनुपालन पर बल देती है।

11. (B) राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने आधिकारिक कर्तव्यों के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं।
अनुच्छेद 14 द्वारा दी गई विधि के समक्ष समता का नियम निरपेक्ष नहीं है और इसके कुछ संवैधानिक अपवाद हैं। संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। इसके अलावा उनके कार्यकाल के दौरान उन पर कोई आपराधिक कार्यवाही भी नहीं चलाई जा सकती है। यह संवैधानिक संरक्षण उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने में मदद करता है।

12. (A) P-3, Q-4, R-2, S-1
भारतीय संविधान के भाग 3 में समता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों का स्पष्ट विभाजन है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और कानूनों के समान संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान जैसे विशिष्ट आधारों पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समता प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। इस प्रकार प्रत्येक अनुच्छेद समता के अधिकार के विशिष्ट पहलू को स्पष्ट करता है।

13. (A) बोधगम्य अंतरक (इंटेलिजेंट डिफरेंशिया) और साध्य उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध (रैशनल नेक्सस)
अनुच्छेद 14 वर्ग विधान का निषेध करता है लेकिन व्यक्तियों या वस्तुओं के न्यायसंगत वर्गीकरण की अनुमति देता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कोई भी वर्गीकरण केवल तब वैध माना जाता है जब वह दो शर्तों को पूरा करे। पहली शर्त यह है कि वर्गीकरण बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए, जो समूह में शामिल और बाहर किए गए लोगों के बीच स्पष्ट अंतर करे। दूसरी शर्त यह है कि उस अंतरक का कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध होना अनिवार्य है।

14. (C) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को आदेश देता है कि वह किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल पांच विशिष्ट आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये पांच आधार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान हैं। केवल शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि इन पांच आधारों के अलावा अन्य आधारों पर किया गया वर्गीकरण असंवैधानिक नहीं होगा। यह अनुच्छेद सामाजिक समता सुनिश्चित करने और किसी भी नागरिक के साथ अनुचित पक्षपात को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक ढाल प्रदान करता है।

15. (D) महिलाएँ और बच्चे
अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव का सामान्य निषेध लागू होने के बावजूद, अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के हित में विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है। यह प्रावधान सकारात्मक कार्रवाई का एक उदाहरण है, जो समाज के ऐतिहासिक रूप से कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। इसके तहत राज्य महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण या बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा जैसी विशेष योजनाएँ बना सकता है, जिन्हें समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाता है।

16. (C) 93वाँ संशोधन अधिनियम, 2005
वर्ष 2005 के 93वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15(5) को शामिल किया गया था। यह प्रावधान राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष नियम बनाने का अधिकार देता है। इसके तहत निजी शिक्षण संस्थानों सहित सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हों या न हों, केवल अल्पसंख्यक संस्थानों को इससे बाहर रखा गया है।

17. (B) अनुच्छेद 15(2)
संविधान का अनुच्छेद 15(2) यह व्यवस्था करता है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होता है। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले सामाजिक भेदभाव और छुआछूत जैसी कुरीतियों का पूर्ण रूप से अंत करना और नागरिक समानता स्थापित करना है।

18. (A) केवल I, II और III
अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समता की गारंटी देता है। यह नागरिकों के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान या निवास के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। इसके अतिरिक्त, यह संसद को कुछ विशिष्ट नौकरियों के लिए निवास की शर्त तय करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16(4) राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए पदों में आरक्षण प्रदान करने से नहीं रोकता, बल्कि विशेष शक्ति देता है, इसलिए चौथा कथन असत्य है।

Click Here to Buy book on Flipkart

19. (B) अनुच्छेद 16(4)
द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, का गठन वर्ष 1979 में किया गया था। इस आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। यह संपूर्ण व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत प्राप्त शक्तियों के संदर्भ में लागू की गई थी। अनुच्छेद 16(4) राज्य को उन पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करने में सक्षम बनाता है जिनका सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

20. (A) 77वाँ संशोधन अधिनियम, 1995
वर्ष 1995 के 77वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 16 में एक नया खंड 16(4A) जोड़ा गया था। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण का प्रावधान करने में सक्षम बनाना था। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले में निर्णय दिया था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, जिसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद ने यह महत्वपूर्ण संशोधन पारित किया था।

21. (A) धार्मिक संस्थाएँ अपने पदाधिकारियों के लिए उस विशिष्ट धर्म को मानने की शर्त रख सकती हैं
अनुच्छेद 16(5) सार्वजनिक रोजगार में समानता के सामान्य नियम का एक विशिष्ट अपवाद प्रदान करता है। इसके अनुसार, यदि कोई कानून यह तय करता है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था का पदाधिकारी या उसके शासी निकाय का सदस्य उसी विशिष्ट धर्म को मानने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तो ऐसा कानून पूरी तरह से वैध होगा। यह संवैधानिक प्रावधान धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता और उनकी धार्मिक प्रकृति को बनाए रखने के उद्देश्य से समता के अधिकार में एक अपवाद के रूप में शामिल किया गया है।

22. (B) 50%
प्रसिद्ध इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला, जिसे मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है, में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण व्यवस्था पर ऐतिहासिक फैसला दिया था। न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 16(4) के तहत सरकारी नौकरियों में दिया जाने वाला कुल आरक्षण किसी भी सामान्य परिस्थिति में 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। इस 50% की सीमा को समानता के अधिकार और दक्षता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य संवैधानिक मानक के रूप में स्थापित किया गया था।

23. (B) अस्पृश्यता
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के पूर्ण उन्मूलन और इसके किसी भी रूप में आचरण पर प्रतिबंध से संबंधित है। यह अनुच्छेद घोषित करता है कि अस्पृश्यता से उपजी किसी भी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। यह भारतीय संविधान के सबसे कठोर प्रावधानों में से एक है, जो बिना किसी अपवाद के पूर्ण अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य सदियों पुरानी सामाजिक बुराई को खत्म करके समाज में मानवीय गरिमा और समानता की स्थापना करना है।

24. (C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके आचरण को दंडनीय अपराध घोषित करता है, इसलिए पहला कथन सही है। हालाँकि, भारत के संविधान में या किसी विधायती अधिनियम में अस्पृश्यता शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। उच्च न्यायालयों ने अपने निर्णयों में स्पष्ट किया है कि इसका तात्पर्य ऐतिहासिक रूप से कुछ जातियों पर थोपी गई सामाजिक विकृतियों से है। इस प्रकार कारण गलत होने के कारण सही उत्तर का चयन किया गया है।

NODIA

25. (D) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम
अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रावधानों को लागू करने हेतु संसद ने वर्ष 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया था। आगे चलकर इस अधिनियम में व्यापक संशोधन किए गए और वर्ष 1976 में इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। यह कानून छुआछूत का आचरण करने वाले व्यक्तियों के लिए कड़े दंड की व्यवस्था करता है। इसके तहत दोषी पाए गए व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है, जिससे सामाजिक सुधार संभव हो सका है।

26. (A) यह पूर्ण (निरपेक्ष) है और किसी भी युक्तियुक्त प्रतिबंध के अधीन नहीं है।
संविधान के अनुच्छेद 17 की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अधिकार पूर्ण यानी निरपेक्ष प्रकृति का है। अधिकांश मूल अधिकारों पर लोक व्यवस्था, नैतिकता या सुरक्षा के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 17 पर कोई अपवाद लागू नहीं होता। इसके अलावा, यह अधिकार राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होता है। यदि कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता का आचरण करता है तो उसे संवैधानिक रूप से संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है।

27. (B) सैन्य या शैक्षणिक सम्मान
संविधान का अनुच्छेद 18(1) राज्य को किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान करने से रोकता है, लेकिन इस नियम के दो स्पष्ट अपवाद हैं। राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सैन्य सम्मान जैसे परमवीर चक्र और शैक्षणिक सम्मान जैसे डॉक्टरेट उपाधियों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इसका उद्देश्य समाज में कुलीन वर्ग के वंशानुगत विशेषाधिकारों को समाप्त करना और समतावादी समाज की स्थापना करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति कृत्रिम उपाधियों के माध्यम से विशेषाधिकार प्राप्त न कर सके।

28. (B) राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे भारत रत्न और पद्म विभूषण
बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामला 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि ये पुरस्कार उपाधियाँ नहीं हैं, बल्कि केवल उत्कृष्ट नागरिक सेवाओं और योगदान की मान्यता हैं। हालाँकि, न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि पुरस्कार

प्राप्तकर्ता इन राष्ट्रीय सम्मानों का उपयोग अपने नाम के आगे या पीछे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में कदापि नहीं कर सकते हैं।

29. (A) कोई भी नागरिक किसी भी परिस्थिति में किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18(2) एक अत्यंत स्पष्ट और पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। यह प्रतिबंध पूर्ण है और इसके लिए राष्ट्रपति या सरकार की सहमति का भी कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं दिया गया है। इस नियम का मूल उद्देश्य देश के नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार के विदेशी प्रभाव, असमानता या गैर-समान सामाजिक वर्गीकरण को पूरी तरह से रोकना है।

30. (C) केवल I और III
अनुच्छेद 18 के अनुसार, यदि कोई विदेशी व्यक्ति राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करता है, तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि, भेंट या पद स्वीकार नहीं कर सकता। अतः पहला और तीसरा कथन पूरी तरह सही हैं। दूसरा कथन गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने बालाजी राघवन मामले में स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि राष्ट्रीय पुरस्कारों जैसे पद्म श्री का उपयोग नाम के आगे या पीछे उपसर्ग अथवा प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता।

31. (D) संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की स्वतंत्रता
मूल संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों को सात मौलिक स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई थी। इनमें अनुच्छेद 19(1)(f) के अंतर्गत संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की स्वतंत्रता भी शामिल थी। वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस स्वतंत्रता को मूल अधिकारों के भाग से पूरी तरह से हटा दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप अब अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को केवल छह मौलिक स्वतंत्रताएँ ही प्राप्त हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का आधार हैं।

32. (A) अनुच्छेद 19(1)(a) - वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यह अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित है। वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अपने विचारों को किसी भी माध्यम से व्यक्त करने का अधिकार शामिल है, जिसमें मुद्रित प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट भी आते हैं। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, इसलिए इसकी स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति के मूल अधिकार का ही एक अभिन्न अंग स्वीकार किया गया है।

33. (B) बहुसंख्यक राजनीतिक समर्थन का अभाव
संविधान का अनुच्छेद 19(2) राज्य को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर केवल आठ विशिष्ट आधारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। इनमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय का अवमान, मानहानि और अपराध-उद्दीपन शामिल हैं। राजनीतिक समर्थन का अभाव इनमें शामिल नहीं है, इसलिए सरकार इस आधार पर किसी नागरिक के अभिव्यक्ति के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती है।

34. (D) नहीं, हड़ताल का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, बल्कि यह वैधानिक कानूनों द्वारा शासित होता है।
अनुच्छेद 19(1)(c) नागरिकों को संगम या संघ या सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार देता है, लेकिन इसमें हड़ताल करने का मूल अधिकार शामिल नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मुकदमों में यह स्पष्ट किया है कि हड़ताल का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह केवल औद्योगिक विवाद अधिनियम जैसे वैधानिक कानूनों द्वारा विनियमित एक वैधानिक अधिकार है। व्यापार संघ बनाने की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि सदस्यों को हड़ताल पर जाने का संवैधानिक अधिकार मिल जाता है।

NODIA

35. (C) 97वाँ संशोधन अधिनियम, 2011
वर्ष 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) में एक नया आयाम जोड़ा गया था। इस संशोधन के माध्यम से नागरिकों को संगम या संघ बनाने के अधिकार के साथ-साथ सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार भी एक मूल अधिकार के रूप में प्रदान किया गया। इसके अलावा, इस संशोधन ने संविधान में सहकारी समितियों के संदर्भ में भाग 9B भी जोड़ा, जिसका उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना और उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करना था।

36. (A) वाक् और अभिव्यक्ति → सम्मेलन → संघ/संगम → संचरण
संविधान के अनुच्छेद 19(1) में सूचीबद्ध स्वतंत्रताओं का एक विशिष्ट क्रम दिया गया है। सबसे पहले अनुच्छेद 19(1)(a) में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है। इसके बाद अनुच्छेद 19(1)(b) में शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता है। तीसरे स्थान पर अनुच्छेद 19(1)(c) में संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। चौथे स्थान पर अनुच्छेद 19(1)(d) में भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है।

37. (A) किसी व्यक्ति को तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय लागू विधि का उल्लंघन न किया हो।
अनुच्छेद 20(1) कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करता है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को केवल उस कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसे करते समय कानूनन अपराध नहीं था। इसके अलावा, किसी व्यक्ति को अपराध के समय निर्धारित दंड से अधिक दंड भी नहीं दिया जा सकता है। यह नियम केवल आपराधिक मामलों पर लागू होता है, सिविल या कर कानूनों पर नहीं। यह प्रावधान विधायिका को भूतलक्षी प्रभाव से नए आपराधिक कानून बनाने से रोकता है।

38. (D) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 20(2) में दोहरे दंड से संरक्षण का सिद्धांत शामिल है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अदालत में अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। यह संरक्षण केवल किसी न्यायिक न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष हुई कार्यवाहियों पर ही लागू होता है। विभागीय या प्रशासनिक अनुशासनात्मक कार्यवाहियों पर यह नियम लागू नहीं होता, इसलिए पुलिस या प्रशासनिक स्तर पर अलग से विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

39. (B) केवल आपराधिक कार्यवाहियों पर
अनुच्छेद 20(3) अपने विरुद्ध साक्ष्य देने से संरक्षण प्रदान करता है, जिसे आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह अधिकार केवल आपराधिक कार्यवाहियों पर ही लागू होता है, जहाँ किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया गया हो। यह अधिकार सिविल कार्यवाहियों या उन कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता जो आपराधिक प्रकृति की नहीं हैं। इसके अलावा, फिंगरप्रिंट, हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान देने के लिए बाध्य करना इस अधिकार का उल्लंघन नहीं है।

40. (C) हाँ, यह नागरिकों, विदेशियों और निगमों जैसे कानूनी व्यक्तियों तक विस्तारित है।
अनुच्छेद 20 के तहत प्राप्त अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण भारत के नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों को भी समान रुप से उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, यह अधिकार केवल प्राकृतिक व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह कंपनियों और निगमों जैसे कानूनी व्यक्तियों तक भी विस्तारित है। यह प्रावधान कानूनी शासन के सिद्धांतों को मजबूत करता है और किसी भी व्यक्ति को मनमाने आपराधिक अभियोजन या गैर-कानूनी दंड से सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे उसका नागरिकता दर्जा कुछ भी हो।

41. (C) अनुच्छेद 20 और 21
वर्ष 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह ऐतिहासिक व्यवस्था की गई कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है तथा अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मूल अधिकारों के प्रवर्तन को रोक सकते हैं, परंतु इन दोनों अनुच्छेदों को छू भी नहीं सकते हैं।

42. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
अनुच्छेद 21 की विस्तृत न्यायिक व्याख्याओं में विभिन्न अधिकारों को शामिल किया गया है। के.एस. पुट्टस्वामी मामले में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 का भाग माना गया। ओल्गा टेलिस मामले में आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल किया गया। मेनका गांधी मामले में विदेश जाने के अधिकार को स्वतंत्रता के अंतर्गत मान्यता मिली। उन्नीकृष्णन मामले में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक माना गया था।

43. (B) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह शब्दावली मूल रुप से जापानी संविधान से ली गई थी। हालाँकि, मेनका गांधी मामले के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस अवधारणा का दायरा व्यापक करते हुए इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और अमेरिकी सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांतों को भी शामिल मान लिया है।

44. (B) आजीविका का अधिकार
वर्ष 1985 के ऐतिहासिक ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 21 के दायरे में एक महत्वपूर्ण विस्तार किया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जीवन का अधिकार केवल जैविक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आजीविका का अधिकार भी शामिल है। न्यायालय ने माना कि आजीविका का साधन छीने जाने पर जीवन जीना असंभव हो जाएगा, इसलिए किसी भी व्यक्ति को उसकी आजीविका से बिना न्यायसंगत प्रक्रिया के वंचित नहीं किया जा सकता।

45. (A) के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ
वर्ष 2017 में के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायालय ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदान किए गए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न और मौलिक हिस्सा है। इस निर्णय ने नागरिकों की व्यक्तिगत स्वायत्तता, गोपनीयता और शारीरिक अखंडता को राज्य के मनमाने हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करने का एक मजबूत संवैधानिक आधार तैयार किया है।

46. (C) अनुच्छेद 48A
सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का विस्तार करते हुए इसमें प्रदूषण मुक्त जल और हवा में जीने के अधिकार को शामिल किया है। यह व्याख्या संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 48A के साथ पूरी तरह सुसंगत है। अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है। न्यायपालिका ने इन दोनों प्रावधानों को जोड़कर पर्यावरणीय न्याय का मार्ग प्रशस्त किया है।

47. (C) 86वाँ संशोधन अधिनियम, 2002
वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को एक नया मूल अधिकार बनाकर शामिल किया गया था। इस ऐतिहासिक संशोधन ने 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को एक संवैधानिक मूल अधिकार का दर्जा

Downloaded from www.pdf.tube

दिया। इस अधिकार को व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए संसद ने वर्ष 2009 में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई अधिनियम भी पारित किया था।

48. (B) केवल I, III और IV
अनुच्छेद 21A केवल 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की गारंटी देता है, इसमें उच्च या पेशेवर शिक्षा शामिल नहीं है। इसलिए दूसरा कथन गलत है। पहला कथन सही है क्योंकि यह राज्य को अनिवार्य शिक्षा का आदेश देता है। तीसरा कथन भी सही है क्योंकि 2009 में आरटीई अधिनियम लागू किया गया। चौथा कथन सही है क्योंकि इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 के विषय-वस्तु में परिवर्तन किया गया था ताकि शैशवावस्था की देखरेख को शामिल किया जा सके।

49. (B) 6 से 14 वर्ष
संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। राज्य यह शिक्षा उस तरीके से प्रदान करेगा जिसे वह कानून बनाकर निर्धारित करे। यह प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित है और 14 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं या उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होता है। इसका उद्देश्य देश में साक्षरता बढ़ाना है।

50. (D) भाग IV में राज्य के नीति निदेशक तत्व
वर्ष 2002 में 86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A के शामिल होने से पूर्व, बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान मुख्य रूप से संविधान के भाग 4 में स्थित राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में शामिल था। मूल अनुच्छेद 45 में राज्य को संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया था, जो गैर-न्याययोग्य था।

51. (A) दंडात्मक और निवारक हिरासत (निरोध)
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को दो अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करके संरक्षण प्रदान करता है। पहली श्रेणी दंडात्मक हिरासत की है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा अपराध सिद्ध होने के बाद दंडित करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। दूसरी श्रेणी निवारक निरोध की है, जिसमें किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने से रोकने के लिए केवल आशंका के आधार पर हिरासत में लिया जाता है। दोनों स्थितियों के लिए अलग कानूनी नियम लागू होते हैं।

52. (B) यात्रा का समय छोड़कर 24 घंटे
अनुच्छेद 22(2) के तहत दंडात्मक हिरासत के मामलों में यह अनिवार्य प्रावधान है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। यह नियम गैर-कानूनी पुलिस हिरासत और दुर्व्यवहार से नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

NODIA

53. (C) 3 माह
अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति की अधिकतम अवधि के संबंध में सुरक्षात्मक नियम दिए गए हैं। सलाहकारी बोर्ड की अनुकूल राय प्राप्त किए बिना किसी भी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक निवारक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। यदि हिरासत की अवधि तीन महीने से आगे बढ़ानी हो, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता रखने वाले सदस्यों से बने सलाहकार बोर्ड द्वारा इस विस्तार की समीक्षा करना और मंजूरी देना कानूनन अनिवार्य होता है।

54. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
अनुच्छेद 22(3) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि गिरफ्तारी और हिरासत से मिलने वाले प्रक्रियात्मक संरक्षण किसी भी शत्रु अन्य देशीय यानी शत्रु देश के नागरिक पर लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा, निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को भी सामान्य गिरफ्तारी वाले अधिकार प्राप्त नहीं होते। संविधान किसी शत्रु देश के व्यक्तियों को दंडात्मक और प्रक्रियात्मक सुरक्षा देने से इनकार करता है, इसलिए कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा सही व्याख्या प्रस्तुत करते हैं।

55. (B) मानव दुर्व्यापार और बेगार (जबरन श्रम)
संविधान का अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार की गारंटी प्रदान करता है। यह अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार, बेगार यानी बिना वेतन का जबरन श्रम और इसी प्रकार के अन्य सभी प्रकार के बलात् श्रम को पूरी तरह से प्रतिबंधित और अवैध घोषित करता है। इस प्रावधान का उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध माना जाता है। यह अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों को उपलब्ध है तथा यह राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के उत्पीड़न के विरुद्ध भी सुरक्षा देता है।

56. (C) राज्य सैन्य या सामाजिक सेवा जैसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है।
अनुच्छेद 23(2) में जबरन श्रम के निषेध का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अपवाद दिया गया है। इसके अनुसार, राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा या अनिवार्य सामाजिक सेवा लागू करने से नहीं रोका जा सकता है। ऐसी सेवा लागू करते समय राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऐसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ली गई सेवा को अनुच्छेद 23 के तहत गैर-कानूनी बलात् श्रम नहीं माना जाता है।

57. (B) अनुच्छेद 23
अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 और बंधुआ श्रम पद्धति उन्मूलन अधिनियम 1976 जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक कानून सीधे संविधान के अनुच्छेद 23 से अपना संवैधानिक

जनादेश प्राप्त करते हैं। अनुच्छेद 23 संसद को मानव दुर्व्यापार, वैश्यावृत्ति और बंधुआ मजदूरी जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सख्त दंडात्मक कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 35 के साथ मिलकर, यह प्रावधान संसद को इन शोषणकारी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए विधायी ढाँचा तैयार करने में मदद करता है।

58. (A) हाँ, यह नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों को उपलब्ध है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह देश में मौजूद गैर-नागरिकों और विदेशियों को भी समान रूप से प्राप्त है। यह अधिकार मानव गरिमा की सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए संविधान निर्माताओं ने इसे सार्वभौमिक प्रकृति का बनाया है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी देश का नागरिक हो, भारत में बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी या किसी भी रूप में बलात् श्रम का शिकार नहीं बनाया जा सकता।

59. (B) 14 वर्ष
संविधान का अनुच्छेद 24 बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खान या अन्य जोखिम भरे नियोजन में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा उन्हें कारखानों या खदानों जैसे खतरनाक वातावरण में होने वाले शोषण से बचाकर उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है।

60. (C) केवल I और III
मूल संविधान के अनुच्छेद 24 का पाठ केवल कारखानों, खदानों और अन्य जोखिम भरे नियोजन में ही 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर रोक लगाता था। यह गैर-जोखिम वाले या सुरक्षित व्यवसायों में बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता था और न ही घरेलू उद्यमों को कवर करता था। इसलिए पहला और तीसरा कथन सही हैं। वर्ष 2016 के संशोधन के बाद ही सभी प्रकार के व्यवसायों में बाल श्रम को व्यापक रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

61. (A) स्कूल के बाद पारिवारिक उद्यमों में मदद करने को छोड़कर, किसी भी व्यवसाय में
बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 ने बाल श्रम कानून में व्यापक बदलाव किए। इस संशोधन ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और इसे एक संज्ञेय अपराध बना दिया। इसमें केवल एक अपवाद रखा गया है कि बच्चा अपनी शिक्षा को प्रभावित किए बिना स्कूल के समय के बाद या छुट्टियों के दौरान अपने परिवार या पारिवारिक उद्यमों में सहायता कर सकता है।

62. (C) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और बाल श्रम से संबंधित कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। यह वैधानिक निकाय देश में बाल अधिकारों के संरक्षण, अनुच्छेद 24 के कार्यान्वयन और निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम की स्थिति का निरीक्षण करता है तथा बाल कल्याण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाता है।

63. (D) लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार देता है। हालाँकि, यह धार्मिक स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। अनुच्छेद 25(1) में स्पष्ट किया गया है कि यह अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और भाग 3 के अन्य प्रावधानों के अधीन है। इसका अर्थ है कि राज्य सार्वजनिक व्यवस्था और जनस्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए धार्मिक आचरणों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

64. (C) अपने धार्मिक विश्वासों के सिद्धांतों का दूसरों के समक्ष प्रसार या व्याख्या करने का अधिकार।
अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का प्रचार करने के अधिकार का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा अपने धार्मिक विचारों और सिद्धांतों को दूसरों के सामने प्रकट करने या उनका प्रसार करने से है। सर्वोच्च न्यायालय ने रेव स्टेनिसलॉस मामले में यह स्पष्ट कर दिया था कि प्रचार करने के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति को जबरन, धोखे या लालच से अपने धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि ऐसा धर्मांतरण दूसरे व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।

65. (B) इसके पास कम से कम 1,00,000 पंजीकृत अनुयायी होने चाहिए।
अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार केवल धार्मिक संप्रदायों को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक संप्रदाय के लिए तीन अनिवार्य शर्तें निर्धारित की हैं। पहला, यह ऐसे व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनकी एक समान विश्वास प्रणाली हो। दूसरा, इसका एक सामान्य संगठन होना अनिवार्य है। तीसरा, इसे एक विशिष्ट नाम से पुकारा जाना चाहिए। अनुयायियों की किसी न्यूनतम संख्या जैसे 1,00,000 की कोई संवैधानिक या न्यायिक शर्त नहीं रखी गई है।

66. (A) II, III, IV, I
मूल अधिकारों से संबंधित इन ऐतिहासिक मुकदमों का सही कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला वर्ष 1967 में आया था। इसके पश्चात प्रसिद्ध केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला वर्ष 1973 में तय हुआ था। इसके बाद मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला वर्ष 1978 में आया था। अंत में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला वर्ष 1980 में तय हुआ था, जिसने मूल ढाँचे को सुदृढ़ किया।

Click Here to Buy book on Amazon

67. (A) किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर राजस्व खर्च करने का।
अनुच्छेद 27 यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जिनकी आय का उपयोग विशेष रुप से किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या रख-रखाव के लिए किया जाता है। इसका अर्थ है कि राज्य करों से प्राप्त सार्वजनिक धन का उपयोग किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं कर सकता। हालाँकि, यह प्रावधान शुल्क लगाने पर रोक नहीं लगाता, यदि शुल्क का उपयोग धर्मनिरपेक्ष सेवाओं के लिए किया जाए।

68. (C) पूर्णतः राज्य-निधि से पोषित संस्थान
अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के संबंध में चार प्रकार के संस्थानों का वर्गीकरण करता है। इसमें पहली श्रेणी पूरी तरह से राज्य-निधि द्वारा पोषित संस्थानों की है। अनुच्छेद 28(1) के अनुसार, पूर्णतः राज्य द्वारा संचालित या वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा देना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यह नियम भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखने और सरकारी स्कूलों में धार्मिक तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।

69. (A) उसे बनाए रखने (संरक्षित करने) का
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29(1) सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के तहत यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को, जिसकी अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने या संरक्षित करने का पूर्ण अधिकार होगा। यह प्रावधान भारत की विविध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करता है तथा अल्पसंख्यकों के साथ-साथ नागरिकों के सभी समूहों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार देता है।

70. (D) संविधान में कहीं भी "अल्पसंख्यक" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है, लेकिन संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण राष्ट्रीय स्तर के बजाय राज्य की कुल जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिए। वर्तमान में धार्मिक और भाषाई समूहों को उनकी राज्यस्तरीय संख्यात्मक स्थिति के आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाता है, लेकिन इसकी कोई संवैधानिक परिभाषा नहीं है।

71. (B) धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को
संविधान का अनुच्छेद 30(1) केवल दो आधारों पर अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, जो धर्म या भाषा हैं। यह प्रावधान सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासनिक संचालन का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपने बच्चों को अपनी संस्कृति और भाषा के अनुसार शिक्षा दे सकें। यह अधिकार गैर-अल्पसंख्यक वर्गों या केवल क्षेत्रीय समुदायों को अनुच्छेद 30 के तहत प्राप्त नहीं है।

72. (A) P-2, Q-3, R-1, S-4
धार्मिक और सांस्कृतिक अनुच्छेदों का सही मिलान इस प्रकार है। अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 29 नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 30 भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है।

73. (D) यह किसी धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।
अनुच्छेद 30(2) राज्य द्वारा दी जाने वाली शैक्षणिक सहायता के संदर्भ में समता सुनिश्चित करता है। इसके अनुसार, राज्य शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता देने में किसी भी संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह संस्था किसी धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन के तहत काम कर रही है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि सहायता आवंटित करते समय अल्पसंख्यक संचालित संस्थानों के साथ सरकारी स्तर पर कोई निष्पक्षता-विरोधी या भेदभावपूर्ण व्यवहार न हो।

NODIA

74. (D) अनुच्छेद 32
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। उनके अनुसार, यदि यह अनुच्छेद न हो तो पूरा संविधान अर्थहीन हो जाएगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जो नागरिकों को अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। यही अनुच्छेद मूल अधिकारों की वास्तविक गारंटी और सुरक्षा प्रदान करता है।

75. (B) भारत का सर्वोच्च न्यायालय
अनुच्छेद 32(2) मूल अधिकारों को लागू कराने और प्रवर्तित कराने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण शामिल हैं। यद्यपि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही यह संवैधानिक अधिकार दिया गया है।

76. (B) उच्च न्यायालय मूल अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के लिए रिट जारी करते हैं; सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के लिए जारी करता है।
सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार केवल भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के प्रवर्तन तक ही सीमित है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों का रिट क्षेत्राधिकार अधिक व्यापक है। उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ-साथ किसी भी अन्य सामान्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकते हैं। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने से इनकार नहीं कर सकता, जबकि उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार एक विवेकाधीन शक्ति माना जाता है।

77. (A) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश द्वारा।
अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार को केवल राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान निलंबित किया जा सकता है। यह निलंबन अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी एक औपचारिक आदेश के माध्यम से ही संभव है। इसके अलावा सामान्य परिस्थितियों में या बिना राष्ट्रपति के आदेश के इस संवैधानिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता।

78. (A) केवल I, II और III
अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मूल अधिकार है, जो इसे अत्यंत विशेष बनाता है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक और अंतिम गारंटीदाता है। इसके अलावा संसद कानून बनाकर किसी अन्य निचले न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। अतः पहले तीन कथन पूरी तरह सत्य हैं। चौथा कथन गलत है क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनन्य नहीं है, बल्कि यह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के समवर्ती है।

79. (D) शरीर को प्रस्तुत किया जाए
बंदी प्रत्यक्षीकरण लैटिन भाषा का एक कानूनी शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए या बंदी को प्रत्यक्ष लाया जाए। यह रिट न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा हुआ है। इस रिट के माध्यम से न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है ताकि उसकी गिरफ्तारी और निरोध की कानूनी वैधानिकता की जाँच की जा सके।

80. (C) सार्वजनिक और निजी दोनों निकायों के विरुद्ध
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट अन्य अधिकांश संवैधानिक रिटों की तुलना में काफी अलग और अद्वितीय है। यह रिट सार्वजनिक प्राधिकारियों तथा सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को किसी निजी व्यक्ति द्वारा भी गैर-कानूनी तरीके से बंधक बनाया गया हो या कैद में रखा गया हो, तो उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करके उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दे सकता है।

81. (B) कोई निजी व्यक्ति या निकाय
परमादेश एक महत्वपूर्ण कानूनी आदेश है, जिसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह रिट न्यायालय द्वारा किसी लोक अधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय या सार्वजनिक निकाय को उनके कानूनी या वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश देने के लिए जारी की जाती है। हालाँकि, परमादेश रिट को किसी निजी व्यक्ति या गैर-सरकारी निजी निकाय के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा गैर-संवैधानिक या गैर-वैधानिक विवेकाधीन कार्यों को लागू करने के लिए भी इसे जारी नहीं किया जा सकता।

82. (D) राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल
परमादेश रिट जारी करने के संदर्भ में संविधान कुछ संवैधानिक पदों को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन या शक्तियों के प्रयोग के लिए परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती है। यह छूट उन्हें बिना किसी न्यायिक दबाव के अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने की अनुमति देती है, जबकि मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर परमादेश लागू हो सकता है।

83. (A) अंतिम आदेश जारी होने के बाद
प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों ही रिटें मुख्य रूप से न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती हैं, लेकिन दोनों के जारी होने के समय में अंतर होता है। प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती है जब कार्यवाही अभी निचले न्यायालय में लंबित हो, ताकि उसे अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोका जा सके। इसके विपरीत, उत्प्रेषण रिट तब जारी की जाती है जब निचला न्यायालय पहले ही अंतिम आदेश या निर्णय पारित कर चुका हो, जिससे उस गलत आदेश को रद्द किया जा सके।

84. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
वर्ष 1991 से पहले उत्प्रेषण रिट केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों के खिलाफ ही जारी की जा सकती थी। लेकिन 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देकर इसका दायरा बढ़ा दिया। न्यायालय ने तय किया कि उत्प्रेषण रिट प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है यदि उनके कार्य व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों को प्रभावित करते हों। अतः कथन और कारण दोनों पूरी तरह सत्य हैं और कारण, कथन की बिल्कुल सही व्याख्या प्रस्तुत करता है।

85. (A) किसी सार्वजनिक पद के दावे की वैधानिकता की जाँच करने के लिए
अधिकार-पृच्छा रिट का शाब्दिक अर्थ है आपका क्या अधिकार या प्राधिकार है। यह रिट न्यायालय द्वारा यह जाँचने के लिए जारी की जाती है कि किसी सार्वजनिक या संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति उस पद को धारण करने का कानूनी अधिकार

Downloaded from www.pdf.tube

रखता है या नहीं। यदि यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने गैर-कानूनी तरीके से या योग्यता के बिना किसी सार्वजनिक पद पर कब्जा कर रखा है, तो न्यायालय इस रिट के द्वारा उस व्यक्ति को पद से हटा सकता है।

86. (D) अधिकार-पृच्छा
सामान्य नियम यह है कि रिट याचिका केवल वही व्यक्ति दायर कर सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो, जिसे पीड़ित व्यक्ति का सिद्धांत या लोकस स्टैंडाई कहा जाता है। हालाँकि, अधिकार-पृच्छा रिट इस नियम का एक प्रमुख अपवाद है। इस रिट के मामलों में याचिकाकर्ता का व्यक्तिगत रूप से पीड़ित होना आवश्यक नहीं है। कोई भी जनहित से प्रेरित नागरिक या इच्छुक व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद के अवैध कब्जे को चुनौती देने के लिए अधिकार-पृच्छा रिट याचिका न्यायालय में दायर कर सकता है।

87. (B) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में
भारतीय संविधान की वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में निहित है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। यद्यपि संसद कानून बनाकर निचले न्यायालयों को भी रिट क्षेत्राधिकार दे सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई केंद्रीय कानून नहीं बनाया गया है, इसलिए वर्तमान में केवल यही दोनों उच्च न्यायालय सशक्त हैं।

88. (B) 44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978
मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत एक महत्वपूर्ण मूल अधिकार के रूप में स्थापित था। हालाँकि, भूमि सुधारों, संपत्ति के वितरण और कल्याणकारी नीतियों को लागू करने में आने वाली कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए संसद ने कदम उठाया। वर्ष 1978 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा लाए गए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से पूरी तरह से निष्कासित कर दिया गया था।

89. (A) अनुच्छेद 300A
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों से हटाए जाने के बाद, संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में एक नया अनुच्छेद 300A जोड़कर स्थापित किया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी तरीके से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार न रहकर केवल एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में विद्यमान है।

90. (B) केवल I और III
संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, लेकिन यह एक संवैधानिक अधिकार बना हुआ है, इसलिए पहला कथन सही है। यह अधिकार कार्यपालकीय कार्रवाई के साथ-साथ विधायी कार्रवाई दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। इसके उल्लंघन होने पर पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता, बल्कि उसे उच्च न्यायालय या सामान्य सिविल न्यायालय की शरण लेनी होगी, इसलिए तीसरा कथन पूरी तरह सत्य है।

91. (B) विशिष्ट कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने वाले अपवाद
संविधान से संपत्ति के अधिकार और अनुच्छेद 31 के हटने के बावजूद, अनुच्छेद 31A, 31B और 31C को संविधान में बनाए रखा गया है। ये तीनों प्रावधान मूल अधिकारों के सामान्य नियमों के अपवाद के रूप में कार्य करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य कृषि सुधारों, संपत्ति के अधिग्रहण, नौवीं अनुसूची के कानूनों और कुछ नीति निदेशक तत्वों को लागू करने वाले विशिष्ट विधानों को अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर होने वाली न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान करना है।

92. (A) समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की छह श्रेणियों को एक विशेष और निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया गया है। प्रथम श्रेणी समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) है। द्वितीय श्रेणी स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22) है। तृतीय श्रेणी शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24) है। चतुर्थ श्रेणी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28) है। इसके बाद संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्रमानुसार आते हैं।

93. (A) संपदाओं का अर्जन और संबंधित कृषि सुधार
वर्ष 1951 के पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31A जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद कानूनों की पांच श्रेणियों को अनुच्छेद 14 और 19 के तहत दी गई न्यायिक चुनौती से सुरक्षा प्रदान करता है। यह मुख्य रूप से संपदाओं के अर्जन, कृषि सुधारों, जागीरदारी प्रणाली के उन्मूलन, सरकारी नियंत्रण में कंपनियों के प्रबंधन और खनिज अधिकारों के संशोधन से जुड़े कानूनों से संबंधित है, ताकि राज्य बिना कानूनी रुकावट के सामाजिक सुधार कर सके।

94. (C) नौवीं अनुसूची
वर्ष 1951 के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31B और नौवीं अनुसूची को एक साथ शामिल किया गया था। अनुच्छेद 31B की यह विशेषता है कि यदि किसी कानून या नियम को नौवीं अनुसूची में डाल दिया जाता है, तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों को अदालती मुकदमों से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना था।

95. (B) अनुच्छेद 39(b) और 39(c)
वर्ष 1971 के 25वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि यदि कोई कानून संविधान के भाग 4 में दिए गए

NODIA

नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 39(b) या 39(c) को लागू करने के लिए बनाया जाता है, तो उस कानून को अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान भौतिक संसाधनों के समान वितरण को प्राथमिकता देता है।

96. (A) 1वाँ संशोधन → 4वाँ संशोधन → 17वाँ संशोधन → 25वाँ संशोधन
संपत्ति के अधिकार के संवैधानिक इतिहास में संशोधन कानूनों का एक निश्चित कालानुक्रम है। सबसे पहले 1951 का 1वाँ संशोधन अधिनियम पारित हुआ, जिसने अनुच्छेद 31A और 31B को जोड़ा। इसके बाद 1955 का 4वाँ संशोधन अधिनियम पारित हुआ, जिसने क्षतिपूर्ति के नियमों को बदला। फिर 1964 का 17वाँ संशोधन अधिनियम आया, जिसने नौवीं अनुसूची का विस्तार किया। अंत में 1971 का 25वाँ संशोधन आया, जिसने अनुच्छेद 31C को शामिल करके संपत्ति अधिकारों को सीमित किया।

97. (B) सशस्त्र बलों और पुलिस बलों के सदस्य
संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को यह विशेष शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और दूरसंचार प्रणालियों में कार्यरत कर्मियों के मूल अधिकारों को कानून बनाकर प्रतिबंधित या निरसित कर सकती है। इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य इन संवेदनशील सुरक्षा बलों के सदस्यों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों का उचित पालन सुनिश्चित करना और उनके बीच उच्च स्तर का अनुशासन बनाए रखना है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

98. (B) अनुच्छेद 19
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल की आधिकारिक उद्घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 358 के प्रभाव से अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत छह मौलिक स्वतंत्रताएँ स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं। इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा किसी अलग से विशेष आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यह प्रभाव पूरी तरह से संवैधानिक होता है।

99. (A) निलंबित अधिकारों को निर्दिष्ट करने वाले एक राष्ट्रपति के आदेश की
अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 358 के विपरीत, जहाँ अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकारों के प्रवर्तन को रोकने के लिए एक पृथक और विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश जारी करने की संवैधानिक आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति अपने आदेश में उन विशिष्ट अधिकारों का उल्लेख करते हैं जिन्हें न्यायालयों के माध्यम से लागू करने का अधिकार आपातकाल की अवधि तक निलंबित रहेगा।

100. (C) युद्ध या बाह्य आक्रमण
वर्ष 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 के प्रयोग की सीमाएँ निर्धारित कीं। इस संशोधन के अनुसार, अनुच्छेद 19 के तहत दी गई छह स्वतंत्रताओं को केवल तभी स्वतः निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण यानी बाह्य आपातकाल के आधार पर की गई हो। यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक आपातकाल के आधार पर लागू किया गया हो, तो अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएँ कदापि निलंबित नहीं होंगी।

101. (C) अनुच्छेद 20 और 21
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह ऐतिहासिक नियम बनाया गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करके अन्य मूल अधिकारों को लागू कराने के अधिकार को भले ही निलंबित कर दें, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के तहत दिए गए अधिकारों को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण और जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल के दौरान भी नागरिकों के लिए पूरी तरह लागू रहते हैं।

102. (A) P-4, Q-3, R-1, S-2
अनुच्छेदों और उनके प्रावधानों का सही मिलान इस प्रकार है। अनुच्छेद 31C कुछ नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाले कानूनों को सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों के लिए अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 34 किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 358 आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त स्वतंत्रताओं के स्वतः निलंबन का नियम निर्धारित करता है।

103. (B) मूल अधिकार अपरिवर्तनीय हैं और इन्हें छीनने के लिए संशोधन नहीं किया जा सकता है।
वर्ष 1967 के ऐतिहासिक आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय की ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने 6-5 के बहुमत से एक दूरगामी निर्णय दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मूल अधिकार पवित्र और अपरिवर्तनीय प्रकृति के हैं। संसद के पास संविधान में संशोधन करके भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को छीनने या कम करने की कोई शक्ति नहीं है। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 केवल संशोधन की प्रक्रिया बताता है, शक्ति नहीं।

104. (A) शंकरी प्रसाद मामला (1951)
वर्ष 1967 के गोलकनाथ मामले में निर्णय देते समय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले को उलट दिया था। इससे पहले वर्ष 1951 के शंकरी प्रसाद मामले और 1965 के सज्जन सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति है। गोलकनाथ फैसले ने इस पुराने कानूनी रुख को पूरी तरह बदलकर संसदीय शक्ति पर सीमा लगा दी।

Click Here to Buy book on Flipkart

105. (A) 24वाँ संशोधन अधिनियम, 1971
गोलकनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद ने वर्ष 1971 में 24वाँ संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। इस संशोधन के माध्यम से संसद ने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया और स्पष्ट रुप से यह घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में कटौती करने या उन्हें समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन करने की पूर्ण संवैधानिक शक्ति निहित है।

106. (A) यह निर्णय केवल भविष्य के मामलों पर लागू होता है, जिससे अतीत के संवैधानिक संशोधन सुरक्षित रहते हैं।
गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अमरीकी न्यायशास्त्र से प्रेरित होकर भविष्यलक्ष्यी निर्णय का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉस्पेक्टिव ओवररुलिंग लागू किया। इसका तात्पर्य यह था कि न्यायालय का यह नया फैसला कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, केवल भविष्य में किए जाने वाले संशोधनों और निर्णयों पर लागू होगा। इस सिद्धांत के प्रयोग से अतीत में किए गए प्रथम, चतुर्थ और सत्रहवें संवैधानिक संशोधन पूरी तरह से वैध और सुरक्षित बने रहे।

107. (C) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक मूल ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में किया गया था। इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति तो है, लेकिन वह इस शक्ति का प्रयोग करके संविधान के मूल ढांचे या मौलिक विशेषताओं को नष्ट, परिवर्तित या कमजोर नहीं कर सकती है।

108. (D) I, II, III और IV
सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मुकदमों में संविधान की कई विशेषताओं को मूल ढांचे का हिस्सा घोषित किया है। केशवानंद भारती और बाद के मामलों में संविधान की सर्वोच्चता, भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण और संविधान का परिसंघीय या संघीय ढांचा, इन सभी को मूल ढांचे का अभिन्न अंग माना गया है। अतः दिए गए सभी चारों तत्व मूल ढांचे की श्रेणी में पूरी तरह शामिल हैं।

109. (C) 13
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 भारत के न्यायिक इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा माना जाता है। इस ऐतिहासिक मामले की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कुल 13 न्यायाधीशों की अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था। इस पीठ ने 7-6 के बेहद सूक्ष्म और बारीक बहुमत से अपना फैसला सुनाया, जिसने संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करते हुए मूल ढांचे के सिद्धांत की नींव रखी थी।

110. (C) इसने 24वें संशोधन को वैध ठहराया, जिससे संसद को मूल ढाँचे के अधीन रहते हुए अधिकारों में परिवर्तन करने की अनुमति मिली।
केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से बरकरार रखा। न्यायालय ने गोलकनाथ फैसले को उलटते हुए माना कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। हालाँकि, न्यायालय ने इस संसदीय शक्ति पर एक अनिवार्य संवैधानिक सीमा लगा दी कि संसद संशोधन के माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है।

111. (C) अनुच्छेद 21
वर्ष 1978 के प्रसिद्ध मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले ने मुख्य रुप से अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किए गए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे का अभूतपूर्व विस्तार किया। इस निर्णय से पूर्व अनुच्छेद 21 की व्याख्या केवल कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा तक सीमित थी। मेनका गांधी फैसले के बाद न्यायालय ने यह तय किया कि यह अधिकार विधायिका के मनमाने कानूनों के विरुद्ध भी सुरक्षा देता है और इसमें गरिमापूर्ण जीवन शामिल है।

112. (C) मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज
मेनका गांधी मामला 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह क्रांतिकारी व्यवस्था दी कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर एक-दूसरे से अलग-थलग नहीं हैं, बल्कि वे आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। इन तीनों अनुच्छेदों के बीच पाए जाने वाले इस घनिष्ठ और सामंजस्यपूर्ण संवैधानिक संबंध को भारतीय न्यायशास्त्र में मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। इसका अर्थ है कि किसी एक अनुच्छेद का परीक्षण करते समय अन्य दोनों को ध्यान में रखना होगा।

113. (B) उचित, न्यायसंगत, तर्कसंगत और अ-मनमाना
मेनका गांधी फैसले 1978 से पहले अनुच्छेद 21 में उल्लिखित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ केवल यह था कि प्रक्रिया किसी औपचारिक कानून द्वारा बनाई गई हो। परंतु मेनका गांधी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया केवल औपचारिक ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह प्रक्रिया उचित, न्यायसंगत, तर्कसंगत और अ-मनमानी भी होनी चाहिए। यदि कोई कानून अनुचित या कठोर प्रक्रिया बनाता है, तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है।

114. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
मेनका गांधी मामले 1978 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में अमेरिकी विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से शामिल कर लिया। न्यायालय ने माना कि स्वतंत्रता से वंचित करने वाली कानूनी प्रक्रिया का निष्पक्ष, न्यायसंगत और तर्कसंगत होना अनिवार्य है। इसलिए कथन और कारण दोनों पूरी तरह सत्य हैं

Downloaded from www.pdf.tube

और कारण, कथन की बिल्कुल सही व्याख्या प्रस्तुत करता है, जिसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नई मजबूती दी।

115. (A) मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच
वर्ष 1980 के मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों और भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाए रखने पर विशेष बल दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व एक-दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं और भारतीय संविधान इन्हीं दोनों के बीच बने बारीक संतुलन की नींव पर मजबूती से खड़ा है।

116. (C) अनुच्छेद 14 और 19 के अधिकारों पर सभी नीति निदेशक तत्वों को
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने अनुच्छेद 31C का विस्तार करके यह प्रावधान करने का प्रयास किया था कि सभी नीति निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 में दिए गए मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता दी जाए। वर्ष 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। न्यायालय ने माना कि मूल अधिकारों पर नीति निदेशक तत्वों को पूर्ण प्राथमिकता देना संविधान के सामंजस्य और मूल ढांचे को बिगाड़ना है।

117. (A) संसद की सीमित संशोधन शक्ति
मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था दी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति स्वयं में सीमित है और यह सीमित संशोधन शक्ति ही संविधान की एक मूल विशेषता यानी मूल ढांचा है। इसलिए संसद अपनी इस सीमित संशोधन शक्ति का प्रयोग करके खुद को संविधान में संशोधन करने की असीमित या पूर्ण शक्ति प्रदान नहीं कर सकती है।

118. (D) मिनर्वा मिल्स मामला
यह प्रसिद्ध टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1980 के ऐतिहासिक मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में की गई थी। मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ ने पीठ की ओर से बोलते हुए कहा था कि भारतीय संविधान की इमारत भाग 3 के मूल अधिकारों और भाग 4 के नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन की नींव पर उठाई गई है। इनमें से किसी एक को दूसरे पर पूर्ण प्राथमिक अधिकार देना संविधान की मूल आत्मा और सामंजस्य को पूरी तरह नष्ट कर देगा।

119. (B) मूल अधिकार न्याययोग्य हैं जबकि नीति निदेशक तत्व न्याययोग्य नहीं हैं।
मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संवैधानिक प्रकृति में सबसे बड़ा और मौलिक अंतर उनकी न्याययोग्यता को लेकर है। संविधान के भाग 3 में शामिल मूल अधिकार न्याययोग्य हैं, जिसका अर्थ है कि यदि इनका उल्लंघन होता है तो नागरिक न्याय प्राप्ति के लिए सीधे न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके विपरीत भाग 4 में दिए गए नीति निदेशक तत्व न्याययोग्य नहीं हैं, जिन्हें लागू कराने के लिए अदालती कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

120. (D) I, II और III
चंपकम दोराइराजन मामला 1951, गोलकनाथ मामला 1967 और मिनर्वा मिल्स मामला 1980, ये तीनों ऐतिहासिक मुकदमे मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच प्राथमिकता और टकराव से गहराई से जुड़े रहे हैं। चंपकम दोराइराजन मामले में मूल अधिकारों को सर्वोच्च माना गया, गोलकनाथ मामले में संसद की शक्ति सीमित हुई और मिनर्वा मिल्स मामले में दोनों भागों के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन स्थापित किया गया। अतः तीनों मामले इस संवैधानिक विषय से जुड़े हैं।

121. (D) मूल अधिकार नीति निदेशक तत्वों पर प्रभावी होंगे।
वर्ष 1951 के मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराइराजन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के टकराव पर पहला ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय दिया कि भाग 3 के मूल अधिकार भाग 4 के नीति निदेशक तत्वों पर पूरी तरह से प्रभावी होंगे और नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों का सहायक बनकर कार्य करना होगा। यदि कोई नीति निदेशक तत्व मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो मूल अधिकार ही माना जाएगा।

NODIA

122. (A) अनुच्छेद 14 और 19
मिनर्वा मिल्स मामले 1980 के बाद की वर्तमान संवैधानिक स्थिति के अनुसार, अनुच्छेद 31C केवल आंशिक रूप से ही वैध बचा है। इसके तहत केवल वही कानून सुरक्षित हैं जो संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 39(b) और 39(c) को लागू करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे विशिष्ट कानूनों को केवल अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) और अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता का अधिकार) के उल्लंघन के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

123. (A) IV, II, III, I
मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति से संबंधित इन चार प्रमुख संवैधानिक मामलों का सही कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला वर्ष 1951 में तय हुआ था। इसके पश्चात सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामला वर्ष 1965 में आया। फिर आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला वर्ष 1967 में तय हुआ। अंत में ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला वर्ष 1973 में तय हुआ था।

124. (B) हाँ, बशर्ते संविधान का मूल ढांचा नष्ट न हो।
केशवानंद भारती मामले 1973 में स्थापित कानूनी सिद्धांत के अनुसार, संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की व्यापक संवैधानिक शक्ति है। हालाँकि, संसद की यह शक्ति निरपेक्ष नहीं है। संसद मूल अधिकारों में संशोधन केवल तब तक कर सकती है जब तक कि उस संशोधन से संविधान की मौलिक संरचना यानी मूल ढांचा प्रभावित या नष्ट न हो।

125. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
ऐतिहासिक मामलों और उनके सिद्धांतों का सही मिलान इस प्रकार है। गोलकनाथ मामला 1967 भविष्यलक्ष्यी निर्णय के सिद्धांत से संबंधित है। केशवानंद भारती मामला 1973 संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। मेनका गांधी मामला 1978 विधि की सम्यक प्रक्रिया और निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा है। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 भाग 3 के मूल अधिकारों और भाग 4 के नीति निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन स्थापित करता है।

126. (C) अनुच्छेद 368 के तहत बनाए गए कानून अनुच्छेद 13 के अधीन नहीं हैं।
वर्ष 1971 के 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 13 में एक नया खंड 13(4) शामिल किया गया था। यह खंड स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए किसी भी संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। इसका सीधा अर्थ यह था कि संसद द्वारा पारित संवैधानिक संशोधनों को अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं माना जाएगा और उन्हें मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जा सकेगा।

127. (B) केवल I, III और IV
संविधान के कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि कुछ नागरिकों और विदेशियों दोनों को मिलते हैं। अनुच्छेद 15, 16 और 29 केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध हैं, इसलिए पहला और चौथा कथन सत्य हैं। इसके विपरीत अनुच्छेद 21 नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, अतः तीसरा कथन सही है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता केवल नागरिकों तक ही सीमित रखी गई है।

128. (C) अनुच्छेद 18(1) (उपाधियों का अंत)
संविधान का अनुच्छेद 18(1) स्पष्ट रूप से राज्य को आदेश देता है कि वह सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यह प्रावधान पूरी तरह से राज्य की शक्तियों पर एक संवैधानिक प्रतिबंध है और यह निजी व्यक्तियों के विरुद्ध लागू नहीं होता है। इसके विपरीत अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23 जैसे अधिकार राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के गलत आचरण और शोषणकारी कृत्यों के विरुद्ध भी नागरिकों को व्यापक संरक्षण प्रदान करते हैं।

129. (B) सशस्त्र बल, पुलिस बल, गुप्तचर एजेंसियाँ और संबद्ध संचार प्रणाली
संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर विशिष्ट बलों के मूल अधिकारों को सीमित या समाप्त कर सकती है। इस अनुच्छेद का दायरा केवल थल सेना, नौसेना और वायु सेना तक ही सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत थल सेना, नौसेना, वायु सेना के अलावा पुलिस बल, खुफिया एजेंसियों, राष्ट्रीय सुरक्षा बलों और इन बलों के लिए स्थापित की गई संचार या सूचना प्रणालियों में कार्यरत सभी कर्मचारी और कर्मी शामिल किए गए हैं।

130. (C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
संविधान का अनुच्छेद 34 भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लागू होने के दौरान मूल अधिकारों पर संसद द्वारा प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था करता है, इसलिए कथन सही है। हालाँकि, भारत के संविधान में मार्शल लॉ शब्द को कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। यह अंग्रेजी सामान्य कानून की एक अवधारणा है जिसका अर्थ असाधारण परिस्थितियों में सेना द्वारा शासन चलाना है। अतः कारण गलत होने के कारण सही उत्तर का चयन किया गया है।

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Amazon

अध्याय 06
राज्य के नीति-निदेशक तत्व

1. राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) भारत के संविधान के किस भाग में निहित हैं?
(A) भाग III
(B) भाग IV
(C) भाग IV-A
(D) भाग V

2. भारत के संविधान में अनुच्छेदों का कौन-सा निरंतर क्रम राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है?
(A) अनुच्छेद 12 से 35
(B) अनुच्छेद 36 से 51
(C) अनुच्छेद 37 से 52
(D) अनुच्छेद 51A से 60

3. भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली थी?
(A) आयरलैंड
(B) संयुक्त राज्य अमेरिका
(C) सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ
(D) ऑस्ट्रेलिया

4. राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में 'गैर-न्यायोचित' शब्द का मूल अर्थ क्या है?
(A) इन्हें किसी भी परिस्थिति में संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है।
(B) ये उच्चतम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से प्रवर्तनीय हैं लेकिन उच्च न्यायालयों द्वारा नहीं।
(C) इनके उल्लंघन की स्थिति में इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता है।
(D) ये केवल संघ सरकार पर लागू होते हैं, राज्य सरकारों पर नहीं।

5. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): राज्य के नीति निदेशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।
कारण (R): संविधान यह घोषणा करता है कि नीति निदेशक तत्व फिर भी देश के शासन में मूलभूत हैं।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

NODIA

6. कौन-सा अनुच्छेद विशेष रूप से यह घोषित करता है कि नीति निदेशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, किंतु विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा?
(A) अनुच्छेद 36
(B) अनुच्छेद 37
(C) अनुच्छेद 38
(D) अनुच्छेद 39

7. राज्य के नीति निदेशक तत्व किस ऐतिहासिक दस्तावेज में उल्लिखित 'अनुदेश-प्रपत्र' (Instrument of Instructions) के समान हैं?
(A) भारत सरकार अधिनियम, 1919
(B) नेहरू रिपोर्ट, 1928
(C) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(D) उद्देश्य प्रस्ताव, 1946

8. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन निम्नलिखित में से किस रूप में किया था?
(A) संविधान की अंतरात्मा
(B) संविधान का मूल ढांचा
(C) संविधान की अनोखी विशेषताएं
(D) संविधान की आत्मा

9. निम्नलिखित संवैधानिक सलाहकारों में से किसने व्यक्तिगत अधिकारों को न्यायोचित और गैर-न्यायोचित श्रेणियों में विभाजित करने की सिफारिश की थी?
(A) के.एम. मुंशी
(B) अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
(C) टी.टी. कृष्णमाचारी
(D) सर बी.एन. राव

10. सूची I में DPSP से संबंधित कथनों को सूची II में उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: DPSP से संबंधित कथन
P. एक ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है
Q. संविधान की अंतरात्मा (मूल अधिकारों के साथ)
R. पवित्र आकांक्षाएं
S. भावनाओं का सच्चा कूड़ादान
सूची II: विचारक

1. टी.टी. कृष्णमाचारी
2. आइवर जेनिंग्स
3. ग्रैनविल ऑस्टिन
4. के.टी. शाह

(A) P-4, Q-3, R-2, S-1
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-4, Q-2, R-3, S-1
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

11. भारत में राज्य के नीति निदेशक तत्वों द्वारा मुख्य रूप से किस व्यापक उद्देश्य को स्थापित करने का प्रयास किया गया है?
(A) प्रतिनिधि राजनीतिक लोकतंत्र
(B) सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र
(C) सहभागितापूर्ण प्रत्यक्ष लोकतंत्र
(D) केंद्रीकृत सत्तावादी शासन

12. संविधान के अनुच्छेद 36 के अनुसार, भाग IV में 'राज्य' शब्द का वही अर्थ है जो संविधान के किस अन्य भाग में है?
(A) भाग II
(B) भाग III
(C) भाग V
(D) भाग VI

13. मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे सटीक अंतर है?
(A) मूल अधिकार राज्य पर नकारात्मक सीमाएं लगाते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए सकारात्मक निर्देश हैं।
(B) मूल अधिकार केवल सकारात्मक आदेशों के रूप में कार्य करते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व नकारात्मक आदेशों के रूप में कार्य करते हैं।
(C) मूल अधिकारों का उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है, जबकि नीति निदेशक तत्व राजनीतिक लोकतंत्र का निर्माण करना चाहते हैं।
(D) मूल अधिकार विशेष रूप से भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होते हैं।

14. राज्य के नीति निदेशक तत्वों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. ये एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का निर्माण करते हैं।
II. ये 'कल्याणकारी राज्य' की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं, न कि 'पुलिस राज्य' की।
III. ये सामाजिक न्याय के लिए स्थापित विशेष अधिकरणों में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा कथन समूह सही है?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

15. संविधान में परिकल्पित "आर्थिक लोकतंत्र" की अवधारणा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसमें निहित है?
(A) प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य
(B) मूल अधिकार और नौवीं अनुसूची
(C) पहली अनुसूची और भाग XI
(D) राज्य के नीति निदेशक तत्व

16. नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. ये न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने में न्यायालयों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं।
II. ये किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं।
III. यदि कोई कानून किसी नीति निदेशक तत्व को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है, तो उसे अनुच्छेद 14 या 19 के संबंध में 'युक्तियुक्त' माना जा सकता है।
IV. ये अपने विपरीत किसी भी संविधान-पूर्व कानून को स्वतः अमान्य कर देते हैं।
कथनों का कौन-सा समूह सही है?
(A) केवल I, II और IV
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, II और III
(D) केवल I, III और IV

17. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है?
(A) अनुच्छेद 38
(B) अनुच्छेद 39
(C) अनुच्छेद 40
(D) अनुच्छेद 41

18. यद्यपि संविधान औपचारिक रूप से नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण नहीं करता है, फिर भी विद्वान सामान्यतः इन्हें निम्नलिखित में से किन तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं?
(A) लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक-समाजवादी
(B) सामाजिक रूप से रुढ़िवादी, उदारवादी और कट्टरपंथी-लोकतांत्रिक
(C) पारंपरिक-सांस्कृतिक, आधुनिक और उत्तर-आधुनिक
(D) समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक

19. राज्य को आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का निर्देश देने वाला प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 38 में जोड़ा गया था?
(A) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
(B) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
(C) 86वां संशोधन अधिनियम, 2002

Downloaded from www.pdf.tube

(D) 97वां संशोधन अधिनियम, 2011

20. निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में उल्लिखित विशिष्ट निर्देशों में से एक नहीं है?
(A) सभी नागरिकों के लिए जीविका के पर्याप्त साधनों का समान अधिकार
(B) सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का न्यायसंगत वितरण
(C) राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
(D) पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन

21. संविधान के अनुच्छेद 39(b) और 39(c) क्रमशः निम्नलिखित में से किन विषयों से संबंधित हैं?
(A) भौतिक संसाधनों का वितरण और धन का संकेंद्रण रोकना
(B) समान कार्य के लिए समान वेतन तथा शिक्षा का अधिकार
(C) बाल शोषण की रोकथाम और काम का अधिकार
(D) प्रसूति सहायता का प्रावधान और श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी

22. "समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना" का निर्देश किस अनुच्छेद में निहित है?
(A) अनुच्छेद 38
(B) अनुच्छेद 39A
(C) अनुच्छेद 41
(D) अनुच्छेद 43A

23. नीति निदेशक तत्वों का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद विशेष रूप से बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की स्थिति में काम पाने, शिक्षा पाने और लोक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करने का निर्देश देता है?
(A) अनुच्छेद 41
(B) अनुच्छेद 42
(C) अनुच्छेद 43
(D) अनुच्छेद 44

24. संविधान का अनुच्छेद 42 राज्य को निम्नलिखित में से किसके लिए उपबंध करने का निर्देश देता है?
(A) वंचितों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता
(B) उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी
(C) काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता
(D) कृषि और पशुपालन का संगठन

25. कौन-सा अनुच्छेद राज्य को सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करने का निर्देश देता है?
(A) अनुच्छेद 41
(B) अनुच्छेद 42
(C) अनुच्छेद 43
(D) अनुच्छेद 43A

26. उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से कौन-सा नीति निदेशक तत्व जोड़ा गया था?
(A) अनुच्छेद 39A
(B) अनुच्छेद 43A
(C) अनुच्छेद 43B
(D) अनुच्छेद 48A

27. DPSP के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांत महात्मा गांधी की विचारधारा पर आधारित हैं। कौन-सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करने का निर्देश देता है?
(A) अनुच्छेद 39
(B) अनुच्छेद 40
(C) अनुच्छेद 44
(D) अनुच्छेद 47

NODIA

28. नीति निदेशक तत्वों के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए:
I. ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।
II. स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेयों और औषधियों के सेवन का प्रतिषेध करना।
III. देश भर में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना।
इनमें से कौन-सा/से प्रावधान विशुद्ध रूप से गांधीवादी सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है/करते हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

29. सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का निर्देश किस अनुच्छेद में निहित है?
(A) अनुच्छेद 43
(B) अनुच्छेद 43A
(C) अनुच्छेद 43B
(D) अनुच्छेद 46

30. किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान के भाग IV में सहकारी समितियों से संबंधित निर्देश जोड़ा?
(A) 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
(B) 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
(C) 97वां संशोधन अधिनियम, 2011
(D) 103वां संशोधन अधिनियम, 2019

31. संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य पर समाज के किन वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का कर्तव्य आरोपित करता है?
(A) देश भर में छह वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे
(B) धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय
(C) संवेदनशील महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और बेसहारा व्यक्ति
(D) अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य दुर्बल वर्ग

32. कौन-सा अनुच्छेद राज्य को गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू व वाहक मवेशियों के वध पर रोक लगाने तथा उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है?
(A) अनुच्छेद 46
(B) अनुच्छेद 47
(C) अनुच्छेद 48
(D) अनुच्छेद 48A

33. DPSP में उदार-बौद्धिक सिद्धांत उदारवाद की विचारधारा को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद विशेष रूप से इस श्रेणी के अंतर्गत आता है?
(A) अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायतें)
(B) अनुच्छेद 43 (कुटीर उद्योग)
(C) अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता)
(D) अनुच्छेद 46 (दुर्बल वर्गों की अभिवृद्धि)

34. संविधान का अनुच्छेद 44 भारत के नागरिकों के लिए किसका प्रावधान करता है?
(A) संपत्ति का अधिकार
(B) गरीबी रेखा से नीचे के सभी लोगों के लिए समान बुनियादी आय
(C) स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
(D) भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता

35. 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु को परिवर्तित कर दिया गया था। वर्तमान अनुच्छेद 45 राज्य को क्या प्रदान करने का निर्देश देता है?
(A) छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा
(B) चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा
(C) मेधावी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता
(D) सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पौष्टिक मध्याह्न भोजन का प्रावधान

36. कौन-सा अनुच्छेद राज्य पर राष्ट्रीय महत्व घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक, स्थान या वस्तु का संरक्षण करने की बाध्यता आरोपित करता है?
(A) अनुच्छेद 48A
(B) अनुच्छेद 49
(C) अनुच्छेद 50
(D) अनुच्छेद 51

37. संविधान का अनुच्छेद 50 शासन के किस महत्वपूर्ण पहलू से संबंधित है?
(A) लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
(B) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि
(C) पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्यजीवों की रक्षा
(D) आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से कृषि का संगठन

38. सूची I में दिए गए नीति निदेशक तत्व को सूची II में उसके संबंधित अनुच्छेद के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: नीति निदेशक तत्व
P. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि
Q. पर्यावरण तथा वन्यजीवों का संरक्षण
R. पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना
S. समान नागरिक संहिता
सूची II: अनुच्छेद
1. अनुच्छेद 47
2. अनुच्छेद 44
3. अनुच्छेद 51
4. अनुच्छेद 48A
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-1, Q-2, R-3, S-4

39. निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का निर्देश शामिल है?
(A) अनुच्छेद 46
(B) अनुच्छेद 47
(C) अनुच्छेद 48
(D) अनुच्छेद 49

40. अनुच्छेद 51 के तहत, राज्य निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी का प्रयास करेगा?
(A) राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना
(B) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना
(C) सभी युवाओं के लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण सुनिश्चित करना
(D) अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना

41. संविधान के भाग IV में उल्लिखित निम्नलिखित नीति निदेशक तत्वों का सही संख्यात्मक क्रम चुनिए:

Click Here to Buy book on Flipkart

I. ग्राम पंचायतों का संगठन
II. समान नागरिक संहिता
III. कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
IV. राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण
(A) I, II, IV, III
(B) I, II, III, IV
(C) II, I, IV, III
(D) II, IV, I, III

42. 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने मूल सूची में चार नए नीति निदेशक तत्व जोड़े। निम्नलिखित में से कौन-सा उनमें से एक नहीं था?
(A) आय, प्रतिष्ठा और अवसरों में असमानताओं को कम करना (अनुच्छेद 38)
(B) बच्चों और युवाओं के स्वस्थ विकास के अवसर सुरक्षित करना (अनुच्छेद 39)
(C) समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना (अनुच्छेद 39A)
(D) पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन करना और वन एवं वन्यजीवों की रक्षा करना (अनुच्छेद 48A)

43. युवाओं और बालकों के शोषण को रोकने के लिए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 39 में कौन-सा खंड विशेष रूप से अंतःस्थापित किया गया था?
(A) खंड (c)
(B) खंड (d)
(C) खंड (e)
(D) खंड (f)

44. मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच टकराव के ऐतिहासिक विकास में, उच्चतम न्यायालय के किस मामले में यह स्थापित किया गया था कि टकराव की स्थिति में मूल अधिकार प्रभावी होंगे और नीति निदेशक तत्व उनके सहायक के रूप में कार्य करेंगे?
(A) ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामला (1950)
(B) चंपकम दोरैराजन मामला (1951)
(C) आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला (1967)
(D) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला (1973)

45. किस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संसद किसी भी मूल अधिकार को छीन या कम नहीं कर सकती है, जिसका अर्थ है कि नीति निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है?
(A) शंकरी प्रसाद मामला (1951)
(B) सज्जन सिंह मामला (1965)
(C) गोलकनाथ मामला (1967)
(D) मिनर्वा मिल्स मामला (1980)

46. गोलकनाथ मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद ने कौन-सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, जिससे अनुच्छेद 31C अंतःस्थापित हुआ?
(A) 24वां संशोधन अधिनियम, 1971
(B) 25वां संशोधन अधिनियम, 1971
(C) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
(D) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978

NODIA

47. अनुच्छेद 31C के मूल प्रावधान के अनुसार, अनुच्छेद 39(b) और (c) में निर्दिष्ट निदेशक तत्वों को लागू करने वाली किसी विधि को किन मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जा सकता?
(A) अनुच्छेद 14, 19 और 21
(B) अनुच्छेद 14, 19 और 31
(C) अनुच्छेद 19, 21 और 22
(D) अनुच्छेद 15, 16 और 19

48. केशवानंद भारती मामले (1973) में, अनुच्छेद 31C के दूसरे भाग (जिसमें कहा गया था कि ऐसी नीति को प्रभावी करने की घोषणा करने वाले किसी कानून को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती) के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्या निर्णय था?
(A) सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए इसे पूरी तरह से वैध माना गया।
(B) भाग IV के सभी नीति निदेशक तत्वों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया।
(C) इसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीनने के कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया गया।
(D) इसे केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों पर लागू करने के लिए संशोधित किया गया।

49. 42वें संशोधन अधिनियम (1976) ने अनुच्छेद 31C के दायरे का विस्तार करके निम्नलिखित में से किसे इसके संरक्षण में शामिल करने का प्रयास किया?
(A) भाग IV में निहित केवल गांधीवादी नीति निदेशक तत्व
(B) भाग IV में निर्दिष्ट सभी नीति निदेशक तत्व
(C) भाग IV में निर्दिष्ट केवल उदार-बौद्धिक सिद्धांत
(D) भाग III के प्रावधानों को निरस्त करने वाला राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई भी कानून

50. मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि भारतीय संविधान निम्नलिखित के बीच संतुलन की आधारशिला पर टिका है:
(A) कार्यपालिका और न्यायपालिका
(B) संघ सरकार और राज्य सरकारें
(C) लोकसभा और राज्यसभा
(D) मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व

51. मिनर्वा मिल्स फैसले के बाद, नीति निदेशक तत्वों पर मूल अधिकारों की प्राथमिकता के संबंध में वर्तमान संवैधानिक स्थिति क्या है?
(A) मूल अधिकार सामान्यतः प्रभावी होते हैं, लेकिन अनुच्छेद

39(b) और (c) को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता प्राप्त है।
(B) सभी परिस्थितियों में सभी मूल अधिकारों पर सभी नीति निदेशक तत्वों की पूर्ण सर्वोच्चता है।
(C) नीति निदेशक तत्व केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं।
(D) किसी भी परिस्थिति में किसी भी मूल अधिकार के विरुद्ध किसी भी नीति निदेशक तत्व को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है।

52. सूची I में दिए गए संवैधानिक मामले को सूची II में DPSP से संबंधित उसके प्राथमिक फैसले के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: संवैधानिक मामला
P. चंपकम दोरैराजन मामला
Q. गोलकनाथ मामला
R. केशवानंद भारती मामला
S. मिनर्वा मिल्स मामला
सूची II: प्राथमिक फैसला
1. DPSP को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
2. न्यायिक समीक्षा एक मूल विशेषता है; 31C का दूसरा भाग शून्य है।
3. मूल अधिकारों और DPSP के बीच संतुलन मूल ढांचे का हिस्सा है।
4. DPSP को मूल अधिकारों के अनुरूप होना होगा और उनके सहायक के रूप में कार्य करना होगा।
(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-1, Q-4, R-3, S-2
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

53. मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच टकराव को सुलझाने के लिए केरल शिक्षा विधेयक मामले (1957) में उच्चतम न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से किस सिद्धान्त को लागू किया गया था?
(A) सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वियन का सिद्धांत
(B) ग्रहण का सिद्धांत
(C) पृथक्करणीयता का सिद्धांत
(D) पित्त और सार का सिद्धांत

54. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): प्रत्येक संवैधानिक परिस्थिति में नीति निदेशक तत्व पूरी तरह से मूल अधिकारों के अधीन हैं।
कारण (R): किसी नीति निदेशक तत्व को प्रभावी बनाने के लिए संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

55. नीति निदेशक तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. संविधान स्पष्ट रूप से DPSP को समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी श्रेणियों में विभाजित करता है।
II. कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्देश देने वाला अनुच्छेद 43, एक गांधीवादी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है।
III. समान नागरिक संहिता का निर्देश देने वाले अनुच्छेद 44 को उदार-बौद्धिक सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
IV. अनुच्छेद 47 में एक समाजवादी तत्व (जीवन स्तर को ऊंचा उठाना) और एक गांधीवादी तत्व (नशीले पेयों का प्रतिषेध) दोनों शामिल हैं।
कथनों का कौन-सा समूह सही है?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, III और IV
(D) I, II, III और IV

NODIA

56. स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम दो दशकों के दौरान अनुच्छेद 39(b) और (c) के विधायी कार्यान्वयन ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उपाय का रूप लिया?
(A) बैंकिंग क्षेत्र और नागरिक उड्डयन का व्यापक राष्ट्रीयकरण
(B) सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना
(C) जमींदारी उन्मूलन सम्बंधी भूमि सुधार कानूनों का अधिनियमन
(D) कई राज्यों में समान नागरिक संहिता का अधिनियमन

57. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948) और बोनस भुगतान अधिनियम (1965) किस विशिष्ट नीति निदेशक तत्व को प्रभावी बनाने के लिए बनाए गए विधानों के प्रमुख उदाहरण हैं?
(A) अनुच्छेद 41 (काम का अधिकार)
(B) अनुच्छेद 42 (प्रसूति सहायता)
(C) अनुच्छेद 43 (कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी)
(D) अनुच्छेद 46 (दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक हित)

58. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 किस विशिष्ट संवैधानिक निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था?
(A) अनुच्छेद 39(a)
(B) अनुच्छेद 39(d)
(C) अनुच्छेद 41
(D) अनुच्छेद 42

59. मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित उद्देश्य को पूरा करता है?
(A) अनुच्छेद 41
(B) अनुच्छेद 42

(C) अनुच्छेद 43
(D) अनुच्छेद 45

60. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में अनुच्छेद 51 के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए:
I. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना।
II. राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना।
III. अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना।
IV. मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहन देना।
उपर्युक्त में से कौन-सा समूह अनुच्छेद 51 के मूल संवैधानिक पाठ का प्रतिनिधित्व करता है?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

61. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था। यह किस DPSP को सीधे लागू करता है?
(A) अनुच्छेद 38
(B) अनुच्छेद 39A
(C) अनुच्छेद 41
(D) अनुच्छेद 46

62. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, किस नीति निदेशक तत्व की व्यावहारिक पूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है?
(A) अनुच्छेद 40
(B) अनुच्छेद 43
(C) अनुच्छेद 47
(D) अनुच्छेद 48

63. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 किस नीति निदेशक तत्व को वैधानिक समर्थन देने के लिए अधिनियमित किए गए थे?
(A) अनुच्छेद 47
(B) अनुच्छेद 48
(C) अनुच्छेद 48A
(D) अनुच्छेद 49

64. भारत में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) की स्थापना मुख्य रूप से किस नीति निदेशक तत्व के अनुरूप थी?
(A) अनुच्छेद 43 (कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना)
(B) अनुच्छेद 46 (दुर्बल वर्गों के आर्थिक हितों की अभिवृद्धि)
(C) अनुच्छेद 48 (कृषि का संगठन)
(D) अनुच्छेद 50 (शक्तियों का पृथक्करण)

65. DPSP को प्रभावित करने वाले संवैधानिक संशोधनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. 42वें संशोधन ने पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के निर्देश को जोड़ा।
II. 44वें संशोधन ने आय और प्रतिष्ठा में असमानताओं को कम करने का निर्देश जोड़ा।
III. 86वें संशोधन ने भाग IV से अनुच्छेद 45 को पूरी तरह से हटा दिया।
IV. 97वें संशोधन ने सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निर्देश जोड़ा।
कौन-सा समूह सही है?
(A) केवल I, II और IV
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, II और III

66. दंड प्रक्रिया संहिता (1973) ने न्यायिक मजिस्ट्रेटों को कार्यपालक मजिस्ट्रेटों से अलग किया, जिससे किस अनुच्छेद में निहित निर्देश का कार्यान्वयन हुआ?
(A) अनुच्छेद 44
(B) अनुच्छेद 49
(C) अनुच्छेद 50
(D) अनुच्छेद 51

67. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) नागरिकों के कल्याण से संबंधित किस मौलिक निर्देश को प्रभावी बनाता है?
(A) जीविका का अधिकार (अनुच्छेद 39(a)) और काम का अधिकार (अनुच्छेद 41)
(B) निःशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय का अधिकार (अनुच्छेद 39A)
(C) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 45)
(D) औद्योगिक प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी (अनुच्छेद 43A)

68. भारत के कुछ राज्यों, जैसे गुजरात और बिहार, ने मद्यपान पर प्रतिबंध लगाते हुए कड़े शराबबंदी कानून बनाए हैं। यह किस संवैधानिक निर्देश का प्रत्यक्ष कार्यान्वयन है?
(A) अनुच्छेद 46
(B) अनुच्छेद 47
(C) अनुच्छेद 48
(D) अनुच्छेद 49

69. भारत के विभिन्न राज्यों ने गोवध पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किए हैं। यह विधायी कार्रवाई किस अनुच्छेद से संवैधानिक आधार प्राप्त करती है?
(A) अनुच्छेद 46
(B) अनुच्छेद 47
(C) अनुच्छेद 48
(D) अनुच्छेद 48A

Downloaded from www.pdf.tube

70. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना का उद्देश्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना है, जैसा कि किस अनुच्छेद द्वारा निर्देशित किया गया है?
(A) अनुच्छेद 41
(B) अनुच्छेद 43
(C) अनुच्छेद 45
(D) अनुच्छेद 46

71. 'समान नागरिक संहिता' (UCC) का सिद्धांत निरंतर चर्चा का विषय रहा है। स्वतंत्रता के बाद से ही समान नागरिक संहिता लागू रखने वाला भारत का राज्य कौन-सा है?
(A) महाराष्ट्र
(B) गोवा
(C) केरल
(D) गुजरात

72. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): संविधान निर्माताओं ने नीति निदेशक तत्वों को गैर-न्यायोचित और कानूनी रूप से गैर-प्रवर्तनीय बनाया।
कारण (R): स्वतंत्र भारत के पास इन सभी को तुरंत लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी थी।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

73. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने नीति निदेशक तत्वों की गैर-न्यायोचित प्रकृति का औचित्य सिद्ध करते हुए कहा था कि इनके पीछे वास्तविक शक्ति क्या है?
(A) भारत का उच्चतम न्यायालय और संवैधानिक न्यायालय
(B) मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति
(C) अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एजेंसियां और संधियां
(D) लोकमत और मतदाता

74. के. संथानम के अनुसार, संविधान में नीति निदेशक तत्वों को शामिल करने से किनके बीच संवैधानिक टकराव पैदा हो सकता है?
(A) राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री तथा केंद्र व राज्य के बीच
(B) उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के बीच
(C) लोकसभा और राज्यसभा के बीच
(D) भारत के निर्वाचन आयोग और संसद के बीच

75. मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच टकराव के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का सही कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) गोलकनाथ मामला, चंपकम दोरैराजन मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, केशवानंद भारती मामला
(B) चंपकम दोरैराजन मामला, गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला
(C) केशवानंद भारती मामला, गोलकनाथ मामला, चंपकम दोरैराजन मामला, मिनर्वा मिल्स मामला
(D) चंपकम दोरैराजन मामला, केशवानंद भारती मामला, गोलकनाथ मामला, मिनर्वा मिल्स मामला

NODIA

76. भाग IV के अतिरिक्त संविधान के अन्य भागों में भी राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं। कौन-सा अनुच्छेद यह निर्देशित करता है कि प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के साथ, सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का ध्यान रखा जाएगा?
(A) अनुच्छेद 330
(B) अनुच्छेद 335
(C) अनुच्छेद 340
(D) अनुच्छेद 350A

77. भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश किस अनुच्छेद में निहित है?
(A) अनुच्छेद 29
(B) अनुच्छेद 30
(C) अनुच्छेद 350A
(D) अनुच्छेद 351

78. सूची I में दिए गए DPSP अनुच्छेदों को सूची II में उनके वैचारिक वर्गीकरण के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: DPSP अनुच्छेद
P. अनुच्छेद 39 (धन का न्यायसंगत वितरण)
Q. अनुच्छेद 43 (कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना)
R. अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता)
S. अनुच्छेद 48 (गोवध पर रोक)
सूची II: वैचारिक वर्गीकरण
1. उदार-बौद्धिक सिद्धांत
2. समाजवादी सिद्धांत
3. गांधीवादी सिद्धांत
(A) P-2, Q-3, R-1, S-3
(B) P-3, Q-2, R-1, S-1
(C) P-2, Q-1, R-3, S-3
(D) P-1, Q-2, R-3, S-3

79. संघ के लिए हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देने और उसका विकास करने का निर्देश, ताकि यह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, किस अनुच्छेद में निहित है?
(A) अनुच्छेद 343
(B) अनुच्छेद 345
(C) अनुच्छेद 350A
(D) अनुच्छेद 351

80. क्या भाग IV के बाहर निहित संवैधानिक निर्देश (जैसे अनुच्छेद 335, 350A और 351) न्यायालयों द्वारा न्यायोचित हैं?
(A) हां, भाग IV के विपरीत वे पूरी तरह से न्यायोचित हैं।
(B) हां, लेकिन केवल अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में।
(C) नहीं, ये भाग IV के निर्देशों की तरह ही गैर-न्यायोचित हैं।
(D) ये केवल तभी न्यायोचित हैं जब संसद इस हेतु विधि पारित करती है।

81. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1951 किस नीति निदेशक तत्व द्वारा राज्य पर आरोपित दायित्व को लागू करने के लिए पारित किया गया था?
(A) अनुच्छेद 48A
(B) अनुच्छेद 49
(C) अनुच्छेद 50
(D) अनुच्छेद 51

82. निम्नलिखित में से कौन-सी आलोचना संवैधानिक विद्वानों द्वारा नीति निदेशक तत्वों के विरुद्ध की जाती है?
(A) वे अत्यधिक कठोर हैं और विधायी लचीलेपन को रोकते हैं।
(B) वे वैध कानूनों को निरस्त करने के लिए न्यायपालिका को अत्यधिक शक्ति देते हैं।
(C) वे स्वभाव से पुराने हैं और आधुनिक समाज को संबोधित करने में विफल रहते हैं।
(D) इनमें कानूनी शक्ति का अभाव है और ये केवल नैतिक उपदेश मात्र हैं।

83. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): मिनर्वा मिल्स मामले में उच्चतम न्यायालय ने 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए अनुच्छेद 31C के विस्तार को निरस्त कर दिया।
कारण (R): न्यायालय ने माना कि मूल अधिकारों पर सभी नीति निदेशक तत्वों को पूर्ण प्राथमिकता देने से संविधान का मूल ढांचा नष्ट हो जाएगा।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

84. किस संवैधानिक संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया, जिससे संपत्ति अधिकार और भूमि सुधार संबंधी निर्देशों के बीच टकराव का समाधान हुआ?
(A) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
(B) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
(C) 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
(D) 86वां संशोधन अधिनियम, 2002

85. शाह बानो मामले (1985) ने मुख्य रूप से किस नीति निदेशक तत्व के कार्यान्वयन से संबंधित राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया?
(A) अनुच्छेद 39(d) - समान कार्य के लिए समान वेतन
(B) अनुच्छेद 44 - समान नागरिक संहिता
(C) अनुच्छेद 45 - प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख
(D) अनुच्छेद 47 - नशीले पेयों पर प्रतिषेध

86. DPSP का कौन-सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य अपनी नीति को इस प्रकार निर्देशित करेगा कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो?
(A) अनुच्छेद 39(e)
(B) अनुच्छेद 39(f)
(C) अनुच्छेद 41
(D) अनुच्छेद 42

87. स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा अपनाई गई पंचवर्षीय योजनाएं मुख्य रूप से संविधान के किस भाग में निर्धारित सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को साकार करने के लिए तैयार की गई थीं?
(A) भाग I
(B) भाग II
(C) भाग III
(D) भाग IV

88. 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसने गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 39A जोड़ा।
II. इसने उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी के लिए अनुच्छेद 43A जोड़ा।
III. इसने पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए अनुच्छेद 48A जोड़ा।
इनमें से कौन-सा समूह इस संशोधन द्वारा किए गए परिवर्तनों को सही ढंग से दर्शाता है?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

89. अनुच्छेद 47 के तहत, अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना किसके अंतर्गत स्वीकार किया गया है?
(A) नागरिकों के मौलिक अधिकार
(B) नागरिकों के मौलिक कर्तव्य
(C) राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां
(D) राज्य के प्राथमिक कर्तव्य

90. किस विद्वान ने नीति निदेशक तत्वों का वर्णन 'अनुदेश-प्रपत्र' (Instrument of Instructions) के रूप में किया था?
(A) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

Click Here to Buy book on Amazon

(B) प्रोफेसर के.टी. शाह
(C) डॉ. एल.एम. सिंघवी
(D) प्रोफेसर एम.वी. पायली

91. पंचशील और गुटनिरपेक्षता जैसे भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित संवैधानिक जनादेश से प्रेरित हैं?
(A) अनुच्छेद 48
(B) अनुच्छेद 49
(C) अनुच्छेद 50
(D) अनुच्छेद 51

92. राज्य प्रायोजित वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS), अपनी संवैधानिक वैधता मुख्य रुप से किस नीति निदेशक तत्व से प्राप्त करती हैं?
(A) अनुच्छेद 38
(B) अनुच्छेद 41
(C) अनुच्छेद 44
(D) अनुच्छेद 47

93. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 मुख्य रुप से किस वैचारिक धारा को दर्शाता है?
(A) गांधीवादी और उदार-बौद्धिक सिद्धांतों का संयोजन
(B) कड़ाई से समाजवादी सिद्धांत
(C) पूरी तरह से उदार-बौद्धिक सिद्धांत
(D) केवल अंतर्राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत

94. "पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन" की संवैधानिक स्थिति क्या है?
(A) केवल एक वैधानिक अधिकार, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है
(B) अनुच्छेद 14 के अंतर्गत एक मूल अधिकार
(C) अनुच्छेद 39 के तहत राज्य का एक नीति निदेशक तत्व
(D) अनुच्छेद 51A के तहत एक मौलिक कर्तव्य

95. कौन-सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य अपनी नीति को इस प्रकार निर्देशित करेगा कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो?
(A) अनुच्छेद 39(a)
(B) अनुच्छेद 39(b)
(C) अनुच्छेद 39(c)
(D) अनुच्छेद 39(d)

96. किस देश का संविधान आयरिश संविधान में नीति निदेशक तत्वों को शामिल करने का प्रेरणा स्रोत बना, जिससे प्रेरित होकर भारतीय संविधान में इन्हें शामिल किया गया?
(A) वाइमर गणराज्य का संविधान
(B) फ्रांस का संविधान
(C) स्पेन का संविधान
(D) स्विट्ज़रलैंड का संविधान

97. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 उस संवैधानिक निर्देश को पूरा करने के लिए बनाया गया जो मूल रुप से किस अनुच्छेद में निहित था?
(A) अनुच्छेद 41
(B) अनुच्छेद 45
(C) अनुच्छेद 46
(D) अनुच्छेद 47

98. निम्नलिखित में से किस संस्था/प्राधिकरण ने यह माना है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मूल अधिकारों की व्याख्या करने में नीति निदेशक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं?
(A) भारत का निर्वाचन आयोग
(B) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(C) वित्त आयोग
(D) भारत का उच्चतम न्यायालय

99. सूची I में दिए गए अधिनियम को सूची II में उससे संबंधित प्राथमिक DPSP अनुच्छेद के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: अधिनियम
P. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
Q. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
R. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
S. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
सूची II: प्राथमिक DPSP अनुच्छेद
1. अनुच्छेद 42
2. अनुच्छेद 39A
3. अनुच्छेद 48A
4. अनुच्छेद 43
(A) P-2, Q-1, R-4, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

NODIA

100. यदि भारत में कोई राज्य सरकार अपनी नीतियां बनाते समय नीति निदेशक तत्वों की उपेक्षा करती है, तो नागरिकों के पास क्या संवैधानिक उपचार उपलब्ध है?
(A) उच्च न्यायालय में परमादेश रिट दायर करना
(B) सीधे उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर करना
(C) कोई न्यायिक उपचार नहीं है; इसका उपचार मताधिकार द्वारा ही संभव है
(D) राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति से अपील करना

101. अनुच्छेद 43 राज्य को श्रमिकों के लिए 'निर्वाह मजदूरी' सुरक्षित करने का निर्देश देता है। 'निर्वाह मजदूरी' और 'न्यूनतम मजदूरी' में मौलिक अंतर क्या है?
(A) न्यूनतम मजदूरी में केवल जीवन निर्वाह शामिल है,

टी.टी. कृष्णमाचारी ने इन्हें भावनाओं का सच्चा कूड़ादान कहा था। यह सुमेलित क्रम संविधान सभा के विभिन्न दृष्टिकोणों को दर्शाता है।

11. (B) सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र
राज्य के नीति निदेशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए ये तत्व एक खाका प्रदान करते हैं। केवल राजनीतिक लोकतंत्र नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आर्थिक समता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करके एक वास्तविक कल्याणकारी राज्य के निर्माण हेतु इन सिद्धांतों को संविधान में जोड़ा गया।

12. (B) भाग III
संविधान का अनुच्छेद 36 यह स्पष्ट करता है कि भाग IV में 'राज्य' शब्द का वही अर्थ है जो भाग III (मूल अधिकार) के अनुच्छेद 12 में दिया गया है। इसके अंतर्गत भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थित सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। इस प्रकार, नीति निदेशक तत्व केंद्र और राज्य स्तर की सभी विधायी तथा कार्यपालक संस्थाओं पर समान रूप से लागू होते हैं।

13. (A) मूल अधिकार राज्य पर नकारात्मक सीमाएं लगाते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए सकारात्मक निर्देश हैं।
मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में मौलिक अंतर उनकी प्रकृति का है। मूल अधिकार राज्य की शक्तियों पर नकारात्मक प्रतिबंध लगाते हैं, क्योंकि ये राज्य को नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण करने से रोकते हैं। इसके विपरीत, नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए सकारात्मक निर्देश हैं, जो राज्य को जनकल्याण और सामाजिक न्याय के लिए नीतियां बनाने तथा कानून लागू करने के लिए निरंतर प्रेरित और निर्देशित करते हैं।

14. (A) केवल I और II
नीति निदेशक तत्व एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। ये तत्व औपनिवेशिक काल के 'पुलिस राज्य' की अवधारणा को बदलकर 'कल्याणकारी राज्य' की स्थापना पर बल देते हैं। हालांकि, ये सिद्धांत किसी भी अधिकरण या न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं कराए जा सकते। इसलिए, केवल प्रथम और द्वितीय कथन सही हैं, जबकि तृतीय कथन कानूनी रूप से असत्य है।

15. (D) राज्य के नीति निदेशक तत्व
संविधान में परिकल्पित 'आर्थिक लोकतंत्र' की अवधारणा मुख्य रूप से राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित है। मूल अधिकार नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व आर्थिक सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इनमें धन के न्यायसंगत वितरण, जीविका के साधनों की उपलब्धता और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के प्रावधान शामिल हैं, जो वास्तविक आर्थिक लोकतंत्र की आधारशिला हैं।

16. (C) केवल I, II और III
नीति निदेशक तत्व न्यायालयों के लिए न्यायिक समीक्षा में सहायक और कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करने में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। यदि कोई कानून किसी निदेशक तत्व को लागू करने के लिए बनाया गया है, तो न्यायालय उसे अनुच्छेद 14 या 19 के संदर्भ में युक्तियुक्त मान सकता है। हालांकि, ये तत्व किसी संविधान-पूर्व कानून को स्वतः निरस्त नहीं करते, इसलिए चौथा कथन गलत है।

17. (A) अनुच्छेद 38
संविधान का अनुच्छेद 38 राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। यह अनुच्छेद राज्य को आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करने का प्रयास करने का भी निर्देश देता है, जो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आधार है।

18. (D) समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक
यद्यपि भारत के संविधान में नीति निदेशक तत्वों का कोई औपचारिक या लिखित वर्गीकरण नहीं किया गया है, फिर भी उनकी विषय-वस्तु और दिशा के आधार पर विद्वान उन्हें तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित करते हैं। ये तीन श्रेणियां हैं: समाजवादी सिद्धांत (जो सामाजिक-आर्थिक न्याय पर बल देते हैं), गांधीवादी सिद्धांत (जो ग्राम स्वराज और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देते हैं) तथा उदार-बौद्धिक सिद्धांत (जो आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टि पर आधारित हैं)।

19. (B) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अनुच्छेद 38 के तहत एक नया प्रावधान (खंड 2) जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य को यह विशेष निर्देश दिया गया कि वह न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने और कम करने का निरंतर प्रयास करेगा।

20. (C) राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
संविधान का अनुच्छेद 39 राज्य को जीविका के पर्याप्त साधन, भौतिक संसाधनों का न्यायसंगत वितरण, धन के संकेंद्रण को रोकने, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा बालकों के स्वास्थ्य संरक्षण का निर्देश देता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने का निर्देश अनुच्छेद 39 में नहीं, बल्कि अनुच्छेद 50 में शामिल है। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 39 के निर्देशों में सम्मिलित नहीं है।

Downloaded from www.pdf.tube

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from
PRINTED BOOKS has up to
4× HIGHER RETENTION
than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY
PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

(A) जवाहरलाल नेहरू
(B) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
(C) सरदार वल्लभभाई पटेल
(D) के.टी. शाह

112. किस अनुच्छेद के तहत राज्य संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों, स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करने के लिए बाध्य है?
(A) अनुच्छेद 48A
(B) अनुच्छेद 49
(C) अनुच्छेद 50
(D) अनुच्छेद 51A

113. 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किन भागों को संशोधित/प्रभावित किया?
(A) केवल भाग III (मूल अधिकार)
(B) केवल भाग IV (नीति निदेशक तत्व)
(C) भाग III और भाग IV दोनों
(D) केवल भाग IX (पंचायतें)

114. विभिन्न DPSP को लागू करने के लिए बनाए गए निम्नलिखित अधिनियमों को उनके अधिनियमन के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम
II. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
III. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम
IV. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनिए:
(A) II, III, IV, I
(B) II, IV, III, I
(C) III, II, I, IV
(D) IV, II, III, I

115. अनुच्छेद 47 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह राज्य को अपने लोगों के पोषण स्तर को ऊंचा उठाने का निर्देश देता है।
II. यह राज्य को अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का निर्देश देता है।
III. यह लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानता है।
IV. यह सभी आधुनिक एलोपैथिक दवाओं के पूर्ण प्रतिषेध का आदेश देता है।
कौन-सा समूह अनुच्छेद 47 के प्रावधानों को सही ढंग से दर्शाता है?
(A) केवल I, II और IV
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल I, II और III
(D) केवल II, III और IV

NODIA

116. DPSP के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संयुक्त राष्ट्र और उसके शांति अभियानों में भारत की सक्रिय भागीदारी के संवैधानिक आधार के रूप में उद्धृत किया जाता है?
(A) अनुच्छेद 48
(B) अनुच्छेद 49
(C) अनुच्छेद 50
(D) अनुच्छेद 51

117. DPSP एक "कल्याणकारी राज्य" की स्थापना पर जोर देता है। भारतीय संविधान में परिकल्पित कल्याणकारी राज्य की मुख्य विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन-सा करता है?
(A) नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने वाला राज्य।
(B) एक ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों की सभी गतिविधियों पर पूर्ण, केंद्रीकृत नियंत्रण रखता है।
(C) एक ऐसा राज्य जो अपने कार्यों को केवल आंतरिक कानून-व्यवस्था और सुरक्षा तक सीमित रखता है।
(D) एक ऐसा राज्य जो नागरिकों को सार्वजनिक सेवाएं देने के लिए केवल निजी उद्यमों पर निर्भर रहता है।

118. DPSP के संदर्भ में, अनुच्छेद 36 में 'राज्य' शब्द में क्या शामिल नहीं है?
(A) भारत की सरकार और संसद
(B) प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल
(C) भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी
(D) वाणिज्यिक अनुबंधों का निष्पादन करने वाले निजी निगम

119. नीति निदेशक तत्वों की एक प्रमुख आलोचना यह है कि वे "अतार्किक रूप से व्यवस्थित" हैं। इस आलोचना का क्या अर्थ है?
(A) वे संविधान के अलग-अलग भागों में असंगत रूप से बिखरे हुए हैं।
(B) पाठ में तार्किक और सुसंगत वैचारिक वर्गीकरण का अभाव है।
(C) उन्हें मौलिक कर्तव्यों के बाद रखा जाना चाहिए था।
(D) वे संविधान की प्रस्तावना के मूल्यों के विपरीत हैं।

120. निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों में कोई बदलाव या जोड़ नहीं किया?
(A) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
(B) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
(C) 61वां संशोधन अधिनियम, 1989
(D) 86वां संशोधन अधिनियम, 2002

121. यह निर्देश कि बालकों को आर्थिक आवश्यकता के कारण अपनी आयु या शक्ति के अनुकूल न होने वाले रोजगारों में

जबकि निर्वाह मजदूरी में शिक्षा, स्वास्थ्य और विश्राम भी शामिल हैं।
(B) निर्वाह मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम होती है और इसमें केवल बुनियादी आवश्यकताएं शामिल होती हैं।
(C) निर्वाह मजदूरी केवल कृषि श्रमिकों पर लागू होती है, जबकि न्यूनतम मजदूरी औद्योगिक श्रमिकों पर लागू होती है।
(D) संवैधानिक कानून में वे समानार्थी शब्द हैं और उनके बीच कोई अंतर नहीं है।

102. नीति निदेशक तत्वों का कौन-सा अनुच्छेद राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश देता है?
(A) अनुच्छेद 41
(B) अनुच्छेद 42
(C) अनुच्छेद 43
(D) अनुच्छेद 43A

103. संविधान में कहा गया है कि राज्य नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC) सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। गोवा के अतिरिक्त, हाल ही में 2024 में किस राज्य की विधानसभा ने UCC विधेयक पारित किया?
(A) राजस्थान
(B) उत्तराखंड
(C) मध्य प्रदेश
(D) उत्तर प्रदेश

104. मूल अधिकारों (FR) और राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के बीच संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?
(A) मूल अधिकार राज्य पर नकारात्मक सीमाएं लगाते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व सकारात्मक निर्देश हैं।
(B) मूल अधिकार न्यायालयों में न्यायोचित हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व गैर-न्यायोचित हैं।
(C) सभी टकरावों में DPSP को हमेशा मूल अधिकारों पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
(D) मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं।

105. अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों के संवर्धन को शामिल करना भारत के किस क्षेत्र में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है?
(A) भारी औद्योगिक निर्माण क्षेत्र
(B) अंतरिक्ष अनुसंधान और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम
(C) अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक संबंध और द्विपक्षीय व्यापार
(D) ग्रामीण और कृषि आर्थिक विकास

106. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): राज्य के नीति निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन के लिए विधि (कानून) के निर्माण की आवश्यकता होती है।
कारण (R): ये स्वतः लागू नहीं होते हैं और मूल अधिकारों की तरह नागरिकों पर इनका तत्काल बाध्यकारी प्रभाव नहीं होता है।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

107. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य को लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है?
(A) अनुच्छेद 48
(B) अनुच्छेद 49
(C) अनुच्छेद 50
(D) अनुच्छेद 51

108. निम्नलिखित विधायी/प्रशासनिक उपायों पर विचार कीजिए:
I. जमींदारी प्रथा का उन्मूलन
II. योजना आयोग (अब नीति आयोग) की स्थापना
III. मातृत्व लाभ अधिनियम का पारित होना
IV. वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण
राज्य के नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा उपर्युक्त में से कौन-से कदम उठाए गए थे?
(A) केवल I और III
(B) केवल II और IV
(C) केवल I, II और III
(D) I, II, III और IV

109. भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण दोहरी प्रकृति का है। जहाँ अनुच्छेद 48A इसे राज्य के लिए नीति निदेशक तत्व बनाता है, वहीं कौन-सा अनुच्छेद इसे नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य बनाता है?
(A) अनुच्छेद 51A(a)
(B) अनुच्छेद 51A(e)
(C) अनुच्छेद 51A(g)
(D) अनुच्छेद 51A(k)

110. DPSP का कौन-सा अनुच्छेद यह बताता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके?
(A) अनुच्छेद 39(a)
(B) अनुच्छेद 39(b)
(C) अनुच्छेद 39(c)
(D) अनुच्छेद 39(d)

111. "निदेशक तत्व बैंक के उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है।" यह कथन किसके द्वारा दिया गया था?

Click Here to Buy book on Flipkart

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) भाग IV
भारतीय संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का समावेश किया गया है। यह भाग संविधान में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है। इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य देश में एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। राज्य जब भी अपनी नीतियों और कानूनों का निर्माण करता है, तो उसे इन सिद्धांतों को ध्यान में रखने का निर्देश दिया जाता है।

2. (B) अनुच्छेद 36 से 51
भारतीय संविधान का भाग IV अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जबकि अनुच्छेद 37 में इनकी गैर-न्यायोचित प्रकृति और शासन में मूलभूत महत्व को स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 38 से 51 के बीच विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया गया है।

3. (A) आयरलैंड
भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की थी। आयरलैंड ने स्वयं इन सिद्धांतों को 1937 के अपने संविधान में स्पेन के संविधान से शामिल किया था। भारत में इन सिद्धांतों को शामिल करने का प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के सामाजिक और आर्थिक आदर्शों को संवैधानिक रूप देना तथा भारत को एक वास्तविक सामाजिक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित करना था।

4. (C) इनके उल्लंघन की स्थिति में इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा कानूनी रुप से लागू नहीं कराया जा सकता है।
राज्य के नीति निदेशक तत्वों की 'गैर-न्यायोचित' प्रकृति का तात्पर्य यह है कि यदि राज्य इनका उल्लंघन करता है या इन्हें लागू करने में विफल रहता है, तो नागरिक इनके प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। मूल अधिकारों के विपरीत, इनके हनन पर न्यायालय कोई आदेश या रिट जारी नहीं कर सकता है। इनका क्रियान्वयन पूरी तरह से राज्य की वित्तीय और प्रशासनिक क्षमता पर निर्भर करता है।

5. (B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
संविधान का अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि नीति निदेशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं हैं। इसके साथ ही, यह अनुच्छेद यह घोषणा भी करता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। यद्यपि दोनों कथन पूरी तरह सत्य हैं, लेकिन राज्य का यह संवैधानिक कर्तव्य इनकी गैर-न्यायोचित प्रकृति का कारण नहीं है।

6. (B) अनुच्छेद 37
संविधान का अनुच्छेद 37 नीति निदेशक तत्वों के कानूनी स्वरुप को निर्धारित करता है। यह अनुच्छेद विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि इस भाग में शामिल सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। तथापि, यह स्पष्ट किया गया है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं और राज्य का यह नैतिक एवं संवैधानिक कर्तव्य है कि वह विधि का निर्माण करते समय इन सिद्धांतों को लागू करे।

7. (C) भारत सरकार अधिनियम, 1935
राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत सरकार अधिनियम, 1935 में निहित 'अनुदेश-प्रपत्र' (Instrument of Instructions) के समान हैं। जिस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर-जनरल और गवर्नरों को निर्देश जारी किए जाते थे, उसी प्रकार भारतीय संविधान ने विधायिका और कार्यपालिका के लिए इन सिद्धांतों को अनुदेश के रूप में शामिल किया है। अंतर केवल इतना है कि ये निर्देश एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य के कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए हैं।

8. (C) संविधान की अनोखी विशेषताएं
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान की 'अनोखी विशेषताएं' या नवीन विशेषताएं कहा था। उनका मानना था कि ये सिद्धांत संविधान के सामाजिक-आर्थिक दर्शन को प्रकट करते हैं। मूल अधिकारों के साथ मिलकर नीति निदेशक तत्व संविधान की मूल आत्मा और चेतना का निर्माण करते हैं, जिनका उद्देश्य भारत में केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना भी है।

9. (D) सर बी.एन. राव
संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव ने नागरिकों के अधिकारों को दो अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करने की सिफारिश की थी। एक श्रेणी में न्यायोचित अधिकारों को रखा गया, जिन्हें भाग III में मूल अधिकारों के रूप में शामिल किया गया। दूसरी श्रेणी में गैर-न्यायोचित अधिकारों को रखा गया, जिन्हें भाग IV में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया, जिन्हें राज्य संसाधन उपलब्ध होने पर लागू करेगा।

10. (A) P-4, Q-3, R-2, S-1
विभिन्न विद्वानों ने नीति निदेशक तत्वों पर अलग-अलग टिप्पणियां की हैं। के.टी. शाह ने इन्हें एक ऐसे चेक के समान बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने मूल अधिकारों के साथ इन्हें संविधान की अंतरात्मा कहा। सर आइवर जेनिंग्स ने इन्हें पवित्र आकांक्षाएं माना, जबकि

Downloaded from www.pdf.tube

32. (C) अनुच्छेद 48
संविधान का अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का निर्देश देता है। इसी अनुच्छेद में यह प्रावधान भी शामिल है कि राज्य गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों की नस्लों के परिरक्षण व सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए विशेष कदम उठाएगा। यह गांधीवादी और कृषि-आर्थिक सिद्धांतों का एक प्रमुख हिस्सा है।

33. (C) अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता)
उदार-बौद्धिक सिद्धांत आधुनिकता, धर्मनिरपेक्षता और प्रशासनिक सुधारों की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुच्छेद 44, जो भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है, इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। जबकि अनुच्छेद 40, 43 और 46 मुख्य रूप से गांधीवादी और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

34. (D) भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता
संविधान का अनुच्छेद 44 यह प्रावधान करता है कि राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों, जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने से संबंधित नियमों में धर्मनिरपेक्षता और कानून के समक्ष समता स्थापित करना है, ताकि राष्ट्रीय एकरूपता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिले।

35. (A) छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा
86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु में बदलाव किया गया। इसके तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया कि वह छह वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई) उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। वहीं, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार बना दिया गया।

36. (B) अनुच्छेद 49
संविधान का अनुच्छेद 49 राज्य पर यह दायित्व आरोपित करता है कि वह संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक, स्थान या वस्तु का विरूपण, विनाश, हटने, अंतरण या निर्यात से संरक्षण करे। यह प्रावधान देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है।

37. (A) लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
संविधान का अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और स्वायत्तता को सुरक्षित करना है। इसके कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित होता है कि न्यायिक कार्यों में कार्यपालिका का कोई अनुचित हस्तक्षेप न हो और कानून का शासन प्रभावी रूप से बना रहे।

38. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण, वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्धन की बात करता है। अनुच्छेद 47 राज्य को अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार का निर्देश देता है। अनुच्छेद 44 भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का उपबंध करता है।

NODIA

39. (C) अनुच्छेद 48
संविधान के अनुच्छेद 48 में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही, यह अनुच्छेद मवेशियों की नस्लों में सुधार करने और दुधारू व वाहक पशुओं के वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने का उपबंध भी करता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है।

40. (C) सभी युवाओं के लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण सुनिश्चित करना
संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत व सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधियों के प्रति आदर बढ़ाने तथा विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का निर्देश देता है। इसमें सभी युवाओं के लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण का कोई प्रावधान या निर्देश शामिल नहीं है। अतः यह विकल्प अनुच्छेद 51 के दायरे से बाहर है।

41. (A) I, II, IV, III
संविधान के भाग IV में अनुच्छेद कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित हैं। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में आता है, समान नागरिक संहिता का प्रावधान अनुच्छेद 44 में निहित है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण अनुच्छेद 49 के अंतर्गत वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में निर्धारित किया गया है। अतः इनका सही संख्यात्मक क्रम I, II, IV, III है।

42. (A) आय, प्रतिष्ठा और अवसरों में असमानताओं को कम करना (अनुच्छेद 38)
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा चार नए नीति निदेशक तत्व जोड़े गए थे: बच्चों का स्वस्थ विकास (अनुच्छेद 39(f)), निःशुल्क विधिक सहायता (अनुच्छेद 39A), उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी (अनुच्छेद 43A) तथा पर्यावरण संरक्षण (अनुच्छेद 48A)। जबकि आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानताओं को कम करने का निर्देश अनुच्छेद 38(2) में 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा जोड़ा गया था।

21. (A) भौतिक संसाधनों का वितरण और धन का संकेंद्रण रोकना
अनुच्छेद 39(b) और 39(c) भारतीय संविधान के दो अत्यंत महत्वपूर्ण समाजवादी प्रावधान हैं। अनुच्छेद 39(b) यह निर्दिष्ट करता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सर्वसाधारण का हित हो सके। वहीं, अनुच्छेद 39(c) राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो।

22. (B) अनुच्छेद 39A
संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय की अभिवृद्धि करने और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या किसी अन्य असमर्थता के कारण कोई भी नागरिक न्याय पाने के अवसर से वंचित न रहे, जिससे न्यायसंगत समाज बन सके।

23. (A) अनुच्छेद 41
संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने तथा बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करे। यह प्रावधान सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क स्थापित करने और नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

24. (C) काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 राज्य को दो प्रमुख कार्य करने का स्पष्ट निर्देश देता है। पहला, कार्यस्थल पर काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करना, ताकि श्रमिकों के स्वास्थ्य का शोषण न हो। दूसरा, महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का उपबंध करना। इसी अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कल्याणकारी कानून बनाए गए हैं।

25. (C) अनुच्छेद 43
संविधान का अनुच्छेद 43 राज्य को यह प्रयास करने का निर्देश देता है कि कृषि, उद्योग या अन्य क्षेत्रों में लगे सभी कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का पूर्ण उपभोग प्राप्त हो सके। यह अनुच्छेद श्रमिकों को केवल न्यूनतम वेतन ही नहीं, बल्कि उनके सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों को सुनिश्चित करने वाले एक मानवीय जीवन स्तर की गारंटी देने पर बल देता है।

26. (B) अनुच्छेद 43A
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 43A अंतःस्थापित किया गया था। यह नीति निदेशक तत्व राज्य को किसी उद्योग में लगे उपक्रमों, स्थापनाओं या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान बनाने या अन्य कदम उठाने का स्पष्ट निर्देश देता है। इसका उद्देश्य औद्योगिक लोकतंत्र और श्रम-प्रबंधन सहयोग को बढ़ावा देना है।

27. (B) अनुच्छेद 40
संविधान का अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांतों का एक प्रमुख स्तंभ है। यह राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करने और उन्हें ऐसी शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। इसी अनुच्छेद को व्यावहारिक रूप देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था।

28. (A) केवल I और II
गांधीवादी सिद्धांत महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान व्यक्त विचारों पर आधारित हैं। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना (अनुच्छेद 43) और नशीले पेयों का प्रतिषेध (अनुच्छेद 47) विशुद्ध रूप से गांधीवादी आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके विपरीत, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान (अनुच्छेद 44) एक उदार-बौद्धिक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। अतः केवल प्रथम और द्वितीय प्रावधान सही हैं।

29. (C) अनुच्छेद 43B
संविधान का अनुच्छेद 43B राज्य को यह निर्देश देता है कि वह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह प्रावधान सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था में सहकारिता के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संविधान के भाग IV में जोड़ा गया था।

30. (C) 97वां संशोधन अधिनियम, 2011
97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था। इस संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण और प्रोत्साहन देने के लिए भाग III में मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(c)), भाग IV में नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 43B) तथा भाग IXB के रूप में नए प्रावधान शामिल किए, ताकि देश में सहकारिता आंदोलन सशक्त हो सके।

31. (D) अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य दुर्बल वर्ग
संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य पर यह विशेष कर्तव्य सौंपता है कि वह जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। साथ ही, यह अनुच्छेद राज्य को इन वर्गों की सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करने तथा उनके उत्थान के लिए नीतियां बनाने का निर्देश देता है।

Click Here to Buy book on Amazon

प्रवेश करने के लिए विवश न किया जाए, किस अनुच्छेद में निहित है?
(A) अनुच्छेद 24
(B) अनुच्छेद 39(e)
(C) अनुच्छेद 41
(D) अनुच्छेद 45

122. अनुच्छेद 43 के तहत, राज्य सभी कर्मकारों के लिए काम की ऐसी दशाएं सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा जो शिष्ट जीवन स्तर और किसका पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करे?
(A) अवकाश तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर
(B) पूर्ण राजनीतिक शक्ति और प्रशासनिक प्राधिकार
(C) व्यापक निजी संपत्ति और स्वामित्व अधिकार
(D) असीमित निःशुल्क अंतर्राष्ट्रीय यात्रा विशेषाधिकार

123. अनुच्छेद 50 (कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण) के पीछे का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है?
(A) प्रशासनिक फाइलों का तीव्र निष्पादन
(B) न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता
(C) सरकारी व्यय में कमी
(D) न्यायिक अधिकारियों का जिला कलेक्टर के अधीन होना

124. निम्नलिखित में से कौन-सा तर्क भारत में समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) को लागू करने के विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाता है?
(A) भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता
(B) सिविल कानून बनाने के लिए संसद की विधायी क्षमता का अभाव
(C) अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार
(D) अल्पसंख्यक समुदायों में अपने पर्सनल लॉ के खोने की आशंका

125. नीति निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. न्यायपालिका रिट के माध्यम से राज्य को किसी नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है।
II. किसी नीति निदेशक तत्व को प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया कानून निरस्त नहीं किया जा सकता, भले ही वह मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो।
III. विधि निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का एक नैतिक और राजनीतिक दायित्व है।
कथनों का कौन-सा समूह सही है?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

126. मूल अधिकारों और DPSP के बीच संबंध से जुड़े निम्नलिखित उच्चतम न्यायालय के मामलों को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. मिनर्वा मिल्स मामला
II. केशवानंद भारती मामला
III. गोलकनाथ मामला
IV. चंपकम दोरैराजन मामला
सही क्रम चुनिए:
(A) IV, III, II, I
(B) IV, II, III, I
(C) III, IV, II, I
(D) II, IV, I, III

127. कौन-सा अनुच्छेद राज्य को जनता के दुर्बल वर्गों के, और विशेष रूप से, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करने का निर्देश देता है?
(A) अनुच्छेद 45
(B) अनुच्छेद 46
(C) अनुच्छेद 47
(D) अनुच्छेद 48

128. किसने कहा था कि "नीति निदेशक तत्व अनुदेश-प्रपत्र के समान हैं... अंतर केवल इतना है कि वे विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश हैं"?
(A) जवाहरलाल नेहरू
(B) महात्मा गांधी
(C) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
(D) सरदार पटेल

129. राज्यों के भूमि सुधार कानून मुख्य रूप से किस विशिष्ट नीति निदेशक तत्व में उल्लिखित संवैधानिक उद्देश्य को पूरा करते हैं?
(A) अनुच्छेद 39(b) और (c)
(B) अनुच्छेद 41 और 42
(C) अनुच्छेद 44 और 45
(D) अनुच्छेद 48 और 48A

130. मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संबंध का सबसे उपयुक्त वर्णन निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) सभी कानूनी परिस्थितियों में मूल अधिकार नीति निदेशक तत्वों के पूरी तरह से अधीन हैं।
(B) जब भी नीति निदेशक तत्वों का मूल अधिकारों से टकराव होता है, वे स्वतः प्रवर्तनीय हो जाते हैं।
(C) वे पूरी तरह से स्वतंत्र संवैधानिक क्षेत्र हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है।
(D) संविधान मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन पर आधारित है, जो इसके मूल ढांचे का भाग है।

NODIA

43. (D) खंड (f)
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 39 में खंड (f) को अंतःस्थापित किया गया था। यह खंड राज्य को यह निर्देश देता है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमापूर्ण वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं, तथा बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की नैतिक व भौतिक परित्याग से और शोषण से सुरक्षा की जाए। यह बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

44. (B) चंपकम दोरैराजन मामला (1951)
चंपकम दोरैराजन बनाम मद्रास राज्य मामला (1951) में उच्चतम न्यायालय ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया कि यदि मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच कोई टकराव होता है, तो मूल अधिकार ही प्रभावी होंगे। न्यायालय ने माना कि नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए और वे मूल अधिकारों के सहायक के रूप में कार्य करेंगे, न कि उनके विरोधी के रूप में।

45. (C) गोलकनाथ मामला (1967)
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला (1967) में उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मूल अधिकार पवित्र और अलंघनीय हैं। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद किसी भी मूल अधिकार को छीन या कम नहीं कर सकती है। इसका सीधा अर्थ यह था कि भाग IV के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के उद्देश्य से भी संसद भाग III में दिए गए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती।

46. (B) 25वां संशोधन अधिनियम, 1971
गोलकनाथ मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के प्रभाव को दूर करने और नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए संसद ने 25वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 पारित किया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। इस अनुच्छेद का उद्देश्य अनुच्छेद 39(b) और 39(c) में निहित समाजवादी सिद्धांतों को लागू करने वाले कानूनों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना था।

47. (B) अनुच्छेद 14, 19 और 31
25वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए मूल अनुच्छेद 31C के अनुसार, यदि कोई कानून अनुच्छेद 39(b) या 39(c) के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाया जाता है, तो उसे अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार), अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 31 (संपत्ति का अधिकार) के उल्लंघन के आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जा सकता था, भले ही वह इन अधिकारों को सीमित करता हो।

48. (C) इसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीनने के कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया गया।
केशवानंद भारती मामले (1973) में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31C के प्रथम भाग की वैधता को तो बरकरार रखा, लेकिन इसके दूसरे भाग को असंवैधानिक घोषित कर दिया। दूसरे भाग में यह प्रावधान था कि ऐसी नीति को प्रभावी करने वाले कानून को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक समीक्षा संविधान का मूल ढांचा है, जिसे छीना नहीं जा सकता।

49. (B) भाग IV में निर्दिष्ट सभी नीति निदेशक तत्व
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने अनुच्छेद 31C के दायरे का अत्यधिक विस्तार करने का प्रयास किया। मूल रूप से यह संरक्षण केवल अनुच्छेद 39(b) और (c) तक सीमित था, लेकिन इस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि भाग IV में उल्लिखित किसी भी नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए बनाए गए कानून को अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता।

50. (D) मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व
मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में उच्चतम न्यायालय ने यह ऐतिहासिक व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन की आधारशिला पर टिका हुआ है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इन दोनों के बीच सामंजस्य और संतुलन बनाए रखना संविधान के मूल ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा है, तथा इनमें से किसी एक को दूसरे पर पूर्ण प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।

51. (A) मूल अधिकार सामान्यतः प्रभावी होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 39(b) और (c) को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता प्राप्त है।
मिनर्वा मिल्स फैसले के बाद वर्तमान संवैधानिक स्थिति यह है कि सामान्यतः मूल अधिकारों को नीति निदेशक तत्वों पर प्राथमिकता प्राप्त है। हालांकि, इसका एक महत्वपूर्ण अपवाद है: अनुच्छेद 39(b) और 39(c) में निर्दिष्ट समाजवादी नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के मूल अधिकारों पर संवैधानिक प्राथमिकता और संरक्षण प्राप्त रहता है।

52. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
चंपकम दोरैराजन मामले में व्यवस्था दी गई कि DPSP को मूल अधिकारों के सहायक के रूप में कार्य करना होगा। गोलकनाथ मामले में तय हुआ कि DPSP के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। केशवानंद भारती मामले में 31C के दूसरे भाग को रद्द कर न्यायिक समीक्षा को बरकरार रखा गया। मिनर्वा मिल्स मामले में मूल अधिकारों और DPSP के संतुलन को मूल ढांचा माना गया।

53. (A) सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का सिद्धांत
केरल शिक्षा विधेयक मामले (1957) में उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच टकराव को सुलझाने के लिए 'सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का सिद्धांत' (डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन) लागू किया था। इसके अनुसार, न्यायालयों को संविधान के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिए कि मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों दोनों का सम्मान हो सके तथा उनके बीच टकराव को न्यूनतम किया जा सके।

Downloaded from www.pdf.tube

54. (D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।
नीति निदेशक तत्व प्रत्येक संवैधानिक परिस्थिति में मूल अधिकारों के पूरी तरह अधीन नहीं हैं, क्योंकि अनुच्छेद 39(b) और (c) को लागू करने वाले कानून अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता रखते हैं, इसलिए अभिकथन गलत है। हालांकि, न्यायिक दृष्टान्तों के अनुसार केवल नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों के आवश्यक तत्व समाप्त नहीं किए जा सकते, अतः कारण सही माना जाता है।

55. (B) केवल II, III और IV
संविधान में नीति निदेशक तत्वों का स्पष्ट रूप से कोई विभाजन या वर्गीकरण नहीं किया गया है, इसलिए पहला कथन गलत है। हालांकि, विषय-वस्तु के आधार पर अनुच्छेद 43 (कुटीर उद्योग) गांधीवादी सिद्धांत है, अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता) उदारवादी सिद्धांत है, तथा अनुच्छेद 47 में जीवन स्तर ऊंचा उठाने का समाजवादी और शराबबंदी का गांधीवादी तत्व शामिल है। अतः कथन II, III और IV पूरी तरह सही हैं।

56. (C) जमींदारी उन्मूलन सम्बंधी भूमि सुधार कानूनों का अधिनियमन
स्वतंत्रता के बाद शुरुआती दो दशकों में अनुच्छेद 39(b) और 39(c) के तहत धन और कृषि संसाधनों के न्यायसंगत वितरण के लिए व्यापक भूमि सुधार कानून पारित किए गए। इसके अंतर्गत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, बिचौलियों की समाप्ति, काश्तकारी सुधार तथा भूमि जोत की अधिकतम सीमा तय करने जैसे कदम उठाए गए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का अहितकारी संकेंद्रण रोका जा सके और कृषकों को अधिकार मिले।

57. (C) अनुच्छेद 43 (कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी)
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948) और बोनस भुगतान अधिनियम (1965) संविधान के अनुच्छेद 43 में उल्लिखित निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए बनाए गए प्रमुख कानून हैं। यह अनुच्छेद राज्य को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, काम की उचित दशाएं और एक शिष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का स्पष्ट निर्देश प्रदान करता है।

58. (B) अनुच्छेद 39(d)
समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 संविधान के अनुच्छेद 39(d) में निहित संवैधानिक निर्देश का अनुपालन करने के लिए बनाया गया था। यह अनुच्छेद राज्य को स्पष्ट रूप से यह निर्देशित करता है कि वह अपनी नीतियों के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था सुनिश्चित करे, जिससे कार्यस्थल पर लैंगिक आधार पर होने वाले वेतन भेदभाव को समाप्त किया जा सके।

59. (B) अनुच्छेद 42
मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) संविधान के अनुच्छेद 42 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पारित किया गया था। अनुच्छेद 42 राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं के साथ-साथ विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए प्रसूति सहायता का उपबंध करने का निर्देश देता है। यह कानून गर्भावस्था के दौरान महिला श्रमिकों के रोजगार, स्वास्थ्य और आर्थिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

60. (D) I, II, III और IV
संविधान का अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति के मुख्य संवैधानिक आधारों को निर्धारित करता है। इसके मूल पाठ में चारों महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत व सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधियों का आदर करना तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने को प्रोत्साहन देना। अतः ये सभी कथन पूरी तरह सही हैं।

61. (B) अनुच्छेद 39A
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था, जो सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 39A को लागू करता है। यह अनुच्छेद राज्य को समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्गों को निःशुल्क व सक्षम विधिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है, ताकि आर्थिक या अन्य असमर्थता के कारण कोई भी नागरिक न्याय से वंचित न रहे।

62. (A) अनुच्छेद 40
73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में निहित नीति निदेशक तत्व का प्रत्यक्ष और व्यावहारिक कार्यान्वयन है। अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करने और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां व प्राधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है। इस संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।

63. (C) अनुच्छेद 48A
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरण कानून संविधान के अनुच्छेद 48A को वैधानिक आधार प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। अनुच्छेद 48A राज्य को देश के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन करने और वनों तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का स्पष्ट निर्देश देता है, जिससे जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखा जा सके।

NODIA

64. (A) अनुच्छेद 43 (कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना)
भारत में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की स्थापना मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 43 के अनुरूप की गई थी। अनुच्छेद 43 राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करने का निर्देश देता है। इस आयोग का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

65. (A) केवल I, II और IV
42वें संशोधन ने अनुच्छेद 48A (पर्यावरण संरक्षण), 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 38(2) (असमानताओं को कम करना) और

97वें संशोधन ने अनुच्छेद 43B (सहकारी समितियां) को जोड़ा। 86वें संशोधन ने अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु को बदला था, इसे हटाया नहीं था, इसलिए कथन III गलत है। अतः केवल कथन I, II और IV सही हैं, जो DPSP में किए गए संवैधानिक सुधारों को दर्शाते हैं।

66. (C) अनुच्छेद 50
दंड प्रक्रिया संहिता (1973) द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेटों को कार्यपालक मजिस्ट्रेटों से अलग करके अलग कैडर बनाया गया। यह विधायी सुधार सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 50 में निहित निर्देश का कार्यान्वयन करता है। अनुच्छेद 50 राज्य को लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने का निर्देश देता है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और बाह्य दबावों से मुक्त रह सके।

67. (A) जीविका का अधिकार (अनुच्छेद 39(a)) और काम का अधिकार (अनुच्छेद 41)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) संविधान के अनुच्छेद 39(a) (जीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार) और अनुच्छेद 41 (काम पाने का अधिकार) को प्रभावी बनाता है। यह योजना ग्रामीण परिवारों को कानूनी रूप से न्यूनतम 100 दिनों के अकुशल शारीरिक कार्य की गारंटी देकर वित्तीय सुरक्षा और आजीविका प्रदान करती है, जिससे ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में मदद मिलती है।

68. (B) अनुच्छेद 47
गुजरात और बिहार जैसे राज्यों द्वारा लागू किए गए कड़े शराबबंदी कानून संविधान के अनुच्छेद 47 का प्रत्यक्ष कार्यान्वयन हैं। अनुच्छेद 47 राज्य को अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानने का निर्देश देता है। यह अनुच्छेद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेयों और औषधियों के सेवन पर प्रतिषेध लगाने पर बल देता है।

69. (C) अनुच्छेद 48
भारत के विभिन्न राज्यों द्वारा गोवध पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाए गए कानून संविधान के अनुच्छेद 48 से संवैधानिक शक्ति और आधार प्राप्त करते हैं। अनुच्छेद 48 राज्य को गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों की नस्लों के संरक्षण एवं सुधार करने तथा उनके वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने का स्पष्ट निर्देश देता है, जो ग्रामीण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़ा है।

70. (D) अनुच्छेद 46
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना है। यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 46 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप है, जो राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के अर्थ व शिक्षा संबंधी हितों की अभिवृद्धि करने तथा सामाजिक अन्याय से रक्षा का निर्देश देता है।

71. (B) गोवा
गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां स्वतंत्रता के बाद से ही समान नागरिक संहिता (UCC) लागू रही है। गोवा में 1867 का पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू है, जो धार्मिक संप्रदायों के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों पर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित मामलों में समान रूप से लागू होता है। यह अनुच्छेद 44 के संवैधानिक आदर्श का एक व्यावहारिक उदाहरण है।

72. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
संविधान निर्माताओं ने नीति निदेशक तत्वों को गैर-न्यायोचित बनाया क्योंकि नव-स्वतंत्र भारत के पास इन्हें तुरंत लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक संसाधनों का अभाव था। यदि इन्हें न्यायोचित बना दिया जाता, तो राज्य पर अत्यधिक मुकदमों का बोझ पड़ता और सरकार के लिए कार्य करना कठिन हो जाता। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है।

73. (D) लोकमत और मतदाता
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने नीति निदेशक तत्वों की गैर-न्यायोचित प्रकृति का बचाव करते हुए स्पष्ट किया था कि इनके पीछे वास्तविक कानूनी शक्ति भले न हो, लेकिन लोकमत और मतदाता ही इनकी असली शक्ति हैं। उन्होंने कहा था कि कोई भी निर्वाचित सरकार, जो जनता के प्रति जवाबदेह है, चुनाव के समय इन निर्देशों की अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठा सकती और उसे जनता को जवाब देना होगा।

74. (A) राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री तथा केंद्र व राज्य के बीच
संवैधानिक विद्वान के. संथानम का मत था कि नीति निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल करने से केंद्र और राज्यों के बीच तथा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव उत्पन्न हो सकता है। यदि केंद्र राज्य को DPSP लागू करने का निर्देश दे और राज्य न माने, या यदि राष्ट्रपति विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को DPSP का उल्लंघन मानकर रोकने का प्रयास करे, तो गतिरोध पैदा हो सकता है।

75. (B) चंपकम दोरैराजन मामला, गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला
मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के टकराव पर उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का सही कालानुक्रमिक क्रम है: चंपकम दोरैराजन मामला (1951), गोलकनाथ मामला (1967), केशवानंद भारती मामला (1973) और मिनर्वा मिल्स मामला (1980)। चंपकम मामले में मूल अधिकारों को सर्वोच्चता दी गई, जबकि मिनर्वा मिल्स मामले में दोनों के बीच संतुलन को संविधान का मूल ढांचा माना गया।

76. (B) अनुच्छेद 335
भाग IV के बाहर संविधान के भाग XVI में निहित अनुच्छेद 335 राज्य को एक महत्वपूर्ण निर्देश देता है। इसके अनुसार, संघ या किसी राज्य के मामलों से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करते समय, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की

Click Here to Buy book on Flipkart

42वें, 44वें और 86वें संविधान संशोधन अधिनियमों ने भाग IV के नीति निदेशक तत्वों में नए प्रावधानों को जोड़ा या उनकी विषय-वस्तु में बदलाव किया था।

121. (B) अनुच्छेद 39(e)
संविधान का अनुच्छेद 39(e) राज्य को यह निर्देश देता है कि वह अपनी नीतियों को इस प्रकार बनाए जिससे नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर अपनी आयु या शक्ति के अनुकूल न होने वाले रोजगारों में प्रवेश न करना पड़े। यह प्रावधान विशेष रुप से बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने तथा उनके आर्थिक शोषण को रोकने के लिए संवैधानिक सुरक्षा चक्र प्रदान करता है।

122. (A) अवकाश तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर
संविधान के अनुच्छेद 43 के अनुसार, राज्य सभी कर्मकारों के लिए काम की ऐसी दशाएं सुरक्षित करने का प्रयास करेगा जो एक शिष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, यह अनुच्छेद स्पष्ट रुप से श्रमिकों के लिए 'अवकाश का पूर्ण उपभोग तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर' सुनिश्चित करने का निर्देश भी देता है, ताकि उनका व्यक्तिगत और सामाजिक विकास संतुलित रुप से हो सके।

123. (B) न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता
अनुच्छेद 50 में निहित कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का मूल उद्देश्य न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता, निष्पक्षता और स्वायत्तता को सुरक्षित करना है। जब न्यायिक कार्य करने वाले अधिकारी कार्यपालिका के नियंत्रण और प्रभाव से मुक्त होते हैं, तो वे बिना किसी भय या पक्षपात के न्याय कर सकते हैं। यह सिद्धांत लोकतांत्रिक ढांचे में कानून के शासन को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है।

124. (B) सिविल कानून बनाने के लिए संसद की विधायी क्षमता का अभाव
समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) को लागू करने के विरोध में कई तर्क दिए जाते हैं, जैसे भारत की अपार धार्मिक विविधता, अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की आशंकाएं। हालांकि, संसद की विधायी क्षमता के अभाव का तर्क इसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं होता है, क्योंकि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के तहत संसद को विवाह, तलाक और उत्तराधिकार पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

125. (C) केवल I और III
न्यायालय रिट जारी करके विधायिका को DPSP लागू करने के लिए कानून बनाने हेतु बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि ये गैर-न्यायोचित हैं। साथ ही, विधि निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का नैतिक और राजनीतिक दायित्व है। हालांकि, DPSP को लागू करने के लिए बनाया गया कोई कानून यदि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, तो उसे निरस्त किया जा सकता है। अतः केवल कथन I और III सही हैं।

126. (A) IV, III, II, I
मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संबंधों पर उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसलों का सही कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है: सबसे पहले चंपकम दोरैराजन मामला (1951) आया, उसके बाद गोलकनाथ मामला (1967) हुआ, तत्पश्चात केशवानंद भारती मामला (1973) आया, और अंत में मिनर्वा मिल्स मामला (1980) आया। अतः विकल्प IV, III, II, I सही कालानुक्रम को दर्शाता है।

NODIA

127. (B) अनुच्छेद 46
संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य को जनता के दुर्बल वर्गों, विशेष रुप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करने का निर्देश देता है। यह अनुच्छेद राज्य पर यह संवैधानिक दायित्व भी डालता है कि वह इन शोषित वर्गों की सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय करे।

128. (C) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में चर्चा के दौरान कहा था कि नीति निदेशक तत्व 1935 के अधिनियम में उल्लिखित अनुदेश-प्रपत्र के समान हैं। उन्होंने स्पष्ट किया था कि इन दोनों में अंतर केवल इतना है कि नीति निदेशक तत्व किसी औपनिवेशिक शासक द्वारा नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों वाली विधायिका और कार्यपालिका के लिए भारतीय संविधान द्वारा दिए गए सकारात्मक अनुदेश हैं।

129. (A) अनुच्छेद 39(b) और (c)
विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए भूमि सुधार कानून मुख्य रुप से संविधान के अनुच्छेद 39(b) और 39(c) में उल्लिखित सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लागू किए गए थे। इन अनुच्छेदों का लक्ष्य समुदाय के कृषि संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना और कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में भूमि का संकेंद्रण रोकना था, ताकि ग्रामीण भारत में न्यायसंगत आर्थिक व्यवस्था स्थापित की जा सके।

130. (D) संविधान मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन पर आधारित है, जो इसके मूल ढांचे का भाग है।
मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रुप से यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन की नींव पर निर्मित है। न्यायालय ने माना कि इन दोनों के बीच सामंजस्य बनाए रखना संविधान के मूल ढांचे (बेसिक स्ट्रक्चर) का अभिन्न हिस्सा है, तथा इनमें से किसी एक को पूर्ण प्राथमिकता देकर दूसरे को समाप्त नहीं किया जा सकता।

औद्योगीकरण, सामाजिक न्याय और आर्थिक असमानता को कम करने जैसे सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया, जो कल्याणकारी राज्य की नींव हैं।

88. (D) I, II और III
1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नीति निदेशक तत्वों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इस संशोधन द्वारा गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता देने के लिए अनुच्छेद 39A, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी हेतु अनुच्छेद 43A तथा पर्यावरण, वन एवं वन्यजीवों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 48A को अंतःस्थापित किया गया। अतः यह विकल्प इन तीनों परिवर्तनों को सही ढंग से दर्शाता है।

89. (D) राज्य के प्राथमिक कर्तव्य
संविधान का अनुच्छेद 47 यह स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को राज्य अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। यह अनुच्छेद स्वास्थ्य सुरक्षा को केवल एक प्रशासनिक लक्ष्य न मानकर राज्य के मुख्य संवैधानिक दायित्व के रूप में स्थापित करता है, जिसके अंतर्गत हानिकारक नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध शामिल है।

90. (A) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन 'अनुदेश-प्रपत्र' (Instrument of Instructions) के रूप में किया था। उन्होंने संविधान सभा में स्पष्ट किया था कि जिस प्रकार भारत सरकार अधिनियम, 1935 में गवर्नर-जनरल के लिए अनुदेश जारी किए गए थे, उसी प्रकार ये तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए निर्देश हैं। अंतर केवल इतना है कि ये जनकल्याणकारी शासन की स्थापना के लिए हैं।

91. (D) अनुच्छेद 51
भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांत, जैसे पंचशील, गुटनिरपेक्षता और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, संविधान के अनुच्छेद 51 में निहित संवैधानिक जनादेश से प्रेरित हैं। अनुच्छेद 51 राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति आदर बढ़ाने का निर्देश देता है, जो हमारी विदेश नीति का मुख्य आधार है।

92. (B) अनुच्छेद 41
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) जैसी राज्य प्रायोजित पेंशन योजनाएं अपनी संवैधानिक वैधता मुख्य रूप से अनुच्छेद 41 से प्राप्त करती हैं। अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता की सीमाओं में बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी और निःशक्तता की स्थितियों में नागरिकों को लोक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करने का निर्देश देता है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।

93. (A) गांधीवादी और उदार-बौद्धिक सिद्धांतों का संयोजन
संविधान का अनुच्छेद 48 गांधीवादी और उदार-बौद्धिक दोनों सिद्धांतों का एक अनूठा संयोजन प्रस्तुत करता है। कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का भाग उदार-बौद्धिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जबकि गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू मवेशियों के वध पर रोक लगाने और नस्ल सुधार का प्रावधान गांधीवादी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है।

94. (C) अनुच्छेद 39 के तहत राज्य का एक नीति निदेशक तत्व
"पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन" भारत के संविधान में अनुच्छेद 39(d) के अंतर्गत एक नीति निदेशक तत्व के रूप में उल्लिखित है। यद्यपि यह स्वयं में एक अलग मूल अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, फिर भी उच्चतम न्यायालय ने कई फैसलों में इसे अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) के साथ मिलाकर एक संवैधानिक लक्ष्य और सिद्धांत के रूप में माना है।

95. (C) अनुच्छेद 39(c)
संविधान का अनुच्छेद 39(c) यह निर्दिष्ट करता है कि राज्य अपनी नीति को इस प्रकार संचालित करेगा जिससे आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। यह एक प्रमुख समाजवादी प्रावधान है जिसका उद्देश्य आर्थिक शक्ति के कुछ ही हाथों में केंद्रित होने को रोकना और समाज में आर्थिक विषमता को कम करना है।

96. (C) स्पेन का संविधान
भारतीय संविधान निर्माताओं ने नीति निदेशक तत्वों को आयरलैंड के 1937 के संविधान से ग्रहण किया था। आयरलैंड के संविधान में इन सामाजिक और आर्थिक नीति सिद्धांतों को स्पेन के संविधान से शामिल किया गया था। इस प्रकार, नीति निदेशक तत्वों का ऐतिहासिक विकास स्पेन से आयरलैंड और फिर आयरलैंड से भारतीय संविधान की यात्रा को दर्शाता है, जिसने कल्याणकारी राज्य की नींव रखी।

97. (B) अनुच्छेद 45
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 उस संवैधानिक निर्देश को पूरा करने के लिए बनाया गया था जो मूल रूप से अनुच्छेद 45 में निहित था। मूल अनुच्छेद 45 में राज्य को संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था, जिसे बाद में अनुच्छेद 21A बनाया गया।

98. (D) भारत का उच्चतम न्यायालय
भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में यह व्यवस्था दी है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मूल अधिकारों की व्याख्या करते समय नीति निदेशक तत्वों को एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में देखा जाना चाहिए। न्यायालय के अनुसार, भाग III और भाग IV दोनों एक-दूसरे

NODIA

संगति के साथ, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जाएगा। यह सामाजिक न्याय और दक्षता का संतुलन बनाता है।

77. (C) अनुच्छेद 350A
संविधान के भाग XVII में शामिल अनुच्छेद 350A भाग IV के बाहर स्थित एक प्रमुख संवैधानिक निर्देश है। यह अनुच्छेद प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को यह निर्देश देता है कि वह भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा, ताकि उनका सहज विकास हो सके।

78. (A) P-2, Q-3, R-1, S-3
अनुच्छेद 39 (धन का न्यायसंगत वितरण) समाजवादी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 43 (कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना) और अनुच्छेद 48 (गोवध पर रोक लगाना) महात्मा गांधी की विचारधारा पर आधारित होने के कारण गांधीवादी सिद्धांत हैं। अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता) आधुनिकता और धर्मनिरपेक्षता को दर्शाने के कारण एक उदार-बौद्धिक सिद्धांत है। अतः विकल्प P-2, Q-3, R-1, S-3 सही है।

79. (D) अनुच्छेद 351
संविधान के भाग XVII में निहित अनुच्छेद 351 संघ पर यह विशेष कर्तव्य आरोपित करता है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार और विकास को बढ़ावा दे। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हिंदी भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बन सके। यह निर्देश भाग IV से बाहर स्थित तीन प्रमुख संवैधानिक निर्देशों में से एक है।

80. (C) नहीं, ये भाग IV के निर्देशों की तरह ही गैर-न्यायोचित हैं।
संविधान के भाग IV के बाहर निहित निर्देश (जैसे अनुच्छेद 335, 350A और 351) भी भाग IV के नीति निदेशक तत्वों के समान ही गैर-न्यायोचित प्रकृति के हैं। इनके उल्लंघन पर भी नागरिकों को सीधे न्यायालय जाकर रिट जारी कराने का अधिकार प्राप्त नहीं है। हालांकि, न्यायपालिका कानूनों का अर्थान्वयन करते समय इन निर्देशों को ध्यान में रखती है और ये भी शासन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

81. (B) अनुच्छेद 49
प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1951 संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत राज्य पर आरोपित दायित्व को लागू करने के लिए पारित किया गया था। अनुच्छेद 49 राज्य को राष्ट्रीय महत्व घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को विनाश, विरूपण तथा क्षति से संरक्षित और सुरक्षित रखने का स्पष्ट संवैधानिक निर्देश देता है।

82. (D) इनमें कानूनी शक्ति का अभाव है और ये केवल नैतिक उपदेश मात्र हैं।
संविधानविदों द्वारा नीति निदेशक तत्वों की मुख्य आलोचना यह की जाती है कि इनमें कानूनी शक्ति का अभाव है और ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। आलोचकों के अनुसार, कानूनी मंजूरी के बिना ये सिद्धांत केवल नैतिक उपदेश या घोषणापत्र मात्र बनकर रह जाते हैं। प्रोफेसर के.टी. शाह जैसे विद्वानों ने इसी आधार पर इनकी तुलना एक ऐसे चेक से की थी जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है।

83. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
मिनर्वा मिल्स मामले में उच्चतम न्यायालय ने 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31C में किए गए उस विस्तार को निरस्त कर दिया जिसने सभी नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी थी। न्यायालय ने माना कि मूल अधिकारों पर DPSP को पूर्ण सर्वोच्चता देने से संविधान का मूल ढांचा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का संतुलन ही मूल ढांचा है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही हैं।

84. (B) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों (अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31) की सूची से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस संशोधन से संपत्ति के अधिकार और भूमि सुधार तथा समाज कल्याण संबंधी नीति निदेशक तत्वों के कार्यान्वियन के बीच लंबे समय से चला आ रहा संवैधानिक संघर्ष समाप्त हो गया।

85. (B) अनुच्छेद 44 - समान नागरिक संहिता
शाह बानो मामला (1985) मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित समान नागरिक संहिता (UCC) के कार्यान्वयन से संबंधित एक व्यापक राष्ट्रीय बहस का कारण बना। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला के भरण-पोषण के अधिकार को बरकरार रखा और टिप्पणी की कि देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने से राष्ट्रीय एकीकरण और महिलाओं के अधिकारों में सुधार होगा।

86. (A) अनुच्छेद 39(e)
संविधान का अनुच्छेद 39(e) राज्य को यह निर्देश देता है कि वह अपनी नीति को इस प्रकार निर्देशित करे जिससे पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। इसके साथ ही, यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर अपनी आयु या शक्ति के अनुकूल न होने वाले रोजगारों में न जाना पड़े।

87. (D) भाग IV
स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा शुरु की गई पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य संविधान के भाग IV में निहित राज्य के नीति निदेशक तत्वों को व्यावहारिक रूप देना था। इन योजनाओं के माध्यम से निर्धनता उन्मूलन, कृषि विकास,

Downloaded from www.pdf.tube

रूप में शामिल करता है, वहीं 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 51A(g) इसे भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य बनाता है। इसके अनुसार, वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है।

110. (B) अनुच्छेद 39(b)
संविधान का अनुच्छेद 39(b) राज्य को यह निर्देश देता है कि वह अपनी नीति को इस प्रकार संचालित करे जिससे समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। यह प्रावधान समाजवाद के विचार से अनुप्राणित है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में संसाधनों का न्यायसंगत पुनर्वितरण सुनिश्चित करना है।

111. (D) के.टी. शाह
"निदेशक तत्व एक ऐसे चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है"—यह प्रसिद्ध टिप्पणी प्रोफेसर के.टी. शाह द्वारा संविधान सभा में की गई थी। उन्होंने नीति निदेशक तत्वों की गैर-न्यायोचित प्रकृति और वैधानिक अनिवार्यता के अभाव की आलोचना करते हुए यह तर्क दिया था कि राज्य अपनी आर्थिक सुविधा और इच्छा के अनुसार ही इन्हें लागू करने के लिए बाध्य होगा।

112. (B) अनुच्छेद 49
संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत राज्य संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों, स्थानों या वस्तुओं का विरूपण, विनाश, हटने या निर्यात से संरक्षण करने के लिए बाध्य है। यह संवैधानिक निर्देश देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक अवशेषों तथा वास्तुकला के नमूनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने का प्रयास करता है।

113. (C) भाग III और भाग IV दोनों
2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए भाग III और भाग IV दोनों को प्रभावित किया। इसने भाग III के अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत 'सहकारी समितियां बनाने' को एक मौलिक अधिकार बनाया तथा भाग IV में अनुच्छेद 43B जोड़कर सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन व स्वायत्त संचालन को एक नीति निदेशक तत्व के रूप में स्थापित किया।

114. (A) II, III, IV, I
विभिन्न DPSP को लागू करने के लिए बनाए गए अधिनियमों का सही कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है: सबसे पहले न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948) आया, उसके बाद वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (1972) अधिनियमित हुआ, तत्पश्चात विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (1987) पारित किया गया, और अंत में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) लागू हुआ। अतः विकल्प II, III, IV, I सही है।

115. (C) केवल I, II और III
संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानने का निर्देश देता है। यह अनुच्छेद केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेयों और औषधियों के सेवन पर रोक लगाता है, न कि सभी आधुनिक एलोपैथिक दवाओं पर। इसलिए कथन I, II और III सही हैं, जबकि चौथा कथन असत्य है।

116. (D) अनुच्छेद 51
संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति आदर बढ़ाने तथा विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने का निर्देश देता है। इसी अनुच्छेद को संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके विभिन्न विश्व शांति अभियानों में भारत की निरंतर और सक्रिय भागीदारी के मुख्य संवैधानिक आधार के रूप में उद्धृत किया जाता है, जो भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को प्रकट करता है।

117. (A) नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने वाला राज्य।
भारतीय संविधान में परिकल्पित 'कल्याणकारी राज्य' की मुख्य विशेषता एक ऐसा राज्य बनना है जो अपने सभी नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम करता है। यह अवधारणा पुलिस राज्य के विचार से विपरीत है, क्योंकि यह केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित न रहकर नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व अपने ऊपर लेती है।

NODIA

118. (D) वाणिज्यिक अनुबंधों का निष्पादन करने वाले निजी निगम
अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग IV में 'राज्य' की वही परिभाषा है जो भाग III के अनुच्छेद 12 में दी गई है। इसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल तथा सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। वाणिज्यिक अनुबंधों का निष्पादन करने वाले निजी निगम या निजी संस्थाएं, जब तक वे सार्वजनिक या सरकारी कार्य न कर रही हों, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।

119. (B) पाठ में तार्किक और सुसंगत वैचारिक वर्गीकरण का अभाव है।
नीति निदेशक तत्वों की एक प्रमुख आलोचना यह है कि वे 'अतार्किक रूप से व्यवस्थित' हैं। सर आइवर जेनिंग्स जैसे आलोचकों का मानना था कि संविधान के पाठ में इन सिद्धांतों का कोई सुसंगत, तार्किक या वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं किया गया है। महत्वपूर्ण और सामान्य तथा बड़े और छोटे मुद्दों को बिना किसी स्पष्ट क्रम के एक साथ मिला दिया गया है, जिससे पाठ में वैचारिक स्पष्टता की कमी दिखाई देती है।

120. (C) 61वां संशोधन अधिनियम, 1989
61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1989 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। इस संशोधन का राज्य के नीति निदेशक तत्वों से कोई संबंध नहीं था। इसके विपरीत,

10. यदि राजस्थान की विधानसभा राज्य में विधान परिषद के सृजन का संकल्प पारित करती है, तो इस परिवर्तन को लागू करने के लिए इसके पश्चात् संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है?
(A) साधारण बहुमत
(B) अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत
(C) आधे राज्यों के अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत
(D) दोनों सदनों का पूर्ण बहुमत

11. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: प्रावधान
P. नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
Q. मूल अधिकार
R. वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी परिषद)
S. राज्य विधान परिषद का उत्सादन
सूची II: संशोधन के लिए आवश्यक बहुमत
1. अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत
2. संसद में साधारण बहुमत
3. विशेष बहुमत + राज्यों का अनुसमर्थन
4. साधारण बहुमत (अनुच्छेद 169)
(A) P-2, Q-1, R-3, S-4
(B) P-4, Q-1, R-3, S-2
(C) P-2, Q-3, R-1, S-4
(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

12. संविधान में संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 में यथाविहित "विशेष बहुमत" का अर्थ है:
(A) सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई का बहुमत
(B) कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत
(C) कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत तथा दो-तिहाई राज्यों का अनुमोदन
(D) सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का तीन-चौथाई बहुमत

13. संविधान के किस भाग में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है?
(A) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
(B) राज्य के नीति निदेशक तत्व
(C) सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची
(D) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय

14. आवश्यक संशोधन के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
(A) नागरिकता का अर्जन और समाप्ति - साधारण बहुमत
(B) संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग - विशेष बहुमत
(C) संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति - केवल विशेष बहुमत
(D) राष्ट्रपति का निर्वाचन - साधारण बहुमत

15. विशेष बहुमत की गणना में 'कुल सदस्य संख्या' की अवधारणा का तात्पर्य है:
(A) संसद के सदन का गठन करने वाले निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या
(B) मतदान के दिन उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या
(C) रिक्तियों या अनुपस्थितियों की परवाह किए बिना सदन की कुल सदस्य संख्या
(D) सभी मनोनीत सदस्यों को छोड़ कर सदन की कुल सदस्य संख्या

16. अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन करते समय राज्य विधानमंडलों में आवश्यक बहुमत की प्रकृति क्या होती है?
(A) राज्य विधानसभा का विशेष बहुमत
(B) राज्य विधानसभा का पूर्ण बहुमत
(C) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत
(D) राज्य विधानसभा का साधारण बहुमत

17. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन करने वाले संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
कारण (R): संविधान का ढांचा परिसंघीय होने के कारण यह आवश्यक बनाता है कि राज्यों के संवैधानिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व को सीधे प्रभावित करने वाले संशोधनों में उनकी सहमति शामिल हो।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

18. वह निर्धारित समय-सीमा क्या है जिसके भीतर राज्य विधानमंडलों को उन्हें भेजे गए संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन या अस्वीकरण करना अनिवार्य है?
(A) प्रेषण से 3 महीने की निश्चित अवधि
(B) संविधान द्वारा कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं है
(C) प्रेषण से 6 महीने की निश्चित अवधि
(D) पारित होने से अधिकतम 1 वर्ष की समय-सीमा

19. यदि किसी संविधान संशोधन विधेयक के लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, तो इसे राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए कब प्रस्तुत किया जाता है?
(A) संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होते ही तुरंत

Click Here to Buy book on Amazon

अध्याय 07
संवैधानिक संशोधन

1. भारत के संविधान के किस भाग और अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया का विवरण दिया गया है?
   (A) भाग XIX, अनुच्छेद 365
   (B) भाग XX, अनुच्छेद 368
   (C) भाग XXI, अनुच्छेद 369
   (D) भाग XXII, अनुच्छेद 371

2. संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
   (A) इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
   (B) इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है।
   (C) यदि विशेष बहुमत द्वारा समर्थित हो, तो इसे राज्य विधानमंडल द्वारा आरंभ किया जा सकता है।
   (D) इसे किसी मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

3. अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
   (A) दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।
   (B) विधेयक का प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है।
   (C) विधिवत पारित होने के बाद राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी अनुमति देनी ही होगी।
   (D) राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन के लिए कोई विधेयक या प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकते।

4. किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देना अनिवार्य कर दिया गया था?
   (A) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
   (B) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
   (C) 24वां संशोधन अधिनियम, 1971
   (D) प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951

5. संविधान के संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   I. संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
   II. राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं।
   III. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधानों के लिए आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
   (A) केवल I और II
   (B) केवल II और III
   (C) केवल I और III
   (D) I, II और III

6. संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है?
   (A) भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन और उनके निर्वाचन की विधि
   (B) संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण
   (C) सातवीं अनुसूची की किसी भी सूची से संबंधित प्रावधान
   (D) नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन

7. संविधान के अनुसार, संसद में गणपूर्ति (कोरम) से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए किसकी आवश्यकता होती है?
   (A) संसद का विशेष बहुमत
   (B) संसद का साधारण बहुमत
   (C) संसद का विशेष बहुमत और आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन
   (D) लोकसभा का पूर्ण बहुमत

8. निम्नलिखित में से किसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, भले ही वह संवैधानिक पाठ में परिवर्तन करता हो?
   (A) नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों में परिवर्तन
   (B) राज्य के नीति निदेशक तत्वों में परिवर्तन
   (C) राज्य विधान परिषदों का सृजन या उत्सादन
   (D) संघ की कार्यपालिका शक्ति को प्रभावित करने वाले परिवर्तन

9. अनुच्छेद 368 के बाहर के संवैधानिक मामलों के लिए संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में 'साधारण बहुमत' का क्या अर्थ है?
   (A) सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक का बहुमत
   (B) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत
   (C) सदन की कुल सदस्य संख्या का दो-तिहाई बहुमत
   (D) सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत

NODIA

30. दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था?
(A) 7वां संशोधन अधिनियम, 1956
(B) 15वां संशोधन अधिनियम, 1963
(C) 24वां संशोधन अधिनियम, 1971
(D) 31वां संशोधन अधिनियम, 1973

31. 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के उत्तर में पारित किया गया था?
(A) शंकरी प्रसाद मामला
(B) केशवानंद भारती मामला
(C) आई.सी. गोलकनाथ मामला
(D) मिनर्वा मिल्स मामला

32. 24वें संशोधन अधिनियम, 1971 का मुख्य प्रावधान क्या था?
(A) इसने घोषित किया कि संविधान के मूल ढांचे को संसद द्वारा बदला नहीं जा सकता है
(B) इसने निजी संपत्ति के मूल अधिकार को सीमित किया और अनिवार्य मुआवजा तय किया
(C) इसने संविधान की सातवीं अनुसूची में एक नई समवर्ती विधायी सूची को जोड़ा
(D) इसने मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की संसद की शक्ति की पुष्टि की

33. 25वें संशोधन अधिनियम, 1971 का उद्देश्य कुछ नीति निदेशक तत्वों को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने से बचाना था। वे विशिष्ट निदेशक तत्व कौन से थे?
(A) अनुच्छेद 38
(B) अनुच्छेद 39(b) और (c)
(C) अनुच्छेद 44
(D) अनुच्छेद 50

34. 25वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) इसने संपत्ति के मूल अधिकार को एक निरपेक्ष संवैधानिक अधिकार के रूप में बहाल किया
(B) इसने संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में 'मुआवजे' शब्द के स्थान पर 'राशि' शब्द प्रतिस्थापित किया
(C) इसे केशवानंद भारती मामले में पूरी तरह असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया गया था
(D) इसने भारतीय संविधान के पाठ से नौवीं अनुसूची को पूरी तरह से हटा दिया

35. 24वें संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसने अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया।
II. इसने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देना अनिवार्य बना दिया।
III. इसे केशवानंद भारती मामले में पूरी तरह असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

36. किस संविधान संशोधन में यह स्पष्ट रुप से प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए किसी भी संशोधन पर लागू नहीं होगी?
(A) प्रथम संशोधन अधिनियम
(B) 24वां संशोधन अधिनियम
(C) 42वां संशोधन अधिनियम
(D) 44वां संशोधन अधिनियम

37. व्यापक परिवर्तनों के कारण किस संविधान संशोधन को "लघु-संविधान" कहा जाता है?
(A) 24वां संशोधन अधिनियम
(B) 42वां संशोधन अधिनियम
(C) 44वां संशोधन अधिनियम
(D) 73वां संशोधन अधिनियम

38. 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े। निम्नलिखित में से कौन सा सही समूह है?
(A) समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता
(B) समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक
(C) संप्रभु, पंथनिरपेक्ष, अखंडता
(D) संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष

39. मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था?
(A) भाग III-A
(B) भाग IV-A
(C) भाग IX-A
(D) भाग XIV-A

40. 42वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों को कैसे परिवर्तित किया?
(A) इसने राष्ट्रपति को अपने स्वविवेक से केंद्रीय मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने की अनुमति दी
(B) इसने मंत्रिमंडल की सलाह को पुनर्विचार के प्रावधान के बिना राष्ट्रपति पर स्पष्ट रूप से बाध्यकारी बना दिया
(C) इसने राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित सभी संवैधानिक संशोधनों पर पूर्ण वीटो शक्ति प्रदान की
(D) इसके तहत राष्ट्रपति को किसी भी मामले में मंत्रिमंडल की सलाह स्वीकार करने से पहले उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना आवश्यक था

41. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

Downloaded from www.pdf.tube

(B) सभी राज्य विधानमंडलों से औपचारिक मंजूरी प्राप्त करने के बाद
(C) भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा और मंजूरी के बाद
(D) दोनों सदनों द्वारा पारित होने और आवश्यक राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के बाद

20. निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए निश्चित रूप से कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी?
(A) अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन प्रक्रिया में संशोधन करना
(B) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के दायरे को बदलना
(C) नीति निदेशक तत्वों के दायरे और अनुप्रयोग का विस्तार करना
(D) किसी राज्य की विधान परिषद का उत्सादन या सृजन करना

21. 1951 का प्रथम संशोधन अधिनियम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित न्यायिक निर्णयों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अधिनियमित किया गया था?
(A) निवारक निरोध कानून
(B) भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन
(C) जमींदारी उन्मूलन और कृषि सुधार
(D) राष्ट्रीय आपातकाल का लागू होना

22. भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी?
(A) आठवीं अनुसूची
(B) नौवीं अनुसूची
(C) दसवीं अनुसूची
(D) ग्यारहवीं अनुसूची

23. प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसने वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के तीन और आधार जोड़े।
II. इसने राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया।
III. इसने भूमि सुधार कानूनों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 31A और 31B को अंतःस्थापित किया।
IV. इसने संपत्ति के मूल अधिकार को विधिक अधिकार में बदल दिया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

24. प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा अनुच्छेद 19(1)(a) में निम्नलिखित में से किसे युक्तियुक्त प्रतिबंध के रूप में नहीं जोड़ा गया था?
(A) लोक व्यवस्था
(B) भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता
(C) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
(D) अपराध उद्दीपन

NODIA

25. 1951 में भारत के संविधान का पहला संशोधन किसने पारित किया था?
(A) प्रथम आम चुनावों के बाद भारत की निर्वाचित संसद ने
(B) अध्यादेश के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति ने
(C) अनंतिम संसद के रूप में कार्य कर रही संविधान सभा ने
(D) एक विशेष संवैधानिक सम्मेलन ने

26. 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 मुख्य रूप से किससे संबंधित था?
(A) संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल करना
(B) आम चुनावों में नागरिकों के लिए न्यूनतम मतदान आयु घटाना
(C) संसद सदस्यों के लिए दल-बदल विरोधी प्रावधान लागू करना
(D) राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करना

27. 7वें संविधान संशोधन ने राज्यों के तत्कालीन वर्गीकरण को समाप्त कर दिया। निम्नलिखित में से किन श्रेणियों को हटाया गया था?
(A) भाग A, भाग B, भाग C, और भाग D राज्य
(B) केवल भाग A और भाग B राज्य श्रेणियां
(C) केवल भाग B और भाग C राज्य श्रेणियां
(D) केवल भाग C और भाग D राज्य श्रेणियां

28. किस संशोधन ने एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया?
(A) प्रथम संशोधन
(B) 7वां संशोधन
(C) 15वां संशोधन
(D) 24वां संशोधन

29. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इन संवैधानिक संशोधनों के अधिनियमन का सही कालानुक्रमिक क्रम दर्शाता है?
(A) 7वां संशोधन, 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 52वां संशोधन
(B) 24वां संशोधन, 7वां संशोधन, 52वां संशोधन, 42वां संशोधन
(C) 7वां संशोधन, 42वां संशोधन, 24वां संशोधन, 52वां संशोधन
(D) 42वां संशोधन, 7वां संशोधन, 24वां संशोधन, 52वां संशोधन

के पूरक हैं और जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का विस्तार DPSP के आलोक में किया गया है।

99. (A) P-2, Q-1, R-4, S-3
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (1987) निःशुल्क विधिक सहायता (अनुच्छेद 39A) से संबंधित है। मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) प्रसूति सहायता (अनुच्छेद 42) को लागू करता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948) कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी (अनुच्छेद 43) सुनिश्चित करता है। वन (संरक्षण) अधिनियम (1980) पर्यावरण और वनों के संरक्षण (अनुच्छेद 48A) के उद्देश्य को पूरा करता है।

100. (C) कोई न्यायिक उपचार नहीं है; इसका उपचार मताधिकार द्वारा ही संभव है
यदि कोई राज्य सरकार नीतियां बनाते समय नीति निदेशक तत्वों की उपेक्षा करती है, तो नागरिकों के पास कोई न्यायिक उपचार उपलब्ध नहीं है क्योंकि DPSP गैर-न्यायोचित हैं। इस स्थिति में एकमात्र संवैधानिक उपचार मताधिकार और आवधिक चुनाव हैं। नागरिक चुनावों के माध्यम से ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, जैसा कि डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि असली शक्ति जनता के पास है।

101. (A) न्यूनतम मजदूरी में केवल जीवन निर्वाह शामिल है, जबकि निर्वाह मजदूरी में शिक्षा, स्वास्थ्य और विश्राम भी शामिल हैं।
निर्वाह मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी में मुख्य अंतर यह है कि न्यूनतम मजदूरी केवल किसी श्रमिक के भोजन, वस्त्र और मकान जैसी बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसके विपरीत, अनुच्छेद 43 में उल्लिखित 'निर्वाह मजदूरी' का दायरा व्यापक है, जिसमें भोजन के अलावा बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, मनोरंजन और विश्राम के अवसर भी शामिल हैं, ताकि एक शिष्ट जीवन स्तर मिले।

102. (B) अनुच्छेद 42
संविधान का अनुच्छेद 42 राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश देता है। इसका उद्देश्य यह देखना है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वच्छता और मानवीय माहौल बना रहे, ताकि श्रमिकों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके अलावा, यही अनुच्छेद महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता और सुविधाओं का उपबंध करने का निर्देश भी राज्य को देता है।

103. (B) उत्तराखंड
गोवा के बाद, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा ने फरवरी 2024 में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित किया। स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। यह कदम संविधान के अनुच्छेद 44 में दिए गए उस नीति निदेशक तत्व को लागू करने की दिशा में उठाया गया है, जो राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान सिविल कानून बनाने की बात करता है।

104. (C) सभी टकरावों में DPSP को हमेशा मूल अधिकारों पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संबंध के संदर्भ में यह कहना गलत है कि सभी टकरावों में DPSP को हमेशा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मिनर्वा मिल्स मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि दोनों के बीच संतुलन संविधान का मूल ढांचा है। केवल अनुच्छेद 39(b) और (c) को लागू करने वाले कानूनों को ही अनुच्छेद 14 और 19 पर संवैधानिक प्राथमिकता प्राप्त है।

105. (D) ग्रामीण और कृषि आर्थिक विकास
अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों के संवर्धन को शामिल करना भारत के ग्रामीण और कृषि आर्थिक विकास में सहकारिता की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। सहकारी समितियां किसानों, दुग्ध उत्पादकों और छोटे कारीगरों को ऋण, इनपुट तथा विपणन सुविधाएं प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाती हैं। यह प्रावधान लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त बनाता है।

106. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा कानून बनाना आवश्यक होता है। ये तत्व स्वतः लागू नहीं होते हैं और न ही ये मूल अधिकारों की तरह नागरिकों को सीधे प्रवर्तनीय अधिकार प्रदान करते हैं। जब तक सरकार इन्हें लागू करने के लिए उपयुक्त विधान नहीं बनाती, तब तक इन्हें न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। अतः अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं।

107. (C) अनुच्छेद 50
संविधान का अनुच्छेद 50 राज्य को लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का स्पष्ट निर्देश देता है। इस पृथक्करण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायिक कार्यों का निष्पादन करने वाले अधिकारी कार्यपालिका के प्रभाव या नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र रहें, जिससे नागरिकों को निष्पक्ष न्याय मिल सके और कानून का शासन बना रहे।

108. (D) I, II, III और IV
सरकार ने नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जमींदारी उन्मूलन और कृषि सुधार (अनुच्छेद 39(b)), योजना आयोग की स्थापना (अनुच्छेद 38), मातृत्व लाभ अधिनियम पारित करना (अनुच्छेद 42) तथा वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण (अनुच्छेद 39(c))—ये सभी उपाय समाज कल्याण, आर्थिक समानता और श्रमिकों की सुरक्षा के संवैधानिक निर्देशों को पूरा करने के लिए ही लागू किए गए थे।

109. (C) अनुच्छेद 51A(g)
भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण की दोहरी व्यवस्था है। जहां अनुच्छेद 48A इसे राज्य के लिए नीति निदेशक तत्व के

Click Here to Buy book on Flipkart

सूची I: 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया प्रावधान
P. अनुच्छेद 39A
Q. अनुच्छेद 43A
R. अनुच्छेद 48A
S. भाग XIVA
सूची II: विषय
1. पर्यावरण और वन्यजीवों का संरक्षण
2. अधिकरण
3. समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
4. प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

42. 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था?
(A) 6 वर्ष
(B) 7 वर्ष
(C) 10 वर्ष
(D) आपातकाल के दौरान अनिश्चित काल

43. 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 मुख्य रूप से किस उद्देश्य से लाया गया था?
(A) 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किए गए विवादित प्रावधानों को निरस्त करने के लिए
(B) भारत के प्रधानमंत्री की कार्यपालक शक्तियों को मजबूत और विस्तारित करने के लिए
(C) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए
(D) भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची और दायरे का विस्तार करने के लिए

44. 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 352 में "आंतरिक अशांति" के स्थान पर किस शब्द को प्रतिस्थापित किया गया?
(A) गृह युद्ध
(B) सशस्त्र विद्रोह
(C) बाह्य आक्रमण
(D) घरेलू हिंसा

45. 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के बाद संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या थी?
(A) इसे भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों से पूरी तरह से हटा दिया गया था
(B) इसे भाग III से स्थानांतरित करके भाग XII में अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया
(C) यह अत्यंत कड़े प्रतिबंधों के अधीन एक मूल अधिकार बना रहा
(D) इसे राज्य के एक गैर-न्यायोचित नीति निदेशक तत्व में परिवर्तित कर दिया गया था

46. 44वें संशोधन अधिनियम ने संसदीय कार्यवाहियों के संबंध में निम्नलिखित में से किस गतिविधि को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया?
(A) संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियों की सत्य रिपोर्टों का समाचार पत्रों में प्रकाशन
(B) संसद सदस्यों को दल के निर्देशों के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से मतदान करने का संवैधानिक संरक्षण
(C) सार्वजनिक मीडिया माध्यमों पर शून्यकाल की कार्यवाहियों का अप्रतिबंधित प्रसारण
(D) अपने कार्यकाल के दौरान सभी आपराधिक कार्यवाहियों से संसद सदस्यों को पूर्ण उन्मुक्ति

47. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने यह अनिवार्य बना दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही की जा सकती है।
कारण (R): यह सुरक्षा उपाय प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल की औपचारिक सहमति के बिना एकतरफा आपातकाल लगाने से रोकने के लिए लागू किया गया था।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

48. 44वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति में संशोधन किया गया ताकि वे:
(A) यदि सलाह को असंवैधानिक मानते हैं तो उसे पूरी तरह से निरस्त कर सकें
(B) सलाह को परामर्शदात्री राय के लिए उच्चतम न्यायालय को भेज सकें
(C) सलाह स्वीकार करने के बजाय लोकसभा को तुरंत भंग कर सकें
(D) मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकें

49. 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 संविधान में किस अनुसूची को अंतःस्थापित करने के लिए प्रसिद्ध है?
(A) आठवीं अनुसूची
(B) नौवीं अनुसूची
(C) दसवीं अनुसूची
(D) ग्यारहवीं अनुसूची

50. 52वें संशोधन अधिनियम का लोकप्रिय नाम क्या है?
(A) पंचायती राज अधिनियम
(B) दल-बदल विरोधी कानून
(C) भूमि सीमा समझौता

Downloaded from www.pdf.tube

(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

130. संवैधानिक संशोधनों और उनके अधिनियमित होने के दशकों के निम्नलिखित संयोजनों पर विचार कीजिए:

I. प्रथम संशोधन - 1950 का दशक
II. 42वां संशोधन - 1970 का दशक
III. 73वां संशोधन - 1990 का दशक
IV. 101वां संशोधन - 2010 का दशक

उपर्युक्त संयोजनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, III और IV
(D) I, II, III और IV

NODIA

62. 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार, पंचायतों में महिलाओं के लिए अनिवार्य न्यूनतम सीटों का आरक्षण कितना है?
(A) कुल सीटों का एक-चौथाई
(B) कुल सीटों का एक-तिहाई
(C) कुल सीटों का आधा
(D) राज्य में महिला जनसंख्या के अनुपात में

63. 73वें संशोधन के अंतर्गत, पंचायत चुनावों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है?
(A) भारत का निर्वाचन आयोग
(B) जिला मजिस्ट्रेट
(C) राज्य निर्वाचन आयोग
(D) राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

64. 73वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रखे गए कितने कार्यात्मक विषयों की सूची है?
(A) 18
(B) 21
(C) 29
(D) 35

65. 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान करता है: नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद, और नगर निगम।
II. इसके अंतर्गत तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिका के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों के गठन की आवश्यकता होती है।
III. इसने नगरपालिकाओं के लिए 29 कार्यात्मक विषयों को शामिल करते हुए बारहवीं अनुसूची जोड़ी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

66. 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 किससे संबंधित है?
(A) ग्रामीण स्थानीय शासन
(B) शहरी स्थानीय शासन
(C) सहकारी समितियां
(D) अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद

67. जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान करने के लिए 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा अनुच्छेद अंतःस्थापित किया गया था?
(A) अनुच्छेद 243ZA
(B) अनुच्छेद 243ZB
(C) अनुच्छेद 243ZD
(D) अनुच्छेद 243ZE

68. 74वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए कितने कार्यात्मक विषय शामिल हैं?
(A) 18
(B) 22
(C) 29
(D) 32

69. 74वें संशोधन के अनुसार, किसी नगरपालिका का कार्यकाल, जब तक कि पहले विघटित न कर दिया जाए, कितना होता है?
(A) इसकी प्रथम बैठक की तारीख से 3 वर्ष
(B) इसकी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष
(C) निर्वाचन परिणामों की घोषणा की तारीख से 5 वर्ष
(D) राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर निर्भर

70. 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 ने किस नए अनुच्छेद को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया?
(A) अनुच्छेद 21A
(B) अनुच्छेद 22A
(C) अनुच्छेद 23A
(D) अनुच्छेद 24A

71. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: 86वें संशोधन द्वारा संशोधित या जोड़ा गया अनुच्छेद
P. अनुच्छेद 21A
Q. अनुच्छेद 45
R. अनुच्छेद 51A(k)
S. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
सूची II: प्रावधान
1. छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रावधान
2. माता-पिता/संरक्षक का अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य
3. 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार
4. अनुच्छेद 21A को लागू करने हेतु विधायी अधिनियमन
(A) P-3, Q-1, R-2, S-4
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

72. 86वें संशोधन अधिनियम से पूर्व, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का विषय नीति निदेशक तत्वों के किस अनुच्छेद में निहित था?

Click Here to Buy book on Amazon

(D) राजभाषा अधिनियम

51. मूल 52वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत (91वें संशोधन से पूर्व), किसी राजनीतिक दल में विभाजन को मान्यता दी गई थी और अयोग्यता लागू नहीं होती थी यदि इसमें विधान दल के कम से कम कितने सदस्य शामिल थे?
(A) आधा (1/2)
(B) एक-तिहाई (1/3)
(C) दो-तिहाई (2/3)
(D) एक-चौथाई (1/4)

52. 52वें संशोधन अधिनियम के अनुसार, दल-बदल के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय लेने का अंतिम प्राधिकारी कौन है?
(A) लोकसभा अध्यक्ष
(B) भारत के राष्ट्रपति
(C) भारत का निर्वाचन आयोग
(D) भारत का उच्चतम न्यायालय

53. दल-बदल विरोधी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों पर लागू होता है।
II. एक मनोनीत सदस्य अयोग्य हो जाता है यदि वह अपना स्थान ग्रहण करने के छह महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।
III. एक निर्दलीय सदस्य अयोग्य हो जाता है यदि वह अपने निर्वाचन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।
IV. दल-बदल पर अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

54. 61वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
(A) मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना
(B) पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण
(C) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का प्रयोग
(D) आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता

55. मतदान की आयु कम करने के लिए 61वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था?
(A) अनुच्छेद 324
(B) अनुच्छेद 325
(C) अनुच्छेद 326
(D) अनुच्छेद 327

56. मतदान की आयु घटाने वाला 61वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था?
(A) 1985
(B) 1989
(C) 1992
(D) 1993

57. 61वें संशोधन के अंतर्गत मतदान की आयु में कमी किन चुनावों पर लागू होती है?
(A) केवल राज्यसभा और राज्य विधान परिषद
(B) केवल पंचायत और नगरपालिका
(C) लोकसभा और राज्य विधानसभाएं
(D) केवल लोकसभा

58. मतदान की आयु घटाने के लिए 61वां संशोधन अधिनियम किसके प्रधानमंत्रित्व काल में पारित किया गया था?
(A) इंदिरा गांधी
(B) मोरारजी देसाई
(C) वी.पी. सिंह
(D) राजीव गांधी

59. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधिनियमन और कार्यान्वयन के निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए:
1. आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन
2. लोकसभा में 73वां संशोधन विधेयक पारित होना
3. राष्ट्रपति की अनुमति
4. 73वें संशोधन का अनुपालन करने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम का प्रवर्तन
उपर्युक्त चरणों का सही कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) 2, 1, 3, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 4, 2, 1, 3

60. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा?
(A) भाग IX
(B) भाग IX-A
(C) भाग X
(D) भाग XI

61. 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार, जिस राज्य की जनसंख्या एक निश्चित सीमा से अधिक न हो, वह मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन न करने का विकल्प चुन सकता है। यह जनसंख्या सीमा क्या है?
(A) 10 लाख
(B) 20 लाख
(C) 30 लाख
(D) 50 लाख

NODIA

I. इसने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया।
II. इसके लिए आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता थी।
III. इसने पंचायतों की कराधान शक्तियों को समाप्त कर दिया।
IV. इसने केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की स्थापना की।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I, II और IV
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

84. 101वें संशोधन अधिनियम के लिए राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता क्यों थी?
(A) इसने सातवीं अनुसूची की विधायी सूचियों को संशोधित किया जिससे राज्यों की कराधान शक्तियां प्रभावित हुईं
(B) इसने संविधान के मूल ढांचे की आवश्यक विशेषताओं को मूलभूत रूप से बदल दिया
(C) इसने संसद के दोनों सदनों में राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन किया
(D) इसने भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक प्रक्रियाओं को बदल दिया

85. 103वां संविधान संशोधन अधिनियम शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक नियोजन में किसके लिए अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान करता है?
(A) अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी)
(B) ट्रांसजेंडर व्यक्ति एवं लैंगिक रूप से गैर-अनुकूलित नागरिक
(C) नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)
(D) विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातीय समुदाय

86. ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने के लिए 103वें संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों के किन अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था?
(A) अनुच्छेद 14 और 15
(B) अनुच्छेद 15 और 16
(C) अनुच्छेद 16 और 17
(D) अनुच्छेद 19 और 21

87. 103वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण:
(A) 50% की कुल आरक्षण सीमा का पालन करते हुए मौजूदा कोटे के अंतर्गत है
(B) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित मौजूदा 27% कोटे से काटा गया है
(C) राज्य सरकार की नौकरियों को छोड़कर केवल केंद्र सरकार के पदों पर लागू है
(D) एससी, एसटी और ओबीसी कोटे के अतिरिक्त है, जिससे कुल आरक्षण 50% से अधिक हो सकता है

88. 103वें संशोधन द्वारा प्रदान किए गए ईडब्ल्यूएस आरक्षण के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) यह निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर लागू होता है।
(B) यह अनुच्छेद 30(1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होता है।
(C) यह उन व्यक्तियों के लिए है जो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की योजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।
(D) राज्य पारिवारिक आय और आर्थिक प्रतिकूलता के अन्य सूचकों के आधार पर ईडब्ल्यूएस स्थिति के लिए मानदंड निर्धारित करता है।

89. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाल के संवैधानिक संशोधनों (101वें से 104वें तक) में शामिल विषयों का सही कालानुक्रमिक क्रम दर्शाता है?
(A) जीएसटी, एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, एससी/एसटी कोटे का विस्तार
(B) जीएसटी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा, एससी/एसटी कोटे का विस्तार
(C) ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जीएसटी, एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा, एससी/एसटी कोटे का विस्तार
(D) एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा, जीएसटी, एससी/एसटी कोटे का विस्तार, ईडब्ल्यूएस आरक्षण

90. 'मूल ढांचा' सिद्धांत, जो संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था?
(A) शंकरी प्रसाद मामला (1951)
(B) आई.सी. गोलकनाथ मामला (1967)
(C) केशवानंद भारती मामला (1973)
(D) मिनर्वा मिल्स मामला (1980)

91. अनुच्छेद 368 के संबंध में केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय का मुख्य निर्णय क्या था?
(A) संसद मूल ढांचे को बदले बिना संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है
(B) संसद को किसी भी मूल अधिकार में संशोधन करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है
(C) केवल एक नई बुलाई गई संविधान सभा ही मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है
(D) संसद की संविधान संशोधन शक्ति निरपेक्ष है और न्यायिक समीक्षा से परे है

92. मूल ढांचा सिद्धांत का तात्पर्य है कि:
(A) संसद द्वारा पारित कोई भी संशोधन वैध है यदि सभी राज्य विधानमंडलों द्वारा औपचारिक रूप से अनुसमर्थित हो
(B) संसद के पास सीमित संशोधन शक्तियां हैं और वह संविधान की मूल पहचान को नष्ट नहीं कर सकती है
(C) भारत का संविधान पूरी तरह से अनम्य है और किसी भी

Downloaded from www.pdf.tube

परिस्थिति में इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है
(D) मूल ढांचे के तत्वों को स्वयं अनुच्छेद 368 के पाठ के भीतर स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है

93. किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 42वें संशोधन अधिनियम के उस प्रावधान को अमान्य कर दिया, जिसने संसद की संशोधन शक्ति को निरपेक्ष और न्यायिक समीक्षा से मुक्त बनाने का प्रयास किया था?
(A) वामन राव मामला (1981)
(B) मिनर्वा मिल्स मामला (1980)
(C) एस.आर. बोम्मई मामला (1994)
(D) इंदिरा नेहरु गांधी मामला (1975)

94. 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को निरस्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत का उपयोग किया गया था। यह संशोधन किससे संबंधित था?
(A) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) की स्थापना
(B) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा
(C) भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते का कार्यान्वयन
(D) सहकारी समितियों के लिए संवैधानिक दर्जा और नियामक ढांचा

95. संविधान की संशोधन योग्यता से संबंधित निम्नलिखित मामलों पर विचार कीजिए:
I. शंकरी प्रसाद मामला
II. गोलकनाथ मामला
III. केशवानंद भारती मामला
उपर्युक्त में से किस मामले में यह निर्णय सुनाया गया था कि संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है?
(A) केवल I और II
(B) केवल II
(C) केवल III
(D) केवल II और III

96. निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के "मूल ढांचे" का अंग माना जाता है?
(A) संविधान में असीमित संशोधन करने की संसद की शक्ति
(B) राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की प्रणाली
(C) नौवीं अनुसूची
(D) संविधान की सर्वोच्चता

97. एस.आर. बोम्मई मामले (1994) में, किस अवधारणा पर मूल ढांचे की एक आवश्यक विशेषता के रूप में बल दिया गया था?
(A) विधि का शासन
(B) संसदीय प्रणाली
(C) पंथनिरपेक्षता
(D) कल्याणकारी राज्य

98. निम्नलिखित में से किसे उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के मूल ढांचे के अंग के रूप में मान्यता नहीं दी गई है?
(A) न्यायिक समीक्षा
(B) संपत्ति का अधिकार
(C) स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन
(D) न्यायपालिका की स्वतंत्रता

99. मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन को संविधान की एक मूल विशेषता माना जाता है। यह किस मामले में स्थापित किया गया था?
(A) गोलकनाथ मामला
(B) केशवानंद भारती मामला
(C) एल. चंद्र कुमार मामला
(D) मिनर्वा मिल्स मामला

100. उच्चतम न्यायालय द्वारा पहचाने गए मूल ढांचे के तत्वों के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए।
(A) उपाधियों का अंत
(B) संविधान का परिसंघीय/संसदीय स्वरुप
(C) विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण
(D) भारतीय राजव्यवस्था की संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य प्रकृति

101. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: ऐतिहासिक निर्णय
P. शंकरी प्रसाद मामला (1951)
Q. गोलकनाथ मामला (1967)
R. केशवानंद भारती मामला (1973)
S. आई.आर. कोएल्हो मामला (2007)
सूची II: संशोधन शक्ति पर मुख्य निर्णय
1. संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है
2. संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती
3. मूल ढांचे का सिद्धांत
4. 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-3, S-4
(C) P-1, Q-3, R-2, S-4
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

102. आई.आर. कोएल्हो मामले (2007) में, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित वह तिथि कौन सी थी जिसके बाद नौवीं अनुसूची में शामिल कोई भी कानून मूल ढांचे के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है?
(A) 26 जनवरी, 1950
(B) 24 अप्रैल, 1973
(C) 25 जून, 1975
(D) 19 अप्रैल, 1976

NODIA

103. गोलकनाथ मामले में यह घोषित करने के लिए क्या तर्क दिया गया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है?
(A) मूल अधिकार अंतर्निहित प्राकृतिक अधिकार हैं जिन्हें राज्य के कानूनों द्वारा सीमित या बदला नहीं जा सकता है
(B) मूल ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत मूल अधिकारों को बदलने वाले संशोधन प्रतिबंधित हैं
(C) संविधान सभा ने मूल अधिकारों में भविष्य के सभी संशोधनों पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिया था
(D) अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'विधि' है और यह मूल अधिकारों को छीन या कम नहीं कर सकता है

104. शंकरी प्रसाद मामले में किस संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी?
(A) प्रथम संशोधन
(B) चौथा संशोधन
(C) सातवां संशोधन
(D) सत्रहवां संशोधन

105. केशवानंद भारती मामले के बाद की वर्तमान विधिक स्थिति के अंतर्गत, यदि कोई संशोधन किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है किंतु मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है, तो क्या स्थिति होगी?
(A) संशोधन अमान्य होगा।
(B) इसके लिए राष्ट्रीय जनमत संग्रह के माध्यम से अनुमोदन आवश्यक होगा।
(C) संशोधन वैध होगा।
(D) राष्ट्रपति इस पर वीटो कर सकते हैं।

106. तुलनात्मक संवैधानिक अध्ययनों में, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया को सामान्यतः किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है?
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका के समान अत्यंत अनम्य संशोधन प्रक्रिया
(B) यूनाइटेड किंगडम के समान अत्यधिक नम्य संशोधन प्रक्रिया
(C) नई संविधान सभा का गठन किए बिना पूरी तरह से गैर-संशोधन योग्य
(D) नम्यता और अनम्यता दोनों के तत्वों का एक अनूठा संश्लेषण

107. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): भारत में संशोधन की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में अधिक नम्य है।
कारण (R): संयुक्त राज्य अमेरिका में, संशोधन को तीन-चौथाई राज्यों द्वारा अनुसमर्थित किया जाना अनिवार्य है, जबकि भारत में, केवल कुछ प्रावधानों के लिए राज्य अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है और इसमें केवल आधे राज्य शामिल होते हैं।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

108. स्विस और ऑस्ट्रेलियाई संविधानों के विपरीत, भारतीय संविधान संवैधानिक संशोधन की किस पद्धति का प्रावधान नहीं करता है?
(A) राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन विधेयकों का अनुसमर्थन
(B) जनमत संग्रह के माध्यम से जनता द्वारा संशोधनों की प्रत्यक्ष स्वीकृति
(C) विशेष संसदीय बहुमत द्वारा संशोधन विधेयकों का पारित होना
(D) साधारण संसदीय मतदान द्वारा संवैधानिक परिवर्तनों का पारित होना

109. किस संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान को "नम्यता और अनम्यता के बीच एक संतुलन" स्थापित करने वाला बताया था?
(A) ग्रैनविले ऑस्टिन
(B) के.सी. व्हीयर
(C) आइवर जेनिंग्स
(D) ए.वी. डाइसी

110. निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान की 'नम्यता' को दर्शाता है?
(A) अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्य विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन
(B) राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया
(C) अनुच्छेद 368 में निर्दिष्ट संशोधन प्रक्रिया और शक्तियों का दायरा
(D) संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण

111. संसद में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के संबंध में किस प्रक्रियात्मक नियम का सख्ती से पालन किया जाता है?
(A) इसे संसद के संयुक्त सत्र में विचार-विमर्श के पश्चात पारित किया जाना चाहिए
(B) इसे भारत के उच्चतम न्यायालय से पूर्व मंजूरी प्राप्त होना आवश्यक है
(C) इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए
(D) इसे संवैधानिक विशेषज्ञों की एक विशेष समिति द्वारा तैयार किया जाना चाहिए

Click Here to Buy book on Flipkart

(A) अनुच्छेद 39
(B) अनुच्छेद 41
(C) अनुच्छेद 45
(D) अनुच्छेद 46

73. 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था?
(A) वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का कर्तव्य
(B) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करने का कर्तव्य
(C) छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चे के माता-पिता या संरक्षक द्वारा शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य
(D) हमारी सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य

74. 86वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 21A के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी दी गई है?
(A) 0 से 6 वर्ष
(B) 6 से 14 वर्ष
(C) 6 से 18 वर्ष
(D) 14 से 18 वर्ष

75. 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या पर एक सीमा निर्धारित की। यह सीमा क्या है?
(A) लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10%
(B) लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%
(C) संसद (दोनों सदनों को मिलाकर) की कुल सदस्य संख्या का 15%
(D) लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 20%

76. 91वें संशोधन के अनुसार, राजस्थान राज्य में (जहां विधानसभा में 200 सदस्य हैं), मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है:
(A) 20
(B) 25
(C) 30
(D) 40

77. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 ने दसवीं अनुसूची के उस प्रावधान को समाप्त कर दिया जो एक-तिहाई सदस्यों द्वारा विभाजन की स्थिति में अयोग्यता से छूट देता था।
कारण (R): विभाजन के लिए छूट का बार-बार दुरुपयोग दल-बदल कराने और विशाल मंत्रिमंडल बनाने के लिए किया जाता था।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

78. 91वें संशोधन अधिनियम द्वारा किसी राज्य के लिए मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम निर्धारित संख्या कितनी है?
(A) 10
(B) 12
(C) 15
(D) 20

79. 91वें संशोधन के अंतर्गत, संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित है और दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य ठहराया जाता है, वह निम्नलिखित के लिए भी अयोग्य होगा:
(A) अगले आम चुनाव में मतदान करने या उम्मीदवार के रूप में भाग लेने से
(B) छह वर्ष के लिए भविष्य में कोई भी संसदीय या राज्य विधायी चुनाव लड़ने से
(C) मंत्री नियुक्त होने से या कोई लाभ का राजनीतिक पद धारण करने से
(D) किसी भी राजनीतिक दल की ओर से सार्वजनिक रैलियों में बोलने या प्रचार करने से

80. 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है?
(A) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
(B) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण
(C) बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता
(D) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

81. 101वें संशोधन द्वारा संसद और राज्य विधानमंडलों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में कानून बनाने की समवर्ती शक्ति देने के लिए कौन सा नया अनुच्छेद अंतःस्थापित किया गया था?
(A) अनुच्छेद 246A
(B) अनुच्छेद 269A
(C) अनुच्छेद 279A
(D) अनुच्छेद 368A

82. केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच, जीएसटी परिषद, 101वें संशोधन द्वारा जोड़े गए किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है?
(A) अनुच्छेद 268A
(B) अनुच्छेद 269A
(C) अनुच्छेद 279A
(D) अनुच्छेद 280A

83. 101वें संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

NODIA

(C) विस्तृत प्रशासनिक प्रावधानों का समावेश जिनमें बार-बार अद्यतन की आवश्यकता होती है
(D) केंद्र पर राज्य सरकारों द्वारा डाला गया निरंतर राजनीतिक दबाव

122. भारत में संशोधन प्रक्रिया की एक मुख्य आलोचना क्या है?
(A) किसी भी छोटे बदलाव के लिए सभी राज्य विधानमंडलों से सर्वसम्मति आवश्यक होना
(B) संविधान संशोधन विधेयकों पर अत्यधिक राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग
(C) राज्यसभा के आक्षेपों को दूर करने के लिए संयुक्त बैठकों का बार-बार उपयोग
(D) जनमत संग्रह आयोजित करने के लिए किसी भी संवैधानिक प्रावधान का न होना

123. संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया में राज्य विधानमंडलों की भूमिका को आलोचकों द्वारा सीमित क्यों माना जाता है?
(A) वे किसी भी संवैधानिक संशोधन को आरंभ नहीं कर सकते।
(B) उनके अनुसमर्थन की आवश्यकता केवल कुछ चुनिंदा प्रावधानों के लिए ही होती है।
(C) उनके अनुसमर्थन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है।
(D) उपर्युक्त सभी

124. 'मूल ढांचा' सिद्धांत की आलोचना मुख्य रूप से किस आधार पर की गई है?
(A) यह अत्यधिक अनम्य है और आवश्यक सामाजिक-आर्थिक सुधारों को रोकता है
(B) यह संविधान में अपरिभाषित है और पूरी तरह से न्यायिक व्याख्या पर निर्भर करता है
(C) यह संसद के भीतर अत्यधिक विधायी और संवैधानिक शक्ति को केंद्रित करता है
(D) यह अनिवार्य करता है कि राज्य विधानमंडल प्रत्येक वरिष्ठ न्यायिक नियुक्ति को मंजूरी दें

125. भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के विरुद्ध की गई निम्नलिखित आलोचनाओं पर विचार कीजिए:
I. संविधान का बड़ा हिस्सा अकेले संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
II. संविधान में संशोधन की प्रक्रिया वही है जो साधारण विधि के लिए है।
III. संविधान इस विषय पर मौन है कि क्या राज्य एक बार दी गई अपनी स्वीकृति (अनुसमर्थन) वापस ले सकते हैं या नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

126. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने किसे संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया?
(A) सहकारी समितियां
(B) नगरपालिकायें
(C) गैर-सरकारी संगठन
(D) स्वयं सहायता समूह

127. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: संशोधन अधिनियम
P. 52वां संशोधन
Q. 61वां संशोधन
R. 73वां संशोधन
S. 86वां संशोधन
सूची II: मुख्य विषय
1. मतदान की आयु घटाई गई
2. दल-बदल विरोधी कानून
3. शिक्षा का अधिकार
4. पंचायती राज
(A) P-2, Q-1, R-4, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

128. 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी की सीटों के आरक्षण को अगले दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया, और इसके अतिरिक्त इसने:
(A) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाकर 15% कर दिया
(B) सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम मतदान आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी
(C) आठवीं अनुसूची में तीन अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ा
(D) आंग्ल-भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने के संवैधानिक प्रावधान को समाप्त कर दिया

NODIA

129. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): भारत में संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के विकास में संसद और न्यायपालिका के बीच महत्वपूर्ण टकराव देखा गया है।
कारण (R): संपत्ति के अधिकारों और मूल अधिकारों से संबंधित न्यायिक व्याख्याओं के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा लगातार कई संविधान संशोधन पारित किए गए थे।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

112. यदि संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध उत्पन्न होता है, तो संवैधानिक प्रावधान क्या है?
(A) राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं
(B) लोकसभा का निर्णय स्वतः ही मान्य होता है
(C) विधेयक को निर्णय के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है
(D) संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, अतः विधेयक समाप्त हो जाता है

113. साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. एक साधारण विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन विधेयक के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
II. साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन संशोधन विधेयक के लिए नहीं।
III. राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए साधारण विधेयक लौटा सकते हैं, लेकिन संशोधन विधेयक पर अनुमति देना उनके लिए अनिवार्य है।
IV. दोनों के लिए राज्य अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

114. किस स्थिति को रोकने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनिवार्य स्वीकृति का प्रावधान शामिल किया गया था?
(A) राज्य विधानमंडलों को स्थापित संसदीय संशोधन प्रक्रियाओं की उपेक्षा करने से रोकने के लिए
(B) राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा पारित संशोधनों पर जेबी वीटो का प्रयोग करने से रोकने के लिए
(C) उच्चतम न्यायालय को स्वीकृति से पूर्व संवैधानिक संशोधन विधेयकों की समीक्षा करने से रोकने के लिए
(D) अल्पमत सरकार को सर्वसम्मति के बिना विवादास्पद संशोधन लागू करने से रोकने के लिए

115. संसद में संविधान संशोधन विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है?
(A) केवल एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री द्वारा
(B) केवल संसद के किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा
(C) केवल भारत के प्रधानमंत्री द्वारा
(D) मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य किसी के भी द्वारा

116. संवैधानिक संशोधनों के संदर्भ में, भारत में राज्य विधानमंडल:
(A) संविधान में संशोधन के लिए कोई विधेयक या प्रस्ताव प्रस्तुत करने की शक्ति नहीं रखते हैं
(B) राज्य सूची के विषयों से संबंधित संवैधानिक संशोधन स्वतंत्र रूप से आरंभ कर सकते हैं
(C) अपनी विधान परिषद को समाप्त करने के लिए संवैधानिक संशोधन आरंभ कर सकते हैं
(D) राज्य के राज्यपाल के पद से संबंधित संवैधानिक संशोधन आरंभ कर सकते हैं

117. यद्यपि राज्य विधानमंडल संवैधानिक संशोधन आरंभ नहीं कर सकता है, फिर भी संसद द्वारा निम्नलिखित में से किस विषय पर कार्रवाई करने के लिए राज्य विधानमंडल का संकल्प एक अनिवार्य पूर्व-शर्त है?
(A) राज्य की सीमाएं बदलना या परिवर्तित करना
(B) दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही साझा राज्यपाल नियुक्त करना
(C) राज्य विधानमंडल के भीतर विधान परिषद का सृजन करना या उसका उत्सादन करना
(D) राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई आधिकारिक भाषा को बदलना

118. निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक नहीं है?
(A) मूल अधिकार
(B) संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
(C) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय
(D) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व

119. विधायी शक्तियों के वितरण (सातवीं अनुसूची) से संबंधित संशोधन में शामिल निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए:
1. संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत करना
2. भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमति
3. संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना
4. आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन
उपर्युक्त चरणों का सही प्रक्रियात्मक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) 1, 3, 4, 2
(B) 1, 4, 3, 2
(C) 3, 1, 4, 2
(D) 1, 3, 2, 4

120. जब राज्य विधानमंडल किसी संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन करते हैं, तो उन्हें इसे किस बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है?
(A) पूर्ण बहुमत
(B) साधारण बहुमत
(C) विशेष बहुमत
(D) सर्वसम्मति

121. आलोचक प्रायः इस बात की ओर संकेत करते हैं कि भारतीय संविधान में बहुत बार संशोधन किए गए हैं। इसका प्राथमिक संरचनात्मक कारण क्या है?
(A) विशेष संविधान सभा का बार-बार आहूत किया जाना
(B) न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों का पूर्ण अभाव

Downloaded from www.pdf.tube

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) भाग XX, अनुच्छेद 368
भारतीय संविधान में समय के साथ आवश्यक बदलाव करने के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। संविधान के भाग XX के तहत अनुच्छेद 368 संसद को संविधान और इसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रावधान के माध्यम से संसद संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन, विस्तार या निरसन कर सकती है। हालांकि संसद की यह संशोधन शक्ति असीमित नहीं है और इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मूल ढांचे के सिद्धांत के अधीन रखा गया है।

2. (D) इसे किसी मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा। इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। इसे किसी मंत्री या किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। राज्य विधानमंडलों के पास संविधान संशोधन विधेयक को आरंभ करने की कोई शक्ति नहीं होती है। विधेयक को दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है।

3. (A) दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।
अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यदि इस प्रकार के विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच कोई असहमति या गतिरोध उत्पन्न होता है, तो राष्ट्रपति के पास संयुक्त बैठक बुलाने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों में विधेयक स्वतः ही समाप्त हो जाता है। संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है।

4. (C) 24वां संशोधन अधिनियम, 1971
वर्ष 1971 में पारित 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 13 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। इस संशोधन के माध्यम से यह कानूनी रूप से स्पष्ट और अनिवार्य कर दिया गया कि जब संसद के दोनों सदनों द्वारा विधिवत पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होंगे। इससे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति इस विषय पर समाप्त हो गई।

5. (C) केवल I और III
संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जब यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते और उन्हें अनुमति देनी ही होती है। परिसंघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले विषयों, जैसे कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।

6. (D) नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन
भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 की जटिल प्रक्रिया के बिना संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इनमें नए राज्यों का प्रवेश या गठन, राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन शामिल हैं। इसके विपरीत, राष्ट्रपति निर्वाचन और विधायी शक्तियों के वितरण जैसे विषयों के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता अनिवार्य होती है।

7. (B) संसद का साधारण बहुमत
संसद के सत्र का संचालन करने के लिए कुल सदस्यों की एक निश्चित संख्या का उपस्थित होना अनिवार्य होता है, जिसे गणपूर्ति या कोरम कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 100(3) के अनुसार, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे, प्रत्येक सदन की बैठक का कोरम सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दसवां भाग होता है। कोरम से संबंधित इन नियमों में संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत की ही आवश्यकता होती है।

8. (C) राज्य विधान परिषदों का सृजन या उत्सादन
संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधान परिषदों के सृजन या उत्सादन की प्रक्रिया दी गई है। जब संबंधित राज्य की विधानसभा इसके लिए विशेष संकल्प पारित करती है, तब संसद साधारण विधि बनाकर विधान परिषद का गठन या समाप्ति कर सकती है। यद्यपि इससे संवैधानिक पाठ बदलता है, परंतु अनुच्छेद 169(3) के अनुसार इसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। यह प्रक्रिया केवल एक साधारण विधायी कार्य के रूप में संपन्न होती है।

9. (D) सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत
संसदीय प्रक्रिया में 'साधारण बहुमत' का तात्पर्य किसी भी सदन में किसी विषय या विधेयक पर मतदान के समय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से अधिक के बहुमत से होता है। इसमें अनुपस्थित सदस्यों या मतदान में भाग न लेने वाले सदस्यों की गणना नहीं की जाती है। साधारण विधेयक, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और अनुच्छेद 368

NODIA

के दायरे से बाहर के अनेक संवैधानिक मामलों को पारित करने के लिए इसी बहुमत का प्रयोग किया जाता है।

10. (A) साधारण बहुमत
अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि किसी राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से विधान परिषद के सृजन का संकल्प पारित करती है, तो इसके बाद यह प्रस्ताव संसद के पास भेजा जाता है। संसद इस परिवर्तन को लागू करने के लिए साधारण बहुमत से विधि पारित करती है। यह प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के संवैधानिक संशोधन के दायरे से पूरी तरह बाहर रखी गई है। इसलिए संसद को इसे केवल अपने साधारण बहुमत द्वारा ही पारित करने की संवैधानिक आवश्यकता होती है।

11. (A) P-2, Q-1, R-3, S-4
नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के लिए संसद में साधारण बहुमत आवश्यक होता है। मूल अधिकारों में संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित प्रावधानों में बदलाव हेतु संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। राज्य विधान परिषद के उत्सादन के लिए अनुच्छेद 169 के तहत संसद में साधारण बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

12. (B) कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत
अनुच्छेद 368 के अंतर्गत निर्धारित विशेष बहुमत से तात्पर्य है कि संशोधन विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में दो शर्तों को पूरा करना होगा। प्रथम, यह उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। द्वितीय, यह उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। यह कठोर प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संविधान में परिवर्तन केवल व्यापक विधायी सहमति के आधार पर ही किए जा सकें।

13. (B) राज्य के नीति निदेशक तत्व
संविधान के वे प्रावधान जो परिसंघीय ढाँचे से संबंधित नहीं हैं, केवल संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व ऐसे ही क्षेत्र हैं, जिनमें संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, परंतु राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत, राज्यों के प्रतिनिधित्व या न्यायपालिका से जुड़े प्रावधानों में संशोधन के लिए राज्यों का अनुसमर्थन अनिवार्य होता है।

14. (A) नागरिकता का अर्जन और समाप्ति - साधारण बहुमत
नागरिकता का अर्जन और समाप्ति संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित साधारण कानून द्वारा संशोधित की जा सकती है, जिसके लिए अनुच्छेद 368 की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी साधारण बहुमत से संबंधित है। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया परिसंघीय ढांचे को प्रभावित करती है, इसलिए इन प्रावधानों में संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।

15. (C) रिक्तियों या अनुपस्थितियों की परवाह किए बिना सदन की कुल सदस्य संख्या
अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत की आवश्यकता के संदर्भ में 'कुल सदस्य संख्या' का अर्थ सदन के गठन के लिए नियत कुल स्थानों की संख्या से है। इसमें रिक्तियों या सदस्यों की अनुपस्थिति की परवाह किए बिना सदन की पूरी क्षमता को शामिल किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि चाहे सदन में कुछ सीटें खाली हों या कुछ सदस्य अनुपस्थित रहें, कुल संख्या की गणना करते समय पूरे सदन की निर्धारित संख्या को ही आधार बनाया जाता है।

16. (D) राज्य विधानसभा का साधारण बहुमत
जब किसी संविधान संशोधन विधेयक के लिए परिसंघीय प्रावधानों को प्रभावित करने के कारण राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, तो इसे राज्य विधानमंडलों के पास भेजा जाता है। राज्य विधानमंडलों को इस विधेयक को पारित करने के लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि राज्य विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत ही अनुसमर्थन के लिए पर्याप्त होता है। इसके लिए किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता राज्यों के स्तर पर नहीं होती।

17. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
भारतीय संविधान का ढांचा परिसंघीय प्रकृति का है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व एक परिसंघीय विशेषता है। यदि इस व्यवस्था में कोई बदलाव किया जाता है, तो इसके लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन अनिवार्य होता है। यह व्यवस्था राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है ताकि केंद्र एकतरफा निर्णय न ले सके।

18. (B) संविधान द्वारा कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं है
संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि राज्यों को संशोधन विधेयक पर कितने समय के भीतर अपना अनुसमर्थन या अस्वीकरण देना होगा। संसद द्वारा पारित संशोधन विधेयक जब राज्यों के पास अनुसमर्थन के लिए भेजा जाता है, तो राज्य विधानमंडल इस पर निर्णय लेने के लिए अपनी समयावधि तय करने हेतु स्वतंत्र होते हैं। संविधान इस संबंध में पूरी तरह मौन है और राज्यों के लिए कोई निश्चित संवैधानिक समय-सीमा निर्धारित नहीं करता है।

19. (D) दोनों सदनों द्वारा पारित होने और आवश्यक राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के बाद
यदि किसी संविधान संशोधन विधेयक में ऐसा प्रावधान शामिल है जो संविधान के परिसंघीय ढांचे को प्रभावित करता है, तो प्रक्रिया के दो मुख्य चरण होते हैं। पहले इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना

Click Here to Buy book on Amazon

पड़ता है। इसके बाद, कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से इसका अनुसमर्थन होना अनिवार्य है। इन दोनों औपचारिकताओं के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ही विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

20. (A) अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन प्रक्रिया में संशोधन करना
अनुच्छेद 368 स्वयं संविधान की संशोधन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यदि अनुच्छेद 368 में ही कोई संशोधन किया जाता है, तो यह परिसंघीय महत्व का मामला बन जाता है। इस कारण, अनुच्छेद 368 के प्रावधानों में परिवर्तन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य होता है। मूल अधिकार या नीति निदेशक तत्वों के लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती।

21. (C) जमींदारी उन्मूलन और कृषि सुधार
प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 मुख्य रूप से विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के उन न्यायिक निर्णयों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए लाया गया था जिन्होंने जमींदारी उन्मूलन कानूनों को अमान्य ठहराया था। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य कृषि सुधारों और सामाजिक-आर्थिक न्याय से संबंधित कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना था। इसने राज्य को संपत्ति के अधिकार के आधार पर न्यायिक रुकावटों का सामना किए बिना भूमि सुधार लागू करने में सक्षम बनाया।

22. (B) नौवीं अनुसूची
प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा भारतीय संविधान में नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस अनुसूची को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य कृषि सुधारों और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कानूनों को न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर दी जाने वाली चुनौतियों से सुरक्षित रखना था। इसके साथ ही अनुच्छेद 31B भी जोड़ा गया था, जो नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता था।

23. (A) केवल I, II और III
प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 ने अनुच्छेद 19(2) में वाक् स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के तीन नए आधार—लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध उद्दीपन—जोड़े। इसने पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार भी दिया और अनुच्छेद 31A व 31B को अंतःस्थापित किया। हालांकि, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाने का कार्य 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा किया गया था, न कि प्रथम संशोधन द्वारा।

24. (B) भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता
प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तीन नए युक्तियुक्त प्रतिबंध जोड़े गए थे, जो थे: लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, और अपराध उद्दीपन। 'भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता' को प्रतिबंध के एक आधार के रूप में 1951 में नहीं, बल्कि वर्ष 1963 में पारित 16वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 19(2) में शामिल किया गया था।

25. (C) अनंतिम संसद के रूप में कार्य कर रही संविधान सभा ने
वर्ष 1951 में जब प्रथम संविधान संशोधन पारित किया गया था, तब भारत में प्रथम आम चुनाव संपन्न नहीं हुए थे और विधिवत निर्वाचित संसद का गठन नहीं हुआ था। उस समय, भारत की संविधान सभा ही अनंतिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। इस अनंतिम संसद ने ही देश में उत्पन्न भूमि सुधार और सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं से जुड़ी कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 को पारित किया था।

26. (D) राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करना
7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 मुख्य रूप से राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए पारित किया गया था। इस संशोधन के द्वारा भारत में राज्यों के पुराने वर्गीकरण को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और देश को 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। इसने प्रशासनिक पुनर्रचना और राज्यों के क्षेत्रीय सीमाओं के पुनर्निर्धारण का मार्ग प्रशस्त किया।

27. (A) भाग A, भाग B, भाग C, और भाग D राज्य
1950 के मूल संविधान में भारतीय राज्यों को चार अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, जिन्हें भाग A, भाग B, भाग C और भाग D राज्यों के रूप में जाना जाता था। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 ने इस जटिल और असमान वर्गीकरण व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर केवल दो प्रकार की प्रशासनिक इकाइयों का गठन किया गया: राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिससे भारत का नया प्रशासनिक ढांचा तैयार हुआ।

NODIA

28. (B) 7वां संशोधन
7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 153 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इससे पूर्व प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग राज्यपाल की व्यवस्था थी। इस बदलाव ने प्रशासनिक सुविधा और वित्तीय दक्षता को बढ़ावा दिया, विशेष रूप से छोटे राज्यों और पड़ोसी क्षेत्रों के संदर्भ में।

29. (A) 7वां संशोधन, 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 52वां संशोधन
दिए गए संशोधनों का सही कालानुक्रमिक क्रम उनके अधिनियमन वर्ष के आधार पर निर्धारित होता है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1956 में पारित हुआ था। 24वां

बदलने के कारण उत्पन्न होने वाली राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करना था। दसवीं अनुसूची में दल-बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित विस्तृत नियम और प्रक्रियाएं दी गई हैं।

50. (B) दल-बदल विरोधी कानून
52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 को लोकप्रिय रूप से "दल-बदल विरोधी कानून" (एंटी-डिफेक्शन लॉ) के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल के दौरान पारित इस कानून का मुख्य उद्देश्य 'आया राम, गया राम' की राजनीति और राजनीतिक अवसरवादिता पर रोक लगाना था। इसने एक दल के चुनाव चिह्न पर जीतने के बाद दूसरे दल में शामिल होने वाले जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द करने का स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान किया।

51. (B) एक-तिहाई (1/3)
मूल 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के अंतर्गत अयोग्यता से एक अपवाद दिया गया था। इसके अनुसार यदि किसी राजनीतिक दल के विधान दल के कम से कम एक-तिहाई (1/3) सदस्य अलग होकर एक नया दल बनाते थे, तो इसे मान्यता प्राप्त 'विभाजन' माना जाता था और सदस्यों पर दल-बदल कानून लागू नहीं होता था। हालांकि, विभाजन के इस प्रावधान का दुरुपयोग होने के कारण 91वें संशोधन, 2003 द्वारा इस छूट को समाप्त कर दिया गया।

52. (A) लोकसभा अध्यक्ष
52वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, यदि दल-बदल के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो उस पर निर्णय लेने का अंतिम संवैधानिक प्राधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष (स्पीकर) होता है। इसी प्रकार राज्य विधानसभाओं के मामले में यह अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। प्रारंभ में यह निर्णय अंतिम था, किंतु बाद में न्यायपालिका ने इसे न्यायिक समीक्षा के अधीन घोषित कर दिया।

53. (B) केवल I, III और IV
दल-बदल विरोधी कानून संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों के सदस्यों पर लागू होता है। निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी दल में शामिल होने पर अयोग्य हो जाता है। किहोतो होलोहान मामले (1992) में उच्चतम न्यायालय ने तय किया कि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। हालांकि, मनोनीत सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने के छह महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल होने की छूट होती है; छह महीने के बाद शामिल होने पर वह अयोग्य होता है।

54. (A) मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना
61वां संविधान संशोधन अधिनियम एक अत्यंत महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सुधार से संबंधित है। इसके द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इस ऐतिहासिक संशोधन का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में सीधे भाग लेने का अवसर देना और भारतीय लोकतंत्र में युवा शक्ति की भागीदारी को बढ़ाना था, जिससे देश का लोकतांत्रिक ढांचा और अधिक समावेशी बना।

55. (C) अनुच्छेद 326
मतदान की न्यूनतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनावों से संबंधित है, जो यह निर्धारित करता है कि चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इस संशोधन के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी नागरिक मतदान के लिए पात्र हो गए।

56. (B) 1989
यद्यपि 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1988 में संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन यह 28 मार्च 1989 को औपचारिक रूप से लागू हुआ था। आवश्यक राज्यों द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त करने और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद यह 1989 में प्रभावी हुआ। इसके लागू होते ही देश के करोड़ों युवाओं को पहली बार चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ, जिसने भारतीय निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया।

57. (C) लोकसभा और राज्य विधानसभाएं
61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु में की गई कटौती (21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष) मुख्य रूप से लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के प्रत्यक्ष चुनावों पर लागू होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 326 में इन्हीं दो निकायों के लिए वयस्क मताधिकार की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, राज्य स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगरपालिकाओं) के चुनावों में भी 18 वर्ष की यही न्यूनतम मतदान आयु सीमा लागू होती है।

58. (D) राजीव गांधी
मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने वाला 61वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। राजीव गांधी का मानना था कि देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण और राजनीतिक निर्णयों में भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए। इस ऐतिहासिक कदम ने भारत के युवा वर्ग को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया और उन्हें देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बनाया।

59. (A) 2, 1, 3, 4
73वें संविधान संशोधन के कार्यान्वयन की प्रक्रिया का सही क्रम इस प्रकार है: सर्वप्रथम विधेयक का लोकसभा (और राज्यसभा) द्वारा पारित होना (2), परिसंघीय ढांचा प्रभावित होने के कारण आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों द्वारा इसका अनुसमर्थन (1), तत्पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होना (3), और अंत में राज्यों द्वारा इसका पालन करने के लिए अपने पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन कर उन्हें लागू करना, जैसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम (4) है।

Downloaded from www.pdf.tube

मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। यह प्रावधान नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ-साथ राष्ट्र के प्रति उनके उत्तरदायित्वों का स्मरण कराता है।

40. (B) इसने मंत्रिमंडल की सलाह को पुनर्विचार के प्रावधान के बिना राष्ट्रपति पर स्पष्ट रूप से बाध्यकारी बना दिया
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने अनुच्छेद 74(1) में संशोधन करके यह स्पष्ट रूप से अनिवार्य कर दिया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। इस संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति के पास मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का भी कोई संवैधानिक अधिकार नहीं बचा था। इसने केंद्रीय मंत्रिमंडल की कार्यपालक सर्वोच्चता को राष्ट्रपति पर पूरी तरह से स्थापित कर दिया।

41. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39A जोड़ा गया जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी से संबंधित है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण के संरक्षण तथा वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा का निर्देश देता है। इसके अतिरिक्त, संविधान में भाग XIVA अंतःस्थापित किया गया, जो प्रशासनिक और अन्य विषयों के लिए अधिकरणों (ट्रिब्यूनल) की स्थापना से संबंधित प्रावधान करता है।

42. (A) 6 वर्ष
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। यह परिवर्तन आपातकाल की अवधि के दौरान लागू किया गया था। हालांकि, बाद में वर्ष 1978 में पारित 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस बदलाव को निरस्त कर दिया गया और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष की मूल अवधि पर ला दिया गया।

43. (A) 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किए गए विवादित प्रावधानों को निरस्त करने के लिए
44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 जनता पार्टी सरकार द्वारा मुख्य रूप से 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में किए गए विवादित और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत प्रावधानों को निरस्त करने के लिए लाया गया था। इसका उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता को बहाल करना, न्यायपालिका की शक्तियों को पुनः स्थापित करना और भविष्य में राष्ट्रीय आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए मजबूत संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करना था।

44. (B) सशस्त्र विद्रोह
44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन किया गया। इसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के आधारों में से अस्पष्ट शब्द "आंतरिक अशांति" को हटाकर उसके स्थान पर "सशस्त्र विद्रोह" शब्द प्रतिस्थापित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर आपातकाल के संभावित राजनीतिक दुरुपयोग को रोकना था, ताकि केवल वास्तविक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सके।

45. (B) इसे भाग III से स्थानांतरित करके भाग XII में अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया
44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इसके लिए अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया। इसके स्थान पर, संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग XII में एक नया अनुच्छेद 300A जोड़कर केवल एक विधिक (कानूनी) अधिकार बना दिया गया। इसके बाद कोई भी व्यक्ति संपत्ति छीनने पर सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता।

NODIA

46. (A) संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियों की सत्य रिपोर्टों का समाचार पत्रों में प्रकाशन
44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 361A जोड़ा गया। इस प्रावधान ने समाचार पत्रों और मीडिया को संसद या राज्य विधानमंडलों के किसी भी सदन की कार्यवाहियों की सही और निष्पक्ष रिपोर्टों के प्रकाशन के लिए पूर्ण संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया। यह संरक्षण तब तक प्राप्त होता है जब तक कि प्रकाशन द्वेषपूर्ण न हो या सदन ने अपनी कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक न लगाई हो।

47. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
1975 में प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत सलाह पर आपातकाल लगाए जाने के अनुभव के बाद, 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने अनुच्छेद 352 में संशोधन किया। इसके द्वारा यह अनिवार्य बनाया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल तब कर सकते हैं जब केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) उन्हें लिखित रूप में ऐसी सिफारिश करे। इस संवैधानिक सुरक्षा उपाय का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री द्वारा एकतरफा फैसला लेकर आपातकाल लगाने की संभावना को समाप्त करना था।

48. (D) मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकें
44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ने अनुच्छेद 74(1) में एक महत्वपूर्ण परंतु (प्रोवाइज़ो) जोड़ा। इसके अनुसार, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वे मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई किसी भी सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। हालांकि, यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद वही सलाह राष्ट्रपति को पुनः भेजती है, तो राष्ट्रपति उस सलाह को स्वीकार करने और उसके अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं।

49. (C) दसवीं अनुसूची
52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 भारतीय संविधान में दसवीं अनुसूची को अंतःस्थापित करने के लिए जाना जाता है। इस अनुसूची को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल की बुराई को रोकना और विधायकों की निष्ठा

संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1971 में लागू किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 में अधिनियमित किया गया था। इसके पश्चात, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1985 में लाया गया था। इस प्रकार विकल्प A सही कालानुक्रमिक क्रम को स्पष्ट रुप से दर्शाता है।

30. (A) 7वां संशोधन अधिनियम, 1956
7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा अनुच्छेद 231 में संशोधन करके संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह कानून बनाकर दो या अधिक राज्यों, या दो से अधिक राज्यों और किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। इस प्रावधान के कारण पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा गुवाहाटी उच्च न्यायालय जैसे साझा उच्च न्यायालयों का गठन संभव हो सका, जिससे न्यायिक न्याय सुलभ हुआ।

31. (C) आई.सी. गोलकनाथ मामला
24वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 उच्चतम न्यायालय द्वारा आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला (1967) में दिए गए निर्णय की प्रतिक्रिया में पारित किया गया था। गोलकनाथ मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों को छीन या कम नहीं कर सकती। संसद ने अपनी संवैधानिक शक्ति को पुनः स्थापित करने और मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति की पुष्टि के लिए यह संशोधन किया।

32. (D) इसने मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की संसद की शक्ति की पुष्टि की
24वें संशोधन अधिनियम, 1971 का मुख्य उद्देश्य गोलकनाथ मामले के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करना था। इसने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 दोनों में संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित करने, बदलने या निरस्त करने की पूर्ण शक्ति है। इसके साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 13(2) के तहत 'विधि' शब्द अनुच्छेद 368 के संशोधनों पर लागू नहीं होगा।

33. (B) अनुच्छेद 39(b) और (c)
25वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31C जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39(b) और 39(c) में निहित समाजवादी सिद्धांतों—जैसे भौतिक संसाधनों का न्यायसंगत वितरण और धन का संकेंद्रण रोकना—को लागू करने वाले कानूनों को संरक्षण देना था। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि ऐसे कानूनों को अनुच्छेद 14, 19 या 31 के उल्लंघन के आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता।

34. (B) इसने संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में 'मुआवजे' शब्द के स्थान पर 'राशि' शब्द प्रतिस्थापित किया
25वें संशोधन अधिनियम, 1971 ने अनुच्छेद 31(2) में संशोधन करके अनिवार्य अधिग्रहण के बदले दिए जाने वाले 'मुआवजे' (कंपनसेशन) शब्द को 'राशि' (अमाउंट) शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया। इसका उद्देश्य अदालतों को यह तय करने से रोकना था कि राज्य द्वारा दी जाने वाली राशि बाजार मूल्य के बराबर पर्याप्त है या नहीं। इसने सरकार को सार्वजनिक कल्याण और भूमि सुधार के लिए कम लागत पर निजी संपत्ति के अधिग्रहण का अधिकार प्रदान किया।

35. (A) केवल I और II
24वें संशोधन अधिनियम, 1971 ने अनुच्छेद 13 और 368 दोनों में संशोधन किया और यह स्पष्ट किया कि संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। इसने राष्ट्रपति के लिए संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देना बाध्यकारी बना दिया। केशवानंद भारती मामले (1973) में उच्चतम न्यायालय ने इस संशोधन की वैधता को स्वीकार किया था और इसे पूरी तरह असंवैधानिक घोषित नहीं किया था, बल्कि केवल मूल ढांचे के सिद्धांत की सीमा तय की थी।

36. (B) 24वां संशोधन अधिनियम
24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 में खंड (4) और अनुच्छेद 368 में खंड (3) जोड़ा गया। इन प्रावधानों के माध्यम से यह स्पष्ट रुप से निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात (जो मूल अधिकारों से असंगत विधियों को शून्य घोषित करती है) अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए किसी भी संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। इससे संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का निर्बाध संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ।

37. (B) 42वां संशोधन अधिनियम
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 को भारतीय संविधान के इतिहास में व्यापक और बड़े परिवर्तनों के कारण "लघु-संविधान" (मिनी-कॉन्स्टिट्यूशन) कहा जाता है। इसने प्रस्तावना, मूल अधिकारों, नीति निदेशक तत्वों, संसद, न्यायपालिका और राज्य विधानमंडलों से जुड़े अनेक अनुच्छेदों में दूरगामी बदलाव किए। इस संशोधन ने संविधान के ढांचे को व्यापक रूप से प्रभावित किया और इसमें मूल कर्तव्यों सहित कई नए भागों को भी शामिल किया।

38. (A) समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए थे, जो हैं: 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता'। प्रस्तावना में 'प्रभुत्वसंपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य' के स्थान पर 'प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य' प्रतिस्थापित किया गया और 'राष्ट्र की एकता' के स्थान पर 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' शब्द शामिल किया गया। प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार यह संशोधन हुआ है।

39. (B) भाग IV-A
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। इसके लिए संविधान में एक नया भाग IV-A जोड़ा गया, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल था। इस संशोधन द्वारा शुरुआत में नागरिकों के लिए 10

Click Here to Buy book on Flipkart

60. (A) भाग IX
73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने भारतीय संविधान में एक नया भाग IX जोड़ा, जिसका शीर्षक "पंचायतें" रखा गया। इस संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसके तहत अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243O तक के प्रावधान अंतःस्थापित किए गए, जिनमें त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, सीटों के आरक्षण, पंचायतों के कार्यकाल, शक्तियों और वित्त आयोग के गठन से संबंधित विस्तृत संवैधानिक नियम शामिल किए गए।

61. (B) 20 लाख
73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर) का प्रावधान किया गया है। हालांकि, अनुच्छेद 243B(2) में यह छूट दी गई है कि जिस राज्य की कुल जनसंख्या 20 लाख से अधिक न हो, वह राज्य मध्यवर्ती (ब्लॉक या प्रखंड) स्तर पर पंचायतों का गठन न करने का विकल्प चुन सकता है। ऐसे राज्यों में केवल ग्राम और जिला स्तर पर ही पंचायतें गठित की जाती हैं।

62. (B) कुल सीटों का एक-तिहाई
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243D(3) के अनुसार, पंचायतों में सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या में से कम से कम एक-तिहाई (1/3) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होना अनिवार्य है। इस आरक्षण में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। इसके अलावा, अध्यक्ष पदों के लिए भी एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं।

63. (C) राज्य निर्वाचन आयोग
73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 243K के तहत पंचायतों के सभी चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) तैयार करने और चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक स्वतंत्र 'राज्य निर्वाचन आयोग' में निहित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह संस्था पंचायतों के चुनाव समय पर और स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए जिम्मेदार है।

64. (C) 29
73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में कुल 29 कार्यात्मक विषय सूचीबद्ध किए गए हैं जो पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इनमें कृषि, ग्रामीण विकास, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, सड़कें, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण स्थानीय विषय शामिल हैं। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर इन 29 विषयों से संबंधित कार्य और शक्तियां पंचायतों को सौंप सकते हैं।

65. (A) केवल I और II
74वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन और 3 लाख या उससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में वार्ड समितियों की स्थापना का प्रावधान किया। हालांकि, इसने नगरपालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक विषयों को शामिल करते हुए बारहवीं अनुसूची जोड़ी थी, न कि 29 विषयों को। 29 कार्यात्मक विषय 73वें संशोधन द्वारा ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के लिए जोड़े गए थे, इसलिए केवल पहला और दूसरा कथन सही है।

66. (B) शहरी स्थानीय शासन
74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 मुख्य रूप से भारत में शहरी स्थानीय शासन (नागरिक स्वशासन) को मजबूत करने और उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। इस संशोधन के माध्यम से शहरों और कस्बों में नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के गठन, उनके चुनावों, शक्तियों और वित्तीय संसाधनों को संवैधानिक रूप से सुनिश्चित किया गया, ताकि शहरी क्षेत्रों में कुशल और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की जा सके।

67. (C) अनुच्छेद 243ZD
74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 243ZD अंतःस्थापित किया गया था। यह अनुच्छेद प्रत्येक जिले के स्तर पर एक 'जिला योजना समिति' (डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी) के गठन का प्रावधान करता है। इस समिति का मुख्य कार्य जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना और संपूर्ण जिले के लिए एक एकीकृत विकास योजना का प्रारूप तैयार करना है, जिससे समन्वित विकास हो सके।

68. (A) 18
74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भारतीय संविधान में बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में नगरपालिकाओं के अधिकार क्षेत्र और कार्यात्मक दायरे के अंतर्गत आने वाले कुल 18 विषय शामिल किए गए हैं। इन विषयों में नगर नियोजन, भूमि उपयोग का विनियमन, सड़कें और पुल, जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएं, और शहरी गरीबी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण नागरिक और बुनियादी ढांचे से जुड़े मामले सूचीबद्ध हैं।

69. (B) इसकी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष
74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष का होता है, जब तक कि उसे विधि की स्थापित प्रक्रिया द्वारा इससे पहले भंग न कर दिया जाए। यदि किसी नगरपालिका को 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर दिया जाता है, तो विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य होता है।

70. (A) अनुच्छेद 21A
86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इस अनुच्छेद

Downloaded from www.pdf.tube

91. (A) संसद मूल ढांचे को बदले बिना संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है
केशवानंद भारती मामले (1973) में उच्चतम न्यायालय का मुख्य निर्णय यह था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन करने की शक्ति व्यापक है, जिसके अंतर्गत वह मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। हालांकि, न्यायालय ने यह ऐतिहासिक सीमा तय की कि संसद अपनी संशोधन शक्ति का प्रयोग करके संविधान के 'मूल ढांचे' (बेसिक स्ट्रक्चर) की आवश्यक विशेषताओं को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती है।

92. (B) संसद के पास सीमित संशोधन शक्तियां हैं और वह संविधान की मूल पहचान को नष्ट नहीं कर सकती है
मूल ढांचा सिद्धांत का मूल तात्पर्य यह है कि संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति एक निर्मित और सीमित शक्ति है, न कि निरपेक्ष या असीमित शक्ति। संसद संशोधन के नाम पर भारतीय संविधान की आधारभूत पहचान, दर्शन और लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट या समाप्त नहीं कर सकती है। यदि संसद द्वारा पारित कोई संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर सकती है।

93. (B) मिनर्वा मिल्स मामला (1980)
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला (1980) में उच्चतम न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में जोड़े गए खंड (4) और (5) को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया था। इन खंडों के माध्यम से संसद ने अपनी संशोधन शक्ति को असीमित बनाने और संविधान संशोधनों को किसी भी अदालत में चुनौती दिए जाने से रोकने का प्रयास किया था। न्यायालय ने कहा कि सीमित संशोधन शक्ति स्वयं मूल ढांचा है।

94. (A) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) की स्थापना
वर्ष 2014 में संसद द्वारा पारित 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (NJAC) की स्थापना की गई थी। वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन मामले में इस 99वें संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया। न्यायालय ने माना कि यह संशोधन 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' को प्रभावित करता है, जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।

95. (B) केवल II
आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला (1967) में उच्चतम न्यायालय की 11 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने पूर्व निर्णयों (शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह) को उलटते हुए यह फैसला सुनाया था कि संसद संविधान के भाग III में दिए गए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। न्यायालय ने कहा था कि मूल अधिकार पारलौकिक और अपरिवर्तनीय हैं तथा अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत साधारण 'विधि' ही माना जाएगा।

96. (D) संविधान की सर्वोच्चता
भारतीय संविधान की सर्वोच्चता उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित 'मूल ढांचे' का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि देश में संविधान ही सर्वोच्च कानून है और सरकार का कोई भी अंग—विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका—संविधान से ऊपर नहीं है। संसद असीमित संशोधन शक्ति या नौवीं अनुसूची का सहारा लेकर संविधान की इस सर्वोच्चता को समाप्त नहीं कर सकती। अन्य विकल्प मूल ढांचे का हिस्सा नहीं हैं।

97. (C) पंथनिरपेक्षता
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामला (1994) में उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 'पंथनिरपेक्षता' (धर्मनिरपेक्षता) को भारतीय संविधान के 'मूल ढांचे' की एक आवश्यक और अभिन्न विशेषता घोषित किया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यदि कोई राज्य सरकार पंथनिरपेक्षता के विपरीत कार्य करती है, तो उस पर अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

NODIA

98. (B) संपत्ति का अधिकार
उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान के मूल ढांचे का अंग माना है। हालांकि, 'संपत्ति के अधिकार' को मूल ढांचे का हिस्सा नहीं माना गया है। वास्तव में, 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी (भाग III) से पूरी तरह हटाकर केवल एक विधिक (कानूनी) अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में स्थापित किया गया था।

99. (D) मिनर्वा मिल्स मामला
मिनर्वा मिल्स मामला (1980) में उच्चतम न्यायालय ने यह ऐतिहासिक सिद्धांत स्थापित किया कि भाग III में दिए गए मूल अधिकारों और भाग IV में दिए गए राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन और सद्भाव बनाए रखना भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता (मूल ढांचा) है। न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि संविधान इन दोनों के बीच संतुलन की नींव पर खड़ा है और किसी एक को दूसरे पर पूर्ण प्राथमिकता देकर इस संतुलन को नष्ट नहीं किया जा सकता।

100. (A) उपाधियों का अंत
उच्चतम न्यायालय द्वारा पहचाने गए मूल ढांचे के तत्वों में संविधान का परिसंघीय व संसदीय स्वरूप, शक्तियों का पृथक्करण, और भारत की संप्रभु, लोकतांत्रिक व गणराज्य प्रकृति शामिल हैं। हालांकि, 'उपाधियों का अंत' (अनुच्छेद 18) एक विशिष्ट मौलिक अधिकार तो है, लेकिन न्यायपालिका द्वारा इसे अलग से संविधान के 'मूल ढांचे' का तत्व घोषित नहीं किया गया है। इसलिए दिए गए विकल्पों में से यह असंगत विकल्प है।

एकीकृत राष्ट्रीय बाजार और 'एक राष्ट्र, एक कर' की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से नया कर ढांचा स्थापित किया।

81. (A) अनुच्छेद 246A
101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 246A अंतःस्थापित किया गया। यह प्रावधान संसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में कानून बनाने की समवर्ती (एक साथ) शक्ति प्रदान करता है। इससे पूर्व, अप्रत्यक्ष कर लगाने की शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच विशेष रूप से बंटी हुई थीं। इस नए अनुच्छेद ने कराधान के क्षेत्र में सहकारी संघवाद का एक नया ढांचा तैयार किया।

82. (C) अनुच्छेद 279A
101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 279A जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संशोधन लागू होने के 60 दिनों के भीतर एक संयुक्त निकाय के रूप में 'वस्तु एवं सेवा कर परिषद' (जीएसटी परिषद) का गठन करने का अधिकार दिया गया। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। यह परिषद जीएसटी से जुड़े सभी प्रमुख फैसलों की सिफारिश करती है।

83. (A) केवल I, II और IV
101वें संशोधन ने जीएसटी लागू किया, परिसंघीय कराधान शक्तियों को बदलने के कारण आधे राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त किया, और केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद का गठन किया। हालांकि, इस संशोधन ने पंचायतों या स्थानीय निकायों की कराधान शक्तियों को समाप्त नहीं किया। स्थानीय स्वायत्त निकायों के वित्तीय अधिकार अपनी जगह बने रहे, इसलिए पहला, दूसरा और चौथा कथन पूरी तरह से सही है।

84. (A) इसने सातवीं अनुसूची की विधायी सूचियों को संशोधित किया जिससे राज्यों की कराधान शक्तियां प्रभावित हुईं
101वें संविधान संशोधन अधिनियम को पारित करने के लिए कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि इसने संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ और राज्य सूचियों को संशोधित किया। इसने राज्यों की वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने की विशेष शक्तियों को प्रभावित किया और केंद्र व राज्यों की कराधान व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया। परिसंघीय ढांचे और राज्यों के राजस्व अधिकारों से जुड़ा होने के कारण राज्यों की सहमति अनिवार्य थी।

85. (C) नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)
103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 नागरिकों के अनारक्षित श्रेणी के 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' (EWS) के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। इस संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों और निजी (सहायता प्राप्त व गैर-सहायता प्राप्त) शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के नागरिकों को अधिकतम 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य उन निर्धन व्यक्तियों को आर्थिक राहत देना है जो एससी, एसटी या ओबीसी कोटे में शामिल नहीं हैं।

86. (B) अनुच्छेद 15 और 16
ईडब्ल्यूएस (EWS) कोटा लागू करने के लिए 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा संविधान के भाग III में निहित मूल अधिकारों के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किए गए। इसके तहत अनुच्छेद 15 में खंड (6) और अनुच्छेद 16 में खंड (6) अंतःस्थापित किए गए। अनुच्छेद 15(6) शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु तथा अनुच्छेद 16(6) सरकारी नौकरियों व नियुक्तियों में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10% तक आरक्षण देने की राज्य को अनुमति प्रदान करता है।

87. (D) एससी, एसटी और ओबीसी कोटे के अतिरिक्त है, जिससे कुल आरक्षण 50% से अधिक हो सकता है
103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के लिए पहले से चले आ रहे आरक्षित कोटे से पूरी तरह अलग और अतिरिक्त है। यह आरक्षण केवल उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो एससी, एसटी या ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं उठा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, देश में कुल आरक्षण सीमा उच्चतम न्यायालय द्वारा तय 50% की सीमा से अधिक हो जाती है।

88. (B) यह अनुच्छेद 30(1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होता है।
103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत स्थापित और संचालित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होता है। संविधान का अनुच्छेद 15(6) स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यक संस्थानों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के दायरे से बाहर रखता है, ताकि अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षणिक संस्थान चलाने के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। अन्य सभी निजी व सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में यह व्यवस्था लागू होती है।

89. (A) जीएसटी, एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, एससी/एसटी कोटे का विस्तार
दिए गए संवैधानिक संशोधनों का सही कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है: 101वां संशोधन (2016) जीएसटी से संबंधित है; 102वां संशोधन (2018) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है; 103वां संशोधन (2019) ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने से संबंधित है; तथा 104वां संशोधन (2019) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी/एसटी सीटों के आरक्षण का विस्तार करने से संबंधित है।

90. (C) केशवानंद भारती मामला (1973)
भारतीय संविधान का प्रसिद्ध 'मूल ढांचा' (बेसिक स्ट्रक्चर) सिद्धांत उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले (1973) के ऐतिहासिक निर्णय में प्रतिपादित किया गया था। 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी पीठ ने 7-6 के बहुमत से निर्णय दिया था कि हालांकि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, लेकिन वह संविधान की मौलिक पहचान या उसके मूल ढांचे को नष्ट या समाप्त नहीं कर सकती।

Click Here to Buy book on Amazon

को शामिल करके शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों के भाग III के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। इसके तहत राज्य के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वह कानून बनाकर 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करे।

71. (A) P-3, Q-1, R-2, S-4
86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जो 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का मूल अधिकार देता है। अनुच्छेद 45 को संशोधित कर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था देखरेख का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 51A(k) के तहत माता-पिता का शिक्षा का अवसर देने का मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इन प्रावधानों को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए ही संसद ने 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया।

72. (C) अनुच्छेद 45
वर्ष 2002 में पारित 86वें संशोधन अधिनियम से पहले, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में निहित था। चूंकि यह केवल एक निदेशक तत्व था, इसलिए यह न्यायालय द्वारा न्यायोचित या बाध्यकारी नहीं था। 86वें संशोधन ने इसे अनुच्छेद 21A के तहत एक कानूनी रूप से प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार बना दिया।

73. (C) छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चे के माता-पिता या संरक्षक द्वारा शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य
86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अनुच्छेद 51A में संशोधन करके 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसे खंड (k) के रूप में शामिल किया गया। इसके अनुसार, यह भारत के प्रत्येक नागरिक का, जो माता-पिता या संरक्षक है, कर्तव्य बनाया गया कि वह छह से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चे या प्रतिपाल्य (वार्ड) को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करे, ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

74. (B) 6 से 14 वर्ष
86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 21A के तहत केवल 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की संवैधानिक गारंटी दी गई है। इस आयु सीमा के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार बन गया है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 के तहत राज्य का नीति निदेशक तत्व है।

75. (B) लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%
91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1A) को अंतःस्थापित किया गया। इसके अनुसार, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। इस प्रावधान को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य जंबो मंत्रिमंडलों के गठन पर रोक लगाना, सरकारी खर्च में कटौती करना और राजनीतिक सौदेबाजी के माध्यम से मंत्रियों के पद बांटने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना था।

76. (C) 30
91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के तहत अनुच्छेद 164(1A) द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं। अतः 200 का 15% निकालने पर यह संख्या 30 आती है। इस प्रकार राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं।

77. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
52वें संशोधन द्वारा पारित दल-बदल कानून की दसवीं अनुसूची में एक-तिहाई सदस्यों द्वारा 'विभाजन' को अयोग्यता से छूट दी गई थी। इस प्रावधान का बार-बार दुरुपयोग राजनीतिक दलों को तोड़ने और असंतुष्टों को मंत्री पद का लालच देकर बड़े मंत्रिमंडल बनाने में किया जाता था। इस खामी को दूर करने के लिए 91वें संशोधन, 2003 ने विभाजन वाली छूट को समाप्त कर दिया और मंत्रिमंडल का आकार भी सीमाबद्ध कर दिया।

78. (B) 12
91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा राज्यों के लिए मंत्रियों की अधिकतम संख्या (विधानसभा का 15%) तय करने के साथ-साथ एक न्यूनतम सीमा भी निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 164(1A) के अनुसार, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी। यह प्रावधान छोटे राज्यों में सरकार के कुशल संचालन के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रशासनिक मंत्रियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु शामिल किया गया था।

79. (C) मंत्री नियुक्त होने से या कोई लाभ का राजनीतिक पद धारण करने से
91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के अनुसार, यदि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत अयोग्य ठहराया जाता है, तो वह अयोग्यता की अवधि के दौरान मंत्री नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त, वह ऐसे किसी भी लाभ के राजनीतिक पद (पारिश्रमिक वाले निकाय) को धारण करने के लिए भी अयोग्य होगा, जो सरकार के अधीन आता है।

80. (D) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)
101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 भारत में 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) लागू करने से संबंधित है। यह देश में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार लाने वाला एक ऐतिहासिक संशोधन था। इसने केंद्र और राज्यों के विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट और मनोरंजन कर को समाप्त करके एक

NODIA

101. (A) P-1, Q-2, R-3, S-4
शंकरी प्रसाद मामले (1951) में न्यायालय ने माना कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ मामले (1967) में निर्णय दिया गया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती मामले (1973) ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। आई.आर. कोएल्हो मामले (2007) में फैसला सुनाया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल कानून मूल ढांचे के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।

102. (B) 24 अप्रैल, 1973
आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य मामला (2007) में उच्चतम न्यायालय ने यह ऐतिहासिक कट-ऑफ तिथि 24 अप्रैल, 1973 निर्धारित की थी। यह वही तारीख है जिस दिन केशवानंद भारती मामले का निर्णय आया था और मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की इस आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि वह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है या नहीं।

103. (D) अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'विधि' है और यह मूल अधिकारों को छीन या कम नहीं कर सकता है
गोलकनाथ मामले (1967) में उच्चतम न्यायालय ने मुख्य रूप से यह तर्क दिया था कि अनुच्छेद 368 केवल संशोधन की प्रक्रिया प्रदान करता है, न कि संशोधन की शक्ति। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत 'विधि' (कानून) के दायरे में आता है। इसलिए, कोई भी संविधान संशोधन जो मूल अधिकारों को छीनता या कम करता है, अनुच्छेद 13 के तहत शून्य और असंवैधानिक होगा।

104. (A) प्रथम संशोधन
शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला (1951) में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। इस संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31A और 31B तथा नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसने संपत्ति के अधिकार को सीमित किया था। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में संसद के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति में मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है।

105. (C) संशोधन वैध होगा।
केशवानंद भारती मामले (1973) के बाद स्थापित वर्तमान कानूनी स्थिति यह है कि संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन करने का अधिकार रखती है, जब तक कि वह संशोधन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट या क्षति न पहुंचाए। यदि संसद द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन किसी सामान्य मौलिक अधिकार का उल्लंघन या संशोधन करता है, लेकिन संविधान की आधारभूत विशेषताओं या उसके मूल ढांचे पर कोई आघात नहीं करता है, तो ऐसा संशोधन न्यायालय द्वारा पूर्णतः वैध और संवैधानिक माना जाएगा।

106. (D) नम्यता और अनम्यता दोनों के तत्वों का एक अनूठा संश्लेषण
तुलनात्मक संवैधानिक अध्ययन में भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया को नम्यता (लचीलेपन) और अनम्यता (कठोरता) का एक अनूठा मिश्रण माना जाता है। यह ब्रिटेन के संविधान की तरह पूरी तरह से लचीला नहीं है, जहां साधारण कानून की तरह संशोधन हो सकता है, और न ही अमेरिका के संविधान की तरह अत्यधिक कठोर है, जहां प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से, कुछ विशेष बहुमत से, और कुछ विशेष बहुमत के साथ राज्यों के अनुसमर्थन से बदले जा सकते हैं।

107. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
भारत की संविधान संशोधन प्रक्रिया अमेरिकी प्रक्रिया की तुलना में अधिक नम्य है। अमेरिका में किसी भी संशोधन के लिए तीन-चौथाई (75%) राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन अनिवार्य होता है, जो अत्यंत कठोर प्रक्रिया है। इसके विपरीत, भारत में संविधान का एक बड़ा हिस्सा केवल संसद द्वारा बदला जा सकता है, और परिसंघीय विषयों के लिए केवल आधे (50%) राज्यों का अनुसमर्थन ही पर्याप्त होता है। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण सही व्याख्या प्रस्तुत करता है।

108. (B) जनमत संग्रह के माध्यम से जनता द्वारा संशोधनों की प्रत्यक्ष स्वीकृति
स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में संवैधानिक संशोधनों के लिए 'जनमत संग्रह' (रेफरेंडम) की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई जाती है, जिसमें जनता सीधे मतदान करके संशोधनों को स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करती है। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया में जनमत संग्रह या प्रत्यक्ष जनभागीदारी का कोई प्रावधान नहीं है। भारत में संविधान संशोधन की पूरी शक्ति केवल निर्वाचित जनप्रतिनिधियों (संसद और राज्य विधानमंडलों) के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की जाती है।

109. (B) के.सी. व्हीयर
प्रसिद्ध ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ और विचारक के.सी. व्हीयर (K.C. Wheare) ने भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए कहा था कि यह "नम्यता और अनम्यता के बीच एक उचित संतुलन" स्थापित करती है। उनके अनुसार, भारतीय संविधान निर्माताओं ने अति-लचीलेपन की बुराइयों और अति-कठोरता की जटिलताओं से बचते हुए एक ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण प्रक्रिया अपनाई जो स्थिरता बनाए रखने के साथ-साथ आवश्यक परिवर्तन की अनुमति भी देती है।

110. (A) अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्य विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन
संविधान का अनुच्छेद 169 भारतीय संविधान की 'नम्यता' (लचीलेपन) को प्रदर्शित करता है। इसके तहत राज्य में विधान परिषद के सृजन या समाप्ति के लिए संसद साधारण बहुमत से कानून पारित कर सकती है। इस प्रक्रिया द्वारा संवैधानिक

Downloaded from www.pdf.tube

व्यवस्था में परिवर्तन होता है, फिर भी इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता। इसके विपरीत, राष्ट्रपति निर्वाचन या शक्तियों के बंटवारे में संशोधन के लिए विशेष बहुमत और राज्य अनुसमर्थन की अत्यंत कठोर प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।

111. (C) इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए
संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में प्रक्रियात्मक नियम यह है कि इसे संसद के दोनों सदनों—लोकसभा और राज्यसभा—द्वारा पृथक-पृथक रूप से विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। प्रत्येक सदन में विधेयक का कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक है। एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है।

112. (D) संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, अतः विधेयक समाप्त हो जाता है
यदि किसी संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के बीच असहमति या गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। साधारण विधेयकों की तरह यहाँ गतिरोध सुलझाने का कोई विकल्प नहीं होता। परिणामस्वरुप, यदि एक सदन संशोधन विधेयक को खारिज कर देता है या पारित नहीं करता, तो वह संविधान संशोधन विधेयक स्वतः ही पूरी तरह समाप्त हो जाता है।

113. (A) केवल I, II और III
साधारण विधेयक साधारण बहुमत से और संशोधन विधेयक विशेष बहुमत से पारित होता है। साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जबकि संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, परंतु 24वें संशोधन के बाद संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना अनिवार्य है। हालांकि, साधारण विधेयकों के लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए केवल पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है।

114. (B) राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा पारित संशोधनों पर जेबी वीटो का प्रयोग करने से रोकने के लिए
24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन करके राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देना अनिवार्य बना दिया गया था। इस प्रावधान को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित और राज्यों द्वारा अनुसमर्थित (यदि आवश्यक हो) संवैधानिक संशोधनों पर अपने जेबी वीटो (पॉकेट वीटो) या निलंबनकारी वीटो की शक्तियों का प्रयोग करके गतिरोध न उत्पन्न कर सकें।

115. (D) मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य किसी के भी द्वारा
संविधान संशोधन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के संबंध में कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। इसे किसी केंद्रीय मंत्री (सरकारी सदस्य) द्वारा या संसद के किसी भी गैर-सरकारी सदस्य (प्राइवेट मेंबर) द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा, इसे संसद के किसी भी सदन, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी पहले पेश किया जा सकता है। विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या सिफारिश की आवश्यकता भी नहीं होती है।

116. (A) संविधान में संशोधन के लिए कोई विधेयक या प्रस्ताव प्रस्तुत करने की शक्ति नहीं रखते हैं
भारत में संविधान संशोधन प्रक्रिया की एक मुख्य विशेषता यह है कि राज्यों के विधानमंडलों के पास संविधान में संशोधन करने के लिए कोई भी विधेयक या प्रस्ताव संसद के समक्ष प्रस्तुत करने या आरंभ करने की कोई संवैधानिक शक्ति नहीं होती है। संविधान संशोधन विधेयक को केवल और केवल भारत की संसद (लोकसभा या राज्यसभा) में ही आरंभ किया जा सकता है। राज्यों की भूमिका केवल संसद द्वारा भेजे गए चुनिंदा परिसंघीय संशोधनों पर अनुसमर्थन देने तक सीमित होती है।

117. (C) राज्य विधानमंडल के भीतर विधान परिषद का सृजन करना या उसका उत्सादन करना
यद्यपि राज्य विधानमंडल सीधे संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन (गठन) या उत्सादन (समाप्ति) के लिए राज्य विधानसभा का संकल्प एक अनिवार्य पूर्व-शर्त है। जब राज्य विधानसभा विशेष बहुमत से इसका संकल्प पारित करके संसद को भेजती है, तभी संसद इस विषय पर साधारण बहुमत से कानून बनाकर संविधान की दूसरी अनुसूची में तदनुसार बदलाव कर सकती है।

118. (A) मूल अधिकार
संविधान के वे प्रावधान जो परिसंघीय ढांचे और केंद्र-राज्य संबंधों को सीधे प्रभावित नहीं करते हैं, उनमें संशोधन के लिए राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। मूल अधिकार (भाग III) और राज्य के नीति निदेशक तत्व (भाग IV) ऐसे ही विषय हैं जिन्हें केवल संसद अपने दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। इसके विपरीत, न्यायपालिका, शक्तियों के बंटवारे और संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में संशोधन हेतु राज्यों का अनुमोदन आवश्यक होता है।

119. (A) 1, 3, 4, 2
सातवीं अनुसूची में संशोधन की प्रक्रियात्मक श्रृंखला का सही क्रम इस प्रकार है: सर्वप्रथम, संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है (1)। इसके पश्चात, विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होता है (3)। चूंकि यह परिसंघीय मामला है, इसलिए इसके बाद कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से इसका अनुसमर्थन किया जाता है (4)।

NODIA

अंत में, विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है (2)।

120. (B) साधारण बहुमत
जब कोई संविधान संशोधन विधेयक परिसंघीय प्रावधानों को प्रभावित करने के कारण अनुसमर्थन के लिए राज्यों के पास भेजा जाता है, तो राज्य विधानमंडलों को इसे पारित करने के लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। राज्य की विधानसभा (और यदि विधान परिषद हो तो वह भी) में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प ही पर्याप्त माना जाता है। राज्यों को इसके लिए अपनी विधानसभाओं में विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है।

121. (C) विस्तृत प्रशासनिक प्रावधानों का समावेश जिनमें बार-बार अद्यतन की आवश्यकता होती है
भारतीय संविधान में अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। इसका प्राथमिक संरचनात्मक कारण यह है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है, जिसमें न केवल मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। समय के साथ बदलती प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के अनुरूप इन प्रशासनिक नियमों को अद्यतन (अपडेट) करने के लिए संसद को बार-बार संवैधानिक संशोधन का सहारा लेना पड़ता है।

122. (D) जनमत संग्रह आयोजित करने के लिए किसी भी संवैधानिक प्रावधान का न होना
भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचकों द्वारा इस आधार पर मुख्य आलोचना की जाती है कि इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों, जैसे 'जनमत संग्रह' (रेफरेंडम) या 'पहल' (इनिशिएटिव) का कोई स्थान नहीं है। अत्यंत महत्वपूर्ण या दूरगामी प्रभाव वाले संवैधानिक परिवर्तनों के समय भी देश की आम जनता से सीधे उनकी राय या स्वीकृति लेने का कोई संवैधानिक प्रावधान भारतीय व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है, जिससे सारी शक्तियां केवल जनप्रतिनिधियों तक सीमित रहती हैं।

123. (D) उपर्युक्त सभी
संशोधन प्रक्रिया में राज्यों की सीमित भूमिका की आलोचना तीन मुख्य कारणों से होती है: प्रथम, राज्य विधानमंडल कोई भी संवैधानिक संशोधन विधेयक स्वयं प्रस्तुत नहीं कर सकते। द्वितीय, केवल परिसंघीय ढांचे से जुड़े गिने-चुने प्रावधानों पर ही राज्यों की सहमति मांगी जाती है, जबकि बड़े हिस्से को संसद अकेले बदल सकती है। तृतीय, राज्यों को अनुसमर्थन देने या खारिज करने के लिए संविधान में कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की गई है। अतः उपर्युक्त सभी कारण सही हैं।

124. (B) यह संविधान में अपरिभाषित है और पूरी तरह से न्यायिक व्याख्या पर निर्भर करता है
'मूल ढांचा' (बेसिक स्ट्रक्चर) सिद्धांत की आलोचना आलोचकों और संवैधानिक विद्वानों द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर की जाती है कि यह शब्द संविधान के पाठ में कहीं भी परिभाषित या उल्लेखित नहीं है। यह पूरी तरह से न्यायपालिका के स्वविवेक और समय-समय पर आने वाले न्यायिक निर्णयों की व्याख्या पर निर्भर करता है। आलोचकों का तर्क है कि इससे न्यायिक अतिसक्रियता (जुडिशल ओवररीच) को बढ़ावा मिलता है और निर्वाचित संसद की विधायी सर्वोच्चता सीमित होती है।

125. (C) केवल I और III
आलोचना के रूप में यह सही है कि संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले संसद द्वारा (विशेष बहुमत से) संशोधित किया जा सकता है और राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती। साथ ही, यदि कोई राज्य एक बार संशोधन का अनुसमर्थन कर देता है, तो क्या वह बाद में अपनी सहमति वापस ले सकता है या नहीं, इस पर संविधान मौन है। हालांकि, कथन II गलत है क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया साधारण विधि की प्रक्रिया से अलग और अधिक कठोर होती है।

126. (A) सहकारी समितियां
97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने भारत में 'सहकारी समितियों' (को-ऑपरेटिव सोसाइटीज) को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस संशोधन द्वारा तीन प्रमुख बदलाव किए गए: अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया, अनुच्छेद 43B के तहत इसे नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया, और संविधान में एक नया भाग IX-B अंतःस्थापित किया गया जिसमें सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक संचालन से जुड़े नियम शामिल किए गए।

127. (A) P-2, Q-1, R-4, S-3
52वां संविधान संशोधन (1985) दसवीं अनुसूची के माध्यम से दल-बदल विरोधी कानून लागू करने से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन (1989) अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन (1992) भाग IX जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन (2002) अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा का अधिकार प्रदान करने से संबंधित है।

128. (D) आंग्ल-भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने के संवैधानिक प्रावधान को समाप्त कर दिया
104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सीटों के आरक्षण की समयावधि को अगले 10 वर्षों (2030 तक) के लिए बढ़ा दिया। इसके साथ ही, इस संशोधन ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अनुच्छेद 331 और 333 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय (एंग्लो-इंडियन) समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने के संवैधानिक प्रावधान को आगे न बढ़ाकर समाप्त कर दिया।

Click Here to Buy book on Flipkart

10. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।

अभिकथन (A): भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के प्रवर्तन को भारत के किसी निर्दिष्ट भाग तक सीमित कर सकते हैं।

कारण (R): 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के प्रवर्तन को भारत के किसी निर्दिष्ट भाग तक सीमित करने में सक्षम बनाया।

निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है

11. अनुच्छेद 352 के अनुसार, राष्ट्रपति किसकी लिखित सिफारिश प्राप्त होने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं?

(A) प्रधानमंत्री
(B) केंद्रीय मंत्रिमंडल
(C) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(D) संसद

12. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा और उसके अनुमोदन के संबंध में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए:

I. राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश
II. राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा
III. दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित होना
IV. उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनिए:

(A) I, II, IV, III
(B) II, I, III, IV
(C) I, IV, II, III
(D) II, IV, I, III

13. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा किस समय-सीमा के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए?

(A) 14 दिनों के भीतर
(B) एक महीने के भीतर
(C) दो महीने के भीतर
(D) छह महीने के भीतर

14. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अनुमोदित करने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है?

(A) दोनों सदनों में साधारण बहुमत
(B) दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत
(C) दोनों सदनों में विशेष बहुमत
(D) लोकसभा में विशेष बहुमत और राज्यसभा में साधारण बहुमत

15. यदि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय लोकसभा भंग हो जाती है, तो उद्घोषणा कब तक प्रभाव में बनी रहती है?

(A) उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा औपचारिक समीक्षा के बाद 30 दिनों तक
(B) नए आम चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने से 6 महीने तक
(C) उस तारीख से 30 दिनों तक जब राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा उद्घोषणा को रद्द या संशोधित करने का निर्णय लेते हैं
(D) पुनर्गठित नई लोकसभा की पहली बैठक की तारीख से 30 दिनों तक, शर्त यह है कि राज्यसभा ने इसे अनुमोदित कर दिया हो

16. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों का क्या होता है?

(A) वे पूरी तरह से निलंबित हो जाती हैं, और राज्य के सभी लंबित विधेयक तुरंत शून्य हो जाते हैं
(B) वे विशेष रूप से राज्यपाल को स्थानांतरित कर दी जाती हैं, जो मंत्रिमंडल की सलाह के बिना उनका प्रयोग करते हैं
(C) वे निलंबित नहीं होती हैं, लेकिन संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की समवर्ती शक्ति प्राप्त हो जाती है
(D) उद्घोषणा जारी होते ही राज्य विधानमंडल को तुरंत भंग कर दिया जाता है

17. केंद्र-राज्य संबंधों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. केंद्र की कार्यपालक शक्ति का विस्तार किसी भी राज्य को यह निर्देश देने तक होता है कि उसकी कार्यपालक शक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाए।
II. संसद राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए सशक्त हो जाती है।
III. राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकते हैं।
IV. राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाता है, और केंद्र प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल I, II और IV
(B) केवल I, II और III
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

18. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून आपातकाल के समाप्त होने के बाद कितने समय बाद निष्प्रभावी हो जाता है?

(A) तीन महीने
(B) छह महीने
(C) एक वर्ष
(D) दो वर्ष

NODIA

अध्याय 08
आपातकालीन प्रावधान

1. भारत के संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंधों का विस्तृत विवरण दिया गया है?
   (A) भाग XV
   (B) भाग XVI
   (C) भाग XVIII
   (D) भाग XX

2. आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान को अपनाने में भारतीय संविधान के निर्माताओं को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान ने अत्यधिक प्रभावित किया?
   (A) संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान
   (B) ब्रिटेन का संविधान
   (C) भारत सरकार अधिनियम, 1919
   (D) जर्मनी का वाइमर संविधान

3. केंद्र सरकार को आपातकालीन शक्तियां प्रदान करने के पीछे मुख्य औचित्य क्या है?
   (A) देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा करना
   (B) राष्ट्रपति को संकट के समय तानाशाह के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना
   (C) संविधान के संघीय ढांचे में स्थायी रूप से परिवर्तन करना
   (D) संसद को स्वेच्छा से राज्य विधानमंडलों को भंग करने की अनुमति देना

4. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के संविधान में प्रदान किया गया आपातकाल का प्रकार नहीं है?
   (A) राष्ट्रीय आपातकाल
   (B) राज्य आपातकाल / राष्ट्रपति शासन
   (C) सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आपातकाल
   (D) वित्तीय आपातकाल

5. भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंधों का ढांचा, विशेष रूप से संघ द्वारा राज्य की शक्तियों के अधिग्रहण के संबंध में, मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक अधिनियम से लिया गया है?
   (A) भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
   (B) भारत सरकार अधिनियम, 1919
   (C) भारत सरकार अधिनियम, 1935
   (D) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

6. 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से पहले, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का वैध आधार निम्नलिखित में से कौन-सा था?
   (A) सशस्त्र विद्रोह
   (B) संवैधानिक तंत्र की विफलता
   (C) वित्तीय अस्थिरता
   (D) आंतरिक अशांति

7. राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   I. इसे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जा सकता है।
   II. इसे युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के वास्तविक रूप से घटित होने से पहले भी घोषित किया जा सकता है, यदि राष्ट्रपति आश्वस्त हों कि इसका आसन्न खतरा है।
   III. इसे बिना किसी अपवाद के हमेशा भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर लागू किया जाना चाहिए।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (A) केवल I और II
   (B) केवल II और III
   (C) केवल I और III
   (D) I, II और III

8. 44वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 352 की शब्दावली में क्या मौलिक परिवर्तन किया?
   (A) इसने "बाह्य आक्रमण" शब्द को "विदेशी आक्रमण की कार्रवाई" से प्रतिस्थापित कर दिया
   (B) इसने "सशस्त्र विद्रोह" वाक्यांश को "गृहयुद्ध की शुरुआत" से प्रतिस्थापित कर दिया
   (C) इसने "आंतरिक अशांति" को "सशस्त्र विद्रोह" से प्रतिस्थापित कर दिया
   (D) इसने "युद्ध" शब्द को "आधिकारिक सैन्य संघर्ष" से प्रतिस्थापित कर दिया

9. जब 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण' के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो इसे तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है?
   (A) आंतरिक आपातकाल
   (B) संप्रभु आपातकाल
   (C) पूर्ण आपातकाल
   (D) बाह्य आपातकाल

NODIA

129. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
भारत के संवैधानिक इतिहास में संसद और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के संतुलन को लेकर निरंतर टकराव देखा गया है। जब भी न्यायपालिका ने संपत्ति के अधिकार, भूमि सुधार या मूल अधिकारों के संदर्भ में कोई निर्णय दिया, संसद ने प्रथम, 24वें, 25वें और 42वें संशोधनों जैसे कानूनों के माध्यम से उन न्यायिक निर्णयों के प्रभाव को पलटने का प्रयास किया। मिनर्वा मिल्स और केशवानंद भारती जैसे मामलों में इस टकराव की पराकाष्ठा देखी गई। अतः दोनों कथन सही हैं।

130. (D) I, II, III और IV
सभी संयोजनों का कालानुक्रमिक दशक सही है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1951 (1950 का दशक) में अधिनियमित किया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 (1970 का दशक) में पारित हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 (1990 का दशक) में अधिनियमित किया गया था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम (जीएसटी) वर्ष 2016 (2010 का दशक) में लागू किया गया था। अतः सभी चारों युग्म पूरी तरह सही सुमेलित हैं।

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

19. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का सामान्य कार्यकाल किस प्रकार प्रभावित होता है?
(A) इसे संसद द्वारा कानून बनाकर एक बार में एक वर्ष के लिए, कितनी भी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है
(B) इसे किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, यहाँ तक कि सक्रिय सैन्य संघर्ष के दौरान भी नहीं
(C) आपातकाल की उद्घोषणा होने पर यह स्वतः ही पांच वर्ष के लिए बढ़ जाता है
(D) इसे राष्ट्रपति द्वारा कार्यपालक आदेश के माध्यम से एक बार में छह महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है

20. यदि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को संशोधित करने वाला आदेश जारी करते हैं, तो ऐसा आदेश कब तक लागू रहता है?
(A) जब तक संसद के विशेष बहुमत के संकल्प द्वारा आपातकाल रद्द नहीं कर दिया जाता
(B) देश भर में आपातकाल के औपचारिक रूप से समाप्त होने के तीन महीने बाद तक
(C) उस वित्तीय वर्ष के अंत तक जिसमें आपातकाल समाप्त होता है
(D) जब तक वित्त आयोग संसद से इसकी पूर्ण वापसी की औपचारिक सिफारिश नहीं करता

21. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: संवैधानिक प्रावधान
P. अनुच्छेद 352
Q. अनुच्छेद 356
R. अनुच्छेद 358
S. अनुच्छेद 359
सूची II: विषय-वस्तु
1. मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन
2. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा
3. अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रताओं का स्वतः निलंबन
4. राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में प्रावधान
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-2, Q-4, R-3, S-1
(B) P-2, Q-3, R-4, S-1
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-1, Q-4, R-3, S-2

22. अनुच्छेद 358 के तहत, अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकार केवल तभी स्वतः निलंबित होते हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर घोषित किया जाता है?
(A) सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक अशांति
(B) आसन्न वित्तीय संकट
(C) संवैधानिक तंत्र की विफलता
(D) युद्ध या बाह्य आक्रमण

23. 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा संरक्षित किए गए कौन-से दो मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते?
(A) अनुच्छेद 14 और 15
(B) अनुच्छेद 19 और 20
(C) अनुच्छेद 20 और 21
(D) अनुच्छेद 21 और 22

24. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रुप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): अनुच्छेद 359 स्वतः किसी भी मूल अधिकार को निलंबित नहीं करता है।
कारण (R): अनुच्छेद 359 केवल राष्ट्रपति को निर्दिष्ट मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति देता है।
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है

25. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के बीच अंतर को सटीक रुप से रेखांकित करता है?
(A) अनुच्छेद 358 पूरे देश में मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करता है, जबकि अनुच्छेद 359 हमेशा किसी निर्दिष्ट राज्य पर ही लागू होता है
(B) अनुच्छेद 358 स्पष्ट रुप से राष्ट्रपति को एक विशिष्ट कार्यपालक आदेश जारी करने की शक्ति देता है, जबकि अनुच्छेद 359 स्वतः संचालित होता है
(C) अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित करता है, जबकि अनुच्छेद 359 वास्तविक मूल अधिकारों को निलंबित करता है
(D) अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल की स्थिति में लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 359 बाह्य और आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है

NODIA

26. अनुच्छेद 356 के तहत, राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे आश्वस्त हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती। यह समाधान किस पर आधारित हो सकता है?
(A) राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य आधारों पर
(B) केवल राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर
(C) राज्य के मुख्यमंत्री से प्राप्त जानकारी पर
(D) राज्य विधानसभा की बाध्यकारी सिफारिश पर

27. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति शासन लगाने का एक आधार प्रदान करता है। यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है यदि:

(A) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों में कटौती
(B) नागरिकों के निजी बैंक खातों और व्यक्तिगत वित्तीय संपत्तियों का अधिग्रहण
(C) सभी विदेशी मुद्रा और बाह्य वित्तीय लेन-देन का पूर्ण निलंबन
(D) सभी प्रभावित राज्यों में राज्य वित्त आयोगों का स्थायी उन्मूलन

46. वित्तीय आपातकाल के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. संघ की कार्यपालक शक्ति का विस्तार किसी भी राज्य को वित्तीय औचित्य के निर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश देने तक है।
II. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जा सकता है।
III. इसके जारी रहने के लिए हर छह महीने में बार-बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
IV. राष्ट्रपति संघ की सेवा करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन में कटौती के निर्देश जारी कर सकते हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और IV
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, III और IV
(D) I, II, III और IV

47. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: राष्ट्रीय आपातकाल का वर्ष
P. 1962
Q. 1971
R. 1975
S. 1977
सूची II: तात्कालिक कारण/संदर्भ
1. आंतरिक आपातकाल का निरसन
2. नेफा (NEFA) में चीनी आक्रमण
3. पाकिस्तान द्वारा आक्रमण जिसके कारण युद्ध हुआ
4. आंतरिक अशांति और राजनीतिक संकट
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-3, Q-2, R-1, S-4
(B) P-2, Q-4, R-3, S-1
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

48. भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की पहली उद्घोषणा अक्टूबर 1962 में जारी की गई थी। यह कब तक लागू रही?
(A) 1964
(B) 1965
(C) 1968
(D) 1971

49. जून 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन ऐतिहासिक रूप से सटीक है?
(A) भारतीय संवैधानिक इतिहास में यह पहली बार था कि बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी
(B) इसकी घोषणा तब की गई थी जब 1971 का आपातकाल (बाह्य आक्रमण के आधार पर) पहले से ही लागू था
(C) इसे तुरंत न्यायालय में चुनौती दी गई और एक महीने के भीतर उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया
(D) इसकी घोषणा सभी प्रमुख विपक्षी दलों की सर्वसम्मत लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद की गई थी

50. 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे?
(A) वी.वी. गिरि
(B) नीलम संजीव रेड्डी
(C) ज्ञानी ज़ैल सिंह
(D) फखरुद्दीन अली अहमद

51. 1971 और 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल दोनों को औपचारिक रूप से किस वर्ष वापस लिया गया था?
(A) 1976
(B) 1977
(C) 1978
(D) 1979

52. उच्च न्यायालय का कौन-सा ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा निर्वाचन को रद्द करके 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का तात्कालिक कानूनी कारण बना?
(A) केरल उच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले का निर्णय
(B) पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ मामले का निर्णय
(C) इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा राज नारायण मामले का निर्णय
(D) बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले का निर्णय

53. 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल विशेष रूप से उस समय मौजूद किस संवैधानिक वाक्यांश के तहत लागू किया गया था?
(A) आंतरिक अशांति
(B) आसन्न गृहयुद्ध
(C) संवैधानिक तंत्र की विफलता
(D) सशस्त्र विद्रोह

54. जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ राजनीतिक आंदोलन, जिसने 1975 के आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार की, उसे आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था?

Click Here to Buy book on Amazon

न्यायालय रिपोर्ट को वैध ठहराता है → संसद विस्तार पारित करती है
(D) राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा विस्तार करते हैं → संसद विशेष बहुमत से पारित करती है → निर्वाचन आयोग सत्यापित करता है

36. जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति की ओर से राज्य का प्रत्यक्ष प्रशासन कौन चलाता है?
(A) मुख्यमंत्री
(B) राज्य के मुख्य सचिव
(C) राज्य के राज्यपाल
(D) राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

37. जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो राज्य विधानसभा का क्या होता है?
(A) इसे राष्ट्रपति द्वारा या तो निलंबित कर दिया जाता है या भंग कर दिया जाता है
(B) इसे स्थायी रूप से भंग कर दिया जाता है और तुरंत नए चुनाव कराए जाते हैं
(C) यह कार्य करती रहती है लेकिन केवल साधारण विधेयक पारित कर सकती है, धन विधेयक नहीं
(D) इसका संसद में विलय कर दिया जाता है

38. राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के दौरान किसी राज्य के लिए संसद या राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानून कब तक लागू रहते हैं?
(A) केवल तब तक जब तक कि कार्यपालक आदेश द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा रद्द नहीं कर दी जाती
(B) राष्ट्रपति शासन के निरसन के बाद अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए
(C) राज्य विधानसभा के पुनः गठन के बाद ठीक एक वर्ष के लिए
(D) तब तक लागू रहते हैं जब तक कि उन्हें राज्य विधानमंडल द्वारा निरस्त या परिवर्तित न कर दिया जाए

39. अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के दौरान, राष्ट्रपति किसमें निहित या उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को स्वयं ग्रहण नहीं कर सकते हैं?
(A) राज्य के राज्यपाल
(B) राज्य का उच्च न्यायालय
(C) राज्य की मंत्रिपरिषद
(D) राज्य लोक सेवा आयोग

40. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य उच्च न्यायालय की शक्तियों को ग्रहण करने से राष्ट्रपति को संवैधानिक रूप से रोका गया है।
कारण (R): राज्य उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति, दर्जा और शक्तियां राष्ट्रपति शासन के दौरान भी अप्रभावित रहती हैं।
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है

NODIA

41. जब राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य विधानसभा निलंबित या भंग हो जाती है, तो राज्य का बजट पारित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है?
(A) अध्यादेश के माध्यम से राज्य के वित्त मंत्री
(B) राज्यपाल
(C) भारतीय रिज़र्व बैंक
(D) संसद

42. अनुच्छेद 360 के तहत, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं यदि वे आश्वस्त हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे:
(A) भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है
(B) केंद्र सरकार का संचयी राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 10% से अधिक है
(C) विदेशी मुद्रा भंडार आवश्यक आयातों के लिए दो महीने के कवर से नीचे गिर जाता है
(D) राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए किसी वित्तीय ऋण के भुगतान में चूक करती है

43. वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा किस समय-सीमा के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए?
(A) एक महीने
(B) दो महीने
(C) तीन महीने
(D) छह महीने

44. संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने के बाद वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितनी अवधि तक जारी रह सकता है?
(A) संसदीय अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष, जिसके लिए वार्षिक नवीनीकरण की आवश्यकता होती है
(B) अधिकतम तीन वर्ष, जिसके बाद संवैधानिक संशोधन अनिवार्य है
(C) अधिकतम पांच वर्ष, जो वित्त आयोग द्वारा समीक्षा के अधीन है
(D) कोई अधिकतम सीमा नहीं है; यह तब तक अनिश्चित काल के लिए जारी रहता है जब तक कि इसे रद्द न कर दिया जाए

45. निम्नलिखित में से कौन-सी एक असाधारण कार्यपालक कार्रवाई है जो वित्तीय आपातकाल के दौरान की जा सकती है?

(A) राज्य सरकार निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य विधानसभा चुनाव कराने में विफल रहती है
(B) राज्य केंद्र के किसी भी निर्देश का अनुपालन करने या उसे प्रभावी करने में विफल रहता है
(C) राज्य सरकार लगातार तीन वित्तीय वर्षों के लिए अत्यधिक बजट घाटे का प्रस्ताव करती है
(D) राज्यपाल एक स्थिर सरकार बनाने के लिए स्पष्ट राजनीतिक बहुमत खोजने में असमर्थ रहते हैं

28. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति की प्रकृति का वर्णन करता है?
(A) यह एक निरपेक्ष, गैर-न्याययोग्य शक्ति है
(B) यह एक सशर्त शक्ति है जो दुर्भावना के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है
(C) यह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना प्रयोग की जाने वाली एक विवेकाधीन शक्ति है
(D) यह एक अनन्य शक्ति है जिसके लिए उच्चतम न्यायालय की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है

29. अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए:
I. जहाँ आम चुनावों के बाद राज्य विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हुआ हो (त्रिशंकु विधानसभा)।
II. जहाँ मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है और कोई अन्य दल वैकल्पिक सरकार बनाने में सक्षम या इच्छुक नहीं होता है।
III. जहाँ राज्य सरकार जानबूझकर संविधान और कानून के विरुद्ध कार्य कर रही हो।

एस.आर. बोम्मई मामले के दिशानिर्देशों के अनुसार, उपर्युक्त में से कौन-सा/से राष्ट्रपति शासन लगाने का वैध आधार प्रस्तुत करता है/करते हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

30. स्थापित न्यायिक नज़ीरों के अनुसार, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति शासन लगाने का अवैध या अमान्य आधार माना जाता है?
(A) राज्य विधानसभा में असाध्य गतिरोध के कारण उत्पन्न संवैधानिक गतिरोध
(B) बड़े पैमाने पर आंतरिक विद्रोह जहाँ राज्य सरकार जानबूझकर सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा देती है
(C) राज्य में सत्तारुढ़ दल को लोकसभा के आम चुनावों में भारी हार का सामना करना पड़ता है
(D) राज्य सरकार संघ द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का लगातार उल्लंघन करती है

31. राष्ट्रपति शासन लगाने वाली उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से किस समय-सीमा के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए?
(A) एक महीने
(B) दो महीने
(C) तीन महीने
(D) छह महीने

32. अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को अनुमोदित करने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है?
(A) पूर्ण बहुमत
(B) विशेष बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3)
(C) साधारण बहुमत
(D) आधे राज्यों के अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत

33. संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने के बाद, राष्ट्रपति शासन छह महीने की अवधि के लिए जारी रहता है। विशिष्ट शर्तों के अधीन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है?
(A) सभी परिस्थितियों में कुल मिलाकर एक वर्ष
(B) संसदीय अनुमोदन के बाद कुल मिलाकर दो वर्ष
(C) तीन वर्ष
(D) विशेष परिस्थितियों के तहत कुल मिलाकर पांच वर्ष

34. 44वें संशोधन अधिनियम के अनुसार, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए कौन-सी विशिष्ट शर्त (शर्तें) पूरी होनी चाहिए?
(A) राज्य के राज्यपाल को एक नई विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, और न्यायिक समीक्षा के बाद उच्चतम न्यायालय को इसकी पुष्टि करनी होगी
(B) राज्य के दो-तिहाई निर्वाचित सांसदों को संसद में प्रस्तावित विस्तार के पक्ष में औपचारिक रुप से मतदान करना होगा
(C) अंतर-राज्य परिषद और केंद्रीय मंत्रिमंडल को लिखित रुप में राष्ट्रपति को सर्वसम्मति से विस्तार की सिफारिश करनी होगी
(D) राष्ट्रीय आपातकाल लागू होना चाहिए, या निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने में कठिनाइयों का प्रमाणन करना चाहिए

35. अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का सही क्रम चुनिए:
(A) संसद संकल्प पारित करती है → निर्वाचन आयोग चुनाव कराने में असमर्थता का प्रमाणन करता है → राष्ट्रपति विस्तार पर हस्ताक्षर करते हैं
(B) निर्वाचन आयोग चुनाव कराने में असमर्थता का प्रमाणन करता है → संसद साधारण बहुमत से संकल्प पारित करती है → विस्तार प्रभावी होता है
(C) राज्यपाल आपातकाल की रिपोर्ट देते हैं → उच्चतम

Downloaded from www.pdf.tube

(A) लोकतांत्रिक सुधार के लिए दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन
(B) संपूर्ण स्वराज और नागरिक अधिकार आंदोलन
(C) देशव्यापी भूदान और ग्रामदान आंदोलन
(D) नवनिर्माण आंदोलन और संपूर्ण क्रांति

55. 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की पृष्ठभूमि से संबंधित निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए:
I. 1971 के युद्ध के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट।
II. जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा आयोजित देशव्यापी रेलवे हड़ताल।
III. उच्चतम न्यायालय द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर पूर्ण और बिना शर्त रोक लगाना।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

56. 1975 के आपातकाल के निरसन के बाद, जनता पार्टी सरकार ने आपातकाल के दौरान की गई आधिक्य की कार्रवाइयों और शक्तियों के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया। उस आयोग का नाम बताइए:
(A) कोठारी आयोग
(B) सरकारिया आयोग
(C) शाह आयोग
(D) नानावटी आयोग

57. 1975 के आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बंदी बनाने के लिए सरकार द्वारा किस निवारक निरोध अधिनियम का व्यापक प्रयोग किया गया था?
(A) आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (TADA)
(B) आतंकवाद निवारण अधिनियम (POTA)
(C) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA)
(D) आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का अधिनियम (MISA)

58. 1975 के आपातकाल के दौरान किस प्रसिद्ध मामले में उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि अवैध हिरासत को चुनौती देने के लिए नागरिकों को बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका के लिए न्यायालय जाने का कोई अधिकार नहीं है?
(A) ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला
(B) ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य
(C) मेनका गांधी बनाम भारत संघ
(D) आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य

59. 1975 के आपातकाल की उद्घोषणा के तुरंत बाद सरकार द्वारा कार्यपालक आदेश पारित करके निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता को गंभीर रूप से सीमित कर दिया गया था?
(A) धर्म की स्वतंत्रता
(B) पूर्व-सेंसरशिप के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता
(C) अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
(D) संपत्ति के उत्तराधिकार का अधिकार

NODIA

60. 1975 के आपातकाल के दौरान, 42वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को कैसे प्रभावित किया?
(A) इसने कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष कर दिया
(B) इसने सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया
(C) इसने आपातकाल हटाए जाने तक कार्यकाल को अनिश्चित बना दिया
(D) इसने विघटन से मुक्त, 7 वर्षों की एक निश्चित अवधि लागू की

61. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): 1975 के आपातकाल के दौरान, उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कोई बंदी अपनी हिरासत को अदालत में चुनौती नहीं दे सकता, भले ही वह दुर्भावनापूर्ण हो।
कारण (R): उस समय, अनुच्छेद 359 ने राष्ट्रपति को अनुच्छेद 21 सहित सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने का आदेश जारी करने की अनुमति दी थी।
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है

62. किस संवैधानिक संशोधन ने यह अनिवार्य किया कि प्रधानमंत्री की एकतरफा शक्ति को रोकने के लिए राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं?
(A) 38वां संशोधन अधिनियम
(B) 42वां संशोधन अधिनियम
(C) 44वां संशोधन अधिनियम
(D) 52वां संशोधन अधिनियम

63. 1975 के बाद शुरु किए गए सुरक्षा उपायों में से एक यह है कि कुछ मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालयों में जाने के अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये अधिकार कौन-से हैं?
(A) वाक्-स्वातंत्र्य, शांतिपूर्ण सम्मेलन, और संघ बनाने का अधिकार
(B) शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध
(C) अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, और धर्म के प्रचार का अधिकार

99. वह प्रावधान जिसने आपातकाल घोषित करने में राष्ट्रपति के समाधान को पुनः न्यायिक समीक्षा के अधीन बनाया, किस संशोधन अधिनियम द्वारा पुनस्थापित किया गया?
(A) 42वां संशोधन अधिनियम
(B) 43वां संशोधन अधिनियम
(C) 44वां संशोधन अधिनियम
(D) 52वां संशोधन अधिनियम

100. किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह माना कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है यदि यह पूरी तरह से बाहरी और अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित है या दुर्भावनापूर्ण है?
(A) केशवानंद भारती मामला (1973)
(B) आई.आर. कोएल्हो मामला (2007)
(C) मिनर्वा मिल्स मामला (1980)
(D) गोलकनाथ मामला (1967)

101. एस.आर. बोम्मई मामले में स्थापित राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की न्यायिक समीक्षा के संबंध में, राष्ट्रपति के समाधान का मूल्यांकन करने पर न्यायालय का क्या रुख है?
(A) न्यायालय यह जांच कर सकता है कि क्या प्रासंगिक सामग्री मौजूद थी, लेकिन उस सामग्री की पर्याप्तता पर सवाल नहीं उठा सकता
(B) न्यायालय उस वस्तुनिष्ठ सामग्री की जांच नहीं कर सकता जिस पर कार्यपालिका का समाधान आधारित था
(C) न्यायालय सभी मामलों में राष्ट्रपति के स्थान पर अपना व्यक्तिगत राजनीतिक निर्णय प्रतिस्थापित कर देगा
(D) न्यायालय औपचारिक रूप से राष्ट्रपति से व्यक्तिगत रूप से पीठ के समक्ष उपस्थित होने और निर्णय का औचित्य सिद्ध करने की अपेक्षा करता है

102. जब राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जाती है, तो आपातकाल लगाने के औचित्य को सिद्ध करने का भार किस पर होता है?
(A) याचिकाकर्ता पर जिसने उद्घोषणा को चुनौती दी है
(B) राज्य के बर्खास्त मुख्यमंत्री पर
(C) राज्य के राज्यपाल पर
(D) संघ सरकार पर

103. आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित संवैधानिक न्यायशास्त्र में, "राष्ट्रपति का समाधान" शब्द का अर्थ है:
(A) राष्ट्रपति का व्यक्तिगत समाधान, जिसकी समीक्षा नहीं की जा सकती
(B) वस्तुनिष्ठ सामग्री के आधार पर मंत्रिपरिषद का समाधान
(C) एक औपचारिक संयुक्त संकल्प के माध्यम से व्यक्त संसद के दोनों सदनों का समाधान
(D) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित रूप में दी गई बाध्यकारी सलाह

104. अनुच्छेद 356 के तहत, राष्ट्रपति "राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर... या अन्यथा" कार्य कर सकते हैं। "या अन्यथा" वाक्यांश राष्ट्रपति को क्या करने के लिए सशक्त बनाता है?
(A) गंभीर संकटों में प्रभावित राज्य विधानसभा के बजाय संसद को भंग करने के लिए
(B) पृथक संसदीय अनुमोदन के बिना पूरे राज्य में एक साथ वित्तीय आपातकाल लगाने के लिए
(C) राज्यपाल के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त सामग्री के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए
(D) मंत्रिमंडल की सिफारिश को दरकिनार कर पूरी तरह से व्यक्तिगत विवेकाधिकार पर कार्य करने के लिए

105. यदि उच्चतम न्यायालय यह पाता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना असंवैधानिक और अमान्य था, तो उसके पास कौन-सी उपचारात्मक शक्ति है?
(A) यह केवल बर्खास्त राज्य सरकार के सदस्यों को मौद्रिक मुआवजा दे सकता है
(B) यह निर्वाचन आयोग की प्रत्यक्ष देखरेख में राज्य में नए आम चुनाव कराने का आदेश दे सकता है
(C) यह एक अस्थायी अवधि के लिए राज्य का प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण निर्वाचन आयोग को सौंप सकता है
(D) यह बर्खास्त राज्य सरकार को पुनः बहाल कर सकता है और भंग विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है

106. आपातकालीन उद्घोषणाओं में राष्ट्रपति के समाधान के कानूनी सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. समाधान व्यक्तिगत होता है लेकिन प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होना चाहिए।
II. यदि निर्णय मिश्रित आधारों पर आधारित है—कुछ वैध और कुछ अवैध—तो उद्घोषणा स्वतः ही रद्द हो जाती है।
III. मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की सीधे न्यायालयों द्वारा जांच नहीं की जा सकती, लेकिन जिस सामग्री पर सलाह आधारित थी, उसकी जांच की जा सकती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

107. आपातकाल लगाने में राष्ट्रपति के समाधान को न्यायालयों द्वारा केवल किस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है?
(A) यह निर्णय पूरी तरह से अप्रासंगिक या बाहरी तथ्यात्मक आधारों पर आधारित था
(B) कोई अन्य तर्कसंगत व्यक्ति उसी सामग्री के आधार पर अलग निष्कर्ष पर पहुँच सकता था
(C) इसका प्रयोग अनुचित राजनीतिक या असंवैधानिक उद्देश्यों के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया था
(D) यह राज्य सरकार चलाने वाले किसी विपक्षी दल के साथ राजनीतिक हिसाब चुकता करने के लिए किया गया था

Click Here to Buy book on Flipkart

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from
PRINTED BOOKS has up to
4× HIGHER RETENTION
than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY
PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

आधार पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है
2. पहली बैठक से पहले बिहार विधानसभा का विघटन असंवैधानिक था
3. बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट अनिवार्य है
4. आपातकाल के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर नहीं की जा सकती

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-1, Q-3, R-2, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

73. संविधान के लागू होने के बाद से, राजस्थान राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लगाया गया है?
(A) दो बार
(B) तीन बार
(C) चार बार
(D) पांच बार

74. राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था?
(A) 1967
(B) 1971
(C) 1977
(D) 1980

75. राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का दूसरा उदाहरण (1977) केंद्र में सत्तारूढ़ जनता पार्टी द्वारा कई राज्य सरकारों की सामूहिक बर्खास्तगी से संबंधित था। राजस्थान के वे मुख्यमंत्री कौन थे जिनकी सरकार को 1977 में बर्खास्त कर दिया गया था?
(A) मोहन लाल सुखाड़िया
(B) हरिदेव जोशी
(C) बरकतउल्लाह खान
(D) भैरों सिंह शेखावत

76. बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 1992 में राजस्थान में चौथी और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे?
(A) शिव चरण माथुर
(B) भैरों सिंह शेखावत
(C) अशोक गहलोत
(D) जगन्नाथ पहाड़िया

77. राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को उस सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिनके कार्यकाल के दौरान राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था:
I. हरिदेव जोशी
II. मोहन लाल सुखाड़िया
III. भैरों सिंह शेखावत (1980 बर्खास्तगी)
IV. भैरों सिंह शेखावत (1992 बर्खास्तगी)

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनिए:
(A) I, II, III, IV
(B) II, I, III, IV
(C) II, III, I, IV
(D) I, III, II, IV

78. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 के तहत विशेष रूप से किस मूल अधिकार को स्वतः निलंबन के लिए लक्षित किया गया है?
(A) विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 14)
(B) वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अन्य स्वतंत्रताओं का अधिकार (अनुच्छेद 19)
(C) प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 21)
(D) मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

79. जब संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 358 के प्रवर्तन का भौगोलिक विस्तार क्या होता है?
(A) यह केवल सीमावर्ती राज्यों पर लागू होता है
(B) यह केवल संसद द्वारा निर्दिष्ट राज्यों पर लागू होता है
(C) यह केवल संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होता है
(D) यह स्वतः ही संपूर्ण देश पर लागू होता है

80. अनुच्छेद 358 के तहत अधिकारों का निलंबन कब तक बना रहता है?
(A) अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए, जिसके बाद संसदीय नवीनीकरण की आवश्यकता होती है
(B) जब तक कि भारत का उच्चतम न्यायालय उनकी संवैधानिक बहाली का स्पष्ट आदेश नहीं दे देता
(C) राष्ट्रीय आपातकाल की पूरी अवधि के लिए
(D) राष्ट्रीय आपातकाल आधिकारिक रूप से हटाए जाने के ठीक 30 दिनों बाद तक

81. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने के बाद, आपातकाल के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए कोई कानूनी उपचार उपलब्ध नहीं होता, भले ही उसने अनुच्छेद 19 का उल्लंघन किया हो।
कारण (R): अनुच्छेद 358 आपातकाल के दौरान की गई विधायी और कार्यपालक कार्रवाइयों को आपातकाल के बाद अनुच्छेद 19 के असंगत होने के आधार पर चुनौती दिए जाने से संरक्षण प्रदान करता है।
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है

Downloaded from www.pdf.tube

III. राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता से गंभीर रूप से समझौता होता है।
IV. मूल अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं क्योंकि उन्हें आसानी से निलंबित किया जा सकता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I, II और III
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

118. केंद्र-राज्य संबंधों पर किस प्रमुख आयोग ने यह सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 356 का उपयोग बहुत कम और केवल "अंतिम उपाय के साधन" के रूप में किया जाना चाहिए?
(A) कोठारी आयोग
(B) शाह आयोग
(C) मंडल आयोग
(D) सरकारिया आयोग

119. आपातकालीन प्रावधानों में सुधार के संदर्भ में, "स्थानीय आपातकाल" की अवधारणा (पूरे राज्य में आपातकाल लगाने के बजाय केवल किसी विशिष्ट संकटग्रस्त जिले या भाग में आपातकाल लगाना) की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी?
(A) प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)
(B) सरकारिया आयोग (1988)
(C) संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (2002)
(D) पुंछी आयोग (2010)

120. अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की रिपोर्ट के संबंध में विभिन्न समितियों द्वारा की गई प्रमुख सिफारिश निम्नलिखित में से कौन-सी है?
(A) इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए, और रिपोर्ट देने का दायित्व विशेष रूप से राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंपा जाना चाहिए
(B) यह सख्ती से गोपनीय होनी चाहिए और सभी परिस्थितियों में न्यायिक जांच या संसदीय चर्चा से पूरी तरह मुक्त होनी चाहिए
(C) यह सभी सामग्री तथ्यों और आधारों का सटीक और स्पष्ट विवरण देने वाला एक 'सकारण दस्तावेज' होना चाहिए
(D) इसे आधिकारिक रूप से प्रस्तुत करने से पहले राज्य विधानसभा के दो-तिहाई बहुमत द्वारा औपचारिक रूप से जांचा और अनुमोदित किया जाना चाहिए

121. सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 356 के तहत चरम कार्रवाई करने से पहले केंद्र को:
(A) उच्चतम न्यायालय से पूर्व औपचारिक अनुमति लेनी चाहिए
(B) पहले चरण में पूरे राज्य में अस्थायी वित्तीय आपातकाल लगाना चाहिए
(C) कार्यपालक कार्रवाई की समीक्षा को रोकने के लिए राज्यसभा को भंग कर देना चाहिए
(D) राज्य सरकार को अपना मार्ग सुधारने के लिए चेतावनी जारी करनी चाहिए

122. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: आयोग/समिति
P. सरकारिया आयोग
Q. पुंछी आयोग
R. NCRWC (वेंकटचलैया आयोग)
S. एस.आर. बोम्मई फैसला
सूची II: प्रमुख सिफारिश/रुख
1. "स्थानीय आपातकाल" की अवधारणा प्रस्तुत की
2. पूर्व चेतावनी के साथ अनुच्छेद 356 एक "अंतिम उपाय" होना चाहिए
3. न्यायिक समीक्षा को वैध ठहराया और बहुमत परीक्षण अनिवार्य किया
4. राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग को रोकने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन का सुझाव दिया
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-2, Q-1, R-4, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

123. अनुच्छेद 356 को लागू करने से पहले केंद्र-राज्य विवादों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए सुधार सुधार समितियों द्वारा किस संवैधानिक निकाय को उपयुक्त मंच के रूप में सुझाया गया है?
(A) वित्त आयोग
(B) अंतर-राज्य परिषद
(C) नीति आयोग
(D) क्षेत्रीय परिषदें

NODIA

124. पुंछी आयोग, जिसने आपातकालीन प्रावधानों और केंद्र-राज्य संबंधों पर महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थीं, ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी?
(A) 1983
(B) 1994
(C) 2002
(D) 2010

125. भारत में किस महत्वपूर्ण घटना या फैसले के बाद राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लगाने की आवृत्ति में भारी कमी आई?
(A) 1994 का एस.आर. बोम्मई निर्णय
(B) 1976 में 42वां संशोधन अधिनियम पारित होना
(C) 1977 में राष्ट्रीय आपातकाल का हटना
(D) 2015 में नीति आयोग का गठन

126. हाल के वर्षों में, उच्चतम न्यायालय ने बहुमत परीक्षण की पवित्रता पर बल देते हुए, अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त राज्य सरकारों को बहाल करने के लिए हस्तक्षेप किया है।

केवल अस्थायी रूप से निलंबित होती है
(B) अनुच्छेद 352 के तहत, राज्य कार्यपालिका बनी रहती है लेकिन केंद्र के निर्देशों के अधीन होती है; अनुच्छेद 356 के तहत, इसे बर्खास्त कर दिया जाता है
(C) अनुच्छेद 352 के तहत, राज्यपाल राज्य की सभी शक्तियां ग्रहण कर लेते हैं; अनुच्छेद 356 के तहत, मुख्यमंत्री पूर्ण कार्यपालक शक्ति बनाए रखते हैं
(D) कोई संरचनात्मक अंतर नहीं है; दोनों परिस्थितियों में राज्य कार्यपालिका को पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया जाता है

92. तीन प्रकार के आपातकाल की तुलना करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. अनुच्छेद 352 मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, जबकि अनुच्छेद 356 और 360 का मूल अधिकारों पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है।
II. अनुच्छेद 356 की अधिकतम निर्धारित अवधि तीन वर्ष है, जबकि अनुच्छेद 352 और 360 की कोई अधिकतम समय-सीमा नहीं है।
III. तीनों प्रकार के आपातकाल की घोषणा के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश की आवश्यकता होती है।
IV. तीनों में से किसी भी आपातकाल के निरसन के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, II और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

93. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान की इसके संघीय स्वरूप के संबंध में एक अनूठी विशेषता यह है कि:
(A) बिना किसी औपचारिक संशोधन के संघीय ढांचा एकात्मक ढांचे में बदल जाता है
(B) इसे एकात्मक व्यवस्था में बदलने के लिए विशेष बहुमत द्वारा संविधान में औपचारिक रूप से संशोधन किया जाना चाहिए
(C) राज्यों को संकट के दौरान भारतीय संघ से अस्थायी रूप से अलग होने का अधिकार दिया जाता है
(D) राज्यसभा को निलंबित कर दिया जाता है और सभी संघीय विधायी नियंत्रण मंत्रिमंडल को हस्तांतरित हो जाता है

94. संविधान निर्माताओं में से किसने यह आशा व्यक्त की थी कि अनुच्छेद 356 के तहत कठोर शक्ति एक "मृत पत्र" (अप्रयुक्त प्रावधान) बनी रहेगी और इसका उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा?
(A) सरदार वल्लभभाई पटेल
(B) जवाहरलाल नेहरू
(C) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
(D) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

95. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार होता है?
(A) राष्ट्रपति राज्य के सभी राजस्व को पूरी तरह से रोक सकते हैं और उन्हें सीधे भारत की संचित निधि में भेज सकते हैं
(B) घोषित आपातकाल के दौरान केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होता है
(C) राष्ट्रपति राज्य वित्त आयोगों को स्थायी रूप से समाप्त कर सकते हैं और राज्यों के सभी कराधान कार्यों को ग्रहण कर सकते हैं
(D) राष्ट्रपति संघ और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकते हैं

96. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के संबंध में संसद की विधायी क्षमता किस प्रकार प्रभावित होती है?
(A) संसद राज्य विधानमंडल को प्रतिस्थापित करते हुए, राज्य सूची पर विधान बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त करती है
(B) संसद राज्य सूची पर तब तक विधान नहीं बना सकती जब तक कि राज्य विधानमंडल इसका अनुरोध करने वाला संकल्प पारित न करे
(C) संसद राज्य विधानमंडल के साथ-साथ राज्य सूची पर विधान बनाने की समवर्ती शक्ति प्राप्त करती है
(D) संसद राज्य सूची में केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर विधान बना सकती है

97. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: संविधान सभा में कथन
P. "यह प्रतिक्रियाओं और पश्चगमन का एक अध्याय है।"
Q. "राष्ट्रपति तानाशाह बन जाएंगे।"
R. "राज्य की स्वायत्तता पूरी तरह नष्ट हो जाएगी।"
S. "मुझे आशा है कि वे एक मृत पत्र बने रहेंगे।"
सूची II: वक्ता
1. डॉ. बी.आर. अंबेडकर
2. एच.वी. कामथ
3. के.टी. शाह
4. शिब्बन लाल सक्सेना
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-3, R-4, S-1
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

98. किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने में राष्ट्रपति के समाधान को न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह मुक्त करने का प्रयास किया था?
(A) 24वां संशोधन अधिनियम (1971)
(B) 38वां संशोधन अधिनियम (1975)
(C) 42वां संशोधन अधिनियम (1976)
(D) 44वां संशोधन अधिनियम (1978)

Click Here to Buy book on Amazon

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (C) भाग XVIII
भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक आपातकाल से संबंधित विभिन्न प्रावधान शामिल किए गए हैं। ये प्रावधान देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा करने के उद्देश्य से संविधान में समाविष्ट किए गए हैं। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है तथा देश का संपूर्ण संघीय ढांचा औपचारिक संशोधन के बिना एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाता है।

2. (D) जर्मनी का वाइमर संविधान
आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए निर्माताओं ने जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरणा ली थी। वाइमर संविधान में आपातकालीन स्थितियों के दौरान नागरिक अधिकारों को स्थगित करने की व्यवस्था विद्यमान थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल के समय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य संकट काल में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है।

3. (A) देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा करना
केंद्र सरकार को आपातकालीन शक्तियां प्रदान करने का मुख्य औचित्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। किसी भी असामान्य या संकटकालीन परिस्थिति में, जब देश के अस्तित्व या आंतरिक शांति पर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है, तब केंद्र सरकार को त्वरित निर्णय लेने और प्रभावी कार्रवाई करने हेतु सक्षम बनाना अनिवार्य होता है। ये शक्तियां असाधारण परिस्थितियों से निपटने और संपूर्ण देश में राष्ट्रीय हित तथा कानून का शासन पुनः स्थापित करने के लिए बनाई गई हैं।

4. (C) सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आपातकाल
भारतीय संविधान केवल तीन प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था करता है। इसमें अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल शामिल हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आपातकाल नामक किसी पृथक आपातकाल का कोई प्रावधान शामिल नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी संकटों या महामारी की स्थितियों से निपटने के लिए सामान्य विधिक कानूनों तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम जैसे विशिष्ट अधिनियमों का प्रयोग किया जाता है।

5. (C) भारत सरकार अधिनियम, 1935
भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंधों का प्रशासनिक ढांचा, विशेष रूप से संकट के समय संघ द्वारा राज्यों की शक्तियों का अधिग्रहण, मुख्य रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। 1935 के अधिनियम की धारा 93 और धारा 102 में प्रांतीय स्वायत्तता के निलंबन तथा केंद्र को विशेष आपातकालीन शक्तियां सौंपने के स्पष्ट प्रावधान विद्यमान थे। हालांकि मूल अधिकारों के निलंबन का विचार जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रभावित है, परंतु आपातकाल का संपूर्ण प्रशासनिक ढांचा 1935 के अधिनियम पर ही आधारित है।

6. (D) आंतरिक अशांति
वर्ष 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से पूर्व, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के तीन आधार युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति थे। वर्ष 1975 में घोषित आपातकाल का मुख्य आधार आंतरिक अशांति ही था। परंतु इस शब्द की अस्पष्टता और व्यापक दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए 44वें संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया। इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को प्रतिस्थापित किया गया, जिससे भविष्य में किसी भी सरकार द्वारा इस प्रावधान के राजनीतिक दुरुपयोग को रोका जा सके।

7. (A) केवल I और II
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। राष्ट्रपति इसे युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के वास्तविक रूप से घटित होने से पहले भी घोषित कर सकते हैं, यदि वे आश्वस्त हों कि ऐसा कोई आसन्न खतरा विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, आपातकाल को संपूर्ण देश या उसके किसी विशिष्ट भाग पर लागू किया जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि इसे हमेशा बिना किसी अपवाद के केवल संपूर्ण भारत पर ही लागू किया जाए।

8. (C) इसने "आंतरिक अशांति" को "सशस्त्र विद्रोह" से प्रतिस्थापित कर दिया
वर्ष 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 352 में एक अति महत्वपूर्ण और मौलिक परिवर्तन किया। इसके द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के आधार के रूप में प्रयुक्त अस्पष्ट शब्द आंतरिक अशांति को हटाकर उसके स्थान पर स्पष्ट और विशिष्ट शब्द सशस्त्र विद्रोह को प्रतिस्थापित किया गया। यह परिवर्तन 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर लगाए गए आपातकाल के अनुभवों को ध्यान में रखकर किया गया था, ताकि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आपातकालीन शक्तियों के मनमाने प्रयोग को पूरी तरह से रोका जा सके।

NODIA

108. अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं के संदर्भ में, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान राष्ट्रीय आपातकाल को भारत से अलग तरीके से कैसे संभालता है?
(A) इसमें अनुच्छेद 352 के समान एक संहिताबद्ध प्रावधान है जो सभी राज्यों में संकट के दौरान राज्य सरकारों के पूर्ण कार्यपालक अधिग्रहण की अनुमति देता है
(B) इसमें भारत की तरह विशिष्ट आपातकालीन प्रावधान नहीं हैं, बल्कि इसके स्थान पर यह कांग्रेस (संसद) के विधान और बंदी प्रत्यक्षीकरण के निलंबन पर निर्भर करता है
(C) यह राज्य-स्तरीय आपातकाल के दौरान अलग-अलग राज्यों के राज्यपालों को एकतरफा रूप से संघीय कानूनों को निलंबित करने की अनुमति देता है
(D) यह राष्ट्रीय आपातकाल की किसी भी घोषणा को अनुमोदित करने के लिए तीस दिनों के भीतर देशव्यापी जनमत संग्रह को अनिवार्य बनाता है

109. आपातकाल के दौरान कार्यपालिका को मूल अधिकारों को निलंबित करने की अनुमति देने वाला संवैधानिक ढांचा, जिसे भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा अपनाया गया था, किस देश के संविधान को दर्शाता है?
(A) जर्मनी का वाइमर संविधान
(B) फ्रांस का संविधान
(C) कनाडा का संविधान
(D) स्विट्ज़रलैंड का संविधान

110. अनुच्छेद 356 (राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता) का ढांचा सीधे भारत सरकार अधिनियम, 1935 की किस धारा से जुड़ा है?
(A) धारा 45
(B) धारा 93
(C) धारा 102
(D) धारा 112

111. यूनाइटेड किंगडम में, कौन-सा संवैधानिक सिद्धांत लिखित संविधान में आपातकालीन प्रावधानों के संहिताबद्ध समूह की आवश्यकता को काफी हद तक समाप्त करता है?
(A) संप्रभु राजशाही की पूर्ण विशेषाधिकार शक्तियां
(B) कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का कठोर पृथक्करण
(C) संवैधानिक परंपराओं द्वारा स्थापित दोहरा संघीय ढांचा
(D) संसदीय संप्रभुता की अवधारणा

112. अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक घटनाओं का सही क्रमिक क्रम चुनिए:
(A) मंत्रिमंडल की सिफारिश → राष्ट्रपति की उद्घोषणा → संसदीय अनुमोदन → 6 महीने के लिए जारी रहना
(B) राष्ट्रपति की उद्घोषणा → मंत्रिमंडल की सिफारिश → संसदीय अनुमोदन → 6 महीने के लिए जारी रहना
(C) संसदीय संकल्प → मंत्रिमंडल की सिफारिश → राष्ट्रपति की उद्घोषणा → 1 वर्ष के लिए जारी रहना
(D) प्रधानमंत्री की सलाह → राष्ट्रपति की उद्घोषणा → उच्चतम न्यायालय का सत्यापन → संसदीय अनुमोदन

113. संविधान सभा में आपातकालीन प्रावधानों के खिलाफ की गई एक प्रमुख आलोचना यह थी कि वे:
(A) राष्ट्रीय संकटों के दौरान अलग-अलग राज्यों को बहुत अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करते थे, जिससे केंद्र कमजोर होता था
(B) संघ कार्यपालिका के हाथों में अत्यधिक शक्ति केंद्रित करने की प्रवृत्ति रखते थे, जिससे संघीय स्वरुप नष्ट होता था
(C) केंद्र सरकार के लिए युद्ध काल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित करना बहुत कठिन बनाते थे
(D) प्रधानमंत्री और निर्वाचित मंत्रिपरिषद पर राष्ट्रपति को अत्यधिक संवैधानिक शक्तियां देते थे

114. संविधान सभा में आपातकालीन प्रावधानों की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें "प्रतिक्रियाओं और पश्चगमन का एक अध्याय" किसने कहा था?
(A) जवाहरलाल नेहरु
(B) के.एम. मुंशी
(C) अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
(D) एच.वी. कामथ

115. आपातकालीन प्रावधानों के आलोचकों का तर्क है कि वे स्वाभाविक रूप से किसका मार्ग प्रशस्त करने का जोखिम उत्पन्न करते हैं:
(A) मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति की तानाशाही
(B) राज्य स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र
(C) कार्यपालिका पर न्यायिक तानाशाही
(D) वित्तीय संसाधनों का अत्यधिक विकेंद्रीकरण

116. संघीय ढांचे पर वित्तीय आपातकाल के प्रभाव के संबंध में उठाई गई मुख्य चिंता क्या है?
(A) यह केंद्र को अलग-अलग राज्यों के सभी प्राकृतिक संसाधनों को पूरी तरह से जब्त करने की अनुमति देता है
(B) यह राज्य सरकारों को केंद्रीय बैंक के दिशानिर्देशों से स्वतंत्र एक अलग क्षेत्रीय मुद्रा अपनाने के लिए मजबूर करता है
(C) यह व्यावहारिक रूप से राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को समाप्त कर देता है, जिससे वे केंद्र के नियंत्रण में नगरपालिकाओं के समान हो जाते हैं
(D) यह राज्य के मामलों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के लेखा परीक्षा अधिकार को समाप्त कर देता है

117. आपातकालीन प्रावधानों के खिलाफ उठाई गई निम्नलिखित आलोचनाओं पर विचार कीजिए:
I. संविधान का संघीय ढांचा नष्ट हो जाता है, जिससे संघ सर्वशक्तिमान हो जाता है।
II. राष्ट्रपति के तानाशाह बनने का जोखिम रहता है।

Downloaded from www.pdf.tube

(D) अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

64. 1975 के बाद शुरु किए गए सुरक्षा उपायों के अनुसार, अनुच्छेद 19 के तहत मूल स्वतंत्रताएं केवल तभी स्वतः निलंबित होती हैं जब आपातकाल किस आधार पर घोषित किया जाता है?
(A) क्षेत्र के किसी भी भाग में सशस्त्र विद्रोह
(B) गंभीर आंतरिक अशांति या नागरिक असंतोष
(C) युद्ध या बाह्य आक्रमण
(D) राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होना

65. 44वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संसदीय अनुमोदन की समय-सीमा को घटाकर कितना कर दिया?
(A) छह महीने से तीन महीने
(B) तीन महीने से दो महीने
(C) दो महीने से एक महीने
(D) एक महीने से 14 दिन

66. आपातकालीन उपबंधों में 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा लाए गए परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसने "आंतरिक अशांति" को "सशस्त्र विद्रोह" से प्रतिस्थापित कर दिया।
II. इसने आपातकाल के संसदीय अनुमोदन के लिए 'विशेष बहुमत' की आवश्यकता लागू की।
III. इसने लोकसभा को राष्ट्रीय आपातकाल के निरसन के लिए साधारण बहुमत से संकल्प पारित करने का अधिकार दिया।
IV. इसने वित्तीय आपातकाल घोषित करने की राष्ट्रपति की शक्ति को समाप्त कर दिया।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

67. अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश स्थापित करने वाला उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला 'एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ' के मामले में किस वर्ष सुनाया गया था?
(A) 1980
(B) 1990
(C) 1994
(D) 1998

68. एस.आर. बोम्मई मामले में अनुच्छेद 356 के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित केंद्रीय कानूनी सिद्धांत क्या था?
(A) अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की उद्घोषणा एक राजनीतिक प्रश्न है जो न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह मुक्त है
(B) राज्यपाल की रिपोर्ट एक वैकल्पिक प्रशासनिक इनपुट है और राज्य में अनुच्छेद 356 लगाने के लिए अनिवार्य नहीं है
(C) अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की उद्घोषणा दुर्भावना या अप्रासंगिक आधारों की जांच के लिए न्यायिक समीक्षा के अधीन है
(D) राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के अनुमोदन में संसद की कोई संवैधानिक भूमिका नहीं है

69. एस.आर. बोम्मई फैसले के अनुसार, यह परीक्षण करने का उचित और निर्णायक तरीका क्या है कि कोई राज्य सरकार विधानसभा का विश्वास प्राप्त करती है या नहीं?
(A) विधानसभा के पटल पर बहुमत परीक्षण (फ्लोर टेस्ट)
(B) राज्यपाल का व्यक्तिगत मूल्यांकन
(C) विधायकों द्वारा राज्यपाल को सौंपे गए समर्थन पत्र
(D) निर्वाचन आयोग द्वारा कराया गया गुप्त मतदान

70. एस.आर. बोम्मई मामले में, उच्चतम न्यायालय ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में सरकारों की बर्खास्तगी को बरकरार रखा, और यह बल दिया कि संविधान की 'मूल विशेषता' कौन-सी है?
(A) संघवाद
(B) संसदीय लोकतंत्र
(C) न्यायिक स्वतंत्रता
(D) धर्मनिरपेक्षता

NODIA

71. राज्य विधानसभाओं के मनमाने विघटन के खिलाफ एक सुरक्षा उपाय के रूप में, एस.आर. बोम्मई मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के लागू होने के दौरान राज्य विधानमंडल के संबंध में क्या फैसला सुनाया?
(A) राष्ट्रपति को उद्घोषणा जारी करने के तुरंत बाद औपचारिक रूप से राज्य विधानसभा को भंग कर देना चाहिए
(B) जब तक उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता, तब तक विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता है
(C) राज्यपाल के पास संकट के दौरान किसी भी समय विधानसभा को भंग करने की एकमात्र विवेकाधीन शक्ति बनी रहती है
(D) विधानसभा को स्वतः ही ठीक 3 वर्षों की एक निश्चित अवधि के लिए निलंबित अवस्था में रखा जाना चाहिए

72. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: ऐतिहासिक निर्णय
P. एस.आर. बोम्मई मामला (1994)
Q. मिनर्वा मिल्स मामला (1980)
R. ए.डी.एम. जबलपुर मामला (1976)
S. रामेश्वर प्रसाद मामला (2006)
सूची II: प्रमुख कानूनी निष्कर्ष
1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) को दुर्भावना के

2016 में दो उल्लेखनीय राज्य जहाँ ऐसा हुआ था, वे कौन-से थे?
(A) कर्नाटक और गोवा
(B) महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश
(C) उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश
(D) राजस्थान और गुजरात

127. अनुच्छेद 352 में "सशस्त्र विद्रोह" वाक्यांश से संबंधित समकालीन बहस मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है?
(A) आंतरिक आपातकाल की किसी भी घोषणा को स्थायी रूप से रोकने के लिए इस वाक्यांश को पूरी तरह से हटाना
(B) बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों को शामिल करने के लिए इसकी परिभाषा का विस्तार करना
(C) इसे पुनः मूल संवैधानिक वाक्यांश "आंतरिक अशांति" में परिवर्तित करना
(D) क्या बड़े पैमाने पर आतंकवाद या उग्रवाद सशस्त्र विद्रोह के रूप में योग्य है

128. 1991 में गंभीर भुगतान संतुलन संकट का सामना करने के बावजूद, भारत ने वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की। यह क्या रेखांकित करता है?
(A) संविधान अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से स्पष्ट अनुमति के बिना वित्तीय आपातकाल घोषित करने की मनाही करता है
(B) राष्ट्रपति ने 1991 में मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तुत उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था
(C) "वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा" की सीमा अत्यधिक उच्च है और इसे अंतिम संवैधानिक उपाय के रूप में देखा जाता है
(D) उस समय वित्तीय आपातकाल का संकल्प पारित करने के लिए संसद में आवश्यक विशेष बहुमत का अभाव था

129. अनुच्छेद 356 से संबंधित बहसों की समकालीन प्रासंगिकता अक्सर किसकी पक्षपातपूर्ण भूमिका पर केंद्रित होती है?
(A) राज्य निर्वाचन आयुक्त
(B) राज्य के राज्यपाल
(C) लोकसभा अध्यक्ष
(D) राज्य के मुख्य सचिव

130. वर्तमान में, केंद्र सरकार द्वारा आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग के खिलाफ अंतिम सुरक्षा उपाय मुख्य रूप से किसमें निहित है?
(A) राष्ट्रपति में निहित पूर्ण कार्यपालक वीटो शक्ति
(B) अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का त्वरित राजनयिक हस्तक्षेप और देखरेख
(C) राज्य सरकारों द्वारा बनाए रखी गई निरपेक्ष वित्तीय स्वतंत्रता
(D) न्यायिक समीक्षा का मजबूत तंत्र और एक सक्रिय बहुदलीय संसद

Click Here to Buy book on Flipkart

(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है

82. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अनुच्छेद 358 की प्रयोज्यता के अपवाद की सटीक पहचान करता है?
(A) यह उन भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है जो सशस्त्र बलों में सेवा कर रहे हैं
(B) यह गैर-नागरिकों या वर्तमान में भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होता है
(C) यह स्वायत्त राज्य विधानमंडलों द्वारा स्वतंत्र रूप से बनाए गए राज्य कानूनों पर लागू नहीं होता है
(D) यह तब लागू नहीं होता जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है

83. अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालयों में जाने के अधिकार के निलंबन के लिए क्या आवश्यक है?
(A) एक विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश
(B) एक संवैधानिक संशोधन
(C) उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा पारित एक संकल्प
(D) आपातकाल की घोषणा का स्वतः संचालन

84. अनुच्छेद 359 के तहत जारी राष्ट्रपति के आदेश के क्षेत्रीय विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) इसका संपूर्ण भारत में विस्तार होना आवश्यक है
(B) यह केवल "अशांत क्षेत्र" घोषित क्षेत्रों पर लागू होता है
(C) इसका विस्तार भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग पर हो सकता है
(D) यह केवल विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों पर लागू होता है

85. यदि किसी कानून को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करने के लिए चुनौती दी जाती है, तो अनुच्छेद 358 और 359 के तहत उन्मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसे किस शर्त को पूरा करना होगा?
(A) इसमें यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि यह कानून राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में है
(B) इसे आपातकालीन बैठक के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए
(C) इसे पहले से उच्चतम न्यायालय की पीठ द्वारा औपचारिक रूप से समीक्षित और अनुमोदित होना चाहिए
(D) यह प्रकृति में सख्ती से अस्थायी होना चाहिए, जो 3 महीने से अधिक समय तक लागू न रहे

86. अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए:
I. अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 तक सीमित है, जबकि अनुच्छेद 359 उन सभी मूल अधिकारों तक विस्तृत है जिनका प्रवर्तन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया जाता है।
II. अनुच्छेद 358 अधिकारों को स्वतः निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 स्वतः किसी अधिकार को निलंबित नहीं करता है।
III. अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल की स्थिति में लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 359 बाह्य और आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

87. अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के बावजूद, व्यक्ति अभी भी उपचार प्राप्त करने के लिए न्यायालय का रुख कर सकते हैं यदि उनकी हिरासत किसका उल्लंघन करती है:
(A) भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता और निवास की स्वतंत्रता
(B) अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
(C) बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार और संघ बनाने की स्वतंत्रता
(D) अल्पसंख्यकों के हितों का सांस्कृतिक और शैक्षिक संरक्षण

88. भारतीय संविधान में निर्धारित तीन प्रकार के आपातकाल में से कौन-सा आज तक कभी घोषित नहीं किया गया है?
(A) बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल
(B) आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल
(C) वित्तीय आपातकाल
(D) किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन

89. विभिन्न आपातकाल के लिए आवश्यक संसदीय अनुमोदन बहुमत की तुलना कीजिए। किस संयोजन के लिए केवल "साधारण बहुमत" की आवश्यकता होती है?
(A) राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन
(B) राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल
(C) राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं; सभी के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है

90. किस प्रकार का आपातकाल हर छह महीने में बार-बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता के बिना अनिश्चित काल के लिए जारी रह सकता है?
(A) वित्तीय आपातकाल
(B) अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल
(C) अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन
(D) राज्य आपातकाल / संवैधानिक आपातकाल

91. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की तुलना में राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान राज्य कार्यपालिका की स्थिति में क्या मौलिक अंतर है?
(A) अनुच्छेद 352 के तहत, राज्य कार्यपालिका को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता है; अनुच्छेद 356 के तहत, यह

NODIA

9. (D) बाह्य आपातकाल
जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है, तो इसे संवैधानिक शब्दावली में बाह्य आपातकाल कहा जाता है। दूसरी ओर, जब आपातकाल की घोषणा देश के भीतर होने वाले सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है, तो उसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। बाह्य आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों और केंद्र-राज्य संबंधों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है तथा अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती हैं।

10. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है
भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के प्रवर्तन को भारत के किसी निर्दिष्ट भौगोलिक भाग तक सीमित कर सकते हैं। यह प्रावधान मूल संविधान में मौजूद नहीं था, बल्कि वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संशोधन ने राष्ट्रपति को यह शक्ति दी कि यदि संकट किसी विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित है, तो आपातकाल की घोषणा को केवल उसी निर्दिष्ट क्षेत्र तक सीमित रखा जाए। अतः अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण अभिकथन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है।

11. (B) केंद्रीय मंत्रिमंडल
संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार, राष्ट्रपति केवल तब ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं जब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिखित रूप में ऐसी सिफारिश प्राप्त हो। यह सुरक्षात्मक प्रावधान वर्ष 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रधानमंत्री अकेले या एकतरफा निर्णय लेकर राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की सलाह न दे सकें, जैसा कि वर्ष 1975 में हुआ था। इसमें संपूर्ण कैबिनेट की लिखित सहमति अनिवार्य बनाई गई है।

12. (A) I, II, IV, III
राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया में सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को लिखित सिफारिश भेजी जाती है। इसके पश्चात राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की औपचारिक उद्घोषणा की जाती है। उद्घोषणा जारी होने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। अंत में, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करके इसे स्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार सही प्रक्रियात्मक क्रम I, II, IV, और III है, जो संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

13. (B) एक महीने के भीतर
राष्ट्रपति द्वारा जारी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। मूल संविधान में यह समय-सीमा दो महीने निर्धारित की गई थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे घटाकर एक महीने कर दिया गया। यदि एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदन इसे अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं करते हैं, तो आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः समाप्त और निष्प्रभावी हो जाती है।

14. (C) दोनों सदनों में विशेष बहुमत
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा या इसके जारी रहने के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। इस विशेष बहुमत का अर्थ है सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत। वर्ष 1978 के 44वें संविधान संशोधन से पूर्व इसे साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जा सकता था, परंतु आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कठोर विशेष बहुमत की आवश्यकता को लागू किया गया।

15. (D) पुनर्गठित नई लोकसभा की पहली बैठक की तारीख से 30 दिनों तक, शर्त यह है कि राज्यसभा ने इसे अनुमोदित कर दिया हो
यदि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय लोकसभा भंग हो गई हो या इसका विघटन एक महीने के भीतर हो जाता है, तो यह उद्घोषणा पुनर्गठित नई लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों तक लागू रहती है। हालांकि इसके लिए यह शर्त अनिवार्य है कि राज्यसभा ने इस अवधि के दौरान आपातकाल का अनुमोदन कर दिया हो। यदि नई लोकसभा अपनी पहली बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस उद्घोषणा को अनुमोदित नहीं करती है, तो आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाता है।

NODIA

16. (C) वे निलंबित नहीं होती हैं, लेकिन संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की समवर्ती शक्ति प्राप्त हो जाती है
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां निलंबित या भंग नहीं की जाती हैं। राज्य विधानमंडल अपने सामान्य कार्यों को संचालित करता रहता है, परंतु संसद को राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाने की समवर्ती शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार संसद की विधायी शक्ति का विस्तार राज्य सूची तक हो जाता है। यद्यपि राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है, किंतु संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य के कानून में विरोधाभास होने पर संसदीय कानून ही मान्य होता है।

17. (B) केवल I, II और III
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र की कार्यपालक शक्ति का विस्तार राज्य को कार्यपालक शक्तियों के संचालन संबंधी निर्देश देने तक होता है। संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने हेतु पूर्णतः सक्षम हो जाती है तथा राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण को संशोधित कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान राज्य सरकारों को बर्खास्त नहीं किया जाता है और न ही राज्य विधानमंडलों को निलंबित किया जाता है। राज्य सरकारें केंद्र के निर्देशों के अधीन रहकर कार्य करती रहती हैं। अतः चतुर्थ कथन असत्य है।

18. (B) छह महीने
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल के समाप्त होने के बाद अधिकतम छह महीने की अवधि तक ही प्रभावी रहता है। छह महीने की इस समयावधि के बीत जाने पर ऐसा कानून स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामान्य स्थितियां बहाल होने पर राज्यों की संवैधानिक स्वायत्तता और विधायी अधिकार पुनः अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएं तथा केंद्र का अस्थायी विधायी हस्तक्षेप समाप्त हो सके।

19. (A) इसे संसद द्वारा कानून बनाकर एक बार में एक वर्ष के लिए, कितनी भी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है
राष्ट्रीय आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान संसद कानून बनाकर लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इस प्रकार इसे कितनी भी अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। परंतु आपातकाल के समाप्त हो जाने की स्थिति में extended कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में छह महीने से अधिक समय तक जारी नहीं रह सकता है। यही नियम और प्रक्रिया राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ाने के संदर्भ में भी पूरी तरह लागू होती है।

20. (C) उस वित्तीय वर्ष के अंत तक जिसमें आपातकाल समाप्त होता है
यदि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित करने वाला कोई आदेश जारी करते हैं, तो ऐसा आदेश उस वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू रहता है जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। राष्ट्रपति का ऐसा प्रत्येक आदेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में वित्तीय संसाधनों को राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा आवश्यकताओं की ओर मोड़ने हेतु केंद्र सरकार को पर्याप्त वित्तीय लचीलापन और सामर्थ्य प्रदान करना है।

21. (A) P-2, Q-4, R-3, S-1
अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 358 बाह्य आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं के स्वतः निलंबन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान निर्दिष्ट मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति देता है। अतः सही सुमेलन विकल्प A के अनुसार P-2, Q-4, R-3, S-1 है।

22. (D) युद्ध या बाह्य आक्रमण
अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा दी गई छह मूल स्वतंत्रताएं केवल तब स्वतः निलंबित होती हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो। वर्ष 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट व्यवस्था की गई कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जाता है, तो अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाले अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होंगे। यह संशोधन आंतरिक आधार पर नागरिक स्वतंत्रताओं के अनियंत्रित हनन को रोकने के लिए किया गया था।

23. (C) अनुच्छेद 20 और 21
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह ऐतिहासिक सुरक्षात्मक प्रावधान जोड़ा गया कि अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। आपातकाल के समय भी किसी व्यक्ति को इन मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता और इनके प्रवर्तन हेतु न्यायालय जाने का अधिकार बना रहता है।

24. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 स्वतः किसी भी मूल अधिकार को निलंबित नहीं करता है। इसके बजाय, यह राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे एक विशेष आदेश जारी करके निर्दिष्ट मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के नागरिक अधिकार को निलंबित कर सकें। मूल अधिकार स्वयं बने रहते हैं, केवल उनके कानूनी प्रवर्तन का अधिकार अस्थायी रूप से स्थगित होता है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन की व्याख्या प्रस्तुत करता है।

25. (D) अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल की स्थिति में लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 359 बाह्य और आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है
अनुच्छेद 358 केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण से उत्पन्न बाह्य आपातकाल में ही लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 359 बाह्य तथा सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आंतरिक आपातकाल दोनों स्थितियों में लागू होता है। अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अधिकारों को स्वतः निलंबित करता है, जबकि अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्दिष्ट अन्य अधिकारों के उपचारों को निलंबित करता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 359 देश के किसी भाग विशेष में लागू हो सकता है।

26. (A) राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य आधारों पर
संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होती है या उन्हें अन्य माध्यमों से यह समाधान हो जाता है कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, तो वे राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की औपचारिक रिपोर्ट के बिना भी स्व-विवेक या अन्य विश्वसनीय जानकारियों के आधार पर यह कदम उठाने के लिए संवैधानिक रूप से पूरी तरह सशक्त हैं।

Downloaded from www.pdf.tube

27. (B) राज्य केंद्र के किसी भी निर्देश का अनुपालन करने या उसे प्रभावी करने में विफल रहता है
अनुच्छेद 365 यह स्पष्ट करता है कि यदि कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए किसी भी संवैधानिक निर्देश का अनुपालन करने या उसे प्रभावी बनाने में विफल रहती है, तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना पूर्णतः वैध और कानूनी होगा कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश जारी कर सकते हैं।

28. (B) यह एक सशर्त शक्ति है जो दुर्भावना के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है
अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की राष्ट्रपति की शक्ति निरपेक्ष या अंतिम नहीं है, बल्कि यह एक सशर्त शक्ति है। एस.आर. बोम्मई मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति का यह समाधान वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित होना चाहिए। यदि यह निर्णय दुर्भावनापूर्ण, असंगत या अप्रासंगिक आधारों पर लिया गया है, तो न्यायालय इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है और असंवैधानिक पाए जाने पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को रद्द करके पूर्व सरकार को बहाल कर सकता है।

29. (D) I, II और III
एस.आर. बोम्मई मामले में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार, राष्ट्रपति शासन लगाने के कई वैध आधार स्वीकार किए गए हैं। इसमें आम चुनावों के बाद विधानसभा में त्रिशंकु स्थिति उत्पन्न होना, मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र के बाद वैकल्पिक सरकार का न बनना तथा राज्य सरकार द्वारा जानबूझकर संविधान के विरुद्ध कार्य करना शामिल हैं। ये सभी परिस्थितियां राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता को दर्शाती हैं, इसलिए इन आधारों पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग पूरी तरह से उचित और न्यायसंगत माना गया है।

30. (C) राज्य में सत्तारुढ़ दल को लोकसभा के आम चुनावों में भारी हार का सामना करना पड़ता है
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के अनुसार, केवल लोकसभा चुनावों में राज्य के सत्तारुढ़ दल की पराजय राष्ट्रपति शासन लगाने का वैध आधार नहीं हो सकती। किसी राज्य सरकार को केवल इसलिए बर्खास्त नहीं किया जा सकता कि केंद्रीय चुनावों में उसके दल का प्रदर्शन खराब रहा है। यदि राज्य सरकार को अपनी विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त है और वह संवैधानिक मर्यादाओं के अनुसार कार्य कर रही है, तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग पूरी तरह असंवैधानिक और अवैध माना जाता है।

31. (B) दो महीने
अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने वाली उद्घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। यदि राष्ट्रपति शासन ऐसे समय में लागू किया जाता है जब लोकसभा भंग हो, तो यह नई लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों तक लागू रहता है, बशर्ते राज्यसभा ने इसे दो महीने के भीतर मंजूरी दे दी हो। संसद द्वारा स्वीकृत न होने पर यह उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाती है।

NODIA

32. (C) साधारण बहुमत
अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा को अनुमोदित करने के लिए संसद में केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत का तात्पर्य प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से है। इसके विपरीत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अतः राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव को अपेक्षाकृत सरल संसदीय प्रक्रिया द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

33. (C) तीन वर्ष
संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रपति शासन छह महीने की अवधि तक प्रभावी रहता है। इसे संसद द्वारा प्रत्येक छह महीने में पुनः अनुमोदित करके अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। तीन वर्ष की यह सीमा संवैधानिक रूप से निर्धारित अधिकतम सीमा है। तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक होता है, जैसा कि अतीत में पंजाब राज्य के मामले में किया गया था।

34. (D) राष्ट्रीय आपातकाल लागू होना चाहिए, या निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने में कठिनाइयों का प्रमाणन करना चाहिए
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाने हेतु दो विशिष्ट शर्तों में से किसी एक का पूरा होना अनिवार्य है। पहली शर्त यह है कि संपूर्ण भारत या राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। दूसरी शर्त यह है कि निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि राज्य में विधानसभा चुनाव कराना कठिन है। इन शर्तों के बिना राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।

35. (B) निर्वाचन आयोग चुनाव कराने में असमर्थता का प्रमाणन करता है → संसद साधारण बहुमत से संकल्प पारित करती है → विस्तार प्रभावी होता है
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से अधिक की अवधि तक बढ़ाने के लिए सही प्रक्रियात्मक क्रम आवश्यक है। सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करता है कि संबंधित राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है। इस प्रमाणन के पश्चात संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से राष्ट्रपति शासन के विस्तार का संकल्प पारित करते हैं। इसके उपरांत राष्ट्रपति शासन का विस्तार प्रभावी होता है। यह व्यवस्था अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाई गई है।

36. (C) राज्य के राज्यपाल
जब किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो राज्य की कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति

तथा चौथे अवसर पर बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्पन्न परिस्थितियों के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।

74. (A) 1967
राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन मार्च 1967 में लगाया गया था। वर्ष 1967 के चौथे आम चुनावों के बाद राज्य विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, जिससे त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस राजनीतिक अस्थिरता और अस्पष्ट बहुमत के कारण 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। यह भारत के इतिहास में त्रिशंकु विधानसभा के कारण राष्ट्रपति शासन लगाने के शुरुआती उदाहरणों में से एक था।

75. (B) हरिदेव जोशी
वर्ष 1977 में केंद्र में सत्ता में आई जनता पार्टी सरकार ने नौ राज्यों की कांग्रेस सरकारों को सामूहिक रूप से बर्खास्त कर दिया था। उस समय राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे। अप्रैल 1977 में हरिदेव जोशी सरकार को बर्खास्त करके राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। यह राष्ट्रपति शासन जून 1977 तक लागू रहा, जिसके बाद नए विधानसभा चुनाव कराए गए और राज्य में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ।

76. (B) भैरों सिंह शेखावत
दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद उत्पन्न परिस्थितियों के कारण राजस्थान में चौथी और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उस समय राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। केंद्र सरकार ने धर्मनिरपेक्षता के उल्लंघन का हवाला देते हुए शेखावत सरकार को बर्खास्त कर दिया था। यह राष्ट्रपति शासन दिसंबर 1992 से दिसंबर 1993 तक लगभग एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहा था।

77. (B) II, I, III, IV
राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्रियों का सही कालानुक्रमिक क्रम II, I, III, IV है। सर्वप्रथम 1967 में प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय मोहन लाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे। दूसरे राष्ट्रपति शासन (1977) के समय हरिदेव जोशी राज्य के मुख्यमंत्री थे। तीसरे राष्ट्रपति शासन (1980 बर्खास्तगी) के समय भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। तथा चौथे राष्ट्रपति शासन (1992 बर्खास्तगी) के समय भी भैरों सिंह शेखावत ही राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे।

78. (B) वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अन्य स्वतंत्रताओं का अधिकार (अनुच्छेद 19)
जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 358 के तहत संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त छह मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इन स्वतंत्रताओं में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन, संघ बनाने, भारत में अबाध संचरण, निवास तथा कोई भी व्यापार या आजीविका अपनाने की स्वतंत्रताएं शामिल हैं। इसके लिए किसी पृथक या विशेष राष्ट्रपति आदेश की आवश्यकता नहीं होती है।

79. (D) यह स्वतः ही संपूर्ण देश पर लागू होता है
जब संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र के लिए बाह्य आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 358 का प्रभाव स्वतः ही संपूर्ण देश पर लागू हो जाता है। इसके तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित सभी मौलिक स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती हैं। राज्य सरकारें और संसद ऐसा कोई भी कानून बना सकती हैं या कार्यपालक कदम उठा सकती हैं जो अनुच्छेद 19 के असंगत हो। इसके लिए किसी क्षेत्रीय सीमा या विशिष्ट राज्य-वार आदेश जारी करने की कानूनी आवश्यकता नहीं होती है।

80. (C) राष्ट्रीय आपातकाल की पूरी अवधि के लिए
अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक स्वतंत्रताओं का स्वतः निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए बना रहता है। जैसे ही राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लिया जाता है या यह समाप्त होता है, अनुच्छेद 358 का प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाता है और अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाले सभी मौलिक अधिकार स्वतः पुनर्जीवित हो जाते हैं। इसके लिए अलग से कोई आदेश या संवैधानिक प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है।

81. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है
राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने के बाद, आपातकाल के दौरान बनाए गए उन कानूनों या कार्यपालक कार्रवाइयों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती जो उस समय अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 358 आपातकाल के दौरान की गई ऐसी विधायी और कार्यपालक कार्रवाइयों को आपातकाल के बाद भी कानूनी उन्मुक्ति एवं संरक्षण प्रदान करता है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन का बिल्कुल सटीक और विधिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है।

82. (D) यह तब लागू नहीं होता जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद यह महत्वपूर्ण सीमा निर्धारित की गई कि अनुच्छेद 358 तब लागू नहीं होता जब राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह (आंतरिक आपातकाल) के आधार पर घोषित किया गया हो। अनुच्छेद 358 का स्वतः संचालन केवल और केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण (बाह्य आपातकाल) की स्थिति में ही होता है। यदि आपातकाल का आधार सशस्त्र विद्रोह है, तो अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को मिलने वाले मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होते हैं।

83. (A) एक विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश
अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालयों में जाने के अधिकार को निलंबित करने हेतु एक विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश जारी करना अनिवार्य होता है। यह स्वतः संचालित नहीं होता है। राष्ट्रपति अपने आदेश में उन विशिष्ट मूल अधिकारों का उल्लेख करते हैं जिनके प्रवर्तन का अधिकार

Click Here to Buy book on Amazon

आर्थिक संकट से निपटने के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने हेतु बनाया गया है।

46. (A) केवल I, II और IV
वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्यों को वित्तीय औचित्य के नियमों का पालन करने का निर्देश दे सकता है, राज्य के सभी धन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जा सकता है, तथा सरकारी कर्मचारियों और न्यायाधीशों के वेतनों में कटौती की जा सकती है। हालांकि इसके निरंतर जारी रहने के लिए हर छह महीने में संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार पारित होने पर यह अनिश्चित काल तक लागू रहता है। अतः तीसरा कथन असत्य है।

47. (D) P-2, Q-3, R-4, S-1
वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान NEFA में चीनी आक्रमण के कारण पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। वर्ष 1971 में पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के समय दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ। वर्ष 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। वर्ष 1977 में 1971 और 1975 के आपातकाल को वापस लिया गया। अतः सही सुमेलन P-2, Q-3, R-4, S-1 है, जो भारतीय इतिहास के इन ऐतिहासिक घटनाक्रमों को स्पष्ट करता है।

48. (C) 1968
भारत में प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अक्टूबर 1962 में उत्तर-पूर्वी सीमांत एजेंसी (NEFA) पर चीनी आक्रमण के समय की गई थी। यह आपातकाल जनवरी 1968 तक लागू रहा, जब इसे औपचारिक रूप से वापस लिया गया। इस अवधि के दौरान वर्ष 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध भी घटित हुआ था। यह आपातकाल बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू किया गया था और इसने लगभग छह वर्षों तक देश की प्रशासनिक एवं विधायी व्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित किया था।

49. (B) इसकी घोषणा तब की गई थी जब 1971 का आपातकाल (बाह्य आक्रमण के आधार पर) पहले से ही लागू था
जून 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की एक अद्वितीय ऐतिहासिक विशेषता यह थी कि इसकी घोषणा तब की गई जब वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय लगाया गया बाह्य आपातकाल पहले से ही लागू था। 1971 का आपातकाल बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू था, जबकि 25 जून 1975 को घोषित नया आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया गया था। इस प्रकार देश में एक ही समय में दो अलग-अलग आपातकालीन उद्घोषणाएं एक साथ अस्तित्व में आ गई थीं।

50. (D) फखरुद्दीन अली अहमद
25 जून 1975 को भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने हस्ताक्षर किए थे। यह उद्घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर जारी की गई थी। राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की औपचारिक बैठक और पूर्व लिखित सहमति के बिना ही केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस घटना ने बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा कैबिनेट की लिखित सलाह को अनिवार्य बनाने का मार्ग प्रशस्त किया।

51. (B) 1977
वर्ष 1971 (पाकिस्तान युद्ध के समय बाह्य आधार पर लागू) तथा वर्ष 1975 (आंतरिक अशांति के आधार पर लागू) के दोनों राष्ट्रीय आपातकाल मार्च 1977 में औपचारिक रूप से वापस ले लिए गए थे। मार्च 1977 में हुए छठे लोकसभा चुनावों के ठीक बाद, जिसमें जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी, इन दोनों आपातकालीन उद्घोषणाओं को रद्द कर दिया गया। आपातकाल के हटने के साथ ही देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं और नागरिकों के मौलिक अधिकार पूर्णतः बहाल हो गए।

52. (C) इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा राज नारायण मामले का निर्णय
12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने राज नारायण मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1971 के रायबरेली लोकसभा निर्वाचन को चुनावी धांधली का दोषी मानते हुए रद्द कर दिया था। इस फैसले ने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने पर गंभीर कानूनी और नैतिक संकट खड़ा कर दिया। इस राजनीतिक व विधिक संकट के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के बीच 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया।

NODIA

53. (A) आंतरिक अशांति
वर्ष 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल तत्कालीन संविधान के अनुच्छेद 352 में विद्यमान शब्दावली आंतरिक अशांति के तहत लागू किया गया था। इस प्रावधान का प्रयोग करते हुए सरकार ने तर्क दिया कि देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति और राजनीतिक आंदोलन सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। इस शब्द का अत्यंत व्यापक और मनमाना प्रयोग किए जाने के कारण, 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को स्थापित कर दिया गया।

54. (D) नवनिर्माण आंदोलन और संपूर्ण क्रांति
1975 के आपातकाल की पृष्ठभूमि में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चलाया गया संपूर्ण क्रांति आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण कारक था। इसकी शुरुआत गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन और बिहार के छात्र आंदोलन से हुई थी। जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जनता तथा छात्रों को संगठित किया और देश में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक बदलाव के लिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जिसने तत्कालीन केंद्र सरकार के समक्ष अत्यधिक गंभीर राजनीतिक चुनौती प्रस्तुत की थी।

55. (A) केवल I और II
1975 के आपातकाल की पृष्ठभूमि में 1971 के युद्ध के बाद का गंभीर आर्थिक संकट, बढ़ती मुद्रास्फीति तथा मई 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई ऐतिहासिक देशव्यापी रेलवे हड़ताल मुख्य कारक थे। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद

में निहित हो जाती हैं। राष्ट्रपति की ओर से राज्य का प्रत्यक्ष शासन और प्रशासन राज्य के राज्यपाल द्वारा चलाया जाता है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सलाहकारों या राज्य के मुख्य सचिव की सहायता से प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इस स्थिति में राज्य की मंत्रिपरिषद को भंग या निलंबित कर दिया जाता है और शासन पूरी तरह केंद्रीय नियंत्रण में आ जाता है।

37. (A) इसे राष्ट्रपति द्वारा या तो निलंबित कर दिया जाता है या भंग कर दिया जाता है
राष्ट्रपति शासन की घोषणा के साथ ही राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को या तो निलंबित कर सकते हैं या पूरी तरह भंग कर सकते हैं। यदि विधानसभा को निलंबित किया जाता है, तो संसदीय अनुमोदन प्राप्त होने के बाद उसे पुनः बहाल किया जा सकता है या भंग किया जा सकता है। एस.आर. बोम्मई मामले के अनुसार, जब तक संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन नहीं कर देते, तब तक विधानसभा को भंग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि केवल निलंबित रखा जाना चाहिए।

38. (D) तब तक लागू रहते हैं जब तक कि उन्हें राज्य विधानमंडल द्वारा निरस्त या परिवर्तित न कर दिया जाए
राष्ट्रपति शासन की अवधि के दौरान संबंधित राज्य के लिए संसद या राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रपति शासन के निरस्त होने के बाद भी स्वतः समाप्त नहीं होते। वे कानून तब तक निरंतर लागू और प्रभावी रहते हैं जब तक कि पुनर्गठित राज्य विधानमंडल द्वारा उन्हें निरस्त, संशोधित या पुनः अधिनियमित न कर दिया जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के बाद राज्य में कानूनी शून्यता की स्थिति उत्पन्न न हो।

39. (B) राज्य का उच्च न्यायालय
अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के दौरान, राष्ट्रपति राज्य सरकार और राज्यपाल की सभी शक्तियां स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, परंतु वे राज्य उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। संविधान स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से संबंधित किसी भी संवैधानिक प्रावधान को निलंबित करने या उसकी शक्तियों में हस्तक्षेप करने से रोकता है। उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति, स्वतंत्रता और न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति शासन के दौरान भी पूरी तरह अक्षुण्ण बनी रहती हैं।

40. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है
राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य उच्च न्यायालय की शक्तियों को ग्रहण करने से राष्ट्रपति को संवैधानिक रूप से रोका गया है। इसका कारण यह है कि संविधान का अनुच्छेद 356(1) स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से संबंधित संवैधानिक उपबंधों को निलंबित नहीं कर सकते हैं। उच्च न्यायालय की स्थिति, अधिकार क्षेत्र और स्वतंत्रता राष्ट्रपति शासन से पूरी तरह अप्रभावित रहती है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण अभिकथन का बिल्कुल सही संवैधानिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है।

41. (D) संसद
जब राष्ट्रपति शासन के तहत किसी राज्य की विधानसभा निलंबित या भंग हो जाती है, तो उस राज्य की विधायी शक्तियां संसद को हस्तांतरित हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात् राज्य बजट को स्वीकृत और पारित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व भारत की संसद का होता है। यदि संसद का सत्र न चल रहा हो, तो राष्ट्रपति भारत की संचित निधि में से राज्य के व्यय हेतु अग्रिम स्वीकृति दे सकते हैं, जिसे बाद में संसद से पारित कराना होता है।

42. (A) भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र के भाग की वित्तीय स्थिरता या साख संकट में है, तो वे वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यह घोषणा संपूर्ण देश या इसके किसी विशिष्ट भाग के लिए की जा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक संकट के समय देश की वित्तीय साख को बनाए रखना और आर्थिक व्यवस्था को संतुलित करना है।

43. (B) दो महीने
वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा भंग हो, तो यह नई लोकसभा की पहली बैठक के बाद 30 दिनों तक लागू रहती है, बशर्ते इस दौरान राज्यसभा ने इसे स्वीकृत कर दिया हो। यदि संसद के दोनों सदन दो महीने के भीतर इसे अपनी मंजूरी नहीं देते, तो यह उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाती है।

44. (D) कोई अधिकतम सीमा नहीं है; यह तब तक अनिश्चित काल के लिए जारी रहता है जब तक कि इसे रद्द न कर दिया जाए
एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद, वित्तीय आपातकाल तब तक अनिश्चित काल के लिए जारी रहता है जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा इसे वापस या रद्द न कर दिया जाए। इसके जारी रहने के लिए संसद द्वारा बार-बार या आवधिक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। संविधान में वित्तीय आपातकाल के प्रवर्तन की कोई अधिकतम समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। राष्ट्रपति किसी भी समय एक अनुवर्ती उद्घोषणा जारी करके वित्तीय आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं।

45. (A) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों में कटौती
वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करने के निर्देश दे सकती है। इसके अलावा, एक अत्यंत असाधारण कार्रवाई के रूप में, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित संघ की सेवा करने वाले सभी या किसी भी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती करने के निर्देश जारी कर सकते हैं। यह प्रावधान देश के गंभीर

Downloaded from www.pdf.tube

विद्रोह के आधार पर लागू किया जाता है, तो अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाले अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होते हैं। यह व्यवस्था नागरिक स्वतंत्रताओं के अनियंत्रित और मनमाने हनन को रोकती है।

65. (C) दो महीने से एक महीने
वर्ष 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संसदीय अनुमोदन की समय-सीमा को दो महीने से घटाकर एक महीने कर दिया। मूल संविधान में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित किए जाने के बाद संसद से मंजूरी लेने के लिए दो महीने का समय दिया गया था। परंतु इस अवधि में कार्यपालिका के मनमाने प्रयोग को सीमित करने के उद्देश्य से संसद की पूर्व स्वीकृति की प्रक्रिया को अधिक त्वरित और कठोर बनाते हुए समय-सीमा एक महीने कर दी गई।

66. (A) केवल I, II और III
44वें संविधान संशोधन ने आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से बदला, आपातकाल के अनुमोदन हेतु विशेष बहुमत अनिवार्य किया, तथा लोकसभा को साधारण बहुमत से आपातकाल समाप्त करने का अधिकार दिया। हालांकि, इसने वित्तीय आपातकाल घोषित करने की राष्ट्रपति की शक्ति को समाप्त नहीं किया, बल्कि उसे बरकरार रखा। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 360 में आज भी पूर्ववत मौजूद है। अतः प्रथम, द्वितीय और तृतीय कथन सत्य हैं, जबकि चतुर्थ कथन पूरी तरह असत्य है।

67. (C) 1994
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ का ऐतिहासिक मामला वर्ष 1994 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया था। इस मामले में नौ जजों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के दुरुपयोग को रोकने और केंद्र-राज्य संबंधों को संतुलित करने के लिए अत्यंत व्यापक एवं दूरगामी दिशानिर्देश जारी किए थे। इस फैसले ने राज्यों में राजनीतिक कारणों से बार-बार सरकारों को बर्खास्त करने की प्रवृत्ति पर प्रभावी विराम लगाया और भारतीय संघवाद की नींव को मजबूत किया।

68. (C) अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की उद्घोषणा दुर्भावना या अप्रासंगिक आधारों की जांच के लिए न्यायिक समीक्षा के अधीन है
एस.आर. बोम्मई मामले (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह केंद्रीय कानूनी सिद्धांत स्थापित किया कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है। यदि यह निर्णय दुर्भावना, अप्रासंगिक सामग्री या असंवैधानिक आधारों पर लिया गया है, तो अदालत इसकी गहन जांच कर सकती है। यदि अदालत को लगता है कि कार्रवाई असंवैधानिक थी, तो वह राष्ट्रपति शासन की घोषणा को रद्द करके बर्खास्त राज्य सरकार और भंग विधानसभा को पुनः बहाल कर सकती है।

NODIA

69. (A) विधानसभा के पटल पर बहुमत परीक्षण (फ्लोर टेस्ट)
एस.आर. बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट सिद्धांत दिया कि किसी राज्य सरकार के पास विधानसभा में बहुमत है या नहीं, इसका परीक्षण करने का एकमात्र उचित, संवैधानिक और निर्णायक स्थान 'विधानसभा का पटल' (फ्लोर टेस्ट) है। राज्यपाल अपने व्यक्तिगत आंकलन या बंद कमरे में विधायकों की गिनती के आधार पर सरकार के बहुमत का फैसला नहीं कर सकते। कार्यपालिका को बर्खास्त करने से पहले राज्यपाल के लिए विधानसभा में फ्लोर टेस्ट आयोजित कराना अनिवार्य संवैधानिक प्रक्रिया है।

70. (D) धर्मनिरपेक्षता
एस.आर. बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकारों की बर्खास्तगी को वैध ठहराया। न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि 'धर्मनिरपेक्षता' भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता (बेसिक स्ट्रक्चर) है। यदि कोई राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करती है या ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देती है, तो इसे राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा और वहां अनुच्छेद 356 लगाना पूरी तरह से न्यायसंगत होगा।

71. (B) जब तक उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता, तब तक विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता है
एस.आर. बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 लागू होने के तुरंत बाद राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जाना चाहिए। जब तक संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को अनुमोदित नहीं कर देते, तब तक विधानसभा को केवल निलंबित अवस्था में रखा जाना चाहिए। यदि संसद दो महीने के भीतर इस उद्घोषणा को पारित करने में विफल रहती है, तो निलंबित विधानसभा स्वतः पुनर्जीवित हो जाएगी और राज्य सरकार अपना कार्य पुनः प्रारंभ कर सकेगी।

72. (C) P-3, Q-1, R-4, S-2
एस.आर. बोम्मई मामला (1994) फ्लोर टेस्ट को अनिवार्य बनाता है। मिनर्वा मिल्स मामला (1980) स्थापित करता है कि राष्ट्रीय आपातकाल को दुर्भावना के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। ए.डी.एम. जबलपुर मामला (1976) में माना गया कि आपातकाल में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर नहीं हो सकती। रामेश्वर प्रसाद मामला (2006) में पहली बैठक से पूर्व बिहार विधानसभा के विघटन को असंवैधानिक घोषित किया गया। अतः सही सुमेलन विकल्प C है।

73. (C) चार बार
भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर अब तक राजस्थान राज्य में कुल चार बार अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ये चार अवसर क्रमशः वर्ष 1967, वर्ष 1977, वर्ष 1980 और वर्ष 1992 में आए थे। प्रथम अवसर पर त्रिशंकु विधानसभा के कारण, दूसरे व तीसरे अवसर पर केंद्र में सरकारों के बदलने के बाद राज्य सरकारों की बर्खास्तगी के कारण,

उच्च न्यायालय के फैसले पर पूर्ण रोक नहीं लगाई थी, बल्कि केवल आंशिक एवं सशर्त रोक लगाई थी। जिसके तहत इंदिरा गांधी संसद में बैठ सकती थीं परंतु मतदान नहीं कर सकती थीं। अतः केवल पहला और दूसरा कथन ही सत्य है।

56. (C) शाह आयोग
1977 में आपातकाल के समाप्त होने के बाद सत्ता में आई जनता पार्टी सरकार ने आपातकाल के दौरान की गई अतिशयोक्तियों, शक्तियों के दुरुपयोग, और अवैध हिरासतों की जांच के लिए मई 1977 में एक जांच आयोग का गठन किया। इस आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह ने की थी, इसलिए इसे शाह आयोग कहा जाता है। शाह आयोग ने अपनी व्यापक रिपोर्ट में आपातकाल के दौरान हुई प्रशासनिक अनियमितताओं और सत्ता के दुरुपयोग का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।

57. (D) आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का अधिनियम (MISA)
1975 के आपातकाल के दौरान राजनीतिक विरोधियों, छात्र नेताओं, और कार्यकर्ताओं को बिना किसी मुकदमे के जेल में डालने के लिए सरकार द्वारा 'मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट' अर्थात् मीसा (MISA) का व्यापक प्रयोग किया गया था। इस निवारक निरोध कानून के तहत देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लंबी अवधि तक हिरासत में रखा गया। आपातकाल के दौरान मीसा में संशोधन करके बंदियों के लिए अदालती राहत और न्यायिक समीक्षा के अधिकारों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था।

58. (A) ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला
1976 का ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामला, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला भी कहा जाता है, में सर्वोच्च न्यायालय की पांच जजों की पीठ ने बहुमत से निर्णय दिया कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के लागू रहने पर किसी व्यक्ति को अपनी गैर-कानूनी हिरासत को चुनौती देने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। इस विवादित फैसले की बाद में भारी आलोचना हुई और इसे अंततः न्यायालय द्वारा पलट दिया गया।

59. (B) पूर्व-सेंसरशिप के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता
25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के तुरंत बाद सरकार ने कार्यपालक आदेश पारित करके समाचार पत्रों पर पूर्व-सेंसरशिप लागू कर दी। इसके तहत किसी भी समाचार, लेख या संपादकीय को प्रकाशित करने से पहले सरकारी अधिकारियों द्वारा अनुमोदित कराना अनिवार्य बना दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता को बुरी तरह से दबा दिया गया तथा सरकार के आलोचक पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। इस कदम का मुख्य उद्देश्य सरकार के खिलाफ उठने वाली सभी विरोधी आवाजों और समाचारों को पूरी तरह दबाना था।

60. (B) इसने सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया
1975 के आपातकाल के दौरान पारित 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य तत्कालीन सरकार के कार्यकाल को बढ़ाना था। बाद में, जब 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई, तो उसने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इस प्रावधान को निरस्त कर दिया और लोकसभा व विधानसभाओं के कार्यकाल को पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया।

61. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है
ए.डी.एम. जबलपुर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आपातकाल के समय कोई व्यक्ति अपनी हिरासत को अदालत में चुनौती नहीं दे सकता। इसका मुख्य कारण यह था कि उस समय लागू अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी करके अनुच्छेद 21 सहित सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित कर दिया था। अतः अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण अभिकथन का सही विधिक आधार और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है।

62. (C) 44वां संशोधन अधिनियम
वर्ष 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने यह अनिवार्य प्रावधान किया कि राष्ट्रपति केवल तभी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिखित रुप में सलाह दी जाए। यह संशोधन 1975 के आपातकाल के अनुभवों के आधार पर लाया गया था, जब प्रधानमंत्री ने बिना कैबिनेट से परामर्श किए अकेले राष्ट्रपति को सलाह दे दी थी। इस सुरक्षात्मक उपाय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी प्रधानमंत्री एकतरफा निर्णय लेकर देश पर आपातकाल न थोप सके।

63. (D) अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) तथा अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) द्वारा प्रदत्त अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। नागरिक इन दो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में आपातकाल के दौरान भी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों का रुख कर सकते हैं। यह प्रावधान नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

64. (C) युद्ध या बाह्य आक्रमण
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद यह संवैधानिक सुरक्षा उपाय जोड़ा गया कि अनुच्छेद 19 में दी गई छह मौलिक स्वतंत्रताएं केवल तब ही स्वतः निलंबित होंगी जब आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई हो। यदि राष्ट्रीय आपातकाल देश के भीतर सशस्त्र

Click Here to Buy book on Flipkart

निलंबित किया जा रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रपति इस निलंबन की समय-सीमा और इसके लागू होने वाले भौगोलिक क्षेत्रों का भी स्पष्ट उल्लेख अपने आदेश में करते हैं।

84. (C) इसका विस्तार भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग पर हो सकता है
अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जारी किए जाने वाले राष्ट्रपति आदेश का भौगोलिक विस्तार राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। इसका विस्तार भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर हो सकता है अथवा इसे भारत के किसी विशिष्ट भाग, राज्य या क्षेत्र तक सीमित रखा जा सकता है। यह लचीलापन सरकार को केवल उन्हीं क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति देता है जहाँ वास्तव में संकट या शांति व्यवस्था की गंभीर समस्या बनी हुई है।

85. (A) इसमें यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि यह कानून राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में है
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार, यदि किसी कानून को आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती दिए जाने से सुरक्षा (उन्मुक्ति) प्राप्त करनी है, तो उस कानून में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख होना अनिवार्य है कि यह कानून राष्ट्रीय आपातकाल के प्रवर्तन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, इस कानून के तहत जारी किए गए कार्यपालक आदेशों को भी यह स्पष्ट करना होता है कि वे उसी आपातकालीन कानून के तहत बनाए गए हैं।

86. (D) I, II और III
अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करता है। अनुच्छेद 358 बाह्य आपातकाल में अधिकारों को स्वतः निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 स्वतः निलंबन नहीं करता बल्कि इसके लिए राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल में लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 359 बाह्य और आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू हो सकता है। अतः तीनों कथन सत्य हैं।

87. (B) अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
अनुच्छेद 359 के तहत जारी राष्ट्रपति के आदेश के बावजूद, व्यक्ति न्यायालय का रुख कर सकते हैं यदि उनकी हिरासत अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) या अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) का उल्लंघन करती है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार, राष्ट्रपति आदेश द्वारा भी अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन हेतु न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। यह नागरिकों को मनमानी हिरासत के खिलाफ अभेद्य सुरक्षा प्रदान करता है।

88. (C) वित्तीय आपातकाल
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वर्णित वित्तीय आपातकाल को भारत में आज तक कभी भी घोषित नहीं किया गया है। यद्यपि भारत को वर्ष 1991 में अत्यधिक गंभीर आर्थिक संकट और विदेशी मुद्रा भंडार की कमी का सामना करना पड़ा था, फिर भी सरकार ने वित्तीय आपातकाल लागू किए बिना ही आर्थिक सुधारों और उदारवादी नीतियों के माध्यम से स्थिति पर सफलता पूर्वक नियंत्रण पा लिया था। अतः वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अभी तक अप्रयुक्त रहा है।

89. (B) राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल
राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) और वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) दोनों की उद्घोषणाओं को संसद द्वारा अनुमोदित करने के लिए केवल "साधारण बहुमत" की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा या उसके विस्तार के लिए संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत (सदन की कुल संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का दो-तिहाई) की आवश्यकता होती है। अतः सही संयोजन राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल है।

90. (A) वित्तीय आपातकाल
अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपातकाल, एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित हो जाने के बाद, अनिश्चित काल के लिए जारी रह सकता है। इसके निरंतर लागू रहने के लिए हर छह महीने में बार-बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। यह तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि राष्ट्रपति एक अनुवर्ती उद्घोषणा जारी करके इसे वापस या निरस्त न कर दें। इसके विपरीत, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन को जारी रखने हेतु समय-समय पर संसदीय स्वीकृति अनिवार्य है।

91. (B) अनुच्छेद 352 के तहत, राज्य कार्यपालिका बनी रहती है लेकिन केंद्र के निर्देशों के अधीन होती है; अनुच्छेद 356 के तहत, इसे बर्खास्त कर दिया जाता है
राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान राज्य की कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद बनी रहती है और अपना कार्य करती रहती है, परंतु वह केंद्र सरकार के कार्यकारी निर्देशों के पूरी तरह अधीन हो जाती है। इसके विपरीत, जब राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लगाया जाता है, तो राज्य की मंत्रिपरिषद को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता है तथा राज्य की संपूर्ण कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल के हाथों में चली जाती हैं।

92. (B) केवल I, II और IV
अनुच्छेद 352 मूल अधिकारों को प्रभावित करता है जबकि 356 व 360 नहीं करते। अनुच्छेद 356 की अधिकतम अवधि तीन वर्ष है जबकि 352 व 360 की कोई सीमा नहीं है। तीनों आपातकाल को वापस लेने के लिए किसी भी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु तीनों आपातकाल के लिए लिखित सिफारिश की आवश्यकता नहीं है; लिखित सिफारिश की शर्त केवल अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल) पर लागू होती है। अतः कथन I, II और IV सही हैं।

Downloaded from www.pdf.tube

93. (A) बिना किसी औपचारिक संशोधन के संघीय ढांचा एकात्मक ढांचे में बदल जाता है
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि बिना किसी औपचारिक संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के, देश की संपूर्ण संघीय व्यवस्था एक एकात्मक व्यवस्था में बदल जाती है। संकट के समय केंद्र सरकार अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है और राज्यों पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। डॉ. अंबेडकर के अनुसार, संविधान को परिस्थितियों के अनुसार संघात्मक और एकात्मक दोनों स्वरुपों में ढाला जा सकता है, जो कि इसकी एक अद्भुत विशेषता है।

94. (C) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
संविधान सभा में आपातकालीन प्रावधानों पर हुई बहस के दौरान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने यह आशा व्यक्त की थी कि अनुच्छेद 356 में दी गई कठोर शक्तियां एक "मृत पत्र" (डेड लेटर) बनी रहेंगी। उनका मानना था कि इस अनुच्छेद का प्रयोग बहुत कम और केवल चरम परिस्थितियों में अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाएगा। हालांकि, स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस अनुच्छेद का राजनीतिक कारणों से व्यापक और बार-बार प्रयोग देखा गया है।

95. (D) राष्ट्रपति संघ और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकते हैं
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति के पास यह संवैधानिक अधिकार होता है कि वे आदेश जारी करके केंद्र और राज्यों के बीच करों तथा राजस्व के वितरण से संबंधित संवैधानिक उपबंधों (अनुच्छेद 268 से 279) को संशोधित या निलंबित कर सकें। ऐसा संशोधन उस वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू रह सकता है जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। इस शक्ति का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और संकट की स्थिति में वित्तीय संसाधनों को केंद्र के पास केंद्रित करना है।

96. (C) संसद राज्य विधानमंडल के साथ-साथ राज्य सूची पर विधान बनाने की समवर्ती शक्ति प्राप्त करती है
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल की शक्तियां छीनी या निलंबित नहीं की जाती हैं। हालांकि, संसद को राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाने की समवर्ती विधायी शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसका अर्थ है कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। परंतु यदि संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल के कानून के बीच कोई असंगति या विरोधाभास होता है, तो संसदीय कानून ही मान्य होता है।

97. (B) P-2, Q-3, R-4, S-1
संविधान सभा में एच.वी. कामथ ने कहा था कि आपातकालीन प्रावधान प्रतिक्रियाओं और पश्चगमन का एक अध्याय हैं। के.टी. शाह ने आशंका व्यक्त की थी कि राष्ट्रपति तानाशाह बन जाएंगे। शिब्बन लाल सक्सेना का मानना था कि राज्यों की स्वायत्तता पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। तथा डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने आशा व्यक्त की थी कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र बना रहेगा। अतः सही उत्तर सुमेलन विकल्प B (P-2, Q-3, R-4, S-1) है।

98. (B) 38वां संशोधन अधिनियम (1975)
वर्ष 1975 में पारित 38वें संविधान संशोधन अधिनियम ने यह प्रावधान करके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में राष्ट्रपति के समाधान को पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने का प्रयास किया था। इसके तहत राष्ट्रपति के निर्णय को अंतिम और सर्वोपरि घोषित किया गया था, जिसे किसी भी आधार पर किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल को अदालती चुनौतियों और न्यायिक जांच से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना था।

99. (C) 44वां संशोधन अधिनियम
वर्ष 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 38वें संशोधन के उस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया जिसने राष्ट्रपति के समाधान को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा था। 44वें संशोधन के बाद यह कानूनी स्थिति बहाल की गई कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने में राष्ट्रपति का समाधान पूरी तरह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यदि आपातकाल की घोषणा दुर्भावनापूर्ण, अप्रासंगिक या बाहरी तथ्यों के आधार पर की जाती है, तो न्यायालय उसकी वैधता की जांच कर सकता है और उसे रद्द कर सकता है।

NODIA

100. (C) मिनर्वा मिल्स मामला (1980)
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) के प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रुप से निर्धारित किया कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय ने माना कि यदि आपातकाल का निर्णय पूरी तरह से असंगत, बाहरी तथ्यों पर आधारित या दुर्भावनापूर्ण है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इस फैसले ने यह स्थापित किया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) का अभिन्न हिस्सा है।

101. (A) न्यायालय यह जांच कर सकता है कि क्या प्रासंगिक सामग्री मौजूद थी, लेकिन उस सामग्री की पर्याप्तता पर सवाल नहीं उठा सकता
एस.आर. बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 356 के तहत न्यायिक समीक्षा करते समय अदालत केवल यह जांच कर सकती है कि क्या निर्णय लेने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ सामग्री मौजूद थी या नहीं। अदालत उस सामग्री की पर्याप्तता या गुणवत्ता की जांच नहीं कर सकती और न ही राष्ट्रपति के स्थान पर अपना निर्णय रख सकती है। यदि प्रासंगिक सामग्री मौजूद है, तो अदालत उस सामग्री के आधार पर लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करती है।

102. (D) संघ सरकार पर
जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जाती है, तो उस कार्रवाई के औचित्य को सिद्ध करने का संपूर्ण कानूनी भार (बर्डन ऑफ प्रूफ) संघ सरकार पर होता है। केंद्र सरकार को अदालत के समक्ष वह वस्तुनिष्ठ सामग्री प्रस्तुत करनी होती है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया था कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया

है। यदि केंद्र सरकार ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो उद्घोषणा को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।

103. (B) वस्तुनिष्ठ सामग्री के आधार पर मंत्रिपरिषद का समाधान
आपातकालीन प्रावधानों में उल्लिखित "राष्ट्रपति का समाधान" शब्द का संवैधानिक अर्थ राष्ट्रपति का व्यक्तिगत समाधान नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद का समाधान है। चूंकि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं। हालांकि, यह समाधान पूरी तरह से मनमाना नहीं हो सकता; यह ऐसे वस्तुनिष्ठ तथ्यों और प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होना अनिवार्य है जिनकी आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय द्वारा जांच की जा सके।

104. (C) राज्यपाल के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त सामग्री के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए
अनुच्छेद 356 में प्रयुक्त वाक्यांश "राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर... या अन्यथा" में "या अन्यथा" शब्द राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे राज्यपाल की औपचारिक रिपोर्ट के बिना भी अन्य विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी या सामग्री के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। इन स्रोतों में केंद्रीय खुफिया एजेंसियां, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट या राज्य की प्रत्यक्ष स्थितियां शामिल हो सकती हैं, बशर्ते सामग्री वस्तुनिष्ठ और प्रासंगिक हो।

105. (D) यह बर्खास्त राज्य सरकार को पुनः बहाल कर सकता है और भंग विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है
एस.आर. बोम्मई मामले के निर्णय के अनुसार, यदि सर्वोच्च न्यायालय यह पाता है कि किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत लगाया गया राष्ट्रपति शासन असंवैधानिक, दुर्भावनापूर्ण और अमान्य था, तो न्यायालय के पास विस्तृत उपचारात्मक शक्तियां हैं। न्यायालय बर्खास्त की गई राज्य सरकार को पुनः उसके पद पर बहाल कर सकता है तथा राष्ट्रपति द्वारा भंग की गई राज्य विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है। यह न्यायिक शक्ति राज्य सरकारों को केंद्र के मनमाने हस्तक्षेप से बचाती है।

106. (C) केवल I और III
आपातकालीन उद्घोषणाओं में राष्ट्रपति का समाधान मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होता है जो प्रासंगिक सामग्री पर निर्भर होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 74(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच अदालत नहीं कर सकती, परंतु जिस सामग्री पर वह सलाह आधारित थी, उसकी जांच की जा सकती है। हालांकि निर्णय यदि मिश्रित आधारों पर है, तो वह स्वतः रद्द नहीं होता जब तक कि मुख्य आधार अवैध न हो। अतः कथन I और III सही हैं।

107. (B) कोई अन्य तर्कसंगत व्यक्ति उसी सामग्री के आधार पर अलग निष्कर्ष पर पहुँच सकता था
न्यायालय राष्ट्रपति के समाधान को केवल इस आधार पर रद्द नहीं कर सकता कि यदि कोई अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी उसी सामग्री का मूल्यांकन करता, तो वह किसी अलग निष्कर्ष पर पहुँच सकता था। न्यायालय राष्ट्रपति के विवेक या निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। न्यायालय केवल तब हस्तक्षेप करता है जब निर्णय पूरी तरह अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित हो, अत्यधिक दुर्भावनापूर्ण हो या राजनीतिक उद्देश्यों से संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करके लिया गया हो।

108. (B) इसमें भारत की तरह विशिष्ट आपातकालीन प्रावधान नहीं हैं, बल्कि इसके स्थान पर यह कांग्रेस (संसद) के विधान और बंदी प्रत्यक्षीकरण के निलंबन पर निर्भर करता है
अमेरिकी संविधान में भारत के संविधान की तरह राष्ट्रीय आपातकाल या राज्यों के अधिग्रहण का कोई विस्तृत और संहिताबद्ध संवैधानिक अध्याय मौजूद नहीं है। अमेरिका में संकटकालीन स्थितियों से निपटने के लिए कांग्रेस (अमेरिकी संसद) द्वारा बनाए गए विशिष्ट कानूनों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी संविधान केवल विद्रोह या बाह्य आक्रमण के समय सार्वजनिक सुरक्षा के हित में कांग्रेस को बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) के अधिकार को निलंबित करने की अनुमति प्रदान करता है।

109. (A) जर्मनी का वाइमर संविधान
आपातकाल के दौरान कार्यपालिका को नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की असाधारण शक्ति देने वाला ढांचा जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। वाइमर संविधान के अनुच्छेद 48 में संकट काल के दौरान राष्ट्रपति को नागरिक स्वतंत्रताओं को स्थगित करने और अध्यादेशों के माध्यम से शासन करने का अधिकार प्राप्त था। भारतीय संविधान निर्माताओं ने देश की अखंडता और सुरक्षा की रक्षा हेतु इस प्रावधान को अपनाया, यद्यपि बाद में इसमें कई सुरक्षात्मक संशोधन जोड़े गए।

110. (B) धारा 93
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356, जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति देता है, सीधे भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 93 से प्रेरित और जुड़ा हुआ है। धारा 93 के तहत प्रांतीय राज्यपालों को यह शक्ति दी गई थी कि यदि प्रांतीय सरकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संचालित नहीं हो सकती, तो वे प्रांत का संपूर्ण प्रशासन स्वयं अपने हाथों में ले सकते थे।

111. (D) संसदीय संप्रभुता की अवधारणा
यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) में 'संसदीय संप्रभुता' का सिद्धांत लागू है, जिसके कारण वहां एक लिखित संविधान या उसमें संहिताबद्ध आपातकालीन प्रावधानों के समूह की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रिटेन की संसद सामान्य कानून निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सरकार को कोई भी विशेष शक्तियां प्रदान कर सकती है या नए कानून बना सकती है। वहां संसद की सर्वोच्चता ही संकट के समय विधिक आधार तय करने का कार्य करती है।

Click Here to Buy book on Amazon

112. (A) मंत्रिमंडल की सिफारिश → राष्ट्रपति की उद्घोषणा → संसदीय अनुमोदन → 6 महीने के लिए जारी रहना
अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का सही क्रमिक क्रम सर्वप्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को लिखित सिफारिश भेजना है। इसके पश्चात राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की औपचारिक उद्घोषणा की जाती है। फिर इस उद्घोषणा को एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित कराया जाता है। संसदीय अनुमोदन प्राप्त होने के बाद आपातकाल 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहता है और इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

113. (B) संघ कार्यपालिका के हाथों में अत्यधिक शक्ति केंद्रित करने की प्रवृत्ति रखते थे, जिससे संघीय स्वरूप नष्ट होता था
संविधान सभा में आपातकालीन उपबंधों की सबसे बड़ी आलोचना यह की गई थी कि ये प्रावधान केंद्र सरकार और संघ कार्यपालिका के हाथों में अत्यधिक शक्तियां केंद्रित कर देंगे। आलोचकों का तर्क था कि इससे राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी, संविधान का संघीय ढांचा नष्ट होकर पूर्णतः एकात्मक बन जाएगा और राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल की तानाशाही स्थापित होने का जोखिम उत्पन्न हो जाएगा, जिससे लोकतांत्रिक मूल्य और प्रांतीय स्वतंत्रता बुरी तरह प्रभावित होंगे।

114. (D) एच.वी. कामथ
संविधान सभा के प्रमुख सदस्य एच.वी. कामथ ने आपातकालीन उपबंधों की तीखी आलोचना करते हुए इन्हें "प्रतिक्रियाओं और पश्चगमन का एक अध्याय" (अ चैप्टर ऑफ रिएक्शंस एंड रिग्रेशन) कहा था। उनका मानना था कि ये कठोर प्रावधान नागरिकों की स्वतंत्रता को छीन लेंगे और केंद्र सरकार को अत्यधिक मनमानी शक्तियां प्रदान कर देंगे, जो एक उभरते हुए लोकतांत्रिक राष्ट्र की भावना के प्रतिकूल है। उन्होंने इन उपबंधों को संविधान में शामिल किए जाने का कड़ा विरोध किया था।

115. (A) मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति की तानाशाही
आपातकालीन उपबंधों के आलोचकों का मुख्य तर्क यह रहा है कि संकट काल में शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण यह व्यवस्था अंततः प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति की अधिनायकवादी तानाशाही का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। यदि इन प्रावधानों का उपयोग राजनीतिक स्वायत्तता और नागरिक स्वतंत्रताओं को दबाने के लिए किया जाए, तो लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ सकता है। वर्ष 1975 में लगाया गया आंतरिक आपातकाल आलोचकों की इसी आशंका का एक बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण माना जाता है।

116. (C) यह व्यावहारिक रूप से राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को समाप्त कर देता है, जिससे वे केंद्र के नियंत्रण में नगरपालिकाओं के समान हो जाते हैं
वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) के संबंध में मुख्य चिंता यह है कि इसके लागू होने पर राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। केंद्र सरकार राज्यों को बजट, व्यय, और वित्तीय प्रबंधन के संबंध में बाध्यकारी निर्देश दे सकती है तथा राज्य के धन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जा सकता है। आलोचकों का मानना है कि इससे राज्य सरकारें वित्तीय रूप से केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं और उनकी स्थिति नगरपालिकाओं जैसी हो जाती है।

117. (D) I, II, III और IV
आपातकालीन उपबंधों के खिलाफ यह प्रमुख आलोचनाएं की जाती हैं कि इनसे संविधान का संघीय ढांचा नष्ट होता है और संघ सर्वशक्तिमान बनता है, राष्ट्रपति या कार्यपालिका के तानाशाह बनने का खतरा रहता है, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त होती है, तथा मौलिक अधिकार निलंबित होने के कारण अर्थहीन हो जाते हैं। ये सभी चारों बिंदु संविधान सभा के दौरान और उसके बाद के राजनीतिक न्यायशास्त्र में आलोचकों द्वारा व्यक्त की गई वास्तविक चिंताओं को दर्शाते हैं।

118. (D) सरकारिया आयोग
केंद्र-राज्य संबंधों पर 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का प्रयोग बहुत ही दुर्लभ मामलों में और केवल एक "अंतिम उपाय के साधन" (वेपन ऑफ लास्ट रिसॉर्ट) के रूप में किया जाना चाहिए। आयोग ने बल दिया कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र को बचाने के सभी वैकल्पिक प्रशासनिक और राजनीतिक उपाय पूरी तरह विफल हो जाएं, तभी अनुच्छेद 356 का उपयोग किया जाना चाहिए।

NODIA

119. (D) पुंछी आयोग (2010)
केंद्र-राज्य संबंधों पर वर्ष 2005 में गठित और 2010 में रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले पुंछी आयोग ने "स्थानीय आपातकाल" की नवीन अवधारणा प्रस्तुत की थी। पुंछी आयोग की यह महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि यदि किसी राज्य के केवल किसी विशिष्ट जिले या सीमित भाग में कानून-व्यवस्था का गंभीर संकट उत्पन्न होता है, तो पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के बजाय केवल उसी प्रभावित क्षेत्र में सीमित समय के लिए स्थानीय आपातकाल लागू किया जाना चाहिए।

120. (C) यह सभी सामग्री तथ्यों और आधारों का सटीक और स्पष्ट विवरण देने वाला एक 'सकारण दस्तावेज' होना चाहिए
सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग जैसी विभिन्न सुधार समितियों ने सिफारिश की है कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल द्वारा भेजी जाने वाली रिपोर्ट एक 'सकारण दस्तावेज' (स्पीकिंग डॉक्यूमेंट) होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में उन सभी वस्तुनिष्ठ तथ्यों, परिस्थितियों और आधारों का स्पष्ट और सटीक विवरण होना अनिवार्य है जिनके कारण यह निष्कर्ष निकाला गया कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती। इसका उद्देश्य राज्यपाल द्वारा भेजी जाने वाली पक्षपातपूर्ण या मनमानी रिपोर्टों पर रोक लगाना है।

121. (D) राज्य सरकार को अपना मार्ग सुधारने के लिए चेतावनी जारी करनी चाहिए
सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की चरम कार्रवाई करने से पूर्व केंद्र सरकार को संबंधित राज्य सरकार को एक औपचारिक चेतावनी (वार्निंग) जारी करनी चाहिए। केंद्र को राज्य सरकार को उन विशिष्ट कमियों या संवैधानिक उल्लंघनों के बारे में

सूचित करना चाहिए और उन्हें सुधारने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। केवल तभी जब राज्य सरकार चेतावनी का पालन करने में विफल रहे, चरम कदम के रूप में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए।

122. (A) P-2, Q-1, R-4, S-3
सरकारिया आयोग ने अनुच्छेद 356 को चेतावनी के साथ अंतिम उपाय बनाने का सुझाव दिया। पुंछी आयोग ने स्थानीय आपातकाल की अवधारणा प्रस्तुत की। राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग (NCRWC) ने दुरुपयोग रोकने हेतु अनुच्छेद 356 में संशोधन का सुझाव दिया। तथा एस.आर. बोम्मई फैसले ने न्यायिक समीक्षा को वैध ठहराया व बहुमत परीक्षण को अनिवार्य बनाया। अतः सही उत्तर सुमेलन विकल्प A (P-2, Q-1, R-4, S-3) है।

123. (B) अंतर-राज्य परिषद
विभिन्न प्रशासनिक सुधार समितियों और आयोगों ने अनुच्छेद 356 का प्रयोग करने से पूर्व केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न गंभीर राजनीतिक व प्रशासनिक विवादों पर चर्चा करने और उनका समाधान खोजने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत गठित अंतर-राज्य परिषद (इंटर-स्टेट काउंसिल) को सबसे उपयुक्त संवैधानिक मंच माना है। इस मंच पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार आपस में संवाद स्थापित करके किसी भी आसन्न संवैधानिक संकट का सौहार्दपूर्ण समाधान निकाल सकते हैं।

124. (D) 2010
न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में गठित पुंछी आयोग ने, जिसने आपातकालीन प्रावधानों, राज्यपाल की भूमिका और केंद्र-राज्य संबंधों पर कई दूरगामी और महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की थीं, अपनी विस्तृत रिपोर्ट अप्रैल 2010 में केंद्र सरकार को सौंपी थी। इस आयोग का गठन अप्रैल 2007 में किया गया था। इसकी सिफारिशों में स्थानीय आपातकाल की अवधारणा और अनुच्छेद 355 तथा 356 के प्रयोग में व्यापक बदलाव शामिल थे।

125. (A) 1994 का एस.आर. बोम्मई निर्णय
वर्ष 1994 में आए सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक 'एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ' निर्णय के बाद से भारत में राज्यों के भीतर राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लगाने की बारंबारता में भारी कमी आई। इस निर्णय ने राष्ट्रपति शासन को सख्त न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया तथा बहुमत सिद्ध करने के लिए विधानसभा के पटल पर फ्लोर टेस्ट को अनिवार्य बना दिया, जिससे केंद्र सरकारों द्वारा इस प्रावधान का राजनीतिक दुरुपयोग करना अत्यधिक कठिन हो गया।

126. (C) उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश
वर्ष 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक हस्तक्षेप करते हुए उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया था। न्यायालय ने एस.आर. बोम्मई मामले में स्थापित सिद्धांतों और फ्लोर टेस्ट की पवित्रता पर बल देते हुए दोनों राज्यों में बर्खास्त कांग्रेस सरकारों को पुनः बहाल कर दिया और विधानसभाओं को पुनर्जीवित कर दिया था। यह न्यायिक समीक्षा और भारतीय संघवाद की मजबूती का एक बड़ा उदाहरण था।

127. (D) क्या बड़े पैमाने पर आतंकवाद या उग्रवाद सशस्त्र विद्रोह के रूप में योग्य है
अनुच्छेद 352 में 44वें संशोधन द्वारा शामिल किए गए "सशस्त्र विद्रोह" वाक्यांश से संबंधित समकालीन संवैधानिक बहस मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि क्या उग्रवाद, बड़े पैमाने पर होने वाले हिंसक आतंकवादी हमले या वामपंथी उग्रवाद जैसी स्थितियां सशस्त्र विद्रोह के अंतर्गत आती हैं या नहीं। विधिक विशेषज्ञ इस बात पर विचार-विमर्श करते हैं कि आंतरिक सुरक्षा के इन आधुनिक खतरों के समय राष्ट्रीय आपातकाल के प्रयोग की विधिक सीमाएं और शर्तें क्या होनी चाहिए।

128. (C) "वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा" की सीमा अत्यधिक उच्च है और इसे अंतिम संवैधानिक उपाय के रूप में देखा जाता है
वर्ष 1991 में भारत के अभूतपूर्व वित्तीय संकट के बावजूद वित्तीय आपातकाल घोषित न किया जाना यह दर्शाता है कि अनुच्छेद 360 में उल्लिखित "वित्तीय स्थिरता या साख के लिए खतरा" की संवैधानिक सीमा अत्यधिक उच्च और कठोर है। भारतीय लोकतंत्र में वित्तीय आपातकाल को एक अत्यंत चरम और अंतिम संवैधानिक उपाय माना जाता है। सरकार ने इस आपातकालीन शक्ति का सहारा लेने के बजाय व्यापक आर्थिक और संरचनात्मक सुधार लागू करके संकट से बाहर निकलना उचित समझा।

129. (B) राज्य के राज्यपाल
अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग और उससे संबंधित समकालीन विवादों की प्रासंगिकता अक्सर राज्य के राज्यपालों की पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक भूमिका पर केंद्रित होती है। केंद्र में सत्तारूढ़ दल द्वारा नियुक्त राज्यपालों पर अक्सर यह आरोप लगता है कि वे तटस्थ संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करने के बजाय केंद्र के राजनीतिक हितों को साधने के लिए पक्षपातपूर्ण रिपोर्टें भेजते हैं, जिससे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का मार्ग प्रशस्त होता है।

130. (D) न्यायिक समीक्षा का मजबूत तंत्र और एक सक्रिय बहुदलीय संसद
वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा आपातकालीन उपबंधों के मनमाने प्रयोग और दुरुपयोग के खिलाफ सबसे मजबूत और प्रभावी सुरक्षा उपाय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक समीक्षा का मजबूत तंत्र (विशेषकर एस.आर. बोम्मई निर्णय के सिद्धांत) तथा एक सतर्क व सक्रिय बहुदलीय संसद है। न्यायालय की संवैधानिक निगरानी तथा संसद में विपक्षी दलों की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी सरकार राजनीतिक लाभ के लिए आपातकालीन शक्तियों का असंवैधानिक प्रयोग न कर सके।

Downloaded from www.pdf.tube

18. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।
कारण (R): धन विधेयक के पारित होने पर दोनों सदनों के बीच बने गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

19. राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वह संसद के सदनों का सत्रावसान कर सकता है लेकिन लोकसभा को भंग नहीं कर सकता।
II. वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है।
III. वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में संसद को संबोधित करता है।
उपयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

20. भारत के राष्ट्रपतियों के पद ग्रहण करने का सही कालानुक्रमिक क्रम चुनिए:
(A) डॉ. जाकिर हुसैन, वी. वी. गिरि, फखरुद्दीन अली अहमद, एन. संजीव रेड्डी
(B) वी. वी. गिरि, डॉ. जाकिर हुसैन, एन. संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद
(C) डॉ. जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, वी. वी. गिरि, एन. संजीव रेड्डी
(D) एन. संजीव रेड्डी, डॉ. जाकिर हुसैन, वी. वी. गिरि, फखरुद्दीन अली अहमद

21. संसद में कुछ प्रकार के विधेयकों को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश या मंजूरी की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश संवैधानिक रूप से आवश्यक नहीं है?
(A) किसी राज्य की सीमाओं को बदलने वाला विधेयक
(B) धन विधेयक
(C) अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक
(D) भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित विधेयक

NODIA

22. जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन-सी कार्रवाई 'पॉकेट वीटो' का प्रयोग है?
(A) राष्ट्रपति विधेयक को संसद के औपचारिक संवैधानिक पुनर्विचार के लिए लौटा देता है।
(B) राष्ट्रपति प्रस्तुत किए जाने पर तुरंत विधेयक पर अपनी औपचारिक सहमति दे देता है।
(C) राष्ट्रपति औपचारिक रूप से विधेयक पर अपनी सहमति रोक लेता है, जिससे यह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है।
(D) राष्ट्रपति बिना कोई औपचारिक कार्रवाई किए विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखता है।

23. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I
P. लघुकरण
Q. परिहार
R. विराम
S. प्रविलंबन
सूची II
1. दंड के चरित्र को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना
2. दंड के एक रूप को हल्के रूप में बदलना
3. गर्भावस्था जैसे विशेष तथ्य के कारण कम दंड देना
4. किसी दंड के निष्पादन पर अस्थायी अवधि के लिए रोक लगाना
(A) P-2, Q-1, R-3, S-4
(B) P-1, Q-2, R-4, S-3
(C) P-2, Q-3, R-1, S-4
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

24. अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह सैन्य अदालत (कोर्ट मार्शल) द्वारा दिए गए दंड या सजा पर लागू होती है।
II. यह एक कार्यपालक शक्ति है जो न्यायपालिका से स्वतंत्र है।
III. राष्ट्रपति उन सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है जहाँ सजा मृत्युदंड है।
IV. राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के बिना पूरी तरह से अपने व्यक्तिगत विवेक पर इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है।
उपयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) I, II और III
(B) II, III और IV
(C) I, III और IV
(D) I, II, III और IV

25. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बीच अंतर को दर्शाता है?
(A) राज्यपाल के पास मृत्युदंड को क्षमा करने की अनन्य

8. भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को भारतीय रिज़र्व बैंक में जमानत राशि जमा करनी होती है। इस जमानत राशि की मात्रा कितनी है?
(A) 10,000 रुपये
(B) 15,000 रुपये
(C) 20,000 रुपये
(D) 25,000 रुपये

9. राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र होने के लिए, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किसके सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अर्ह होना चाहिए?
(A) राज्यसभा
(B) संसद के दोनों सदन
(C) राज्य विधानसभा
(D) लोकसभा

10. निम्नलिखित में से कौन-सी स्थिति अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का एक वैध आधार है?
(A) संविधान का उल्लंघन
(B) सिद्ध कदाचार या असमर्थता
(C) लोकसभा में विश्वास खोना
(D) नैतिक अधमता

11. राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित निम्नलिखित चरणों को सही क्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. पहल करने वाले सदन की कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा संकल्प पारित करना।
2. पहल करने वाले सदन के एक-चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित 14 दिनों की अग्रिम सूचना देना।
3. दूसरे सदन द्वारा आरोपों की जाँच।
4. जाँच करने वाले सदन द्वारा अपनी कुल सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करना।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनिए:
(A) 2, 1, 3, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 3, 2, 1, 4

12. राष्ट्रपति के कार्यकाल और त्यागपत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है।
II. राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित त्यागपत्र देकर किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।
III. राष्ट्रपति, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी, तब तक पद धारण कर सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले।
IV. राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को दी जानी चाहिए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) I, II और III
(B) II, III और IV
(C) I, II, III और IV
(D) I, III और IV

13. राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?
(A) महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरु किए जा सकते हैं।
(B) संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य महाभियोग में भाग ले सकते हैं।
(C) राष्ट्रपति को जाँच में उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार है।
(D) राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य महाभियोग में भाग लेते हैं।

14. यदि राष्ट्रपति का पद त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्यथा रिक्त हो जाता है, तो रिक्ति को भरने के लिए चुनाव अधिकतम कितनी समय-सीमा के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए?
(A) रिक्ति की तिथि से तीन महीने
(B) रिक्ति की तिथि से छह महीने
(C) रिक्ति की तिथि से नौ महीने
(D) रिक्ति की तिथि से एक वर्ष

15. संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 77 के तहत, भारत सरकार की सभी कार्यपालक कार्रवाइयाँ किसके नाम से की हुई व्यक्त की जाएँगी?
(A) प्रधानमंत्री
(B) मंत्रिपरिषद्
(C) कैबिनेट सचिव
(D) राष्ट्रपति

16. भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियों के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए:
(A) राज्य का महाधिवक्ता — राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
(B) भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक — राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
(C) मुख्य चुनाव आयुक्त — राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
(D) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष — राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त

17. राष्ट्रपति के पास किसी भी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित करने की शक्ति है और अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह प्रशासनिक शक्ति राष्ट्रपति की शक्तियों की किस श्रेणी के अंतर्गत आती है?
(A) विधायी शक्तियाँ
(B) न्यायिक शक्तियाँ
(C) वित्तीय शक्तियाँ
(D) कार्यपालक शक्तियाँ

Click Here to Buy book on Flipkart

(C) लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्ह होना चाहिए
(D) संघ, राज्य या स्थानीय प्राधिकरण के तहत लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए

35. भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं:
(A) केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
(B) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य
(C) संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
(D) संसद, राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य

36. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I
P. अनुच्छेद 63
Q. अनुच्छेद 64
R. अनुच्छेद 65
S. अनुच्छेद 66
सूची II
1. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
2. उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कार्यों का निर्वहन करना
3. भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा
4. उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद (राज्यसभा) का पदेन सभापति होना
(A) P-3, Q-4, R-2, S-1
(B) P-4, Q-3, R-1, S-2
(C) P-3, Q-2, R-4, S-1
(D) P-1, Q-4, R-2, S-3

37. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करना बंद कर देता है।
कारण (R): संविधान यह निर्दिष्ट करता है कि हितों के टकराव से बचने के लिए एक व्यक्ति एक साथ दो प्रमुख संवैधानिक कार्यपालक और विधायी पीठासीन भूमिकाएँ धारण नहीं कर सकता है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

38. भारत के उपराष्ट्रपति के पदच्युति (हटाने) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. उन्हें राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प और लोकसभा द्वारा सहमत संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है।
II. उनके निष्कासन के लिए राष्ट्रपति जैसी औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।
III. उनके निष्कासन के लिए संविधान में किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है।
IV. निष्कासन का संकल्प पेश करने के लिए कम से कम 14 दिनों की अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) I, II और IV
(B) II, III और IV
(C) I, II, III और IV
(D) I, III और IV

39. भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है?
(A) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(B) लोकसभा अध्यक्ष
(C) राज्यसभा के उपसभापति
(D) भारत के राष्ट्रपति

40. राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने महीनों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है?
(A) तीन महीने
(B) छह महीने
(C) नौ महीने
(D) एक वर्ष

NODIA

41. यदि किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसी घोषणा की तिथि से पहले उनके द्वारा किए गए कार्यों का क्या होता है?
(A) उन्हें पूरी तरह से अमान्य घोषित कर दिया जाता है और भूतकाल से रद्द कर दिया जाता है।
(B) उन्हें संसद द्वारा अनिवार्य समीक्षा के अधीन किया जाता है।
(C) उन्हें प्रारंभ से ही कानूनी रूप से अमान्य और शून्य माना जाता है।
(D) वे अमान्य नहीं होते और पूर्ण प्रभाव में बने रहते हैं।

42. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. संविधान उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी क्षमता में उपराष्ट्रपति के वेतन को निर्दिष्ट करता है।
II. उपराष्ट्रपति अपना नियमित वेतन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में प्राप्त करते हैं।
III. राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों का हकदार होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III

शक्ति है, जबकि राष्ट्रपति के पास नहीं है।
(B) राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास सैन्य अदालत की सजा के संबंध में समान संवैधानिक शक्तियाँ हैं।
(C) राष्ट्रपति सैन्य अदालत की सजा को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है।
(D) राज्यपाल का क्षमादान अधिकार संघ के कानूनों तक विस्तारित है, जबकि राष्ट्रपति का राज्य के कानूनों पर लागू होता है।

26. संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है। यदि संसद कोई पूर्व कार्रवाई नहीं करती है तो ऐसे अध्यादेश की अधिकतम वैधानिक अवधि कितनी होती है?
(A) ठीक 6 महीने
(B) 6 महीने और 6 सप्ताह
(C) 1 वर्ष
(D) जब तक संसद का अगला सत्र पूरी तरह से समाप्त न हो जाए

27. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति कानून निर्माण की समानांतर शक्ति नहीं है।
कारण (R): अध्यादेश केवल तभी प्रख्यापित किया जा सकता है जब या तो संसद के दोनों सदन सत्र में न हों या दोनों सदनों में से कोई एक सत्र में न हो।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

28. निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है यदि इसका प्रयोग कपटपूर्ण/दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया है?
(A) केशवानंद भारती मामला
(B) एस.आर. बोम्मई मामला
(C) मिनर्वा मिल्स मामला
(D) आर.सी. कूपर मामला

29. राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. उनकी सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती।
II. वह केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की सिफारिश करने के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है।
III. वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम भुगतान कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

30. कौन-सा संवैधानिक प्रावधान राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है?
(A) अनुच्छेद 352
(B) अनुच्छेद 356
(C) अनुच्छेद 360
(D) अनुच्छेद 365

31. अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्तों में कटौती के निर्देश जारी कर सकता है?
(A) केवल केंद्र सरकार के प्रशासन के तहत सेवा देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों।
(B) संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल हैं।
(C) केवल राज्य सरकारों के तहत विशेष रूप से काम करने वाले लोक सेवक और कर्मचारी।
(D) केवल संसद के निर्वाचित सदस्य और संसदीय समितियों के सदस्य।

32. निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक विवेक का प्रयोग करता है?
(A) प्रधानमंत्री की नियुक्ति में जब किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो।
(B) गैर-धन विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटाने में।
(C) भारत के राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेक नहीं है; उसके पास केवल परिस्थितिजन्य विवेक है।
(D) यदि मंत्रिपरिषद् ने अपना बहुमत खो दिया है तो लोकसभा को भंग करने में।

33. नाममात्र कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री की संवैधानिक अवधारणा किस देश की राजनीतिक व्यवस्था से ली गई है?
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका
(B) फ्रांस
(C) स्विट्ज़रलैंड
(D) यूनाइटेड किंगडम

NODIA

34. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पात्रता मानदंड नहीं है?
(A) भारत का नागरिक होना चाहिए
(B) 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए

अध्याय 09
केंद्रीय कार्यपालिका

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन राष्ट्रपति की स्थिति का सबसे सटीक वर्णन करता है?
   (A) राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है और शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रयोग करता है।
   (B) राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है और सभी प्रशासनिक कार्यों का निर्देशन करता है।
   (C) राष्ट्रपति एक सलाहकार व्यक्ति है जिसके पास कोई औपचारिक कार्यपालक अधिकार नहीं है।
   (D) राष्ट्रपति भारतीय राज्य का प्रमुख होता है और राष्ट्र की एकजुटता का प्रतिनिधित्व करता है।

2. निम्नलिखित में से कौन-से सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते हैं?
   (A) लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
   (B) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
   (C) राज्यसभा के मनोनीत सदस्य
   (D) दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

3. राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में, राज्य की विधानसभा के एक निर्वाचित सदस्य (विधायक) के मत का मूल्य, वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, किस जनगणना वर्ष पर आधारित राज्य की जनसंख्या का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है?
   (A) 1971
   (B) 1991
   (C) 2001
   (D) 2011

4. राष्ट्रपति चुनाव में, राजस्थान के एक निर्वाचित विधायक के मत के मूल्य की गणना राजस्थान की कुल जनसंख्या (1971 की जनगणना) को राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से विभाजित करके, और प्राप्त भागफल को पुनः किस संख्या से विभाजित करके की जाती है?
   (A) 10
   (B) 100
   (C) 1000
   (D) 10000

5. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
   कथन (A): भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है।
   कारण (R): संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता।
   (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
   (B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
   (C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
   (D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

6. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   I. निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।
   II. पार्टी अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए मतदान खुली मतदान प्रणाली के माध्यम से होता है।
   III. राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न होने वाली सभी शंकाओं और विवादों की जाँच और निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है।
   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (A) केवल I और II
   (B) केवल II और III
   (C) केवल I और III
   (D) I, II और III

7. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
   सूची I
   P. अनुच्छेद 54
   Q. अनुच्छेद 58
   R. अनुच्छेद 60
   S. अनुच्छेद 61
   सूची II
   1. राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएं
   2. राष्ट्रपति पर महाभियोग
   3. राष्ट्रपति का निर्वाचन
   4. राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
   (A) P-1, Q-3, R-2, S-4
   (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
   (C) P-2, Q-1, R-4, S-3
   (D) P-3, Q-1, R-4, S-2

Downloaded from www.pdf.tube

(D) I, II और III

43. भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. पी. वी. नरसिम्हा राव
2. एच. डी. देवगौड़ा
3. वी. पी. सिंह
4. चंद्रशेखर

सही विकल्प चुनिए:
(A) 3, 4, 1, 2
(B) 4, 3, 1, 2
(C) 3, 1, 4, 2
(D) 1, 3, 4, 2

44. भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
(A) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(B) भारत के राष्ट्रपति
(C) शक्ति परीक्षण के माध्यम से लोकसभा
(D) संसद में बहुमत दल

45. संसदीय प्रणाली की परंपराओं के अनुसार, राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाहिए। यदि किसी एक दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति परिस्थितिजन्य विवेक का प्रयोग करता है। ऐसे मामलों में राष्ट्रपति द्वारा नवनियुक्त प्रधानमंत्री को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए आमतौर पर दी जाने वाली मानक समय-सीमा क्या है?
(A) एक सप्ताह
(B) पंद्रह दिन
(C) एक महीना
(D) छह महीने

46. भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है?
(A) क्षेत्रीय परिषदें
(B) वित्त आयोग
(C) निर्वाचन आयोग
(D) अंतर-राज्यीय परिषद

47. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): वर्तमान प्रधानमंत्री का त्यागपत्र या मृत्यु स्वतः ही मंत्रिपरिषद् को विघटित कर देती है।
कारण (R): प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् का प्रमुख होता है और उसके बिना मंत्रिपरिषद् का अस्तित्व या कार्य नहीं हो सकता।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

48. संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत, राष्ट्रपति के साथ संबंधों के संदर्भ में प्रधानमंत्री का मुख्य कर्तव्य क्या है?
(A) प्रशासन और विधान से संबंधित मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देना।
(B) संसदीय पटल पर रखने से पहले व्यापक वार्षिक राष्ट्रीय बजट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना।
(C) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में की जाने वाली सभी न्यायिक नियुक्तियों पर राष्ट्रपति को सलाह देना।
(D) यह गारंटी देना कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित सभी विधायी विधेयकों पर अपनी सहमति दे।

49. भारत के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं था?
(A) मोरारजी देसाई
(B) चरण सिंह
(C) चंद्रशेखर
(D) वी. पी. सिंह

NODIA

50. प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार की गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है।
II. प्रधानमंत्री भारत के महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है।
III. प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा भंग करने की सलाह दे सकता है।
IV. राष्ट्रपति कार्यकारी निर्णयों पर पूछताछ के लिए प्रधानमंत्री को संसद में बुला सकता है।

उपयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) I, II और III
(B) I, II और IV
(C) II, III और IV
(D) I, III और IV

51. वाक्यांश "प्रिमस इंटर पेरेस" (समकक्षों में प्रथम) का प्रयोग प्रायः मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। किसने प्रसिद्ध रूप से प्रधानमंत्री को "मंत्रिमंडल के मेहराब की आधारशिला" के रूप में वर्णित किया था?
(A) सर आइवर जेनिंग्स
(B) बी. आर. अम्बेडकर
(C) लास्की
(D) लॉर्ड मॉर्ले

52. किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद् की सलाह को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया, जिससे उनके लिए ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य हो गया?
(A) 1978 का 44वां संशोधन अधिनियम

(B) 2002 का 86वां संशोधन अधिनियम
(C) 1976 का 42वां संशोधन अधिनियम
(D) 2003 का 91वां संशोधन अधिनियम

53. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I
P. नीति आयोग
Q. राष्ट्रीय एकता परिषद
R. राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद
S. क्षेत्रीय परिषदें
सूची II
1. प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं
2. प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं
3. प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं
4. प्रधानमंत्री अध्यक्ष नहीं हैं (केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में)
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-1, Q-4, R-3, S-2
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

54. 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद् का अधिकतम आकार क्या हो सकता है?
(A) संसद के दोनों सदनों की कुल संख्या का 10%
(B) लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%
(C) संसद के दोनों सदनों की कुल संख्या का 15%
(D) लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10%

55. 'सामूहिक उत्तरदायित्व' का सिद्धांत सरकार की संसदीय प्रणाली की आधारशिला है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत, मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से किस संस्था के प्रति उत्तरदायी होती है?
(A) भारत के राष्ट्रपति
(B) लोकसभा
(C) संसद (दोनों सदन)
(D) मतदाता

56. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): मंत्री व्यक्तिगत रूप से भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
कारण (R): राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से परामर्श किए बिना अपने पूर्ण विवेक से किसी मंत्री को मंत्रिपरिषद् से हटा सकता है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

57. निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिपरिषद् में मंत्रियों की एक मान्यता प्राप्त श्रेणी नहीं है?
(A) स्वतंत्र प्रभार वाले कैबिनेट मंत्री
(B) स्वतंत्र प्रभार वाले या बिना स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री
(C) कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करने वाले उप-मंत्री
(D) संसदीय सचिव

58. किसी मंत्री द्वारा ली जाने वाली शपथ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राष्ट्रपति मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है।
II. गोपनीयता की शपथ मंत्री को कर्तव्य निष्पादन के लिए आवश्यक जानकारी को छोड़कर, अपने विचारार्थ लाई गई किसी भी जानकारी को उजागर न करने का वचन देती है।
III. केंद्रीय मंत्रियों के लिए शपथ का प्रारूप संविधान की दूसरी अनुसूची में दिया गया है।
उपयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

59. यदि संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने वाले व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जाता है, तो क्या होता है?
(A) नियुक्ति शुरु से ही कानूनी रूप से अमान्य है और अनुच्छेद 75 के तहत असंवैधानिक है।
(B) व्यक्ति अनिश्चित काल के लिए सेवा कर सकता है, बशर्ते नियुक्ति को राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई हो।
(C) वह छह महीने के लिए सेवा कर सकता है, जिसके भीतर उसे संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है।
(D) व्यक्ति अनिश्चित काल के लिए मंत्री के रूप में कार्य कर सकता है लेकिन कैबिनेट बैठकों में मतदान के विशेषाधिकार के बिना।

60. कार्यपालिका की निम्नलिखित श्रेणियों को उनके विशिष्ट प्रशासनिक पदानुक्रम और प्रभाव के क्रम में (उच्चतम से निम्नतम) व्यवस्थित कीजिए:
1. कैबिनेट मंत्री
2. प्रधानमंत्री
3. उप-मंत्री
4. राज्य मंत्री
सही क्रम चुनिए:
(A) 2, 1, 4, 3
(B) 1, 2, 4, 3
(C) 2, 1, 3, 4
(D) 2, 4, 1, 3

61. भारतीय संसदीय प्रणाली में, किसी मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व का कोई प्रावधान नहीं है। इसका अर्थ है कि:

Click Here to Buy book on Amazon

(A) सार्वजनिक कार्यों के लिए राष्ट्रपति के आदेशों पर किसी मंत्री के प्रति-हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है।
(B) मंत्रियों को किसी भी नागरिक या व्यक्तिगत अपराध के लिए अदालतों में मुकदमा चलाए जाने से पूर्ण कानूनी छूट प्रदान की जाती है।
(C) कार्यकारी मंत्री मानक संवैधानिक संसदीय नियमों का पालन करने से कानूनी रूप से मुक्त हैं।
(D) केंद्रीय मंत्रियों को आधिकारिक सिविल सेवक अधिनियमों के लिए कानूनी या विभागीय रूप से जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है।

62. मंत्रिपरिषद् और मंत्रिमंडल की तुलना करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. मंत्रिपरिषद् मंत्रिमंडल की तुलना में एक बड़ा निकाय है।
II. राष्ट्रीय नीतियों को आकार देने के लिए मंत्रिमंडल एक निकाय के रूप में बैठक करता है, जबकि मंत्रिपरिषद् शायद ही कभी एकल निकाय के रूप में बैठक करती है।
III. 'मंत्रिमंडल' (Cabinet) शब्द का उल्लेख भारत के संविधान के मूल पाठ में कहीं भी नहीं था।
IV. मंत्रिमंडल निचले सदन के प्रति मंत्रिपरिषद् के सामूहिक उत्तरदायित्व को लागू करता है।
उपयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) I, II और III
(B) I, II और IV
(C) II, III और IV
(D) I, II, III और IV

63. 'मंत्रिमंडल' शब्द को अनुच्छेद 352 में भारत के संविधान में शामिल किया गया था। इस अंतःस्थापन के लिए कौन-सा संविधान संशोधन अधिनियम उत्तरदायी था?
(A) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
(B) 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
(C) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
(D) 91वां संशोधन अधिनियम, 2003

64. भारत में मंत्रिमंडल के कार्यों के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए:
(A) यह भारतीय राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है।
(B) यह सभी प्रमुख विधायी और वित्तीय मामलों से निपटता है।
(C) यह सर्वोच्च कार्यपालक प्राधिकरण और मुख्य नीति-निर्धारण निकाय के रूप में कार्य करता है।
(D) इसके निर्णय सलाहकारी होते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा एकतरफा बदले जा सकते हैं।

65. प्रधानमंत्री और उनके कुछ सबसे प्रभावशाली सहयोगियों, जिनमें कभी-कभी मित्र या परिवार के सदस्य भी शामिल होते हैं, जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, से बने अनौपचारिक निकाय को आमतौर पर क्या कहा जाता है?
(A) किचन कैबिनेट
(B) शैडो कैबिनेट
(C) सुपर कैबिनेट
(D) वॉर कैबिनेट

66. कैबिनेट समितियाँ मंत्रिमंडल के कार्यभार को कम करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाएँ हैं। कैबिनेट समितियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(A) संविधान के अनुच्छेद 77 में इनका स्पष्ट रूप से उल्लेख और जनादेश दिया गया है।
(B) ये विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थापित की जाती हैं।
(C) इनका उद्भव संविधानेत्तर है।
(D) केवल कैबिनेट मंत्री ही इन समितियों के सदस्य हो सकते हैं।

67. निम्नलिखित में से किस कैबिनेट समिति को सरकारी निर्णय लेने में इसके व्यापक प्रभाव के कारण अक्सर 'सुपर-कैबिनेट' के रूप में वर्णित किया जाता है?
(A) आर्थिक मामलों की समिति
(B) नियुक्ति समिति
(C) संसदीय मामलों की समिति
(D) राजनीतिक मामलों की समिति

68. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): संसदीय मामलों की समिति की अध्यक्षता आमतौर पर प्रधानमंत्री करते हैं।
कारण (R): कार्यपालक कार्यों पर अंतिम नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री सभी स्थायी कैबिनेट समितियों का प्रमुख होता है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

NODIA

69. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I
P. राजनीतिक मामलों की समिति
Q. आर्थिक मामलों की समिति
R. नियुक्ति समिति
S. संसदीय मामलों की समिति
सूची II
1. प्रधानमंत्री
2. प्रधानमंत्री
3. प्रधानमंत्री
4. केंद्रीय गृह मंत्री
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1

(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

106. निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के "निलंबनकारी वीटो" का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) बिना कोई कार्रवाई किए किसी विधायी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना।
(B) किसी विधेयक पर आधिकारिक राष्ट्रपति की सहमति को पूरी तरह से रोकना।
(C) गैर-धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना।
(D) संवैधानिक अमान्यता के आधार पर किसी विधेयक को सीधे खारिज करना।

107. संविधान निर्दिष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद् में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 मानते हुए गणितीय रूप से वर्तमान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी संभव है?
(A) 75
(B) 81
(C) 82
(D) 85

108. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I
P. वास्तविक कार्यपालिका
Q. नाममात्र की कार्यपालिका
R. राज्य का प्रमुख
S. सरकार का प्रमुख
सूची II
1. राष्ट्रपति
2. प्रधानमंत्री
3. विधि-अनुसार
4. वस्तुतः
(A) P-4, Q-3, R-1, S-2
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-4, Q-1, R-3, S-2
(D) P-2, Q-3, R-1, S-4

109. संसदीय कार्यवाही में महान्यायवादी की भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. उन्हें संसद की किसी भी समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।
II. संसद में भाग लेते समय, वह संसद सदस्य को उपलब्ध सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का आनंद लेते हैं।
III. वह लोकसभा में टाई की स्थिति में निर्णायक वोट डाल सकते हैं।
उपयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

110. कौन-सा पदाधिकारी भारत सरकार को उन मामलों पर कानूनी सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे संदर्भित किए जाते हैं?
(A) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(B) केंद्रीय कानून मंत्री
(C) भारत के महान्यायवादी
(D) कैबिनेट सचिव

111. निम्नलिखित में से किसे मंत्रिमंडल की निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए भारत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक गैर-संवैधानिक उपकरण माना जाता है?
(A) मंत्रिपरिषद्
(B) कैबिनेट समितियाँ
(C) सर्वोच्च न्यायालय
(D) वित्त आयोग

112. भारतीय प्रधानमंत्री मौलिक रूप से किस आधार पर नियुक्त किया जाता है?
(A) भारत के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव।
(B) सत्तारुढ़ दल में वरिष्ठता।
(C) लोकसभा में बहुमत का नेतृत्व करना।
(D) निर्वाचक मंडल द्वारा चयन।

113. अनुच्छेद 75 के तहत, मंत्रियों के "व्यक्तिगत उत्तरदायित्व" की प्रकृति क्या है?
(A) वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं।
(B) वे व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी हैं।
(C) वे लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी हैं।
(D) वे 5 वर्ष के कार्यकाल के अंत तक किसी भी निष्कासन से सुरक्षित हैं।

114. यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा से संबंधित है, तो उस पर निम्नलिखित में से कौन-सा प्रतिबंध लागू होता है?
(A) वह लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकता।
(B) उसे लोकसभा में बोलने से संवैधानिक रूप से रोका जाता है।
(C) वह नीति आयोग की अध्यक्षता करने के लिए अयोग्य है।
(D) वह लोकसभा के पटल पर मुख्य नीतिगत बयान नहीं दे सकता।

115. राजस्थान के एक निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का एक सदस्य कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। यदि प्रधानमंत्री द्वारा आवश्यक हो तो यह मंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा?

Downloaded from www.pdf.tube

3. पुनः समवेत होने की तिथि से 6 सप्ताह की समाप्ति।
4. अध्यादेश का व्यपगत होना (यदि संसद द्वारा अनुमोदित न किया गया हो)।

सही विकल्प चुनिए:
(A) 1, 2, 4, 3
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 1, 3, 4
(D) 1, 3, 2, 4

79. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

सूची I
P. एपुरु सुधाकर मामला (2006)
Q. यू.एन. राव बनाम इंदिरा गांधी (1971)
R. डी.सी. वाधवा मामला (1987)
S. एस.आर. बोम्मई मामला (1994)

सूची II
1. अध्यादेशों का पुनः प्रख्यापन संविधान के साथ धोखाधड़ी है
2. राष्ट्रपति/राज्यपाल की क्षमादान शक्ति की न्यायिक समीक्षा
3. राष्ट्रपति शासन लागू करने की न्यायिक समीक्षा
4. लोकसभा के विघटन के बाद भी मंत्रिपरिषद् का अस्तित्व में रहना आवश्यक है

(A) P-2, Q-4, R-1, S-3
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

80. 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद् द्वारा दी गई सलाह के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति पर एक महत्वपूर्ण नियंत्रण पेश किया। यह नियंत्रण क्या था?
(A) राष्ट्रपति कानूनी वैधता के लिए किसी भी विवादास्पद कैबिनेट सलाह को सीधे सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है।
(B) राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए सलाह को एक बार मंत्रिपरिषद् को लौटा सकता है।
(C) राष्ट्रपति जब भी मंत्रिपरिषद् की सलाह से असहमत होता है, तो उसे बर्खास्त करने का अधिकार रखता है।
(D) राष्ट्रपति के लिए मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन करने वाली कैबिनेट सलाह को तुरंत खारिज करना अनिवार्य है।

81. भारतीय संघ के संदर्भ में 'विधि-अनुसार' (De jure) और 'वस्तुतः' (De facto) कार्यपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(A) प्रधानमंत्री विधि-अनुसार कार्यपालक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जबकि राष्ट्रपति वस्तुतः कार्यपालक के रूप में कार्य करता है।
(B) कैबिनेट सचिव विधि-अनुसार कार्यपालक के रूप में कार्य करता है, जबकि प्रधानमंत्री वस्तुतः कार्यपालक के रूप में कार्य करता है।
(C) राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों समान विभाजित शक्तियों को साझा करते हुए संयुक्त वस्तुतः कार्यपालक के रूप में कार्य करते हैं।
(D) राष्ट्रपति विधि-अनुसार (नाममात्र) कार्यपालक है, और प्रधानमंत्री वस्तुतः (वास्तविक) कार्यपालक है।

82. कौन-सा संवैधानिक सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि जो मंत्री कैबिनेट के निर्णय से असहमत है और उसका बचाव करने के लिए तैयार नहीं है, उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए?
(A) व्यक्तिगत उत्तरदायित्व
(B) सामूहिक उत्तरदायित्व
(C) पद की गोपनीयता
(D) संवैधानिक नैतिकता

83. प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं?
(A) भारत के राष्ट्रपति
(B) वित्त आयोग
(C) संसद
(D) भारतीय रिज़र्व बैंक

NODIA

84. महान्यायवादी की भूमिका और सहायता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. उन्हें दो सॉलिसिटर जनरल और चार अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
II. अनुच्छेद 76 सीधे महान्यायवादी के साथ-साथ भारत के सॉलिसिटर जनरल के पद का प्रावधान करता है।
III. सॉलिसिटर जनरल एक वैधानिक पद है, संवैधानिक नहीं।

उपयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

85. यदि लोकसभा में किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो आवश्यक संवैधानिक परिणाम क्या होगा?
(A) केवल उस विशिष्ट मंत्री को त्यागपत्र देना होगा।
(B) पूरी मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना होगा।
(C) सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श के बाद राष्ट्रपति मंत्री को हटा देता है।
(D) मंत्री को विश्वास हासिल करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है।

86. निम्नलिखित में से कौन-सी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए एक मूलभूत अर्हता नहीं है, और इसलिए, भारत के महान्यायवादी के लिए भी आवश्यक नहीं है?
(A) भारत का नागरिक होना चाहिए
(B) 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो

11. (A) 2, 1, 3, 4
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। सर्वप्रथम पहल करने वाले सदन के एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ 14 दिनों की अग्रिम सूचना दी जाती है। तत्पश्चात वह सदन अपनी कुल सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करता है। इसके बाद दूसरा सदन आरोपों की जाँच करता है और उसे सही पाने पर दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करता है।

12. (D) I, III और IV
राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है और अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, जिसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने के बावजूद तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। त्यागपत्र मुख्य न्यायाधीश को नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति को दिया जाता है।

13. (D) राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य महाभियोग में भाग लेते हैं।
राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के केवल सदस्य भाग लेते हैं, जिसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, यद्यपि वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। महाभियोग प्रक्रिया संसद की एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें राष्ट्रपति को स्वयं या प्रतिनिधि द्वारा बचाव का अधिकार होता है।

14. (B) रिक्ति की तिथि से छह महीने
अनुच्छेद 62 के तहत, यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या अन्य कारणों से अचानक रिक्त हो जाता है, तो उस रिक्ति को भरने के लिए चुनाव हर हाल में रिक्ति होने की तिथि से 6 महीने के भीतर आयोजित किया जाना अनिवार्य है। इस अंतरिम अवधि में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या मुख्य न्यायाधीश को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है।

15. (D) राष्ट्रपति
संविधान के अनुच्छेद 77(1) में यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि भारत सरकार की सभी कार्यपालक कार्रवाइयाँ औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से की हुई व्यक्त की जाएँगी। यद्यपि वास्तविक निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद् द्वारा लिए जाते हैं, फिर भी सभी शासकीय आदेश, संधियाँ और कार्यपालक दस्तावेज़ राष्ट्रपति के नाम पर ही जारी किए जाते हैं तथा निष्पादित किए जाते हैं।

16. (A) राज्य का महाधिवक्ता — राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इसके विपरीत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रकार महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति की शक्तियों के दायरे से बाहर है।

17. (D) कार्यपालक शक्तियाँ
राष्ट्रपति के पास किसी भी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित करने और अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का नियमन करने का अनन्य अधिकार है। यह अधिकार संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूचियों के अंतर्गत आता है और यह राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियों का एक भाग है। इस शक्ति का प्रयोग करके केंद्र सरकार जनजातीय आबादी के हितों की सुरक्षा और उनका समुचित विकास सुनिश्चित करती है।

18. (C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति साधारण विधेयकों पर संसद के दोनों सदनों के बीच बने गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। परंतु धन विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों पर गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा को अंतिम अधिकार प्राप्त होता है, इसलिए वहाँ संयुक्त बैठक संभव नहीं है।

19. (C) केवल II और III
राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र आहुत करने, उनका सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति होती है। वह राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करने की शक्ति रखता है।

20. (A) डॉ. जाकिर हुसैन, वी. वी. गिरि, फखरुद्दीन अली अहमद, एन. संजीव रेड्डी
भारत के राष्ट्रपतियों का सही कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है: डॉ. जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक पद पर रहे, उनके बाद वी. वी. गिरि ने 1969 से 1974 तक सेवा दी। तत्पश्चात फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक पदस्थ रहे और नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। यह क्रम भारत के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास को दर्शाता है।

21. (C) अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक
संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना बाध्यकारी बना दिया गया है। अन्य विधेयकों जैसे धन विधेयक, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक तथा संचित निधि से व्यय वाले विधेयकों हेतु पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है।

Click Here to Buy book on Flipkart

96. भारत के संविधान द्वारा किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है, यह मानते हुए कि वह लोकसभा का सदस्य है?
(A) 21 वर्ष
(B) 25 वर्ष
(C) 30 वर्ष
(D) 35 वर्ष

97. भारतीय राजनीतिक संदर्भ में "कैबिनेट प्रणाली" की अवधारणा गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करती है। मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। यह मौलिक रूप से क्या सुनिश्चित करता है?
(A) कि आम जनता को आधिकारिक वित्तीय व्यय रिकॉर्ड तक पहुंच से पूरी तरह वंचित रखा जाए।
(B) कि सरकार की एकजुटता बनाए रखने के लिए कैबिनेट की बहसें निजी रहें।
(C) कि संसद सदस्यों को कार्यकारी मंत्री के कार्यों पर सवाल उठाने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया जाए।
(D) कि भारत के राष्ट्रपति को कैबिनेट की कार्यवाही के संबंध में जानबूझकर अनभिज्ञ रखा जाए।

98. जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो संविधान के तहत उनके पास निम्नलिखित में से कौन-से विकल्प होते हैं?
(A) वह अपनी सहमति दे सकता है, अपनी सहमति रोक सकता है, या पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटा सकता है।
(B) वह केवल अपनी सहमति दे सकता है या अपनी सहमति रोक सकता है; वह इसे लौटा नहीं सकता।
(C) उसे अपनी सहमति देनी ही होगी; वह इसे रोक नहीं सकता और न ही लौटा सकता है।
(D) वह सलाह के लिए इसे सर्वोच्च न्यायालय में भेज सकता है।

99. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I
P. राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति (कोई स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान नहीं)
Q. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति
R. संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
S. प्रधानमंत्री के कर्तव्य
सूची II
1. अनुच्छेद 73
2. अनुच्छेद 78
3. परिस्थितिजन्य (त्रिशंकु संसद)
4. अनुच्छेद 72
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

100. भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वह राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेता है।
II. राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय, वह राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता।
III. यदि वह त्यागपत्र देना चाहता है, तो उसे अपना त्यागपत्र राज्यसभा के उपसभापति को भेजना होगा।
IV. उनके निर्वाचन के लिए एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है।
उपयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और IV
(C) I, II और IV
(D) II, III और IV

101. यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ रिक्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है?
(A) प्रधानमंत्री
(B) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(C) लोकसभा अध्यक्ष
(D) सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश

102. भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से किसका पद पर रहते हुए निधन हो गया था?
(A) डॉ. एस. राधाकृष्णन
(B) वी. वी. गिरि
(C) कृष्ण कांत
(D) बी. डी. जत्ती

103. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के संदर्भ में, राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी या किसी भी कार्य को स्वयं संभाल सकता है। वह किसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्रवाई करता है?
(A) राज्य के मुख्यमंत्री
(B) राज्य के राज्यपाल
(C) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(D) राज्य विधानमंडल

104. निम्नलिखित में से कौन-सी भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्ति नहीं है?
(A) राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करना
(B) अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करना
(C) प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना
(D) केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना

105. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): भारत के राष्ट्रपति पर "संविधान के उल्लंघन" के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है।
कारण (R): भारत का संविधान अनुच्छेद 61 में "संविधान का उल्लंघन" वाक्यांश को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

Downloaded from www.pdf.tube

(C) 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो
(D) 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो

87. किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सहायता और सलाह से अपने कार्यों का प्रयोग करने के लिए बाध्य है?
(A) अनुच्छेद 73
(B) अनुच्छेद 74
(C) अनुच्छेद 75
(D) अनुच्छेद 78

88. भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वह संविधान संशोधन विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।
II. वह भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
III. वह कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाहकार राय मांग सकता है।
IV. वह निर्वाचन आयोग के परामर्श से संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न का निर्धारण करता है।
उपयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) I, II और III
(B) II, III और IV
(C) I, III और IV
(D) I, II, III और IV

89. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है यदि यह सलाह लोकसभा के विघटन के बाद कार्यवाहक सरकार द्वारा दी जाती है।
कारण (R): एक कार्यवाहक सरकार केवल प्रशासनिक शून्यता को रोकने के लिए कार्य करती है और बड़े नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

90. कौन-सा पदाधिकारी मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच संचार की मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करता है?
(A) कैबिनेट सचिव
(B) प्रधानमंत्री
(C) लोकसभा अध्यक्ष
(D) केंद्रीय गृह मंत्री

91. भारतीय संविधान एक संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है?
(A) शासन व्यवस्था के भीतर नाममात्र और वास्तविक दोनों कार्यपालक प्राधिकारियों की उपस्थिति।
(B) कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों का कठोर पृथक्करण।
(C) विधायिका के लोकप्रिय सदन के प्रति कार्यपालिका शाखा का सामूहिक उत्तरदायित्व।
(D) प्रधानमंत्री द्वारा सरकार का प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व।

92. भारत के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय संसद में उनकी सदस्यता के आधार पर विषम की पहचान कीजिए:
(A) इंदिरा गांधी (1966 में)
(B) एच. डी. देवगौड़ा (1996 में)
(C) मनमोहन सिंह (2004 में)
(D) नरेंद्र मोदी (2014 में)

93. केंद्रीय मंत्रिमंडल में नवनियुक्त एक मंत्री जो संसद के सदस्य नहीं हैं, राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं। राज्यसभा में राजस्थान को कितनी सीटें आवंटित की गई हैं?
(A) 10
(B) 11
(C) 15
(D) 25

NODIA

94. निम्नलिखित में से किसके पास केंद्रीय मंत्रिपरिषद् में मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करने का अधिकार है?
(A) राष्ट्रपति, अपने विवेक से
(B) प्रधानमंत्री
(C) कैबिनेट सचिव
(D) संसद

95. भारत में उप-प्रधानमंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. उप-प्रधानमंत्री का पद संविधान के अनुच्छेद 75 द्वारा स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है।
II. उप-प्रधानमंत्री को नियमित कैबिनेट मंत्री के समान कैबिनेट रैंक प्राप्त होता है।
III. इस पद पर नियुक्तियां ज्यादातर संवैधानिक जनादेश के बजाय राजनीतिक बाध्यताओं से प्रेरित होती हैं।
उपयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

(A) प्रधानमंत्री
(B) लोकसभा अध्यक्ष
(C) राजस्थान के राज्यपाल
(D) भारत के राष्ट्रपति

116. निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने यह अनिवार्य किया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद् की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए, जिससे राष्ट्रपति की नाममात्र भूमिका मजबूत हुई?
(A) 24वां संशोधन
(B) 42वां संशोधन
(C) 61वां संशोधन
(D) 73वां संशोधन

117. राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में 'क्षमा' और 'लघुकरण' में क्या अंतर है?
(A) क्षमा दोषसिद्धि को हटाए बिना सजा के चरित्र को बदल देती है; लघुकरण अपराधी को पूरी तरह से दोषमुक्त कर देता है।
(B) क्षमा सजा और दोषसिद्धि दोनों को हटा देती है; लघुकरण सजा का एक हल्के दंड में प्रतिस्थापन करता है।
(C) क्षमा केवल सजा की अवधि कम करती है; लघुकरण दंड के निष्पादन में अस्थायी रूप से देरी करता है।
(D) उनके बीच कोई कानूनी अंतर नहीं है; दोनों शब्दों का प्रयोग कानून में एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है।

118. राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वह केवल राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के मामलों में ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, बीमारी के दौरान नहीं।
II. राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय, वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन करना बंद कर देता है।
III. वह अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है।
उपयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

119. किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "क्षमादान या परिहार की संवैधानिक वैधता न्यायिक समीक्षा के लिए खुली है यदि निर्णय मनमाना, कपटपूर्ण/दुर्भावनापूर्ण, या बाहरी विचारों पर आधारित है"?
(A) एपुरु सुधाकर मामला
(B) केहर सिंह मामला
(C) दोनों (A) और (B)
(D) एस.पी. गुप्ता मामला

120. उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए:
(A) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा होता है।
(B) इसमें एकल संक्रमणीय मत शामिल होता है।
(C) मतदान गुप्त मतदान द्वारा आयोजित किया जाता है।
(D) राज्य विधानसभाएं इस निर्वाचन में भाग लेती हैं।

121. भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है?
(A) लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव
(B) संसद द्वारा महाभियोग
(C) सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश
(D) राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित संकल्प

122. किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति से संसद के दोनों सदनों के समक्ष 'वार्षिक वित्तीय विवरण' (केंद्रीय बजट) रखवाने की अपेक्षा की जाती है?
(A) अनुच्छेद 110
(B) अनुच्छेद 112
(C) अनुच्छेद 114
(D) अनुच्छेद 116

123. कौन-सी समिति कैबिनेट सचिवालय, सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों में सभी उच्च-स्तरीय नियुक्तियों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है?
(A) राजनीतिक मामलों की समिति
(B) आर्थिक मामलों की समिति
(C) मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति
(D) संसदीय मामलों की समिति

124. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): भारत के राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित सभी विधेयकों पर पूर्ण वीटो शक्ति नहीं है।
कारण (R): राष्ट्रपति 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनिवार्य किए गए अनुसार संविधान संशोधन विधेयकों पर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

125. सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अर्थ है कि:
(A) मंत्रिमंडल केवल सामूहिक निर्णयों के लिए जिम्मेदार है, व्यक्तिगत मंत्री के कार्यों के लिए नहीं।
(B) सभी मंत्री सरकार के सभी कार्यों के लिए संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं।
(C) मंत्रियों को अपनी दैनिक गतिविधियों की रिपोर्ट राष्ट्रपति

Click Here to Buy book on Amazon

को सामूहिक रूप से देनी होगी।
(D) केवल कैबिनेट मंत्री ही जिम्मेदारी उठाते हैं, राज्य मंत्रियों को छोड़कर।

126. मंत्रिपरिषद् के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वह मंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति की सिफारिश कर सकता है।
II. वह मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है।
III. मतभेद की स्थिति में वह किसी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है।
IV. उनके त्यागपत्र से अन्य मंत्रियों के बने रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) I, II और III
(B) II, III और IV
(C) I, III और IV
(D) I, II, III और IV

127. यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है:
(A) केवल वर्तमान प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा।
(B) राष्ट्रपति बिना किसी आगे की प्रक्रिया के तुरंत लोकसभा को भंग कर देता है।
(C) संपूर्ण मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना होगा।
(D) केवल लोकसभा से संबंधित मंत्रियों को त्यागपत्र देना होगा।

128. भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में आवश्यक निर्वाचकों की न्यूनतम संख्या कितनी है?
(A) 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक
(B) 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक
(C) 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक
(D) 100 प्रस्तावक और 100 अनुमोदक

NODIA

129. निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद विशेष रूप से राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है?
(A) अनुच्छेद 74
(B) अनुच्छेद 75
(C) अनुच्छेद 77
(D) अनुच्छेद 78

130. राजस्थान के राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ एक राज्य विधेयक आरक्षित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन इस विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियों का सबसे अच्छा वर्णन करता है (यह मानते हुए कि यह धन विधेयक नहीं है)?
(A) वह सहमति दे सकता है, सहमति रोक सकता है, या राज्यपाल को इसे राज्य के पुनर्विचार के लिए लौटाने का निर्देश दे सकता है।
(B) यदि राज्य विधानमंडल पुनर्विचार के बाद विधेयक को पुनः पारित करता है तो राष्ट्रपति सहमति देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है।
(C) राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के तहत सहमति नहीं रोक सकता है और विधेयक को केवल एक बार लौटाने तक सीमित है।
(D) राष्ट्रपति को 14 दिनों की सख्त संवैधानिक समय-सीमा के भीतर राज्य विधेयक पर अंतिम निर्णय तक पहुंचना होगा।

www.nodia.in

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (D) राष्ट्रपति भारतीय राज्य का प्रमुख होता है और राष्ट्र की एकजुटता का प्रतिनिधित्व करता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भारतीय राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और वह राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली लागू होने के कारण राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालक शक्तियाँ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद् में निहित होती हैं।

2. (C) राज्यसभा के मनोनीत सदस्य
भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अनुच्छेद 54 के तहत एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

3. (A) 1971
राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य निर्धारित करने के लिए 1971 की जनगणना के आधार पर तय की गई राज्य की जनसंख्या का उपयोग किया जाता है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक 1971 की जनगणना को ही जनसंख्या का आधार माना जाएगा।

4. (C) 1000
राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य के एक विधायक के मत का मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है। इसके पश्चात प्राप्त भागफल को 1000 से पुनः विभाजित किया जाता है। इस गणितीय सूत्र का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में मत मूल्य का संतुलन बनाए रखना है।

5. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। भले ही राष्ट्रपति किसी भी सदन में नहीं बैठता, परंतु संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की औपचारिक सहमति प्राप्त किए बिना अधिनियम नहीं बन सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति संसद के सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने जैसी महत्वपूर्ण विधायी शक्तियों का निष्पादन भी करता है।

6. (C) केवल I और III
भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। यह मतदान गुप्त मतदान प्रणाली के तहत आयोजित किया जाता है, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों और शंकाओं की जाँच तथा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 71 के तहत किया जाता है, जिसका निर्णय पूरी तरह अंतिम माना जाता है।

7. (D) P-3, Q-1, R-4, S-2
भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की संरचना तय करता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन की आवश्यक अर्हताओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली पद और गोपनीयता की शपथ से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया की विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है।

8. (B) 15,000 रुपये
भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए 15,000 रुपये की जमानत राशि भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा करना अनिवार्य होता है। यदि चुनाव में उम्मीदवार कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में विफल रहता है, तो यह जमानत राशि ज़ब्त कर ली जाती है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य गैर-गंभीर प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से हतोत्साहित करना है।

9. (D) लोकसभा
संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद की पात्रता के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए तथा लोकसभा का सदस्य चुने जाने की अर्हता रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा या विधानसभा की योग्यता इसके लिए अनिवार्य शर्त नहीं होती है।

10. (A) संविधान का उल्लंघन
अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यद्यपि संविधान में "संविधान का उल्लंघन" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी यह एकमात्र आधार है जिसके तहत संसद महाभियोग चला सकती है। अन्य आधार जैसे सिद्ध कदाचार केवल न्यायाधीशों एवं अन्य संवैधानिक अधिकारियों के निष्कासन हेतु लागू होते हैं।

Downloaded from www.pdf.tube

(C) P-1, Q-4, R-3, S-2
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

70. भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
II. वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसके पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक अर्हताएं होनी चाहिए।
III. उसे भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है।
उपयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

71. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितना है?
(A) पद ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल।
(B) पैंसठ वर्ष की अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने तक।
(C) संविधान द्वारा तय नहीं; राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है।
(D) वैधानिक अनुमोदन के अधीन तीन वर्ष का नवीकरणीय कार्यकाल।

72. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार देता है, लेकिन मतदान के अधिकार के बिना?
(A) अनुच्छेद 76
(B) अनुच्छेद 105
(C) अनुच्छेद 124
(D) अनुच्छेद 88

73. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): भारत के महान्यायवादी को निजी कानूनी अभ्यास से रोक दिया गया है।
कारण (R): महान्यायवादी एक पूर्णकालिक सरकारी सेवक है और सख्त सरकारी रोजगार की श्रेणी में आता है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

74. भारत के महान्यायवादी पर निम्नलिखित में से कौन-सी सीमाएँ लगाई गई हैं?
(A) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व अनुमोदन के बिना उसे किसी भी राज्य सरकार को सलाह देने से रोका गया है।
(B) वह केंद्र सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में अभियुक्त व्यक्तियों का बचाव नहीं कर सकता।
(C) उसे संसद की किसी समिति का सदस्य नियुक्त किए जाने से संवैधानिक रूप से रोका गया है।
(D) उसे किसी भी परिस्थिति में किसी भी निजी कंपनी के निदेशक पद को स्वीकार करने से सख्त रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

75. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बिना स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री से मुख्य रूप से इस कारण भिन्न होता है:
(A) वह विशेष निमंत्रण की आवश्यकता के बिना एक पदेन सदस्य के रूप में नियमित रूप से सभी कैबिनेट बैठकों में भाग लेता है।
(B) वह लोकसभा के बजाय सीधे भारत के राष्ट्रपति के प्रति संवैधानिक रूप से उत्तरदायी है।
(C) वह राष्ट्रपति के औपचारिक अनुमोदन के बिना सीधे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है।
(D) वह अपने ऊपर किसी कैबिनेट मंत्री के बिना अपने आवंटित मंत्रालय पर पूर्ण मंत्री शक्तियों का प्रयोग करता है।

76. शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) के ऐतिहासिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति की शक्ति की प्रकृति को स्पष्ट किया। इस फैसले में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को बरकरार रखा गया था?
(A) राष्ट्रपति के पास मंत्रिपरिषद् की सलाह के बिना कार्य करने की स्वतंत्र कार्यपालक शक्तियाँ हैं।
(B) राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है जो मंत्रिपरिषद् की सलाह से बंधा है।
(C) राष्ट्रपति के पास निरपेक्ष विवेकाधिकार है जो सभी प्रमुख कैबिनेट निर्णयों को ओवरराइड करता है।
(D) राज्य विधेयकों के संबंध में राज्यपाल को राष्ट्रपति की तुलना में व्यापक संवैधानिक विवेक प्राप्त है।

NODIA

77. निम्नलिखित में से कौन-सा मामला राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की न्यायिक समीक्षा से संबंधित है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि राष्ट्रपति की शक्ति निरपेक्ष नहीं है और राज्य विधानसभा का विघटन न्यायिक जांच के अधीन है?
(A) यू.एन. राव बनाम इंदिरा गांधी (1971)
(B) केहर सिंह मामला (1989)
(C) डी.सी. वाधवा मामला (1987)
(D) एस.आर. बोम्मई मामला (1994)

78. राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के पारित होने और व्यपगत होने के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं के क्रम पर विचार कीजिए। उन्हें सही क्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश का प्रख्यापन।
2. संसद का पुनः समवेत होना।

22. (D) राष्ट्रपति बिना कोई औपचारिक कार्रवाई किए विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखता है।
पॉकेट वीटो का तात्पर्य राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर न तो अपनी सहमति देता है, न असहमति जताता है और न ही उसे लौटाता है। राष्ट्रपति विधेयक को बिना किसी समय-सीमा के अनिश्चित काल के लिए अपने पास लंबित रखता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर निर्णय लेने के लिए कोई निश्चित अवधि तय नहीं है।

23. (A) P-2, Q-1, R-3, S-4
अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में लघुकरण का अर्थ दंड का स्वरुप बदलकर उसे हल्का करना है। परिहार में दंड की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि कम की जाती है। विराम के अंतर्गत किसी विशेष परिस्थिति जैसे शारीरिक अपंगता या गर्भावस्था के आधार पर सजा को कम किया जाता है। प्रविलंबन का अर्थ दंड, विशेषकर मृत्युदंड के निष्पादन पर अस्थायी रोक लगाना है।

24. (A) I, II और III
अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति एक कार्यपालक शक्ति है, जो न्यायपालिका से स्वतंत्र होती है। यह शक्ति सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजा तथा मृत्युदंड के सभी मामलों में लागू होती है। हालांकि, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग अपने व्यक्तिगत विवेक से नहीं करता, बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। मारू राम मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को स्पष्ट किया था।

25. (C) राष्ट्रपति सैन्य अदालत की सजा को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है।
राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में दो प्रमुख अंतर हैं। पहला अंतर यह है कि राष्ट्रपति सैन्य अदालत (कोर्ट मार्शल) द्वारा दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति नहीं होती। दूसरा अंतर यह है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, वह केवल उसका लघुकरण या परिहार कर सकता है।

26. (B) 6 महीने और 6 सप्ताह
अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह होती है। संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है। जब संसद का पुनः समवेत सत्र शुरू होता है, तो अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाता है।

27. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद की विधायी शक्ति के समानांतर नहीं है, बल्कि यह केवल आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की एक कार्यपालक शक्ति है। अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद का कोई एक या दोनों सदन सत्र में न हों। यदि संसद सत्र में हो तो अध्यादेश जारी करना असंवैधानिक माना जाता है, क्योंकि कानून बनाना संसद का मूल अधिकार है।

28. (D) आर.सी. कूपर मामला
आर. सी. कूपर बनाम भारत संघ (1970) के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की संतुष्टि की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यदि अध्यादेश जारी करने का निर्णय कपटपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण या राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से लिया गया है, तो अदालत उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इस फैसले ने कार्यपालक शक्ति के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया।

29. (D) I, II और III
राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में कई महत्वपूर्ण अधिकार शामिल हैं। धन विधेयक और अनुदान की मांगें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं की जा सकतीं। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे के लिए हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करता है। इसके अलावा, किसी अप्रत्याशित संकट से निपटने के लिए वह भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम धनराशि स्वीकृत कर सकता है।

30. (A) अनुच्छेद 352
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अथवा इनके गंभीर खतरे की स्थिति में पूरे भारत या इसके किसी भाग में लागू किया जा सकता है। 44वें संशोधन के बाद अब कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा कर सकता है।

31. (B) संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल हैं।
अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा होने पर, राष्ट्रपति संघ या राज्यों के तहत सेवा करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती के निर्देश दे सकता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। वित्तीय स्थिरता बहाल करने के उद्देश्य से यह एक अत्यंत दुर्लभ और असाधारण संवैधानिक उपाय माना जाता है।

32. (C) भारत के राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेक नहीं है; उसके पास केवल परिस्थितिजन्य विवेक है।
भारतीय संविधान राष्ट्रपति को कोई स्पष्ट 'संवैधानिक विवेक' प्रदान नहीं करता है, क्योंकि अनुच्छेद 74 के तहत वह मंत्रिपरिषद् की सलाह मानने के लिए बाध्य है। हालाँकि, राष्ट्रपति के पास कुछ 'परिस्थितिजन्य विवेक' होते हैं, जैसे त्रिशंकु लोकसभा में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, अल्पमत सरकार द्वारा परामर्श देने पर लोकसभा भंग करना या अविश्वास प्रस्ताव के बाद सरकार को बर्खास्त करना।

Click Here to Buy book on Flipkart

56. (C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
अनुच्छेद 75(2) के तहत मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उनके प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं। हालाँकि, राष्ट्रपति किसी मंत्री को अपने पूर्ण विवेक से नहीं हटा सकता। वह केवल प्रधानमंत्री की सलाह और सिफारिश पर ही किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। इस प्रकार कार्यपालक निष्कासन में प्रधानमंत्री का परामर्श संवैधानिक रूप से अनिवार्य शर्त होती है।

57. (D) संसदीय सचिव
भारत में मंत्रिपरिषद् की तीन मान्यता प्राप्त श्रेणियां होती हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार या संबद्ध) तथा उप-मंत्री। संसदीय सचिव मंत्रियों की मान्यता प्राप्त श्रेणी का हिस्सा नहीं हैं। यद्यपि अतीत में कभी-कभी प्रशासनिक सहायता हेतु इनकी नियुक्ति की जाती रही है, परंतु 91वें संशोधन और आधुनिक व्यवस्था में इन्हें मंत्रिपरिषद् के औपचारिक पदानुक्रम में शामिल नहीं माना जाता।

58. (A) केवल I और II
राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को अपना पद संभालने से पहले पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। गोपनीयता की शपथ मंत्री को सरकारी रहस्यों को सुरक्षित रखने का वचन देती है। हालाँकि, केंद्रीय मंत्रियों तथा संसद सदस्यों के लिए शपथ का निर्धारित प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है, दूसरी अनुसूची में नहीं। दूसरी अनुसूची वेतन और भत्तों से संबंधित है।

59. (C) वह छह महीने के लिए सेवा कर सकता है, जिसके भीतर उसे संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है।
अनुच्छेद 75(5) के तहत ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री या प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। हालाँकि, उस व्यक्ति को अपनी नियुक्ति की तिथि से निरंतर 6 महीने की अवधि के भीतर संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) का सदस्य बनना अनिवार्य होता है, अन्यथा 6 महीने समाप्त होते ही उसका मंत्री पद स्वतः समाप्त हो जाता है।

60. (A) 2, 1, 4, 3
भारत की कार्यपालिका का प्रशासनिक और नीतिगत पदानुक्रम उच्चतम से निम्नतम क्रम में इस प्रकार निर्धारित है: सर्वप्रथम प्रधानमंत्री संपूर्ण सरकार और मंत्रिपरिषद् का प्रमुख होता है। इसके बाद मंत्रिमंडल (कैबिनेट) के मंत्री आते हैं जो नीति-निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तीसरे स्थान पर राज्य मंत्री और सबसे निचले स्तर पर उप-मंत्री आते हैं जो वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता करते हैं।

61. (A) सार्वजनिक कार्यों के लिए राष्ट्रपति के आदेशों पर किसी मंत्री के प्रति-हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है।
ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्रियों के विधिक उत्तरदायित्व की कोई प्रणाली नहीं है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए किसी भी सार्वजनिक आदेश या अध्यादेश पर किसी मंत्री के प्रति-हस्ताक्षर (Counter-signature) की कानूनी आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, अदालतें यह जाँच नहीं कर सकतीं कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी थी, जिससे यह प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय रहती है।

62. (D) I, II, III और IV
मंत्रिपरिषद् एक व्यापक निकाय है जिसमें सभी श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल इसका एक छोटा निर्णय लेने वाला आंतरिक समूह है। 'मंत्रिमंडल' शब्द मूल संविधान में नहीं था। मंत्रिमंडल सरकार की मुख्य नीति-निर्माता संस्था है जो नियमित बैठकें करती है और लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद् के सामूहिक उत्तरदायित्व को व्यावहारिक रूप से संचालित और लागू करती है।

63. (C) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
'मंत्रिमंडल' (Cabinet) शब्द को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था। इसे 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। इस संशोधन के अनुसार आपातकाल की घोषणा केवल तभी की जा सकती है जब प्रधानमंत्री और कैबिनेट रैंक के मंत्रियों वाली 'मंत्रिमंडल' की लिखित सिफारिश प्राप्त हो। संविधान में केवल इसी अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है।

64. (D) इसके निर्णय सलाहकारी होते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा एकतरफा बदले जा सकते हैं।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में मंत्रिमंडल सर्वोच्च नीति-निर्माता और निर्णय लेने वाली कार्यपालक संस्था है। इसके निर्णय केवल औपचारिक सलाहकारी नहीं होते, बल्कि वे संपूर्ण सरकार पर बाध्यकारी नीतियां बनते हैं। यद्यपि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है, फिर भी वह सामूहिक निर्णयों को एकतरफा नहीं बदल सकता, क्योंकि संसदीय प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व और आम सहमति के सिद्धांत पर कार्य करती है।

65. (A) किचन कैबिनेट
'किचन कैबिनेट' या 'आंतरिक मंत्रिमंडल' एक छोटा, अनौपचारिक निकाय होता है जिसमें प्रधानमंत्री के कुछ अत्यंत विश्वसनीय कैबिनेट सहयोगी, मित्र या परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर त्वरित निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री अक्सर इस समूह से परामर्श करते हैं। यह एक गैर-संवैधानिक और अनौपचारिक संस्था है जो औपचारिक कैबिनेट से परे काम करती है।

66. (C) इनका उद्भव संविधानेत्तर है।
कैबिनेट समितियाँ संविधानेत्तर (Non-constitutional) या संविधान से परे की संस्थाएँ हैं। संविधान में इनका सीधा उल्लेख नहीं है, बल्कि इनका गठन कार्य आवंटन नियमों (Rules of Business) के तहत किया जाता है। प्रधानमंत्री समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार इनका गठन करता है। हालाँकि इनमें मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री होते हैं, लेकिन गैर-कैबिनेट मंत्रियों को भी इनकी सदस्यता दी जा सकती है।

NODIA

परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति केवल लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह और सिफारिश के आधार पर ही की जाती है।

45. (C) एक महीना
जब लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री को सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए विश्वास मत प्राप्त करने हेतु आमतौर पर 1 महीने का मानक समय प्रदान करता है।

46. (D) अंतर-राज्यीय परिषद
भारत का प्रधानमंत्री अंतर-राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की अध्यक्षता भी करता है। प्रांतीय या क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है।

47. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् का प्रमुख और सरकार की धुरी होता है। संविधान के तहत मंत्रिपरिषद् का अस्तित्व प्रधानमंत्री से ही जुड़ा होता है। इसलिए यदि वर्तमान प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है या उसका पद पर रहते हुए निधन हो जाता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद् स्वतः ही विघटित हो जाती है। इसके विपरीत, किसी अन्य मंत्री के त्यागपत्र से केवल एक रिक्ति उत्पन्न होती है।

48. (A) प्रशासन और विधान से संबंधित मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देना।
अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह संघ के प्रशासन और विधान से संबंधित मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को दे। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति संघ के मामलों के प्रशासन या विधायी प्रस्तावों के संबंध में कोई जानकारी मांगे, तो प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि वह ऐसी जानकारी राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करे।

49. (C) चंद्रशेखर
चंद्रशेखर भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इस पद पर आसीन होने से पहले कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। इसके विपरीत, मोरारजी देसाई (बॉम्बे राज्य), चरण सिंह (उत्तर प्रदेश) तथा वी. पी. सिंह (उत्तर प्रदेश) प्रधानमंत्री बनने से पूर्व अपने-अपने राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे। चंद्रशेखर सीधे केंद्रीय राजनीति के माध्यम से प्रधानमंत्री बने थे।

50. (A) I, II और III
राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह पर पुनर्विचार की मांग कर सकता है, परंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह उस पर बाध्यकारी होती है। प्रधानमंत्री महान्यायवादी तथा सीएजी जैसे अधिकारियों की नियुक्ति में परामर्श देता है और राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह दे सकता है। हालाँकि, राष्ट्रपति कार्यकारी निर्णयों पर पूछताछ करने के लिए प्रधानमंत्री को संसद में नहीं बुला सकता है।

51. (D) लॉर्ड मॉर्ले
ब्रिटिश राजनीतिक विचारक लॉर्ड मॉर्ले ने प्रधानमंत्री की स्थिति का वर्णन करते हुए उन्हें "मंत्रिमंडल के मेहराब की आधारशिला" (Key-stone of the cabinet arch) कहा था। उन्होंने प्रधानमंत्री को "समकक्षों में प्रथम" (Primus inter pares) भी माना। यह उक्ति सरकार की संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल के गठन, उसके संचालन और समाप्ति में प्रधानमंत्री की केंद्रीय एवं सर्वोपरि भूमिका को रेखांकित करती है।

52. (C) 1976 का 42वां संशोधन अधिनियम
1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 74(1) में संशोधन करके यह स्पष्ट रूप से अनिवार्य बना दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। बाद में 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को केवल एक बार सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बनी रही।

53. (A) P-1, Q-2, R-3, S-4
भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। ये निकाय राष्ट्रीय नीतियां और केंद्र-राज्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। इसके विपरीत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री इन परिषदों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

54. (B) लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%
2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 75(1A) को जोड़ा गया। इसके अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद् में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। इस संवैधानिक संशोधन का मुख्य उद्देश्य जंबो मंत्रिमंडलों के गठन पर रोक लगाना और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करना था।

NODIA

55. (B) लोकसभा
संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन अर्थात 'लोकसभा' के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्री अपने सभी कार्यों और नीतियों के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। यदि लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद् को सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है।

33. (D) यूनाइटेड किंगडम
भारत ने वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जो यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) की राजनीतिक व्यवस्था से प्रेरित है। इस प्रणाली में राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति) नाममात्र की कार्यपालिका होता है, जबकि सरकार का प्रमुख (प्रधानमंत्री) वास्तविक कार्यपालिका के रूप में शासन चलाता है। यह व्यवस्था शक्तियों के पूर्ण पृथक्करण के बजाय विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय पर आधारित है।

34. (C) लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्ह होना चाहिए
उपराष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक पात्रताओं में भारत का नागरिक होना, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी होना तथा किसी लाभ के पद पर न होना शामिल है। हालाँकि, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अर्ह होना चाहिए, न कि लोकसभा के। लोकसभा का सदस्य चुने जाने की अर्हता राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य शर्त होती है।

35. (B) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य
अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्मित निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जो इन दोनों चुनावों में प्रमुख अंतर है।

36. (A) P-3, Q-4, R-2, S-1
उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेदों में अनुच्छेद 63 यह उल्लेख करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि और प्रक्रिया को निर्धारित करता है।

37. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि एक व्यक्ति एक ही समय में कार्यपालक प्रमुख और विधायी पीठासीन अधिकारी की दोहरी भूमिकाओं का संचालन नहीं कर सकता। इस अवधि के दौरान सभापति के कर्तव्यों का पालन राज्यसभा के उपसभापति द्वारा किया जाता है।

38. (D) I, III और IV
उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के प्रभावी बहुमत से पारित तथा लोकसभा की सहमति वाले संकल्प की आवश्यकता होती है। इसके लिए कम से कम 14 दिनों की अग्रिम सूचना देनी होती है। संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का कोई आधार उल्लेखित नहीं है। इसके अलावा, इसके लिए महाभियोग जैसी जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता भी नहीं होती है।

39. (D) भारत के राष्ट्रपति
अनुच्छेद 67 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। यदि वह अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र देना चाहता है, तो उसे अपना हस्तलिखित त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करना होता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही सौंपता है, जिससे संवैधानिक निरंतरता बनी रहती है।

40. (B) छह महीने
जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के कारण अचानक रिक्त हो जाता है, तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालता है। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक ही इस पद पर रह सकता है। इस 6 महीने की समय-सीमा के भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन संपन्न कराना अनिवार्य होता है ताकि स्थायी व्यवस्था स्थापित हो सके।

41. (D) वे अमान्य नहीं होते और पूर्ण प्रभाव में बने रहते हैं।
अनुच्छेद 71 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का फैसला केवल भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर देता है, तो उस निर्णय की तिथि से पहले उस व्यक्ति द्वारा उपराष्ट्रपति या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किए गए सभी कार्य वैध रहते हैं तथा अमान्य नहीं होते हैं।

42. (C) केवल II और III
भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के रूप में उस पद के लिए किसी वेतन का प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में नियमित वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। हालाँकि, जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या उसके कार्यों का निर्वहन करता है, तो वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन, भत्तों और विशेषाधिकारों का पूर्ण रूप से हकदार बन जाता है।

43. (A) 3, 4, 1, 2
भारत के इन प्रधानमंत्रियों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है: वी. पी. सिंह ने दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक कार्य किया। उनके पश्चात चंद्रशेखर ने नवंबर 1990 से जून 1991 तक पद संभाला। तत्पश्चात पी. वी. नरसिम्हा राव जून 1991 से मई 1996 तक प्रधानमंत्री रहे और एच. डी. देवगौड़ा ने जून 1996 से अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया।

44. (B) भारत के राष्ट्रपति
संविधान के अनुच्छेद 75(1) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। संसदीय

Downloaded from www.pdf.tube

67. (D) राजनीतिक मामलों की समिति
राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Political Affairs) को सरकारी तंत्र में इसके अत्यधिक प्रभाव और व्यापक शक्तियों के कारण 'सुपर-कैबिनेट' कहा जाता है। यह समिति देश के सभी महत्वपूर्ण घरेलू, विदेश और राजनीतिक नीतिगत मुद्दों का संचालन एवं समाधान करती है। इस अति-प्रभावशाली समिति की अध्यक्षता हमेशा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

68. (D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।
संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते, बल्कि इसकी अध्यक्षता आमतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री या कोई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री करता है। यद्यपि प्रधानमंत्री अधिकांश स्थायी कैबिनेट समितियों की अध्यक्षता करते हैं (जैसे राजनीतिक, आर्थिक और नियुक्ति समितियां), परंतु वह सभी समितियों के प्रमुख नहीं होते हैं। इसलिए पहला कथन तथ्यात्मक रूप से गलत है।

69. (A) P-1, Q-2, R-3, S-4
विभिन्न कैबिनेट समितियों की अध्यक्षता विशिष्ट मंत्रियों द्वारा की जाती है। राजनीतिक मामलों की समिति, आर्थिक मामलों की समिति तथा मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति—इन तीनों अति-महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। इसके विपरीत, संसद के सत्रों और विधायी कार्यों का समन्वय करने वाली संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है।

70. (D) I, II और III
भारत का महान्यायवादी (Attorney General) देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी बनने के लिए व्यक्ति के पास सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता होनी चाहिए। उसे भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सरकार का पक्ष रखने और सुनवाई का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है।

71. (C) संविधान द्वारा तय नहीं; राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है।
संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त (Pleasure of the President) पद धारण करता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति द्वारा उसे किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है। परंपरा के अनुसार, जब सरकार बदलती है या मंत्रिपरिषद् त्यागपत्र देती है, तो महान्यायवादी भी त्यागपत्र दे देता है।

72. (D) अनुच्छेद 88
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) की कार्यवाही, संयुक्त बैठक तथा संसद की किसी भी समिति में बोलने और भाग लेने का विशेष अधिकार प्रदान करता है। हालाँकि, अनुच्छेद 88 यह भी स्पष्ट करता है कि महान्यायवादी को संसद के भीतर किसी भी प्रस्ताव या विधेयक पर मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

73. (D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।
भारत का महान्यायवादी कोई पूर्णकालिक सरकारी सेवक नहीं है और न ही वह सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में आता है। इसलिए उसे निजी कानूनी वकालत करने से पूरी तरह से नहीं रोका गया है। वह निजी मामलों में वकालत कर सकता है, बशर्ते वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या मुकदमा न लड़े। इस प्रकार पहला कथन गलत है परंतु कारण में दिया गया वर्णन सही है।

74. (B) वह केंद्र सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में अभियुक्त व्यक्तियों का बचाव नहीं कर सकता।
महान्यायवादी के स्वतंत्र निजी अभ्यास पर कुछ संवैधानिक और विधिक सीमाएं आरोपित की गई हैं। वह भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्तियों का बचाव या वकालत नहीं कर सकता है। इसके अलावा, वह सरकार की सहमति के बिना किसी व्यावसायिक कंपनी या निगम में निदेशक का पद स्वीकार नहीं कर सकता तथा सरकार के खिलाफ सलाह नहीं दे सकता।

NODIA

75. (D) वह अपने ऊपर किसी कैबिनेट मंत्री के बिना अपने आवंटित मंत्रालय पर पूर्ण मंत्री शक्तियों का प्रयोग करता है।
स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और बिना स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री में मुख्य अंतर प्रशासनिक नियंत्रण का होता है। स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री अपने मंत्रालय या विभाग का प्रभारी होता है और सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है; उसके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता। वहीं साधारण राज्य मंत्री किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करता है और उसकी सहायता करता है।

76. (B) राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है जो मंत्रिपरिषद् की सलाह से बंधा है।
शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) के प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया कि राष्ट्रपति केवल एक संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख है। राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का प्रयोग हमेशा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद् की सहायता और सलाह से ही करना अनिवार्य है। राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत निर्णय नहीं ले सकता है।

77. (D) एस.आर. बोम्मई मामला (1994)
एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की उद्घोषणा निरपेक्ष नहीं है और यह पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि राष्ट्रपति शासन दुर्भावनापूर्ण आधार पर लगाया जाता है, तो न्यायालय भंग विधानसभा को पुनः बहाल कर सकता है।

उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य होने के नाते राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेता है। इसके अलावा त्यागपत्र वह उपसभापति को नहीं, बल्कि राष्ट्रपति को सौंपता है।

101. (B) भारत के मुख्य न्यायाधीश
राष्ट्रपति (कार्यवहन) अधिनियम 1969 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद किसी कारणवश एक साथ रिक्त हो जाते हैं, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। यदि मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त हो, तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश इस जिम्मेदारी को निभाता है, जैसा कि 1969 में न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला ने किया था।

102. (C) कृष्ण कांत
कृष्ण कांत भारत के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ था। उन्होंने 1997 से 2002 तक भारत के 10वें उपराष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएँ दी थीं। जुलाई 2002 में उनका कार्यकाल समाप्त होने से कुछ ही समय पूर्व अचानक निधन हो गया। भारत के अन्य किसी भी उपराष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान नहीं हुई है।

103. (B) राज्य के राज्यपाल
संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा इस बात से संतुष्ट होने पर कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। इसके बाद राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं।

104. (D) केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्ति नहीं है, बल्कि यह अधिकार भारत के प्रधानमंत्री के पास होता है। राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियों में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करना, केंद्र शासित प्रदेशों का अपने प्रशासकों के माध्यम से प्रशासन चलाना तथा प्रधानमंत्री एवं अन्य केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करना शामिल होता है।

105. (C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर "संविधान के उल्लंघन" के आधार पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। हालाँकि, भारतीय संविधान में "संविधान का उल्लंघन" क्या है, इस वाक्यांश की कोई स्पष्ट व्याख्या या परिभाषा नहीं दी गई है। इसलिए पहला कथन सही है, जबकि कारण में दी गई बात असत्य और तथ्यात्मक रूप से गलत है।

106. (C) गैर-धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना।
राष्ट्रपति के 'निलंबनकारी वीटो' (Suspensive Veto) का अर्थ है जब वह संसद द्वारा पारित किसी साधारण (गैर-धन) विधेयक को अपनी सहमति न देकर संसद के पास पुनर्विचार हेतु वापस लौटा देता है। हालाँकि, यदि संसद उस विधेयक को बिना किसी संशोधन के या संशोधन के साथ दोबारा साधारण बहुमत से पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य हो जाता है।

107. (C) 82
91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद् में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 550 मानी जाए, तो 550 का 15 प्रतिशत 82.5 आता है। गणितीय और संवैधानिक नियमों के तहत मंत्रियों की अधिकतम संख्या 82 संभव होगी।

108. (A) P-4, Q-3, R-1, S-2
भारत में वास्तविक कार्यपालिका 'वस्तुतः' (De facto) होती है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करती है। नाममात्र की कार्यपालिका 'विधि-अनुसार' (De jure) होती है जो राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति भारतीय राज्य का प्रमुख (Head of the State) होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख (Head of the Government) होता है। यह व्यवस्था संसदीय प्रणाली के मूल स्वरूप को दर्शाती है।

109. (A) केवल I और II
अनुच्छेद 88 और 105 के तहत भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या संसदीय समिति का सदस्य नामित हो सकता है और बैठकों में भाग ले सकता है। इस दौरान वह एक सांसद को मिलने वाले सभी विशेषाधिकारों का उपभोग करता है। हालाँकि, वह संसद का सदस्य न होने के कारण किसी भी स्थिति में, यहाँ तक कि टाई होने पर भी मतदान नहीं कर सकता।

110. (C) भारत के महान्यायवादी
अनुच्छेद 76 के तहत भारत का महान्यायवादी केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार को कानून से जुड़े जिन मामलों पर राय देने के लिए संदर्भित किया जाता है, उन सभी विषयों पर विधिक सलाह देना महान्यायवादी का प्राथमिक कर्तव्य है। वह सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है।

111. (B) कैबिनेट समितियाँ
कैबिनेट समितियाँ भारत में गैर-संवैधानिक या संविधानेत्तर निकाय हैं, जिनका गठन कार्यपालिका की प्रक्रिया को आसान बनाने और मंत्रिमंडल के बोझ को कम करने हेतु किया जाता है। ये समितियां जटिल नीतिगत मुद्दों का गहन अध्ययन करती हैं और त्वरित निर्णय लेने में मदद करती हैं। यद्यपि ये संविधान में उल्लेखित नहीं हैं, फिर भी सरकार चलाने में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

112. (C) लोकसभा में बहुमत का नेतृत्व करना।
भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का मुख्य आधार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होना है। संसदीय शासन प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति

Click Here to Buy book on Amazon

89. (B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
जब लोकसभा भंग हो जाती है, तो अंतरिम या कार्यवाहक सरकार केवल प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए कार्य करती है और कोई प्रमुख नीतिगत फैसला नहीं ले सकती। यू. एन. राव बनाम इंदिरा गांधी (1971) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 74(1) अनिवार्य है और राष्ट्रपति हमेशा मंत्रिपरिषद् की सलाह पर ही कार्य करेगा, भले ही लोकसभा भंग हो चुकी हो।

90. (B) प्रधानमंत्री
संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच संचार की मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह प्रधानमंत्री का संवैधानिक दायित्व है कि वह संघ के प्रशासन, नीतिगत मामलों तथा विधायी प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों की जानकारी समय-समय पर राष्ट्रपति को दे तथा राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराए।

91. (B) कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों का कठोर पृथक्करण।
संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं होता, बल्कि इनमें घनिष्ठ समन्वय और सामंजस्य पाया जाता है। कार्यपालिका के सदस्य विधायिका में से ही चुने जाते हैं। शक्तियों का कठोर पृथक्करण अध्यक्षीय शासन प्रणाली (जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका) की मुख्य विशेषता है, जो भारतीय संसदीय व्यवस्था में लागू नहीं होता है।

92. (D) नरेंद्र मोदी (2014 में)
इंदिरा गांधी (1966), एच. डी. देवगौड़ा (1996) तथा मनमोहन सिंह (2004) जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब वे राज्यसभा के सदस्य थे या किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इसके विपरीत, नरेंद्र मोदी 2014 में अपनी पहली नियुक्ति के समय लोकसभा के निर्वाचित सदस्य (वाराणसी सीट से) के रूप में चुने गए थे। इस आधार पर वे अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न हैं।

93. (A) 10
भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में आवंटित सीटों का विवरण दिया गया है। इस अनुसूची के अनुसार राजस्थान राज्य को राज्यसभा में कुल 10 सीटें आवंटित की गई हैं। यदि संसद का सदस्य न होने वाला कोई व्यक्ति मंत्री बनता है, तो वह इन 10 सीटों में से किसी भी रिक्त सीट पर चुनाव लड़कर सदस्य बन सकता है।

94. (B) प्रधानमंत्री
केंद्रीय सरकार में मंत्रियों के बीच विभागों (मंत्रालयों) का आवंटन और उनमें फेरबदल करने का अनन्य अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है। यद्यपि मंत्रियों की औपचारिक नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु राष्ट्रपति यह कार्य पूरी तरह प्रधानमंत्री की सलाह और सिफारिश पर करता है। प्रधानमंत्री यह तय करता है कि किस मंत्री को कौन-सा मंत्रालय सौंपा जाएगा।

95. (B) केवल II और III
भारत के संविधान में 'उप-प्रधानमंत्री' का कोई स्पष्ट उल्लेख या पद का प्रावधान नहीं है; यह एक संविधानेत्तर पद है। उप-प्रधानमंत्री की नियुक्ति मुख्य रूप से राजनीतिक आवश्यकताओं, गठबंधन संतुलन या दलीय गुटबाज़ी को शांत करने के लिए की जाती है। प्रशासनिक और संवैधानिक रूप से उप-प्रधानमंत्री को कैबिनेट मंत्री का ही दर्जा और वेतन-भत्ते प्राप्त होते हैं।

96. (B) 25 वर्ष
संविधान में प्रधानमंत्री के लिए अलग से न्यूनतम आयु तय नहीं है। परंतु अनुच्छेद 75 और 84 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनकर प्रधानमंत्री बनता है, तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी।

97. (B) कि सरकार की एकजुटता बनाए रखने के लिए कैबिनेट की बहसें निजी रहें।
संसदीय व्यवस्था में मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। गोपनीयता का यह सिद्धांत मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करता है कि कैबिनेट बैठकों में होने वाली नीतियां, विचार-विमर्श और मंत्रियों की भिन्न राय जनता या मीडिया के सामने सार्वजनिक न हों। इससे सरकार की आंतरिक एकजुटता बनी रहती है और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत मजबूती से लागू होता है।

98. (B) वह केवल अपनी सहमति दे सकता है या अपनी सहमति रोक सकता है; वह इसे लौटा नहीं सकता।
संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार जब कोई धन विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति या तो उस पर अपनी सहमति दे सकता है या अपनी सहमति रोक सकता है। परंतु राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता, क्योंकि धन विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है।

99. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां संविधान में स्पष्ट नहीं हैं, यह त्रिशंकु संसद जैसी परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियाँ प्रदान करता है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को प्रशासनिक और विधायी निर्णयों की सूचना देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है।

NODIA

100. (B) केवल II और IV
जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। हालाँकि,

78. (B) 1, 2, 3, 4
अध्यादेश की प्रक्रिया का सही क्रमिक क्रम इस प्रकार है: सर्वप्रथम संसद का सत्र न होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश प्रख्यापित करता है। इसके पश्चात संसद के दोनों सदन पुनः समवेत होते हैं। पुनः समवेत होने की तिथि से 6 सप्ताह की समय-सीमा की गणना की जाती है। यदि इन 6 सप्ताह में संसद इसे स्वीकृत नहीं करती, तो अध्यादेश स्वतः निष्प्रभावी होकर व्यपगत हो जाता है।

79. (A) P-2, Q-4, R-1, S-3
संवैधानिक विधि से जुड़े प्रमुख मामलों में एपुरु सुधाकर मामला राष्ट्रपति/राज्यपाल की क्षमादान शक्ति की न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। यू.एन. राव मामला स्थापित करता है कि लोकसभा विघटित होने पर भी मंत्रिपरिषद् बनी रहती है। डी.सी. वाधवा मामले में बार-बार अध्यादेश जारी करने को असंवैधानिक ठहराया गया, जबकि बोम्मई मामला अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा से संबंधित है।

80. (B) राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए सलाह को एक बार मंत्रिपरिषद् को लौटा सकता है।
1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 74(1) में एक महत्वपूर्ण परंतु जोड़ा। इसके अनुसार राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद् द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने का अधिकार दिया गया। हालाँकि, यदि मंत्रिपरिषद् पुनर्विचार के पश्चात वही सलाह दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति उस सलाह को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह बाध्य होता है।

81. (D) राष्ट्रपति विधि-अनुसार (नाममात्र) कार्यपालक है, और प्रधानमंत्री वस्तुतः (वास्तविक) कार्यपालक है।
भारत की संवैधानिक संरचना में 'विधि-अनुसार' (De jure) कार्यपालक की भूमिका राष्ट्रपति निभाता है, क्योंकि संघ की सभी शक्तियां औपचारिक रूप से उसमें निहित होती हैं। इसके विपरीत, 'वस्तुतः' (De facto) कार्यपालक की भूमिका प्रधानमंत्री निभाता है, जो सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद् के माध्यम से शासन की वास्तविक शक्तियों एवं नीतियों का संचालन तथा प्रयोग करता है।

82. (B) सामूहिक उत्तरदायित्व
सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह अनिवार्य बनाता है कि मंत्रिमंडल के सभी निर्णय सर्वसम्मत माने जाएंगे। यदि कोई मंत्री कैबिनेट के किसी निर्णय से असहमत है और संसद या जनता के समक्ष उसका बचाव करने में असमर्थ महसूस करता है, तो नैतिक और संवैधानिक नियमों के तहत उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और आर. शंमुगम चेट्टी इसके उदाहरण हैं।

83. (C) संसद
भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री और अन्य सभी मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते समय-समय पर भारत की संसद द्वारा निर्मित विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जब तक संसद इस संबंध में नया कानून नहीं बनाती, तब तक मंत्रियों के वेतन और भत्ते संविधान की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार ही दिए जाते हैं। इनका निर्धारण कार्यपालिका अपने स्तर पर नहीं कर सकती।

84. (C) केवल I और III
भारत के महान्यायवादी को उसके विधिक दायित्वों के निष्पादन में सहायता प्रदान करने के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। हालाँकि, अनुच्छेद 76 केवल महान्यायवादी के संवैधानिक पद का प्रावधान करता है। सॉलिसिटर जनरल का पद संवैधानिक नहीं है, बल्कि यह एक वैधानिक/प्रशासनिक व्यवस्था है जिसका गठन संसदीय नियमों के तहत किया गया है।

85. (B) पूरी मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना होगा।
अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री या पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, या सरकार के किसी नीतिगत विधेयक को खारिज कर देती है, तो इसका अर्थ संपूर्ण सरकार में विश्वास की कमी माना जाता है। इस स्थिति में केवल वही मंत्री नहीं बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है।

86. (D) 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा तय नहीं की गई है, और इसलिए यही नियम महान्यायवादी पर भी लागू होता है। महान्यायवादी बनने हेतु केवल यह आवश्यक है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, अथवा राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो।

87. (B) अनुच्छेद 74
संविधान के अनुच्छेद 74(1) में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार ही अपनी कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है, जिसे 42वें और 44वें संशोधनों द्वारा संशोधित और स्पष्ट किया गया था।

88. (B) II, III और IV
राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श मांग सकता है तथा चुनाव आयोग से परामर्श कर सांसदों की अयोग्यता का फैसला करता है। हालाँकि, वह संविधान संशोधन विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि 24वें संशोधन 1971 के बाद ऐसे विधेयकों पर सहमति देना राष्ट्रपति के लिए पूरी तरह बाध्यकारी बना दिया गया है।

Downloaded from www.pdf.tube

को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, तो सबसे बड़े गठबंधन के नेता को यह अवसर दिया जाता है।

113. (A) वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अनुसार केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के 'प्रसादपर्यन्त' (Pleasure of the President) पद धारण करते हैं। इसे मंत्रियों का 'व्यक्तिगत उत्तरदायित्व' कहा जाता है। इसका व्यावहारिक तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उसकी व्यक्तिगत विफलता या मतभेद के आधार पर कभी भी बर्खास्त कर सकता है, भले ही सरकार को बहुमत प्राप्त हो।

114. (A) वह लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकता।
यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है, तो वह संसद के दोनों सदनों में बोल सकता है और कार्यवाही में भाग ले सकता है। परंतु, संवैधानिक नियमानुसार वह लोकसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव या किसी अन्य प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि संसद सदस्य केवल उसी सदन में वोट दे सकता है जिसका वह औपचारिक सदस्य होता है।

115. (D) भारत के राष्ट्रपति
अनुच्छेद 75 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद् के सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त ही पद पर बने रहते हैं। इसलिए यदि कोई कैबिनेट मंत्री अपना पद छोड़ना चाहता है या प्रधानमंत्री उससे इस्तीफा मांगता है, तो वह अपना औपचारिक त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को ही संबोधित करके सौंपता है, न कि किसी अन्य अधिकारी को।

116. (B) 42वां संशोधन
1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 74(1) में संशोधन करके यह कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। इस संशोधन ने राष्ट्रपति की भूमिका को पूरी तरह से एक नाममात्र और औपचारिक संवैधानिक प्रमुख के रूप में सीमित और स्थापित कर दिया।

117. (B) क्षमा सजा और दोषसिद्धि दोनों को हटा देती है; लघुकरण सजा का एक हल्के दंड में प्रतिस्थापन करता है।
राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत 'क्षमा' (Pardon) व्यक्ति की सजा और दोषसिद्धि दोनों को पूरी तरह समाप्त कर देती है, जिससे व्यक्ति निर्दोष हो जाता है। इसके विपरीत, 'लघुकरण' (Commutation) में केवल दंड के स्वरूप को बदलकर उसे कम या हल्का किया जाता है, जैसे मृत्युदंड को बदलकर कठोर कारावास में परिवर्तित करना।

118. (B) केवल II और III
जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन बंद कर देता है। वह अधिकतम 6 महीने की अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में रह सकता है। हालाँकि, वह केवल मृत्यु या त्यागपत्र में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति की बीमारी या अनुपस्थिति के दौरान भी उनके कार्यों का निर्वहन कर सकता है।

119. (C) दोनों (A) और (B)
केहर सिंह मामला (1989) और एपुरु सुधाकर मामला (2006) दोनों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। यदि क्षमादान का फैसला मनमाना, दुर्भावनापूर्ण, कपटपूर्ण या बाहरी राजनीतिक कारणों से प्रभावित पाया जाता है, तो न्यायालय उस आदेश को रद्द कर सकता है।

NODIA

120. (D) राज्य विधानसभाएं इस निर्वाचन में भाग लेती हैं।
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रक्रिया से होता है। राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत, उपराष्ट्रपति के इस चुनाव में राज्यों की विधानसभाएं और उनके सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसलिए राज्य विधानसभाओं की भागीदारी वाला कथन गलत है।

121. (B) संसद द्वारा महाभियोग
भारत के राष्ट्रपति को उनका 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व केवल संसद द्वारा चलाए जाने वाले महाभियोग (Impeachment) प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 61 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल सदस्यता के दो-तिहाई विशेष बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य होता है।

122. (B) अनुच्छेद 112
संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष 'वार्षिक वित्तीय विवरण' (जिसे सामान्य भाषा में केंद्रीय बजट कहा जाता है) रखवाए। इस विवरण में भारत सरकार की उस वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का पूर्ण लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाता है।

123. (C) मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet) केंद्रीय सचिवालय, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों तथा रक्षा बलों में सभी शीर्ष स्तरीय प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय नियुक्तियों पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और केंद्रीय गृह मंत्री इसके सदस्य के रूप में कार्य करते हैं।

124. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारत के राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित सभी विधेयकों पर निरपेक्ष या पूर्ण वीटो शक्ति नहीं होती है। इसका कारण यह है कि 1971 के 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा

यह प्रावधान कर दिया गया है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयकों पर अपनी अनुमति रोकने या वीटो का प्रयोग करने के लिए अधिकृत नहीं है; उसे इन पर सहमति देनी ही होती है।

125. (B) सभी मंत्री सरकार के सभी कार्यों के लिए संयुक्त रुप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं।
सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भारतीय संसदीय प्रणाली का मूल आधार है, जो अनुच्छेद 75(3) में निहित है। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। सभी मंत्री संसद और जनता के सामने सरकार की नीतियों तथा कार्यों के लिए एक साथ संयुक्त रुप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं।

126. (A) I, II और III
प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश करता है, उनके विभागों का आवंटन एवं फेरबदल करता है तथा मतभेद होने पर मंत्री को हटाने की सलाह दे सकता है। हालाँकि, यदि प्रधानमंत्री स्वयं पद से त्यागपत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अन्य मंत्रियों का पद बना नहीं रहता, बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद् स्वतः ही विघटित हो जाती है।

127. (C) संपूर्ण मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना होगा।
यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद् के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) बहुमत से पारित हो जाता है, तो इसका अर्थ यह है कि सरकार ने निचले सदन का विश्वास खो दिया है। इस स्थिति में केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद् को सामूहिक उत्तरदायित्व के संवैधानिक नियम के तहत तुरंत अपने पदों से त्यागपत्र देना पड़ता है।

128. (B) 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक
भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 सदस्यों के प्रस्तावक के रूप में और कम से कम 20 अन्य सदस्यों के अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। (राष्ट्रपति चुनाव में यह संख्या 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होती है)। इसका उद्देश्य गैर-गंभीर उम्मीदवारों को रोकना है।

129. (D) अनुच्छेद 78
संविधान का अनुच्छेद 78 विशेष रूप से राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का निर्धारण करता है। इसके तहत प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि वह देश के प्रशासन, मंत्रिपरिषद् के निर्णयों तथा विधायी प्रस्तावों के संबंध में सभी जानकारी राष्ट्रपति को दे, और राष्ट्रपति द्वारा किसी विशेष मुद्दे पर मांगी गई जानकारी भी उनके समक्ष प्रस्तुत करे।

130. (A) वह सहमति दे सकता है, सहमति रोक सकता है, या राज्यपाल को इसे राज्य के पुनर्विचार के लिए लौटाने का निर्देश दे सकता है।
अनुच्छेद 201 के तहत जब राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी गैर-धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे सकता है या रोक सकता है। वह राज्यपाल को विधेयक वापस राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का निर्देश भी दे सकता है। संसद के विपरीत, राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः पारित करने पर भी राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य नहीं होता।

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Flipkart

अध्याय 10

भारत की संसद

1. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की संसद की द्विसदनीय संरचना को स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है?
   (A) अनुच्छेद 74
   (B) अनुच्छेद 79
   (C) अनुच्छेद 80
   (D) अनुच्छेद 81

2. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प भारत में राष्ट्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका को अपनाने के मूल औचित्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
   (A) यह सुनिश्चित करना कि सभी विधानों में यथासंभव विलंब हो
   (B) राष्ट्रपति को बहुसंख्यक सदस्यों को मनोनीत करने की अनुमति देना
   (C) आपातकाल के दौरान प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों को उपेक्षित करना
   (D) राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना तथा एक पुनरीक्षण सदन के रूप में कार्य करना

3. भारतीय संसद के संदर्भ में, किस निकाय/पद को किसी भी सदन का सदस्य न होने के बावजूद संसद का अभिन्न अंग माना जाता है?
   (A) भारत के राष्ट्रपति
   (B) भारत के मुख्य न्यायाधीश
   (C) भारत के उपराष्ट्रपति
   (D) भारत के महान्यायवादी

4. भारतीय संसद की द्विसदनीय संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   I. केंद्र में द्विसदनीय विधायिका पहली बार भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा प्रारंभ की गई थी।
   II. राज्यसभा समग्र रूप से भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है।
   III. संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को मुख्य रूप से ब्रिटिश मॉडल के आधार पर अपनाया।
   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (A) केवल I और II
   (B) केवल I और III
   (C) केवल II और III
   (D) I, II और III

5. भारतीय संसद की संप्रभुता ब्रिटिश संसद की संप्रभुता से किस प्रकार मौलिक रूप से भिन्न है?
   (A) भारतीय संसद एक लिखित संविधान तथा न्यायिक समीक्षा की सीमाओं के भीतर कार्य करती है।
   (B) भारतीय संसद पूर्णतः संप्रभु है और इसके कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती।
   (C) भारतीय संसद को संविधान संशोधनों के लिए राष्ट्राध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
   (D) भारत के विपरीत ब्रिटिश संसद एक कठोर संघात्मक ढाँचे के तहत कार्य करती है।

6. लोकसभा में प्रतिनिधित्व के लिए राजस्थान राज्य को कितने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए हैं?
   (A) 20
   (B) 25
   (C) 30
   (D) 33

7. 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद लोकसभा की वर्तमान अधिकतम स्वीकृत सदस्य संख्या कितनी है?
   (A) 545
   (B) 550
   (C) 552
   (D) 543

8. विभिन्न राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन वर्तमान में किस जनगणना वर्ष के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर स्थिर किया गया है?
   (A) 1971
   (B) 1991
   (C) 2001
   (D) 2011

9. लोकसभा की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   I. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षित हैं।
   II. आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान 2019 में समाप्त कर दिया गया था।
   III. 61वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई

Downloaded from www.pdf.tube

(D) अनुच्छेद 352

31. राज्यसभा को एक स्थाई निकाय के रूप में वर्णित किया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर इसके कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं?
(A) आधे (एक-बटा दो)
(B) एक-तिहाई
(C) एक-चौथाई
(D) दो-तिहाई

32. पूर्ण अवधि के लिए राज्यसभा के लिए निर्वाचित किसी व्यक्तिगत सदस्य का निश्चित कार्यकाल कितना होता है?
(A) 4 वर्ष
(B) 5 वर्ष
(C) 6 वर्ष
(D) कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता; वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं

33. यह संवैधानिक प्रावधान कि राज्यसभा भंग नहीं होगी, किस अनुच्छेद में उल्लिखित है?
(A) अनुच्छेद 80
(B) अनुच्छेद 81
(C) अनुच्छेद 83
(D) अनुच्छेद 85

34. राज्यसभा के स्थायित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. किसी व्यक्तिगत सदस्य का कार्यकाल स्वयं संविधान के मूल पाठ में स्पष्ट रूप से छह वर्ष निर्धारित किया गया है।
II. उप-चुनाव में निर्वाचित सदस्य केवल उस रिक्ति की शेष अवधि के लिए ही सेवा करता है जिसे वह भरता है।
III. राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी भी बार पुनः निर्वाचन के पात्र होते हैं।
उपर्युक्त कथनों का कौन-सा संयोजन सही है?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

35. कौन-सा विशिष्ट विधान संसद को राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित करने का अधिकार देता है?
(A) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
(B) संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951
(C) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
(D) संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959

36. लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि कौन निश्चित करता है?
(A) प्रधानमंत्री
(B) मुख्य निर्वाचन आयुक्त
(C) भारत के राष्ट्रपति
(D) निवर्तमान अध्यक्ष

37. यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहते हैं, तो उन्हें अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना होगा?
(A) लोकसभा के उपाध्यक्ष को
(B) भारत के राष्ट्रपति को
(C) प्रधानमंत्री को
(D) भारत के मुख्य न्यायाधीश को

38. लोकसभा अध्यक्ष के पास सदन में "निर्णायक मत" (कास्टिंग वोट) होता है। यह मत किस परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है?
(A) संविधान संशोधन विधेयक पर प्रारंभिक मतदान के दौरान
(B) भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान
(C) जब भी धन विधेयक पेश किया जाता है
(D) केवल मत बराबर होने की स्थिति में गतिरोध दूर करने के लिए

39. लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है।
II. अध्यक्ष दल-बदल के आधार पर उत्पन्न होने वाली लोकसभा सदस्य की अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय लेता है।
III. कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
IV. अध्यक्ष स्वतः ही सभी संसदीय समितियों का सभापति बन जाता है।
उपर्युक्त कथनों का कौन-सा संयोजन सही है?
(A) I, II और III
(B) II, III और IV
(C) I, III और IV
(D) I, II, III और IV

NODIA

40. लोकसभा में सामयिक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) का प्राथमिक कार्य क्या है?
(A) भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक के दौरान सदन की अध्यक्षता करना
(B) सत्तारूढ़ गठबंधन दल और विपक्ष के नेताओं के बीच आधिकारिक संपर्क के रूप में कार्य करना
(C) नए सदस्यों को शपथ दिलाना तथा अध्यक्ष के चुनाव का संचालन करना
(D) एक स्थाई अध्यक्ष के आधिकारिक रूप से चुने जाने तक धन विधेयकों का मूल्यांकन और प्रमाणन करना

41. लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि कौन निर्धारित करता है?
(A) भारत के राष्ट्रपति
(B) प्रधानमंत्री

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from
PRINTED BOOKS has up to
4× HIGHER RETENTION
than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

(D) P-2, Q-1, R-3, S-4

20. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन राज्यसभा की तुलना में लोकसभा की अनन्य शक्ति को सही रूप से उजागर करता है?
(A) केवल लोकसभा ही भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध औपचारिक महाभियोग की कार्रवाई शुरू कर सकती है।
(B) केवल लोकसभा ही नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन को अधिकृत करने वाला बाध्यकारी संकल्प पारित कर सकती है।
(C) मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।
(D) केवल लोकसभा ही देशभर में राष्ट्रीय आपातकाल की वैधानिक उद्घोषणा को मंजूरी दे सकती है।

21. राज्यसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं?
(A) 9
(B) 10
(C) 11
(D) 15

22. भारतीय संविधान की कौन-सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यों की परिषद (राज्यसभा) में सीटों के आवंटन का विवरण देती है?
(A) पहली अनुसूची
(B) तीसरी अनुसूची
(C) चौथी अनुसूची
(D) छठी अनुसूची

23. भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत करते हैं जिन्हें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो?
(A) विधि, चिकित्सा, अभियांत्रिकी और पत्रकारिता
(B) साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा
(C) खेल, सिनेमा, साहित्य और रक्षा
(D) अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, विज्ञान और समाज सेवा

24. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प दिए गए राज्यों का राज्यसभा में उनकी आवंटित सीटों की संख्या के आधार पर सही अवरोही क्रम दर्शाता है?
(A) उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार
(B) उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार
(C) महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु
(D) उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु

25. राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है?
(A) संबंधित राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने वाले वयस्क नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
(B) उस विशेष राज्य से निर्वाचित लोकसभा के वर्तमान सदस्यों द्वारा
(C) संबंधित राज्य के भीतर स्थानीय निकायों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा
(D) राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा

26. संविधान का अनुच्छेद 249 राज्यसभा को संसद को किस सूची में सूचीबद्ध विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करने की विशेष शक्ति प्रदान करता है?
(A) राज्य सूची
(B) संघ सूची
(C) समवर्ती सूची
(D) अवशिष्ट सूची

27. अनुच्छेद 249 के तहत एक वैध संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा में किस विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है?
(A) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत
(B) सदन की कुल सदस्यता का पूर्ण बहुमत
(C) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत
(D) सदन की कुल सदस्यता का कम से कम दो-तिहाई बहुमत

28. अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा द्वारा पारित संकल्प प्रारंभिक रूप से कितनी अवधि तक लागू रहता है?
(A) तीन महीने
(B) छह महीने
(C) एक वर्ष
(D) जब तक कि इसे लोकसभा द्वारा रद्द न कर दिया जाए

29. अनुच्छेद 249 के अनुप्रयोग से संबंधित निम्नलिखित चरणों को सही क्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. संसद निर्दिष्ट राज्य सूची के विषय पर एक विधान बनाती है।
2. राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित करती है।
3. नवीनीकृत न किए जाने पर संकल्प एक वर्ष पूरा होने पर समाप्त हो जाता है।
4. संकल्प की समाप्ति के छह महीने बाद कानून का प्रभाव समाप्त हो जाता है।

उपर्युक्त अनुक्रम का कौन-सा संयोजन सही है?
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 1, 2, 4, 3

30. निम्नलिखित में से कौन-सी राज्यसभा की एक अनन्य शक्ति है जो प्रकृति में अनुच्छेद 249 के समान है, लेकिन नई प्रशासनिक सेवाओं के सृजन से संबंधित है?
(A) अनुच्छेद 312
(B) अनुच्छेद 315
(C) अनुच्छेद 324

Click Here to Buy book on Amazon

(A) सीधे सदन के पटल पर दिया गया मौखिक उत्तर, जिसके बाद तुरंत खुली बहस होती है।
(B) औपचारिक विधायी कार्य शुरू होने से पहले शून्यकाल के दौरान दिया गया मौखिक मंत्रालीन वक्तव्य।
(C) पटल पर रखा गया लिखित उत्तर, जिस पर कोई पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है।
(D) प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप और स्पष्टीकरण वक्तव्य।

89. लोकसभा में दैनिक कार्यसूची के निम्नलिखित चरणों को सामान्य बैठक के दौरान उनके घटित होने के सामान्य क्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. शून्यकाल
2. प्रश्नकाल
3. नियमित विधायी/सरकारी कार्य

उपर्युक्त अनुक्रम का कौन-सा संयोजन सही है?
(A) 1, 2, 3
(B) 2, 1, 3
(C) 3, 2, 1
(D) 2, 3, 1

90. "अल्पसूचना प्रश्न" वह प्रश्न है जो अविलंबनीय लोक महत्व के मामले से संबंधित होता है। ऐसा प्रश्न पूछने के लिए निर्धारित सूचना अवधि क्या है?
(A) 10 दिनों से कम
(B) ठीक 15 दिन
(C) 21 दिनों से कम नहीं
(D) न्यूनतम 30 दिन

91. भारतीय संसदीय प्रक्रिया में "शून्यकाल" उल्लेखनीय है क्योंकि यह:
(A) ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संसदीय अभ्यास से सीधे उधार लिया गया एक स्पष्ट प्रक्रियात्मक प्रावधान है।
(B) बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठाने का एक अनौपचारिक साधन है।
(C) लोकसभा की लिखित प्रक्रिया नियमों के भीतर स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध एक औपचारिक प्रक्रियात्मक तंत्र है।
(D) केवल महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयकों पर बहस करने और उन्हें पारित करने के लिए समर्पित एक विशेष प्रति घंटा ब्लॉक है।

92. भारतीय नवाचार के रूप में भारतीय संसदीय कार्यवाहियों में शून्यकाल किस वर्ष से अस्तित्व में है?
(A) 1950
(B) 1962
(C) 1975
(D) 1985

93. संसद की दैनिक बैठक के दौरान शून्यकाल आमतौर पर कब शुरू होता है?
(A) दैनिक प्रश्नकाल सत्र के प्रारंभ होने से ठीक पहले।
(B) प्रश्नकाल के ठीक बाद जब तक कि नियमित कार्यसूची शुरू न हो जाए।
(C) सूचीबद्ध सभी सरकारी कार्यों के पूरी तरह से पूर्ण हो जाने के बाद विधायी दिवस के अंत में।
(D) दोपहर के अवकाश के बाद केवल देर शाम को सदन की बैठक के दौरान।

94. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों को सदस्यों द्वारा बिना कोई औपचारिक पूर्व सूचना दिए शून्यकाल के दौरान उठाया जा सकता है।
कारण (R): शून्यकाल स्पष्ट रूप से परिभाषित है और लोकसभा के प्रक्रिया के औपचारिक नियमों के भीतर सख्त नियमों द्वारा संचालित होता है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है परंतु कारण (R) सही है।

95. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प शून्यकाल के दौरान मंत्री के उत्तर की बाध्यकारी प्रकृति की सबसे अच्छी विशेषता बताता है?
(A) संबंधित मंत्री सदन के पटल पर तत्काल मौखिक उत्तर देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है।
(B) मंत्री को 24 घंटे के भीतर सदन सचिवालय को एक व्यापक लिखित उत्तर प्रस्तुत करना होगा।
(C) यदि उत्तर नहीं दिया जाता है तो उठाया गया मुद्दा स्वतः ही किसी संसदीय समिति को भेज दिया जाता है।
(D) मंत्री शून्यकाल के दौरान उठाए गए मामलों पर जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है।

NODIA

96. मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल कहाँ पेश किया जा सकता है?
(A) राज्यसभा में
(B) संसद की संयुक्त बैठक में
(C) लोकसभा में
(D) भारत के उच्चतम न्यायालय में

97. संविधान का अनुच्छेद 75 अविश्वास प्रस्ताव का मूल आधार प्रदान करता है। यह सिद्धांत क्या है?
(A) विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के कठोर पृथक्करण का सिद्धांत।
(B) लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व।
(C) भारत के राष्ट्रपति के प्रति प्रत्येक मंत्री का प्रत्यक्ष व्यक्तिगत उत्तरदायित्व।
(D) प्रधानमंत्री की पूर्ण कार्यकारी सर्वोच्चता और अतिरुपी अधिकार।

(C) संसदीय कार्य मंत्री
(D) लोकसभा अध्यक्ष

42. लोकसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के बीच संस्थागत संबंध क्या है?
(A) उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है और सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होता है।
(B) उपाध्यक्ष प्रशासनिक रूप से अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है और उसे उनके द्वारा जारी सभी प्रत्यक्ष कार्यकारी आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है।
(C) जब भी अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता कर रहे होते हैं, तो उपाध्यक्ष मुख्य रूप से अध्यक्ष के नामित व्यक्तिगत एजेंट के रूप में कार्य करता है।
(D) उपाध्यक्ष के पास धन विधेयकों पर अध्यक्ष द्वारा लिए गए सभी प्रक्रियात्मक निर्णयों की समीक्षा करने और उन्हें रद्द करने का अंतिम अधिकार होता है।

43. संसदीय परंपराओं और नियमों के अनुसार, संसदीय समितियों के संबंध में उपाध्यक्ष को क्या विशेष अधिकार प्राप्त है?
(A) वे किसी भी स्थाई या तदर्थ संसदीय समिति में वोट देने वाले सदस्य के रूप में कार्य करने से संवैधानिक रूप से प्रतिबंधित हैं।
(B) किसी संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त होने पर, वे स्वतः ही इसके सभापति बन जाते हैं।
(C) उनके लिए संसदीय लोक लेखा समिति के पदेन सभापति के रूप में कार्य करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
(D) वे संसद की स्थाई प्राकलन समिति के नामित पदेन सभापति के रूप में लगातार कार्य करते हैं।

44. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के पद के रिक्त होने पर या सदन की बैठक से अध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर उनके कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करता है।
कारण (R): सदन की अध्यक्षता करते समय, उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष के समान ही शक्तियां होती हैं और उनके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है परंतु कारण (R) सही है।

45. 11वीं लोकसभा (1996) के बाद से, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के राजनीतिक जुड़ाव के संबंध में काफी हद तक एक परंपरा का पालन किया गया है। यह परंपरा क्या है?
(A) अध्यक्ष सत्तारुढ़ दल से आता है और उपाध्यक्ष विपक्ष से।
(B) परंपरा के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का मुख्य सत्तारुढ़ दल से होना अनिवार्य है।
(C) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को पारंपरिक रूप से केवल मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक विपक्षी दलों से ही चुना जाता है।
(D) उपाध्यक्ष को हमेशा लोकसभा में बैठे गैर-दलीय मनोनीत सदस्यों में से चुना जाता है।

46. राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कौन कार्य करता है?
(A) राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य
(B) संसदीय कार्य मंत्री
(C) भारत के उपराष्ट्रपति
(D) राज्यसभा के सदस्यों द्वारा इस भूमिका के लिए विशेष रूप से चुना गया व्यक्ति

47. लोकसभा अध्यक्ष के विपरीत, राज्यसभा के सभापति सदन के सदस्य नहीं होते हैं। मतदान के संबंध में इसका एक प्रमुख परिणाम क्या है?
(A) सभापति के पास किसी भी सदस्य की तरह सभी साधारण विधायी मामलों पर प्रथमतः वोट देने का पूर्ण अधिकार होता है।
(B) सभापति को किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि मत बराबर होने पर भी, वोट डालने से पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।
(C) सभापति को केवल तभी वोट डालने की अनुमति है जब सदन संविधान संशोधन विधेयकों पर विचार करता है।
(D) सभापति केवल मत बराबर होने की स्थिति में ही निर्णायक वोट देते हैं।

48. यदि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तो सभापति की स्थिति क्या होगी?
(A) उन्हें तुरंत पद खाली कर देना चाहिए और भारत के राष्ट्रपति को औपचारिक त्यागपत्र सौंप देना चाहिए।
(B) वे बहस के दौरान सदन की अध्यक्षता करने का अधिकार बनाए रखते हैं लेकिन उन्हें बोलने से सख्त मना किया गया है।
(C) वे सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते, लेकिन बोल सकते हैं और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।
(D) वे बैठकों की अध्यक्षता करने और प्रथमतः सामान्य वोट देने की अपनी सभी पदेन शक्तियों को बनाए रखते हैं।

49. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (पद)
P. लोकसभा अध्यक्ष
Q. राज्यसभा के सभापति
R. राज्यसभा के उपसभापति
S. सामयिक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर)
सूची II: (नियुक्ति/चुनाव की पद्धति)
1. लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित
2. उपराष्ट्रपति द्वारा ग्रहण की जाने वाली पदेन भूमिका
3. राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित
4. भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त

Downloaded from www.pdf.tube

थी।

IV. लोकसभा के लिए निर्वाचित होने हेतु उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए।

उपर्युक्त कथनों का कौन-सा संयोजन सही है?

(A) I, II और III
(B) I, II और IV
(C) II, III और IV
(D) I, III और IV

10. संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत, जनगणना के बाद स्थापित परिसीमन आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है?

(A) लोकसभा में सीटों के आवंटन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनःसमायोजन करना
(B) राष्ट्रीय संसदीय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करना
(C) सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत चुनाव खर्च के विवरण का लेखा-परीक्षण करना
(D) मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्रशासनिक नियुक्ति प्रक्रियाओं की देखरेख करना

11. लोकसभा की पहली बैठक के लिए नियत तिथि से उसका सामान्य कार्यकाल कितना होता है?

(A) 4 वर्ष
(B) 5 वर्ष
(C) 6 वर्ष
(D) जब तक सत्तारूढ़ दल अपना बहुमत न खो दे

12. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, संसद द्वारा विधि बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है?

(A) 3 महीने
(B) 6 महीने
(C) 1 वर्ष
(D) 2 वर्ष

13. लोकसभा को उसका सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भंग करने की शक्ति किस संवैधानिक प्राधिकारी के पास है?

(A) भारत के राष्ट्रपति
(B) मुख्य निर्वाचन आयुक्त
(C) लोकसभा अध्यक्ष
(D) भारत के मुख्य न्यायाधीश

14. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।

कथन (A): लोकसभा को उसकी सामान्य पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले भंग किया जा सकता है।

कारण (R): भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता के बिना, पूरी तरह से अपने विवेक से लोकसभा को भंग करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं।

(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है परंतु कारण (R) सही है।

NODIA

15. जब लोकसभा भंग होती है, तो लोकसभा में लंबित विधेयक का क्या होता है?

(A) इसे राज्यसभा को स्थानांतरित कर दिया जाता है।
(B) इसे नई लोकसभा का गठन होने तक स्थगित रखा जाता है।
(C) इसे स्वतः ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेज दिया जाता है।
(D) यह पूर्णतः व्यपगत (समाप्त) हो जाता है।

16. निम्नलिखित में से किस वित्तीय प्रक्रिया पर लोकसभा का अनन्य अधिकार है?

(A) वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा करना
(B) संविधान संशोधन विधेयक पेश करना
(C) अनुदान की मांगों पर मतदान करना
(D) साधारण विधेयक पारित करना

17. विधायी शक्तियों के संदर्भ में, राज्यसभा धन विधेयक को पारित करने में अधिकतम कितनी अवधि का विलंब कर सकती है?

(A) 14 दिन
(B) 30 दिन
(C) 3 महीने
(D) 6 महीने

18. निम्नलिखित में से किसके पास यह प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं?

(A) वित्त मंत्री
(B) भारत के राष्ट्रपति
(C) राज्यसभा के सभापति
(D) लोकसभा अध्यक्ष

19. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची I: (विधायी संकल्पना)

P. धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया
Q. "धन विधेयक" की परिभाषा
R. वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
S. विनियोग विधेयक

सूची II: (संविधान का अनुच्छेद)

1. अनुच्छेद 109
2. अनुच्छेद 110
3. अनुच्छेद 112
4. अनुच्छेद 114

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-1, Q-2, R-4, S-3

लिए लौटा सकते हैं।
IV. यदि संसद विधेयक को संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के पुनः पारित कर देती है, तो भी राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों का कौन-सा संयोजन सही है?
(A) I, II और III
(B) I, II और IV
(C) II, III और IV
(D) I, III और IV

60. जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित साधारण विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो अनुच्छेद 111 के तहत, राष्ट्रपति किस प्रकार निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करते हैं?
(A) स्वीकृति को स्थाई रूप से रोककर
(B) सदनों के पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटाकर
(C) न्यायिक समीक्षा के लिए विधेयक को उच्चतम न्यायालय भेजकर
(D) बिना कोई कार्रवाई किए विधेयक को अपनी जेब में रखकर (पॉकेट वीटो)

61. संसद में धन विधेयक पेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी शर्त अनिवार्य है?
(A) इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है।
(B) इसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाना अनिवार्य है।
(C) इसे किसी भी निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है।
(D) इसके लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

62. अनुच्छेद 110 के अनुसार, किसी विधेयक को धन विधेयक तब माना जाता है जब उसमें केवल निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रावधान हों?
(A) अर्थदंड या अन्य आर्थिक शास्तियां लगाना
(B) लाइसेंसों के लिए फीसों की मांग या उनका भुगतान
(C) किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन
(D) स्थानीय नगर निकायों के उद्देश्यों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कर लगाना या बदलना

63. यदि राज्यसभा सिफारिशों के साथ धन विधेयक को लोकसभा को लौटाती है, तो लोकसभा के लिए आवश्यक कार्रवाई क्या है?
(A) विधेयक को सफलतापूर्वक पारित करने के लिए सभी सुझाई गई सिफारिशों को स्वीकार करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
(B) मतभेदों को सुलझाने के लिए उसे तुरंत राष्ट्रपति से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अनुरोध करना चाहिए।
(C) संसदीय असहमति को सुलझाने के लिए उसे राष्ट्रपति के कार्यकारी हस्तक्षेप की औपचारिक याचिका देनी चाहिए।
(D) वह किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

64. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं।
कारण (R): धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित नहीं किया जा सकता है, और इसे 14 दिनों के भीतर वापस किया जाना अनिवार्य है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है परंतु कारण (R) सही है।

65. अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक और अनुच्छेद 117(1) के तहत वित्त विधेयक (श्रेणी-I) के बीच मौलिक अंतर क्या है?
(A) मानक धन विधेयक के विपरीत, वित्त विधेयक श्रेणी-I को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की किसी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है।
(B) श्रेणी-I में अनुच्छेद 110 के मामलों के साथ-साथ सामान्य कानून शामिल होते हैं, और राज्यसभा इसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है।
(C) वित्त विधेयक श्रेणी-I राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी उत्पन्न हो सकता है, जबकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही उत्पन्न हो सकता है।
(D) वित्त विधेयक श्रेणी-I अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक के प्रावधानों से पूरी तरह मुक्त है, जबकि धन विधेयक को संयुक्त बैठक में भेजा जा सकता है।

66. संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, विधायी गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है?
(A) प्रधानमंत्री
(B) लोकसभा अध्यक्ष
(C) राज्यसभा के सभापति
(D) भारत के राष्ट्रपति

67. लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन-सा अधिकारी करता है?
(A) लोकसभा के उपाध्यक्ष
(B) राज्यसभा के सभापति
(C) राज्यसभा के उपसभापति
(D) वरिष्ठतम केंद्रीय कैबिनेट मंत्री

68. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के विधेयकों के लिए संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती?
(A) साधारण विधेयक और वित्त विधेयक
(B) साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक

Click Here to Buy book on Flipkart

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-1, Q-3, R-2, S-4
(D) P-4, Q-2, R-3, S-1

50. जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं, तो राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन कौन करता है?
(A) प्रधानमंत्री
(B) लोकसभा अध्यक्ष
(C) केंद्रीय मंत्रिमंडल में वरिष्ठतम मंत्री
(D) राज्यसभा के उपसभापति

51. संविधान के अनुसार, संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर हो सकता है?
(A) 3 महीने
(B) 6 महीने
(C) 9 महीने
(D) 12 महीने

52. कौन-सा संसदीय शब्द दैनिक बैठक के केवल स्थगन के बजाय, सदन के सत्र की समाप्ति को संदर्भित करता है?
(A) स्थगन
(B) गणपूर्ति (कोरम)
(C) सत्रावसान
(D) विघटन

53. "अनिश्चित काल के लिए स्थगन" संसद की बैठक को अनिश्चित अवधि के लिए समाप्त कर देता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन घोषित करने का अधिकार किसके पास है?
(A) संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी
(B) भारत के राष्ट्रपति
(C) प्रधानमंत्री
(D) संसदीय कार्य मंत्री

54. संसद के सत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. संसद के प्रत्येक सदन को आहूत करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।
II. सदन के सत्रावसान से लंबित विधेयक व्यपगत (समाप्त) नहीं होते हैं।
III. विघटन लोकसभा और राज्यसभा दोनों पर समान रूप से लागू होता है।
उपर्युक्त कथनों का कौन-सा संयोजन सही है?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

NODIA

55. संसदीय शब्दावली में "लेम-डक सत्र" शब्द किसको संदर्भित करता है?
(A) वार्षिक धन विधेयक को प्रस्तुत करने और उस पर मतदान के लिए विशेष रूप से बुलाया गया एक विशेष संसदीय सत्र।
(B) नई लोकसभा के चुने जाने के बाद निवर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र।
(C) सदन की एक औपचारिक बैठक जिसके दौरान विपक्षी सदस्य सामूहिक रूप से सभी संसदीय कार्यवाहियों का बहिष्कार करते हैं।
(D) राष्ट्रपति द्वारा पारंपरिक प्रारंभिक अभिभाषण दिए बिना आयोजित किया जाने वाला एक आपातकालीन संसदीय सत्र।

56. किसी साधारण विधेयक की विधायी प्रक्रिया के दौरान, सदन में "प्रथम वाचन" क्या गठित करता है?
(A) पूरे सदन द्वारा विधेयक की विस्तृत खंड-दर-खंड जांच और विचार
(B) औपचारिक बहस के बाद पूरे विधेयक को पारित करने पर अंतिम मतदान
(C) विधेयक का पुरःस्थापन (पेश करना) और राजपत्र में इसका प्रकाशन
(D) विधेयक के प्रावधानों को तुरंत संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाना

57. विधेयक के पारित होने के किस चरण में सदन विस्तृत, खंड-दर-खंड चर्चा और संशोधनों पर मतदान करता है?
(A) प्रथम वाचन
(B) द्वितीय वाचन
(C) तृतीय वाचन
(D) राष्ट्रपति की स्वीकृति और राजपत्र अधिसूचना चरण

58. किसी विधेयक के "तृतीय वाचन" के चरण में, सदस्यों के लिए चर्चा का दायरा क्या होता है?
(A) बहस पूरे विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने तक सीमित होती है।
(B) व्यक्तिगत खंडों में नए संशोधन पेश करने पर केंद्रित व्यापक पंक्ति-दर-पंक्ति बहस।
(C) विधेयक की समग्र संवैधानिक वैधता की जांच करने तक सीमित विशिष्ट बहस।
(D) वह प्रक्रिया जहां किसी सामान्य बहस की अनुमति नहीं होती है और सदन को तुरंत अंतिम मतदान के लिए आगे बढ़ना होता है।

59. किसी साधारण विधेयक के पारित होने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. एक साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
II. इसे किसी मंत्री द्वारा और साथ ही किसी निजी सदस्य द्वारा भी पेश किया जा सकता है।
III. राष्ट्रपति साधारण विधेयक को संसद के पुनर्विचार के

सुधारों पर रिपोर्ट देना।
(D) सभी नए प्रस्तावित कराधान कानूनों की समग्र संवैधानिक वैधता का व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन और प्रमाणन करना।

79. प्राकलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह स्वतंत्रता के बाद भारत में 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर स्थापित की गई थी।
II. यह बजट अनुमानों की जांच संसद द्वारा उन पर मतदान किए जाने के बाद ही करती है।
III. समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा हमेशा सत्तारुढ़ दल से की जाती है।
IV. कोई मंत्री समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं हो सकता।
उपर्युक्त कथनों का कौन-सा संयोजन सही है?
(A) I, II और III
(B) I, III और IV
(C) II, III और IV
(D) I, II, III और IV

80. प्राकलन समिति को कभी-कभी अनौपचारिक रूप से "सतत मितव्ययिता समिति" के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है?
(A) क्योंकि यह सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश की सुरक्षा के लिए दैनिक राष्ट्रीय शेयर बाजार के रुझानों की लगातार निगरानी करती है।
(B) क्योंकि इसके सदस्य बिना किसी औपचारिक स्थगन के पूरे कैलेंडर वर्ष में लगातार स्थाई सत्र में बैठते हैं।
(C) क्योंकि यह प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता लाने के लिए नीतिगत विकल्प सुझाती है।
(D) क्योंकि इसके पास भारतीय रिजर्व बैंक को कार्यकारी निधि जारी करने पर तुरंत रोक लगाने का आदेश देने की वैधानिक शक्तियां हैं।

81. सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति (CoPU) का गठन 1964 में निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर किया गया था?
(A) संथानम समिति
(B) कृष्ण मेनन समिति
(C) सरकारिया आयोग
(D) कोठारी आयोग

82. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति की संरचना का सही वर्णन करता है?
(A) 30 सदस्य: लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10
(B) 22 सदस्य: लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7
(C) 15 सदस्य: सभी लोकसभा से
(D) 20 सदस्य: प्रत्येक सदन से 10

83. सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा किस सदन के सदस्यों में से की जाती है?
(A) केवल लोकसभा से
(B) केवल राज्यसभा से
(C) वरिष्ठता के आधार पर किसी भी सदन से
(D) सदैव किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य से

84. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प भारत में दी गई संसदीय वित्तीय समितियों की प्रारंभिक स्थापना के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है?
(A) प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति
(B) लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति
(C) सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति
(D) लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति, प्राकलन समिति

85. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति का कार्य नहीं है?
(A) व्यावसायिक सिद्धांतों से अलग प्रमुख सरकारी नीति की जांच करना।
(B) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की विस्तृत वार्षिक वित्तीय रिपोर्टों और तुलन-पत्रों की गहन जांच करना।
(C) सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा और मूल्यांकन करना।
(D) यह आकलन करना कि क्या सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंधन कुशल व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार कुशलतापूर्वक किया जा रहा है।

86. लोकसभा की सामान्य बैठक के दौरान, संसदीय दिवस की शुरुआत आमतौर पर किस प्रक्रियात्मक साधन से होती है?
(A) शून्यकाल
(B) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
(C) आधे घंटे की चर्चा
(D) प्रश्नकाल

87. प्रश्नकाल के संदर्भ में, "तारांकित प्रश्न" को "अतारांकित प्रश्न" से क्या अलग करता है?
(A) तारांकित प्रश्न के लिए पटल पर रखे गए औपचारिक लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है, जहाँ पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।
(B) तारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, जिससे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मिलती है।
(C) तारांकित प्रश्न वर्तमान कैबिनेट मंत्रियों के बजाय विशेष रूप से निजी सदस्यों को संबोधित किया जाता है।
(D) तारांकित प्रश्न केवल वित्तीय बजट आवंटन और राजस्व मांगों से संबंधित होता है।

88. सदन के समक्ष रखे गए "अतारांकित प्रश्न" पर संबंधित मंत्री से किस प्रकार का उत्तर प्राप्त होता है?

NODIA

(C) धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक
(D) वित्त विधेयक और धन विधेयक

69. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (ऐतिहासिक संयुक्त बैठक)
P. दहेज निषेध विधेयक
Q. बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक
R. आतंकवादी गतिविधि निवारण विधेयक (पोटा)
सूची II: (पारित होने का वर्ष)
1. 1961
2. 1978
3. 2002
4. 1956
(A) P-1, Q-2, R-3
(B) P-2, Q-1, R-3
(C) P-1, Q-3, R-2
(D) P-3, Q-2, R-1

70. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक गठित करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति (कोरम) क्या है?
(A) केवल लोकसभा के कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा (1/10)
(B) दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का दसवां हिस्सा (1/10)
(C) दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का पांचवां हिस्सा (1/5)
(D) दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का आधा हिस्सा (1/2)

71. भारतीय संसद की लोक लेखा समिति (PAC) में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं?
(A) 15 सदस्य
(B) 22 सदस्य
(C) 30 सदस्य
(D) 45 सदस्य

72. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प लोक लेखा समिति (PAC) के प्राथमिक कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विस्तृत वार्षिक बजट आवंटन का अनुमान लगाना और उसे मंजूरी देना।
(B) वित्त मंत्रालय के सीधे परामर्श से व्यापक नए कराधान विधान का मसौदा तैयार करना।
(C) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच करना।
(D) सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों की सीधी देखरेख और निगरानी करना।

73. 1967 से स्थापित एक संसदीय परंपरा के अनुसार, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चयन हमेशा निम्नलिखित में से किया जाता है:
(A) सत्तारुढ़ दल से
(B) राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों से
(C) सत्तारुढ़ गठबंधन के वरिष्ठतम सदस्यों से
(D) लोकसभा में विपक्ष से

74. लोक लेखा समिति (PAC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसका गठन पहली बार 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1921 में किया गया था।
II. किसी मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है।
III. इसके सदस्य लोकसभा और राज्यसभा से समान रूप से लिए जाते हैं।
उपर्युक्त कथनों का कौन-सा संयोजन सही है?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

75. लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है?
(A) 1 वर्ष
(B) 2 वर्ष
(C) 3 वर्ष
(D) लोकसभा के कार्यकाल के सह-सहवर्ती (साथ-साथ)

76. सदस्यों की संख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन-सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है?
(A) लोक लेखा समिति
(B) प्राकलन समिति
(C) सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति
(D) कार्य परामर्शदात्री समिति

77. प्रमुख वित्तीय समितियों में प्राकलन समिति अद्वितीय है क्योंकि इसकी सदस्यता में शामिल होते हैं:
(A) विशेष रूप से केवल लोकसभा से 30 सदस्य
(B) दोनों सदनों से समान प्रतिनिधित्व
(C) लोकसभा से 22 और राज्यसभा से 8 सदस्य
(D) विशेष रूप से केवल राज्यसभा से 15 सदस्य

78. संसद की प्राकलन समिति का मूल जनादेश (कार्य) क्या है?
(A) कार्यकारी विभागों द्वारा पहले से किए गए सभी व्ययों का व्यापक उत्तर-परीक्षा कानूनी और वित्तीय लेखा-परीक्षण करना।
(B) प्रशासनिक भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और सार्वजनिक घोटालों के विशिष्ट मामलों की स्वतंत्र जांच करना।
(C) बजट अनुमानों के अनुरूप मितव्ययिता और नीतिगत

Downloaded from www.pdf.tube

98. सदन में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों को समर्थन में खड़ा होना पड़ता है?
(A) 10 सदस्य
(B) 25 सदस्य
(C) 50 सदस्य
(D) 100 सदस्य

99. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (प्रस्ताव का प्रकार)
P. अविश्वास प्रस्ताव
Q. निंदा प्रस्ताव
R. स्थगन प्रस्ताव
S. विशेषाधिकार प्रस्ताव
सूची II: (मुख्य विशेषता)
1. किसी विशिष्ट नीतिगत विफलता के लिए किसी व्यक्तिगत मंत्री के खिलाफ लाया जा सकता है
2. इसे स्वीकार करने के कारणों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है; पूरी परिषद को लक्षित करता है
3. अविलंबनीय लोक महत्व के एक निश्चित मामले को उठाने का प्रयास करता है
4. तब लाया जाता है जब कोई मंत्री तथ्यों को छिपाकर संसदीय अधिकारों का उल्लंघन करता है
(A) P-2, Q-1, R-3, S-4
(B) P-1, Q-2, R-4, S-3
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-1, Q-2, R-3, S-4

100. यदि लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव सफलतापूर्वक पारित हो जाता है, तो संवैधानिक रूप से अनिवार्य परिणाम क्या होता है?
(A) राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है।
(B) राज्यसभा को भंग किया जाना चाहिए।
(C) मंत्रिपरिषद को तुरंत त्यागपत्र देना होगा।
(D) भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यकारी नियंत्रण संभालते हैं।

101. संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) लोक महत्व के किसी अविलंबनीय मामले की ओर ध्यान आकर्षित करना।
(B) कोरम की कमी के कारण सदन की दैनिक बैठक को अगले कार्य दिवस तक स्थगित करना।
(C) राष्ट्रपति के आदेश पर संसद के जारी सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करना।
(D) सरकार द्वारा पेश किए गए लंबित धन विधेयक पर अंतिम वोट में जानबूझकर देरी करना।

102. स्थगन प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व शामिल होता है। परिणाम स्वरूप, किस सदन को इस साधन का उपयोग करने की अनुमति है?
(A) केवल राज्यसभा
(B) लोकसभा और राज्यसभा दोनों
(C) केवल राज्य विधानसभाएं
(D) केवल लोकसभा

103. कौन-सा संसदीय साधन विशेष रूप से एक भारतीय नवाचार है जो किसी सदस्य को अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने और एक आधिकारिक बयान का अनुरोध करने की अनुमति देता है?
(A) धन्यवाद प्रस्ताव
(B) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
(C) स्थगन प्रस्ताव
(D) सार्वजनिक मामलों पर आधे घंटे की चर्चा

104. स्थगन प्रस्ताव पर प्रतिबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसमें एक से अधिक मामलों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
II. इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए।
III. यह ऐसे मामले पर चर्चा को पुनर्जीवित कर सकता है जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी है।
उपर्युक्त कथनों का कौन-सा संयोजन सही है?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

105. संसदीय नियमों के अनुसार, यदि कोई स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस पर चर्चा कम से कम कितने समय तक चलनी चाहिए?
(A) 1 घंटा
(B) 2 घंटे और 30 मिनट
(C) 4 घंटे
(D) संपूर्ण शेष दिवस

NODIA

106. किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दसवीं अनुसूची जोड़कर संविधान में दल-बदल विरोधी कानून को समाविष्ट किया गया था?
(A) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
(B) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
(C) 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
(D) 91वां संशोधन अधिनियम, 2003

107. दसवीं अनुसूची के तहत, किसी सदन का मनोनीत सदस्य अपना पद ग्रहण करने की तिथि से किस अवधि की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होने पर अयोग्यता के अधीन हो जाता है?
(A) 1 महीने
(B) 3 महीने
(C) 6 महीने
(D) 1 वर्ष

है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। यदि कोई सदस्य बीच में पद त्याग देता है या मृत्यु हो जाती है तो उपचुनाव में चुना गया नया सदस्य केवल शेष अवधि के लिए कार्य करता है।

33. (C) अनुच्छेद 83
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि का निर्धारण करता है। अनुच्छेद 83(1) में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य सभा का विघटन नहीं होगा और यह एक स्थाई निकाय के रूप में निरंतर कार्य करेगी। इसी अनुच्छेद में यह प्रावधान भी शामिल है कि इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होंगे जिससे सदन का स्थायित्व और निरंतरता हमेशा बनी रहे।

34. (B) केवल II और III
राज्य सभा के सदस्यों का 6 वर्ष का कार्यकाल मूल संविधान में वर्णित नहीं था, बल्कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा निर्धारित किया गया है। उपचुनाव में चुना गया सदस्य केवल पूर्व सदस्य की शेष अवधि के लिए ही पद धारण करता है। इसके अतिरिक्त राज्य सभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी भी बार पुनः चुनाव लड़ने और निर्वाचित होने के पात्र होते हैं। उनके पुनः निर्वाचन पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है।

35. (A) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
भारतीय संविधान ने स्वयं राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया था, बल्कि यह अधिकार संसद को सौंपा था। संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पारित करके राज्य सभा सदस्यों की अवधि 6 वर्ष निर्धारित की। इसी अधिनियम के अंतर्गत प्रथम राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल तय करने के लिए लॉटरी प्रणाली का उपयोग किया गया था ताकि प्रत्येक 2 वर्ष में एक-तिहाई सदस्यों की सेवानिवृत्ति का चक्र प्रारंभ किया जा सके।

36. (C) भारत के राष्ट्रपति
लोक सभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित करने का संवैधानिक अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। नई लोक सभा के गठन के तुरंत बाद राष्ट्रपति अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख घोषित करते हैं। इस घोषित तिथि पर लोक सभा अपने सदस्यों में से किसी एक को साधारण बहुमत द्वारा अध्यक्ष के रूप में चुनती है। चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रोटेम स्पीकर सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

37. (A) लोकसभा के उपाध्यक्ष को
यदि लोक सभा अध्यक्ष स्वेच्छा से अपना पद छोड़ना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र लोक सभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करके सौंपता है। इसी प्रकार यदि उपाध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को संबोधित करता है। यह परस्पर त्यागपत्र की संवैधानिक व्यवस्था संसद के भीतर दोनों पदाधिकारियों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बनाए रखने तथा कार्यपालिका के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने के लिए निर्मित की गई है।

38. (D) केवल मत बराबर होने की स्थिति में गतिरोध दूर करने के लिए
लोक सभा अध्यक्ष सामान्यतः प्रथमतः सदन में किसी विषय पर मतदान नहीं करता है। हालांकि यदि किसी प्रस्ताव या विधेयक पर मतदान के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ जाएं तो इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए अध्यक्ष अपने 'निर्णायक मत' अर्थात कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है। अध्यक्ष का यह मत निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है और इसका उद्देश्य सदन में उत्पन्न बराबरी के गतिरोध का समाधान करना होता है।

39. (A) I, II और III
लोक सभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है तथा दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेता है। इसके अतिरिक्त कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय भी अध्यक्ष ही करता है। हालांकि अध्यक्ष स्वतः सभी समितियों का प्रमुख नहीं बनता, वह केवल नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति तथा कार्य परामर्शदात्री समिति का ही सभापति होता है।

40. (C) नए सदस्यों को शपथ दिलाना तथा अध्यक्ष के चुनाव का संचालन करना
नई लोक सभा के गठन के पश्चात राष्ट्रपति सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को सामयिक अध्यक्ष अर्थात प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य नए निर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाना तथा नए लोक सभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराना होता है। एक बार स्थाई अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाने के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है।

41. (D) लोकसभा अध्यक्ष
लोक सभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित करने की शक्ति लोक सभा अध्यक्ष में निहित होती है। अध्यक्ष द्वारा तिथि निश्चित किए जाने के बाद लोक सभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करते हैं। उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष के चुने जाने के तुरंत बाद आयोजित किया जाता है ताकि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का संचालन सुचारु रूप से बिना किसी बाधा के जारी रखा जा सके।

42. (A) उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है और सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होता है।
लोक सभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष का अधीनस्थ या सहायक नहीं होता है। वह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद धारण करता है जो सीधे लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जब उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता कर रहा होता है तो उसके पास अध्यक्ष के समान ही सभी शक्तियां और अधिकार होते हैं। उसके द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ अध्यक्ष के पास कोई अपील नहीं की जा सकती और न ही उन्हें बदला जा सकता है।

Click Here to Buy book on Amazon

(D) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश

118. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष निम्नलिखित में से किस नियुक्ति के लिए चयन समितियों का अनिवार्य सदस्य बनकर जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं?
(A) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG)
(B) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर
(C) भारतीय सशस्त्र बलों के थल सेनाध्यक्ष
(D) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के निदेशक

119. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (संसदीय भूमिका/शब्द)
P. सदन का नेता
Q. नेता प्रतिपक्ष
R. सचेतक (व्हिप)
S. शैडो कैबिनेट (छाया मंत्रिमंडल)
सूची II: (विवरण)
1. दलीय रेखा के अनुसार उपस्थित रहने और वोट देने के लिए दलीय सदस्यों को निर्देश देता है
2. आमतौर पर प्रधानमंत्री या कोई मनोनीत मंत्री
3. सरकार पर नजर रखने के लिए विपक्ष द्वारा गठित एक वैकल्पिक मंत्रिमंडल
4. कोरम पूरा करने वाले सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता
(A) P-2, Q-4, R-1, S-3
(B) P-4, Q-2, R-3, S-1
(C) P-2, Q-4, R-3, S-1
(D) P-1, Q-3, R-2, S-4

120. "छाया मंत्रिमंडल" (शैडो कैबिनेट) की अवधारणा मंत्रिमंडल प्रणाली की एक अनूठी संस्था है जो मुख्य रूप से किस देश से उत्पन्न हुई है?
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका
(B) फ्रांस
(C) यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन)
(D) जर्मनी

121. संसदीय प्रक्रिया में, "गिलोटिन" शब्द का क्या अर्थ है?
(A) अध्यक्ष के आदेश पर रक्षा कर्मियों द्वारा लगातार व्यवधान डालने वाले सदस्य को जबरन बाहर निकालना।
(B) कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का तत्काल संवैधानिक विघटन।
(C) सदन में पराजय के बाद पूरी मंत्रिपरिषद का अनिवार्य औपचारिक त्यागपत्र।
(D) समय की कमी के कारण बिना चर्चा वाले खंडों या मांगों पर मतदान कराना।

122. अनुदानों, विधेयकों और नीतियों की जांच में संसद की सहायता के लिए वर्तमान में कितनी विभाग-संबंधित स्थाई समितियां (DRSCs) अस्तित्व में हैं?
(A) 12
(B) 18
(C) 24
(D) 30

123. भारतीय संसद में विभाग-संबंधित स्थाई समितियों की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) साधारण विधायी विधेयकों पर राज्यसभा की विधायी जांच को प्रभावी ढंग से दरकिनार करना।
(B) विशेष रूप से वित्तीय मामलों में संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को बढ़ाना।
(C) कैबिनेट के नीतिगत निर्णयों की समीक्षा करने और उन्हें निरस्त करने के लिए अधिकृत एक कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करना।
(D) संसद सदस्यों के वित्तीय मुआवजे में आवधिक कटौती का मूल्यांकन और सिफारिश करना।

124. जो मामले प्रश्नकाल, आधे घंटे की चर्चा या स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नहीं उठाए जा सकते, उन्हें लोकसभा में किसी सदस्य द्वारा किस प्रक्रियात्मक नियम के तहत उठाया जा सकता है?
(A) नियम 377
(B) नियम 193
(C) नियम 184
(D) नियम 110

125. हाल के दशकों में, भारतीय संसद की उत्पादकता अक्सर लगातार व्यवधानों से प्रभावित हुई है। निम्नलिखित में से कौन-सा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त प्रक्रियात्मक तंत्र नहीं है, बल्कि सदस्यों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक विघटनकारी रणनीति है?
(A) सदन के गर्भगृह में जाना
(B) व्यवस्था का प्रश्न (पॉइंट ऑफ ऑर्डर)
(C) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
(D) नियम 193 के तहत अल्पकालिक चर्चा

126. निम्नलिखित में से किस स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा समान संवैधानिक शक्तियों का आनंद लेती हैं?
(A) कार्यकारी मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत अनुदान की मांगों पर मतदान करना और उन्हें पारित करना।
(B) अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को पेश करना और उस पर प्रारंभिक विचार करना।
(C) संविधान संशोधन विधेयकों को पारित करना।
(D) अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की सिफारिश करने वाले संकल्प पारित करना।

NODIA

127. निम्नलिखित में से कौन-सी एक विशेष अनन्य शक्ति है जो केवल राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को नहीं?
(A) अनुच्छेद 352 के तहत जारी राष्ट्रीय आपातकाल की कार्यकारी उद्घोषणा को मंजूरी देना।
(B) भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ औपचारिक संवैधानिक महाभियोग के आरोप शुरू करना।

सीटों के आवंटन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्समायोजन करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या का प्रतिनिधित्व यथासंभव समान रहे।

11. (B) 5 वर्ष
लोक सभा का सामान्य कार्यकाल उसकी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। 5 वर्ष की अवधि पूरी होते ही लोक सभा स्वतः भंग हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इस अवधि के समाप्त होने से पहले भी प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे भंग कर सकता है। समय से पूर्व विघटन की स्थिति में नए आम चुनाव आयोजित कराए जाते हैं।

12. (C) 1 वर्ष
संविधान के अनुच्छेद 83 के अंतर्गत जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो संसद कानून बनाकर लोक सभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। यह विस्तार एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए ही किया जा सकता है। आपातकाल की समाप्ति के पश्चात लोक सभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में 6 महीने से अधिक समय तक विस्तारित नहीं रह सकता है और नया चुनाव कराना आवश्यक होता है।

13. (A) भारत के राष्ट्रपति
संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत लोक सभा को उसकी सामान्य अवधि पूरी होने से पहले भंग करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति इस अधिकार का प्रयोग मुख्य रूप से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। जब लोक सभा भंग कर दी जाती है तो उसके कार्यकाल का अंत हो जाता है और देश में नई लोक सभा के गठन के लिए नए आम चुनाव आयोजित कराए जाते हैं।

14. (C) कथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
भारत के राष्ट्रपति के पास लोक सभा को उसके 5 वर्ष के सामान्य कार्यकाल से पहले भंग करने की संवैधानिक शक्ति होती है। हालांकि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग अपनी स्वेच्छा से स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को लोक सभा भंग करने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य होता है। इस प्रकार विघटन की प्रक्रिया पूरी तरह से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर करती है।

15. (D) यह पूर्णतः व्यपगत (समाप्त) हो जाता है।
जब लोक सभा भंग होती है तो उसमें लंबित सभी विधायी कार्य समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई विधेयक लोक सभा में लंबित है या लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया है किंतु राज्य सभा में लंबित है तो लोक सभा के विघटन के साथ ही वह विधेयक व्यपगत अर्थात समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में नई गठित लोक सभा को उस विधेयक पर पुनः नए सिरे से विधायी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है।

16. (C) अनुदान की मांगों पर मतदान करना
वित्तीय मामलों में लोक सभा को राज्य सभा की तुलना में अत्यधिक व्यापक और अनन्य शक्तियां प्राप्त हैं। सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अनुदान की मांगों पर मतदान करने और उन्हें स्वीकृत करने का अधिकार केवल और केवल लोक सभा के पास होता है। राज्य सभा अनुदान की मांगों पर केवल चर्चा कर सकती है किंतु उसे उन पर मतदान करने अथवा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

17. (A) 14 दिन
धन विधेयक के मामले में लोक सभा को एकाधिकार प्राप्त है। लोक सभा द्वारा पारित धन विधेयक जब राज्य सभा के विचारार्थ भेजा जाता है तो राज्य सभा उसे अधिकतम 14 दिनों की अवधि तक ही अपने पास रोक सकती है। यदि राज्य सभा 14 दिनों के भीतर विधेयक को वापस नहीं लौटाती है तो वह विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है जिस रूप में लोक सभा ने पारित किया था।

18. (D) लोकसभा अध्यक्ष
संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई प्रस्तुत विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम और सर्वोपरि निर्णय करने की शक्ति लोक सभा अध्यक्ष के पास होती है। जब किसी धन विधेयक को राज्य सभा या राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उस पर लोक सभा अध्यक्ष का हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न होता है। लोक सभा अध्यक्ष के इस निर्णय को किसी भी सदन या न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

19. (A) P-1, Q-2, R-3, S-4
भारतीय संविधान में विभिन्न वित्तीय प्रक्रियाओं के लिए विशिष्ट अनुच्छेद निर्धारित किए गए हैं। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों से संबंधित विशेष प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट से संबंधित है जबकि अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है। ये सभी अनुच्छेद मिलकर भारत की विधायी वित्तीय व्यवस्था का आधार निर्मित करते हैं।

20. (C) मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी कारण सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोक सभा में ही पेश किया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव लोक सभा में पारित हो जाता है तो संपूर्ण सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्य सभा के पास मंत्रिपरिषद को हटाने अथवा अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होता है।

21. (B) 10
भारतीय संसद के उच्च सदन अर्थात राज्य सभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए 10 सीटें आवंटित की गई हैं। इन 10 सदस्यों का चुनाव राजस्थान विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल

Downloaded from www.pdf.tube

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) अनुच्छेद 79
भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत की संसद की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर बनेगी। इन दो सदनों को क्रमशः राज्यसभा अर्थात राज्यों की परिषद और लोकसभा अर्थात जनता का सदन कहा जाता है। यह व्यवस्था भारत में राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक द्विसदनीय प्रणाली की स्थापना करती है।

2. (D) राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना तथा एक पुनरीक्षण सदन के रूप में कार्य करना
भारत में राष्ट्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका को अपनाने का मुख्य औचित्य देश की संघात्मक संरचना को सुदृढ़ करना है। ऊपरी सदन अर्थात राज्यसभा विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यह सदन निचले सदन द्वारा जल्दबाज़ी या भावना में बहकर पारित किए गए कानूनों पर पुनर्विचार करने वाले एक द्वितीय समीक्षात्मक निकाय के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

3. (A) भारत के राष्ट्रपति
भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वह संसद का अनिवार्य अभिन्न अंग माना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न हो जाए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति संसद के सत्र आहूत और सत्रावसान भी करता है।

4. (B) केवल I और III
भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। इसके अतिरिक्त भारत ने मुख्य रूप से ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल के आधार पर संसदीय प्रणाली को अपनाया है। लोकसभा संपूर्ण देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है जबकि राज्यसभा राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधि संस्था है। इस प्रकार भारतीय व्यवस्था में जन-प्रतिनिधित्व और राज्य-प्रतिनिधित्व का संतुलन स्थापित किया गया है।

5. (A) भारतीय संसद एक लिखित संविधान तथा न्यायिक समीक्षा की सीमाओं के भीतर कार्य करती है।
ब्रिटिश संसद की असीमित संप्रभुता के विपरीत भारतीय संसद की शक्तियां सीमित हैं। भारत में एक लिखित संविधान है जो संसद की शक्तियों की सीमाएं तय करता है। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की वैधानिकता की जांच करने का अधिकार न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा के रूप में निहित है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है।

NODIA

6. (B) 25
भारत में लोक सभा के लिए राजस्थान राज्य को कुल 25 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि राजस्थान से जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर 25 सांसद निर्वाचित होकर संसद के निचले सदन में पहुंचते हैं। सीटों का यह आवंटन राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया गया है जिससे संसदीय लोकतंत्र में राज्य की उचित सहभागिता बनी रहे।

7. (B) 550
104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के लागू होने से पूर्व लोक सभा की अधिकतम स्वीकृत सदस्य संख्या 552 थी जिसमें 2 मनोनीत आंग्ल-भारतीय सदस्य शामिल थे। इस संशोधन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के नामांकन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप लोक सभा की वर्तमान अधिकतम स्वीकृत सदस्य संख्या घटकर 550 रह गई है जिसमें 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जा सकते हैं।

8. (A) 1971
संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार विभिन्न राज्यों के बीच लोक सभा सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर स्थिर किया गया है। जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस व्यवस्था को वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक के लिए फ्रीज किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 2026 तक सभी राज्यों में लोक सभा सीटों की संख्या 1971 के आंकड़ों पर ही आधारित रहेगी।

9. (A) I, II और III
लोक सभा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात पर आधारित है। 104वें संशोधन अधिनियम द्वारा आंग्ल-भारतीयों के दो सदस्यों के मनोनीत करने का प्रावधान समाप्त किया गया तथा 61वें संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। हालांकि लोक सभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना अनिवार्य है न कि 30 वर्ष।

10. (A) लोकसभा में सीटों के आवंटन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनःसमायोजन करना
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत प्रत्येक जनगणना की समाप्ति के पश्चात संसद द्वारा विधि बनाकर एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। इस परिसीमन आयोग का प्राथमिक दायित्व लोक सभा तथा राज्य विधानसभाओं में

सभा में सभापति के पास होता है। सामान्यतः जब सत्र का कार्य पूर्ण हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी इसकी घोषणा करते हैं।

54. (A) केवल I और II
संविधान के अनुसार संसद के सदनों को सत्र के लिए आहूत करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति ही मंत्रिपरिषद की सलाह पर सत्रावसान की घोषणा करता है जिससे लंबित विधेयक समाप्त नहीं होते। विघटन केवल लोक सभा पर लागू होता है क्योंकि राज्य सभा एक स्थाई सदन है जिसका विघटन कभी नहीं किया जा सकता। इसलिए राज्य सभा पर विघटन का नियम लागू होने का कथन पूरी तरह गलत है।

55. (B) नई लोकसभा के चुने जाने के बाद निवर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र।
"लेम-डक सत्र" संसदीय शब्दावली में नई लोक सभा के निर्वाचन के पश्चात निवर्तमान लोक सभा के अंतिम सत्र को संदर्भित करता है। इस सत्र में वे वर्तमान सांसद भाग लेते हैं जो नए चुनावों में पुनः निर्वाचित नहीं हो पाते हैं। ऐसे सदस्यों को "लेम-डक" कहा जाता है। यह सत्र पुरानी लोक सभा के विधायी कार्यों को औपचारिक रूप से समाप्त करने और नई लोक सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आयोजित होता है।

56. (C) विधेयक का पुरःस्थापन (पेश करना) और राजपत्र में इसका प्रकाशन
किसी साधारण विधेयक की विधायी यात्रा में "प्रथम वाचन" उस चरण को कहते हैं जब विधेयक को सदन में पेश किया जाता है। इस चरण में विधेयक का शीर्षक और उसके उद्देश्यों का कथन पढ़ा जाता है तथा उसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। प्रथम वाचन के दौरान विधेयक पर कोई चर्चा या बहस आयोजित नहीं की जाती और न ही इस स्तर पर कोई संशोधन या मतदान होता है।

57. (B) द्वितीय वाचन
किसी विधेयक का "द्वितीय वाचन" सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत विधायी चरण होता है। इस चरण के दौरान सदन विधेयक के सिद्धान्तों और प्रावधानों पर सामान्य चर्चा करता है, इसे प्रवर समिति को भेज सकता है तथा इसके प्रत्येक खंड पर गहनता से विचार-विमर्श करता है। इसी चरण में सदस्य विधेयक के अलग-अलग प्रावधानों पर संशोधन पेश करते हैं और उन संशोधनों पर मतदान आयोजित किया जाता है।

58. (A) बहस पूरे विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने तक सीमित होती है।
विधेयक के "तृतीय वाचन" के चरण में चर्चा का दायरा अत्यंत सीमित होता है। इस चरण में केवल विधेयक को समग्र रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने पर ही बहस की अनुमति दी जाती है। इस स्तर पर विधेयक के किसी भी खंड में कोई नया संशोधन पेश करने की अनुमति नहीं होती है। यदि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत इसे स्वीकृति दे देता है तो विधेयक पारित मान लिया जाता है।

59. (A) I, II और III
साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इसे पारित होने के बाद राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। हालांकि यदि संसद इसे पुनः पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। इसलिए संसद द्वारा दोबारा पारित विधेयक पर स्वीकृति रोकने का राष्ट्रपति का दावा गलत है क्योंकि दूसरी बार स्वीकृति देना अनिवार्य होता है।

60. (B) सदनों के पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटाकर
जब दोनों सदनों द्वारा पारित साधारण विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति उसे संसद को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति की इस शक्ति को निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को बिना किसी संशोधन के या संशोधनों के साथ पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना संवैधानिक रूप से बाध्यकारी होता है।

61. (A) इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है।
संविधान के अनुसार संसद में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश प्राप्त होना एक अनिवार्य शर्त है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक लोक सभा में पेश नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त धन विधेयक को केवल लोक सभा में ही पेश किया जा सकता है, इसे राज्य सभा में पहले पेश करने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है।

62. (C) किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन
अनुच्छेद 110 के अनुसार किसी विधेयक को धन विधेयक केवल तब माना जाता है जब उसमें किसी कर के अधिरोपण, समाप्ति, छूट, परिवर्तन या नियमन जैसे विषय शामिल हों। इसमें भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या भारत की संचित निधि से धन की निकासी के प्रावधान भी होते हैं। जुर्माना लगाने या स्थानीय निकायों द्वारा कर लगाने से संबंधित विधेयकों को धन विधेयक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है।

63. (D) वह किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
जब लोक सभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्य सभा को भेजा जाता है तो राज्य सभा 14 दिनों के भीतर सिफारिशों के साथ उसे वापस कर सकती है। लोक सभा राज्य सभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। यदि लोक सभा किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो विधेयक संशोधित रूप में पारित माना जाता है, अन्यथा मूल रूप में ही पारित होता है।

64. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
धन विधेयक के संबंध में राज्य सभा की शक्तियां अत्यंत सीमित हैं। राज्य सभा न तो धन विधेयक को पूरी तरह अस्वीकृत कर सकती है और न ही उसमें स्वयं कोई प्रत्यक्ष संशोधन कर

Click Here to Buy book on Flipkart

संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ये प्रतिनिधि राज्य सभा में राजस्थान राज्य के हितों एवं दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं और संसदीय कार्यवाहियों में निरंतर अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

22. (C) चौथी अनुसूची
भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य सभा में आवंटित सीटों का पूरा विवरण दिया गया है। प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आकार के आधार पर राज्य सभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। उदाहरण के रूप में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक सीटें मिली हैं जबकि कम जनसंख्या वाले राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को कम सीटें आवंटित की गई हैं।

23. (B) साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा
संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति राज्य सभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इन सदस्यों का चयन ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट विशेषज्ञों के अनुभव और ज्ञान का लाभ देश की सर्वोच्च विधायी प्रक्रिया में प्राप्त करना है।

24. (A) उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार
राज्य सभा में राज्यों को सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। दिए गए राज्यों में उत्तर प्रदेश के पास सर्वाधिक 31 सीटें हैं, इसके पश्चात महाराष्ट्र के पास 19 सीटें हैं। तमिलनाडु के पास 18 सीटें हैं तथा बिहार के पास 16 सीटें हैं। इस प्रकार सीटों की संख्या के आधार पर इन राज्यों का सही अवरोही क्रम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा अंत में बिहार राज्य बनता है।

25. (D) राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा
राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है। संबंधित राज्य की विधान सभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही राज्य सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इस चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। विधान सभा के मनोनीत सदस्य राज्य सभा चुनावों में मतदान करने के पात्र नहीं होते हैं जिससे राज्यों की प्रत्यक्ष जन-प्रतिनिधि संस्था का महत्व बना रहता है।

26. (A) राज्य सूची
संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सभा को यह विशेष अधिकार प्रदान करता है कि वह राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। राज्य सभा चूंकि राज्यों की प्रतिनिधि संस्था है, इसलिए संघ द्वारा राज्य सूची के विषयों पर अतिक्रमण रोकने और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर त्वरित विधायी कदम उठाने के उद्देश्य से यह अनन्य शक्ति विशेष रूप से केवल राज्य सभा को दी गई है।

27. (C) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत
अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सभा को राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए एक विशेष संकल्प पारित करना पड़ता है। इस संकल्प का सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। यह विशेष बहुमत सुनिश्चित करता है कि राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का निर्णय राज्यों के व्यापक समर्थन और सहमति पर आधारित हो।

28. (C) एक वर्ष
अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सभा द्वारा पारित संकल्प एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए ही प्रभावी रहता है। यदि संसद इस विषय पर कानून बनाना जारी रखना चाहती है तो राज्य सभा को हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाने हेतु पुनः नया संकल्प पारित करना पड़ता है। यह समय सीमा यह सुनिश्चित करती है कि संघ द्वारा राज्यों के विधायी अधिकारों का अनिश्चितकाल के लिए अधिग्रहण न हो सके।

29. (B) 2, 1, 3, 4
अनुच्छेद 249 की प्रक्रिया में सर्वप्रथम राज्य सभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करती है। तत्पश्चात संसद उस राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण करती है। यदि संकल्प को पुनः नवीनीकृत न किया जाए तो वह 1 वर्ष बाद समाप्त हो जाता है। संकल्प की समाप्ति के 6 महीने पश्चात संसद द्वारा निर्मित उस कानून का प्रभाव भी स्वतः ही पूरी तरह समाप्त हो जाता है।

30. (A) अनुच्छेद 312
संविधान का अनुच्छेद 312 राज्य सभा को एक अनन्य शक्ति प्रदान करता है। इसके तहत राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करके संघ और राज्यों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार संसद को दे सकती है। जब तक राज्य सभा ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं करती तब तक संसद किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना के लिए कानून नहीं बना सकती है।

31. (B) एक-तिहाई
राज्य सभा एक स्थाई सदन है और इसका विघटन कभी नहीं होता है। इस सदन के निरंतरता बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इन सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। इस चक्रीय व्यवस्था के कारण राज्य सभा की निरंतरता बिना किसी रुकावट के सदैव बनी रहती है।

32. (C) 6 वर्ष
राज्य सभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यद्यपि राज्य सभा एक स्थाई निकाय है और यह कभी भंग नहीं होती, परंतु इसके व्यक्तिगत सदस्यों की अवधि निश्चित होती

Downloaded from www.pdf.tube

(C) भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की सिफारिश करने वाला समावेदन पारित करना।
(D) अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की सिफारिश करना।

128. भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की मांग करने वाला एक औपचारिक संकल्प कहाँ शुरु किया जा सकता है?
(A) केवल लोकसभा में
(B) संसद के किसी भी सदन में
(C) केवल राज्यसभा में
(D) केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा

129. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति को संयुक्त बैठक बुलाकर सुलझाया नहीं जा सकता है।
कारण (R): अनुच्छेद 368 में यह आवश्यक है कि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग अपेक्षित विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है परंतु कारण (R) सही है।

130. यद्यपि दोनों सदनों को एक महीने के भीतर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को मंजूरी देनी होगी, लेकिन इसे वापस लेने (रद्द करने) की मांग करने वाला संकल्प पारित करने की शक्ति अनन्य रूप से किसमें निहित है?
(A) राष्ट्रपति के स्वयं के विवेक में
(B) राज्यसभा में
(C) अंतर-राज्य परिषद में
(D) लोकसभा में

NODIA

43. (B) किसी संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त होने पर, वे स्वतः ही इसके सभापति बन जाते हैं।
संसदीय परंपराओं और नियमों के अंतर्गत लोक सभा के उपाध्यक्ष को एक विशेष विशेषाधिकार प्राप्त है। यदि उपाध्यक्ष को किसी भी संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है तो वह उस समिति का स्वतः ही पदेन सभापति बन जाता है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य संसदीय समितियों के संचालन में उपाध्यक्ष के अनुभव और संवैधानिक पद की गरिमा का लाभ उठाना तथा समितियों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और निष्पक्ष बनाना है।

44. (B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पद रिक्त होने या उसकी अनुपस्थिति में लोक सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। पीठासीन अधिकारी के रूप में उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के समान ही समस्त शक्तियां प्राप्त होती हैं और उसके प्रक्रियात्मक निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। हालांकि यह शक्ति की समानता उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन का कारण नहीं है बल्कि यह पीठासीन अधिकारी की गरिमा बनाए रखने का नियम है।

45. (A) अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से आता है और उपाध्यक्ष विपक्ष से।
11वीं लोक सभा के समय से भारत में एक स्वस्थ संसदीय परंपरा विकसित हुई है जिसके अनुसार लोक सभा अध्यक्ष का पद सत्तारूढ़ दल या गठबंधन को दिया जाता है जबकि उपाध्यक्ष का पद प्रमुख विपक्षी दल को प्रदान किया जाता है। इस परंपरा का उद्देश्य संसदीय प्रणाली में सर्वसम्मति, निष्पक्षता और विपक्ष के प्रति सम्मान व्यक्त करना है ताकि विधायी कार्यवाहियों में संतुलन और लोकतांत्रिक मूल्यों की गरिमा निरंतर बनी रहे।

46. (C) भारत के उपराष्ट्रपति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। पदेन शब्द का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होगा वह स्वतः ही राज्य सभा के सभापति की भूमिका भी ग्रहण कर लेगा। यद्यपि उपराष्ट्रपति राज्य सभा का सदस्य नहीं होता है फिर भी वह सदन का पीठासीन अधिकारी होता है और उसकी समस्त कार्यवाहियों का संचालन करता है।

47. (D) सभापति केवल मत बराबर होने की स्थिति में ही निर्णायक वोट देते हैं।
राज्य सभा का सभापति चूंकि सदन का सदस्य नहीं होता है इसलिए उसे आम विधायी मामलों पर प्रथमतः मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। हालांकि सदन की कार्यवाहियों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए उसे एक विशेष अधिकार दिया गया है। यदि किसी प्रस्ताव या विधेयक पर मतदान के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो सभापति गतिरोध दूर करने के लिए अपना निर्णायक मत दे सकता है।

48. (C) वे सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते, लेकिन बोल सकते हैं और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।
जब राज्य सभा में उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तो वह सभापति के रूप में सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। हालांकि वह सदन में उपस्थित रह सकता है, बोल सकता है और कार्यवाही में भाग ले सकता है। चूंकि वह राज्य सभा का सदस्य नहीं होता इसलिए वह इस संकल्प या किसी अन्य मामले पर मतदान करने का हकदार नहीं होता है। यह नियम निष्पक्षता के सिद्धांत पर आधारित है।

49. (A) P-1, Q-2, R-3, S-4
लोक सभा अध्यक्ष का चुनाव लोक सभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्य सभा के सभापति का पद भारत का उपराष्ट्रपति पदेन रूप से ग्रहण करता है। राज्य सभा का उपसभापति राज्य सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाता है। इसके विपरीत सामयिक अध्यक्ष अर्थात प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई लोक सभा की पहली बैठक का संचालन करने तथा सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए की जाती है।

50. (D) राज्यसभा के उपसभापति
जब भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो वह राज्य सभा के सभापति के रूप में कार्य करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में राज्य सभा के सभापति के पद के सभी कर्तव्यों और दायित्वों का पालन राज्य सभा के उपसभापति द्वारा किया जाता है। इस अवधि के दौरान उपसभापति को सभापति के समान ही सभी शक्तियां और भत्ते प्राप्त होते हैं।

51. (B) 6 महीने
संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका सीधा अर्थ यह है कि संसद को एक वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य मिलना चाहिए। हालांकि व्यावहारिक रूप से भारत में संसद के तीन नियमित सत्र आयोजित किए जाते हैं जिन्हें बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र कहा जाता है।

52. (C) सत्रावसान
संसदीय शब्दावली में दैनिक बैठक के समापन को स्थगन कहा जाता है जबकि पूरे सत्र की औपचारिक समाप्ति को सत्रावसान कहा जाता है। सत्रावसान की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के माध्यम से की जाती है। सत्रावसान से केवल सदन की बैठकें समाप्त होती हैं, परंतु सदन के समक्ष लंबित विधेयक या कार्य व्यपगत नहीं होते हैं। वे अगले सत्र में पुनः विचार के लिए जारी रखे जा सकते हैं।

53. (A) संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी
जब सदन की बैठक को बिना कोई अगली तिथि या समय निर्धारित किए समाप्त कर दिया जाता है तो इसे "अनिश्चित काल के लिए स्थगन" कहा जाता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन घोषित करने का अधिकार केवल संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी अर्थात लोक सभा में अध्यक्ष और राज्य

Click Here to Buy book on Amazon

108. दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए किस संवैधानिक प्राधिकारी को अधिकृत किया गया है?
(A) भारत के राष्ट्रपति
(B) संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी
(C) मुख्य निर्वाचन आयुक्त
(D) भारत के उच्चतम न्यायालय

109. दल-बदल विरोधी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ने वाला सदस्य अयोग्यता का भागी होता है।
II. अपने दलीय सचेतक (व्हिप) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत मतदान करने वाला सदस्य अयोग्यता का भागी होता है।
III. विभाजन (एक-तिहाई सदस्य) के मामले में अयोग्यता से छूट को 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा हटा दिया गया था।
IV. कानून वर्तमान में दल-बदल से छूट देता है यदि किसी विधायी दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य दल में विलय कर लेते हैं।
उपर्युक्त कथनों का कौन-सा संयोजन सही है?
(A) I, II और III
(B) I, III और IV
(C) II, III और IV
(D) I, II, III और IV

110. किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992) के ऐतिहासिक मामले में, उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दसवीं अनुसूची के तहत पीठासीन अधिकारी का निर्णय:
(A) अंतिम, बाध्यकारी और किसी भी प्रकार के न्यायिक हस्तक्षेप या समीक्षा से पूरी तरह मुक्त है।
(B) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा औपचारिक अनुसमर्थन के बाद ही कानूनी रूप से वैध है।
(C) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
(D) प्रकृति में पूरी तरह से सलाहकारी है और राष्ट्रपति द्वारा अनिवार्य अनुमोदन के अधीन है।

111. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों और उसकी समितियों को विशेष रूप से विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान करता है?
(A) अनुच्छेद 74
(B) अनुच्छेद 105
(C) अनुच्छेद 110
(D) अनुच्छेद 123

112. संसदीय विशेषाधिकारों के तहत, संसद सदस्य को सदन के सत्र के दौरान और ऐसे सत्र से कितने दिन पहले और बाद की अवधि के दौरान सिविल मामलों में गिरफ्तारी से उन्मुक्ति प्राप्त होती है?
(A) 14 दिन
(B) 30 दिन
(C) 40 दिन
(D) 60 दिन

113. सदन के भीतर किसी संसद सदस्य को दी गई वाक्-स्वातंत्र्य के विशेषाधिकार का दायरा क्या है?
(A) कानूनी उन्मुक्ति केवल वित्तीय विधेयकों और बजट से संबंधित बयानों और वोटों तक सीमित है।
(B) संसद में कही गई किसी बात या दिए गए किसी वोट के संबंध में न्यायालय से उन्मुक्ति।
(C) अध्यक्ष के पूर्व लिखित अनुमोदन की आवश्यकता वाले न्यायिक कार्यवाहियों से सशर्त उन्मुक्ति।
(D) आपराधिक अभियोजन के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी रहते हुए, सिविल मानहानि मुकदमों से व्यापक सुरक्षा।

114. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): संसद सदस्य संसद के चल रहे सत्र के दौरान भी आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं।
कारण (R): गिरफ्तारी से स्वतंत्रता का संसदीय विशेषाधिकार विशेष रूप से केवल सिविल मामलों पर लागू होता है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है परंतु कारण (R) सही है।

NODIA

115. निम्नलिखित में से कौन-सा प्राधिकारी, संसद का अभिन्न अंग होने के बावजूद, अनुच्छेद 105 के तहत निर्धारित संसदीय विशेषाधिकारों का आनंद नहीं लेता है?
(A) भारत के राष्ट्रपति
(B) लोकसभा अध्यक्ष
(C) भारत के महान्यायवादी
(D) केंद्रीय मंत्री

116. लोकसभा में आधिकारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, नेता के दल को सदन की कुल शक्ति का कम से कम कितना हिस्सा प्राप्त होना चाहिए?
(A) एक-पांचवां हिस्सा (1/5)
(B) एक-दसवां हिस्सा (1/10)
(C) एक-तिहाई हिस्सा (1/3)
(D) एक-चौथाई हिस्सा (1/4)

117. संसद में नेता प्रतिपक्ष को वैधानिक मान्यता प्राप्त है और उन्हें किसके समकक्ष वेतन, भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं?
(A) कैबिनेट मंत्री
(B) राज्य मंत्री
(C) उपमंत्री

सकती है। उसे केवल अपनी सिफारिशें देने का अधिकार है और विधेयक को 14 दिनों के भीतर वापस लौटाना अनिवार्य होता है। यही सीमित शक्तियां यह स्पष्ट करती हैं कि धन विधेयक पर केवल लोक सभा का प्रभुत्व रहता है।

65. (B) श्रेणी-I में अनुच्छेद 110 के मामलों के साथ-साथ सामान्य कानून शामिल होते हैं, और राज्यसभा इसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है।
अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक में केवल कर और व्यय से संबंधित मामले होते हैं, जबकि वित्त विधेयक श्रेणी-I में अनुच्छेद 110 के विषयों के साथ-साथ सामान्य विधायन के प्रावधान भी शामिल होते हैं। धन विधेयक की भांति इसे भी केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोक सभा में लाया जा सकता है, परंतु राज्य सभा के पास वित्त विधेयक श्रेणी-I को अस्वीकृत या संशोधित करने की पूरी शक्ति प्राप्त होती है।

66. (D) भारत के राष्ट्रपति
जब किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में असहमति या गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार प्राप्त होता है। यह आहूत बैठक विधायी गतिरोध को समाप्त करने के लिए आयोजित की जाती है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं ताकि विधेयक पर निर्णय लिया जा सके।

67. (A) लोकसभा के उपाध्यक्ष
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सामान्यतः लोक सभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यदि लोक सभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो लोक सभा का उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो राज्य सभा का उपसभापति बैठक की अध्यक्षता करता है। राज्य सभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता क्योंकि वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता।

68. (C) धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक
संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाने वाली संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों तथा वित्त विधेयकों के लिए ही उपलब्ध है। धन विधेयकों के मामले में लोक सभा को अनन्य अधिकार प्राप्त हैं इसलिए संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार संविधान संशोधन विधेयक के लिए दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है, इसलिए इस पर भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती।

69. (A) P-1, Q-2, R-3
भारतीय संसदीय इतिहास में अब तक केवल तीन बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। दहेज निषेध विधेयक को पारित करने के लिए मई 1961 में पहली संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक के संदर्भ में मई 1978 में दूसरी संयुक्त बैठक आयोजित हुई थी। अंततः आतंकवादी गतिविधि निवारण विधेयक अर्थात पोटा के लिए मार्च 2002 में तीसरी बार संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया था।

70. (B) दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का दसवां हिस्सा (1/10)
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कार्यवाही को वैध रूप से संचालित करने के लिए नियत गणपूर्ति अर्थात कोरम का होना आवश्यक है। संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या का दसवां हिस्सा अर्थात 1/10 होती है। यदि बैठक के समय यह न्यूनतम उपस्थिति दर्ज नहीं होती है तो पीठासीन अधिकारी बैठक को स्थगित करने या निलंबित करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य होता है।

71. (B) 22 सदस्य
भारतीय संसद की लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या 22 निर्धारित की गई है। इन 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोक सभा द्वारा चुने जाते हैं और शेष 7 सदस्य राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। समिति के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है जिससे संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों को उनकी क्षमता के अनुरूप प्रतिनिधित्व मिल सके।

72. (C) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच करना।
लोक लेखा समिति का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए गए वित्तीय लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की सूक्ष्म जांच करना है। यह समिति यह सुनिश्चित करती है कि संसद द्वारा स्वीकृत धन को उसी मद और उद्देश्य के लिए खर्च किया गया है जिसके लिए वह दिया गया था। इस प्रकार यह समिति वित्तीय अनियमितताओं को उजागर कर कार्यपालिका की जवाबदेही तय करती है।

73. (D) लोकसभा में विपक्ष से
वर्ष 1967 से भारत में एक सर्वमान्य संसदीय परंपरा स्थापित की गई है जिसके तहत लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोक सभा में विपक्षी दल के सदस्यों में से की जाती है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोक सभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। विपक्षी दल से अध्यक्ष नियुक्त करने की इस परंपरा का मुख्य उद्देश्य सरकारी व्यय की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना और पारदर्शिता बनाए रखना है।

74. (A) केवल I और II
लोक लेखा समिति का गठन सर्वप्रथम 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ था। इसमें मंत्रियों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होता है ताकि निष्पक्षता बनी रहे। हालांकि इसके सदस्य दोनों सदनों से समान रूप से नहीं लिए जाते, बल्कि 15 सदस्य लोक सभा से और केवल 7 सदस्य राज्य सभा से चुने जाते हैं। इस प्रकार तीसरा कथन पूरी तरह से असत्य और तथ्यात्मक रूप से गलत है।

Downloaded from www.pdf.tube

75. (A) 1 वर्ष
लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए होता है। प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों द्वारा नए सिरे से समिति के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। 1 वर्ष का यह निश्चित कार्यकाल यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न सांसदों को इस महत्वपूर्ण वित्तीय समिति में कार्य करने का अवसर मिले और कार्यपालिका के खर्चों की नियमित निगरानी निरंतर बनी रहे।

76. (B) प्राकलन समिति
संसद की सभी वित्तीय समितियों में प्राकलन समिति सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी समिति है। इस समिति में कुल 30 सदस्य शामिल होते हैं। प्राकलन समिति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके सभी 30 सदस्य केवल लोक सभा से ही चुने जाते हैं और इसमें राज्य सभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। यह समिति वित्तीय अनुमानों में मितव्ययिता और प्रशासनिक सुधारों का सुझाव देती है।

77. (A) विशेष रूप से केवल लोकसभा से 30 सदस्य
प्राकलन समिति अपनी संरचना के मामले में एक अनूठी वित्तीय समिति है क्योंकि इसमें केवल लोक सभा से ही 30 सदस्य शामिल होते हैं। राज्य सभा का कोई भी सदस्य इस समिति में शामिल नहीं किया जाता है। लोक सभा वित्तीय मामलों में जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करने वाला प्राथमिक सदन है, इसलिए प्राकलन समिति में केवल लोक सभा के सदस्यों को ही स्थान दिया गया है जो बजट अनुमानों की सूक्ष्म समीक्षा करते हैं।

78. (C) बजट अनुमानों के अनुरूप मितव्ययिता और नीतिगत सुधारों पर रिपोर्ट देना।
प्राकलन समिति का मूल कार्य बजट में शामिल अनुमानों की विस्तृत जांच करना और यह सुझाव देना है कि प्रशासन में किस प्रकार मितव्ययिता, कार्यकुशलता तथा संगठन सुधार लाए जा सकते हैं। यह समिति यह देखती है कि नीतियों के ढांचे के भीतर रहते हुए धन का सही उपयोग कैसे किया जाए। यह बजट अनुमानों पर अपनी रिपोर्ट देकर वित्तीय संसाधनों के अपव्यय को रोकने में मदद करती है।

79. (D) I, II, III और IV
प्राकलन समिति की स्थापना 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर हुई थी। यह समिति संसद द्वारा बजट स्वीकृत किए जाने के बाद अनुमानों की जांच करती है। लोक सभा अध्यक्ष हमेशा सत्तारूढ़ दल के सदस्य को ही इसका अध्यक्ष नियुक्त करता है और इसमें कोई मंत्री सदस्य नहीं बन सकता। इस प्रकार इस समिति से संबंधित दिए गए सभी चार कथन पूर्णतः सत्य और प्रासंगिक हैं।

80. (C) क्योंकि यह प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता लाने के लिए नीतिगत विकल्प सुझाती है।
प्राकलन समिति को अनौपचारिक रूप से "सतत मितव्ययिता समिति" के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह पूरे वर्ष सरकारी विभागों के बजट अनुमानों और खर्चों का निरंतर परीक्षण करती रहती है। यह समिति प्रशासन में अपव्यय को रोकने, दक्षता बढ़ाने और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियां तथा संगठनात्मक सुधार सुझाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन का उपयोग बिना किसी बर्बादी के कुशलपूर्वक किया जाए।

81. (B) कृष्ण मेनन समिति
भारत में सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति का गठन वर्ष 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। इस समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सरकारी उपक्रमों, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के वित्तीय प्रबंधन, व्यावसायिक स्वायत्तता तथा उनकी कार्यकुशलता की विशेष रूप से जांच करना था ताकि सार्वजनिक उपक्रमों के संचालन में संसद की प्रभावी देखरेख और जवाबदेही स्थापित की जा सके।

82. (B) 22 सदस्य: लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7
सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इन 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोक सभा से चुने जाते हैं तथा शेष 7 सदस्य राज्य सभा से निर्वाचित किए जाते हैं। सदस्यों का चुनाव प्रति वर्ष संसद द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। यह व्यवस्था समिति में संसद के दोनों सदनों के उचित और संतुलित प्रतिनिधित्व को मजबूती से सुनिश्चित करती है।

83. (A) केवल लोकसभा से
सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोक सभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन अनिवार्य रूप से केवल लोक सभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। यदि राज्य सभा के सदस्य भी इस समिति में शामिल होते हैं, किंतु उन्हें समिति का अध्यक्ष बनने की पात्रता नहीं होती है। यह व्यवस्था वित्तीय मामलों में लोक सभा के मुख्य नियंत्रण को दर्शाती है।

84. (B) लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति
भारत में प्रमुख संसदीय वित्तीय समितियों की स्थापना का सही कालानुक्रमिक क्रम लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति है। लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में हुई थी। इसके पश्चात स्वतंत्रता के बाद 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर प्राकलन समिति का गठन किया गया। अंततः 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश के आधार पर सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति स्थापित की गई।

NODIA

85. (A) व्यावसायिक सिद्धांतों से अलग प्रमुख सरकारी नीति की जांच करना।
सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति को प्रमुख सरकारी नीतियों की जांच करने का अधिकार प्राप्त नहीं है यदि वे नीतियां व्यावसायिक सिद्धांतों से अलग हटकर नीतिगत मामलों से संबंधित हों। यह समिति सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्टों, लेखा-परीक्षा विवरणों और उनकी व्यावसायिक दक्षता की जांच तक ही सीमित रहती है। सरकार की शुद्ध राजनीतिक

या व्यापक राष्ट्रीय नीतियों का मूल्यांकन करना इस समिति के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है।

86. (D) प्रश्नकाल
लोक सभा की सामान्य बैठक का पहला घंटा आमतौर पर 'प्रश्नकाल' के लिए समर्पित होता है। यह संसदीय कार्य दिवस का पहला महत्वपूर्ण चरण होता है जो सुबह 11 बजे शुरु होता है। इस घंटे के दौरान संसद सदस्य मंत्रियों से सरकार के कामकाज, नीतियों और प्रशासनिक निर्णयों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नकाल कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण स्थापित करने का एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी साधन माना जाता है।

87. (B) तारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, जिससे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मिलती है।
प्रश्नकाल के दौरान "तारांकित प्रश्न" वह प्रश्न होता है जिस पर सदस्य सदन के पटल पर संबंधित मंत्री से मौखिक उत्तर की अपेक्षा करता है। तारांकित प्रश्न की पहचान उस पर बने तारांक चिन्ह से होती है। मंत्री द्वारा मौखिक उत्तर दिए जाने के बाद सदस्य को उस विषय से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्राप्त होती है जिससे विषय पर और अधिक स्पष्टता प्राप्त की जा सके।

88. (C) पटल पर रखा गया लिखित उत्तर, जिस पर कोई पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है।
"अतारांकित प्रश्न" वह प्रश्न होता है जिसके लिए सदस्य मंत्री से मौखिक उत्तर के बजाय लिखित उत्तर की मांग करता है। संबंधित मंत्री द्वारा इस प्रश्न का उत्तर लिखित रुप में सदन के पटल पर रख दिया जाता है। चूंकि अतारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित में दिया जाता है, इसलिए इस पर सदन में कोई मौखिक चर्चा नहीं होती और न ही इसके आधार पर कोई पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है।

89. (B) 2, 1, 3
लोक सभा की दैनिक बैठक का सामान्य क्रम अत्यधिक व्यवस्थित होता है। बैठक का प्रारंभ सबसे पहले सुबह 11 बजे 'प्रश्नकाल' से होता है। प्रश्नकाल की समाप्ति के तुरंत बाद दोपहर 12 बजे 'शून्यकाल' शुरु होता है। शून्यकाल समाप्त होने के पश्चात सदन की कार्यसूची में दर्ज नियमित विधायी कार्य, विधेयकों पर बहस तथा सरकारी कार्य आरंभ होते हैं। इस प्रकार दैनिक कार्यसूची का क्रम 2, 1, 3 बनता है।

90. (A) 10 दिनों से कम
"अल्पसूचना प्रश्न" वह प्रश्न होता है जो लोक महत्व के किसी अविलंबनीय मामले से संबंधित होता है। ऐसा प्रश्न पूछने के लिए सामान्य प्रश्न की तुलना में कम समय की लिखित सूचना देनी होती है। अल्पसूचना प्रश्न के लिए 10 दिनों से कम समय की पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। इस प्रश्न का उत्तर भी संबंधित मंत्री द्वारा सदन में मौखिक रूप से ही प्रदान किया जाता है।

91. (B) बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठाने का एक अनौपचारिक साधन है।
"शून्यकाल" भारतीय संसदीय प्रणाली की एक विशेष और अनूठी प्रक्रिया है। यह बिना किसी पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मामलों को उठाने का एक अनौपचारिक साधन है। शून्यकाल का उल्लेख लोक सभा या राज्य सभा की प्रक्रिया के नियमों की पुस्तक में कहीं नहीं किया गया है। यह व्यवस्था सांसदों को बिना लंबी प्रक्रिया के तात्कालिक मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचने का अवसर प्रदान करती है।

92. (B) 1962
भारतीय संसदीय व्यवस्था में 'शून्यकाल' एक अभिनव भारतीय नवाचार के रूप में वर्ष 1962 से अस्तित्व में आया। इस प्रक्रिया का विचार भारतीय प्रेस और सांसदों के अनौपचारिक प्रयासों से विकसित हुआ था। शून्यकाल के दौरान बिना किसी पूर्व लिखित नोटिस के अविलंबनीय लोक महत्व के मामले सदन में उठाए जाने लगे। तब से यह व्यवस्था भारतीय संसद के दैनिक कामकाज का एक अनिवार्य अंग बन चुकी है।

93. (B) प्रश्नकाल के ठीक बाद जब तक कि नियमित कार्यसूची शुरु न हो जाए।
संसद की दैनिक बैठक के दौरान शून्यकाल का समय सामान्यतः दोपहर 12 बजे शुरु होता है। यह प्रश्नकाल के समाप्त होने के ठीक बाद और दिन की नियमित कार्यसूची शुरु होने के बीच का समय अंतराल होता है। इसी शून्य समय अंतराल के कारणइसे 'शून्यकाल' नाम दिया गया है। इस समय का उपयोग सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के ज्वलंत और तात्कालिक मुद्दों को उठाने के लिए करते हैं।

94. (C) कथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
शून्यकाल के दौरान संसद सदस्य बिना कोई पूर्व सूचना दिए अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठा सकते हैं, इसलिए पहला कथन पूरी तरह सत्य है। हालांकि शून्यकाल का उल्लेख लोक सभा या राज्य सभा के प्रक्रिया नियमों की संहिताबद्ध पुस्तक में कहीं भी नहीं है। यह एक अनौपचारिक भारतीय संसदीय नवाचार है, इसलिए कारण वाला कथन कि यह सख्त नियमों से संचालित होता है, पूरी तरह असत्य है।

95. (D) मंत्री शून्यकाल के दौरान उठाए गए मामलों पर जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है।
शून्यकाल के दौरान सांसदों द्वारा उठाए गए मामलों पर संबंधित मंत्री का तुरंत उत्तर देना संवैधानिक या प्रक्रियात्मक रुप से अनिवार्य नहीं होता है। चूंकि यह मुद्दे बिना किसी पूर्व लिखित सूचना के अचानक उठाए जाते हैं, इसलिए मंत्री उसी समय उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता। हालांकि मंत्री चाहे तो तात्कालिक उत्तर दे सकता है या बाद में विस्तृत लिखित जानकारी सदन के पटल पर रख सकता है।

96. (C) लोकसभा में
मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोक सभा में ही पेश किया जा सकता है। इसका मुख्य संवैधानिक कारण यह है कि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार अर्थात मंत्रिपरिषद

Click Here to Buy book on Flipkart

वाली समिति में प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होते हैं। यह व्यवस्था पारदर्शी चयन और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है।

119. (A) P-2, Q-4, R-1, S-3
सदन का नेता आमतौर पर प्रधानमंत्री या मनोनीत मंत्री होता है। नेता प्रतिपक्ष कोरम पूरा करने वाले सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होता है। सचेतक अर्थात व्हिप दलीय सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने और दलीय रेखा के अनुसार मतदान करने का निर्देश जारी करता है। शैडो कैबिनेट विपक्ष द्वारा गठित एक वैकल्पिक मंत्रिमंडल है जो सरकारी मंत्रालयों के कामकाज पर लगातार नजर रखने के लिए बनाया जाता है।

120. (C) यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन)
"छाया मंत्रिमंडल" अर्थात शैडो कैबिनेट की अवधारणा ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली की एक अनूठी और ऐतिहासिक संस्था है। यूनाइटेड किंगडम में विपक्षी दल द्वारा एक छाया मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है जिसमें प्रमुख विपक्षी सांसद सरकारी मंत्रियों के कार्यों पर नजर रखते हैं। यदि सत्तारूढ़ दल की सरकार गिर जाती है तो यह छाया मंत्रिमंडल तुरंत एक वैकल्पिक सरकार बनाने और जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार रहता है।

121. (D) समय की कमी के कारण बिना चर्चा वाले खंडों या मांगों पर मतदान कराना।
संसदीय प्रक्रिया में "गिलोटिन" एक ऐसा प्रक्रियात्मक साधन है जिसका प्रयोग बजट या विधेयकों पर समय की कमी होने पर किया जाता है। जब अनुदान की मांगों पर आवंटन समय समाप्त हो जाता है तो जिन मांगों पर चर्चा नहीं हो सकी होती है उन पर भी बिना किसी आगे की बहस के सीधा मतदान करा लिया जाता है। इस प्रक्रिया को विधायी कार्यप्रणाली में 'गिलोटिन' कहा जाता है।

122. (C) 24
भारतीय संसद में वर्तमान में कुल 24 विभाग-संबंधित स्थाई समितियां अस्तित्व में हैं। इन 24 समितियों में से 16 समितियां लोक सभा के अंतर्गत कार्य करती हैं जबकि 8 समितियां राज्य सभा के क्षेत्राधिकार में आती हैं। प्रत्येक समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं जिनमें 21 लोक सभा से और 10 राज्य सभा से चुने जाते हैं। ये समितियां विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के कामकाज और बजट की जांच करती हैं।

123. (B) विशेष रूप से वित्तीय मामलों में संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को बढ़ाना।
विभाग-संबंधित स्थाई समितियों की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय और विधायी मामलों में संसद के प्रति कार्यपालिका की निरंतर जवाबदेही को मजबूत करना है। ये समितियां विभिन्न मंत्रालयों के बजट अनुदानों, वार्षिक रिपोर्टों और महत्वपूर्ण विधेयकों की सूक्ष्मता से जांच करती हैं। इस व्यवस्था से संसद को सरकारी कामकाज पर अधिक प्रभावी, गहन और विशेषज्ञतापूर्ण नियंत्रण बनाए रखने में अभूतपूर्व सहायता प्राप्त होती है।

124. (A) नियम 377
लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों का 'नियम 377' सांसदों को एक विशेष अवसर प्रदान करता है। जो सार्वजनिक मुद्दे प्रश्नकाल, आधे घंटे की चर्चा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नहीं उठाए जा सकते, उन्हें सदस्य नियम 377 के तहत लोक सभा में उठा सकते हैं। यह नियम सांसदों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को उठाने का अधिकार देता है।

125. (A) सदन के गर्भगृह में जाना
लोक सभा या राज्य सभा में "सदन के गर्भगृह में जाना" अर्थात वैल में उतरना कोई मान्यता प्राप्त प्रक्रियात्मक नियम नहीं है, बल्कि यह विरोध व्यक्त करने की एक विघटनकारी रणनीति है। जब सदस्य पीठासीन अधिकारी के आसन के पास बने गर्भगृह में आकर नारेबाजी करते हैं तो सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होती है। इसके विपरीत व्यवस्था का प्रश्न और अल्पकालिक चर्चाएं नियमों के तहत स्वीकृत प्रक्रियाएं हैं।

126. (C) संविधान संशोधन विधेयकों को पारित करना।
संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के मामले में लोक सभा और राज्य सभा दोनों सदनों को बिल्कुल समान शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग अपने विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है। इस मामले में न तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है और न ही लोक सभा राज्य सभा को दरकिनार कर सकती है।

127. (D) अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की सिफारिश करना।
संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की सिफारिश करने का अनन्य और विशेष अधिकार केवल राज्य सभा के पास निहित है। जब राज्य सभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों के विशेष बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करती है तभी संसद कानून बनाकर नई सेवा बना सकती है। लोक सभा स्वतः ही अपनी पहल पर ऐसा कोई संकल्प पेश नहीं कर सकती।

NODIA

128. (C) केवल राज्यसभा में
भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए औपचारिक संकल्प केवल और केवल राज्य सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। राज्य सभा द्वारा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प को जब लोक सभा अपना साधारण बहुमत दे देती है तो उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। इसे केवल राज्य सभा में लाया जा सकता है।

वह मनोनीत सदस्य अपना पद ग्रहण करने के शुरुआती 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता लेता है तो उस पर यह अयोग्यता लागू नहीं होती है।

108. (B) संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी
दल-बदल विरोधी कानून के तहत किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न पर अंतिम निर्णय लेने का संवैधानिक अधिकार संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। लोक सभा के मामले में लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा के मामले में सभापति इस पर निर्णय लेते हैं। जब तक पीठासीन अधिकारी का निर्णय नहीं आ जाता तब तक सदस्य की सदस्यता पर कोई अंतिम प्रभाव नहीं पड़ता।

109. (D) I, II, III और IV
दल-बदल कानून के तहत स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ने या सचेतक के निर्देशों का उल्लंघन करने पर सदस्य अयोग्य हो जाता है। 91वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा एक-तिहाई सदस्यों के विभाजन वाली छूट को समाप्त कर दिया गया। अब केवल तभी छूट मिलती है जब किसी विधायी दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य दल में विलय करते हैं। अतः दिए गए सभी चारों कथन सत्य हैं।

110. (C) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू 1992 के मामले में उच्चतम न्यायालय की पीठ ने फैसला सुनाया कि दसवीं अनुसूची के तहत निर्णय देते समय पीठासीन अधिकारी एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है। इसलिए पीठासीन अधिकारी का अयोग्यता संबंधी निर्णय अंतिम नहीं है बल्कि वह उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इस निर्णय ने पीठासीन अधिकारियों के स्वेच्छाचारी अधिकारों पर अंकुश लगाया।

111. (B) अनुच्छेद 105
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 विशेष रूप से संसद के सदनों, उनके सदस्यों तथा उनकी समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का विस्तृत वर्णन करता है। यह अनुच्छेद सांसदों को बिना किसी भय या बाहरी दबाव के अपने विधायी एवं संसदीय कर्तव्यों का स्वतंत्र रूप से पालन करने की संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें वाक्-स्वातंत्र्य और न्यायालयी कार्यवाहियों से उन्मुक्ति की महत्वपूर्ण व्यवस्था शामिल है।

112. (C) 40 दिन
संसदीय विशेषाधिकारों के अंतर्गत किसी संसद सदस्य को संसद का सत्र शुरु होने से 40 दिन पहले, सत्र के दौरान तथा सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक केवल सिविल मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्राप्त होती है। यह सुरक्षा सदस्यों को उनके संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा न आने देने के उद्देश्य से दी गई है। हालांकि यह विशेष उन्मुक्ति आपराधिक मामलों या निवारक निरोध पर लागू नहीं होती।

113. (B) संसद में कही गई किसी बात या दिए गए किसी वोट के संबंध में न्यायालय से उन्मुक्ति।
अनुच्छेद 105(2) के अंतर्गत संसद सदस्यों को सदन के भीतर वाक्-स्वातंत्र्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त है। किसी भी संसद सदस्य द्वारा संसद में या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात अथवा दिए गए किसी मत के संबंध में देश की किसी भी अदालत में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। यह विशेषाधिकार सदस्यों को बिना किसी भय के अपनी बात रखने की पूरी आजादी देता है।

114. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
संसद सदस्य चल रहे सत्र के दौरान भी आपराधिक मामलों या निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी से उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि गिरफ्तारी से स्वतंत्रता का संसदीय विशेषाधिकार केवल सिविल मुकदमों तक ही सीमित है। आपराधिक मामलों में सांसदों को आम नागरिकों की भांति ही विधि की प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए कथन और कारण दोनों बिल्कुल सही हैं।

115. (A) भारत के राष्ट्रपति
हालांकि भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अनिवार्य एवं अभिन्न अंग होता है, परंतु वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इसी कारण राष्ट्रपति अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों और मंत्रियों को मिलने वाले संसदीय विशेषाधिकारों का उपभोग नहीं करता है। राष्ट्रपति के पास संविधान के अन्य अनुच्छेदों जैसे अनुच्छेद 361 के तहत अपने पद की अलग संवैधानिक उन्मुक्तियां और विशेष संरक्षण प्राप्त होते हैं।

116. (B) एक-दसवां हिस्सा (1/10)
लोक सभा में आधिकारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी विपक्षी दल के पास लोक सभा की कुल सदस्य संख्या का कम से कम दसवां हिस्सा अर्थात 1/10 हिस्सा होना अनिवार्य है। यदि किसी भी विपक्षी दल के पास सदन की कुल सीटों का न्यूनतम 10 प्रतिशत हिस्सा नहीं होता है तो उसके नेता को औपचारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष का दर्जा प्रदान नहीं किया जाता है।

117. (A) कैबिनेट मंत्री
संसद में नेता प्रतिपक्ष के पद को 'संसद में विरोधी दल के नेता का वेतन और भत्ता अधिनियम 1977' द्वारा वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इस कानून के अनुसार लोक सभा और राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष को केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री के समकक्ष वेतन, भत्ते तथा अन्य सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यह व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष के नेता की गरिमा और महत्व को बढ़ाती है।

118. (D) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के निदेशक
लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष देश की कई महत्वपूर्ण संवैधानिक और वैधानिक नियुक्तियों के लिए गठित उच्च स्तरीय चयन समितियों के अनिवार्य सदस्य होते हैं। उदाहरण स्वरूप केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति करने

NODIA

20. सूची I में दिए गए प्रमुख मामलों को सूची II में दिए गए उनके मुख्य विषय-वस्तु के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: प्रमुख मामले
P. केशवानंद भारती मामला
Q. एस. आर. बोम्मई मामला
R. विशाखा मामला
S. एम. सी. मेहता मामला
सूची II: मुख्य विषय-वस्तु
1. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ दिशानिर्देश
2. पर्यावरण संरक्षण और पूर्ण दायित्व
3. मूल ढाँचे का सिद्धांत
4. संघवाद और अनुच्छेद 356 का प्रयोग
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

21. जब उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति को न्यायालय की गरिमा गिराने या उसके प्राधिकार को कम करने के लिए दंडित करता है, तो वह विशेष रुप से किस शक्ति का उपयोग करता है?
(A) आपराधिक अवमानना शक्ति
(B) अपीलीय शक्ति
(C) सिविल अवमानना शक्ति
(D) परामर्शदायी शक्ति

22. न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए गठित समिति में शामिल होते हैं:
(A) भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश
(B) उच्चतम न्यायालय के दो सेवारत न्यायाधीश और किसी उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश
(C) भारत के उच्चतम न्यायालय में कार्यरत तीन वरिष्ठतम सेवारत न्यायाधीश
(D) उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधिवेत्ता

23. जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति और प्राथमिक विकास किस देश में हुआ?
(A) यूनाइटेड किंगडम
(B) संयुक्त राज्य अमेरिका
(C) भारत गणराज्य
(D) ऑस्ट्रेलिया

24. निम्नलिखित में से किसे भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है?
(A) न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़
(B) न्यायमूर्ति हंस राज खन्ना
(C) न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर
(D) न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला

25. 'लोकस स्टैंडाई' (सुनवाई का अधिकार) में ढील देना जनहित याचिका का मूलभूत आधार है। 'लोकस स्टैंडाई' का अर्थ क्या है?
(A) सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय का भौतिक स्थान और भौगोलिक क्षेत्राधिकार
(B) न्यायिक अपील दायर करने के लिए कानून द्वारा निर्धारित सख्त प्रक्रियात्मक समय-सीमा
(C) संवैधानिक विवाद मामलों में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य का मानक
(D) किसी न्यायालय के समक्ष मामला लाने का किसी पक्षकार का कानूनी अधिकार

26. भारत में जनहित याचिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह केवल उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है, उच्च न्यायालयों में नहीं।
II. यह वंचित वर्गों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है।
III. न्यायालय को संबोधित पत्रों या टेलीग्रामों को जनहित याचिका के तहत रिट याचिका के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
IV. प्रांगन्याय का सिद्धांत निरंतर जन-क्षति से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सख्ती से लागू नहीं होता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, III और IV
(D) I, II, III और IV

27. ऐतिहासिक जनहित याचिका मामला 'बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ' मुख्य रुप से किस मुद्दे से संबंधित था?
(A) विचाराधीन बंदियों के अधिकार
(B) बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन
(C) गंगा में पर्यावरणीय प्रदूषण
(D) घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा

28. न्यायिक कामकाज के संदर्भ में, 'न्यायिक सक्रियता' को 'न्यायिक अतिसक्रियता' से क्या अलग करता है?
(A) न्यायिक सक्रियता एक असंवैधानिक सिद्धांत है, जबकि न्यायिक अतिसक्रियता एक सर्वमान्य और वैध संवैधानिक सिद्धांत है।
(B) सक्रियता अधिकारों की अग्रसक्रिय रूप से रक्षा करती है, जबकि अतिसक्रियता विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों का अतिक्रमण करती है।
(C) न्यायिक सक्रियता केवल उच्च न्यायालयों की कार्यवाही पर लागू होती है, जबकि न्यायिक अतिसक्रियता विशेष रुप से भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर लागू होती है।
(D) न्यायिक सक्रियता के लिए एक बड़ी संवैधानिक पीठ

Downloaded from www.pdf.tube

129. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
संविधान संशोधन विधेयक पर लोक सभा और राज्य सभा के बीच मतभेद उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। इसका कारण यह है कि अनुच्छेद 368 में स्पष्ट रूप से यह अनिवार्यता रखी गई है कि प्रत्येक संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग अपने विशेष बहुमत से पारित होना होगा। अतः कथन और कारण दोनों बिल्कुल सही और तर्कसंगत हैं।

130. (D) लोकसभा में
यद्यपि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को जारी रखने के लिए एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक होता है, परंतु आपातकाल को निरस्त या वापस लेने का संकल्प पारित करने की अनन्य शक्ति केवल लोक सभा के पास निहित है। यदि लोक सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की समाप्ति का संकल्प पारित करती है तो राष्ट्रपति को आपातकाल वापस लेना पड़ता है।

www.nodia.in

NODIA

सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य सभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। केवल लोक सभा के पास ही मतदान द्वारा सरकार के बहुमत का परीक्षण करने की शक्ति होती है।

97. (B) लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व।
संविधान का अनुच्छेद 75(3) अविश्वास प्रस्ताव का मुख्य संवैधानिक आधार है। इसमें यह स्पष्ट रूप से निहित है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन अर्थात लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक उत्तरदायित्व के इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे लोक सभा में बहुमत के सदस्यों का विश्वास और समर्थन प्राप्त रहता है।

98. (C) 50 सदस्य
लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए प्रक्रिया नियमों के अनुसार कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है। जब कोई सदस्य अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देता है तो पीठासीन अध्यक्ष सदन में उपस्थित सदस्यों से प्रस्ताव के समर्थन में खड़े होने को कहता है। यदि कम से कम 50 सदस्य प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हो जाते हैं तो प्रस्ताव को चर्चा हेतु स्वीकार कर लिया जाता है।

99. (A) P-2, Q-1, R-3, S-4
अविश्वास प्रस्ताव में कारणों का उल्लेख आवश्यक नहीं होता और यह संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव किसी विशिष्ट नीतिगत विफलता के लिए लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे को उठाने हेतु लाया जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव तब लाया जाता है जब कोई मंत्री तथ्यों को छुपाकर संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है। यह सुमेल संसदीय प्रक्रियाओं की सटीक व्याख्या करता है।

100. (C) मंत्रिपरिषद को तुरंत त्यागपत्र देना होगा।
यदि लोक सभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से सफलतापूर्वक पारित हो जाता है तो इसका सीधा संवैधानिक परिणाम यह होता है कि पूरी मंत्रिपरिषद को तुरंत अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव का पारित होना इस बात का प्रमाण होता है कि सरकार ने लोक सभा में अपना बहुमत खो दिया है। इसके पश्चात राष्ट्रपति नए मंत्रिमंडल के गठन या चुनाव की प्रक्रिया शुरू करते हैं।

101. (A) लोक महत्व के किसी अविलंबनीय मामले की ओर ध्यान आकर्षित करना।
संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य हाल ही में घटित लोक महत्व के किसी अत्यधिक अविलंबनीय मामले की ओर पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना होता है। इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने पर सदन के नियमित सूचीबद्ध कार्यों को रोककर उस विशेष आपातकालीन मुद्दे पर तुरंत चर्चा शुरू की जाती है। यह प्रस्ताव सरकार की किसी गंभीर प्रशासनिक चूक या असफलता को उजागर करने का एक माध्यम है।

102. (D) केवल लोकसभा
स्थगन प्रस्ताव में सरकार की नीतियों या विफलता के प्रति निंदा का तत्व स्पष्ट रूप से शामिल होता है। संविधान के तहत मंत्रिपरिषद केवल लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए स्थगन प्रस्ताव लाने का अधिकार केवल और केवल लोक सभा को ही प्राप्त है। राज्य सभा इस साधन का उपयोग नहीं कर सकती क्योंकि राज्य सभा में पारित किसी निंदात्मक प्रस्ताव से सरकार के अस्तित्व पर कोई सीधा संकट नहीं पड़ता।

103. (B) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
'ध्यानाकर्षण प्रस्ताव' एक पूरी तरह से भारतीय संसदीय नवाचार है जो प्रक्रिया के नियमों में संहिताबद्ध है। इसके माध्यम से कोई सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले की ओर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकता है। मंत्री उस मुद्दे पर एक आधिकारिक बयान देता है। यह व्यवस्था सांसदों को तात्कालिक विषयों पर सरकार से त्वरित और प्रामाणिक स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर देती है।

104. (A) केवल I और II
स्थगन प्रस्ताव पर कई प्रक्रियात्मक प्रतिबंध लागू होते हैं। इसमें केवल एक ही निश्चित विषय शामिल होना चाहिए और विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह ऐसे किसी विषय पर चर्चा को पुनर्जीवित नहीं कर सकता जिस पर उसी सत्र में पहले ही चर्चा हो चुकी हो। अतः तीसरा कथन गलत है क्योंकि स्थगन प्रस्ताव के तहत पुनरावृत्ति की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं दी जाती।

105. (B) 2 घंटे और 30 मिनट
लोक सभा नियमों के अनुसार यदि कोई स्थगन प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया जाता है तो उस पर बहस की अवधि कम से कम ढाई घंटे अर्थात 2 घंटे और 30 मिनट की होनी चाहिए। इतनी समय सीमा इसलिए तय की गई है ताकि अविलंबनीय लोक महत्व के उस गंभीर मुद्दे पर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्य अपने विचार रख सकें और सरकार अपनी सफाई प्रस्तुत कर सके।

106. (C) 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
भारतीय संविधान में 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से एक नई दसवीं अनुसूची जोड़ी गई जिसे सामान्यतः दल-बदल विरोधी कानून कहा जाता है। इस ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल की बुराई को रोकना और विधायकों तथा सांसदों में दलीय निष्ठा को बढ़ावा देना था। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत लाभ या प्रलोभन के आधार पर होने वाले अवांछित दल-बदल पर प्रभावी कानूनी प्रतिबंध लगाया गया।

107. (C) 6 महीने
दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी सदन का मनोनीत सदस्य अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 6 महीने की अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो वह अयोग्यता के अधीन हो जाता है। हालांकि यदि

Click Here to Buy book on Amazon

अभिकथन (A): भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का प्रत्याभूतिदाता और संरक्षक है।

कारण (R): अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार प्रदान करता है।

(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

11. अधीनस्थ न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करने से रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी रिट जारी की जाती है?
(A) परमादेश
(B) प्रतिषेध
(C) उत्प्रेषण
(D) अधिकार-पृच्छा

12. भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है?
(A) विधि की सम्यक प्रक्रिया
(B) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
(C) संसदीय संप्रभुता की परंपराएं
(D) अलिखित संवैधानिक पूर्ववृत्त

13. भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
II. न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव के अलावा संसद में उनके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती है।
III. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत करने की अनुमति है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

14. उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 'कॉलेजियम प्रणाली' किसके द्वारा बनाई गई थी?
(A) संसद के एक अधिनियम द्वारा
(B) एक संविधान संशोधन द्वारा
(C) स्वयं उच्चतम न्यायालय के निर्णयों द्वारा
(D) विधि आयोग की सिफारिशों द्वारा

15. किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि न्यायिक नियुक्तियों की परामर्श प्रक्रिया के लिए बहुसंख्यक न्यायाधीशों को मिलाकर एक कॉलेजियम बनाना आवश्यक है?
(A) प्रथम न्यायाधीश मामला (1981)
(B) तृतीय न्यायाधीश मामला (1998)
(C) चतुर्थ न्यायाधीश मामला (2015)
(D) द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993)

16. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लाया गया था?
(A) 97वाँ संशोधन अधिनियम
(B) 98वाँ संशोधन अधिनियम
(C) 99वाँ संशोधन अधिनियम
(D) 100वाँ संशोधन अधिनियम

17. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने (महाभियोग) की प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही क्रम चुनिए:
(A) राष्ट्रपति का आदेश → जांच समिति → सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव → संसद में मतदान
(B) सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव → जांच समिति → संसद में मतदान → राष्ट्रपति का आदेश
(C) जांच समिति → सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव → राष्ट्रपति का आदेश → संसद में मतदान
(D) सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव → संसद में मतदान → जांच समिति → राष्ट्रपति का आदेश

18. अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय के "अभिलेख न्यायालय" होने का मुख्य महत्व क्या है?
(A) यह राज्य सरकारों द्वारा दायर सभी संवैधानिक मामलों के आधिकारिक रिकॉर्ड रखता है।
(B) यह पूरे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक रिकॉर्ड की देखरेख और रखरखाव करता है।
(C) इसे अपनी सभी कार्यवाहियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड करने का संवैधानिक जनादेश प्राप्त है।
(D) इसके निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और यह अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है।

NODIA

19. अनुच्छेद 141 के तहत, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। क्या यह बाध्यकारी प्रकृति स्वयं उच्चतम न्यायालय पर लागू होती है?
(A) नहीं, उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है और उन्हें उलट सकता है।
(B) हाँ, उच्चतम न्यायालय अपने पिछले निर्णयों से पूर्णतः बाध्य है।
(C) हाँ, लेकिन केवल पाँच या अधिक न्यायाधीशों की पीठों द्वारा दिए गए निर्णयों के लिए।
(D) नहीं, लेकिन केवल राष्ट्रपति ही उच्चतम न्यायालय को उसके पिछले निर्णयों से छूट दे सकते हैं।

अध्याय 11

भारत का सर्वोच्च न्यायालय एवं जनहित याचिका

1. भारत के संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए किसे अधिकृत किया गया है?
   (A) भारत के राष्ट्रपति
   (B) विधि द्वारा संसद
   (C) भारत के मुख्य न्यायाधीश
   (D) भारत का विधि आयोग

2. वर्ष 1950 में जब भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था, तब मुख्य न्यायाधीश सहित इसकी स्वीकृत संख्या कितनी थी?
   (A) 7
   (B) 8
   (C) 10
   (D) 11

3. निम्नलिखित में से कौन-सी भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए संवैधानिक योग्यता नहीं है?
   (A) उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए
   (B) वह भारत का नागरिक होना चाहिए
   (C) वह कम से कम पाँच वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो
   (D) वह राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए

4. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
   (A) वे 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करते हैं।
   (B) वे छह वर्ष की निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं।
   (C) वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करते हैं।
   (D) वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।

5. वर्ष 1993 से स्थापित परंपरा और व्यवहार के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है?
   (A) उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है।
   (B) राष्ट्रपति विधि मंत्री की सलाह के आधार पर सबसे योग्य न्यायाधीश का चयन करते हैं।
   (C) निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश सेवारत न्यायाधीशों के बीच चुनाव कराते हैं।
   (D) संसद मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव पारित करती है।

6. संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का विस्तार निम्नलिखित में से किस विवाद पर नहीं होता है?
   (A) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच
   (B) दो या अधिक राज्यों के बीच
   (C) एक ओर भारत सरकार और कोई राज्य तथा दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच
   (D) संविधान से पूर्व की किसी संधि या सनद से उत्पन्न विवाद

7. सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है?
   (A) अनुच्छेद 132
   (B) अनुच्छेद 133
   (C) अनुच्छेद 134
   (D) अनुच्छेद 136

8. आपराधिक मामलों में, उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना भी उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, यदि उच्च न्यायालय ने:
   (A) अधीनस्थ न्यायालय के दंडादेश के विरुद्ध अपील पर अभियुक्त व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया हो
   (B) विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दिए गए मृत्युदंड की पुष्टि की हो
   (C) दोषमुक्ति के आदेश को उलट दिया हो और अभियुक्त को मृत्युदंड दिया हो
   (D) अपील पर दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हो

9. अनुच्छेद 143 के तहत, भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्शदायी राय मांग सकते हैं। इस क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
   (A) उच्चतम न्यायालय अपने पास संदर्भित सभी मामलों पर अपनी सलाह देने के लिए बाध्य है।
   (B) भारत के राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा दी गई राय को मानने के लिए पूर्णतः बाध्य हैं।
   (C) अनुच्छेद 143 के तहत दी गई परामर्शदायी राय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी कानून बनती है।
   (D) उच्चतम न्यायालय सार्वजनिक महत्व के संदर्भों पर अपनी राय देने से इनकार कर सकता है।

10. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।

Downloaded from www.pdf.tube

की आवश्यकता होती है, जबकि न्यायिक अतिसक्रियता आमतौर पर एकल न्यायाधीश द्वारा की जाती है।

29. जनहित याचिका के अत्यधिक उपयोग पर प्रायः की जाने वाली मुख्य आलोचना निम्नलिखित में से कौन-सी है?
(A) कार्यपालिका के लिए आरक्षित नीतिगत निर्णयों में न्यायिक हस्तक्षेप।
(B) यह देश भर की अधीनस्थ अदालतों के समग्र प्रशासनिक कार्यभार को अत्यधिक और अनावश्यक रूप से कम करता है।
(C) यह मौलिक अधिकारों के प्राथमिक प्रवर्तन से संस्थागत ध्यान को हटाता है।
(D) यह गरीब और अशिक्षित नागरिकों के लिए न्याय तक लोकतांत्रिक पहुँच को गंभीर रूप से सीमित करता है।

30. जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालयों में किस अनुच्छेद के तहत दायर की जा सकती है?
(A) अनुच्छेद 136
(B) अनुच्छेद 227
(C) अनुच्छेद 226
(D) अनुच्छेद 141

31. उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार की तुलना उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से करने पर, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(A) उच्चतम न्यायालय किसी भी कानूनी उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय विशेष रूप से मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए रिट जारी कर सकते हैं।
(B) संवैधानिक रिट जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का सभी राज्यों में समान क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है।
(C) संविधान के तहत उच्चतम न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार पूरी तरह से विवेकाधीन है, जो उच्च न्यायालयों के अनिवार्य रिट क्षेत्राधिकार से भिन्न है।
(D) उच्च न्यायालय मौलिक और कानूनी दोनों अधिकारों के लिए रिट जारी करते हैं; उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करता है।

32. भारतीय न्यायिक प्रणाली में ई-कोर्ट परियोजना शुरू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) सभी न्यायिक मुकदमों के लिए मौजूदा भौतिक अदालत भवनों को पूरी तरह से आभासी (वर्चुअल) अदालतों से बदलना।
(B) स्वचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों को छोटे अपराधों में अंतिम निर्णय देने की अनुमति देना।
(C) डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्यायिक दक्षता और पहुँच को बढ़ाना।
(D) सभी लंबित आपराधिक मुकदमों में स्थापित वैधानिक प्रक्रियात्मक संहिताओं को पूरी तरह से दरकिनार करना।

33. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड एक पहल है जिसका उद्देश्य है:
(A) सभी न्यायिक अधिकारियों के राष्ट्रीय पेंशन और भविष्य निधि का प्रबंधन और लेखा परीक्षा करना।
(B) लंबित और निपटाए गए मामलों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना।
(C) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की दैनिक प्रशासनिक गतिविधियों और आधिकारिक यात्राओं पर नज़र रखना।
(D) स्वतंत्रता से पूर्व के सभी ऐतिहासिक कानूनी दस्तावेजों और औपनिवेशिक सुनवाई अभिलेखागार का डिजिटलीकरण करना।

34. मामलों की लंबितता को दूर करने के उच्चतम न्यायालय के प्रयास के संदर्भ में, "लोक अदालत" क्या है?
(A) जटिल कानूनी प्रश्नों की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित एक विशेष संवैधानिक पीठ।
(B) निर्वाचित प्रतिनिधियों और भ्रष्ट राजनेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष रूप से नामित एक त्वरित आपराधिक अदालत।
(C) पुराने औपनिवेशिक कानूनों की समीक्षा करने वाले वरिष्ठ वकीलों की एक वैधानिक सलाहकार समिति।
(D) लंबित या पूर्व-मुकदमेबाज़ी विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक वैकल्पिक मंच।

NODIA

35. राजस्थान की एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका से उत्पन्न कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ किस ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने दिशानिर्देश निर्धारित किए?
(A) विशाखा बनाम राजस्थान राज्य
(B) शाह बानो मामला
(C) निर्भया मामला
(D) रूपन देयोल बजाज बनाम के. पी. एस. गिल मामला

36. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को रद्द कर दिया।
कारण (R): न्यायालय ने माना कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता किया, जो संविधान का मूल ढांचा है।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

37. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को भारत के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील के लिए विशेष अनुमति याचिका स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करता है?
(A) अनुच्छेद 136

(D) न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप

112. उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के संबंध में बेमेल की पहचान कीजिए:
(A) भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच विवाद
(B) दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद
(C) संसद सदस्य के चुनाव से संबंधित विवाद
(D) केंद्र सरकार और कई राज्यों के बीच विवाद

113. न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत, निम्नलिखित में से कौन-सा कृत्य अवमानना नहीं है?
(A) किसी संवैधानिक न्यायालय के अधिकार को नीचा दिखाना या कम करना
(B) लंबित कार्यवाहियों की जानकारी के बिना निर्दोष प्रकाशन
(C) न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश या आदेश की जानबूझकर की गई अवज्ञा
(D) किसी न्यायिक कार्यवाही के उचित क्रम में प्रतिकूल प्रभाव डालना या हस्तक्षेप करना

114. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): उच्चतम न्यायालय निचली अदालत को उत्प्रेषण की रिट जारी कर सकता है।
कारण (R): उत्प्रेषण की रिट किसी अधीनस्थ न्यायालय, न्यायाधिकरण या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी द्वारा पहले से पारित आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

115. प्रतिषेध की रिट किसके विरुद्ध उपलब्ध है?
(A) न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी
(B) विधायी निकाय
(C) निजी व्यक्ति
(D) विशुद्ध रूप से प्रशासनिक रूप से कार्य करने वाले प्रशासनिक प्राधिकारी

116. भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को भारत में जनहित याचिका न्यायशास्त्र की नींव रखने के लिए न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के साथ व्यापक रूप से जाना जाता है?
(A) न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन
(B) न्यायमूर्ति ए. एस. आनंद
(C) न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती
(D) न्यायमूर्ति वाई. के. सब्रवाल

117. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा में 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
II. सदस्यों की आवश्यक संख्या द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद सदन का पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य है।
III. आवश्यक विशेष बहुमत उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई का बहुमत है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

118. ऐतिहासिक 'श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ' मामले में, उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को रद्द कर दिया। यह मामला किसका एक प्रमुख उदाहरण है:
(A) अनुच्छेद 131 के तहत प्रयोग किया गया मूल संघीय क्षेत्राधिकार
(B) दीवानी विवाद के मामलों में सामान्य अपीलीय क्षेत्राधिकार
(C) राष्ट्रपति के संदर्भ पर प्रयोग किया गया परामर्शदायी क्षेत्राधिकार
(D) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाली न्यायिक समीक्षा

119. पारंपरिक विरोधी मुकदमे की तुलना में जनहित याचिका की एक परिभाषित विशेषता यह है:
(A) इसके लिए याचिकाकर्ता का परिणाम में प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कानूनी हित होना आवश्यक है।
(B) यह गैर-विरोधी और जन कल्याण के लिए सहयोगात्मक है।
(C) इसे केवल पारंपरिक निजी कानून सिद्धांतों का उपयोग करके ही लड़ा और तय किया जा सकता है।
(D) यह अदालत को स्वतंत्र तथ्य-अन्वेषण आयोगों को नियुक्त करने से पूरी तरह से रोकता है।

120. गोलकनाथ मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनाए गए 'भविष्यलक्षीय निर्णय का सिद्धांत' का वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है?
(A) एक रद्द किया गया कानून अतीत के साथ-साथ भविष्य के सभी लेन-देन के लिए पूरी तरह से वैध और प्रभावी रहता है।
(B) अदालत केवल भविष्य के विवादों के लिए कानून बना सकती है और अतीत के अधिनियमों की व्याख्या करने से रोक दी गई है।
(C) नया कानूनी नियम केवल भविष्य के मामलों पर लागू होता है, जिससे पिछले निर्णय बरकरार रहते हैं।

Click Here to Buy book on Flipkart

सूची II: प्रावधान
1. उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
2. उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
3. उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा
4. उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना

(A) P-2, Q-4, R-3, S-1
(B) P-2, Q-3, R-4, S-1
(C) P-1, Q-4, R-3, S-2
(D) P-4, Q-2, R-1, S-3

47. निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ "हम आदेश देते हैं" है?
(A) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(B) प्रतिषेध
(C) उत्प्रेषण
(D) परमादेश

48. निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध परमादेश की रिट जारी नहीं की जा सकती है?
(A) वैधानिक कर्तव्य का पालन करने में विफल रहने वाला सार्वजनिक अधिकारी
(B) अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण
(C) भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल
(D) एक स्थानीय नगरपालिका

49. किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार में त्वरित सुनवाई का अधिकार शामिल है, जिससे विचाराधीन बंदियों के संबंध में जनहित याचिकाओं की शुरुआती नींव रखी गई?
(A) ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामला
(B) हुसैनआरा खातून बनाम बिहार राज्य मामला
(C) एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (ओलियम गैस लीक मामला)
(D) सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन मामला

50. भारतीय उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में "पत्रात्मक क्षेत्राधिकार" की अवधारणा का तात्पर्य है:
(A) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवादों का निर्णय करने की अनन्य शक्ति।
(B) द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय संधियों की व्याख्या करने का संवैधानिक क्षेत्राधिकार।
(C) वाणिज्यिक विवादों को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की अंतर्निहित न्यायिक शक्ति।
(D) न्यायालय को लिखे गए पत्रों या पोस्टकार्डों को औपचारिक रिट याचिका के रूप में स्वीकार करना।

51. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाले 'कॉलेजियम' में भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं?
(A) चार
(B) दो
(C) तीन
(D) पांच

52. उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. संसद उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों में कटौती नहीं कर सकती है।
II. उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक खर्चों पर संसद द्वारा प्रतिवर्ष मतदान किया जाता है।
III. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
IV. सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध भावी हितों के टकराव को रोकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

53. सिविल कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में होती है यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करता है कि मामले में व्यापक महत्व का कानून का सारवान प्रश्न शामिल है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद द्वारा शासित है?
(A) अनुच्छेद 133
(B) अनुच्छेद 132
(C) अनुच्छेद 134
(D) अनुच्छेद 135

54. निम्नलिखित में से किसे भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का वैध आधार नहीं माना जाता है?
(A) सिद्ध कदाचार
(B) असमर्थता
(C) केंद्र सरकार के खिलाफ फैसला सुनाना
(D) A और B दोनों ही केवल वैध आधार हैं

55. अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति अनुच्छेद 137 में निहित है। इस समीक्षा की सुनवाई आमतौर पर की जाती है:
(A) निजी कक्ष में अकेले बैठे एक एकल न्यायाधीश द्वारा
(B) निर्णय सुनाने वाली पीठ द्वारा
(C) न्यायिक सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा
(D) नौ न्यायाधीशों की एक पूर्ण संवैधानिक पीठ द्वारा

56. उच्चतम न्यायालय की प्रक्रियाओं के संदर्भ में "क्यूरेटिव पिटीशन" (उपचारात्मक/रोगहर्त्ता याचिका) क्या है?
(A) अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों में लिपिकीय और

Downloaded from www.pdf.tube

(A) इसका सिविल, आपराधिक और संवैधानिक अपीलों को कवर करने वाला एक व्यापक क्षेत्राधिकार है।
(B) भारतीय उच्चतम न्यायालय को अपने अतीत के निर्णयों की समीक्षा करने या बदलने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है।
(C) भारतीय उच्चतम न्यायालय में संघीय इकाइयों के बीच विवादों में मूल क्षेत्राधिकार का अभाव है।
(D) भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सीधे आम जनता द्वारा चुने जाते हैं।

75. उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है यदि उन्होंने उच्च न्यायालय में कम से कम कितने समय तक सेवा की हो:
(A) 3 वर्ष
(B) 5 वर्ष
(C) 7 वर्ष
(D) 10 वर्ष

76. किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रसिद्ध रूप से टिप्पणी की थी कि "मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व संविधान के रथ के दो पहिये हैं"?
(A) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
(B) मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
(C) शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ
(D) सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य

77. नवतेज सिंह जोहर मामले (2018) में उच्चतम न्यायालय के आदेश को एक ऐतिहासिक फैसला माना जाता है क्योंकि:
(A) इसने धारा 377 के तहत सहमति से समलैंगिक कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया।
(B) इसने राष्ट्रीय आधार योजना की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से बरकरार रखा।
(C) इसने ट्रिपल तलाक की तत्काल धार्मिक प्रथा को असंवैधानिक रूप से समाप्त कर दिया।
(D) इसने सबरीमाला मंदिर परिसर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी।

78. भारत में ई-कोर्ट परियोजना चरण II के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसमें जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का संगणकीकरण (कंप्यूटरकरण) शामिल है।
II. इसमें यातायात चालान के लिए आभासी अदालत की शुरुआत शामिल है।
III. यह सभी आपराधिक मुकदमों के लिए भौतिक सुनवाई को पूरी तरह से ऑनलाइन सुनवाई से बदल देता है।
IV. यह ई-कोर्ट वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन केस स्थिति और फैसले प्रदान करता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और IV
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I और IV
(D) I, II, III और IV

79. उच्चतम न्यायालय के नियमों के तहत, पर्यावरण के मुद्दों से संबंधित जनहित याचिका आमतौर पर किसके समक्ष रखी जाती है?
(A) एकल-न्यायाधीश कक्ष
(B) राष्ट्रपति सचिवालय
(C) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
(D) एक विशेष हरित पीठ

80. 99वें संविधान संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने कितने बहुमत से रद्द कर दिया था?
(A) 3:2
(B) 4:1
(C) 5:0
(D) उन्हें एकल न्यायाधीश द्वारा रद्द कर दिया गया था।

81. किस उच्चतम न्यायालय के फैसले को आमतौर पर 'मंडल आयोग मामला' कहा जाता है जिसने आरक्षण पर 50% की सीमा तय की थी?
(A) एम. नागराज बनाम भारत संघ
(B) इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ
(C) अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ
(D) मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराइराजन

82. न्यायिक निर्णयों के माध्यम से कॉलेजियम प्रणाली के विकास का सही क्रमिक क्रम चुनिए:
(A) एस. पी. गुप्ता मामला → सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन मामला → इन री स्पेशल रेफरेंस 1 ऑफ 1998
(B) सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन मामला → एस. पी. गुप्ता मामला → इन री स्पेशल रेफरेंस 1 ऑफ 1998
(C) इन री स्पेशल रेफरेंस 1 ऑफ 1998 → एस. पी. गुप्ता मामला → सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन मामला
(D) एस. पी. गुप्ता मामला → इन री स्पेशल रेफरेंस 1 ऑफ 1998 → सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन मामला

83. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन:
(A) भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और अमतदेय होते हैं
(B) बजट में हर साल संसद द्वारा इस पर मतदान किया जाता है
(C) भारत की आकस्मिकता निधि पर भारित होते हैं
(D) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिए जाते हैं जहां उन्होंने पहले सेवा की थी

NODIA

अवमानना की श्रेणी में नहीं आती है।

65. उच्चतम न्यायालय के परामर्शदायी क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राष्ट्रपति कानून के किसी प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के तथ्य के प्रश्न को न्यायालय के पास भेज सकते हैं।
II. अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय की राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है।
III. राष्ट्रपति संविधान-पूर्व संधियों से उत्पन्न विवादों को परामर्शदायी राय के लिए उच्चतम न्यायालय में भेज सकते हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

66. संविधान के तहत, उच्चतम न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसमें निहित है?
(A) वैधानिक अधिनियमों के माध्यम से भारत की संसद में
(B) कार्यपालक सलाह पर कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति में
(C) स्वतंत्र रूप से केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय में
(D) राष्ट्रपति की स्वीकृति से उच्चतम न्यायालय में

67. अधिकार-पृच्छा की रिट जारी की जा सकती है:
(A) सार्वजनिक पद के दावे की वैधानिकता की जांच करने के लिए
(B) किसी गैर-निष्पादित सार्वजनिक प्राधिकारी को उसके अनिवार्य वैधानिक कर्तव्य को पूरा करने का निर्देश देने के लिए
(C) अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण को उसके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकने के लिए
(D) अवैध हिरासत के तहत रखे गए व्यक्ति की तत्काल रिहाई सुनिश्चित करने के लिए

68. 'तृतीय न्यायाधीश मामले' (1998 का विशेष संदर्भ 1) में बहस का मुख्य कानूनी मुद्दा क्या था?
(A) कॉलेजियम प्रणाली का पूर्ण संवैधानिक उन्मूलन और प्रतिस्थापन
(B) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का संरचनात्मक परिचय
(C) परामर्श का दायरा और कॉलेजियम की संरचना
(D) सेवारत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाना

69. 'मूल ढांचा' सिद्धांत का तात्पर्य है कि:
(A) संसद अनुच्छेद 368 के माध्यम से मूल विशेषताओं को नहीं बदल सकती है।
(B) भारत के राष्ट्रपति के पास किसी भी संविधान संशोधन विधेयक पर पूर्ण वीटो पावर होती है।
(C) उच्चतम न्यायालय के पास संविधान के किसी भी हिस्से को फिर से लिखने की एकतरफा शक्ति है।
(D) नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।

70. भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर कितनी बार सफलतापूर्वक महाभियोग चलाया गया है और पद से हटाया गया है?
(A) एक बार
(B) दो बार
(C) तीन बार
(D) कभी नहीं

71. निम्नलिखित में से कौन-सी समिति/आयोग ऐतिहासिक रूप से भारत में न्यायिक सुधारों की सिफारिशों और मामलों की लंबितता से निपटने से जुड़ा है?
(A) कोठारी आयोग
(B) मलिमथ समिति
(C) सरकारिया आयोग
(D) मंडल आयोग

72. सूची I में दी गई रिटों को सूची II में दिए गए उनके शाब्दिक अर्थों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: रिट
P. बंदी प्रत्यक्षीकरण
Q. उत्प्रेषण
R. अधिकार-पृच्छा
S. परमादेश
सूची II: शाब्दिक अर्थ
1. प्रमाणित होना
2. किस प्राधिकार से
3. हम आदेश देते हैं
4. सशरीर प्रस्तुत करना
(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-4, Q-2, R-1, S-3
(C) P-3, Q-1, R-2, S-4
(D) P-1, Q-4, R-3, S-2

73. निम्नलिखित में से कौन-सा उच्चतम न्यायालय का एक प्रमुख मामला है जिसने निजता के अधिकार के संबंध में मौलिक अधिकारों के न्यायशास्त्र को आकार दिया?
(A) ए. डी. एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामला
(B) श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामला
(C) इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला
(D) के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामला

74. कौन-सी प्रमुख विशेषता भारत के उच्चतम न्यायालय को हाउस ऑफ लॉर्ड्स (ब्रिटेन में पूर्व सर्वोच्च न्यायालय) या अमेरिकी उच्चतम न्यायालय से अलग करती है?

Click Here to Buy book on Amazon

(B) अनुच्छेद 132
(C) अनुच्छेद 142
(D) अनुच्छेद 134

38. "पूर्ण न्याय" का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने की अनुमति देता है। कौन-सा अनुच्छेद यह शक्ति प्रदान करता है?
(A) अनुच्छेद 141
(B) अनुच्छेद 143
(C) अनुच्छेद 144
(D) अनुच्छेद 142

39. उच्चतम न्यायालय में तदर्थ (Ad-hoc) न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. सत्र आयोजित करने या जारी रखने के लिए गणपूर्ति (कोरम) की कमी होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन्हें नियुक्त किया जा सकता है।
II. उनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है।
III. किसी भी प्रख्यात विधिवेत्ता को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

40. उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को किसी भी समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए कौन नियुक्त कर सकता है?
(A) न्यायपालिका से परामर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति
(B) विशेष बहुमत द्वारा पारित एक संयुक्त प्रस्ताव के माध्यम से भारत की संसद
(C) राष्ट्रपति की सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश
(D) भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल

41. भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में, 'संविधान पीठ' क्या है?
(A) भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी सेवारत न्यायाधीशों की एक पूर्ण पीठ।
(B) विशेष रूप से कार्यपालक आदेशों और वैधानिक नियमों से निपटने वाली एक विशेष पीठ।
(C) आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक संयुक्त न्यायिक पीठ।
(D) संवैधानिक व्याख्या के मुद्दों का फैसला करने वाली पाँच या अधिक न्यायाधीशों की पीठ।

42. निम्नलिखित में से कौन-सा विषय उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है?
(A) सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा अपील
(B) कानून का सारवान प्रश्न शामिल होने वाले सिविल मामलों में अपील
(C) आपराधिक मामलों में अपील जहाँ उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड दिया है
(D) मूल रूप से सीधे उच्चतम न्यायालय में दायर अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद

43. भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों को उनकी नियुक्ति के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. एन. वी. रमणा
II. रंजन गोगोई
III. एस. ए. बोबडे
IV. डी. वाई. चंद्रचूड़
(A) II, III, I, IV
(B) I, II, III, IV
(C) III, II, I, IV
(D) II, I, III, IV

NODIA

44. क्या होता है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति या अन्य कारणों से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं?
(A) भारत के कानून मंत्री अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश के सभी प्रशासनिक कार्यों को संभालते हैं।
(B) राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।
(C) वरिष्ठतम न्यायाधीश तुरंत नए स्थायी मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्वतः शपथ लेता है।
(D) मुख्य न्यायाधीश के लौटने तक उच्चतम न्यायालय सभी न्यायिक कार्यों को निलंबित कर देता है।

45. भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुमति देती है:
(A) विधायी अधिनियमों और कार्यपालक आदेशों को असंवैधानिक घोषित करने की।
(B) लागू करने से पहले मंत्रिमंडल द्वारा तैयार की गई सामाजिक नीतियों की समीक्षा करने और सीधे वीटो करने की।
(C) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों की समीक्षा करने और उन्हें रद्द करने की।
(D) राज्य सरकारों के दैनिक प्रशासनिक कार्यों का निर्देशन और पर्यवेक्षण करने की।

46. सूची I में दिए गए संविधान के अनुच्छेदों को सूची II में दिए गए उनके संबंधित प्रावधानों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: संविधान के अनुच्छेद
P. अनुच्छेद 124
Q. अनुच्छेद 129
R. अनुच्छेद 137
S. अनुच्छेद 143

84. निम्नलिखित में से कौन-सी शक्ति उच्चतम न्यायालय को एक उच्च न्यायालय में लंबित मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अनुमति देती है?
(A) मूल संवैधानिक क्षेत्राधिकार
(B) अपीलीय क्षेत्राधिकार
(C) अनुच्छेद 139A के तहत शक्ति
(D) अपील के लिए विशेष अनुमति क्षेत्राधिकार

85. उच्चतम न्यायालय में उन सभी मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है जिनमें भारत सरकार का संबंध होता है?
(A) भारत के महान्यायावादी
(B) केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री
(C) कैबिनेट सचिव
(D) मुख्य चुनाव आयुक्त

86. निम्नलिखित में से किसे इसके आलोचकों द्वारा महज न्यायिक सक्रियता के बजाय 'न्यायिक अतिसक्रियता' का उदाहरण माना जाता है?
(A) अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन' की मौलिक परिभाषा का व्यापक विस्तार करना।
(B) शहरी वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन में सीएनजी ईंधन के अनन्य उपयोग को अनिवार्य बनाना।
(C) गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले असंवैधानिक वैधानिक कानूनों को रद्द करना।
(D) राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध का निर्देश देना और दूरी की सीमा तय करना।

87. किस अनुच्छेद के तहत संविधान स्पष्ट रुप से कहता है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकारी, सिविल और न्यायिक, उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे?
(A) अनुच्छेद 141
(B) अनुच्छेद 144
(C) अनुच्छेद 142
(D) अनुच्छेद 143

88. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): जनहित याचिका के कारण उच्चतम न्यायालय में मामलों की लंबितता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
कारण (R): जनहित याचिका लगभग किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक कारणों के लिए अदालत तक पहुंचने की अनुमति देती है, जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी तुच्छ और तंग करने वाली याचिकाएं दायर होती हैं।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

89. एक प्रख्यात विधिवेत्ता को सीधे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रावधान के तहत आज तक उच्चतम न्यायालय में कितने प्रख्यात विधिवेत्ताओं को नियुक्त किया गया है?
(A) शून्य
(B) एक
(C) तीन
(D) पांच

90. भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से गहराई से प्रभावित है?
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका
(B) यूनाइटेड किंगडम
(C) कनाडा
(D) आयरलैंड

91. बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह सार्वजनिक प्राधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है।
II. यह अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
III. यदि निरोध विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वैध है तो इसे जारी नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

92. समवर्ती सूची के किसी विषय के संबंध में केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच टकराव की स्थिति में, उच्चतम न्यायालय द्वारा समर्थित सामान्य रुख क्या है?
(A) राज्य कानून सभी परिस्थितियों में केंद्रीय वैधानिक कानून को सार्वभौमिक रूप से ओवरराइड करता है।
(B) केंद्रीय कानून तब तक लागू रहता है जब तक कि राज्य के कानून को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न हुई हो।
(C) उच्चतम न्यायालय तुरंत और स्वतः दोनों कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर देता है।
(D) क्षेत्राधिकार विवाद को बाध्यकारी मध्यस्थता के लिए सीधे अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों को संदर्भित किया जाता है।

93. संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का सारवान प्रश्न शामिल होने वाले मामले का फैसला करने के लिए संविधान पीठ बनाने के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी है?
(A) तीन
(B) पांच
(C) सात
(D) नौ

Downloaded from www.pdf.tube

प्रारूपण त्रुटियों को सुधारने के लिए दायर की गई एक वैधानिक याचिका।
(B) नैदानिक लापरवाही से सुरक्षा की मांग करने वाले डॉक्टरों द्वारा दायर एक विशेष याचिका।
(C) न्याय की विफलता को रोकने के लिए पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद का एक अंतिम कानूनी उपाय।
(D) एक असाधारण याचिका जो कार्यपालिका को न्यायिक आदेशों को पलटने की अनुमति देती है।

57. उच्चतम न्यायालय के किस ऐतिहासिक फैसले ने "क्यूरेटिव पिटीशन" (उपचारात्मक याचिका) की अवधारणा प्रस्तुत की?
(A) मेनका गांधी बनाम भारत संघ
(B) एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ
(C) टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य
(D) रुपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा

58. पारंपरिक मुकदमेबाजी में 'लोकस स्टैंडाई' के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका के लिए इसमें कैसे संशोधन किया?
(A) इसने जन-भावना वाले नागरिकों को अदालत तक पहुँचने में असमर्थ वंचित लोगों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी।
(B) अदालत ने घोषणा की कि किसी भी सामान्य दीवानी मुकदमे को दायर करने के लिए अब लोकस स्टैंडाई के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है।
(C) अदालत ने फैसला सुनाया कि केवल भारत के महान्यायावादी ही नागरिकों के लिए प्रतिनिधि जनहित के मामले दायर कर सकते हैं।
(D) अदालत ने याचिकाकर्ताओं के लिए कोई भी जनहित याचिका दायर करने से पहले भारी जमानत राशि जमा करना अनिवार्य कर दिया।

59. उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के मामलों पर आमतौर पर जनहित याचिका के रूप में विचार नहीं किया जाता है?
(A) बंधुआ मजदूरी के मामले
(B) भवन स्वामी और किरायेदार विवाद
(C) उपेक्षित बच्चे
(D) दंगा पीड़ितों की याचिकाएं

60. उच्चतम न्यायालय ने किस प्रसिद्ध मामले में खतरनाक या अंतर्निहित जोखिम वाले उद्योगों में लगे उद्यमों के लिए "पूर्ण दायित्व" का सिद्धांत स्थापित किया?
(A) भोपाल गैस त्रासदी मामला
(B) एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (ओलियम गैस लीक मामला)
(C) वेल्लोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ
(D) रुरल लिटिगेशन एंड एंटाइटेलमेंट केंद्र बनाम यू. पी. राज्य

61. संघवाद के संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय ने दृढ़तापूर्वक कहा कि संघवाद संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है और राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लगाने के लिए सख्त दिशानिर्देश निर्धारित किए?
(A) एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ
(B) एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ
(C) आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य
(D) राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ

62. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): भारत का उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है।
कारण (R): संविधान किसी भी विशेष न्यायाधिकरण या अर्ध-न्यायिक निकायों को उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से बाहर काम करने से सख्ती से रोकता है।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

63. 'न्यायिक सक्रियता' और 'न्यायिक संयम' के बीच मौलिक अंतर क्या है?
(A) सक्रियता अदालतों को स्थापित कानूनी मिसालों का सख्ती से पालन करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि संयम पूरी तरह से नई सार्वजनिक नीतियां बनाने को प्रोत्साहित करता है।
(B) सक्रियता जनहित याचिकाओं को अत्यधिक सीमित करती है, जबकि संयम जनहित याचिकाओं को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित और बढ़ावा देता है।
(C) सक्रियता का अर्थ है कि न्यायाधीश मुकदमों के दौरान राज्य के अभियोजक के रूप में कार्य करते हैं, जबकि संयम का अर्थ है कि वे विशेष रूप से बचाव पक्ष के वकील के रूप में कार्य करते हैं।
(D) सक्रियता का अर्थ है एक अग्रसक्रिय भूमिका निभाना, जबकि संयम निर्वाचित शाखाओं के प्रति आदर व्यक्त करने की वकालत करता है।

64. उच्चतम न्यायालय की अवमानना शक्ति के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए:
(A) सिविल अवमानना का अर्थ न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश या आदेश की जानबूझकर की गई अवज्ञा है।
(B) आपराधिक अवमानना में किसी भी ऐसे मामले का प्रकाशन शामिल है जो किसी न्यायालय की गरिमा को गिराता है या उसकी अवमानना करता है।
(C) उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों की अवमानना के लिए व्यक्तियों को दंडित नहीं कर सकता है।
(D) न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग

NODIA

(A) मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय में मूल क्षेत्राधिकार का पूरी तरह से अभाव है।
(B) उच्च न्यायालय रिट याचिका दायर करने के लिए काफी कम वैधानिक न्यायालय शुल्क लेते हैं।
(C) अनुच्छेद 32 में संशोधन किया गया है और अब इसे मौलिक अधिकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।
(D) अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 से व्यापक है।

103. किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसमें मूल ढांचा सिद्धांत के अधीन संशोधन किया जा सकता है?
(A) बेरुबारी यूनियन रेफरेंस मामला
(B) केशवानंद भारती मामला
(C) एल. आई. सी. ऑफ इंडिया मामला
(D) ए. के. गोपालन मामला

104. भारत के मुख्य न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. मुख्य न्यायाधीश 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' हैं और उनके पास विभिन्न पीठों को मामले आवंटित करने का विशेषाधिकार है।
II. मास्टर ऑफ द रोस्टर के रूप में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को उच्चतम न्यायालय में कभी चुनौती नहीं दी गई है।
III. मुख्य न्यायाधीश सीबीआई निदेशक की चयन समिति का हिस्सा हैं।
IV. मुख्य न्यायाधीश संसदीय मंजूरी के बिना एकतरफा संविधान में संशोधन कर सकते हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और III
(B) केवल I, II और III
(C) केवल II और IV
(D) केवल I, III और IV

105. उच्चतम न्यायालय का कौन-सा अनुच्छेद उसे "पूर्ण न्याय" करने के लिए मामला उठाने की अनुमति देता है, भले ही कोई विशिष्ट कानून सटीक स्थिति को कवर न करता हो?
(A) अनुच्छेद 143 के तहत परामर्शदायी शक्तियां
(B) अनुच्छेद 132 के तहत अपीलीय शक्तियां
(C) अनुच्छेद 32 के तहत रिट शक्तियां
(D) अनुच्छेद 142 के तहत अंतर्निहित शक्तियां

106. उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की सामान्य समय-सीमा क्या है?
(A) 30 दिन
(B) 60 दिन
(C) 90 दिन
(D) 120 दिन

107. "प्रक्रियात्मक सम्यक प्रक्रिया" की अवधारणा अमेरिकी है, जबकि भारतीय संविधान ने मूल रूप से "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" को अपनाया था। किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनिवार्य रूप से उनका सम्मिश्रण किया, जिसके लिए प्रक्रिया का "न्यायसंगत, निष्पक्ष और तर्कसंगत" होना आवश्यक हो गया?
(A) रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य
(B) मेनका गांधी बनाम भारत संघ
(C) बॉम्बे राज्य बनाम एफ. एन. बलसारा
(D) पी. ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य

108. यह प्रावधान कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को विशेष बहुमत द्वारा समर्थित संसद के प्रत्येक सदन द्वारा संबोधन के बाद पारित राष्ट्रपति के आदेश के अलावा पद से नहीं हटाया जा सकता है, सुनिश्चित करता है:
(A) न्यायिक सर्वोच्चता
(B) न्यायिक स्वतंत्रता
(C) न्यायिक सक्रियता
(D) कार्यपालिका के प्रति न्यायिक जवाबदेही

109. संपत्ति के अधिकार और मूल ढांचे से संबंधित निम्नलिखित ऐतिहासिक निर्णयों को उनके सुनाए जाने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. आई. सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
II. शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ
III. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
IV. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
(A) II, I, IV, III
(B) I, II, III, IV
(C) II, IV, I, III
(D) I, III, II, IV

110. आपराधिक मामलों के स्थानांतरण के संबंध में कौन-सा कथन उच्चतम न्यायालय की शक्ति का सटीक वर्णन करता है?
(A) उच्चतम न्यायालय को राज्य की सीमाओं के पार आपराधिक मुकदमों को स्थानांतरित करने से संवैधानिक रूप से रोक दिया गया है।
(B) केवल भारत के राष्ट्रपति ही चल रहे आपराधिक मामले के प्रशासनिक स्थानांतरण का आदेश दे सकते हैं।
(C) निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय राज्यों के बीच आपराधिक मामलों को स्थानांतरित कर सकता है।
(D) आपराधिक मामले के स्थानांतरण के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पूर्व सहमति अनिवार्य है।

111. वह केंद्रीय विवाद क्या था जिसके कारण कॉलेजियम प्रणाली का निर्माण हुआ?
(A) न्यायाधीशों के कम वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित विवाद
(B) ई-कोर्ट परियोजना की शुरुआत
(C) अधीनस्थ न्यायालयों के पदों को भरने में देरी

Click Here to Buy book on Flipkart

94. ए. डी. एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976) मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले, जिसे अक्सर 'बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला' कहा जाता है, ने फैसला सुनाया कि:
(A) अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक मानव अधिकारों को किसी भी राष्ट्रीय परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है।
(B) राष्ट्रपति के पास उच्चतम न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना आपातकाल घोषित करने की कोई संवैधानिक शक्ति नहीं है।
(C) आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 के प्रवर्तन के लिए अदालत जाने के अधिकार का निलंबन।
(D) आपातकाल के दौरान निवारक निरोध से संबंधित सभी कार्यपालक आदेश पूरी तरह से असंवैधानिक हैं।

95. ए. डी. एम. जबलपुर मामले में फैसले के बाद, किस संविधान संशोधन ने बाद में अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित होने से बचाया?
(A) 42वाँ संशोधन अधिनियम
(B) 46वाँ संशोधन अधिनियम
(C) 52वाँ संशोधन अधिनियम
(D) 44वाँ संशोधन अधिनियम

96. उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के संदर्भ में 'स्वतः संज्ञान' शब्द का क्या अर्थ है?
(A) अधीनस्थ न्यायालयों को जटिल संवैधानिक मामले सौंपने की विवेकाधीन शक्ति
(B) अपने पिछले निर्णयों की समीक्षा करने के लिए अदालत को दी गई संवैधानिक शक्ति
(C) बिना किसी याचिका के अदालत द्वारा अपनी पहल पर की गई कार्रवाई
(D) राज्य या केंद्र सरकार द्वारा सीधे दायर की गई एक औपचारिक रिट याचिका

97. जनहित याचिका में उच्चतम न्यायालय द्वारा विकसित 'सतत परमादेश' की अवधारणा का उपयोग किसके लिए किया जाता है?
(A) न्यायिक कार्यवाही को तुरंत बंद करने वाला एक एकल व्यापक अंतिम आदेश जारी करने के लिए।
(B) समय के साथ मामले को खुला रखकर कार्यपालक अनुपालन की निगरानी करने के लिए।
(C) किसी व्यक्ति पर तब तक लगातार अवमानना दंड लगाने के लिए जब तक कि वह खुली अदालत में औपचारिक रूप से माफी न मांग ले।
(D) अधीनस्थ न्यायालयों को सभी समान लंबित मामलों की सुनवाई स्थायी रूप से रोकने का आदेश देने के लिए।

98. सूची I में दिए गए जनहित याचिका मामलों को सूची II में दिए गए विषय वस्तु या सिद्धांत के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: मामले
P. परमानंद कटारा बनाम भारत संघ
Q. मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य
R. डी. के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य
S. ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम
सूची II: विषय वस्तु / सिद्धांत
1. शिक्षा का अधिकार
2. आजीविका का अधिकार
3. गिरफ्तारी और निरोध के लिए दिशानिर्देश
4. तत्काल चिकित्सा सहायता का अधिकार
(A) P-4, Q-1, R-3, S-2
(B) P-1, Q-4, R-2, S-3
(C) P-4, Q-3, R-1, S-2
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

99. उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिकाओं में "अनुकरणीय जुर्माना" लगाने की प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) जनहित याचिका के नाम पर दायर की जाने वाली तुच्छ याचिकाओं को हतोत्साहित करना।
(B) केंद्र सरकार के खजाने के लिए अतिरिक्त गैर-कर राजस्व उत्पन्न करना।
(C) प्रशासनिक अदालत के कर्मचारियों के वेतन और मासिक भत्तों का भुगतान करना।
(D) आर्थिक रूप से वंचित नागरिकों के लिए सार्वजनिक कानूनी सहायता सेवाओं का वित्तपोषण करना।

NODIA

100. निम्नलिखित में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा व्याख्यायित 'शक्तियों के पृथक्करण' के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अंगों के बीच पूर्ण, कठोर और निरपेक्ष पृथक्करण।
(B) एक ऐसी व्यवस्था जहां न्यायपालिका के पास कार्यपालिका शाखा पर पूर्ण प्रशासनिक शक्ति होती है।
(C) नियंत्रण और संतुलन के साथ कार्यात्मक पृथक्करण, न कि कठोर विभाजन।
(D) एक ऐसी व्यवस्था जहां विधायिका सर्वोच्च है और इसके वैधानिक कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है।

101. विभिन्न जनहित याचिकाओं के माध्यम से स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को शामिल करने के लिए किस मौलिक अधिकार की व्यापक व्याख्या और विस्तार किया गया?
(A) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21)
(B) समता का अधिकार (अनुच्छेद 14)
(C) वाक् स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19)
(D) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

102. अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने अक्सर इस बात पर जोर दिया है कि याचिकाकर्ता को सामान्य रूप से सबसे पहले अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जाना चाहिए। इसका प्राथमिक कारण क्या है?

(D) न्यायालय किसी भी कानूनी परिस्थिति में अपने अतीत के न्यायिक पूर्ववृत्तों को नहीं उलट सकता है।

121. मामलों के भारी बकाया से निपटने के लिए, 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' मूल रूप से किस वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किए गए थे?
(A) 10वाँ वित्त आयोग
(B) 11वाँ वित्त आयोग
(C) 12वाँ वित्त आयोग
(D) 13वाँ वित्त आयोग

122. वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय में एक आंतरिक प्रशासनिक संकट के दौरान, चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनकी प्राथमिक शिकायत किससे संबंधित थी?
(A) कॉलेजियम के कामकाज और मास्टर ऑफ रोस्टर की भूमिका के मुद्दे
(B) उनके न्यायिक वेतन, भत्तों और सेवानिवृत्ति पेंशन में प्रस्तावित कटौती
(C) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ढांचे के राष्ट्रीय कार्यान्वयन में संरचनात्मक देरी
(D) उच्चतम न्यायालय के भौतिक परिसर को स्थानांतरित करने की प्रस्तावित प्रशासनिक योजनाएं

123. 'अंतर-राज्यीय जल विवादों' पर उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार:
(A) संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत पूरी तरह से अनन्य, मूल और अंतिम है।
(B) अनुच्छेद 262 के तहत अपवर्जित है, हालांकि सीमित समीक्षा शक्तियां बनी रहती हैं।
(C) नागरिकों द्वारा केवल एक औपचारिक जनहित याचिका दायर करके ही लागू किया जा सकता है।
(D) केवल नौ न्यायाधीशों की एक पूर्ण संवैधानिक पीठ द्वारा ही सुना और तय किया जा सकता है।

124. जनहित याचिकाओं और जटिल उच्चतम न्यायालय के मामलों में अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द 'एमिकस क्यूरी' का क्या अर्थ है?
(A) न्यायालय का एक आधिकारिक विरोधी या कानूनी दुश्मन
(B) कार्यवाहियों में सहायता करने वाला अदालत का मित्र (न्याय मित्र)
(C) याचिका दायर करने वाला मुख्य मूल याचिकाकर्ता
(D) मुख्य बचावकर्ता राज्य सरकार प्राधिकारी

125. उच्चतम न्यायालय ने 'निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार' को किस अनुच्छेद के तहत अंतर्निहित एक मौलिक अधिकार घोषित किया है?
(A) अनुच्छेद 21
(B) अनुच्छेद 14
(C) अनुच्छेद 19
(D) अनुच्छेद 25

126. उच्चतम न्यायालय में दायर 'पुनर्विचार याचिका' आमतौर पर फैसले या आदेश के सुनाए जाने के कितने दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए?
(A) 15 दिन
(B) 30 दिन
(C) 60 दिन
(D) 90 दिन

127. कौन-सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही दंडित किया जा सकता है, और उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी अत्यधिक सुरक्षा की जाती है?
(A) कार्योत्तर कानून
(B) स्व-अभिशंसन
(C) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(D) दोहरा दंड

NODIA

128. यदि भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ अपने पद खाली कर देते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है?
(A) भारत के प्रधानमंत्री
(B) लोकसभा अध्यक्ष
(C) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(D) किसी राज्य के वरिष्ठतम राज्यपाल

129. न्यायिक लंबितता के संदर्भ में "देर से मिला न्याय, न्याय न मिलने के बराबर है" वाक्यांश अक्सर उद्धृत किया जाता है। उच्चतम न्यायालय एक वर्ष में लगभग कितने कार्य दिवसों पर कार्य करता है?
(A) 190 से 200 दिन
(B) ठीक 250 कैलेंडर दिन
(C) ठीक 300 कार्य दिवस
(D) ठीक 365 पूरे वर्ष के दिन

130. उच्चतम न्यायालय में हाल की डिजिटलीकरण पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. प्राधिकारियों को तुरंत अदालती आदेश भेजने के लिए फास्टर (इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का तेज़ और सुरक्षित प्रेषण) शुरू किया गया था।
II. सुपेस (न्यायालय की दक्षता में सहायता के लिए उच्चतम न्यायालय पोर्टल) कानूनी शोध में न्यायाधीशों की सहायता के लिए पेश किया गया एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता टूल है।
III. पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक पीठ की कार्यवाहियों की लाइव-स्ट्रीमिंग शुरू की गई थी।
IV. साइबर सुरक्षा चिंताओं के कारण ई-फाइलिंग प्रणाली को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

के हनन पर सीधे न्यायालय जाने की व्यवस्था है। हालांकि, रिट जारी करने का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को भी मौलिक अधिकारों तथा अन्य विधिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अतः रिट क्षेत्राधिकार अनन्य नहीं है।

11. (B) प्रतिषेध
प्रतिषेध की रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण को अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी जारी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाही को रोकना होता है जब निचली अदालत बिना अधिकार क्षेत्र के काम कर रही हो। यह रिट केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है, किसी प्रशासनिक निकाय के विरुद्ध नहीं।

12. (B) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार मूल रुप से अनुच्छेद 21 में उल्लिखित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत पर निर्मित है। इसका तात्पर्य है कि न्यायालय यह जांच करता है कि क्या विधायिका द्वारा बनाया गया कानून उचित प्रक्रिया और संवैधानिक सीमाओं का पालन करके निर्मित किया गया है। यद्यपि समय के साथ न्यायिक व्याख्याओं द्वारा इसमें सम्यक प्रक्रिया के तत्वों का समावेश भी किया गया है, पर मूल ढांचा प्रक्रियात्मक ही है।

13. (A) केवल I और II
न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित किए जाते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं होता। इसके अतिरिक्त, न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा केवल महाभियोग प्रस्ताव के समय ही की जा सकती है। हालांकि, सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने से पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।

14. (C) स्वयं उच्चतम न्यायालय के निर्णयों द्वारा
उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादलों की प्रक्रिया को विनियमित करने वाली कॉलेजियम प्रणाली का निर्माण किसी संसदीय अधिनियम या संवैधानिक संशोधन द्वारा नहीं हुआ था। इस प्रणाली का विकास स्वयं उच्चतम न्यायालय के विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों, विशेष रूप से द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 और तृतीय न्यायाधीश मामले 1998 के माध्यम से हुआ था। इसका प्राथमिक उद्देश्य नियुक्तियों में कार्यपालिका के राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकना और निष्पक्षता सुनिश्चित करना था।

15. (D) द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993)
वर्ष 1993 के द्वितीय न्यायाधीश मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से फैसला सुनाते हुए कॉलेजियम प्रणाली की नींव रखी थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के तहत मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श की प्रक्रिया का वास्तविक अर्थ सहमति है। इस फैसले में यह अनिवार्य कर दिया गया कि परामर्श प्रक्रिया के तहत मुख्य न्यायाधीश और उनके दो वरिष्ठतम सहयोगियों का एक निकाय मिलकर ही न्यायाधीशों की नियुक्तियों का निर्णय लेगा।

16. (C) 99वाँ संशोधन अधिनियम
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से किया गया था। इसका उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की पुरानी कॉलेजियम प्रणाली को एक नए पारदर्शी निकाय से बदलना था जिसमें न्यायिक और कार्यपालक दोनों प्रतिनिधि शामिल हों। हालांकि, वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय ने इस संशोधन को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को पुनः बहाल कर दिया।

17. (B) सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव → जांच समिति → संसद में मतदान → राष्ट्रपति का आदेश
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पेश करने से शुरु होती है। प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की जाती है, जो आरोपों की जांच करती है। समिति द्वारा दोष सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से मतदान होता है। अंत में, संसद द्वारा पारित संबोधन के आधार पर राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं।

18. (D) इसके निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और यह अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है।
अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, जिसके दो मुख्य कानूनी निहितार्थ हैं। पहला, इसके सभी निर्णयों, कार्यवाहियों और अभिलेखों को स्थायी स्मृति और साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, जिन्हें किसी भी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा, इस न्यायालय के पास अपनी अवमानना करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को दंडित करने की अंतर्निहित संवैधानिक शक्ति प्राप्त होती है।

19. (A) नहीं, उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है और उन्हें उलट सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी निचले न्यायालयों पर अनिवार्य रुप से बाध्यकारी होता है। हालांकि, यह बाध्यता स्वयं उच्चतम न्यायालय पर लागू नहीं होती है। उच्चतम न्यायालय को अपने पूर्व में दिए गए निर्णयों की पुनरसमीक्षा करने तथा जनहित या न्याय के उद्देश्य से अपने स्वयं के पुराने निर्णयों को बदलने या पलटने की पूर्ण संवैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त है।

20. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। एस. आर. बोम्मई मामला राज्यों में राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को

Downloaded from www.pdf.tube

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) विधि द्वारा संसद
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने और उसे बढ़ाने का अधिकार भारत की संसद को प्राप्त है। संविधान के प्रारंभ में मुख्य न्यायाधीश के अलावा सात अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था। संसद समय-समय पर विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करती रही है। राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने का अधिकार नहीं है।

2. (B) 8
26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ और उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया, तब इसकी स्वीकृत कुल सदस्य संख्या 8 निर्धारित की गई थी। इसमें भारत के एक मुख्य न्यायाधीश तथा सात अन्य न्यायाधीश शामिल थे। बाद में मामलों की बढ़ती संख्या और न्यायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसद ने कानून बनाकर समय-समय पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की, जो वर्तमान में बढ़कर 34 हो चुकी है।

3. (A) उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(3) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्तियों के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख है। इसके तहत व्यक्ति का भारत का नागरिक होना, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम पाँच वर्ष तक न्यायाधीश रहना या दस वर्ष तक अधिवक्ता रहना अथवा राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता होना अनिवार्य है। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

4. (C) वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बना रहता है। संविधान में न्यायाधीशों के लिए किसी निश्चित कार्यकाल जैसे पाँच या छह वर्ष का प्रावधान नहीं है। वे राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं अथवा संसद की सिफारिश पर सिद्ध कदाचार के आधार पर पदमुक्त हो सकते हैं।

5. (A) उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है।
द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद यह व्यवस्था स्थापित की गई कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। हालांकि संविधान में वरिष्ठता का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था, लेकिन न्यायिक स्वतंत्रता और कार्यपालक हस्तक्षेप को रोकने के लिए इस परंपरा को बाध्यकारी माना गया। राष्ट्रपति केवल इस स्थापित वरिष्ठता क्रम के आधार पर ही नियुक्ति करते हैं।

6. (D) संविधान से पूर्व की किसी संधि या सनद से उत्पन्न विवाद
संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों पर मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। हालांकि, संविधान के लागू होने से पूर्व की गई किसी संधि, समझौते, सनद या अन्य समान प्रसंविदाओं से उत्पन्न होने वाले विवाद इसके दायरे से बाहर रखे गए हैं। ऐसे मामलों में राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत परामर्शदायी क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय से विधिक राय मांग सकते हैं।

7. (B) अनुच्छेद 133
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 133 सिविल मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों या आदेशों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निर्धारित करता है। यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित है और उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है, तो ऐसे सिविल विवाद की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। यह संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है।

8. (C) दोषमुक्ति के आदेश को उलट दिया हो और अभियुक्त को मृत्युदंड दिया हो
अनुच्छेद 134 के अनुसार आपराधिक मामलों में बिना उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के भी उच्चतम न्यायालय में सीधे अपील की जा सकती है। ऐसा तब होता है जब उच्च न्यायालय ने किसी अभियुक्त व्यक्ति की निचले न्यायालय द्वारा दी गई दोषमुक्ति के आदेश को उलटकर उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई हो। इस स्थिति में अपील करना अभियुक्त का संवैधानिक अधिकार बन जाता है ताकि अन्याय से बचा जा सके।

9. (D) उच्चतम न्यायालय सार्वजनिक महत्व के संदर्भों पर अपनी राय देने से इनकार कर सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी कानून या तथ्य के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। सार्वजनिक महत्व के मामलों में उच्चतम न्यायालय अपनी राय देने के लिए बाध्य नहीं है और वह राय देने से इनकार कर सकता है। इसके अलावा न्यायालय द्वारा दी गई परामर्शदायी राय केवल एक सलाह होती है, जिसे मानने के लिए राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं होते हैं।

10. (C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक और प्रत्याभूतिदाता है क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत अधिकारों

NODIA

73. (D) के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामला
के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) के ऐतिहासिक मामले में नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है, जिसने भारत में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण और मानवाधिकार न्यायशास्त्र को नया आयाम दिया।

74. (A) इसका सिविल, आपराधिक और संवैधानिक अपीलों को कवर करने वाला एक व्यापक क्षेत्राधिकार है।
भारत का उच्चतम न्यायालय अमेरिकी उच्चतम न्यायालय और ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तुलना में अधिक व्यापक क्षेत्राधिकार रखता है। अमेरिकी न्यायालय केवल संघीय और संवैधानिक मुद्दों तक सीमित है, जबकि भारतीय उच्चतम न्यायालय देश का एकीकृत सर्वोच्च न्यायालय है। इसके पास संवैधानिक व्याख्याओं के साथ-साथ सभी राज्यों के सिविल और आपराधिक मामलों की अपीलों पर निर्णय देने की पूर्ण शक्ति उपलब्ध है।

75. (B) 5 वर्ष
संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी उच्च न्यायालय में या लगातार दो या अधिक ऐसे न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। वैकल्पिक रूप से, वह किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो।

76. (B) मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) के ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व संविधान रूपी रथ के दो पहिये हैं। न्यायालय ने दोनों के बीच संतुलन और सामंजस्य को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया था और यह स्पष्ट किया था कि एक को दूसरे पर निरपेक्ष प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है।

77. (A) इसने धारा 377 के तहत सहमति से समलैंगिक कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया।
नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ (2018) मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को आंशिक रूप से रद्द कर दिया था। न्यायालय ने वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। न्यायालय ने माना कि यह प्रावधान समलैंगिक व्यक्तियों के समानता और निजता के अधिकारों का हनन करता है।

78. (A) केवल I, II और IV
ई-कोर्ट परियोजना चरण 2 के तहत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का संगणकीकरण किया गया है और यातायात चालानों के लिए आभासी अदालतें शुरु की गई हैं। यह पोर्टल मुकदमों की स्थिति और फैसलों की ऑनलाइन जानकारी भी प्रदान करता है। हालांकि, यह सभी आपराधिक मुकदमों की भौतिक सुनवाई को पूरी तरह समाप्त नहीं करता, बल्कि आवश्यकतानुसार हाइब्रिड और ऑनलाइन सुनवाई का विकल्प उपलब्ध कराता है।

79. (D) एक विशेष हरित पीठ
उच्चतम न्यायालय में पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण और पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित जनहित याचिकाओं की त्वरित और विशेषज्ञ सुनवाई के लिए मुकदमों को एक विशेष हरित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाता है। यह विशेष पीठ पर्यावरणीय क्षति को रोकने, सतत विकास सुनिश्चित करने और पर्यावरण से जुड़े जटिल कानूनों तथा तकनीकी पहलुओं पर त्वरित न्यायिक आदेश पारित करने का कार्य करती है।

80. (B) 4:1
वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को 4:1 के बहुमत से रद्द कर दिया था। चार न्यायाधीशों ने माना कि यह आयोग न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है, जबकि एक न्यायाधीश ने एनजेएसी के समर्थन में अपना असहमतिपूर्ण फैसला सुनाया था।

81. (B) इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) के मामले को आमतौर पर मंडल आयोग मामले के नाम से जाना जाता है। नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। हालांकि, न्यायालय ने यह ऐतिहासिक व्यवस्था भी दी कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

82. (A) एस. पी. गुप्ता मामला → सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन मामला → इन री स्पेशल रेफरेंस 1 ऑफ 1998
कॉलेजियम प्रणाली का न्यायिक विकास तीन प्रमुख मामलों से हुआ है। सबसे पहले 1981 में एस. पी. गुप्ता मामला (प्रथम न्यायाधीश मामला) आया जिसमें कार्यपालिका को प्राथमिकता दी गई। इसके बाद 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन मामला (द्वितीय न्यायाधीश मामला) हुआ जिसने कॉलेजियम बनाया। अंत में 1998 में इन री स्पेशल रेफरेंस मामला (तृतीय न्यायाधीश मामला) हुआ जिसने कॉलेजियम का विस्तार किया।

83. (A) भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और अमतदेय होते हैं
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि इन खर्चों पर संसद में प्रतिवर्ष मतदान कराने की आवश्यकता नहीं होती है। यह संवैधानिक व्यवस्था न्यायपालिका की वित्तीय स्वायत्तता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, ताकि न्यायाधीश

Click Here to Buy book on Amazon

रोकने और संघवाद की रक्षा से संबंधित है। विशाखा मामला कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु दिशानिर्देश प्रदान करता है, जबकि एम. सी. मेहता मामला पर्यावरण संरक्षण तथा अंतर्निहित जोखिम वाले उद्योगों के पूर्ण दायित्व के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है।

21. (A) आपराधिक अवमानना शक्ति
न्यायालय की अवमानना अधिनियम के अनुसार, जब कोई व्यक्ति किसी ऐसा प्रकाशन या कृत्य करता है जिससे न्यायालय की गरिमा गिरती है, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है या न्यायिक प्राधिकार में बाधा उत्पन्न होती है, तो उसे आपराधिक अवमानना माना जाता है। सिविल अवमानना में केवल अदालती आदेशों की जानबूझकर की गई अवज्ञा शामिल होती है, जबकि अदालत के अधिकार को चुनौती देना आपराधिक अवमानना के दायरे में आता है।

22. (D) उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधिवेत्ता
न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत न्यायाधीश पर लगे आरोपों की पड़ताल के लिए तीन सदस्यों की एक स्वतंत्र समिति बनाई जाती है। इस समिति में उच्चतम न्यायालय का एक सेवारत न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति की दृष्टि में एक प्रख्यात विधिवेत्ता शामिल होते हैं। यह समिति निष्पक्ष जांच करके अपनी रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी को सौंपती है, जिसके आधार पर आगे की प्रक्रिया संचालित होती है।

23. (B) संयुक्त राज्य अमेरिका
जनहित याचिका (पीआईएल) की अवधारणा की उत्पत्ति और शुरुआती विकास सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इसे 1960 के दशक में गरीब, अल्पसंख्यक और वंचित समूहों को कानूनी सहायता प्रदान करने तथा सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों को अदालत में उठाने के लिए शुरु किया गया था। बाद में भारतीय न्यायपालिका ने इस अवधारणा को अपनाते हुए देश की सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल इसका विस्तार किया।

24. (C) न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर
भारत में जनहित याचिका की नींव रखने और इसे न्यायिक प्रणाली में स्थापित करने का श्रेय मुख्य रुप से न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती को दिया जाता है। इन्होंने 1970 और 1980 के दशक में पारंपरिक प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए आम जनता और वंचित वर्गों की न्याय तक पहुँच को सुलभ बनाया। इनके प्रयासों से मानवाधिकारों की रक्षा में अभूतपूर्व प्रगति हुई।

25. (D) किसी न्यायालय के समक्ष मामला लाने का किसी पक्षकार का कानूनी अधिकार
लोकस स्टैंडाई का तात्पर्य किसी पीड़ित व्यक्ति का वह कानूनी अधिकार है जिसके तहत वह अपने अधिकारों के हनन के विरुद्ध स्वयं न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर सकता है। पारंपरिक कानूनी व्यवस्था में केवल प्रभावित व्यक्ति ही अदालत जा सकता था। हालांकि, जनहित याचिका के आगमन के बाद इस नियम में ढील दी गई ताकि कोई भी सार्वजनिक भावना से प्रेरित नागरिक दूसरों के अधिकारों के लिए भी न्याय मांग सके।

26. (B) केवल II, III और IV
जनहित याचिका केवल उच्चतम न्यायालय ही नहीं बल्कि उच्च न्यायालयों में भी दायर की जा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य वंचित और कमजोर वर्गों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन करना है। न्यायालय पत्रात्मक क्षेत्राधिकार के तहत पत्रों या टेलीग्रामों को भी याचिका के रूप में स्वीकार कर सकता है। इसके अतिरिक्त, निरंतर जन-क्षति से जुड़े जनहित के मुद्दों पर प्रांगन्याय का पारंपरिक सिद्धांत सख्ती से लागू नहीं किया जाता है।

NODIA

27. (B) बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन
बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ मामला भारत में बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन और शोषण के विरुद्ध अधिकारों की रक्षा से संबंधित एक ऐतिहासिक जनहित याचिका थी। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कठोर कदम उठाते हुए खदानों में काम करने वाले अमानवीय परिस्थितियों में फंसे बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास के लिए सरकार को कड़े निर्देश जारी किए थे। यह फैसला मानवाधिकारों के संरक्षण में मील का पत्थर साबित हुआ।

28. (B) सक्रियता अधिकारों की अग्रसक्रिय रुप से रक्षा करती है, जबकि अतिसक्रियता विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों का अतिक्रमण करती है।
न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और संविधान के प्रवर्तन के लिए अग्रसक्रिय भूमिका निभाती है। इसके विपरीत, जब न्यायपालिका अपनी संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करते हुए विधायिका और कार्यपालिका के नीतिगत तथा प्रशासनिक मामलों में अनावश्यक रुप से हस्तक्षेप करने लगती है, तो इसे न्यायिक अतिसक्रियता कहा जाता है। अतिसक्रियता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।

29. (A) कार्यपालिका के लिए आरक्षित नीतिगत निर्णयों में न्यायिक हस्तक्षेप।
जनहित याचिका का अत्यधिक उपयोग करने पर इसकी मुख्य आलोचना यह की जाती है कि यह कार्यपालिका और विधायिका के विशुद्ध नीतिगत निर्णयों में न्यायिक हस्तक्षेप को बढ़ाती है। आलोचकों के अनुसार, अदालतों द्वारा नीति-निर्माण और प्रशासनिक निर्णयों को अपने हाथ में लेने से संविधान द्वारा स्थापित शक्तियों के संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे अदालतों पर तुच्छ याचिकाओं का अनावश्यक बोझ भी बढ़ जाता है।

30. (C) अनुच्छेद 226
भारत में जनहित याचिकाएं संवैधानिक प्रावधानों के तहत दायर की जाती हैं। उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिका स्वीकार की जाती

की सिफारिश भेजने से पहले इन चार वरिष्ठ न्यायाधीशों की आम सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

52. (B) केवल I, III और IV
उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए संसद इसके क्षेत्राधिकार को कम नहीं कर सकती और न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल उनकी सुरक्षा तय करता है। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध भी निष्पक्षता बनाए रखता है। हालांकि, उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और इन पर संसद में प्रतिवर्ष मतदान नहीं कराया जाता, जिससे इसकी वित्तीय स्वायत्तता सुरक्षित रहती है।

53. (A) अनुच्छेद 133
संविधान का अनुच्छेद 133 सिविल मामलों में उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करने की प्रक्रिया का नियमन करता है। यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र दे दे कि संबंधित सिविल मुकदमे में सामान्य महत्व का कोई कानून का सारवान प्रश्न शामिल है और उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा होना आवश्यक है, तो अपील दायर की जा सकती है।

54. (C) केंद्र सरकार के खिलाफ फैसला सुनाना
संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल दो आधारों पर ही पद से हटाया जा सकता है: सिद्ध कदाचार या असमर्थता। केंद्र सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी के विरुद्ध फैसला सुनाना न्यायाधीश को हटाने का वैध आधार नहीं है। यह प्रावधान न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता और बिना किसी राजनीतिक भय या पक्षपात के न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

55. (B) निर्णय सुनाने वाली पीठ द्वारा
अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है। सामान्य प्रक्रिया के तहत पुनर्विचार याचिका की सुनवाई खुली अदालत के बजाय न्यायाधीशों के निजी कक्ष में की जाती है। आमतौर पर यह सुनवाई उसी पीठ द्वारा की जाती है जिसने मूल निर्णय सुनाया होता है, जब तक कि वह न्यायाधीश सेवानिवृत्त या उपलब्ध न हो गए हों।

56. (C) न्याय की विफलता को रोकने के लिए पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद का एक अंतिम कानूनी उपाय।
उपचारात्मक याचिका या क्यूरेटिव पिटीशन उच्चतम न्यायालय द्वारा विकसित एक अंतिम कानूनी उपाय है। जब किसी मामले में पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो जाती है, तब न्याय की गंभीर विफलता या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन को रोकने के लिए इस याचिका का उपयोग किया जाता है। यह न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और अंतिम सत्य की रक्षा करने का एक असाधारण साधन है।

57. (D) रुपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा
वर्ष 2002 के ऐतिहासिक रुपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले में उच्चतम न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से उपचारात्मक याचिका (क्यूरेटिव पिटीशन) की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। न्यायालय ने माना कि अपने ही अंतिम फैसलों के पुनरीक्षण के बाद भी न्याय की विफलता को दूर करने के लिए न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस याचिका को स्वीकार कर सकता है।

58. (A) इसने जन-भावना वाले नागरिकों को अदालत तक पहुँचने में असमर्थ वंचित लोगों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी।
जनहित याचिका के विकास में उच्चतम न्यायालय ने लोकस स्टैंडाई के पारंपरिक नियम को उदार बनाया। पहले केवल वही व्यक्ति अदालत जा सकता था जिसका व्यक्तिगत अधिकार प्रभावित हुआ हो। नए बदलाव के तहत, यदि निर्धनता या अज्ञानता के कारण कोई वर्ग न्याय पाने में असमर्थ है, तो कोई भी जन-भावना से प्रेरित नागरिक या संस्था उनके पक्ष में अदालत का रुख कर सकती है।

59. (B) भवन स्वामी और किरायेदार विवाद
उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार केवल व्यापक जनहित से जुड़े मुद्दों को ही जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया जाता है। व्यक्तिगत या निजी प्रकृति के विवादों जैसे भवन स्वामी और किरायेदार के बीच के झगड़े, मकान खाली कराने या व्यक्तिगत संपत्ति विवादों को जनहित याचिका नहीं माना जाता है। ऐसे मामलों के निपटारे के लिए सामान्य दीवानी अदालती प्रक्रिया अपनाई जाती है।

60. (B) एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (ओलियम गैस लीक मामला)
वर्ष 1987 के ओलियम गैस लीक मामले (एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ) में उच्चतम न्यायालय ने पूर्ण दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि खतरनाक या अंतर्निहित रूप से जोखिम भरे उद्योगों में लगे प्रतिष्ठानों को किसी भी दुर्घटना या क्षति के लिए बिना किसी अपवाद के पूर्णतः उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इस फैसले ने पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया।

61. (A) एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ
एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संघवाद भारतीय संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा है। इस मामले में न्यायालय ने राज्यों में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की कार्यपालक शक्ति पर कड़े प्रतिबंध लगाए और यह व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

62. (C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है जो देश के सभी निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अंतिम अपीलें सुनता है। हालांकि, कारण गलत है क्योंकि

Downloaded from www.pdf.tube

41. (D) संवैधानिक व्याख्या के मुद्दों का फैसला करने वाली पाँच या अधिक न्यायाधीशों की पीठ।
उच्चतम न्यायालय में संविधान पीठ का तात्पर्य ऐसे न्यायाधीशों की पीठ से होता है जिसमें कम से कम पाँच न्यायाधीश शामिल होते हैं। अनुच्छेद 145(3) के अनुसार जब किसी मामले में संविधान की व्याख्या से जुड़ा कानून का कोई महत्वपूर्ण और सारवान प्रश्न निहित होता है, या अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा कोई परामर्श मांगा जाता है, तब ऐसे मामलों की सुनवाई संविधान पीठ द्वारा की जाती है।

42. (A) सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा अपील
उच्चतम न्यायालय के पास व्यापक अपीलीय क्षेत्राधिकार उपलब्ध है, लेकिन सशस्त्र बलों से संबंधित कानून के तहत गठित किसी भी न्यायाधिकरण या अदालत द्वारा पारित फैसलों के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 136 सैन्य न्यायाधिकरणों को इसके दायरे से स्पष्ट रुप से बाहर रखता है। बाकी सिविल, आपराधिक और संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

43. (A) II, III, I, IV
भारत के मुख्य न्यायाधीशों का सही कालानुक्रमिक क्रम रंजन गोगोई, एस. ए. बोबडे, एन. वी. रमणा और डी. वाई. चंद्रचूड़ है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई अक्टूबर 2018 में मुख्य न्यायाधीश बने थे, उनके बाद नवंबर 2019 में एस. ए. बोबडे ने पदभार संभाला। अप्रैल 2021 में एन. वी. रमणा तथा नवंबर 2022 में डी. वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे।

44. (B) राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।
अनुच्छेद 126 के अनुसार जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या वे अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों, तो राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति इस कार्य के लिए उच्चतम न्यायालय के अन्य सेवारत न्यायाधीशों में से किसी एक को अस्थायी रुप से मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक और न्यायिक दायित्वों हेतु नियुक्त करते हैं।

45. (A) विधायी अधिनियमों और कार्यपालक आदेशों को असंवैधानिक घोषित करने की।
न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार देती है कि वह संसद या राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों की संवैधानिक वैधता की जांच कर सके। यदि कोई कानून या नीतिगत आदेश संविधान के प्रावधानों या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उच्चतम न्यायालय उसे असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर रद्द कर सकता है।

46. (A) P-2, Q-4, R-3, S-1
संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 129 न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान करता है। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की पुनरसमीक्षा करने की शक्ति देता है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को कानूनी और सार्वजनिक मामलों में उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है।

47. (D) परमादेश
परमादेश की रिट का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं होता है। यह एक न्यायिक आदेश है जो किसी सार्वजनिक अधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय या निगम को उसके वैधानिक या सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है, जब वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है। इस रिट का उपयोग गैर-सरकारी निकायों या निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है।

48. (C) भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल
परमादेश की रिट किसी सार्वजनिक संस्था या अधिकारी को उसके कानूनी कर्तव्यों के निर्वहन हेतु जारी की जाती है। हालांकि, भारतीय संविधान के तहत भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को इस रिट से पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, यह रिट किसी निजी व्यक्ति, गैर-सरकारी संस्था या गैर-वैधानिक संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए भी जारी नहीं की जा सकती है।

49. (B) हुसैनआरा खातून बनाम बिहार राज्य मामला
हुसैनआरा खातून बनाम बिहार राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए माना कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में त्वरित सुनवाई का अधिकार शामिल है। इस मामले के माध्यम से जेलों में बंद हजारों असहाय विचाराधीन बंदियों को राहत मिली और इसने भारत में प्रारंभिक जनहित याचिकाओं के विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया।

50. (D) न्यायालय को लिखे गए पत्रों या पोस्टकार्डों को औपचारिक रिट याचिका के रूप में स्वीकार करना।
पत्रात्मक क्षेत्राधिकार का तात्पर्य उस न्यायिक प्रक्रिया से है जिसके तहत न्यायालय आम नागरिकों द्वारा लिखे गए साधारण पत्रों, पोस्टकार्डों या टेलीग्रामों को ही औपचारिक रिट याचिका के रूप में स्वीकार कर लेता है। उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिकाओं को बढ़ावा देने और गरीब तथा असहाय लोगों को महंगी कानूनी प्रक्रियाओं के बिना सीधे न्याय दिलाने के लिए इस नवोन्मेषी प्रक्रियात्मक व्यवस्था को विकसित किया था।

51. (A) चार
उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाले कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तृतीय न्यायाधीश मामले 1998 के बाद यह नियम स्थापित किया गया था कि मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति या तबादले

NODIA

(A) केवल I, II और IV
(B) केवल I, II और III
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Flipkart

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण जैसे विशेष निकायों को अनुच्छेद 136 के अपीलीय क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। संविधान किसी भी निकाय को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं करता, बल्कि कुछ विशेष मामलों में अलग अपीलीय ढाँचे का प्रावधान भी करता है।

63. (D) सक्रियता का अर्थ है एक अग्रसक्रिय भूमिका निभाना, जबकि संयम निर्वाचित शाखाओं के प्रति आदर व्यक्त करने की वकालत करता है।
न्यायिक सक्रियता में न्यायाधीश सामाजिक परिवर्तन लाने और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु नीतिगत मामलों में अग्रसक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसके विपरीत, न्यायिक संयम का सिद्धांत यह वकालत करता है कि न्यायपालिका को अपनी सीमाओं में रहना चाहिए और विधायिका तथा कार्यपालिका जैसी निर्वाचित संवैधानिक संस्थाओं के नीति-निर्माण अधिकारों का सम्मान करते हुए उनमें हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। यह संतुलन बनाए रखने हेतु आवश्यक है।

64. (C) उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों की अवमानना के लिए व्यक्तियों को दंडित नहीं कर सकता है।
उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय होने के नाते स्वयं की अवमानना के साथ-साथ अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों की अवमानना के लिए भी व्यक्तियों को दंडित करने की पूर्ण संवैधानिक शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, सिविल अवमानना आदेशों की अवज्ञा से जुड़ी होती है जबकि आपराधिक अवमानना गरिमा को ठेस पहुँचाती है। न्यायिक कार्यवाहियों की निष्पक्ष और सत्य रिपोर्टिंग करना अवमानना के दायरे में नहीं आता।

65. (B) केवल I और III
अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी कानून या तथ्य के प्रश्न अथवा संविधान-पूर्व संधियों से उत्पन्न विवादों को परामर्श हेतु उच्चतम न्यायालय के पास भेज सकते हैं। हालांकि, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस अनुच्छेद के तहत दी गई परामर्शदायी राय केवल सलाहकारी प्रकृति की होती है। राष्ट्रपति इस राय को मानने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं होते हैं।

66. (D) राष्ट्रपति की स्वीकृति से उच्चतम न्यायालय में
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपनी कार्यप्रणाली, अभ्यासों और अदालती प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। हालांकि, इन नियमों को लागू करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की औपचारिक स्वीकृति और अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यह व्यवस्था न्यायालय को स्वायत्तता प्रदान करने के साथ-साथ संवैधानिक संतुलन भी बनाए रखती है।

67. (A) सार्वजनिक पद के दावे की वैधानिकता की जांच करने के लिए
अधिकार-पृच्छा की रिट का शाब्दिक अर्थ किस प्राधिकार से होता है। यह रिट किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर किए गए दावे की वैधानिकता की जांच करने के लिए जारी की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी अनाधिकृत व्यक्ति को किसी सार्वजनिक या संवैधानिक पद पर गैर-कानूनी रूप से कब्जा करने से रोकना है, ताकि पद के दुरुपयोग को समय रहते रोका जा सके।

68. (C) परामर्श का दायरा और कॉलेजियम की संरचना
वर्ष 1998 के तृतीय न्यायाधीश मामले में मुख्य कानूनी मुद्दा संविधान में प्रयुक्त परामर्श शब्द के वास्तविक विस्तार और कॉलेजियम की संरचना को स्पष्ट करना था। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत मांगे गए संदर्भ पर न्यायालय ने निर्णय दिया कि मुख्य न्यायाधीश अकेले फैसला नहीं लेंगे, बल्कि वे चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से राष्ट्रपति को नियुक्तियों हेतु सिफारिशें भेजेंगे।

69. (A) संसद अनुच्छेद 368 के माध्यम से मूल विशेषताओं को नहीं बदल सकती है।
केशवानंद भारती मामले में प्रतिपादित मूल ढांचा सिद्धांत का मूल अर्थ यह है कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन वह अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके संविधान की मौलिक विशेषताओं या मूल ढांचे को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। लोकतंत्र, संघवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता जैसे तत्व संविधान के इस अपरिवर्तनीय मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं।

70. (D) कभी नहीं
भारतीय इतिहास में आज तक उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर सफलतापूर्वक महाभियोग नहीं चलाया गया है और न ही किसी न्यायाधीश को पद से हटाया गया है। यद्यपि न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी और न्यायमूर्ति सौमित्र सेन जैसे कुछ न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई थी, लेकिन मतदान में प्रस्ताव पारित न होने या पद से त्यागपत्र दे देने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

71. (B) मलिमथ समिति
मलिमथ समिति का गठन वर्ष 2000 में भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार और अदालतों में लंबित मामलों से निपटने के सुझाव देने के लिए किया गया था। इस समिति ने 2003 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें जांच प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने, पीड़ित अधिकारों को मजबूत करने और मुकदमों के त्वरित निपटारे हेतु अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई थीं। अन्य समितियां अलग-अलग विषयों से जुड़ी हैं।

72. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना होता है। उत्प्रेषण की रिट का अर्थ पूर्णतः सूचित या प्रमाणित होना है। अधिकार-पृच्छा का अर्थ किस प्राधिकार या वारंट से होता है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक पद के दावे की जांच की जाती है। इसी प्रकार, परमादेश का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं होता है, जो सार्वजनिक कर्तव्य पालन हेतु जारी किया जाता है।

Downloaded from www.pdf.tube

है। इसी प्रकार, राज्यों के उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत जनहित याचिकाएं स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 226 का दायरा व्यापक है क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य विधिक अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।

31. (D) उच्च न्यायालय मौलिक और कानूनी दोनों अधिकारों के लिए रिट जारी करते हैं; उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करता है।
रिट जारी करने के क्षेत्राधिकार के मामले में उच्च न्यायालय का दायरा उच्चतम न्यायालय से अधिक व्यापक है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है। इसके विपरीत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य किसी भी सामान्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन हेतु भी रिट जारी करने का अधिकार रखते हैं।

32. (C) डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्यायिक दक्षता और पहुँच को बढ़ाना।
भारतीय न्यायिक प्रणाली में ई-कोर्ट परियोजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय व्यवस्था की दक्षता, पारदर्शिता और पहुँच को बेहतर बनाना है। इसके तहत अदालती प्रक्रियाओं का संगणकीकरण, मामलों की ई-फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई और मुकदमों की स्थिति का ऑनलाइन विवरण प्रदान किया जाता है। इससे वादकारियों को सुलभ और त्वरित न्याय प्राप्त करने में मदद मिलती है।

33. (B) लंबित और निपटाए गए मामलों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना।
राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड ई-कोर्ट परियोजना के तहत निर्मित एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय डेटाबेस है। इसका उद्देश्य देश भर के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों में लंबित और निपटाए गए मुकदमों का एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड रखना है। यह प्रणाली मुकदमों की निगरानी, न्यायिक देरी को कम करने और नीति-निर्माण में पारदर्शिता लाने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में कार्य करती है।

34. (D) लंबित या पूर्व-मुकदमेबाज़ी विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक वैकल्पिक मंच।
लोक अदालत न्यायालयों में लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने और मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए गठित एक वैकल्पिक विवाद समाधान मंच है। यह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत एक वैधानिक निकाय है। लोक अदालतों में अदालतों में लंबित या पूर्व-मुकदमेबाजी चरण के मामलों को दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति और समझौते के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाता है।

35. (A) विशाखा बनाम राजस्थान राज्य
राजस्थान की एक सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी के मामले से उत्पन्न विशाखा बनाम राजस्थान राज्य याचिका में उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था। न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत व्यापक दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों ने बाद में 2013 के कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम का आधार तैयार किया था।

36. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2015 में 99वें संविधान संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया था। न्यायालय का मानना था कि इस आयोग में कार्यपालिका की मौजूदगी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। चूंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है, इसलिए संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो इसे बाधित करे।

37. (A) अनुच्छेद 136
संविधान का अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय को एक विशेष अपीलीय शक्ति प्रदान करता है जिसे विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) कहा जाता है। इसके तहत न्यायालय भारत के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण (सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को छोड़कर) द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील स्वीकार करने का सर्वाधिकार रखता है। यह उच्चतम न्यायालय की एक व्यापक और विवेकाधीन संवैधानिक शक्ति है।

38. (D) अनुच्छेद 142
संविधान का अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक आदेश या डिक्री पारित करने की विशेष शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति का उपयोग करके न्यायालय कानूनी तकनीकी बाधाओं से परे जाकर पक्षों को पूर्ण राहत दे सकता है। अनुच्छेद 142 के तहत जारी किए गए आदेश पूरे भारत के राज्यक्षेत्र में समान रूप से लागू और प्रवर्तनीय होते हैं।

39. (A) केवल I और II
अनुच्छेद 127 के तहत जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने के लिए गणपूर्ति पूरी न हो रही हो, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श आवश्यक होता है। हालांकि, केवल किसी उच्च न्यायालय के योग्य न्यायाधीश को ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

40. (C) राष्ट्रपति की सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश
संविधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश को कार्य अवधि के दौरान वे सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

NODIA

बिना किसी राजनीतिक दबाव या वित्तीय अनिश्चितता के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

84. (C) अनुच्छेद 139A के तहत शक्ति
संविधान के अनुच्छेद 139A के तहत उच्चतम न्यायालय को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह किसी एक उच्च न्यायालय में लंबित मामले या याचिका को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सके। यदि न्यायालय को लगता है कि कई उच्च न्यायालयों में विधि के समान प्रश्न शामिल हैं, तो न्याय के हित में वह मामलों को अपने पास स्थानांतरित या किसी एक उच्च न्यायालय में भेज सकता है।

85. (A) भारत के महान्यायावादी
भारत के महान्यायावादी (अटॉर्नी जनरल) देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं और वे उच्चतम न्यायालय में उन सभी मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें सरकार एक पक्षकार होती है। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त महान्यायावादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है और वे कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह भी प्रदान करते हैं।

86. (D) राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध का निर्देश देना और दूरी की सीमा तय करना।
राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश को आलोचकों द्वारा न्यायिक अतिसक्रियता का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। आलोचकों का तर्क है कि आबकारी नीति और दूरी की सीमा तय करना विशुद्ध रूप से कार्यपालिका और विधायिका का नीतिगत विषय है, जिसमें न्यायपालिका द्वारा ऐसा कड़ा निर्देश देना शक्तियों के पृथक्करण का अतिक्रमण करता है।

87. (B) अनुच्छेद 144
संविधान के अनुच्छेद 144 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि भारत के राज्यक्षेत्र में स्थित सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि कार्यपालिका, पुलिस और निचली अदालतें उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों, निर्देशों और डिक्रियों के निष्पादन तथा उन्हें लागू करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।

88. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
जनहित याचिका व्यवस्था ने निस्संदेह समाज के कल्याण में योगदान दिया है, लेकिन इसके कारण अदालतों में मुकदमों की संख्या और लंबितता में भारी वृद्धि हुई है। चूंकि जनहित याचिका के तहत लोकस स्टैंडाई में ढील दी गई है, इसलिए कई बार लोग व्यक्तिगत प्रचार या तंग करने की नीयत से तुच्छ याचिकाएं दायर कर देते हैं, जिससे न्यायालय का बहुमूल्य समय नष्ट होता है।

89. (A) शून्य
संविधान के अनुच्छेद 124(3)(c) के अनुसार राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता को सीधे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि, भारतीय न्यायिक इतिहास में आज तक इस विशिष्ट प्रावधान के तहत किसी भी प्रख्यात विधिवेत्ता को सीधे उच्चतम न्यायालय में नियुक्त नहीं किया गया है। अब तक नियुक्त सभी न्यायाधीश या तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं या वरिष्ठ अधिवक्ता।

90. (A) संयुक्त राज्य अमेरिका
भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा (न्यायिक पुनरावलोकन) की अवधारणा मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इस शक्ति के तहत उच्चतम न्यायालय विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी आदेशों की जांच करता है। यदि कोई कानून संविधान के प्रावधानों के विपरीत पाया जाता है, तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है, जिससे संविधान की सर्वोच्चता बनी रहती है।

91. (D) I, II और III
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसी व्यक्ति को गैर-कानूनी हिरासत से मुक्त कराने के लिए जारी की जाती है और यह सार्वजनिक अधिकारियों तथा निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। यह अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हालांकि, यदि व्यक्ति का निरोध विधि द्वारा स्थापित वैध प्रक्रिया के तहत किया गया है, तो यह रिट जारी नहीं की जा सकती।

92. (B) केंद्रीय कानून तब तक लागू रहता है जब तक कि राज्य के कानून को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न हुई हो।
संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार समवर्ती सूची के विषय पर यदि केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच टकराव होता है, तो केंद्रीय कानून लागू रहता है। हालांकि, यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा गया हो और राष्ट्रपति ने उसे अपनी सहमति दे दी हो, तो उस संबंधित राज्य में राज्य कानून प्रभावी रहता है, बशर्ते संसद बाद में उसमें संशोधन न करे।

93. (B) पांच
संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत यह निर्धारित किया गया है कि जिस मामले में संविधान की व्याख्या से जुड़ा कानून का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित हो, उसकी निर्णय प्रक्रिया हेतु गठित संविधान पीठ में कम से कम पाँच न्यायाधीश होने चाहिए। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए परामर्श की सुनवाई के लिए भी न्यूनतम पाँच न्यायाधीशों की पीठ आवश्यक होती है।

94. (C) आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 के प्रवर्तन के लिए अदालत जाने के अधिकार का निलंबन।
ए. डी. एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976) के चर्चित मामले में उच्चतम न्यायालय के बहुचर्चित फैसले ने यह व्यवस्था दी थी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान नागरिकों का अनुच्छेद 21 के तहत अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता

Click Here to Buy book on Amazon

(D) कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करना और कम से कम 2 सीटें जीतना

19. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के कार्यालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है?
(A) अनुच्छेद 148
(B) अनुच्छेद 149
(C) अनुच्छेद 150
(D) अनुच्छेद 151

20. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है।
II. CAG छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करता है।
III. CAG के वेतन और सेवा की अन्य शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
IV. CAG के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भारत की आकस्मिकता निधि पर भारित होते हैं।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, II और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

21. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के कार्यप्रणाली के संदर्भ में, "औचित्य लेखापरीक्षा" (Propriety Audit) का मुख्य रूप से क्या अर्थ है?
(A) सार्वजनिक व्यय की बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और मितव्ययिता की जांच करना।
(B) सख्त कानूनी और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी खातों की लेखापरीक्षा करना।
(C) यह जांच करना कि व्यय उसे शासित करने वाले प्राधिकार के अनुरुप है या नहीं।
(D) कर वंचना का पता लगाने और उसे समाप्त करने के लिए समग्र सरकारी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करना।

22. सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र के पश्चात्, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक:
(A) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे के नियोजन के लिए पात्र होते हैं।
(B) केवल राज्य के राज्यपाल जैसे कार्यकारी पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं।
(C) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं।
(D) केंद्र या राज्य सरकारों के अधीन किसी भी आगे के पद के लिए अपात्र होते हैं।

23. भारत में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) और लोक लेखा समिति (PAC) के बीच संबंध के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) CAG लोक लेखा समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
(B) PAC संसद के समक्ष रखे गए CAG के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की जांच करती है।
(C) CAG वार्षिक केंद्रीय बजट तैयार करते हैं जबकि PAC इसे औपचारिक रुप से मंजूरी देती है।
(D) PAC के पास CAG रिपोर्ट को अस्वीकृत करने और नई लेखापरीक्षा का आदेश देने का अधिकार है।

24. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कर्तव्य या शक्ति नहीं है?
(A) भारत की संचित निधि से संबंधित खातों की लेखापरीक्षा करना।
(B) ऋण से संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों के सभी लेन-देन की लेखापरीक्षा करना।
(C) केंद्र सरकार के खातों को संकलित करना और उनका रखरखाव करना।
(D) संघ या राज्यों के राजस्व से बड़े पैमाने पर वित्तपोषित निकायों की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा करना।

25. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए।
सूची I: (CAG से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद)
P. अनुच्छेद 148
Q. अनुच्छेद 149
R. अनुच्छेद 150
S. अनुच्छेद 151
सूची II: (विषय-वस्तु)
1. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
2. CAG के कर्तव्य और शक्तियां
3. संघ और राज्यों के खातों का प्रारुप
4. CAG की नियुक्ति और सेवा शर्तें
(A) P-4, Q-2, R-3, S-1
(B) P-2, Q-4, R-1, S-3
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

NODIA

26. निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक निगम की प्रत्यक्ष लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नहीं की जाती है?
(A) भारतीय रिज़र्व बैंक
(B) दामोदर घाटी निगम
(C) तेल और प्राकृतिक गैस निगम
(D) एयर इंडिया (निजीकरण से पूर्व)

27. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: CAG केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के खातों

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from
PRINTED BOOKS has up to
4× HIGHER RETENTION
than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

सिद्धांतों के आधार पर आवश्यक आदेश जारी कर सकता है ताकि पक्षों को न्याय मिल सके।

106. (C) 90 दिन
उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने की सामान्य समय-सीमा 90 दिन निर्धारित है। यह अवधि निर्णय सुनाए जाने की तिथि से गिनी जाती है। हालांकि, यदि याचिकाकर्ता देरी का पर्याप्त और न्यायसंगत कारण प्रस्तुत करता है, तो उच्चतम न्यायालय अपने विवेक से इस समय-सीमा में छूट प्रदान कर याचिका को स्वीकार कर सकता है।

107. (B) मेनका गांधी बनाम भारत संघ
मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) के ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अर्थ का व्यापक विस्तार किया। न्यायालय ने माना कि केवल कोई कानून होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वह प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष और तर्कसंगत भी होनी चाहिए। इस फैसले के माध्यम से भारतीय न्यायशास्त्र में अमेरिकी सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांतों का समावेश हुआ।

108. (B) न्यायिक स्वतंत्रता
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए कठिन और जटिल प्रक्रिया बनाई गई है, जिसके तहत संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकते हैं। यह कठिन संवैधानिक प्रक्रिया न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा की गारंटी देती है, जिसका मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखना है ताकि वे बिना डर के काम कर सकें।

109. (A) II, I, IV, III
संपत्ति के अधिकार और संशोधन शक्तियों से जुड़े मामलों का सही कालानुक्रमिक क्रम सबसे पहले शंकरी प्रसाद मामला (1951) है। इसके बाद आई. सी. गोलकनाथ मामला (1967) आया जिसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन पर रोक लगाई गई। तत्पश्चात केशवानंद भारती मामला (1973) आया जिसने मूल ढांचा सिद्धांत दिया, और अंत में मिनर्वा मिल्स मामला (1980) आया जिसने इस सिद्धांत को पुनः सुदृढ़ किया।

110. (C) निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय राज्यों के बीच आपराधिक मामलों को स्थानांतरित कर सकता है।
उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह निष्पक्ष न्याय और स्वतंत्र सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किसी आपराधिक मामले को एक राज्य की अदालत से दूसरे राज्य की अदालत में स्थानांतरित कर दे। यदि न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि किसी विशेष राज्य के माहौल में स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, तो वह पक्षों के आवेदन पर मामले के स्थानांतरण का आदेश जारी कर सकता है।

111. (D) न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप
कॉलेजियम प्रणाली के निर्माण का मुख्य कारण न्यायाधीशों की नियुक्तियों और तबादलों में कार्यपालिका के अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकना था। 1970 के दशक में मुख्य न्यायाधीशों के चयन में वरिष्ठता का उल्लंघन करने की घटनाओं के बाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसलों के माध्यम से नियुक्तियों का अधिकार स्वयं अपने और वरिष्ठ न्यायाधीशों के हाथों में केंद्रित कर लिया।

112. (C) संसद सदस्य के चुनाव से संबंधित विवाद
संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में केवल संघ और राज्यों के बीच होने वाले अंतर-सरकारी विवाद शामिल होते हैं। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के आपसी विवाद आते हैं। संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य के चुनाव से संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आते; ऐसे मामलों की शुरुआती सुनवाई उच्च न्यायालय में होती है।

113. (B) लंबित कार्यवाहियों की जानकारी के बिना निर्दोष प्रकाशन
न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी लंबित न्यायिक कार्यवाही के बारे में जाने बिना सद्भावपूर्वक या निर्दोष रूप से किसी सामग्री का प्रकाशन करता है, तो इसे अवमानना नहीं माना जाता है। इसके विपरीत अदालती आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना, अदालत के प्राधिकार को कम करना या न्यायिक प्रक्रिया में अनुचित हस्तक्षेप करना दंडनीय अवमानना की श्रेणी में आता है।

114. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
उत्प्रेषण की रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण के विरुद्ध जारी की जाती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी निचली अदालत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करके पारित किए गए किसी अवैध आदेश को रद्द करना होता है। चूंकि यह आदेश रद्द करने हेतु जारी होती है, इसलिए कारण अभिकथन की पूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करता है।

115. (A) न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी
प्रतिषेध की रिट विशेष रूप से केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। इसका उद्देश्य अधीनस्थ अदालतों को अपनी क्षेत्राधिकार की सीमाओं का उल्लंघन करने से रोकना है। यह रिट विधायिका, निजी व्यक्तियों या विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कार्य करने वाले निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि इसका सीधा संबंध न्यायालयों की चालू कार्यवाहियों के निलंबन से है।

116. (C) न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती को न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर के साथ देश में जनहित याचिका (पीआईएल) के न्यायशास्त्र का जनक माना जाता है।

Downloaded from www.pdf.tube

न्यायमूर्ति भगवती ने पत्रात्मक क्षेत्राधिकार की शुरुआत की और लोकस स्टैंडाई के कड़े नियमों को शिथिल करते हुए आम जनता के पत्रों को ही रिट याचिका के रूप में स्वीकार कर न्याय तक पहुँच को व्यापक बनाया।

117. (B) केवल I और III
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। इस प्रस्ताव को स्वीकृत होने के बाद संसद में विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। हालांकि, प्रस्ताव पेश होने के बाद सदन का पीठासीन अधिकारी उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है; वह अपने विवेक से प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

118. (D) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाली न्यायिक समीक्षा
श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) मामले में उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया था। यह मामला न्यायिक समीक्षा की उस शक्ति का एक प्रमुख उदाहरण है जिसका प्रयोग करके न्यायालय ने नागरिकों की इंटरनेट पर अभिव्यक्ति और वाक् स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) की रक्षा की और विधायिका के अतिरंजित कानून को निरस्त किया।

119. (B) यह गैर-विरोधी और जन कल्याण के लिए सहयोगात्मक है।
जनहित याचिका और पारंपरिक मुकदमेबाज़ी के बीच मुख्य अंतर यह है कि जनहित याचिका एक गैर-विरोधी और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसमें दो पक्षों के बीच जीत या हार की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती, बल्कि न्यायालय, याचिकाकर्ता और राज्य मिलकर सार्वजनिक कल्याण और मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए एक साथ कार्य करते हैं, जिससे समाज के पीड़ित और कमजोर वर्गों को राहत मिल सके।

120. (C) नया कानूनी नियम केवल भविष्य के मामलों पर लागू होता है, जिससे पिछले निर्णय बरकरार रहते हैं।
गोलकनाथ मामले में प्रयुक्त भविष्यलक्षीय निर्णय का सिद्धांत (डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉस्पेक्टिव ओवररूलिंग) यह निर्धारित करता है कि न्यायालय द्वारा घोषित नया कानूनी नियम या व्याख्या केवल भविष्य में आने वाले मामलों पर ही लागू होगी। इसके प्रभाव से पुराने निर्णय, बीत चुकी कार्यवाहियाँ और अतीत में किए गए कार्य पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं, ताकि समाज में किसी प्रकार की अराजकता या कानूनी अस्थिरता उत्पन्न न हो।

121. (B) 11वाँ वित्त आयोग
भारत में निचली अदालतों में मुकदमों के भारी बकाये से निपटने और लंबे समय से लंबित आपराधिक मामलों का तेजी से निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था। इन विशेष अदालतों की स्थापना मूल रूप से 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2000 में की गई थी, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

122. (A) कॉलेजियम के कामकाज और मास्टर ऑफ रोस्टर की भूमिका के मुद्दे
जनवरी 2018 में उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने भारतीय न्यायिक इतिहास में पहली बार एक अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनकी मुख्य शिकायतें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' के रूप में मामलों के मनमाने आवंटन और कॉलेजियम प्रणाली के पारदर्शी कामकाज में आ रही बाधाओं से जुड़ी हुई थीं, जिसे लेकर देश भर में व्यापक प्रशासनिक चर्चाएं हुई थीं।

123. (B) अनुच्छेद 262 के तहत अपवर्जित है, हालांकि सीमित समीक्षा शक्तियां बनी रहती हैं।
संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह अंतर-राज्यीय नदियों के जल विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु विशेष कानून बना सके। इस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए गए कानूनों द्वारा ऐसे विवादों को उच्चतम न्यायालय के सामान्य मूल क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। हालांकि, न्यायाधिकरणों के निर्णयों पर कानूनी और संवैधानिक प्रश्नों के लिए न्यायालय की सीमित समीक्षा शक्तियाँ बनी रहती हैं।

124. (B) कार्यवाहियों में सहायता करने वाला अदालत का मित्र (न्याय मित्र)
एमिकस क्यूरी एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ अदालत का मित्र (न्याय मित्र) होता है। जनहित याचिकाओं या जटिल कानूनी मुकदमों में, जब न्यायालय को किसी निष्पक्ष कानूनी विशेषज्ञता या स्वतंत्र जांच की आवश्यकता होती है, तो वह किसी वरिष्ठ वकील को न्याय मित्र के रूप में नियुक्त करता है। यह न्याय मित्र बिना किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व किए न्यायालय को सही निर्णय तक पहुँचने में मदद करता है।

125. (A) अनुच्छेद 21
उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि निर्धन और असहाय अभियुक्तों के लिए 'मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार' अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। यद्यपि अनुच्छेद 39A में इसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में है, पर न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है।

126. (B) 30 दिन
उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार अपने दिए गए किसी निर्णय या आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका (रिव्यू पिटीशन) दायर करने की निर्धारित समय-सीमा निर्णय सुनाए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर होती है। यदि इस अवधि के भीतर याचिका दायर नहीं की जाती है, तो याचिकाकर्ता को देरी के लिए उचित और संतोषजनक कारण स्पष्ट करते हुए समय सीमा बढ़ाने हेतु अलग से आवेदन करना पड़ता है।

NODIA

127. (D) दोहरा दंड
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) के तहत नागरिकों को दोहरे दंड के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्राप्त है। इस सिद्धान्त का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उसे दो बार दंडित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय इस संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करता है ताकि न्यायिक उत्पीड़न को रोका जा सके।

128. (C) भारत के मुख्य न्यायाधीश
राष्ट्रपति कार्य निर्वहन अधिनियम 1969 के अनुसार यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रुप में कार्य करते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश का पद भी खाली हो, तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश इस दायित्व का निर्वहन करते हैं। वर्ष 1969 में न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला ने इस व्यवस्था के तहत कार्य किया था।

129. (A) 190 से 200 दिन
भारत का उच्चतम न्यायालय एक वर्ष में सामान्यतः लगभग 190 से 200 कार्य दिवसों तक कार्य करता है। ग्रीष्मकालीन अवकाश, शीतकालीन अवकाश और अन्य सरकारी छुट्टियों के कारण कार्य दिवस सीमित होते हैं। मुकदमों के भारी बकाया को देखते हुए कार्य दिवसों की इस संख्या पर अक्सर बहस होती है, हालांकि न्यायाधीश अवकाश की अवधि के दौरान भी महत्वपूर्ण फैसलों के लेखन और शोध का कार्य करते हैं।

130. (B) केवल I, II और III
उच्चतम न्यायालय में फास्टर प्रणाली का उपयोग अदालती आदेशों को अधिकारियों तक तुरंत भेजने के लिए किया जाता है, जबकि सुपेस एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता टूल है जो न्यायाधीशों को शोध में सहायता देता है। पारदर्शिता हेतु संवैधानिक पीठों की कार्यवाहियों की लाइव-स्ट्रीमिंग भी शुरु की गई है। हालांकि, ई-फाइलिंग प्रणाली को रद्द नहीं किया गया है, बल्कि इसे डिजिटल न्याय वितरण को बढ़ावा देने के लिए निरंतर लागू रखा गया है।

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Flipkart

और जीवन की रक्षा के लिए अदालत जाने का अधिकार निलंबित रहता है। इस निर्णय को भारतीय न्यायिक इतिहास में एक विवादास्पद फैसला माना जाता है।

95. (D) 44वाँ संशोधन अधिनियम
ए. डी. एम. जबलपुर मामले के विवादित फैसले के बाद वर्ष 1978 में 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में यह महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी नागरिकों के अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) के अधिकारों को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता।

96. (C) बिना किसी याचिका के अदालत द्वारा अपनी पहल पर की गई कार्रवाई
स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) शब्द का अर्थ न्यायपालिका द्वारा बिना किसी पीड़ित पक्ष या याचिकाकर्ता की औपचारिक याचिका के, किसी समाचार या जनहित के मुद्दे पर अपनी स्वयं की पहल से विधिक कार्रवाई शुरू करना है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मानवाधिकार उल्लंघन, पर्यावरणीय क्षति या गंभीर सामाजिक अन्याय की घटनाओं में समाचार पत्रों या मीडिया रिपोर्टों के आधार पर सीधे संज्ञान लेते हैं।

97. (B) समय के साथ मामले को खुला रखकर कार्यपालक अनुपालन की निगरानी करने के लिए।
सतत परमादेश की अवधारणा का प्रयोग जनहित याचिकाओं में उच्चतम न्यायालय द्वारा तब किया जाता है जब किसी मामले में दीर्घकालिक निगरानी की आवश्यकता होती है। इसके तहत न्यायालय एक ही बार में अंतिम आदेश देकर मामला बंद करने के बजाय याचिका को खुला रखता है और समय-समय पर कार्यपालिका को निर्देश देकर उनके द्वारा किए गए सुधारों और अनुपालन की निरंतर समीक्षा करता रहता है।

98. (A) P-4, Q-1, R-3, S-2
परमानंद कटारा मामला दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता का अधिकार प्रदान करता है। मोहिनी जैन मामले ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में पहचान दी। डी. के. बासु मामले में गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत के दौरान अपनाए जाने वाले कड़े दिशानिर्देश तय किए गए, जबकि ओल्गा टेलिस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका के अधिकार को शामिल किया।

99. (A) जनहित याचिका के नाम पर दायर की जाने वाली तुच्छ याचिकाओं को हतोत्साहित करना।
जनहित याचिका प्रणाली में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुकरणीय जुर्माना या लागत लगाने की प्रथा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत प्रचार, राजनीतिक लाभ या दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों से दायर की जाने वाली तुच्छ याचिकाओं को हतोत्साहित करना है। न्यायालय ऐसी याचिकाओं को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाता है ताकि सार्वजनिक कोष और अदालत के कीमती समय का दुरुपयोग होने से रोका जा सके।

100. (C) नियंत्रण और संतुलन के साथ कार्यात्मक पृथक्करण, न कि कठोर विभाजन।
भारत में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका की तरह कठोर विभाजन पर आधारित नहीं है। उच्चतम न्यायालय की व्याख्या के अनुसार भारतीय संविधान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कार्यात्मक पृथक्करण को स्वीकार करता है, जिसमें नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था शामिल है। प्रत्येक अंग अपनी सीमाओं में कार्य करता है और साथ ही दूसरे अंगों के असंवैधानिक कृत्यों पर नज़र भी रखता है।

101. (A) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21)
उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए अनुच्छेद 21 में उल्लिखित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्यापक व्याख्या की है। न्यायालय ने माना है कि केवल जीवित रहना ही जीवन नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रदूषण मुक्त हवा, स्वच्छ पेयजल और स्वस्थ पर्यावरण प्राप्त होना नागरिक का मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है।

102. (D) अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 से व्यापक है।
उच्चतम न्यायालय याचिकाकर्ताओं को सीधे उसके पास आने से पहले अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जाने की सलाह इसलिए देता है क्योंकि उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 से अधिक व्यापक है। अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन तक सीमित है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य सामान्य विधिक अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।

103. (B) केशवानंद भारती मामला
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने बेरुबारी संघ के पिछले फैसले को पलटते हुए निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, बशर्ते संशोधन से इसके मूल ढांचे को क्षति न पहुँचे।

104. (A) केवल I और III
भारत के मुख्य न्यायाधीश 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' होते हैं और उन्हें पीठों का गठन करने तथा मामले आवंटित करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, वे सीबीआई निदेशक की चयन समिति के सदस्य भी होते हैं। हालांकि, मास्टर ऑफ द रोस्टर के रूप में उनकी भूमिका को याचिकाओं द्वारा चुनौती दी जा चुकी है तथा वे संविधान संशोधन नहीं कर सकते।

105. (D) अनुच्छेद 142 के तहत अंतर्निहित शक्तियां
संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो उसे उसके सामने लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने का अधिकार देती हैं। यदि किसी विशिष्ट परिस्थिति को कवर करने के लिए कोई लागू कानून या नियम मौजूद नहीं है, तो भी न्यायालय न्याय के

NODIA

9. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता है?
(A) मतदाता सूचियों की तैयारी और आवधिक पुनरीक्षण
(B) संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना
(C) राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिह्न आवंटित करना
(D) पंचायतों और नगरपालिकाओं के पदों के लिए चुनाव कराना

10. भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के प्रादेशिक क्षेत्रों का निर्धारण करता है।
II. इसके पास धांधली या बूथ कैप्चरिंग की स्थिति में चुनाव रद्द करने की शक्ति है।
III. यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों का निपटारा करता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

11. मतदाता पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के साथ किस प्रमुख प्रौद्योगिकी एकीकरण को अनिवार्य किया गया था?
(A) समेकित गणना के लिए टोटलाइज़र मशीनें
(B) वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) प्रणाली
(C) बायोमेट्रिक मतदाता प्रमाणीकरण प्रौद्योगिकी
(D) ब्लॉकचेन-आधारित सुरक्षित डिजिटल मतदान

12. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के निर्वाचन आयोग के साथ परिसीमन आयोग के संबंध का सबसे उपयुक्त वर्णन है?
(A) परिसीमन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सीधे नियंत्रण में कार्य करने वाला एक अधीनस्थ निकाय है।
(B) परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके पदेन सदस्य होते हैं।
(C) सीमा-निर्धारण चरण के दौरान परिसीमन आयोग निर्वाचन आयोग का स्थान ले लेता है।
(D) परिसीमन आयोग निर्वाचन आयोग के निर्णयों के विरुद्ध एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है।

13. भारत में संवैधानिक निकायों के चुनावी क्षेत्राधिकार से संबंधित सही युग्म की पहचान कीजिए।
(A) भारत का निर्वाचन आयोग - राज्य विधान परिषदें
(B) राज्य निर्वाचन आयोग - राज्य विधानसभाएं
(C) भारत का निर्वाचन आयोग - जिला योजना समितियां
(D) राज्य निर्वाचन आयोग - छावनी बोर्ड

14. भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से कौन-सा चुनाव संचालित नहीं करता है?
(A) भारत के राष्ट्रपति का चुनाव
(B) भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव
(C) राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव
(D) राज्य विधान परिषदों का चुनाव

NODIA

15. भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): संविधान ने सेवानिवृत्त निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा आगे की किसी भी नियुक्ति से वंचित नहीं किया है।
कारण (R): भारत का निर्वाचन आयोग एक सलाहकार निकाय है, स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी नहीं।
सही विकल्प का चयन कीजिए:
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

16. स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे?
(A) टी. एन. शेषन
(B) के. वी. के. सुंदरम
(C) सुकुमार सेन
(D) एस. पी. सेन वर्मा

17. भारत में चुनावी विवादों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: संविधान का अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को स्पष्ट रूप से वर्जित करता है।
कथन II: निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित किसी भी विधि की वैधता पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(A) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है और कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

18. निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत, राज्य विधानसभा चुनाव में पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किस शर्त को पूरा करना आवश्यक है?
(A) कुल वैध मतों का कम से कम 4% प्राप्त करना और 1 सीट जीतना
(B) विधानसभा की कुल सीटों में से कम से कम 10% सीटें जीतना
(C) बिना कोई सीट जीते, कुल वैध मतों का कम से कम 8% प्राप्त करना

37. भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 किस तिथि को पूर्ण रूप से लागू हुआ?
(A) 15 अगस्त 2005
(B) 12 अक्टूबर 2005
(C) 26 जनवरी 2006
(D) 1 अप्रैल 2005

38. RTI अधिनियम, 2005 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग की अधिकतम अनुमत संरचना क्या है?
(A) एक मुख्य सूचना आयुक्त और 5 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं
(B) एक मुख्य सूचना आयुक्त और ठीक 10 सूचना आयुक्त
(C) एक अध्यक्ष और चार सदस्य
(D) एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त

39. भारत में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति की संरचना का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है?
(A) प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता संयुक्त रूप से।
(B) प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक मनोनीत कैबिनेट मंत्री।
(C) भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एक नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।
(D) प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त रूप से।

40. भारत में सूचना के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): सूचना का अधिकार भारत के संविधान द्वारा अंतर्निहित रूप से गारंटीकृत है।
कारण (R): उच्चतम न्यायालय ने जानने के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भाग के रूप में व्याख्यायित किया है।
सही विकल्प का चयन कीजिए:
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

41. आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2(h) के अनुसार, निम्नलिखित में से किसे "लोक प्राधिकारी" नहीं माना जाता है?
(A) संविधान द्वारा या उसके तहत स्थापित या गठित कोई भी निकाय
(B) संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा स्थापित कोई भी निकाय
(C) समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधियों द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठन
(D) बिना किसी सरकारी सहायता के निजी ट्रस्ट द्वारा स्थापित पूर्णतः निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय

42. RTI अधिनियम, 2005 की कौन-सी धारा सूचना के प्रकटन से छूट से स्पष्ट रूप से संबंधित है?
(A) धारा 4
(B) धारा 6
(C) धारा 8
(D) धारा 20

43. सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: इसने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल पांच वर्ष निश्चित करने के लिए 2005 के आरटीआई अधिनियम में संशोधन किया।
कथन II: इसने केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों की पदावधि, वेतन और भत्ते निर्धारित करने का अधिकार दिया।
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(A) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है और कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

44. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
(A) व्यक्तिगत नागरिकों को कथित भ्रष्ट आचरण के लिए सरकारी अधिकारियों पर सीधे अभियोग चलाने में सक्षम बनाना।
(B) पारदर्शिता को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना और सरकार को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाना।
(C) न्यायिक प्रणाली से बाहर एक वैकल्पिक समानांतर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।
(D) सभी आंतरिक मंत्रिमंडल विचार-विमर्श प्रक्रियाओं को अनिवार्य रूप से सीधे सार्वजनिक वेबसाइटों पर प्रकाशित करना।

45. केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. जांच करते समय, आयोग के पास व्यक्तियों को समन भेजने और उनकी उपस्थिति लागू कराने के संबंध में सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं।
II. इसके पास दस्तावेजों की खोज और निरीक्षण की अपेक्षा करने की शक्ति है।
III. यह किसी भी ऐसे अभिलेख की जांच कर सकता है जिस पर आरटीआई अधिनियम लागू होता है, और ऐसा कोई भी अभिलेख किसी भी आधार पर इससे रोका नहीं जा सकता है।
IV. यह किसी दोषी जन सूचना अधिकारी को कठोर कारावास की सजा सुना सकता है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

Downloaded from www.pdf.tube

की लेखापरीक्षा करता है।
कथन II: CAG संसद का एक अधिकारी होता है और वह राष्ट्रपति के प्रति नहीं, बल्कि सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होता है।
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(A) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है और कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

28. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) और लोक लेखा समिति (PAC) के बीच संबंध का सही वर्णन करता है?
(A) CAG लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है।
(B) CAG की नियुक्ति सीधे लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है।
(C) CAG लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
(D) CAG सीधे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

29. 1976 में, CAG के कर्तव्यों के संबंध में केंद्र सरकार के वित्तीय प्रशासन में एक बड़ा सुधार प्रस्तुत किया गया था। वह क्या था?
(A) CAG को केंद्र सरकार के लेखा संकलन के कर्तव्यों से मुक्त करना।
(B) राज्यों में व्यापक पर्यावरण लेखापरीक्षा करने के लिए CAG को सशक्त बनाना।
(C) प्रमुख निजी क्षेत्र के निगमों की लेखापरीक्षा करने के लिए CAG को वैधानिक शक्ति प्रदान करना।
(D) सभी स्थानीय स्व-सरकार की लेखापरीक्षा करने की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी CAG को सौंपना।

30. केंद्रीय खातों पर CAG की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के प्रक्रमण में शामिल चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए।
1. CAG राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
2. लोक लेखा समिति रिपोर्ट की जांच करती है।
3. राष्ट्रपति रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं।
4. PAC अपने निष्कर्ष संसद को प्रस्तुत करती है।

(A) 1, 3, 2, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 3, 1, 2, 4
(D) 2, 1, 3, 4

31. भारत में किसी राज्य के खातों से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक किसे प्रस्तुत करते हैं?
(A) भारत के राष्ट्रपति को
(B) राज्य के मुख्यमंत्री को
(C) राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को
(D) राज्य के राज्यपाल को

32. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को पद से हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस आधार का सिद्ध होना आवश्यक है?
(A) संविधान का उल्लंघन या दिवालियापन
(B) संसद के विश्वास का अभाव
(C) साबित कदाचार या असमर्थता
(D) कार्यालय में वित्तीय अनियमितता

33. CAG द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाने वाली लेखापरीक्षा रिपोर्टों के प्रकारों के संबंध में असत्य युग्म की पहचान कीजिए।
(A) विनियोग खातों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट - यह जांच करती है कि क्या धन इच्छित उद्देश्यों पर खर्च किया गया था।
(B) मौद्रिक नीति पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट - भारतीय रिज़र्व बैंक के रेपो दर निर्णयों का मूल्यांकन करती है।
(C) वित्त खातों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट - संघ की वार्षिक प्राप्तियों और संवितरणों को दर्शाती है।
(D) सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट - वैधानिक निगमों के वाणिज्यिक कामकाज की जांच करती है।

34. निम्नलिखित में से कौन-सा व्यय CAG द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन नहीं है?
(A) भारत की संचित निधि से सभी परिचालन व्यय
(B) प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि से वार्षिक व्यय
(C) भारत के लोक लेखे से कुल सार्वजनिक व्यय
(D) कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा अधिकृत गुप्त सेवा व्यय

35. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वह उस प्रारूप के निर्धारण के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है जिसमें केंद्र और राज्यों के खाते रखे जाएंगे।
II. वह किसी कर या शुल्क के शुद्ध आगमों को अभिनिश्चित और प्रमाणित करता है।
III. उसके पास बजट अनुमानों से अधिक व्यय को मंजूरी देने का अधिकार है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

36. भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत, संघ और राज्यों के खाते किस प्रारूप में रखे जाएंगे, यह कौन निर्धारित करता है?
(A) स्वतंत्र रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(B) भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री
(C) CAG की सलाह पर राष्ट्रपति
(D) संसदीय लोक लेखा समिति

NODIA

अध्याय 12
संघ के संवैधानिक एवं वैधानिक निकाय

1. भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है?
   (A) अनुच्छेद 324
   (B) अनुच्छेद 328
   (C) अनुच्छेद 330
   (D) अनुच्छेद 332

2. भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
   (A) इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चार निर्वाचन आयुक्त होते हैं।
   (B) निर्वाचन आयुक्तों की संख्या संविधान द्वारा निश्चित की गई है और इसे बदला नहीं जा सकता।
   (C) 1950 में अपनी स्थापना के समय से ही यह एक बहु-सदस्यीय निकाय रहा है।
   (D) राष्ट्रपति समय-समय पर निर्वाचन आयुक्तों की संख्या निर्धारित करते हैं।

3. भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को पद से हटाने की प्राथमिक प्रक्रिया क्या है?
   (A) उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर, जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है
   (B) मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा
   (C) साधारण बहुमत से राज्यसभा द्वारा पारित संकल्प द्वारा
   (D) भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा

4. भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए।
   (A) निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है।
   (B) मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
   (C) संविधान निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए आवश्यक विशिष्ट शैक्षणिक योग्यताओं को निर्धारित करता है।
   (D) किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जा सकता है।

5. भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता (MCC) किस समय से लागू होती है?
   (A) उस तिथि से जब निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है
   (B) राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि से
   (C) अभ्यर्थी द्वारा उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि से
   (D) मतदान के प्रथम चरण से ठीक 30 दिन पहले

6. भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   कथन I: भारत का निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में पंजीकृत और मान्यता देने वाला एकमात्र प्राधिकारी है।
   कथन II: यदि कोई पंजीकृत राजनीतिक दल आम चुनाव में कोई सीट जीतने में असफल रहता है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
   निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
   (A) कथन I सही है और कथन II गलत है।
   (B) कथन I गलत है और कथन II सही है।
   (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
   (D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

7. भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिए निर्धारित पदावधि क्या है?
   (A) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो
   (B) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो
   (C) 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो
   (D) 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो

8. भारत में चुनावी शासन के संदर्भ में, 'आदर्श आचार संहिता' शब्द का मुख्य रूप से क्या अर्थ है?
   (A) चुनावी अपराधों को नियंत्रित करने के लिए संसद द्वारा पारित नियमों का एक वैधानिक समूह।
   (B) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 324 के तहत प्रदान किया गया एक संवैधानिक अधिदेश।
   (C) आचरण को विनियमित करने के लिए राजनीतिक दलों के बीच सहमति से विकसित दिशानिर्देश।
   (D) चुनाव अवधि के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा जारी कार्यकारी आदेशों का एक समूह।

Click Here to Buy book on Amazon

(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, II और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

46. निम्नलिखित में से कौन-सा संगठन आरटीआई अधिनियम, 2005 की अनुसूची II (अधिनियम से छूट प्राप्त संगठन) में सूचीबद्ध नहीं है?
(A) रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW)
(B) इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB)
(C) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
(D) सीमा सुरक्षा बल (BSF)

47. आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत, यदि मांगी गई सूचना किसी तृतीय पक्ष से संबंधित है या उसके द्वारा प्रदान की गई है और उस तृतीय पक्ष द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, तो जन सूचना अधिकारी का क्या कर्तव्य है?
(A) गोपनीय तृतीय पक्ष की सूचना शामिल होने के आधार पर आरटीआई आवेदन को सीधे निरस्त कर दें।
(B) अधिकतम सार्वजनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए तुरंत मांगी गई जानकारी प्रदान करें।
(C) अंतिम निपटान के लिए पूरा आरटीआई आवेदन सीधे संबंधित तृतीय पक्ष को स्थानांतरित करें।
(D) उत्तर/अभ्यावेदन आमंत्रित करने के लिए 5 दिनों के भीतर तृतीय पक्ष को सूचित करें।

48. आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत जन सूचना अधिकारी (PIO) द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने के लिए निर्धारित सामान्य समय-सीमा क्या है?
(A) अनुरोध प्राप्त होने से 15 दिन
(B) अनुरोध प्राप्त होने से 30 दिन
(C) अनुरोध प्राप्त होने से 45 दिन
(D) अनुरोध प्राप्त होने से 60 दिन

49. यदि आरटीआई अनुरोध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो सूचना कितने समय के भीतर प्रदान की जानी चाहिए?
(A) 24 घंटे
(B) 48 घंटे
(C) 72 घंटे
(D) 5 दिन

50. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए।
सूची I: (RTI के प्रावधान)
P. धारा 4
Q. धारा 6
R. धारा 19
S. धारा 20
सूची II: (विवरण)
1. सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध
2. अपील
3. शास्तियां
4. लोक प्राधिकारियों द्वारा स्वतः संज्ञान से सूचना का प्रकटन
(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-1, Q-4, R-3, S-2
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

51. आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत शास्ती प्रणाली के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए।
(A) आवेदन लेने से इंकार करने पर शास्ती - 250 रुपये प्रति दिन, अधिकतम 25,000 रुपये तक
(B) भ्रामक सूचना देने पर शास्ती - सरकारी सेवा से अनिवार्य निलंबन
(C) अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश - प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेशित की जा सकती है
(D) यह साबित करने का भार कि अस्वीकृति उचित थी - आरटीआई आवेदक पर होता है

52. आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: आरटीआई अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी उसी लोक प्राधिकारी के भीतर केंद्रीय/राज्य जन सूचना अधिकारी से वरिष्ठ रैंक का अधिकारी होता है।
कथन II: प्रथम अपील का निपटारा सामान्यतः अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(A) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है और कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

NODIA

53. निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सूचना आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर है?
(A) राज्य विधानसभा का सचिवालय
(B) केंद्र सरकार का एक मंत्रालय
(C) केंद्र सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
(D) राष्ट्रपति सचिवालय

54. केंद्रीय स्तर पर, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए कौन-सा मंत्रालय/विभाग नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है?
(A) गृह मंत्रालय
(B) विधि और न्याय मंत्रालय
(C) प्रधानमंत्री कार्यालय
(D) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

55. भारत में लोकपाल संस्था की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित घटनाक्रमों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:

(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

91. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, किस तिथि को लागू हुआ?
(A) 24 अप्रैल 1993
(B) 1 जून 1993
(C) 2 अक्टूबर 1992
(D) 24 अप्रैल 1994

92. 73वां संशोधन प्रत्येक राज्य में पंचायती राज की त्रि-स्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है। हालांकि, एक निश्चित सीमा से अधिक जनसंख्या न होने वाले राज्य को मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के गठन से छूट दी गई है। यह जनसंख्या सीमा क्या है?
(A) 10 लाख
(B) 20 लाख
(C) 30 लाख
(D) 50 लाख

93. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243G के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) पंचायतों को स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने की शक्तियां प्रदान करता है।
(B) प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना को अनिवार्य बनाता है।
(C) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है।
(D) स्थानीय स्व-सरकार के खातों के लेखापरीक्षा के लिए विस्तृत वैधानिक तंत्र निर्धारित करता है।

94. निम्नलिखित में से कौन-सा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का एक ऐच्छिक (वैकल्पिक) प्रावधान है, अनिवार्य नहीं?
(A) मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव।
(B) सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के लिए पांच वर्ष का कार्यकाल अनिवार्य रूप से निश्चित करना।
(C) कर लगाने और एकत्र करने के लिए पंचायतों को वित्तीय शक्तियां सौंपना।
(D) सभी पंचायतों में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से कम से कम एक-तिहाई सीटों का अनिवार्य आरक्षण।

95. निम्नलिखित कार्यात्मक विषयों पर विचार कीजिए:
I. कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है।
II. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण भी है।
III. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
IV. अग्निशमन सेवाएं।
उपर्युक्त में से कौन-से कार्यात्मक विषय पंचायतों को सौंपी गई संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

96. अनुच्छेद 243D के तहत पंचायतों में सीटों के आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की संख्या के कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
कथन II: राज्य विधानमंडल पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण को एक-तिहाई से अधिक नहीं बढ़ा सकता है।
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(A) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है और कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

97. भारत में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा करने या उसमें सुधार के सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन नहीं किया गया था?
(A) बलवंत राय मेहता समिति
(B) स्वर्ण सिंह समिति
(C) अशोक मेहता समिति
(D) एल. एम. सिंघवी समिति

98. पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में, "ग्राम सभा" की परिभाषा क्या है?
(A) गांव की सीमाओं के भीतर रहने वाले सभी स्थायी वयस्क निवासियों की एक सभा।
(B) ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्राथमिक निर्वाचित कार्यकारी शासी समिति।
(C) गांव के विकास की निगरानी के लिए प्रखंड विकास अधिकारियों द्वारा नियुक्त एक सलाहकार समिति।
(D) पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट ग्राम से संबंधित मतदाता सूचियों में पंजीकृत व्यक्तियों से बना निकाय।

99. भारत के संविधान का अनुच्छेद 243K निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
(A) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के लिए निर्वाचन
(B) राज्य वित्त आयोग का गठन और कार्य
(C) स्थानीय चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर स्पष्ट रोक
(D) पंचायतों के खातों के लेखापरीक्षा से संबंधित प्रावधान

100. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए।

Downloaded from www.pdf.tube

(C) तेलंगाना
(D) ओडिशा

65. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के संबंध में निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 सभी राज्यों में लोकायुक्तों की स्थापना का अनिवार्य प्रावधान करता है।
कारण (R): राज्य सरकारें केंद्रीय विधायी जनादेश के बिना आंतरिक भ्रष्टाचार को प्रबंधित करने में असमर्थ पाई गईं।
सही विकल्प का चयन कीजिए:
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

66. लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक को किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई?
(A) 2011
(B) 2012
(C) 2013
(D) 2014

67. लोकपाल के सदस्यों की संरचनात्मक योग्यताओं के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए।
(A) न्यायिक सदस्य - पूर्व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(B) अध्यक्ष - अनिवार्य रूप से वर्तमान मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होने चाहिए
(C) गैर-न्यायिक सदस्य - भ्रष्टाचार विरोधी नीति में कम से कम 15 वर्षों का विशेष अनुभव होना चाहिए
(D) कुल प्रतिनिधित्व - कुल नियुक्त सदस्यों में से कम से कम 33% अनिवार्य रूप से महिलाएं होनी चाहिए

68. लोकपाल के "जांच विंग" की क्या भूमिका है?
(A) भ्रष्ट लोक सेवकों पर सीधे उच्चतम न्यायालय के समक्ष अभियोग चलाना।
(B) अंतिम आपराधिक निर्णय देने वाली एक विशेष त्वरित अदालत के रूप में कार्य करना।
(C) लोक सेवकों द्वारा किए गए कथित अपराधों की प्रारंभिक जांच करना।
(D) अभियुक्त अधिकारियों की सभी जब्त परिसंपत्तियों और संपत्तियों का प्रबंधन और सुरक्षा करना।

69. लोकपाल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: वाद लंबित रहने के दौरान भी लोकपाल के पास भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त संपत्ति, आगम और लाभों को जब्त करने की शक्ति है।
कथन II: लोकपाल के पास भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े लोक सेवकों के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है।
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(A) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है और कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

70. लोकपाल और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के बीच संबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. लोकपाल द्वारा सीबीआई को सौंपे गए मामलों के लिए लोकपाल के पास सीबीआई पर अधीक्षण की शक्ति है।
II. लोकपाल द्वारा भेजे गए मामले की जांच करने वाले सीबीआई अधिकारियों का स्थानांतरण लोकपाल की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है।
III. लोकपाल जुड़े मामलों में तलाशी और जब्ती अभियानों के लिए सीबीआई को अधिकृत कर सकता है।
IV. लोकपाल सीबीआई के लिए संपूर्ण वित्तपोषण और बजट प्रदान करता है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

71. लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए निर्धारित पदावधि क्या है?
(A) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो
(B) 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो
(C) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो
(D) 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो

72. लोकपाल द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच शुरु करने के लिए निम्नलिखित में से किस शर्त का पूरा होना आवश्यक है?
(A) जांच शुरू करने के लिए लोकपाल के सभी वर्तमान सदस्यों का साधारण बहुमत का निर्णय पर्याप्त है।
(B) कोई भी प्रारंभिक जांच शुरु करने से पहले भारत के राष्ट्रपति को औपचारिक पूर्व स्वीकृति देनी होगी।
(C) कम से कम दो-तिहाई बहुमत से लोकपाल की पूर्ण पीठ द्वारा अनुमोदन।
(D) भारत का उच्चतम न्यायालय एकत्र किए गए प्रारंभिक साक्ष्यों की स्वतंत्र रूप से समीक्षा और अनुमोदन करेगा।

NODIA

I. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम का अधिनियमन।
II. प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा लोकपाल के लिए सिफारिश।
III. लोकसभा में पहली बार लोकपाल विधेयक पेश किया जाना।
IV. भारत द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का अनुसमर्थन।
(A) II, III, IV, I
(B) III, II, IV, I
(C) II, IV, III, I
(D) III, IV, II, I

56. भारत में किस आयोग ने सबसे पहले लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की स्पष्ट रुप से सिफारिश की थी?
(A) कोठारी आयोग (1964)
(B) भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति (1962)
(C) प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)
(D) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005)

57. "ओम्बुड्समैन" की अवधारणा, जिस पर लोकपाल आधारित है, सबसे पहले किस देश में उत्पन्न हुई थी?
(A) यूनाइटेड किंगडम
(B) न्यूज़ीलैंड
(C) फ्रांस
(D) स्वीडन

58. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुसार लोकपाल की संरचना के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होंगे।
(B) एक अध्यक्ष और नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले निश्चित अधिकतम 4 सदस्य।
(C) एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, जिनमें प्रत्येक भारतीय राज्य का अनिवार्य प्रतिनिधित्व होगा।
(D) पूरी तरह से सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से बना एक निकाय।

59. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत, भारत के प्रधानमंत्री को लोकपाल के क्षेत्राधिकार में लाया गया है। हालांकि, लोकपाल प्रधानमंत्री के खिलाफ निम्नलिखित में से किससे संबंधित आरोपों की जांच नहीं कर सकता है?
(A) विभागों में सिविल सेवकों और न्यायिक अधिकारियों की उच्च-स्तरीय प्रशासनिक नियुक्तियां।
(B) अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, लोक व्यवस्था और अंतरिक्ष।
(C) राष्ट्रीय चुनाव अभियानों के दौरान लिए गए नीतिगत फैसले और दिए गए भाषण।
(D) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के प्रबंधन से संबंधित वित्तीय निर्णय।

60. लोकपाल के क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसका क्षेत्राधिकार संसद के सभी सदस्यों पर है।
II. इसका क्षेत्राधिकार केंद्र सरकार के समूह A, B, C और D के अधिकारियों और कर्मचारियों पर है।
III. इसका क्षेत्राधिकार 10 लाख रुपये से अधिक का विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाली किसी भी सोसाइटी या ट्रस्ट पर है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

61. भारतीय संदर्भ में, 'लोकायुक्त' को किस प्रकार सर्वोत्तम परिभाषित किया जा सकता है?
(A) लोक सेवकों की जांच करने वाला एक राज्य-स्तरीय भ्रष्टाचार विरोधी ओम्बुड्समैन।
(B) केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की जांच के लिए स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का भ्रष्टाचार विरोधी ओम्बुड्समैन।
(C) प्रत्येक सरकारी प्रशासनिक कार्यालय के भीतर नियुक्त एक आंतरिक विभागीय सतर्कता अधिकारी।
(D) केवल लोक सेवक भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए नियुक्त एक विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट।

62. निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति का सदस्य नहीं है?
(A) प्रधानमंत्री
(B) लोकसभा अध्यक्ष
(C) राज्यसभा में विपक्ष के नेता
(D) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के कोई न्यायाधीश

63. लोकपाल के लिए खोज समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: चयन समिति उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने में सहायता के लिए एक खोज समिति का गठन कर सकती है।
कथन II: खोज समिति के कम से कम 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होंगे।
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(A) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है और कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

64. केंद्रीय 2013 अधिनियम से पहले लोकायुक्त संस्था को पारित करने या स्थापित करने वाले शुरुआती राज्यों में निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य शामिल नहीं था?
(A) महाराष्ट्र
(B) राजस्थान

Click Here to Buy book on Flipkart

(B) प्रधानमंत्री
(C) केंद्रीय गृह मंत्री
(D) भारत के मुख्य न्यायाधीश

82. 2019 के संशोधन के बाद NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए संशोधित पदावधि क्या है?
(A) 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक
(B) 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक
(C) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक
(D) 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक

83. NHRC और राज्य मानव अधिकार आयोग (SHRC) के बीच क्षेत्राधिकार विभाजन से संबंधित सही युग्म की पहचान कीजिए।
(A) SHRC - राज्य और समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित उल्लंघनों की जांच करता है
(B) SHRC - सभी राज्यों में विशेष रूप से संघ सूची के तहत उल्लंघनों की जांच करता है
(C) NHRC - एक साथ हस्तक्षेप कर सकता है भले ही SHRC पहले से ही मामले की जांच कर रहा हो
(D) NHRC - सभी स्थानीय पंचायत स्तर की शिकायतों पर विशेष कानूनी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है

84. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार "मानव अधिकार" की सबसे उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से कौन-सी है?
(A) भारत की संसद द्वारा अनुसमर्थित अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत कड़ाई से गारंटीकृत नागरिक और राजनीतिक अधिकार।
(B) विशेष रूप से भारत के संविधान के भाग III के तहत परिगणित मौलिक अधिकार जो रिट द्वारा प्रवर्तनीय हैं।
(C) संविधान या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं द्वारा गारंटीकृत जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार जो न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।
(D) विशिष्ट संवैधानिक प्रावधानों की परवाह किए बिना वैश्विक स्तर पर सभी मनुष्यों में अंतर्निहित मौलिक प्राकृतिक अधिकार।

85. संस्थानों का दौरा करने की NHRC की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. NHRC राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी भी जेल का निरीक्षण कर सकता है।
II. NHRC ऐसे किसी भी संस्थान का निरीक्षण कर सकता है जहाँ व्यक्तियों को इलाज, सुधार या संरक्षण के लिए रखा जाता है।
III. NHRC को किसी भी राज्य जेल का निरीक्षण करने से पहले उच्चतम न्यायालय के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

86. NHRC के अध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: NHRC के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
कथन II: कदाचार के आधार पर कार्रवाई करने से पहले राष्ट्रपति को हटाने के मामले की जांच के लिए मामला उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करना होगा।
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(A) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है और कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

87. निम्नलिखित में से किस संवैधानिक या वैधानिक निकाय का प्रमुख NHRC का पदेन सदस्य नहीं है?
(A) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष
(B) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष
(C) दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त
(D) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष

88. सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकार उल्लंघनों की शिकायतों से निपटने में NHRC द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?
(A) NHRC सशस्त्र बलों के खिलाफ स्वतंत्र रूप से पूर्ण सीबीआई जांच का आदेश दे सकता है।
(B) NHRC के पास सैन्य कर्मियों को सीधे समन भेजने, जांच करने और गिरफ्तार करने की पूरी शक्ति है।
(C) केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगना और सिफारिशें करना।
(D) NHRC कानूनन सशस्त्र बल कर्मियों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त करने से पूरी तरह से वर्जित है।

89. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
(A) मुंबई
(B) जेनेवा
(C) कोलकाता
(D) नई दिल्ली

90. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के संबंध में निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): मानव अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा NHRC की अक्सर बाध्यकारी शक्तियों के बिना एक सलाहकार निकाय के रूप में आलोचना की जाती है।
कारण (R): इसकी सिफारिशें संबंधित सरकार या प्राधिकारी पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं।
सही विकल्प का चयन कीजिए:

Downloaded from www.pdf.tube

(A) राज्य वित्त आयोग
(B) नीति आयोग
(C) केवल केंद्रीय वित्त आयोग
(D) राज्य निर्वाचन आयोग

110. राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राज्य निर्वाचन आयोग में पंचायतों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित है।
II. राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य विधानमंडल और स्थानीय निकायों दोनों के चुनाव कराने का अधिकार है।
III. राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

111. स्वतंत्र भारत में 1959 में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन-सा था?
(A) आंध्र प्रदेश
(B) महाराष्ट्र
(C) गुजरात
(D) राजस्थान

112. राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: राज्य का राज्यपाल प्रत्येक पांच वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है।
कथन II: पंचायतों के संसाधनों को पूरक बनाने के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के उपायों का सुझाव देने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग के पास कोई भूमिका या अधिदेश नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(A) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है और कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

113. निम्नलिखित में से कौन-सा पंचायती राज संस्थाओं के लिए राजस्व का स्रोत नहीं है?
(A) संपत्ति और स्थानीय बाजारों पर कर
(B) निगम कर
(C) पंचायतों द्वारा प्रबंधित सड़कों पर पथकर
(D) राज्य सरकार से सहायता अनुदान

114. भारत में शहरी स्थानीय निकायों की शब्दावली के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए।
(A) अधिसूचित क्षेत्र समिति - विशेष रूप से पूरी तरह से विकसित बड़े शहर के लिए राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा बनाई गई
(B) पोर्ट ट्रस्ट - प्रमुख नागरिक हवाई अड्डों के आसपास नागरिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए स्थापित
(C) विशेष उद्देश्य एजेंसी - महानगरों के सभी प्रशासनिक और कार्यकारी कार्यों को प्रबंधित करने के लिए स्थापित
(D) नगर क्षेत्र समिति - छोटे नगरों का प्रशासन करती है

115. भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): वित्तीय स्वायत्तता भारत में पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।
कारण (R): राज्य सरकारें आमतौर पर स्थानीय निकायों को पर्याप्त कराधान शक्तियां और वित्तीय संसाधन सौंपने में अनिच्छुक रही हैं।
सही विकल्प का चयन कीजिए:
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

116. शहरी स्थानीय निकायों के रूप में कार्यरत छावनी बोर्ड अन्य नगरपालिकाओं से भिन्न हैं क्योंकि वे:
(A) आपातकालीन प्रशासनिक प्रावधानों के तहत सीधे राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा शासित होते हैं।
(B) पूरी तरह से स्वायत्त निजी संस्थाएं हैं जिन्हें विशेष रूप से सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के अधिकारियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
(C) एक केंद्रीय अधिनियम के तहत बनाए गए हैं और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित होते हैं।
(D) संवैधानिक संशोधनों द्वारा बनाए गए हैं और सीधे राज्य निर्वाचन आयोग के दायरे में रखे गए हैं।

NODIA

117. अनुच्छेद 243M के तहत, 73वें संशोधन (पंचायती राज) के प्रावधान कुछ राज्यों और क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा उस अनुच्छेद में उल्लिखित छूट प्राप्त राज्यों में से एक नहीं है?
(A) सिक्किम
(B) नागालैंड
(C) मेघालय
(D) मिजोरम

118. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) को अधिनियमित करने का उद्देश्य क्या था?
(A) सभी निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों को स्थानीय स्व-सरकार के किसी भी वैधानिक रूप से पूरी तरह से छूट देना।
(B) पारंपरिक जनजातीय परिषदों को पूरी तरह से मनोनीत कार्यकारी प्रशासनिक निकायों से बदलना।
(C) यह अनिवार्य करना कि राज्य के राज्यपाल स्थानीय

सूची I: (अनुच्छेद)
P. अनुच्छेद 243A
Q. अनुच्छेद 243D
R. अनुच्छेद 243I
S. अनुच्छेद 243K
सूची II: (प्रावधान)
1. राज्य निर्वाचन आयोग
2. ग्राम सभा
3. राज्य वित्त आयोग
4. सीटों का आरक्षण
(A) P-2, Q-4, R-3, S-1
(B) P-4, Q-2, R-1, S-3
(C) P-2, Q-3, R-4, S-1
(D) P-1, Q-4, R-3, S-2

101. भारत में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित असत्य युग्म की पहचान कीजिए।
(A) छावनी बोर्ड - किसी औद्योगिक टाउनशिप के लिए
(B) नगर पंचायत - ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तनशील (संक्रमणकालीन) क्षेत्र के लिए
(C) नगरपालिका परिषद - छोटे शहरी क्षेत्र के लिए
(D) नगर निगम - बड़े शहरी क्षेत्र के लिए

102. अनुच्छेद 243ZD के तहत गठित जिला योजना समिति (DPC) का संवैधानिक अधिदेश क्या है?
(A) पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच क्षेत्राधिकार सीमा विवादों को निपटाने के लिए एक वैधानिक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।
(B) जिले के सभी शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के वित्तीय खातों की व्यापक रूप से लेखापरीक्षा और समीक्षा करना।
(C) जिला स्थानीय निकायों को भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान सीधे आवंटित और वितरित करना।
(D) पंचायत और नगरपालिका योजनाओं को समेकित करना और जिला विकास योजना का प्रारूप तैयार करना।

103. महानगर योजना समिति (MPC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रत्येक महानगर क्षेत्र में एक महानगर योजना समिति होनी चाहिए।
कथन II: ऐसी समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से निर्वाचित होंगे।
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(A) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है और कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

104. निम्नलिखित में से कौन-सा विषय संविधान की बारहवीं अनुसूची (नगरपालिकाओं को सौंपे गए विषय) में सूचीबद्ध नहीं है?
(A) नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन
(B) अग्निशमन सेवाएं
(C) लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलसम्भर विकास
(D) शव गाड़ना और कब्रिस्तान, दाह-क्रिया और श्मशान स्थल

105. भारत सरकार द्वारा पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों के गठन का सही कालानुक्रमिक क्रम चुनिए।
1. जी. वी. के. राव समिति
2. बलवंत राय मेहता समिति
3. एल. एम. सिंघवी समिति
4. अशोक मेहता समिति
(A) 2, 4, 1, 3
(B) 2, 1, 4, 3
(C) 4, 2, 3, 1
(D) 2, 4, 3, 1

106. यदि किसी पंचायत को समय से पहले भंग कर दिया जाता है, तो उसके विघटन की तिथि से कितनी अधिकतम अवधि के भीतर नई पंचायत गठित करने के लिए चुनाव पूरे हो जाने चाहिए?
(A) 1 माह
(B) 3 माह
(C) 6 माह
(D) 1 वर्ष

107. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, कितनी जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन अनिवार्य है?
(A) 1 लाख या अधिक
(B) 2 लाख या अधिक
(C) 3 लाख या अधिक
(D) 5 लाख या अधिक

108. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद 243-I के तहत राज्य वित्त आयोग की भूमिका का सही वर्णन करता है?
(A) यह राज्य का वार्षिक वित्तीय बजट तैयार करता है और इसे सीधे विधानसभा में प्रस्तुत करता है।
(B) पंचायत के वित्त की समीक्षा करता है और राज्य-पंचायत कर वितरण सिद्धांतों की सिफारिश करता है।
(C) यह सभी ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्व-सरकारों के खातों की वार्षिक वित्तीय लेखापरीक्षा करता है।
(D) यह निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन और भत्ते के ढांचे का निर्धारण और पुनरीक्षण करता है।

109. स्थानीय निकायों के वित्तपोषण के संदर्भ में, राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान कानूनी रूप से किस निकाय की सिफारिशों के तहत प्रदान किया जाता है?

Click Here to Buy book on Amazon

केवल संसद द्वारा की जा सकती है।
(C) निर्वाचित कार्यपालिका को पूरी तरह से बदलने के लिए गैर-निर्वाचित निकायों की व्यवस्थित स्थापना।
(D) नियंत्रण और संतुलन द्वारा सीमित सरकार।

128. भारत में निम्नलिखित निकायों को उनकी स्थापना के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
II. भारत का निर्वाचन आयोग
III. केंद्रीय सूचना आयोग
IV. लोकपाल संस्था (केंद्रीय स्तर पर)
(A) II, I, III, IV
(B) II, III, I, IV
(C) I, II, III, IV
(D) II, I, IV, III

129. 1990 के दशक के दौरान, भारत के निर्वाचन आयोग के कामकाज में किस मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में परिवर्तनकारी चुनावी सुधार हुए?
(A) सुकुमार सेन
(B) टी. एन. शेषन
(C) एम. एस. गिल
(D) जे. एम. लिंगदोह

130. निम्नलिखित में से कौन-सी रिपोर्ट भारत की संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक नहीं है?
(A) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट
(B) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट
(C) केंद्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट
(D) किसी राज्य की वार्षिक राज्य वित्त आयोग रिपोर्ट

NODIA

चुनाव कराए बिना सीधे ग्राम पंचायतों का प्रशासन करें।
(D) आवश्यक संशोधनों के साथ संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना।

119. राज्य निर्वाचन आयुक्त की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, संविधान अनिवार्य करता है कि उन्हें हटाया जा सकता है:
(A) मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद के प्रसादपर्यंत।
(B) केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर, जिस रीति और आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
(C) विधायी भागीदारी के बिना राज्यपाल के एक कार्यकारी आदेश द्वारा।
(D) राज्य कैबिनेट द्वारा एक प्रत्यक्ष प्रशासनिक स्थानांतरण द्वारा।

120. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए:
I. इसने भारत के संविधान में भाग IX-A जोड़ा।
II. इसने नगरपालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक विषयों वाली बारहवीं अनुसूची पेश की।
III. इसने वार्ड समितियों का गठन अनिवार्य किया।
IV. इसने शहरी पुलिस का नियंत्रण नगर निगमों को हस्तांतरित कर दिया।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, II और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

121. भारत में निम्नलिखित निकायों में से कौन-सा वैधानिक निकाय के बजाय स्पष्ट रूप से एक संवैधानिक निकाय है?
(A) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
(B) केंद्रीय सूचना आयोग
(C) लोकपाल संस्था
(D) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

122. विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1997) के ऐतिहासिक फैसले में, उच्चतम न्यायालय ने किस जांच निकाय की स्वतंत्रता और कामकाज से संबंधित दिशानिर्देश निर्धारित किए थे?
(A) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)
(B) राज्य निर्वाचन आयोग
(C) भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
(D) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

123. CAG और संसद को जोड़ने वाली जवाबदेही व्यवस्था के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) CAG के पास सीधे लोकसभा में धन विधेयक पेश करने का संवैधानिक अधिकार है।
(B) लोक लेखा समिति कार्यपालिका को वित्तीय रूप से जवाबदेह ठहराने के लिए CAG की लेखापरीक्षा रिपोर्टों का उपयोग करती है।
(C) वार्षिक बजट पारित करने से पहले संसद को CAG से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
(D) CAG संसद द्वारा पारित कराधान कानूनों की संवैधानिक वैधता का औपचारिक रूप से मूल्यांकन करता है।

124. निम्नलिखित में से कौन-सी संस्था अपना जनादेश संविधान के किसी विशिष्ट अनुच्छेद के बजाय संसद के अधिनियम से प्राप्त करती है?
(A) भारत का निर्वाचन आयोग
(B) केंद्रीय सूचना आयोग
(C) राज्य वित्त आयोग
(D) राज्य निर्वाचन आयोग

125. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए।
सूची I: (स्वतंत्र/वैधानिक निकाय)
P. केंद्रीय सूचना आयोग
Q. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
R. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
S. भारत का निर्वाचन आयोग
सूची II: (प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए नोडल मंत्रालय/विभाग)
1. वित्त मंत्रालय
2. विधि एवं न्याय मंत्रालय
3. गृह मंत्रालय
4. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(A) P-4, Q-3, R-1, S-2
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-4, Q-1, R-3, S-2
(D) P-2, Q-3, R-1, S-4

126. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) किसी भी संसदीय कानून से मुक्त एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है।
कथन II: CIC की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के माध्यम से की गई थी, जो इसे एक वैधानिक निकाय बनाता है।
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(A) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है और कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

127. लोकतांत्रिक शासन के संदर्भ में "संविधानवाद" की परिभाषा क्या है?
(A) त्वरित कार्यकारी निर्णय लेने के लिए निरपेक्ष केंद्रीकृत प्राधिकार का समर्थन करने वाली विचारधारा।
(B) यह सिद्धांत कि संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या

Downloaded from www.pdf.tube

73. भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) का गठन हुआ?
(A) 1990
(B) 1992
(C) 1993
(D) 1995

74. मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए कौन पात्र है?
(A) भारत के कोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
(B) केवल वही व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रहा हो
(C) उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त वरिष्ठ न्यायाधीश
(D) मानव अधिकारों के क्षेत्र में प्रख्यात कोई विशिष्ट व्यक्ति

75. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए।
सूची I: (वैधानिक आयोग)
P. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
Q. राष्ट्रीय महिला आयोग
R. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
S. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
सूची II: (NHRC से जुड़ाव)
1. 2019 संशोधन द्वारा NHRC के पदेन सदस्य के रूप में जोड़ा गया
2. मूल 1993 अधिनियम के तहत अध्यक्ष एक पदेन सदस्य है
3. वंचित लिंग के अधिकारों से संबंधित है, पदेन सदस्य
4. दलितों के अधिकारों से संबंधित है, पदेन सदस्य
(A) P-2, Q-3, R-4, S-1
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

76. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) की संरचना के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) सभी शिकायतों की सख्त कानूनी जांच सुनिश्चित करने के लिए NHRC में विशेष रूप से न्यायिक सदस्य होते हैं।
(B) मानव अधिकारों की विशेषज्ञता वाले तीन सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला हो।
(C) NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव सीधे संसद के संयुक्त सत्र द्वारा किया जाता है।
(D) NHRC के अध्यक्ष 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने की निश्चित अवधि के लिए पद धारण करते हैं।

77. यदि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) राज्य के पुलिस अधिकारी द्वारा मानव अधिकारों के कथित उल्लंघन की जांच करता है और इसे सही पाता है, तो NHRC सीधे क्या कार्रवाई कर सकता है?
(A) संबंधित सरकार को अभियोग चलाने की सिफारिश करना।
(B) आपराधिक कानून के तहत दोषी पुलिस अधिकारी को सीधे कारावास की सजा सुनाना।
(C) अधिकारी के मासिक वेतन से सीधे क्षतिपूर्ति राशि काटना।
(D) अधिकारी को सरकारी प्रशासनिक सेवा से पदच्युत करने का बाध्यकारी आदेश जारी करना।

NODIA

78. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: NHRC उस तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकता जिस तिथि को मानव अधिकारों का कथित उल्लंघन हुआ था।
कथन II: सरकारी तंत्र पर निर्भर रहे बिना सभी शिकायतों की जांच के लिए NHRC के पास अपना स्वतंत्र, पूर्ण जांच कर्मचारी वर्ग है।
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(A) कथन I सही है और कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है और कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

79. निम्नलिखित में से कौन-सी शक्ति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में निहित नहीं है?
(A) साक्षियों को समन भेजना और उनकी उपस्थिति लागू कराना तथा शपथ पर उनकी जांच करना
(B) किसी भी दस्तावेज की खोज और उसे पेश करवाना
(C) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी लोक अभिलेख की मांग करना
(D) मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को मौद्रिक अर्थदंड से दंडित करना

80. निम्नलिखित में से कौन-सा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) का अनिवार्य कार्य नहीं है?
(A) बंदियों की रहने की स्थिति का अध्ययन करने के लिए जेलों या हिरासत केंद्रों का निरीक्षण करना।
(B) आतंकवाद के कृत्यों सहित उन कारकों की समीक्षा करना जो मानव अधिकारों के उपभोग में बाधा डालते हैं।
(C) न्यायसंगत धन वितरण सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक नीति की समीक्षा करना।
(D) किसी न्यायालय की सहमति से उसके समक्ष लंबित मानव अधिकार उल्लंघन के किसी भी मामले में हस्तक्षेप करना।

81. NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा बहु-सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन इस समिति की अध्यक्षता करता है?
(A) भारत के राष्ट्रपति

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (A) अनुच्छेद 324
भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु एक स्वायत्त तथा स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडलों, भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करने और संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण करने का कार्य करता है।

2. (D) राष्ट्रपति समय-समय पर निर्वाचन आयुक्तों की संख्या निर्धारित करते हैं।
भारत के संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करें। यद्यपि 1950 में यह एक-सदस्यीय निकाय था, परंतु 1989 और पुनः 1993 से इसे बहु-सदस्यीय निकाय में परिवर्तित कर दिया गया। संविधान में आयुक्तों की संख्या निश्चित नहीं की गई है, वरन यह शक्ति राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखी गई है।

3. (A) उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर, जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाने के लिए संविधान में कड़े सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं। उन्हें पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर केवल साबित कदाचार या असमर्थता पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है।

4. (C) संविधान निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए आवश्यक विशिष्ट शैक्षणिक योग्यताओं को निर्धारित करता है।
भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए कोई विशिष्ट कानूनी, शैक्षणिक या प्रशासनिक योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई हैं। इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्त निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा आगे की नियुक्तियों से भी प्रतिबंधित नहीं किया गया है। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल की सुरक्षा और अन्य सदस्यों को उनकी सिफारिश पर ही हटाने जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि स्वायत्तता बनी रहे।

5. (A) उस तिथि से जब निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है
आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देशों का एक समूह है। यह उस तिथि से तुरंत लागू हो जाती है जिस दिन निर्वाचन आयोग प्रेस वार्ता में चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा करता है। यह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना और संसाधनों का दुरुपयोग रोकना है।

6. (A) कथन I सही है और कथन II गलत है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत भारत का निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने वाला एकमात्र प्राधिकारी है। हालांकि, यदि कोई पंजीकृत दल आम चुनाव में कोई सीट नहीं जीत पाता है, तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द नहीं होता है। किसी दल का पंजीकरण केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों जैसे धोखाधड़ी या असंवैधानिक गतिविधियों की स्थिति में ही रद्द किया जा सकता है।

7. (B) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, निर्धारित किया गया है। वे किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं या कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व हटाए जा सकते हैं। उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और सुविधाएं मिलती हैं।

8. (C) आचरण को विनियमित करने के लिए राजनीतिक दलों के बीच सहमति से विकसित दिशानिर्देश।
आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को विनियमित करने के लिए स्वयं राजनीतिक दलों के बीच सहमति से विकसित दिशानिर्देशों का एक समूह है। यह कोई वैधानिक कानून नहीं है, बल्कि एक नैतिक संहिता है जिसे निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य चुनावी अनुशासन बनाए रखना है।

9. (D) पंचायतों और नगरपालिकाओं के पदों के लिए चुनाव कराना
भारत का निर्वाचन आयोग केवल संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। स्थानीय निकायों जैसे पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के तहत गठित संबंधित राज्य निर्वाचन आयोगों की होती है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनावों का संचालन नहीं करता है, क्योंकि यह राज्य आयोग का कार्य है।

10. (A) केवल I और II
भारत का निर्वाचन आयोग परिसीमन आयोग अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर देश भर में निर्वाचन क्षेत्रों के प्रादेशिक क्षेत्रों का निर्धारण करता है। इसके पास धांधली, बूथ कैप्चरिंग या हिंसा की स्थिति में किसी चुनाव को रद्द करने की पूर्ण शक्ति होती है। हालांकि, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवादों

Click Here to Buy book on Flipkart

तैयार करने और चुनाव कराने का संपूर्ण अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान सुरक्षा प्राप्त है।

100. (A) P-2, Q-4, R-3, S-1
संविधान के भाग IX में पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेदों का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 243A ग्राम सभा के गठन और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 243D पंचायतों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243I राज्य वित्त आयोग के गठन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 243K राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है।

101. (A) छावनी बोर्ड - किसी औद्योगिक टाउनशिप के लिए
भारत में शहरी स्थानीय निकायों का गठन क्षेत्र की जनसांख्यिकीय और प्रशासनिक विशेषताओं के आधार पर होता है। नगर पंचायत संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए, नगरपालिका परिषद छोटे शहरी क्षेत्र के लिए और नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्र के लिए होती है। छावनी बोर्ड का गठन औद्योगिक टाउनशिप के लिए नहीं, बल्कि रक्षा छावनी क्षेत्रों में नागरिक आबादी का प्रशासन चलाने के लिए किया जाता है।

102. (D) पंचायत और नगरपालिका योजनाओं को समेकित करना और जिला विकास योजना का प्रारूप तैयार करना।
संविधान के अनुच्छेद 243ZD के अनुसार, प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति (DPC) का गठन किया जाना अनिवार्य है। इस समिति का मुख्य संवैधानिक दायित्व जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं को समेकित करना और संपूर्ण जिले के लिए एक एकीकृत जिला विकास योजना का प्रारूप तैयार करके राज्य सरकार को भेजना होता है।

103. (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
अनुच्छेद 243ZE के तहत, प्रत्येक महानगर क्षेत्र में एक समग्र विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए महानगर योजना समिति (MPC) का गठन किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के अनुसार, इस समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य महानगर क्षेत्र की नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से ही निर्वाचित किए जाते हैं ताकि स्थानीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

104. (C) लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलसम्भर विकास
74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं को सौंपे गए 18 कार्यात्मक विषय शामिल हैं, जैसे शहरी नियोजन, अग्निशमन सेवाएं, और कब्रिस्तान या श्मशान स्थल। हालांकि, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलसम्भर विकास का विषय ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है और इसे संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के तहत पंचायतों के कार्यात्मक दायरे में शामिल किया गया है।

105. (A) 2, 4, 1, 3
भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विकास और समीक्षा के लिए गठित समितियों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है: बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था, अशोक मेहता समिति 1977 में बनी, जी. वी. के. राव समिति का गठन 1985 में किया गया, और एल. एम. सिंघवी समिति 1986 में गठित की गई थी, जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की पुरजोर सिफारिश की थी।

106. (C) 6 माह
संविधान के अनुच्छेद 243E के तहत पंचायतों का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यदि किसी पंचायत को 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले समय से पूर्व भंग या विघटित कर दिया जाता है, तो विघटन की तिथि से 6 महीने की अवधि के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। हालांकि, यदि शेष कार्यकाल 6 महीने से कम बचा हो, तो नया चुनाव कराना आवश्यक नहीं होता।

107. (C) 3 लाख या अधिक
74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 243S में यह अनिवार्य प्रावधान किया गया है कि जिन नगरपालिकाओं की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, उनके क्षेत्राधिकार के भीतर एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाना आवश्यक होगा। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी स्थानीय शासन में नागरिकों की सीधी भागीदारी और जन-सुनवाई को बढ़ावा देना है।

108. (B) पंचायत के वित्त की समीक्षा करता है और राज्य-पंचायत कर वितरण सिद्धांतों की सिफारिश करता है।
अनुच्छेद 243-I के तहत, राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। इस आयोग का मुख्य कार्य पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना तथा राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, चुंगी और शुल्कों के शुद्ध आगमों का राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वितरण के सिद्धांतों के संबंध में राज्यपाल को सिफारिशें प्रस्तुत करना है।

NODIA

109. (A) राज्य वित्त आयोग
संविधान के अनुच्छेद 243I के तहत गठित राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही राज्य सरकार की संचित निधि में से पंचायतों और नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। राज्य वित्त आयोग उन सिद्धांतों का निर्धारण करता है जिनके आधार पर स्थानीय निकायों को वित्तीय संसाधन हस्तांतरित किए जाते हैं ताकि वे अपनी प्रशासनिक और विकास संबंधी आवश्यकताओं को सुचारु रूप से पूरा कर सकें।

110. (C) केवल I और III
संविधान के अनुच्छेद 243K के तहत राज्य निर्वाचन आयोग में पंचायतों और नगरपालिकाओं के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त

22. (D) केंद्र या राज्य सरकारों के अधीन किसी भी आगे के पद के लिए अपात्र होते हैं।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को निष्पक्षता प्रदान करने के लिए संविधान में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि वे अपना पद छोड़ने या सेवानिवृत्त होने के पश्चात् भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी आगे के पद के लिए पूरी तरह अपात्र हो जाते हैं। इससे बिना किसी प्रलोभन के स्वतंत्र कार्यप्रणाली सुनिश्चित होती है।

23. (B) PAC संसद के समक्ष रखे गए CAG के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की जांच करती है।
लोक लेखा समिति संसद की एक महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है जो संसद के समक्ष प्रस्तुत किए गए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की गहन जांच करती है। CAG समिति की बैठकों में उपस्थित होकर तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। इसी निकट सहयोग के कारण CAG को लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है।

24. (C) केंद्र सरकार के खातों को संकलित करना और उनका रखरखाव करना।
1976 में हुए विभागीयकरण सुधारों के बाद केंद्र सरकार के खातों के संकलन और रख-रखाव का कार्य CAG से अलग करके अन्य सेवा को सौंप दिया गया था। वर्तमान में CAG केंद्र सरकार के खातों का संकलन नहीं करता, बल्कि केवल खातों की स्वतंत्र लेखापरीक्षा करता है। हालांकि राज्यों के स्तर पर लेखा संकलन का कार्य CAG द्वारा ही होता है।

25. (A) P-4, Q-2, R-3, S-1
भारतीय संविधान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से संबंधित प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 148 CAG की नियुक्ति और सेवा शर्तों का निर्धारण करता है। अनुच्छेद 149 CAG के कर्तव्यों तथा शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 खातों के प्रारूप का निर्धारण करता है, जबकि अनुच्छेद 151 के तहत CAG अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है।

26. (A) भारतीय रिज़र्व बैंक
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सार्वजनिक निकायों की लेखापरीक्षा संबंधी शक्तियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक जैसे वित्तीय निकायों की प्रत्यक्ष लेखापरीक्षा CAG द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि निजी व्यावसायिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। CAG केवल अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है अथवा विशिष्ट परिस्थितियों में ही संसदीय समीक्षा हेतु विशेष प्रतिवेदन की मांग कर सकता है।

27. (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों की संचित निधि से होने वाले व्यय तथा प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करता है। CAG संसद का एक अधिकारी होता है और वह वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संसद की ओर से ही कार्य करता है। वह कार्यपालिका के प्रति नहीं, बल्कि सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होता है ताकि जवाबदेही बनी रहे।

28. (A) CAG लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है।
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और लोक लेखा समिति के बीच अत्यंत घनिष्ठ संबंध होता है। CAG को लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। जब लोक लेखा समिति संसद में CAG की रिपोर्टों की जांच करती है, तब CAG समिति को जटिल वित्तीय मामलों को समझने में महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।

NODIA

29. (A) CAG को केंद्र सरकार के लेखा संकलन के कर्तव्यों से मुक्त करना।
वर्ष 1976 में केंद्र सरकार के वित्तीय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण सुधार किया गया था, जिसके तहत लेखांकन को लेखापरीक्षा से पृथक कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप CAG को केंद्र सरकार के खातों को संकलित करने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया और यह कार्य नागरिक लेखा सेवा को सौंपा गया। अब CAG केवल लेखापरीक्षा कार्य ही संभालता है।

30. (A) 1, 3, 2, 4
केंद्रीय खातों पर CAG की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रक्रिया निर्धारित चरणों में पूरी होती है। सर्वप्रथम CAG अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तत्पश्चात राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। इसके बाद लोक लेखा समिति रिपोर्ट की जांच करती है और अंत में अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है।

31. (D) राज्य के राज्यपाल को
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार, भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक किसी राज्य के खातों से संबंधित अपनी वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। इसके पश्चात् राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। तत्पश्चात् राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति उस रिपोर्ट की विस्तृत जांच और समीक्षा का कार्य संपन्न करती है।

32. (C) साबित कदाचार या असमर्थता
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को पद की पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है। उन्हें उनके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। CAG को पद से हटाने के दो ही संवैधानिक आधार हैं: साबित कदाचार या असमर्थता। इसके लिए संसदीय संकल्प अनिवार्य है।

33. (B) मौद्रिक नीति पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट - भारतीय रिज़र्व बैंक के रेपो दर निर्णयों का मूल्यांकन करती है।
CAG मुख्य रूप से तीन प्रकार की लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है: विनियोग खातों पर, वित्त खातों पर और सार्वजनिक उपक्रमों पर। मौद्रिक नीति और रेपो दर संबंधी निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, और CAG मौद्रिक नीति

नामक दो स्वतंत्र संस्थाएं स्थापित करने की स्पष्ट सिफारिश की थी।

57. (D) स्वीडन
'ओम्बुड्समैन' की संस्थागत अवधारणा सबसे पहले 1809 में स्वीडन में उत्पन्न हुई थी, जहाँ इसका गठन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक स्वतंत्र सरकारी प्रतिनिधि के रूप में किया गया था। बाद में इस मॉडल को दुनिया भर के कई देशों द्वारा अपनाया गया, जिसके आधार पर भारत में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं का ढांचा विकसित किया गया।

58. (A) एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होंगे।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, लोकपाल एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य शामिल हो सकते हैं। इन 8 सदस्यों में से कम से कम 50% अनिवार्य रूप से न्यायिक सदस्य होंगे। इसके अलावा, कुल सदस्यों में से कम से कम 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होने चाहिए।

59. (B) अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, लोक व्यवस्था और अंतरिक्ष।
2013 का अधिनियम भारत के प्रधानमंत्री को लोकपाल के क्षेत्राधिकार में लाता है। हालांकि, लोकपाल प्रधानमंत्री के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष से जुड़े मामलों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच शुरु करने के लिए लोकपाल की पूर्ण पीठ के दो-तिहाई बहुमत की स्वीकृति आवश्यक होती है।

60. (D) I, II और III
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत लोकपाल का क्षेत्राधिकार अत्यंत व्यापक है। इसमें प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के सभी मंत्री, संसद के सभी सदस्य (सांसद), तथा केंद्र सरकार के समूह A, B, C और D के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा, 10 लाख रुपये से अधिक का वार्षिक विदेशी योगदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं, ट्रस्टों या सोसाइटियों के पदाधिकारी भी इसके दायरे में आते हैं।

61. (A) लोक सेवकों की जांच करने वाला एक राज्य-स्तरीय भ्रष्टाचार विरोधी ओम्बुड्समैन।
भारतीय प्रशासनिक और कानूनी ढांचे में 'लोकायुक्त' एक राज्य-स्तरीय भ्रष्टाचार विरोधी ओम्बुड्समैन संस्था है, जिसे राज्य सरकार के लोक सेवकों, मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और कुशासन के आरोपों की जांच के लिए गठित किया जाता है। राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने 2013 के केंद्रीय अधिनियम से बहुत पहले ही अपने राज्यों में लोकायुक्त संस्था स्थापित कर ली थी।

62. (C) राज्यसभा में विपक्ष के नेता
लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक उच्चस्तरीय चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। इस पांच-सदस्यीय चयन समिति में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश), और एक प्रख्यात कानूनविद शामिल होते हैं। इसमें राज्यसभा में विपक्ष के नेता शामिल नहीं होते हैं।

63. (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
लोकपाल अधिनियम के तहत, चयन समिति लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करने हेतु एक खोज समिति का गठन कर सकती है। अधिनियम में यह अनिवार्य प्रावधान है कि खोज समिति के कम से कम 50% सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक समूहों और महिलाओं में से चयनित किए जाएंगे ताकि सामाजिक प्रतिनिधित्व बना रहे।

64. (C) तेलंगाना
2013 के केंद्रीय लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम से बहुत पहले ही कई भारतीय राज्यों ने लोकायुक्त संस्था की स्थापना कर ली थी। ओडिशा ने 1970 में सबसे पहले कानून पारित किया, जबकि महाराष्ट्र ने 1971 में लोकायुक्त की स्थापना की। इसके बाद राजस्थान ने भी 1973 में लोकायुक्त गठित किया। तेलंगाना राज्य का गठन 2014 में हुआ था, इसलिए वह शुरुआती राज्यों में शामिल नहीं था।

65. (C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 सभी राज्यों के लिए अधिनियम लागू होने के एक वर्ष के भीतर लोकायुक्त संस्था स्थापित करना अनिवार्य बनाता है। हालांकि, इसका कारण यह नहीं था कि राज्य सरकारें अक्षम थीं, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश में भ्रष्टाचार विरोधी एकसमान और एकीकृत कानूनी ढांचा तैयार करना था। अतः दिया गया अभिकथन सही है परंतु उसका कारण असत्य है।

66. (D) 2014
लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा दिसंबर 2013 में पारित किया गया था। इस ऐतिहासिक विधेयक को 1 जनवरी 2014 को भारत के राष्ट्रपति की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी और यह अधिनियम 16 जनवरी 2014 को प्रभावी रूप से लागू हुआ। इस अधिनियम ने भारत में उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक मजबूत संवैधानिक-वैधानिक संस्था का निर्माण किया।

67. (A) न्यायिक सदस्य - पूर्व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
लोकपाल के न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति का भारत के उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना आवश्यक है। अध्यक्ष के लिए भी यही योग्यताएं लागू होती हैं

Downloaded from www.pdf.tube

45. (A) केवल I, II और III
केंद्रीय सूचना आयोग के पास किसी शिकायत की जांच करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं, जिनमें व्यक्तियों को समन भेजना, दस्तावेजों की खोज एवं निरीक्षण करना तथा शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना शामिल है। आयोग आरटीआई लागू होने वाले किसी भी रिकॉर्ड की जांच कर सकता है। हालांकि, आयोग के पास किसी अधिकारी को कारावास की सजा सुनाने की कोई न्यायिक शक्ति नहीं होती है।

46. (C) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
RTI अधिनियम, 2005 की अनुसूची II में उन खुफिया और सुरक्षा संगठनों की सूची दी गई है जिन्हें अधिनियम के लागू होने से छूट प्राप्त है, जैसे RAW, IB और BSF। हालांकि, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) एक वित्तीय एवं राजस्व निकाय है और यह अनुसूची II में सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए इस पर RTI अधिनियम के प्रावधान सामान्य रूप से लागू होते हैं।

47. (D) उत्तर/अभ्यावेदन आमंत्रित करने के लिए 5 दिनों के भीतर तृतीय पक्ष को सूचित करें।
RTI अधिनियम, 2005 के अनुसार, यदि मांगी गई सूचना किसी तृतीय पक्ष से संबंधित है और उसने उसे गोपनीय माना है, तो जन सूचना अधिकारी को अनुरोध प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर उस तृतीय पक्ष को लिखित नोटिस देना अनिवार्य होता है। इसके बाद तृतीय पक्ष को 10 दिनों के भीतर अपना अभ्यावेदन या आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है।

48. (B) अनुरोध प्राप्त होने से 30 दिन
RTI अधिनियम, 2005 के तहत, जन सूचना अधिकारी (PIO) के लिए आरटीआई आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर मांगी गई सूचना प्रदान करना या कारण बताते हुए आवेदन को अस्वीकार करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यदि आवेदन सहायक जन सूचना अधिकारी के माध्यम से जमा किया जाता है, तो इस निर्धारित समय-सीमा में 5 अतिरिक्त दिन जोड़ दिए जाते हैं।

49. (B) 48 घंटे
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में यह विशेष प्रावधान किया गया है कि यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ऐसी तत्काल स्थिति में जन सूचना अधिकारी को सूचना अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर जानकारी प्रदान करनी होगी, ताकि जीवन या स्वतंत्रता की रक्षा में कोई विलंब न हो।

50. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 लोक प्राधिकारियों द्वारा स्वतः संज्ञान से सूचनाओं के प्रकटन से संबंधित है। धारा 6 नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया बताती है। धारा 19 प्रथम और द्वितीय अपील के प्रावधानों को निर्दिष्ट करती है, जबकि धारा 20 सूचना देने में देरी या इंकार करने वाले अधिकारियों पर शास्तियां लगाने का प्रावधान करती है।

51. (A) आवेदन लेने से इंकार करने पर शास्ती - 250 रुपये प्रति दिन, अधिकतम 25,000 रुपये तक
आरटीआई अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, यदि कोई जन सूचना अधिकारी बिना किसी वाजिब कारण के आवेदन लेने से मना करता है या सूचना देने में देरी करता है, तो सूचना आयोग उस पर 250 रुपये प्रति दिन की दर से शास्ती लगा सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी की जा सकती है।

NODIA

52. (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत, यदि आवेदक को समय पर सूचना न मिले या वह प्राप्त उत्तर से असंतुष्ट हो, तो वह उसी लोक प्राधिकारी के भीतर जन सूचना अधिकारी से वरिष्ठ रैंक के अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर कर सकता है। अधिनियम के अनुसार, इस प्रथम अपील का निपटारा अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर (विशेष परिस्थितियों में 45 दिन) किया जाना अनिवार्य है।

53. (A) राज्य विधानसभा का सचिवालय
केंद्रीय सूचना आयोग का क्षेत्राधिकार केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोक प्राधिकारियों तक ही सीमित है। राज्य विधानसभा का सचिवालय पूरी तरह से संबंधित राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, इसलिए इससे जुड़े आरटीआई मामलों का निपटारा राज्य सूचना आयोग द्वारा किया जाता है, न कि केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा।

54. (D) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
भारत में केंद्रीय स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन, नियमों के निर्माण और प्रशासनिक प्रबंधन के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाला कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह विभाग आरटीआई से संबंधित दिशा-निर्देश जारी करने और आयोग के प्रशासनिक कार्यों का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है।

55. (A) II, III, IV, I
भारत में लोकपाल संस्था के विकास में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) ने सबसे पहले इसकी सिफारिश की थी। इसके बाद 1968 में पहली बार लोकसभा में लोकपाल विधेयक पेश किया गया था। भारत ने 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का अनुसमर्थन किया, जिसके पश्चात व्यापक जन आंदोलन के बाद संसद द्वारा 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया।

56. (C) प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)
भारत में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने नागरिकों की शिकायतों के निवारण और उच्च प्रशासनिक पदों पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सबसे पहले स्कैंडिनेवियाई 'ओम्बुड्समैन' की तर्ज पर केंद्रीय स्तर पर 'लोकपाल' और राज्य स्तर पर 'लोकायुक्त'

पर कोई पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार या प्रस्तुत नहीं करता है। यह उसका कार्य नहीं है।

34. (D) कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा अधिकृत गुप्त सेवा व्यय
CAG भारत और राज्यों की संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे से होने वाले सभी व्ययों की लेखापरीक्षा करता है। हालांकि, गुप्त सेवा व्यय के मामले में, CAG प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत व्यय के विवरणों पर ही भरोसा करता है और कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा अधिकृत इस प्रकार के गुप्त सेवा व्ययों की विस्तृत लेखापरीक्षा या वाउचरों की जांच नहीं कर सकता है।

35. (A) केवल I और II
CAG राष्ट्रपति को उस प्रारूप के संबंध में सलाह देता है जिसमें केंद्र और राज्यों के खाते रखे जाएंगे। वह किसी कर या शुल्क के शुद्ध आगमों को अभिनिश्चित और प्रमाणित करता है। हालांकि, CAG के पास बजट अनुमानों से अधिक व्यय को मंजूरी देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अतिरिक्त व्यय को मंजूरी देने की शक्ति केवल संसद या संबंधित राज्य विधानमंडल के पास निहित होती है।

36. (C) CAG की सलाह पर राष्ट्रपति
भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, संघ और राज्यों के खाते किस प्रारूप में रखे जाएंगे, इसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की सलाह पर किया जाता है। यह प्रावधान केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर लेखांकन प्रणाली में एकरूपता, मानक प्रारूप और पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से संविधान में शामिल किया गया है।

37. (B) 12 अक्टूबर 2005
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 भारत की संसद द्वारा जून 2005 में पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी अधिकारियों से सूचना मांगने का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता और सरकार की जवाबदेही में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

38. (D) एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 12(2) के अनुसार, केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना में एक मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और ऐसे अन्य सूचना आयुक्त शामिल होते हैं जिनकी संख्या दस से अधिक नहीं होगी। इन आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक विशिष्ट प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सिफारिश समिति के आधार पर की जाती है।

39. (B) प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक मनोनीत कैबिनेट मंत्री।
मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक तीन-सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री (जो समिति के अध्यक्ष होते हैं), लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। यह समिति पारदर्शी और निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों का मूल्यांकन करती है।

40. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
सूचना का अधिकार संविधान में अंतर्निहित मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों में यह व्यवस्था दी है कि जानने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अभिन्न भाग है। इसलिए, नागरिकों को सरकारी कामकाज की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है।

41. (D) बिना किसी सरकारी सहायता के निजी ट्रस्ट द्वारा स्थापित पूर्णतः निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय
RTI अधिनियम, 2005 की धारा 2(h) के तहत "लोक प्राधिकारी" में संविधान या संसद/राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा स्थापित निकाय, तथा सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं। हालांकि, बिना किसी सरकारी वित्तीय सहायता या नियंत्रण के चलने वाले पूर्णतः निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों को लोक प्राधिकारी की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है।

42. (C) धारा 8
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 उन सूचनाओं से संबंधित है जिन्हें प्रकट करने से छूट प्राप्त है। इसके अंतर्गत भारत की प्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, रणनीतिक हित, विदेशी राज्यों के साथ संबंध, न्यायालय की अवमानना, और वाणिज्यिक गोपनीयता से जुड़ी सूचनाओं को सार्वजनिक करने से मना किया जा सकता है, यदि लोक हित से अधिक गोपनीयता आवश्यक हो।

43. (B) कथन I गलत है और कथन II सही है।
सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने सूचना आयुक्तों के पांच वर्ष के निश्चित कार्यकाल के प्रावधान को समाप्त कर दिया। इस संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की पदावधि, वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तों को नियमों के माध्यम से निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया। इस संशोधन ने आयोग की स्वायत्तता पर बहस छिड़ दी थी।

44. (B) पारदर्शिता को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना और सरकार को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाना।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र में नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और खुलेपन को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और सरकार तथा उसके विभागों को नागरिकों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाना है। यह अधिनियम आम नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास उपलब्ध जानकारी प्राप्त करने का एक प्रभावी तंत्र प्रदान करता है।

Click Here to Buy book on Amazon

या वह कोई प्रख्यात व्यक्ति हो सकता है। गैर-न्यायिक सदस्यों को भ्रष्टाचार विरोधी नीति और प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है।

68. (C) लोक सेवकों द्वारा किए गए कथित अपराधों की प्रारंभिक जांच करना।
लोकपाल के संस्थागत ढांचे में एक समर्पित "जांच विंग" का प्रावधान किया गया है, जिसकी अध्यक्षता एक निदेशक करता है। इस जांच विंग की प्राथमिक भूमिका लोकपाल को प्राप्त शिकायतों के आधार पर लोक सेवकों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कथित अपराधों की निष्पक्ष और त्वरित प्रारंभिक जांच करना है ताकि यह तय किया जा सके कि मामला पूर्ण जांच के योग्य है या नहीं।

69. (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
2013 के अधिनियम के अनुसार, लोकपाल को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। वाद के लंबित रहने के दौरान भी लोकपाल के पास भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित की गई परिसंपत्तियों, लाभों और संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क या जब्त करने का अधिकार है। इसके अलावा, लोकपाल भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे लोक सेवकों के तबादले या निलंबन की सिफारिश भी संबंधित प्राधिकारी से कर सकता है।

70. (A) केवल I, II और III
लोकपाल को उन मामलों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) पर अधीक्षण और दिशा-निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है जो लोकपाल द्वारा सीबीआई को सौंपे जाते हैं। लोकपाल की सहमति के बिना ऐसे मामलों की जांच करने वाले सीबीआई अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। लोकपाल तलाशी और जब्ती के लिए सीबीआई को अधिकृत कर सकता है, लेकिन सीबीआई का संपूर्ण बजट और वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा ही प्रदान किया जाता है।

71. (B) 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो
लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, निर्धारित किया गया है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वे लोकपाल में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं और न ही वे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य लाभ के पद को धारण कर सकते हैं।

72. (C) कम से कम दो-तिहाई बहुमत से लोकपाल की पूर्ण पीठ द्वारा अनुमोदन।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुसार, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के किसी आरोप की जांच या प्रारंभिक जांच शुरू करने के लिए विशेष सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं। इसके लिए लोकपाल की पूर्ण पीठ के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा अनुमोदन और निर्णय लिया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ऐसी जांच की सुनवाई बंद कमरे में आयोजित की जाती है।

73. (C) 1993
भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संसद द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 पारित किया गया था। यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 से प्रभावी हुआ (और अध्यादेश को कानून में बदला गया)। इसी अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) का एक स्वायत्त वैधानिक निकाय के रूप में गठन किया गया, जो देश में मानव अधिकारों का संरक्षक है।

74. (A) भारत के कोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 से पूर्व केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही NHRC के अध्यक्ष पद के लिए पात्र थे। हालांकि, 2019 के संशोधन के माध्यम से योग्यताओं के दायरे का विस्तार किया गया। अब भारत का कोई भी पूर्व मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के लिए पूरी तरह पात्र है।

75. (A) P-2, Q-3, R-4, S-1
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) की संरचना में विभिन्न राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्षों को पदेन सदस्यों के रूप में शामिल किया जाता है। मूल 1993 के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य थे। 2019 के संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग और दिव्यांगजनों के मुख्य आयुक्त को भी पदेन सदस्य बनाया गया।

76. (B) मानव अधिकारों की विशेषज्ञता वाले तीन सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला हो।
मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बाद NHRC में अध्यक्ष के अलावा पांच पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इनमें दो सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से (एक पूर्व न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय और एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय) होते हैं तथा तीन सदस्य मानव अधिकारों से संबंधित व्यावहारिक अनुभव या ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाते हैं, जिनमें कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य है।

77. (A) संबंधित सरकार को अभियोग चलाने की सिफारिश करना।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक मुख्य रूप से सिफारिशी और सलाहकार निकाय है। यदि अपनी जांच में आयोग किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन पाता है, तो NHRC स्वयं सीधे सजा नहीं सुना सकता। इसके बजाय, आयोग संबंधित सरकार को दोषी अधिकारी के खिलाफ कानूनी अभियोग चलाने, विभागीय कार्रवाई करने और पीड़ित को वित्तीय राहत प्रदान करने की सिफारिश प्रस्तुत करता है।

NODIA

78. (A) कथन I सही है और कथन II गलत है।
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 36(2) के अनुसार, NHRC किसी भी ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकता है जो मानव अधिकारों के कथित उल्लंघन की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के बाद उठाया गया हो। हालांकि, NHRC के पास पूरी तरह से अपना अलग जांच कर्मचारी वर्ग सीमित है और वह अक्सर जटिल जांच कार्यों के लिए केंद्र या राज्यों की सरकारी जांच एजेंसियों पर निर्भर रहता है।

79. (D) मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को मौद्रिक अर्थदंड से दंडित करना
NHRC को अपनी जांच प्रक्रिया संचालित करते समय दीवानी (सिविल) अदालत की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिनमें साक्षियों को समन भेजना, गवाही लेना, दस्तावेजों की खोज करना और लोक अभिलेख मंगाना शामिल है। हालांकि, आयोग के पास उल्लंघनकर्ताओं को सीधे दंडित करने, जेल भेजने या मौद्रिक अर्थदंड लगाने की कोई न्यायिक या दंडात्मक शक्ति नहीं है। यह केवल संबंधित सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है।

80. (C) न्यायसंगत धन वितरण सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक नीति की समीक्षा करना।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्य मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, जेलों और सुधार गृहों का निरीक्षण करना, मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा मानवाधिकार चेतना फैलाना है। देश की मौद्रिक नीति या धन के वितरण की समीक्षा करना भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्त मंत्रालय का कार्य है, यह मानवाधिकार आयोग के अनिवार्य कार्यों के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता है।

81. (B) प्रधानमंत्री
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक छः-सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। इस चयन समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। समिति के अन्य सदस्यों में लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति शामिल होते हैं।

82. (B) 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक
2019 में किए गए मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम के माध्यम से NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की अवधि को घटा दिया गया है। संशोधन के बाद अब अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर बने रहते हैं। इसके अलावा, 2019 संशोधन के बाद वे पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होते हैं।

83. (A) SHRC - राज्य और समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित उल्लंघनों की जांच करता है
राज्य मानव अधिकार आयोग (SHRC) केवल संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) और समवर्ती सूची (सूची III) में आने वाले विषयों से संबंधित मानव अधिकार उल्लंघनों की जांच कर सकता है। हालांकि, यदि किसी मामले की जांच पहले से ही NHRC या किसी अन्य वैधानिक आयोग द्वारा की जा रही है, तो SHRC उस मामले की जांच नहीं कर सकता है, जिससे क्षेत्राधिकार का दोहराव न हो।

84. (C) संविधान या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं द्वारा गारंटीकृत जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार जो न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(1)(d) के अनुसार, "मानव अधिकार" से संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में समाहित और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार अभिप्रेत हैं। यह व्यापक परिभाषा मानवाधिकारों को केवल नागरिक अधिकारों तक सीमित न रखकर व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता के सभी पहलुओं से जोड़ती है।

85. (A) केवल I और II
NHRC को राज्य सरकार के नियंत्रण में आने वाली किसी भी जेल, हिरासत केंद्र या अन्य संस्थान का निरीक्षण करने का अधिकार है जहाँ व्यक्तियों को उपचार, सुधार या संरक्षण के लिए रखा गया है। इसका उद्देश्य कैदियों के रहने की स्थिति का अध्ययन करना और सुधार की सिफारिश करना है। आयोग को जेलों का दौरा करने के लिए किसी न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।

86. (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
NHRC के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य को केवल राष्ट्रपति द्वारा सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है। हालांकि, राष्ट्रपति कदाचार के आधार पर कोई भी आदेश जारी करने से पहले मामले को जांच के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करते हैं। यदि उच्चतम न्यायालय जांच के बाद हटाने की सिफारिश करता है, तब राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकते हैं।

87. (B) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष
2019 के संशोधन के पश्चात NHRC में कुल सात पदेन सदस्य शामिल हैं: राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, अन्य पिछड़े वर्गों, और बाल अधिकार संरक्षण के लिए गठित राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त। हालांकि, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष NHRC के पदेन सदस्य नहीं हैं, क्योंकि उनका आयोग इस सूची में शामिल नहीं किया गया है।

88. (C) केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगना और सिफारिशें करना।
जब सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के कथित उल्लंघन की शिकायतें NHRC को प्राप्त होती हैं, तो आयोग की शक्तियाँ सीमित होती हैं। अधिनियम की धारा 19 के तहत, आयोग स्वयं सीधे जांच करने के बजाय केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगता है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आयोग अपनी सिफारिशें

Downloaded from www.pdf.tube

सरकार को भेजता है और केंद्र सरकार तीन महीने के भीतर की गई कार्रवाई से आयोग को अवगत कराती है।

89. (D) नई दिल्ली
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम आयोग को भारत में केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से अन्य स्थानों पर भी अपने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की कानूनी शक्ति प्रदान करता है, यद्यपि इसका मुख्य प्रशासनिक केंद्र नई दिल्ली में ही स्थित 'मानव अधिकार भवन' में संचालित होता है।

90. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को अक्सर आलोचकों द्वारा "दंतहीन बाघ" कहा जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। आयोग द्वारा की गई सिफारिशें संबंधित सरकारों या प्राधिकरणों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं। NHRC स्वयं कोई अंतिम सजा देने या अपने निर्णयों को सीधे लागू कराने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।

91. (A) 24 अप्रैल 1993
73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, जिसने भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और स्थायित्व प्रदान किया, 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ था। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को "राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस" के रूप में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इस संशोधन ने संविधान में नया भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी।

92. (B) 20 लाख
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार देश भर में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायती राज की त्रि-स्तरीय प्रणाली का अनिवार्य प्रावधान किया गया है। हालांकि, अधिनियम के अनुच्छेद 243B में यह विशेष छूट दी गई है कि जिस राज्य की कुल जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन न करने का विकल्प उपलब्ध रहता है।

93. (A) पंचायतों को स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने की शक्तियां प्रदान करता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G राज्य विधानमंडलों को पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार सौंपने की अनुमति देता है जो उन्हें स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। इसमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी शामिल है।

94. (C) कर लगाने और एकत्र करने के लिए पंचायतों को वित्तीय शक्तियां सौंपना।
73वें संशोधन अधिनियम में अनिवार्य और स्वेच्छिक दो प्रकार के प्रावधान शामिल हैं। त्रि-स्तरीय प्रणाली की स्थापना, 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल, और महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य प्रावधान हैं। हालांकि, पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर लगाने और एकत्र करने की वित्तीय शक्तियां प्रदान करना राज्य विधानमंडलों के लिए एक स्वेच्छिक (वैकल्पिक) प्रावधान है, जो पूरी तरह राज्यों की इच्छा पर निर्भर है।

95. (A) केवल I, II और III
संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के दायरे में आने वाले 29 कार्यात्मक विषय सूचीबद्ध हैं। इनमें कृषि और कृषि विस्तार, ग्रामीण विद्युतीकरण, तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) स्पष्ट रूप से शामिल हैं। हालांकि, अग्निशमन सेवाएं पंचायतों की ग्यारहवीं अनुसूची का भाग नहीं हैं, बल्कि यह विषय संविधान की बारहवीं अनुसूची के तहत नगरपालिकाओं (शहरी स्थानीय निकायों) को सौंपा गया है।

96. (A) कथन I सही है और कथन II गलत है।
संविधान के अनुच्छेद 243D के अनुसार, सभी स्तरों पर पंचायतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होना अनिवार्य है। हालांकि, यह न्यूनतम सीमा है, और राज्य विधानमंडलों को महिलाओं के लिए आरक्षण को 50% तक बढ़ाने का पूर्ण अधिकार है, जैसा कि बिहार, मध्य प्रदेश और कई राज्यों ने किया है।

97. (B) स्वर्ण सिंह समिति
बलवंत राय मेहता समिति (1957), अशोक मेहता समिति (1977) और एल. एम. सिंघवी समिति (1986) सभी भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विकास, पुनर्गठन और संवैधानिक सशक्तिकरण से संबंधित थीं। इसके विपरीत, स्वर्ण सिंह समिति (1976) का गठन भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश करने के उद्देश्य से किया गया था, इसका पंचायती राज से कोई संबंध नहीं था।

98. (D) पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट ग्राम से संबंधित मतदाता सूचियों में पंजीकृत व्यक्तियों से बना निकाय।
अनुच्छेद 243(b) के अनुसार, "ग्राम सभा" से तात्पर्य ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से बने निकाय से है। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का सबसे प्राथमिक और प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक अंग है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है तथा ग्राम पंचायत के कार्यों, व्यय और विकास योजनाओं की निगरानी करता है।

99. (A) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के लिए निर्वाचन
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243K पंचायतों के चुनावों के निष्पक्ष संचालन से संबंधित है। यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि पंचायतों के लिए सभी निर्वाचनों की मतदाता सूचियां

NODIA

का निपटारा संविधान के तहत केवल उच्चतम न्यायालय ही करता है।

11. (B) वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) प्रणाली
भारत के उच्चतम न्यायालय ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं के विश्वास को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल प्रणाली के एकीकरण को अनिवार्य किया था। यह प्रणाली मतदाता को एक कागजी पर्ची के माध्यम से यह सत्यापित करने की सुविधा देती है कि उसका मत सही दर्ज हुआ है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है।

12. (B) परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके पदेन सदस्य होते हैं।
परिसीमन आयोग एक उच्चस्तरीय निकाय है जिसकी स्थापना भारत के राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत की जाती है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। परिसीमन आयोग का मुख्य कार्य हाल की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना है ताकि समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

13. (A) भारत का निर्वाचन आयोग - राज्य विधान परिषदें
भारत का निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानमंडलों के चुनावों का संचालन करता है। दूसरी ओर, राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243K के तहत केवल स्थानीय स्व-सरकारों जैसे पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए उत्तरदायी है। इसलिए राज्य विधान परिषद का चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग के ही अधिकार क्षेत्र में आता है।

14. (C) राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव
भारत का निर्वाचन आयोग देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानमंडलों के चुनावों का संचालन करता है। हालांकि, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित नहीं किया जाता है। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव स्वयं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही सदन के आंतरिक नियमों के अनुसार प्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है।

15. (C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
भारतीय संविधान में सेवानिवृत्त निर्वाचन आयुक्तों को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आगे किसी भी नियोजन से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, जो कि एक संवैधानिक विशेषता है। हालांकि, भारत का निर्वाचन आयोग कोई महज सलाहकार निकाय नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र तथा स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकारी है जो देश में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु सर्वोच्च अधिकार धारण करता है।

16. (C) सुकुमार सेन
सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, जिन्होंने 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान ही भारत के ऐतिहासिक प्रथम दो आम चुनाव सफलता पूर्वक आयोजित किए गए थे। उन्होंने भारतीय चुनावी व्यवस्था की मजबूत नींव रखी और विशाल लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रक्रिया को स्थापित किया।

17. (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर स्पष्ट रोक लगाता है। इसके तहत परिसीमन या निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी चुनाव को केवल निर्धारित चुनाव याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है।

18. (D) कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करना और कम से कम 2 सीटें जीतना
निर्वाचन प्रतीक आदेश, 1968 के तहत किसी पंजीकृत दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए विभिन्न शर्तों में से एक शर्त यह है कि उसने संबंधित राज्य की विधानसभा चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त किया हो और साथ ही कम से कम 2 सीटें जीती हों।

19. (A) अनुच्छेद 148
भारत के संविधान के भाग V के अंतर्गत अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान किया गया है। CAG को भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख तथा सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें पद की पूर्ण सुरक्षा भी प्रदान की गई है।

20. (A) केवल I, II और III
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। संसद उनके वेतन और सेवा शर्तों को निर्धारित करती है। हालांकि, CAG कार्यालय के सभी प्रशासनिक व्यय, जिनमें वेतन और भत्ते शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, न कि आकस्मिकता निधि पर।

21. (A) सार्वजनिक व्यय की बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और मितव्ययिता की जांच करना।
औचित्य लेखापरीक्षा से तात्पर्य नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाने वाली उस विशेष जांच से है जिसमें केवल नियमों के पालन तक सीमित न रहकर यह देखा जाता है कि सार्वजनिक व्यय में बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और मितव्ययिता का पालन हुआ है या नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी धन का कोई अनुचित अपव्यय बिल्कुल न होने पाए।

Click Here to Buy book on Flipkart

की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। हालांकि, राज्य विधानमंडल के चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की होती है, राज्य निर्वाचन आयोग केवल स्थानीय निकायों के चुनाव कराता है।

111. (D) राजस्थान
स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक शुभारंभ सबसे पहले राजस्थान राज्य में हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जयंती के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु ने राजस्थान के नागौर जिले में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन किया था। इसके तुरंत बाद, 1959 में ही आंध्र प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य बना।

112. (A) कथन I सही है और कथन II गलत है।
अनुच्छेद 243I के तहत राज्य के राज्यपाल प्रत्येक पांच वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। हालांकि, केंद्रीय वित्त आयोग की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है; संविधान के अनुच्छेद 280(3)(bb) के अनुसार, केंद्रीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों को पूरक बनाने के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करता है।

113. (B) निगम कर
पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व के मुख्य स्रोतों में स्थानीय संपत्तियों, मेलों और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर, सड़कों और पुलों पर पथकर (टोल), तथा राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला सहायता अनुदान शामिल हैं। निगम कर (कॉरपोरेट टैक्स) एक प्रत्यक्ष कर है जो केंद्र सरकार द्वारा कंपनियों की आय पर लगाया और एकत्र किया जाता है, यह पंचायतों के राजस्व का स्रोत नहीं है।

114. (D) नगर क्षेत्र समिति - छोटे नगरों का प्रशासन करती है
भारत में नगर क्षेत्र समिति (Town Area Committee) का गठन छोटे नगरों के नागरिक प्रशासन के लिए राज्य विधानमंडल के एक विशेष अधिनियम द्वारा किया जाता है। यह एक अर्ध-नगरपालिका निकाय होता है जिसे सीमित नागरिक कार्य जैसे सफाई, पथ प्रकाश और नाली निर्माण का दायित्व सौंपा जाता है। अधिसूचित क्षेत्र समिति तीव्र गति से विकसित हो रहे नए या औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बनाई जाती है।

115. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
भारत में पंचायती राज संस्थाएं संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बावजूद वित्तीय स्वायत्तता की गंभीर चुनौती का सामना कर रही हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि अधिकांश राज्य सरकारें अपने राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण को बनाए रखने की अनिच्छा के कारण स्थानीय स्व-सरकारों को पर्याप्त कराधान शक्तियां, राजस्व स्रोत और वित्तीय संसाधन हस्तांतरित करने में संकोच करती हैं, जिससे स्थानीय निकाय अनुदानों पर निर्भर रहते हैं।

116. (C) एक केंद्रीय अधिनियम के तहत बनाए गए हैं और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित होते हैं।
छावनी बोर्ड नागरिक शासन के अन्य शहरी निकायों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे राज्य कानून के बजाय एक केंद्रीय अधिनियम (छावनी अधिनियम, 2006) के तहत गठित किए जाते हैं। ये बोर्ड सीधे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। इनका गठन रक्षा प्रतिष्ठानों के साथ लगी नागरिक आबादी को जलापूर्ति, सफाई और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है।

117. (A) सिक्किम
संविधान के अनुच्छेद 243M के तहत, भाग IX (पंचायती राज) के प्रावधान नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों तथा कुछ विशेष जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पारंपरिक जनजातीय परिषदें कार्यरत हैं। हालांकि, सिक्किम इस छूट प्राप्त सूची में शामिल नहीं है; सिक्किम में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज प्रणाली पूर्ण रुप से लागू और संचालित होती है।

118. (D) आवश्यक संशोधनों के साथ संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना।
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) का मुख्य उद्देश्य संविधान के भाग IX के पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को आवश्यक संशोधनों और अपवादों के साथ पांचवीं अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों में विस्तारित करना था। इसका मकसद जनजातीय समुदायों की परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और रीति-रिवाजों का संरक्षण करते हुए उन्हें ग्राम सभा के माध्यम से वास्तविक स्व-शासन का अधिकार देना था।

119. (B) केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर, जिस रीति और आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त की निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 243K(2) में यह अनिवार्य प्रावधान किया गया है कि उन्हें उनके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिस रीति और आधारों पर किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, परंतु उन्हें राज्यपाल द्वारा मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता।

120. (A) केवल I, II और III
74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने भारतीय संविधान में भाग IX-A और 18 कार्यात्मक विषयों वाली बारहवीं अनुसूची जोड़ी। इसने 3 लाख या अधिक आबादी वाले शहरों में वार्ड समितियों का गठन भी अनिवार्य किया। हालांकि, इस संशोधन ने शहरी पुलिस का नियंत्रण नगर निगमों को हस्तांतरित नहीं किया; पुलिस और लोक व्यवस्था अब भी पूरी तरह से राज्य सरकार का विषय बनी हुई है।

121. (D) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) एक संवैधानिक निकाय हैं जिनकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद

Downloaded from www.pdf.tube

I. मुख्यमंत्री
II. कैबिनेट मंत्री
III. राज्य मंत्री
IV. संसदीय सचिव

राज्य मंत्रिपरिषद के आकार के लिए 15% की संवैधानिक सीमा निर्धारित करने में उपर्युक्त में से कौन-सी श्रेणियां आमतौर पर शामिल की जाती हैं?
(A) I, II और III
(B) II, III और IV
(C) I, II और IV
(D) I, III और IV

61. राज्य मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: मंत्रियों के वेतन और भत्ते सीधे संविधान में निर्दिष्ट हैं और राज्य विधानमंडल द्वारा इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है।
कथन II: किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

62. भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्य के मंत्री के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप शामिल हैं?
(A) दूसरी अनुसूची
(B) तीसरी अनुसूची
(C) चौथी अनुसूची
(D) छठी अनुसूची

63. संविधान के अनुच्छेद 164(2) के तहत, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी?
(A) संबंधित राज्य के राज्यपाल
(B) राज्य के मुख्यमंत्री
(C) राज्य के मतदाताओं
(D) राज्य विधानसभा

64. राज्य स्तर पर संसदीय प्रणाली में "सामूहिक उत्तरदायित्व" के सिद्धांत का मौलिक निहितार्थ क्या है?
(A) प्रत्येक व्यक्तिगत मंत्री अपने आवंटित विभाग के प्रशासनिक कार्यों के लिए पूरी तरह और विशेष रूप से जिम्मेदार है।
(B) संपूर्ण निर्वाचित विधानमंडल सामूहिक रूप से राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार के प्रति उत्तरदायी और अधीनस्थ है।
(C) मंत्रियों को मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों का सार्वजनिक रूप से समर्थन करना चाहिए अन्यथा त्यागपत्र दे देना चाहिए।
(D) खराब नीतियों के कारण राज्य के राजकोष को हुए किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए मंत्रियों को व्यक्तिगत और वित्तीय रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

65. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है:
कथन (A): सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद "एक साथ तैरती और एक साथ डूबती है।"
कारण (R): जब विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

NODIA

66. द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों में सामूहिक उत्तरदायित्व और विधान परिषद के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) मंत्रिपरिषद विधानसभा और विधान परिषद दोनों के प्रति समान रूप से उत्तरदायी है।
(B) सामूहिक उत्तरदायित्व लागू करने के लिए विधान परिषद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।
(C) विधान परिषद व्यक्तिगत मंत्रियों को बर्खास्त कर सकती है लेकिन संपूर्ण मंत्रिपरिषद को नहीं।
(D) मंत्रिपरिषद विधान परिषद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होती है।

67. निम्नलिखित में से कौन-सी घटना सामूहिक उत्तरदायित्व की विफलता को सबसे दृढ़ता से दर्शाएगी, जिससे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र आवश्यक हो जाएगा?
(A) विधानसभा में किसी सरकारी धन विधेयक का गिर जाना (पराजित होना)।
(B) विधानसभा में किसी गैर-सरकारी विधेयक का गिर जाना।
(C) किसी मंत्री द्वारा पार्टी विचारधारा के विपरीत विवादास्पद सार्वजनिक बयान देना।
(D) किसी साधारण विधेयक पर स्वीकृति देने में राज्यपाल द्वारा देरी किया जाना।

68. भारत के संविधान के अनुसार, राज्य सरकार में व्यक्तिगत मंत्री किसके प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं?
(A) मुख्यमंत्री
(B) विधानसभा
(C) राज्यपाल
(D) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

69. यद्यपि मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, व्यवहार में, इस प्रसाद का प्रयोग किया जाता है:
(A) मुख्यमंत्री की बाध्यकारी सलाह पर।

अध्याय 13

राजस्थान की राज्य कार्यपालिका

1. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है?
   (A) अनुच्छेद 153
   (B) अनुच्छेद 154
   (C) अनुच्छेद 155
   (D) अनुच्छेद 156

2. राज्यपाल की नियुक्ति और पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   I. राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है।
   II. राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
   III. संविधान राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाने की एक विशिष्ट प्रक्रिया प्रदान करता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (A) I और II
   (B) II और III
   (C) I और III
   (D) I, II और III

3. राजस्थान के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है?
   (A) राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
   (B) भारत का राष्ट्रपति
   (C) राजस्थान का मुख्यमंत्री
   (D) राजस्थान का निवर्तमान राज्यपाल

4. राज्यपाल की नियुक्ति से जुड़ी परंपराओं के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए।
   (A) व्यक्ति को सामान्यतः बाहरी होना चाहिए, जो उस राज्य से संबंधित न हो जहाँ उसकी नियुक्ति की जा रही है।
   (B) राष्ट्रपति पारंपरिक रूप से नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है।
   (C) संविधान राष्ट्रपति को राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की सलाह मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता है।
   (D) नियुक्ति की परंपराओं का उद्देश्य राज्यपाल के पद की राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित करना है।

5. राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह की नियुक्ति से पूर्व, राज्य के प्रमुख को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था?
   (A) राजप्रमुख
   (B) मुख्य आयुक्त
   (C) उपराज्यपाल
   (D) प्रीमियर (प्रधान)

6. भारत के संविधान द्वारा किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए न्यूनतम कितनी आयु निर्धारित की गई है?
   (A) 25 वर्ष
   (B) 30 वर्ष
   (C) 35 वर्ष
   (D) 40 वर्ष

7. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है:
   कथन (A): राज्य विधानसभा के किसी सदस्य को यदि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उसे अपनी सीट से त्यागपत्र देना होगा।
   कारण (R): संविधान यह अनिवार्य करता है कि राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा।
   (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
   (B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
   (C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
   (D) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

8. निम्नलिखित में से कौन-सी राज्यपाल के पद के लिए स्पष्ट रूप से उल्लिखित संवैधानिक योग्यता या शर्त नहीं है?
   (A) वह भारत का नागरिक हो
   (B) कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
   (C) लोक प्रशासन या राजनीति में अनुभव होना चाहिए
   (D) सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो

9. संविधान के अनुच्छेद 158 के अनुसार, एक ही व्यक्ति को एक साथ दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर उसकी उपलब्धियों और भत्तों का क्या होता है?
   (A) राज्यपाल को उन सभी राज्यों का पूरा संयुक्त वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं।
   (B) संपूर्ण वेतन और भत्तों का भुगतान सीधे केंद्र सरकार के राजकोष से किया जाता है।
   (C) जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राज्यपाल की उपलब्धियों का पूरा वित्तीय बोझ उठाता है।

Click Here to Buy book on Amazon

(D) राज्यों के बीच राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में आवंटित किए जाते हैं।

10. क्या ऐसा व्यक्ति जो जन्म से भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन बाद में देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की है, राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है?
(A) हाँ, संविधान केवल भारत की नागरिकता की मांग करता है, चाहे वह किसी भी प्रकार प्राप्त की गई हो।
(B) नहीं, केवल जन्म से भारत के नागरिक ही संवैधानिक रूप से राज्यपाल पद के लिए पात्र हैं।
(C) हाँ, शर्त यह है कि वह नियुक्ति से पूर्व लगातार पंद्रह वर्षों तक भारत के राज्यक्षेत्र में रहा हो।
(D) नहीं, देशीयकृत नागरिकों को राज्य सरकारों में संवैधानिक कार्यपालक पद धारण करने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

11. राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किस अनुच्छेद के तहत करेगा?
(A) अनुच्छेद 153
(B) अनुच्छेद 154
(C) अनुच्छेद 161
(D) अनुच्छेद 163

12. राज्य के निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए:
I. राजस्थान का महाधिवक्ता
II. राज्य निर्वाचन आयुक्त
III. राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
IV. राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
उपर्युक्त में से किन अधिकारियों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है?
(A) I, II और III
(B) I, II और IV
(C) II, III और IV
(D) I, III और IV

13. राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति पर निम्नलिखित में से कौन-सी एक सीमा है?
(A) राज्यपाल आरपीएससी के सदस्य को हटा नहीं सकता; केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है।
(B) राज्यपाल के पास आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है।
(C) राज्यपाल के पास आरपीएससी के सदस्यों की कुल संख्या और सेवा शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति नहीं है।
(D) आरपीएससी में किसी आकस्मिक रिक्ति के दौरान राज्यपाल को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने से रोका गया है।

14. राजस्थान में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल कार्य करता है:
(A) राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से बाध्य होकर।
(B) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अनिवार्य और बाध्यकारी सलाह पर।
(C) विश्वविद्यालय अधिनियमों के तहत एक स्वतंत्र सांविधिक क्षमता में।
(D) भारत के राष्ट्रपति की पूर्व औपचारिक स्वीकृति के अधीन।

15. राज्य कार्यपालिका के संबंध में सूची I के अनुच्छेदों को सूची II के उनके संबंधित प्रावधानों से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (अनुच्छेद)
P. अनुच्छेद 153
Q. अनुच्छेद 161
R. अनुच्छेद 165
S. अनुच्छेद 167
सूची II: (प्रावधान)
1. राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
2. राज्य के लिए महाधिवक्ता
3. राज्यों के राज्यपाल
4. क्षमा आदि प्रदान करने, दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति
(A) P-3, Q-4, R-2, S-1
(B) P-4, Q-3, R-1, S-2
(C) P-3, Q-1, R-2, S-4
(D) P-2, Q-4, R-3, S-1

NODIA

16. संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति केवल तभी लागू होती है जब:
(A) मुख्यमंत्री प्रख्यापन के लिए राज्यपाल को स्पष्ट रूप से एक औपचारिक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करता है।
(B) भारत की संसद के दोनों सदन वर्तमान में सत्र में न हों।
(C) राज्य विधानमंडल वर्तमान में सत्र में न हो।
(D) संपूर्ण राज्य प्रशासन को अनुच्छेद 356 के तहत आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति शासन के अधीन रखा गया हो।

17. राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने और राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति होती है।
कथन II: अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर राज्यपाल राज्य विधान परिषद को भंग कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

18. राज्य विधानमंडल के दो लगातार सत्रों के बीच संविधान द्वारा अनिवार्य अधिकतम समय-अंतराल कितना हो सकता है, जिसे राज्यपाल को यह सुनिश्चित करना होता है कि वह सीमा न लांघे?
(A) तीन माह
(B) छह माह
(C) नौ माह
(D) बारह माह

19. राजस्थान के राज्यपाल प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद के प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्य विधानसभा को संबोधित करते हैं। यह किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है?
(A) अनुच्छेद 174
(B) अनुच्छेद 175
(C) अनुच्छेद 176
(D) अनुच्छेद 177

20. राजस्थान जैसे एकसदनीय राज्य विधानमंडल में किसी साधारण विधायी विधेयक के पारित होने के निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए:
1. विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है।
2. विधेयक विधानसभा में पुरःस्थापित (प्रस्तुत) और पढ़ा जाता है।
3. राज्यपाल अनुमति देता है, जिससे यह अधिनियम बन जाता है।
4. विधेयक राज्यपाल के विचारार्थ भेजा जाता है।

निम्नलिखित में से कौन-सा इन चरणों का सही कालानुक्रम दर्शाता है?
(A) 2, 1, 4, 3
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 4, 1, 3
(D) 4, 2, 1, 3

21. कौन-सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, उन बातों को छोड़कर जिनमें वह अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए अपेक्षित है?
(A) अनुच्छेद 162
(B) अनुच्छेद 163
(C) अनुच्छेद 164
(D) अनुच्छेद 166

22. राज्यपाल की परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तब मुख्यमंत्री की नियुक्ति।
II. जब मंत्रिपरिषद सदन के पटल पर अपना बहुमत सिद्ध न कर सके, तो उसे बर्खास्त करना।
III. जब मुख्यमंत्री को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, तब राज्य विधानसभा को भंग करना।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) I और II
(B) II और III
(C) I और III
(D) I, II और III

23. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है:
कथन (A): राज्यपाल को ऐसे किसी भी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना अनिवार्य है जो राज्य उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है।
कारण (R): संविधान राज्य विधानमंडल द्वारा किए जाने वाले अतिक्रमण से राज्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहता है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

24. राजस्थान के राज्यपाल के लिए सबसे उपयुक्त कार्रवाई क्या होगी जब कोई सत्तारुढ़ दल विभाजन के कारण अपना बहुमत खो देता है, और मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग करने की सलाह देता है?
(A) विधानसभा को तुरंत भंग कर दें क्योंकि राज्यपाल संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य है।
(B) विकल्पों की तलाश किए बिना स्वचालित रूप से अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की तत्काल सिफारिश करें।
(C) विघटन से इनकार करें और एक वैकल्पिक स्थायी सरकार के गठन की संभावनाएं तलाशें।
(D) इस बात के लिए राष्ट्रपति के स्पष्ट निर्देशों की अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करें कि विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए या नहीं।

25. निम्नलिखित में से कौन-सा राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का अपवाद है?
(A) राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को सुरक्षित रखना।
(B) राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करना।
(C) विधायी प्रस्तावों के संबंध में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना।
(D) मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण करना।

26. संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत, जब कोई साधारण विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा राज्यपाल के लिए संवैधानिक रूप से वैध विकल्प नहीं है?

Downloaded from www.pdf.tube

42. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है?
(A) अनुच्छेद 162
(B) अनुच्छेद 163
(C) अनुच्छेद 164
(D) अनुच्छेद 165

43. आम चुनावों के बाद राज्य सरकार के गठन में आमतौर पर अपनाई जाने वाली घटनाओं के सही क्रम का चयन कीजिए।
(A) चुनाव परिणाम → विश्वास मत → मुख्यमंत्री की नियुक्ति → शपथ ग्रहण समारोह
(B) चुनाव परिणाम → मुख्यमंत्री की नियुक्ति → शपथ ग्रहण समारोह → विश्वास मत
(C) मुख्यमंत्री की नियुक्ति → चुनाव परिणाम → शपथ ग्रहण समारोह → विश्वास मत
(D) शपथ ग्रहण समारोह → चुनाव परिणाम → विश्वास मत → मुख्यमंत्री की नियुक्ति

44. मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) राज्यपाल विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए कानूनी रुप से बाध्य है।
(B) राज्यपाल आमतौर पर विधानसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है।
(C) केवल विधानसभा के सदस्य को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है; गैर-सदस्य किसी भी परिस्थिति में शपथ नहीं ले सकता।
(D) मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति का पूर्व अनुसमर्थन आवश्यक है।

45. यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो संवैधानिक आवश्यकता क्या है?
(A) उसे छह महीने के भीतर राज्य विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करनी होगी अन्यथा त्यागपत्र देना होगा।
(B) उसे शपथ लेने के एक महीने के भीतर सीधे राज्यपाल द्वारा औपचारिक रुप से विधानसभा के लिए मनोनीत किया जाना चाहिए।
(C) उसे तुरंत अपना त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि किसी गैर-विधायक को मुख्यमंत्री नियुक्त करना स्वभावतः असंवैधानिक है।
(D) उसे पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने रहने की अनुमति है, बशर्ते वह शुरुआती विश्वास मत पास कर ले।

46. 1952 के प्रथम आम चुनावों के बाद राजस्थान के प्रथम लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मुख्यमंत्री होने का श्रेय किसे प्राप्त है?
(A) हीरालाल शास्त्री
(B) जयनारायण व्यास
(C) टीकाराम पालीवाल
(D) मोहनलाल सुखाड़िया

47. मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है।
II. मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
III. मुख्यमंत्री का त्यागपत्र या मृत्यु स्वतः ही मंत्रिपरिषद को विघटित कर देती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) I और II
(B) II और III
(C) I और III
(D) I, II और III

48. मुख्यमंत्री के कार्यों के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए।
(A) वह राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है।
(B) वह राज्य विधानमंडल के सत्रों को आहूत करने और सत्रावसान करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है।
(C) वह राज्य लोक सेवा आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
(D) वह किसी भी समय राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करता है।

49. जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी मंत्री से त्यागपत्र मांगता है और मंत्री इनकार कर देता है, तो मुख्यमंत्री के पास उपलब्ध मानक संवैधानिक विकल्प क्या है?
(A) मुख्यमंत्री मंत्री को बर्खास्त करने का एकतरफा कार्यपालक आदेश जारी कर सकता है।
(B) मुख्यमंत्री राज्यपाल को उस मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है।
(C) मुख्यमंत्री को विधानसभा में मंत्री के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव शुरु करना होगा।
(D) मंत्री को बाहर करने के लिए मुख्यमंत्री को स्वयं त्यागपत्र देना होगा।

NODIA

50. इस सिद्धांत कि "मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल रुपी मेहराब की आधारशिला है" का तात्पर्य है कि:
(A) मुख्यमंत्री को विधानसभा द्वारा पारित सभी विधायी विधेयकों पर पूर्ण संवैधानिक वीटो शक्ति प्राप्त है।
(B) मुख्यमंत्री को उसके कार्यकाल के दौरान पद से नहीं हटाया जा सकता भले ही वह विधानसभा में बहुमत का विश्वास खो दे।
(C) मुख्यमंत्री पूरी तरह से मंत्रिमंडल के अधीनस्थ है और उसे बिना किसी अपवाद के सभी बहुमत वाले कैबिनेट निर्णयों का पालन करना अनिवार्य है।
(D) मुख्यमंत्री के बिना मंत्रिपरिषद का अस्तित्व या

(B) इसे तुरंत एक द्विसदनीय विधानमंडल में बदल दिया जाता है।
(C) यह कानून बनाना जारी रखती है लेकिन केवल समवर्ती सूची के विषयों पर।
(D) इसे या तो भंग कर दिया जाता है या निलंबन की अवस्था में रखा जाता है।

35. राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए।
(A) राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह परे है।
(B) यदि राज्य सरकार संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है तो इसे लागू किया जा सकता है।
(C) राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी कार्य कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है।
(D) इसे दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।

36. किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान, राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग आमतौर पर किसके द्वारा किया जाता है?
(A) राज्य के राज्यपाल द्वारा
(B) स्वतंत्र रूप से भारत के राष्ट्रपति द्वारा
(C) भारत की संसद द्वारा
(D) राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा

37. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है:
कथन (A): भारत के राष्ट्रपति के विपरीत, किसी राज्य के राज्यपाल के पास मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं होती है।
कारण (R): संविधान अनुच्छेद 72 के तहत स्पष्ट रूप से मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति में निहित करता है, चाहे सजा राज्य कानून के तहत हो या संघ कानून के तहत।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

38. सैन्य अदालत (कोर्ट मार्शल) द्वारा दी गई सजा के संबंध में, राज्य के राज्यपाल के पास:
(A) राष्ट्रपति के समान क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं।
(B) सजा को क्षमा कर सकता है लेकिन इसे कम नहीं कर सकता।
(C) केवल रक्षा मंत्री की पूर्व सहमति से ही क्षमा प्रदान कर सकता है।
(D) क्षमा, प्रविलंबन या विराम प्रदान करने की कोई शक्ति नहीं होती है।

39. राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों की तुलना करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. दोनों केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संबंधित विधानमंडल सत्र में न हो।
II. दोनों मंत्रिस्तरीय सलाह के बिना पूरी तरह से अपने व्यक्तिगत विवेकाधिकार से इस शक्ति का प्रयोग करते हैं।
III. किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो एक नियमित विधायी अधिनियम का होता है।
IV. यदि किसी समान विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देशों के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से गलत है/हैं?
(A) I और II
(B) केवल II
(C) III और IV
(D) I और IV

40. निम्नलिखित में से किस पहलू में राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति भारत के राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है?
(A) राज्यपाल केवल राज्य का नाममात्र का प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति वास्तविक सर्वोच्च कार्यपालक के रूप में कार्य करता है।
(B) राज्यपाल सीधे राज्य विधानमंडल द्वारा चुना जाता है, जबकि राष्ट्रपति एक राष्ट्रीय निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है।
(C) राष्ट्रपति के विपरीत, संविधान राज्यपाल को स्पष्ट विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता है।
(D) राज्यपाल एक निश्चित कार्यकाल के लिए पद धारण करता है जिसे कम नहीं किया जा सकता, जबकि राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है।

41. राज्यपाल को पद से हटाने की प्रक्रिया भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया से मौलिक रूप से किस प्रकार भिन्न है?
(A) राज्यपाल को राज्य विधानसभा में साधारण बहुमत के प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है, जबकि राष्ट्रपति को संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
(B) राज्यपाल को केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायिक आदेश के माध्यम से हटाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति को संसदीय वोट द्वारा हटाया जाता है।
(C) राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को संसद में आयोजित समान संवैधानिक महाभियोग की कार्यवाही के माध्यम से हटाया जाता है।
(D) राष्ट्रपति के विपरीत, राज्यपाल महाभियोग के बिना राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।

Click Here to Buy book on Flipkart

(A) अनुमति देने से पहले सीधे विधेयक में संशोधन करना
(B) विधेयक पर अनुमति की घोषणा करना
(C) यह घोषणा करना कि वह विधेयक पर अनुमति रोकता है
(D) विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटाना

27. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए:
I. विधेयक पर अनुमति देना
II. विधेयक पर अनुमति रोकना
III. विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटाना
IV. विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना
धन विधेयक प्राप्त होने पर राज्यपाल के पास उपर्युक्त में से कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं?
(A) I, II और III
(B) I, II और IV
(C) II, III और IV
(D) I, III और IV

28. किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने की राज्यपाल की शक्ति के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) यदि धन विधेयक स्पष्ट रूप से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो राज्यपाल के पास उसे लौटाने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है।
(B) यदि विधानमंडल द्वारा संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के विधेयक पुनः पारित कर दिया जाता है, तो स्वीकृति देना अनिवार्य है।
(C) यदि सुझाये गए संशोधनों की अनदेखी की जाती है, तो राज्यपाल के पास किसी भी गैर-धन विधेयक को बार-बार लौटाने का विवेकाधिकार है।
(D) किसी भी विधायी विधेयक को राज्य विधानसभा को वापस लौटाने के लिए राष्ट्रपति की औपचारिक पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

29. अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखे गए राज्य विधेयक का क्या होता है?
(A) एक बार राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित हो जाने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति की कोई भूमिका नहीं रह जाती है।
(B) राष्ट्रपति प्राप्ति के छह महीने के भीतर स्वीकृति देने या विधेयक को वापस लौटाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है।
(C) राष्ट्रपति केवल स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति रोक सकता है, लेकिन संवैधानिक रूप से इसे राज्य विधानमंडल को लौटाने से प्रतिबंधित है।
(D) यदि राष्ट्रपति द्वारा विचार किए जाने से पहले राज्य विधानसभा भंग हो जाती है, तो सुरक्षित रखा गया विधेयक स्वतः ही व्यपगत हो जाता है।

30. साधारण विधेयक पर स्वीकृति रोकने की राज्यपाल की शक्ति द्वारा किस संवैधानिक सिद्धांत का पालन किया जाता है?
(A) कार्यपालिका के वीटो पर राज्य विधानमंडल की अंतिम और पूर्ण विधायी सर्वोच्चता सुनिश्चित करना।
(B) संसदीय सर्वोच्चता के अधीन सभी राज्य अधिनियमों की पूर्ण संवैधानिक अधीनता स्थापित करना।
(C) जल्दबाज़ी में बनाए गए या असंवैधानिक विधान को रोकना।
(D) राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों पर न्यायिक समीक्षा शक्तियों का पूर्ण उन्मूलन प्राप्त करना।

31. सूची I में दी गई संवैधानिक शक्तियों को सूची II में उनकी प्रकृति के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (शक्ति)
P. अनुच्छेद 164 (मंत्रियों की नियुक्ति)
Q. अनुच्छेद 161 (क्षमादान)
R. अनुच्छेद 200 (विधेयकों पर अनुमति)
S. अनुच्छेद 356 की रिपोर्ट
सूची II: (शक्ति की प्रकृति)
1. कार्यपालिका शक्ति
2. विवेकाधीन शक्ति
3. विधायी शक्ति
4. न्यायिक शक्ति
(A) P-1, Q-4, R-3, S-2
(B) P-2, Q-3, R-4, S-1
(C) P-1, Q-2, R-3, S-4
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

NODIA

32. किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है?
(A) अनुच्छेद 352
(B) अनुच्छेद 355
(C) अनुच्छेद 356
(D) अनुच्छेद 360

33. राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से राज्य का प्रशासन चलाता है।
II. राज्यपाल निलंबित राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है।
III. राज्यपाल राज्य प्रशासन के लिए मुख्य सचिव और अन्य लोक सेवकों की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) I और II
(B) I और III
(C) II और III
(D) I, II और III

34. जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो राज्य विधानसभा की सामान्य स्थिति क्या होती है?
(A) इसे स्थायी रूप से समाप्त कर दिया जाता है।

कार्यप्रणाली संभव नहीं है।

51. राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संचार के मुख्य माध्यम के रूप में कौन कार्य करता है?
(A) मुख्यमंत्री
(B) मुख्य सचिव
(C) विधानसभा अध्यक्ष
(D) महाधिवक्ता

52. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को निर्धारित करता है?
(A) अनुच्छेद 164
(B) अनुच्छेद 165
(C) अनुच्छेद 166
(D) अनुच्छेद 167

53. राज्य कार्यपालिका के संबंध में सूची I के अनुच्छेदों को सूची II में उनकी विषय-वस्तु के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (अनुच्छेद)
P. अनुच्छेद 163
Q. अनुच्छेद 164
R. अनुच्छेद 166
S. अनुच्छेद 167
सूची II: (विषय-वस्तु)
1. जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
2. राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
3. राज्य की सरकार के कार्य का संचालन
4. मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध (नियुक्ति, कार्यकाल आदि)
(A) P-2, Q-4, R-3, S-1
(B) P-4, Q-2, R-1, S-3
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-3, Q-4, R-2, S-1

54. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है:
कथन (A): राज्यपाल मुख्यमंत्री से ऐसे किसी भी विषय को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है जिस पर किसी व्यक्तिगत मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है।
कारण (R): यह संवैधानिक प्रावधान मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को सुनिश्चित और लागू करने का कार्य करता है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

55. राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री के संबंध का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है?
(A) मुख्यमंत्री सीधे राज्यपाल के प्रशासनिक एजेंट के रूप में कार्य करता है और केवल राजभवन द्वारा जारी कार्यपालक आदेशों का क्रियान्वयन करता है।
(B) मुख्यमंत्री एक संवैधानिक कड़ी के रूप में कार्य करता है जो राज्यपाल को राज्य के सभी मामलों की जानकारी देता है।
(C) मुख्यमंत्री पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और संवैधानिक रूप से राज्यपाल को कार्यपालक निर्णयों की जानकारी देने के लिए आवश्यक नहीं है।
(D) मुख्यमंत्री राज्यपाल के साथ कोई प्रत्यक्ष व्यक्तिगत बातचीत नहीं रखता है, क्योंकि सभी आधिकारिक संचार मुख्य सचिव के माध्यम से होते हैं।

56. यदि राजस्थान के राज्यपाल राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित विशिष्ट जानकारी मांगते हैं, तो मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह:
(A) केवल राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित होने पर ही जानकारी प्रदान करे।
(B) यदि अनुरोध गुप्त कैबिनेट मामलों से संबंधित है तो उसे अस्वीकार कर दे।
(C) राज्यपाल द्वारा मांगी गई ऐसी जानकारी प्रदान करे।
(D) राज्यपाल को सूचना का अधिकार आवेदन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दे।

57. 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी?
(A) 10 प्रतिशत
(B) 12 प्रतिशत
(C) 15 प्रतिशत
(D) 20 प्रतिशत

NODIA

58. राजस्थान विधानसभा की क्षमता (200 सदस्य) के आधार पर, मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्रियों की अनुमति है?
(A) 20
(B) 25
(C) 30
(D) 35

59. राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम कितने मंत्रियों की संवैधानिक आवश्यकता होती है?
(A) 10
(B) 12
(C) 15
(D) कोई न्यूनतम सीमा निर्दिष्ट नहीं है।

60. मंत्रियों की निम्नलिखित श्रेणियों पर विचार कीजिए:

148 के तहत सीधे तौर पर की गई है। इसके विपरीत, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (1993 अधिनियम), केंद्रीय सूचना आयोग (2005 आरटीआई अधिनियम) और लोकपाल (2013 अधिनियम) संसद द्वारा पारित कानूनों के माध्यम से स्थापित वैधानिक निकाय हैं, जिनका उल्लेख मूल या संशोधित संविधान में नहीं है।

122. (A) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)
विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1997) के ऐतिहासिक मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई (CBI) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्वायत्तता, निष्पक्षता और कार्यप्रणाली से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए थे। इस निर्णय के परिणामस्वरुप सीबीआई निदेशक को कम से कम दो वर्ष का निश्चित कार्यकाल प्रदान किया गया और सीवीसी को वैधानिक दर्जा देने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

123. (B) लोक लेखा समिति कार्यपालिका को वित्तीय रुप से जवाबदेह ठहराने के लिए CAG की लेखापरीक्षा रिपोर्टों का उपयोग करती है।
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्टों को राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपते हैं, जिन्हें संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है। इसके पश्चात संसद की लोक लेखा समिति (PAC) कार्यपालिका को वित्तीय रुप से जवाबदेह ठहराने के लिए CAG की इन रिपोर्टों की गहनता से जांच करती है। CAG समिति की बैठकों में उपस्थित होकर जांच प्रक्रिया में निरंतर तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।

124. (B) केंद्रीय सूचना आयोग
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत की गई है। इसके विपरीत, भारत का निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324), राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I) और राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243K) सभी संवैधानिक निकाय हैं क्योंकि इनका प्रावधान सीधे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत स्पष्ट रुप से किया गया है।

125. (A) P-4, Q-3, R-1, S-2
विभिन्न निकायों के प्रशासनिक नियंत्रण हेतु नोडल मंत्रालय निर्धारित हैं। केंद्रीय सूचना आयोग कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए गृह मंत्रालय नोडल एजेंसी है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय वित्त मंत्रालय से प्रशासनिक रुप से जुड़ा है, जबकि भारत का निर्वाचन आयोग प्रशासनिक और बजटीय उद्देश्यों के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

126. (B) कथन I गलत है और कथन II सही है।
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) कोई संवैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इसकी स्थापना संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत की गई थी। इसलिए, CIC एक वैधानिक निकाय के रुप में कार्य करता है जो संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों और संशोधनों के अधीन और उनके अनुसार ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है।

127. (D) नियंत्रण और संतुलन द्वारा सीमित सरकार।
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में "संविधानवाद" उस राजनीतिक दर्शन को संदर्भित करता है जिसके अनुसार सरकार की शक्तियां असीम नहीं होतीं, बल्कि वे संविधान, विधि के शासन, शक्तियों के पृथक्करण तथा नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था द्वारा सीमित होती हैं। संविधानवाद का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और शासन के निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी प्रयोग को प्रभावी ढंग से रोकना है।

128. (A) II, I, III, IV
इन निकायों की स्थापना का सही कालानुक्रम इस प्रकार है: भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के तहत हुई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 1993 के अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 के आरटीआई अधिनियम के तहत हुई, जबकि केंद्रीय स्तर पर लोकपाल संस्था की स्थापना 2013 के अधिनियम के पश्चात 2019 में हुई थी।

129. (B) टी. एन. शेषन
टी. एन. शेषन ने 1990 से 1996 तक भारत के 10वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रुप में कार्य करते हुए देश की चुनावी प्रक्रिया में क्रांतिकारी और अभूतपूर्व बदलाव किए। उन्होंने आदर्श आचार संहिता को कड़ाई से लागू किया, मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत की, और चुनावी खर्च तथा बाहुबल के इस्तेमाल पर सख्त अंकुश लगाकर भारत के निर्वाचन आयोग को एक अत्यंत शक्तिशाली और स्वायत्त निकाय बनाया।

130. (D) किसी राज्य की वार्षिक राज्य वित्त आयोग रिपोर्ट
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग की वार्षिक एवं लेखापरीक्षा रिपोर्टें केंद्र सरकार के माध्यम से भारत की संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती हैं। हालांकि, किसी राज्य की राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपी जाती है, जिसे केवल संबंधित राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है, संसद के समक्ष नहीं।

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

(B) मंत्री के प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर पूरी तरह से राज्यपाल के विवेकाधिकार पर।
(C) राज्य लोकायुक्त द्वारा अनिवार्य जांच के बाद।
(D) भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के अधीन।

70. राज्य के मंत्रियों के उत्तरदायित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होता है।
II. व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करने से संबंधित है।
III. ब्रिटिश प्रणाली की तर्ज पर भारतीय संविधान में मंत्रियों के कानूनी उत्तरदायित्व के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) I और II
(B) II और III
(C) I और III
(D) I, II और III

71. भारत में व्यक्तिगत मंत्रिस्तरीय उत्तरदायित्व के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए।
(A) यदि मंत्रिपरिषद को विधानसभा का विश्वास प्राप्त हो, तब भी किसी मंत्री को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है।
(B) कानूनी जिम्मेदारी तय करने के लिए किसी सार्वजनिक कार्य के लिए राज्यपाल के आदेश पर मंत्री द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
(C) व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के लिए आवश्यक है कि मंत्री अपने आवंटित विभाग के प्रशासन के लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह हो।
(D) मुख्यमंत्री असंतुष्ट मंत्री से त्यागपत्र मांगकर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लागू कर सकता है।

72. संविधान का कौन-सा विशिष्ट अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व दोनों की नींव स्थापित करता है?
(A) अनुच्छेद 163
(B) अनुच्छेद 164
(C) अनुच्छेद 166
(D) अनुच्छेद 167

73. राज्य सरकार में "मंत्रिपरिषद" और "मंत्रिमंडल (कैबिनेट)" के बीच मौलिक अंतर क्या है?
(A) मंत्रिमंडल में राज्य के मंत्रियों की सभी प्रशासनिक श्रेणियां शामिल हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में केवल कैबिनेट रैंक के मंत्री शामिल हैं।
(B) मंत्रिमंडल की नियुक्ति सीधे राज्यपाल द्वारा की जाती है, जबकि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति केवल मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है।
(C) कोई कार्यात्मक या कानूनी अंतर नहीं है; संपूर्ण संविधान में दोनों शब्द पूरी तरह से समानार्थी और विनिमय योग्य हैं।
(D) मंत्रिपरिषद एक बड़ा संवैधानिक निकाय है; मंत्रिमंडल इसका छोटा नीति-निर्माता मुख्य भाग है।

74. "किचन कैबिनेट" (या आंतरिक कैबिनेट) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: यह संविधान के अनुच्छेद 163 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित एक औपचारिक, संवैधानिक संस्था है।
कथन II: इसमें अक्सर मुख्यमंत्री और कुछ अत्यधिक भरोसेमंद सहयोगी शामिल होते हैं, जिनमें कभी-कभी बाहरी सलाहकार या मित्र भी शामिल होते हैं, जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

NODIA

75. राज्य की राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च निर्णय लेने वाले प्राधिकारी और सर्वोच्च कार्यपालक अंग के रूप में कौन-सा निकाय कार्य करता है?
(A) राज्य विधानसभा
(B) राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट)
(C) राज्यपाल का कार्यालय
(D) राज्य नियोजन आयोग

76. राज्य मंत्रिमंडल सचिवालय की सही भूमिका की पहचान कीजिए।
(A) यह राज्य विधानसभा से स्वतंत्र रूप से सीधे विधायी अधिनियमों और राज्य के कानूनों को तैयार करता है।
(B) यह मंत्रिमंडल का एजेंडा तैयार करता है और मंत्रिमंडल के निर्णयों के कार्यान्वयन का समन्वय करता है।
(C) यह मुख्य रूप से सिविल सेवकों द्वारा अनुशासनात्मक अपीलों के लिए एक सर्वोच्च न्यायिक अपीलीय अधिकरण के रूप में कार्य करता है।
(D) यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को पूरी तरह से अतिक्रमित करते हुए सभी राज्य सरकार के खर्चों का स्वतंत्र रूप से वित्तीय लेखा-परीक्षा करता है।

77. राज्य कार्यपालिका तंत्र के भीतर सूची I के प्रशासनिक पदों को सूची II में उनकी मानक भूमिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (पद)
P. मुख्यमंत्री
Q. राज्यपाल
R. मुख्य सचिव
S. महाधिवक्ता
सूची II: (भूमिका)
1. राज्य का विधिगत प्रमुख
2. राज्य का वास्तविक कार्यपालक प्रमुख
3. राज्य सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार
4. मुख्यमंत्री का मुख्य प्रशासनिक सलाहकार

महाधिवक्ता को राज्यपाल द्वारा।

115. राज्य स्तर पर जटिल संवैधानिक मुद्दों के संबंध में राज्यपाल के प्राथमिक कानूनी सलाहकार के रूप में कौन-सा पदाधिकारी कार्य करता है?
(A) महाधिवक्ता
(B) राज्य विधि सचिव
(C) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(D) लोकायुक्त

116. राजस्थान में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में जहाँ किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, राज्यपाल के लिए संवैधानिक रूप से सबसे उपयुक्त प्रारंभिक कदम क्या होगा?
(A) किसी भी राजनीतिक दल को आमंत्रित किए बिना अनुच्छेद 356 के तहत तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करें।
(B) सभी निर्वाचन क्षेत्रों में नए सिरे से राज्यव्यापी चुनाव कराने के लिए नवगठित विधानसभा को तुरंत भंग कर दें।
(C) सबसे बड़े एकल दल या चुनाव-पूर्व गठबंधन को सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित करें।
(D) वर्तमान मुख्यमंत्री को बहुमत परीक्षण के माध्यम से बहुमत साबित करने का दबाव डाले बिना लगातार पद पर बने रहने की अनुमति दें।

117. उच्चतम न्यायालय के किस ऐतिहासिक फैसले ने अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में सख्त दिशा-निर्देश स्थापित किए और यह अनिवार्य किया कि सरकार के बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पर ही किया जाना चाहिए?
(A) केशवानंद भारती मामला (1973)
(B) मिनर्वा मिल मामला (1980)
(C) एस.आर. बोम्मई मामला (1994)
(D) एल. चंद्र कुमार मामला (1997)

118. जब राज्यपाल दो अलग-अलग राजनीतिक नेताओं से बहुमत के समर्थन के परस्पर विरोधी दावों का सामना करता है, तो स्थापित लोकतांत्रिक परंपरा यह आदेश देती है कि राज्यपाल को:
(A) राजभवन में व्यक्तिगत रूप से विधायकों के हस्ताक्षरों का सत्यापन करना चाहिए।
(B) पुलिस को दावों की जांच करने का निर्देश देना चाहिए।
(C) विधानसभा बुलाए बिना केवल अपने व्यक्तिगत विवेकाधिकार से मामले का फैसला करना चाहिए।
(D) यथाशीघ्र विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने का आदेश देना चाहिए।

119. क्या सबसे उपयुक्त कारण है कि पुंछी आयोग जैसे आयोगों ने राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका को सीमित करने की सिफारिश की?
(A) राज्यपालों के पास उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक औपचारिक शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव होता है।
(B) इससे प्रशासनिक बोझ बढ़ता है और नियुक्तियों को लेकर राज्य सरकार के साथ टकराव पैदा होता है।
(C) भारत का संविधान स्पष्ट रूप से राज्यपाल को राज्य निकायों में कोई द्वितीयक सांविधिक पद या पदेन स्थिति धारण करने से रोकता है।
(D) केंद्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे सांविधिक निकायों के माध्यम से सभी राज्य विश्वविद्यालयों पर प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण ग्रहण करना चाहती है।

120. राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार कीजिए:
I. नियुक्त व्यक्ति राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए।
II. संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए।
III. सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सक्रिय राजनीतिज्ञों को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
उपर्युक्त में से कौन-सी सिफारिशें सरकारीया आयोग द्वारा की गई थीं?
(A) I और II
(B) II और III
(C) I और III
(D) I, II और III

121. राजस्थान राज्य के गठन के बाद से इसमें कितनी बार राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल) लागू किया गया है?
(A) दो बार
(B) तीन बार
(C) चार बार
(D) पांच बार

122. राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू होने के वर्षों का सही क्रम चुनिए।
(A) 1967, 1977, 1980, 1992
(B) 1965, 1975, 1982, 1990
(C) 1967, 1975, 1980, 1992
(D) 1970, 1977, 1985, 1995

123. 1967 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान राजस्थान के राज्यपाल कौन थे?
(A) सरदार हुकम सिंह
(B) डॉ. संपूर्णानंद
(C) रघुकुल तिलक
(D) एम. चेन्ना रेड्डी

124. सूची I में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के वर्ष को सूची II में लागू होने के समय के राज्यपाल के साथ सुमेलित कीजिए:

Click Here to Buy book on Amazon

अपना इस्तीफा देने के लिए बाध्य होते हैं।
(D) सिविल सेवकों को जो भी सरकार सत्ता में हो, उसकी निष्ठापूर्वक सेवा करनी चाहिए।

87. राज्य सरकार के सचिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: सचिव किसी विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है और प्रभारी मंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
कथन II: यदि सचिव को लगता है कि मंत्री का अंतिम निर्णय राजनीति से प्रेरित है, तो उसके पास उसे रद्द करने का कानूनी अधिकार है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

88. राजनीतिक कार्यपालिका के विपरीत स्थायी कार्यपालिका (नौकरशाही) की विशेषताओं के संबंध में विषम विकल्प पहचानिए।
(A) कार्यकाल की सुरक्षा
(B) प्रतियोगी योग्यता परीक्षाओं के आधार पर चयन
(C) मतदाताओं के प्रति प्रत्यक्ष जवाबदेही
(D) राजनीतिक तटस्थता और अनामता

89. हाल के संरचनात्मक मानकों के अनुसार, राजस्थान विधानसभा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है?
(A) 160
(B) 180
(C) 200
(D) 220

90. राजस्थान में जिलों का हालिया पुनर्गठन (नए जिलों का सृजन) मुख्य रूप से राज्य के कार्यपालक तंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है?
(A) जिला प्रशासनिक इकाइयों और प्रशासनिक क्षेत्रीय तैनातियों का विस्तार करके।
(B) राज्य विधानसभा में निर्वाचित सीटों की कुल संवैधानिक संख्या को स्वचालित रूप से बढ़ाकर।
(C) आंतरिक जिला सीमाओं को औपचारिक रूप से फिर से खींचने के लिए अनुच्छेद 3 के तहत एक अनिवार्य संघीय संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता द्वारा।
(D) केंद्र सरकार से राज्य द्वारा प्राप्त वार्षिक वैधानिक बजट आवंटन को काफी हद तक कम करके।

91. वर्तमान परिसीमन के अनुसार, राजस्थान विधानसभा में क्रमशः अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?
(A) SC के लिए 34 और ST के लिए 25
(B) SC के लिए 30 और ST के लिए 20
(C) SC के लिए 25 और ST के लिए 34
(D) SC के लिए 40 और ST के लिए 30

92. लागू होने के बाद राजस्थान की भावी विधानसभाओं पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम) के सही प्रभाव की पहचान कीजिए।
(A) यह संवैधानिक रूप से राज्य विधानसभा की सभी सीटों का 50% केवल महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करेगा।
(B) यह विधानसभा की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है।
(C) यह राज्य सरकार को पूरी तरह से मनोनीत महिला सदस्यों से निर्मित एक विधान परिषद स्थापित करने के लिए बाध्य करेगा।
(D) यह मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति की पात्रता को केवल विधानसभा की महिला सदस्यों तक सीमित करता है।

NODIA

93. राजस्थान विधानसभा की वर्तमान क्षमता (200 सीटें) 1971 की जनगणना पर आधारित है। किस वर्ष तक सीटों की इस कुल संख्या को एक संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थिर कर दिया गया है?
(A) 2024
(B) 2026
(C) 2030
(D) 2035

94. राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों पर विचार कीजिए:
1. भैरोंसिंह शेखावत
2. मोहनलाल सुखाड़िया
3. वसुंधरा राजे
4. अशोक गहलोत
निम्नलिखित में से कौन-सा उनके पहली बार पद ग्रहण करने का सही कालानुक्रम दर्शाता है?
(A) 2, 1, 4, 3
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 4, 1, 3
(D) 4, 1, 2, 3

95. सूची I में राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को सूची II में उनकी विशिष्टता के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (मुख्यमंत्री)
P. मोहनलाल सुखाड़िया
Q. बरकतुल्लाह खान
R. भैरोंसिंह शेखावत
S. वसुंधरा राजे
सूची II: (विशिष्टता)
1. राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री
2. राजस्थान के प्रथम गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री
3. राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री
4. राजस्थान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री
(A) P-4, Q-3, R-2, S-1

20. (A) 2, 1, 4, 3
एकसदनीय विधानमंडल में साधारण विधेयक सबसे पहले विधानसभा में प्रस्तुत और पढ़ा जाता है। इसके पश्चात विभिन्न चरणों की चर्चा और मतदान के बाद विधानसभा विधेयक को पारित करती है। पारित होने के बाद विधेयक संवैधानिक स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है। अंत में जब राज्यपाल विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान कर देता है, तो वह कानून या अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। यह विधायी प्रक्रिया का सही क्रम है।

21. (B) अनुच्छेद 163
संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अनुसार राज्यपाल को अपने कार्यों का निष्पादन करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। जिन बातों में संविधान द्वारा राज्यपाल को अपने विवेकाधिकार से कार्य करने की अपेक्षा की गई है, उन्हें छोड़कर राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। यह प्रावधान राज्य स्तर पर संसदीय शासन प्रणाली की नींव रखता है जहाँ वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में होती है।

22. (A) I और II
राज्यपाल के पास कुछ परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। यदि चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति में विवेकाधिकार का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त यदि मंत्रिपरिषद सदन में अपना बहुमत खो देती है और त्यागपत्र देने से मना करती है तो वह उसे बर्खास्त कर सकता है। परंतु पूर्ण बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री की सलाह पर ही विधानसभा भंग की जाती है, इसमें अनियंत्रित विवेकाधिकार नहीं होता।

23. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
अनुच्छेद 200 के तहत यदि कोई विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की शक्तियों को इस प्रकार कम करता है कि उसकी संवैधानिक स्थिति खतरे में पड़ जाए, तो राज्यपाल के लिए उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना अनिवार्य है। संविधान यह बाध्यता इसलिए आरोपित करता है ताकि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी कानून के जरिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उच्च न्यायालय की शक्तियों का अतिक्रमण न किया जा सके।

24. (C) विघटन से इनकार करें और एक वैकल्पिक स्थायी सरकार के गठन की संभावनाएं तलाशें।
जब कोई सत्तारूढ़ दल विभाजन के कारण अपना बहुमत खो देता है और मुख्यमंत्री विधानसभा भंग करने की सलाह देता है, तो राज्यपाल इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। ऐसे समय में राज्यपाल को पहले वैकल्पिक स्थायी सरकार के गठन की संभावनाएं तलाशनी चाहिए। यदि कोई वैकल्पिक सरकार बनने की स्थिति न हो, तभी विधानसभा भंग की जानी चाहिए। यह कदम लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

25. (D) मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण करना।
राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों में राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना तथा मुख्यमंत्री से प्रशासनिक जानकारी मांगना शामिल है। परंतु मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों का निर्धारण करने की शक्ति राज्यपाल का विवेकाधिकार नहीं है। यह अधिकार अनुच्छेद 164(5) के तहत राज्य विधानमंडल के पास निहित होता है, जो समय-समय पर कानून बनाकर इनका निर्धारण करता है।

26. (A) अनुमति देने से पहले सीधे विधेयक में संशोधन करना
अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई साधारण विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके पास चार विकल्प होते हैं। वह अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है या राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। परंतु राज्यपाल के पास स्वयं सीधे विधेयक के पाठ में संशोधन करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, क्योंकि कानून बनाने की शक्ति केवल विधानमंडल में निहित है।

27. (B) I, II और IV
धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल के पास सीमित विकल्प होते हैं। वह विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है या उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। हालांकि राज्यपाल किसी भी परिस्थिति में धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस नहीं लौटा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धन विधेयक आमतौर पर राज्यपाल की पूर्व सिफारिश या अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

28. (B) यदि विधानमंडल द्वारा संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के विधेयक पुनः पारित कर दिया जाता है, तो स्वीकृति देना अनिवार्य है।
अनुच्छेद 200 के अंतर्गत यदि राज्यपाल किसी गैर-धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटाता है और विधानमंडल उस विधेयक को संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के पुनः पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है, तो राज्यपाल को उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है और न ही वह किसी साधारण विधेयक को बार-बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है।

29. (A) एक बार राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित हो जाने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति की कोई भूमिका नहीं रह जाती है।
अनुच्छेद 201 के अनुसार जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेता है, तो उस विधेयक पर राज्यपाल की भूमिका समाप्त हो जाती है। इसके बाद पूरी प्रक्रिया राष्ट्रपति के अधीन आ जाती है। राष्ट्रपति या तो विधेयक पर अपनी स्वीकृति देता है या उसे रोक लेता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेजने का निर्देश देता है, तो भी अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति को ही देनी होती है।

Downloaded from www.pdf.tube

होने की योग्यता होनी चाहिए।
(B) व्यक्ति के पास उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए।
(C) व्यक्ति ने राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया होना चाहिए।
(D) व्यक्ति को विधि की डिग्री के साथ एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी होना चाहिए।

107. राज्य के महाधिवक्ता के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
I. राज्य विधानसभा में बोलने का अधिकार।
II. राज्य विधानमंडल की किसी भी समिति की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, जिसका उन्हें सदस्य नामित किया जा सकता है।
III. राज्य विधानसभा में विधायी विधेयकों पर मतदान करने का अधिकार।
IV. उन सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का आनंद जो राज्य विधानमंडल के सदस्य को उपलब्ध हैं।
उपर्युक्त में से कौन-से अधिकार और विशेषाधिकार महाधिवक्ता को प्राप्त हैं?
(A) I, II और IV
(B) I, II और III
(C) II, III और IV
(D) I, III और IV

108. राजस्थान के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है?
(A) एक विशिष्ट अधिनियम के माध्यम से राजस्थान विधानसभा द्वारा
(B) राजस्थान के राज्यपाल द्वारा
(C) राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
(D) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा

109. महाधिवक्ता के पद की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?
(A) महाधिवक्ता एक पूर्णकालिक सरकारी सेवक होता है जिसे निजी वकालत करने से रोका जाता है।
(B) महाधिवक्ता संपूर्ण राज्य क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च गैर-न्यायिक संवैधानिक विधि अधिकारी के रूप में कार्य करता है।
(C) महाधिवक्ता राज्य के राज्यपाल के संवैधानिक प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
(D) यह एक स्थापित परंपरा है कि जब भी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है तो महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र दे देता है।

110. राज्य के गठन के बाद नियुक्त राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे?
(A) एम.बी. शर्मा
(B) एल.एस. सिंघवी
(C) जी.सी. कासलीवाल
(D) बी.पी. अग्रवाल

NODIA

111. सूची I में दिए गए राज्य स्तरीय पदों को सूची II में उन्हें हटाने की शक्ति रखने वाले प्राधिकारी के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (पद)
P. राज्य निर्वाचन आयुक्त
Q. सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग
R. राजस्थान के महाधिवक्ता
S. राजस्थान के मुख्य सचिव
सूची II: (हटाने वाला प्राधिकारी)
1. भारत के राष्ट्रपति
2. राजस्थान के राज्यपाल
3. राज्य सरकार / मुख्यमंत्री
(A) P-1, Q-1, R-2, S-3
(B) P-2, Q-2, R-1, S-3
(C) P-1, Q-2, R-3, S-1
(D) P-2, Q-1, R-3, S-2

112. प्रमुख राज्य कार्यपालक पदों की कार्यकाल सीमाओं या अवधि के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए।
(A) राज्यपाल — आमतौर पर पांच वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत के अधीन
(B) आरपीएससी के सदस्य — छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
(C) महाधिवक्ता — संविधान के तहत पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल
(D) मुख्यमंत्री — जब तक वे विधानसभा में बहुमत का आनंद लेते हैं

113. यद्यपि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, उन्हें केवल पद से हटाया जा सकता है:
(A) राज्य विधानसभा में दो-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा।
(B) उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
(C) राज्य कैबिनेट की बाध्यकारी सलाह पर राज्यपाल द्वारा।
(D) भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा।

114. आरपीएससी के सदस्य और महाधिवक्ता को हटाने की प्रक्रिया के बीच मौलिक अंतर यह है कि:
(A) दोनों अधिकारियों को सीधे राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है, बशर्ते कि आरपीएससी सदस्य की पूर्व में उच्चतम न्यायालय से जांच हुई हो।
(B) आरपीएससी सदस्य को एक औपचारिक विधायी प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है, जबकि महाधिवक्ता को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जाता है।
(C) हटाने की प्रक्रियाओं में कोई संवैधानिक अंतर नहीं है; दोनों पूरी तरह से राज्यपाल के व्यक्तिगत प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
(D) आरपीएससी सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है;

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (C) अनुच्छेद 155
भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। उसकी नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है।

2. (A) I और II
भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख होने के साथ-साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। संविधान में राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। उसे हटाने का पूर्ण अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास निहित है, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।

3. (A) राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को उसके पद की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। शपथ ग्रहण के दौरान राज्यपाल संविधान और कानून के संरक्षण, रक्षण तथा प्रतिरक्षा करने की प्रतिज्ञा लेता है। वह राज्य की जनता के कल्याण और सेवा में समर्पित रहने की भी शपथ लेता है।

4. (C) संविधान राष्ट्रपति को राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की सलाह मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता है।
राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण परंपराएं प्रचलित हैं। पहली परंपरा के अनुसार राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहाँ उसकी नियुक्ति हो रही है। दूसरी परंपरा के तहत राष्ट्रपति नियुक्ति से पूर्व मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श करता है। ये परंपराएं राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने में सहायक हैं। परंतु संविधान में राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री की सलाह मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करने का कोई प्रावधान नहीं है।

5. (A) राजप्रमुख
राजस्थान के एकीकरण के समय राज्य के प्रशासनिक प्रमुख को राजप्रमुख कहा जाता था। सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राजप्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर राज्यपाल का संवैधानिक पद सृजित किया गया। 1 नवंबर 1956 को गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल नियुक्त किए गए। इससे पूर्व महाराजा मानसिंह द्वितीय राजस्थान के अंतिम राजप्रमुख के रूप में कार्यरत थे।

6. (C) 35 वर्ष
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक अहर्ताओं का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त होने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। संविधान में इस पद के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है तथा न ही कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय की गई है।

7. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
संविधान के अनुच्छेद 158(1) में राज्यपाल के पद के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। यदि संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उसे राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करने की तिथि से सदन में अपनी सीट खाली मान ली जाती है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल का पद पूरी तरह से गैर-राजनीतिक और संवैधानिक गरिमा से युक्त रहे।

8. (C) लोक प्रशासन या राजनीति में अनुभव होना चाहिए
संविधान के अनुच्छेद 157 और 158 में राज्यपाल पद की योग्यताएं और शर्तें वर्णित हैं। मुख्य आवश्यकताओं में भारत का नागरिक होना, 35 वर्ष की आयु पूरी करना, किसी लाभ के पद पर न होना तथा संसद या विधानमंडल का सदस्य न होना शामिल है। संविधान में लोक प्रशासन या राजनीति में अनुभव होने की शर्त का कोई उल्लेख नहीं है। यह केवल एक राजनीतिक परिपाटी हो सकती है परंतु कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है।

9. (D) राज्यों के बीच राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में आवंटित किए जाते हैं।
सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 158(3A) के तहत जब एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उसकी उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे। यह वित्तीय बोझ दोनों राज्यों में विभाजित करता है।

Click Here to Buy book on Flipkart

सूची I: (वर्ष)
P. 1967
Q. 1977
R. 1980
S. 1992
सूची II: (राज्यपाल)
1. डॉ. संपूर्णानंद
2. वेदपाल त्यागी (कार्यवाहक)
3. रघुकुल तिलक
4. एम. चेन्ना रेड्डी
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-1, Q-3, R-2, S-4
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

125. 1992 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू होना मुख्य रूप से किस बड़ी राष्ट्रीय घटना के संवैधानिक दुष्परिणामों से जुड़ा था?
(A) राष्ट्रीय आपातकाल का लागू होना।
(B) प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या।
(C) केंद्र में जनता पार्टी द्वारा जीता गया भारी जनादेश।
(D) अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया जाना।

126. स्वीकृति रोकने की राज्यपाल की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: संविधान एक विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित करता है जिसके भीतर राज्यपाल को उसके समक्ष प्रस्तुत विधेयक पर कार्रवाई करनी होती है।
कथन II: किसी विशिष्ट समय-सीमा का न होना राज्यपाल को किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रखकर "पॉकेट वीटो" का प्रयोग करने की अनुमति देता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

127. भारत में राज्यपाल के पद के संबंध में बार-बार उठाए जाने वाले सही समकालीन विवाद या सुधार प्रस्ताव की पहचान कीजिए।
(A) निरंतर राजनीतिक निरंतरता की गारंटी के लिए राज्यपाल के पद को औपचारिक रूप से एक वंशानुगत संवैधानिक पद बनाना।
(B) राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल को वापस बुलाने या हटाने की क्रियाविधि।
(C) विधानसभा द्वारा पारित सभी राज्य बजट प्रस्तावों और धन विधेयकों पर राज्यपाल को पूर्ण संवैधानिक वीटो अधिकार प्रदान करना।
(D) राज्य के राज्यपालों को नियुक्त करने की अनन्य संवैधानिक शक्ति भारत के राष्ट्रपति से सीधे भारत के मुख्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करना।

128. यदि राजस्थान विधानसभा राज्यपाल को वापस बुलाने या हटाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित करती है, तो इसका कानूनी प्रभाव क्या है?
(A) अनिवार्य राष्ट्रपति प्रशासनिक समीक्षा लंबित रहने तक राज्यपाल को तुरंत आधिकारिक निलंबन के तहत रखा जाता है।
(B) यह कानूनी रूप से भारत के राष्ट्रपति को अधिकतम 30 दिनों की समय-सीमा के भीतर राज्यपाल को पद से वापस बुलाने के लिए बाध्य करता है।
(C) कानूनी रूप से प्रभावी होने से पहले प्रस्ताव को उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा औपचारिक रूप से समीक्षित और अनुमोदित किया जाना चाहिए।
(D) इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य करता है।

129. निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए:
I. राज्य के विधेयकों पर स्वीकृति देने में देरी।
II. राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति।
III. सरकार के गठन के दौरान पक्षपातपूर्ण व्यवहार के आरोप।
IV. सिविल सेवकों के दैनिक कार्य के प्रशासनिक तबादलों में हस्तक्षेप।
उपर्युक्त में से कौन-से हालिया राजनीतिक इतिहास में राज्य कार्यपालिका और राज्यपाल के बीच टकराव के सबसे सामान्य स्रोत रहे हैं?
(A) I, II और III
(B) I, II और IV
(C) II, III और IV
(D) I, III और IV

130. गैर-लोकतांत्रिक नियुक्ति होने की आलोचनाओं के बावजूद राज्यपाल के पद को बनाए रखने का सबसे उपयुक्त संवैधानिक औचित्य क्या है?
(A) एक सहायक राजनीतिक तंत्र प्रदान करना जो गैर-निर्वाचित व्यक्तियों को राज्य की नौकरशाही पर प्रत्यक्ष कार्यपालक अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है।
(B) बजटीय मामलों पर निर्वाचित राज्य मंत्रिमंडल को अतिरोहित करने के लिए संवैधानिक रूप से अधिकृत समानांतर कार्यपालक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।
(C) सभी राज्य जिलों में स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं की दैनिक परिचालन गतिविधियों का सीधे संचालन और पर्यवेक्षण करना।
(D) संघ और राज्य को जोड़ना, एकता और संवैधानिक शासन व्यवस्था बनाए रखना।

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

(A) P-2, Q-1, R-4, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

78. नवगठित राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सचिव के रूप में सेवा करने का श्रेय किसे प्राप्त है?
(A) बी. जी. राव
(B) वी. नारायणन
(C) के. राधाकृष्णन
(D) भगवंत सिंह मेहता

79. निम्नलिखित भूमिकाओं पर विचार कीजिए:
I. मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार
II. राज्य मंत्रिमंडल का सचिव
III. राज्य सिविल सेवाओं का प्रमुख
IV. राज्य विधानमंडल का संवैधानिक प्रमुख
उपर्युक्त में से कौन-सी भूमिकाएं राज्य के मुख्य सचिव द्वारा निभाई जाती हैं?
(A) I, II और III
(B) I, II और IV
(C) II, III और IV
(D) I, III और IV

80. राज्य सरकार के मुख्य सचिव को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है?
(A) स्वतंत्र रूप से राज्य के राज्यपाल के पास
(B) भारत के राष्ट्रपति के पास
(C) राज्य के मुख्यमंत्री के पास
(D) संघ लोक सेवा आयोग के पास

81. राज्य में मुख्य सचिव के पद के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए।
(A) मुख्य सचिव सीधे राज्य प्रशासन के आधिकारिक मुख्य जनसंपर्क अधिकारी और मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है।
(B) मुख्य सचिव का संवैधानिक रूप से 5 वर्ष का कार्यकाल निश्चित होता है।
(C) मुख्य सचिव का चयन वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में से वरिष्ठता, प्रशासनिक योग्यता और कार्यपालक विश्वास के संयोजन के आधार पर किया जाता है।
(D) मुख्य सचिव राज्य में बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विभागों के बीच सर्वोच्च संकट प्रबंधक और समन्वयक के रूप में कार्य करता है।

82. राज्य प्रशासन के भीतर मुख्य सचिव की स्थिति का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है?
(A) राज्य के गृह सचिव के अधीनस्थ।
(B) निर्वाचन आयोग के समानांतर एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी।
(C) मुख्य रूप से सिविल सेवाओं के बाहर से चुना गया एक राजनीतिक व्यक्ति।
(D) सचिवों में प्रथम।

83. राजस्थान सरकार में मुख्य सचिव का पद संभालने वाली पहली महिला कौन थीं?
(A) कुशल सिंह
(B) उषा शर्मा
(C) मीनाक्षी हूजा
(D) अलका कला

84. राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी नौकरशाही के बीच संबंधों में, भूमिकाओं का सामान्यतः स्वीकृत विभाजन क्या है?
(A) प्रशासनिक नौकरशाही सभी उच्च-स्तरीय नीतियां बनाती है, जबकि राजनीतिक कार्यपालक उन्हें स्थानीय स्तर पर लागू करते हैं।
(B) दोनों शाखाएं पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से नीतियां बनाती हैं, जिससे राज्यपाल मध्यस्थता करता है और संघर्षों को सुलझाता है।
(C) राजनीतिक कार्यपालिका नीति निर्धारित करती है; नौकरशाही उसका क्रियान्वयन करती है।
(D) गैर-पक्षपातपूर्ण प्रशासनिक तटस्थता की गारंटी के लिए नौकरशाही राजनीतिक निगरानी से पूरी तरह मुक्त होकर काम करती है।

85. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है:
कथन (A): राज्य सरकार में सिविल सेवक राजनीतिक अनामत्ता के सिद्धांत के तहत कार्य करते हैं।
कारण (R): वे सीधे विधानसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं और उन्हें सार्वजनिक बहसों में अपनी नीतियों का बचाव करना होता है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

86. भारत में सिविल सेवकों की राजनीतिक तटस्थता को नियंत्रित करने वाले सही सिद्धांत की पहचान कीजिए।
(A) सक्रिय सरकारी सेवा में रहते हुए एक सिविल सेवक को कानूनी रूप से किसी भी पंजीकृत राजनीतिक दल में कार्यकारी पद संभालने की अनुमति है।
(B) राज्य की नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन की गारंटी के लिए सिविल सेवकों को सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक विचारधारा के साथ जुड़ाव को सार्वजनिक रूप से घोषित करना चाहिए।
(C) जब भी राजनीतिक चुनाव के कारण राज्य सरकार में बदलाव होता है, तो सिविल सेवक संवैधानिक रूप से

NODIA

10. (A) हाँ, संविधान केवल भारत की नागरिकता की मांग करता है, चाहे वह किसी भी प्रकार प्राप्त की गई हो।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए व्यक्ति का केवल भारत का नागरिक होना आवश्यक है। इसमें नागरिकता प्राप्त करने के माध्यम जैसे जन्म, वंशानुक्रम या देशीयकरण के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है। इसलिए देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी राज्यपाल नियुक्त होने के लिए पात्र होता है। अमेरिका के विपरीत भारत में केवल जन्मजात नागरिक होने की बाध्यता नहीं रखी गई है।

11. (B) अनुच्छेद 154
संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करता है। यहाँ अधीनस्थ अधिकारियों का तात्पर्य राज्य के मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से है। यद्यपि राज्यपाल औपचारिक कार्यपालक प्रमुख होता है, किंतु वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है।

12. (A) I, II और III
राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है। वह राज्य के महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। हालांकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल केवल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य करता है।

13. (A) राज्यपाल आरपीएससी के सदस्य को हटा नहीं सकता; केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है।
अनुच्छेद 316 के तहत राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। किंतु अनुच्छेद 317 के अनुसार उन्हें पद से हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास निहित है। राष्ट्रपति केवल कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट के पश्चात ही उन्हें हटा सकता है। यह संवैधानिक प्रावधान आयोग के सदस्यों को स्वतंत्रता प्रदान करता है ताकि वे बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्षता से कार्य कर सकें।

14. (C) विश्वविद्यालय अधिनियमों के तहत एक स्वतंत्र सांविधिक क्षमता में।
राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका एक सांविधिक शक्ति है जो उसे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियमों के माध्यम से प्राप्त होती है। इस क्षमता में कार्य करते समय वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य नहीं होता है। वह कुलपतियों की नियुक्ति और विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक मामलों में अपनी स्वतंत्र सांविधिक शक्तियों का प्रयोग करता है, बशर्ते वह कानून के दायरे में हो।

15. (A) P-3, Q-4, R-2, S-1
संविधान का अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल के पद का उपबंध करता है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान, दंड के निलंबन, परिहार या लघुकरण की न्यायिक शक्तियां दी गई हैं। अनुच्छेद 165 राज्य के लिए महाधिवक्ता के पद की व्यवस्था करता है जो राज्य का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को प्रशासनिक निर्णयों की जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है।

16. (C) राज्य विधानमंडल वर्तमान में सत्र में न हो।
अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यह विधायी शक्ति केवल तभी प्रयोग की जा सकती है जब राज्य विधानमंडल के दोनों सदन या एकसदनीय विधानमंडल की स्थिति में वह सदन सत्र में न हो। यदि राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जिसका प्रभाव विधायी अधिनियम के समान होता है।

17. (A) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने और राज्य विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। हालांकि विधान परिषद एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, केवल समाप्त या सृजित किया जा सकता है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर भी विधान परिषद को भंग करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, जबकि विधानसभा को भंग किया जा सकता है।

18. (B) छह माह
संविधान के अनुच्छेद 174(1) के अनुसार राज्यपाल समय-समय पर राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। परंतु विधानमंडल के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व है कि वर्ष में कम से कम दो सत्र अनिवार्य रुप से आयोजित हों।

19. (C) अनुच्छेद 176
संविधान का अनुच्छेद 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। इसके तहत राज्यपाल प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा को संबोधित करता है। इस अभिभाषण में राज्य सरकार की भावी नीतियां, कार्यक्रम और विधायी प्रस्ताव शामिल होते हैं। यह अभिभाषण वास्तव में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है जिसे राज्यपाल सदन में प्रस्तुत करता है।

Click Here to Buy book on Amazon

(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-4, Q-2, R-3, S-1
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

96. राजस्थान के इतिहास में सबसे लंबी कुल अवधि तक सेवा करने का रिकॉर्ड किस मुख्यमंत्री के नाम है?
(A) अशोक गहलोत
(B) भैरोंसिंह शेखावत
(C) मोहनलाल सुखाड़िया
(D) हरिदेव जोशी

97. पद पर रहते हुए निधन होने वाले राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे?
(A) जयनारायण व्यास
(B) बरकतुल्लाह खान
(C) मथुरा दास माथुर
(D) शिवचरण माथुर

98. राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के ऐतिहासिक कार्यकालों के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए।
(A) अशोक गहलोत ने तीन अलग-अलग कार्यकालों में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है।
(B) भैरोंसिंह शेखावत बाद में भारत के उपराष्ट्रपति बने।
(C) हरिदेव जोशी ने कई बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया लेकिन कभी भी अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया।
(D) टीकाराम पालीवाल ने मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा पूर्ण 5 साल का कार्यकाल पूरा किया।

99. लोकतांत्रिक चुनावों द्वारा विधानसभा की स्थापना से पहले, 1949 में राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री (प्रीमियर) के रूप में किसे मनोनीत किया गया था?
(A) हीरालाल शास्त्री
(B) माणिक्य लाल वर्मा
(C) गोकुलभाई भट्ट
(D) जयनारायण व्यास

100. संविधान की कौन-सी अनुसूची दल-बदल के आधार पर राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है?
(A) आठवीं अनुसूची
(B) नौवीं अनुसूची
(C) दसवीं अनुसूची
(D) ग्यारहवीं अनुसूची

101. दल-बदल विरोधी कानून को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था?
(A) 42वां संशोधन अधिनियम
(B) 44वां संशोधन अधिनियम
(C) 52वां संशोधन अधिनियम
(D) 73वां संशोधन अधिनियम

102. दल-बदल विरोधी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. एक स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य अयोग्य हो जाता है यदि वह चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।
II. एक मनोनीत सदस्य अयोग्य हो जाता है यदि वह अपना पद ग्रहण करने की तारीख से छह महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।
III. दल-बदल के आधार पर अयोग्यता तब लागू नहीं होती जब कोई दल किसी अन्य दल में विलय हो जाता है और विधान दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य विलय के लिए सहमत होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) I और II
(B) II और III
(C) I और III
(D) I, II और III

NODIA

103. दसवीं अनुसूची के तहत राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्नों पर अंतिम निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है?
(A) राजस्थान के राज्यपाल
(B) विधानसभा अध्यक्ष
(C) राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(D) भारत का निर्वाचन आयोग

104. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है:
कथन (A): दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
कारण (R): उच्चतम न्यायालय ने किहोतो होलोहान मामले (1992) में फैसला सुनाया कि दसवीं अनुसूची के तहत मामलों का निर्णय करते समय अध्यक्ष एक अधिकरण के रूप में कार्य करता है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

105. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है?
(A) अनुच्छेद 165
(B) अनुच्छेद 166
(C) अनुच्छेद 177
(D) अनुच्छेद 214

106. राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) व्यक्ति के पास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त

30. (C) जल्दबाज़ी में बनाए गए या असंवैधानिक विधान को रोकना।
साधारण विधेयक पर स्वीकृति रोकने या उसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटाने की राज्यपाल की वीटो शक्ति का मुख्य उद्देश्य जल्दबाज़ी में, बिना विचार-विमर्श के या असंवैधानिक रूप से तैयार किए गए कानूनों को रोकना है। यह शक्ति राज्य विधानमंडल को अपने निर्णयों पर पुनः गंभीर चिंतन करने का अवसर प्रदान करती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि राज्य के कानून संविधान के प्रावधानों और जनहित के प्रतिकूल न हों।

31. (A) P-1, Q-4, R-3, S-2
अनुच्छेद 164 के तहत मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का हिस्सा है। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमादान प्रदान करना राज्यपाल की न्यायिक शक्ति में आता है। अनुच्छेद 200 में दिए गए विधेयकों पर अनुमति देने का अधिकार राज्यपाल की विधायी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना राज्यपाल की एक प्रमुख विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है।

32. (C) अनुच्छेद 356
संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यदि राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है। इस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन (राज्य आपातकाल) की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी यह कदम उठाने के लिए संवैधानिक रूप से सक्षम होता है।

33. (B) I और III
राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का प्रत्यक्ष प्रशासन चलाता है। इस दौरान राज्य मंत्रिपरिषद निलंबित या बर्खास्त कर दी जाती है, इसलिए राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता के बिना कार्य करता है। वह राज्य प्रशासन को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए मुख्य सचिव, सलाहकारों और अन्य वरिष्ठ सिविल सेवकों की सेवाओं का प्रत्यक्ष उपयोग करता है।

34. (D) इसे या तो भंग कर दिया जाता है या निलंबन की अवस्था में रखा जाता है।
राजस्थान में जब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो राज्य विधानसभा को या तो भंग कर दिया जाता है या फिर निलंबित अवस्था में रखा जाता है। संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का अनुमोदन होने तक आमतौर पर विधानसभा को निलंबित रखा जाता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की विधायी शक्ति भारत की संसद को हस्तांतरित हो जाती है और विधानसभा अपनी सामान्य कार्यप्रणाली रोक देती है।

35. (A) राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह परे है।
एस.आर. बोम्मई मामले (1994) में उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यदि राष्ट्रपति शासन गलत मंशा से या अप्रासंगिक आधारों पर लगाया गया है तो अदालत उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होता है।

36. (C) भारत की संसद द्वारा
किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां संसद को सौंप दी जाती हैं। इस अवधि के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत होती है। संसद इन शक्तियों को राष्ट्रपति या उसके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी को भी सौंप सकती है। राज्य का राज्यपाल इस समय केवल कार्यपालक आदेश जारी कर सकता है, परंतु विधायी अधिकार संसद के पास रहते हैं।

37. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को मृत्युदंड को पूरी तरह क्षमा करने की अनन्य शक्ति प्रदान करता है, चाहे वह सजा संघ कानून के तहत दी गई हो या राज्य कानून के तहत। इसके विपरीत अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति तो है, परंतु वह मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकता। वह केवल मृत्युदंड के लघूकरण, निलंबन या परिहार का आदेश दे सकता है, पूर्ण क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है।

38. (D) क्षमा, प्रविलंबन या विराम प्रदान करने की कोई शक्ति नहीं होती है।
सैन्य अदालत (कोर्ट मार्शल) द्वारा दिए गए दंड या सजा के मामले में राज्य के राज्यपाल के पास क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार देने की कोई संवैधानिक शक्ति नहीं होती है। यह अधिकार अनुच्छेद 72 के तहत विशेष रूप से केवल भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, इसलिए सैन्य अदालतों के फैसले के खिलाफ राहत देने का अधिकार भी केवल राष्ट्रपति को ही दिया गया है।

39. (B) केवल II
राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संबंधित विधानमंडल या संसद सत्र में न हो। दोनों द्वारा जारी अध्यादेशों का प्रभाव विधायी अधिनियम के समान होता है। परंतु अध्यादेश जारी करने की शक्ति व्यक्तिगत विवेकाधिकार नहीं है, बल्कि यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग की जाती है। इसके अलावा राज्यपाल को कुछ विशेष विषयों पर अध्यादेश जारी करने से पूर्व राष्ट्रपति के निर्देशों की आवश्यकता होती है।

Downloaded from www.pdf.tube

लगाना तथा संसद और राज्य विधानमंडलों में चुनी हुई सरकारों को राजनीतिक स्थायित्व प्रदान करना था।

102. (D) I, II और III
दसवीं अनुसूची के अनुसार स्वतंत्र निर्वाचित सदस्य यदि चुनाव के बाद किसी दल में शामिल होता है तो अयोग्य हो जाता है। मनोनीत सदस्य यदि 6 माह के बाद किसी दल में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। हालांकि यदि किसी दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य दल में विलय के लिए सहमत होते हैं, तो इसे वैध माना जाता है और उन पर दल-बदल कानून के तहत अयोग्यता लागू नहीं होती।

103. (B) विधानसभा अध्यक्ष
संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत राज्य विधानसभा के किसी सदस्य की दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। जब कोई दल-बदल की याचिका दायर की जाती है, तो अध्यक्ष एक अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए मामले की सुनवाई करता है और अपना निर्णय देता है। अध्यक्ष की मंजूरी के बिना अयोग्यता लागू नहीं होती।

104. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
किहोतो होलोहान मामले (1992) में उच्चतम न्यायालय की पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के मामलों का फैसला करते समय विधानसभा अध्यक्ष एक अधिकरण के रूप में कार्य करता है। इसलिए अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम नहीं है और वह उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के अधीन है। न्यायालय अयोग्यता के निर्णयों की संवैधानिक वैधता की जांच कर सकता है।

105. (A) अनुच्छेद 165
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। वह राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी और मुख्य विधिक सलाहकार होता है। वह राज्य सरकार को उन कानूनी मामलों पर सलाह देता है जो राज्यपाल द्वारा उसे सौंपे जाते हैं तथा अदालतों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है।

106. (A) व्यक्ति के पास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए।
संविधान के अनुच्छेद 165(1) के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति में वे सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक हैं। इसके लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसने भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो।

107. (A) I, II और IV
अनुच्छेद 177 के तहत महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल के सदनों में बोलने और उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। उसे विधानमंडल की किसी समिति का सदस्य भी नामित किया जा सकता है। उसे विधायकों को प्राप्त सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां मिलती हैं। परंतु महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसे सदन में प्रस्तुत किसी भी विधायी विधेयक या प्रस्ताव पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

108. (B) राजस्थान के राज्यपाल द्वारा
संविधान में महाधिवक्ता के वेतन और भत्तों को निश्चित रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अनुच्छेद 165(3) के अनुसार महाधिवक्ता को ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त होता है जो राज्यपाल द्वारा अवधारित या निर्धारित किया जाए। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इसलिए उसके भत्तों और वित्तीय पारिश्रमिक का निर्धारण भी राज्य विधानमंडल के स्थान पर सीधे राज्यपाल के आदेशों द्वारा ही किया जाता है।

109. (A) महाधिवक्ता एक पूर्णकालिक सरकारी सेवक होता है जिसे निजी वकालत करने से रोका जाता है।
महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक कानून अधिकारी होता है, परंतु वह कोई पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं होता है। उसे सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है और उसे निजी कानूनी वकालत करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, बशर्ते वह राज्य सरकार के खिलाफ किसी मामले में पैरवी न करे। वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और सरकार बदलने पर आमतौर पर अपना त्यागपत्र दे देता है।

110. (C) जी.सी. कासलीवाल
राजस्थान राज्य के एकीकरण और पुनर्गठन के पश्चात राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बनने का गौरव जी.सी. कासलीवाल को प्राप्त हुआ था। उन्होंने 1956 में राजस्थान के पहले महाधिवक्ता के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया था। राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में उन्होंने उच्च न्यायालय में राज्य सरकार का प्रभावी प्रतिनिधित्व किया और नवगठित राज्य के कानूनी ढांचे को मजबूत आधार प्रदान करने में भूमिका निभाई।

111. (A) P-1, Q-1, R-2, S-3
राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। आरपीएससी के सदस्यों को भी जांच के बाद राष्ट्रपति ही हटा सकता है। इसके विपरीत राज्य के महाधिवक्ता को राज्यपाल द्वारा किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है। वहीं मुख्य सचिव प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसे राज्य सरकार या मुख्यमंत्री द्वारा स्थानांतरित या पद से हटाया जा सकता है।

NODIA

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from
PRINTED BOOKS has up to
4× HIGHER RETENTION
than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

50. (D) मुख्यमंत्री के बिना मंत्रिपरिषद का अस्तित्व या कार्यप्रणाली संभव नहीं है।
प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक लॉर्ड मार्ले ने मुख्यमंत्री को "मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला" कहा है। इसका अर्थ यह है कि पूरी मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के इर्द-गिर्द घूमती है। वही मंत्रियों को नियुक्त करवाता है, विभागों का बंटवारा करता है और बैठकों का नेतृत्व करता है। यदि मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, तो मंत्रिपरिषद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अतः उसके बिना मंत्रिपरिषद कार्य नहीं कर सकती।

51. (A) मुख्यमंत्री
संसदीय व्यवस्था में मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य संचार के प्रमुख माध्यम के रूप में कार्य करता है। राज्य प्रशासन, नीतिगत निर्णयों और विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल तक पहुँचाना मुख्यमंत्री का संवैधानिक दायित्व है। राज्यपाल द्वारा मांगी गई कोई भी प्रशासनिक जानकारी प्रदान करना भी मुख्यमंत्री का ही कर्तव्य होता है, जिससे शासन में पारदर्शिता बनी रहती है।

52. (D) अनुच्छेद 167
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 स्पष्ट रूप से राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री का यह दायित्व है कि वह राज्य के प्रशासनिक मामलों और विधान के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराए। इसके अतिरिक्त यदि राज्यपाल राज्य प्रशासन के विषय में कोई जानकारी मांगता है, तो वह प्रस्तुत करना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है।

53. (A) P-2, Q-4, R-3, S-1
अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और सामूहिक उत्तरदायित्व से संबंधित उपबंध शामिल हैं। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्य संचालन और कार्यपालक कार्यवाहियों के नामकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को राज्य के प्रशासनिक मामलों तथा विधायी प्रस्तावों की जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का विवरण दिया गया है।

54. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
अनुच्छेद 167(c) के तहत यदि किसी व्यक्तिगत मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया है किंतु उस पर पूरी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस विषय को पूरी मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने की मांग कर सकता है। यह संवैधानिक प्रावधान मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को मजबूत करता है, ताकि सभी प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर संपूर्ण मंत्रिमंडल की सर्वसम्मति और सामूहिक स्वीकृति सुनिश्चित हो सके।

55. (B) मुख्यमंत्री एक संवैधानिक कड़ी के रूप में कार्य करता है जो राज्यपाल को राज्य के सभी मामलों की जानकारी देता है।
मुख्यमंत्री राज्य में संवैधानिक प्रमुख (राज्यपाल) और वास्तविक कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) के बीच मुख्य योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन और विधायी मामलों के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की नियमित जानकारी राज्यपाल को प्रदान करे। वह राज्यपाल को राज्य की समस्त प्रशासनिक गतिविधियों से अवगत रखता है।

56. (C) राज्यपाल द्वारा मांगी गई ऐसी जानकारी प्रदान करे।
संविधान के अनुच्छेद 167(b) के तहत यदि राज्यपाल राज्य के मामलों के प्रशासन या विधान के प्रस्तावों से संबंधित कोई विशेष जानकारी मांगता है, तो मुख्यमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह मांगी गई जानकारी तुरंत राज्यपाल को उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री इस अनुरोध को टाल नहीं सकता और न ही इसे गुप्त बताकर इनकार कर सकता है, क्योंकि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते जानकारी पाने का हकदार है।

57. (C) 15 प्रतिशत
वर्ष 2003 में पारित 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 164(1A) जोड़ा गया। इसके अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य जंबो मंत्रिमंडलों के गठन को रोकना, राजनीतिक निष्ठा बदलने के प्रलोभन को समाप्त करना तथा सरकारी खर्च में कमी लाना था।

58. (C) 30
राजस्थान विधानसभा में कुल 200 निर्वाचित सदस्य हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिकतम 15 प्रतिशत तक ही सीमित हो सकता है। अतः 200 सदस्यों का 15 प्रतिशत निकालने पर 30 की संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल अधिकतम संख्या 30 हो सकती है, जिससे अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते।

59. (B) 12
91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुच्छेद 164(1A) में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। यह नियम छोटे राज्यों में प्रशासनिक दक्षता और विभिन्न विभागों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। अतः किसी राज्य मंत्रिपरिषद में अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत तथा न्यूनतम सीमा मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्रियों की तय की गई है।

60. (A) I, II और III
राज्य मंत्रिपरिषद के आकार की 15 प्रतिशत की संवैधानिक सीमा की गणना करते समय मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य

Click Here to Buy book on Flipkart

के आधार पर मुख्य सचिव का चयन करता है। मुख्य सचिव का कार्यकाल भी मुख्यमंत्री के विश्वास और विवेक पर निर्भर करता है।

81. (B) मुख्य सचिव का संवैधानिक रूप से 5 वर्ष का कार्यकाल निश्चित होता है।
मुख्य सचिव का पद कोई निश्चित संवैधानिक कार्यकाल वाला पद नहीं है। उनका कार्यकाल पूरी तरह से राज्य के मुख्यमंत्री की इच्छा और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री जब चाहे मुख्य सचिव को बदल सकता है या उनका स्थानांतरण कर सकता है। हालांकि मुख्य सचिव राज्य प्रशासन के मुख्य प्रवक्ता, वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी और प्राकृतिक आपदाओं के समय सर्वोच्च संकट प्रबंधक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं।

82. (D) सचिवों में प्रथम।
राज्य प्रशासनिक पदानुक्रम में मुख्य सचिव को "सचिवों में प्रथम" माना जाता है। वह राज्य सचिवालय का वरिष्ठतम अधिकारी होता है और सभी विभागों के सचिवों का मार्गदर्शन तथा नियंत्रण करता है। यद्यपि सभी सचिव अपने-अपने विभागों के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, परंतु मुख्य सचिव संपूर्ण राज्य नौकरशाही का प्रमुख होता है और समन्वय तथा नियंत्रण की दृष्टि से उसका स्थान सर्वोच्च होता है।

83. (A) कुशल सिंह
राजस्थान के प्रशासनिक इतिहास में श्रीमती कुशल सिंह को राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 2009 में इस उच्च प्रशासनिक पद को संभाला था। वह 1974 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी थीं। उनके बाद श्रीमती उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनीं। कुशल सिंह ने राज्य प्रशासन में महिला नेतृत्व की एक नई दिशा और मिसाल कायम की थी।

84. (C) राजनीतिक कार्यपालिका नीति निर्धारित करती है; नौकरशाही उसका क्रियान्वयन करती है।
लोक प्रशासन में राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी नौकरशाही के बीच स्पष्ट कार्य विभाजन होता है। निर्वाचित राजनीतिक कार्यपालिका (मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद) जनता की आकांक्षाओं के अनुसार नीतियां और कानून निर्धारित करती है। वहीं स्थायी कार्यपालिका अर्थात प्रशासनिक नौकरशाही अपनी तकनीकी विशेषज्ञता, अनुभव और निष्पक्षता के आधार पर उन स्वीकृत नीतियों और कानूनों को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करती है तथा प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखती है।

85. (C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
सिविल सेवक राजनीतिक अनामत्ता के सिद्धांत के तहत कार्य करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। वे सीधे विधानमंडल के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं, और न ही वे सार्वजनिक मंचों या बहसों में सरकारी नीतियों का बचाव करते हैं। नीतियों की सफलता या विफलता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग के राजनीतिक मंत्री की होती है, जो संसद या विधानसभा के प्रति सीधे उत्तरदायी होता है।

86. (D) सिविल सेवकों को जो भी सरकार सत्ता में हो, उसकी निष्ठापूर्वक सेवा करनी चाहिए।
भारतीय सिविल सेवा का मूल आधार राजनीतिक तटस्थता का सिद्धांत है। इसके अनुसार सिविल सेवकों को अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक मान्यताओं से परे रहकर, सत्ता में आने वाली किसी भी राजनीतिक दल की सरकार की नीतियों को निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से लागू करना अनिवार्य है। उन्हें किसी राजनीतिक दल से जुड़ाव रखने, चुनाव प्रचार करने या सार्वजनिक रूप से राजनीतिक विचार व्यक्त करने से आचरण नियमों द्वारा सख्ती से रोका जाता है।

87. (A) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
राज्य सरकार में सचिव अपने विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है और वह नीति-निर्माण तथा प्रशासन के संबंध में प्रभारी मंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति निर्वाचित मंत्री के पास ही होती है। यदि सचिव मंत्री के निर्णय से असहमत भी हो, तो भी उसके पास मंत्री के फैसले को रद्द करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता, उसे मंत्री का आदेश मानना पड़ता है।

88. (C) मतदाताओं के प्रति प्रत्यक्ष जवाबदेही
स्थायी कार्यपालिका अर्थात नौकरशाही की मुख्य विशेषताओं में कार्यकाल की सुरक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा योग्यता आधारित चयन, राजनीतिक तटस्थता और अनामत्ता शामिल हैं। मतदाताओं के प्रति प्रत्यक्ष जवाबदेही राजनीतिक कार्यपालिका (नेताओं व मंत्रियों) की विशेषता होती है, जो हर पांच साल में चुनावों का सामना करते हैं। नौकरशाही प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं चुनी जाती, इसलिए उसकी जनता के प्रति सीधी चुनावी जवाबदेही नहीं होती है।

89. (C) 200
वर्तमान परिसीमन और संवैधानिक संरचना के अनुसार राजस्थान विधानसभा में कुल 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। वर्ष 1952 में प्रथम विधानसभा चुनाव के समय सीटों की संख्या 160 थी, जो बाद में बढ़कर 1977 में छठी विधानसभा के दौरान 200 हो गई। राजस्थान एकसदनीय विधानमंडल वाला राज्य है जहाँ केवल विधानसभा अस्तित्व में है और राज्य के सभी 200 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं।

90. (A) जिला प्रशासनिक इकाइयों और प्रशासनिक क्षेत्रीय तैनातियों का विस्तार करके।
राजस्थान में नए जिलों के गठन से राज्य के कार्यपालक और प्रशासनिक तंत्र में सीधा प्रभाव पड़ता है। इससे जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य विभागीय अधिकारियों के नए पदों का सृजन होता है और प्रशासनिक इकाइयों का विस्तार होता है। नए जिलों के गठन से प्रशासनिक पहुंच जनता के निकट होती है, परंतु इससे विधानसभा सीटों की संख्या पर तुरंत कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सीटें परिसीमन आयोग द्वारा तय होती हैं।

NODIA

के कानूनी उत्तरदायित्व की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया है। भारत में किसी मंत्री द्वारा राज्यपाल के आदेशों पर प्रतिहस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती है और न ही अदालतें मंत्रियों की सलाह की जांच कर सकती हैं।

71. (B) कानूनी जिम्मेदारी तय करने के लिए किसी सार्वजनिक कार्य के लिए राज्यपाल के आदेश पर मंत्री द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
भारत में मंत्रियों के कानूनी उत्तरदायित्व की व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत, जहाँ राजा के प्रत्येक आदेश पर मंत्री का प्रतिहस्ताक्षर अनिवार्य होता है, भारत में राज्यपाल के सार्वजनिक कार्यों और आदेशों पर मंत्रियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करने की कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा अनुच्छेद 163(3) के अनुसार मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है।

72. (B) अनुच्छेद 164
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रियों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की आधारशिला है। अनुच्छेद 164(1) जहाँ यह तय करता है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे (जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का आधार है), वहीं अनुच्छेद 164(2) यह स्थापित करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इस प्रकार यही अनुच्छेद मंत्रिस्तरीय उत्तरदायित्व के दोनों सिद्धांतों को संवैधानिक मान्यता देता है।

73. (D) मंत्रिपरिषद एक बड़ा संवैधानिक निकाय है; मंत्रिमंडल इसका छोटा नीति-निर्माता मुख्य भाग है।
मंत्रिपरिषद एक व्यापक संवैधानिक निकाय है जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री सभी शामिल होते हैं। इसके विपरीत मंत्रिमंडल (कैबिनेट) मंत्रिपरिषद का एक छोटा और अधिक शक्तिशाली आंतरिक भाग होता है, जिसमें केवल वरिष्ठ कैबिनेट रैंक के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल ही राज्य के वास्तविक नीति-निर्माण और प्रशासनिक निर्णयों का संचालन करता है, जबकि मंत्रिपरिषद की बैठकें नीतियों को मंजूरी देने के लिए कभी-कभार ही होती हैं।

74. (B) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
"किचन कैबिनेट" या आंतरिक कैबिनेट कोई संवैधानिक या सांविधिक निकाय नहीं है, बल्कि यह एक अनौपचारिक और गैर-संवैधानिक संस्था है। इसमें मुख्यमंत्री और उनके कुछ अत्यंत प्रभावशाली तथा विश्वसनीय सहयोगी शामिल होते हैं, जिनमें कभी-कभार रिश्तेदार या मित्र भी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक निर्णय इसी छोटे समूह में लिए जाते हैं। संविधान में कहीं भी किचन कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है।

75. (B) राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट)
राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था तथा सर्वोच्च कार्यपालक अंग के रूप में कार्य करता है। यह राज्य सरकार की सभी महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण करता है, विधायी प्रस्तावों को मंजूरी देता है तथा अंतर-विभागीय विवादों को सुलझाता है। यद्यपि सभी कार्यपालक निर्णय राज्यपाल के नाम से लिए जाते हैं, किंतु वास्तविक सत्ता और नियंत्रण राज्य कैबिनेट के पास ही केंद्रित रहता है।

76. (B) यह मंत्रिमंडल का एजेंडा तैयार करता है और मंत्रिमंडल के निर्णयों के कार्यान्वयन का समन्वय करता है।
राज्य मंत्रिमंडल सचिवालय राज्य प्रशासन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नोडल अंग है। इसका मुख्य कार्य मंत्रिमंडल और उसकी समितियों को सचिवीय सहायता प्रदान करना है। यह कैबिनेट बैठकों का एजेंडा तैयार करता है, बैठकों की कार्यवाही का विवरण रखता है तथा मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन का विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करता है। यह मुख्य सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण में सीधे कार्य करता है।

NODIA

77. (A) P-2, Q-1, R-4, S-3
राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यपालक प्रमुख होता है, जबकि राज्यपाल राज्य का औपचारिक या विधिगत प्रमुख होता है। मुख्य सचिव राज्य लोक सेवा का प्रशासनिक प्रमुख और मुख्यमंत्री का मुख्य प्रशासनिक सलाहकार होता है। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। ये सभी पद राज्य के प्रशासनिक और संवैधानिक ढांचे को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

78. (C) के. राधाकृष्णन
राजस्थान राज्य के गठन और एकीकरण के पश्चात राज्य के प्रथम मुख्य सचिव बनने का गौरव के. राधाकृष्णन को प्राप्त हुआ था। उन्होंने 13 अप्रैल 1949 से 2 मई 1950 तक इस पद पर अपनी सेवाएं दीं। मुख्य सचिव राज्य की सिविल सेवाओं का प्रशासनिक प्रमुख होता है। नवगठित राजस्थान राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और विभिन्न रियासतों के प्रशासनिक तंत्र को एकीकृत करने में उनकी भूमिका अत्यंत सराहनीय रही थी।

79. (A) I, II और III
राज्य का मुख्य सचिव अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिकाएं निभाता है। वह मुख्यमंत्री का मुख्य प्रशासनिक सलाहकार, राज्य मंत्रिमंडल का सचिव तथा राज्य की संपूर्ण सिविल सेवाओं का प्रमुख होता है। वह प्रशासनिक तंत्र का समन्वय करता है और संकट के समय मुख्य प्रबंधक होता है। हालांकि राज्य विधानमंडल का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, मुख्य सचिव का संबंध मुख्य रूप से राज्य की कार्यपालिका और नौकरशाही के संचालन से होता है।

80. (C) राज्य के मुख्यमंत्री के पास
राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति पूर्ण रूप से राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। इस नियुक्ति में किसी प्रतियोगी परीक्षा या अन्य निकाय की भूमिका नहीं होती। मुख्यमंत्री वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के कैडर में से प्रशासनिक क्षमता, अनुभव, वरिष्ठता और व्यक्तिगत विश्वास

40. (C) राष्ट्रपति के विपरीत, संविधान राज्यपाल को स्पष्ट विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता है।
संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को स्पष्ट रूप से संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं, जहाँ वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। इसके विपरीत राष्ट्रपति के पास संविधान में ऐसी कोई स्पष्ट लिखित विवेकाधीन शक्ति नहीं है; उसे 44वें संशोधन के बाद मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना होता है। यह एक मौलिक अंतर है जो राज्यपाल को कुछ परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर देता है।

41. (D) राष्ट्रपति के विपरीत, राज्यपाल महाभियोग के बिना राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
राष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत संसद में संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग की एक जटिल प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इसके विपरीत राज्यपाल को पद से हटाने के लिए संविधान में महाभियोग जैसी किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। राज्यपाल अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बना रहता है और केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसे किसी भी समय पद से हटा सकता है।

42. (C) अनुच्छेद 164
संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर ही की जाती है। सामान्यतः राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक कार्यपालक प्रमुख होता है और वह राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन करने तथा उसका नेतृत्व करने के लिए उत्तरदायी होता है।

43. (B) चुनाव परिणाम → मुख्यमंत्री की नियुक्ति → शपथ ग्रहण समारोह → विश्वास मत
आम चुनावों के बाद सरकार गठन की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव परिणामों की आधिकारिक घोषणा की जाती है। इसके पश्चात राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। फिर राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। शपथ ग्रहण के बाद यदि आवश्यक हो, तो मुख्यमंत्री को तय सीमा के भीतर सदन के पटल पर विश्वास मत हासिल करना होता है।

44. (B) राज्यपाल आमतौर पर विधानसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है।
संसदीय लोकतंत्र की स्थापित परिपाटी के अनुसार राज्यपाल विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने वाले दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। हालांकि यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, तो राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। गैर-विधायक व्यक्ति भी मुख्यमंत्री नियुक्त हो सकता है बशर्ते वह छह माह में सदस्यता प्राप्त कर ले। इसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुसमर्थन की कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं होती है।

45. (A) उसे छह महीने के भीतर राज्य विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करनी होगी अन्यथा त्यागपत्र देना होगा।
अनुच्छेद 164(4) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त होता है जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उसे अपनी नियुक्ति की तारीख से निरंतर छह महीने की अवधि के भीतर विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। यदि वह छह महीने के भीतर सदस्यता प्राप्त करने में विफल रहता है, तो छह महीने की समाप्ति पर उसका मुख्यमंत्री या मंत्री का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है।

46. (C) टीकाराम पालीवाल
वर्ष 1952 में आयोजित राजस्थान के प्रथम आम चुनावों के बाद लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बने थे। उन्होंने मार्च 1952 से नवंबर 1952 तक इस पद पर कार्य किया। हीरालाल शास्त्री और जयनारायण व्यास चुनाव से पूर्व मनोनीत मुख्यमंत्री रहे थे। टीकाराम पालीवाल ने राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखने और प्रथम निर्वाचित सरकार का संचालन करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

47. (D) I, II और III
मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख और केंद्रीय धुरी होता है। वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है तथा कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने या उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है। यह प्रावधान दर्शाता है कि मुख्यमंत्री के बिना मंत्रिपरिषद का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है और वही पूरी सरकार का नेतृत्व करता है।

48. (C) वह राज्य लोक सेवा आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
मुख्यमंत्री राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है और विधानमंडल के सत्र आहूत करने तथा विधानसभा भंग करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है। परंतु वह राज्य लोक सेवा आयोग का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है। आयोग का अध्यक्ष एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री प्रशासनिक और नीतिगत मामलों का प्रमुख होता है, निष्पादक निकायों का पदेन प्रमुख नहीं।

49. (B) मुख्यमंत्री राज्यपाल को उस मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है।
संसदीय शासन प्रणाली में मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का निर्बाध नेता होता है। यदि किसी मंत्री के साथ नीतिगत मतभेद होते हैं या मुख्यमंत्री किसी मंत्री से त्यागपत्र मांगता है और मंत्री मना कर देता है, तो मुख्यमंत्री के पास दो मानक विकल्प होते हैं। वह या तो राज्यपाल को उस मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है या फिर स्वयं त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को पुनर्गठित कर सकता है।

Downloaded from www.pdf.tube

91. (A) SC के लिए 34 और ST के लिए 25
वर्तमान परिसीमन आदेशों के अनुसार राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटों में से अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें से अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 34 सीटें तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 25 सीटें आरक्षित हैं। शेष 141 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। यह आरक्षण समाज के वंचित वर्गों को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।

92. (B) यह विधानसभा की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है।
106वें संविधान संशोधन अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) का मुख्य उद्देश्य लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना है। लागू होने के बाद यह राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटों में से लगभग एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देगा। इससे राज्य के नीति-निर्माण और विधायी प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी और राजनीतिक सशक्तिकरण में अभूतपूर्व वृद्धि होगी।

93. (B) 2026
84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा सीटों की कुल संख्या 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक स्थिर रहेगी। इसी कारण राजस्थान विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 200 पर ही बनी हुई है, जो 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली जनगणना के बाद नया परिसीमन लागू होगा।

94. (A) 2, 1, 4, 3
राजस्थान के इन मुख्यमंत्रियों के पहली बार पद ग्रहण करने का सही कालानुक्रम मोहनलाल सुखाड़िया (1954), भैरोंसिंह शेखावत (1977), अशोक गहलोत (1998) तथा वसुंधरा राजे (2003) है। मोहनलाल सुखाड़िया ने सबसे पहले 1954 में कार्यभार संभाला था। भैरोंसिंह शेखावत 1977 में राज्य के प्रथम गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। अशोक गहलोत ने 1998 में पहली बार पद संभाला और वसुंधरा राजे ने 2003 में राज्य की कमान संभाली थी।

95. (A) P-4, Q-3, R-2, S-1
मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के सबसे लंबे समय (17 वर्ष) तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। बरकतुल्लाह खान राज्य के प्रथम एवं एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। भैरोंसिंह शेखावत 1977 में राज्य के प्रथम गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। वसुंधरा राजे वर्ष 2003 में राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं। यह सुमेलित क्रम राज्य के राजनीतिक इतिहास के प्रमुख पड़ावों को दर्शाता है।

96. (C) मोहनलाल सुखाड़िया
राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में मोहनलाल सुखाड़िया के नाम सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का कीर्तिमान है। उन्होंने 1954 से 1971 तक लगातार लगभग 17 वर्षों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। उनके कार्यकाल में राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई तथा कृषि, शिक्षा और बुनियादी ढांचे का व्यापक विकास किया गया था।

97. (B) बरकतुल्लाह खान
बरकतुल्लाह खान राजस्थान के ऐसे पहले और एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। उन्होंने जुलाई 1971 से अक्टूबर 1973 तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 11 अक्टूबर 1973 को हृदय गति रुक जाने के कारण पद पर रहते हुए उनका देहावसान हो गया था। वे 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान राज्य के प्रशासनिक प्रमुख थे और उन्होंने कुशल नेतृत्व प्रदान किया था।

98. (D) टीकाराम पालीवाल ने मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा पूर्ण 5 साल का कार्यकाल पूरा किया।
टीकाराम पालीवाल ने मार्च 1952 से नवंबर 1952 तक केवल आठ महीने ही मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था, उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। अशोक गहलोत तीन बार मुख्यमंत्री रहे हैं और भैरोंसिंह शेखावत बाद में भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। हरिदेव जोशी ने तीन बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, परंतु वे कभी भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे।

99. (A) हीरालाल शास्त्री
वर्ष 1949 में वृहत् राजस्थान के गठन के पश्चात पंडित हीरालाल शास्त्री को राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया था। उन्होंने 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक इस पद पर कार्य किया। उस समय लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हुए थे, इसलिए वे मनोनीत प्रमुख थे। उन्होंने एकीकरण के शुरुआती दौर में प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने और रियासतों को एक सूत्र में पिरोने में ऐतिहासिक योगदान दिया था।

100. (C) दसवीं अनुसूची
भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची दल-बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करती है। इसे आमतौर पर दल-बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता को रोकना, अवसरवादी राजनीतिक दल-बदल पर अंकुश लगाना तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की शुचिता और मतदाताओं के जनादेश का सम्मान बनाए रखना है, ताकि राजनीतिक निष्ठा न बदली जा सके।

101. (C) 52वां संशोधन अधिनियम
दल-बदल विरोधी कानून को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इसके द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई तथा अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन किए गए। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य विधायिकाओं में राजनीतिक दल-बदल की बुराई को समाप्त करना, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर रोक

NODIA

मंत्री (स्वतंत्र प्रभार या सामान्य) की श्रेणियों को शामिल किया जाता है। संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद के औपचारिक संवैधानिक सदस्य नहीं माने जाते हैं, हालांकि उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। इसलिए 15 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का निर्धारण करते समय केवल तीनों स्तरों के मंत्रियों की गणना की जाती है।

61. (B) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते संविधान में निश्चित रूप से निर्दिष्ट नहीं हैं; बल्कि अनुच्छेद 164(5) के अनुसार इनका निर्धारण समय-समय पर राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर किया जाता है। हालांकि अनुच्छेद 164(3) के तहत किसी मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। इसलिए मंत्रियों की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाना एक अनिवार्य संवैधानिक प्रक्रिया है।

62. (B) तीसरी अनुसूची
भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदों, जैसे राज्य के मंत्रियों, विधायकों, न्यायाधीशों आदि द्वारा ली जाने वाली पद और गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान के निर्धारित प्रारूप शामिल हैं। जब कोई व्यक्ति राज्य में मंत्री के रूप में नियुक्त होता है, तो वह अनुच्छेद 164(3) के अनुसार तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के तहत ही राज्यपाल के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है।

63. (D) राज्य विधानसभा
संविधान के अनुच्छेद 164(2) में स्पष्ट रूप से यह उपबंध किया गया है कि राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद केवल तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है। यदि विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को तुरंत त्यागपत्र देना पड़ता है।

64. (C) मंत्रियों को मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों का सार्वजनिक रूप से समर्थन करना चाहिए अन्यथा त्यागपत्र दे देना चाहिए।
सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय प्रणाली का एक आधारभूत सिद्धांत है। इसका तात्पर्य यह है कि मंत्रिमंडल की बैठकों में भले ही किसी विषय पर मंत्रियों के अलग विचार हों, लेकिन एक बार निर्णय ले लिए जाने के बाद सभी मंत्रियों को सार्वजनिक रूप से उस निर्णय का समर्थन करना अनिवार्य होता है। यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय से असहमत है और उसका समर्थन नहीं कर सकता, तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होता है।

65. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
"एक साथ तैरना और एक साथ डूबना" सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का सटीक निरुपण है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद एक एकल इकाई के रूप में कार्य करती है। जब राज्य विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है या सरकार का कोई महत्वपूर्ण धन विधेयक गिर जाता है, तो केवल मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि विधान परिषद से आने वाले मंत्रियों सहित पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है।

66. (D) मंत्रिपरिषद विधान परिषद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होती है।
द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों में भी मंत्रिपरिषद केवल राज्य विधानसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, विधान परिषद के प्रति नहीं। विधान परिषद के पास सरकार को हटाने या अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की कोई संवैधानिक शक्ति नहीं होती है। यद्यपि विधान परिषद के सदस्य मंत्री बन सकते हैं और सदन में प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, किंतु सरकार का अस्तित्व केवल विधानसभा के बहुमत और विश्वास पर ही टिका होता है।

67. (A) विधानसभा में किसी सरकारी धन विधेयक का गिर जाना (पराजित होना)।
राज्य विधानसभा में किसी सरकारी धन विधेयक या बजट का पराजित हो जाना यह सिद्ध करता है कि सरकार ने सदन में अपना बहुमत खो दिया है। यह स्थिति सीधे तौर पर सामूहिक उत्तरदायित्व की विफलता को दर्शाती है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री और उसकी संपूर्ण मंत्रिपरिषद को नैतिक एवं संवैधानिक आधार पर तुरंत त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि बहुमत के बिना सरकार चलाना असंवैधानिक और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ होता है।

68. (C) राज्यपाल
संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्य सरकार के व्यक्तिगत मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत (ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर) अपना पद धारण करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, किंतु व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर रहता है। हालांकि राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है।

69. (A) मुख्यमंत्री की बाध्यकारी सलाह पर।
यद्यपि संविधान में यह लिखा है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, परंतु व्यावहारिक और संवैधानिक रूप से राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है। यदि मुख्यमंत्री किसी मंत्री के कार्य से संतुष्ट नहीं है, तो वह राज्यपाल को उस मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। राज्यपाल अपनी इच्छा से किसी मंत्री को बिना मुख्यमंत्री की सिफारिश के नहीं हटा सकता है।

70. (A) I और II
राज्य के मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 164(2) के तहत विधानसभा के प्रति होता है, जबकि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करने से जुड़ा है। भारत में ब्रिटेन की तरह मंत्रियों

Click Here to Buy book on Amazon

112. (C) महाधिवक्ता — संविधान के तहत पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल
संविधान में महाधिवक्ता के कार्यकाल की कोई निश्चित सीमा तय नहीं की गई है। अनुच्छेद 165(3) के अनुसार महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल उसे किसी भी समय पद से हटा सकता है। इसके विपरीत राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, आरपीएससी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है तथा मुख्यमंत्री का कार्यकाल विधानसभा के बहुमत पर निर्भर करता है।

113. (B) उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
अनुच्छेद 243K के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भले ही राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु उसे पद से हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठोर है। उसे केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अर्थात संसद द्वारा दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर पारित प्रस्ताव के बाद ही राष्ट्रपति उसे हटा सकता है।

114. (D) आरपीएससी सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है; महाधिवक्ता को राज्यपाल द्वारा।
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, परंतु उन्हें हटाने के प्राधिकारी भिन्न हैं। आरपीएससी के सदस्यों को अनुच्छेद 317 के तहत केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट के बाद ही हटाया जा सकता है। इसके विपरीत महाधिवक्ता का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता और वह अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है तथा राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है।

115. (A) महाधिवक्ता
राज्य स्तर पर उत्पन्न होने वाले जटिल संवैधानिक और कानूनी मुद्दों पर राज्यपाल तथा राज्य सरकार के प्राथमिक विधि सलाहकार के रूप में महाधिवक्ता कार्य करता है। अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह राज्य सरकार और राज्यपाल को उन विधिक विषयों पर सलाह दे जो उसे संदर्भित किए जाएं। वह उच्च न्यायालयों में राज्य सरकार का मुख्य पक्ष भी प्रस्तुत करता है।

116. (C) सबसे बड़े एकल दल या चुनाव-पूर्व गठबंधन को सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित करें।
त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो राज्यपाल को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना पड़ता है। स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं और सरकारीया आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यपाल को सबसे पहले सबसे बड़े एकल दल या चुनाव-पूर्व बने गठबंधन के नेता को सरकार बनाने और सदन के पटल पर एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए।

117. (C) एस.आर. बोम्मई मामला (1994)
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करना न्यायिक समीक्षा के अधीन है। न्यायालय ने यह अनिवार्य नियम स्थापित किया कि किसी सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसका परीक्षण केवल और केवल राज्य विधानसभा के पटल पर ही होना चाहिए, न कि राजभवन में राज्यपाल के व्यक्तिगत आकलन से।

NODIA

118. (D) यथाशीघ्र विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने का आदेश देना चाहिए।
जब राज्यपाल के समक्ष दो राजनीतिक दल सरकार बनाने और बहुमत होने का परस्पर विरोधी दावा प्रस्तुत करते हैं, तो संवैधानिक मर्यादा का तकाजा है कि राज्यपाल खुद निर्णय न ले। उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार बहुमत का वास्तविक फैसला केवल विधानसभा के पटल पर ही होना चाहिए। इसलिए राज्यपाल को बिना कोई देरी किए यथाशीघ्र राज्य विधानसभा का सत्र बुलाकर शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश देना चाहिए।

119. (B) इससे प्रशासनिक बोझ बढ़ता है और नियुक्तियों को लेकर राज्य सरकार के साथ टकराव पैदा होता है।
पुंछी आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राज्यपाल को राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से मुक्त किया जाना चाहिए। आयोग का मानना था कि कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका से उनके पद पर अनावश्यक प्रशासनिक बोझ बढ़ता है और कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर निर्वाचित राज्य सरकार तथा राज्यपाल के बीच बार-बार राजनीतिक टकराव पैदा होता है। इससे विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक स्वायत्तता भी प्रभावित होती है।

120. (D) I, II और III
केंद्र-राज्य संबंधों पर गठित सरकारीया आयोग (1983) ने राज्यपाल पद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं। आयोग ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के बाहर का होना चाहिए, उसकी नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए तथा हाल ही में सक्रिय राजनीति में रहे व्यक्ति को तुरंत राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

121. (C) चार बार
राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद से अब तक कुल चार बार अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन (राज्य आपातकाल) लागू किया जा चुका है। ये चार अवसर 1967, 1977, 1980 और 1992 में आए थे। पहली बार 1967 में स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण राष्ट्रपति शासन लगा था, जबकि बाद के अवसरों पर राजनीतिक घटनाक्रमों, सरकारों के विघटन तथा राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।

122. (A) 1967, 1977, 1980, 1992
राजस्थान में चार बार राष्ट्रपति शासन लागू होने का सही कालानुक्रमिक वर्ष 1967, 1977, 1980 तथा 1992 है। प्रथम बार मार्च 1967 में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में लगा था। दूसरी बार अप्रैल 1977 में केंद्र में जनता पार्टी सरकार द्वारा राज्य सरकार भंग करने पर लगा। तीसरी बार फरवरी 1980 में कांग्रेस सरकार द्वारा लगाया गया तथा चौथी बार दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद ढांचे के विध्वंस के बाद लगाया गया था।

123. (B) डॉ. संपूर्णानंद
वर्ष 1967 में जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, उस समय डॉ. संपूर्णानंद राज्य के राज्यपाल थे। मार्च 1967 में चौथे आम चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। राजनीतिक अनिश्चितता और हिंसा की आशंका के कारण राज्यपाल डॉ. संपूर्णानंद की सिफारिश पर राज्य में पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।

124. (A) P-1, Q-2, R-3, S-4
राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय राज्यपालों का क्रम इस प्रकार है: 1967 में डॉ. संपूर्णानंद राज्यपाल थे। 1977 में राष्ट्रपति शासन के समय वेदपाल त्यागी कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। 1980 में जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तब रघुकुल तिलक राज्य के राज्यपाल थे। अंततः 1992 में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान एम. चेन्ना रेड्डी राजस्थान के राज्यपाल के पद पर आसीन थे।

125. (D) अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया जाना।
दिसंबर 1992 में राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इसका मुख्य कारण 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे का ढहाया जाना और उसके बाद देश भर में उत्पन्न सांप्रदायिक तनाव था। केंद्र सरकार ने इस घटना के बाद भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया था, जिसके तहत राजस्थान में तत्कालीन भैरोंसिंह शेखावत सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।

126. (B) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक पर अनुमति देने या रोकने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की गई है। समय-सीमा का अभाव होने के कारण राज्यपालों द्वारा राज्य विधानमंडल से पारित विधेयकों को अनिर्णीत रखकर लंबे समय तक लंबित रखा जाता है। इस स्थिति को व्यावहारिक रूप से पॉकेट वीटो कहा जाता है, जिससे राज्य सरकार और राज्यपाल के मध्य विधायी कार्यों को लेकर प्रायः तनाव उत्पन्न होता है।

127. (B) राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल को वापस बुलाने या हटाने की क्रियाविधि।
समकालीन राजनीतिक बहस और प्रशासनिक सुधार आयोगों में राज्यपाल के पद को लेकर सबसे प्रमुख प्रस्ताव यह रहा है कि राज्य विधानमंडल को राज्यपाल को वापस बुलाने या हटाने का कुछ अधिकार मिलना चाहिए। वर्तमान में राज्यपाल पूरी तरह केंद्र सरकार और राष्ट्रपति पर निर्भर रहता है। यदि राज्य विधानमंडल के पास महाभियोग या प्रस्ताव द्वारा राज्यपाल को हटाने की शक्ति होगी, तो इससे राज्य की स्वायत्तता और संघीय संतुलन मजबूत होगा।

128. (D) इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य करता है।
भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल की नियुक्ति और पदमुक्ति पूरी तरह से भारत के राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में आती है। यदि कोई राज्य विधानसभा राज्यपाल को पद से हटाने या वापस बुलाने का कोई प्रस्ताव पारित करती भी है, तो उसका कोई कानूनी या संवैधानिक प्रभाव नहीं होता है। राज्यपाल अनुच्छेद 156 के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य करता है, राज्य विधानमंडल के प्रति जवाबदेह नहीं होता।

129. (A) I, II और III
हाल के वर्षों में राज्य कार्यपालिका और राज्यपाल के बीच टकराव के तीन मुख्य बिंदु रहे हैं: राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देने में अनिश्चितकालीन देरी, राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर क्षेत्राधिकार का विवाद तथा चुनाव के बाद सरकार गठन के दौरान राज्यपाल द्वारा किया जाने वाला पक्षपातपूर्ण व्यवहार। हालांकि सिविल सेवकों के दैनिक तबादलों का कार्य सीधे राज्य मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है।

130. (D) संघ और राज्य को जोड़ना, एकता और संवैधानिक शासन व्यवस्था बनाए रखना।
निर्वाचित पद न होने के बावजूद राज्यपाल का पद भारतीय संघीय व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच एक मजबूत संवैधानिक कड़ी के रूप में कार्य करता है। वह राज्य में संविधान के प्रावधानों के पालन की निगरानी करता है तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखता है। जब राज्य में राजनीतिक संकट उत्पन्न होता है, तब राज्यपाल की उपस्थिति संवैधानिक निरंतरता बनाए रखने में सहायक होती है।

Downloaded from www.pdf.tube

अध्याय 14

राजस्थान की राज्य विधानसभा

1. राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है?
(A) 160
(B) 184
(C) 200
(D) 210

2. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभा की संरचना को परिभाषित किया गया है?
(A) अनुच्छेद 168
(B) अनुच्छेद 170
(C) अनुच्छेद 171
(D) अनुच्छेद 173

3. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: विधानसभा
P. प्रथम विधानसभा (1952)
Q. द्वितीय विधानसभा (1957)
R. चतुर्थ विधानसभा (1967)
S. छठी विधानसभा (1977)
सूची II: सीटों की संख्या
1. 184
2. 200
3. 160
4. 176
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-3, Q-1, R-4, S-2
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

4. राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?
(A) 25
(B) 34
(C) 15
(D) 40

5. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): राजस्थान विधानसभा में सीटों की कुल संख्या वर्ष 1977 से 200 पर निश्चित बनी हुई है।
कारण (R): 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक, 1971 की जनगणना के आधार पर राज्य विधानसभाओं में मौजूदा सीटों की कुल संख्या को स्थिर कर दिया गया है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है परंतु कारण (R) सही है।

NODIA

6. निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया?
(A) 101वां संशोधन अधिनियम
(B) 102वां संशोधन अधिनियम
(C) 103वां संशोधन अधिनियम
(D) 104वां संशोधन अधिनियम

7. राजस्थान विधानसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. विधानसभा की वर्तमान स्वीकृत क्षमता 200 है।
II. 200 सीटों में से 34 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं।
III. राज्यपाल वर्तमान में विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय से एक सदस्य मनोनीत करते हैं।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

8. भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) जोधपुर
(B) बीकानेर पश्चिम
(C) जैसलमेर
(D) बाड़मेर

9. भारत में परिसीमन आयोगों का गठन किए जाने वाले वर्षों का सही कालानुक्रमिक क्रम चुनिए, जिसने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को प्रभावित किया:
(A) 1952, 1963, 1973, 2002
(B) 1950, 1961, 1971, 2001
(C) 1952, 1962, 1972, 2002

राज्य विधानसभा नहीं कर सकती।
(B) आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन विधानसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता।
(C) लोकसभा साधारण विधेयकों के लिए संयुक्त बैठक का उपयोग कर सकती है, जबकि विधानसभा नहीं कर सकती।
(D) लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक का निर्णय करते हैं, जबकि राज्यपाल राज्य धन विधेयक का निर्णय करते हैं।

85. लोकसभा की तुलना में राज्य विधानसभा की प्राथमिक प्रतिनिधि प्रकृति में सबसे उपयुक्त अंतर क्या है?
(A) विधानसभा राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है; लोकसभा राष्ट्रीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है।
(B) राज्य विधानसभा स्थानीय निकायों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है, जबकि लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है।
(C) विधानसभा राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा राष्ट्रीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है।
(D) प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित लोकसभा के विपरीत, विधानसभा विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व करती है।

86. राजस्थान में किसी विधायक के विशेषाधिकारों के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए:
(A) विधानमंडल में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के लिए कोई भी सदस्य किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही का भागी नहीं होगा।
(B) दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से स्वतंत्रता आपराधिक मामलों तक विस्तारित नहीं होती है।
(C) विधानसभा को किसी सदस्य की गिरफ्तारी, हिरासत, दोषसिद्धि या रिहाई की तत्काल जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।
(D) विधानसभा का सत्र चलने के दौरान किसी विधायक को निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

87. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, यदि कोई संविधान संशोधन संघीय ढांचे में बदलाव करना चाहता है (जैसे, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व), तो इसके लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। राजस्थान विधानसभा ऐसे संशोधन का अनुसमर्थन कैसे करती है?
(A) विशेष बहुमत द्वारा (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई)।
(B) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा।
(C) राज्यपाल के माध्यम से अध्यादेश पारित करके।
(D) कुल सदस्यता के पूर्ण बहुमत द्वारा।

88. राज्य विधानसभा में चर्चा किए जाने से वर्जित मूलभूत मामलों के संबंध में बेमेल विकल्प चुनिए:
(A) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का आधिकारिक न्यायिक आचरण।
(B) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश का आधिकारिक न्यायिक आचरण।
(C) राज्य के मुख्यमंत्री की सामान्य नीतियां और कार्य।
(D) राष्ट्रीय रक्षा के संबंध में केंद्र सरकार के केंद्रीय नीतिगत निर्णय।

89. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: भारत का संविधान राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम 60 निर्धारित करता है।
कथन II: राजस्थान विधानसभा की 200 की सदस्य संख्या इस संवैधानिक मानदंड के पूरी तरह भीतर है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है परंतु कथन II सही है।

90. संसदीय विशेषाधिकारों के अनुसार, यदि राजस्थान विधानसभा गुप्त बैठक आयोजित करने का निर्णय लेती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही कानूनी रूप से अनुमत है?
(A) विधानसभा अपनी कार्यवाहियों के प्रकाशन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सकती है।
(B) कोई समाचार पत्र प्रेस की स्वतंत्रता का हवाला देकर कार्यवाहियों को प्रकाशित कर सकता है।
(C) नेता प्रतिपक्ष कार्यवाहियों का प्रसारण कर सकते हैं।
(D) उच्च न्यायालय गुप्त बैठक के सीधे प्रसारण का आदेश दे सकता है।

91. राजस्थान में प्रथम महिला विधायक होने का गौरव किसे प्राप्त है?
(A) कमला बेनीवाल
(B) यशोदा देवी
(C) सुमित्रा सिंह
(D) गायत्री देवी

92. राजस्थान सरकार में मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थीं?
(A) यशोदा देवी
(B) कमला बेनीवाल
(C) वसुंधरा राजे
(D) गिरजा व्यास

93. राजस्थान विधानसभा के ऐतिहासिक संदर्भ में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(A) सुमित्रा सिंह राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थीं।

Click Here to Buy book on Flipkart

(B) उसका प्राथमिक कर्तव्य नियमित अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्य का बजट प्रस्तुत करना है।
(C) वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो आमतौर पर सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है।
(D) वह छह महीने की निश्चित अवधि के लिए पद धारण करता है।

21. राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया?
(A) लाल सिंह शक्तावत
(B) निरंजन नाथ आचार्य
(C) राम किशोर व्यास
(D) परसराम मदेरणा

22. विधानसभा उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वह विधानसभा द्वारा अपने सदस्यों में से चुना जाता है।
II. वह अध्यक्ष के अधीनस्थ रहता है और उसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है।
III. अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर वह अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करता है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

23. जब अध्यक्ष विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हों, तो उपाध्यक्ष की स्थिति क्या होती है?
(A) वह मुख्य विपक्षी दल के मनोनीत नेता के रूप में कार्य करता है।
(B) वह किसी भी अन्य साधारण सदस्य की तरह बैठता है और मतदान करता है।
(C) वह अस्थायी रूप से कैबिनेट मंत्री के कार्यों का निष्पादन करता है।
(D) सत्र के दौरान उसका सदन से बाहर रहना आवश्यक होता है।

24. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: राज्य
P. उत्तर प्रदेश
Q. राजस्थान
R. महाराष्ट्र
S. गुजरात
सूची II: विधान परिषद की उपस्थिति
1. द्विसदनीय (परिषद विद्यमान)
2. एकसदनीय (परिषद अनुपस्थित)
3. द्विसदनीय (परिषद विद्यमान)
4. एकसदनीय (परिषद अनुपस्थित)
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-1, Q-4, R-2, S-3

25. राजस्थान विधानसभा ने राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए किस वर्ष एक संकल्प पारित किया था, जो वर्तमान में केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है?
(A) 2008
(B) 2012
(C) 2015
(D) 2018

26. संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत, संसद किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प पारित करती है:
(A) कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा।
(B) कुल सदस्यता के साधारण बहुमत और सभी राज्य विधानमंडलों के आधे हिस्से के अनुसमर्थन द्वारा।
(C) राज्यपाल के अनुमोदन के अधीन उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा।
(D) मंत्रिमंडल द्वारा समर्थित उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के पूर्ण बहुमत द्वारा।

27. यदि राजस्थान में विधान परिषद का सृजन किया जाता है, तो वर्तमान विधानसभा सदस्य संख्या 200 के आधार पर इसकी अधिकतम अनुमत सदस्य संख्या कितनी होगी?
(A) 40 सदस्य
(B) 50 सदस्य
(C) 66 सदस्य
(D) 100 सदस्य

28. निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विधानसभा उपाध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है?
(A) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करना।
(B) अध्यक्ष के अवकाश पर होने पर किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करना।
(C) अध्यक्षता करते समय मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करना।
(D) अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता किए जाने के दौरान एक साधारण सदस्य के रूप में कार्य करना।

29. यद्यपि राजस्थान विधानसभा ने विधान परिषद के सृजन के लिए संकल्प पारित कर दिया है, फिर भी इसके सृजन की अंतिम शक्ति किसके पास निहित है?
(A) भारत की संसद
(B) राजस्थान के राज्यपाल
(C) भारत के राष्ट्रपति
(D) भारत का सर्वोच्च न्यायालय

Downloaded from www.pdf.tube

(D) 1955, 1965, 1975, 2005

10. संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार, किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है?
(A) 21 वर्ष
(B) 25 वर्ष
(C) 30 वर्ष
(D) 35 वर्ष

11. राजस्थान विधानसभा की अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से सामान्य कार्यावधि कितनी होती है?
(A) 4 वर्ष
(B) 5 वर्ष
(C) 6 वर्ष
(D) जब तक राज्यपाल इसे भंग न कर दें, जिसकी कोई निश्चित अधिकतम अवधि नहीं है

12. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान, राज्य विधानसभा का कार्यकाल संसद द्वारा विधि बनाकर एक बार में अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है?
(A) एक बार में छह महीने
(B) एक बार में एक वर्ष
(C) एक बार में दो वर्ष
(D) एक बार में तीन वर्ष

13. राजस्थान विधानसभा को उसकी सामान्य कार्यावधि समाप्त होने से पहले भंग करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है?
(A) राज्यपाल
(B) मुख्यमंत्री
(C) विधानसभा अध्यक्ष
(D) भारत के राष्ट्रपति

14. राज्य विधानसभा के विघटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) विघटन से वर्तमान सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है।
(B) विघटन के पश्चात आम चुनावों के बाद एक नई विधानसभा का गठन किया जाता है।
(C) विधानसभा के साथ विधान परिषद भी भंग हो जाती है।
(D) विधानसभा के विघटन पर उसमें लंबित सभी विधेयक व्यपगत हो जाते हैं।

15. राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
(A) रामनिवास मिर्धा
(B) पूनमचंद बिश्नोई
(C) शांतिलाल चपलोत
(D) नरोत्तम लाल जोशी

16. राज्य विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वह यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
II. वह राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है।
III. वह दसवीं अनुसूची के तहत किसी सदस्य की अयोग्यता (निर्हता) के प्रश्नों का निर्णय करता है।
IV. वह मुख्यमंत्री के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

17. यदि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं, तो उन्हें अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना होगा?
(A) राजस्थान के राज्यपाल को
(B) विधानसभा के उपाध्यक्ष को
(C) राजस्थान के मुख्यमंत्री को
(D) राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को

18. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रुप में अंकित किया गया है।
कथन (A): विधानसभा अध्यक्ष सामान्य विधायी बहस के दौरान प्रथमतया मतदान नहीं करते हैं।
कारण (R): अध्यक्ष से निष्पक्षता बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है और वे केवल मत बराबर होने की स्थिति में ही निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है परंतु कारण (R) सही है।

NODIA

19. निम्नलिखित परिस्थितियों में से उस अपवाद की पहचान कीजिए जो राज्य विधानसभा के किसी सदस्य का स्थान रिक्त नहीं करता है:
(A) बिना अनुमति के 30 दिनों तक विधानसभा की बैठकों से अनुपस्थित रहना
(B) सदस्य द्वारा विधिवत प्रस्तुत किया गया औपचारिक त्यागपत्र
(C) दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होना
(D) सदस्य का संसद के लिए सफलतापूर्वक चुना जाना

20. राजस्थान विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(A) वह पहली बैठक में नवगठित विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।

39. विधायी सत्रों के संचालन के संबंध में अध्यक्ष एवं राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में बेमेल विकल्प चुनिए:
(A) स्थगन - अध्यक्ष
(B) सत्रावसान - अध्यक्ष
(C) अनिश्चित काल के लिए स्थगन - अध्यक्ष
(D) किसी सदस्य का निलंबन - अध्यक्ष

40. राजस्थान विधानसभा के विघटित होने पर लंबित विधेयकों पर पड़ने वाला सबसे उपयुक्त प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) विधानसभा द्वारा पारित किंतु राज्यपाल की सहमति के लिए लंबित विधेयक तुरंत व्यपगत हो जाता है।
(B) पुनर्विचार के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा लौटाया गया विधेयक स्वतः व्यपगत हो जाता है।
(C) विधानसभा में लंबित विधेयक इसके विघटन पर व्यपगत हो जाता है।
(D) सभी गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक संरक्षित रहते हैं जबकि सरकारी विधेयक व्यपगत हो जाते हैं।

41. राज्य विधानमंडल के संदर्भ में "धन विधेयक" की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है?
(A) अनुच्छेद 110
(B) अनुच्छेद 198
(C) अनुच्छेद 199
(D) अनुच्छेद 200

42. राज्य धन विधेयक की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसे केवल विधानसभा में पुरःस्थापित किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं।
II. इसे केवल राज्यपाल की सिफारिश पर ही पुरःस्थापित किया जा सकता है।
III. इसे सत्ताधारी दल के किसी भी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पुरःस्थापित किया जा सकता है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

43. यदि किसी राज्य में विधान परिषद है, तो धन विधेयक को पारित करने के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए:
(A) विधान परिषद धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती।
(B) विधानसभा विधान परिषद द्वारा अनुशंसित संशोधनों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है।
(C) विधान परिषद को 14 दिनों के भीतर धन विधेयक लौटाना होता है।
(D) यदि परिषद 14 दिनों के भीतर विधेयक नहीं लौटाती है, तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है।

44. राज्य का बजट राजस्थान विधानसभा में किस संवैधानिक शीर्षक के तहत प्रस्तुत किया जाता है?
(A) राज्य वित्तीय अधिनियम
(B) वार्षिक वित्तीय विवरण
(C) संचित निधि विवरण
(D) विनियोग विधेयक

45. राज्य बजट के पारित होने के निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए:
I. अनुदान की मांगों पर मतदान
II. सामान्य चर्चा
III. बजट का प्रस्तुतिकरण
IV. विनियोग विधेयक का पारित होना
निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम दर्शाता है?
(A) III, II, I, IV
(B) III, I, II, IV
(C) II, III, I, IV
(D) I, II, III, IV

46. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: कटौती प्रस्तावों के प्रकार
P. नीतिगत कटौती प्रस्ताव
Q. मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव
R. सांकेतिक कटौती प्रस्ताव
S. लेखाअनुदान
सूची II: उद्देश्य
1. किसी विशिष्ट शिकायत को व्यक्त करने के लिए मांग में 100 रुपये की कमी की जाती है।
2. मूल नीति को असंतोषजनक मानते हुए मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है।
3. व्यय में मितव्ययिता को दर्शाते हुए एक निर्दिष्ट एकमुश्त राशि से मांग घटाई जाती है।
4. वर्ष के एक हिस्से के लिए अनुमानित व्यय हेतु अग्रिम अनुदान।
(A) P-2, Q-3, R-1, S-4
(B) P-3, Q-2, R-1, S-4
(C) P-2, Q-1, R-3, S-4
(D) P-1, Q-3, R-2, S-4

47. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): विधानसभा अध्यक्ष का यह निर्णय अंतिम होता है कि कोई विशिष्ट विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
कारण (R): जब किसी धन विधेयक को सहमति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो उस पर अध्यक्ष का प्रमाण पत्र पृष्ठांकित होना चाहिए।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।

Click Here to Buy book on Amazon

67. राज्य विधानसभा में निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए:

I. निंदा प्रस्ताव में इसे स्वीकार करने के कारणों का उल्लेख होना चाहिए, जबकि अविश्वास प्रस्ताव में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है।
II. निंदा प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत मंत्री के खिलाफ लाया जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ ही लाया जा सकता है।
III. यदि निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद को अनिवार्य रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है।
IV. सरकार में विधानसभा का विश्वास परखने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल I, II और IV
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, II और III

68. विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियात्मक चरणों पर विचार कीजिए:

I. यदि आवश्यक संख्या में सदस्य समर्थन करते हैं तो प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाती है।
II. कोई सदस्य विधानसभा सचिव को प्रस्ताव की लिखित सूचना सौंपता है।
III. बहस होती है और उसके बाद प्रस्ताव पर मतदान होता है।
IV. अध्यक्ष सदन में प्रस्ताव पढ़ते हैं और जो इसके पक्ष में हैं उनसे अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहते हैं।

निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम दर्शाता है?

(A) II, IV, I, III
(B) II, I, IV, III
(C) IV, II, I, III
(D) I, II, IV, III

69. निम्नलिखित में से कौन सा लोक लेखा समिति के कामकाज में एक अंतर्निहित सीमा का प्रतिनिधित्व करता है?

(A) इसकी सिफारिशें परामर्शकारी हैं और राज्य पर बाध्यकारी नहीं हैं।
(B) इसके पास अनुचित व्यय को वास्तव में होने से रोकने का कार्यकारी अधिकार है।
(C) यह आगामी राज्य वार्षिक बजट के लिए विस्तृत वैकल्पिक आर्थिक नीतियां तैयार करती है।
(D) यह दुरुपयोग किए गए धन की वसूली के लिए राज्य विभागों को सीधे बाध्यकारी आदेश जारी कर सकती है।

70. विधानसभा में राज्य सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावों के संबंध में बेमेल विकल्प चुनिए:

(A) स्थगन प्रस्ताव
(B) निंदा प्रस्ताव
(C) अविश्वास प्रस्ताव
(D) धन्यवाद प्रस्ताव

71. दल-बदल विरोधी कानून, जो राजस्थान विधानसभा के सदस्यों पर लागू होता है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है?

(A) आठवीं अनुसूची
(B) नौवीं अनुसूची
(C) दसवीं अनुसूची
(D) ग्यारहवीं अनुसूची

72. 91वें संविधान संशोधन अधिनियम (2003) के अनुसार, किसी राजनीतिक दल का विलय दल-बदल अयोग्यता से तभी सुरक्षित होता है जब विधायी दल के कम से कम कितने सदस्य विलय के लिए सहमत हों?

(A) एक-तिहाई
(B) आधा
(C) दो-तिहाई
(D) तीन-चौथाई

73. राजस्थान विधानसभा में दल-बदल के मामलों के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(A) दल-बदल के मामलों का निर्णय करने के लिए राज्यपाल अंतिम प्राधिकारी हैं।
(B) भारत का निर्वाचन आयोग अध्यक्ष के संदर्भ पर दल-बदल के मामलों का फैसला करता है।
(C) दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित सदस्य को भविष्य के चुनाव लड़ने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाता है।
(D) दल-बदल पर अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

NODIA

74. राजस्थान विधानसभा में "नेता प्रतिपक्ष" की स्थिति का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है?

(A) इसे कैबिनेट मंत्री के पद और भत्तों के साथ वैधानिक मान्यता प्राप्त है।
(B) यह बिना किसी वैधानिक या कानूनी आधार के पूरी तरह से एक अनौपचारिक संसदीय परंपरा है।
(C) नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
(D) यह पद संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत स्पष्ट रूप से परिभाषित एक संवैधानिक पद है।

75. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:

सूची I: राजस्थान के प्रमुख नेता प्रतिपक्ष

P. जसवंत सिंह (1952)
Q. भैरों सिंह शेखावत
R. वसुंधरा राजे
S. गुलाब चंद कटारिया

सूची II: राजनीतिक संदर्भ/दल

1. प्रथम विधानसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष
2. कई बार नेता प्रतिपक्ष और बाद में मुख्यमंत्री के रूप में

(A) सामान्य विधायी कार्यसूची को दरकिनार करना और किसी निर्वाचित सदस्य की व्यक्तिगत शिकायत उठाना।
(B) सीधे राज्य के राज्यपाल से तत्काल लिखित प्रशासनिक उत्तर की मांग करना।
(C) आपातकालीन स्थिति पर चर्चा करने के लिए सदन के संपूर्ण औपचारिक कामकाज को स्थगित करना।
(D) निर्धारित समय से कम समय का नोटिस देकर लोक महत्व का अति आवश्यक प्रश्न पूछना।

58. राजस्थान विधानसभा में समितियों की अध्यक्षता के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए:
(A) अध्यक्ष, कार्य सलाहकार समिति और नियम समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
(B) मुख्यमंत्री, लोक लेखा समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
(C) नेता प्रतिपक्ष, प्राकलन समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
(D) राज्यपाल, सदन के बाहर से विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं।

59. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): शून्यकाल संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है।
कारण (R): शून्यकाल का स्पष्ट उल्लेख राजस्थान विधानसभा की औपचारिक प्रक्रिया नियमावली में किया गया है और इसे उसी के द्वारा विनियमित किया जाता है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है परंतु कारण (R) सही है।

60. अपवाद की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समिति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है?
(A) लोक लेखा समिति
(B) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति
(C) प्राकलन समिति
(D) सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति

61. राजस्थान विधानसभा में लोक लेखा समिति की सामान्य सदस्य संख्या कितनी होती है?
(A) 10 सदस्य
(B) 15 सदस्य
(C) 20 सदस्य
(D) 25 सदस्य

62. राज्य स्तर पर लोक लेखा समिति के निम्नलिखित कार्यों और विशेषताओं पर विचार कीजिए:
I. यह राज्य से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच करती है।
II. इसमें केवल मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं।
III. परंपरा के अनुसार, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति आमतौर पर विपक्षी दल से की जाती है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

63. राजस्थान विधानसभा में पालन की जाने वाली मानक संसदीय परंपराओं के तहत, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
(A) राज्य के राज्यपाल
(B) राज्य के मुख्यमंत्री
(C) राज्य के वित्त मंत्री
(D) विधानसभा अध्यक्ष

64. राजस्थान विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है?
(A) 20 सदस्य
(B) 30 सदस्य
(C) 40 सदस्य
(D) 50 सदस्य

65. अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(A) इसे विशिष्ट दुर्व्यवहार के लिए किसी व्यक्तिगत मंत्री के खिलाफ लाया जा सकता है।
(B) इसे केवल विधानसभा में लाया जा सकता है।
(C) सदन में इसे स्वीकार करने के विशिष्ट कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
(D) यदि यह पारित हो जाता है, तो केवल मुख्यमंत्री त्यागपत्र देते हैं जबकि मंत्रिमंडल बना रहता है।

66. राजस्थान विधानसभा में वित्तीय समितियों (लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति) की सदस्यता के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए:
(A) सदस्य प्रतिवर्ष विधानसभा द्वारा अपने सदस्यों में से चुने जाते हैं।
(B) कोई भी मंत्री इन समितियों के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए पात्र नहीं है।
(C) एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
(D) यदि कोई सदस्य मंत्री चुना जाता है, तो वह अपनी समिति की सीट बरकरार रखता है।

Downloaded from www.pdf.tube

(D) कथन (A) गलत है परंतु कारण (R) सही है।

48. राजस्थान विधानसभा में "लेखाअनुदान" का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है?
(A) किसी ऐसे संविधान संशोधन को पारित करने का संकल्प जो सीधे राज्य के बजट आवंटन को प्रभावित करता है।
(B) विधानसभा में अंतिम मतदान प्रक्रिया जो औपचारिक रुप से वार्षिक विनियोग विधेयक को मंजूरी देती है।
(C) बजट के पारित होने तक राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला एक अग्रिम अनुदान।
(D) वर्ष के दौरान अधिकृत व्यय कम पड़ने पर प्रदान किया जाने वाला एक अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान।

49. राज्य स्तर पर संसदीय लोकतंत्र के संदर्भ में, यदि राज्य का बजट विधानसभा में अस्वीकृत हो जाता है तो इसका राजनीतिक परिणाम क्या होता है?
(A) केवल वित्त मंत्री को राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देना होता है।
(B) मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।
(C) राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत वित्तीय शक्तियां ग्रहण कर लेते हैं।
(D) बजट स्वतः ही स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है।

50. राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के संबंध में बेमेल विकल्प चुनिए:
(A) राज्यपाल का वेतन
(B) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन
(C) विधानसभा अध्यक्ष का वेतन
(D) राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रियों के वेतन

51. राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान, "तारांकित प्रश्न" को "अतारांकित प्रश्न" से क्या अलग करता है?
(A) तारांकित प्रश्न के लिए सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इस पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है।
(B) तारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है, जबकि अतारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है।
(C) तारांकित प्रश्न केवल गैर-सरकारी सदस्यों से पूछे जाते हैं, मंत्रियों से नहीं।
(D) तारांकित प्रश्न केवल नेता प्रतिपक्ष द्वारा ही पूछा जा सकता है।

52. विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है?
(A) अल्प सूचना प्रश्न - 15 दिनों से अधिक के नोटिस की आवश्यकता होती है।
(B) अतारांकित प्रश्न - पूरक प्रश्नों की अनुमति देता है।
(C) तारांकित प्रश्न - मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है।
(D) गैर-सरकारी सदस्य से प्रश्न - सामान्य प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित किया जाता है।

53. विधायी कार्यवाहियों में "शून्यकाल" सदस्यों के लिए पूर्व सूचना के बिना मामले उठाने का एक अनौपचारिक साधन है। यह आमतौर पर कब शुरू होता है?
(A) प्रश्नकाल के तुरंत बाद
(B) प्रश्नकाल के तुरंत पहले
(C) स्थगन से पहले सायंकाल में
(D) केवल सत्र के अंतिम दिन

54. राज्य विधानसभा की समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. स्थायी समितियां प्रकृति में स्थायी होती हैं।
II. तदर्थ समितियां अस्थायी होती हैं और अपना कार्य पूरा होने पर समाप्त हो जाती हैं।
III. लोक लेखा समिति तदर्थ समिति का एक उदाहरण है।
IV. प्राकलन समिति सबसे बड़ी वित्तीय समिति है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, II और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

55. राज्य के वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए राजस्थान विधानसभा के भीतर कितनी प्राथमिक वित्तीय समितियां कार्य करती हैं?
(A) दो
(B) तीन
(C) चार
(D) पांच

56. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: राजस्थान विधानसभा की समितियां
P. लोक लेखा समिति
Q. प्राकलन समिति 'क' एवं 'ख'
R. सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति
S. कार्य सलाहकार समिति
सूची II: सामान्य विशेषताएं
1. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों की जांच करती है।
2. प्रशासन में दक्षता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देती है।
3. राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के कामकाज की जांच करती है।
4. सदन की समय सारणी को विनियमित करती है।
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-1, Q-3, R-2, S-4
(D) P-3, Q-2, R-1, S-4

57. विधानसभा में "अल्प सूचना प्रश्न" का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है?

NODIA

कार्य किया
3. 2023 से पहले हाल की विधानसभाओं में भाजपा से नेता प्रतिपक्ष
4. नेता प्रतिपक्ष जो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं

(A) P-1, Q-2, R-4, S-3
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-4, Q-2, R-1, S-3

76. दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के अपवादों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. यदि कोई सदस्य विभाजन के कारण अपना दल छोड़ देता है जहाँ एक-तिहाई सदस्य एक नया समूह बनाते हैं।
II. यदि किसी सदस्य का मूल राजनीतिक दल किसी अन्य दल में विलय हो जाता है और विधायी दल के दो-तिहाई सदस्य सहमत होते हैं।
III. यदि कोई सदस्य, अध्यक्ष चुने जाने के बाद, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन वर्तमान में लागू वैध अपवादों का प्रतिनिधित्व करता है/करते हैं?

(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

77. आधिकारिक तौर पर मुख्य विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने और अपने नेता को नेता प्रतिपक्ष नामित करने के लिए, राजस्थान विधानसभा में किसी दल को कम से कम कितनी सीटें हासिल करनी होंगी?

(A) कुल सीटों का 10% (अर्थात 20 सीटें)
(B) कुल सीटों का 15% (अर्थात 30 सीटें)
(C) कुल सीटों का 20% (अर्थात 40 सीटें)
(D) सीटों की कोई भी संख्या, जब तक कि वह दूसरा सबसे बड़ा दल है

78. किसी विधायक की अयोग्यता के आधार को उसके निर्णायक प्राधिकारी से जोड़ने वाले गलत युग्म की पहचान कीजिए:

(A) दसवीं अनुसूची (दल-बदल) के तहत अयोग्यता - विधानसभा अध्यक्ष
(B) लाभ का पद धारण करने के लिए अनुच्छेद 191 के तहत अयोग्यता - राज्य के राज्यपाल
(C) विकृतचित्त होने के कारण अयोग्यता - मुख्यमंत्री
(D) चुनाव में भ्रष्ट आचरण से संबंधित विवाद - उच्च न्यायालय

79. विपक्ष की भूमिका के संदर्भ में, "छाया मंत्रिमंडल" मुख्य रूप से किस देश की संसदीय प्रणाली से जुड़ी एक संस्था है, जिसका राजस्थान विधानसभा में औपचारिक रूप से पालन नहीं किया जाता है?

(A) संयुक्त राज्य अमेरिका
(B) फ्रांस
(C) स्विट्ज़रलैंड
(D) यूनाइटेड किंगडम

80. अपवाद की पहचान कीजिए। राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित कोई निर्दलीय सदस्य दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य हो जाता है यदि वह:

(A) किसी लोकप्रिय विधेयक के खिलाफ मतदान करता है।
(B) बजट सत्र के दौरान मतदान से अनुपस्थित रहता है।
(C) अपने निर्वाचन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।
(D) सदन में मुख्यमंत्री की आलोचना करता है।

81. राज्य विधानमंडल और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित की गई हैं?

(A) अनुच्छेद 105
(B) अनुच्छेद 194
(C) अनुच्छेद 212
(D) अनुच्छेद 226

82. राज्य विधानसभा द्वारा प्राप्त निम्नलिखित विशेषाधिकारों पर विचार कीजिए:

I. अपनी रिपोर्ट और कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का अधिकार।
II. बाहरी व्यक्तियों को अपनी कार्यवाहियों से बाहर रखने का अधिकार।
III. अपने विशेषाधिकारों के हनन के लिए सदस्यों के साथ-साथ बाहरी व्यक्तियों को भी दंडित करने का अधिकार।
IV. सत्र के दौरान सदस्यों को जूरी सेवा से छूट।

उपर्युक्त में से कौन सा संयोजन सदस्यों के व्यक्तिगत विशेषाधिकारों के बजाय सदन के सामूहिक विशेषाधिकारों का प्रतिनिधित्व करता है?

(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, III और IV
(D) I, II, III और IV

83. राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य को दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से स्वतंत्रता प्राप्त है। यह उन्मुक्ति विधानसभा के सत्र के दौरान और कितनी अवधि तक प्रभावी रहती है?

(A) सत्र से 14 दिन पहले और बाद तक
(B) सत्र से 30 दिन पहले और बाद तक
(C) सत्र से 40 दिन पहले और बाद तक
(D) सत्र से 60 दिन पहले और बाद तक

84. राज्य विधानसभा और लोकसभा की विधायी प्रक्रियाओं के बीच अंतर को स्पष्ट करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(A) लोकसभा धन विधेयक प्रारंभ कर सकती है, लेकिन

Click Here to Buy book on Flipkart

30. राजस्थान द्वारा द्विसदनीय विधानमंडल के बजाय एकसदनीय विधानमंडल के साथ कार्य करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) संविधान पश्चिमी राज्यों को द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित करने से स्पष्ट रूप से मना करता है।
(B) राजस्थान की जनसंख्या दूसरे सदन के लिए अनिवार्य संवैधानिक सीमा से कम है।
(C) राज्य के संकल्प के बावजूद संसद ने इसे स्थापित करने के लिए अधिनियम पारित नहीं किया है।
(D) राजस्थान के राज्यपाल ने विधान परिषद स्थापित करने के विधानसभा के संकल्प पर वीटो लगा दिया।

31. राजस्थान विधानसभा के दो सत्रों के बीच अधिकतम अनुमत अंतराल कितना है?
(A) तीन महीने
(B) चार महीने
(C) छह महीने
(D) एक वर्ष

32. विधानसभा के सत्रों से संबंधित निम्नलिखित शब्दावली पर विचार कीजिए:
I. आहूत करना
II. स्थगन
III. अनिश्चित काल के लिए स्थगन
IV. सत्रावसान
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सदन की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करने की कार्यवाही का सही वर्णन करता है?
(A) आहूत करना
(B) स्थगन
(C) अनिश्चित काल के लिए स्थगन
(D) सत्रावसान

33. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल समय-समय पर राज्य विधानसभा को आहूत करते हैं?
(A) अनुच्छेद 174
(B) अनुच्छेद 175
(C) अनुच्छेद 176
(D) अनुच्छेद 177

34. विधानसभा में राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए:
(A) राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में विधानसभा को संबोधित करते हैं।
(B) राज्यपाल का भाषण मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना स्वतंत्र रूप से तैयार किया जाता है।
(C) राज्यपाल के अभिभाषण में संदर्भित किसी भी मामले पर चर्चा या मतदान की अनुमति नहीं है।
(D) यह प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में होता है।

35. राज्य विधानसभा में किसी साधारण विधेयक के पारित होने के निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए:
I. विधेयक के सिद्धांतों पर सामान्य चर्चा (द्वितीय वाचन - प्रथम चरण)
II. खंड-दर-खंड विचार और मतदान (द्वितीय वाचन - द्वितीय चरण)
III. विधेयक को पुरःस्थापित करना और राजपत्र में प्रकाशन (प्रथम वाचन)
IV. विधेयक के पारित होने पर अंतिम मतदान (तृतीय वाचन)
निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम दर्शाता है?
(A) III, I, II, IV
(B) I, III, II, IV
(C) III, II, I, IV
(D) I, II, III, IV

36. जब राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित कोई साधारण विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध संवैधानिक विकल्प नहीं है?
(A) वह विधेयक पर अपनी सहमति दे सकते हैं।
(B) वह विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकते हैं।
(C) वह स्वयं विधेयक में संशोधन कर सकते हैं और इसे सीधे अधिनियम के रूप में लागू कर सकते हैं।
(D) वह विधेयक को (यदि यह धन विधेयक नहीं है) सदन के पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं।

37. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): राजस्थान के राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकते हैं।
कारण (R): यदि कोई विधेयक उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को संकट में डालता है, तो राज्यपाल अनिवार्य रूप से इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखते हैं।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है परंतु कारण (R) सही है।

NODIA

38. दो सदनों के बीच (द्विसदनीय राज्यों में) साधारण विधेयक पर गतिरोध को दूर करने के लिए राज्य विधानमंडल में (संसद की तुलना में) निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अनुपस्थित है?
(A) पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटाना
(B) राज्यपाल की सहमति
(C) राष्ट्रपति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखना
(D) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

(B) महिला प्रतिनिधियों ने राजस्थान में अध्यक्ष का संवैधानिक पद कभी नहीं संभाला है।
(C) 1952 में चुनी गई पहली राजस्थान विधानसभा में 50% महिला सदस्य थीं।
(D) वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री बनने से पहले राजस्थान की महिला राज्यपाल के रूप में कार्य किया।

94. अपवाद की पहचान कीजिए। "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" (106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023) महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का अनिवार्य प्रावधान करता है, जो निम्नलिखित में से किस निकाय पर लागू नहीं होता है (क्योंकि वहां पहले से प्रावधान है)?
(A) लोकसभा
(B) राज्य विधानसभाएं
(C) पंचायती राज संस्थाएं
(D) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा

95. राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव किस वर्ष आयोजित किए गए थे?
(A) 1949
(B) 1950
(C) 1952
(D) 1956

96. 1956 की किस महत्वपूर्ण घटना के कारण राजस्थान विधानसभा में सीटों की संख्या 160 से बढ़कर 190 हो गई थी?
(A) राजस्थान राज्य में पूर्ववर्ती मत्स्य संघ का औपचारिक राजनीतिक विलय।
(B) 1951 की जनगणना के दौरान दर्ज की गई सामान्य कुल जनसंख्या वृद्धि।
(C) अजमेर-मेरवाड़ा राज्य का राजस्थान में विलय।
(D) विधान परिषद नामक दूसरे सदन का विधायी सृजन।

97. उन ऐतिहासिक अवधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जब राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था:
I. राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 1967 में लागू किया गया था।
II. केंद्र में सरकार बदलने के बाद 1977 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।
III. राज्य में राष्ट्रपति शासन की सबसे लंबी अवधि 1992 में राज्य सरकार की बर्खास्तगी के बाद रही।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

98. राजस्थान विधानसभा की अवधि को उसके क्रमांक से जोड़ने वाले गलत युग्म की पहचान कीजिए:
(A) प्रथम विधानसभा: 1952 – 1957
(B) द्वितीय विधानसभा: 1957 – 1962
(C) पांचवीं विधानसभा: 1972 – 1977
(D) छठी विधानसभा: 1977 – 1985

99. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह स्पष्ट करता है कि पांचवीं राजस्थान विधानसभा (1972) का कार्यकाल अपनी सामान्य पांच वर्ष की अवधि से आगे क्यों बढ़ गया था?
(A) अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा।
(B) 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पूर्ण सशस्त्र संघर्ष का शुरु होना।
(C) विधान परिषद के सृजन का संकल्प सक्रिय रूप से लंबित था।
(D) राज्य चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ था।

100. 1952 में अपने गठन के समय, राजस्थान विधानसभा सवाई मानसिंह टाउन हॉल में बैठती थी। विधानसभा किस वर्ष ज्योति नगर, जयपुर में अपने वर्तमान आधुनिक भवन में स्थानांतरित हुई?
(A) 1985
(B) 1992
(C) 2001
(D) 2008

101. वह सबसे प्रभावी संवैधानिक साधन कौन सा है जिसके माध्यम से राजस्थान विधानसभा मंत्रिपरिषद की दैनिक जवाबदेही सुनिश्चित करती है?
(A) प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछना और प्रस्ताव लाना।
(B) औपचारिक विधानसभा कार्यवाही के माध्यम से राज्य के राज्यपाल पर महाभियोग चलाना।
(C) संसद द्वारा भेजे गए संविधान संशोधन विधेयकों को पारित करने से इनकार करना।
(D) राज्य लोक सेवा आयोग में सीधे सदस्यों की नियुक्ति करना।

NODIA

102. राजस्थान विधानसभा में "गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक" का तात्पर्य किसके द्वारा पुरःस्थापित विधेयक से है?
(A) केवल मुख्य विपक्षी दल से संबंधित कोई भी निर्वाचित सदस्य।
(B) विधायक के माध्यम से लाया गया कोई कॉर्पोरेट प्रतिनिधि या निजी नागरिक।
(C) विधानसभा में सेवारत कोई निर्दलीय विधायक।
(D) कोई भी विधायक जो मंत्री नहीं है।

103. यद्यपि संविधान सत्रों के बीच अधिकतम छह महीने के अंतराल का आदेश देता है, कई राज्य विधानसभाओं ने न्यूनतम बैठकों के लिए आंतरिक नियम बनाए हैं। आमतौर पर, राजस्थान के आकार के राज्य विधानमंडलों के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम कितने दिनों की बैठक की सिफारिश की जाती है?
(A) 30 दिन
(B) 60 दिन

आवश्यक अधिनियम पारित नहीं किया है। जब तक संसद कानून नहीं बनाती, तब तक राज्य में दूसरा सदन अस्तित्व में नहीं आ सकता है।

31. (C) छह महीने
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार, राज्य विधानसभा के दो सत्रों के मध्य अधिकतम अनुमत अंतराल छह महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि राज्यपाल को समय-समय पर विधानसभा को इस प्रकार आहूत करना होता है कि अंतिम सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने का अंतर न हो। सामान्यतः राजस्थान विधानसभा के प्रतिवर्ष तीन सत्र (बजट, मानसून और शीतकालीन) आयोजित किए जाते हैं।

32. (C) अनिश्चित काल के लिए स्थगन
जब पीठासीन अधिकारी बिना किसी अगली तिथि या समय की घोषणा किए विधानसभा की बैठक को समाप्त कर देते हैं, तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है। यह शक्ति केवल विधानसभा के अध्यक्ष के पास निहित होती है। इसके विपरीत, सामान्य स्थगन किसी निश्चित समय या दिन के लिए होता है, जबकि आहूत करना और सत्रावसान की शक्तियां राज्य के राज्यपाल के संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं, जो सत्र की औपचारिक शुरुआत और समाप्ति दर्शाती हैं।

33. (A) अनुच्छेद 174
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 174 राज्य के राज्यपाल को समय-समय पर राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर आहूत करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसे वह उपयुक्त समझे। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने और विधानसभा को भंग करने का भी अधिकार प्राप्त है। राज्यपाल इन विधायी शक्तियों का प्रयोग सामान्यतः मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की परामर्श और सहायता के आधार पर ही करते हैं।

34. (D) यह प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में होता है।
संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल का विशेष अभिभाषण दो विशिष्ट अवसरों पर होता है: प्रत्येक आम चुनाव के बाद नई विधानसभा के प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में। यह अभिभाषण राज्य मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें सरकार की नीतियों, भावी योजनाओं और उपलब्धियों का विस्तृत ब्योरा होता है। इसके पश्चात् सदन में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा और मतदान किया जाता है।

35. (A) III, I, II, IV
राज्य विधानसभा में साधारण विधेयक पारित होने की एक निश्चित प्रक्रिया है। सबसे पहले प्रथम वाचन में विधेयक को पुरःस्थापित किया जाता है और राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद द्वितीय वाचन के प्रथम चरण में सिद्धांतों पर सामान्य चर्चा होती है। तत्पश्चात द्वितीय चरण में खंड-दर-खंड विचार तथा संशोधनों पर मतदान होता है। अंत में तृतीय वाचन में संपूर्ण विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए अंतिम मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

36. (C) वह स्वयं विधेयक में संशोधन कर सकते हैं और इसे सीधे अधिनियम के रूप में लागू कर सकते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत जब कोई साधारण विधेयक पारित होकर राज्यपाल के पास आता है, तो वे सहमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं, पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं या राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकते हैं। परंतु राज्यपाल को स्वयं विधेयक में संशोधन करने या उसे सीधे कानून के रूप में लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। कानून बनाने की मूल शक्ति केवल निर्वाचित विधायिका के पास ही संरक्षित रखी गई है।

37. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
राजस्थान के राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकते हैं। यदि कोई विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति और उसकी शक्तियों को इस प्रकार प्रभावित करता है कि उसकी स्वतंत्र स्थिति संकट में पड़ जाए, तो राज्यपाल के लिए ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है। अतः कारण, दिए गए कथन की बिल्कुल सही और तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत करता है।

38. (D) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
राज्य विधानमंडल में किसी साधारण विधेयक पर दो सदनों (विधानसभा और विधान परिषद) के मध्य गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त बैठक का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। यह व्यवस्था केवल संसद (लोकसभा और राज्यसभा) के लिए लागू होती है। राज्य स्तर पर विधानसभा का निर्णय ही अंतिम और सर्वोपरि माना जाता है। यदि विधान परिषद विधेयक को रोकती है, तो विधानसभा उसे पुनः पारित करके विधान परिषद के प्रभाव को निरस्त कर सकती है।

39. (B) सत्रावसान - अध्यक्ष
विधायी प्रक्रियाओं में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। सदन का स्थगन, अनिश्चित काल के लिए स्थगन और अनुशासनहीनता पर किसी सदस्य का निलंबन करने का अधिकार केवल विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। दूसरी ओर, विधानसभा के सत्र का औपचारिक सत्रावसान करने और सत्र को आहूत करने की शक्ति विशेष रूप से राज्य के राज्यपाल के पास निहित होती है। अतः सत्रावसान को अध्यक्ष से जोड़ना प्रक्रियात्मक दृष्टि से पूर्णतः बेमेल है।

40. (C) विधानसभा में लंबित विधेयक इसके विघटन पर व्यपगत हो जाता है।
जब राज्य विधानसभा विघटित होती है, तो उस समय उसमें लंबित सभी विधेयक स्वतः ही व्यपगत हो जाते हैं। हालांकि, जो विधेयक विधानसभा द्वारा पारित हो चुके हैं और राज्यपाल या राष्ट्रपति की सहमति के लिए लंबित हैं, वे व्यपगत नहीं होते। इसके अलावा, यदि राष्ट्रपति ने किसी विधेयक पर पुनर्विचार

Downloaded from www.pdf.tube

(C) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है परंतु कथन II सही है।

114. तुलनात्मक संदर्भ के लिए, राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है?
(A) 200
(B) 117
(C) 403
(D) 230

115. राजस्थान के पड़ोसी राज्यों और उनके विधानमंडल के प्रकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है?
(A) हरियाणा - एकसदनीय विधानमंडल
(B) उत्तर प्रदेश - एकसदनीय विधानमंडल
(C) गुजरात - द्विसदनीय विधानमंडल
(D) पंजाब - द्विसदनीय विधानमंडल

116. राजस्थान विधानसभा की इसके पड़ोसी राज्यों से तुलना करने वाले सही कथन की पहचान कीजिए:
(A) अपने सभी पड़ोसी राज्य विधानमंडलों में राजस्थान में विधानसभा सीटों की कुल संख्या सबसे अधिक है।
(B) राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में विधान परिषदों के साथ कार्यात्मक द्विसदनीय विधानमंडल हैं।
(C) राजस्थान के विपरीत, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है।
(D) हरियाणा की कुल विधानसभा सदस्य संख्या राजस्थान की तुलना में काफी बड़ी है।

117. कम जनसंख्या वाले राज्यों में आमतौर पर एकसदनीय विधानमंडल होते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित पड़ोसी राज्यों में से किस राज्य में राजस्थान (200) से कम विधानसभा सीटें हैं?
(A) हरियाणा (90)
(B) उत्तर प्रदेश (403)
(C) मध्य प्रदेश (230)
(D) महाराष्ट्र (288)

118. राज्य को उसकी विधानसभा सदस्य संख्या से सुमेलित करने वाले गलत युग्म की पहचान कीजिए:
(A) राजस्थान - 200
(B) गुजरात - 182
(C) पंजाब - 117
(D) हरियाणा - 120

119. विधायी निकायों में एक उल्लेखनीय प्रक्रियात्मक सुधार "गिलोटिन" है। राजस्थान विधानसभा में राज्य के बजट के संदर्भ में, यह किसको संदर्भित करता है?
(A) भ्रष्टाचार के आरोपी मंत्री को तुरंत बर्खास्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव।
(B) एक निश्चित समय पर सभी शेष अनुदान मांगों पर मतदान कराना।
(C) लगातार अव्यवस्था फैलाने वाले विधानसभा सदस्यों को सदन से बाहर निकालना।
(D) वार्षिक बजट परिव्यय को आधा करने के लिए राज्यपाल द्वारा आपातकालीन शक्ति का प्रयोग करना।

120. विधान परिषद की उपस्थिति (द्विसदनीयता) के आधार पर राजस्थान के भौगोलिक पड़ोसियों में से बेमेल विकल्प चुनिए:
(A) पंजाब
(B) हरियाणा
(C) उत्तर प्रदेश
(D) गुजरात

121. राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से, आरक्षित सीटों (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को मिलाकर) की कुल संख्या कितनी है?
(A) 34
(B) 49
(C) 59
(D) 69

122. यदि राजस्थान विधानसभा का कोई सदस्य लोकसभा के लिए निर्वाचित होता है, तो उसे कितने दिनों के भीतर राज्य विधानसभा से त्यागपत्र देना होगा, ऐसा न करने पर संसद में उसकी सीट रिक्त हो जाती है?
(A) 7 दिन
(B) 14 दिन
(C) 30 दिन
(D) 6 महीने

123. संविधान का आदेश है कि राज्य विधानमंडल की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए?
(A) वर्ष में एक बार
(B) वर्ष में दो बार
(C) वर्ष में तीन बार
(D) वर्ष में चार बार

124. जब राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो संविधान के तहत वह विशिष्ट समय सीमा क्या है जिसके भीतर राज्यपाल को कार्रवाई करनी होती है?
(A) प्रस्तुति की तारीख से अधिकतम 14 दिनों की अवधि के भीतर
(B) प्रस्तुति की तारीख से अधिकतम 30 दिनों की अवधि के भीतर
(C) प्रस्तुति की तारीख से अधिकतम 6 महीने की अवधि के भीतर
(D) कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं है।

125. राज्य विधानमंडल द्वारा स्वीकृति मिलने तक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राजस्थान आकस्मिकता निधि को किस प्राधिकारी के अधीन रखा गया है?

NODIA

आयु 25 वर्ष होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके पास संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के तहत निर्धारित अन्य सभी योग्यताएं होनी चाहिए। वहीं विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष तथा मतदान हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित है।

11. (B) 5 वर्ष
राजस्थान विधानसभा की सामान्य कार्यअवधि अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष होती है। 5 वर्ष की यह अवधि समाप्त होते ही विधानसभा स्वतः ही भंग हो जाती है। हालांकि, इस निर्धारित अवधि से पूर्व भी राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद कानून बनाकर विधानसभा के कार्यकाल को एक समय में एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

12. (B) एक बार में एक वर्ष
अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान, संसद विधि बनाकर राज्य विधानसभा की सामान्य अवधि को एक बार में अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ा सकती है। हालांकि, आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात् यह विस्तार किसी भी स्थिति में छह महीने की अवधि से अधिक जारी नहीं रह सकता है। यह संवैधानिक व्यवस्था आपातकालीन परिस्थितियों में विधायी निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से निर्मित की गई है।

13. (A) राज्यपाल
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्य के राज्यपाल को विधानसभा को उसकी सामान्य अवधि से पूर्व भंग करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। राज्यपाल आमतौर पर यह शक्ति मंत्रिपरिषद, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं, की सलाह पर प्रयोग में लाते हैं। यदि सरकार अपना बहुमत खो देती है और कोई वैकल्पिक सरकार बनना संभव न हो, तो राज्यपाल अपने स्वविवेक से भी विधानसभा को भंग करके नए चुनाव कराने का निर्देश दे सकते हैं।

14. (C) विधानसभा के साथ विधान परिषद भी भंग हो जाती है।
राज्य विधानसभा का विघटन होने पर केवल विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होता है। यदि राज्य में विधान परिषद विद्यमान है, तो वह भंग नहीं होती क्योंकि विधान परिषद एक स्थायी सदन है, जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। विधानसभा के विघटन के साथ ही उसमें लंबित सभी विधेयक और प्रस्ताव व्यपगत हो जाते हैं तथा नए आम चुनावों के बाद नई विधानसभा गठित होती है।

15. (D) नरोत्तम लाल जोशी
नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उन्होंने 29 मार्च 1952 से 23 मार्च 1957 तक इस पद पर निष्ठापूर्वक कार्य किया। वे झुंझुनू निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। उनके कार्यकाल के दौरान राजस्थान में लोकतांत्रिक और विधायी परंपराओं की नींव रखी गई। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सदन के नियमों के संचालन और निष्पक्ष विधायी कार्यवाहियों की स्थापना में अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी।

16. (B) केवल I और III
विधानसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं और उसका यह निर्णय अंतिम होता है। साथ ही, वह दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दल-बदल से संबंधित सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय देता है। राज्य में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, अध्यक्ष मुख्यमंत्री के प्रसादपर्यंत पद धारण नहीं करता, बल्कि वह सदन के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है।

17. (B) विधानसभा के उपाध्यक्ष को
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, यदि राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपने पद से स्वेच्छा से त्यागपत्र देना चाहता है, तो उसे अपना त्यागपत्र लिखित रूप में विधानसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करना होता है। इसी प्रकार, यदि उपाध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे, तो वह अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। यह प्रक्रिया विधायिका की आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखने और कार्यपालिका के हस्तक्षेप को रोकने के लिए संविधान निर्माताओं द्वारा निर्धारित की गई एक मानक प्रक्रिया है।

18. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
राज्य विधानसभा के अध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करते समय सामान्य चर्चा या मतदान के दौरान प्रथमतया अपना वोट नहीं डालते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि पीठासीन अधिकारी होने के नाते उनसे पूर्ण निष्पक्षता और तटस्थता की अपेक्षा की जाती है। वे केवल तभी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं जब किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ जाएं, जिसे निर्णायक मत कहा जाता है।

19. (A) बिना अनुमति के 30 दिनों तक विधानसभा की बैठकों से अनुपस्थित रहना
संविधान के अनुच्छेद 190 के अनुसार, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिनों तक बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है। 30 दिनों की अनुपस्थिति पर स्थान स्वतः रिक्त नहीं होता। वहीं औपचारिक त्यागपत्र देने, दल-बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित होने या संसद का सदस्य चुने जाने की स्थिति में राज्य विधानसभा में संबंधित सदस्य की सीट तुरंत प्रभाव से रिक्त मानी जाती है।

20. (C) वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो आमतौर पर सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है।
राजस्थान विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः नवगठित विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को इस पद के लिए चुना जाता है। राज्यपाल सामयिक अध्यक्ष को पद की शपथ दिलाते हैं।

Click Here to Buy book on Amazon

उत्तर (व्याख्या सहित)

NODIA

1. (C) 200
राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की वर्तमान स्वीकृत संख्या 200 है। वर्ष 1952 में प्रथम विधानसभा गठन के समय सदस्यों की कुल संख्या 160 निर्धारित की गई थी। इसके पश्चात् विभिन्न परिसीमन आयोगों की सिफारिशों और राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप सीटों की संख्या में लगातार वृद्धि की गई। वर्ष 1977 में छठी विधानसभा के समय सीटों की संख्या बढ़ाकर 200 की गई, जो वर्ष 2026 तक के लिए स्थिर रखी गई है।

2. (B) अनुच्छेद 170
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 प्रत्येक राज्य की विधानसभा की संरचना का स्पष्ट विवरण देता है। इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों से मिलकर बनेगी। इसमें अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। यह अनुच्छेद विधानसभा क्षेत्रों के प्रादेशिक परिसीमन तथा जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधियों के आवंटन की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है।

3. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
राजस्थान विधानसभा के इतिहास में विभिन्न कालखंडों में सदस्यों की संख्या परिवर्तित हुई है। वर्ष 1952 में गठित प्रथम विधानसभा में 160 सीटें थीं। वर्ष 1957 की द्वितीय विधानसभा में अजमेर के विलय के बाद सीटों की संख्या बढ़कर 176 हो गई। वर्ष 1967 की चतुर्थ विधानसभा के दौरान यह संख्या बढ़कर 184 हुई तथा वर्ष 1977 की छठी विधानसभा में इसे और बढ़ाकर कुल 200 कर दिया गया।

4. (A) 25
राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटों में से अनुसूचित जनजातियों के लिए 25 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों के लिए 34 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। इस प्रकार कुल 59 सीटें इन विशेष वर्गों के लिए आरक्षित हैं। यह आरक्षण व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में निहित सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के अंतर्गत समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में शामिल करने हेतु लागू की गई है।

5. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
राजस्थान विधानसभा में सीटों की कुल संख्या वर्ष 1977 से 200 पर नियत है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि वर्ष 2026 के पश्चात् होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों की संख्या वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर स्थिर रहेगी। अतः दिया गया कारण कथन की पूर्ण एवं सटीक व्याख्या करता है, जो संसदीय संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

6. (D) 104वां संशोधन अधिनियम
104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इससे पूर्व, राज्यपाल को यदि यह प्रतीत होता था कि विधानसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वे एक सदस्य को मनोनीत कर सकते थे। इस संशोधन के पश्चात् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को अगले दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।

7. (A) केवल I और II
राजस्थान विधानसभा की कुल स्वीकृत क्षमता 200 है, जिसमें से अनुसूचित जातियों के लिए 34 सीटें और अनुसूचित जनजातियों के लिए 25 सीटें आरक्षित हैं। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राज्यपाल द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। इसलिए अब विधानसभा के सभी 200 सदस्य केवल प्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से ही चुने जाते हैं और नामांकन का प्रावधान निष्प्रभावी हो चुका है।

8. (C) जैसलमेर
भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। यह निर्वाचन क्षेत्र थार मरुस्थल के एक विशाल भूभाग को कवर करता है और जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण इसका भौगोलिक विस्तार अत्यंत व्यापक है। परिसीमन के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण जनसंख्या और भौगोलिक निरंतरता को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिसके कारण कम आबादी वाले सीमावर्ती जिलों में विधानसभा क्षेत्रों का आकार काफी बड़ा होता है।

9. (C) 1952, 1962, 1972, 2002
भारत में परिसीमन आयोगों का गठन समय-समय पर संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों के तहत किया जाता है। भारत में अब तक चार बार परिसीमन आयोगों का गठन वर्ष 1952, 1962, 1972 और 2002 में किया गया है। इन आयोगों का मुख्य कार्य नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोक सभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निरूपण करना तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का पुनः निर्धारण करना होता है।

10. (B) 25 वर्ष
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार, किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम

(C) 90 दिन
(D) 120 दिन

104. राजस्थान विधानसभा के डिजिटलीकरण प्रयासों के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए:
(A) कागजी विधेयकों को पूरी तरह से समाप्त करना और सभी कार्यवाहियों के लिए नेवा पर पूरी तरह निर्भर रहना।
(B) भौतिक मतदान प्रक्रिया को घर से अनिवार्य रिमोट ऑनलाइन मतदान से बदलना।
(C) कागज रहित प्रणाली की दिशा में बहसों और प्रश्नों को डिजिटल रूप से संरक्षित करना।
(D) केवल यूएनडीपी से पूर्ण कार्यान्वयन निधि प्राप्त करना।

105. संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत, राजस्थान से राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन भाग लेता है?
(A) मनोनीत सदस्यों सहित राजस्थान विधानसभा के सभी सदस्य।
(B) विधानसभा और स्थानीय निकायों दोनों के निर्वाचित सदस्य।
(C) राष्ट्रीय चुनावों में सीधे मतदान करने वाली राजस्थान की आम जनता।
(D) केवल विधानसभा के निर्वाचित विधायक।

106. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: राज्य के विधायकों द्वारा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाता है।
कथन II: यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि राजनीतिक दलों को राज्य विधानसभा में उनकी संख्यात्मक शक्ति के लगभग आनुपातिक रूप से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिले।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है परंतु कथन II सही है।

107. राज्यसभा में राजस्थान राज्य को कितनी सीटें आवंटित की गई हैं, जिसके लिए विधानसभा निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करती है?
(A) 10
(B) 15
(C) 25
(D) 34

108. राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संबंध में राजस्थान विधानसभा की विधायी भूमिका के विषय में गलत कथन की पहचान कीजिए:
(A) राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का वही कानूनी बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल के अधिनियम का होता है।
(B) राज्यपाल एक बार प्रख्यापित किए जाने के बाद अध्यादेश को वापस नहीं ले सकते हैं।
(C) सदन के पुनः समवेत होने पर अध्यादेश को अनिवार्य रूप से विधानसभा के समक्ष रखा जाना चाहिए।
(D) अध्यादेश विधानमंडल के पुनः समवेत होने की तिथि से छह सप्ताह की समाप्ति पर स्वतः ही समाप्त हो जाता है।

109. यदि राजस्थान सरकार को विधानसभा के सत्र में न होने पर तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तो वह अध्यादेश के माध्यम से ऐसा करती है। विधानसभा द्वारा अनुसमर्थित किए बिना ऐसे अध्यादेश की अधिकतम सैद्धांतिक जीवन अवधि कितनी हो सकती है?
(A) पुनः समवेत होने से ठीक छह सप्ताह
(B) ठीक छह कैलेंडर महीने की अवधि
(C) छह महीने और छह सप्ताह
(D) एक पूरा कैलेंडर वर्ष

110. विधानसभा में सरकार का त्यागपत्र कराने के बजाय मुख्य रूप से जानकारी मांगने और लोक महत्व के मामलों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधनों में से बेमेल विकल्प चुनिए:
(A) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
(B) आधे घंटे की चर्चा
(C) अविश्वास प्रस्ताव
(D) अल्पकालिक चर्चा

111. राजस्थान सहित राज्य विधानमंडलों के कामकाज को कागज रहित बनाने के लिए लागू की गई 'नेवा' पहल का पूर्ण रूप क्या है?
(A) नेशनल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एप्लीकेशन
(B) न्यू ई-विज़न असेंबली
(C) नेशनल ई-वेरिफिकेशन ऑफ एक्ट्स
(D) नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन

112. हाल के वर्षों में राजस्थान विधानसभा के कामकाज में पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने का प्रत्यक्ष उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रेस दीर्घा में प्रवेश से पूरी तरह प्रतिबंधित करना।
(B) प्रश्नकाल का संचालन केवल बंद कमरे के गुप्त सत्रों में करना।
(C) विधानसभा की कार्यवाहियों का सीधा सजीव प्रसारण।
(D) समिति की रिपोर्टों के औपचारिक प्रकाशन को सीमित करना।

113. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: राजस्थान विधानसभा की कार्यवाहियों का समर्पित मंचों पर सीधा प्रसारण किया जाता है, जिससे नागरिक अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को देख सकते हैं।
कथन II: सीधे प्रसारण में सदन की स्पष्ट रूप से घोषित "गुप्त बैठकों" सहित सभी बैठकें शामिल हैं।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

Downloaded from www.pdf.tube

सामयिक अध्यक्ष का मुख्य कार्य नए चुने गए विधायकों को शपथ दिलाना तथा नियमित विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करना होता है। नियमित अध्यक्ष चुने जाते ही यह पद स्वतः समाप्त हो जाता है।

21. (A) लाल सिंह शक्तावत
लाल सिंह शक्तावत राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष चुने गए थे। वे प्रथम विधानसभा (1952-1957) की अवधि के दौरान इस पद पर आसीन रहे। उन्होंने अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाहियों का कुशलतापूर्वक संचालन किया। उपाध्यक्ष का पद एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, जो विधानसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है और वह अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर सदन की अध्यक्षता और संसदीय परंपराओं का निर्वहन करने के लिए अधिकृत होता है।

22. (C) केवल I और III
विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या वे अनुपस्थित हों, तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करता है। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का अधीनस्थ नहीं होता; वह सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होता है और उसका पद एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। इसलिए केवल पहला और तीसरा विवरण ही सही है, जबकि दूसरा कथन पूरी तरह असत्य एवं भ्रामक है।

23. (B) वह किसी भी अन्य साधारण सदस्य की तरह बैठता है और मतदान करता है।
जब विधानसभा के अध्यक्ष सदन की बैठक की अध्यक्षता कर रहे होते हैं, तो उपाध्यक्ष की स्थिति एक सामान्य विधायक जैसी होती है। वह सदन में किसी भी अन्य साधारण सदस्य की भांति बैठता है, चर्चाओं में भाग लेता है और सामान्य विधायी कार्यवाहियों तथा विधेयकों पर अपना मतदान कर सकता है। वह केवल तभी पीठासीन अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करता है जब वह स्वयं अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का संचालन कर रहा हो।

24. (A) P-1, Q-2, R-3, S-4
भारत के राज्यों में विधानमंडल की संरचना भिन्न है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में द्विसदनीय विधानमंडल हैं, जहाँ विधानसभा के साथ विधान परिषद भी विद्यमान है। इसके विपरीत, राजस्थान और गुजरात में एकसदनीय विधानमंडल है, जहाँ केवल विधानसभा ही कार्य कर रही है और विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है। भारत के केवल छह राज्यों में ही वर्तमान में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था लागू है, जबकि शेष राज्यों में एकसदनीय व्यवस्था प्रभावी है।

25. (B) 2012
राजस्थान विधानसभा ने राज्य में विधान परिषद के सृजन हेतु अप्रैल 2012 में संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत एक विशेष संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया था। इस प्रस्ताव में 66 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना का सुझाव दिया गया था। यह संकल्प केंद्र सरकार को आवश्यक केंद्रीय अधिनियम पारित करने के लिए भेजा गया था, जो वर्तमान में संसद और भारत सरकार के विचाराधीन है तथा अंतिम मंजूरी और कानून निर्माण की प्रतीक्षा कर रहा है।

26. (A) कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा।
संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार, संसद किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साद कर सकती है, यदि उस राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प पारित करे। इसके लिए विधानसभा की कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई विशेष बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। इसके बाद ही केंद्रीय संसद साधारण विधि बनाकर विधान परिषद का गठन या समाप्ति कर सकती है।

27. (C) 66 सदस्य
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार, किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की वर्तमान संख्या 200 है, इसलिए प्रस्तावित विधान परिषद की अधिकतम स्वीकृत सदस्य संख्या 66 हो सकती है। इसके साथ ही संविधान यह भी प्रावधान करता है कि किसी भी स्थिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए।

28. (B) अध्यक्ष के अवकाश पर होने पर किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करना।
किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का विशेष एकाधिकार केवल विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। उपाध्यक्ष केवल अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की बैठकों का संचालन करता है या मत बराबर होने पर निर्णायक मत देता है। जब अध्यक्ष सदन में उपस्थित होते हैं, तो उपाध्यक्ष साधारण सदस्य के रूप में कार्य करता है। धन विधेयक का प्रमाण पत्र पृष्ठांकित करने की शक्ति उपाध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है।

29. (A) भारत की संसद
यद्यपि राजस्थान विधानसभा ने राज्य में विधान परिषद के सृजन हेतु अनुच्छेद 169 के तहत विशेष बहुमत से संकल्प पारित कर दिया है, परंतु इसके निर्माण की अंतिम और अनन्य शक्ति केवल भारत की संसद के पास निहित है। जब तक संसद इस संबंध में कानून पारित नहीं करती, तब तक विधान परिषद का गठन नहीं हो सकता। संसद को ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करने, संशोधित करने या खारिज करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

30. (C) राज्य के संकल्प के बावजूद संसद ने इसे स्थापित करने के लिए अधिनियम पारित नहीं किया है।
राजस्थान में वर्तमान में एकसदनीय विधानमंडल कार्य कर रहा है। इसका सबसे उपयुक्त कारण यह है कि यद्यपि राजस्थान विधानसभा ने वर्ष 2012 में विधान परिषद के गठन हेतु संवैधानिक संकल्प पारित करके केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन भारत की संसद ने अभी तक इसे स्थापित करने के लिए

NODIA

अनुदान की मांगों के माध्यम से मतदेय व्यय के रूप में पारित किए जाते हैं।

51. (A) तारांकित प्रश्न के लिए सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इस पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है।
प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिन पर एक विशेष चिन्ह (तारा) अंकित होता है। इनके लिए संबंधित मंत्री द्वारा सदन के पटल पर मौखिक उत्तर दिया जाता है। मौखिक उत्तर दिए जाने के कारण प्रश्नकर्ता सदस्य को विषय के स्पष्टीकरण हेतु पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्राप्त होती है। इसके विपरीत, अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रुप में दिया जाता है और उन पर कोई पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है।

52. (C) तारांकित प्रश्न - मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है।
संसदीय प्रक्रियाओं में तारांकित प्रश्नों का उत्तर संबंधित मंत्री द्वारा सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है और इन पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए जाते हैं और उन पर पूरक प्रश्न संभव नहीं होते। अल्प सूचना प्रश्नों के लिए सामान्य 10 दिनों की अवधि से कम का नोटिस आवश्यक होता है। मंत्रियों के अलावा गैर-सरकारी सदस्यों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं यदि मामला उनके निजी विधेयकों से संबंधित हो।

53. (A) प्रश्नकाल के तुरंत बाद
शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली का एक अनौपचारिक साधन है। यह प्रतिदिन की कार्यसूची में प्रश्नकाल के समाप्त होते ही तुरंत प्रारंभ होता है। इस समय के दौरान सदस्य बिना किसी पूर्व लिखित सूचना के लोक महत्त्व के अत्यावश्यक मामलों को उठाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। चूंकि यह काल दोपहर बारह बजे शुरु होता था, इसलिए इसे शून्यकाल नाम दिया गया। यह विधायिका को कार्यपालिका पर तत्काल नियंत्रण का अवसर प्रदान करता है।

54. (B) केवल I, II और IV
राज्य विधानसभा में स्थायी समितियां निरंतर कार्य करने वाली स्थायी प्रकृति की होती हैं, जबकि तदर्थ समितियां किसी विशेष कार्य हेतु गठित की जाती हैं और कार्य पूर्ण होने पर भंग हो जाती हैं। प्राकलन समिति सबसे बड़ी वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति एक स्थायी वित्तीय समिति का उदाहरण है, तदर्थ समिति का नहीं। अतः कथन I, II और IV सही हैं, जबकि लोक लेखा समिति को तदर्थ बताना पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप से गलत है।

55. (C) चार
राजस्थान विधानसभा में राज्य के सार्वजनिक वित्त और वित्तीय प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए मुख्य रुप से चार वित्तीय समितियां कार्यरत हैं। इनमें लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति 'क', प्राकलन समिति 'ख' तथा सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति शामिल हैं। ये समितियां सरकारी खर्चों की प्रामाणिकता, वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक धन के सदुपयोग और राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों के आर्थिक कामकाज की सूक्ष्मता से जांच करती हैं तथा अपनी विस्तृत रिपोर्ट सदन को सौंपती हैं।

56. (A) P-1, Q-2, R-3, S-4
राजस्थान विधानसभा की समितियां विशिष्ट भूमिकाएं निभाती हैं। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वार्षिक रिपोर्टों की वित्तीय जांच करती है। प्राकलन समितियां 'क' व 'ख' प्रशासनिक दक्षता और मितव्ययिता के लिए वैकल्पिक नीतियों की सिफारिश करती हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति सरकारी निगमों के वित्तीय कामकाज को देखती है। वहीं कार्य सलाहकार समिति सदन के दैनिक समय-सारणी तथा विधायी कार्यसूची के संचालन को व्यवस्थित और विनियमित करने का कार्य करती है।

57. (D) निर्धारित समय से कम समय का नोटिस देकर लोक महत्व का अति आवश्यक प्रश्न पूछना।
अल्प सूचना प्रश्न वह प्रश्न होता है जो लोक महत्व के किसी अति आवश्यक विषय से संबंधित होता है और जिसे सामान्यतः निर्धारित दस दिनों से कम समय की सूचना देकर पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न का उत्तर संबंधित मंत्री द्वारा सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अत्यावश्यक सार्वजनिक मामलों पर बिना किसी अनावश्यक विलंब के सरकार से त्वरित तथ्यात्मक उत्तर और स्पष्टीकरण प्राप्त करना होता है।

58. (A) अध्यक्ष, कार्य सलाहकार समिति और नियम समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
राजस्थान विधानसभा में प्रक्रियात्मक नियमों के अनुसार, विधानसभा अध्यक्ष स्वयं कार्य सलाहकार समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। लोक लेखा समिति या प्राकलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति विपक्ष या अन्य सदस्यों में से अध्यक्ष द्वारा की जाती है, परंतु मुख्यमंत्री या राज्यपाल इनके अध्यक्ष नहीं होते हैं। इस प्रकार विधायी कार्यसूची के नियमन में अध्यक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और अग्रणी होती है।

59. (C) कथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था का एक अनूठा और मौलिक नवाचार है जो 1962 से प्रचलन में आया। हालांकि, इसका कोई औपचारिक उल्लेख राजस्थान विधानसभा या संसद की प्रक्रिया नियमावली में नहीं है। यह बिना किसी लिखित नियम के विकसित हुई एक अनौपचारिक व्यवस्था है। इसलिए कथन A पूरी तरह सत्य है कि यह भारतीय आविष्कार है, परंतु कारण R गलत है क्योंकि यह किसी लिखित नियम पुस्तिका का भाग नहीं है।

60. (B) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति
राजस्थान विधानसभा में लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति 'क' व 'ख' तथा सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति को वित्तीय समितियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके विपरीत, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति एक वित्तीय समिति नहीं है, बल्कि यह एक विधायी समीक्षा समिति है। इसका मुख्य कार्य

Click Here to Buy book on Flipkart

का संदेश दिया है, तो वह भी संरक्षित रहता है। इस प्रकार विघटन से केवल लंबित विधायी कार्य ही समाप्त होते हैं।

41. (C) अनुच्छेद 199
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 199 राज्य विधानमंडल के संदर्भ में "धन विधेयक" की स्पष्ट परिभाषा प्रदान करता है। इसके अनुसार, किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन तथा राज्य की संचित निधि से धन की निकासी या जमा करने से संबंधित विषयों वाले विधेयक को धन विधेयक माना जाता है। वहीं अनुच्छेद 110 संसद के लिए धन विधेयक को परिभाषित करता है तथा अनुच्छेद 198 इसके पारित होने की विशेष प्रक्रिया बताता है।

42. (A) केवल I और II
धन विधेयक केवल राज्य विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। इसे केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जाता है और यह केवल एक सरकारी विधेयक होता है जिसे केवल कोई मंत्री ही पेश कर सकता है। किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अतः पहला और दूसरा कथन पूर्णतः सत्य हैं, जबकि तीसरा कथन प्रक्रियात्मक नियमों के सर्वथा विपरीत है।

43. (B) विधानसभा विधान परिषद द्वारा अनुशंसित संशोधनों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है।
धन विधेयक के मामले में राज्य विधानसभा को सर्वाधिकार प्राप्त हैं। विधान परिषद इसे न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही इसमें अपनी मर्जी से संशोधन कर सकती है। वह केवल 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ विधेयक लौटा सकती है। विधानसभा विधान परिषद की किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। यदि 14 दिनों में विधेयक नहीं लौटता, तो इसे मूल रूप में पारित मान लिया जाता है।

44. (B) वार्षिक वित्तीय विवरण
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत राज्य का बजट राजस्थान विधानसभा में "वार्षिक वित्तीय विवरण" के संवैधानिक शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। इसमें संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विस्तृत ब्योरा होता है। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में इस विवरण को सदन के समक्ष रखवाते हैं। सामान्य बोलचाल में इसे बजट कहा जाता है, किंतु संवैधानिक शब्दावली में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण ही निर्दिष्ट किया गया है।

45. (A) III, II, I, IV
राज्य विधानसभा में बजट पारित होने की प्रक्रिया चार क्रमिक चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले वित्त मंत्री द्वारा सदन में बजट प्रस्तुत किया जाता है। इसके पश्चात बजट की सामान्य रूपरेखा पर सामान्य चर्चा आयोजित होती है। तीसरे चरण में विभिन्न विभागों के लिए अनुदान की मांगों पर विस्तृत विचार और मतदान किया जाता है। अंत में, संचित निधि से धन की निकासी को अधिकृत करने के लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है।

46. (A) P-2, Q-3, R-1, S-4
बजट चर्चा के दौरान विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाता है। नीतिगत कटौती प्रस्ताव मांग की मूल नीति से असहमति दर्शाते हुए राशि घटाकर 1 रुपया करने का प्रस्ताव करता है। मितव्ययिता कटौती में व्यय कम करने के लिए एकमुश्त राशि घटाई जाती है। सांकेतिक कटौती किसी विशिष्ट शिकायत हेतु मांग में 100 रुपये कम करती है। वहीं लेखाअनुदान पूर्ण बजट पारित होने तक अंतरिम अवधि के खर्च हेतु दिया जाने वाला अग्रिम आवंटन होता है।

47. (B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
विधानसभा में यह तय करने का अंतिम अधिकार केवल अध्यक्ष के पास होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। जब किसी धन विधेयक को राज्यपाल की सहमति हेतु भेजा जाता है, तो उस पर अध्यक्ष का हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र होना आवश्यक होता है। यद्यपि दोनों कथन स्वतंत्र रूप से पूर्ण सत्य हैं, परंतु प्रमाण पत्र की उपस्थिति अध्यक्ष के अंतिम निर्णय के पीछे का कारण नहीं है, बल्कि यह केवल एक प्रक्रियात्मक सत्यापन है।

48. (C) बजट के पारित होने तक राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला एक अग्रिम अनुदान।
लेखाअनुदान राज्य सरकार को नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में बजट की पूर्ण प्रक्रिया संपन्न होने तक अपने दैनिक खर्चों को चलाने के लिए दिया जाने वाला एक अग्रिम वित्तीय आवंटन है। चूंकि बजट पर व्यापक चर्चा और अनुदान मांगों के मतदान में काफी समय लगता है, इसलिए संविधान का अनुच्छेद 206 विधानसभा को यह शक्ति देता है कि वह विनियोग विधेयक पारित होने से पूर्व ही सरकार को संचित निधि से आवश्यक धनराशि अग्रिम रूप से स्वीकृत कर दे।

49. (B) मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।
संसदीय लोकतंत्र में राज्य का बजट पास होना सरकार के स्थायित्व की प्राथमिक शर्त है। यदि राज्य का बजट या उससे जुड़ा विनियोग विधेयक विधानसभा में अस्वीकृत हो जाता है, तो इसका अर्थ यह माना जाता है कि सरकार ने सदन में अपना बहुमत खो दिया है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को तुरंत राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपना पड़ता है या फिर सरकार को नए चुनावों का सामना करना पड़ता है।

50. (D) राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रियों के वेतन
राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय पर केवल चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं। इसमें राज्यपाल का वेतन-भत्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन शामिल होते हैं। इसके विपरीत, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रियों के वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित व्यय नहीं होते, बल्कि ये विधानसभा द्वारा वार्षिक बजट में

Downloaded from www.pdf.tube

(A) राज्यपाल
(B) मुख्यमंत्री
(C) राज्य के वित्त मंत्री
(D) विधानसभा अध्यक्ष

126. दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत, एक विशिष्ट पदधारक को विशेष छूट दी गई है, जो पद पर चुने जाने पर अयोग्य ठहराए बिना स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ सकता है। वह पदधारक कौन है?
(A) मुख्यमंत्री
(B) नेता प्रतिपक्ष
(C) विधानसभा अध्यक्ष
(D) सत्ताधारी दल के मुख्य सचेतक

127. राजस्थान विधानसभा की कौन सी समिति सदन के अधिकारों और उन्मुक्तियों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करती है?
(A) आचार समिति
(B) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति
(C) सामान्य प्रयोजन समिति
(D) विशेषाधिकार समिति

128. राजस्थान विधानसभा के इतिहास में, किस आम चुनाव में किसी एकल राजनीतिक दल ने 200 में से 163 सीटें हासिल की थीं, जो कि उसकी अब तक की सर्वाधिक सीटें हैं?
(A) 1980 विधानसभा चुनाव
(B) 1998 विधानसभा चुनाव
(C) 2013 विधानसभा चुनाव
(D) 2018 विधानसभा चुनाव

129. जबकि सुमित्रा सिंह राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थीं, पहली महिला उपाध्यक्ष कौन थीं?
(A) कमला बेनीवाल
(B) तारा भंडारी
(C) वसुंधरा राजे
(D) सूर्यकांता व्यास

130. राजस्थान विधानसभा की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति (कोरम) क्या है?
(A) पीठासीन अधिकारी सहित सदन की कुल सदस्यता का एक-चौथाई।
(B) पीठासीन अधिकारी सहित सदन की कुल सदस्यता का एक-तिहाई।
(C) सभी साधारण परिस्थितियों में सदन में ठीक 50 सदस्य उपस्थित हों।
(D) 10 सदस्य या कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा, जो भी अधिक हो।

NODIA

यह जांचना है कि कार्यपालिका द्वारा बनाए जा रहे नियम, उप-नियम और विनियम संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा प्रदत्त शक्तियों की सीमा के भीतर हैं या नहीं।

61. (A) 10 सदस्य
राजस्थान विधानसभा में लोक लेखा समिति की सामान्य सदस्य संख्या 10 होती है। इन सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य चुने जाने का पात्र नहीं होता है। यह समिति राज्य के सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने तथा वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

62. (C) केवल I और III
लोक लेखा समिति राज्य से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच करती है। स्थापित संसदीय परंपरा के अनुसार, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के सदस्यों में से की जाती है। इस समिति के सदस्यों का चुनाव विधानसभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, मुख्यमंत्री के नामांकन द्वारा नहीं। अतः पहला और तीसरा कथन सही है, जबकि दूसरा कथन पूरी तरह असत्य है।

63. (D) विधानसभा अध्यक्ष
राजस्थान विधानसभा की सुस्थापित संसदीय परंपराओं और नियमों के अनुसार, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की औपचारिक नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अध्यक्ष इस समिति के चुने गए सदस्यों में से ही किसी एक को इसका सभापति नियुक्त करते हैं। परंपरा के अनुसार, इस समिति के अध्यक्ष पद पर विपक्षी दल के किसी वरिष्ठ सदस्य को ही प्राथमिकता दी जाती है, ताकि सरकारी खर्चों की निष्पक्ष और तटस्थ वित्तीय जांच सुनिश्चित की जा सके।

64. (C) 40 सदस्य
राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया नियमावली के अनुसार, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को चर्चा हेतु स्वीकार किए जाने के लिए कम से कम 40 सदस्यों (सदन की कुल क्षमता का 20%) के समर्थन की आवश्यकता होती है। जब कोई सदस्य प्रस्ताव पेश करता है, तो अध्यक्ष इसके समर्थन में सदस्यों को खड़े होने के लिए कहते हैं। यदि 40 या उससे अधिक सदस्य खड़े होते हैं, तो प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति और तिथि नियत की जाती है।

65. (B)इसे केवल विधानसभा में लाया जा सकता है।
अविश्वास प्रस्ताव केवल राज्य की विधानसभा में ही लाया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रुप से केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे पेश करने के लिए कारणों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को तुरंत त्यागपत्र देना पड़ता है। इसे किसी व्यक्तिगत मंत्री के विरुद्ध नहीं, बल्कि केवल पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ ही लाया जा सकता है।

66. (D) यदि कोई सदस्य मंत्री चुना जाता है, तो वह अपनी समिति की सीट बरकरार रखता है।
वित्तीय समितियों के सदस्य प्रतिवर्ष विधानसभा सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुने जाते हैं। कोई भी मंत्री इन समितियों का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होता है। यदि समितियों का कोई निर्वाचित सदस्य बाद में राज्य सरकार में मंत्री नियुक्त हो जाता है, तो वह नियुक्ति की तिथि से ही समिति की अपनी सदस्यता तुरंत खो देता है। अतः मंत्री बनने पर समिति की सीट बरकरार रहने का कथन गलत है।

67. (A) केवल I, II और IV
निंदा प्रस्ताव में इसे स्वीकार करने के कारणों का उल्लेख करना अनिवार्य होता है और यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह के खिलाफ लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध आता है और इसमें कारण बताना आवश्यक नहीं होता। यदि निंदा प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार को इस्तीफा देना अनिवार्य नहीं है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी सरकार गिर जाती है। अतः कथन I, II और IV सही हैं।

68. (A) II, IV, I, III
अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में चलती है। सर्वप्रथम कोई सदस्य विधानसभा सचिव को प्रस्ताव की लिखित सूचना देता है। इसके बाद अध्यक्ष सदन में प्रस्ताव पढ़कर सुनाते हैं और समर्थन देने वाले सदस्यों को अपने स्थान पर खड़े होने को कहते हैं। यदि आवश्यक न्यूनतम संख्या में सदस्य समर्थन करते हैं तो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। अंत में, विस्तृत बहस आयोजित की जाती है और प्रस्ताव पर अंतिम मतदान होता है।

69. (A) इसकी सिफारिशें परामर्शकारी हैं और राज्य पर बाध्यकारी नहीं हैं।
लोक लेखा समिति वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है, किंतु इसके कामकाज में एक अंतर्निहित सीमा यह है कि इसकी सिफारिशें केवल परामर्शकारी प्रकृति की होती हैं। राज्य सरकार या इसके विभिन्न विभाग इन सिफारिशों को लागू करने के लिए कानूनी रुप से बाध्य नहीं हैं। इसके पास अनुचित व्यय को रोकने का कोई कार्यकारी अधिकार या दंड देने की शक्ति नहीं होती, यह केवल रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

70. (D) धन्यवाद प्रस्ताव
स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव वे विधायी साधन हैं जिनका उपयोग विधानसभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा सरकार को घेरने, उसकी नीतियों की आलोचना करने तथा उसकी जवाबदेही तय करने हेतु किया जाता है। इसके विपरीत, धन्यवाद प्रस्ताव राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सरकार की नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों के समर्थन में लाया जाता

Click Here to Buy book on Amazon

न्यूनतम 20 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। यदि गणपूर्ति नहीं होती है तो बैठक स्थगित कर दी जाती है।

www.nodia.in

NODIA

विधायक के लिए इस प्रकार की अयोग्यता का कारण नहीं बनता है।

81. (B) अनुच्छेद 194
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। इसमें सदन में भाषण की स्वतंत्रता, कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार तथा सदस्यों को दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार शामिल हैं। वहीं अनुच्छेद 105 संसद और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान प्रदान करता है।

82. (A) केवल I, II और III
सामूहिक विशेषाधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को नहीं, बल्कि पूरे सदन को एक निकाय के रूप में प्राप्त होते हैं। इनमें अपनी रिपोर्ट एवं कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का अधिकार, गैर-सदस्यों को सदन से बाहर निकालने का अधिकार और विशेषाधिकार हनन पर दंडित करने की शक्ति शामिल है। इसके विपरीत, सत्र के दौरान जूरी सेवा से छूट सदस्यों का एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, न कि संपूर्ण सदन का सामूहिक विशेषाधिकार।

83. (C) सत्र से 40 दिन पहले और बाद तक
राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से विशेष सुरक्षा और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यह उन्मुक्ति विधानसभा सत्र के चलने के दौरान तथा सत्र के प्रारंभ होने से 40 दिन पहले और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक प्रभावी रहती है। यह विशेषाधिकार विधायकों को बिना किसी बाधा के अपने विधायी कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता करता है। हालांकि, यह सुरक्षा केवल दीवानी मामलों में है, आपराधिक मामलों में नहीं।

84. (C) लोकसभा साधारण विधेयकों के लिए संयुक्त बैठक का उपयोग कर सकती है, जबकि विधानसभा नहीं कर सकती।
संसद में दोनों सदनों के बीच किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इसके विपरीत, राज्य स्तर पर यदि विधानसभा और विधान परिषद के मध्य किसी विधेयक पर असहमति होती है, तो संयुक्त बैठक का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ऐसे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल राज्य विधानसभा के पास ही निहित होता है, जो विधान परिषद के विरोध को निरस्त कर सकती है।

85. (A) विधानसभा राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है; लोकसभा राष्ट्रीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है।
राज्य विधानसभा की प्राथमिक प्रतिनिधि प्रकृति राज्य के स्थानीय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की विशिष्ट प्राथमिकताओं, समस्याओं और क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करने में निहित है। इसके विपरीत, लोकसभा पूरे देश के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है और राष्ट्रीय स्तर की नीतियों तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ध्यान केंद्रित करती है। दोनों ही निकाय जनता द्वारा प्रत्यक्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं, किंतु उनके विधायी क्षेत्राधिकार और क्षेत्रीय सरोकार भिन्न होते हैं।

86. (D) विधानसभा का सत्र चलने के दौरान किसी विधायक को निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
विधायकों को प्राप्त गिरफ्तारी से छूट का विशेषाधिकार केवल दीवानी (नागरिक) मामलों तक ही सीमित है। यह सुरक्षा आपराधिक मामलों, देशद्रोह या निवारक निरोध (प्रिवेंटिव डिटेंशन) अधिनियम के तहत की जाने वाली गिरफ्तारियों पर लागू नहीं होती है। अतः विधानसभा सत्र के दौरान भी किसी सदस्य को निवारक निरोध के अंतर्गत वैध रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है, बशर्ते इसकी सूचना विधानसभा अध्यक्ष को तुरंत दे दी जाए।

87. (B) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा।
अनुच्छेद 368 के तहत यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक देश के संघीय ढांचे को प्रभावित करता है, तो संसद से पारित होने के पश्चात् इसे कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन हेतु भेजा जाता है। राज्य विधानमंडल (जैसे राजस्थान विधानसभा) में ऐसे संशोधन का अनुसमर्थन करने के लिए किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती; इसे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से ही अनुमोदित किया जाता है।

88. (C) राज्य के मुख्यमंत्री की सामान्य नीतियां और कार्य।
राज्य विधानसभा में भारत के उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए न्यायिक आचरण पर चर्चा करने पर पूर्ण संवैधानिक प्रतिबंध है। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा नीति जैसे राष्ट्रीय विषयों पर भी राज्य चर्चा नहीं करता। परंतु राज्य के मुख्यमंत्री की सामान्य प्रशासनिक नीतियों, निर्णयों और कार्यों पर चर्चा करना विधानसभा का प्राथमिक दायित्व है। अतः यह विकल्प प्रतिबंध की श्रेणी में नहीं आता है।

89. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 यह स्पष्ट आदेश देता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की स्वीकृत संख्या 200 निर्धारित है। यह संख्या संवैधानिक रूप से तय की गई 60 से 500 की निर्धारित सीमा के पूर्णतः भीतर है। अतः दोनों कथन तथ्यात्मक एवं संवैधानिक रूप से बिल्कुल सही हैं।

90. (A) विधानसभा अपनी कार्यवाहियों के प्रकाशन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सकती है।
संसदीय विशेषाधिकारों के अंतर्गत, यदि राजस्थान विधानसभा किसी संवेदनशील विषय पर गुप्त बैठक आयोजित करने का निर्णय लेती है, तो उसे अपनी कार्यवाहियों के प्रकाशन को पूरी तरह से रोकने का सामूहिक विशेषाधिकार प्राप्त है। इस

Downloaded from www.pdf.tube

(C) भारत के उच्चतम न्यायालय का एक बाध्यकारी संवैधानिक निर्णय
(D) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत राष्ट्रपति का आदेश

11. निम्नलिखित में से कौन-सी भारत में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की संवैधानिक अर्हता नहीं है?
(A) उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
(B) वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
(C) उसने भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो।
(D) वह कम से कम दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो।

12. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: संवैधानिक अनुच्छेद
P. अनुच्छेद 214
Q. अनुच्छेद 217
R. अनुच्छेद 219
S. अनुच्छेद 222
सूची II: विषय-वस्तु
1. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
2. किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण
3. राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
4. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की नियुक्ति और शर्तें
(A) P-4, Q-3, R-1, S-2
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-1, Q-4, R-3, S-2

13. किस संवैधानिक प्राधिकारी के पास राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने की शक्ति है?
(A) अपनी एकमात्र न्यायिक क्षमता में कार्य करने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश
(B) भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति
(C) राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने वाले राजस्थान के राज्यपाल
(D) कार्यपालिका की सिफारिश पर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री

14. कॉलेजियम प्रणाली के तहत, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रस्ताव सामान्यतः किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है?
(A) संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(B) कार्यपालिका की सलाह पर कार्य करने वाले राज्य के राज्यपाल
(C) मंत्रालय के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री
(D) शीर्ष कॉलेजियम के माध्यम से भारत के मुख्य न्यायाधीश

15. राज्य विधानमंडल चुनावों के संदर्भ में उच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार क्या है?
(A) उच्च न्यायालय के पास राज्य के चुनाव विवादों पर मूल क्षेत्राधिकार का अभाव है।
(B) चुनाव याचिकाएं सबसे पहले सक्षम जिला न्यायालय में दायर की जानी चाहिए।
(C) यह विधायकों के निर्वाचन से संबंधित चुनाव याचिकाओं पर सीधे सुनवाई कर सकता है।
(D) केवल उच्चतम न्यायालय के पास राज्य विधानमंडल चुनावों पर क्षेत्राधिकार है।

16. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है।
II. अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सदैव परामर्श किया जाता है।
III. यदि कॉलेजियम अपनी सिफारिशों को दोहराता है, तो वे राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती हैं।
IV. किसी प्रख्यात विधिवेत्ता को सीधे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा संयोजन सही है?
(A) केवल I, II और IV
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, III और IV
(D) केवल I, II और III

17. राजस्थान उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है?
(A) अनुच्छेद 32
(B) अनुच्छेद 136
(C) अनुच्छेद 226
(D) अनुच्छेद 227

18. किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाकर रखा है, बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए उच्च न्यायालय द्वारा कौन-सी रिट जारी की जाती है?
(A) परमादेश
(B) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(C) प्रतिषेध
(D) उत्प्रेषण

19. उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) यह जिला न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों के विरुद्ध सिविल अपीलों की सुनवाई करता है।

NODIA

स्थानांतरित हुई। इस नए भवन का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति के0 आर0 नारायणन द्वारा किया गया था।

101. (A) प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछना और प्रस्ताव लाना।
संसदीय व्यवस्था में विधानसभा का प्राथमिक दायित्व कार्यपालिका पर निरंतर नियंत्रण रखना है। राजस्थान विधानसभा में प्रतिदिन सत्र की शुरुआत में प्रश्नकाल आयोजित होता है, जहाँ विधायक मंत्रियों से सीधे तीखे प्रश्न पूछकर प्रशासनिक कार्यों, बजटीय व्यय तथा सार्वजनिक समस्याओं पर सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। इसके अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कामरोको प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव जैसे विधायी साधनों के माध्यम से मंत्रिपरिषद की दैनिक निगरानी और विधायी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है।

102. (D) कोई भी विधायक जो मंत्री नहीं है।
संसदीय शब्दावली में, राज्य सरकार के मंत्रियों के अलावा किसी भी अन्य विधानसभा सदस्य द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गए विधेयक को "गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक" (प्राइवेट मेंबर बिल) कहा जाता है। इसमें चाहे वह सत्ताधारी दल का साधारण विधायक हो, निर्दलीय सदस्य हो या विपक्षी दल का कोई विधायक हो, यदि वह मंत्री नहीं है तो उसके द्वारा लाया गया विधेयक इसी श्रेणी में आएगा। मंत्रियों द्वारा लाए जाने वाले विधेयकों को "सरकारी विधेयक" कहा जाता है।

103. (B) 60 दिन
यद्यपि संविधान केवल यह शर्त तय करता है कि दो सत्रों में छह महीने से अधिक का अंतर न हो, परंतु कुशल विधायी कामकाज के लिए विभिन्न सम्मेलनों द्वारा सिफारिश की गई है कि राजस्थान जैसे बड़े राज्यों की विधानमंडलों की बैठक वर्ष में कम से कम 60 दिन अवश्य होनी चाहिए। इससे विधायकों को जनहित के मुद्दों को उठाने, विधेयकों की सूक्ष्मता से समीक्षा करने और राज्य के बजट एवं प्रशासनिक कार्यों पर उचित नियंत्रण रखने का पर्याप्त समय प्राप्त होता है।

104. (C) कागज रहित प्रणाली की दिशा में बहसों और प्रश्नों को डिजिटल रूप से संरक्षित करना।
राजस्थान विधानसभा ने अपने कामकाज में आधुनिक तकनीक को अपनाकर डिजिटलीकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत विधानसभा की पुरानी बहसों, विधायी रिकॉर्डों, तारांकित प्रश्नों के उत्तरों तथा विधेयकों के प्रारूपों को डिजिटल रूप में परिवर्तित और सुरक्षित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य कागज के उपयोग को कम करके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना और आम नागरिकों तथा शोधकर्ताओं के लिए विधायी डेटा तक आसान पहुंच बनाना है।

105. (D) केवल विधानसभा के निर्वाचित विधायक।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, राज्यों से राज्यसभा (संसद के उच्च सदन) के प्रतिनिधियों का चुनाव संबंधित राज्य की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचन प्रक्रिया में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य (यदि कोई हो) तथा आम नागरिक सीधे भाग नहीं लेते हैं। यह प्रणाली अप्रत्यक्ष चुनाव पर आधारित होती है जिसमें निर्वाचित विधायक ही निर्वाचक मंडल के रूप में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने हेतु राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं।

106. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
राज्य विधानसभा के विधायकों द्वारा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि राज्य विधानसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों को प्राप्त सीटों के अनुपात में ही उन्हें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिले। इस व्यवस्था से अल्पसंख्यकों और छोटे दलों को भी अपनी संख्या बल के आधार पर उच्च सदन में प्रतिनिधि भेजने का न्यायसंगत अवसर प्राप्त होता है। अतः दोनों कथन पूरी तरह सत्य हैं।

107. (A) 10
भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के तहत राजस्थान राज्य को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए कुल 10 सीटें आवंटित की गई हैं। इन सीटों को भरने के लिए राजस्थान विधानसभा के 200 निर्वाचित विधायक निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। अतः इन 10 सीटों के लिए समय-समय पर विधानसभा द्वारा चुनाव संपन्न कराए जाते हैं।

108. (B) राज्यपाल एक बार प्रख्यापित किए जाने के बाद अध्यादेश को वापस नहीं ले सकते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का वही कानूनी प्रभाव होता है जो विधानमंडल के अधिनियम का होता है। हालांकि, राज्यपाल किसी भी समय प्रख्यापित अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, इसलिए यह कहना कि वे इसे वापस नहीं ले सकते, पूरी तरह गलत है। जब विधानसभा का सत्र पुनः शुरू होता है तो अध्यादेश को उसके समक्ष रखा जाता है और यह सत्र शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह में समाप्त हो जाता है।

109. (C) छह महीने और छह सप्ताह
यदि विधानसभा सत्र में न हो, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। चूंकि दो सत्रों के बीच अधिकतम अनुमत अंतराल छह महीने का हो सकता है और विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर अध्यादेश को छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना अनिवार्य होता है, इसलिए किसी अध्यादेश की अधिकतम सैद्धांतिक जीवन अवधि छह महीने और छह सप्ताह हो सकती है। यदि इस अवधि में इसे पारित नहीं किया जाता तो अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है।

110. (C) अविश्वास प्रस्ताव
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा और अल्पकालिक चर्चा ऐसे विधायी साधन हैं जिनका उद्देश्य सरकार से जानकारी प्राप्त करना और लोक महत्व के अत्यावश्यक विषयों पर मंत्रियों का ध्यान आकृष्ट करना होता है। इन प्रक्रियाओं से सरकार के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं पड़ता। इसके विपरीत,

Click Here to Buy book on Flipkart

है। अतः धन्यवाद प्रस्ताव सरकार को कटघरे में खड़ा करने का नहीं, बल्कि उसकी नीतियों का अनुमोदन करने का साधन है।

71. (C) दसवीं अनुसूची
दल-बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में शामिल है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। यह कानून राजस्थान विधानसभा सहित देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं और संसद के सदस्यों पर समान रुप से लागू होता है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक निष्ठा बदलने की अनुचित प्रवृत्ति पर रोक लगाना तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं एवं चुनी हुई सरकारों में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना है।

72. (C) दो-तिहाई
91वें संविधान संशोधन अधिनियम (2003) के द्वारा दसवीं अनुसूची में संशोधन किया गया। इसके तहत यह व्यवस्था की गई कि किसी राजनीतिक दल का किसी अन्य दल में विलय तभी वैध माना जाएगा और सदस्यों को दल-बदल अयोग्यता से छूट मिलेगी, जब संबंधित विधायी दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। इससे पूर्व एक-तिहाई सदस्यों द्वारा किए गए विभाजन को भी मान्यता प्राप्त थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है।

73. (D) दल-बदल पर अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
दसवीं अनुसूची के तहत विधानसभा सदस्यों की दल-बदल संबंधी अयोग्यता का निर्णय करने का प्रारंभिक अधिकार केवल विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किहोतो होलोहन मामले में निर्णय दिया था कि अध्यक्ष का यह निर्णय अंतिम नहीं है और यह उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के अधीन है। दल-बदल के तहत अयोग्य घोषित व्यक्ति तुरंत चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं होता, वह पुनः चुनाव लड़ सकता है।

74. (A) इसे कैबिनेट मंत्री के पद और भत्तों के साथ वैधानिक मान्यता प्राप्त है।
राजस्थान विधानसभा में "नेता प्रतिपक्ष" का पद एक वैधानिक पद है, जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून के माध्यम से औपचारिक कानूनी दर्जा दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष को राज्य सरकार में एक कैबिनेट मंत्री के समान वेतन, भत्ते, दर्जा और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वह सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होता है, जो सरकार की नीतियों की आलोचना करने तथा सदन में विपक्ष की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाने का कार्य करता है।

75. (A) P-1, Q-2, R-4, S-3
जसवंत सिंह 1952 की प्रथम राजस्थान विधानसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष चुने गए थे। भैरों सिंह शेखावत ने कई बार नेता प्रतिपक्ष और बाद में राज्य के मुख्यमंत्री के रुप में कार्य किया। वसुंधरा राजे नेता प्रतिपक्ष रहने के बाद राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं। वहीं गुलाब चंद कटारिया हाल की विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष के पद पर आसीन रहे हैं।

76. (B) केवल II और III
वर्तमान में लागू दल-बदल कानून के तहत अयोग्यता से दो प्रमुख अपवाद उपलब्ध हैं: पहला, यदि मूल दल का किसी अन्य दल में विलय होता है और विधायी दल के दो-तिहाई सदस्य इसके लिए सहमत होते हैं। दूसरा, यदि कोई सदस्य विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर निष्पक्षता बनाए रखने हेतु अपने दल से इस्तीफा देता है। एक-तिहाई सदस्यों द्वारा विभाजन का पुराना अपवाद 91वें संशोधन द्वारा समाप्त किया जा चुका है।

77. (A) कुल सीटों का 10% (अर्थात 20 सीटें)
राजस्थान विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को आधिकारिक रुप से मुख्य विपक्षी दल के रुप में मान्यता प्राप्त करने और उसके नेता को "नेता प्रतिपक्ष" का दर्जा दिए जाने हेतु सदन की कुल सीटों का कम से कम 10% हासिल करना अनिवार्य होता है। चूंकि राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 200 है, इसलिए मुख्य विपक्षी दल बनने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम 20 सदस्यों का होना संवैधानिक एवं विधायी रुप से आवश्यक है।

78. (C) विकृतचित्त होने के कारण अयोग्यता - मुख्यमंत्री
किसी विधायक के विकृतचित्त या दिवालिया होने के आधार पर अनुच्छेद 191 के तहत अयोग्यता का निर्णय राज्य के राज्यपाल द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह पर किया जाता है, मुख्यमंत्री द्वारा नहीं। दसवीं अनुसूची में अयोग्यता का फैसला विधानसभा अध्यक्ष करते हैं, जबकि चुनाव में भ्रष्ट आचरण से संबंधित विवादों का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अतः मुख्यमंत्री को अयोग्यता का निर्णायक प्राधिकारी दर्शाना पूर्णतः गलत युग्म है।

79. (D) यूनाइटेड किंगडम
"छाया मंत्रिमंडल" (शैडो कैबिनेट) की अवधारणा मुख्य रुप से यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) की वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली से जुड़ी हुई है। इसमें विपक्षी दल प्रत्येक सरकारी मंत्री के प्रतिरुप के रुप में अपने वरिष्ठ नेताओं का एक दल गठित करता है जो संबंधित विभागों के कामकाज पर कड़ी नजर रखता है। यद्यपि भारत और राजस्थान ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया है, परंतु यहाँ आधिकारिक रुप से छाया मंत्रिमंडल जैसी व्यवस्था का गठन नहीं किया जाता है।

80. (C) अपने निर्वाचन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।
संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार, यदि राज्य विधानसभा के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रुप में निर्वाचित कोई सदस्य अपने चुनाव के पश्चात् स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो वह दल-बदल विरोधी कानून के तहत अपनी विधानसभा सदस्यता के लिए तुरंत अयोग्य हो जाता है। किसी विधेयक के खिलाफ मतदान करना, अनुपस्थित रहना या मुख्यमंत्री की आलोचना करना निर्दलीय

NODIA

द्विसदनीयता की उपस्थिति के आधार पर उत्तर प्रदेश इन सभी पड़ोसी राज्यों से सर्वथा भिन्न है।

121. (C) 59
राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटों में से आरक्षित सीटों की कुल संख्या 59 है। भारतीय संविधान के तहत सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। इस कुल संख्या में से 34 सीटें अनुसूचित जातियों (SC) के लिए तथा 25 सीटें अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए विशेष रूप से आरक्षित की गई हैं, जबकि शेष 141 सीटें सामान्य वर्ग के लिए खुली रखी गई हैं।

122. (B) 14 दिन
यदि राज्य विधानसभा का कोई निर्वाचित सदस्य संसद के किसी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) के लिए चुन लिया जाता है, तो कानून के अनुसार उसे 14 दिनों के भीतर राज्य विधानसभा से औपचारिक रूप से त्यागपत्र देना होता है। यदि वह निर्धारित 14 दिनों की इस अवधि के भीतर विधानसभा से अपना त्यागपत्र नहीं देता है, तो संसद में उसकी नवनिर्वाचित सीट स्वतः ही रिक्त मान ली जाती है। यह नियम दोहरे प्रतिनिधित्व को रोकने हेतु बनाया गया है।

123. (B) वर्ष में दो बार
संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार, दो सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल छह महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। इस संवैधानिक अनिवार्यता के फलस्वरूप राज्य विधानमंडल की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित होना अनिवार्य है। यद्यपि सुचारू विधायी कामकाज और बजटीय नियंत्रण के लिए राजस्थान विधानसभा में सामान्यतः प्रतिवर्ष तीन सत्र (बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र) आयोजित किए जाते हैं, परंतु संवैधानिक न्यूनतम आवश्यकता वर्ष में दो बैठकों की ही है।

124. (D) कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत, जब राज्य विधानसभा द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल द्वारा उस पर सहमति देने, उसे रोकने या पुनर्विचार हेतु लौटाने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस निश्चित समय सीमा के अभाव के कारण राज्यपाल के पास जेबी वीटो (पॉकेट वीटो) जैसी स्थिति बन जाती है, जिससे वे विधेयक पर निर्णय लेने में आवश्यक समय ले सकते हैं।

125. (A) राज्यपाल
संविधान के अनुच्छेद 267(2) के तहत राजस्थान की आकस्मिकता निधि (कंटिंजेंसी फंड) को राज्य के राज्यपाल के अधीन रखा गया है। किसी प्राकृतिक आपदा, महामारी या अन्य अनपेक्षित आपातकालीन स्थिति के समय जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, तो राज्यपाल इस निधि से अग्रिम धन निकालने की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि, इस प्रकार निकाले गए धन के लिए बाद में राज्य विधानमंडल की औपचारिक कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य होता है।

NODIA

126. (C) विधानसभा अध्यक्ष
संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत एक विशिष्ट संवैधानिक पदधारक यानी विधानसभा अध्यक्ष (या उपाध्यक्ष) को विशेष छूट प्रदान की गई है। यदि कोई सदस्य विधानसभा अध्यक्ष के पद पर चुने जाने के पश्चात् अपनी निष्पक्षता बनाए रखने हेतु स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की प्राथमिक सदस्यता छोड़ देता है या पद छोड़ने के बाद पुनः दल में शामिल होता है, तो उसे दल-बदल के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है।

127. (D) विशेषाधिकार समिति
राजस्थान विधानसभा की विशेषाधिकार समिति एक महत्वपूर्ण निकाय के रूप में कार्य करती है जो सदन तथा उसके सदस्यों के अधिकारों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच करती है। जब कोई सदस्य या बाहरी व्यक्ति सदन के विशेषाधिकार का हनन करता है, तो अध्यक्ष इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजते हैं। यह समिति एक अर्ध-न्यायिक निकाय की भांति साक्ष्य एकत्रित करती है और अपनी सुविचारित रिपोर्ट सदन को सौंपती है।

128. (C) 2013 विधानसभा चुनाव
राजस्थान विधानसभा के राजनीतिक इतिहास में, दिसंबर 2013 में आयोजित 14वें आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करते हुए कुल 200 सीटों में से रिकॉर्ड 163 सीटें हासिल की थीं। यह राज्य के चुनावी इतिहास में किसी भी एकल राजनीतिक दल द्वारा जीती गई सर्वाधिक सीटों का सर्वकालिक रिकॉर्ड है। इस ऐतिहासिक जनादेश के बाद वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राज्य में पूर्ण बहुमत वाली सरकार का गठन किया गया था।

129. (B) तारा भंडारी
राजस्थान विधानसभा के इतिहास में जहाँ सुमित्रा सिंह को पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है, वहीं तारा भंडारी राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष चुनी गई थीं। उन्होंने 1998 में इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को सुशोभित किया था। उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की बैठकों का निष्पक्ष संचालन किया और राज्य की विधायी प्रक्रियाओं में महिला नेतृत्व की एक सशक्त तथा अनुकरणीय मिसाल कायम की थी।

130. (D) 10 सदस्य या कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा, जो भी अधिक हो।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189(3) के अनुसार, राज्य विधानसभा की किसी भी बैठक को आयोजित करने तथा वैध रूप से कार्यवाहियों का संचालन करने के लिए गणपूर्ति (कोरम) पीठासीन अधिकारी सहित 10 सदस्य या सदन की कुल सदस्यता का दसवां भाग (जो भी अधिक हो) निर्धारित है। राजस्थान विधानसभा की 200 सदस्यों की क्षमता के अनुसार

स्थिति में कोई भी समाचार पत्र या बाहरी मीडिया बिना अनुमति कार्यवाहियों को प्रकाशित नहीं कर सकता। गुप्त बैठक का उल्लंघन करना सदन के विशेषाधिकार का गंभीर हनन माना जाता है और इसके लिए दंडित किया जा सकता है।

91. (B) यशोदा देवी
यशोदा देवी को राजस्थान के विधायी इतिहास में प्रथम महिला विधायक होने का गौरव प्राप्त है। वे नवंबर 1953 में बांसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हुए उप-चुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंची थीं। वर्ष 1952 में हुए प्रथम सामान्य चुनावों में कोई भी महिला चुनाव नहीं जीत सकी थी। यशोदा देवी के इस ऐतिहासिक निर्वाचन ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और प्रतिनिधित्व का नया मार्ग प्रशस्त किया।

92. (B) कमला बेनीवाल
कमला बेनीवाल राजस्थान सरकार में मंत्री बनने वाली पहली महिला थीं। वे 1954 में मोहनलाल सुखाड़िया मंत्रिमंडल में उपमंत्री के रूप में शामिल हुई थीं। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में राज्य सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों का कुशलतापूर्वक संचालन किया। बाद में उन्होंने गुजरात सहित कई राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं। राज्य के प्रशासनिक विकास और महिला सशक्तिकरण में उनका योगदान अत्यंत सराहनीय माना जाता है।

93. (A) सुमित्रा सिंह राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थीं।
सुमित्रा सिंह राजस्थान विधानसभा के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनी थीं। वे 2003 में 12वीं राजस्थान विधानसभा की अध्यक्ष चुनी गई थीं और उन्होंने संपूर्ण कार्यकाल के दौरान सदन का सफलतापूर्वक संचालन किया। 1952 की पहली विधानसभा में कोई भी महिला निर्वाचित होकर नहीं आई थी, बल्कि बाद में उप-चुनाव द्वारा पहली महिला विधायक बनीं। अतः सुमित्रा सिंह द्वारा अध्यक्ष पद संभालना राज्य में महिला सशक्तिकरण का एक ऐतिहासिक उदाहरण है।

94. (C) पंचायती राज संस्थाएं
106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 ("नारी शक्ति वंदन अधिनियम") के माध्यम से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 243D के तहत पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% से 50% आरक्षण की व्यवस्था बहुत पहले से ही लागू है।

95. (C) 1952
राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव जनवरी 1952 में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए थे। उस समय कुल 160 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुए थे। इन चुनावों के पश्चात 29 मार्च 1952 को राजस्थान की प्रथम विधानसभा का औपचारिक गठन किया गया था। प्रथम आम चुनावों के बाद पंडित टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मुख्यमंत्री बने तथा नरोत्तम लाल जोशी को विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था।

96. (C) अजमेर-मेरवाड़ा राज्य का राजस्थान में विलय।
1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने के साथ ही 'सी' श्रेणी के राज्य अजमेर-मेरवाड़ा का राजस्थान में पूर्ण विलय हो गया था। इस विलय के परिणामस्वरूप, अजमेर विधानसभा की 30 सीटें राजस्थान विधानसभा में शामिल कर दी गईं। इसके कारण राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 160 से बढ़कर 190 हो गई। यह घटना राजस्थान के भौगोलिक और राजनीतिक एकीकरण के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई।

97. (D) I, II और III
राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 1967 में अस्पष्ट जनादेश के कारण लागू किया गया था। वर्ष 1977 में केंद्र में सरकार बदलने पर राज्य सरकार को भंग कर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसके अलावा, 1992 में बाबरी मस्जिद ढांचा ढहाए जाने के बाद लगाया गया चौथा राष्ट्रपति शासन अब तक का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था, जो लगभग एक वर्ष तक प्रभावी रहा। अतः दिए गए तीनों कथन ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह सत्य हैं।

98. (D) छठी विधानसभा: 1977 – 1985
छठी राजस्थान विधानसभा की अवधि 1977 से 1980 तक ही रही थी। वर्ष 1980 में केंद्र में नई सरकार के गठन के पश्चात् छठी विधानसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया गया था और नए चुनाव कराए गए थे। इसलिए इसका कार्यकाल 1977 से 1985 तक दर्शाना पूरी तरह बेमेल और गलत है। अन्य सभी विकल्प - प्रथम (1952-57), द्वितीय (1957-62) और पांचवीं (1972-77) विधानसभा की अवधियों का सही और सटीक वर्णन करते हैं।

99. (A) अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा।
वर्ष 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, आपातकाल के दौरान संसद कानून बनाकर राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए 1972 में चुनी गई पांचवीं राजस्थान विधानसभा की सामान्य 5 वर्ष की अवधि को बढ़ाकर 1977 तक विस्तारित कर दिया गया था।

100. (C) 2001
वर्ष 1952 में अपने गठन के समय से ही राजस्थान विधानसभा जयपुर के प्रसिद्ध सवाई मानसिंह टाउन हॉल (हवा महल के पास) में संचालित होती थी। लगभग चार दशकों से अधिक समय तक वहां कार्य करने के पश्चात्, राजस्थान विधानसभा मार्च 2001 में ज्योति नगर, जयपुर में निर्मित अपने वर्तमान भव्य, आधुनिक और विशाल नए भवन में आधिकारिक रूप से

Downloaded from www.pdf.tube

अध्याय 15

राजस्थान उच्च न्यायालय

1. राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था?
   (A) 26 जनवरी 1950
   (B) 29 अगस्त 1949
   (C) 1 नवंबर 1956
   (D) 15 अगस्त 1947

2. राजस्थान की निम्नलिखित पूर्व रियासतों में से किस रियासत का राज्य के एकीकरण से पूर्व अपना उच्च न्यायालय नहीं था?
   (A) जोधपुर
   (B) जैसलमेर
   (C) जयपुर
   (D) बीकानेर

3. निम्नलिखित में से किसे राजस्थान उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था?
   (A) न्यायमूर्ति के.एन. वांचू
   (B) न्यायमूर्ति कैलाश नाथ काटजू
   (C) न्यायमूर्ति जे.एम. पांचाल
   (D) न्यायमूर्ति कमल कांत वर्मा

4. राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
   (A) यह राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के तहत स्थापित किया गया।
   (B) यह 1950 में पारित एक संवैधानिक संशोधन के तहत स्थापित किया गया।
   (C) यह भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रत्यक्ष आदेश द्वारा स्थापित किया गया।
   (D) यह 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया।

5. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
   कथन I: राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या 50 है।
   कथन II: किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या भारत के संविधान द्वारा निर्धारित की जाती है और इसे राष्ट्रपति द्वारा बदला नहीं जा सकता है।
   उपर्युक्त कथनों के आलोक में, सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:
   (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
   (B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
   (C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
   (D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

6. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है?
   (A) राजस्थान के राज्यपाल
   (B) भारत के राष्ट्रपति
   (C) भारत के मुख्य न्यायाधीश
   (D) राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

NODIA

7. भारत के संविधान के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है?
   (A) 60 वर्ष
   (B) 62 वर्ष
   (C) 65 वर्ष
   (D) 70 वर्ष

8. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रुप में अंकित किया गया है:
   अभिकथन (A): राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थित है।
   कारण (R): बी.आर. पटेल समिति ने राजधानी के रुप में जयपुर के प्रशासनिक और राजनीतिक महत्व को संतुलित करने के लिए उच्च न्यायालय को जोधपुर में स्थापित करने की सिफारिश की थी।
   (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
   (B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
   (C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।
   (D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है।

9. सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर किस वर्ष राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया गया था?
   (A) 1956
   (B) 1958
   (C) 1966
   (D) 1977

10. 1977 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ को किस कानूनी माध्यम द्वारा पुनर्जीवित किया गया था?
    (A) राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित एक वैधानिक अधिनियम
    (B) भारत की संसद द्वारा पारित एक केंद्रीय विधायी अधिनियम

अविश्वास प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य सरकार में सदन के विश्वास की परीक्षा करना होता है, जिसके पारित होने पर सरकार को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है। अतः यह बेमेल विकल्प है।

111. (D) नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन
'नेवा' का पूर्ण रूप "नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन" (National e-Vidhan Application) है। यह भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित एक मिशन मोड डिजिटल परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की सभी राज्य विधानसभाओं के विधायी कामकाज को पूरी तरह से कागज रहित (पेपरलेस), पारदर्शी और त्वरित बनाना है। इसके माध्यम से सदन की कार्यसूची, प्रश्न, उत्तर और विधेयकों के प्रारूप विधायकों को डिजिटल रूप में उनके टैबलेट पर ही उपलब्ध कराए जाते हैं।

112. (C) विधानसभा की कार्यवाहियों का सीधा सजीव प्रसारण।
राजस्थान विधानसभा के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने और आम नागरिकों तक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा की कार्यवाहियों का सीधा सजीव प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) आरंभ किया गया है। टेलीविजन और डिजिटल माध्यमों से प्रसारण होने से नागरिक अपने निर्वाचित विधायकों के भाषणों, प्रश्नों और बजटीय बहसों को सीधे देख सकते हैं। इससे जनप्रतिनिधियों में जनता के प्रति नैतिक जवाबदेही तथा विधायी कार्यों की सुचिता में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

113. (C) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।
राजस्थान विधानसभा की सामान्य कार्यवाहियों का टीवी और ऑनलाइन माध्यमों पर सीधा प्रसारण किया जाता है ताकि नागरिक विधायी कामकाज को देख सकें। हालांकि, यदि सदन किसी संवेदनशील या सुरक्षा संबंधी मुद्दे पर "गुप्त बैठक" आयोजित करने का निर्णय लेता है, तो ऐसी बैठकों का सीधा प्रसारण पूरी तरह से वर्जित होता है और उनकी मीडिया कवरेज प्रतिबंधित रहती है। इसलिए पहला कथन सही है, जबकि गुप्त बैठकों के सीधे प्रसारण वाला दूसरा कथन असत्य है।

114. (D) 230
राजस्थान का पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से एक बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश की एकसदनीय विधानसभा में कुल स्वीकृत सीटों की संख्या 230 है। तुलनात्मक रूप से, राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में भी राजस्थान की भांति केवल एक ही सदन (विधानसभा) कार्य कर रहा है तथा वहां विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है। इन दोनों पड़ोसी राज्यों की विधायी संरचना में कई समानताएं पाई जाती हैं।

115. (A) हरियाणा - एकसदनीय विधानमंडल
राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ एकसदनीय विधानमंडल विद्यमान है, अर्थात वहाँ केवल विधानसभा (90 सीटें) ही कार्य कर रही है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है जहाँ विधानसभा के साथ विधान परिषद भी स्थित है। गुजरात और पंजाब में भी एकसदनीय विधानमंडल ही हैं। अतः हरियाणा और एकसदनीय विधानमंडल का युग्म पूरी तरह से सही और तथ्यात्मक रूप से सटीक मेल प्रदर्शित करता है।

116. (C) राजस्थान के विपरीत, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है।
राजस्थान में केवल एक सदन (विधानसभा) वाला एकसदनीय विधानमंडल है, जबकि उसके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल कार्य कर रहा है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल हैं। पड़ोसी राज्यों में सबसे अधिक विधानसभा सीटें (403 सीटें) उत्तर प्रदेश में हैं, न कि राजस्थान में। इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में केवल एकसदनीय व्यवस्था लागू है। अतः उत्तर प्रदेश से संबंधित तुलनात्मक कथन ही पूर्ण सत्य है।

117. (A) हरियाणा (90)
कम आबादी और छोटे भौगोलिक आकार वाले राज्यों में आमतौर पर सीटों की संख्या कम होती है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसकी विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, जो राजस्थान की 200 सीटों की तुलना में काफी कम हैं। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश (403 सीटें), मध्य प्रदेश (230 सीटें) और महाराष्ट्र (288 सीटें) ऐसे राज्य हैं जिनकी विधानसभा सीटों की संख्या राजस्थान की कुल सीटों से काफी अधिक है।

118. (D) हरियाणा - 120
हरियाणा की विधानसभा में कुल स्वीकृत सीटों की संख्या 90 है, इसलिएइसे 120 दर्शाना पूरी तरह से गलत युग्म है। अन्य विकल्पों में राजस्थान (200 सीटें), गुजरात (182 सीटें) और पंजाब (117 सीटें) की विधानसभा सीटों का विवरण बिल्कुल सही और तथ्यात्मक रूप से सटीक दिया गया है। राज्य विधानसभा की सीटों का यह निर्धारण वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोगों द्वारा निर्धारित किया गया था।

119. (B) एक निश्चित समय पर सभी शेष अनुदान मांगों पर मतदान कराना।
"गिलोटिन" संसदीय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण नियम है। राज्य के बजट पर चर्चा के लिए निर्धारित समय सीमा समाप्त होने पर, विधानसभा अध्यक्ष बिना किसी आगे की बहस के उन सभी शेष अनुदान मांगों को एक साथ मतदान के लिए रख देते हैं जिन पर चर्चा नहीं हो सकी है। इस प्रक्रिया को गिलोटिन कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि निश्चित समय सीमा के भीतर संपूर्ण वित्तीय आवंटन प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जा सके।

120. (C) उत्तर प्रदेश
राजस्थान के भौगोलिक पड़ोसी राज्यों में उत्तर प्रदेश एक बेमेल विकल्प है क्योंकि उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है, अर्थात वहाँ विधानसभा के साथ-साथ विधान परिषद भी कार्यरत है। इसके विपरीत, राजस्थान के अन्य पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और गुजरात में एकसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है जहाँ विधान परिषद मौजूद नहीं है। अतः

Click Here to Buy book on Amazon

(B) यह सत्र न्यायालयों द्वारा दी गई मृत्युदंड की सजा के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है।
(C) यह राज्य के विशेष वैधानिक अधिकरणों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।
(D) सत्र न्यायालय द्वारा दी गई मृत्युदंड की सजा के लिए उच्च न्यायालय की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है।

20. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से व्यापक है।
कारण (R): उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि सामान्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।
(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है।

21. किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी रिट जारी की जा सकती है?
(A) अधिकार-पृच्छा
(B) परमादेश
(C) प्रतिषेध
(D) बंदी प्रत्यक्षीकरण

22. अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के संदर्भ में, सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए।
(A) इसमें क्षेत्रीय न्यायालयों और अधिकरणों पर प्रशासनिक और न्यायिक अधीक्षण शामिल है।
(B) यह राज्य के सामान्य अधीनस्थ न्यायालयों पर केवल प्रशासनिक अधीक्षण तक ही सीमित है।
(C) इसका विस्तार सशस्त्र बलों से संबंधित कानूनों के तहत स्थापित सैन्य अधिकरणों और न्यायालयों तक है।
(D) यह उच्च न्यायालय को नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को संशोधित या परिवर्तित करने का अधिकार देता है।

23. क्षेत्राधिकार के प्रकार और उसके विवरण का सही सुमेलित युग्म पहचानिए।
(A) मूल क्षेत्राधिकार - अधीनस्थ विचारण न्यायालयों से उत्पन्न अपीलों की सुनवाई
(B) अपीलीय क्षेत्राधिकार - मुकदमों की सुनवाई करने और न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति
(C) परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार - उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल को कानूनी सलाह देना
(D) पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार - निचले न्यायालयों और अधिकरणों पर नियंत्रण

24. संविधान के अनुच्छेद 226 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह अपने आप में एक मौलिक अधिकार है।
II. यह उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी को रिट जारी करने की अनुमति देता है।
III. अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान इसे निलंबित किया जा सकता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा संयोजन सही है?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

25. अनुच्छेद 32 के तहत, कोई व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। सुलभता के मामले में अनुच्छेद 226 की तुलना कैसे की जाती है?
(A) अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय जाने से पहले जिला न्यायालय का द्वार खटखटाना अनिवार्य बनाता है।
(B) अनुच्छेद 226 केवल उच्चतम न्यायालय से अपीलों की अनुमति देता है।
(C) अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को राहत देने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है।
(D) अनुच्छेद 226 नागरिकों को राज्य अधिकारियों के विरुद्ध राहत मांगने से रोकता है।

NODIA

26. निम्नलिखित में से कौन-सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है?
(A) जोधपुर
(B) उदयपुर
(C) बीकानेर
(D) कोटा

27. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: रिट
P. बंदी प्रत्यक्षीकरण
Q. परमादेश
R. अधिकार-पृच्छा
S. उत्प्रेषण
सूची II: शाब्दिक अर्थ
1. किस अधिकार या प्राधिकार से
2. प्रमाणित होना या सूचित किया जाना
3. हम आदेश देते हैं
4. शरीर को प्रस्तुत किया जाए
(A) P-4, Q-3, R-1, S-2
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-4, Q-1, R-3, S-2
(D) P-1, Q-2, R-4, S-3

Q. सुलह
R. मध्यस्थता समझौता
S. लोक अदालत
सूची II: विशेषता
1. सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत वैधानिक मंच
2. तटस्थ तीसरा पक्ष साक्ष्य और कानून के आधार पर एक बाध्यकारी निर्णय/पंचाट देता है
3. तटस्थ तीसरा पक्ष सक्रिय रूप से निपटारे के विकल्पों और प्रस्तावों का सुझाव देता है
4. तटस्थ तीसरा पक्ष मामले के गुणों का मूल्यांकन किए बिना या समाधान का प्रस्ताव दिए बिना बातचीत को सुगम बनाता है
(A) P-2, Q-3, R-4, S-1
(B) P-1, Q-4, R-3, S-2
(C) P-2, Q-4, R-3, S-1
(D) P-3, Q-2, R-1, S-4

47. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था?
(A) 1987
(B) 1993
(C) 1999
(D) 2002

48. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22B के तहत विशेष रूप से जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों से निपटने के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की गई है।
कथन II: यदि पक्षकार सुलह समझौते पर पहुँचने में विफल रहते हैं, तो स्थायी लोक अदालत गुण-दोष के आधार पर विवाद का फैसला नहीं कर सकती है।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में, सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

49. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक के रूप में कौन कार्य करता है?
(A) कार्यपालिक क्षमता में राजस्थान के पदेन राज्यपाल
(B) मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री
(C) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(D) राज्य मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान के विधि मंत्री

50. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आमतौर पर किसे नियुक्त किया जाता है?
(A) कार्यपालिक मामलों के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करने वाले राज्य के मुख्य सचिव
(B) राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश
(C) कानून के संवैधानिक प्रावधानों के तहत नियुक्त राज्य के महाधिवक्ता
(D) राज्य विधि विभाग द्वारा सीधे नियुक्त एक नामित वरिष्ठ अधिवक्ता

51. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न रहे?
(A) अनुच्छेद 38
(B) अनुच्छेद 39A
(C) अनुच्छेद 41
(D) अनुच्छेद 46

52. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के तहत निःशुल्क विधिक सेवाओं की पात्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य पात्र है।
II. एक महिला या बच्चा पात्र है।
III. एक औद्योगिक कर्मकार पात्र है।
IV. आय की परवाह किए बिना भारत का प्रत्येक नागरिक पात्र है।
उपर्युक्त में से कौन-सा संयोजन सही है?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, III और IV
(D) I, II, III और IV

53. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है?
(A) जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर)
(B) पुलिस अधीक्षक
(C) जिला न्यायाधीश
(D) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

54. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) राज्य के आपराधिक मामलों के लिए सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय।
(B) पूरे राज्य में लोक अदालतों का आयोजन और संचालन करने के लिए उत्तरदायी।
(C) व्यापक विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविरों के आयोजन में संलग्न।
(D) पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं और सहायता प्रदान करने के लिए अधिकृत।

55. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

Downloaded from www.pdf.tube

(A) अनुच्छेद 44
(B) अनुच्छेद 50
(C) अनुच्छेद 51
(D) अनुच्छेद 227

38. किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है?
(A) उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा
(B) स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
(C) कार्यपालिका की सिफारिशों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा
(D) खुली परीक्षाओं के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा

39. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): उच्च न्यायालय के पास राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होता है।
कारण (R): अनुच्छेद 235 जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण, जिसमें न्यायिक सेवा के व्यक्तियों की पदस्थापना और पदोन्नति शामिल है, उच्च न्यायालय में निहित करता है।
(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।
(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है।

40. विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों के सुलह और त्वरित निपटारे को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कुटुंब न्यायालयों की स्थापना का आधार बनने वाला कुटुंब न्यायालय अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था?
(A) 1976
(B) 1984
(C) 1995
(D) 2005

41. कुटुंब न्यायालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(A) विधि व्यवसायियों को कुटुंब न्यायालय में पक्षों का प्रतिनिधित्व करने का पूर्ण अधिकार है।
(B) कुटुंब न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में उल्लिखित साक्ष्य और प्रक्रिया के कड़े नियमों का सख्ती से पालन करते हैं।
(C) कुटुंब न्यायालय का प्राथमिक उद्देश्य सुलह को बढ़ावा देना और त्वरित निपटारे को सुरक्षित करना है।
(D) कुटुंब न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील सीधे उच्चतम न्यायालय में होती है।

42. लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय/पंचाट की मूल विशेषता क्या है?
(A) इसे 30 दिनों की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में अपील के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है।
(B) यह केवल एक परामर्शदात्री दस्तावेज के रूप में कार्य करता है और इसमें कोई बाध्यकारी कानूनी प्रवर्तनीयता नहीं होती है।
(C) कानूनी रूप से मान्य होने के लिए इसे जिला न्यायाधीश द्वारा औपचारिक रूप से समीक्षा और पुष्ट किया जाना चाहिए।
(D) यह सिविल न्यायालय की एक बाध्यकारी डिक्री है जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है।

43. लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. उनके पास किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित विवादों में समझौता कराने और उनका निपटारा करने का क्षेत्राधिकार है।
II. वे मुकदमेबाजी से पूर्व के चरण में भी मामलों का निपटारा कर सकते हैं।
III. यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो अशमनीय आपराधिक मामलों का भी लोक अदालतों में निपटारा किया जा सकता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा संयोजन सही है?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

NODIA

44. भारत में वैधानिक दर्जा प्राप्त करने से पहले एक स्वैच्छिक और सुलह संस्था के रूप में प्रथम लोक अदालत शिविर किस राज्य में (1982 में) आयोजित किया गया था?
(A) राजस्थान
(B) गुजरात
(C) महाराष्ट्र
(D) उत्तर प्रदेश

45. निम्नलिखित में से किस वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र में सामान्यतः एक तटस्थ तीसरे पक्ष की आवश्यकता होती है जो बातचीत को सुगम बनाता है और निर्णय थोपे बिना पक्षों को सर्वसम्मति से स्वीकार्य समझौते तक पहुँचने में मदद करता है?
(A) मध्यस्थता / अधिनिर्णयन
(B) सुगमकर्ता मध्यस्थता
(C) मुकदमेबाजी
(D) न्यायनिर्णयन

46. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र
P. मध्यस्थता

(C) नाथद्वारा (राजसमंद)
(D) बस्सी (जयपुर)

81. भारत में फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना शुरुआत में किस वित्त आयोग की सिफारिश पर की गई थी?
(A) 9वां वित्त आयोग
(B) 10वां वित्त आयोग
(C) 11वां वित्त आयोग
(D) 12वां वित्त आयोग

82. राजस्थान में विशेष न्यायालयों और अधिकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. अपराधों के त्वरित विचारण के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत विशेष न्यायालयों को नामित किया गया है।
II. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 उच्च मूल्य वाले वाणिज्यिक विवादों को तेजी से निपटाने के लिए विशेष न्यायालयों का प्रावधान करता है।
III. विशेष न्यायालय स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करते हैं।
IV. राजस्थान में सभी विशेष न्यायालयों के फैसले उच्च न्यायालय को दरकिनार करते हैं और केवल उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाते हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा संयोजन सही है?
(A) केवल I, II और IV
(B) केवल I, II और III
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

83. राजस्थान में रियल एस्टेट परियोजनाओं और घर खरीदारों के हितों की रक्षा से संबंधित विवादों और अपीलों से कौन-सा विशेष अधिकरण निपटता है?
(A) लोक सेवा विवादों के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण
(B) पर्यावरण संरक्षण मामलों के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण
(C) उपभोक्ताओं के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
(D) स्थावर संपदा (रेरा) अपीलीय अधिकरण

84. उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) जनहित याचिका में 'सुनवाई के अधिकार' का पारंपरिक नियम सख्ती से लागू होता है।
(B) यह मूल रूप से न्यायिक सक्रियता का परिणाम है।
(C) इसे मुख्य न्यायाधीश को संबोधित किसी पत्र या पोस्टकार्ड के आधार पर भी शुरू किया जा सकता है।
(D) इसका प्राथमिक उद्देश्य वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना और व्यापक जनहित के मामलों का समाधान करना है।

85. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प भारतीय निर्णयशास्त्र में जनहित याचिका और न्याय तक पहुँच से संबंधित अवधारणाओं के सही कालानुक्रमिक विकास को दर्शाता है?
(A) सुनवाई के अधिकार में ढील, पत्र याचिका क्षेत्राधिकार, जनहित याचिका दिशा-निर्देशों का संस्थागतीकरण, सामाजिक क्रिया याचिका
(B) जनहित याचिका दिशा-निर्देशों का संस्थागतीकरण, सुनवाई के अधिकार में ढील, पत्र याचिका क्षेत्राधिकार, सामाजिक क्रिया याचिका
(C) सामाजिक क्रिया याचिका, जनहित याचिका दिशा-निर्देशों का संस्थागतीकरण, सुनवाई के अधिकार में ढील, पत्र याचिका क्षेत्राधिकार
(D) पत्र याचिका क्षेत्राधिकार, सुनवाई के अधिकार में ढील, सामाजिक क्रिया याचिका, जनहित याचिका दिशा-निर्देशों का संस्थागतीकरण

86. जनहित याचिका के संदर्भ में 'सुनवाई के अधिकार' में ढील का मूल अर्थ क्या है?
(A) कोई भी जनहित से प्रेरित संस्था वंचित नागरिकों की ओर से याचिका दायर कर सकती है।
(B) यह सार्वजनिक छुट्टियों या रविवार को अदालतों द्वारा औपचारिक न्यायिक सुनवाई करने पर पूर्ण प्रतिबंध निर्दिष्ट करता है।
(C) यह सख्ती से आदेश देता है कि केवल व्यक्तिगत रूप से पीड़ित पक्ष के पास ही याचिका दायर करने का कानूनी अधिकार है।
(D) यह न्यायालय में प्रत्येक कार्यवाही के दौरान एक प्रमाणित कानूनी अधिवक्ता की भौतिक उपस्थिति को अनिवार्य बनाता है।

87. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: तेजी से राहत पाने के लिए निजी विवादों के लिए निजी व्यक्तियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं के खिलाफ आम तौर पर एक जनहित याचिका दायर की जा सकती है।
कथन II: पर्यावरण संबंधी कुछ अपवादों को छोड़कर, एक जनहित याचिका केवल राज्य या सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने वाले सार्वजनिक प्राधिकारियों के खिलाफ ही पोषणीय है।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में, सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

88. जनहित याचिका के तहत किसी पत्र या टेलीग्राम को रिट याचिका मानने की उच्च न्यायालय की शक्ति को किस रूप में जाना जाता है?
(A) अपीलीय क्षेत्राधिकार
(B) पत्र याचिका क्षेत्राधिकार
(C) परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार
(D) अन्वेषणात्मक क्षेत्राधिकार

Click Here to Buy book on Flipkart

कथन I: राजस्थान में सामान्य आय मानदंडों के तहत ₹3,00,000 से अधिक की वार्षिक आय वाला व्यक्ति आम तौर पर निःशुल्क विधिक सहायता का हकदार होता है।
कथन II: बड़े पैमाने पर आपदाओं, जातीय हिंसा या प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ित अपनी आय की परवाह किए बिना निःशुल्क विधिक सहायता के हकदार हैं।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में, सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

56. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य घटक है।
कारण (R): भारत के उच्चतम न्यायालय ने हुस्नआरा खातून मामले में यह माना कि एक निष्पक्ष सुनवाई का तात्पर्य आरोपी के लिए विधिक प्रतिनिधित्व तक पहुँच होना है।
(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।
(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है।

57. तालुका विधिक सेवा समिति का मूल उद्देश्य क्या है?
(A) ग्रामीण पंचायत निकायों के लिए स्थानीय प्रशासनिक नियमों का निर्माण और अधिनियमन करना।
(B) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध औपचारिक अपीलों की सुनवाई करना और उनका फैसला करना।
(C) तालुका स्तर पर विधिक सेवाएं और जागरूकता प्रदान करना।
(D) तालुका न्यायालयों के लिए सिविल न्यायिक अधिकारियों की भर्ती करना और उन्हें नियुक्त करना।

58. मानक दिशा-निर्देशों के तहत निःशुल्क विधिक सहायता की पात्रता के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए।
(A) न्यायिक हिरासत में बंद व्यक्ति
(B) मानव तस्करी का शिकार व्यक्ति
(C) मानसिक रूप से बीमार या दिव्यांग व्यक्ति
(D) एक बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट संस्था

59. निम्नलिखित विधिक सेवा प्राधिकरणों को उनके पदानुक्रम (उच्चतम से निम्नतम क्षेत्राधिकार) के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
2. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
3. तालुका विधिक सेवा समिति
4. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनिए:
(A) 2, 4, 1, 3
(B) 2, 1, 4, 3
(C) 4, 2, 1, 3
(D) 1, 3, 4, 2

60. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले पद से कैसे हटाया जा सकता है?
(A) राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सीधे जारी एक कार्यपालिक आदेश द्वारा।
(B) संसदीय विशेष बहुमत के समावेदन के बाद राष्ट्रपति द्वारा।
(C) राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद राज्यपाल द्वारा।
(D) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित एकतरफा प्रशासनिक आदेश द्वारा।

61. न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संवैधानिक आधार क्या हैं?
(A) अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार
(B) साबित कदाचार या असमर्थता
(C) संविधान का उल्लंघन और नैतिक अधोगति
(D) उच्चतम न्यायालय की अवज्ञा

62. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
II. इस प्रस्ताव को लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा में 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।
III. आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा संयोजन सही है?
(A) I, II और III
(B) केवल I और II
(C) केवल II और III
(D) केवल I और III

63. किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने का प्रयास किया था, जिसे बाद में उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था?
(A) 97वां संशोधन
(B) 99वां संशोधन
(C) 101वां संशोधन
(D) 103वां संशोधन

64. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: न्यायपालिका पर प्रमुख वाद

Downloaded from www.pdf.tube

28. उत्प्रेषण रिट और प्रतिषेध रिट के बीच मौलिक अंतर क्या है?
(A) प्रतिषेध प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है, जबकि उत्प्रेषण केवल निजी गैर-वैधानिक निकायों तक सीमित है।
(B) प्रतिषेध कार्यवाही के दौरान क्षेत्राधिकार के उल्लंघन को रोकता है, जबकि उत्प्रेषण पूर्ण हो चुके आदेशों को रद्द करता है।
(C) उत्प्रेषण अनुच्छेद 226 के तहत किसी राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा ही जारी किया जा सकता है।
(D) प्रतिषेध का उद्देश्य केवल मौलिक अधिकारों को लागू करना है, जबकि उत्प्रेषण केवल वैधानिक कानूनी अधिकारों को लागू करने का कार्य करता है।

29. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: किसी निजी व्यक्ति या विशुद्ध रूप से निजी कंपनी के विरुद्ध सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने के लिए परमादेश रिट जारी की जा सकती है।
कथन II: भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उनके आधिकारिक कर्तव्यों के पालन के लिए परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में, सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

30. सिविल और आपराधिक मामलों के लिए जिला स्तर पर किस न्यायालय को सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी माना जाता है?
(A) जिला एवं सत्र न्यायालय
(B) अपनी अपीलीय क्षमता में कार्य करने वाला राज्य का उच्च न्यायालय
(C) जिला स्तर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय
(D) राज्य के कानून के तहत स्थापित कुटुंब न्यायालय

31. अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए पात्र होने हेतु किसी अधिवक्ता के पास कम से कम कितने वर्षों का वकालत का अनुभव होना चाहिए?
(A) 5 वर्ष
(B) 7 वर्ष
(C) 10 वर्ष
(D) 12 वर्ष

32. राजस्थान में अधीनस्थ न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. जिला न्यायाधीशों के अलावा राज्य की न्यायिक सेवा में व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
II. ऐसी नियुक्तियां राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद की जाती हैं।
III. जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार में निहित है।
IV. जिला न्यायाधीश को सिविल मामलों में मूल और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा संयोजन सही है?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, III और IV
(D) केवल I, II और IV

NODIA

33. अधीनस्थ न्यायपालिका में निम्नलिखित पदों में से असंगत पद की पहचान कीजिए।
(A) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
(B) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट
(C) उप-खंड मजिस्ट्रेट
(D) अपर सत्र न्यायाधीश

34. एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानूनी रूप से अधिकतम कितनी अवधि के कारावास की सजा सुना सकता है?
(A) 3 वर्ष
(B) 7 वर्ष
(C) 10 वर्ष
(D) आजीवन कारावास

35. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प उच्चतम से निम्नतम क्रम में जिला स्तर पर आपराधिक न्यायालयों का सही पदानुक्रमित क्रम दर्शाता है?
(A) सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट
(B) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट
(C) सत्र न्यायालय, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट
(D) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट

36. जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश के बीच अंतर के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) सत्र न्यायाधीश उच्च न्यायालय की पुष्टि के बिना मृत्युदंड की सजा को निष्पादित कर सकता है।
(B) एक ही न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश के रूप में दोहरा कार्य करता है।
(C) सिविल विवादों का निर्णय करते समय, न्यायिक अधिकारी को जिला न्यायाधीश के रूप में नामित किया जाता है।
(D) आपराधिक अपराधों की सुनवाई करते समय, न्यायिक अधिकारी को सत्र न्यायाधीश के रूप में नामित किया जाता है।

37. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण को सुनिश्चित करता है?

72. राजस्थान में न्यायपालिका के डिजिटलीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड राजस्थान की अदालतों में लंबित और निपटाए गए मामलों का व्यापक डेटा प्रदान करता है।
II. यातायात उल्लंघनों को ऑनलाइन प्रबंधित करने के लिए राजस्थान में ई-चालान और आभासी अदालतें लागू की गई हैं।
III. संवेदनशील गवाहों और विचाराधीन कैदियों के साक्ष्य दर्ज करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग किया जाता है।
IV. न्यायालय की प्रक्रियाओं में डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा संयोजन सही है?

(A) केवल I, II और IV
(B) केवल I, II और III
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

73. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

(A) न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में कार्य करना।
(B) उच्चतम न्यायालय के लिए विशेष आभासी अदालती सुनवाई और कार्यवाही आयोजित करना।
(C) अदालती लंबितता और देरी की निगरानी के लिए मामलों का एक डेटाबेस तैयार करना।
(D) निचले न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों को साइबर कानून मामलों में प्रशिक्षित करना।

74. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: राजस्थान उच्च न्यायालय कागजी कार्रवाई को कम करने और सुलभता बढ़ाने के लिए मामलों की ई-फाइलिंग की अनुमति देता है।

कथन II: ई-फाइलिंग ने राज्य में मुकदमेबाजी के लिए सभी अदालती शुल्कों के भुगतान को समाप्त कर दिया है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

75. राजस्थान उच्च न्यायालय सहित भारतीय न्यायालयों में मामलों की अत्यधिक लंबितता के प्रमुख कारण के रूप में निम्नलिखित में से किसे सबसे उपयुक्त रूप से पहचाना गया है?

(A) न्यायिक रिक्तियां, प्रक्रियात्मक देरी और स्थगन।
(B) वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का व्यापक और बार-बार उपयोग।
(C) जनसंख्या की तुलना में नियुक्त न्यायाधीशों के अनुपात में भारी वृद्धि।
(D) निचले न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील करने के लिए वैधानिक तंत्र की पूर्ण कमी।

76. निम्नलिखित में से कौन-सा राजस्थान में मामलों की लंबितता को कम करने के लिए एक मान्यता प्राप्त पहल नहीं है?

(A) विवाद समाधान के लिए नियमित रूप से निरंतर मेगा लोक अदालतों का आयोजन करना।
(B) जनहित याचिकाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना।
(C) विशिष्ट जघन्य अपराधों से निपटने के लिए निर्दिष्ट त्वरित न्यायालय स्थापित करना।
(D) पात्र आपराधिक मामलों में दण्ड सौदेबाजी के प्रावधानों को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना।

77. 2019 में उद्घाटित राजस्थान उच्च न्यायालय की नवनिर्मित, अत्याधुनिक इमारत किस क्षेत्र में स्थित है?

(A) सी-स्कीम, जयपुर
(B) झालामंड, जोधपुर
(C) रातानाडा, जोधपुर
(D) मानसरोवर, जयपुर

78. दिसंबर 2019 में जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किस प्राधिकारी/व्यक्ति द्वारा किया गया था?

(A) राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द
(B) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
(C) भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे
(D) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

79. राजस्थान में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. वे मुख्य रूप से बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन जैसे जघन्य अपराधों के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए थे।
II. इन न्यायालयों की स्थापना आंशिक रूप से केंद्र प्रायोजित योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
III. प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए वे प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों का पालन किए बिना काम करते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा संयोजन सही है?

(A) केवल II और III
(B) केवल I और III
(C) केवल I और II
(D) I, II और III

80. जमीनी स्तर पर न्याय तक पहुँच प्रदान करने के लिए 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया गया था। 2010 में राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था?

(A) फलोदी (जोधपुर)
(B) नोखा (बीकानेर)

Click Here to Buy book on Amazon

P. एस.पी. गुप्ता वाद (प्रथम न्यायाधीश मामला)
Q. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन वाद (द्वितीय न्यायाधीश मामला)
R. विशेष संदर्भ मामला 1, 1998 (तृतीय न्यायाधीश मामला)
S. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग वाद (चतुर्थ न्यायाधीश मामला)

सूची II: मुख्य परिणाम/वर्ष

1. 2015, 99वें संशोधन को रद्द किया
2. 1993, कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना की और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह को बाध्यकारी बनाया
3. 1981, यह माना कि 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' नहीं है
4. 1998, कॉलेजियम का विस्तार 5-सदस्यीय निकाय के रूप में किया

(A) P-2, Q-3, R-1, S-4
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-1, Q-2, R-3, S-4
(D) P-3, Q-2, R-4, S-1

65. उच्चतम न्यायालय के निर्णयों द्वारा स्थापित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण का कौन-सा आधार/शर्त नकारात्मक या अमान्य है?
(A) यह लोकहित में होना चाहिए।
(B) यह भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद किया जाना चाहिए।
(C) इसे दंडात्मक उपाय या सजा के रूप में किया जा सकता है।
(D) स्थानांतरित करने वाले और प्राप्त करने वाले उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के विचार प्राप्त किए जाने चाहिए।

66. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालय सहित भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील के लिए विशेष अनुमति देने की अनुमति देता है।
कथन II: उच्च न्यायालय प्रशासनिक रूप से उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ है और उससे दैनिक प्रशासनिक निर्देश प्राप्त करता है।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में, सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

67. किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय ऐसे मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र देता है जिसमें संविधान की व्याख्या के संबंध में विधि का कोई सारवान प्रश्न शामिल हो?
(A) अनुच्छेद 131
(B) अनुच्छेद 132
(C) अनुच्छेद 137
(D) अनुच्छेद 143

68. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के बीच संबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?
(A) उच्चतम न्यायालय सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखता है।
(B) उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी उच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है।
(C) उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ अपील उच्चतम न्यायालय में होती है।
(D) न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उच्चतम न्यायालय एकतरफा रूप से उच्च न्यायालय में लंबित मामले को वापस ले सकता है और स्वयं उसका निपटारा कर सकता है।

69. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): किसी राज्य का उच्च न्यायालय भारत के उच्चतम न्यायालय का अधीनस्थ प्रशासनिक निकाय नहीं है।
कारण (R): भारतीय संविधान कानूनों को लागू करने के लिए एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली स्थापित करता है, लेकिन उच्च न्यायालय अपनी प्रशासनिक स्वायत्तता और शक्तियां सीधे संविधान से प्राप्त करते हैं।
(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।
(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है।

70. संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में सही सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए।
(A) अनुच्छेद 215 - अभिलेख न्यायालय
(B) अनुच्छेद 223 - कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
(C) अनुच्छेद 224 - अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति
(D) अनुच्छेद 228 - कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण

NODIA

71. ई-न्यायालय राष्ट्रीय पोर्टल और पहल को मुख्य रूप से किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था?
(A) मानव न्यायिक अधिकारियों को पूरी तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों से बदलना।
(B) राज्य के विचारण न्यायालयों में लंबित सभी मुकदमों को अनिवार्य रूप से सीधे उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करना।
(C) प्रक्रिया के पारंपरिक वैधानिक नियमों और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पूरी तरह से दरकिनार करना।
(D) निचले न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण करना और ऑनलाइन न्यायिक सेवाएं प्रदान करना।

89. उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्यतः जनहित याचिका के रूप में स्वीकार न की जाने वाली मामलों की निम्नलिखित श्रेणियों में से असंगत श्रेणी की पहचान कीजिए।
(A) बंधुआ मजदूरी और मानवाधिकार उल्लंघनों से संबंधित याचिकाएं।
(B) सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों द्वारा या उनकी ओर से दायर याचिकाएं।
(C) व्यक्तिगत कर्मचारियों के सेवा और पेंशन संबंधी विवाद।
(D) पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिक असंतुलन को चुनौती देने वाली याचिकाएं।

90. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: अधिकरण/मंच
P. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण
Q. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण
R. राष्ट्रीय हरित अधिकरण
S. राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
सूची II: विषय-वस्तु
1. पर्यावरण संरक्षण और वनों का संरक्षण
2. वस्तुओं और सेवाओं में कमी के संबंध में शिकायतें
3. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा मामले
4. राज्य सरकार के कर्मचारियों के सेवा मामले
(A) P-4, Q-3, R-1, S-2
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-1, Q-2, R-3, S-4
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

91. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को संबोधित करने वाले ऐतिहासिक विशाखा दिशा-निर्देश किस राज्य की एक सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ हुए क्रूर अपराध से उत्पन्न हुए थे?
(A) राजस्थान
(B) उत्तर प्रदेश
(C) मध्य प्रदेश
(D) महाराष्ट्र

92. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निपटाए गए 'निखिल सोनी बनाम भारत संघ' मामले के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) इसने राज्य में सभी पंचायत स्तरीय चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के अनिवार्य उपयोग का निर्देश दिया।
(B) इसने जैन धर्म की 'संथारा' प्रथा को अवैध घोषित किया, जिस पर बाद में उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी।
(C) इसने सभी राज्य विश्वविद्यालयों में लागू वैधानिक आरक्षण प्रणाली को पूरी तरह से अमान्य और समाप्त कर दिया।
(D) इसने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में निहित प्रमुख संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों को रद्द कर दिया।

93. किस कुख्यात सामाजिक बुराई के कारण राजस्थान में एक ऐतिहासिक कानूनी और सामाजिक लड़ाई हुई जिसके परिणामस्वरूप सती (निवारण) आयोग अधिनियम, 1987 लागू हुआ?
(A) भंवरी देवी मामला
(B) रूप कंवर मामला
(C) खेजड़ली नरसंहार
(D) छगन राज मामला

94. निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य की अदालतों में लागू हालिया न्यायिक सुधारों की विशेषता नहीं है?
(A) अधीनस्थ न्यायाधीशों को प्रशासनिक नौकरशाहों से बदलना।
(B) ई-स्टैंपिंग प्रणालियों और अदालती शुल्कों के ई-भुगतान का व्यापक परिचय।
(C) चुनिंदा संवैधानिक अदालती कार्यवाहियों के लिए सार्वजनिक लाइव स्ट्रीमिंग सुविधा लागू करना।
(D) त्वरित आर्थिक विवाद समाधान के लिए समर्पित विशेष वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना करना।

95. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: राजस्थान उच्च न्यायालय ने पारदर्शिता और खुले न्याय को सुनिश्चित करने के लिए अपनी कार्यवाहियों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरु की है।
कथन II: अदालतों में लाइव स्ट्रीमिंग न्यायाधीशों के निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में, सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

96. संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत, उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियों के लिए मानक प्राधिकृत भाषा क्या है, जब तक कि राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से अन्यथा प्रावधान न करें?
(A) हिंदी
(B) हिंदी और अंग्रेजी दोनों बारी-बारी से
(C) स्थानीय राज्य बोली (राजस्थानी)
(D) अंग्रेजी

97. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के तहत कुछ वाणिज्यिक मुकदमों के लिए निम्नलिखित में से किस वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को एक अनिवार्य पूर्व-संस्थागत चरण बनाया गया है?
(A) मध्यस्थता
(B) न्यायिक अधिनिर्णयन
(C) मध्यस्थता / सुलह
(D) लोक अदालत

98. दंड प्रक्रिया संहिता में शुरु की गई अवधारणा जो एक आरोपी को कम सजा के बदले में अपना अपराध स्वीकार करने की

Downloaded from www.pdf.tube

अनुमति देती है, जिससे अदालती लंबितता कम होती है, उसे क्या कहा जाता है?
(A) दोहरा जोखिम
(B) दण्ड सौदेबाजी
(C) अपराधों का शमन
(D) दोषमुक्ति

99. किसी कानूनी अवधारणा और उसके विवरण के गलत युग्म की पहचान कीजिए।
(A) न्याय मित्र - किसी मामले में सहायता के लिए नियुक्त न्यायालय का मित्र
(B) प्रांग्न्याय - पहले से निर्णित मामले पर उन्हीं पक्षों द्वारा पुनः मुकदमा नहीं चलाया जा सकता
(C) स्वतः संज्ञान - अदालत द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर की गई कार्रवाई
(D) एकपक्षीय - सभी पक्षों की उपस्थिति और सुनवाई के साथ दिया गया फैसला

100. राजस्थान उच्च न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियम मुख्य रूप से किसमें संकलित हैं?
(A) राजस्थान उच्च न्यायालय नियम, 1952
(B) व्यापक राजस्थान राज्य न्यायिक कोड नियम, 1960
(C) उच्चतम न्यायालय के पद्धति और प्रक्रिया नियम, 2013
(D) राजस्थान अदालतों के लिए सिविल प्रक्रिया का वैधानिक कोड

101. 1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के समय इसका प्रारंभिक ढांचा क्या था?
(A) 1 मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश
(B) 1 मुख्य न्यायाधीश और 5 अन्य सहयोगी न्यायाधीश
(C) 1 मुख्य न्यायाधीश और 20 अन्य सहयोगी न्यायाधीश
(D) 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य सहयोगी न्यायाधीश

102. यदि राजस्थान उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति से पहले त्यागपत्र देना चाहता है, तो त्यागपत्र किसे संबोधित होना चाहिए?
(A) भारत के राष्ट्रपति
(B) राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(C) राजस्थान के राज्यपाल
(D) भारत के मुख्य न्यायाधीश

103. अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) वे मानक सेवानिवृत्ति आयु तक स्थायी आजीवन कार्यकाल के साथ नियुक्त किए जाते हैं।
(B) वे राज्य की कार्यपालिक सलाह पर कार्य करने वाले राज्यपाल द्वारा सीधे नियुक्त किए जाते हैं।
(C) उनके पास नियमित न्यायाधीशों की तुलना में कम संवैधानिक अधिकार होते हैं और वे रिट जारी नहीं कर सकते हैं।
(D) उन्हें बकाए मामलों को निपटाने के लिए अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

104. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन का भार किस पर होता है?
(A) वेतन और पेंशन दोनों राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।
(B) राज्य की संचित निधि वेतन देती है, जबकि संघ की निधि पेंशन देती है।
(C) वेतन और पेंशन दोनों भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
(D) वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जबकि पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होती है।

105. अनुच्छेद 215 के तहत 'अभिलेख न्यायालय' के रूप में उच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसके निर्णय, कार्यवाहियां और कार्य शाश्वत स्मृति और साक्ष्य के लिए दर्ज किए जाते हैं।
II. इन अभिलेखों की सटीकता पर किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में सवाल उठाया जा सकता है।
III. इसके पास अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है।
उपर्युक्त में से कौन-सा संयोजन सही है?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

106. अधिकार-पृच्छा रिट 'सुनवाई के अधिकार' के सामान्य नियमों का एक अपवाद है। इसे निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है?
(A) वैधानिक सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति
(B) संवैधानिक सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति
(C) आवश्यक योग्यता न होने पर भी सरकारी पद पर नियुक्त व्यक्ति
(D) किसी निजी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी में निजी प्रबंधकीय पद धारण करने वाला व्यक्ति

107. सिविल और आपराधिक अवमानना का विवरण देते हुए, अदालत की अवमानना के लिए सजा को नियंत्रित करने वाला वैधानिक ढांचा किस अधिनियम में पाया जाता है?
(A) न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971
(B) भारतीय दंड संहिता, 1860
(C) न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985
(D) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

108. भारतीय कानून के तहत 'सिविल अवमानना' को 'आपराधिक अवमानना' से क्या अलग करता है?
(A) सिविल अवमानना में सख्ती से अदालत में शारीरिक

NODIA

व्यवधान शामिल है, जबकि आपराधिक अवमानना में केवल मौखिक चिल्लाना शामिल है।
(B) सिविल अवमानना आदेश की अवज्ञा है, जबकि आपराधिक अवमानना अदालत की गरिमा को ठेस पहुँचाना है।
(C) सिविल अवमानना केवल कानूनी अधिवक्ताओं द्वारा की जा सकती है, जबकि आपराधिक अवमानना आम जनता द्वारा की जाती है।
(D) सिविल अवमानना जेल की सजा द्वारा पूरी तरह से गैर-दंडनीय है, जबकि आपराधिक अवमानना में अनिवार्य हिरासत की सजा होती है।

109. राज्यों के एकीकरण के दौरान राजस्थान की राजधानी जयपुर और उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थापित करने का अंतिम निर्णय लेने में किस समिति की सिफारिश महत्वपूर्ण थी?
(A) फजल अली आयोग
(B) बी.आर. पटेल समिति
(C) के.एम. मुंशी समिति
(D) स्वर्ण सिंह समिति

110. निम्नलिखित में से कौन-सा अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के प्रशासनिक अधीक्षण के अंतर्गत आता है?
(A) अधीनस्थ न्यायालयों से विवरण मांगना
(B) उनकी कार्यपद्धति और कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए सामान्य नियम बनाना और जारी करना
(C) बही और खातों को बनाए रखने के लिए प्रारूप निर्धारित करना
(D) उपर्युक्त सभी

111. ऐतिहासिक रूप से, आधुनिक ग्राम न्यायालयों से पहले राजस्थान में ग्राम स्तर पर छोटे सिविल और आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए किन निकायों का गठन किया गया था?
(A) जिला स्तर पर जिला परिषदें
(B) पारंपरिक खाप पंचायतें
(C) न्याय पंचायतें
(D) ब्लॉक समिति परिषदें

112. ग्राम न्यायालयों की अध्यक्षता एक न्यायाधिकारी द्वारा की जाती है। मानक न्यायिक पदानुक्रम में न्यायाधिकारी का समकक्ष पद क्या है?
(A) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश
(B) वरिष्ठ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
(C) जिला कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(D) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट

113. ग्राम न्यायालय में विधिक प्रतिनिधित्व के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) वकीलों और अधिवक्ताओं को ग्राम न्यायालयों में पेश होने से पूरी तरह से और सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है।
(B) केवल उच्चतम न्यायालय में नामांकित वरिष्ठ अधिवक्ताओं को ही ग्राम न्यायालयों में मामले प्रस्तुत करने की अनुमति है।
(C) यह विवाद सुलह के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं और मध्यस्थों को शामिल कर सकता है।
(D) राज्य सरकार अनिवार्य रूप से दोनों मुकदमेबाज पक्षों का मार्गदर्शन और सहायता करने के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश को नियुक्त करती है।

114. किसी अधीनस्थ न्यायालय में एक सामान्य सिविल मुकदमे के निम्नलिखित चरणों को सही प्रक्रियात्मक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. वाद पत्र दाखिल करना
2. विवादकों का निर्माण
3. समन की तामील
4. लिखित कथन दाखिल करना

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनिए:
(A) 1, 4, 3, 2
(B) 1, 3, 4, 2
(C) 3, 1, 4, 2
(D) 1, 2, 3, 4

115. कुटुंब न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की मुख्य विशेषता क्या है?
(A) वे विशेष रूप से पारिवारिक व्यवसायों के बीच वाणिज्यिक कॉर्पोरेट प्रशासन विवादों से निपटते हैं।
(B) उनके पास दहेज से संबंधित गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड देने का पूर्ण वैधानिक अधिकार है।
(C) वे साक्ष्य अधिनियम द्वारा अनिवार्य कठोर, अपरिवर्तनीय साक्ष्य प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करते हैं।
(D) वे वैवाहिक विवादों, दाम्पत्य अधिकारों और संरक्षकता का समाधान करते हैं।

116. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357A के तहत राजस्थान में लागू पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत, पीड़ित को दी जाने वाली मुआवजे की राशि कौन तय करता है?
(A) जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
(B) राज्य सरकार का गृह विभाग
(C) स्थानीय जिला थाना प्रभारी अधिकारी
(D) मुख्यमंत्री राज्य राहत कोष समिति

117. निम्नलिखित में से कौन-सा लोक अदालतों का एक नकारात्मक पहलू या सीमा है?
(A) वे बिना अदालती शुल्क के त्वरित न्याय प्रदान करती हैं।
(B) उन्हें वकीलों द्वारा अनिवार्य कानूनी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है।
(C) उनके निर्णयों/पंचाटों की उच्च न्यायालयों में अपील नहीं की जा सकती।
(D) वे पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण निपटारे को बढ़ावा देती हैं।

Click Here to Buy book on Flipkart

56. (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
निःशुल्क विधिक सहायता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग माना गया है। प्रसिद्ध हुस्नआरा खातून मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि किसी आरोपी के लिए निष्पक्ष सुनवाई का अर्थ उसे कानूनी प्रतिनिधित्व की पहुँच उपलब्ध कराना है। यदि कोई आरोपी गरीबी के कारण वकील नहीं रख पाता, तो राज्य का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह उसे मुफ्त वकील प्रदान करे।

57. (C) तालुका स्तर पर विधिक सेवाएं और जागरुकता प्रदान करना।
तालुका विधिक सेवा समिति का गठन तालुका या उप-खंड स्तर पर कानूनी सहायता सेवाओं को जमीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए किया जाता है। इसकी अध्यक्षता वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के निवासियों को मुफ्त कानूनी सहायता देना, विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करना और लोक अदालतों के माध्यम से स्थानीय विवादों का समाधान कराना है। यह समिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में अपने कार्यों का निष्पादन करती है।

58. (D) एक बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट संस्था
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान समाज के वंचित, गरीब और असहाय वर्गों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसमें हिरासत में बंद व्यक्ति, मानव तस्करी के शिकार, मानसिक रूप से बीमार या दिव्यांग व्यक्ति और कम आय वाले नागरिक पूरी तरह पात्र होते हैं। इसके विपरीत commercial उद्देश्यों के लिए कार्य करने वाली बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट संस्थाएँ या लाभ कमाने वाले व्यावसायिक संगठन मुफ्त कानूनी सहायता पाने के पात्र नहीं हैं।

59. (A) 2, 4, 1, 3
भारत में विधिक सेवा प्राधिकरणों की संरचना चार स्तरीय पदानुक्रम में व्यवस्थित है। सर्वोच्च स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) केंद्र स्तर पर कार्य करता है। इसके पश्चात राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) का स्थान आता है। तीसरे स्तर पर जिला स्तर का संचालन करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करता है। सबसे निचले स्तर पर तालुका या उप-खंड स्तर पर तालुका विधिक सेवा समिति स्थापित की जाती है।

60. (B) संसदीय विशेष बहुमत के समावेदन के बाद राष्ट्रपति द्वारा।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार किसी न्यायाधीश को केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है। यह आदेश संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित महाभियोग प्रस्ताव के समावेदन पर आधारित होना चाहिए। यह प्रक्रिया सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के तहत संचालित होती है।

61. (B) साबित कदाचार या असमर्थता
संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के केवल दो संवैधानिक आधार निर्धारित किए गए हैं: साबित कदाचार और असमर्थता। न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 इन आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन की प्रक्रिया निर्धारित करता है। समिति में एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधिवेत्ता शामिल होते हैं। समिति द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने पर ही संसद में निष्कासन प्रस्ताव पर मतदान होता है।

NODIA

62. (A) I, II और III
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसे लोकसभा में न्यूनतम 100 सदस्यों या राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्ताव स्वीकार होने पर अध्यक्ष या सभापति द्वारा आरोपों की जांच हेतु तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठित की जाती है। यदि समिति आरोपों को सही पाती है, तो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाते हैं।

63. (B) 99वां संशोधन
99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2014 के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) की स्थापना का प्रयास किया गया था। इसका उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की पुरानी कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित करना था। हालाँकि, वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने चौथे न्यायाधीश मामले में इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। न्यायालय ने माना कि यह संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है।

64. (D) P-3, Q-2, R-4, S-1
न्यायपालिका से जुड़े ऐतिहासिक मुकदमों ने नियुक्ति प्रक्रिया को आकार दिया है। प्रथम न्यायाधीश मामला 1981 में हुआ जिसने परामर्श को सहमति नहीं माना। द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 में हुआ जिसने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की और मुख्य न्यायाधीश की सलाह बाध्यकारी बनाई। तृतीय न्यायाधीश मामला 1998 में हुआ जिसने कॉलेजियम का विस्तार 5 सदस्यों तक किया। चतुर्थ न्यायाधीश मामला 2015 में हुआ जिसने 99वें संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निरस्त कर दिया।

65. (C) इसे दंडात्मक उपाय या सजा के रूप में किया जा सकता है।
उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण केवल सार्वजनिक हित या न्याय प्रशासन की बेहतरी के लिए ही किया जा सकता है। इसे कभी भी दंडात्मक उपाय या सजा के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। स्थानांतरण की प्रक्रिया

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs, you are wasting valuable time.

Research shows that learning from **PRINTED BOOKS** has up to **4× HIGHER RETENTION** than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS** move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND** in competition.

In competitive exams, being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

128. न्यायिक समीक्षा के संबंध में सही सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए।
(A) न्यायिक सक्रियता - मौलिक अधिकारों का विस्तार किए बिना सख्त शाब्दिक वैधानिक व्याख्या
(B) न्यायिक संयम - कार्यपालिक नीति निर्माण और शासन के मामलों में अदालतों का सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना
(C) न्यायिक अतिसक्रियता - अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का वैध और उचित प्रयोग
(D) न्यायिक समीक्षा - संविधान के विरुद्ध वैधानिक कानूनों का परीक्षण करने की शक्ति

129. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा भारतीय संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है।
कथन II: राज्य के वित्त को प्रबंधित करने के लिए सामान्य समय के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में, सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

130. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली न्यायिक समीक्षा की शक्ति का तात्पर्य है:
(A) केवल अपने पहले सुनाए गए निर्णयों की समीक्षा करने और उन्हें बदलने का सीमित अधिकार।
(B) संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले राज्य के कानूनों को अमान्य घोषित करने की शक्ति।
(C) भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा करने, उन्हें संशोधित करने या रद्द करने की अपीलीय शक्ति।
(D) विधानसभा द्वारा पारित होने से पहले विधायी विधेयकों को वीटो करने की संवैधानिक शक्ति।

NODIA

मृत्युदंड के आदेश को तब तक निष्पादित नहीं किया जा सकता जब तक कि राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा उसकी औपचारिक पुष्टि न कर दी जाए।

37. (B) अनुच्छेद 50
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इस पृथक्करण का मूल उद्देश्य न्यायपालिका की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और तटस्थता बनाए रखना है ताकि कार्यपालिक हस्तक्षेप के बिना निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित हो सके। इसके परिणामस्वरुप न्यायिक अधिकारियों को प्रशासनिक और राजस्व कार्यों से पूरी तरह अलग रखा जाता है।

38. (A) उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा
संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के साथ अनिवार्य परामर्श के पश्चात ही करते हैं। उच्च न्यायालय की सिफारिश इस प्रक्रिया में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल योग्य और निष्पक्ष व्यक्तियों को ही न्यायिक पदों पर नियुक्त किया जाए और न्यायिक स्वतंत्रता में कोई कार्यपालिक हस्तक्षेप न हो।

39. (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय को राज्य के सभी जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण प्राप्त है। इसमें न्यायिक अधिकारियों की पदस्थापना, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति और अनुशासनिक कार्यवाही शामिल हैं। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि अधीनस्थ न्यायपालिका राज्य कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रहकर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। अतः उच्च न्यायालय का यह नियंत्रण संस्थागत स्वायत्तता और निष्पक्ष न्याय प्रणाली की आधारशिला प्रस्तुत करता है।

40. (B) 1984
विवाह, पारिवारिक विवादों और संरक्षकता से संबंधित मुकदमों के सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के लिए संसद द्वारा कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य पारंपरिक अदालती मुकदमों की कठोर प्रक्रियाओं को हटाकर सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से पारिवारिक मामलों का त्वरित निस्तारण करना है। राजस्थान में इस अधिनियम के तहत विभिन्न जिलों में कुटुंब न्यायालयों की स्थापना की गई है जो परिवार से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर परामर्श और विधिक समाधान प्रदान करते हैं।

41. (C) कुटुंब न्यायालय का प्राथमिक उद्देश्य सुलह को बढ़ावा देना और त्वरित निपटारे को सुरक्षित करना है।
कुटुंब न्यायालय अधिनियम का मूल उद्देश्य विवाह और पारिवारिक मामलों में टकराव कम करना तथा पक्षों के बीच समझौता कराना है। ये न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के कड़े और जटिल नियमों से बंधे नहीं होते, बल्कि अपनी प्रक्रिया स्वयं तय कर सकते हैं। इनमें वकीलों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं होता तथा न्यायालय की अनुमति से ही वकील उपस्थित हो सकते हैं। इनके निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में की जाती है।

42. (D) यह सिविल न्यायालय की एक बाध्यकारी डिक्री है जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत आयोजित लोक अदालत द्वारा पारित पंचाट को सिविल न्यायालय की डिक्री का दर्जा प्राप्त होता है। लोक अदालत का निर्णय सभी पक्षों पर अंतिम और पूर्णतः बाध्यकारी होता है। इस निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की जा सकती, क्योंकि यह दोनों पक्षों की आपसी सहमति से तय होता है। यदि कोई पक्ष असंतुष्ट रहता है तो वह नियमित न्यायालय में नया मुकदमा दायर करने के लिए स्वतंत्र होता है।

43. (A) केवल I और II
लोक अदालत के पास किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों और मुकदमेबाजी से पूर्व चरण के विवादों का निपटारा आपसी सहमति से कराने का क्षेत्राधिकार है। यह सिविल मामलों, पारिवारिक विवादों और शमनीय आपराधिक मुकदमों का समाधान कराती है। हालाँकि, अशमनीय आपराधिक मामले कानूनन समझौता योग्य नहीं होते, इसलिए ऐसे गंभीर अपराधों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। इससे न्याय प्रणाली में सौहार्दपूर्ण समझौते को प्रोत्साहन मिलता है।

44. (B) गुजरात
भारत में लोक अदालत की अवधारणा एक स्वैच्छिक और अनौपचारिक निपटान मंच के रूप में प्रारंभ हुई थी। पहली लोक अदालत का आयोजन 1982 में गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले के ऊना में किया गया था। इस प्रयोग की सफलता के बाद इसे देश भर में लोकप्रिय बनाया गया। बाद में इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के माध्यम से वैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे इसके निर्णयों को कानूनी मान्यता और सिविल न्यायालय की डिक्री का स्तर प्राप्त हुआ।

45. (B) सुगमकर्ता मध्यस्थता
सुगमकर्ता मध्यस्थता एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया है जिसमें एक निष्पक्ष और तटस्थ तीसरा व्यक्ति विवादित पक्षों के बीच बातचीत को आसान बनाता है। मध्यस्थ पक्षों पर अपना कोई फैसला नहीं थोपता, बल्कि उन्हें स्वयं एक सर्वसम्मति से स्वीकार्य समझौते तक पहुँचने में मदद करता है। यह प्रक्रिया गोपनीयता, सहयोग और संवाद पर आधारित होती है, जिससे पक्षों के आपसी संबंध बने रहते हैं और अदालती मुकदमों के समय और खर्च में भारी बचत होती है।

Downloaded from www.pdf.tube

9. (B) 1958
राज्य पुनर्गठन के पश्चात गठित पी. सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया गया था। इस निर्णय के बाद जोधपुर को राज्य का एकमात्र न्यायिक केंद्र बनाया गया था ताकि एकीकृत क्षेत्राधिकार बना रहे। हालाँकि, बाद में पूर्वी राजस्थान के नागरिकों को न्यायिक पहुंच में हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों और बढ़ते कार्यभार को देखते हुए जयपुर में पुनः पीठ स्थापित करने की मांग लगातार उठती रही।

10. (D) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत राष्ट्रपति का आदेश
राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ को वर्ष 1977 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) के अंतर्गत जारी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। इस पीठ का औपचारिक उद्घाटन जनवरी 1977 में हुआ। इसके माध्यम से राजस्थान के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी जिलों के मुकदमों की सुनवाई जयपुर में की जाने लगी। इस कदम ने जोधपुर मुख्य पीठ पर बढ़ते मामलों के दबाव को कम किया और पूर्वी क्षेत्रों के नागरिकों के लिए न्याय सुलभ बनाया।

11. (A) उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आवश्यक अर्हताओं में व्यक्ति का भारत का नागरिक होना, भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्षों तक न्यायिक पद धारण करना या कम से कम दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना शामिल है। अतः आयु संबंधी न्यूनतम सीमा का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, यद्यपि व्यावहारिक रूप से अनुभवी व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता है।

12. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
भारतीय संविधान का भाग 6 राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 219 न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन करता है। अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात कर सकते हैं।

13. (B) भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति
संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत भारत के राष्ट्रपति को किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण दूसरे उच्च न्यायालय में करने की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम से परामर्श करने के बाद ही करते हैं। इस स्थानांतरण का उद्देश्य जनहित और न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता को बनाए रखना होता है। किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण दंडात्मक आधार पर नहीं किया जा सकता है।

14. (A) संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रारंभ की जाती है। मुख्य न्यायाधीश अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श करके उपयुक्त अभ्यर्थियों के नामों की सिफारिश राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भेजते हैं। इसके पश्चात यह प्रस्ताव केंद्रीय कानून मंत्रालय के माध्यम से भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के पास अंतिम स्वीकृति हेतु भेजा जाता है।

15. (C) यह विधायकों के निर्वाचन से संबंधित चुनाव याचिकाओं पर सीधे सुनवाई कर सकता है।
उच्च न्यायालय के पास राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवादों और याचिकाओं पर सीधे विचार करने का मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत राज्य विधानसभा या विधान परिषद के चुनाव की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं सीधे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के पास ऐसे निर्वाचन संबंधी विवादों पर प्राथमिक सुनवाई करने की शक्ति नहीं होती, जिससे चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मामलों का त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित होता है।

16. (D) केवल I, II और III
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श अनिवार्य होता है। यदि कॉलेजियम अपनी सिफारिश दोहराता है तो सरकार पर वह बाध्यकारी होती है। उच्च न्यायालय में प्रख्यात विधिवेत्ता को सीधे न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, यह सुविधा केवल उच्चतम न्यायालय के लिए उपलब्ध है।

17. (C) अनुच्छेद 226
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ किसी भी अन्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर रिट जारी की जा सकती है। उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण जैसी रिट जारी कर सकते हैं। यह क्षेत्राधिकार राज्य के भौगोलिक सीमा के भीतर आने वाले सभी प्राधिकरणों तथा व्यक्तियों पर लागू होता है और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करता है।

18. (B) बंदी प्रत्यक्षीकरण
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का अर्थ शरीर को प्रस्तुत करना होता है। जब किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या निजी व्यक्ति द्वारा अवैध रुप से हिरासत में रखा जाता है, तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय यह रिट जारी करता है। इसके माध्यम से हिरासत में लेने वाले अधिकारी को बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

NODIA

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) 29 अगस्त 1949
राजस्थान उच्च न्यायालय का औपचारिक उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में किया गया था। राजप्रमुख महाराजा मानसिंह ने न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई थी। एकीकरण के समय राज्य की रियासतों में संचालित विभिन्न पृथक न्यायालयों को समाप्त करके एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था बनाई गई। प्रारंभ में जोधपुर में मुख्य पीठ की स्थापना हुई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में कमल कांत वर्मा ने कार्य किया। यह संस्था राज्य में कानून व्यवस्था और न्याय बनाए रखती है।

2. (B) जैसलमेर
राजस्थान के एकीकरण से पूर्व रियासती काल में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा जैसी प्रमुख रियासतों में अपने स्वयं के उच्च न्यायालय कार्यरत थे। इसके विपरीत जैसलमेर रियासत के पास अपना कोई स्वतंत्र उच्च न्यायालय नहीं था। एकीकरण प्रक्रिया के दौरान राज्य पुनर्गठन के साथ ही रियासती न्यायालयों का विलय कर दिया गया। इसके पश्चात पूरे राज्य के लिए एक समान और एकीकृत न्यायिक प्रणाली का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत वर्तमान उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया।

3. (D) न्यायमूर्ति कमल कांत वर्मा
राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के समय न्यायमूर्ति कमल कांत वर्मा को पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्होंने 29 अगस्त 1949 को शपथ ली और राज्य में एक व्यवस्थित न्यायपालिका की नींव रखी। इससे पूर्व वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश और उदयपुर रियासत में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे चुके थे। उनके कार्यकाल के दौरान रियासती अदालतों के विलय और नवगठित उच्च न्यायालय की प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ करने का कार्य निष्पादित किया गया था।

4. (A) यह राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के तहत स्थापित किया गया।
राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के तहत किया गया था। इस अध्यादेश को राज्य के एकीकरण के समय राजप्रमुख द्वारा जारी किया गया था। इसके माध्यम से रियासतों के तत्कालीन पृथक उच्च न्यायालयों को समाप्त करके एक एकीकृत उच्च न्यायालय की स्थापना का कानूनी आधार तैयार किया गया। इस विधायी संरचना ने संपूर्ण राजस्थान क्षेत्र के लिए एक समान क्षेत्राधिकार और न्यायिक प्रशासन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

5. (C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 50 निर्धारित की गई है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। भारतीय संविधान के तहत किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित रूप से तय नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार, राष्ट्रपति समय-समय पर कार्यभार की आवश्यकता को देखते हुए उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित और परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए संसद या संविधान द्वारा इसकी कोई स्थिर सीमा तय नहीं की जाती है।

6. (A) राजस्थान के राज्यपाल
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेना अनिवार्य होता है। यह संवैधानिक प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान के प्रति निष्ठा सुनिश्चित करती है। यद्यपि न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु शपथ दिलाने का कार्य राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल द्वारा संपन्न किया जाता है।

7. (B) 62 वर्ष
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष निर्धारित है। मूल संविधान में यह आयु सीमा 60 वर्ष थी, जिसे 15वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1963 द्वारा बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। न्यायाधीश सेवानिवृत्ति से पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं या संसद द्वारा सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाए जा सकते हैं। इसके विपरीत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है।

8. (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थित है। राज्यों के पुनर्गठन और एकीकरण के समय गठित बी.आर. पटेल समिति ने सिफारिश की थी कि जयपुर को राज्य की प्रशासनिक राजधानी बनाया जाए, जबकि उच्च न्यायालय की स्थापना जोधपुर में की जाए। इस सिफारिश का मुख्य उद्देश्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्रशासनिक और राजनीतिक संतुलन बनाए रखना था। इसी रिपोर्ट के आधार पर जोधपुर को न्यायपालिका के मुख्य केंद्र के रूप में चुना और विकसित किया गया था।

Click Here to Buy book on Amazon

अधिकार या प्राधिकार से है, जिसका प्रयोग अवैध पदधारण की जांच के लिए होता है। उत्प्रेषण का अर्थ प्रमाणित होना या सूचित किया जाना है, जो निचले न्यायालयों के रिकॉर्ड मांगने के लिए प्रयुक्त होता है।

28. (B) प्रतिषेध कार्यवाही के दौरान क्षेत्राधिकार के उल्लंघन को रोकता है, जबकि उत्प्रेषण पूर्ण हो चुके आदेशों को रद्द करता है।
प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों रिटें न्यायिक या अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती हैं, लेकिन उनके लागू होने के चरण भिन्न हैं। प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती है जब मामला निचले न्यायालय में लंबित हो और उसे अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करने से रोकना हो। इसके विपरीत उत्प्रेषण रिट तब जारी की जाती है जब निचला न्यायालय आदेश पारित कर चुका हो, ताकि उस अवैध आदेश को रद्द किया जा सके और मामले को स्वयं या वरिष्ठ न्यायालय स्थानांतरित किया जा सके।

29. (D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
परमादेश रिट केवल सार्वजनिक कर्तव्य का पालन न करने वाले सरकारी प्राधिकारियों, संवैधानिक निकायों या लोक अधिकारियों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। इसे किसी विशुद्ध रूप से निजी व्यक्ति या निजी कंपनी के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों और शक्तियों के प्रयोग के लिए परमादेश रिट की न्यायिक प्रक्रिया से पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त होती है।

30. (A) जिला एवं सत्र न्यायालय
जिला स्तर पर सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होता है। जब यह न्यायालय सिविल विवादों की सुनवाई करता है तो इसे जिला न्यायालय कहा जाता है और इसके प्रमुख को जिला न्यायाधीश कहते हैं। जब यह आपराधिक मुकदमों का विचारण करता है तो इसे सत्र न्यायालय कहा जाता है और प्रमुख को सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। यह जिला स्तर की संपूर्ण अधीनस्थ न्यायपालिका पर प्रशासनिक और न्यायिक अधीक्षण रखता है।

31. (B) 7 वर्ष
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके पास कम से कम 7 वर्षों का वकील या अधिवक्ता के रूप में निरंतर कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। साथ ही उसकी सिफारिश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पहले से संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में है, तो उसके लिए अनुभव की यह शर्त भिन्न प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होती है।

32. (D) केवल I, II और IV
जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त राज्य की अन्य न्यायिक सेवाओं में अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। जिला न्यायाधीश को सिविल मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं। हालाँकि, जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार में नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत पूरी तरह से राज्य के उच्च न्यायालय में निहित होता है, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।

NODIA

33. (C) उप-खंड मजिस्ट्रेट
उप-खंड मजिस्ट्रेट (एसडीएम) एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है जो राज्य की प्रशासनिक सेवा का हिस्सा होता है और कानून व्यवस्था तथा राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्य संभालता है। इसके विपरीत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर सत्र न्यायाधीश राज्य की स्वतंत्र न्यायिक सेवा के सदस्य होते हैं, जो केवल न्यायिक कार्यों और आपराधिक विचारण का संचालन करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण के अनुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट न्यायिक पदानुक्रम से अलग होते हैं।

34. (B) 7 वर्ष
दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कानून द्वारा अधिकृत कोई भी ऐसा सजा सुना सकता है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक अवधि के कारावास की न हो। इस प्रकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने की सजा देने के लिए सक्षम होता है। सात वर्ष से अधिक की सजा सुनाने की शक्ति केवल सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश के पास ही सुरक्षित होती है।

35. (A) सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला स्तर पर आपराधिक न्याय प्रणाली का पदानुक्रम सर्वोच्च स्तर पर सत्र न्यायालय से प्रारंभ होता है, जिसे मृत्युदंड सहित विधि द्वारा निर्धारित कोई भी सजा देने का अधिकार है। इसके पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय आता है जो सात वर्ष तक की सजा दे सकता है। इसके नीचे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थान होता है जो तीन वर्ष तक की सजा सुना सकता है। सबसे निचले स्तर पर द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है जो एक वर्ष तक की सजा दे सकता है।

36. (A) सत्र न्यायाधीश उच्च न्यायालय की पुष्टि के बिना मृत्युदंड की सजा को निष्पादित कर सकता है।
जिला स्तर पर एक ही न्यायिक अधिकारी सिविल मामलों की सुनवाई करते समय जिला न्यायाधीश और आपराधिक मामलों की सुनवाई करते समय सत्र न्यायाधीश कहलाता है। सत्र न्यायाधीश को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी सजा देने का अधिकार है, जिसमें मृत्युदंड भी शामिल है। हालाँकि, दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए

118. मामलों के बकाए को कम करने के लिए पूरे राजस्थान में निरंतर मेगा लोक अदालतों और मोबाइल लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए कौन-सी संस्था उत्तरदायी है?
(A) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
(B) राज्य राजस्थान लोक सेवा आयोग निकाय
(C) राजस्थान राज्य की आधिकारिक बार काउंसिल
(D) राज्य राजस्थान पुलिस विभाग एजेंसी

119. राजस्थान में न्यायिक प्रशासन के संदर्भ में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले क्षेत्रीय प्रभाग के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है?
(A) प्रशासनिक राजस्व जिला
(B) महानगरीय पुलिस कमिश्नरेट
(C) नामित न्यायिक पंचायत
(D) न्यायमंडल

120. राजस्थान के कुछ हिस्सों में 'संध्याकालीन न्यायालयों' की स्थापना के पीछे सबसे उपयुक्त उद्देश्य चुनिए।
(A) शाम के गैर-कार्य घंटों के दौरान न्यायिक जागरूकता और सार्वजनिक मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन करना।
(B) कामकाजी नागरिकों के लिए छोटे अपराधों और ट्रैफिक चालानों का निपटारा करना।
(C) विशेष रूप से हाई-प्रोफाइल संवैधानिक मामलों और अति-आवश्यक जनहित याचिकाओं की सुनवाई करना।
(D) अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों को कई द्वितीयक रोजगार पद धारण करने में सक्षम बनाना।

121. भारत के संविधान के अनुसार किसी उच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीशों की अनुमति है?
(A) वैधानिक कानून द्वारा प्रति राज्य उच्च न्यायालय में सख्ती से 30 न्यायाधीशों तक सीमित।
(B) सभी राज्य उच्च न्यायालयों में अधिकतम 50 न्यायाधीशों की सीमा निर्धारित है।
(C) भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार 100 न्यायाधीशों तक सीमित।
(D) संविधान द्वारा अनिश्चित; कार्यभार के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित।

122. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: यदि राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है और कोई अन्य व्यवस्था नहीं की जाती है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकते हैं।
कथन II: आपातकाल की स्थिति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश स्वतः ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में, सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

123. क्या उच्च न्यायालय के पास उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 143 के समान 'परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार' है?
(A) नहीं, संविधान के तहत उच्च न्यायालयों के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का अभाव है।
(B) हाँ, उच्च न्यायालय के पास कानूनी मामलों पर राज्यपाल को सलाह देने की वैधानिक शक्ति है।
(C) हाँ, उच्च न्यायालय नीति पर मुख्यमंत्री के लिए प्राथमिक परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करता है।
(D) हाँ, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की अनुमति है लेकिन यह केवल मौलिक अधिकारों के मामलों तक ही सीमित है।

124. जोधपुर में स्थित पुरानी राजस्थान उच्च न्यायालय इमारत के डिजाइन को निम्नलिखित में से कौन-सी वास्तुकला शैली अत्यधिक प्रभावित करती है?
(A) आधुनिकतावादी कांच और स्टील स्थापत्य डिजाइन
(B) इंडो-सारसेनिक और राजपूत
(C) विक्टोरियन गॉथिक स्थापत्य शैली की संरचना
(D) शास्त्रीय रोमन और न्यू-ग्रेशियन वास्तुकला

125. निम्नलिखित में से किसने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने?
(A) न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता
(B) न्यायमूर्ति के.एन. वांचू
(C) न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा
(D) न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर

126. परमादेश रिट के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(A) यह किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को उसके अनिवार्य सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य कर सकती है।
(B) इसे किसी विधानमंडल को विशेष कानून पारित करने के लिए बाध्य करने हेतु जारी किया जा सकता है।
(C) इसे भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है।
(D) यह एक स्वचालित अधिकार है और न्यायालय के पास इसे देने से मना करने का कोई विवेक नहीं है।

127. अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय को उसके कर्मचारियों पर नियंत्रण प्रदान करके उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार, उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कौन करता है?
(A) कार्यपालिक परीक्षाओं के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग
(B) परिषद की सलाह पर कार्य करने वाले राज्य के राज्यपाल
(C) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनका मनोनीत व्यक्ति
(D) वैधानिक अधिनियमों के माध्यम से राज्य विधानसभा

Downloaded from www.pdf.tube

46. (A) P-2, Q-3, R-4, S-1
वैकल्पिक विवाद समाधान के विभिन्न रूप हैं। मध्यस्थता में तटस्थ तीसरा पक्ष साक्ष्य के आधार पर बाध्यकारी पंचाट देता है। सुलह में मध्यस्थ स्वयं समाधान के प्रस्तावों का सुझाव देता है। मध्यस्थता समझौते में मध्यस्थ बिना किसी निर्णय के केवल पक्षों के बीच संवाद सुगम बनाता है। लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत एक वैधानिक मंच है जो सिविल व शमनीय मामलों में सौहार्दपूर्ण समझौता और त्वरित निस्तारण कराने का कार्य करता है।

47. (A) 1987
भारतीय संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में अधिनियमित किया गया था, जिसे पूरे देश में 9 नवंबर 1995 को लागू किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर, गरीब और वंचित वर्गों को मुफ्त तथा सक्षम कानूनी सहायता प्रदान करना है। इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन किया गया तथा लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा और शक्तियाँ प्रदान की गईं।

48. (C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22B के अंतर्गत परिवहन, डाक, बिजली, जल आपूर्ति और स्वच्छता जैसी जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए स्थायी लोक अदालतों का गठन किया जाता है। यदि पक्षकार सुलह प्रक्रिया के माध्यम से किसी समझौते पर पहुँचने में विफल रहते हैं, तो स्थायी लोक अदालत को मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है, जो सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है।

49. (C) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक के रूप में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं। यह व्यवस्था कानूनी सहायता संरचना में न्यायपालिका के सर्वोच्च मार्गदर्शन को सुनिश्चित करती है। मुख्य संरक्षक के रूप में वे राज्य में मुफ्त कानूनी सहायता योजनाओं के क्रियान्वयन, लोक अदालतों के आयोजन और न्यायिक साक्षरता अभियानों की दिशा तय करते हैं। उनकी अध्यक्षता में यह संस्था निर्धन और कमजोर वर्गों को सुलभ न्याय दिलाने का कार्य करती है।

50. (B) राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। यह मनोनयन राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से संपन्न होता है। कार्यकारी अध्यक्ष प्राधिकरण के दैनिक प्रशासनिक कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के पर्यवेक्षण और राज्य भर में मुफ्त कानूनी सेवाओं के प्रभावी संचालन का नेतृत्व करते हैं ताकि सुलभ न्याय सुनिश्चित हो सके।

51. (B) अनुच्छेद 39A
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और उपयुक्त विधान या योजनाओं द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करे। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नागरिक आर्थिक अक्षमता या अन्य किसी निर्योग्यता के कारण न्याय पाने से वंचित न रहे।

52. (A) केवल I, II और III
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, महिलाएं, बच्चे और औद्योगिक कर्मकार आय की सीमा के बिना निःशुल्क विधिक सेवाओं के पात्र होते हैं। इनके अतिरिक्त हिरासत में बंद व्यक्ति और दिव्यांग जन भी पात्र हैं। हालाँकि, सामान्य वर्ग के पुरुषों या सभी नागरिकों के लिए आय की सीमा तय की गई है। अतः केवल नागरिक होना निःशुल्क विधिक सहायता की असीमित पात्रता की गारंटी नहीं देता है।

53. (C) जिला न्यायाधीश
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जिले में गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के अध्यक्ष के रूप में संबंधित जिले के जिला न्यायाधीश कार्य करते हैं। वे जिला स्तर पर कानूनी जागरूकता शिविरों, लोक अदालतों के आयोजन तथा पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी वकील और सहायता उपलब्ध कराने का प्रबंधन करते हैं। जिला न्यायाधीश का नेतृत्व यह सुनिश्चित करता है कि जिले में न्यायिक सहायता कार्यक्रम पारदर्शी और प्रभावी ढंग से संचालित हों।

NODIA

54. (A) राज्य के आपराधिक मामलों के लिए सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एक वैधानिक प्रशासनिक निकाय है, जो समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है और लोक अदालतों का संचालन करता है। यह कोई अपीलीय न्यायालय नहीं है; राज्य में आपराधिक मामलों के लिए सर्वोच्च अपीलीय निकाय राजस्थान उच्च न्यायालय है। विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य कार्य कानूनी साक्षरता फैलाना, मध्यस्थता को बढ़ावा देना तथा निर्धन नागरिकों के लिए न्याय की पहुँच को सुलभ और सरल बनाना है।

55. (D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
राजस्थान में सामान्य आय मानदंडों के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय की सीमा निश्चित रूप से निर्धारित की गई है, जो 3,00,000 रुपये से अधिक वाले व्यक्तियों को सामान्यतः पात्र नहीं मानती। दूसरी ओर, प्राकृतिक आपदाओं, जातीय हिंसा, बड़े पैमाने की विभीषिकाओं या मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए आय की कोई सीमा लागू नहीं होती है। ऐसे पीड़ित अपनी वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना कानूनी सहायता पाने के पूर्ण हकदार होते हैं।

जाता है। यदि हिरासत गैर-कानूनी पाई जाती है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश देता है।

19. (D) सत्र न्यायालय द्वारा दी गई मृत्युदंड की सजा के लिए उच्च न्यायालय की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है।
उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय होता है, जो अधीनस्थ सिविल और आपराधिक न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार जब कोई सत्र न्यायालय किसी अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा सुनाता है, तो उस सजा को तब तक निष्पादित नहीं किया जा सकता जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि न कर दी जाए। उच्च न्यायालय मामले के समस्त साक्ष्यों की पुनः समीक्षा करने के पश्चात ही पुष्टि प्रदान करता है।

20. (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार की तुलना में विस्तृत है। उच्चतम न्यायालय केवल भाग 3 में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है। इसके विपरीत उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, बल्कि सामान्य वैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार कार्यक्षेत्र की व्यापकता की दृष्टि से उच्च न्यायालय की शक्ति अधिक विस्तृत मानी जाती है।

21. (C) प्रतिषेध
प्रतिषेध रिट का शाब्दिक अर्थ रोकना या मना करना होता है। यह रिट किसी उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक अधिकरणों को तब जारी की जाती है जब वे अपने संवैधानिक या वैधानिक क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर रहे हों। इसका मुख्य उद्देश्य निचले न्यायालयों को अपनी सीमाओं से बाहर जाने से रोकना होता है। यह केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, तथा प्रशासनिक अधिकारियों या निजी व्यक्तियों के विरुद्ध इसे जारी नहीं किया जा सकता है।

22. (A) इसमें क्षेत्रीय न्यायालयों और अधिकरणों पर प्रशासनिक और न्यायिक अधीक्षण शामिल है।
संविधान का अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों पर पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। इस शक्ति में प्रशासनिक नियंत्रण के साथ-साथ न्यायिक अधीक्षण भी शामिल है। उच्च न्यायालय निचले न्यायालयों से विवरण मांग सकता है, कार्यपद्धति के नियम बना सकता है और उनके फैसलों में न्याय की विफलता होने पर सुधार कर सकता है। हालांकि, सशस्त्र बलों से संबंधित कानूनों के तहत गठित सैन्य न्यायालय इसके दायरे से बाहर हैं।

23. (D) पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार - निचले न्यायालयों और अधिकरणों पर नियंत्रण
उच्च न्यायालयों के पास विविध प्रकार के क्षेत्राधिकार होते हैं। पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों की कार्यप्रणाली पर प्रशासनिक और न्यायिक नियंत्रण रखता है। मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ प्रथम दृष्टया मुकदमों की सुनवाई करना है, जबकि अपीलीय क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों को चुनौती देने पर लागू होता है। उच्च न्यायालय के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार नहीं होता, क्योंकि यह केवल भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है।

24. (B) केवल II और III
अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार एक संवैधानिक शक्ति है, परंतु यह स्वयं में मौलिक अधिकार नहीं है जैसा कि अनुच्छेद 32 है। यह उच्च न्यायालय को अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर व्यक्तियों और अधिकारियों को आदेश या रिट जारी करने का अधिकार देता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, जिससे रिट याचिकाओं का दायरा भी प्रभावित होता है।

25. (C) अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को राहत देने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है।
अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जाना स्वयं में एक मौलिक अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों की गारंटी के कारण उच्चतम न्यायालय राहत देने से इनकार नहीं कर सकता। इसके विपरीत अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय परिस्थिति के अनुसार रिट जारी करने या याचिकाकर्ता को किसी अन्य वैकल्पिक कानूनी तंत्र का उपयोग करने का सुझाव दे सकता है। इसलिए यह संवैधानिक उपचार प्राप्त करने का एक विवेकाधीन अधिकार माना जाता है।

26. (D) कोटा
राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी जिले आते हैं, जिनमें कोटा शामिल है। इसके अतिरिक्त भरतपुर, अलवर, अजमेर, दौसा, सवाई माधोपुर जैसे जिले भी जयपुर पीठ के प्रशासनिक और न्यायिक दायरे में सम्मिलित हैं। दूसरी ओर पश्चिमी और उत्तरी जिले जैसे जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर मुख्य पीठ जोधपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। यह प्रशासनिक विभाजन राज्य में न्यायिक कार्यों के सुचारु संचालन हेतु किया गया है।

27. (A) P-4, Q-3, R-1, S-2
रिटों के शाब्दिक अर्थ उनके विधिक स्वरूप को दर्शाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ शरीर को प्रस्तुत किया जाए होता है, जिसका उपयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किया जाता है। परमादेश का अर्थ हम आदेश देते हैं है, जो सार्वजनिक कर्तव्य पालन हेतु जारी होता है। अधिकार-पृच्छा का अर्थ किस

Click Here to Buy book on Flipkart

भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा पूरी की जाती है, जिसमें संबंधित दोनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के विचार भी अनिवार्य रूप से शामिल किए जाते हैं।

66. (C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय को एक असाधारण अपीलीय शक्ति प्रदान करता है, जिसके तहत वह भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) स्वीकार कर सकता है। हालाँकि, उच्च न्यायालय प्रशासनिक रूप से उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ नहीं हैं। उच्च न्यायालय अपनी प्रशासनिक स्वायत्तता, शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार सीधे संविधान से प्राप्त करते हैं, न कि उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक निर्देशों से।

67. (B) अनुच्छेद 132
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 132 उच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि यदि किसी मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई सारवान प्रश्न निहित है, तो वह उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। यह प्रमाण पत्र सिविल, आपराधिक या अन्य कार्यवाहियों में दिया जा सकता है। इसके आधार पर पक्षकार उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं, जिससे संवैधानिक प्रावधानों की अंतिम और सर्वमान्य व्याख्या शीर्ष अदालत द्वारा सुनिश्चित की जा सके।

68. (A) उच्चतम न्यायालय सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखता है।
उच्चतम न्यायालय भारत की शीर्ष अदालत है और उसके द्वारा घोषित कानून संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सभी उच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई भी उच्चतम न्यायालय करता है। हालाँकि, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट नहीं लिखता है। उच्च न्यायालय एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और उसके न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक कर्मचारी या subordinate नहीं होते हैं।

69. (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
भारत में एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली है जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय स्थित है, परंतु राज्य का उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का अधीनस्थ प्रशासनिक निकाय नहीं है। संविधान के भाग 6 के तहत उच्च न्यायालय अपनी प्रशासनिक स्वायत्तता, शक्तियाँ और पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार सीधे संविधान से प्राप्त करते हैं। उच्चतम न्यायालय अपीलीय और संवैधानिक मामलों में वरिष्ठ है, लेकिन उच्च न्यायालय के दैनिक प्रशासनिक संचालन में उसका सीधा हस्तक्षेप या प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता है।

70. (A) अनुच्छेद 215 - अभिलेख न्यायालय
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को 'अभिलेख न्यायालय' का दर्जा प्रदान करता है। इसके तहत उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियों और निर्णयों को स्थायी साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाता है तथा इसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त होती है। अन्य अनुच्छेदों में अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से, अनुच्छेद 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति से तथा अनुच्छेद 228 कुछ मामलों के स्थानांतरण से संबंधित है।

71. (D) निचले न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण करना और ऑनलाइन न्यायिक सेवाएं प्रदान करना।
ई-न्यायालय राष्ट्रीय मिशन परियोजना की शुरुआत भारतीय न्याय प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और सुलभ बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसका प्राथमिक लक्ष्य देश के सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण करना है। इसके माध्यम से वादियों और अधिवक्ताओं को मामलों की स्थिति, आदेशों की प्रतियां, ई-फाइलिंग और ऑनलाइन अदालती सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यह पहल कागजी कार्रवाई को कम करने और अदालती प्रक्रियाओं में लगने वाले समय की बचत करने में सहायक सिद्ध हुई है।

72. (B) केवल I, II और III
राजस्थान में न्यायपालिका के डिजिटलीकरण के तहत राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड का उपयोग लंबित मामलों की निगरानी के लिए किया जाता है। ट्रैफिक उल्लंघनों के लिए ई-चालान और आभासी अदालतें स्थापित की गई हैं तथा कैदियों और गवाहों की गवाही के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग हो रहा है। हालाँकि, डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग प्रतिबंधित नहीं है, बल्कि अदालती प्रक्रियाओं और आदेशों की प्रतियों को प्रमाणित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षरों को व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है।

73. (C) अदालती लंबितता और देरी की निगरानी के लिए मामलों का एक डेटाबेस तैयार करना।
राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) ई-न्यायालय परियोजना के तहत निर्मित एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर के उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित तथा निपटाए गए मुकदमों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना है। यह प्रणाली न्यायिक अधिकारियों और नीति निर्धारकों को अदालती लंबितता, मुकदमों में देरी के कारणों की पहचान करने और न्यायिक प्रबंधन में सुधार के लिए प्रभावी रणनीति बनाने में मदद करती है।

74. (C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्याय प्रणाली में दक्षता लाने, समय बचाने और कागजी कार्रवाई कम करने के उद्देश्य से मुकदमों की ई-फाइलिंग व्यवस्था शुरू की है। इसके माध्यम से अधिवक्ता और वादी अपने दस्तावेज डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं। हालाँकि, ई-फाइलिंग का अर्थ अदालती शुल्क की समाप्ति नहीं है। वादियों को निर्धारित कोर्ट फीस का भुगतान

Downloaded from www.pdf.tube

ई-कोर्ट फीस प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से करना अनिवार्य होता है।

75. (A) न्यायिक रिक्तियां, प्रक्रियात्मक देरी और स्थगन।
राजस्थान उच्च न्यायालय और भारतीय अदालतों में मुकदमों की अत्यधिक लंबितता का मुख्य कारण स्वीकृत पदों की तुलना में न्यायाधीशों की बड़ी संख्या में रिक्तियां होना है। इसके अतिरिक्त जटिल और पुरानी प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं, वकीलों द्वारा बार-बार स्थगन मांगना और बुनियादी ढांचे की कमी इस समस्या को और गंभीर बनाती हैं। जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में न्यायिक जनशक्ति का न बढ़ना भी न्याय में होने वाली देरी के लिए एक प्रमुख कारक सिद्ध हुआ है।

76. (B) जनहित याचिकाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना।
राजस्थान में मुकदमों के बकाए को निपटाने के लिए अनेक सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, जिनमें मेगा लोक अदालतों का आयोजन, त्वरित निस्तारण हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना और दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दण्ड सौदेबाजी को बढ़ावा देना शामिल है। जनहित याचिकाएं नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक माध्यम हैं, इसलिए इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना न तो व्यावहारिक है और न ही इसे लंबितता कम करने की पहल के रूप में अपनाया गया है।

77. (B) झालामंड, जोधपुर
राजस्थान उच्च न्यायालय का नवनिर्मित, अत्याधुनिक और विशाल भवन जोधपुर शहर के झालामंड क्षेत्र में स्थित है। इस नए परिसर का निर्माण आधुनिक आवश्यकताओं, बढ़ते कार्यभार और वकीलों तथा वादियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें आधुनिक अदालत कक्ष, डिजिटल सुविधाएं और पर्यावरण-अनुकूल बुनियादी ढांचा शामिल है। यह भवन राजस्थान की समृद्ध वास्तुकला और आधुनिक न्यायिक तकनीक का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है।

78. (A) राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द
जोधपुर के झालामंड में निर्मित राजस्थान उच्च न्यायालय के नए भवन का औपचारिक उद्घाटन 7 दिसंबर 2019 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द द्वारा किया गया था। इस भव्य समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। यह नया परिसर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है।

79. (C) केवल I और II
राजस्थान में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना मुख्य रूप से बलात्कार और पोक्सो अधिनियम से जुड़े जघन्य अपराधों के त्वरित विचारण हेतु की गई है। ये न्यायालय केंद्र प्रायोजित योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित होते हैं। ये न्यायालय मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाते हैं, परंतु वे प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों का पूरी तरह पालन करते हैं और अभियुक्तों को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान करते हैं।

80. (D) बस्सी (जयपुर)
ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को उनके द्वार पर सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संसद द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 पारित किया गया था। इस कानून के क्रियान्वयन के अंतर्गत वर्ष 2010 में राजस्थान के पहले ग्राम न्यायालय की स्थापना जयपुर जिले के बस्सी में की गई थी। यह न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायाधिकारी द्वारा संचालित होता है और स्थानीय सिविल तथा छोटे आपराधिक विवादों का निस्तारण करता है।

81. (C) 11वां वित्त आयोग
भारत में फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की सिफारिश सर्वप्रथम 11वें वित्त आयोग द्वारा की गई थी। आयोग ने देश की अदालतों में लंबित मुकदमों के भारी बकाए, विशेष रूप से लंबे समय से जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए वित्तीय अनुदान देने का प्रस्ताव रखा था। इसके पश्चात वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने राज्यों के सहयोग से त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन शुरु किया था।

82. (B) केवल I, II और III
राजस्थान में विशेष न्यायालयों का गठन विशिष्ट कानूनों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 और एनडीपीएस अधिनियम के तहत त्वरित सुनवाई के लिए किया गया है। इन विशेष न्यायालयों के फैसलों को दरकिनार करके सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं होती; बल्कि कानून के अनुसार इनके आदेशों के विरुद्ध पहली अपील संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में ही दायर की जाती है, जो नियमित अपीलीय व्यवस्था का हिस्सा है।

83. (D) स्थावर संपदा (रेरा) अपीलीय अधिकरण
राजस्थान में रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने, भवन निर्माताओं की जवाबदेही तय करने और घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए स्थावर संपदा (रेरा) अपीलीय अधिकरण का गठन किया गया है। यह विशेष अधिकरण रियल एस्टेट विनियमन प्राधिकरण (रेरा) के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। यह घर खरीदारों और डेवलपर्स के बीच संपत्ति के कब्जे में देरी या अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न विवादों का शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करता है।

NODIA

84. (A) जनहित याचिका में 'सुनवाई के अधिकार' का पारंपरिक नियम सख्ती से लागू होता है।
जनहित याचिका (पीआईएल) भारतीय न्यायिक प्रणाली में न्यायिक सक्रियता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें 'सुनवाई के अधिकार' के पारंपरिक कठोर नियम को शिथिल कर दिया गया है, ताकि कोई भी जनहित से प्रेरित व्यक्ति या संस्था असहाय पीड़ितों के लिए अदालत जा सके। इसे केवल एक पत्र या पोस्टकार्ड के माध्यम से भी शुरु किया जा सकता

है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब, पीड़ित और वंचित वर्गों के मानवाधिकारों की रक्षा करना है।

85. (A) सुनवाई के अधिकार में ढील, पत्र याचिका क्षेत्राधिकार, जनहित याचिका दिशा-निर्देशों का संस्थागतीकरण, सामाजिक क्रिया याचिका
भारतीय न्यायशास्त्र में जनहित याचिका का विकास चरणबद्ध रूप से हुआ। सर्वप्रथम पीड़ित व्यक्ति ही अदालत जा सकता था, परंतु न्यायालयों ने सुनवाई के अधिकार के नियम में ढील देकर अन्य व्यक्तियों को याचिका दायर करने की अनुमति दी। इसके बाद साधारण पत्रों को याचिका मानने का पत्र याचिका क्षेत्राधिकार विकसित हुआ। कालंतर में दुरुपयोग रोकने के लिए जनहित याचिका दिशा-निर्देशों का संस्थागतीकरण हुआ और व्यापक सामाजिक बदलाव के लिए इसे सामाजिक क्रिया याचिका का रूप मिला।

86. (A) कोई भी जनहित से प्रेरित संस्था वंचित नागरिकों की ओर से याचिका दायर कर सकती है।
पारंपरिक कानून में नियम था कि केवल वही व्यक्ति अदालत जा सकता है जिसके अधिकारों का व्यक्तिगत रूप से हनन हुआ हो। जनहित याचिका के संदर्भ में इस नियम को शिथिल कर दिया गया है। इसका मूल अर्थ यह है कि यदि कोई वर्ग गरीबी, अज्ञानता या सामाजिक असफलता के कारण स्वयं न्यायालय आने में असमर्थ है, तो कोई भी जनहित से प्रेरित नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता या संस्था उनकी ओर से याचिका दायर कर सकती है।

87. (D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
जनहित याचिका का प्राथमिक उद्देश्य व्यापक जनहित और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। इसलिए इसे दो निजी व्यक्तियों या निजी कंपनियों के बीच व्यक्तिगत या व्यावसायिक विवादों को सुलझाने के लिए दायर नहीं किया जा सकता। पर्यावरण संबंधी कुछ अपवादों को छोड़कर, जनहित याचिका केवल राज्य, सरकारी विभागों या सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ ही पोषणीय होती है, जहाँ सार्वजनिक दायित्व के उल्लंघन का प्रश्न शामिल हो।

88. (B) पत्र याचिका क्षेत्राधिकार
जब उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय किसी गरीब, पीड़ित या असहाय नागरिक द्वारा भेजे गए साधारण पत्र, पोस्टकार्ड या टेलीग्राम को औपचारिक रिट याचिका के रूप में स्वीकार करके सुनवाई करता है, तो इस अधिकारिता को पत्र याचिका क्षेत्राधिकार कहा जाता है। यह जनहित याचिका का एक अनूठा और मानवीय रूप है। यह व्यवस्था प्रक्रियात्मक जटिलताओं को दरकिनार कर निर्धन नागरिकों के लिए न्याय की त्वरित और सुलभ पहुँच सुनिश्चित करने में सहायक बनती है।

89. (C) व्यक्तिगत कर्मचारियों के सेवा और पेंशन संबंधी विवाद।
उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत कर्मचारियों के सेवा, वेतन, स्थानांतरण और पेंशन संबंधी विवादों को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि इनके लिए विशिष्ट ट्रिब्यूनल उपलब्ध हैं। इसके विपरीत बंधुआ मजदूरी, मानवाधिकार उल्लंघन, सांप्रदायिक दंगा पीड़ितों की सहायता और पर्यावरण प्रदूषण जैसे व्यापक सामाजिक प्रभाव वाले मामलों को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करने के स्पष्ट प्रावधान बनाए गए हैं।

90. (D) P-3, Q-4, R-1, S-2
विभिन्न अधिकरण विशिष्ट विषयों का निपटारा करते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (केट) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा मामलों से निपटता है। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण राज्य सरकार के कर्मचारियों के सेवा विवादों की सुनवाई करता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों को देखता है। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग वस्तुओं और सेवाओं में कमी से जुड़ी उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करता है।

91. (A) राजस्थान
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित ऐतिहासिक 'विशाखा दिशा-निर्देश' राजस्थान की एक निर्भीक सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी के साथ हुए क्रूर अपराध के बाद दायर जनहित याचिका से उत्पन्न हुए थे। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1997 में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में यह निर्णय दिया था। इन दिशा-निर्देशों ने देश भर के कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु कानूनी ढांचा तैयार किया, जिससे बाद में 2013 का वैधानिक अधिनियम बना।

92. (B) इसने जैन धर्म की 'संथारा' प्रथा को अवैध घोषित किया, जिस पर बाद में उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने निखिल सोनी बनाम भारत संघ मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए जैन धर्म की प्राचीन धार्मिक प्रथा 'संथारा' या 'सल्लेखना' को आत्महत्या के समान मानते हुए अवैध घोषित कर दिया था। इस फैसले का व्यापक विरोध होने के पश्चात मामला उच्चतम न्यायालय पहुँचा। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के इस आदेश पर रोक लगा दी और इस धार्मिक प्रथा से जुड़े संवैधानिक अधिकारों पर अंतिम निर्णय हेतु याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली।

93. (B) रूप कंवर मामला
वर्ष 1987 में राजस्थान के सीकर जिले के देवराला गाँव में घटित रूप कंवर सती कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस कुख्यात घटना के विरोध में देश भर में व्यापक कानूनी और सामाजिक आंदोलन हुआ। इसके परिणामस्वरूप सरकार को सती प्रथा के महिमामंडन और रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाना पड़ा। इस आंदोलन के आधार पर संसद द्वारा सती (निवारण) आयोग अधिनियम, 1987 लागू किया गया, जिससे इस प्रथा को संज्ञेय अपराध बनाया गया।

Click Here to Buy book on Amazon

20. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रुप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): स्वतंत्रता के बाद से जिला कलेक्टर की भूमिका में महत्वपूर्ण बदलाव आया है।
कारण (R): पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत ने कई विकास कार्यों को कलेक्टर के सीधे नियंत्रण से बाहर कर दिया।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

21. राजस्थान के राजस्व प्रशासन में जिला कलेक्टर और पटवारी के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कौन सा पदाधिकारी कार्य करता है?
(A) ग्राम विकास अधिकारी
(B) उपखंड अधिकारी (एसडीओ)
(C) तहसीलदार
(D) खंड विकास अधिकारी (बीडीओ)

22. निम्नलिखित में से कौन सा जिला कलेक्टर की 'मजिस्ट्रेट संबंधी' (दंडनायक) शक्तियों को सर्वोत्तम रुप से परिभाषित करता है?
(A) भू-राजस्व वसूलना, भूमि अभिलेखों को अद्यतन करना और कृषि भूमि के आकलन का प्रबंधन करना
(B) लोक व्यवस्था बनाए रखना और निवारक निरोध कानूनों का पालन कराना
(C) विभिन्न राज्य एजेंसियों के मध्य अंतर-विभागीय विकासात्मक गतिविधियों का समन्वय करना
(D) जिले के भीतर स्थानीय नगर निकायों के चुनावों का संचालन और पर्यवेक्षण करना

23. राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) इसका गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया था।
(B) यह राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है।
(C) इसकी सिफारिशें परामर्शदायी (सलाहकारी) प्रकृति की होती हैं।
(D) यह मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सीधे दंडित कर सकता है।

24. वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए कौन पात्र है?
(A) उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश
(B) केवल उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश
(C) उच्चतम न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश
(D) मानव अधिकारों के क्षेत्र में 10 वर्षों के अनुभव वाला एक प्रख्यात समाजसेवी

25. सूची I के निकायों को सूची II में दिए गए उनके संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: निकाय
P. अध्यक्ष, आरपीएससी
Q. लोकायुक्त
R. राज्य निर्वाचन आयुक्त
S. जिला कलेक्टर
सूची II: नियुक्ति प्राधिकारी
1. मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली समिति की सलाह पर राज्यपाल
2. राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यपाल
3. विपक्ष के नेता और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने वाली मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली समिति की सलाह पर राज्यपाल
4. राज्य सरकार (कार्मिक विभाग)
(A) P-2, Q-3, R-2, S-4
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-1, R-3, S-4
(D) P-3, Q-1, R-2, S-4

26. राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें शामिल हैं:
(A) मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष (विपक्ष के नेता)
(B) मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल
(C) मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्य सचिव
(D) राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष

NODIA

27. राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए वर्तमान में निर्धारित पदावधि क्या है?
(A) 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो
(B) 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो
(C) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो
(D) 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो

28. राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
(A) न्यायमूर्ति एन. के. जैन

104. (B) राज्य की संचित निधि वेतन देती है, जबकि संघ की निधि पेंशन देती है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वित्तीय प्रावधानों के संबंध में संविधान में एक विशिष्ट व्यवस्था बनाई गई है। कार्यरत न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिस पर राज्य विधानमंडल में मतदान नहीं होता। हालाँकि, सेवानिवृत्ति के पश्चात न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि कई न्यायाधीश अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित होते हैं।

105. (C) केवल I और III
संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके निर्णय और कार्यवाहियां स्थायी साक्ष्य के रूप में दर्ज की जाती हैं और उनकी प्रामाणिकता पर किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसके अतिरिक्त अभिलेख न्यायालय होने के नाते उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना करने वाले व्यक्ति को दंडित करने की निहित संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, जिसमें कारावास और जुर्माना दोनों प्रकार की सजाएं शामिल हो सकती हैं।

106. (D) किसी निजी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी में निजी प्रबंधकीय पद धारण करने वाला व्यक्ति
अधिकार-पृच्छा रिट का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति किस कानूनी प्राधिकार से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन है। यह रिट केवल उन सार्वजनिक या संवैधानिक पदों के विरुद्ध जारी की जा सकती है जो कानून या संविधान द्वारा सृजित हैं। इसे किसी निजी कंपनी, निजी फर्म या गैर-वैधानिक संस्था के निजी प्रबंधकीय पद पर कार्य कर रहे व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे पद सार्वजनिक दायित्व के दायरे में नहीं आते हैं।

107. (A) न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971
भारत में अदालतों की गरिमा बनाए रखने और न्यायिक आदेशों की अवहेलना को रोकने के लिए 'न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971' लागू है। यह अधिनियम सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। इसमें अवमानना की कार्यवाही चलाने, बचाव के आधारों और दी जाने वाली सजा की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के साथ मिलकर यह कानून न्यायपालिका के सम्मान और अधिकारों का संरक्षण करता है।

108. (B) सिविल अवमानना आदेश की अवज्ञा है, जबकि आपराधिक अवमानना अदालत की गरिमा को ठेस पहुँचाना है।
न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के अनुसार सिविल अवमानना का अर्थ किसी अदालत के निर्णय, डिक्री, आदेश या निर्देश की जानबूझकर की गई अवज्ञा या उल्लंघन है। इसके विपरीत आपराधिक अवमानना में ऐसे किसी भी कार्य या प्रकाशन को शामिल किया जाता है जो अदालत की गरिमा को ठेस पहुँचाता हो, उसके अधिकार को कम करता हो, या न्यायिक कार्यवाही के निष्पक्ष संचालन में बाधा उत्पन्न करता हो। दोनों अवमाननाओं के लिए सजा के प्रावधान मौजूद हैं।

109. (B) बी.आर. पटेल समिति
राजस्थान की पूर्व रियासतों के एकीकरण के समय प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बंटवारे हेतु बी.आर. पटेल समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने सिफारिश की थी कि जयपुर को राज्य की प्रशासनिक राजधानी बनाया जाए, जबकि उच्च न्यायालय की स्थापना जोधपुर में की जाए। इस सिफारिश का मुख्य उद्देश्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना था। इसी समिति के सुझावों के आधार पर 1949 में उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थापित हुआ।

110. (D) उपर्युक्त सभी
संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर पूर्ण प्रशासनिक अधीक्षण प्राप्त है। इस शक्ति के अंतर्गत उच्च न्यायालय निचले न्यायालयों से मुकदमों का विवरण मांग सकता है, उनकी कार्यपद्धति को विनियमित करने के लिए सामान्य नियम बना सकता है तथा बही और खातों को बनाए रखने के लिए प्रारूप निर्धारित कर सकता है। यह नियंत्रण अधीनस्थ न्यायपालिका की कार्यकुशलता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।

111. (C) न्याय पंचायतें
आधुनिक ग्राम न्यायालयों और पंचायती राज अधिनियमों के लागू होने से पूर्व राजस्थान में ग्राम स्तर पर छोटे सिविल और आपराधिक मुकदमों को निपटाने के लिए 'न्याय पंचायतों' का गठन किया गया था। ये निकाय स्थानीय स्तर पर छोटे-मोटे विवादों, चोरी, भूमि सीमा विवादों और आपसी झगड़ों का निपटारा करते थे। इनका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को गांव में ही त्वरित और सस्ता न्याय उपलब्ध कराना था, जिससे नियमित जिला न्यायालयों पर मुकदमों का भार न बढ़े।

112. (D) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट
ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत प्रत्येक ग्राम न्यायालय की अध्यक्षता एक न्यायाधिकारी द्वारा की जाती है। कानून के अनुसार न्यायाधिकारी की योग्यता, वेतन और शर्तें वही होती हैं जो राज्य न्यायिक सेवा में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की होती हैं। न्यायाधिकारी की नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। यह अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर मोबाइल कोर्ट के रूप में भी मुकदमों का निस्तारण करने में सक्षम होता है।

113. (C) यह विवाद सुलह के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं और मध्यस्थों को शामिल कर सकता है।
ग्राम न्यायालयों की प्रक्रिया को अनौपचारिक और सुलह-उन्मुख बनाया गया है। ये न्यायालय विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं, परामर्शदाताओं और मध्यस्थों की सहायता ले सकते हैं। इनमें अधिवक्ताओं की उपस्थिति पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, परंतु प्राथमिक बल पक्षों के बीच समझौते पर दिया जाता है। यह लचीली प्रक्रिया ग्रामीणों को बिना जटिल अदालती औपचारिकता के सुलभ और त्वरित न्याय प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है।

Downloaded from www.pdf.tube

अध्याय 16

राजस्थान के राज्य निगरानी एवं वैधानिक निकाय

1. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है?
(A) अनुच्छेद 312
(B) अनुच्छेद 315
(C) अनुच्छेद 320
(D) अनुच्छेद 323

2. राजस्थान लोक सेवा आयोग की वर्तमान में स्वीकृत सदस्य संख्या (संरचना) क्या है?
(A) एक अध्यक्ष और पांच सदस्य
(B) एक अध्यक्ष और छह सदस्य
(C) एक अध्यक्ष और सात सदस्य
(D) एक अध्यक्ष और आठ सदस्य

3. राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
(A) एस. सी. त्रिपाठी
(B) डी. एस. तिवारी
(C) एस. के. घोष
(D) एम. एम. वर्मा

4. राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) कोई सदस्य अपना पद ग्रहण करने की तिथि से छह वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है।
(B) कोई सदस्य 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण कर सकता है।
(C) कोई सदस्य राज्य के राज्यपाल को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकता है।
(D) किसी सदस्य को कदाचार के आधार पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

5. निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्राथमिक कार्य नहीं है?
(A) राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करना
(B) सिविल सेवाओं में भर्ती की पद्धतियों से संबंधित विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना
(C) चयनित उम्मीदवारों की अंतिम नियुक्ति करना और उन्हें कार्यग्रहण पत्र जारी करना
(D) राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना

NODIA

6. राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पृष्ठभूमि के संबंध में संवैधानिक आवश्यकता क्या है?
(A) सभी सदस्यों के पास कम से कम दस वर्षों का प्रशासनिक सिविल सेवा अनुभव होना आवश्यक है।
(B) कम से कम आधे सदस्यों को दस वर्षों का सरकारी सेवा का अनुभव होना चाहिए।
(C) सभी सदस्यों को प्रख्यात विधि विशेषज्ञ या प्रमुख विश्वविद्यालय का शिक्षाविद होना चाहिए।
(D) किसी भी सदस्य के लिए कोई विशिष्ट संवैधानिक योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई हैं।

7. राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. आरपीएससी के व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।
II. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
III. आरपीएससी का कोई सदस्य दूसरे कार्यकाल के लिए उसी पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

8. राजस्थान लोक सेवा आयोग को किस वर्ष जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया था?
(A) 1949
(B) 1956
(C) 1961
(D) 1973

9. राजस्थान में राज्य सेवा अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षाओं का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है?
(A) कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार
(B) राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
(C) राजस्थान लोक सेवा आयोग
(D) संबंधित प्रशासनिक विभाग

10. राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की परामर्शदायी भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राज्य सरकार को सिविल सेवाओं में भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर आरपीएससी से परामर्श

औपचारिक परामर्शदात्री राय देने के लिए संवैधानिक रूप से अधिकृत नहीं हैं।

124. (B) इंडो-सारसेनिक और राजपूत
जोधपुर में स्थित पुरानी राजस्थान उच्च न्यायालय की ऐतिहासिक इमारत अपनी भव्य स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। इस इमारत का डिज़ाइन इंडो-सारसेनिक और पारंपरिक राजपूत वास्तुकला शैली का एक सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करता है। इसमें मेहराब, विस्तृत गुंबद, अलंकृत झरोखे और नक्काशीदार पत्थर के काम शामिल हैं, जो राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। यह स्थापत्य शैली राजपूताना के तत्कालीन भव्य राजकीय भवनों की पहचान रही है।

125. (B) न्यायमूर्ति के.एन. वांचू
न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचू (के.एन. वांचू) ने वर्ष 1951 से 1958 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। वे इस पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीशों में से एक थे। बाद में उन्हें उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत किया गया, जहाँ वे वर्ष 1967 में भारत के 10वें मुख्य न्यायाधीश बने। उन्होंने भारत की न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

126. (A) यह किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को उसके अनिवार्य सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य कर सकती है।
परमादेश रिट का शाब्दिक अर्थ 'हम आदेश देते हैं' होता है। यह रिट किसी सार्वजनिक अधिकारी, संस्था, निचली अदालत या सरकार को उसका कानूनी या संवैधानिक कर्तव्य पूरा करने का निर्देश देने के लिए जारी की जाती है, जिसे करने से उसने इनकार कर दिया हो। हालाँकि, इस रिट को विधानमंडल के विरुद्ध कानून बनाने हेतु या राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के विरुद्ध उनके संवैधानिक कर्तव्यों के निष्पादन के लिए जारी नहीं किया जा सकता है।

127. (C) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनका मनोनीत व्यक्ति
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय की प्रशासनिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। इसके अनुसार उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उनके द्वारा निर्देशित किसी अन्य न्यायाधीश अथवा अधिकारी द्वारा की जाती हैं। इस नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता। इन कर्मचारियों की सेवा शर्तें भी मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं।

128. (D) न्यायिक समीक्षा - संविधान के विरुद्ध वैधानिक कानूनों का परीक्षण करने की शक्ति
'न्यायिक समीक्षा' न्यायपालिका की वह मौलिक शक्ति है जिसके तहत वह संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के प्रावधानों या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उसे असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर सकता है। यह शक्ति संविधान की सर्वोच्चता और विधि के शासन को बनाए रखने का कार्य करती है।

129. (C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के 'मूल ढांचे' का एक अनिवार्य अंग है, जिसे संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिन पर विधानमंडल द्वारा कटौती का मतदान नहीं हो सकता। सामान्य समय में राज्य विधानमंडल या सरकार उनके कार्यकाल के दौरान वेतनों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती। केवल वित्तीय आपातकाल के दौरान ही इसमें कटौती संभव है।

130. (B) संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले राज्य के कानूनों को अमान्य घोषित करने की शक्ति।
राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली न्यायिक समीक्षा की शक्ति का अर्थ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी अधिनियम, नियम या कार्यपालिक आदेश का संवैधानिक परीक्षण करना है। यदि न्यायालय यह पाता है कि कोई राज्य कानून भारतीय संविधान के प्रावधानों या नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विपरीत है, तो उसके पास उस कानून को शून्य घोषित करने का पूर्ण अधिकार है। यह शक्ति संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है।

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Flipkart

94. (A) अधीनस्थ न्यायाधीशों को प्रशासनिक नौकरशाहों से बदलना।
आधुनिक न्यायिक सुधारों का उद्देश्य न्याय प्रणाली की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाना है। इसमें ई-स्टैंपिंग, अदालती शुल्क के ऑनलाइन भुगतान, संवैधानिक मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग और वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना जैसी पहलें शामिल हैं। हालाँकि, अधीनस्थ न्यायाधीशों को प्रशासनिक नौकरशाहों से बदलना किसी सुधार का हिस्सा नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूरी तरह स्वतंत्र रखने का स्पष्ट निर्देश प्रदान करता है।

95. (C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, सुगमता और खुले न्याय के सिद्धांत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनी अदालती कार्यवाहियों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरु की है। यह तकनीक नागरिकों को सुनवाई देखने का अवसर देती है। लाइव स्ट्रीमिंग से न्यायाधीशों के निजता के मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि अदालती सुनवाई सार्वजनिक प्रक्रिया होती है और सार्वजनिक न्याय प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना न्याय का प्राथमिक उद्देश्य माना जाता है।

96. (D) अंग्रेजी
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार, जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे, उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियों की प्राधिकृत भाषा अंग्रेजी होगी। हालाँकि, अनुच्छेद 348(2) के तहत किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी या राज्य की किसी आधिकारिक भाषा के प्रयोग को अधिकृत कर सकता है। परंतु फैसलों, निर्णयों और आदेशों का अंग्रेजी अनुवाद होना अनिवार्य रहता है।

97. (C) मध्यस्थता / सुलह
वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत निर्दिष्ट मूल्य से अधिक वाले कमर्शियल मुकदमों के लिए मुकदमेबाजी से पूर्व मध्यस्थता और सुलह की प्रक्रिया को एक अनिवार्य चरण बनाया गया है। यदि किसी मामले में तत्काल अंतरिम राहत की आवश्यकता नहीं है, तो वादी को अदालत जाने से पहले इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक विवादों का त्वरित, सौहार्दपूर्ण और बिना मुकदमेबाज़ी के समाधान सुनिश्चित करना है ताकि अदालतों का बोझ घटे।

98. (B) दण्ड सौदेबाजी
दंड प्रक्रिया संहिता में वर्ष 2006 में 'दण्ड सौदेबाजी' (प्ली बार्गेनिंग) की अवधारणा को शामिल किया गया था। यह एक पूर्व-विचारण प्रक्रिया है जहाँ अभियुक्त कम सजा या हल्के आरोपों के बदले में स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। यह व्यवस्था केवल सात वर्ष से कम सजा वाले अपराधों और गैर-गंभीर मुकदमों में लागू होती है। इसका मुख्य उद्देश्य अदालतों में लंबित मुकदमों के बोझ को कम करना और त्वरित न्याय प्रदान करना है।

99. (D) एकपक्षीय - सभी पक्षों की उपस्थिति और सुनवाई के साथ दिया गया फैसला
विधिक शब्दावली में 'एकपक्षीय' (एक्स-पार्टी) आदेश या निर्णय का अर्थ वह फैसला होता है जो दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में, केवल उपस्थित पक्ष की सुनवाई के आधार पर दिया जाता है। अतः यह सभी पक्षों की उपस्थिति को नहीं दर्शाता। इसके विपरीत 'न्याय मित्र' न्यायालय की सहायता करने वाला निष्पक्ष वकील होता है, 'प्रांग्न्याय' पूर्व-निर्णित मामले पर दोबारा मुकदमे को रोकता है और 'स्वतः संज्ञान' न्यायालय द्वारा स्वयं उठाई गई न्यायिक कार्यवाही है।

100. (A) राजस्थान उच्च न्यायालय नियम, 1952
राजस्थान उच्च न्यायालय की कार्यपद्धति, प्रक्रियाओं, रिट याचिकाओं की प्रस्तुति और प्रशासनिक संचालन को विनियमित करने वाले नियम मुख्य रूप से 'राजस्थान उच्च न्यायालय नियम, 1952' में संकलित किए गए हैं। इन नियमों का निर्माण संविधान के अनुच्छेद 225 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया था। ये नियम अदालती कामकाजों, वकीलों के आचरण, ई-फाइलिंग, पीठों के गठन और अपीलीय प्रक्रियाओं के संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।

101. (A) 1 मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश
29 अगस्त 1949 को जब राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तब इसकी प्रारंभिक स्वीकृत संरचना में 1 मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य सहयोगी न्यायाधीश शामिल थे। राजप्रमुख द्वारा अध्यादेश जारी करके रियासती अदालतों के स्थान पर इस एकीकृत न्यायालय का गठन किया गया था। कालांतर में राज्य के पुनर्गठन, जनसंख्या वृद्धि और मुकदमों के बढ़ते कार्यभार को देखते हुए न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को बढ़ाकर 50 तक विस्तारित किया गया है।

102. (A) भारत के राष्ट्रपति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1)(a) के अनुसार, यदि उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण होने से पूर्व त्यागपत्र देना चाहता है, तो उसे अपना त्यागपत्र लिखित रूप में भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके भेजना होता है। चूंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए उनके त्यागपत्र को स्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार भी देश के राष्ट्रपति के पास ही निहित होता है।

103. (D) उन्हें बकाए मामलों को निपटाने के लिए अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।
संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में मुकदमों के बकाए को निपटाने या कार्य में अस्थायी वृद्धि से निपटने के लिए योग्य व्यक्तियों को अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। यह नियुक्ति अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी रूप से की जाती है। अपर न्यायाधीशों के पास नियमित न्यायाधीशों के समान ही सभी संवैधानिक शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार होते हैं, परंतु वे 62 वर्ष की आयु के बाद पद पर नहीं रह सकते।

NODIA

करना अनिवार्य है।

II. आरपीएससी द्वारा दी गई सलाह राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होती है।

III. राज्यपाल ऐसे विनियम बना सकते हैं जिनमें उन विषयों का उल्लेख हो जिनमें आरपीएससी से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) केवल III

11. राज्य सेवाओं के लिए आरपीएससी की भर्ती प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही क्रम चुनिए:

(A) रिक्तियों की अधिसूचना, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, सरकार को अनुशंसा
(B) रिक्तियों की अधिसूचना, मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, साक्षात्कार, सरकार को अनुशंसा
(C) रिक्तियों की अधिसूचना, प्रारंभिक परीक्षा, साक्षात्कार, मुख्य परीक्षा, सरकार को अनुशंसा
(D) रिक्तियों की अधिसूचना, सरकार को अनुशंसा, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार

12. जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, राजस्थान में जिला कलेक्टर का प्राथमिक कार्य क्या है?

(A) राजस्व वसूली का पर्यवेक्षण करना और सभी ग्रामीण भूमि अभिलेखों का रखरखाव करना
(B) सार्वजनिक शांति बनाए रखना और जिला पुलिस बल का पर्यवेक्षण करना
(C) पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकासात्मक कार्यक्रमों को लागू करना
(D) नगरपालिका प्रशासन और शहरी स्थानीय निकायों की देखरेख करना

13. निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जिला कलेक्टर को जिले में शस्त्र लाइसेंस जारी करने का अधिकार देता है?

(A) भारतीय दंड संहिता, 1860
(B) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
(C) आयुध अधिनियम, 1959
(D) राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007

14. जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में, जिला कलेक्टर सीधे किसके प्रति उत्तरदायी होता है?

(A) राजस्थान की राज्य कार्यपालिका
(B) राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव
(C) संबंधित संभाग के संभागीय आयुक्त
(D) केंद्रीय और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों

15. राजस्थान में जिला कलेक्टर के राजस्व कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. कलेक्टर जिला स्तर पर सर्वोच्च राजस्व अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य करता है।

II. कलेक्टर भू-राजस्व और अन्य सरकारी बकाया की वसूली के लिए उत्तरदायी होता है।

III. कलेक्टर कृषि राहत वितरण के लिए प्राकृतिक आपदाओं के दौरान फसल के नुकसान का आकलन करता है।

IV. कलेक्टर राजस्व अभिलेखों में राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने के लिए अधिकृत है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) I, II और III
(B) II, III और IV
(C) I, III और IV
(D) I, II और IV

16. प्राकृतिक आपदा के दौरान, जिला कलेक्टर किसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है?

(A) राज्य आपदा मोचन बल इकाई
(B) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(C) जिला नागरिक सुरक्षा सलाहकार परिषद
(D) जिला पर्यावरण संरक्षण समिति

NODIA

17. राजस्थान में जिला प्रशासन किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षी नियंत्रण में कार्य करता है?

(A) मुख्यमंत्री कार्यालय
(B) संभागीय आयुक्त
(C) कार्मिक विभाग
(D) राजस्व मंत्री

18. निम्नलिखित में से कौन सा जिला मजिस्ट्रेट का कानून-व्यवस्था से संबंधित कार्य नहीं है?

(A) गंभीर अपराधियों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी करना
(B) दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू करना
(C) पुलिस थानों और जेलों का निरीक्षण करना
(D) सरकार को जिले की वार्षिक आपराधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

19. जिले के शिष्टाचार (प्रोटोकॉल) प्रशासन में जिला कलेक्टर की भूमिका का सबसे उपयुक्त वर्णन पहचानिए।

(A) केवल मुख्यमंत्री की आधिकारिक राज्य यात्राओं और स्थानीय दौरों का प्रबंधन और पर्यवेक्षण करना
(B) औपचारिक शिष्टाचार कर्तव्यों को सख्ती से और विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक को सौंपना
(C) जिले में अति विशिष्ट व्यक्तियों और राज्य के अतिथियों के दौरों के लिए मुख्य शिष्टाचार अधिकारी
(D) जिले का दौरा करने वाले केवल विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के लिए आधिकारिक शिष्टाचार का प्रबंधन और समन्वय करना

114. (B) 1, 3, 4, 2
सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक सामान्य सिविल मुकदमे की कार्यवाही निश्चित चरणों में आगे बढ़ती है। सर्वप्रथम वादी द्वारा न्यायालय में 'वाद पत्र दाखिल' किया जाता है। इसके पश्चात न्यायालय प्रतिवादी को उपस्थित होने के लिए 'समन की तामील' करता है। समन प्राप्त होने पर प्रतिवादी अपना उत्तर यानी 'लिखित कथन दाखिल' करता है। अंत में, दोनों पक्षों के दावों और दांवों के आधार पर न्यायालय द्वारा विचारणीय 'विवादकों का निर्माण' किया जाता है।

115. (D) वे वैवाहिक विवादों, दाम्पत्य अधिकारों और संरक्षकता का समाधान करते हैं।
कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 के तहत गठित कुटुंब न्यायालयों का प्राथमिक क्षेत्राधिकार विवाह और पारिवारिक संबंधों से जुड़े विवादों का निस्तारण करना है। इनमें विवाह विच्छेद, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, भरण-पोषण, बच्चों की संरक्षकता और संपत्ति विभाजन से जुड़े मामले शामिल हैं। इन न्यायालयों का मुख्य जोर औपचारिक मुकदमों की बजाय परामर्श और मध्यस्थता के माध्यम से परिवारों को जोड़ने और विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने पर होता है।

116. (A) जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357A के तहत लागू पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत, अपराध के शिकार व्यक्तियों या उनके आश्रितों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि तय करने का अधिकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास होता है। जब न्यायालय मुआवजे की सिफारिश करता है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण घटना के प्रभाव, चोट की गंभीरता और पुनर्वास की आवश्यकता का आकलन करके मुआवजे की राशि निर्धारित करता है।

117. (C) उनके निर्णयों/पंचाटों की उच्च न्यायालयों में अपील नहीं की जा सकती।
लोक अदालतें त्वरित और बिना किसी अदालती शुल्क के न्याय देने का एक बेहतरीन माध्यम हैं, परंतु इनकी एक प्रमुख सीमा यह है कि इनके द्वारा दिए गए पंचाट के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील दायर नहीं की जा सकती। चूंकि लोक अदालत का फैसला दोनों पक्षों की आपसी सहमति से होता है, इसलिए कानूनन इसे अंतिम माना जाता है। यदि कोई पक्ष बाद में असंतुष्ट महसूस करता है तो उसके पास अपीलीय तंत्र का विकल्प उपलब्ध नहीं होता।

118. (A) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
पूरे राजस्थान में अदालती मुकदमों के बकाए को कम करने, लंबित मामलों को आपसी समझौते से निपटाने और मुकदमों को पूर्व-अदालती स्तर पर ही हल करने के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) उत्तरदायी है। यह संस्था नियमित अंतराल पर राष्ट्रीय लोक अदालतों, निरंतर मेगा लोक अदालतों और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए मोबाइल लोक अदालतों का आयोजन करती है, जिससे आम नागरिकों को त्वरित न्याय मिल सके।

119. (D) न्यायमंडल
राजस्थान में न्यायिक प्रशासन की संगठनात्मक संरचना के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रशासनिक और न्यायिक क्षेत्राधिकार में आने वाले पूरे क्षेत्रीय प्रभाग या जिला न्यायिक इकाई के लिए पारंपरिक रूप से 'न्यायमंडल' शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक न्यायमंडल में जिला न्यायालय के साथ-साथ उस जिले के अंतर्गत आने वाले सभी अधीनस्थ सिविल और आपराधिक न्यायालय सम्मिलित होते हैं, जो मुख्य जिला न्यायाधीश के प्रशासनिक अधीक्षण में कार्य करते हैं।

120. (B) कामकाजी नागरिकों के लिए छोटे अपराधों और ट्रैफिक चालानों का निपटारा करना।
राजस्थान में 'संध्याकालीन न्यायालयों' (इवनिंग कोर्ट्स) की स्थापना का मुख्य उद्देश्य नियमित कार्य समय के बाद छोटे-मोटे अपराधों, यातायात चालानों और समन मामलों का शीघ्र निस्तारण करना है। यह व्यवस्था उन कामकाजी नागरिकों और कर्मचारियों के लिए अत्यधिक सुविधाजनक सिद्ध होती है जो दिन के समय काम के कारण अदालत नहीं आ सकते। इससे न केवल नागरिकों का समय बचता है बल्कि नियमित अदालतों पर छोटे मामलों का बोझ भी कम होता है।

121. (D) संविधान द्वारा अनिश्चित; कार्यभार के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित।
भारतीय संविधान में किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कोई निश्चित या अधिकतम संख्या तय नहीं की गई है। संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने अन्य न्यायाधीश होंगे जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझें। इस प्रकार न्यायाधीशों की संख्या पूर्णतः अनिश्चित है और राष्ट्रपति मुकदमों की लंबित संख्या तथा कार्यभार की समीक्षा के आधार पर प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए यह संख्या निर्धारित करते हैं।

122. (C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
यदि किसी राज्य के राज्यपाल का पद मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारणों से अचानक रिक्त हो जाता है और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती, तो राष्ट्रपति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करने का दायित्व सौंप सकते हैं। हालाँकि, आपातकाल या किसी भी परिस्थिति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के स्वतः मुख्यमंत्री बनने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि दोनों पद संवैधानिक रूप से भिन्न हैं।

123. (A) नहीं, संविधान के तहत उच्च न्यायालयों के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का अभाव है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 केवल भारत के उच्चतम न्यायालय को 'परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार' प्रदान करता है, जिसके तहत राष्ट्रपति कानूनी या सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर सलाह मांग सकते हैं। उच्च न्यायालयों को ऐसा कोई संवैधानिक परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। उच्च न्यायालय केवल मूल, अपीलीय, रिट और पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं। वे राज्य सरकार या राज्यपाल को किसी विधिक विषय पर

Downloaded from www.pdf.tube

(B) न्यायमूर्ति एस. सगीर अहमद
(C) न्यायमूर्ति कांता भटनागर
(D) न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया

29. क्या राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग किसी ऐसे मामले की जांच कर सकता है जो पहले से ही किसी राज्य आयोग के समक्ष लंबित है?
(A) हां, यह सभी राज्य स्तरीय आयोगों पर अधिरोही संवैधानिक शक्तियां रखता है।
(B) हां, लेकिन केवल राज्यपाल की पूर्व लिखित स्वीकृति के अधीन।
(C) नहीं, यह किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित मामलों की जांच नहीं कर सकता।
(D) नहीं, जब तक कि राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए।

30. राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) द्वारा मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायत पर संज्ञान लेने पर शामिल निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए:
1. शिकायत की प्राप्ति
2. राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगना
3. जांच
4. अंतिम सिफारिश
निम्नलिखित में से कौन सा इन चरणों का सही क्रम दर्शाता है?
(A) शिकायत की प्राप्ति, जांच, राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगना, अंतिम सिफारिश
(B) शिकायत की प्राप्ति, राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगना, जांच, अंतिम सिफारिश
(C) जांच, शिकायत की प्राप्ति, राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगना, अंतिम सिफारिश
(D) राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगना, शिकायत की प्राप्ति, अंतिम सिफारिश, जांच

31. राज्य मानव अधिकार आयोग की एक प्रमुख सीमा यह है कि वह किसी भी शिकायत की जांच नहीं कर सकता यदि वह कथित उल्लंघन के कितने समय बाद की गई हो?
(A) छह महीने
(B) एक वर्ष
(C) दो वर्ष
(D) तीन वर्ष

32. निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है?
(A) बंदियों की रहने की स्थिति का अध्ययन करने के लिए राज्य की जेलों और हिरासत केंद्रों का दौरा करना
(B) सशस्त्र बलों के विरुद्ध मानव अधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच करना
(C) मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को वित्तीय मुआवजे और राहत की सिफारिश करना
(D) मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रदान की गई संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना

33. राज्य मानव अधिकार आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. उन्हें राज्य के राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
II. उन्हें केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
III. पद से हटाने के लिए साबित कदाचार या असमर्थता के आरोपों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व जांच की आवश्यकता होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) I और III
(B) II और III
(C) केवल I
(D) केवल II

34. राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
(A) 1970
(B) 1973
(C) 1985
(D) 1993

35. लोक सेवकों की निम्नलिखित श्रेणियों पर विचार कीजिए:
I. राजस्थान के मुख्यमंत्री
II. राज्य सरकार के मंत्री
III. राज्य विधानसभा के सदस्य (विधायक)
IV. राज्य सरकार के सिविल सेवक
उपर्युक्त में से कौन सी श्रेणी राजस्थान लोकायुक्त के जांच क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है?
(A) I, II और IV
(B) केवल II और IV
(C) I, II, III और IV
(D) II, III और IV

36. राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे?
(A) न्यायमूर्ति के. एस. सिद्धू
(B) न्यायमूर्ति एम. बी. शर्मा
(C) न्यायमूर्ति डी. पी. गुप्ता
(D) न्यायमूर्ति आई. डी. दुआ

37. राजस्थान के लोकायुक्त अपने कार्यों के निष्पादन पर अपनी वार्षिक समेकित रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं?
(A) राजस्थान के मुख्यमंत्री
(B) राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(C) राजस्थान के राज्यपाल
(D) राज्य विधानमंडल

38. लोकायुक्त के तहत शिकायत निवारण प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए:
1. शपथ पत्र (हलफनामा) के साथ निर्धारित प्रारुप में शिकायत प्रस्तुत करना
2. लोकायुक्त कार्यालय द्वारा शिकायत की प्रारंभिक जांच

NODIA

एजेंट के रूप में कार्य करता है।
(C) अत्यंत गंभीर कानून और व्यवस्था की स्थितियों में मृत्युदंड देने की पूर्ण न्यायिक शक्तियां जिला कलेक्टर के पास होती हैं।
(D) जिला कलेक्टर जिले के भीतर कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न विशिष्ट विभागों की गतिविधियों का समन्वय करता है।

112. राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए मतदाता सूची तैयार करता है।
II. राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए उत्तरदायी है।
III. राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) I और II
(B) I और III
(C) II और III
(D) केवल I

113. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत, यदि कोई नामित अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करने में विफल रहता है, तो कौन कार्रवाई करता है?
(A) प्रशासनिक हस्तक्षेप के माध्यम से राज्य मानव अधिकार आयोग
(B) अधिनियम के तहत नामित प्रथम और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
(C) भ्रष्टाचार निवारण क्षेत्राधिकार में कार्यरत राजस्थान लोकायुक्त
(D) संवैधानिक रिट याचिकाओं के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय

114. आरपीएससी का कौन सा कार्यात्मक प्रभाग परीक्षा के बाद उम्मीदवारों के दस्तावेजों और पात्रता के सत्यापन की प्रक्रिया को संभालता है?
(A) परीक्षा अनुभाग
(B) भर्ती अनुभाग
(C) गोपनीय अनुभाग
(D) विधि अनुभाग

115. राजस्थान में निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए:
1. मुख्य सचिव
2. उपखंड अधिकारी (एसडीओ)
3. संभागीय आयुक्त
4. जिला कलेक्टर
निम्नलिखित में से कौन सा उनके प्रशासनिक पदानुक्रम का सही अवरोही क्रम दर्शाता है?
(A) 1, 3, 4, 2
(B) 1, 4, 3, 2
(C) 3, 1, 4, 2
(D) 1, 3, 2, 4

116. राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) और राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि:
(A) एसएचआरसी के निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, जबकि एसआईसी के निर्णय विशुद्ध रूप से सलाहकारी प्रकृति के हैं
(B) एसआईसी के निर्णय जुर्माना शक्तियों के साथ बाध्यकारी हैं; एसएचआरसी की सिफारिशें सलाहकारी हैं
(C) एसएचआरसी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि एसआईसी सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है
(D) एसएचआरसी एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित है, जबकि एसआईसी विशुद्ध रूप से एक वैधानिक संरचना है

117. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है?
(A) चयन समिति के सभी तीनों नामित सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है
(B) गणपूर्ति के लिए चयन समिति के कम से कम दो सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है
(C) अन्य सदस्यों की उपस्थिति की परवाह किए बिना मुख्यमंत्री की उपस्थिति अनिवार्य है
(D) आरटीआई अधिनियम के तहत समिति में रिक्तियों के कारण नियुक्तियां अमान्य नहीं होती हैं

118. राजस्थान में राज्य निगरानी निकायों में हाल के सुधारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राज्य सूचना आयोग में अपीलों की ई-फाइलिंग शुरु की गई है।
II. एसएचआरसी और एसआईसी की सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग तेजी से किया जा रहा है।
III. राजस्थान संपर्क पोर्टल एक एकल डिजिटल ढांचे का उपयोग करके सभी राज्य विभागों की शिकायतों को एकीकृत करता है।
IV. हाल ही में राज्य विधानसभा के प्रस्ताव के माध्यम से लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) I, II और III
(B) II, III और IV
(C) I, III और IV
(D) I, II, III और IV

119. राजस्थान में लागू "सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012" की मुख्य परिभाषित विशेषता क्या है?
(A) समय सीमा के भीतर शिकायतों की सुनवाई के लिए

Click Here to Buy book on Amazon

कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

49. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
(A) 1992
(B) 1993
(C) 1994
(D) 1995

50. सूची I में दी गई वैधानिक/संवैधानिक निकायों को सूची II में पद धारण करने की उनकी अधिकतम आयु सीमा से सुमेलित कीजिए।
सूची I: निकाय
P. राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य
Q. राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष
R. राज्य सूचना आयुक्त
S. राजस्थान लोकायुक्त
सूची II: अधिकतम आयु सीमा
1. 65 वर्ष
2. 62 वर्ष
3. 70 वर्ष
4. 65 वर्ष (2019 के आरटीआई संशोधन नियमों के अनुसार)
(A) P-2, Q-3, R-4, S-1
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-3, Q-2, R-1, S-4

51. राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं?
(A) भारत के राष्ट्रपति
(B) कानून द्वारा राज्य विधानमंडल
(C) राज्य के राज्यपाल
(D) भारत निर्वाचन आयोग

52. सूची I के संवैधानिक अनुच्छेदों को सूची II के उनके संबंधित प्रावधानों से सुमेलित कीजिए।
सूची I: अनुच्छेद
P. अनुच्छेद 243-K
Q. अनुच्छेद 243-ZA
R. अनुच्छेद 315
S. अनुच्छेद 323
सूची II: प्रावधान
1. नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन
2. लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन (रिपोर्ट)
3. संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग
4. पंचायतों के लिए निर्वाचन
(A) P-4, Q-1, R-3, S-2
(B) P-1, Q-4, R-3, S-2
(C) P-4, Q-1, R-2, S-3
(D) P-3, Q-2, R-4, S-1

53. राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना किसके प्रावधानों के तहत की गई थी?
(A) भारत का संविधान
(B) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
(C) राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2000
(D) शासकीय गुप्तबात अधिनियम, 1923

54. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अनुसार राजस्थान राज्य सूचना आयोग की सही संरचना की पहचान कीजिए।
(A) एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और 5 से अधिक राज्य सूचना आयुक्त नहीं
(B) एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक राज्य सूचना आयुक्त नहीं
(C) एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और ठीक 10 राज्य सूचना आयुक्त
(D) तीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और 7 से अधिक राज्य सूचना आयुक्त नहीं

55. राजस्थान की निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए:
1. राजस्थान लोक सेवा आयोग
2. राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग
3. राजस्थान लोकायुक्त
4. राजस्थान राज्य सूचना आयोग
निम्नलिखित में से कौन सा उनकी औपचारिक स्थापना का प्राचीनतम से नवीनतम का सही क्रम दर्शाता है?
(A) 1, 3, 2, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 3, 1, 2, 4
(D) 1, 3, 4, 2

56. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं है?
(A) अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले राज्य के मुख्यमंत्री
(B) राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष
(C) प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
(D) मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत राज्य का एक कैबिनेट मंत्री

NODIA

57. आरटीआई शिकायत की जांच करते समय राज्य सूचना आयोग के पास क्या शक्ति होती है?
(A) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आपराधिक न्यायालय की शक्तियां
(B) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियां
(C) लोक सूचना अधिकारी को गिरफ्तार करने की शक्ति
(D) लोक सूचना अधिकारी को सेवा से पदच्युत करने की शक्ति

95. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।

अभिकथन (A): राज्य मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन की किसी भी ऐसी घटना की जांच नहीं कर सकता है जिसे घटित हुए एक वर्ष से अधिक का समय बीत चुका हो।

कारण (R): समय-बाधित शिकायतें साक्ष्य मूल्य खो देती हैं, और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में वैधानिक सीमा को सख्ती से परिभाषित किया गया है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

96. राजस्थान लोकायुक्त द्वारा राज्य सरकार को दी गई सिफारिशों की स्थिति क्या है?

(A) वे कार्यपालिका पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं और 90 दिनों के भीतर पूरी तरह से लागू की जानी चाहिए
(B) सलाहकारी हैं, लेकिन अस्वीकृति की स्थिति में विधानसभा में एक स्पष्टीकरण ज्ञापन रखना आवश्यक है
(C) राज्य के राज्यपाल द्वारा औपचारिक लिखित स्वीकृति के बाद ही वे कानूनी रूप से बाध्यकारी बनती हैं
(D) उनका कोई कानूनी महत्व नहीं है और वे विशुद्ध रूप से सरकार के लिए अनौपचारिक सलाहकारी सुझावों के रूप में कार्य करती हैं

97. आज राजस्थान में जिला कलेक्टर की 'विकास' संबंधी भूमिका का सबसे उपयुक्त वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है?

(A) सभी व्यक्तिगत ग्राम पंचायतों को विकास कोष सीधे स्वीकृत और वितरित करना
(B) जिला स्तर पर राज्य और केंद्रीय विकास योजनाओं के लिए मुख्य समन्वयक
(C) 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद विकास योजना में कोई भूमिका न निभाना
(D) सभी स्थानीय विकास व्यय के लिए अंतिम लेखा परीक्षा प्राधिकारी के रूप में कार्य करना

98. राज्य मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम द्वारा यथा परिभाषित "मानव अधिकार" से तात्पर्य किन अधिकारों से है?

(A) संविधान या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं द्वारा गारंटीकृत जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार
(B) निजी संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा और सभी वर्गों में आर्थिक समानता को बढ़ावा देना
(C) विशेष रूप से राजनीतिक भागीदारी, मतदान का अधिकार और विधायी निकायों में प्रतिनिधित्व
(D) राज्य की सीमाओं के पार अप्रतिबंधित मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक लेनदेन और आर्थिक आवाजाही

99. जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला राजस्व अदालत में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन सा अधिकारी करता है?

(A) राजस्व न्यायिक जिले के लिए आधिकारिक तौर पर नियुक्त लोक अभियोजक
(B) राजस्व मामलों में राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला नामित सरकारी वकील
(C) राज्य प्रशासन की ओर से कार्य करने वाला वरिष्ठ जिला राजस्व अधिकारी
(D) राज्य के वकील की आवश्यकता नहीं है; अधिकारी स्वयं का प्रतिनिधित्व करते हैं या मामले निजी होते हैं

100. सूची I में निगरानी निकायों से संबंधित शब्दावलियों को सूची II में उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची I: शब्दावली

P. स्वतः संज्ञान
Q. पदेन
R. गणपूर्ति
S. परमादेश

सूची II: अर्थ

1. किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश देने वाली अदालत द्वारा जारी रिट
2. किसी प्राधिकारी द्वारा स्वयं के संज्ञान पर की गई कार्रवाई
3. किसी अन्य पद पर होने के कारण कोई पद धारण करना
4. किसी बैठक के संचालन के लिए उपस्थित होने हेतु आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या

(A) P-2, Q-3, R-4, S-1
(B) P-3, Q-2, R-1, S-4
(C) P-1, Q-3, R-4, S-2
(D) P-2, Q-4, R-3, S-1

101. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।

अभिकथन (A): राज्य सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए अपीलीय प्राधिकारी नहीं है।

कारण (R): दोनों आयोग इस बात के आधार पर परस्पर अपवर्जित क्षेत्राधिकार में कार्य करते हैं कि लोक प्राधिकारी केंद्र या राज्य सरकार से संबंधित है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

102. राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(A) आयोग के आसीन सदस्यों द्वारा सीधे चुने जाते हैं

Downloaded from www.pdf.tube

(B) II, III और IV
(C) I, III और IV
(D) I, II और IV

68. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत, द्वितीय अपील का निस्तारण करने के लिए राज्य सूचना आयोग के लिए अधिकतम समय सीमा क्या है?
(A) प्राप्ति से ठीक 30 दिनों के भीतर
(B) विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 45 दिन
(C) दायर करने की तिथि से 90 दिनों के भीतर
(D) अधिनियम में कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं है

69. राजस्थान में मतदाता सूची तैयार करने से पूर्व नगर निकायों और पंचायतों के चुनावों के लिए वार्डों के संरचनात्मक परिसीमन की जिम्मेदारी किस प्राधिकारी की है?
(A) स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग
(B) राज्यपाल के परामर्श से भारत निर्वाचन आयोग
(C) राज्य सरकार (स्वायत्त शासन और पंचायती राज विभाग)
(D) स्वतंत्र परिसीमन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने वाला जिला कलेक्टर

70. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): राज्य निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
कारण (R): राज्य निर्वाचन आयोग अपनी शक्तियां सीधे संविधान (73वें और 74वें संशोधन) से प्राप्त करता है और यह भारत निर्वाचन आयोग का अधीनस्थ निकाय नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

71. राजस्थान लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है, जो उसकी एक प्रति किसके समक्ष रखवाएंगे?
(A) भारत के राष्ट्रपति
(B) राज्य विधानमंडल
(C) मुख्यमंत्री कार्यालय
(D) राजस्थान उच्च न्यायालय

72. जिला पुलिस बल का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है?
(A) जिला कलेक्टर
(B) पुलिस अधीक्षक (एसपी)
(C) पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी)
(D) संभागीय आयुक्त

73. यद्यपि पुलिस अधीक्षक जिला पुलिस बल का प्रमुख होता है, लेकिन उसे किसके सामान्य नियंत्रण और निर्देशन के तहत कार्य करना होता है?
(A) केवल गृह मंत्री
(B) केवल पुलिस महानिरीक्षक
(C) जिला मजिस्ट्रेट
(D) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

74. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): सिविल सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों में आरपीएससी की सलाह राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होती है।
कारण (R): आरपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य सिविल सेवाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकना है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

NODIA

75. सूची I के प्रथम अध्यक्षों/प्रमुखों को सूची II में राजस्थान के उनके संबंधित संगठनों से सुमेलित कीजिए।
सूची I: संगठन प्रमुख
P. राज्य मानव अधिकार आयोग
Q. राज्य सूचना आयोग
R. राज्य निर्वाचन आयोग
S. लोकायुक्त
सूची II: व्यक्ति
1. आई. डी. दुआ
2. कांता भटनागर
3. एम. डी. कोरानी
4. अमर सिंह राठौड़
(A) P-2, Q-3, R-4, S-1
(B) P-3, Q-2, R-1, S-4
(C) P-2, Q-4, R-3, S-1
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

76. आपदा प्रबंधन के संदर्भ में, राज्य स्तर पर कौन सी समिति राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करती है?
(A) राज्य कार्यकारी समिति
(B) राज्य आपदा राहत समिति
(C) राज्य संकट प्रबंधन समूह
(D) राज्य सतर्कता समिति

77. आरपीएससी की बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) बनाने हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है?

(A) आयोग के अध्यक्ष सहित न्यूनतम दो सदस्य
(B) आयोग के अध्यक्ष सहित न्यूनतम तीन सदस्य
(C) आयोग की कुल स्वीकृत सदस्य संख्या का कम से कम आधा
(D) आरपीएससी नियमों द्वारा विनियमित; कोई संवैधानिक गणपूर्ति निर्धारित नहीं है

78. लोकायुक्त की सिफारिश से व्यथित (पीड़ित) कोई लोक सेवक किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकता है?
(A) अनुच्छेद 32
(B) अनुच्छेद 226
(C) अनुच्छेद 136
(D) अनुच्छेद 163

79. सूची I के कार्यात्मक क्षेत्रों को सूची II में संबंधित निगरानी निकाय के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: कार्यात्मक क्षेत्र
P. पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का संचालन
Q. मंत्रियों के बीच भ्रष्टाचार की जांच
R. सरकारी रिकॉर्ड को प्रकट न करने पर जुर्माना
S. हिरासत में उत्पीड़न के खिलाफ मुआवजे की सिफारिश
सूची II: निकाय
1. राज्य सूचना आयोग
2. राज्य मानव अधिकार आयोग
3. राज्य निर्वाचन आयोग
4. लोकायुक्त
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-1, Q-4, R-3, S-2

80. जिला राजस्व प्रशासन में पदानुक्रम (निम्नतम से उच्चतम) का सही क्रम चुनिए:
(A) पटवारी, गिरदावर (राजस्व निरीक्षक), नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी (एसडीओ), जिला कलेक्टर
(B) पटवारी, नायब तहसीलदार, गिरदावर, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी (एसडीओ), जिला कलेक्टर
(C) ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उपखंड अधिकारी (एसडीओ), जिला कलेक्टर
(D) गिरदावर, पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी (एसडीओ), जिला कलेक्टर

81. राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान जिला स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (जिला निर्वाचन अधिकारी) के रूप में कौन कार्य करता है?
(A) जिला न्यायाधीश
(B) जिला कलेक्टर
(C) पुलिस अधीक्षक
(D) उपखंड अधिकारी (एसडीएम)

82. कौन सा कथन राज्य सूचना आयोग से संबंधित धारा 8 के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अपवाद की सही पहचान करता है?
(A) राज्य सरकार के किसी विभाग के वार्षिक बजट आवंटन से संबंधित विवरण
(B) ऐसी सूचना जिससे संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होता हो
(C) किसी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से संबंधित सामान्य जानकारी
(D) आवंटित और पूर्ण किए गए सरकारी खरीद निविदाओं से संबंधित पूर्ण सार्वजनिक रिकॉर्ड

83. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील प्रक्रिया का सही क्रम चुनिए:
(A) राज्य सूचना आयोग, लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(B) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, लोक सूचना अधिकारी, राज्य सूचना आयोग
(C) लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, राज्य सूचना आयोग
(D) राज्य सूचना आयोग, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, लोक सूचना अधिकारी

84. निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जिला स्तर पर गठित "सतर्कता समितियों" का सर्वोत्तम वर्णन करता है?
(A) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की निगरानी के लिए नियुक्त समितियां
(B) सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामान्य जन शिकायतों की देखरेख करने वाली समितियां
(C) जिला अदालतों के न्यायिक फैसलों की समीक्षा के लिए स्थापित समितियां
(D) निजी क्षेत्र की संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण करने के लिए अधिकृत समितियां

85. राज्य और संघ निकायों के बीच समन्वय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. भारत निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय चुनावों के मामलों में राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दे सकता है।
II. यदि राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुरोध किया जाए और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाए, तो यूपीएससी संयुक्त भर्ती की योजनाओं को तैयार करने और संचालित करने में आरपीएससी की सहायता कर सकता है।
III. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किसी मामले को राज्य मानव अधिकार आयोग को स्थानांतरित कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) I और II
(B) II और III
(C) केवल II
(D) I, II और III

Click Here to Buy book on Flipkart

86. राजस्थान में नागरिकों के लिए 'मतदाता पहचान पत्र' कौन सा निकाय जारी करता है?
(A) राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग
(B) भारत निर्वाचन आयोग
(C) स्वायत्त शासन विभाग
(D) राजस्थान लोक सेवा आयोग

87. राजस्थान लोक सेवा आयोग की वित्तीय स्वायत्तता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. सदस्यों के वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।
II. आरपीएससी का बजट राज्य विधानमंडल के मतदान के अधीन है।
III. आरपीएससी कर्मचारियों की पेंशन राज्य विधानमंडल द्वारा अमतदेय है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

88. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य है, लेकिन राज्य मानव अधिकार आयोग में उसका कोई समानांतर पदेन समकक्ष नहीं है?
(A) राज्य महिला आयोग की पदेन अध्यक्ष
(B) राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पदेन अध्यक्ष
(C) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पदेन अध्यक्ष
(D) राज्य आयोग में पदेन सदस्यों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है

89. यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच के लंबित रहने के दौरान निलंबित किया जाना है, तो निलंबन आदेश जारी करने का अधिकार किसके पास है?
(A) भारत के राष्ट्रपति
(B) राजस्थान के राज्यपाल
(C) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(D) राजस्थान के मुख्यमंत्री

90. राजस्थान लोकायुक्त की सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह बेनामी शिकायतों के आधार पर जांच शुरु नहीं कर सकता।
II. इसमें अपनी सिफारिशों को लागू कराने की शक्ति का अभाव है।
III. इसका पूर्व मुख्यमंत्रियों पर क्षेत्राधिकार नहीं है।
IV. यह अदालतों की न्यायिक कार्यवाइयों की समीक्षा नहीं कर सकता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) I, II और IV
(B) II, III और IV
(C) I, II, III और IV
(D) I, III और IV

91. 'विभागीय पदोन्नति समिति' (डीपीसी), जिसमें आरपीएससी का एक सदस्य भाग लेता है, का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) आंतरिक राज्य सेवा पदोन्नति के लिए प्रतियोगी लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना
(B) योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर सिविल सेवकों की पदोन्नति के लिए सिफारिश करना
(C) सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों के लिए वैधानिक सेवानिवृत्ति लाभों को अंतिम रूप देना और स्वीकृत करना
(D) राज्य सेवा अधिकारियों की प्रशासनिक पदस्थापनाओं और तबादलों का प्रबंधन और आवंटन करना

92. निगरानी निकायों और उनके मूल सिद्धांतों के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए:
(A) आरपीएससी – राज्य भर्ती में प्राथमिक योग्यता प्रणाली (मेरिट सिस्टम) के प्रहरी के रूप में कार्य करना
(B) लोकायुक्त – भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के आरोपों की जांच करना
(C) राज्य सूचना आयोग – पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही को बढ़ावा देना
(D) राज्य निर्वाचन आयोग – चुनाव याचिकाओं का निर्णय करना

93. जिला कलेक्टर के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए:
I. जिला जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करना
II. जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करना
III. जिला क्रेडिट योजना तैयार करना
IV. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करना
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कलेक्टर की बहुआयामी भूमिका को सटीक रूप से दर्शाता है?
(A) I, II और IV
(B) II, III और IV
(C) I, II और III
(D) I, II, III और IV

94. राज्य सूचना आयोग की अवधारणा किसकी आवश्यकता के कारण अनिवार्य हुई थी?
(A) उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों के भारी बकाये को काफी कम करना
(B) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को संस्थागत रूप देना
(C) राज्य सरकार के जनसंपर्क और आधिकारिक मीडिया संचार का प्रबंधन करना
(D) विदेशी एजेंसियों से संवेदनशील राज्य के रहस्यों और गोपनीय फाइलों की रक्षा करना

Downloaded from www.pdf.tube

3. सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश अग्रेषित करना
4. संबंधित लोक सेवक से टिप्पणी/स्पष्टीकरण मांगना

निम्नलिखित में से कौन सा इन चरणों का सही कालानुक्रमिक क्रम दर्शाता है?
(A) 1, 2, 4, 3
(B) 1, 4, 2, 3
(C) 2, 1, 4, 3
(D) 1, 2, 3, 4

39. वर्तमान वैधानिक प्रावधानों के अनुसार राजस्थान में लोकायुक्त के लिए निर्धारित पदावधि क्या है?
(A) 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
(B) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
(C) 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु
(D) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु

40. राजस्थान के लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है।
II. इस समिति में मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं।
III. लोकायुक्त स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू कर सकता है।
IV. लोकायुक्त के पास दोषी लोक सेवक पर आपराधिक अदालत में सीधे मुकदमा चलाने की शक्ति है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) I, II और III
(B) II, III और IV
(C) I, III और IV
(D) I, II और IV

41. निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है?
(A) जिला प्रमुख
(B) नगर निगम का महापौर
(C) राजस्थान के महालेखाकार
(D) राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का अध्यक्ष

42. केंद्रीय लोकपाल की तुलना में राजस्थान लोकायुक्त की एक प्रमुख सीमा क्या है?
(A) मुख्यमंत्री की जांच करने में असमर्थता
(B) सिविल सेवकों की जांच करने में असमर्थता
(C) समर्पित जांच प्रभाग का अभाव
(D) आम जनता से शिकायतें लेने में असमर्थता

43. लोकायुक्त के पर्यवेक्षी कार्यों के समानांतर राज्य स्तर पर प्राथमिक भ्रष्टाचार विरोधी जांच एजेंसी के रूप में कौन सी संस्था कार्य करती है?
(A) राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग
(B) राजस्थान पुलिस अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी)
(C) राजस्थान राज्य सूचना आयोग
(D) राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी)

44. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था?
(A) अनुच्छेद 243-I
(B) अनुच्छेद 243-K
(C) अनुच्छेद 243-J
(D) अनुच्छेद 243-L

45. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल द्वारा किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है।
कारण (R): राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

46. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का प्राथमिक जनादेश क्या है?
(A) राज्य विधानसभा के लिए चुनावों का संचालन और पर्यवेक्षण करना
(B) राजस्थान में सभी लोकसभा संसदीय क्षेत्रों के लिए चुनाव कराना
(C) राज्य के राजनीतिक दलों के पंजीकरण और औपचारिक मान्यता को विनियमित करना
(D) पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कराना

NODIA

47. राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे?
(A) अमर सिंह राठौड़
(B) नेक राम भसीन
(C) इंद्रजीत खन्ना
(D) ए. के. पांडे

48. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है।
कारण (R): विशाल ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को संभालने के लिए, कार्यकुशलता सुनिश्चित करने हेतु कई आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन

(B) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक आईएएस अधिकारी होते हैं
(C) जब भी नियुक्त अध्यक्ष अनुपस्थित होता है, आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं
(D) नियुक्ति पर छह वर्ष की एक निश्चित संवैधानिक पदावधि रखते हैं

103. राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम के तहत "कुप्रशासन" शब्द में शामिल है:
(A) अनुचित प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण होने वाला अन्याय या कठिनाई
(B) केवल प्रत्यक्ष वित्तीय रिश्वतखोरी और मौद्रिक भ्रष्टाचार में शामिल कार्रवाइयां
(C) राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित और अधिनियमित नीतिगत निर्णय
(D) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक और प्रशासनिक कार्रवाइयां

104. निम्नलिखित में से किसे राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के कामकाज में एक प्राथमिक चुनौती माना जाता है?
(A) राज्य विधानसभा के विधायी दायरे में असंवैधानिक अतिक्रमण
(B) राज्य सरकार पर वित्तीय और कर्मचारियों की निर्भरता
(C) पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीधे बाध्यकारी गिरफ्तारी वारंट जारी करने की शक्ति
(D) राज्य पुलिस बलों पर प्रत्यक्ष परिचालन नियंत्रण और कमान

105. राजस्थान संपर्क पोर्टल पर सामान्य शिकायत निवारण चक्र में निम्नलिखित कार्रवाइयों पर विचार कीजिए:
1. नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करता है।
2. शिकायत बंद कर दी जाती है और नागरिक से फीडबैक एकत्र किया जाता है।
3. शिकायत संबंधित विभागीय अधिकारी को भेजी जाती है।
4. अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करता है और समाधान की स्थिति अद्यतन करता है।

निम्नलिखित में से कौन सा इन कार्रवाइयों का सही कालानुक्रमिक क्रम दर्शाता है?
(A) 1, 3, 4, 2
(B) 1, 4, 3, 2
(C) 3, 1, 4, 2
(D) 1, 3, 2, 4

106. राजस्थान में, "पंचायती राज संस्थाओं" के चुनाव ऐतिहासिक रूप से पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित किए जाते थे। किस वर्ष में राज्य निर्वाचन आयोग ने यह जिम्मेदारी संभाली?
(A) 1993
(B) 1994
(C) 1995
(D) 1999

107. राजस्थान के मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री को अपने लोकायुक्त के दायरे में शामिल किया है?
(A) अपने विशेष लोकायुक्त कानून के तहत विशेष रूप से केरल राज्य
(B) वैधानिक संशोधन के तहत विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य
(C) मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे कई राज्य
(D) किसी भी भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं किया है

108. यदि कोई अभ्यर्थी आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा की ओएमआर शीट की प्रति मांगना चाहता है, तो वह किस अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करेगा?
(A) राजस्थान सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम
(B) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
(C) राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011
(D) शासकीय गुप्तबात अधिनियम, 1923

109. आरपीएससी के निर्णयों को अत्यधिक विश्वसनीय माने जाने का प्राथमिक कारण क्या है?
(A) क्योंकि इसकी सभी गतिविधियों और निर्णयों का सीधा पर्यवेक्षण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है
(B) इसकी स्वायत्त संवैधानिक स्थिति और सदस्यों के कार्यकाल की सुरक्षा
(C) क्योंकि इसके सभी सदस्य सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और निगमित किए जाते हैं
(D) क्योंकि इसके भर्ती संबंधी निर्णयों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती

110. राज्य सूचना आयोग की जांच की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह व्यक्तियों को समन भेज सकता है तथा उनकी उपस्थिति को लागू करा सकता है और उन्हें शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए बाध्य कर सकता है।
II. यह दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की मांग कर सकता है।
III. यह सूचना के प्रकटीकरण के संबंध में उच्च न्यायालय के अंतिम फैसलों की समीक्षा कर सकता है और उन्हें बदल सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) I और II
(B) I और III
(C) II और III
(D) I, II और III

111. राजस्थान में जिला प्रशासन के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) जिला प्रशासन की मूल इकाई है।
(B) जिला कलेक्टर जिला स्तर पर राज्य सरकार के मुख्य

Click Here to Buy book on Amazon

58. राजस्थान के प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे?
(A) टी. श्रीनिवासन
(B) सुरेश चौधरी
(C) एम. डी. कोरानी
(D) डी. बी. गुप्ता

59. राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. सूचना देने में देरी के लिए राज्य सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर ₹250 प्रति दिन के हिसाब से अधिकतम ₹25,000 तक का जुर्माना लगा सकता है।
II. राज्य सूचना आयोग केवल प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध ही अपील प्राप्त करता है।
III. राज्य सूचना आयोग के निर्णय बाध्यकारी होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) I और II
(B) I और III
(C) II और III
(D) I, II और III

60. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें (आरटीआई संशोधन अधिनियम, 2019 के बाद) वही होंगी जो किसके द्वारा निर्धारित की जाएंगी?
(A) केंद्र सरकार
(B) राज्य सरकार
(C) राज्य के राज्यपाल
(D) भारत के राष्ट्रपति

61. राजस्थान में निम्नलिखित पर्यवेक्षी/निगरानी तंत्रों में से असंगत विकल्प की पहचान कीजिए।
(A) राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग
(B) राजस्थान राज्य सूचना आयोग
(C) राजस्थान लोकायुक्त का कार्यालय
(D) राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

62. "राजस्थान संपर्क" पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) सूचना का अधिकार आवेदनों के ऑनलाइन जमा करने और स्थिति देखने की सुविधा प्रदान करना
(B) नागरिक शिकायतों को दर्ज करने और निवारण के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करना
(C) आरपीएससी द्वारा आयोजित आधिकारिक परीक्षा परिणामों और भर्तियों को प्रकाशित करना
(D) राज्य सरकार के अधिकारियों की दैनिक उपस्थिति की निगरानी और रिकॉर्ड रखना

63. निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में 'उप-लोकायुक्त' की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है?
(A) लोकायुक्त के अवकाश पर होने पर विकल्प के रूप में कार्य करना
(B) लोकायुक्त की सहायता करना और उनके द्वारा सौंपे गए जांच कार्यों को संचालित करना
(C) विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित मामलों की जांच करना
(D) लोकायुक्त के निर्णयों पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना

64. राजस्थान के लोकायुक्त के पास शिकायत आम तौर पर उस तिथि से कितनी अवधि के भीतर दर्ज की जानी चाहिए जिस दिन शिकायतकर्ता को शिकायत की गई कार्रवाई के बारे में पता चला?
(A) 1 वर्ष
(B) 3 वर्ष
(C) 5 वर्ष
(D) 7 वर्ष

65. विभिन्न पदाधिकारियों को पद से हटाने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. आरपीएससी के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
II. राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
III. एसएचआरसी के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
IV. राजस्थान के लोकायुक्त को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) I, II और III
(B) I, II और IV
(C) II, III और IV
(D) I, III और IV

NODIA

66. लोकायुक्त की अवधारणा मुख्य रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से प्रेरित है?
(A) यूके की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था
(B) स्कैंडिनेवियाई लोकपाल (ऑम्बुड्समैन) प्रणाली
(C) फ्रांस में महानिरीक्षक प्रशासनिक प्रणाली
(D) यूएसए का संघीय व्यापार आयोग मॉडल

67. राजस्थान में शिकायत निवारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. 'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम' 2011 में अधिनियमित किया गया था।
II. 'राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम' 2012 में अधिनियमित किया गया था।
III. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 राजस्थान संपर्क से जुड़ी हुई है।
IV. सरकारी कर्मचारियों के सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों का निवारण सख्ती से राजस्थान संपर्क के माध्यम से ही किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) I, II और III

नागरिकों का कानूनी अधिकार
(B) सभी आपराधिक मामलों में मुफ्त कानूनी सहायता और रक्षा वकील की गारंटी देना
(C) यह सुनिश्चित करना कि सभी विभागीय सरकारी बैठकें जनता के लिए पूरी तरह से खुली रखी जाएं
(D) राज्य विधानसभा के सभी सत्रों के अनिवार्य सीधे टेलीविजन प्रसारण का प्रावधान करना

120. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): जिला कलेक्टर जिले के मुख्य शिष्टाचार अधिकारी के रूप में कार्य करता है।
कारण (R): अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरों को संभालते समय कलेक्टर को किसी भी सिविल या आपराधिक दायित्व से कानूनी छूट प्राप्त होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

121. "राज्य सतर्कता आयोग" राज्य स्तर पर केंद्रीय स्तर के किस निकाय के समानांतर कार्य करता है?
(A) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)
(B) केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)
(C) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)
(D) नीति आयोग

122. राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम के तहत, यदि कोई शिकायत झूठी और तुच्छ पाई जाती है, तो क्या कार्रवाई की जा सकती है?
(A) लोकायुक्त शिकायतकर्ता पर ₹1,00,000 तक का सीधा वित्तीय जुर्माना लगा सकता है
(B) शिकायतकर्ता पर मुकदमा चलाया जा सकता है और कारावास से दंडित किया जा सकता है
(C) लोकायुक्त व्यक्ति को भविष्य में शिकायतें दर्ज करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर सकता है
(D) कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि जन शिकायतें दर्ज करना एक मौलिक अधिकार माना जाता है

123. जिला स्तर पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में "फर्जी लाभार्थियों" की पहचान करने और उन्हें हटाने के कार्य की देखरेख मुख्य रूप से किसके द्वारा की जाती है?
(A) उपखंड अधिकारी (एसडीएम)
(B) जिला कलेक्टर
(C) राज्य निर्वाचन आयोग
(D) पुलिस अधीक्षक

124. राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्यता प्राप्त आधार नहीं है?
(A) दिवालिया घोषित होना
(B) अपने पद के कर्तव्यों से बाहर किसी सवेतन रोजगार में संलग्न होना
(C) सिविल सेवा अभ्यर्थियों के बीच अलोकप्रिय होना
(D) मानसिक या शारीरिक अक्षमता

125. सूची I के शिकायत निवारण मंचों/अधिनियमों को सूची II में उनके प्राथमिक केंद्र बिंदु से सुमेलित कीजिए।
सूची I: मंच / अधिनियम
P. सूचना का अधिकार अधिनियम
Q. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम
R. राजस्थान संपर्क
S. लोकायुक्त
सूची II: प्राथमिक केंद्र बिंदु
1. अधिसूचित सेवाओं का समयबद्ध प्रावधान
2. केंद्रीकृत सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित जन शिकायत निवारण
3. लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार की जांच
4. सरकारी अभिलेखों में पारदर्शिता
(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-1, Q-4, R-3, S-2
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

126. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): राज्य सूचना आयोग अपनी प्रभावशीलता के लिए नागरिक समाज और जन जागरूकता पर अत्यधिक निर्भर करता है।
कारण (R): आरटीआई अधिनियम एक मांग-आधारित कानून है जहां नागरिकों को सूचना के लिए अनुरोध शुरु करना होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

127. निम्नलिखित में से कौन सा निकाय वित्तीय आवंटन के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (पंचायतों और नगरपालिकाओं) के कामकाज की समीक्षा करने के लिए अधिकृत है?
(A) राज्य निर्वाचन आयोग
(B) राज्य वित्त आयोग
(C) आरपीएससी
(D) राज्य सूचना आयोग

Downloaded from www.pdf.tube

से संबंधित कोई मामला पहले से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या कानून के तहत गठित किसी अन्य वैधानिक आयोग के समक्ष विचाराधीन या लंबित है, तो राज्य आयोग उस मामले की समानांतर जांच नहीं कर सकता है। यह नियम जांच प्रक्रिया के दोहरेपन को रोकने हेतु बनाया गया है।

30. (B) शिकायत की प्राप्ति, राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगना, जांच, अंतिम सिफारिश
राज्य मानव अधिकार आयोग में शिकायत निवारण की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। सर्वप्रथम पीड़ित या नागरिक द्वारा आयोग के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत या प्राप्त की जाती है। शिकायत दर्ज होने के बाद आयोग प्रारंभिक रूप से संबंधित विभाग या राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगता है। रिपोर्ट के संतोषजनक न होने पर आयोग स्वयं या अपनी जांच एजेंसी के माध्यम से जांच करता है और अंत में निष्कर्षों के आधार पर सरकार को अपनी अंतिम सिफारिश भेजता है।

31. (B) एक वर्ष
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 36(2) में यह वैधानिक प्रावधान किया गया है कि राज्य मानव अधिकार आयोग किसी भी ऐसे मामले या शिकायत की जांच शुरु नहीं कर सकता है, जिसे घटित हुए एक वर्ष से अधिक का समय बीत चुका हो। कालबाधित होने के कारण एक वर्ष से अधिक पुरानी घटनाओं पर आयोग संज्ञान लेने से वंचित रहता है, ताकि पुराने मामलों की आड़ में अनावश्यक मुकदमों को रोका जा सके।

32. (B) सशस्त्र बलों के विरुद्ध मानव अधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच करना
राज्य मानव अधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार से सैन्य एवं सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों को बाहर रखा गया है। अधिनियम के अनुसार सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना, वायु सेना और केंद्रीय पुलिस बल) द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करने का अधिकार केवल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास निहित है। राज्य आयोग केवल राज्य पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और सिविल कर्मचारियों द्वारा किए गए उल्लंघनों की ही जांच कर सकता है।

33. (B) II और III
राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भले ही राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें पद से हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही पदमुक्त कर सकते हैं। इसके लिए अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट आवश्यक होती है। जांच में आरोप सही पाए जाने के पश्चात ही राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश जारी किया जाता है।

34. (B) 1973
राजस्थान में प्रशासनिक भ्रष्टाचार, कुप्रशासन और लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतों की जांच के उद्देश्य से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम वर्ष 1973 में पारित किया गया था। यह अधिनियम 3 फरवरी 1973 को लागू हुआ था। इस वैधानिक ढांचे के माध्यम से राज्य में लोकायुक्त संस्था की औपचारिक स्थापना की गई, जिससे लोक जीवन में पारदर्शिता, उच्च नैतिक मानकों और प्रशासनिक जवाबदेही को सुदृढ़ किया जा सके।

NODIA

35. (B) केवल II और IV
राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत लोकायुक्त के जांच क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके दायरे में राज्य सरकार के मंत्री, लोक सेवक, जिला प्रमुख और स्थानीय निकायों के अध्यक्ष आते हैं। हालांकि, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य (विधायक), उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को लोकायुक्त के जांच क्षेत्राधिकार से पूरी तरह बाहर रखा गया है।

36. (D) न्यायमूर्ति आई. डी. दुआ
राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के लागू होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आई. डी. दुआ को राजस्थान का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। उन्होंने 28 अगस्त 1973 को अपना पदभार ग्रहण किया। राज्य में लोकायुक्त कार्यालय की प्रशासनिक नींव रखने तथा लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की निष्पक्ष जांच व्यवस्था स्थापित करने में उनका प्रारंभिक नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण रहा।

37. (C) राजस्थान के राज्यपाल
राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लोकायुक्त प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों, जांचों और अनुशंसित कार्यवाहियों का एक वार्षिक समेकित विवरण तैयार करता है। यह वार्षिक रिपोर्ट लोकायुक्त द्वारा सीधे राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य सरकार के स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं, जहाँ इस पर व्यापक चर्चा की जाती है।

38. (A) 1, 2, 4, 3
लोकायुक्त के पास शिकायत निवारण की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से संचालित होती है। सबसे पहले शिकायतकर्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र के साथ शिकायत प्रस्तुत की जाती है। इसके पश्चात लोकायुक्त कार्यालय शिकायत की प्राथमिक जांच करता है। मामले में तथ्य पाए जाने पर संबंधित लोक सेवक से उसकी टिप्पणी या स्पष्टीकरण माँगा जाता है। अंत में, संपूर्ण जांच के आधार पर लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट एवं सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित करता है।

39. (B) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
राजस्थान में लोकायुक्त के कार्यकाल का वैधानिक प्रावधान राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया है। वर्तमान नियमों के अनुसार लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले पूरी हो) तय किया गया है। वर्ष 2018 में कार्यकाल को बढ़ाकर 8

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) अनुच्छेद 315
भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 में संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत राजस्थान राज्य के लिए भी 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। यह आयोग राज्य में प्रशासनिक सेवाओं हेतु पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से योग्य अभ्यर्थियों का चयन करता है। यह एक स्वतंत्र तथा स्वायत्त संवैधानिक संस्था है।

2. (C) एक अध्यक्ष और सात सदस्य
राजस्थान लोक सेवा आयोग की शुरुआत में एक अध्यक्ष और दो सदस्य निर्धारित किए गए थे। समय के साथ प्रशासनिक कार्यों की वृद्धि और भर्तियों के सुचारु संचालन हेतु इसकी सदस्य संख्या में क्रमिक संशोधन किए गए। वर्तमान समय में स्वीकृत संरचना के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष तथा सात अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इन सभी सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह संरचना आयोग की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित बनाती है।

3. (C) एस. के. घोष
राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के समय जयपुर उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर शरद कुमार घोष (एस. के. घोष) को आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने 20 अगस्त 1949 को इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद का कार्यभार ग्रहण किया था। आयोग के प्रारंभिक चरण में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की नींव रखने में उनका योगदान सराहनीय रहा। इनके नेतृत्व में आयोग ने कार्य प्रारंभ किया।

4. (D) किसी सदस्य को कदाचार के आधार पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, परंतु उन्हें पद से हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 317 के अंतर्गत सिद्ध कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जांच के बाद राष्ट्रपति ही हटाने का आदेश जारी करते हैं। राज्यपाल को केवल जांच प्रक्रिया के दौरान संबंधित सदस्य को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए राज्यपाल सदस्यों को सीधे पद से बर्खास्त करने के लिए अधिकृत नहीं होते हैं।

5. (C) चयनित उम्मीदवारों की अंतिम नियुक्ति करना और उन्हें कार्यग्रहण पत्र जारी करना
राज्य लोक सेवा आयोग एक अनुशंसित और परामर्शदायी संस्था है। इसका मुख्य कार्य परीक्षाओं का आयोजन करना, साक्षात्कार लेना तथा उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करके राज्य सरकार को भेजना है। सफल उम्मीदवारों को अंतिम नियुक्ति प्रदान करना, पदस्थापन आदेश जारी करना तथा कार्यग्रहण पत्र देना संबंधित प्रशासनिक विभाग और राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार होता है। आयोग सीधे तौर पर नियुक्ति प्रदान करने वाला प्राधिकारी नहीं होता है।

6. (B) कम से कम आधे सदस्यों को दस वर्षों का सरकारी सेवा का अनुभव होना चाहिए।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अर्हता के संबंध में यह अनिवार्यता निर्धारित की गई है कि आयोग के कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्यों को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम दस वर्षों का प्रशासनिक या सरकारी सेवा का अनुभव होना चाहिए। शेष सदस्यों हेतु यह नियम बाध्यकारी नहीं है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी इसमें प्रतिनिधित्व मिल सके।

7. (A) केवल I और II
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिन पर विधानमंडल में मतदान नहीं होता। राज्यपाल द्वारा इनकी सेवा शर्तें निर्धारित की जाती हैं। संविधान के अनुच्छेद 319 के तहत आयोग का कोई भी सदस्य अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद उसी पद पर पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होता है, यद्यपि वह अध्यक्ष या अन्य लोक सेवा आयोगों में पद धारण कर सकता है।

8. (B) 1956
राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर में हुई थी। राज्य के पुनर्गठन के समय गठित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1956 में प्रशासनिक सुगमता और प्रशासनिक संतुलन स्थापित करने हेतु आयोग के मुख्यालय को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। तब से आयोग का मुख्य कार्यालय अजमेर में ही स्थित है, जहां से यह अपनी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का संचालन करता है।

9. (C) राजस्थान लोक सेवा आयोग
राजस्थान लोक सेवा आयोग न केवल राज्य की विभिन्न प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवाओं में सीधी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है, बल्कि राज्य सेवा के अधिकारियों की विभागीय परीक्षाओं और पदोन्नति से संबंधित प्रक्रियाओं का भी नियमन करता है। परिवीक्षाधीन अधिकारियों के स्थायीकरण और दक्षता वृद्धि के मूल्यांकन हेतु आयोग नियमित रूप से इन परीक्षाओं को आयोजित करता है, जिससे प्रशासनिक तंत्र की

Click Here to Buy book on Flipkart

128. राजस्थान में निगरानी निकायों (एसएचआरसी, एसआईसी, लोकायुक्त) के लिए एक प्रमुख प्रणालीगत चुनौती क्या है?
(A) वैधानिक समर्थन या विधायी अधिकार का पूर्ण अभाव
(B) सदस्य पदों में रिक्तियां और अपर्याप्त सहायक कर्मचारी
(C) केंद्र सरकार द्वारा अत्यधिक परिचालन हस्तक्षेप और निर्देश
(D) राज्य की राजधानी में एक स्थायी भौतिक कार्यालय भवन का न होना

129. सामान्य वैधानिक संरचना के अनुसार सूची I के निगरानी निकायों को सूची II में दिए गए उनके संबंधित रिपोर्टिंग या अपीलीय प्राधिकारी से सुमेलित कीजिए।
सूची I: निगरानी निकाय
P. राज्य सूचना आयोग
Q. राज्य निर्वाचन आयोग
R. जिला कलेक्टर (राजस्व मामले)
S. आरपीएससी
सूची II: रिपोर्टिंग / अपीलीय प्राधिकारी
1. राजस्व अपीलीय प्राधिकारी / राजस्व मंडल
2. राज्यपाल (वार्षिक रिपोर्ट)
3. उच्च न्यायालय (रिट क्षेत्राधिकार)
4. राज्यपाल / राज्य विधानमंडल (वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुति)
(A) P-3, Q-2, R-1, S-4
(B) P-4, Q-3, R-1, S-2
(C) P-2, Q-3, R-1, S-4
(D) P-4, Q-2, R-1, S-3

NODIA

130. राज्य सिविल सेवाओं की निष्ठा और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए, संविधान यह अनिवार्य करता है कि आरपीएससी के आधे सदस्यों को सरकारी सेवा में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है?
(A) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय सार्वजनिक शासन
(B) प्रशासनिक विशेषज्ञता और विषय-ज्ञान
(C) न्यायिक स्वतंत्रता और संवैधानिक शक्तियों का पृथक्करण
(D) विधायी सर्वोच्चता और कार्यपालक जवाबदेही

विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके आधिकारिक दौरों के दौरान स्थापित शिष्टाचार नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करता है।

20. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
स्वतंत्रता के बाद भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से जिला कलेक्टर की भूमिका केवल राजस्व वसूली तक सीमित न रहकर विकास केंद्रित हो गई। 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार सौंपे जाने से कई विकासात्मक योजनाएं और स्थानीय निर्णय प्रक्रियाएं सीधे तौर पर लोकतांत्रिक निकायों के अधीन आ गईं। इस प्रशासनिक बदलाव ने कलेक्टर के सीधे नियंत्रण को कम करके उसकी भूमिका को समन्वयक तथा परामर्शदाता में परिवर्तित कर दिया।

21. (C) तहसीलदार
राजस्थान के राजस्व प्रशासन में तहसीलदार जिला कलेक्टर और पटवारी के मध्य एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी प्रशासनिक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तहसील स्तर पर तहसीलदार भू-राजस्व प्रशासन, भूमि अभिलेखों के अद्यतनीकरण और पटवारियों के कार्यों के नियमित पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। वह पटवारी द्वारा प्रस्तुत राजस्व मामलों की जांच करता है और उन्हें उपखंड अधिकारी तथा जिला कलेक्टर तक पहुँचाने में मुख्य भूमिका निभाता है।

22. (B) लोक व्यवस्था बनाए रखना और निवारक निरोध कानूनों का पालन कराना
जिला कलेक्टर की दंडनायक या मजिस्ट्रेट संबंधी शक्तियां मुख्यतः जिले में लोक व्यवस्था, शांति और सुरक्षा बनाए रखने से जुड़ी हुई हैं। इसके अंतर्गत वह निरोधात्मक आदेश जारी करने, दंगा नियंत्रण के निर्देश देने, निवारक निरोध कानूनों के तहत असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा सार्वजनिक उपद्रव को रोकने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाने हेतु अधिकृत होता है। यह शक्तियां उसे जिला स्तर पर शांति व्यवस्था का संरक्षक बनाती हैं।

23. (D) यह मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सीधे दंडित कर सकता है।
राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत एक वैधानिक संस्था के रूप में गठित है। यह राज्य और समवर्ती सूची के विषयों पर मानव अधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है। हालांकि, आयोग की प्रकृति परामर्शदायी है। यह पीड़ित को मुआवजा देने या दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश तो कर सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को सीधे सजा या दंड देने का कानूनी अधिकार इसके पास नहीं है।

24. (A) उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में वर्ष 2019 में किए गए संशोधन के पश्चात राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद की योग्यता में विस्तार किया गया है। अब किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी इस पद पर नियुक्त होने के लिए पूर्णतः पात्र हैं। इस संशोधन का उद्देश्य आयोग के अध्यक्ष पद हेतु उपयुक्त एवं अनुभवी न्यायिक व्यक्तियों की उपलब्धता को सुगम बनाना है।

25. (A) P-2, Q-3, R-2, S-4
विभिन्न संवैधानिक तथा वैधानिक पदों पर नियुक्तियों हेतु निश्चित प्रक्रियाएं निर्धारित हैं। आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। लोकायुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता तथा मुख्य न्यायाधीश की चयन समिति की सिफारिश पर राज्यपाल करते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर होती है, जबकि जिला कलेक्टर की नियुक्ति राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा की जाती है।

26. (A) मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष (विपक्ष के नेता)
राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन एक उच्चस्तरीय वैधानिक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इस चयन समिति के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। समिति के अन्य सदस्यों में राज्य के गृह मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। यदि राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में हो, तो उसके सभापति और नेता प्रतिपक्ष भी इस चयन प्रक्रिया में शामिल होते हैं।

NODIA

27. (B) 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो
मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से पूर्व राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु था। हालांकि, 2019 के संशोधन द्वारा इस पदावधि को घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु (जो भी पहले पूरी हो) कर दिया गया है। इसके साथ ही, कार्यकाल की समाप्ति के बाद वे पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं, बशर्ते उनकी आयु सीमा 70 वर्ष से अधिक न हुई हो।

28. (C) न्यायमूर्ति कांता भटनागर
राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना हेतु जनवरी 1999 में अधिसूचना जारी की गई थी और मार्च 2000 में आयोग ने पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कांता भटनागर को इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनके कार्यकाल में आयोग के सांगठनिक ढांचे को मजबूती मिली और राज्य में आम जनता के मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु प्राथमिक आधारशिला रखी गई।

29. (C) नहीं, यह किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित मामलों की जांच नहीं कर सकता।
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार पर कुछ सीमाएं आरोपित की गई हैं। यदि मानवाधिकार उल्लंघन

सूची बनाने तथा समय पर चुनाव संपन्न कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी इसे सौंप दी गई।

50. (A) P-2, Q-3, R-4, S-1
विभिन्न निगरानी निकायों के प्रमुखों और सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु अलग-अलग निर्धारित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हेतु यह सीमा 70 वर्ष निर्धारित की गई है। सूचना का अधिकार संशोधन नियम 2019 के तहत राज्य सूचना आयुक्त की आयु सीमा 65 वर्ष है। राजस्थान लोकायुक्त पद के लिए भी अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है।

51. (C) राज्य के राज्यपाल
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-K(2) के प्रावधानों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्मित नियमों के तहत निर्धारित की जाती हैं। हालांकि, संविधान में स्पष्ट सुरक्षा दी गई है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के पश्चात उनकी सेवा शर्तों में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो उनके लिए अलाभकारी या अनुकूल न हो, जिससे आयोग की संवैधानिक स्वायत्तता अक्षुण्ण बनी रहे।

52. (A) P-4, Q-1, R-3, S-2
संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में प्रमुख प्रशासनिक निकायों का उल्लेख है। अनुच्छेद 243-K पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 243-ZA नगरपालिकाओं के निर्वाचनों का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 315 में संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही, अनुच्छेद 323 के अंतर्गत लोक सेवा आयोगों द्वारा अपनी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (प्रतिवेदन) राज्यपाल या राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने का प्रावधान निहित है।

53. (B) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा पारित 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' की धारा 15 के तहत की गई थी। इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए राज्य सरकार ने 13 अप्रैल 2006 को एक अधिसूचना के माध्यम से इस आयोग का औपचारिक गठन किया। यह एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, जो राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता, जन जवाबदेही और नागरिकों के सूचना पाने के अधिकार को प्रभावी बनाता है।

54. (B) एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक राज्य सूचना आयुक्त नहीं
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(2) के अनुसार राज्य सूचना आयोग का वैधानिक ढांचा निर्धारित किया गया है। आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता है तथा आवश्यकतानुसार उतने राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं जो संख्या में दस से अधिक न हों। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक विशेष चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है, ताकि जन शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण किया जा सके।

55. (A) 1, 3, 2, 4
राजस्थान की प्रमुख संस्थाओं की स्थापना का ऐतिहासिक कालक्रम इस प्रकार है: राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना सबसे पहले 1949 में हुई थी। इसके पश्चात लोकायुक्त कार्यालय का गठन वर्ष 1973 में किया गया। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की अधिसूचना 1999 में जारी हुई तथा इसने 2000 में कार्य प्रारंभ किया। सबसे अंत में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी।

56. (C) प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक तीन-सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। समिति के अन्य दो सदस्यों में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तथा मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत राज्य का एक कैबिनेट मंत्री शामिल होता है। इस प्रांतीय चयन समिति में केंद्र सरकार या किसी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है।

57. (B) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियां
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी शिकायत या अपील की जांच करते समय राज्य सूचना आयोग के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय (दीवानी अदालत) की शक्तियां निहित होती हैं। इसके तहत आयोग व्यक्तियों को समन जारी कर सकता है, दस्तावेज मंगा सकता है, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त कर सकता है और किसी भी सार्वजनिक कार्यालय से रिकॉर्ड की मांग कर सकता है, जिससे निष्पक्ष जांच हो सके।

58. (C) एम. डी. कोरानी
राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन अप्रैल 2006 में किया गया था। इस नवनिर्मित आयोग के प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रुप में एम. डी. कोरानी को नियुक्त किया गया था। उन्होंने राज्य में सूचना के अधिकार को व्यावहारिक रुप से लागू करने, नागरिकों की अपीलों के निपटारे के लिए प्रशासनिक ढांचा तैयार करने और सार्वजनिक प्राधिकरणों में पारदर्शिता तथा सुशासन की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

59. (B) I और III
राज्य सूचना आयोग सूचना देने में अनुचित देरी या इनकार करने पर दोषी लोक सूचना अधिकारी पर ₹250 प्रति दिन की दर से अधिकतम ₹25,000 तक का जुर्माना लगा सकता है। आयोग के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। इसके अलावा, आयोग केवल प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णयों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह उन मामलों में भी सीधे शिकायतें

Downloaded from www.pdf.tube

वर्ष कर दिया गया था, लेकिन वर्ष 2019 में संशोधन विधेयक पारित करके इसे पुनः घटाकर 5 वर्ष की मूल अवधि पर ला दिया गया।

40. (A) I, II और III
राजस्थान के लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक तीन-सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। लोकायुक्त के पास शिकायतों पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरु करने का अधिकार है। हालांकि, लोकायुक्त एक सिफारिशी निकाय है; इसके पास किसी लोक सेवक पर सीधे अदालत में मुकदमा चलाने या आपराधिक सजा देने की स्वतंत्र शक्ति नहीं होती है।

41. (C) राजस्थान के महालेखाकार
राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम के तहत केवल राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले जन प्रतिनिधियों और राज्य के लोक सेवकों की जांच का प्रावधान है। राजस्थान के महालेखाकार (अकाउंटेंट जनरल) भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारी होते हैं, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) तथा केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। इसलिए वे राज्य लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से पूरी तरह बाहर होते हैं और उनकी जांच लोकायुक्त नहीं कर सकता।

42. (A) मुख्यमंत्री की जांच करने में असमर्थता
केंद्रीय लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत भारत के प्रधानमंत्री को कुछ शर्तों के साथ लोकपाल की जांच के दायरे में शामिल किया गया है। इसके विपरीत, राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अंतर्गत राज्य के मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के जांच क्षेत्राधिकार से स्पष्ट रुप से बाहर रखा गया है। यह अंतर राज्य लोकायुक्त की शक्तियों की एक प्रमुख सीमा माना जाता है, जिससे उच्च राजनीतिक पदों पर जांच का दायरा सीमित हो जाता है।

43. (D) राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी)
राजस्थान में लोक सेवकों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और वित्तीय अनियमितताओं की आपराधिक जांच करने वाली प्राथमिक कार्यकारी एजेंसी राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) है। जहां लोकायुक्त एक स्वतंत्र जांच एवं सिफारिशी संस्था के रुप में कार्य करता है, वहीं एसीबी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीधे प्राथमिकी दर्ज करके, छापे मारकर, साक्ष्य जुटाकर तथा दोषियों पर अदालतों में मुकदमा चलाकर त्वरित आपराधिक कार्रवाई करती है।

44. (B) अनुच्छेद 243-K
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243-K को जोड़ा गया, जो राज्यों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसी प्रकार, शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) के चुनावों हेतु अनुच्छेद 243-ZA में प्रावधान है। राजस्थान में इन्हीं संवैधानिक अनुच्छेदों के तहत एक-सदस्यीय राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है।

NODIA

45. (D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।
संविधान के अनुच्छेद 243-K के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण नहीं करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद की सुरक्षा प्राप्त है और उसे केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद द्वारा हटाया जाता है। अतः राज्यपाल उन्हें अपनी इच्छा से स्वेच्छापूर्वक पदमुक्त नहीं कर सकते हैं।

46. (D) पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कराना
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्य जनादेश राज्य में पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) तथा शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम) के निष्पक्ष और समयबद्ध चुनावों का संचालन करना है। यह आयोग इन स्थानीय निकायों हेतु मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए पूर्णतः संवैधानिक रुप से उत्तरदायी होता है।

47. (A) अमर सिंह राठौड़
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जुलाई 1994 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद की गई थी। इस नवगठित आयोग के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त के रुप में अमर सिंह राठौड़ को नियुक्त किया गया था। उन्होंने राज्य में पंचायती राज और नगर निकायों के सुचारु चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष स्थानीय लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली की सशक्त नींव रखी।

48. (D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।
राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग एक एकल-सदस्यीय निकाय है, जिसमें केवल राज्य निर्वाचन आयुक्त ही मुख्य प्राधिकारी होता है। भारत निर्वाचन आयोग के विपरीत, जो एक बहु-सदस्यीय निकाय है, राज्य स्तर पर केवल एक ही आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। हालांकि प्रशासनिक कार्यों में सहायता हेतु राज्य सरकार द्वारा एक सचिव तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं, जो चुनाव प्रक्रिया के सफल संपादन में सहयोग करते हैं।

49. (C) 1994
भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के लागू होने के पश्चात राज्यों में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने हेतु स्वतंत्र तंत्र का गठन अनिवार्य किया गया। इसी अनुपालन में राजस्थान में 1 जुलाई 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग की औपचारिक स्थापना की गई। आयोग के गठन के साथ ही राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं की मतदाता

कुशलता और कार्यक्षमता में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

10. (B) केवल I और III
राजस्थान लोक सेवा आयोग एक सलाहकारी संस्था है। यद्यपि राज्य सरकार को सिविल सेवाओं में भर्ती की पद्धतियों, पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों पर आयोग से परामर्श करना अनिवार्य होता है, परंतु आयोग द्वारा दी गई सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसे नियम बना सकते हैं जिनके तहत कुछ विशिष्ट प्रशासनिक विषयों को आयोग के परामर्शदायी दायरा से बाहर रखा जा सकता है।

11. (A) रिक्तियों की अधिसूचना, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, सरकार को अनुशंसा
राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवाओं में चयन हेतु एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया का प्रथम चरण संबंधित विभागों से प्राप्त रिक्तियों की औपचारिक अधिसूचना जारी करना होता है। इसके उपरांत योग्य अभ्यर्थियों हेतु प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसके बाद सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाता है और अंत में आयोग योग्य अभ्यर्थियों की सूची सरकार को भेजता है।

12. (B) सार्वजनिक शांति बनाए रखना और जिला पुलिस बल का पर्यवेक्षण करना
राजस्थान में जिला कलेक्टर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा अन्य कानूनों के तहत जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है। इस भूमिका में उनका मुख्य उत्तरदायित्व जिले में कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक शांति और सौहार्द बनाए रखना होता है। वह दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निरोधात्मक आदेश जारी करने, जुलूसों का नियमन करने तथा जिला पुलिस बल के कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण करने की शक्ति रखते हैं ताकि जिले में आंतरिक सुरक्षा बनी रहे।

13. (C) आयुध अधिनियम, 1959
आयुध अधिनियम, 1959 तथा उसके तहत बने नियमों के अंतर्गत जिला कलेक्टर को जिले के भीतर शस्त्र लाइसेंस जारी करने, उनका नवीनीकरण करने तथा उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस रद्द करने का अधिकार प्राप्त है। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कलेक्टर नागरिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आवेदकों की पृष्ठभूमियों की जांच करवाता है। इसके पश्चात ही विवेकपूर्ण निर्णय लेकर पात्र व्यक्तियों को हथियार रखने की आधिकारिक स्वीकृति दी जाती है।

14. (D) केंद्रीय और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों
लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय निकायों के चुनावों के दौरान जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। इस क्षमता में वह भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों के वैधानिक दिशा-निर्देशों तथा प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत कार्य करता है। वह जिले में मतदाता सूचियों को अद्यतन करने, मतदान केंद्रों की व्यवस्था करने और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए सीधे निर्वाचन आयोगों के प्रति उत्तरदायी होता है।

15. (A) I, II और III
राजस्थान में जिला कलेक्टर जिले का शीर्ष राजस्व अधिकारी होता है। वह जिला स्तर पर सर्वोच्च राजस्व अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है तथा भू-राजस्व एवं अन्य बकाया सरकारी करों की वसूली के लिए उत्तरदायी होता है। प्राकृतिक आपदाओं के समय फसलों के नुकसान का आकलन करना और राहत कोष का वितरण कराना भी उसकी जिम्मेदारी है। हालाँकि, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार केवल राज्य विधानमंडल एवं संसद के पास होता है।

16. (B) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिला कलेक्टर इस प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। प्राकृतिक आपदा या आपातकालीन स्थिति के दौरान राहत, बचाव, पुनर्वास और संसाधनों के समन्वय का संपूर्ण दायित्व कलेक्टर के कंधों पर होता है। वह विभिन्न सरकारी विभागों और राहत एजेंसियों के बीच त्वरित तालमेल बनाकर आपदा जोखिम को कम करता है।

17. (B) संभागीय आयुक्त
राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जिलों को विभिन्न संभागों में विभाजित किया गया है। संभागीय आयुक्त अपने संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के प्रशासन, राजस्व संग्रह और विकास कार्यों का वरिष्ठ स्तर पर पर्यवेक्षण करता है। जिला कलेक्टर प्रशासनिक रूप से संभागीय आयुक्त के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करता है। संभागीय आयुक्त जिला कलेक्टरों की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करता है तथा अंतर-जिला समन्वय सुनिश्चित करता है।

18. (A) गंभीर अपराधियों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी करना
जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कानून-व्यवस्था बनाए रखना कलेक्टर का प्राथमिक दायित्व है। वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर सकता है, पुलिस थानों एवं जेलों का निरीक्षण कर सकता है तथा सरकार को आपराधिक रिपोर्ट भेज सकता है। परंतु गंभीर अपराधियों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी करने का अधिकार विशेष रूप से न्यायिक दंडाधिकारी अथवा आपराधिक अदालतों के पास निहित होता है, जो न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में आता है।

19. (C) जिले में अति विशिष्ट व्यक्तियों और राज्य के अतिथियों के दौरों के लिए मुख्य शिष्टाचार अधिकारी
जिले के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में जिला कलेक्टर मुख्य शिष्टाचार (प्रोटोकॉल) अधिकारी की भूमिका निभाता है। जिले में आने वाले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा अन्य अति विशिष्ट अतिथियों या राज्य के मेहमानों की सुरक्षा, आवास, परिवहन और आधिकारिक कार्यक्रमों का सुचारु प्रबंधन कलेक्टर की देखरेख में किया जाता है। वह सभी

Click Here to Buy book on Amazon

प्राप्त कर सकता है जहाँ लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति ही नहीं की गई हो।

60. (A) केंद्र सरकार
सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने के पश्चात राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें निर्धारित करने की शक्ति केंद्र सरकार को सौंप दी गई है। इस संशोधन से पूर्व इनके वेतन-भत्ते चुनाव आयुक्तों के समान वैधानिक रूप से तय थे, परंतु अब केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों के आधार पर ही इनकी सेवा शर्तों का नियमन किया जाता है।

61. (D) राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
राजस्थान में राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग और लोकायुक्त का कार्यालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार नियंत्रण करने वाले पर्यवेक्षी एवं निगरानी निकाय हैं। इसके विपरीत, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक कार्यकारी भर्ती एजेंसी है जिसका प्राथमिक कार्य गैर-राजपत्रित और अधीनस्थ पदों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना है। अतः कार्यप्रणाली और उद्देश्य की दृष्टि से कर्मचारी चयन बोर्ड अन्य तीनों से भिन्न है।

62. (B) नागरिक शिकायतों को दर्ज करने और निवारण के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करना
राजस्थान संपर्क पोर्टल राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख ई-गवर्नेंस पहल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य के नागरिकों को अपनी प्रशासनिक शिकायतों को दर्ज कराने और उनके समयबद्ध निवारण हेतु एक एकीकृत, पारदर्शी और केंद्रीकृत मंच प्रदान करना है। नागरिक इस ऑनलाइन पोर्टल या टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 181 के माध्यम से सरकारी विभागों से जुड़ी समस्याओं की शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उनकी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं।

63. (B) लोकायुक्त की सहायता करना और उनके द्वारा सौंपे गए जांच कार्यों को संचालित करना
राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में उप-लोकायुक्त की नियुक्ति का वैधानिक प्रावधान शामिल है। उप-लोकायुक्त का प्राथमिक कार्य लोकायुक्त के कार्यों में सहायता करना और लोकायुक्त द्वारा सौंपे गए विशिष्ट प्रशासनिक या भ्रष्टाचार संबंधी जांच मामलों का संचालन करना होता है। उप-लोकायुक्त कोई स्वतंत्र अपीलीय संस्था नहीं है, बल्कि वह लोकायुक्त के समग्र मार्गदर्शन और प्रशासनिक नियंत्रण में ही अपने शासकीय कर्तव्यों का निष्पादन करता है।

64. (C) 5 वर्ष
राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम के अनुसार लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराने की एक निश्चित वैधानिक समय सीमा तय की गई है। शिकायतकर्ता को जिस तिथि को शिकायत के आधारभूत तथ्य या कार्रवाई की जानकारी प्राप्त होती है, उस तिथि से 5 वर्षों के भीतर ही लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज करानी होती है। 5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों पर लोकायुक्त द्वारा सामान्यतः विचार या जांच शुरू नहीं की जाती है।

65. (A) I, II और III
आरपीएससी अध्यक्ष और राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष दोनों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, परंतु उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया वही है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। लोकायुक्त को राज्यपाल सीधे बर्खास्त नहीं कर सकते; उन्हें पदमुक्त करने के लिए विधानमंडल में विशेष प्रस्ताव पारित होने तथा जांच की आवश्यकता होती है।

66. (B) स्कैंडिनेवियाई लोकपाल (ऑम्बुड्समैन) प्रणाली
भारत में लोकायुक्त और लोकपाल की अवधारणा मुख्य रूप से स्वीडन तथा अन्य स्कैंडिनेवियाई देशों में प्रचलित 'ऑम्बुड्समैन' प्रणाली से ली गई है। 1809 में स्वीडन में स्थापित यह प्रणाली नागरिकों को प्रशासनिक अतिचार, कुप्रशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक स्वतंत्र शिकायत निवारण मंच प्रदान करती है। इसी मॉडल के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु लोकायुक्त संस्थाओं का वैधानिक गठन किया गया।

67. (A) I, II और III
राजस्थान में नागरिक केंद्रित सुशासन हेतु 'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम' 2011 में तथा 'राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम' 2012 में लागू किया गया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 भी राजस्थान संपर्क पोर्टल से एकीकृत है। हालांकि, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग आम नागरिकों की शिकायतों के लिए होता है; सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों और विभागीय मामलों का निवारण इस पोर्टल के बजाय संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा किया जाता है।

NODIA

68. (D) अधिनियम में कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं है
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के लिए अपील का निस्तारण करने हेतु 30 से 45 दिनों की निश्चित समय सीमा का प्रावधान किया गया है। परंतु, अधिनियम की धारा 19 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा द्वितीय अपील का निपटारा करने के लिए कोई विशिष्ट या बाध्यकारी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आयोग अपीलों का निस्तारण अपने आंतरिक कार्यबोझ और प्राथमिकताओं के आधार पर करता है।

69. (C) राज्य सरकार (स्वायत्त शासन और पंचायती राज विभाग)
राजस्थान में नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से पूर्व वार्डों का भौगोलिक परिसीमन और संरचनात्मक पुनर्निर्धारण करने का अधिकार राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग तथा पंचायती राज विभाग के पास होता है। राज्य निर्वाचन आयोग परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात तैयार की गई वार्ड संरचना के आधार पर मतदाता सूचियाँ अद्यतन करता है और चुनाव आयोजित करता है, परंतु परिसीमन का मूल कार्य राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है।

70. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों के माध्यम से जोड़े गए अनुच्छेद 243-K और 243-ZA के तहत राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। यह भारत निर्वाचन आयोग का अधीनस्थ कार्यालय नहीं है और न ही उसके नियंत्रण में आता है। राज्य निर्वाचन आयोग अपनी शक्तियाँ सीधे संविधान से प्राप्त करता है और स्थानीय निकायों के चुनावों के संचालन में पूरी तरह स्वायत्त होता है।

71. (B) राज्य विधानमंडल
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा किए गए कार्यों का एक वार्षिक प्रतिवेदन (रिपोर्ट) राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य सरकार के उस ज्ञापन के साथ, जिसमें आयोग की सलाह न मानने के कारणों का उल्लेख होता है, राज्य विधानमंडल (विधानसभा) के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं, जहाँ इस पर समीक्षा और विधायी चर्चा की जाती है।

72. (B) पुलिस अधीक्षक (एसपी)
जिले में पुलिस प्रशासन का ढांचा सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु पुलिस अधीक्षक (एसपी) को जिला पुलिस बल का मुख्य प्रशासनिक और परिचालन प्रमुख बनाया जाता है। वह जिला स्तर पर पुलिस बल के अनुशासन, आंतरिक प्रबंधन, अपराध रोकथाम, थानों के पर्यवेक्षण और बल के दैनिक संचालन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। भारतीय पुलिस सेवा का यह अधिकारी जिले की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का नेतृत्व करता है।

73. (C) जिला मजिस्ट्रेट
पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 4 के अनुसार जिला पुलिस बल का कमान और नियंत्रण पुलिस अधीक्षक में निहित होता है, परंतु उसे जिला मजिस्ट्रेट (जिला कलेक्टर) के सामान्य नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण के तहत कार्य करना पड़ता है। जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के अंतिम उत्तरदायित्व के कारण जिला मजिस्ट्रेट को पुलिस प्रशासन पर सामान्य पर्यवेक्षी अधिकार प्राप्त हैं, जिससे नागरिक और पुलिस प्रशासन में संतुलन बना रहे।

74. (D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य सिविल सेवाओं को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाना और निष्पक्षता बनाए रखना है। हालांकि, सिविल सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामलों में आयोग द्वारा दी गई सलाह राज्य सरकार के लिए परामर्शदायी प्रकृति की होती है, बाध्यकारी नहीं। सरकार आयोग की सिफारिश से असहमत हो सकती है, लेकिन उसे अपनी असहमति का स्पष्ट कारण राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।

75. (A) P-2, Q-3, R-4, S-1
राजस्थान के प्रमुख संगठनों के प्रथम प्रमुखों का सही सुमेल इस प्रकार है: राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष न्यायमूर्ति कांता भटनागर थीं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त एम. डी. कोरानी बने। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त अमर सिंह राठौड़ थे। इसके अलावा, राजस्थान के पहले लोकायुक्त के रूप में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आई. डी. दुआ को नियुक्त किया गया था।

76. (A) राज्य कार्यकारी समिति
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस प्राधिकरण को अपने कार्यों के निष्पादन, आपातकालीन तैयारियों और आपदा नीतियों के क्रियान्वयन में प्रशासनिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति गठित की जाती है। यह समिति विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करके आपदा मोचन का संचालन करती है।

77. (D) आरपीएससी नियमों द्वारा विनियमित; कोई संवैधानिक गणपूर्ति निर्धारित नहीं है
भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोगों की बैठकों के संचालन के लिए किसी विशिष्ट न्यूनतम गणपूर्ति (कोरम) का उल्लेख नहीं किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की बैठकों और कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति का निर्धारण आयोग के अपने आंतरिक नियमों तथा विनियमों द्वारा किया जाता है। आयोग के अध्यक्ष अपनी सुविधानुसार बैठकों का आयोजन करते हैं और आन्तरिक नियमों के तहत ही निर्णयों को अंतिम रूप दिया जाता है।

78. (B) अनुच्छेद 226
राजस्थान में लोकायुक्त एक वैधानिक और सिफारिशी संस्था है। यदि लोकायुक्त की किसी जांच रिपोर्ट, सिफारिश या प्रतिकूल टिप्पणी से कोई लोक सेवक या व्यक्ति व्यथित होता है, तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकता है। उच्च न्यायालय अपने असाधारण न्यायिक क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए लोकायुक्त के आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है और राहत प्रदान कर सकता है।

79. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
विभिन्न संस्थाएं अपने विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों का संचालन करती हैं। पंचायती राज संस्थाओं के स्वतंत्र चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच लोकायुक्त द्वारा की जाती है। समय पर सूचना न देने पर जुर्माने की शक्ति राज्य सूचना आयोग में निहित है, जबकि हिरासत में उत्पीड़न के मामलों में पीड़ित को वित्तीय राहत की सिफारिश राज्य मानव अधिकार आयोग करता है।

Downloaded from www.pdf.tube

80. (A) पटवारी, गिरदावर (राजस्व निरीक्षक), नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी (एसडीओ), जिला कलेक्टर
राजस्थान के जिला राजस्व प्रशासन में पदानुक्रम का सही आरोही क्रम (निम्नतम से उच्चतम) इस प्रकार है: सबसे निचले स्तर पर पटवारी होता है, जिसके ऊपर गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) कार्य करता है। इसके पश्चात नायब तहसीलदार, तहसीलदार और उपखंड अधिकारी (एसडीओ) आते हैं। राजस्व प्रशासन का शीर्ष पद जिला कलेक्टर का होता है। यह पदानुक्रमित संरचना राज्य में भू-अभिलेखों के रखरखाव और राजस्व वसूली को सुव्यवस्थित बनाती है।

81. (B) जिला कलेक्टर
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा 1951 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के रूप में नामित किया जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कलेक्टर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों की स्थापना, चुनाव अधिकारियों की तैनाती, सुरक्षा व्यवस्था तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होता है।

82. (B) ऐसी सूचना जिससे संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होता हो
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 में उन अपवादों की सूची दी गई है जिनके तहत सूचना प्रकट करने से छूट प्राप्त है। धारा 8(1)(c) के अनुसार ऐसी कोई भी जानकारी, जिसके प्रकटीकरण से भारत की संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होता हो, नागरिकों को प्रदान नहीं की जा सकती। राज्य सूचना आयोग ऐसे मामलों में सार्वजनिक निकायों को सूचना देने से छूट प्रदान करता है।

83. (C) लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, राज्य सूचना आयोग
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने की एक क्रमिक प्रक्रिया है। नागरिक सर्वप्रथम संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के पास आवेदन जमा करता है। सूचना न मिलने या असंतुष्ट होने पर 30 दिनों के भीतर विभाग के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जाती है। यदि प्रथम अपील में भी राहत न मिले, तो अंतिम चरण के रूप में राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की जाती है।

84. (B) सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामान्य जन शिकायतों की देखरेख करने वाली समितियां
राजस्थान में जिला स्तर पर गठित 'जिला सतर्कता समितियां' मुख्य रूप से आम नागरिकों की शिकायतों के निवारण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के सुचारू संचालन की देखरेख करती हैं। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्य करने वाली ये समितियाँ राशन वितरण में अनियमितताओं, प्रशासनिक देरी और आम जनता को होने वाली समस्याओं को हल करने का कार्य करती हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर सुशासन और पारदर्शिता बनी रहे।

85. (B) II और III
राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय चुनावों के संचालन में पूरी तरह स्वतंत्र है और भारत निर्वाचन आयोग के अधीन नहीं आता। हालांकि, यदि राज्य के राज्यपाल अनुरोध करें और राष्ट्रपति स्वीकृति दें, तो संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) संयुक्त भर्ती योजनाओं में राज्य आयोग की सहायता कर सकता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अंतर-आयोग समन्वय के तहत किसी मानवाधिकार उल्लंघन के मामले को राज्य मानव अधिकार आयोग को स्थानांतरित कर सकता है।

86. (B) भारत निर्वाचन आयोग
भारत में नागरिकों के लिए 'मतदाता पहचान पत्र' (एपिक कार्ड) जारी करने और राष्ट्रीय मतदाता सूची तैयार करने का एकाधिकार भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के पास है। यद्यपि राज्य स्तर पर जिला कलेक्टर और प्रशासनिक मशीनरी इस कार्य को संपादित करती है, परंतु यह पूरी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के प्रत्यक्ष संवैधानिक अधिकार और पर्यवेक्षण के अंतर्गत ही पूरी की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग केवल स्थानीय निकायों के चुनाव कराता है।

87. (B) केवल I और III
राजस्थान लोक सेवा आयोग की वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिन पर विधानमंडल में मतदान नहीं होता है। हालांकि, आयोग का वार्षिक प्रशासनिक बजट और कार्यालय संचालन व्यय राज्य विधानमंडल की बजटीय स्वीकृति और मतदान के अधीन होता है। यह संवैधानिक व्यवस्था आयोग को निष्पक्षता से कार्य करने का आधार प्रदान करती है।

88. (D) राज्य आयोग में पदेन सदस्यों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के अध्यक्षों को पदेन सदस्य का दर्जा प्राप्त है। इसके विपरीत, राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) की वैधानिक संरचना में पदेन सदस्यों का ऐसा कोई संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान नहीं किया गया है। राज्य आयोग केवल अपने नियुक्त अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों से मिलकर बनता है।

89. (B) राजस्थान के राज्यपाल
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार, राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य के खिलाफ सिद्ध कदाचार के आरोपों की जांच जब उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा रही होती है, तो उस जांच अवधि के दौरान संबंधित सदस्य को पद से निलंबित करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल के पास होता है। यद्यपि अंतिम निष्कासन केवल राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, परंतु निलंबन का अंतरिम आदेश राज्यपाल जारी करते हैं।

NODIA

के आसानी से पदमुक्त नहीं किया जा सकता। यह स्वतंत्रता आयोग को बाहरी राजनीतिक या प्रशासनिक दबावों से मुक्त होकर निष्पक्षता से कार्य करने का आधार देती है।

110. (A) I और II
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत शिकायतों और अपीलों की जांच करते समय राज्य सूचना आयोग के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं। आयोग गवाहों को समन जारी कर सकता है, शपथ पत्र पर मौखिक या लिखित साक्ष्य ले सकता है तथा किसी भी विभाग से गोपनीय फाइलों और दस्तावेजों के प्रकटीकरण एवं निरीक्षण की मांग कर सकता है। हालांकि, आयोग उच्च न्यायालय के न्यायिक फैसलों की समीक्षा या उन्हें बदलने का अधिकार नहीं रखता।

111. (C) अत्यंत गंभीर कानून और व्यवस्था की स्थितियों में मृत्युदंड देने की पूर्ण न्यायिक शक्तियां जिला कलेक्टर के पास होती हैं।
राजस्थान में जिला कलेक्टर जिला प्रशासन का मुख्य स्तंभ है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और विभिन्न विभागों का समन्वय करता है। हालांकि, भारत में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार कलेक्टर के पास मृत्युदंड देने जैसी कोई न्यायिक शक्ति नहीं होती। मृत्युदंड या गंभीर आपराधिक सजा देने का अधिकार केवल स्वतंत्र न्यायपालिका अर्थात सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास ही सुरक्षित होता है।

112. (B) I और III
राज्य निर्वाचन आयोग का प्राथमिक संवैधानिक कार्य पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के लिए स्वतंत्र चुनाव कराना, उनकी मतदाता सूची तैयार करना और निर्दलीय व स्थानीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना है। इसके विपरीत, विधानसभा सीटों का भौगोलिक परिसीमन करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार द्वारा गठित स्वतंत्र परिसीमन आयोग के पास होती है, न कि राज्य निर्वाचन आयोग के पास। अतः परिसीमन का कार्य इस आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

113. (B) अधिनियम के तहत नामित प्रथम और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत यदि कोई पदनाम अधिकारी तय सीमा के भीतर अधिसूचित सेवा प्रदान करने में विफल रहता है, तो नागरिक के पास अधिनियम के तहत गठित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का अधिकार होता है। द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी दोषी अधिकारी पर वित्तीय जुर्माना लगा सकता है तथा सेवा में देरी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।

114. (B) भर्ती अनुभाग
राजस्थान लोक सेवा आयोग का भर्ती अनुभाग लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के बाद सफल उम्मीदवारों के शैक्षणिक दस्तावेजों, जाति प्रमाण पत्रों, आयु तथा पात्रता की विस्तृत जांच और सत्यापन का कार्य संभालता है। यह अनुभाग विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों की अर्हता सुनिश्चित करता है और अंतिम रूप से पात्र पाए गए योग्य उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार करके राज्य सरकार के संबंधित विभागों को प्रेषित करने का कार्य करता है।

115. (A) 1, 3, 4, 2
राजस्थान के प्रशासनिक पदानुक्रम का सही अवरोही क्रम (उच्चतम से निम्नतम) इस प्रकार है: राज्य स्तर पर प्रशासनिक तंत्र का सर्वोच्च अधिकारी मुख्य सचिव होता है। इसके पश्चात संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त प्रशासनिक देखरेख करता है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जबकि उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी (एसडीओ/एसडीएम) कार्य करता है। यह ढांचा राज्य में सुचारु शासन संचालन सुनिश्चित करता है।

116. (B) एसआईसी के निर्णय जुर्माना शक्तियों के साथ बाध्यकारी हैं; एसएचआरसी की सिफारिशें सलाहकारी हैं
राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) और राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) में मुख्य अंतर यह है कि एसआईसी के निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं तथा उसके पास दोषी अधिकारियों पर ₹25,000 तक का जुर्माना लगाने की वैधानिक शक्ति होती है। इसके विपरीत, एसएचआरसी मुख्यतः एक सिफारिशी निकाय है जिसकी सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और वह सीधे तौर पर जुर्माना लगाने या सजा देने के लिए अधिकृत नहीं होता है।

117. (D) आरटीआई अधिनियम के तहत समिति में रिक्तियों के कारण नियुक्तियां अमान्य नहीं होती हैं
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(6) में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली चयन समिति में किसी सदस्य का पद रिक्त होने मात्र से नियुक्ति प्रक्रिया अमान्य नहीं मानी जाएगी। यदि चयन समिति के तीन सदस्यों में से कोई पद रिक्त है, तब भी उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति या बहुमत से की गई सिफारिश वैध मानी जाती है।

118. (A) I, II और III
राजस्थान में प्रशासनिक निगरानी तंत्र को मजबूत करने हेतु हाल के वर्षों में कई तकनीकी सुधार किए गए हैं। राज्य सूचना आयोग में अपीलों की ऑनलाइन ई-फाइलिंग सुविधा शुरु की गई है तथा एसएचआरसी और एसआईसी की सुनवाइयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग बढ़ रहा है। साथ ही राजस्थान संपर्क पोर्टल एकीकृत मंच प्रदान करता है। हालांकि, लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है; यह अभी भी एक वैधानिक निकाय ही है।

119. (A) समय सीमा के भीतर शिकायतों की सुनवाई के लिए नागरिकों का कानूनी अधिकार
'राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012' का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की प्रशासनिक शिकायतों और समस्याओं की समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम नागरिकों को एक कानूनी अधिकार प्रदान करता है जिसके तहत ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक गठित

Click Here to Buy book on Flipkart

अलग से सरकारी वकील की स्थायी आवश्यकता नहीं होती है, जब तक कि राज्य का प्रत्यक्ष वित्तीय हित प्रभावित न हो।

100. (A) P-2, Q-3, R-4, S-1
निगरानी निकायों से जुड़ी शब्दावलियों का सही अर्थ इस प्रकार है: स्वतः संज्ञान का तात्पर्य किसी प्राधिकारी द्वारा किसी घटना पर स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई करना है। पदेन का अर्थ किसी मुख्य पद पर होने के कारण स्वतः दूसरा पद धारण करना है। गणपूर्ति का अर्थ किसी बैठक के संचालन हेतु न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या है। परमादेश एक अदालती रिट है जो किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को उसके कानूनी कर्तव्य पालन का आदेश देती है।

101. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग एक-दूसरे के अधीनस्थ निकाय नहीं हैं। दोनों आयोग अपने-अपने क्षेत्राधिकार में पूरी तरह स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। केंद्रीय आयोग केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों से जुड़ी अपीलों की सुनवाई करता है, जबकि राज्य सूचना आयोग केवल राज्य सरकार के विभागों से संबंधित मामलों को देखता है। अतः राज्य आयोग केंद्रीय आयोग के फैसलों के खिलाफ अपीलीय मंच नहीं है।

102. (B) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक आईएएस अधिकारी होते हैं
राजस्थान लोक सेवा आयोग का सचिव आयोग का मुख्य कार्यपालक और प्रशासनिक अधिकारी होता है। सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारियों में से की जाती है। सचिव आयोग के दैनंदिन प्रशासनिक कार्यों, पत्राचार, परीक्षाओं के आयोजन और आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के निष्पादन का प्रबंधन करता है। वह आयोग की संवैधानिक बैठकों और प्रशासनिक तंत्र के मध्य एक मुख्य समन्वयकारी कड़ी के रूप में कार्य करता है।

103. (A) अनुचित प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण होने वाला अन्याय या कठिनाई
राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत "कुप्रशासन" शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत लोक सेवकों द्वारा की गई ऐसी कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई या प्रक्रिया शामिल है जो पक्षपातपूर्ण, अनुचित, अत्यधिक विलंबकारी या उपेक्षापूर्ण हो और जिसके कारण किसी नागरिक को अकारण अन्याय, मानसिक प्रताड़ना या कठिनाई का सामना करना पड़ा हो। यह केवल वित्तीय भ्रष्टाचार तक सीमित न होकर प्रशासनिक अकर्मण्यता को भी कवर करता है।

104. (B) राज्य सरकार पर वित्तीय और कर्मचारियों की निर्भरता
राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की प्रभावशीलता के समक्ष एक प्रमुख प्रणालीगत चुनौती राज्य सरकार पर इसकी अत्यधिक वित्तीय और प्रशासनिक निर्भरता है। आयोग के पास अपने स्वतंत्र कैडर के जांच अधिकारी और पर्याप्त बजट नहीं होता, जिसके कारण इसे कर्मचारियों की तैनाती और जांच व्यवस्था हेतु राज्य पुलिस तथा प्रशासनिक तंत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। यह निर्भरता कभी-कभी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की गति को बाधित करती है।

105. (A) 1, 3, 4, 2
राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत निवारण का क्रमबद्ध चरण इस प्रकार संचालित होता है: सर्वप्रथम नागरिक अपनी समस्या को पोर्टल पर दर्ज करता है। इसके बाद प्रणाली द्वारा शिकायत स्वतः संबंधित विभागीय अधिकारी को हस्तांतरित कर दी जाती है। संबंधित अधिकारी शिकायत की जांच करके आवश्यक समाधान करता है और पोर्टल पर स्थिति को अद्यतन करता है। अंत में शिकायत को निस्तारित मानकर बंद किया जाता है और नागरिक से फीडबैक प्राप्त किया जाता है।

106. (B) 1994
राजस्थान में 73वें संविधान संशोधन के लागू होने से पूर्व पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का संचालन राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता था। 1992 के संवैधानिक संशोधन के पश्चात स्थानीय निकायों के स्वतंत्र चुनाव हेतु संवैधानिक आवश्यकता उत्पन्न हुई। इसके अनुपालन में जुलाई 1994 में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और तब से पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के चुनावों का संपूर्ण संचालन इस आयोग द्वारा किया जाने लगा।

107. (C) मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे कई राज्य
भारत के विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त कानूनों के दायरे में भिन्नता पाई जाती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के जांच क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। इसके विपरीत मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे कई भारतीय राज्यों ने अपने लोकायुक्त अधिनियमों में संशोधन करके मुख्यमंत्री पद को भी लोकायुक्त की जांच के दायरे में शामिल किया है, जिससे उच्च राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

108. (B) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा की अपनी उत्तर पुस्तिका (ओएमआर शीट) की प्रति प्राप्त करना चाहता है, तो वह 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' के वैधानिक प्रावधानों का प्रयोग कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों को अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण करने और उनकी प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने का कानूनी अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त है।

109. (B) इसकी स्वायत्त संवैधानिक स्थिति और सदस्यों के कार्यकाल की सुरक्षा
राजस्थान लोक सेवा आयोग के निर्णयों और भर्ती प्रक्रियाओं की उच्च विश्वसनीयता का मुख्य कारण इसकी संवैधानिक स्वायत्तता है। संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत गठित इस निकाय के सदस्यों को अनुच्छेद 317 के माध्यम से कार्यकाल की विशेष सुरक्षा प्राप्त है, जिससे उन्हें बिना कठिन जांच प्रक्रिया

Downloaded from www.pdf.tube

90. (C) I, II, III और IV
राजस्थान लोकायुक्त संस्था की अपनी निश्चित सीमाएं हैं। यह बेनामी शिकायतों पर संज्ञान नहीं ले सकता और इसके पास अपनी सिफारिशों को बाध्यकारी रुप से लागू कराने की शक्ति नहीं है। लोकायुक्त के दायरे से पूर्व मुख्यमंत्रियों तथा वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों को बाहर रखा गया है। इसके अलावा, यह अदालतों की न्यायिक कार्यवाहियों और फैसलों की समीक्षा या जांच नहीं कर सकता, जिससे इसकी शक्तियाँ केवल सलाहकारी और सीमित जांच तक ही रहती हैं।

91. (B) योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर सिविल सेवकों की पदोन्नति के लिए सिफारिश करना
विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) का प्राथमिक उद्देश्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया का निष्पक्ष संचालन करना है। इस समिति में राजस्थान लोक सेवा आयोग का एक प्रतिनिधि या सदस्य शामिल होता है। समिति कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन, सेवा रिकॉर्ड, वरिष्ठता और योग्यता का पारदर्शी मूल्यांकन करके पदोन्नति हेतु योग्य अधिकारियों के नामों की सिफारिश राज्य सरकार से करती है।

92. (D) राज्य निर्वाचन आयोग — चुनाव याचिकाओं का निर्णय करना
राज्य निर्वाचन आयोग का प्राथमिक कार्य पंचायती राज और नगर निकायों के चुनावों का संचालन, अधीक्षण और मतदाता सूची तैयार करना है। हालांकि, चुनाव संपन्न होने के बाद चुनावी विवादों और चुनाव याचिकाओं का निपटारा करना राज्य निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, बल्कि यह अधिकार संबंधित जिला अदालतों तथा उच्च न्यायालय के पास निहित होता है। अन्य सभी संस्थाएं अपने वर्णित प्राथमिक उद्देश्यों के साथ पूरी तरह मेल खाती हैं।

93. (D) I, II, III और IV
राजस्थान में जिला कलेक्टर बहुआयामी प्रशासनिक भूमिका निभाता है। वह जिले का शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ-साथ जिला जनगणना अधिकारी के रुप में कार्य करता है और जाति तथा मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत है। इसके अलावा वह जिला क्रेडिट योजना के समन्वय और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के पदेन अध्यक्ष के रूप में जिले के समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास का कुशल नेतृत्व करता है।

94. (B) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को संस्थागत रुप देना
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों को प्रदान की गई वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में सूचना प्राप्त करने का अधिकार अंतर्निहित माना गया है। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आलोक में शासन में पारदर्शिता लाने और नागरिकों के इस मौलिक अधिकार को संस्थागत रूप देने हेतु 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग की स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई।

95. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 36(2) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि राज्य मानव अधिकार आयोग किसी भी ऐसी घटना की जांच नहीं कर सकता जिसे घटित हुए एक वर्ष से अधिक बीत चुका हो। समय बीत जाने से साक्ष्य की सत्यता प्रभावित होती है और पुरानी शिकायतों पर कानूनी कार्यवाही करना कठिन होता है। इसलिए अधिनियम में यह वैधानिक सीमा तय की गई है ताकि समयबद्ध जांच संभव हो सके।

96. (B) सलाहकारी हैं, लेकिन अस्वीकृति की स्थिति में विधानसभा में एक स्पष्टीकरण ज्ञापन रखना आवश्यक है
राजस्थान लोकायुक्त द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित सिफारिशें परामर्शदायी प्रकृति की होती हैं और वे कार्यपालिका पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं। हालांकि, अधिनियम के अनुसार यदि राज्य सरकार लोकायुक्त की किसी सिफारिश को अस्वीकार करती है या लागू नहीं करती है, तो सरकार को असहमति के स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए एक विवरण ज्ञापन राज्य विधानमंडल (विधानसभा) के पटल पर रखना अनिवार्य होता है, जिससे विधायी जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

97. (B) जिला स्तर पर राज्य और केंद्रीय विकास योजनाओं के लिए मुख्य समन्वयक
आधुनिक समय में जिला कलेक्टर की भूमिका केवल कर संग्रह तक सीमित न रहकर विकास प्रशासन की ओर स्थानांतरित हो गई है। वर्तमान में कलेक्टर जिला स्तर पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों, गरीबी उन्मूलन योजनाओं और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का मुख्य समन्वयक होता है। वह विभिन्न सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है।

98. (A) संविधान या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं द्वारा गारंटीकृत जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(1)(d) में "मानव अधिकार" की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार मानव अधिकारों से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत गरिमा से संबंधित हैं तथा जो भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत हैं या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में समाहित हैं और भारत में अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग इन्हीं मूल अधिकारों की सुरक्षा का कार्य करता है।

NODIA

99. (D) राज्य के वकील की आवश्यकता नहीं है; अधिकारी स्वयं का प्रतिनिधित्व करते हैं या मामले निजी होते हैं
जिला Collector की अध्यक्षता वाली जिला राजस्व अदालत मुख्य रूप से भू-राजस्व, भूमि सीमाओं और काश्तकारी अधिकारों से जुड़े मामलों का निपटारा करती है। इन मामलों में सामान्यतः निजी पक्षों के बीच भूमि विवाद होते हैं अथवा राजस्व अधिकारी अपनी आधिकारिक क्षमता में मामले प्रस्तुत करते हैं। इसलिए प्रत्येक नियमित राजस्व मामले के लिए

लोक सुनवाई अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या रखकर एक निश्चित समय सीमा के भीतर उसकी औपचारिक सुनवाई और समाधान प्राप्त किया जा सकता है, जिससे प्रशासनिक सुशासन सुदृढ़ होता है।

120. (C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
जिला कलेक्टर जिले में अति विशिष्ट अतिथियों के दौरों के समय मुख्य शिष्टाचार अधिकारी के रूप में कार्य करता है और सभी व्यवस्थाओं की देखरेख करता है। हालांकि, इस दायित्व को निभाते समय कलेक्टर को किसी भी सिविल या आपराधिक कानूनी दायित्व से पूर्ण कानूनी छूट प्राप्त नहीं होती है। यदि कलेक्टर द्वारा किया गया कार्य कानून के दायरे से बाहर या अवैध पाया जाता है, तो उस पर सामान्य कानूनी प्रक्रिया लागू हो सकती है।

121. (B) केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)
राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और प्रशासनिक निष्ठा बनाए रखने हेतु स्थापित राज्य सतर्कता आयोग, केंद्र सरकार के सतर्कता तंत्र में 'केंद्रीय सतर्कता आयोग' (सीवीसी) के समानांतर कार्य करता है। सीवीसी की तर्ज पर यह निकाय राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सतर्कता गतिविधियों का समन्वय करता है, भ्रष्टाचार के मामलों की निगरानी करता है तथा लोक सेवकों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष जांच व्यवस्था सुनिश्चित करता है।

122. (B) शिकायतकर्ता पर मुकदमा चलाया जा सकता है और कारावास से दंडित किया जा सकता है
राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम के तहत लोकायुक्त संस्था के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े वैधानिक प्रावधान किए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर झूठी, भ्रामक या तुच्छ शिकायत दर्ज कराई जाती है, तो लोकायुक्त के पास शिकायतकर्ता के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाने की सिफारिश करने की शक्ति होती है। दोष सिद्ध होने पर झूठी शिकायत करने वाले व्यक्ति को कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

123. (B) जिला कलेक्टर
जिला स्तर पर सरकार की कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन का अंतिम दायित्व जिला कलेक्टर का होता है। कलेक्टर विभिन्न सरकारी विभागों, राशन प्रणालियों और पेंशन योजनाओं की नियमित समीक्षा करता है। वह डेटा सत्यापन और भौतिक जांच के माध्यम से फर्जी या अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने तथा उन्हें सूची से बाहर निकालने के निर्देश देता है, ताकि वास्तविक और पात्र गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे।

124. (C) सिविल सेवा अभ्यर्थियों के बीच अलोकप्रिय होना
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाने के विशिष्ट कानूनी आधार दिए गए हैं, जैसे कि दिवालिया घोषित होना, कार्यकाल के दौरान सवेतन रोजगार में संलग्न होना, अथवा मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ होना। अभ्यर्थियों के बीच अलोकप्रिय होना या किसी परीक्षा व्यवस्था के कारण असंतोष उत्पन्न होना कोई संवैधानिक या कानूनी आधार नहीं है जिसके तहत राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी सदस्य को हटा सकें।

125. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
विभिन्न शिकायत निवारण मंचों का प्राथमिक ध्यान अलग-अलग क्षेत्रों पर केंद्रित है। सूचना का अधिकार अधिनियम सरकारी अभिलेखों और सूचनाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम का उद्देश्य अधिसूचित नागरिक सेवाओं का समयबद्ध प्रावधान सुनिश्चित करना है। राजस्थान संपर्क पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित जन शिकायत निवारण का केंद्रीकृत मंच है, जबकि लोकायुक्त लोक सेवकों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच करता है।

126. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
सूचना का अधिकार अधिनियम एक मांग-आधारित कानून है जो स्वतः लागू नहीं होता, बल्कि इसके लिए नागरिकों को स्वयं आगे बढ़कर सूचना हेतु औपचारिक आवेदन दाखिल करना होता है। इसलिए, राज्य सूचना आयोग की सफलता और प्रभावशीलता पूरी तरह से समाज में नागरिक जागरूकता, सक्रियता और नागरिक समाज संगठनों की सहभागिता पर निर्भर करती है। जब नागरिक जागरूक होकर सूचना मांगते हैं, तभी यह वैधानिक संस्था सुशासन सुनिश्चित कर पाती है।

127. (B) राज्य वित्त आयोग
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-I तथा 243-Y के प्रावधानों के तहत गठित 'राज्य वित्त आयोग' स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (पंचायतों और नगरपालिकाओं) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। यह आयोग राज्य के करों, शुल्कों और पथकरों से प्राप्त कुल राजस्व में से स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए जाने वाले हिस्से की सिफारिश राज्यपाल को करता है, जिससे ग्रामीण और शहरी निकायों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकें।

128. (B) सदस्य पदों में रिक्तियां और अपर्याप्त सहायक कर्मचारी
राजस्थान में विभिन्न निगरानी निकायों (जैसे राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग और लोकायुक्त) की कार्यप्रणाली के समक्ष एक प्रमुख प्रणालीगत बाधा सदस्यों और अध्यक्षों के पदों का समय पर न भरा जाना है। इसके साथ ही, इन निकायों में जांच अधिकारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की कमी के कारण लंबित अपीलों तथा शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, जिससे न्याय मिलने में देरी होती है।

129. (C) P-2, Q-3, R-1, S-4
विभिन्न निकायों के रिपोर्टिंग और अपीलीय प्राधिकारियों का संबंध इस प्रकार है: राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। राज्य निर्वाचन आयोग के फैसलों के खिलाफ संवैधानिक रिट याचिकाएं सीधे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती हैं। जिला कलेक्टर के

Click Here to Buy book on Amazon

राजस्व संबंधी न्यायिक निर्णयों की अपील राजस्व अपीलीय प्राधिकारी या राजस्व मंडल में होती है, जबकि आरपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल एवं विधानमंडल को भेजता है।

130. (B) प्रशासनिक विशेषज्ञता और विषय-ज्ञान
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316(1) के तहत यह अनिवार्य शर्त रखी गई है कि लोक सेवा आयोग के कम से कम आधे सदस्यों को सरकारी सेवा में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इस संवैधानिक प्रावधान का मुख्य उद्देश्य आयोग में प्रशासनिक विशेषज्ञता, विषय-ज्ञान और शासन की व्यावहारिक समझ को शामिल करना है। यह अनुभव आयोग को प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों और पदों के चयन में उच्च स्तर की कुशलता बनाए रखने में सक्षम बनाता है।

www.nodia.in

NODIA

Visit :
www.pdf.tube

Download PDFs For :

- ✓ MPPSC Chapterwise Question Bank
- ✓ KVS/NVS Chapterwise Question Bank
- ✓ KVS/NVS 30 Sample Papers for Tier-II
- ✓ DSSSB TGT Chapterwise Question Bank
- ✓ DSSSB Sample Papers
- ✓ Chapterwise Question Bank
- ✓ JEE NEET Foundation
- ✓ Primary Classes Worksheets
- ✓ Olympiad Guide
- ✓ Sample Papers
- ✓ Previous Year CBSE Papers
- ✓ Previous JEE, NEET and CUET Papers

Nodia Editions LLP

125, Sector 6, Vidhyadhar Nagar, Jaipur 302039

MRP ₹ 450.00

Downloaded from www.pdf.tube